

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

७

(जून-दिसम्बर १९०७)



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

अगस्त १९६२ (श्रावण १८८४ शक)

○ नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६२

साढ़े सात रुपये

कापागउट

नवजानन ट्रस्टका सोज यपूण अनुमतिभ

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमें १९०७ के जूनसे दिसम्बर तक के सात महीनोंकी सामग्री दी गई है। ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियम, जो उपनिवेश मन्त्री द्वारा अस्वीकृत अव्यादेशके स्थानमें बनाया गया था, जैसा हम देख चुके हैं, २१ मार्चको ट्रान्सवाल ससद द्वारा एक ही दिनकी बैठकमें पास कर दिया गया था। उसपर ८ जूनको सम्राटने स्वीकृति दे दी थी और वह १ जुलाईको लागू कर दिया गया था। इस 'खूनी कानून' के विरुद्ध भारतीय समाजका संघर्ष, जो पुराने एम्पायर नाट्यधर्ममें ११ सितम्बर १९०६ को एक विराट सावजनिक सभामें आरम्भ किया गया था, अब अनाक्रामक प्रतिरोध समिति द्वारा चलाया जाने लगा। यह समिति इस कार्यके लिए विशेष रूपमें बनाई गई अस्थायी संस्था थी।

गांधीजीने कानून बननेसे पहले ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिकी तुलना उसके बननेके बादकी स्थितिसे करते हुए कहा था "सारा ट्रान्सवाल ही एक जलील जेलखाना बन जायेगा। नया कानून एशियाइयोंको जिस दुःखद स्थितिमें ला पटकता है, वह सिर्फ उन लोगोंको ही नहीं दिखाई दे सकती, जो शक्तिके मदमें चूर हैं।" (पृष्ठ १९)। कानूनने भारतीयोंपर जो कलक लगा दिया है उसे उमके अंतर्गत बने विनियम मिटा नहीं सकते। यह कानून इसलिए घणित नहीं था कि इसके अन्तर्गत अँगुलियोंके निशान लिये जाते बल्कि इसलिए था कि वह भारतीयोंको ऐसा करनेके लिए बाध्य करता था और उसका इरादा जानबूझकर समाजका अपमान करना था। वह "उनके पौरुषके लिए अपमानजनक और उनके धर्मके हकमें घणित" था। (पृष्ठ २१५)। गांधीजीने प्रस्ताव किया कि यदि कानून रद्द कर दिया जाये तो वे समझौतेके रूपमें स्वेच्छया पजीयन मान लेंगे। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा कि "वे उस उच्चतर धर्मके आगे सिर झुकाये जो मानवजातिको आत्मसम्मान और सच्चाई तथा गम्भीरतासे की हुई घोषणाओंका आदर करनेका आदेश देता है।" (पृष्ठ २३६)। इस उच्चतर धर्मकी शरण लेनेके लिए गांधीजीने ट्रान्सवाल सरकारके 'खूनी कानून' का अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका परामर्श दिया।

किन्तु गांधीजीके लिए अनाक्रामक प्रतिरोध केवल प्रभावकारी राजनीतिक कारवाईका एक रूप नहीं था, जैसा कि वह मताधिकारके लिए संघर्ष करनेवाली ब्रिटिश महिलाओंके लिए था, जिनका प्रशासनिक उल्लेख गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंमें आत्म-सम्मानका भाव भरने और साहस उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हुए अनेक बार किया था। उन्होंने अनाक्रामक प्रतिरोधमें नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वका समावेश किया और थोरोके 'सविनय अवज्ञा' सम्बन्धी प्रबंधमें अपने मिद्धान्तोंका समर्थन देखकर उसे अंग्रेजी और गुजराती दोनोंमें सक्षिप्त किया। किन्तु उन्होंने 'अनाक्रामक प्रतिरोध' शब्दको अपर्याप्त और भ्रामक पाया। उन्होंने कहा कि भारतीयोंका आन्दोलन "वस्तुतः प्रतिरोध नहीं, बल्कि सामूहिक कष्ट-सहनकी नीति है।" (पृष्ठ ६७)। कानूनके विरोधका परिणाम होता जुर्माना। लेकिन भारतीय जुर्माना देनेके बजाय जेल जानेको तैयार थे। अगर परवाने नहीं मिलते तो वे बिना परवाने व्यापार करते। भारतीय कानून तोड़नेके परिणाम जानते थे और उन्हें "शान्तिपूर्ण गौरव और समर्पणके भावसे" (पृष्ठ ८८) सहन करनेको तैयार थे। गांधीजी चाहते थे कि अनाक्रामक

प्रतिराय, जिस रूपसे उन्होंने उसकी कल्पना की थी, धार्मिक शिक्षाका साधन बन जाये। यदि सत्य और 'यायकी' भाग पूरी करनेके लिए मानव निर्मित कानूनको भग करना पड़े तो वह सत्यपर ईमानदारीसे आरुढ़ रहकर किया जाना चाहिए। एक अनुचित कानूनको भग करते हुए स्वयं भारतीय समाजको अपनी व्यक्तिगत और सावजनिक जीवनकी अनेक स्पष्ट वृण्डियोंसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना चाहिए और लगातार इश्वरीय कानूनके आदेशाके अनुसार जीवन बिताना सीखना चाहिए।

गांधीजी अपने जादोलनके आध्यात्मिक तत्त्वपर जो जोर देना चाहते थे वह 'अनाक्रमक प्रतिरोध' शब्दामें स्पष्ट नहीं होता था। वे यह भी अनुभव करते थे कि भारतीयोंको अपने आत्मसम्मानके लिए अपनी भाषाका उपयोग निपुणतासे करना आना चाहिए। इसलिए 'इंडियन ओपिनियन' ने उन शब्दोंका कोई उपयुक्त भारतीय समानार्थक शब्द बतानेके लिए पुरस्कारकी घोषणा की। मगनलाल गांधीने 'सदाग्रह' शब्द सुझाया जिसे गांधीजीने बदलकर 'सत्याग्रह' कर दिया। यह एक उपयुक्त शब्द सिद्ध हुआ, क्योंकि यह गांधीजीकी जीवन भरकी सम्पूर्ण सत्यकी खोजका प्रतीक बन गया।

सघपके फलितार्थों और महत्त्वको पूरी तरहसे जानते हुए, गांधीजी 'इंडियन ओपिनियन'में सप्ताह प्रति-सप्ताह अपने आन्तरिक विचारोंका उडेलते गये। इस प्रकार 'इंडियन ओपिनियन' " भारतीय समाजके तत्काशीन इतिहासका सच्चा दर्पण बन गया ", ('सत्याग्रह इन माउथ आफ्रिका', अध्याय २०)। उन्होंने सघपके प्रत्येक अङ्ककी, उसके कारणों और परिणामाङ्की, उसकी प्रविधियाँ और कार्य-विधियोंकी एवं असफलता और सफलताकी सम्भावनाओंकी, विशेष रूपसे गुजराती लेखामें, निम्नारमें चर्चा की। उन्होंने ईसा और योरो एवं प्राचीन भारतीय गीर-गामागामे आये हुए वगईका प्रतिरोध करनेवाले वीरोसे ही प्रेरणा देनेका प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अपने समयकी मताधिकार आदोलन करनेवाली महिलाआ, ईसाई रुढ़ि-विगधिया, सिन-फेन दलके सदस्या और वोगरोसे भी प्रेरणा ली थी।

पजीयन कार्यालयोपर धरना विगधित किया गया, वह शान्तिपूण और सब प्रकारके 'रोष प्रदान' से मक्त था। उसमें कटु भाषासे वैम ही दूर रहना था जैसे शारीरिक बल प्रयोगसे। जो गोग एशियाई अधिनियमके जुणको टालना चाहते थे, उह इस बातकी भी फिक्र करनी थी कि वे अपने विरोधियोंपर नाममझी-भरी धौस और धमकियोंके रूपमें कही उसमें भी भारी जुआ न डाल दे (पृ० २५८)। धरना प्रभावकारी था — पजीयन कार्यालय नगर-नगर गया, किन्तु बहिष्कारके कारण बेकार रहा। समाजके पाँच प्रतिशतसे कम लोगोंने 'गुलामीका चिट्ठा' लिया, यद्यपि पजीयनकी अवधि अनेक बार बढ़ाई गई। गद्दारोंके, जो 'पियानो बजानेवाले' कहे जाते थे, नाम 'इंडियन ओपिनियन'में छापे गये। इसका उद्देश्य जितना कार्यरोंको लज्जित करना था उतना ही दूसरोंको चेतावनी देना भी था। भय दिलानेकी अपेक्षा आत्मसम्मान अधिक जगाया जाता था। जब भारतीयोंके एक दलने आत्म समर्पणका प्रस्ताव पास किया तब गांधीजीने ४,५०० से अधिक भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे एक "भीमकाय प्रार्थनापत्र" देनेका विचार किया और उसको कार्यावित किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीयोंका बहुत बड़ा भाग कानूनका विरोधी था।

गांधीजीने ब्रिटिश भारतीय सघ, हमीदिया इस्लामिया अजुमन और चीनी सघकी अनेक सभाओंमें भाषण दिये। वे यूरोपीयोंके छोटे-छोटे समूहोंमें बोले और खले मैदानमें

की गई भारतीयोंकी विराट सावजनिक सभाओंमें भी। जब सघष पूरे जोरपर था तब भी उन्होंने आंदोलनके अधिक प्रचलित तरीकोंको जारी रखा। उन्होंने दक्षिण आफ्रिका, भारत और इंग्लैण्डके प्रमुख लोगोंको पत्र लिखे। लंदनमें दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति आवेदन-निवेदनकी और लोक-शिक्षणकी प्रमुख साधन बनी रही। इस खण्डमें ऐसे पत्रोंके, जो उन्होंने गलतफहमी दूर करने, गलतबयानियोंका खण्डन करने और अपने कायके प्रति सहानुभूति जगानेका वैयपूण, सावधानतापूण ओर अथक प्रयत्न करते हुए लिखे, कई उदाहरण हैं। वपके अंतमें वे यह लिख सके कि 'गोरोके सारे अगवार सरकारको बहुत फटकारते हैं और भारतीयोंकी जय बोलते हैं' (पृष्ठ ४४१)।

उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि सघषके उद्देश्य और तरीकोंका महत्व स्थानीय या अस्थायीसे अधिक है, और वे जानते थे कि उनका महत्व सब स्थानोंके मनुष्योंके लिए है। "टान्सवालके भारतीय एक बंद खून गिगाये बिना ही मानव जातिको विस्मित कर देगे" (पृष्ठ ११९) ओर ब्रिटिश राजनीतिज्ञताकी यह एक खरी कसौटी थी साम्राज्यका हाथ सबल गोरोमें निबल भारतीयोंकी रक्षा करेगा अथवा दुबलो और असहायोंको कुचलनेमें अत्याचारीके हाथोंको मजबूत करेगा? (पृष्ठ ८८)। किन्तु अब भी ब्रिटिश संस्थाओंमें गांधीजीका विश्वास ढिगा नहीं था, उन्होंने लिखा "मैंने जिन बातोंको इस साम्राज्यकी खूबी समझा है उनके कारण मैं अपनेको उसका भक्त मानता हूँ। इसीलिए मैंने यह देखकर—चाहे मेरा देखना सही हो या गलत—कि एशियाई कानून सशोषण अविनियममें साम्राज्यके लिए खतरेके बीज छिपे हुए हैं, अपने देशवासियोंको किसी भी कीमतपर, अत्यंत शान्तिपूण और, कहूँ तो, शिष्ट ढंगमें इस अविनियमका विरोध करनेकी सलाह दी है" (पृष्ठ ४०५)।

किन्तु टान्सवालकी सरकारने इन अपीलोंपर कोई कार्रवाई नहीं की। दिसम्बरमें, जिस दिन ट्रान्सवाल प्रवासी अविनियमपर मन्नाटकी स्वीकृति 'गजट' में प्रकाशित की गई, उसी दिन जनरल स्मट्सने गांधीजी और अन्य नेताओंपर मुकदमे चलानेका निश्चय किया। गांधीजीने इस बातका यह मानकर स्वागत किया कि "वास्तवमें यही एक तरीका है जिसमें एशियाई भावनाकी व्यापकता और असलियतकी परख हो सकती है" (पृष्ठ ४६५)।

न्यायालयमें चलाये गये वे मुकदमे, जिनमें अब गांधीजी अधिकांशतः अनाक्रामक प्रति-रोधियोंके बचावके लिए खड़े हुए, उनके बंधे और सावजनिक जीवनकी एक नई अवस्थाके सूचक हैं। एक चतुर वकील होनेके कारण, वे विरोधी कानूनोंकी खुली चुनौतीका उपयोग लोकमत शिक्षणके साधनके रूपमें कर सके। उन्होंने अपने मुवक्किलोंको परामर्श दिया कि वे अपनेको निर्दोष बताये, ताकि अदालत उनके अपने मुखसे ही सुन सके कि उहे क्या कहना है (पृष्ठ ४६३)। इन मुकदमोंने उनके आंदोलनका अबतक के सब प्राथनापत्रों और शिष्टमण्डलोंकी अपेक्षा अधिक प्रचार किया। इनसे साम्राज्य सरकार जाग्रत होने और उन घटनाओंको देखनेके लिए बाध्य हो गई, जो विश्वके इतिहासमें सबसे अधिक सम्य होनेका दावा करनेवाले साम्राज्यके नागरिकोंके साथ घटित हो रही थी।

पाठकोको सूचना

विभिन्न अधिकारियोंको लिखे गये प्राथनापत्र और निवेदन, अखबारोंको भेजे गये पत्र और सभाओंमें स्वीकृत किये गये प्रस्ताव जो इस खण्डमें सम्मिलित किये गये हैं उनको गांधीजीका लिखा माननेके कारण वैसे ही हैं जैसे कि खण्ड १ की भूमिकामें दिये जा चुके हैं। जहां किसी लेखको सम्मिलित करनेके विशेष कारण हैं वहां वे पाद टिप्पणीमें बता दिये गये हैं। 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित गांधीजीके लेख, जिनपर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, उनके आत्मकथा सम्बन्धी लेखोंके सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगनलाल गांधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और अथ उपलब्ध प्रमाण सामग्रीके आधारपर पहचाने गये हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीमें अनुवाद करनेमें अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अनुवाद छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमें व्यवहृत शब्दोंके सक्षिप्त रूप यथासम्भवा पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके उच्चारण सन्दिग्ध ह उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीचमें चौकोर कोष्ठकोमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अश अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर, साधारण टाइपमें ही छापा गया है। इस खण्डमें उपलब्ध भाषणोंके परोक्ष विवरण और न्यायालयोंके काय-विवरण तथा वे शब्द, जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े, गहरी स्याहीमें छापे गये हैं।

शीषकोकी लेखन तिथियां जहां उपलब्ध हैं वहां दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई हैं, किन्तु जहां वे उपलब्ध नहीं हैं वहां उनकी पूर्ति अनुमानों चौकोर कोष्ठकोमें की गई हैं और जहां आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीषकोके अन्तमें सूत्रके साथ दी गई तिथियाँ प्रकाशन की हैं।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनों इतिहास' के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पट्ट संख्याएँ विभिन्न हैं, इसलिए हवाला देनमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

साधन सूत्रोंमें एस० एन० सकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागजपत्रोंका और सी० डब्ल्यू० कलेक्ट्रेड वक्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडमय) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है। सूत्र पत्रितमें कभी-कभी शब्दोंके सक्षिप्त रूप मिलते हैं उनमें सी० ओ० कॅनेनियल ऑफिसका और जे० एंड पी० ज्यूडिशियल और पब्लिक रेकॉर्डसका सक्षिप्त रूप है।

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी गई है। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डमें सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए, हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक ट्रस्ट और संग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, और नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, गांधी स्मारक निधि तथा संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत सेवक समिति, पूना, कलोनियल आफिस पुस्तकालय, तथा इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, लंदन, फीनिक्स आश्रम डबन, प्रिटोरिया आकाद्वज, प्रिटोरिया, श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद, श्री अरुण गांधी बम्बई, और 'इंडियन ओपिनियन', 'रड डेली मेल', 'स्टार' और 'ट्रान्सवाल लीडर' समाचारपत्रोंके आभारी हैं।

अनुसंधान और सदस्योंकी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कोसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, ओर सूचना एवं प्रसार मंत्रालयके अनुसंधान और सदस्य विभाग, नई दिल्ली, साबरमती संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, सावजनिक पुस्तकालय, जोहानिसबर्ग, और ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय, लंदन हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	५
पाठकोका सूचना	९
आभार	११
चित्र सूची	२३
१ जूरियोकी कसाटी (१-६-१९०७)	१
२ वीर क्या करे ? (१-६-१९०७)	३
३ एक पोडका इनाम (१-६-१९०७)	५
४ भारतमे उथल पुथल (१-६-१९०७)	६
५ भारतीय राजा (१-६-१९०७)	७
६ जोहानिसबगकी चिट्ठी (१-६-१९०७)	९
७ भारतके सेवक (१-६-१९०७)	१३
८ तार नैयबको (१-६-१९०७)	१४
९ पत्र प्रधानमंत्रीके सचिवको (१-६-१९०७)	१४
१० सच्ची राये (८-६-१९०७)	१५
११ केपका प्रगसी काना (८-६-१९०७)	१५
१२ एशियाई पजीयन अग्रिनियम (८-६-१९०७)	१६
१३ नया खूनी कानून (८-६-१९०७)	१९
१४ समितिकी भूल (८-६-१९०७)	२५
१५ केपके भारतीय (८-६-१९०७)	२६
१६ स्वर्गीय काल ब्लाड्ड (८-६-१९०७)	२७
१७ हिन्दू विधवाएँ क्या कर सकती हैं ? (८-६-१९०७)	२७
१८ जोहानिसबगकी चिट्ठी (८-६-१९०७)	२८
१९ अफगानिस्तानमे मुसलमानोकी हालत (८-६-१९०७)	३४
२० पत्र 'स्टार' का (८-६-१९०७)	३५
२१ पत्र प्रधानमंत्रीके सचिवको (१२-६-१९०७)	३७
२२ पत्र छगनलाल गाधीको (१२-६-१९०७)	३८
२३ शाही स्वीकृति (१५-६-१९०७)	३९
२४ काननका अत्याचार (१५-६-१९०७)	४०
२५ रोडेशिया और ट्रान्सवाल (१५-६-१९०७)	४१
२६ गिरमिटिया भारतीय मजदूर (१५-६-१९०७)	४१
२७ पूवका ज्ञान (१५-६-१९०७)	४२
२८ जोहानिसबगकी चिट्ठी (१५-६-१९०७)	४३

त्र उपनिवेश सचिवको (१८-६-१९०७)	४७
ये कानूनसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता (२२-६-१९०७)	४७
टाल भागतीय कांग्रेस (२२-६-१९०७)	४९
टालमे जेलका कानून (२२-६-१९०७)	५०
जाज रलवे (२२-६-१९०७)	५०
सुफ अली और स्त्री शिक्षा (२२-६-१९०७)	५१
गोहानिसबगकी चिट्ठी (२२-६-१९०७)	५१
गिम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा (२२-६-१९०७)	५४
गोहानिसबगकी चिट्ठी (२६-६-१९०७)	५६
मेट 'रैंड डेली मेल' को (२८-६-१९०७)	६०
क्रॉड ऐम्स्टहिल (२९-६-१९०७)	६२
अंगद वार्ता (२९-६-१९०७)	६३
दक्षिण आफ्रिकामें अकाल (२९-६-१९०७)	६४
लॉड ऐम्स्टहिल (२९-६-१९०७)	६५
इंग्लैंडकी वहादुर स्त्रिया (२९-६-१९०७)	६५
भारत और ट्रान्सवाल (२९-६-१९०७)	६६
कन्याओंकी शिक्षा (२९-६-१९०७)	६६
भाषण प्रिटोरियाकी सभामें (३०-६-१९०७)	६६
पत्र 'रैंड डेली मेल' को (१-७-१९०७)	६७
जोहानिसबगके ताजे समाचार (३-७-१९०७)	६९
पत्र 'स्टार' को (४-७-१९०७)	७०
खागमे घी (६-७-१९०७)	७१
एक टेक (६-७-१९०७)	७२
समितिकी सलाह (६-७-१९०७)	७४
कैसी दशा ! (६-७-१९०७)	७४
मेटाल, तू जागता है या सोता ? (६-७-१९०७)	७५
सूनी कानून (६-७-१९०७)	७५
प्रिटोरियाकी आम सभा (६-७-१९०७)	८०
मेट 'रैंड डेली मेल' के प्रतिनिधिको (६-७-१९०७)	८२
जोहानिसबगकी चिट्ठी (६-७-१९०७)	८३
पत्र 'रैंड डेली मेल' को (६-७-१९०७)	८६
पत्र 'स्टार' को (७-७-१९०७)	८८
जोहानिसबगकी चिट्ठी (८-७-१९०७)	८९
पत्र 'स्टार' को (९-७-१९०७)	९२
ट्रान्सवालकी नया प्रवासी विधेयक (११-७-१९०७ के पूर्व)	९३
ट्रान्सवालकी नया प्रवासी विधेयक (११-७-१९०७ के पूर्व)	९५
ट्रान्सवालकी नया प्रवासी विधेयक (११-७-१९०७ के पूर्व)	९६

६६	भारतीयाकी कसोटी (१३-७-१९०७)	९७
६७	डवनका कतव्य (१३-७-१९०७)	९८
६८	पूव ज्ञानमाला (१३-७-१९०७)	९९
६९	भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे (१४-७-१९०७)	९९
७०	जोहानिसवगकी चिटठी (१५-७-१९०७)	१००
७१	पत्र उपनिवेश सचिवको (१६-७-१९०७)	१०५
७२	घोर मान हानि (२०-७-१९०७)	१०६
७३	ट्रांसवाल प्रवासी विवेकपर बहस (२०-७-१९०७)	१०७
७४	गिरमिटिया प्रवासी (२०-७-१९०७)	१०९
७५	जनरल स्मटसका हठ (२०-७-१९०७)	११०
७६	द० आ० ब्रि० भा० समितिका काम (२०-७-१९०७)	११०
७७	लाविटो बे (२०-७-१९०७)	१११
७८	नेटालमे परवाने ओर टिकटका विधेयक (२०-७-१९०७)	११२
७९	गिरमिटिया भारतीय (२०-७-१९०७)	११३
८०	भाषण नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामे (२०-७-१९०७)	११४
८१	प्राथनापत्र ट्रान्सवाल विधान-परिषदको (२२-७-१९०७)	११५
८२	प्राथनापत्र नेटाल विधान-सभाको (२५-७-१९०७)	११७
८३	परवाना कार्यालयके बहिष्कारका भित्तिपत्र (२६-७-१९०७ के पूव)	११८
८४	प्रिटोरियाकी लडाई (२६-७-१९०७)	११८
८५	'मानवजातिका विस्मय' (२७-७-१९०७)	११९
८६	श्री पारमी रुस्तमजीकी उदारता (२७-७-१९०७)	१२०
८७	श्री आदमजी मियाँखाकी मृत्यु (२७-७-१९०७)	१२१
८८	आदमजी मियाँखाका शोकजनक अवसान (२७-७-१९०७)	१२२
८९	खुदाई कानून (२७-७-१९०७)	१२२
९०	अलीकी भूल (२७-७-१९०७)	१२४
९१	केपके भारतीय (२७-७-१९०७)	१२५
९२	वमपर हमला (२७-७-१९०७)	१२६
९३	ईस्ट लंदनको चेतावनी (२७-७-१९०७)	१२८
९४	रूसका उदाहरण (२७-७-१९०७)	१२८
९५	जोहानिसवगकी चिटठी (२७-७-१९०७)	१२९
९६	पत्र उपनिवेश-सचिवको (२७-७-१९०७)	१३४
९७	जोहानिसवगकी चिटठी (२९-७-१९०७)	१३५
९८	भाषण प्रिटोरियामे (३१-७-१९०७)	१३९
९९	प्रिटोरियाकी सावजनिक सभाके प्रस्ताव (३१-७-१९०७)	१४२
१००	भेट 'रेड डेली मेल' को (३१-७-१९०७)	१४३
१०१	ट्रान्सवालकी लडाई (३-८-१९०७)	१४३
१०२	नेटालके भारतीयामे जागति (३-८-१९०७)	१४४

१०३ जोहानिसप्रगकी चिट्ठी (५-८-१९०७)	१८५
१०४ तार मी० वडको (८-८-१९०७)	१८८
१०५ पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवका (८-८-१९०७)	१८८
१०६ तार प्रिटारिया समितिको (१०-८-१९०७ के पूर्व)	१५१
१०७ श्री हाम्पेनकी "अवश्यभावी" (१०-८-१९०७)	१५१
१०८ श्री अलीका प्रिरो (१०-८-१९०७)	१५३
१०९ टान्मवालके भारतीय (१०-८-१९०७)	१५३
११० अब क्या होगा ? (१०-८-१९०७)	१५४
१११ समितिकी लडाई (१०-८-१९०७)	१५५
११२ जनरल स्मट्सका उत्तर (१०-८-१९०७)	१५५
११३ अलीका पत्र (१०-८-१९०७)	१५६
११४ हमारा कतव्य (१०-८-१९०७)	१५६
११५ केपके भारतीय (१०-८-१९०७)	१५७
११६ एस्टकाटकी अपील (१०-८-१९०७)	१५८
११७ रामका पत्र (१०-८-१९०७)	१५८
११८ उन्नती कृषि-समितिका जोशपन (१०-८-१९०७)	१५९
११९ उमर हाजी आमद जवरी (१०-८-१९०७)	१५९
१२० एक पारसी महिलाकी हिम्मत (१०-८-१९०७)	१६०
१२१ भाषण श्रीदिया उरुमिया जजुमने (११-८-१९०७)	१६०
१२२ तार पीटमसगन भारतायाका (११-८-१९०७)	१६२
१२३ तार पाचफुमके भारतायाका (११-८-१९०७)	१६२
१२४ पत्र 'रैड डेली मेल' को (१२-८-१९०७)	१६३
१२५ पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवका (१५-८-१९०७)	१६४
१२६ भारतीय प्रस्तावका क्या अर्थ ? (१७-८-१९०७)	१६६
१२७ पारमसगन प्रसार (१७-८-१९०७)	१६७
१२८ तत्मानका पत्र (१७-८-१९०७)	१६८
१२९ नगरपालिकापालिका चतारनी (१७-८-१९०७)	१६८
१३० धाया (१७-८-१९०७)	१६९
१३१ मासिक उपद्रव (१७-८-१९०७)	१७०
१३२ तार साहसका तथा फर्म (१७-८-१९०७)	१७०
१३३ तार उन्नत ब्राजी पाना राखनका सानन (१७-८-१९०७)	१७१
१३४ जाहानिसप्रगकी चिट्ठी (१७-८-१९०७)	१७२
१३५ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' का (१७-८-१९०७)	१७७
१३६ पत्र 'स्टार' को (१९-८-१९०७)	१७८
१३७ भारतीय मुसलमानोसे अपील (१९-८-१९०७)	१७९
१३८ पत्र 'स्टार' को (२०-८-१९०७)	१८१
१३९ पत्र 'रैड डेली मेल' को (२०-८-१९०७)	१८२

१८० आवेदनपत्र उपनिवेशमन्त्रीको (२३-८-१९०७)	१८३
१४१ तार द० आ० ब्रि० भा० समितिको (२३-८-१९०७ के बाद)	१८८
१४२ प्रस्तावित समझौता (२४-८-१९०७)	१८९
१४३ खुले दिलकी सहानुभूति (२४-८-१९०७)	१९०
१४४ पाठकोको सूचना (२४-८-१९०७)	१९०
१४५ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (२४-८-१९०७)	१९१
१४६ श्री गांधीकी सूचना (२४-८-१९०७)	१९१
१४७ क्या हम 'याय परिषद' में जा सकते हैं? (२४-८-१९०७)	१९२
१४८ क्या नेटालमें खूनी कानून बन सकता है? (२४-८-१९०७)	१९३
१४९ सच्चा मित्र (२४-८-१९०७)	१९३
१५० हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र (२४-८-१९०७)	१९४
१५१ एस्टकोटकी अपील (२४-८-१९०७)	१९४
१५२ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२४-८-१९०७)	१९५
१५३ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको (२८-८-१९०७)	१९९
१५४ प्रवास प्रार्थनापत्र (३१-८-१९०७)	१९९
१५५ केपके भारतीय (३१-८-१९०७)	२०१
१५६ लेडीस्मिथके व्यापारी (३१-८-१९०७)	२०१
१५७ दादाभाई जयंती (३१-८-१९०७)	२०२
१५८ बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता (३१-८-१९०७)	२०३
१५९ लेडीस्मिथके परवाने (३१-८-१९०७)	२०४
१६० 'हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन वृत्तांत' क्यों बढ़ हुआ? (३१-८-१९०७)	२०५
१६१ केप टाउनके भारतीय (३१-८-१९०७)	२०६
१६२ बहादुरी किसे कहा जाये? (३१-८-१९०७)	२०६
१६३ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (३१-८-१९०७)	२०७
१६४ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको (१-९-१९०७ के पूर्व)	२०९
१६५ तार दादाभाई नौरोजीको (४-९-१९०७)	२१०
१६६ भाषण डबनमें (४-९-१९०७)	२१०
१६७ भाषण कांग्रेसकी सभामें (४-९-१९०७)	२११
१६८ पत्र उपनिवेश-सचिवको (७-९-१९०७ के पूर्व)	२१३
१६९ सविनय अवज्ञाका वम (७-९-१९०७)	२१४
१७० 'इंडियन ओपिनियन' का परिशिष्टांक (७-९-१९०७)	२१६
१७१ सुस्वागतम् (७-९-१९०७)	२१६
१७२ अनाक्रमक प्रतिरोधके लाभ (७-९-१९०७)	२१७
१७३ प्रधानमन्त्रीके विचार (७-९-१९०७)	२१८
१७४ नेटाल नगरपालिका मताधिकार अधिनियम (७-९-१९०७)	२१९
१७५ डॉक्टर नडीकी पुस्तिका (७-९-१९०७)	२२०
१७६ कानूनका विरोध—एक कतव्य [१] (७-९-१९०७)	२२०

१७७ डबनमे अँगुलियोकी छाप देनेका आतक (७-९-१९०७)	२२२
१७८ जोहानिसबगकी चिट्ठी (७-९-१९०७)	२२३
१७९ पत्र एशियाई पजीयकको (११-९-१९०७)	२२७
१८० न घरके न घाटके (१४-९-१९०७)	२२८
१८१ क्या दशा होगी ? (१४-९-१९०७)	२२८
१८२ "कानूनके सामने मोम" (१४-९-१९०७)	२२९
१८३ रिचका प्रयास (१४-९-१९०७)	२३०
१८४ भारतीयोकी परेशानी (१४-९-१९०७)	२३०
१८५ कानूनका विरोध — एक कतव्य [२] (१४-९-१९०७)	२३१
१८६ जोहानिसबगकी चिट्ठी (१४-९-१९०७)	२३३
१८७ पत्र डब्ल्यू० वी० हल्स्टेनको (१७-९-१९०७)	२३५
१८८ तार गो० कृ० गोखलेको (२१-९-१९०७ के पूर्व)	२३७
१८९ भीमकाय प्रायनापत्र (२१-९-१९०७ के पूर्व)	२३७
१९० भीमकाय प्रायनापत्र (२१-९-१९०७)	२३९
१९१ वीनेन परवानेकी अपील (२१-९-१९०७)	२४०
१९२ ट्रान्सवालकी लडाई (२१-९-१९०७)	२४१
१९३ नेटालका परवाना कानून (२१-९-१९०७)	२४२
१९४ भारतीय सावजनिक पुस्तकालय (२१-९-१९०७)	२४३
१९५ भारतसे कुमुक (२१-९-१९०७)	२४३
१९६ अँगूठा निशानीका कानून (२१-९-१९०७)	२४४
१९७ जोहानिसबगकी चिट्ठी (२१-९-१९०७)	२४५
१९८ पत्र प्रधानमंत्रीके सचिवको (२१-९-१९०७)	२५०
१९९ पत्र जे० ए० नैसरको (१४-९-१९०७)	२५२
२०० जोहानिसबगकी चिट्ठी (२५-९-१९०७)	२५३
२०१ तार सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको (२५-९-१९०७ के बाद)	२५६
२०२ भारतस सहायता (२८-९-१९०७)	२५७
२०३ धरनेदारका कतव्य (२८-९-१९०७)	२५७
२०४ जनरल बाथा और एशियाई कानून (२८-९-१९०७)	२५८
२०५ भारतीय फेरीवालाके खिलाफ लडाई (२८-९-१९०७)	२५९
२०६ हमारा परिशिष्ट (२८-९-१९०७)	२६०
२०७ स्वयंसेवकोका कतव्य (२८-९-१९०७)	२६०
२०८ क्या भारत जाग गया ? (२८-९-१९०७)	२६१
२०९ "बीच रुई जरि जाय" (२८-९-१९०७)	२६१
२१० मिन्नमें स्वराज्यका आन्दोलन (२९-९-१९०७)	२६२
२११ पत्र जे० ए० नैसरको (२८-९-१९०७)	२६२
२१२ पत्र 'रैंड डेली मेल' को (२८-९-१९०७)	२६४
२१३ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें (२९-९-१९०७)	२६५

२१४	प्राथनापत्र तुर्कीके महा वाणिज्य दूतको (५-१०-१९०७ के पूर्व)	२६६
२१५	जॉज गाडफ्रे (५-१०-१९०७)	२६६
२१६	गरीब किंतु बहादुर भारतीय (५-१०-१९०७)	२६७
२१७	भारतीय मतदाता (५-१०-१९०७)	२६७
२१८	केपमे सघ (५-१०-१९०७)	२६८
२१९	जोहानिसबगकी चिट्ठी (५-१०-१९०७)	२६८
२२०	पत्र मगनलाल गाधीको (६-१०-१९०७)	२७३
२२१	पत्र उपनिवेश सचिवको (७-१०-१९०७)	२७४
२२२	पत्र 'रैंड डेली मेल' को (९-१०-१९०७)	२७६
२२३	केपके भारतीय (१२-१०-१९०७)	२७७
२२४	'इंडियन ओपिनियन' के बारेमे (१२-१०-१९०७)	२७८
२२५	दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (१२-१०-१९०७)	२७९
२२६	स्मट्सका भाषण (१२-१०-१९०७)	२८०
२२७	वाईबगका भाषण (१२-१०-१९०७)	२८२
२२८	केपके भारतीय (१२-१०-१९०७)	२८२
२२९	जोहानिसबगकी चिट्ठी (१२-१०-१९०७)	२८४
२३०	द० आ० ब्रि० भा० समितिको पत्र (१४-१०-१९०७ के पूर्व)	२८९
२३१	पत्र मगनलाल गाधीको (१४-१०-१९०७)	२९०
२३२	पत्र पुलिस कमिश्नरको (१५-१०-१९०७)	२९०
२३३	पत्र 'स्टार' को (१८-१०-१९०७)	२९१
२३४	रिचकी सेवाएँ (१९-१०-१९०७)	२९३
२३५	जनरल बोथाका अनुकरण (१९-१०-१९०७)	२९३
२३६	पीटसके मुकदमेसे लेने योग्य सीख (१९-१०-१९०७)	२९४
२३७	रिचकी सेवाएँ (१९-१०-१९०७)	२९५
२३८	ट्रान्सवालमे दूकान बन्द करनेके समयका कानून (१९-१०-१९०७)	२९५
२३९	जोहानिसबगकी चिट्ठी (१९-१०-१९०७)	२९६
२४०	पत्र 'स्टार' को (२४-१०-१९०७)	३०१
२४१	पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को (२६-१०-१९०७ के पूर्व)	३०२
२४२	स्वर्गीय श्री अलेक्जैंडर (२६-१०-१९०७)	३०४
२४३	अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके लिए (२६-१०-१९०७)	३०५
२४४	राष्ट्र-पितामह (२६-१०-१९०७)	३०६
२४५	मेमन लोगोकी विपरीत बुद्धि (२६-१०-१९०७)	३०६
२४६	ट्रान्सवालके भारतीयोंका कतव्य (२६-१०-१९०७)	३०७
२४७	लेडीस्मिथके भारतीय व्यापारी (२६-१०-१९०७)	३०८
२४८	भारतके राष्ट्र पितामह (२६-१०-१९०७)	३०९
२४९	स्वर्गीय अधीक्षक अलेक्जैंडर (२६-१०-१९०७)	३०९
२५०	जोहानिसबगकी चिट्ठी (२६-१०-१९०७)	३१०

२५१ पत्र सर विलियम वेडरबनको (३१-१०-१९०७ के पूर्व)	३१९
२५२ पत्र उपनिवेश सचिवको (१-११-१९०७)	३२०
२५३ पत्र 'ट्रांसवाल लीडर' को (१-११-१९०७)	३२२
२५४ पत्र सर विलियम वेडरबनको (२-११-१९०७ के पूर्व)	३२३
२५५ जनरल स्मट्सकी बहादुरी (?) (२-११-१९०७)	३२४
२५६ सच्ची मित्रता (२-११-१९०७)	३२५
२५७ ब्रूमफॉटोनका 'मित्र' फिर भारतीयोंकी सहायतापर (२-११-१९०७)	३२५
२५८ लन्दनमें मुसलमानोंकी बैठक (२-११-१९०७)	३२८
२५९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२-११-१९०७)	३२८
२६० पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको (४-११-१९०७)	३३२
२६१ पत्र अखबारोंको (६-११-१९०७)	३३४
२६२ श्री लैबिस्टर (९-११-१९०७)	३३७
२६३ ईद मुबारक (९-११-१९०७)	३३८
२६४ नया वष शुभ हो (९-११-१९०७)	३३८
२६५ समझदारके लिए इशारा (९-११-१९०७)	३३९
२६६ बढ़ाई गई अवधि (९-११-१९०७)	३४०
२६७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (९-११-१९०७)	३४०
२६८ पत्र 'ट्रांसवाल लीडर' को (९-११-१९०७)	३४८
२६९ पत्र जनरल स्मट्सको (९-११-१९०७)	३४९
२७० रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा (११-११-१९०७)	३५१
२७१ भेट 'ट्रांसवाल लीडर' को (११-११-१९०७)	३५१
२७२ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा (१४-११-१९०७)	३५२
२७३ प्रस्ताव सावजनिक सभामें (१४-११-१९०७)	३५६
२७४ पत्र गो० कृ० गोखलेको (१४-११-१९०७)	३५७
२७५ अग्नेदारोंके विरुद्ध मुकदमा (१५-११-१९०७)	३५७
२७६ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को (१५-११-१९०७)	३५९
२७७ कैक्सटन हॉलकी सभा (१६-११-१९०७)	३६०
२७८ लाजपतरायकी रिहाई (१६-११-१९०७)	३६१
२७९ सम्राटकी सालगिरह (१६-११-१९०७)	३६२
२८० लन्दनमें मुसलमानोंकी सभा (१६-११-१९०७)	३६२
२८१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चन्दा (१६-११-१९०७)	३६२
२८२ बचे हुए मेमन (१६-११-१९०७)	३६३
२८३ पण्डितजीका जीवन-चरित्र (१६-११-१९०७)	३६३
२८४ भारतके लालाजीने क्या किया ? (१६-११-१९०७)	३६३
२८५ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा (१६-११-१९०७)	३६५
२८६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (१६-११-१९०७)	३६७
२८७ डर्बनमें दीवाली महोत्सव (१६-११-१९०७)	३७१

२८८ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे (१७-११-१९०७)	३७२
२८९ पत्र भारतके वाइसरायको (१८-११-१९०७)	३७२
२९० ट्रांसवालके भारतीयोंको सूचना (१९-११-१९०७)	३७४
२९१ पत्र मणिलाल गांधीको (२१-११-१९०७)	३७४
२९२ पत्र गो० कृ० गोखलेको (२२-११-१९०७)	३७५
२९३ पत्र 'ट्रांसवाल लीडर' को (२३-११-१९०७ के पूर्व)	३७६
२९४ पण्डितजीकी देण सेवा (२३-११-१९०७)	३७७
२९५ धरनेदारोंका मुकदमा (२३-११-१९०७)	३७७
२९६ कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि (२३-११-१९०७)	३७८
२९७ केपके भारतीय कब जागेंगे ? (२३-११-१९०७)	३७८
२९८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२३-११-१९०७)	३७९
२९९ भाषण हमीदिया अजुमनकी सभामे (२४-११-१९०७)	३८२
३०० प्राथनापत्र गायकवाडको (२५-११-१९०७)	३८३
३०१ प्राथनापत्र उच्चायुक्तको (२६-११-१९०७ के पूर्व)	३८४
३०२ पत्र अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षको (२६-११-१९०७ के पूर्व)	३८५
३०३ जाहानिसबर्गकी चिट्ठी (२६-११-१९०७)	३८६
३०४ भाषण चीनी सभामे (२७-११-१९०७)	३९४
३०५ हम विरोध क्यों करते हैं (३०-११-१९०७)	३९६
३०६ हम कानूनके विरुद्ध क्यों ? (३०-११-१९०७)	३९७
३०७ हमारा परिशिष्ट (३०-११-१९०७)	३९९
३०८ खूनी कानून तथा उसके अंतगत बनाये गये विनियम (३०-११-१९०७)	४००
३०९ पत्र उच्चायुक्तके निजी सचिवको (३-१२-१९०७)	४०५
३१० मुहम्मद इशाकका मुकदमा (६-१२-१९०७)	४०७
३११ पत्र उपनिवेश सचिवको (७-१२-१९०७ के पूर्व)	४०८
३१२ पत्र उच्चायुक्तको (७-१२-१९०७ के पूर्व)	४०९
३१३ रिचकी सेवाएँ (७-१२-१९०७)	४१०
३१४ कानून स्वीकार करनेवालोंका क्या होगा ? (७-१२-१९०७)	४११
३१५ रामसुन्दर पण्डित (७-१२-१९०७)	४१२
३१६ नेटालमे युद्ध स्वयंसेवक (७-१२-१९०७)	४१२
३१७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (७-१२-१९०७)	४१३
३१८ भारतीयोंका मुकदमा (९-१२-१९०७)	४१९
३१९ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को (१२-१२-१९०७)	४२१
३२० स्वर्गीय आराथून (१४-१२-१९०७)	४२२
३२१ फोक्सरेस्टके मुकदमे (१४-१२-१९०७)	४२३
३२२ नेटाल परवाना अधिनियम (१४-१२-१९०७)	४२३
३२३ स्वर्गीय नवाब मोहसीन उल-मुल्क (१४-१२-१९०७)	४२४
३२४ जमन पूर्व आफ्रिका लाइन (१४-१२-१९०७)	४२४

३२५	भारतीयोपर हमला (१४-१२-१९०७)	४२५
३२६	नेटालमे परवाना सम्बन्धी अर्जीके विनियम (१४-१२-१९०७)	४२७
३२७	जोहानिसबगकी चिट्ठी (१४-१२-१९०७)	४२८
३२८	पत्र उपनिवेश सचिवको (१४-१२-१९०७)	४३४
३२९	पत्र उपनिवेश सचिवको (१८-१२-१९०७)	४३५
३३०	पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको (२०-१२-१९०७)	४३६
३३१	अधीरता (२१-१२-१९०७)	४३७
३३२	रामसुन्दर पण्डित (२१-१२-१९०७)	४३८
३३३	हाजी हबीब (२१-१२-१९०७)	४३८
३३४	रामसुन्दर पण्डित (२१-१२-१९०७)	४३९
३३५	जोहानिसबगकी चिट्ठी (२१-१२-१९०७)	४३९
३३६	पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको (२१-१२-१९०७)	४४३
३३७	भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे (२२-१२-१९०७)	४४४
३३८	भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे (२७-१२-१९०७)	४४४
३३९	डेलगोआ-बेके भारतीय (२८-१२-१९०७)	४४७
३४०	बेराजगार लोगोका क्या किया जाये ? (२८-१२-१९०७)	४४८
३४१	वहादुर स्त्रिया (२८-१२-१९०७)	४४९
३४२	डेलगोआ-बेके भारतीय (२८-१२-१९०७)	४५०
३४३	दाऊद मुहम्मदको बधाई (२८-१२-१९०७)	४५०
३४४	कुछ अंग्रेजी शब्द (२८-१२-१९०७)	४५१
३४५	भारतकी दशा (२८-१२-१९०७)	४५१
३४६	अरबी ज्ञान (२८-१२-१९०७)	४५३
३४७	जोहानिसबगकी चिट्ठी (२८-१२-१९०७)	४५४
३४८	जोहानिसबगमे मुकदमा (२८-१२-१९०७)	४५८
३४९	श्री पी० के० नायडू और अय लोगोका मुकदमा (२८-१२-१९०७)	४६०
३५०	भाषण सरकारी चौकमे (२८-१२-१९०७)	४६४
३५१	पत्र 'स्टार' को (३०-१२-१९०७)	४६५
३५२	भाषण चीनी सभमे (३०-१२-१९०७)	४६८
३५३	भेट रायटरको (३०-१२-१९०७)	४६९
३५४	जोहानिसबगकी चिट्ठी (३१-१२-१९०७)	४७०
३५५	पत्र एशियाई पजीयकको (३१-१२-१९०७)	४७५
	परिशिष्ट	४७६
	सामग्रीके साधन-सूत्र	५२०
	तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	५२१
	शीर्षक-साकेतिका	५२६
	साकेतिका	५३०

चित्र-सूची

प्रिटोरियामे आम सभा	८८
छगनलाल गाधीको पत्र	८९
प्रिटोरियाके सत्याग्रही	२९६
‘स्टार’ को पत्र	२९७
व्यंग्य-चित्र (देशनिकालेके अधिकारपर)	४३२
व्यंग्य चित्र (सत्याग्रहके सम्बन्धमे)	४३३

१ जूरियोकी कसौटी

इस पत्रने जमसे ही अपनी प्रवृत्तियोंको प्रयत्नपूर्वक दक्षिण जाफ्रिकावासी भारतीयोपर असर करनेवाले प्रश्नो तक सीमित रखा है। हमारी धारणा है कि पत्रकारिताकी दृष्टिसे दूसरे प्रश्न चाहे जितने वाञ्छनीय हो, हमे अपनी मर्यादा स्वीकार करनी चाहिए और उच्चस्तरीय नीतिसे सम्बद्ध अथवा ऐसे प्रश्नोमे, जिनका इस देशके भारतीयोसे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, दखल नहीं देना चाहिए।

लेकिन हर नियमके अपवाद होते हैं। हमे लगता है कि अगर हम सुप्रसिद्ध एमटोगाके मुकदमेपर^१, जिसकी ओर आज लोगोका ध्यान इतना अधिक आकृष्ट है, कुछ नहीं कहते तो अपने पेशेके प्रति वफादार नहीं होंगे। यह विषय वतनी नीतिके मन्त्रसे उठकर मानवताके प्रश्नको स्पष्ट करता है और किसी हद तक इसमे निहित सिद्धान्त भारतीयोपर भी लागू होते हैं। इसलिए हम 'नेटाल मक्युरी' मे प्रकाशित एक अत्यन्त तर्कपूर्ण और सहृदय अप्रलेखका कुछ अंश सहृण उद्धृत करते हैं। यह जूरी प्रणालीपर, विशेषकर उस अवस्थामे जब वह गोरो और कालोके बीच हुए मुकदमोपर लागू होती है, एक खुला आरोप है। हम अपने सहयोगीसे वतनी लोगोके प्रति खास दुर्व्यवहार करनेके उस आरोपका खण्डन करनेमे सहमत हैं, जो कुछ क्षेत्रोमे नेटालक विरुद्ध लगाया गया है और जिसका आधार एमटोगाके मुकदमेमे न्यायका गला घोटा जाना है। हमारा विश्वास है कि नेटालमे जो-कुछ हुआ, वह वैसी ही परिस्थितियोंमे दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी हिस्सेमे या दक्षिण आफ्रिका जैसी स्थितियोंवाले किसी अन्य देशमे भी हो सकता है। राग-द्वेष और पूर्वग्रहोसे ग्रसित जूरियोके सम्बन्धमे दूसरे देशोके मुकाबले नेटालका कोई एकाधिपत्य नहीं है। लेकिन इस बातसे कि दक्षिण आफ्रिकामे एमटोगाके मुकदमे जैसी बातें घटित होती हैं, जनताकी अंतरात्माको जागना चाहिए, और जिन लोगोको दक्षिण आफ्रिकाकी नीतिका खयाल है उन्हे सोचना चाहिए कि क्या अब जूरी-पद्धतिके बारेमे अपने विचार बदलनेका समय नहीं आ पहुँचा। दक्षिण आफ्रिका जैसे देशमे, जहा कोई आरामतलब बग नहीं है और जहा सभी देशोके लोग इकट्ठे होते हैं, 'याय-प्रशासनके लिए जिन पद्धतियोंकी व्यवस्था की जा सकती थी उनमे जूरी प्रणाली लगभग सबसे बुरी है। जूरी-प्रणालीकी सफलताकी बुनियादी शत यह है कि अभियुक्तके अपराधकी जाच उसकी बराबरीके लोग करे। और यह मानना मनुष्यकी बुद्धिकी तौहीन करना होगा कि दक्षिण आफ्रिकामे, जब प्रश्न गोरो और कालोके बीचका हो, अपराधकी ऐसी भी कोई जाच होती है।

जो लोग सचार्डको तौलना नहीं जानते और अपने सामने प्रस्तुत बातोपर सन्तुलित मस्तिष्कसे विचार नहीं कर सकते वे भावनाके अतिरेकमे, सम्भवत, किसी सही निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकते। लिबरपूल एक सुव्यवस्थित और पुराना स्थान है, जहा एक-जैसे लोग बसते हैं और उनकी अपनी परम्पराएँ हैं, जिनके अनुसार वे आचरण कर सकते हैं। लेकिन

१ एमटोगा एक आफ्रिकी था जिसे कुछ लोगोने एक अपराधके मदेहमे पीटा था। बादमें उस पर मुकदमा चलाया गया तो जूरीके सदस्योंने उसे दोषी ठहराया। लेकिन गवर्नरने उसे निर्दोष मानकर छड़ा दिया।

वहा भी श्रीमती एम० हेन्रिकके मुकदमेका निणय करनेके लिए स्वर्गीय 'यायमर्ति' स्टीफेनके समान योग्य न्यायाधीशकी आवश्यकता पडी थी। तब दक्षिण आफ्रिका जैसे देशमें, जहा अभी विभिन्न राष्ट्रीयताएँ घुलने मिलनेकी प्रक्रियामे ही गुजर रही है और दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रका उदय अब भी बुल और सुदूर भविष्यक गभमें छिपा हुआ है, जूरियासे कोई सन्तोष कैमे प्राप्त हा सकता है। जहा समानताकी कोई बुनियाद नहीं, वहा हम समानताके पुजारी नहीं है। यह सम्भव है कि ऐसे मुकदमाम, जहा सवाल गोरा और कालोका हो, जूरी पद्धतिका समाप्त करनके किसी भी प्रयत्नका झूठी समानताकी दुहाई देकर विरोध किया जायेगा। हमारी धारणा है कि कोई भी वतनी या रगदार जातिका व्यक्ति, जो इस प्रकारका रुख अख्तियार करता है, सच्ची समानताको नहीं जानता। आज उनके द्वारा, या उनके लिए, तकसम्मत ढंगसे जो कुछ मांगा जा सकता है वह है कानूनकी दृष्टिमें समानताका हक। यूरोपके विभिन्न भागसे आनेवाले गारे कोई साम्राज्य प्रेम लेकर दक्षिण आफ्रिका नहीं आते। ऐसे गोरोसे, जहाँतक उनके आगे उन लोगोंके बीचकी बात है, जिन्हें वे अपनेसे हीन समझते हैं, न तो साम्राज्यीय दायित्वाके बारेमें सोचनेकी अपक्षा की जा सकती और न ही न्याय तथा समान अधिकारकी किन्ही अन्य मायताआके बारेमें। यदि वे, उनके अन्दर मान्यताकी जो भी भावना हो, उसकी प्रेरणापर कुछ करते हैं तो वह बात अलग है।

इसलिए हम आशा हैं कि कोई भी रगदार व्यक्ति या एशियाई — क्योंकि हमारी बात एशियाईधारा भी उसी तरह लागू हाती है जिम तरह दूसरी रगदार जातियाके लोगपर — उस आन्दोलनका विरोध करनेकी जान कभी नहीं मोचगा जिमे नेटालके अखबाराने सवथा स्वाधरित और न्यायपूर्ण भावनाओमें प्रेरित होकर, जूरियो द्वारा यूरोपीया और काली जातियाक बीच न्याय करनेके तरीकेका खत्म करनेके लिए प्रारम्भ किया है। अगर जूरियो द्वारा फैसल किये जानका तरीका हमेशाके लिए खत्म हो जाये तो यह सचमुच एक बहुत बड़ी बात हागी, लेकिन यह एक इतना पुराना वहम है कि जनमतसे इसका सवथा परित्याग कर देनेकी आशा करना कठिन है। और न यही सम्भव है कि, जहाँतक सिफ गोराका सवाल है, उस प्रणालीके विरुद्ध कोई जोरदार तक पेश किया जा सके।

हम विश्वास हैं कि अगर इस विषयको वही ठोड दिया गया, जहा अग्रजाराने ठोड दिया है, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दक्षिण आफ्रिकाक गिरजाका वहाके मूल निवासियाक हितका — हम उन्हें अस्वीकार नहीं कहेंगे — सरक्षक माना जाना है सो ठीक ही, और हालांकि तात्कालिक सवाल नेटालमें उठा है, हम लगता है कि गिरजामे भी इसके साथ साथ आन्दोलन हाना चाहिए तथा सम्प्रतिन दक्षिण आफ्रिकी सरकाराके पास अलग अलग प्राथनापत्र भेजना चाहिए कि गारे और रगदार लोगोंक बीच जूरिया द्वारा न्यायकी पद्धतिका बन्द कर दिया जाये। हमारा यह भी विश्वास है कि गिरजा द्वारा किये हुए ऐमे आन्दोलनको दक्षिण आफ्रिकाके वतनी और रगदार समुदायाका समर्थन देने पैमानेपर मिठना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

२ वीर क्या करे ?

कदम आगे बढ़ाओ ! अब देर मत करो !

आज उठेगे, कल उठेगे, कहकर दिन मत बढ़ाओ । सोचते-सोचते मागने बड़े विघ्न आ जाते ह । कुटुम्बकी माया कसे छूट सकती है, कुटुम्बका क्या होगा, इस तरहके विचारोंमें जो फँसा रहता है वह बिल्कुल स्त्रण है । वह रणमें क्या जायगा ? जबतक वह इधर विचारोंमें ही डूबा हुआ है, उधर शत्रु छापा मार देगा और तब वह घबड़ा जायेगा, रक्षा करना भारी पड़ जायेगा । आग लगनेपर कुआ खोदनेवाला पश्चात बुद्धि कहलाता है । बाढ़ आ जानेपर बाप बनानेवालेको क्या कभी सफलता मिलेगी ?

इसलिए सजधजकर एक साथ रणमें लड़ने चलो । शत्रुके सामने अपना भाला लेकर डट जाओ और उसे ललकारो ।

ट्रान्सवालका नया कानून अब भी धूम धड़ाका मचाये हुए है । कहावत तो ऐसी है कि जो गरजता है सो बरसता नहीं, और जो भोकता है सो काटता नहीं । किन्तु इसमें शक नहीं कि नया कानून तो जैसा गरज रहा है, वैसा बरसेगा भी । जनरल बोथाके^१ आते ही, सम्भव है, वह 'गजट' में प्रकाशित हो जायेगा । अतः इस कानूनके खिलाफ जेलके प्रस्तावके^२ रूपमें जो लड़ाई चल रही है उसपर ओर अधिक विचार करे ।

उपयुक्त भजन देखेंगे तो उसमें कवि कहता है कि साहसका काम करते समय विचारके फेरमें पड़ना बेकार है । युद्धमें कूदनेवाले इस बातका विचार नहीं करते कि कुटुम्बका क्या होगा, व्यापारका क्या होगा । भारतीय जनता केवल ईश्वरपर ही भरोसा रखनेवाली है । हमने उसी ईश्वरके सामने शपथ लेकर नये कानूनके सामने न झुकनेका निणय किया है । वह निणय करनेके पहले विचार करना योग्य था और वह विचार किया

१ मूल गुजराती गीत इस प्रकार है

पगला भरवा माडो रे !
हवे नव वार ल्गाडो रे !
आज ऊठशु काल ऊठशु,
लम्बावो नहि दहाडा,
विचार करता विघनो मोटा,
वचमा आवे आडा,
कुडव माया वयम छोडाये,
कुडवर्तु वयम थारो,
एम फस्यां ते जनानी पूरो,
रणमा शुं पछी जाशे ?
विचार करता खालो पड़ता,

शतरू छापी मारे,
बचाव करवो गमरातां ते,
पछी पड़े थई भारे,
भाग लागते कुवो खोदवो,
पच्छम बुद्धिया थावु,
पाणी आवे पाल बाँधवी,
तेमा ते शु फायु ?
सजी करीने सहु जण साथे
रणमां लड़वा चालो,
शतरूनी सामे रही ऊभा
धुरकावीने भालो ।

२ लुई बोथा, १९०७-१० में ट्रान्सवालके और १९१०-१९ में दक्षिण आफ्रिका मक्के प्रधानमन्त्री ।

३ सितम्बर १९०६ का प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव, देखिए खण्ड ५ पृष्ठ ४३४ ।

भी गया। अब विचार करनेका समय नहीं रहा। अब तो जो निश्चय किया गया है उसपर दब रहनेका समय आ गया है। शेख सादी^१ 'गुलिस्ता' में कह गये हैं कि मनुष्य जितना विचार अपनी रोजीके बारेमें करता है, उतना ही यदि रोजी देनेवालेके बारेमें करे तो निस्मदेह स्वर्गमें उसका स्थान फरिश्तासे भी ऊँचा हो जायेगा। उसी प्रकार इस बार हमें रोजी, कुटुम्ब या व्यापारका विचार करनेके बजाय उन सबको पालनेवाले, उनका उत्कर्ष करनेवालेका विचार करके अगीकार किये हुए कामको पूरा करना है। सब ठोड दग, किन्तु सबके अन्तरमें रहनेवाले परमेश्वरपर भरोसा रखकर यदि हम कोई काम करेंगे तो वह मालिक हम कभी नहीं छोड़ेगा।

अब हम अपने राज्यकताओंका उदाहरण लें। जब बोअर लोगोंने महान ब्रिटिश प्रजासे युद्ध शुरू किया था, स्पर्गीय क्रूगरने^२ अपने कुटुम्ब या अपनी दौलतका विचार नहीं किया। जनरल जुबट लउते लउते मरे। जनरल स्मट्स^३ भी लडे थे। डॉ० फ्राउज़ने^४ दो वर्षकी कैद भागी, उनकी जोहानिसबर्गकी जायदाद बर्बाद हो गई। श्री डी'विलियस, जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, कैद भोग चुके हैं। उनके पैरमें गालिया लगी थी। जनरल बोथा स्वयं आगिरी समय तक लडे थे। बोअर औरते भी बहुत-स कष्ट सहन करत हुए शान्त बैठे रही। व अपने अपने बच्चा और पतियाका हिम्मत देती थी। इससे आज वे अपना खाय़ा हुआ सब कुछ वापस पा गये हैं।

अंग्रेज स्वयं भी क्या करते जाये हैं, यह हम जानत हैं। जान हम्डनने^५ बर्बाद होकर लोहाके दुख दूर किये। लॉड कालिन कैम्बल^६ यका मादा चीनसे आया था। हुक्म मिलते ही वह १८५८ में फिर रवाना हो गया। उमने घड़ी-भर भी आराम नहीं किया। लाड जॉज हेमिटनके^७ आठ निकटवर्ती रिश्तेदार बाअर युद्धमें उपस्थित थे। प्रधान मंत्री स्पर्गीय लॉड सैन्टिस्वरीका^८ लउका मेफेकिगमें^९ घिर गया था। लाड राबटसका^{१०} इकलौता लडका युद्धमें मारा गया, और आज उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है।

ट्रांसवालके भारतीय समाजको जो-कुछ भी करना है, वह इन उदाहरणोंके सामने कुछ नहीं है। हमें राज्यका विरोध नहीं करना है, न हमें हथियार लेकर ही लडना है। हमें

१ शेख मुस्लिहूद्दीन सादी (११८४-१२९२), प्रसिद्ध फारसी कवि, गुलिस्ता और बोस्ताँ के लेखक।

२ टान्सवालक राष्ट्रपति (१८८३-१९००) देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २४३-४।

३ उपनिवेश सचिव, १९०७-१० दक्षिण आफ्रिका मध्ये प्रधानमन्त्री, १९१९-२४।

४ जोहानिसबर्गके सरकारी वकील, आरम्भकथा (भाग २ अध्याय १३) में गांधीजीने इनके विषयमें लिखा है।

५ (१५९४-१६४३), अंग्रेज देशभक्त और संसदीय अधिकारोंके समर्थक, देखिए, खण्ड ५, पृष्ठ ४८९।

६ (१७९२-१८६३), १९५३-५६ के क्रिमिया युद्धमें लड़े थे, १८५७ में भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष, नियुक्त हुए थे। लगता है, यहाँ गलतीसे क्रिमिया और १८५७ के लिए क्रमशः चीन और १८५८ दे दिये गये हैं।

७ भारत-मन्त्री, १८९५-१९०३।

८ (१८३०-१९०३), इंग्लैंडके प्रधानमन्त्री १८८५-६, १८८६-९२ और १८९५-१९०२।

९ केप प्रदेशका एक नगर, जिसपर १८९९-१९०२ के बोअर युद्धके समय घेरा बाला गया था। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३६।

१० (१८३२-१९१४), १८८५ से १८९३ तक भारत और १८९९ से १९०० तथा १९०१ से १९०४ तक दक्षिण आफ्रिकाके प्रधान सेनाध्यक्ष।

तो जेल जाकर मामूली कष्ट सहन करना है और, व्यापारमे कदाचित, कुछ नुकसान उठाना है। क्या इतनेसे भी हम डरेगे? हम तो आशा किये बैठे हैं कि कहीं इससे भी ज्यादा आवश्यकता हो तो भारतीय समाज नहीं डरेगा। डरना है केवल खुदासे। उसके बाद किसीसे भी डरनेकी बात नहीं रहती, यह सभी शास्त्र सिखाते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

३ एक पौडका इनाम

शीषक हमने इनामका दिया है, किन्तु पाठको इनामकी ओर कम दृष्टि रखनी है। आजकल भारतीयोंके लिए मौसम नये कानून तथा जेलके प्रस्तावका है। इसलिए जो भारतीय गुजराती या हिंदुस्तानी (उर्दू या हिंदी)मे जेलके प्रस्तावके समर्थनमे सरस गीत बनाकर भेजेगा उसे उपयुक्त इनाम दिया जायेगा। हमे आशा है कि जिन्हे गीत रचनेका अभ्यास है वे इस प्रतिस्पर्धाको चूकेगे नहीं। जरूरी यह है कि गीत पुरस्कारके लिए नहीं, बल्कि इज्जतके लिए बनाकर भेजा जाये। उसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं

- (१) बीस लकीरोसे ज्यादा न हो।
- (२) शब्द सरल हो।
- (३) राग चाहे जो हो, वीर-रसकी लावनी ज्यादा पसन्द की जायेगी।
- (४) अक्षर साफ हो, स्याहीसे एव कागजके एक ही ओर लिखा जाये।
- (५) गीतके अन्तमे कविका नाम व पता दिया जाये।
- (६) गीतमे मुसलमानो एव हिन्दुओंकी बहादुरीके वतमान तथा प्राचीन उदाहरण दिये जाये। दूसरे होंगे तो वे भी चल सकेंगे।
- (७) जेल जानेके प्रस्तावपर डटे रहनेके सम्बन्धमे समय समयपर जो ठोस कारण दिये जा चुके हैं उनका समावेश किया जाये।
- (८) ये गीत अधिकसे अधिक १२ जूनके सवेरे तक फीनिक्स पहुँच जाने चाहिए, अथवा जोहानिसबग कार्यालय (बॉक्स ६५२२) मे १४ जूनको मिलने चाहिए।

नतीजा २२ तारीखके अकमे प्रकाशित किया जायेगा। आशा है, बहुत लोग प्रयत्न करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

४ भारतमें उथल-पुथल

दुनियाके सभी हिस्सोमें आज तरह-तरहकी घटनाएँ हो रही हैं। जगह-जगह हम “हमारा देश” का नारा सुनते हैं। मिस्त्रवामी कहते हैं कि “मिस्त्र मिस्त्रियोंके लिए है”। चीनियाने हॉंगकॉंगमें कई गाराको कत्ल कर दिया है। हन्शी कहते हैं कि “हमारे हक हमें मिलने चाहिए।” ईरानमें स्वराज्य स्थापित हो गया है। अफगानिस्तानकी ताकत बर गई है। अब रहा भारत। वहाँ भी “भारत भारतीयोंके लिए” का नारा बुलंद है, और उसके ठीक जगह-जगह हम बातका प्रयत्न किया जा रहा है कि हिन्दू मुस्लिम एकता हो। पंजाबमें एक मुसलमानने ‘हिन्दू मुसलमान’ नामसे एक पत्र शुरू किया है और वह कहता है, दोनों कौमोमें एकता होनी चाहिए। दूसरी ओरसे ‘बन्दे मातरम्’ जैसे पत्र अंग्रेजी राज्यको उखाड़ फेंकनेके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ‘पंजाबी’ पत्रपर मुकदमा चल जानेसे वहाँ उपद्रव हो गया, जिसमें अग्रगण्य भारतीयोंने भी हिस्सा लिया। उनमें से कुछ लोग पकड़े गये हैं। कुछको नैज निकाला दिया जायेगा और कुछ जेल जायेंगे। लाला लाजपतराय^१ जैसे विद्वान सज्जन भी इनमें शामिल हैं। ऐसी परिस्थितिमें हम क्या करें, इसपर सामान्यतः विचार किया जाना चाहिए। हम कर तो कुछ नहीं सकते, किन्तु समझदार लोग इस बातका भी खयाल रखते हैं कि वे अपने मनकी वृत्तियाँ कैसी रखें।

क्या अंग्रेजी राज्यको भारतसे उखाड़ दिया जाये? और यदि उखाड़नेका विचार हो तो क्या उखाड़ा जा सकता है? इन दोनों प्रश्नोका हम यह उत्तर दे सकते हैं कि उस राज्यको उखाड़ फेंकनेमें नुकसान है और हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम उखाड़ना चाहें तो उखाड़ सकें। इस कथनसे हम यह सूचित नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी राज्य बहुत भारी है और उससे भारतको अलम्ब्य लाभ हुए हैं, या, भारत यदि ठान ले तो अंग्रेजी राज्यको हटा नहीं सकता। किन्तु हम मानते हैं कि अंग्रेज लोग चाहें जितनी बेरमानीमें भारतमें घुसे हों, उनमें हमें बहुत सीखना है। वे बहादुर और विवेकी गेग हैं। कुल मिलाकर प्रामाणिक हैं। स्वायत्तके समय अंधे भी हो जाने ह, किन्तु बहादुरीको देखकर कुर्बान होते हैं। वह कौम जबरदस्त है तथा भारतको उसका कम बल नहीं। इसलिए भारतमें अंग्रेजी राज्य अस्त हो, यह चाहनेकी गुंजाइश ही नहीं रहनी।

तब क्या लाला लाजपतराय जैसे पुरुषकी हम उपेक्षा करें? यह भी नहीं हो सकता। पंजाबके गेगाको और उन दूसराको, जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, हम शूरवीर मानते हैं। वे देशभक्त हैं और देशके लिए काट झेग रहें हैं, और उस हद तक वे हमारे लिए आदरके पात्र हैं। किन्तु जिस हद तक वे अंग्रेजी राज्यको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उस हद तक भूल करते जान पड़ते हैं। उनके विद्रोहकी जो सजा कानून उन्हें देगा उसे, जान पड़ता है, उन्होंने भोगनेका निश्चय किया है। हमें उनका विरोध नहीं करना है। उनके कण्ठोसे भारतीय प्रजा सुखी होगी। वे विरोध करते हैं सो अंग्रेजी राज्यके दोषोंके कारण। अंग्रेजी

^१ ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपतराय (१८६५-१९२८), १९२० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष। उन्हें १९०७ में देशनिकाला दिया गया था। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १३४।

राज्यके कारण भारत कगाल होता जा रहा है। भारतमें प्लेग फैला, उसका कारण भी बहुत कुछ अंग्रेजी राज्य ही है। हिंदू मुसलमानके बीच वैर बढ़ानेवाला भी वही है। हम इतनी अधम स्थितिमें पहुँचकर आज नपुंसककी जिंदगी बिता रहे हैं, उसका कारण भी अंग्रेजी राज्य ही है। इन दोषोंसे उबकर कुछ भारतीय नेता सारी अंग्रेज कौमको दोष देते हैं। उनके विद्रोहसे, सम्भव है, ये दोष कुछ हद तक दूर हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त वे चूँकि हमारे ही भारतीय भाई हैं, इसलिए उनकी ओर जरा भी बुरी भावना रखे बिना उनके जोशके लिए उन्हें धन्यवाद देना है।

वास्तवमें दोष हमारा है। हम अपने दोष दूर कर ले तो जो अंग्रेजी राज्य आज दुःखस्वरूप बना हुआ है वह सुखस्वरूप बन सकता है। पश्चिमकी शिक्षा लिये बिना और पश्चिमके सम्पत्तियों आये बिना ग़ैरक भावनाका जाग्रत होना सम्भव नहीं है। यह भावना आ जाये तो अंग्रेज बिना लड़ें ही हमारे अभिलषित अविकार हमें दे सकते हैं, और हम यदि उन्हें जानेको कहें तो वे जा भी सकते हैं। अंग्रेजी उपनिवेशोंकी यही स्थिति है। उसका कारण यह नहीं कि वे ग़ोरे वणके हैं, बल्कि यह है कि वे बहादुर हैं। यदि अपने अपेक्षित हक न मिलें तो वे नाराज हो सकते हैं, इसलिए वे एक कुटुम्बके माने जाते हैं।

सक्षेपमें हमें अंग्रेजी राज्यसे वैर नहीं है। विद्रोह करनेवालोंकी बहादुरी हमारे लिए गव करने जैसी है। जो बहादुरी वे बताते हैं वही हम भी दिखायें और अंग्रेजी राज्यके जानेकी इच्छा करनेके बजाय हम यह इच्छा करें कि उपनिवेशियोंके समान ही होशियार और जोशीले बनकर जो अधिकार हमें चाहिए उनकी मांग करें तथा लें, साथ ही साथ हम अंग्रेजी राज्यकी खूबियोंको जान लें और सीखें, तथा अविक कुशल बनें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

५ भारतीय राजा

माननीय स्वर्गीय अमीर अब्दुरहमान^१ लिख गये हैं

अपनी यात्रामें मैंने एक खेदजनक बात देखी, जिसका मेरे मनपर बहुत असर पड़ा। बेचारे भारतीय राजाओंकी पोशाक औरतो जैसी थी। वे बालोंमें हीरेकी पिने लगाये थे, और कानोंमें कुण्डल, हाथोंमें पहुँची, गलेमें सोनेका हार और दूसरी चीजें, जो औरते पहनती हैं, पहने थे। उनके इजारकी कलियोंपर रत्न जड़े हुए थे और इजारके नाडेमें लोलक लगे हुए थे, जो लगभग पाव तक पहुँचते थे। वे अज्ञान, आलस्य और मौज शौकमें मग्न थे। दुनियामें क्या हो रहा है, या क्या है, इसका उन्हें भान नहीं है। उनका समय शराब और अफीम पीनेमें बीतता है। वे मानते हैं कि अगर हम पैदल चलेगें तो हमारे ओहदेमें खामी आयेगी।

१ अब्दुरहमान ख़ाँ (१८४४-१९०१), अफ़ग़ानिस्तानके शासक, १८८१-१९०१।

यह चित्र बहुत कुछ हूबहू है। आज कुछ भारतीय राजा लोग ऐसा नहीं करते, यह भी कहा जा सकता है। फिर भी आज हम यह सवाल नहीं उठा रहे कि कितने राजा ऐसा नहीं करते। हकीकत यह है कि यह स्थिति हमारे दारिद्र्यका एक सबल कारण है।

फिर ऐसी अधम दशा सिर्फ राजाओंकी ही हो सो बात नहीं। प्रजामें भी ऐसी बाते बहुत दिखाई देती हैं। हमारी टीका खासकर हिन्दू भारतीयोंपर लागू होती है। बड़े माने जानेवाले लोगों और उनके लड़कोंके लक्षण बहुत-कुछ मरहूम अमीर द्वारा खींचे गये चित्रके समान ही दिखाई पड़ते हैं। मौज शौक, आभूषण, रेशमी और सुनहरे कपड़े — सामान्यतः हम यही स्थिति देखते हैं। सम्य माने जानेवाले लोग आभूषण आदि नहीं पहनते तो दूसरी तरहसे अपना शौक पूरा करते हैं। इसमें किसीको दोष देनेकी बात नहीं। जो रुढ़ि लम्बे समयसे चली आ रही है वह एकदम दूर नहीं हो सकती।

लेकिन हम दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंको यह सबक लेना है कि हम सब, छोटे बड़े, उन दोषोंसे मुक्त रहे। हमारी और हमारे देशकी स्थिति इतनी बुरी है कि हमारे लिए यह समय सदा शोकावस्थामें रहनेका है। जहां दर हफ्ते हजारों व्यक्ति भूख या प्लेगसे मरते हैं, वहाँ हम ऐशो-आराम कैसे भोग सकते हैं? हम निश्चित रूपसे मानते हैं, हर भारतीय पुरुषका अपना मन विरक्त कर लेना चाहिए। हमारी पोशाक वगैरहमें जवाहरान रेशम या साने आदिका दोष नहीं होना चाहिए।

इंग्लैंडका राजा

उपर्युक्त लेखका जबरदस्त समर्थन करनेवाली हमारी इस वारकी लन्दनकी चिट्ठी है। सम्राट एडवर्डका पौत्र आज १३ वर्षका है। उसे आज ही से सख्त तालीम दी जा रही है। उसे दूसरे लड़कोंके साथ पढ़ना पड़ता है और जो सादा खाना दूसरे विद्यार्थियोंको दिया जाता है वही इस युवराजको भी दिया जायेगा। जिसका राजा इस प्रकारका आचरण करता है उस देशकी प्रजा भी ऐसी ही है। वह प्रजा यदि सुखी हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या? हमें उसमें ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उसके समान बनना है। कोई यह न सोचे कि वह प्रजा भी ता मौज-शौक करती ही है। इस विचारसे आलस्य प्रकट होता है। व लोग अपना काम करनेके बाद मौज शौक करते हैं, और वह मौज शौक भी उन्हें शोभा देता है। इतना हानेपर भी हमें उनके मौज शौक रूपी दोषका अनुकरण नहीं करना है। हमें ता हसके समान अच्छेको चुन लेना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी^१

नया कानून विशेष प्रश्न

इस कानूनके सम्बन्धमें अब भी प्रश्न आते रहते हैं। यह देखकर मुझे खुशी होती है। इस तरहके जितने भी प्रश्न पूछे जायेंगे उनका इस पत्रमें खुलासा किया जायेगा।

उच्च पञ्जीयनपत्रवाले क्या करें ?

‘गजट’ की सूचनाके अनुसार एक भारतीयने अपने पञ्जीयनके जावारपर अनुमतिपत्र कार्यालयमें अर्जी दी है। उसके विषयमें श्री मुहम्मद दावजी पटेल वाकसूटूमसे नीचे लिखी बातें पूछते हैं

- (१) क्या निश्चित माना जाता है कि इस अर्जीको अनुमतिपत्र कार्यालय स्वीकार कर लेगा।
- (२) यदि ऐसा हो तो चौथे प्रस्तावमें अडचन आती है, इसलिए वह व्यक्ति अपनी अर्जी वापस ले ले या नहीं ?
- (३) वापस लेनेपर पुलिस उसे पकड़ेगी या नहीं ?
- (४) यदि पकड़ लिया गया और मजिस्ट्रेटने बाहर जानेका हुक्म दिया तो फिर वह क्या करे ?
- (५) यदि वह व्यक्ति ऐसा करे और उसपर मुकदमा चले तो बचाव करनेके लिए श्री गांधी आयेंगे या नहीं ?

इन प्रश्नोंके उत्तर ये हैं कि इस व्यक्तिको और ऐसी स्थितिके सभी व्यक्तियोंको जबतक नया कानून ‘गजट’ में नहीं आया है तबतक अर्जी वापस लेनेकी जरूरत नहीं और न ही इस विषयमें आगे कोई कारवाई करनेकी जरूरत है। नये कानूनके ‘गजट’ में आते ही अर्जी वापस ले लेनी होगी। शायद इस सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटके सामने मुकदमा चलाया जायेगा और उस व्यक्तिका तथा उसके समान वैसे ही अन्य व्यक्तियोंका, जो पञ्जीयनके सच्चे हकदार होंगे, श्री गांधी बचाव करेंगे। यह बचाव किस प्रकार किया जायेगा, इसके लिए पिछली जोहानिसबर्गकी चिट्ठीया देख ली जाये। अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार करनेका मतलब यह होता है कि आगे उस कार्यालयसे किसी भी प्रकारका व्यवहार न किया जाये। ट्रान्सवालमें रहनेवाले जिन लोगोंके मुकदमें अभी उस कार्यालयमें चल रहे हैं, उन्हें वापस नहीं लेना है। यह कदम ‘गजट’ में कानूनके प्रकाशित होते ही उठाया जाये।

श्री गांधी पहले जेल चले जाये तो क्या होगा ?

एक भाई पूछते हैं कि श्री गांधीको यदि पहले जेलमें बैठा दिया गया तो फिर बचावका क्या होगा ? यह प्रश्न ठीक किया गया है। किन्तु श्री गांधी किस प्रकार बचाव करनेवाले हैं, यह समझ लेना है। बचावमें गांधीको सिर्फ यही कहना है कि उनकी सलाहसे लोगोंने जेल जानेका निश्चय किया है। इसलिए पहले जेल उन्हें (श्री गांधीको) दी जानी चाहिए। इस तरह बचाव करनेकी जरूरत ही न पड़े और सीधे श्री गांधीको ही जेलमें बन्द कर दिया जाये तब यही माना जायेगा कि बचाव हो चुका। श्री गांधीकी उपस्थितिका मुख्य हेतु

१ इस शीर्षकसे ये संवादपत्र “हमारे विशेष सवाददाता द्वारा प्रेषित” रूपमें इण्डियन ओपिनियनमें हर हफ्ते प्रकाशित किये जाते थे। पहला संवादपत्र मार्च ३, १९०६ को प्रकाशित हुआ था, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २१५ १६।

अभियुक्तको धीरज बँधाना है। यदि कोम और श्री गांधीके सौभाग्यसे उन्हें ही जेलमे बंद कर दिया गया तब भी उममे लोगोके लिए डरने जसी तो कोई बात नहीं रहती। इसके अलावा श्री गांधी जेलमे बैठे बैठे भी बचाव तो कर ही सकते हैं, यानी यह कि वे खुदामे प्रायना कर सकते हैं कि सब भारतीयोको हिम्मत दे। इस समय मुझे यह भी कह देना चाहिए कि सारे भारतीयाने जेलका प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसका मुख्य कारण यह है कि नया कानून अपमानजनक है। इसलिए, प्रत्येक भारतीयको आखिर अपना टेक तो रखनी ही है।

स्त्री-बच्चोके भरण पोषणके लिए निधि कहाँ है ?

यह प्रश्न पूछनेवाले सज्जन लिखते हैं कि सघके पास तो बहुत ही थोड़े पैसे हैं, फिर निर्वाह कहासे होगा ? अभी कानून 'गजट' मे आया नहीं है। उसके 'गजट' मे प्रकाशित होने ही अप्रगण्य लोग गांव गांव जाकर लोगोंको समझायेगे और चन्दा इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा ईस्ट लन्दन और नेटालके प्रमुख लोग लिख चुके हैं कि वहाँमे मदद दी जायेगी। इसीके साथ यह भी व्यवस्था हुई है कि श्री गांधीके जेल जानेपर 'इंडियन ओपिनियन' के सम्पादक श्री पोलक जगह-जगह जाकर चन्दा एकत्रित करेंगे तथा लोगोको धीरज बँधायेंगे और समझायेंगे। कुछ गोराने भी मदद देनेको कहा है।

जर्मिस्टन बस्ती

जर्मिस्टन बस्तीमे भारतीयोको काफिरोंके समान पास दिये जाते थे। उसके बारेमे ब्रिटिश भारतीय सघने स्थानीय सरकारको लिखा था। उसका उत्तर आया है कि अब वैसे पास नहीं दिये जायेंगे। अतः बस्तीमे रहनेवालाको उन पासोको मढ़वा कर नमूनेके तौरपर रखना हो तो रख सकते हैं। दूसरी बार यदि ऐसा हो तो भारतीयोका कतव्य है कि पास न ले तथा उसके लिए साफ इनकार कर दें।

खान-मजदूरोकी हड़ताल

हम अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कार और जेलकी बाते कर रहे हैं। खदानोके गोरे मजदूर अधिक वेतनके लिए हड़ताल कर रहे हैं। फलस्वरूप लगभग दस खदानोका काम रुक गया है। सब समझते हैं कि ये गोरे मजदूर जितना कमाते हैं वह सब खर्च कर देते हैं। उनमे कुछ विवाहित हैं। किन्तु अपनी रोजी तथा अपने बाल बच्चोका खयाल न करके, अपने हकके लिए, चालू रोजी छोड़कर बाहर निकल पड़े हैं। उनकी बेइज्जतीका तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी जिमे उन्होने अपना हक माना है उसके लिए अधिकारियो एव करोड़पति खान मालिकोके सामने कमर कसी है। उनकी मांग उचित है या नहीं, इसपर अभी हमें विचार नहीं करना है। इस अवसरपर हम तो उनके जोश और मर्दानगीका अनुकरण करना है।

ईस्ट लन्दनसे प्रोत्साहन और किम्बरलेकी गलतफहमी

ईस्ट लन्दनके भारतीयोकी आरसे सघके अध्यक्षके नाम सहानुभूतिपूर्ण पत्र आया है और श्री ए० जी० इस्माइलने लिखा है कि सारे भारतीय कानूनका अनादर करके निश्चित ही जेल जायेंगे। उन्होने वहाँ मदद मिलनेके बारेमे भी लिखा है। दूसरी ओर किम्बरलेसे सहानुभूतिपूर्ण तार आया है। लेकिन लिखा है कि भारतीय समाजको जेलका कदम उठानेके पहले विचार करना चाहिए। यह किम्बरलेकी गलतफहमी है। भारतीय कोम खुदाको माननेवाली है, इसलिए अब वह उसका अनादर नहीं कर सकती। इसके अलावा पक्का विचार करनेके

बाद ही सितम्बर महीनेमें जेलका प्रस्ताव पास किया गया था। इसलिए हर भारतीयके लिए लाजिम है कि वह हम ट्रान्सवालवालोंको आवश्यक प्रोत्साहन दे और खुदासे प्रार्थना करे कि सच्ची कसौटीके समय वह हमें हिम्मत बख्से।

जर्मन पूर्व आफ्रिकामें भारतीय

‘स्टार’ का विलायतस्थित सवाददाता तारसे सूचित करता है कि जमन उपनिवेश-समितिकी बैठक जमनीमें हुई थी। उसमें कुछ सदस्योंने कहा कि भारतीय व्यापारी जमन पूर्व आफ्रिकामें छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको नुकसान पहुँचाते हैं। वे काफ़िरोको ठगते हैं। विद्रोहके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। इसलिए उनके लिए दक्षिण आफ्रिकामें समान कानून बनाये जाने चाहिए। इस समितिकी कायसमितिनें यह रिपोर्ट दी है कि यद्यपि भारतीय व्यापारियोंपर कुछ डलजाम तो लगाये ही जा सकते हैं, फिर भी कुल मिलाकर कहना होगा कि उनके होनेसे फायदा हुआ है। उन्हें निकाल देनेका कानून बनानेसे इंग्लैंडमें खीचातानी होना सम्भव है। दूसरे कुछ सदस्योंने, जो उपनिवेशकी हालतसे परिचित थे, भारतीय व्यापारियोंका बचाव किया।

झूठी गवाहीके लिए सजा

पुनसामी नामक धोबीपर झूठी गवाही देनेके अपराधमें सर विलियम स्मिथके पास मुकदमा चला था। उसने दूसरे भारतीयोंपर गलत अभियोग लगाया था कि वे अपराधी हैं, जब कि वह जानता था कि वे निरपराध हैं। पच्चेन सामीको अपराधी ठहराया और न्यायाधीशने उसे १८ महीनेकी मख्त कैदकी सजा दी। इस उदाहरणसे जो झूठी गवाही देते नहीं डरते उन लोगोंको चेत्त जाना चाहिए।

निर्धारित समयपर दूकानें बन्द करनेकी हलचल

तारीख २२ को जोहानिसबर्ग नगर परिषदमें निर्धारित समयपर दूकानें बन्द करनेकी बात चली थी। परिषदमें बहुत ही मतभेद रहा इसलिए सदस्य एक नियमपर नहीं पहुँच सके और यह नियम किया गया कि इस सम्पूर्ण प्रश्नका निबटारा ससद करे। इसीके साथ ससदके समक्ष निवेदन भी कर दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि आम तौर पर दूकानें छ बजे बन्द की जायें तथा बुधवारको एक बजे, शनिवारको रातके ९ बजे और त्यौहारके दिन बिलकुल बन्द रहे। जब दूकानें बन्द हो उस समय फेरीवालोंको भी अपना रोजगार बन्द रखना चाहिए। किन्तु इस तरहका कानून अभी बना नहीं है। यह उसके बननेकी तैयारी समझे। जो भारतीय अपने-आप ही समझकर जल्दी दूकान बन्द करने लगेंगे, वे मीर माने जायेंगे।

जोहानिसबर्गमें भूमि-कर

इस बार भूमि-कर सबा पेनी प्रतिशत निश्चित किया गया है। उस करका हिसाब १ जनवरीसे ३० जून १९०७ तक लगाया जायेगा। २४ जून १९०७ को वह कर जमा करना होगा। जो २४ तारीख तक नहीं जमा कर पायेंगे उन्हें १ प्रतिशत प्रतिमाहकी दरसे व्याज देना होगा।

चीनियोंकी सभा और जेलका प्रस्ताव

पिछले रविवारको चीनी सघकी एक सभा उसके हालमें हुई थी। उसमें करीबन तीन सौ चीनी, विशेषतः व्यापारी, हाजिर थे। श्री एम क्विनने अध्यक्षका स्थान ग्रहण किया था।

निमन्त्रण पाकर श्री गांधी भी उपस्थित हुए थे।^१ उन्होंने सारी बातें समझाते हुए कहा कि नये कानूनके अन्तर्गत चीनी और भारतीयोंको एक ही माना गया है। नया कानून एशियाई जनताके लिए अपमानजनक है, इसलिए चीनियोंको भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिन प्रश्नोंका इस 'चिट्ठी' में हल बताया गया है, उन्हींका हल उपयुक्त बैठकमें भी बताया गया। आखिर यही तय हुआ कि हर चीनी अपने धर्मके अनुसार यह शपथ ले कि वह नया अनुमति-पत्र कभी नहीं लेगा, और जेल जाना पड़ा तो जायेगा।

अनुमतिपत्रका मुकदमा

लाला नामक भारतीयपर अभी कुछ दिनोंमें अनुमतिपत्र सम्बन्धी मुकदमा चल रहा है। वह २७ तारीखको श्री वेडरबर्गके पास चला था। अधीक्षक वरनॉनने बयान देते हुए कहा

मुझे लोगोंसे अनुमतिपत्र मागनेका हक है। जो अनुमतिपत्रके आधारपर प्रवेश पाना चाहते हैं उनके हकोंकी जांच करना भी मेरा काम है। २० अप्रैलको मैंने लालाको अपने दफ्तरके पास देखा। लालाने कहा “मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कई लोग अनुमतिपत्र माँगते हैं। उसके बारेमें यदि आप मुझे सूचना देंगे तो हम दोनों बहुत पैसे कमायेंगे। हर व्यक्तिमें म २० पौंड लूंगा। उसमें से ८ पौंड आपको दूंगा। यहाँ झूठे अनुमतिपत्रवाले भारतीय और चीनी बहुत हैं। उनके अनुमतिपत्र यदि आप सच्चे कर दें तो मैं आपको २० पौंड दूंगा। यह मेरे हाथमें एक अनुमतिपत्र है। इसपर हस्ताक्षर करके पास कर दें। इस तरह आप प्रतिमाह ४०० पौंड कमायेंगे और मैं २०० पौंड कमाऊँगा। और श्री हैरिसको २०० पौंड मिलेंगे। मुझे मालूम है कि जोहानिसबर्गमें झूठे फार्म चलते हैं, और बिना अनुमतिपत्रके बहुत से भारतीय हैं।” दूसरे दिन मैंने लालाको बुलाया। वह आया और उसके साथ थोड़ी बात करके घटी बजाई और उसे पकड़वा दिया। अदालतमें जाते हुए लालाने कहा “साहब, आपने पैसा कमानेका एक मुनहरा अवसर खो दिया।”

सिपाही हैरिसने भी ऊपर जैसा ही बयान दिया। श्री चैमनेने^२ बयानमें कहा

मेरा काम अनुमतिपत्रों सम्बन्धी सारी अजियाकी जाँच करना है। पुलिसकी रिपोर्ट खराब होनेपर शायद ही अनुमतिपत्र दिया जाता है। मेरा फैसला ही निर्णायक माना जायेगा, यद्यपि गवर्नर उस फैसलेको बदल सकता है। भारतीयोंकी अर्जी मैं उपनिवेश-सचिवके समक्ष पेश करता हूँ। लाला मेरे पास दो बार आया था। वह कहता था कि कुछ भारतीयोंके पास झूठे अनुमतिपत्र रहते हैं। मैंने एक बार उसे रेलसे बिना किराये आनेकी अनुमति दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊँगा। लेकिन वह एक भी खबर नहीं लाया।

लालाने बयान दिया

मेरे पास एक भारतीय अनुमतिपत्रके लिए आया। मैंने उससे 'ना' कहा। उसके बाद उसने अनुमतिपत्र बताया जो ठीक नहीं था। उसपर से मैं श्री चैमनेके पास गया

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ५१३।

२ प्रवासी-संरक्षक, बम्बई पश्चिमार्ध पंजीयक नियुक्त किये गये थे, देखिए “जोहानिसबर्गकी चिट्ठी”, पृष्ठ ५६।

और मैंने उनसे कहा कि उस व्यक्तिको उस अनुमतिपत्रके लिए ३० पौड देने पड़े हैं। श्री चैमनेने उस व्यक्तिको आफिसमें ले जानेको कहा। बादमें मैंने श्री वरनॉनके पास जाकर कहा कि यदि श्री चैमनेके पास खबर पहुँचा दोगे तो मैंसे दूंगा। इसमें मेरा उद्देश्य यह बतलाना था कि झूठे अनुमतिपत्र किस प्रकार निकलते हैं। मुझे आशा थी कि उसके लिए जनाम मिलेगा। मैं सम्राटकी एक वफादार प्रजा हूँ, इसलिए मुझे आशा थी कि मुझे अपनी वफादारीके लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई रकम निश्चित नहीं की गई थी। हेरिसने यह बात की थी कि एक भारतीयने १०० पौड देनेको कहा है। मैंने अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं किया था। इसी बीच मुझे पकड़ लिया गया।

फौजदारी वकीलने लालासे प्रिटोरियासे मित्रे पत्रके बारेमें प्रश्न पूछे। लालाने कहा कि पत्रका अनुवाद ठीक नहीं है। इसलिए श्री टामसनने एक सप्ताहकी और मोहलत मागी और मुकदमा ४ जून तक के लिए स्थगित किया गया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

७ भारतके सेवक

‘इंडियन सोशियलॉजिस्ट’में एक विद्वान भारतवासीने भारत सेवकोका एक मण्डल स्थापित करनेके सम्बन्धमें लेख लिखा है। उसका सार हम नीचे दे रहे हैं

यह तो अब बहुतेरे भारतीय समझते और चाहते हैं कि भारत सुसंगठित और स्वतन्त्र बने, किन्तु उस भावनाको सफल बनानेके लिए जो नैतिक बल चाहिए वह नहीं है। जो अपने देशकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्हें अपना जीवन ऐशोआराममें नहीं बिताना है, बल्कि अपने कतव्य निभानेमें लगाना है। भारतकी आबादी दुनियाका पाचवाँ भाग है। उसका स्तर उठाना ही भारतके सेवकोका काम है। ये सेवक भारतीय जनताके ‘यासी’ हैं। उन्हें धन, मान, शारीरिक सुखोंकी आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, और अपना जीवन भारतका समर्पित करना चाहिए। समस्त भय निकाल देना चाहिए, और इस सेवाको अपने वमके अगके समान मानना चाहिए। ऐसे देशभक्त व्यक्ति बातोंकी अपेक्षा कामसे ही अपने निमल उत्साहका सञ्चार समस्त जनतामें कर सकेंगे।

ऐसे उज्ज्वल उत्साहकी आवश्यकता तो है ही, साथमें ज्ञानकी भी आवश्यकता है। इसलिए भारत-सेवकोको भारतका इतिहास जानना चाहिए। भारतके लिए अब क्या जरूरी है, यह समझना चाहिए। अन्य देशोंके इतिहासका भी अध्ययन करना चाहिए।

यह उत्साह और ज्ञान, दोनों ही, कुटुम्ब जालमें फैले हुए मनुष्यके पास अधिक समय तक नहीं टिकते। सच्चे सेवकके लिए लगोटेबंद रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करना आवश्यक है। विवाहित होते हुए भी जो लोग देश-सेवक होना चाहते हैं वे अपनी पत्नी और बच्चोंको इसी कामके लिए तैयार कर सकते हैं। भारतीय स्त्रियाँ अज्ञान हैं। उनमें स्वदेशाभिमान जगानेकी बहुत बड़ी जरूरत है। परन्तु जो लोग विवाहित नहीं हैं, उन्हें यदि उपर्युक्त सेवा

करनी हो तो अविवाहित रहना उन्नत मार्ग है। महान् देशभक्त मैजिनी^१ कहा करते थे कि उनका विवाह तो देशके साथ हुआ है।

आखिरी बात यह है कि ऐसे सेवकमें श्रद्धा चाहिए। उमें यह विचार करनेकी आवश्यकता नहीं कि कल राटी कहामें मिलेगी। जिसे दात दिये हैं, उमें चबेना देनेका ध्यान मालिक रखेगा ही।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९०७

८ तार तैयबको

[जोहानिसबग]

जून १, १९०७

तैयब^२

मारफत गुल

केप टाउन

२१ तारीखका उत्तर क्या नहीं? शीघ्र उत्तर दीजिए।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एम० एन० ३/३५)से।

९ पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको^३

जोहानिसबग

जून १, १९०७

सचिव

परममाननीय प्रधानमन्त्री

प्रिटोरिया

महोदय,

चूँकि एशियाई पजीयन अधिनियम अभीतक साम्राज्यीय सरकार और स्थानीय सरकारके बीच पत्र व्यवहारका विषय बना हुआ है, इसलिए मरे मघने मुझे आदेश दिया है कि मैं प्रधानमन्त्रीके सामने एक ऐसा सुझाव रखनेके लिए भट करनेकी अनुमति प्राप्त करूँ जिसके अनुसार अधिनियमको 'गज़ट' में प्रकाशित करनेकी आवश्यकता ही न रह। कुछ भी हा, यदि

१ जोसेफ मैजिनी (१८०५-७२), इटलीके सुप्रसिद्ध देशभक्त, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३०१।

२ केप टाउनके एक प्रमुख भारतीय।

३ यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

४ यह २२-६-१९०७के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

जनरल बोया, अधिनियमके सम्बन्धमें आगे कोई कदम उठानेसे पहले, मेरे सचके शिष्टमण्डलसे भेट करनेके लिए समय दे तो मेरा सच उनका बहुत आभारी होगा।

मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप कृपापूर्वक मालूम करेंगे कि क्या प्रधानमन्त्रीको हमारे सचके एक छोटे से शिष्टमण्डलसे मिलना सुविधाजनक होगा। यदि, हा, तो कब?¹

आपका आज्ञाकारी सेवक,

ईसप इस्माइल मियाँ

कायवाहक अव्यक्ष,

ब्रि० भा० स०²

[अंग्रेजीसे]

प्राइम मिनिस्टर्स आर्काइव्स, प्रिटोरिया फाइल १४/१/१९०७

१० सच्ची राये

हमें हप है कि विधानसभाके सदस्य श्री सी० पी० राबिन्सन अपने निर्वाचकोसे कुछ खरी बातें कहते आ रहे हैं और वे एक अप्रिय विषयको सही ढंगसे निभानेमें हिचके नहीं। श्री राबिन्सनकी रायमें परवाना अधिकारियोंका, भारतीय प्रार्थियों और दूसरोंके बीच ऐसा भेद करना कि उससे भारतीयोंका हानि पहुँचे, निन्दनीय और अयायपूर्ण है और विशेषकर उस दशामें जब यह चालू व्यापारिक अधिकारियोंका मामला हो। श्री राबिन्सनका यह भी खयाल है कि यदि उपनिवेश भारतीय प्रश्नको हाथमें लेना चाहता है तो उसे स्पष्ट, निर्भीक और सच्चे ढंगसे ऐसा करना चाहिए। न्याय और निष्पक्षताका ऐसे सम्मानपूर्ण ढंगमें पक्ष ग्रहण करनेके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। यदि हमारे सभी विधायक ऐसा ही निर्भीक रह ख अस्तित्वार करे तो शीघ्र ही उपनिवेशको वाकछल और मक्कारीसे बहुत कुछ मुक्ति मिल जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

११ केपका प्रवासी कानून

हम उस भीषण कहानीकी तरफ लोगोका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो मेफेकिगके एक सवाददाताने केपके प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अमलके बारेमें लिखी है। हमारे सवाददाताके कथनानुसार जो भारतीय अपने दस साल पुराने कारोबार और भूसम्पत्ति केपमें छोड़कर भारतको लौट गये थे और जिन्होंने यहासे खाना होनेसे पहले यहाके अधिवासी प्रमाणपत्र नहीं लिये थे उन्हें फिरसे केप लौटनेमें कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है। इसी

१ प्रधानमन्त्रीने शिष्टमण्डलको भेंट नहीं दी।

२ ब्रिटिश भारतीय सच, जोहानिसबर्ग।

प्रकार, जो भारतीय कई सालसे यहाँ रह रहे हैं उन्हें, खाना होते समय, ऐसे प्रमाणपत्र पाना कठिन होता है। सवाददाता यह भी लिखना है कि जब ऐसे प्रमाणपत्र दिये भी जाते हैं तब उनकी मियाद केवल एक मालकी हाती है। इससे अगर कोई भारतीय अपने अंगीकृत देश शुभाशा अन्तरीपके उपनिवेशमें प्रमाणपत्रमें दी गई तारीखके एक दिन बाद भी गैरतना है, तो वह वर्जित प्रवासी बन जाता है। इस प्रकारकी प्रणालीको भारतीयोंका बिना कोई मुआवजा दिये कैसे बाहर निकालनेके लिए जानबूझकर किये गये क्रूर प्रयत्नके सिवाय और क्या कह सकते हैं? इसका इलाज बहुत-कुछ केपके भारतीयोंके हाथमें ही है। और हम वहाँकी विभिन्न सस्थाओंका आगाह करते हैं कि अगर ब्रिटिश भारतीयोंपर यह आसन सकट आया और अगर पाँच साल बाद उन्होंने यह पाया कि केपमें बहुत कम भारतीय बचे हैं, तो समाजके सामने इसके लिए उन सस्थाओंको ही जिम्मेदार समझा जायेगा। हम अपने सवाददाताको सलाह देना चाहेंगे कि वे तबतक बराबर केप टाउनकी भारतीय सस्थाओंको आगाह करते रहें जबतक वे अपनी स्पष्ट जड़ताको त्यागकर सक्रिय न हो जाय।

[अग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१२. एशियाई पजीयन अधिनियम*

भयानक विषमता

जब कि भारतीय एशियाई पजीयन अधिनियमके सामने न झुकनेका अपना पक्का इरादा प्रकट कर रहे हैं, यह मुनासिब है कि उसके बारेमें उनके एनराजोंको भी समझ लिया जाये। इसलिए मैं यहाँ समानान्तर स्तम्भोंमें यह दिखाना चाहता हूँ कि उनकी आज क्या हालत है और नये कानूनके अन्तर्गत क्या हो जायेगी।

इस समय

१ मलायी लोग सन् १८८५ के कानून ३ के अधीन हैं।

नये कानूनके अन्तर्गत

१ वे नये कानूनमें मुक्त कर दिये गये हैं। बहुत से भारतीयोंकी पत्नियाँ और सम्बन्धी मलायी हैं। ऐसे भारतीय जब अपने मलायी सम्बन्धियोंस मिश्रित तब उनकी क्या दशा होगी, यह कहनेकी नहीं, स्वयं ही अनुमान करनेकी बात है।

२ प्रत्येक एशियाई, जिसके पास प्रामाणिक रूपसे प्राप्त अनुमतिपत्र है, ट्रान्सवालन्डा पूर्ण और वैध नागरिक है।

२ वह इस अतिशयमें वंचित हो जाता है, और नया पजीयन प्रमाणपत्र पानेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए उसपर यह सिद्ध करनेका भार डाल दिया जाता है कि उसका वाकायदा प्राप्त अनुमतिपत्र गोखा रूडिमें नहीं लिया गया।

१ यह 'विशेष केस' के रूपमें प्रकाशित हुआ था। जिस रूपमें यह अधिनियम अन्ततः पास हुआ था उसके लिए देखिये परिशिष्ट १।

३ ऑरेज रिवर उपनिवेशमे ३१ मई, सन १९०२ के बाद पैदा हुए एशियाई बच्चे ट्रान्सवालमे आने और रहनेके अधिकारी है।

४ एशियाई लोगोके वतमान अनुमति-पत्र उन्हे ट्रान्सवाल और आरेज रिवर उपनिवेशमे प्रवेश करने व रहनेका अधिकार प्रदान करते है। और यहा यह प्रश्न नही उठता कि उनका आरेज रिवर उपनिवेशमे जानेके लिए कोई उपयोग हे या नही।

५ जिन एशियाइयोको आरेज रिवर उपनिवेशमे रहनेका अनुमतिपत्र प्राप्त हे वे उसके आधारपर ट्रान्सवालमे भी प्रवेश कर सकते है।

६ वतमान अनुमतिपत्र अभिधारकोकी इच्छाके विरुद्ध बदले नही जा सकते।

७ एशियाई बच्चोको अनुमतिपत्र लेनकी जरूरत नही हे।

८ ट्रान्सवालमे इस समय रहनेवाले नाबालिग बिना अनुमतिपत्रोके वहा रहनेके हकदार है और बालिग होनेपर वहासे जानेको बाध्य नही ह।

९ कोई भी एशियाई अपनी शिनाख्तका ब्योरा देनेको बाध्य नही है।

३ ऐसे बच्चोका प्रवेश वर्जित हे।

४ यह अधिकार, जहातक उसके अनु-मतिपत्र द्वारा प्राप्त होनेकी बात है, वापस ले लिया गया हे।

५ ऐसा प्रवेश वर्जित हे।

६ सरकारकी इच्छासे उनमे परिवर्तन किया जा सकता हे।

७ ऐसे बच्चोके सरक्षक-अपन पजीयन-पत्रपर उन बच्चोकी शिनाख्त लिखानेके लिए दण्डविधानकी कडी शर्तोसे बद्ध है, चाहे वे बच्चे कितनी भी कम उम्रके क्यों न हो। बच्चोके ८ वर्षकी अवस्था प्राप्त करनेपर उनके सरक्षकोके लिए फिरसे पजीयकके सामने हाजिर होकर बच्चोका पजीयन कराना ओर शिनाख्त वगैरहके सम्बन्धमे अय विवरण पेश करना आवश्यक है।

८ ऐसे सभी बच्चे, यदि वे १६ वर्षकी उम्र होनेपर पजीयकसे अपना पजीयन प्रमाण-पत्र न ले ले तो, वहासे निकाले जा सकते है, और उन्हे पजीयन प्रमाणपत्र देना पजीयककी इच्छापर निर्भर हे।

९ एक काफिर पुलिसका सिपाही भी उनके प्रमाणपत्र और, समय समयपर विनियम द्वारा निर्धारित, शिनाख्तका ब्योरा तलब कर सकता है। इतनेपर भी वह सिपाही एशियाईको सबसे करीबके थानेमे ले जा सकता हे, जहा उसकी फिरसे वैसी ही जाच हो सकती हे और यदि थानेमे उपस्थित अधिकारी उससे सन्तुष्ट नही होता तो वह एशियाईको रातभर हिरासत रख सकता हे।

१०. कोई भी एशियाई, बिना अनुमति-पत्र निर्यात, शुल्क अदा करके अपना व्यापारिक परवाना प्राप्त कर सकता है।

११. काद भी एशियाई किसी दूसरे एशियाईका नौकरी दनके लिए स्वतन्त्र है।

१२. पजीयकको अभी काफी बड अवि-कार प्राप्त है।

१३. अपने पास दूसराके प्रमाणपत्र रखनेवाले एशियाई अपराधी नहीं माने जात।

१०. किसी भी एशियाईको उम समय तक यह व्यापारिक परवाना नहीं मिल सकता जबतक वह अपना पजीयन-प्रमाणपत्र और, विनियम द्वारा निर्धारित, अपनी शिनाख्तके विवरण पेश न कर द। इसलिए यदि किसी एशियाई व्यापारिक पेढीमे एकसे ज्यादा साझेदार है, ता परवाना अधिकारी परवाना देनेके पहले सभी साझेदारको बुलाकर उन्हे किसी भी अपमानजनक जाचके लिए मजबूर कर सकता है।

११. कोई भी एशियाई जो १६ बपसे कम आयुवाले किसी एशियाईका (अपने पुत्रको भी) उपनिवशमे उसके लिए अनमतिपत्र प्राप्त किय बिना लाता है या एमे किसी बच्चेका अपने कामपर लगाता है, भारी जुर्माने अथवा जेलकी सजाका भागी हागा, और टान्मवालम रहनेका उसका भी अधिकार खत्म कर दिया जा सकता है।

१२. पजीयक वास्तवम एशियाइयाका स्वामी बन जाता है और उनकी व्यक्तिगत आजादीपर उसका लगभग असीम अधिकार हो जाता है।

१३. जिन एशियाइयाके पास एम प्रमाणपत्र है (स्पष्टतः पुत्रका प्रमाणपत्र रखन वाला पिता भी) उहे वे डाकद्वारा [अफिरागीके पास] भेजनेका बाव्य है। इसमे चूकनपर ५० पांड जुर्मान, और जुर्माना न अदा करनपर, जलकी सजा हा सकती है।

ध्यान देने योग्य अतिरिक्त बातें

१. नया कानून काफिरा, केपके अफगोरा (केप वाण्ड) और तुर्की साम्राज्यके ईसाई प्रजाजनापर लागू नहीं हाता, किन्तु उसी साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोपर लागू होता है। इस तरह यह भारतीयों और उनके धर्मका निमन अपमान करता है। और यद्यपि वे सभ्य देशाके निवासी हैं, तथापि यह उन्हें गलामीकी स्थितिमें पहुँचा देता है। यह उन्हें काफिरा, केपके अधगोरो और मलायी लोगोमे भी निम्नतर स्थितिमे डाल देता है।

२. यह धोखाधडीको प्रोत्साहन देता है। सम्भव है, कानूनके बनानेवाओको यह सूझा हो कि किसी एशियाईको मलायी या केपके अधगोरोका रूप धारण करनेसे रोकनेके लिए इसमें कोई बात नहीं है।

३ यह अनुमतिपत्रके दलालोके लिए निरीह एशियाइयोको अपना शिकार बनानेका स्वर्ण अवसर प्रदान करता है। अनुमतिपत्रके अविकारियोको यह अच्छी तरह मालूम होगा कि एशियाई आम तौरपर अजियोके पेचीदे फाम भरनेकी क्षमता नहीं रखते, क्योंकि वे सरकारी विभागोकी काय-प्रणालीसे अपरिचित होते हैं और सहज ही भयभीत हो उठते हैं। इसलिए यह मानकर कि भारतीय और चीनी दोनोको मिश्रकर १२,००० प्रार्थी होंगे, यदि औसतन ३ पौड प्रति व्यक्ति देना पडा तो उनके कमसे कम ३६,००० पौड लुट जायेंगे।

तब एशियाइयोके, ऐसे अजीब कानून और ऐसी लूटके आगे झुक जानेके बजाय, जेल जानेके निश्चयपर कौन ताज्जुब करेगा? सच तो यह है कि उनके लिए अपने निवास कालमे सारा ट्रांसवाल ही एक जलील जेलखाना बन जायेगा। नया कानून एशियाइयोको जिस दुःखद स्थितिमे ला पटकता है, वह सिर्फ उन लोगोको ही नहीं दिखाई दे सकती, जो शक्तिके मदमे चूर हैं।

[अग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१३ नया खूनी कानून

बल निष्फल हिम्मत बिना, वश सम्पं बिन व्यथ,
वित्त व्यथ विद्या बिना, अगुणे^१ ज्ञान अनथ।

इस कानूनका साराश १ सितम्बर [१९०६] के अकमे दिया जा चुका है। फिर भी हम इस बार उसका अनुवाद अधिक ब्योरेके साथ दे रहे हैं, ताकि यह कानून क्या है, इस सम्बन्धमे लोग स्वयं सही सही विचार कर सकें। सितम्बर मासमे हमने जिसका साराश दिया है उस कानून और पास किये गये इस कानूनके बीच कुछ उल्लेखनीय अंतर है और यह पहले मूल कानूनसे भी भारतीय समाजके अधिक विरुद्ध है।

(१) १८८५ का कानून ३ निम्न परिवर्तनके साथ कायम रहेगा।

(२) “एशियाई” शब्दका अर्थ है, कोई भी भारतीय कुली अथवा तुर्कीकी मुसलमान प्रजा। इसमे मलाइयो और गिरमिटमे आये हुए चीनियोका समावेश नहीं होता। (इसके अलावा, पजीयन अधिकारी आदिकी व्याख्या दी गई है। उसे यहा नहीं दे रहे हैं।)

(३) ट्रान्सवालमे वैध रूपसे रहनेवाले प्रत्येक एशियाईको पजीकृत हो जाना चाहिए। इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा।

१ सुमति, दैव्य।

२ बिना गुणके व्यक्तिके लिए।

निम्न व्यक्ति ट्रान्सवालमे वैध रूपसे रहनेवाले एशियाई माने जायेंगे।

- (क) जिस एशियाईका अनुमतिपत्र कानूनके अनुसार अनुमतिपत्र मिला हो, वशत कि वह अनुमतिपत्र वाक्केम अथवा गलत ढंगम प्राप्त किया गया न हो। (मुन्ती अनुमतिपत्रका समावेश इसमें नहीं होता।)
- (ख) प्रत्येक एशियाई, जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वी तारीखको ट्रान्सवालमे रहा हो।
- (ग) जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वी तारीखके पश्चात ट्रान्सवालमे जन्मा हो।
- (घ) प्रत्येक एशियाई, जो इस कानूनके अमलमे आनेकी तारीखको ट्रान्सवालमे मौजूद हो, उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई तारीखमे पहचान निर्धारित स्थानपर और निर्धारित अधिकारीके यहां पंजीयनके लिए आवेदनपत्र दे दे। कानूनके अमलमे लाये जानेकी तारीखके बाद ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेवाला प्रत्येक एशियाई, यदि उसने इस कानूनके अंतगत नया पंजीयनपत्र न लिया हो तो, पंजीयनके लिए अपना आवेदनपत्र प्रविष्ट हानके आठ दिनोंके अंदर भेज दे। परंतु,
- (१) इस धाराके अनुसार आठ वषसे कम उम्रके बालकके लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है।
- (ख) आठ वषसे लेकर सोलह वषके अंदरके बालकके लिए उसका अभिभावक पंजीयनका आवेदनपत्र दे। और अगर वैसा आवेदनपत्र न दिया गया हो तो सोलह वषकी आयु होनेके बाद बालक स्वयं दे।
- (५) पंजीयक वैध रूपसे रहनेवाले एशियाईके आवेदनपर ध्यान देगा। पंजीयक उपयुक्त एशियाईका तथा जिसे वह मान्य करे ऐसे एशियाईका पंजीयनपत्र दे।

यदि पंजीयक किसी एशियाईके आवेदनको अस्वीकृत कर दे, तो उस एशियाईका न्यायाधीशके समक्ष उपस्थित होनेके लिए वह कमसे-कम १४ दिनोंका नोटिस दे, और यदि निश्चित तारीखपर वह उपस्थित न हो, अथवा उपस्थित होकर भी न्यायाधीशको अपने ट्रान्सवालमे रहनेके अधिकारके सम्बन्धमें सन्तुष्ट न कर सके और वह १६ वषकी आयुका हो, तो उसे न्यायाधीश ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दे। और यदि न्यायाधीशको विश्वास हो जाये कि उपयुक्त एशियाई वैध निवासी है तो उस पंजीयकको पंजीयनपत्र देनेका आदेश देना चाहिए।

- (६) जो एशियाई आठ वषसे कम आयुके किसी बालकका अभिभावक हो, उस अपना आवेदनपत्र देत समय पंजीयकको उस बालकके सम्बन्धमें विनियम द्वारा निर्धारित विवरण और हलिया देना चाहिए। यदि उस व्यक्तिका आवेदन स्वीकृत किया गया तो उसके पंजीयनपत्रपर वह विवरण और हलिया लिख दिया जायेगा। फिर, उस बालककी उम्र आठ वष हो जानेपर वह एक वषके अन्दर उस पंजीयन करनेके लिए अपने जिला मजिस्ट्रेटकी मारफत दुबारा अर्जी दे।

ट्रांसवालमे जमे हुए बालकका एशियाई अभिभावक बालककी आठ वर्षकी आयु होनेपर एक वर्षके अंदर उसे पजीकृत करनेके लिए अर्जी दे।

- (क) यदि अभिभावक उक्त प्रकारसे आवेदन न दे तो पजीयक या मजिस्ट्रेट जो समय निश्चित करे उस समय वह अर्जी दे।
- (ख) यदि अभिभावक आवेदन न दे, अथवा आवेदन दिया गया हो किंतु अस्वीकृत हो गया हो, तो १६ वर्षकी आयु हो जानेपर वह बालक स्वयं एक मासके अंदर आवेदन करे। जिस मजिस्ट्रेटके पास ऐसा आवेदनपत्र पहुँचे वह उस आवेदनके साथ सभी कागज पजीयकको भेज दे और यदि पजीयक ठीक समझे तो, आवेदकको पजीयनपत्र दे दे।
- (७) अभिभावकने उपर्युक्त प्रकारसे आठ वर्षसे छोटे बालकका नाम और हुलिया दज न कराया हो और आठ वर्षके बाद बालकका पजीयनपत्र न लिया हो तो १६ वर्षकी उम्र हो जानेपर बालक स्वयं एक महीनेके अन्दर आवेदन करे। ओर पजीयकको उचित मालूम हो तो वह उसे पजीयन-प्रमाणपत्र दे दे।
- (८) इस कानूनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पजीयनके लिए उपयुक्त ढंगसे आवेदन नहीं देगा तो उसपर १०० पौंड तक जुर्माना होगा, और जुर्माना न देनेपर उसे तीन महीने तक की कड़ी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सोलह वर्षसे कम आयुवाले एशियाईको ट्रांसवालमे लायेगा, जो यहाका वैध निवासी न हो, और जो व्यक्ति उस लडकेको नौकर रखेगा, वे दोनों अपराधी समझे जायेगे, उन्हें उपयुक्त प्रकारसे सजा दी जायेगी, उनका पजीयन खारिज कर दिया जायेगा और उन्हें ट्रांसवाल छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा। यदि वे ट्रांसवाल नहीं छोडेगे तो उन्हें कानूनके मुताबिक जुर्माने या जेलकी सजा दी जायेगी।

सोलह वर्षसे ज्यादा उम्रवाला जो भी एशियाई उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित की गई अवधिके पश्चात् ट्रांसवालमे बिना पजीयन-प्रमाणपत्रके पाया जायेगा उसे ट्रांसवाल छोड़नेका आदेश दिया जायेगा और यदि वह ट्रांसवाल नहीं छोडेगा तो उसे जुर्माने अथवा कैदकी सजा होगी।

उपर्युक्त प्रकारका पजीयनपत्र-रहित एशियाई पजीयनका आवेदन न देनेका न्यायालयको सन्तोषप्रद कारण बतायेगा तो उसे न्यायाधीश आवेदन करनेके लिए मोहलत दे सकता है। और उस अवधिमे यदि वह पजीयन न करवा ले तो उसे फिर बाहर जानेका या सजा भोगनेका आदेश दिया जायेगा।

- (९) सोलह वर्षकी आयुवाला जो कोई एशियाई ट्रांसवालमे प्रवेश करेगा अथवा रहता होगा उसे कोई भी पुलिस या उपनिवेश-सचिव द्वारा आदिष्ट व्यक्ति पजीयनपत्र दिखानेके लिए कह सकेगा, और इस कानूनकी धाराओंके अनुसार निर्धारित विवरण तथा हुलिया माग सकेगा।

सोलह वर्षसे कम उम्रवाले एशियाईका अभिभावक उस बालकका पजीयनपत्र दिखाने और विवरण तथा हुलिया प्रस्तुत करनेके लिए उपयुक्त प्रकारसे बाध्य है।

- (१०) जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके अनुसार प्राप्त किया हुआ नया पजीयनपत्र होगा उसे ट्रांसवालमे रहने ओर प्रवेश करनेका हक है।

- (११) जिस व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्तिका पजीयनपत्र अथवा मियादी अनुमतिपत्र मिले उसे सारे दस्तावेज तत्काल पजीयकके पास भेज देने चाहिए। यदि वह नहीं भेजेगा तो उसको ५० पौड तक जुमानेकी अथवा एक महीनेतक की कड़ी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।
- (१२) जिस व्यक्तिका पजीयनपत्र खो जाये उसे तुरन्त नये पजीयनपत्रके लिए अर्जी देनी चाहिए। उस अर्जामे कानूनके मुताबिक सारा विवरण दिया जाये और उसपर पांच शिलिंगके टिकट लगाये जाये।
- (१३) 'गजट' मे निर्धारित की गई तारीखके पश्चात किसी भी एशियाईको राजस्व कानून या नगरपालिकाकी बाराआके अनुसार तबतक परवाना नहीं दिया जायेगा जबतक वह अपना पजीयनपत्र न दिखाये तथा माँगी हुई हकीकत व हुलिया न दे दे।
- (१४) किसी भी एशियाईकी आयुका प्रश्न खड़ा होनेपर यदि वह प्रमाणोके साथ और कोई आयु सिद्ध न कर सके तो पजीयक द्वारा निश्चित की हुई आयु ही सही मानी जायेगी।
- (१५) इस कानूनके अन्तर्गत जो हलफनामा देना पड़ेगा उसपर टिकटकी आवश्यकता नहीं है।
- (१६) जो व्यक्ति पजीयन-प्रमाणपत्रके सम्बन्धमे कुछ धोखा देगा, अथवा झूठ बोलेगा, अथवा दूसरे व्यक्तिको झूठ बोलनेके लिए प्रोत्साहन देगा या सहायता करेगा, अथवा जाली पजीयनपत्र बनायेगा, अथवा और किसीका पजीयनपत्र या जाली पजीयनपत्र काममे लायेगा, अथवा वैसा पजीयनपत्र दूसरोको काममे लानेके लिए देगा, उसपर ५०० पौड तक का जुर्माना होगा, अथवा दो वर्ष तक की कड़ी या सादी कैदकी सजा होगी।
- (१७) उपनिवेश सचिव अपनी इच्छानुसार किसी भी एशियाईको मुद्दी अनुमतिपत्र दे सकता है। उस अनुमतिपत्रके सम्बन्धमे नवी शराकी गते शग हागी और आजतक गेम जितन भी अनुमतिपत्र दिये जा चुके हैं उन सबपर यह कानून लागू समझा जायेगा। मियादी अनुमतिपत्रवालेको शराबकी छूट मिल सकती है। अलावा इसके, जिन एशियाईयोपर यह कानून लागू नहीं होता, उन्हें भी उपनिवेश सचिव शराबकी छूट दे सकता है।
- (१८) गवर्नर निम्नलिखित कामाके लिए नियम बना सकते हैं और रद्द कर सकते हैं
- (क) पजीयनपत्र किस प्रकारका रखा जाये।
 - (ख) पजीयनपत्रके लिए अर्जी किस प्रकार की जाये, किस रूपमे दी जाये, उसमे दी जानेवाली हकीकते क्या हों, हुलियामे क्या क्या लिखा जाये।
 - (ग) पजीयन-प्रमाणपत्र किस प्रकारका लिया जाये।
 - (घ) आठ वर्षसे कम आयुवाले बालकका अभिभावक, वह एशियाई जिससे नवी कलमके अनुसार पजीयनपत्र माँगा जाये, खोये हुए पजीयनपत्रकी प्रतिलिपि माँगनेवाला एशियाई, और व्यापारके लिए परवाना माँगनेवाला एशियाई क्या-क्या हकीकतें, कौन-कौन-सा हुलिया दे।

- (ड) १७ वी कलमके अनुसार किस प्रकार अनुमतिपत्र दिया जाये।
- (१९) प्रत्येक एशियाई अथवा एशियाईके अभिभावकपर, यदि वह अपने लिए ऊपर निर्दिष्ट की गई बातें नहीं करता, और यदि इसके लिए अथवा कोई सजा निर्धारित नहीं की गई है, १०० पौड तक जुर्माना किया जायेगा अथवा उसे तीन महीने तक का सपरिश्रम या सादा कारावास दिया जायेगा।
- (२०) चीनियोसे सम्बन्धित नौकरीका कानून [लेबर इम्प्लोयेशन आर्डिनेंस] एशियाइयो पर लागू नहीं होगा।
- (२१) १८८५ के कानूनकी तारीखसे पहले यदि किसी एशियाईने अपने नामपर जमीन खरीदी होगी तो उसके उत्तराधिकारीको वह जमीन पानेका अधिकार होगा।
- (२२) जबतक सम्राट् स्वीकृति न दे और वह स्वीकृति 'गजट' में प्रकाशित न हो जाये तबतक यह कानून अमलमें नहीं आयेगा।

इस कानूनका असर

सौभाग्यसे यह नहीं दिखाई देता कि कोई भी भारतीय उपयुक्त खूनी कानून स्वीकार करनेको तैयार हो। फिर भी हम नीचे बता रहे हैं कि भारतीयोंकी जो दुदशा आजतक नहीं हुई है वह अब होगी। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि जो भारतीय दब हैं वे और भी दब हो जाये और जिनके मनमें अनिश्चयता है वे शकारहित होकर स्वेच्छापूर्वक कानूनसे मुक्त हो जाये स्वतन्त्र रहे और मद कहलाये।

- १ नया कानून मलाइयोपर लागू नहीं होता, भारतीयोंपर होता है।
- २ काफ़िरो और केप बायजपर नया कानून लागू नहीं होता।
- ३ तुर्किस्तानके ईसाइयोपर नहीं, किंतु मुसलमानोंपर लागू होता है।
- ४ इस समय अपने अँगूठेकी निशानी लगे हुए अनुमतिपत्रवाला प्रत्येक भारतीय वैध निवासी है। नये कानूनसे उसका अधिकार एकदम रद्द हो जाता है और नया अनुमतिपत्र लेते समय उसे उसका असली अनुमतिपत्र कैसे मिला यह बतलाना होगा।
- ५ वतमान अनुमतिपत्र भारतीयकी मर्जीके बिना नहीं बदला जा सकता। नये कानूनके अनुसार मिलनेवाले अनुमतिपत्रोंको सरकार जब चाहेगी तब बदलाना होगा।
- ६ वतमान अनुमतिपत्रोंमें आरेज रिवर कालोनीमें जानेकी छूट है। वह उपयोगी है या नहीं, यह प्रश्न अलग है। नये कानूनके द्वारा आरेज रिवर कालोनीका नाम हट जाता है।
- ७ इस समय आरेज रिवर कालोनीमें अनुमतिपत्र लेकर बसनेवाला भारतीय ट्रान्स-वालमें बेरोक-टोक आ सकता है। नये कानूनसे नहीं आ सकता।
- ८ इस समय कोई भी भारतीय अपना अनुमतिपत्र प्राप्त करनेके लिए अँगूठेकी छाप या हस्ताक्षर देनेके लिए बाध्य नहीं है। नये कानूनके अनुसार सरकार मनमाने ढंगसे समय-समयपर नियम बनाकर या बदलकर हस्ताक्षर देनेके लिए, अँगूठेकी छाप देनेके लिए या और जो भी कुछ करवाना हो, उसके लिए बाध्य कर सकेगी।
- ९ इस समय अनुमतिपत्र सचिवको ही अनुमतिपत्र देखनेका हुक्म है। नये कानूनके अंतर्गत कोई काफ़िर पुलिस भी देख सकेगी।

- १० नये कानूनके अनुसार काफिर पुलिस नाम और हुलिया माग सकती है, और उसमे सन्तुष्ट न होनेपर थानपर ले जा सकती है। यदि नाम हुलिया लेनेपर थाने-दारको भी सन्ताप न हो तो वह उक्त एशियाईको कालकोठरीमे बंद रखकर दूसरे दिन 'याया'रीशके पास ले जा सकता है। वतमान कानूनके अन्तगत यह सब नहीं हो सकता।
- ११ इस समय एक दिनके बालकके लिए अनुमतिपत्र लेना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार उसका नाम हुलिया मागनेकी भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। नये कानूनके अनुसार उस बालकका नाम-हुलिया देकर उसके अभिभावकको वह सब अनुमतिपत्रपर दज करवाना होगा।
- १२ आठ वषकी आयु पार करनेवाले एशियाई बालक इस समय मुक्त है। नये कानूनके अनुसार उपयुक्त ढंगसे विवरण दज करा देनेके बाद भी बालकके आठ वषका होनेपर अभिभावकको फिर अर्जी देनी होगी और नाम हुलिया देकर पजीयन करवाना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो सजा होगी।
- १३ आजकल सोलह वषकी आयु होनेपर एशियाई लडका स्वतंत्र है और अधिकार पूवक रह सकता है। नये कानूनके अनुसार उस लडकेको पजीयनपत्र लेना होगा, जिमे देना या न देना पजीयकके हाथमे है। यदि पजीयनपत्र न दिया गया तो उसे ट्रान्सवाल छोड़ना पड़ेगा।
- १४ अभी सोलह वषस कम आयुवाले लडकेको यदि कोई व्यक्ति ले आये तो उसके लिए सजा नहीं है। नये कानूनके अनुसार ऐसा करनेवाले व्यक्तिके लिए कड़ी सजा है। इतना ही नहीं, उसका पजीयनपत्र रद्द हो जाता है।
- १५ अभी चाहे जो एशियाई व्यापारका परवाना ले सकता है, और उसे अनुमतिपत्र आदि नहीं दिखाने पड़ते। नये कानूनके अनुसार नये पजीयनपत्र ही नहीं दिखाने हाने, बल्कि नाम हुलिया भी देना होगा। यानी किसी भारतीयके दो चार साझेदार हों तो परवाना-अधिकारी उन सबकी उपस्थितिकी माग कर सकेगा, और उपस्थित न होनेपर परवाना देनेसे इनकार कर सकेगा।
- १६ इस समय पजीयककी सत्ता अपेक्षाकृत बहुत कम है। नये कानूनसे, यदि भारतीय उसे मान लेते हैं तो, पजीयक भारतीयाका अन्नदाता बन जाता है।
- १७ नये कानूनके अंतगत प्रत्येक भारतीय आवेदन करनेके लिए तो बाध्य है ही। ऐसा योग्य भारतीय क्वचित् ही हों जो स्वयं अपनी अर्जी लिख सके। अनुमति पत्रके दलालोंने बहुत कमाई की है, किन्तु यदि भारतीय समाज नये कानूनके सामने झुक गया तो उन्हें तो गड़ा हुआ खजाना ही मिल जायेगा। कमसे कम आँक और प्रति व्यक्ति तीन पौंड गिने, तो भी, चूँकि अधिक नहीं तो दस हजार भारतीय अर्जदार तो यहाँ होंगे ही, भारतीयाकी जेबमे से तीस हजार पौंडका ढेर लगेगा।
- १८ ऐसे जुल्मी कानूनको मानकर जो पजीयनपत्र लेगे या लिवायेंगे, उनके लिए यही कहना होगा कि उन लोगोंने उपर्युक्त हिसाबके अनुसार पैसे बँटवा कर भारतीयोंका खून ही बहाया है।

ऐसे कानूनसे किस भारतीयके रोगटे नहीं खड़े होते, किस भारतीयका खून नहीं खौलता, यह जाननेके लिए हम आतुर हैं। और हम नहीं समझ सकते कि कोई भी भारतीय ऐसे कानूनके सामने झुकना चाहेगा। नया कानून गुलामीकी हद है। हम आशा करते हैं कि चाहे जो लाभ होना हो, एक भी भारतीय इस कानूनको स्वीकार नहीं करेगा, और चाहे जैसा नुकसान सहन करके भी उसका सामना करेगा। श्री कैलनबैकने जो लिखा^१ है वह बिल्कुल उचित है कि इस कानूनको यदि हम लोग स्वीकार करते हैं तो सब लोग यही समझेंगे कि हम इसके लायक हैं। स्मरण रखना है कि यह कानून भारतीयोंका अपमान ही नहीं करता, हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गोंको कलकित करता है। कारण भारतसे आनेवाले हिंदू मुसलमानोंपर तो यह कानून लागू होता ही है, इसने उन मुसलमानोंको भी अपनी चपेटमें ले लिया है जो भारतसे नहीं, बल्कि तुर्कीसे (जो यूरोपका हिस्सा माना जाता है) आते हैं, मानो उनके छूट जानेसे ट्रान्सवाल सरकारको कोई अड़चन पड़ जाती। किन्तु उसी देशके ईसाइयोंको कानूनके प्रभावसे मुक्त रखा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१४ समिति की भूल

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिने जनरल बोथाके नाम जो पत्र भेजा है वह बहुत अच्छा है और उसमें सब बातोंका समावेश हो जाता है। इस समितिने इतना काम किया है और वह इतनी अच्छी तरहसे किया है कि उसके लिए हम सर मचरजी^१, श्री रिच^२ और अन्य सदस्योंका जितना आभार माने उतना ही कम है। इसीलिए जनरल बोथाके नाम लिखे गये पत्रमें समितिसे जो भूल हो गई है उसे बताते हुए हमें सकोच होता है। फिर भी उसे बतलाना हमारा कर्तव्य है। उससे समितिका मूल्य कम नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि भूल मनुष्य मात्रसे होती है। समितिने लिखा है कि भारतीय कौमकी मर्जी होगी तो वह अँगुलियोंकी निशानीकी जगह फोटो दे सकती है। समितिकी यही भूल है। फोटो देना या न देना भारतीयोंकी मर्जीपर छोड़ा गया है, फिर भी हम मानते हैं कि समितिकी ओरसे ऐसी सूचना दी ही नहीं जानी चाहिए थी। इसके अलावा समितिके पत्रसे यह भी भासित होता है कि नये कानूनके सम्बन्धमें मानो सबसे बड़ी और केवल यही आपत्ति है कि अँगुलिया लगवाई जायेगी। सच कहा जाये तो अँगुलियोंकी

१ हरमान कैलनबैक, एक जर्मन वास्तुकार, ये गांधीजीके मित्र बन गये थे और उनके साथ सदे जीवनके प्रयोगमें शामिल हो गये थे। इन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके अनाक्रामक प्रतिरोधके समय जेल यात्रा की थी। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३, ३३ ३५।

२ देखिए “ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ३० ३१।

३ सर मचरजी मेरवानजी भावनगरी (१८५१-१९३३), भारतीय बैरिस्टर, संसद-सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके सदस्य। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२०।

४ पृष्ठ ० डब्ल्यू० रिच, लन्दन स्थित दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्री।

निशानी केवल एक बात है। मुख्य बात तो यह है कि यह कानून अनिवार्यताके नस्वको लेकर भारतीय समाजको कलकित करता है और उसे हलके दर्जेका समझता है।

फिर भी इस भूलसे कुछ नुकसान होना सम्भव नहीं। विरोधके खिलाफ की गई लडाइके समय यह गलती नहीं हुई। कानून बन जानेके बाद समितिकी सूचनाका कुछ भी असर होना सम्भव नहीं। क्योंकि, आगेका मामला तो भारतीय कौमके हाथमें है। यह कानून यदि भारतीय समाजको दरअमल पसन्द न हो तो चाह जितने सकट आये, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसके परिणामस्वरूप जेल भागेगा तथा उसीमें मृत्यु मानेगा, क्योंकि उसमें उसकी प्रतिष्ठा रहेगी।

श्री रिच लिखते हैं कि भारतीय कौमके दृढ़ निश्चयस जैसा श्री रीज' समितिसे निकल गये वैसे ही और भी कुछ लोग निकल सकते हैं और वे हमें कालिख लगवानेकी सलाह दे सकते हैं। इससे डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि कानूनके सामने न झुकनेको ही भारतीय समाज अच्छा काम मानता है और अच्छा काम करनेमें किसीका डर रखनेकी जरूरत नहीं रहती। भगवान सदा सच्चेका रक्षक रहा है यह समझकर ट्रान्सवालके भारतीयोंने जो सीधा मार्ग अपनाया है उसपर उन्हें कायम रहना चाहिए।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१५ केपके भारतीय

हम देख रहे हैं कि केपके भारतीयोंकी हालत बहुत बुरी होनेवाली है। मेफेकिगने आया हुआ पत्र हमने इस अकमे अग्रिम दिया है। केपके प्रत्येक भारतीय नेताका ध्यान हम उस ओर आकर्षित कर रहे हैं। केपके कानूनकी सबसे बुरी बात यह है कि उसके कारण पास लिये बिना जो भारतीय केप छोड़कर जायेगा वह लौटकर नहीं आ सकेगा। वह पास केवल एक वषर चल सकता है। सैकड़ भारतीय पासके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते। और पास लिया हो तो भी यह नहीं होता कि पास लेनेकी तारीखसे एक वषर सब वापस लौट आयें। इस कानूनमें सम्भव है कि पांच वषरके अन्दर केपमें से भारतीय खदेड़ दिये जायेंगे। हम आशा करते हैं कि केपके अग्रणी भारतीय इस विषयपर खूब ध्यान देंगे और तत्काल प्रभाव निवार्नेवाला उपाय काममें लायेंगे।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१६ स्वर्गीय कार्ल ब्लाइड

श्री कार्ल ब्लाइडके^१ निधनका समाचार तारसे मिला है। वे एक प्रसिद्ध जर्मन थे। उनका जन्म सन १८२६ में हुआ था। स्वतन्त्रताके लिए ओर अग्रे लोगोके अधिकारोके लिए उन्होंने १८४७ से १८४९ के बीच पांच बार कारावास भोगा था। यह कारावास उन्हें सरकारका विरोध करनेके कारण भोगना पड़ा था। एक बार तो सावजनिक कायके लिए उन्हें फासी तक की सजा दी गई थी, किंतु वे बच गये। बादमें आठ वर्षकी जेल और भोगी। अन्तमें लोगोंने उन्हें जबरदस्ती छुड़ाया। वे महापुरुष मैजिनी और गैरीबाल्डीके^२ मित्र थे। उन्होंने जापानको रूसके खिलाफ मदद दी। स्वयं बहुत विद्वान थे। उन्होंने इतिहासकी बहुत सी पुस्तके लिखी हैं। भारतसे उनको प्रेम था। इतना विद्वान आदमी दूसरोके दुःखके लिए जेलका कष्ट भोगे और फासीपर लटकनेको भी तैयार हो, ऐसे उदाहरण हमारे लिए बहुत ही कामके हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१७ हिन्दू विधवाएँ क्या कर सकती हैं ?

भारतमें बहुत सी सम्पदा बेकार जाती है, यह कोई भी देख सकता है। इस सम्पदामें सब चीजें आ जाती हैं। खनिज पदार्थोंकी कोई परवाह नहीं करता। हमारी रई परदेश जाती है और वहासे कपडा आता है। आलपिन जैसी चीज भी हम विदेशोसे लेते हैं। जो हाल पैसेरूपी सम्पदाका है वही मनुष्यरूपी सम्पदाका दिखाई देता है। बहुतेरे बाबाजी और फकीर भीख मागकर ही गुजर करते हैं। किंतु वे देशके या अपने किसी भी काम नहीं आते। क्योंकि इस प्रकार भीख मागनेसे यह नहीं माना जायेगा कि उन्होंने सच्चा वैराग्य या फकीरी ली है। इसी तरह, खासकर हिंदुओमें, विधवा औरते हजारों हैं, जिनका जीवन बिल्कुल बेकार जाता है, ओर उस हद तक भारतीय सम्पदा नष्ट होती है। उसे रोकनेके विचारसे पूनाके एक परोपकारी प्रोफेसर कर्वेने^३ देशको अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे फग्युसन कालेजमें जीवन निर्वाह-भरको पैसे लेकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूनामें विधवाओकी शिक्षाके लिए कुछ वर्षोंसे एक संस्था बना रखी है, जहाँ विधवा स्त्रियोंको दाई या डाक्टरकी काम सिखाया जाता है। इस संस्थाका काम दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। वे स्वयं उसमें बिना पैसा लिये काम करते हैं, इसलिए उन्हें

१ जर्मनीके एक क्रान्तिकारी, जो बादमें इंग्लैंडमें बस गये थे और निरन्तर राजनीतिक स्वतन्त्रताका समर्थन करते रहे थे।

२ ज्युमैपी गैरीबाल्डी (१८०७-८२), इटलीके देशभक्त और सैनिक, जिन्होंने अपने देशकी स्वाधीनताके लिए संघर्ष किया था।

३ आचार्य डॉ. केशव कर्वे (१८५८) वीमेन्स यूनिवर्सिटी, पूनाके प्रतिष्ठाता।

उतनी ही मदद भी मिल रही है। श्रीमती काशीबाई देवयर, श्रीमती नामजोगी, श्रीमती आठवणे तथा श्रीमती देगपाण्डे, ये सब वहने जिहाने उत्तम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है, मदद करती हैं। इसके अलावा वे गात्र-गात्र घूमकर चन्दा इकट्ठा करती हैं। ऐसे काम हम अपने खुदके श्रमसे इतने ज्यादा कर सकते हैं कि उनमें सरकारकी मददकी जरूरत ही नहीं रहती। चतुर्मुखी शिक्षाकी हमें रयान जरूरत है।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

यह कानून अभी 'गजट' में प्रकाशित नहीं हुआ है। इसी बीच विलायतसे आये हुए तारोंसे मालूम होता है कि बड़ी सरकार अब भी उस सम्बन्धमें विचार कर रही है। लाड ऐम्पहिलने^१ लाडमभामें ग्रहम शुरू की ओर लॉर्ड टैन्सडाउनने^२ कहा कि ट्रान्सवालमें बिना अनुमतिपत्रके कुछ भारतीयोंक घुस जानेकी अपेक्षा सारे समाजका अपमान करना ज्यादा खतरनाक है। लाड एलगिनने^३ उत्तरमें कहा कि नये कानूनपर हस्ताक्षर करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब यही हुआ कि भारतीय समाजका कानूनकी शरण नहीं जाना है। कानूनपर इतनी मन्त बहस हुई और उसकी इतनी छीछलेदर की गई है कि अब उसके सामने झुकनेमें भारतीय समाजकी बड़ी बेइज्जती है।

ट्रान्सवालके छींटे

इस कानूनका प्रभाव यही पड़ रहा हो सो बात नहीं। इसके छींटे जमन पूर्व आफ्रिका तक पहुँचे हैं। जमन पूर्व आफ्रिकाके जमन लोग भारतीय व्यापारियोंमें लाभ ता पूरा उठाना चाहते हैं किन्तु देना बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ जमन उसलिंग गये हैं कि यदि भारतीय व्यापारियोंको कष्ट होगा तो अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप करेगी। उसने जवाबमें जमन समदके एक सदस्यने यह कहा है कि जब अंग्रेज सरकार ट्रान्सवालके मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करती तब जमन लागाक मामलेमें क्या करेगी? इसका मतलब भी यही निकलता है कि भारतीय समाजने जहाँ नया कानून स्वीकार किया, समझ लीजिए तुरन्त ही विदेशोंसे उसके पैर उखड़ जायेंगे। फिर तो वे ही भारतीय बाहर रह सकेंगे जो मजदूरी करके प्रतिष्ठा-रहित जीवन बिताना चाहते हो।

एक प्रमुख गोरेकी सलाह

ट्रान्सवाल समदके एक बड़े सदस्यमें मरी मुलाक़ात हुई थी। उसमें मैंने जेलके प्रस्तावके सम्बन्धमें पूछा। उसने तुरन्त उत्तर दिया कि यदि आप लोग जेठ जायें तो फिर

१ (१८६९ १९३६), मद्रासके गवर्नर, १८९९ १९०६, देखिए "लॉर्ड ऐम्पहिल", पृष्ठ ६५।

२ (१८४५ १९२७), भारतके वास्तव्य और गवर्नर जनरल, १८८८ ९३, विदेश मन्त्री, १९०० ६।

३ उपनिवेश-मन्त्री, १९०५ ८।

दूसरी पैरवीकी जरूरत ही नहीं रहती। मैं नहीं समझता था कि भारतीय इतनी हिम्मत करेंगे, और अपनी कौम और आत्मसम्मानके लिए इतना जोश रखेंगे। आप लोग यदि एकतापूर्वक जेलके प्रस्तावपर डटे रहे तो मैं आपकी यथामुम्भव मदद करूँगा। इतना ही नहीं, विलायतमें सारा उदार दल आपके साथ हागा और नया कानून रद होकर रहेगा। उन्होंने महान अंग्रेजी लेखक स्वर्गीय बकका उदाहरण दिया। बकका कतना था कि हजारों लोगोंको फासी नहीं लगाई जा सकती, न उन्हें जेलमें ही बन्द किया जा सकता।

एक गोरा व्यापारी क्या कहता है ?

एक गोरा व्यापारी सयानेपनका उपदेश देने लगा कि भारतीय समाजको कानूनकी शरण जाना चाहिए। उसमें पूछा गया कि उसके पूजाने लड़ाई लड़ी जिससे अब वह अमन चैनसे रहता है, तो इससे उसका क्या यह खयाल है कि दूसरे सभी अमन चैनसे रहते हैं ? इसका जवाब वह नहीं दे सका। आखिर मैंने उससे उसके एक बड़े ग्राहकके सामने पूछा, “यदि आपका ग्राहक अपना सब-कुछ छोड़कर कौमके लिए जेल चला जाये तो वापस आनेपर क्या आपकी नजरमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी ? आप उसे ज्यादा खुले हाथों मदद नहीं करेंगे ? ” इसके जवाबमें उसने कहा “हां, यह तो ठीक है। लेकिन क्या आप लोगमें इतनी हिम्मत है ? ” आखिर बात यहां आकर रुकती है। बाजारमें अभी भारतीयाका सिक्का खोटा है, इसलिए उसकी कीमत भी छोटे सिक्के जैसी ही आती जाती है।

‘स्टार’ के नाम श्री गांधीका पत्र

जनरल बोथाके लौट आनेसे और इसलिए भी कि विलायतमें समिति अभी कानूनक लिए लड़ रही है, श्री गांधीने ‘स्टार’ के नाम निम्न पत्र लिखा है

जनरल बोथा यहां आ गये हैं। बड़ी सरकार और स्थानीय सरकारके बीच अभी लिखा पढ़ी चालू है, इसलिए आपसे तथा आपकी मारफत उपनिवेशवासियोंसे निवेदन करनेका मुझे और भी प्रलोभन होता है। अब “एशियाई विरोधी” लोगोंको उनके मनकी चीज मिल गई, इतनेसे क्या आप सन्तोष नहीं मान सकते ? और क्या उस कानूनको दूर नहीं रख सकते जिसके कारण भारतीय लोग अपराधी माने जायेंगे ? कानून अभी ‘गजट’में प्रकाशित नहीं किया गया है और न उसके प्रकाशित किये जानेकी जरूरत ही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि भारतीय कौमके साथ सलाह करके नये अनुमतिपत्रका नमूना तैयार किया जाये और जिन लोगोंके पास इस समय अनुमतिपत्र हैं उनका उस नमूनेके अनुसार पंजीयन किया जाये। इस प्रकार यदि सभी एशियाई अपने पंजीयनपत्र बदलवा ले तो फिर उसे अनिवार्य करके उनका अपमान करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु यदि ऐसे स्वेच्छसे पंजीयनपत्र न बदलवानेवाले एशियाई ट्रान्सवालमें निकल आये तो उनके लिए एक छोटा विधेयक पास करके लागू किया जा सकता है। इस तरीकेसे सच्चे लोग झूठोंसे अपने आप छूट जायेंगे और सच्चे सजा पानेसे बच जायेंगे।

उपर्युक्त सुझावमें आप गलती निकाल सके, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। किन्तु यदि आप गलती निकालें तो इसका अर्थ यह होगा कि कानूनका उद्देश्य आपसमें

बिकनेवाले अनुमतिपत्रोंको रोकना नहीं, बल्कि भारतीय समाजपर खुलेआम कलक लगाना है। कलकित करनेका उद्देश्य जाहिर हो, इसके पहले मैं आपको लॉड ऐम्प्टहिलके शब्दोंकी याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा है “इस कानूनमें हमारी (ब्रिटिश) प्रजाकी आबरू जाती है, तना ही नहीं है। हम अपने भारतीय नागरिकोंके साथ वचनसे बंधे हुए हैं कि उन्हें हर तरहसे हमारे समान हक है। यह वचन उन्हें हमारे सम्राटने दिया है। हमारे अधिकारियोंने भी यही कहा है। और महान भारतका कारागार भी इसी नीतिपर चल रहा है। हम उन्हें ब्रिटिश राज्यके नागरिक वचनमें अभिमान महसूस करनेके लिए कहते हैं। हम उन्हें समय समयपर कहते रहते हैं कि वे भारतमें चाहे जिस पदपर पहुँच सकते हैं, और अपने व्यवहारके द्वारा हम उन्हें विश्वास कराते हैं कि वे चाहें जिस देशमें हों, पूरी तरह ब्रिटिश नागरिकोंके रूपमें मान पायेंगे।”

इस कानूनसे लॉड लैन्सडाउनका अत्यन्त शर्म मारूम होती है और उनके मनमें ट्रान्सवालकी स्थितिकी अपेक्षा भारतके अपमानका प्रश्न ज्यादा है। मैंने जो सुझाव दिया है उससे ट्रान्सवालकी स्थितिका कोई खतरा नहीं पैदा होता और नये कानूनसे जिस प्रकार अनुमतिपत्ररहित लोगोंको आनेसे रोका जा सकता है उसी प्रकार इस सुझावके अनुसार चलकर भी हाँ सकता है।

सरकार यदि इस प्रकार न करे तो इसका यह साफ अर्थ है कि नये कानूनका उद्देश्य भारतीय कौमका पछाड़नेके सिवा और कुछ नहीं है। तब तो भेड़ और भेड़ियेवाली बात ही रही। चाहें जिस प्रकारसे भेड़ियाभाईको भेड़के प्राण ही लेने हैं।

कैलनबैंककी सहायता

श्री कैलनबैंक जाहानिसवगके प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। उन्होंने भारतीय समाजको धीरे-धीरे जानने तथा जेलके नियमोंको बगल देनेके लिए ‘स्टार’में निम्नानुसार पत्र लिखा है। यह पत्र श्री गांधीके पत्रके साथ ही छपा है।

यद्यपि कुछ कारणोंमें मैं राजकीय कामोंमें भाग नहीं लेता फिर भी भारतीय समाज अपने उचित हककी रक्षाके लिए कानूनके विरोधमें जेठ जानेने प्रस्ताव द्वारा जो मार्चा कर रहा है उसमें गंभीरता आया है।

अखबारोंका टीका तथा ‘स्टार’ में लिखा हुआ श्री गांधीका पिछला पत्र मैंने पढ़ा है। अखबारोंमें जेलके नियमोंपर टीका की गई है। मैं तो निश्चित मानता हूँ कि एशियाई कानूनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी सभ्यमानवी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। और अपनी तकलीफोंके प्रादुर्भाव भी एशियाई लोगोंका यदि तीव्र पीड़ा न हो तो मानना होगा कि वे कानूनन सत्यता पायें हैं यह ज्ञान भिन्न हो गई। इसलिए जो लोग अपने भाइयोंको कानूनन माननेवाले अपमानका दान कराते हैं उन्हें उपद्रवी कह देना सरासर अनुचित है। जो भारतीय कानून ही आपत्तिजनक बातोंको समझ सकते हैं उनका कतव्य है कि वे अपने भाइयोंको वे आपत्तियाँ दिखायें, उन्हें उनकी प्रतिष्ठाका भान करायें और उन्हें सन्तुष्ट करके कानूनन करवानेकी तजवीज करें। मुझे विश्वास है भारतीय व्यापारियोंके व्यापारके डरके कारण हर गोरेकी विवेक-शक्ति खत्म नहीं हो गई। जो भारतीय कानूनका अपमान सहन करनेके बदले जेल जानेको तैयार हैं, उसे एकका नुकसान

उठानेको तैयार है, मैं मानता हूँ कि ऐसे भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवाले तथा उनकी प्रशंसा करनेवाले गोरे बहुत हैं।

म जानता हूँ कि विभिन्न लोगोमें आवश्यकतासे अधिक होड़ चलती है। लेकिन मने यह दखा हे कि युरोपीय लोग उसे बहुत ही बड़ी रूप देते हैं। ब्रिटिश भारतीय सघने जो सूचना दी है, मैं मानता हूँ कि वह बहुत ही उचित है और यदि सरकारने सघकी सलाह मानी होती तो आज जो नाजुक परिस्थिति पैदा हुई है, वह न होती।

अतमें मैं यह भी कहता हूँ कि म तो अपने भारतीय मित्रोंसे कैदखानेमें मिलने भी जाऊँगा उनकी तकलीफें कम करनेके लिए जो भी करना उचित होगा वह करूँगा तथा उसमें मुझे आनन्द और अभिमान महसूस होगा ।

श्री कैलनबैंक इतने उम्दा पत्रके लिए वधाईके पात्र है। उनके जैसे और भी गोरे निकले तो आश्चर्य नहीं। अभी तो हमने कुछ करके नहीं दिखाया, फिर भी श्री कलनबैंक जैसे सज्जन अपनी सहानुभूति व्यक्त करनेके लिए निकल पड़े हैं। फिर जब हम कुछ करके दिखायेंगे तब तो ऐसे बहुतेरे लोग निकलेगें।

सघकी बैठक

जनरल बोथाके पास शिष्टमण्डल ले जानेके लिए शनिवारको ४-३० बजे सघकी बैठक हुई थी। उसमें श्री ईसप मिया (कायवाहक अध्यक्ष), श्री अब्दुल गनी^१, श्री कुवाडिया, श्री नायडू, श्री उमरजी साले, श्री अलीभाई आकुजी, श्री पिल्ले, श्री मुहम्मद, इमाम अब्दुल कादिर आदि सज्जन उपस्थित थे। श्री हाजी हबीब^२ इस बैठकमें हाजिर होनेके लिए ही प्रिटोरियासे आये थे। कुछ मवालोके सुलझ जानेके बाद श्री हाजी हबीबके प्रस्ताव और श्री कुवाडियाके समर्थनसे जनरल बोथाके पास शिष्टमण्डल ले जाना तय हुआ। 'स्टार' में श्री गांधीने ऊपरका जो निवेदन प्रकाशित कराया है उसे मान्य करनेके लिए सरकारसे निवेदन किया जाये और यदि सरकार उसे मान्य न करे और कानूनमें परिवर्तन न करे तो भारतीय कौम इस कानूनको कभी मजूर नहीं करेगी तथा अपने सितम्बर माहके प्रस्तावपर अड़ी रहेगी, इन सब बातोंको भी जनरल बोथाके सामने पेश करनेका निणय हुआ। शिष्टमण्डलमें श्री ईसप मिया, श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी हबीब, श्री मूनलाइट तथा श्री गांधीको भोजना तय हुआ। उसीके अनुसार श्री ईसप मियाने जनरल बोथासे मुलाकातका दिन निश्चित करनेको लिखा है।^३ उस पत्रके 'इ०ओ०' में प्रकाशित होने तक शिष्टमण्डल जनरल बोथासे मिल भी चुकेगा।

सरकार जेलमें न बन्द करे तो क्या कर सकती है ?

ऐसा प्रश्न उठा है कि कहीं सरकार किसी भारतीयपर नये पजीयनपत्रका मुकदमा न चलाकर सारा वष बीतने तक रुकी रहे, और आखिर उसे परवाना न मिलनेके कारण व्यापार बंद करना पड़े। किन्तु यह असम्भव है। क्योंकि बिना परवानेके व्यापारियोंकी सख्या यदि सैकड़ों हो तो वे किसी भी दिन कानूनकी चपेटमें नहीं आ सकते। व्यापारियोंके

१ ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष, १९०३७।

२ ब्रिटिश भारतीय सघकी प्रिटोरिया समितिके मंत्री।

३ देखिए "पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको", पृष्ठ १४१५।

नौकरोंका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। यदि सरकार ऐसा करेगी तो कानूनका होना न होना बराबर हो जायेगा। किन्तु मान लें कि सरकार केवल व्यापारियोंको ही तग करना चाहती है। उम हाऊसमें मैं पहले जवाब द चुका हूँ कि जेलका डर छोड़ देनेके बाद हमें किमी बातसे डरनेकी जरूरत नहीं रहती। सरकारने यदि परवाना न दिया तो उमका नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारी बिना परवानेके भी व्यापार कर सकेगा। इस तरहके व्यापारमें उसे नया पजीयन न करवाने जितनी ही जाखिम है। नया पजीयन न करवानेमें आखिर जेल जाना पड़ेगा। वही बिना परवानेके व्यापार करनेसे भी होगा। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि बगैर परवाना व्यापार करनेपर एक ही व्यक्तिको सजा होगी, अर्थात् दूकान खुली रह सकेगी और नौकर काम चला सकेगे, जबकि नया पजीयन न करवानेपर सभी लोगोंको पकड़ा जा सकता है।

बिना परवानेके व्यापार करनेवालेका माल नीलाम किया जा सकेगा ?

यह सवाल भी उठा है। नेटालके कानूनके अनुसार माल नीलाम किया जा सकता है। किन्तु ट्रान्सवालके कानूनके अनुसार तो यदि जुर्माना न दिया जाये तो जेल ही जाना होगा। जुर्माना तो किसीका देना ही नहीं है। यानी सरकार व्यापारिक परवानेके आधारपर यदि हमें कसना चाहे भी तो सभी दूकानदार और फेरीवाले बिना परवानेके व्यापार करने लग जायेंगे।

क्या दूकान बन्द की जा सकती है ?

बिना परवानेके व्यापार करनेवालेकी दूकान सरकार बन्द कर सकती है या नहीं, यह सवाल भी उठाया गया है। जबरदस्ती दूकान बंद करनेका कानून दक्षिण आफ्रिकामें किसी भी जगह नहीं है। इसलिए उसका डर रखनेकी जरूरत ही नहीं।

क्या विनियमों द्वारा परिवर्तन हो सकता है ?

यह सवाल उठा है कि जनरल बोथा विनियम बनाकर हमें राहत दे सकन है या नहीं, और हम जितनी चाहते हैं उतनी राहत यदि मिल जाये तो भी क्या कानूनका विग्रह करनेकी आवश्यकता रहती है? पहली बात तो यह जानना रहा कि कानून बनानेसे क्या हो सकता है? कानूनमें तो यही हो सकता है कि केवल अँगूठा लगानेसे या सारी अँगुलिया लगानेसे या हस्ताक्षर करनेसे काम चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन बच्चोंका पजीयन करवाना, पुलिसके द्वारा सताया जाना, पुलिसके पास शिनाख्त लिखवाना वगैरह कानूनकी जा खूनी धारणा है उनमें किमी माराम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संक्षेपमें, कानून हमारे जा कागज टीका लगाता है उसे धाराओं द्वारा नहीं पाछा जा सकता। अतः हम जो सुधार चाहते हैं उन्हें कानूनमें परिवर्तन किये बिना करना जनरल बोथाके लिए सम्भव नहीं है। कानूनमें परिवर्तन किया जानेकी आशा करना बिल्कुल बेकार है। अधिकमें अधिक यही हो सकता है कि कानून अभी 'गजट' में प्रकाशित न हो। ऐसा करनेमें दोना पक्षोंकी प्रतिष्ठा रह सकती है। सरकार यदि कानूनमें ऐसा परिवर्तन करे कि वह कानून हमें स्वीकार्य हो जाये तो उसमें उसकी फजीहत होगी।

स्वतन्त्र भारतीय कुत्तोंसे भी गये-बीते

यहाँ आजकल खेतीकी बड़ी प्रदशनी हो रही है। प्रदशनी-समितिके यह नियम बनाया है कि स्वतन्त्र एशियाई या स्थानीय लोग, जो गोरोंके नौकर न हों, प्रदशनी देखने नहीं जा

सकते। इस प्रदर्शनीमें कुत्तोको जानेकी छूट है। इतना ही नहीं, अच्छे कुत्तोको इनाम भी दिया जाता है। ऐसे कुत्तोके मुकाबले स्वतंत्र भारतीय इस गोरी समितिकी नजरोंमें गये-बीते ह।

अनुमतिपत्र कार्यालय

अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कारको बहुत ही उचित साबित करनेवाला एक किस्सा अभी अभी घटित हुआ मालूम पड़ता है। एक भारतीयको सूचना मिली थी कि उसे अनुमतिपत्र दिया जायेगा। उसे कार्यालयमें जाकर अनुमतिपत्र लेना भर था। इसपर उसे सलाह दी गई कि नये कानूनकी कोई बात न निकाली जाये तो उसे अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए। इससे वह अनुमतिपत्र कार्यालयमें गया। श्री चैमनेने उससे कहा कि तुम नये कानूनको मानोगे, ऐसा वचन दो तभी तुम्हें अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा। इसपर उस बहादुर भारतीयने वचन देनेसे इनकार कर दिया और बिना अनुमतिपत्र लिये चला आया। अतः प्रत्येक भारतीयको समझना चाहिए कि अनुमतिपत्र कार्यालय भारतीयोंके लिए एक फन्दा है।

भारतीय व्यापारी क्या कर सकते हैं ?

बहुतेरे भारतीय व्यापारियोंका कहना है कि डच लोग हमारे विरुद्ध नहीं ह। यह दिखानेके लिए वे सरकारको अर्जी देनेको तैयार हैं। यदि यह बात सच हो तो हर भारतीयको उस अर्जीपर [डचोंकी] सही करवानी चाहिए। उस सम्बन्धमें शोर मचानेकी आवश्यकता नहीं। यदि व्यापारी ऐसा करे तो उन्हें अर्जीका फाम भेजा जायेगा। जो ऐसा कर सके वे सबको लिखकर सूचित कर दें।

फेरीवालोक का नून

फेरीवालोक का नून सरकारने [नगर परिषदको] लौटा दिया है। उसमें परवाना ५ पौडका है। उसे सरकारने ३ पौडका करनेके लिए लिखा है। परिषदकी समितिने फिर सूचित किया है कि वसा करनेसे पैसेका नुकसान होगा, इसलिए ५ पौडकी दर कायम रहनी चाहिए।

अनुमतिपत्रका मुकदमा

अभी अनुमतिपत्रके मुकदमे चलते रहते हैं। दो धोबियोंपर झूठे अनुमतिपत्र इस्तेमाल करने और बिना अनुमतिपत्रके रहनेका अभियोग था। उन्होंने बचावमें कहा कि उन्हें एक भारतीय अनुमतिपत्रके लिए यह कहकर ले गया था कि अनुमतिपत्र अधिकारी जोहानिसबर्ग आता है और अनुमतिपत्र देता है। उनसे ३० पौड प्रति व्यक्ति मागा गया। धोबियोंने देना स्वीकार किया। वे भारतीयके घर गये। वहां चेहरेपर नकाब डाले हुए एक गोरेको देखा। गोरेने अनुमतिपत्र दिया। उन्होंने ३० पौड दिये। वे झूठे अनुमतिपत्रके अभियोगसे बरी हो गये। क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि गोरेने जो अनुमतिपत्र दिये हैं वे झूठे हैं। किन्तु बिना अनुमतिपत्रके रहनेके अपराधमें उन्हें सात दिनमें ट्रांसवाल छोड़नेका हुक्म दिया गया। यह गोरा अधिकारी कौन है, यह जानने जैसी बात है। ऐसी अफवाहें बहुत हैं।

एक अभियोग दूसरे भारतीयपर था। वह एक भारतीयके शपथपत्रको लेकर था। वही भारतीय दुबारा बयान देनेमें बदल गया था, इसलिए मजिस्ट्रेटने अपराधी भारतीयको छोड़कर झूठे गवाहको कैद किया। कहावत है कि दूसरेके लिए गड्ढा खोदनेवाला खुद ही उसमें गिरता है। इन महाशयके सम्बन्धमें यही बात चरिताथ हुई जान पड़ती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

१९ अफगानिस्तानमें मुसलमानोंकी हालत

मुसलमानोंकी प्रशासनके सम्बन्धमें श्री सयद अली, बी ए का एक लेख हम पहले द चुके हैं। उस लेखका दूसरा भाग माचके 'इंडियन रिव्यू' में आया है। उससे निम्न सारांश ले रट ह

तुर्की और ईरानके सम्बन्धमें हम विचार कर चुके हैं। अब अफगानिस्तानके सम्बन्धमें विचार करें, जिनमें अभी अभी बहुत ही तरक्की की है। अमीर अब्दुरहमान खानके गद्दीपर बैठनेसे पहले अफगानिस्तानमें कोई राज्यव्यवस्था नहीं थी, यह कहे तो भी अनुचित न होगा, यद्यपि उस समय भी उनकी 'उलु' और 'मलिक' परिषदें थी। कादी यानी गावाके भिन्न-भिन्न भागोंके लोग अपनी ओरसे सारे गावकी परिषदमें सदस्य भेजते थे। वे लोग 'खेल' नामक परिषदके लिए सदस्य निर्वाचित करते थे और उनमें से 'उलु' का निर्वाचन होता था। परन्तु लोगोंके स्वभावके कारण उस समय राज्यकी बागडोर किसीके हाथमें टिक नहीं पाती थी। उस समय चोरी करनेवालेके हाथ काट दिये जाते थे। कोई गुलाम भाग जाये तो उसके पैर काट दिये जाते थे। सरदारोंके हाथमें अलग-अलग विभागोंकी हुकूमत थी। इन सरदारोंके ऊपर अमीर थे। किन्तु वे लोग अमीरकी सत्ता नहीं मानते थे। पठान स्वयं साहसी हैं इसलिए उन्हें इस प्रकारकी अन्धेरीगर्दी अच्छी लगती थी। उस समय उपर्युक्त सजा ही योग्य थी। जनरल एल्फिन्स्टनने 'एक पठानसे पूछा तो उसने जवाबमें कहा "हमें लडाईसँ सतोप होता है। खतरेमें नहीं डरते, खून देखकर हमें चक्कर नहीं आते, परन्तु अपनी आजादी खोकर हम किसी बादशाहको स्वीकार करनेवाले नहीं हैं।"

जब अमीर अब्दुरहमान गद्दीपर बैठे, उन्होंने महान परिवर्तन किये। उनका अपना राज्य रूस और इंग्लैंड दोनोंके बीच विचालिया मा बना हुआ था। इसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया। कभी वे रूसकी ओर झुकते थे तो कभी इंग्लैंडकी ओर। खुलकर झगडा उन्होंने किसीके साथ नहीं किया और अन्तमें इंग्लैंडके पक्षमें रहे। उनकी इस चालाकीसे यूरोपके राजनीतिज्ञ दग रह गये। मरहूम अमीरने हमेशा लाभ उठाया। पर इसके बदलेमें लाभ दिया किसीको नहीं। राज्यके अन्दर भी अत्यन्त कुशलतापूर्वक उन्होंने सरदारोंके जोरको तोड़ दिया। राजस्व

कानूनमें सुधार किये। भारतीय सरकारकी ओरसे जो बारह लाख और अन्तमें अठारह लाख रुपये वार्षिक अपने लिए मिलते थे, उसका उन्होंने उत्तम उपयोग किया। सेना बनाई, गोला-बारूद जुटाया और व्यापारकी वृद्धि की। बेकार कर हटा दिये, टकसाल स्थापित की। इस समयके गद्दीनशीन अमीरने अफगानिस्तानकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दी है। उन्होंने दो सभाएँ स्थापित की हैं, जिनके नाम हैं — 'दरबारेशाही' और 'क्वाजानशाही'। इस प्रकारकी हुकूमतमें पठानोंके स्वभावमें भी परिवर्तन होने लगा है। यदि इसी प्रकार लम्बे अर्से तक चलता रहा तो शमशेर बहादुर पठान पूर्वमें शक्तिशाली राज्य स्थापित कर सकेंगे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अभीतक अफगानिस्तानी प्रजा राजकीय प्रबन्धमें दखल नहीं देती है। अमीर हबीबुल्ला खान बादशाह है। बहादुर योद्धा है और मुल्ला है। उन्होंने भारतमें एक बार भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी थी। १९०५ का संधिपत्र अमीर निभायेगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अमीर हबीबुल्लाकी गिनती अब बादशाहोंमें होती है। उन्हें २१ तोपोंकी सलामी दी जाती है और ईरानके शाहके पास जितनी सत्ता है उतनी ही अब अफगानिस्तानके अमीरके पास है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९०७

२० पत्र 'स्टार' को

पो० ऑ० बॉक्स ३५५३

[जोहानिसबग]

जून ८, १९०७

सेवामें

सम्पादक

'स्टार'

[जोहानिसबग]

महोदय,

मैंने आज 'गजट' में छपी यह सूचना देखी है कि एशियाई कानून-संशोधन अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति मिल चुकी है और वह एक निश्चित दिन, जो नियत करना है, लागू हो जायेगा। मैं नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, किन्तु इससे कुछ अवकाश रह जाता है, और इसलिए मैं जनताके सम्मुख अधिनियमके व्यापारिक पक्षको रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ अपनी कहानी बतानी पड़ेगी। मैं ट्रान्सवालमें पिछले १९ सालसे बसा हुआ हूँ और मुझे सुलेमान इस्माइल मिया एण्ड क० नामकी पेढीका प्रबन्धक साझेदारके रूपमें प्रतिनिधित्व करनेका सम्मान प्राप्त है। मेरी पेढीका यूरोपीय थोक पेढियोंसे बहुत बड़ा लेनदेन

१ अनुमान है कि इसका मसविदा गांधीजीने बनाया था। यह इंडियन ओपिनियनमें १५-६-१९०७ को प्रकाशित किया गया था।

है। उन्होंने, कहना जरूरी हो तो, इस पेढीके साथ अपने कारोबारमे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ उठाया है। जेमिसनके बावके समय पढीने भारी हानि उठाई थी और फिर भी अपने लेनदारोको रुपयेम सोलह आने चुकाये थे। बोअर युद्धमे भी उनकी ऐसी ही अग्नि परीक्षा हुई थी, तब भी लेनदारोका पूरा रुपया चुकाया गया था। और अब तीसरी बार उसके सामने पूरी बरबादी मुह बाये खडी है। पहले दो उदाहरणोमे कारण मानवीय शक्तिसे बाहरका था — कमसे-कम मेरी पेढीके नियन्त्रणसे परे तो था ही। आज उसका कारण अपना उत्पन्न किया हुआ हागा। क्या? सीबी सादी बात यह है कि एशियाई कानून-सशोधन विवेकको प्रत्येक भारतीय, जो उसे समझता है, विगुद्ध दासताका चिह्न मानता है। उमम ट्रान्सवाल, प्रत्येक भारतीयके लिए, जहातक मैं उनके विचार जानता हूँ, कारावास बन जाता है। इसलिए भारतीयाने फैसला किया है कि वे ऐसे कानूनक आगे नहीं झुकेगे, बल्कि उसकी अवज्ञाके जा भी परिणाम हा, उनका भोगेगे। किमी कानूनकी अवज्ञा करना भारतीयाकी प्रवृत्तिके विरुद्ध है। फिर भी इस कानूनक विरुद्ध उनकी भावना इतनी प्रबल है कि इसकी अवज्ञा करना अच्छाई और इसका पालन करना कायरता भरी बुराई माना जाता है। एक भारतीय व्यापारीके रूपमे जो स्थिति मेरी है वैसी स्थिति मेरे जैसे बहुत से लोगोकी है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे सभी भारतीय यह पूरी तरह नहीं जानते कि कानूनकी अवज्ञा करनेपर सामाजिक दृष्टिकोणसे उनकी कितनी हानि हाता है? किन्तु हमन आपक दशवासियाके पास रहकर यह सोचा है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खाने आर अपमान स्वीकार करनेमे ऐसी हानिको सहन करना अधिक अच्छा है। मैं अपन मिलिकयतनामकी मसूखी क्या मजूर करू और अपनी इज्जत खोकर परवाना दफ्तरमे क्या जाऊँ एवं ऐसा नया मिलिकयतनामा क्यों माँगू जिसमे कई प्रतिबन्ध हों? इसके अतिरिक्त मुसलमान होनेके कारण मैं इस बातपर अत्यधिक रोष प्रकट करता हूँ कि तुर्की साम्राज्यक मुस्लिम प्रजाजन अधिनियमके अपमानास्पद जुएसे मुक्त नहीं ह जब कि उसी साम्राज्यके गर-मुस्लिम प्रजाजन मुक्त हैं। मैं आपसे और जनतासे इन तथ्योको अच्छी तरह तोलनेकी प्रार्थना करता हूँ।

यदि सरकारने यह अधिकार अपने हाथमे न रखा होता कि भारतीयाके दृष्टिकोणमे जा स्थिति अनुचित है, उससे वह अब भी हट सकती है, तो मैंने आपको कष्ट न दिया हाता। स्वच्छासे फिर पजीयन करानेका प्रस्ताव मान लिया जाये और यदि वह सफल न हा ता जा उसे कार्यान्वित न करे उनके अनिवार्य पजीयनके लिए एक दिन नियत कर दिया जाये। यह सच है कि स्वच्छासे पजीयन करानेमे भारतीय बच्चापर 'ठप्पा न लगेगा', किन्तु मैं साफ तौरपर मजूर करूँगा कि चाहे मुझे कितनी ही हानि क्या न उठानी पडे, मैं उस कानूनकी अवज्ञा करनेम न रुकूँगा जिसका अर्थ यह हाता है कि मैं अपने एक दिनके बच्चेका हुलिया लिखाऊँ और यह मौन स्वीकृति दे दू कि वह दुःखमुहा बच्चा भविष्यका भयकरतम अपराधी है। मैंने अपने कई यूरोपीय मित्रासे बातचीत की है। उन सबका यह खयाल है कि हमारी माँग बहुत ही उचित है। मैं आपसे और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ट्रान्सवालमे सम्मानपूर्ण जीवन बितानेके सद्यषमे हमारा समर्थन कर। ईसा जितने ईसाइयोके नबी हैं उतने ही मुसलमानोके भी हैं। उन्होंने एक जगह कहा है "दूसरोके साथ वैसा बरताव करो जैसा

तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करे।” क्या मैं इस ईसाई सरकारसे इस बुद्धिमत्तापूर्ण उक्तिके अनुसरणकी प्रार्थना करूँ ?

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ११-६-१९०७

२१ पत्र प्रधान मन्त्रीके सचिवको

जोहानिसबरा
जून १२, १९०७

कायवाहक सचिव

प्रधान मन्त्री

[प्रिटोरिया]

महोदय,

आपके इसी मासकी ४ तारीखके पत्र सं० १४/१ के सम्बन्धमें, मुझे इस बातपर खेद है कि प्रधान मन्त्री एशियाई पजीयन अधिनियमके^१ बारेमें मेरे सघके शिष्टमण्डलसे मिलना अनावश्यक समझते हैं।

किन्तु यह देखते हुए कि अभी कानूनको लागू करनेकी तारीख ‘गजट’ में प्रकाशित नहीं हुई है, मेरा सघ सरकारसे एक बार फिर प्रार्थना करता है और सादर मुझाव देता है कि स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये और यह अधिनियम बादमें, एक छोटे विधेयकके द्वारा, उन लोगोपर लागू कर दिया जाये जो स्वेच्छया पजीयनके प्रस्तावपर अमल न करे।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

१ प्रधान मन्त्रीका खयाल था कि इससे कोई ‘उपयोगी उद्देश्य’ सिद्ध न होगा, क्योंकि अधिनियमसे सम्बद्ध सम्राट्की स्वीकृतिकी घोषणापर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

२२ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबग

जून १२, १९०७

प्रिय छगनलाल,^१

माटेग्यू जायदादमे, उनके द्वारा किये गये विस्तारके कारण, हमे अतिरिक्त कुछ नही मिलनेवाला है।

मुझे हप है कि कठिनाइयाँ आगेके काय और आगेकी प्रवृत्तियोंके लिए एडका काम करती है। नि सदेह उनका इसी अग्रमे समझना उचित है। ऐसे लोग पीछे हटना या निराश होना नही जानते। तुमने इस साधारण कहावतको उद्धृत किया है कि जो कर्तव्यकी प्रेरणाओके अनुसार काय करते हैं उन्हें सफलता मिलनी ही चाहिए, और ऐसा ही हाना है। परन्तु हमे मतक रहना चाहिए कि हम 'सफलता' शब्दका गलत अर्थ न लगाये। जहा बहुत सी चीजे, जो धार्मिक नही होती, गलतीमे बसी मान ली जाती हैं वहा बहुत-सी बात, जिन्हें हम असफलताएँ समझते हैं, वास्तवमे सफलताएँ होती हैं। इसलिए, इस कहावतकी सत्यताको तो हम स्वीकार कर सकते हैं परन्तु हम सदैव जो काय करना है उसपर दृष्टि रखनी चाहिए और परिणामकी परवाह नही करनी चाहिए।

जहातक मेरा सम्बन्ध है, तुम 'इंडियन आपिनियन' मे इस अधिनियमके^२ तमिल, हिन्दी और उर्दू अनुवाद छाप सकते हो और मेरे पाम अलगसे पत्रक भेज सकते हो। इनको हम जितना ही बाटेगे उतना ही अच्छा होगा। यह अधिनियम अपनी निन्दनीयता आप ही बनाता है। मैं देखता हूँ कि यहाँ भी लोगोपर इसका ऐसा ही प्रभाव पडा है। यद्यपि तुमने मेरे पास चारू अक्की ३५० प्रतियाँ भेजी थी, बहुत कम प्रतिया बच रही हैं। व्यामने प्रिन्टोरियाके लिए ६० प्रतिया मँगवाई थी, और अन्दरूनी इलाकोसे आज मेरे पास १५ प्रतियाकी माँग आई है।

गुजराती टाइपके बारेमे मुझे कोई उत्तर नही मिला है। गोकलदासने^३ मुझे लिखा था कि वह इधर ध्यान देगा, परन्तु उसने मुझे हर तरहसे निराश ही किया है। वह काहिल, लापरवाह और अविश्वासी हो गया है।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

मो० क० गा०

गांधीजीके सक्षिप्त हस्ताक्षर युक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४७५४) से।

१ गांधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके पुत्र। ये इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभाग तथा फीनिक्समें छापाखानेकी देख-रेख करते थे।

२ एशियाई पंजीयन अधिनियम।

३ गांधीजीकी बड़ी बहन रलियातबेनके पुत्र।

२३ शाही स्वीकृति

पजीयन अधिनियमके लिए बहुत दिनोंसे टलती आई शाही स्वीकृति अब 'गजट' में प्रकाशित हो गई है। जनरल बोथाने यद्यपि लाड एलगिनको इस बातका आश्वासन दिया है कि वे ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंका खयाल रखेंगे तथापि उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके एक शिष्ट मण्डलसे मिलना अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि उससे कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि वह कानून पिछले सप्ताह 'गजट' में छप जानेवाला था। लेकिन हम देखते हैं कि यद्यपि कानून 'गजट' में छप गया है, तथापि उसके अमलकी तिथि अनिश्चित कालके लिए बढ़ा दी गई है। वह या तो अभी तय होगी या फिर कभी नहीं होगी। ब्रिटिश भारतीय सघके कायवाहक अध्यक्ष श्री ईसप मियाका पत्र^१, जो 'स्टार' में छपा है और जिसे हमने भी उद्धृत किया है, बहुत ही समयोचित है। श्री ईसप मिया, जो बहुत पुराने व्यापारी हैं और जिनके बहुत बड़े स्वाथ दावपर हैं, जनतासे कहते हैं कि उन्होंने इस कानूनके अपमानको इतने मार्मिक रूपसे अनुभव किया है कि अगर इस कानूनके सामने न झुकनेके लिए उन्हें यही कीमत चुकानी पड़े, तो वे अपना सब-कुछ बलिदान करनेके लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत ही तकसगत प्रस्ताव रखे हैं कि कानूनको लागू करनेकी तिथि अभी निश्चित न की जाये और ब्रिटिश भारतीयोंको और अन्य एशियाइयोंको अपनी नेक-नीयतीका सबूत देनेके लिए इस बातकी छूट दी जाये कि वे स्वेच्छासे अपना पुनः पजीयन कराये। अगर यह प्रयोग असफल साबित हो तो वह कानून उन लोगोपर लागू किया जाये जिन्होंने स्वेच्छासे अपना पुनः पजीयन न कराया हो। हमे आशा है कि ट्रान्सवाल सरकार इस स्पष्टतया उचित सुझावको मान लेगी। जनरल बोथाने ट्रान्सवालकी जनताकी तरफसे कई बार साम्राज्य सरकारके प्रति, ट्रान्सवालको दिये गये उदार विधानके लिए, गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है, और अपनेको सम्पूर्ण साम्राज्यके लिए चिन्तित बताया है। अगर वे भारतको भी साम्राज्यका अंग मानते हैं तो इस बातकी आशा की जा सकती है कि इस आखिरी क्षणमें भी वे भारतीय समझौतेको स्वीकार करके ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंको दुखाना टाल देंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२४ कानूनका अत्याचार

जो पार उतारे औरोको, उसकी भी नाव उतरनी है ।
जो गक करे फिर उसको भी याँ डबकु-डबकु करनी है ।
शमशीर तबर बढूक सना और नशर तीर नहेरनी है ।
याँ जैसी-जसी करनी है, फिर वैसी वैसी भरनी है ।

कविने यो गाया है। 'जैसी करनी वैसी भरनी,' यह जगतप्रसिद्ध कहावत है। इस तरहका जो नियम है वह भारतीय समाजके लिए कुछ बदल नहीं जायेगा। जैसे कडवी बेलमे मीठा फल नहीं लग सकता, पलाममे आम नहीं लग सकता, वैसे ही ट्रान्सवालके भारतीय करेगे कुछ, और होगा कुछ—सो भी नहीं हो सकता। वे लोग मर्दानगी दिखायेंगे तो मदके समान रह सकेंगे। सम्मानके योग्य बात करेंगे तो सम्मान भोगेंगे। दिया हुआ वचन पालेंगे और कहा हुआ करके दिखायेंगे तो उनकी शोभा बढ़ेगी। किन्तु यदि स्वाथ, डर या अन्य किसी कारणसे प्रतिज्ञा-भ्रष्ट होंगे तो समझ लीजिए कि ट्रान्सवालसे भारतीय समाजके अधिकार लद गये। इतना ही नहीं, ट्रान्सवालवालोंके साथ दूसरे भी पिस जायेंगे। ट्रान्सवालमें भारतीय समाजने ऐसा ही बड़ा काम अपने सिर लिया है।

इसके अलावा कवि कहता है कि जो दूसरोको पार उतारेगे वे स्वयं भी पार जायेंगे, यह भी दुनियाका—प्रकृतिका या खुदाका कानून है। यदि हम दूसरेका काम इस तरह करेंगे तो हमारा अपने आप हो जायेगा। बाकी तो पक्षी और जानवर भी करते हैं। किन्तु मनुष्य और पशुमे मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य परोपकारी प्राणी है। जहाँ लोग प्रजाके सुखमे अपना सुख मानते हैं वहाँ सब सुखी रहते हैं। जहाँ सब अपना-अपना देखते हैं, वहाँ सब बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि "जो गक करे फिर उसको भी या डबकु डबकु करनी है।" यह विचार गम्भीर है और सोचे तो सही भी है। जो माँ दुख उठाकर बच्चेकी परवरिश करती है, वह अन्तमे सुखी होती है, कुटुम्बमे जहाँ सब आपसमे एक-दूसरेका दुख बँटाने हैं और अपने दुखकी परवाह नहीं करते, वहाँ कुटुम्ब व्यवस्था निभती चलती है, समाजमे लोग स्वयं दुख उठाकर समाजकी रक्षा करते हैं और उसके द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जहाँ लोग देशके लिए दुख उठाते हैं, मरते हैं, वहाँ वे जिन्दा रहते हैं और देशका नाम चमकाते हैं। इस तरहके गूढ़ नियमको तोड़कर कौन भारतीय सुख भोगना चाहता है? ये उदाहरण स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर देते हैं कि यदि ट्रान्सवालके भारतीय कौमके लिए—अपनी प्रतिष्ठाके लिए—सारे दुख सहनकर, आपत्तियाँ उठाकर, हाथमें लिया हुआ काम पूरा करेंगे तो उनकी विजय होगी। वे अपने वचन काटेगे और इतिहासमे अपना नाम अमर करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२५ रोडेशिया और ट्रान्सवाल

रोडेशिया विधानसभामें चर्चा शुरू हुई है कि जब ट्रान्सवालमें एशियाइयोंके लिए कानून बन गया है तब यहाँ भी बनाया जाना चाहिए तथा भारतीयोंको आनेसे रोकना और उनका पजीयन करना चाहिए। सभी सदस्य इस सम्बन्धमें जोरसे बोले थे। वे सारी बातें हमने ब्योरेके साथ अंग्रेजी विभागमें दी हैं। उनसे हमें यही देखना है कि यदि ट्रान्सवालका कानून कायम रह गया और भारतीय समाज उसके सामने झुक गया तो हर जगह वैसा ही कानून बनाया जायेगा। रोडेशियाके भारतीयोंको केवल इसी तरह मदद दी जा सकती है कि ट्रान्सवालके भारतीय पीछे पैर न रखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२६ गिरमिटिया भारतीय मजदूर

थॉनविल जक्शनमें एक गोरेने एक भारतीय गिरमिटियोंको बुरी तरह पीटा और वह भारतीय मर गया। गोरेपर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसे १० पौंड जुर्माना हुआ। इसका पूरा विवरण हम अन्यत्र दे रहे हैं। यह मामला रोगटे खड़े कर देनेवाला है। भारतीय मर गया और गोरा दस पौंड देकर छूट गया, इसे सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता। फिर भी हमें बदला लेनेके सम्बन्धमें नहीं सोचना है। गोरेको जगतकतकि समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। उसे कठोर दण्ड दिया जाता तो न उससे भारतीयकी जान वापस आती और न दूसरे गिरमिटिये ही वैसे व्यवहारसे बच पाते।

रोग दूर करनेके लिए उसका कारण ढूँढना चाहिए। उसी प्रकार इस स्थितिका कारण खोजेंगे तो पता चलेगा कि गिरमिटकी प्रणाली ही बुराईकी जड़ है। यदि गिरमिटकी प्रणाली ही समाप्त हो जाये तो उपर्युक्त अत्याचार भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि स्वतन्त्र नौकरीमें मनुष्य गिरमिटियाके समान बँध नहीं जाता। उसे पूरा न पड़े तो वह अलग हो सकता है।

श्री राबिन्सनने अपने भाषणमें कहा है कि गिरमिट द्वारा भारतीयोंका आना बन्द होना चाहिए। हम भी ऐसा ही मानते हैं। और इसके लिए कांग्रेसको कारगर उपाय काममें लाना चाहिए। गिरमिट बन्द करनेके हमारे और श्री राबिन्सनके कारण अलग-अलग हैं, किन्तु इसमें कुछ हज नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२७ पूर्वका ज्ञान

जलालुद्दीन रूमी

‘पूर्वका ज्ञान’ नामक पुस्तकमाला इस समय विलायतमें ठापी जा रही है। उसमें से दो पुस्तकें हमारे पास समालोचनाथ आई हैं। पहलीका नाम ‘बुद्ध शिक्षा’^१ और दूसरीका ‘ईरानी सूफी’^२ है। लेखकने ‘ईरानी सूफी’में प्रथम स्थान जलालुद्दीन रूमीको^३ दिया है, उसमें सूफी लोगोका वर्णन, जलालुद्दीनका जीवन वृत्तान्त और उनकी कुछ कविताओका अनुवाद दिया गया है। लेखकका कथन है कि सूफियोको खुदाके बंदे माना जा सकता है। उन लागोकी प्रवृत्ति मुख्यतः हृदय शुद्धि और ईश्वर-भक्तिकी ओर है। कहा जाता है कि एक बार जलालुद्दीन रूमी एक मृत्यु सस्कार देखकर नाचने लगे। इसपर जब कुछ लोगोंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों तो उत्तरमें वे महात्मा बोल उठे “जब पिजड़ेसे जीव बाहर आता है, अपने दुखसे छुटकारा पाता है और अपने सिरजनहारसे मिलने जाता है तब मैं क्यों न खुश होऊँ ?” मालूम होता है कि पुराने जमानेमें स्त्रिया भी ऐसी बातोंमें स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिया करती थी। राबिया बीबी स्वयं सूफी थी। उनमें ईश्वरके प्रति प्रेम इतना गहरा था कि जब किसीने उनमें पूछा कि “आप इवलीसकी निंदा करती हैं या नहीं,” तब उन्होंने तुरन्त जवाब दिया, “मैं ईश्वरका भजन करनेमें इतनी लीन रहती हूँ कि मेरे पास दूसरेकी निन्दा करनेका समय ही नहीं रहता।” सूफी सम्प्रदायके उपदेशोंके अनुसार कोई भी धर्म जिसमें नीति हो बुरा नहीं होता। किसीके पूछनेपर जलालुद्दीनने उत्तरमें कहा था, “जितने जीव हैं, ईश्वरको याद करनेके उतने ही मांग हैं।” वे फिर कहते हैं “ईश्वरका नूर एक है, परन्तु उसकी किरणें अनेक हैं। हम जिस शाखासे चाहे, सच्चे हृदय और शुद्ध वृत्तिके साथ ईश्वरका भजन कर सकते हैं।”

सच्चा ज्ञान क्या है— इस सम्बन्धमें जलालुद्दीन कहते हैं कि “खूनका दाग पानीमें धोया जा सकता है, परन्तु अज्ञानका दाग तो केवल ईश्वरके प्रेमरूपी जलसे ही मिटाया जा सकता है।” इसके उपरान्त कवि कहता है कि “सच्चा ज्ञान तो केवल ईश्वरका ज्ञान है।” ईश्वर कहाँ है— इस प्रश्नके उत्तरमें कवि कहता है, “मने क्रूस तथा ईसाई लोगोको देखा, परन्तु मैंने ईश्वरको क्रूसमें नहीं देखा। मैं मदिरोमें गया, वहाँ भी उसे नहीं देखा, हिमाल और कन्दहारमें भी वह नहीं मिला, और न मिला कन्दरामें। अन्तमें मैंने उसे अपने हृदयमें ढूँढा तो मुझे वह वहाँ दिखाई दिया। अयत्र कही नहीं।” यह पुस्तक बहुत पठनीय है। यदि इससे ऊपरके जैसे बहुत से वाक्य उद्धृत किये जायें, तो भी वे खत्म होनेवाले नहीं हैं। हम इस पुस्तकको मँगवानेकी सबमें मिफारिश करते हैं। इसे पढ़कर हिन्दू तथा मुसलमान बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसका मूल्य विलायतमें २ शिल्लिंग है।

१ द वे ऑफ बुद्ध ।

२ पर्शियन मिस्टिक्स ।

३ (१२०७-७३), ईरानके सूफी कवि ।

शेख सादीका 'गुलिस्ता' भी वहीसे अंग्रेजीमें प्रकाशित हुआ है। उसका मूल्य १ शिलिंग है। 'कुरान शरीफका सार' नामकी पुस्तक भी है। उसकी कीमत १ शिलिंग है। 'बुद्ध शिक्षा' का मूल्य २ शिलिंग और 'जरथुस्त्रके उपदेश' का भी २ शिलिंग है। अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित होनेवाली हैं। इनमें से यदि कोई पुस्तक हमारे पाठकोको चाहिए तो उसके उपयुक्त मूल्यमें प्रति पुस्तक ६ पेनीके हिसाबसे जोड़कर हमें रकम भेज दी जाये। हम पुस्तक खरीदकर भेज देंगे। छ पेनी आवश्यक डाकखर्चके लिए है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

जनरल बोथाने 'खोदा पहाड मारा चूहा' के अनुसार काम किया है। उन्होंने सघको लिखा है कि कानूनको लागू करनेकी सारी तैयारी हो चुकी है, अतः शिष्टमण्डलके मिलनेकी आवश्यकता नहीं। इसलिए सभी 'गजट' देखनेमें लग गये। उसमें कानूनके लागू होनेकी तारीख वगैरह छपनेकी राह देखी। लेकिन 'गजट' में वैसी कोई बात नहीं मिली। 'गजट' में सिर्फ इतनी ही खबर है कि कानूनको सम्राटने स्वीकार कर लिया है। यह कोई नई खबर नहीं है। इसके अलावा उसमें दूसरी खबर यह है कि कानूनको लागू करनेकी तारीख बादमें निश्चित की जायेगी। इसका क्या अर्थ? मैं तो यह अर्थ करता हूँ, सरकार इस चक्करमें पड़ी है कि भारतीय समाजने जेल जानेका जो निणय किया है उसका क्या किया जाये और कानूनको किस प्रकार अमलमें लिया जाये। अर्थ यह हो या दूसरा, इतना तो निश्चित है कि सरकार जेलके प्रस्तावके सम्बन्धमें सोचमें पड़ गई है।

कुछ प्रश्न

इस तरह, स्थिति डावाडोल है। इस बीच भारतीय समाजके लिए अनिवार्य है कि वह अपने हथियार सजाकर तैयार रखे। अब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह अच्छा लक्षण है। एक प्रश्न तो यह पूछा गया है

हमारे विलायतके हितचिन्तक जेलका प्रस्ताव नापसन्द करें तो ?

यह प्रश्न ठीक किया गया है। इसका उत्तर भी सीधा है। समितिके सदस्य अथवा विलायतके अन्य सज्जनोको वहीतक अपना हितचिन्तक समझा जाये जहातक वे हमें अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारकी रक्षा करनेमें मदद करें। उनके विचारोका हम आदर करें किन्तु जब उनके विचार हमारे अधिकारके विरुद्ध जाते हो तब हम उन विचारोसे बँधे हुए नहीं हैं। मान लो कि हमें कोई ईसाई बननेके लिए विवश करता है तो उसका हम विरोध करेंगे। मान लो कि हमारे आजतक हितचिन्तक माने जानेवाले लोग हमें सलाह देते हैं

कि हम ईसाई हो जाये। मुझे विश्वास है कि हम ऐसी सलाहको माय नहीं करेंगे, और इसमें हर हिन्दू और मुसलमान मुझसे सहमत होगा। यह कानून भी लगभग उमी तरहका है। यह हमें नामद बनाता है, यह स्पष्ट है, और नामद बननेकी सलाहका हम कभी नहीं मान सकते। हम सच्चे हैं और खुदा हमारे पक्षमें है इतना काफ़ी है। अन्तमें सत्यकी ही विजय होगी।

जिन्हें सूचनापत्र मिल चुके हैं वे क्या करें ?

नेटालसे एक भाई पूछते हैं कि उन्हें ट्रान्सवाल जानेका आदेश मिला है। उन्हें जाना चाहिए या नहीं ? इतना तो सब जानते होंगे कि यह आदेश अनुमतिपत्र नहीं है। इस आदेशके आधारपर अभी ट्रान्सवाल जाना बेकार है। कौमके निणयके अनुसार अनुमतिपत्र-कार्यालयमें व्यवहार मात्र बन्द है। इसलिए वह आदेश किसी कामका नहीं है। जिनके पाम पुराने अनुमतिपत्र न हो, उनके लिए ज़रूरी है कि वे ट्रान्सवालमें पैर न रखें।

अनुमतिपत्र खो गया हो तो क्या करें ?

जिनने अनुमतिपत्र खो गये हो उन्हें पुराने कानूनके अनुसार प्रतिलिपि नहीं दी जाया करती थी। नये कानूनमें प्रतिलिपि देनेकी व्यवस्था है, किन्तु वह नये अनुमतिपत्रकी प्रतिलिपि होगी। जिसका अनुमतिपत्र खो गया हो उसे कुछ भी कारवाई नहीं करनी है। उसे दूसरे अनुमतिपत्रवालोंके समान निभय होकर बैठना चाहिए।

जिसका अनुमतिपत्र खो गया हो वह प्रवेश कर सकता है ?

एक व्यक्तिका अनुमतिपत्र खो गया। उसे अनुमतिपत्र-कार्यालयकी ओरमें प्रमाणपत्र मिला हुआ है। क्या वह भारतसे लौटनेपर वापस प्रवेश कर सकता है ? उत्तर वह व्यक्ति अनुमतिपत्रवालोंके समान प्रवेश कर सकता है। किन्तु आखिर जेल जाना है, इस बातको याद रखें। जिसे जेलसे डर लगता हो उसके पास अनुमतिपत्र हो या न हो, उसे फिट्टाल ट्रान्सवालमें प्रवेश नहीं करना चाहिए।

परवानेके लिए श्री चैमनेके हस्ताक्षर ?

एक व्यक्तिने वॉक्सबर्गमें परवाना माँगा। उसे परवाना अधिकारीने श्री चैमनेके हस्ताक्षर लानेको कहा। अधिकारीने ऐसा कहा हो तो उसे गैरकानूनी समझा जाये। नया कानून जबतक लागू नहीं होता तबतक अनुमतिपत्र बनलाना भी अनिवार्य नहीं है, तब श्री चैमनेकी अनुमतिकी ता बात ही कौन-सी ?

परवानेके सम्बन्धमें जवाब देते हुए मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि एक सवाद-दाता लिखता है कि कोई कोई बिना परवानेके व्यापार करते हैं। परवाना किमीके नामका और व्यापार किसी औरका, वगैरह। सवाददाताने ऐसे लोगोंके नाम भी भेजे हैं। सब-झूठकी मैं जाँच नहीं कर पाया। किन्तु ऐसे लोगको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यदि सवाददाताकी दी हुई खबर सही हो तो मैं ऐसे लोगोंको सलाह देता हूँ कि वे यह समझकर अपनी बुरी आदत सुधार लें कि कुछ भारतीयोंके गलत कामोंके कारण सारे भारतीयोंको दुख भोगना पड़ता है, और ऐसा आचरण करनेवाले व्यक्तिको भी देर-अबेर सजा भोगनी ही पड़ती है।

चीनियोंकी एकता

चीनियोंने नये कानूनके सामने न झुकनेका निणय किया हे। इस सम्बन्धमे लिख चुका हूँ। वैसा निणय करके वे बैठे न रहे इसलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये हैं कि इस प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करनेवाला नया अनुमतिपत्र नहीं लेगा, जेल जायेगा और जो कोई नया अनुमतिपत्र लेगा उससे भोजन पानीका व्यवहार नहीं रखेगा। इस प्रतिज्ञापत्रपर लगभग नौ सो चीनियोंने हस्ताक्षर कर दिये हैं, सिफ एक सौ हस्ताक्षर लेने बाकी है। वह काम भी जोरोसे चलता दिखाई दे रहा है^१।

एक सुझाव

इस प्रस्तावके सम्मर्पमे कि दूकानका चालू रखनेके लिए दरखास्त देनेके अन्तिम दिन, या जेलसे छूटनेके बाद प्रत्येक दूकानसे एक व्यक्ति अनुमतिपत्र ले सकता है, दूकानदारोको सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार जो अपना व्यापार चालू रखना चाहते हैं वे अपनी कमाइमे से सारा खर्च निकालकर जो बचत हो उसे कानूननिधिमे डाल दे। यदि दूकानदार उक्त सुझावको स्वीकार करते हैं तो उनका यह काय अत्यन्त देशभक्तिपूर्ण होगा।^१

एक हजूरियेपर मुकदमा

एक भारतीय हजूरियेपर पजीयन कार्यालयके मुख्य कारकुनको रिश्वतमे ५० पौंड देनेके अपराधमे प्रिटोरियामे मुकदमा चलाया जा रहा है। एक भाई टीका करते हुए पूछते हैं कि क्या इस तरह रिश्वत देनेवाले आज ही तैयार हुए हैं? इतने दिन तक किसीने रिश्वत देनेका प्रयत्न नहीं किया? यदि प्रयत्न किया गया हो तो उनपर मुकदमा क्या नहीं चलाया गया?

जोहानिसबर्गके निवासियोंको चेतावनी

पुलिस कमिश्नरने सूचना निकाली है कि आजकल बत्ती निरीक्षक बनकर बहुतेरे ठग घरमे घुसनेका प्रयत्न करते हैं। यदि वे नगरपालिकाका पास न दिखाये तो उन्हें कोई अपने घरोमे न आने दे।

फेरीवालोका कानून

फेरीवालोके कानूनके विषयमे अब भी विवाद जारी है। 'स्टार' मे एक महाशय लिखते हैं कि फेरीवालोसे हर नगरपालिकाकी हदमे परवाना मांगा जाये और हदके बाहर भी मांगा जाये। इससे हर फेरीवालोको हर वर्ष ८० पौंड तक देने होंगे। इस तरह जुल्म किया जानेपर फेरीवाले मर जायेंगे और लोगोको फेरीवालोसे जो सुविधा मिल सकती थी वह, दूकानदारोके लाभके लिए, नहीं मिलेगी। इससे कोई यह न समझ ले कि यह लेखक भारतीयोका पक्ष ले रहा है। भारतीयोके अलावा और भी फेरीवाले हैं। किन्तु ये नियम सबपर लागू होते हैं, इसलिए इसमे भारतीयोका बचाव अपने आप हो जाता है।

^१ चीनी सघने बादको लदन स्थित चीनी राजदूतके पास एक याचिका भेजी थी जिसमें अधिनियमके खिलाफ आपत्ति की गई थी। देखिए परिशिष्ट २।

सारांश यह है कि जा नियम विशेषकर भारतीयोंके लिए बनाये जाये उन्हें उनका विरोध करना चाहिए।

शिक्षाका कानून

दस महीनेमें फिर ससदकी बैठक होगी। उसमें नई सरकार शिक्षा विषयक विधेयक पेश करनेवाली है। उस विधेयकमें एक धारा यह है कि गोरे लड़कोंकी पाठशालामें काले लड़के नहीं जा सकेंगे। यानी यदि कोई निजी शाला शुरू करके उसमें गोरे और काले लड़कोंको एक साथ पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ा सकता। काले लड़कोंके लिए सरकारकी इच्छा होगी ता अलगसे शाला शुरू करेगी। यह एक नया ही खेल है। नया कानून स्वीकार करनेके बाद भारतीयोंको क्या मिलनेवाला है, यह हमें शिक्षा विधेयकसे मालूम हो जाता है।

मलायी बस्ती

मलायी बस्तीकी गन्दगीके सम्बन्धमें 'स्टार' में एक भाईने लिखा है। उससे मालूम होता है कि उसमें भारतीयोंका नहीं, बल्कि नगरपालिकाका दोष है। क्योंकि, नगरपालिका न गन्दा पानी उठावाती है और न पीनेके पानीके नल लगवाती है। इसके उत्तरमें नगरपालिकाने लिखा है कि गन्दा पानी उठाया जाता है और बहुत जगहोंपर पानीके नल भी हैं। लोग पैसा खर्च कर तो दूसरी जगह भी दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाके अधिकारीका कहना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि मलायी बस्तीके निवासी गन्दे नहीं हैं। कुछ लोगपर गन्दगीके लिए मुकदमा भी चलाया जा चुका है। मुझे भी स्वीकार करना चाहिए कि गन्दगीके आरोपसे हम इनकार नहीं कर सकते। बहुतेरे घरोंमें कूड़ा रहता है, खिड़कियाँ गन्दी रहती हैं, बाड़ा गन्दा रहता है, पाखानेकी स्थिति बड़ी भयानक होती है और रसोई घर बहुत ही खराब होता है। मैं यह सब पाप मानता हूँ। उसके लिए हमें बहुत सजा भोगनी पड़ती है और आगे भी भोगनी पड़ेगी। लोग सुघरता, खुली हवा और प्रकाशका मूल्य समझने लगे तो हमें बहुत लाभ हो सकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२९ पत्र उपनिवेश सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
जून १८, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

परममाननीय प्रधान मन्त्रीके कायवाहक सचिवने मुझे सूचना दी है कि मेरा इस माहकी १२ तारीखका पत्र, जो एशियाई पजीयन अधिनियमके बारेमें है, आपके विभागको भेज दिया गया है।

मेरा सघ इस बातकी उम्मीद करता है कि इस पत्रमें जिस मसलेका जिक्र है उसपर आप अनुकूलतापूर्वक विचार करेंगे।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३०. नये कानूनसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता

पुरस्कार प्राप्तकर्ता अम्बाराम मगलजी ठाकर

नये कानूनके सम्बन्धमें गीत लिखवानेके लिए हमने पुरस्कारकी योजना^१ शुरू की थी। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे कुल मिलाकर सन्तोषजनक माना जा सकता है। प्रतियोगितामें शामिल होनेवाले २० व्यक्ति थे। सभी कवियोंने सूचित किया है कि उन्होंने पुरस्कारके लिए नहीं, बल्कि अपना उत्साह दिखाने तथा देशसेवाके लिए ही प्रतिस्पर्धामें भाग लिया है। यह उत्साह और भावना प्रशंसनीय है। किन्तु फिर भी हमें कहना चाहिए कि पुरस्कारके लिए लिखनेमें भी देशाभिमानका समावेश नहीं होता, सो बात नहीं। पुरस्कार लेनेमें हमें झेपना नहीं, बल्कि गव महसूस करना चाहिए।

बीस प्रतियोगियोंमें कोई तीन व्यक्तियोंके गीत लगभग समान जान पड़े। इसलिए यह समस्या खड़ी हो गई थी कि किसे पहला स्थान दिया जाये। आखिर नेटाल सनातन धर्म

१ देखिए “एक पौडका इनाम”, पृष्ठ ५।

सभाके अध्यक्षका गीत लगभग पहले स्थानके योग्य मालूम हुआ, इसलिए हमने उन्हें एक पौडका पुरस्कार भेज दिया है। श्री अम्बाराम ठाकरका हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि गीतमें जो उद्देश्य रखा गया है उसके अनुसार स्वयं चलकर वे दूसरोंके सामने आदर्श पेश करेंगे और देशकी सेवा करेंगे। भक्तिमें शौचका और शौचमें भक्तिका समावेश हो तभी उन दोनोंकी शांति बढ़ती है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों पास रखकर हम अपने कतव्यका पालन करते रहेंगे तभी प्रत्येक सकटमें गुजरकर अंतमें विजयी होंगे।

बीस गीतोंके रचयिताओंमें से कुछने अपने नाम हमें भी नहीं बताये। कुछने एकसे ज्यादा गीत भेजे हैं। उनमें से जानने योग्य गीत जिन नामोंमें आये हैं उन नामोंके साथ हम हर सप्ताह प्रकाशित करते रहेंगे। हम किन कविताओंको जानने योग्य मानते हैं और वे किनकी हैं, यह जाननेकी इच्छा यदि पाठकोंका हो तो हम उन्हें बीरज रखनेकी सलाह देते हैं।

इतना लिखनेके बाद हमें यह भी लिखना चाहिए कि गीत लिखनेमें कवियाने ज्यादा लगनसे काम लिया होता तो वे और भी अच्छे बन सकते थे। एक भी गीतमें कोई विशेष ओज या कला नहीं दिखाई दी। यदि और भी ज्यादा शोध की जाती तथा विशेष लगनसे काम लिया जाता तो अच्छे शब्द और उदाहरण मिल सकते थे। पाठकोंको हमारी सलाह है कि वे अधिक श्रम करें और अधिक कुशलता प्राप्त करें।

श्री अम्बाराम मंगलजी ठाकरका गीत^१

‘या होम’ [बलिदानकी पुकार] करके कूद पड़ो। आगे विजय ही विजय है।

ससारमें जितने शूरवीर भक्त या दाता पदा हुए हैं और जिन्होंने अपने कतव्यका पालन किया है उनकी माताएँ धन्य हैं। मालिकपर सच्चा और पूरा भरोसा रखकर मेरे मनमें यही बात छा जाये कि बस जेल ही जाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि दिलमें प्राणसे भी प्यारा देश प्रेम प्रकट हो जाये तो दोस्तों, खुदा सदा हिम्मतवालेकी मददपर रहता है। सब हिलमिलकर यदि एक टुक मन्त्र रखे तो जेलका कड़वा फल तो खाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सारे ससारमें सुख ही सुख है।

१ मूल गीत इस प्रकार है

या होम कराने पड़ो फतेह छे आगे—तज

जग जनम्या जे शूरवीर, भक्त का दाता
कर्तव्य आवरे धन्य, तेहनी माता ॥ टेक ॥

राखी पूरो विश्वास धणीनो साची
बहु जेल, जेलने-जेल पम उर राची ॥ जग ॥

जे फगटे दिलमां प्रेम प्राण शुं प्यारो
हिंमतनी मददे खुदा, सदा छे यारो ॥ जग ॥

सौ हकीमकी बी टेक, एक उर राखो
कड़ु बोसब छे जेल, सुख भव भाखो ॥ जग ॥

धिक चोर चाबिया, ठक घुता थई रहेहुं
मरदो हक मल्ला माट, जेल दु ख सहेहुं ॥ जग ॥

जनम्या ते मरवा माट हिंमत नहिं हारो,
समरथ छे मालिक साथ रहम करनारो ॥ जग ॥

या होम तणो ए अर्थ तर्त तैयारी
हर मेळववा बहु लडे युरोपमां नारी ॥ जग ॥

जापान करावे भान, दाखलो ताजो
हक मागो ठामो ठाम, लेश नहिं लाजो ॥ जग ॥

जुओ अकबरनो इतिहास सिफन्दर पूरो
मह विक्रम, मोम, प्रताप, नेपोलियन शूरो ॥ जग ॥

जग जाहेर पास्या मान अमीरने बोधा
बहादुर तणी ये सान, अवर ते थोधा ॥ जग ॥

रक्षक मक्षक बनी जाय कहो क्यां केहुं
महाराज पबबई, हवे केवळ सहेहुं? ॥ जग ॥

घोर, चुगल, ठग, धूत बनकर रहनेमें धिक्कार है। मर्दों, हकीमी प्राप्तिके हेतु जेलके दुख सहो। जिनका जम हुआ है उन्हें मरना ही है, इसलिए हिम्मत मत हारो। रहम करनेवाला समथ मालिक तुम्हारे साथ है, बलिदानके लिए तुरंत तयार हो जाओ। हक प्राप्त करनेके लिए यूरोपमें औरते भी बहुत लड़ रही ह। जापानका उदाहरण ताजा है। वह हमें अपनी भूली हुई शक्तकी याद दिला रहा है और कह रहा है कि हर जगह हम अपने हक मागे। उसमें लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है।

अकबर और सिकंदरका पूरा इतिहास देखो। बिक्रम, भोज और राणा प्रताप बहादुर थे। नेपोलियन शूर था। इनका सारे ससारमें नाम है। ऐसे ही अफगानिस्तानके अमीर और हमारे प्रधान मंत्री जनरल बोथा ह। बहादुरोकी शान यही है, ओर सब बेकार है।

जब रक्षक ही भत्थक बन जाये तब कहा जाकर फरियाद करे। महाराज एडवड, अब हम और कबतक सहन करें ?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३१ नेटाल भारतीय कांग्रेस

नेटाल भारतीय कांग्रेसने चढ़ा इकट्ठा करना शुरू किया था, लेकिन देखते हैं कि काम अब ढीला पड़ गया है। कांग्रेस अभी कजदार है, यह मंत्रियाकी सूचनासे ज्ञात हो सकता है। कांग्रेसकी उगाहीमें जो ढील होती है उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। यह समय ऐसा नहीं जब ढील सहन हो। कांग्रेसको परवानके सगबधमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, गिरमिटिया कानूनके बारेमें झड़ा उठाना है, ओर समय आनेपर ट्रान्सवालके भारतीयोंकी मदद करनी है। ये तीनों काम बड़े हैं। व्यापारिक परवानोंके बिना व्यापारी पगेशान हागे, इसलिए स्वाथकी दृष्टिसे भी कांग्रेसको अपने खजानेकी हालत अच्छी रखनी चाहिए। कांग्रेसने १८९४ से अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनमें गिरमिटियोंके ऋण्टोमें हाथ बटाना मुरय है।^१ अतः थानविलमें जो घटना हुई है उसके बाद कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती।^२ मुह खोलनेके लिए भी इस देशमें महमूदी^३ लगती है — खच लगता है। ट्रान्सवालके भारतीयोंकी मददके लिए कांग्रेस बँधी हुई है, क्योंकि कांग्रेसने उन्हें लड़ाईमें लगे रहनेकी सलाह दी है। इसके अतिरिक्त ट्रान्सवालकी लड़ाईमें हर भारतीयका स्वाथ समाया हुआ है। इसलिए हम आशा करते हैं कि उपर्युक्त तीनों बातोंका खयाल करके कांग्रेस कायकर्ता कमर कसेगे और पैसे रूपी शस्त्र तुरन्त ही जमा करेंगे, यह काम कलपर टाला नहीं जा सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ १३०५।

२ देखिए गिरमिटिया भारतीय मजदूर, पृष्ठ ४१।

३ चांदोका एक पुराना सिक्का।

३२ नेटालमें जेलका कानून

हमारे नेटालके विधायकोने जो कानून बनाया है वह “एकको गुड और दूसरेको गोबर” वाली कहावतको चरिताय करता है। नेटालके सरकारी ‘गजट’में मातूम होता है कि कैदियोंके चार वर्ग हैं एक गोरा, दूसरा वणसकर, तीसरा भारतीय और चौथा काफिर। गोरो और वणसकरासे यदि सरकार कुछ काम करायें तो वह उहे इनाम देगी। किन्तु यदि भारतीय और काफिर काम करे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, गोरा और वणसकराको एक एक गमछा मिलता है। किन्तु भारतीय और काफिराको वह भी नहीं — माना उन्हें गमछे की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार कैदियाम भी सरकारने जातपातका भेद किया है। वणसकर कैदियोंमें केप वाय, अमरीकी हब्शी, हाटेटाट बगैरहका समावेश हाता है।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३३ हेजाज रेलवे

‘टाटम्स आफ इण्डिया’ के सवाददाताने इस रेलवेकी^१ व्यवस्थापर जो आक्रमण किया था उसका सारांश जब हमने दिया तब कहा था कि हमने उस सवादमें बताये विवरणकी श्री किदवई तथा श्री कादिरमें हकीकत पूछी है। श्री कादिर भारत पहुँच गये हैं। श्री किदवईका हमारा पत्र मिला। उन्होंने जो उत्तर दिया है वह हम नीचे दे रहे हैं। श्री किदवई स्वयं इस्लामिया अजुमनके^२ मंत्री हैं

आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। मैं इस समय श्री रिचके पास हूँ। आपने ‘टाटम्स’ का जो अंश भेजा है वह उन्होंने मुझे दिया है। उसे ठीक तरहमें पढ़नेपर मैं आपको लिखूँगा कि उसमें कौनसी बात सच है। उसमें जो बात गलत होगी उसका उत्तर देनेके लिए मैं कदम उठाऊँगा और जा कुछ म करना चाहता हूँ वह भी आपको बताऊँगा। मेरे सहधर्मी भाइयोंका जिसमें बहुत ही हित समाया हुआ है, ऐसे कायमें आप इतने व्यस्त हैं, इसके लिए आपका उपकार मानता हूँ। हम भारतके हिन्दू और मुसलमानाको एक-दूसरेमें सम्बन्धित बातोंमें इसी प्रकार मेहनत तथा परस्पर सहायता करनी चाहिए।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४८४ ८६ ।

२ अखिल इस्लाम अजुमन, छन्दन ।

३४ यूसुफ अली और स्त्री-शिक्षा

श्री यूसुफ अलीने भारतकी हालतके सम्बन्धमें एक पुस्तक लिखी है। वह बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने स्त्री शिक्षाके बारेमें जो विचार व्यक्त किये हैं वे जानने योग्य हैं। उन्होंने लिखा है कि जबतक भारतमें स्त्रियोंको आवश्यक शिक्षा नहीं मिलती तबतक भारतकी हालत सुधर नहीं सकती। स्त्री पुरुषकी अर्धांगिनी मानी जाती है। यदि हमारा आधा शरीर मुर्दा हो जाये तो हम मानते हैं, हमें लकवा हो गया है और हम बहुतमें कामोंके लिए अयोग्य हो जाते हैं। तब स्त्रीका जो उपयोग होना चाहिए वह न हो, तो सारे भारतको लकवा हो गया है, यही मानना पड़ेगा। और ऐसी हालतमें यदि भारत दूसरे देशोंके आगे टिक न सके तो उसमें आश्चर्यकी बात कौनसी है? इस तरहका विचार हर माता पिताको अपनी लड़कीके बारेमें और सारे भारतवासियोंको स्त्री समाजके बारेमें करना चाहिए। हमें ऐसी हजारों स्त्रियोंकी जरूरत है जो मीराबाई और राबियाबीकी बराबरी करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

ट्रान्सवालकी ससद

नई ससदका दूसरा सत्र १४ तारीखको प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सरकारके कामके ढंगके बारेमें जनरल बोथाने जो भाषण दिया है, वह भारतीय समाजके लिए समझने योग्य है। इसलिए उसका मुख्य हिस्सा नीचे देता हूँ।

चीनी जानेवाले हैं

इस समयके गिरमिटिया चीनियोंको गिरमिट पूरा हो जानेपर वापस भेज दिया जायेगा और बदलेमें दूसरे गिरमिटिया चीनियोंको नहीं आने दिया जायेगा। इस हिसाबसे देखनेपर इस वर्षके अन्तमें १६,००० चीनी ट्रान्सवाल छोड़ेंगे और जो बचेगे वे लगभग १९०७ के अन्ततक चले जायेंगे।

चीनियोंके बदले कौन ?

चीनियोंके चले जानेसे खानोमें मजदूरोकी तंगी होगी। इसका उपाय एक तो यह है कि जहासे भी मिले वहासे काफ़ीरोको जुटाया जाये और उनके द्वारा काम कराया जाये। इसके लिए पुतगीज सरकारसे बातचीत चल रही है। दूसरा उपाय यह है कि जैसे जैसे गोरे मजदूरोको खानोमें काम करनेके लिए प्रोत्साहित किया जाये और अन्तमें ट्रान्सवालको सफेद बनाया जाये। गोरे मजदूर कम वेतनपर काम कर सकें, इसके लिए ट्रान्सवाल चुगी (कस्टम) के

इकरारनामेसे निकल जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो वह दूसरा इकरारनामा कर लेगा। इसका उद्देश्य यह है कि आज जो जकान देनी पड़ती है उसे बहुत ही घटाकर जरूरी चीजाँके दाम गिराये जाये, जिसमें गोरे विलायतमें जितने खचमें गुजर कर लेते हैं लगभग उतने ही कम खचमें यहाँ रह सकें। आज ट्रान्सवालकी सम्पन्नता केवल खान उद्योगपर निर्भर है। खेतीको आवश्यक प्रोत्साहन देकर यह स्थिति दूर की जायेगी। खेतीको प्रोत्साहन देने और खेतोंके बाँध बनानेमें सहायता देनेके लिए एक विशेष बैंक खोला जायगा।

यह बैंक किसानोंको पैसा उधार देगा। इस रकमकी पूर्तिके लिए बड़ी सरकार स्थानीय सरकारका ५०,००,००० पौंड कज दगी।

इस भाषणका असर

इस भाषणमें गान मालिक बड़ी उलझनमें पड़ गये हैं। यह सम्भव नहीं कि उन्हें काफिर ज्यादा तादादमें मिल सकें। इसलिए डर है कि जोहानिसबर्गकी आज जैसी हालत कुछ वर्षों तक बनी रहगी। किन्तु इसका मर्ममें बड़ा असर यह होगा कि शायद भारतीयोंके लिए बारिया सिस्टर गार्मेंका समय आ जाये। स्थानीय सरकारका दृढ़ निश्चय जान पड़ता है कि ट्रान्सवालके मजदूराने मित्रा किसी भी काल आदमीको न रहने दिया जाये। अतः यदि भारतीय कौम जरा भी पस्तहिम्मत दिखाई दी तो उस भगानेमें वह पीछे रहगी, सो जान नहीं। भारतीय समाजने सामने यह समय "मरूँ अथवा मारूँ" का है।

मजदूर रक्षक कानून

जान पड़ता है, मरी पिछड़ी नीकाका जार देनेवाला एक और कानून इस सत्रमें पास होगा। विभिन्न कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंका यदि काम करते समय चोट लग जाये तो उन्हें या उनके बाल-पच्चाकों हर्जाना देनेका कानून 'गजट' में प्रकाशित हुआ है। यह कानून बब्रु गार मजदूरोंपर लागू होता है। यानी, मान ले कि खानमें या दूसरी जगह गार और भारतीय मजदूर साथ साथ काम करते हो और दोनोंके हाथ या पैर यंत्रमें फँसकर टूट जाये तो इस कानूनके अनुसार खान मालिक, गोरे मजदूर और उनके कुटुम्बक निवाहके लिए ता बँधा हुआ है, किन्तु भारतीय मजदूरकी कोई विसात नहीं। उसके ऊपर यदि खुदा न हो तो उसका सवनाश हो जायेगा। उसके अगला कोई यह भी खयाल नहीं कर सकता कि उपयुक्त बैंकमें भारतीयोंका एक कोड़ी भी मित्रगी। वह तो केवल गार किसानोंके लिए है। यह सब बोथाकी बहादुरीकी बलिहारी है। उनके जाति-भाइयाने ट्रान्सवालकी भूमिका बोअर रक्तस सीचा है, इसलिए इस समय व पूरी मुतदरी फसल काटे तो इसपर किसीको आश्चर्य क्या हो? हम यदि अपनेार बाअराकी बहादुरीका याडा सा भी रंग चढ़ा सके तो हमारे लिए भी बूम मच सकती है।

वीनेनका पत्र

श्री कैलनबैकन जेलक सम्बन्धमें भारतीय समाजकी जा प्रशंसा की है, जान पड़ता है वह सक्रामक बन गई है। श्री वान वीनेन नामक एक गोरेने 'स्टार' में एक पत्र लिखा है। उसका सागश नीचे दिया जाता है

विवेकशील लोग भारतीयोंके बारेमें लिखे गये श्री कैलनबैकके पत्रका समर्थन किये बिना नहीं रह सकते। यदि कुछ भारतीय ट्रान्सवालमें आरामसे रहे और व्यापार करे तो

उससे क्या ट्रान्सवाल नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा ? जब हम जगली थे उस समय जो प्रजा सम्पत् थी, उसकी सन्तानको हम अपराधी कहकर निकालते हैं, यह हमें शोभा नहीं देता। भारतीयोंके लिए पजीयन ? जो गोरे स्वयं अपराधी हैं वे ही भारतीयोंके गलेमें यह फंदा डालना चाहते होंगे। मुझे तो भारतीयोंका एक यही दोष दिखाई देता है कि वे उद्यमी हैं। उनपर आलसी गोरे जुल्म करे, यह समझमें आ सकता है। किन्तु यदि वे अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिए ऐसे कानूनका विरोध करे तो उन्हें दोषी कैसे माना जा सकता है ? श्री कैलनबैकके समान मुझे भी अच्छे भारतीयोंका अनुभव हुआ है। श्री गांधीके पत्रसे मालूम होता है कि उनकी माग बहुत ही उचित है। उनकी माग मजूर न हो और वे अपमान सहन करनेके बजाय यदि जेल जानेका निश्चय करे तो उसके लिए उन्हें बर्बाद दी जानी चाहिए।

ईसप मियाँका पत्र

श्री ईसप मियाने 'स्टार'के नाम एक पत्र^१ लिखा है। उसका सारांश नीचे देता हूँ

जनरल बोथको पत्र

ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे श्री ईसप मियाने जनरल बोथको पत्र^२ लिखा है कि सरकारने कानूनको लागू नहीं किया, इसलिए भारतीय समाजकी सूचनाको स्वीकार करना ठीक होगा। उस पत्रके उत्तरमें जनरल बोथाने कहा है कि उसके लिए उपनिवेश सचिवको लिखा जाये। इसपर उपनिवेश सचिवको भी लिखा गया है। उसका जवाब, सम्भव है, इस पत्रके छपने तक आ जायेगा।

'गजट'के बारेमें गडबडी

सम्राटने कानूनको स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्धमें जो सूचना जारी की गई है उसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। कुछ लोग मानते हैं कि कानून दो वर्ष तक लागू नहीं होगा। यह भूल है। सूचनामें बताया गया है कि किसी भी कानूनको सम्राट दो वर्षके अंदर रद्द कर सकते हैं। यह कानून जब सम्राटके सामने पेश किया गया तब उन्होंने कहा था कि वे इस कानूनको रद्द करना नहीं चाहते। अतः इसका यह अर्थ हुआ कि इस कानूनको दो वर्षके अंदर रद्द करनेकी सम्राटको जो सत्ता थी उसे उन्होंने छोड़ दिया है। यानी यह कानून सदाके लिए कायम रहा। किन्तु सदाके लिए कायम रहा कहनेमें मैं भूल कर रहा हूँ। यदि भारतीयोंको यह कानून स्वीकार नहीं है तो इसपर सम्राटके हस्ताक्षर हो जानेपर भी यह उनके लिए तो रद्द ही है।

फ्रीडडॉर्फके व्यापारी

जान पडता है, इस सम्बन्धमें श्री रिच विलायतमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका फल चखनेका समय आ गया है। निगमने जिन दो व्यापारियोंको भारतीय दूकानोंका स्टॉक जाचनेके लिए नियुक्त किया है, उन्होंने सरसरी तौरसे पूछताछ की है। उन सारे आकड़ोंपर

१ इसके बाद गांधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मूलके लिए देखिए "पत्र 'स्टार'की", पृष्ठ ३५-३७।

२ देखिए "पत्र प्रधान मंत्रीके सचिवको", पृष्ठ १४-१५।

अब सरकार विचार करेगी। इसी बीच एक और नई बात सामने आई है। फ्रीड'प अध्यादेश' कुछ गौराका पसंद नहीं है। अतः उस रास्ते भी शायद हम बच सकते हैं।

नये कानूनमें परिवर्तन नहीं होगा

सर जॉज फेरारने^१ जनरल बोथामे पूछा कि सुना जाता है, नये कानूनमें कुछ परिवर्तन करनेके लिए बड़ी सरकारसे कहा जायेगा, वे परिवर्तन कौन से हैं? उसके उत्तरमें जनरल बोथामे कहा “जब भारतीयाका गिफ्टमण्डल मुझमें मिला था और बनी सरकारने भी सलाह दी थी, तब मैंने कहा था कि इस कानूनको इस तरह लागू किया जायेगा कि जिसमें भारतीय भावनाओंको चोट न पहुँचे।” इसपर सर जाजने कहा “यह कोई मेरे सवालका जवाब नहीं है। कानूनकी कौन सी आपत्तिजनक बात हटानेका विचार है?” जनरल बोथामे कहा “एक भी नहीं।”

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्रिटिश भारतीय सघने उनिवेश मन्त्रिबको लिखा है। जनरल बोथामेके उत्तरसे मालूम होता है कि जा लोग कानूनमें परिवर्तनकी आशा रखते हैं उनकी आशा व्यर्थ है। कानून कब लागू होगा और भारतीय कौमकी सूचना मजूर हांगी या नहीं, यह दूसरी बात है। किन्तु ‘दूसरेकी आशा सदा निराशा’ इस बातकी अपन मनम गाँठ बाधकर भारतीय समाजको ट्रान्मवालमें अपनी टेक निभानेके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३६ पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा

प्रस्तावना

अपने विचारके अनुसार इस सप्ताहसे हम उपर्युक्त विषयपर एक लेखमाला प्रारम्भ कर रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान किस भाँति एक दिल बने और रहे, यह सदा हमारा उद्देश्य रहा। ऐसा करनेके अनेक मार्गोंमें से एक यह है कि वे एक दूसरेकी अच्छाईयाँ जान। इसके सिवा हिन्दू और मुसलमान अवसर आनेपर बिना दिग्बावेके एक दूसरेकी सेवा कर। ऊपरकी लेखमाला शुरू करनेमें हमारे दोनों उद्देश्य निहित हैं।

हमारा उद्देश्य भारतीय समाजमें शिक्षा और सदज्ञानका प्रसार करना भी है। इसकी पूर्तिके लिए हमारा इरादा अलगमें पुस्तके छापनेका था और अब भी है। हमें आशा है कि न्यायमूर्ति अमीर अलीकी इस्लाम सम्बन्धी पुस्तकका अनुवाद तथा दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके दुःखकी कथाका प्रकाशन हम कर सकेंगे। किन्तु इसमें कुछ बाधाएँ हैं, जो अभी हटती नहीं हैं। और इसलिए इसमें कुछ देर लगेगी।

इस बीच हमने प्रख्यात लेखक वॉशिंगटन इरविंग रचित पैगम्बरका जीवन-चरित्र प्रति सप्ताह प्रकाशित करना निश्चित किया है। यह प्रत्येक हिन्दू मुसलमानके पढ़ने योग्य है। अधिकतर हिन्दू पैगम्बरके कार्यकलापोंसे अपरिचित हैं और अनेक मुसलमान यह नहीं जानते कि अग्नेजोने

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७६ ७८ ।

२ ट्रान्सवाल विधान परिषदके नामजद सदस्य ।

शोध करके पैगम्बरके विषयमें क्या लिखा है। वाशिंगटन इरविग कृत इतिहास इन दोनों वर्गोंके लोगोके लिए लाभदायक हो सकता है। हम सारेका अनुवाद न देकर उसका मुरय भाग दे रहे ह। वाशिंगटन इरविग कृत यह पुस्तक बड़ी अच्छी मानी जाती है। इसके लेखकने अय गोरे लेखकोकी तरह इस्लामकी बुराई नहीं की है, तथापि सम्भव है कि हमारे वाचकोको उसके विचार कही कही पसन्द न आये। समझदार लोगोको वे विचार भी जानने चाहिए। किसी भी रचनाको पढकर उससे ज्ञान और सार ग्रहण करना पढनेका हेतु होता है। हम यह बात ध्यानमें रखकर नीचेके प्रकरण^१ पढनेकी सलाह देते हैं।

वाशिंगटन इरविग कौन थे ?

हमें अब इस प्रश्नका उत्तर देना है। सन् १७८३ में अमेरिकाके न्यूयॉक नगरमें उनका जन्म हुआ था। वे कई वर्षों तक यूरोपमें रहे। वे अमेरिकाके प्रमुख लेखकोमें से एक थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। पैगम्बरके विषयमें लिखी गई पुस्तक उनमें से एक है। उनकी लेखन-शक्ति बड़ी अच्छी मानी जाती है। उनकी रचनाओंका दूर दूर तक नाम है। वे नीतिमान व्यक्ति थे। उन्होंने जिस महिलासे विवाहका विचार किया था, उसका देहावसान हो जानेके कारण उसकी यादमें वे आजन्म अविवाहित रहे। सन् १८५९ में नवम्बरकी २८ तारीखको अपने निवास स्थानपर इन महान लेखककी मृत्यु हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

१ ये प्रकरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। ये इंडियन ओपिनियनके जुलाई ६ और अगस्त १७ के बीचके अकोंमें प्रकाशित हुए थे। यह लेखमाला ६७ अध्यायका एक अंश प्रकाशित होनेके बाद बन्द कर दी गई थी। देखिए “हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन वृत्तान्त” क्यों बन्द हुआ?”, पृष्ठ २०५ ०६।

३७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[जून २६, १९०७]

नया कानून

ट्रान्सवाल सरकारने शोक सवाद मुना दिया है। उसने श्री चैमने मियाके पत्रके उत्तरमे लिखा है कि जैसा पहले उत्तर दिया जा चुका है, भारतीयोंका मुआव मजूर नहीं किया जा सकता। यानी सरकार कानूनको अमलमें लाना चाहती है। अब तारीखकी ही राह देना शेष है। हमें म शोक सवाद कहना है, किन्तु हमें शक सवाद भी माना जा सकता है। हिम्मतवाक ता हमें शुभ सवाद ही मानने।

नई नियुक्ति

सरकारी 'गजट' में समाचार है कि नये कानूनके अनुसार श्री चैमनेको पजीयक नियुक्त किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय समाज ऐसा वक्त आ देगा कि श्री चैमने साहब जम्हा केने बैठे रहें। उस सवाददाताका नाम तो उस रजिस्ट्रारमें कभी दर्ज नहीं होगा, किन्तु मुदास मरी रिग्लर यह प्रार्थना है कि ऐसी ही सार भारतीयोंकी भावना हो।

बाजारमें छुआछूत

जोहानिसबर्ग का शहर यूरोपीय लोग भारतीयोंको छनेस परहज करके मालूम होते हैं। इस नगरपालिका में प्रस्ताव किया है कि यूरोपीय और काले लोगोंके लिए अलग-अलग विभाग रखे जायें। चीनियोंमें प्राचीन हिम्मेका गिरिया लेनेका निणय भी किया गया है। हमने अपने देशमें भगी रखे हैं, इसलिए हम भी यन् भगी बन गये हैं और अब अनुमतिपत्रकी चिट्ठी गलेमें बांधकर विलकुल बेहाल हो जायेंगे। मुझे याद है कि पोट एलिजाबेथके भारतीयोंपर बाजारमें उसी तरहका जुल्म शुरू किया गया था। उस समय भारतीयोंने बाजारमें जाना बंद कर दिया था। यदि भारतीय फेरीवाले जोहानिसबर्गमें उतनी ही हिम्मत दिखायें तो इस भगी ल्गास मक्ति मिल सकती है। कुछ कहलाकर पेट भरनेमें ना दग जानता बेहतर माना जायेगा।

डच पजीयनपत्रका प्रश्न

लाओ स्टेशनमें एक पत्र देखकर प्लू है कि हमें पाम उचार समयका पुराना पजीयन-पत्र है। डच गवाह भी है। फिर भी उक्त अनुमतिपत्र नहीं मिलता। उसका क्या किया जाय ? जान पड़ता है उन भाउने 'उडियन आपिथिन' नहीं पढ़ा। मैं कह चुका हूँ कि ऐसा भारतीय नये कानून लागू होनेके बाद जरूरी सम चपता चाहता है ना ट्रान्सवालमें रहे, नहीं तो ट्रान्सवाल छोड़ दे।

लेनडैका मत

कुछ भारतीयोंको डर है कि जो भारतीय नया अनुमतिपत्र नहीं लेंगे उन्हें सरकार जबरदस्ती निर्वासित कर सकती है। ऐसी ही शका चीनियोंका भी हुई थी। इसलिए उन्होंने श्री लेनडैकी' राय ली थी। श्री लेनडैने जो राय दी वह निम्नानुसार है

मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है उसके सम्बन्धमे मेरी यह राय है कि नये कानूनमे या दूसरे किसी कानूनमे कानूनका विरोध करनेवालेको जबरदस्ती निर्वासित करनेका अधिकार नहीं है। मेरी जानकारीमे ऐसा एक भी कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत जबरदस्ती निर्वासित करनेका किसीको अधिकार हो। 'अनुमतिपत्र-कानूनकी' सातवीं ओर आठवीं धारामे बताई गई सजाके सिवा ओर कोई सजा नहीं दी जा सकती। (सातवीं-आठवीं उपधाराओमे जो देश न छोड़े उसे जेलमे भेजनेका अधिकार है)।

अतः यही समझना चाहिए कि निर्वासनकी बात दरकिनार हो गई है।

अफवाह

अफवाह है कि नये कानूनके १ जुलाईसे लागू होनेकी सूचना प्रकाशित होनेवाली है। यानी जिन लोगोको गुलामीकी छाप लगवानी हो, उन्हें उस तारीखसे लगा दी जायेगी। अतः रग जमेगा।

भारतीय 'बाजार'

'गजट' मे सूचना आई है कि भारतीय 'बाजार' — वास्तवमे भगी मुहल्ले — अब नगरपरिषदके सुपुर्द किये गये हैं। यह सूचना अभी तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन 'बाजारो' मे भारतीयोको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। यह सब नये कानूनके पीछे घूम रहा है। नया कानून भारतीय कौम रद्द कर दे — रद्द समझ ले — तो बस्ती सम्बन्धी कानूनो तथा वैसे ही दूसरे कानूनोको तुरन्त निद्रा रोग हो जायेगा।

फेरीवालोपर आक्रमण

व्यापारमण्डलने सरकारको लिखा था कि भारतीयोको आनेसे रोका जाये। इसके उत्तरमे उपनिवेश सचिवने लिखा है कि थोड़े ही दिनोंमे जब प्रवास-कानून प्रकाशित हो जायेगा तब भारतीय व्यापार बहुत कुछ रुक जायेगा, क्योंकि, फेरीवालोके लिए सख्त कानून बनाये गये हैं। अतः जो नये कानूनकी चोरछाप लगवाना चाहते हैं वे इससे समझ लें कि उनका क्या हाल होगा। अगले सप्ताह यदि प्रवास विधेयक प्रकाशित हुआ तो उसका अनुवाद देनेका इरादा है। चारों ओर अच्छी तरह आग लग रही है। मैं इन सबको शुभ लक्षण मानता हूँ। रोगके गहरे होनेपर सच्ची बीमारीकी पहचान की जा सकती है।

कर्टिस^१ और नया कानून

श्री कर्टिसने नये कानूनके सम्बन्धमे जो प्रयत्न किये उनके लिए पाचेपस्टम व्यापार-मण्डलने आभार माना है। उसके उत्तरमे श्री कर्टिसने निम्नानुसार लिखा है^२

आपके मण्डलके ११ मईके पत्रके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इस प्रश्नका महत्त्व किसीको न दिखाई दे, यह मेरी समझमे नहीं आ सकता। एशियाइयोसे मेरा निजी कोई झगडा नहीं है। किन्तु मुझे विश्वास है कि गोरे और एशियाइयोका घुलना मिलना दोनोंके लिए खराब है। जिस देशमे अलग-अलग रहना दोनोंके लिए लाभदायक हो वहा दोनोंको अलग-अलग रहना चाहिए। एशियाई प्रश्न व्यापारका प्रश्न है, यह केवल मोटे तौरसे सोचनेपर ही कहा जायेगा। वास्तवमे यह प्रश्न बहुत ही बड़ा है और वैसे ही समझा जाना चाहिए।

१ सन् १९०३ का अध्यादेश ५।

२ ऑथनेल कर्टिस, सहायक उपनिवेश सचिव।

मैं आशा करता हूँ कि कोई यह न समझेगा कि श्री चर्चिलने^१ घोषणा की है इसलिए अविनियम पूरा हो चुका है। जबतक यह कानून यहाँ लागू नहीं हुआ है तबतक विलायतमें दबाव डालनेसे यदि कुछ परिवर्तन हो जाये तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। और यह भी हो सकता है कि परिवर्तनके कारण कानून निम्मा बन जाये। इस कानूनका उद्देश्य यह है कि हर साधिकार भारतीयको पजीकृत किया जाये उसकी अँगुलिप्रोकी छाप ली जाये, जिसमें पजीयनपत्रका हस्तान्तरण न किया जा सके।

लेकिन हमें यह न मानना चाहिए कि कानूनके प्रकाशित हो जानेसे काम हो गया। वह कानून ठीक तरहसे अमलमें आता है या नहीं, इस बातपर बहुत-कुछ निर्भर है। मैंने जो देखा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि सरकारको जा-कुठ करना चाहिए उसमें उसने कुछ भी उठा नहीं रखा है। आशा है कि इस कानूनको प्रभावशाली बनानेमें समाचारपत्र और जनता मदद करेगी। यह कानून ठीक तरहसे अमलमें आ सके, इसलिए समाचारपत्रोंका कतव्य है कि वे अधिकारियोंकी हिम्मत बढ़ाये। अधिकारियोंका काम आसान नहीं है। उनपर जनता यदि भरोसा न रखे तो उनका काम बिल्कुल बिगड़ जानेकी सम्भावना है। मैं आशा करता हूँ कि अधिकारियोंपर आरोप लगाये जाये तो उनके बारेमें जनता बहुत ही सावधानीसे काम करेगी। उनका काम बहुत कठिन है। उनसे बहुत द्वेष किया जायेगा। आरोप लगाये जानेपर यदि वे खुले आम बचाव कर सकते तो कोई बात नहीं। किन्तु यह नहीं हो सकता। उनकी कठिनाई उनके विगठ अधिकारी ही समझ सकते हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि उनपर आरोप लगाये जाये तो उनकी ओर जनता बिल्कुल ध्यान ही न दे, क्योंकि उपनिवेश-सचिव उनकी छानबीन कर सकते हैं। ज़रतक उपनिवेश सचिव अधिकारियोंपर भरोसा रखते हैं तबतक जनताको भी रखना चाहिए। मैं बड़ा अधिकारी था और छोटे अधिकारियोंपर आरोप लगाये जाते थे तो मैं उनकी जाँच करता था। अधिकारी बहुत ही उद्यमी और अपना फज अदा करनेवाले हैं। उनपर जो आरोप लगाये जाते हैं उन्हें जनताको महत्त्व नहीं देना चाहिए।

श्री कर्टिसका यह तमाशा अजीब है। एक ओर तो इन महाशयने कानूनका पास करवानेमें बड़ी मेहनत की, और अब कानूनको अमलमें लानेवाले अधिकारियोंपर कुछ न गुजरे, इसलिए जनताको पहलेसे चेतावनी दे रहे हैं, मानो अधिकारी चाहें जिनका जुल्म करे, उसकी जनताको परवाह नहीं करनी चाहिए। सौभाग्यमें भारतीय समाजको अधिकारियोंकी कतई जरूरत नहीं होगी। किन्तु यदि हाती, तो श्री कर्टिसके पत्रका यह अर्थ हुआ कि जैसे जैक्सनपर मुकदमा चलाया गया था, वैसे ही यदि कोई दूसरा अधिकारी करे तो उसपर मुकदमा चलानेके लिए जनता कुछ न कर। क्योंकि, उपनिवेश-सचिवका उस सम्बन्धमें सारी जानकारी मिलनी पड़ेगी। श्री कर्टिस माहव भूल गए हैं कि सर आर्थर लालीके^२ पास जब कई बार शिकायत गई तब कही उन्हें अपने अधिकारियोंकी स्थितिका ज्ञान हुआ था।

१ (१८७४-) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, सैनिक तथा लेखक। उपनिवेश उपमन्त्री, १९०५-८। इंग्लैंडके प्रधानमन्त्री १९४०-४५ तथा १९५१-५५।

२ टाउन्सवॉल्फे डेफिन्ट गवर्नर १९०२-५। १९०५ में मद्रासके गवर्नर नियुक्त किये गये थे। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २०१ और खण्ड ५, पृष्ठ १६०।

चीनियोकी लडाई

चीनी सघके श्री किममिगने 'स्टार' को निम्नानुसार पत्र लिखा हे

चीनियोकी भावनाओकी जरा भी परवाह किये बिना यह शम-भरा कानून अमलमे लाया जानेवाला है, इससे चीनी समाजको आश्चय हुआ हे।

हम कौन हैं? चीनियोने जो प्रस्ताव पहले पास किया था उसीको फिर यहा पेश करता हूँ कि हम स्वेच्छया पजीयन करवानेको तयार हैं, किंतु गोरे लोग हमे गुलाम बना ले, यह कभी नहीं हो सकता। हम यह व्यवहार सहन नहीं करेगे। इस शमनाक कानूनके सामने हम नहीं झुकेगे। इससे भले वे हमारा कुछ भी करे, चूकि हम सच्चे ह इसलिए अततक लडते रहेगे। हम कोई अनुचित बात नहीं, बल्कि शुद्ध याय माग रह हैं।

अग्रेजोको हम अपने देशमे भले आदमियोके रूपमे जानते हैं। यहा यदि वे हमपर जुल्म करेगे तो हम उन्हे सम्मान देना बंद कर देगे, जिससे चीनमे भी उन सबकी प्रतिष्ठा चली जायेगी।

मिडेलबर्ग-बस्ती

मिडेलबर्ग नगर परिषदने सूचित किया है कि मिडेलबर्गके भारतीय न बस्तीसे निकलते हैं, न जिन बाडोका इस्तेमाल करते हैं उनका किराया देते हैं, और बिना हक उनका उपयोग करते रहते हैं। इसलिए नगर परिषदने उनपर मुकदमा चलानेका निणय किया है। मिडेलबर्गकी बस्तीमे रहनेवाले भारतीयोको इस विषयमे सोचना चाहिए। यदि किराया न देनेकी बात सच हो तो यह ठीक नहीं कहा जा सकता। दोष हमारी ओर तो जरा भी नहीं होना चाहिए।

समितिकी भूल

समितिका तार आज (बुधवारको) मिला। उसमे लिखा हे कि कानूनके विरोधमे जेल जानेके निणयको समिति नापसन्द करती है। मुझे आशा है कि इससे कोई भारतीय परेशान नहीं होगा। समितिकी पसदगीका हम निर्वाह कर पाते तो अच्छा होता। किन्तु समितिने नापसदगी जाहिर की है, उसे भी समझा जा सकता है। समितिके प्रमुख सदस्य भारतके पुराने प्रसिद्ध अधिकारी हैं और आगे भी अधिकारी बन सकते हैं। वे हमें कानूनका विरोध करनेकी सलाह दे, इसीमे आश्चय होगा। वे हमें कानून स्वीकार करनेको कहे, इसमे कुछ आश्चय नहीं है। समितिकी सलाहको हमें वकीलकी सलाहके समान समझना चाहिए। वह हमें कानून भग करनेको नहीं कह सकती। जिनपर कष्ट पडा हो वे ही यह इलाज कर सकते हैं तथा उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इस तारकी खबर देनेके लिए सघकी बैठक की गई थी, जिसमे सघने नीचे लिखे अनुसार तार भेजनेका निणय किया है।

कानूनके सामने झुकनेमे और किसी बातका विचार न करे तब भी इतना तो सोचना ही होगा कि भारतीय समाजने जो खुदाकी शपथ ली हे, वह टटती है और उसे तोडनेको तो समितिकी ओरसे सलाह नहीं मिलनी चाहिए। आशा हे, भारतीयोके प्रति समितिकी सहानुभूति बनी रहेगी।

यह तार ठीक गया है। किन्तु यदि इससे समिति भग भी हो जाये तब भी यह तो हो ही नहीं सकता कि भारतीय समाजने जो काम शुरू किया हे वह बंद हो। भारतीय

समाजका खुदा — ईश्वर — मच्चा मददगार है। उमे वीचमे रखकर शपथ ली गई है और उसीके भरोसे हम पार होंगे।

संशोधन

अपनी पिछली चिट्ठीमें मैं लिख चुका हूँ कि पत्रे हुए चीनी १९०७ में जायेगे। इसकी ओर एक पाठकने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उसका आभार मानते हुए अपनी भूल सुधारना हूँ कि १९०७ की जगह १९०८ राना चाहिए।

[गुजरातीम]

इंडियन ओपिनियन, २०-६-१९०७

३८ भेंट 'रैंड डेली मेल' को

[जून २८, १९०७]

उपर्युक्त घोषणाकी आगाहीपर ट्रान्सवालके भारतीय समाजके रख और प्रतिक्रियाके सम्बन्धमें मेल 'के एक प्रतिनिधिने भारतीय समाजके अग्रणी तथा पथप्रदर्शक श्री मो० क० गांधीसे मुलाकात की थी।

[गांधीजी] यह कहना कठिन है कि इस कानूनके लागू होनेका अन्तिम परिणाम क्या होगा, परन्तु जहाँतक मेरा और मेरे सहयोगियोंका सम्बन्ध है, हम प्रस्तावित पंजीयनको न माननेके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, बल्कि हमारे अन्तर्गत मिलनेवाले सबसे बड़े दण्डको भोगनेके लिए तैयार हैं।

अपने इस भावमें हम किन्ही राजद्रोही इरादोंमें या विराटकी साधारण भावनासे प्रेरित नहीं हैं। इसके पीछे केवल आत्मसम्मानका विचार है।

दूसरे शब्दोंमें, उन्होंने एक बड़े सत्याग्रह सन्ध्याकी भविष्यवाणी की, जिसके बारेमें उन्होंने अनुमान किया था कि उसमें कमसे कम ट्रान्सवालके आधे ब्रिटिश भारतीय भाग लेंगे।

निःसन्देह परिणामस्वी भविष्यवाणी करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वर्षों अप्रयोगके कारण विधानके प्रति विरोध प्रकट करनेका ऐसा ढँग मेरे देशवासियोंके लिए नया है। परन्तु साथ ही ट्रान्सवालके समस्त भागमें मुझे जो पत्र मिले हैं, और 'इंडिया ओपिनियन'के सम्पादकका जा पत्र भेजे गये हैं, उनमें मेरा यह खयाल होता है कि विधानको न माननेकी नीतिपर ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंमें से पूरे ५० प्रतिशत दृढ़ रहेंगे। मैंने अभीतक एक भी ऐसे भारतीयका नाम नहीं सुना जिसने इस कानूनका समर्थन किया हो। बहुतोंसे अनुभव करते हैं कि जल्दी कठिनाइयोंको सहन करनेमें अच्छा यह हागा कि वे दशका छोड़ दें, परन्तु मैं ऐसा एक भी आदमीका नहीं जानना जिसने कभी कहा हो कि वह इस कानूनके अन्तर्गत नया पंजीयन प्रमाणपत्र लेगा।

श्री गांधीने कहा, भारतीय बहुत नाराज हैं और उन्होंने हिसाब लगाया कि नये कानूनके अनुसार पंजीयन करानेसे कमसे-कम ६,००० इनकार करेंगे।

१ ता २८-६-१९०७ के गवर्नमेंट गज़टमें एशियाई कानून संशोधन अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी विनियमोंके प्रकाशन और यह ऐलान हो जानेपर कि उक्त अधिनियम १ जुलाई १९०७ से अमलमें लाया जायेगा, यह मुलाकात हुई थी। 'रैंड डेली मेल'में इन शीर्षकोंके साथ रिपोर्ट छपी थी "लेल जाना अनिवार्य अन्धदेशपर भारतीय ८००० अनाक्रमक प्रतिरोधी सोमवारसे कानून लागू प्रिटोरियासे प्रारम्भ"।

यदि सरकार मुकदमा चलानेपर तुली रही तो ये लोग जेल जायेंगे। इसके कारण निश्चय ही उन्हें बहुत हानि होगी, क्योंकि उनमें से बहुतांके बड़े बड़े स्वाथ ह। परन्तु अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखनेके लिए वे सबस्वकी बलि करनेको तैयार ह।

हम अनुभव करते हैं कि देशके विधानमें, उस दशामें भी जब हम स्वयं उससे प्रभावित हो, हमारी कोई आवाज न होनेके कारण उसके प्रति विरोध प्रकट करनेका एक ही माग रह जाता है कि हम उसको माननेसे सादर इनकार कर दें। यदि कानूनको न माननेके परिणामस्वरूप सरकार अनिवाय पजीयन लागू करनेकी जिद करती है तो हो सकता है कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंके निवासका प्रश्न उपनिवेशियोंके सतोषके मुताबिक सुलझ जाये, अर्थात् भारतीयोंको अतमें इस देशसे चले ही जाना पड़े। यदि ऐसा हो तो उपनिवेशियोंके इस सतोषसे मुझे तबतक ईर्ष्या नहीं होगी जबतक वे उसी साम्राज्यके सदस्य होनेका दावा करते हैं जिसमें सम्बन्धित होनेका मुझे भी सम्मान प्राप्त है। ऐसे दावोंसे उनके व्यवहारका बिल्कुल ही मेल न बैठेगा। खासकर तब, जब इस बातको ध्यानमें रखा जाये कि भारतीयोंने सरकारसे किये गये किसी भी वादेके अनुसार आचरण करनेमें अपने आपको समथ सिद्ध कर दिया है।

भारतीयोंने स्वेच्छया पजीयन करानेका वचन दिया है। वह उतना ही कारगर होगा जितना कि अनिवाय पजीयन। इस बारेमें बहुत कुछ कहा गया है कि कानून नरम है और उसमें एशियाइयोंकी भावनाओंपर चोट करनेवाली कोई बात नहीं है। परन्तु मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उपनिवेशोंमें स्वीकार किये गये समस्त प्रतिबन्धक कानूनोंको मने पड़ा है और मैं जानता हूँ कि जैसा अपमानजनक और गिरानेवाला यह पजीयन अधिनियम है वैसा कोई और नहीं है।

पुराने एम्पायर नाटकघरमें हुई विराट सभाका हवाला देते हुए श्री गांधीने अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने कहा कि सभाचारपत्रोंके अनुमानके अनुसार सभामें २,००० भारतीय उपस्थित थे और उन्होंने सब सम्मतिसे यह गम्भीर घोषणा की थी कि वे बलात पजीयनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे महसूस करते हैं, उस घोषणाका सच्चाईके साथ पालन किया जायेगा^१।

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, २९-६-१९०७

१ यह विवरण निम्नलिखित सम्पादकीय टिप्पणीके साथ समाप्त किया गया था पिछली मईमशहूरीके अनुसार ट्रान्सवालमें ९,९८६ भारतीय हैं, जिनमें ८६४७ पुरुष हैं। प्रिटोरियाके नगरपालिका क्षेत्रमें १,६८१ भारतीय हैं जिनमें १४४५ पुरुष हैं। ३१ चीनी भी हैं जो सब पुरुष हैं।

३९ लॉर्ड ऐम्सहिल

लॉर्ड ऐम्सहिलने दक्षिण आफ्रिकामें एक निराश्रित पक्षका माहस और उद्यमके साथ समथन करके दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीयाकी चिर वृत्तजता अर्जित की है। एशियाई पजीयन अधिनियमपर विवादका आरम्भ करत हुए लॉर्ड महादयने लॉर्डसभामें जो भाषण दिया, उसमें प्रकट होता है कि उनके लिए सारी दुनियाकी ब्रिटिश प्रजा समान है और ब्रिटिश राजनयिकोका वचन, यद्यपि वह उन जानियाका दिया गया है, जो उसके भग होनेपर किसी प्रकारकी नाराजगी व्यक्त करनेमें असमर्थ हैं, किसी प्रतिज्ञापत्रसे कुछ कम नहीं है। हमें आशा है लॉर्ड महादयने जिस प्रकार प्रारम्भ किया है उसी प्रकार वे आगे बढ़ते रहेंगे और तबतक शांत नहीं होंगे जबतक इस प्रथम काटिके प्रश्नको उचित स्थान तक नहीं पहुँचा देंगे।

वह इन महत्त्वका प्रश्न है कि सर जॉज फेरारको भी मानना पड़ा है कि यह ट्रान्सवालमें चीनियाकी गिरमित खतम करने या साम्राज्य सरकारसे ट्रान्सवालमें कृषिके विकासके लिए वज प्राप्त करनेसे बहुत अधिक महत्त्व रखता है। भारतीय समाचारपत्रोंकी जो कतरने हालमें हमारे पास आई हैं उनमें पता चलता है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंसे सम्बन्धित घटनाओंमें भारतीय जनताके मनपर गहरा असर डाला है। इसलिए यह खेदकी बात है कि ऐसे महत्त्वके प्रश्नपर लॉर्ड एलगिनने, जो इसके सही निबटारेके लिए जिम्मेवार हैं, इसपर ठीक तरह गौर नहीं किया। हमें यह देखकर दुःख होता है कि लॉर्ड महादयने, शायद अनजानमें, ट्रान्सवाल-सरकारके भुलावेमें आकर प्रवासके सवालको ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयाके प्रति हानेवाले बरतावके सवालके साथ उलझा दिया है। ब्रिटिश भारतीय सचने हमारे ख्यालमें निर्णायक रूपमें सिद्ध कर दिया है कि एशियाई पजीयन अधिनियम ब्रिटिश भारतीयाके प्रवासका नियमित नहीं करता और अगर शान्ति रक्षा अध्यादेशको वापस ले लिया गया, जमा कि लॉर्ड सेल्वानने^१ कहा है कि इसे वापस ले लेना चाहिए, तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा और, दृग्जमल, उसकी योजना बन भी गई है। पजीयन अधिनियम प्रवासके मामलेको किसी प्रकार हल तो नहीं करता, केकिन ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयाका अपमानित जरूर करता है और अपने परिणामरूपमें ब्रिटिश सविधानके चिर-पोषित सिद्धान्तका—अर्थात् इस सिद्धान्तको कि प्रत्येक मनुष्यका तबतक निर्दोष समझना चाहिए जबतक वह अपराधी नहीं साबित हो जाता, और एक निर्दोष व्यक्तिको दण्ड मिले इसकी बजाय यह अच्छा है कि अपराधी बिना दण्ड पाये बच निकले—बदल देता है। यह कानून प्रत्येक भारतीयको अपराधी मान लेता है और यह साबित करनेका भार उसीपर डालता है कि वह अपराधी नहीं है, अर्थात् वह ट्रान्सवालमें कानूनी तरीकेसे दाखिल हुआ है। फिर, यह ट्रान्सवालक तमाम एशियाई समुदायको बुरी तरह दण्डित करता है, ताकि कुछ धोखेबाज एशियाई चोरीसे ट्रान्सवालमें न चले जायें, और तब भी

^१ दक्षिण आफ्रिकामें उच्चायुक्त और १९०५ से १९१० तक ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज रिबर उपनिवेशके गवर्नर।

कानूनका यह उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि पजीयन उन एशियाइयोको रोक नहीं सकता जो धोखेबाज हैं और इस देशमें चोरीमें दाखिल होना चाहते हैं और यहां तबतक रहना चाहते हैं जबतक कि वे पकड़ न लिये जायें। यह अविनियम वैसा ही है जैसे ईमानदार लोगोको इसलिए जेलमें बंद कर दिया जाये कि चोर चोरी न कर सके।

इसके अलावा, लॉर्ड एलगिनने इस कथन मात्रको सही मान लिया है कि अनुमतिपत्रोका नाजायज व्यापार हुआ है। ब्रिटिश भारतीय सघने कई बार इसका सबूत मागा है, लेकिन वह आजतक नहीं मिल सका। श्री चैमनेका प्रतिवेदा^१, जैसा कि हमने बताया है एशियाइयोके कथनका पूरा समर्थन करता है। इस प्रकार यह कानून एशियाई समुदायके साथ दोहरा अत्याय करता है। एक तो, यह एशियाई समुदायके विरुद्ध झूठे इलजामपर आधारित है और दूसरे, प्रभावमें यह एक दण्ड देनेवाला विधान है। इसलिए अगर ट्रांसवालके चीनो और भारतीय निवासियोने यह तय कर लिया हो कि अनिवार्य पजीयन और उसके साथ लगी हुई अन्य सब बातोंके सामने नहीं झुकेंगे तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। अगर एशियाई दरअसल इस कानूनको बुरा समझते हैं, तो चाहे इसमें जितना माली नुकसान सहना पड़े, इसे न मानना ही उनके लिए सीधा रास्ता है और हमें विश्वास है कि अपने इस सघषमें उन्हें लाड ऐम्प्टहिल और उनके साथियोंकी सहानुभूति मिलेगी। इस सघषसे उन्हें कोई रियायत या लाभ नहीं मिलनेवाला है, परंतु दीन और असहाय लोगोकी सच्ची दुआएँ उन्हें मिलेगी।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४० अगद-वार्ता

कहा जाता है कि रामचन्द्रजीने रावणसे लड़ाई शुरू की, उसके पहले समझौतेकी वार्ताके लिए अगदको रावणके पास भेजा था। उस जमानेके रिवाजके अनुसार सच्ची बहादुरी इसमें होती थी कि युद्ध करनेके पहले शत्रुको उसकी गलती सुधारनेका पूरा मौका दिया जाये। शत्रुके सामने झुकते भी थे। झुकनेमें कोई हलकापन नहीं है। किन्तु इतना करनेपर भी यदि शत्रु नहीं मानता था तो पूरी ताकत दिखाते थे और सकल्पित काय करते थे। पुराने जमानेमें सारी दुनियाके लोग ऐसा ही करते थे। आज भी ऐसा करना अच्छा माना जाता है।

रामने रावणके साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार भारतीय समाजने ट्रांसवाल सरकारके साथ किया है। जितनी नम्रता बरती जा सकती थी उतना बरती गई है। फिर भी जबतक कानून सारे भारतीय समाजपर लागू नहीं हो जाता तबतक ट्रांसवाल सरकार सुखी नहीं होगी।

रामने अगदको समझौता-वार्ताके लिए भेजा था। अगदके बहुत समझानेपर भी रावण नहीं माना। और चूँकि अत्याय उसका था इसलिए अन्तमें उसे हारना पड़ा। ब्रिटिश भारतीय सघकी मारफत सरकारसे अनुनय विनय करनेपर श्री स्मट्सकी ओरसे भारतीय

समाजका अब अन्तिम उत्तर मित्रा है कि सरकारको भारतीय समाजका स्वेच्छया पजीयनका सुझाव मजूर नहीं है। यानी अब यही जानना शेष रहा कि कानूनको लागू करनेकी तारीख कब प्रकाशित होती है। इसीका साथ हम यह भी मान लेना होगा कि सरकार अपने मनके कानून बनाती है। कानून बनानेमें अंगुठियाकी निगानी लनेके बारेमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन इससे भारतीय समाजका कुछ काम नहीं होगा। इसलिए भारतीय समाजको अब लड़ाईकी ही तैयारी करनी रही। लड़ाईके लिए भारतीय समाजको और कुछ नहीं, केवल जेलके प्रस्तावों पर अटल रहनेकी दृढ़ता चाहिए। इसके बिना और किसी बातकी जरूरत नहीं। हमारा नाम जो पत्र आया है उसमें प्रकट होता है कि भारतीय समाज उसके लिए त्रिलकुल तैयार बैठा है। ट्रांसवाल सरकारने जो हमारी बात नहीं मानी, इसके लिए तब तो नाराज होनेके बजाय खुश होना चाहिए। सच झूठकी परीक्षा अब हो जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-९-१९०७

४१ दक्षिण आफ्रिकामें अकाल

दक्षिण आफ्रिकामें वर्तमान समय बहुत ही खराब बीत रहा है। हर जगह तपी दिव्बाईं दंती है। गोर और काले सबकी हालत खराब हो गई है। उसमें जमीनवालों और व्यापारियोंकी ज्यादा मुश्किल है। इस समय दूरदर्शी व्यक्तियोंकी सोचना चाहिए कि क्या किया जाय। व्यापार और भी कमजोर होगा। जमीनका मूल्य और भी घटता जायेगा। यह कहाँतक निभेगा? उस मुल्कका यह सकट वर्षाकी कमीके कारण नहीं, न फसल मिगानेमें है, बल्कि इसलिए है कि जहाँमें पैसा आता था वह जगह बेकार हो गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि खेतीमें नुकसान नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक भारतीयको सलाह देते हैं कि इस अवसरका लाभ उठाकर जिससे जितना बन सके उतना वह खेतीपर ध्यान दे। व्यापारी और दूसरे सब भारतीय खेती पर सकते हैं। उसमें बहुत पैसकी आवश्यकता नहीं रहता, न उसमें खरबाने बगैरहका सवाल उठता है। हमारी निश्चित राय है कि यदि भारतीय समाज खेतीका जो अधिक ध्यान देता तो उस लाभ होगा। इतना ही नहीं, खेतीका जो उस मुल्कमें भारतीयोंके विरुद्ध जो आपत्ति है उस दूर करनेमें भी मदद कर सकता है। यह मुल्क गरीब है। इसलिए यहाँ बहुत प्रकारकी फसलें पैदा की जा सकती हैं। और यदि वे यहाँ न गये तो उन्हें बाहर भेजा जा सकता है। ट्रांसवालमें डच लोग खेतीके द्वारा दशकों सम्पन्न बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं। वही नेटालम भी हो रहा है। इससे प्रत्येक भारतीयका चेतना चाहिए कि वह जमीन जोतनेकी ओर ध्यान दे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-९-१९०७

४२ लॉर्ड ऐम्स्टहिल

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति अभी नये कानूनके सम्बन्धमे जोर लगा रही है। लॉर्ड ऐम्स्टहिल, जो इस समितिके अध्यक्ष बनाये गये हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लॉर्डसभामे उन्होंने जो भाषण^१ दिया है उसकी ओर हम पाठकोंका ध्यान खींचते हैं। उससे ज्ञात होता है कि नये कानूनसे विलायतमे बहुत ही उत्तेजना फैल गई है। सभी समझने लगे हैं कि भारतीय समाजपर बहुत जुल्म हो रहा है। अब उस जुल्मकी वास्तविकता सिद्ध करनेके लिए भारतीय समाजकी जिम्मेदारी है कि वह जेलवाले प्रस्तावपर दबतापूर्वक डटा रहे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४३ इंग्लैंडकी बहादुर स्त्रियाँ

इंग्लैंडकी स्त्रियाँ अपने लिए मताधिकार प्राप्त करना चाहती हैं।^१ उनकी सभाकी अधिकृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उससे मालूम होता है कि वह सभा अपने कामके लिए हर सप्ताह करीब १०० पौंड खर्च करती है और आजतक, यानी दो वर्षके अंदर, सब स्त्रियोने मिलकर अपनी बहनोके अधिकारोके लिए लगभग छ वर्षकी कैद भोगी है। सभाके मन्त्रीने लिखा है कि उस सभाका काम चलानेके लिए अभी २०,००० पौंडकी जरूरत है। उसने प्रत्येक सदस्यसे यह रकम इकट्ठी करनेके लिए कहा है।

जब अंग्रेज स्त्रियोको उनके ही समाजसे हक प्राप्त करनेमे इतना पसा खर्च करना और इतना दुख उठाना पड़ता है तब भारतीय कौमको दूसरी कौमसे अधिकार प्राप्त करनेमे कितना खर्च करना और कितना दुख उठाना होगा? यह हिसाब प्रत्येक भारतीय समझ ले और फिर सोचे कि यदि पूरे १३,००० भारतीय जेल चले जाये और यदि वे १३,००० पौंड खर्च करे तो उससे इस कायमे कोई बड़ा खर्च नहीं होगा। कुल मिलाकर ट्रान्स-वालकी भारतीय कौमने अभी तो २,००० पौंड भी खर्च नहीं किये हैं, न कोई जेल ही गया है। इतनेपर भी यह मानना कि अधिकार मिल ही जाने चाहिए, सरासर भूल मालूम होती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

१ यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

२ यह उल्लेख इंग्लैंडमें चलनेवाले स्त्रियोके ससदीय मताधिकार आन्दोलनके सम्बन्धमें है। श्रीमती एम्लिन पैक्वहर्स्ट (१८५८-१९२८) के नेतृत्वमें महिलाओने जो मधुर्ष चलाया था उसमें धरना देना अनशन करना, और जेल जाना शामिल था।

४४ भारत और ट्रान्सवाल

इस समय भारतकी नजर ट्रान्सवालपर है। मद्रासमें दस हजार भारतीयाकी सभाने प्रस्ताव किया है कि भारतीयाका दक्षिण आफ्रिकामें कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए उपनिवेशके गांगको भारतमें कोई नोकरी अथवा अन्य अवसर नहीं मिलता चाहिए। लाहौरका 'ट्रिब्यून' लिखता है कि यदि भारतीय समाज अतएव अपना उत्साह कायम रखे तो बहुत लाभ होगा। अनेक भारतीय अखबारोंमें चर्चा हो रही है और सभी सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं। लाड लैसडाउन जैसे अधिकारी साच रहे हैं कि यहाँके भारतीय समाजके ऊपर जो जुल्म होता है उसका भारतपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन सब लक्षणोंसे प्रकट होता है कि भारतीय कौमके हाथ अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेका अमूल्य अवसर लगा है।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४५ कन्याओंकी शिक्षा

अलीगढ़में कुछ समय पहले मुस्लिम जनाना नामल गल्स स्कूलकी स्थापना हुई थी और उसकी दिनोदिन तरक्की होनी जा रही है। उस स्कूलको सहायता देनेके लिए मंग्रारमें प्रायतना की गई है। उस स्कूलके लिए खास जगह ली गई है और उसके साथ ग्रन्थालय बनानेकी भी योजना है। क्विडरगाटन पद्धतिके अनुसार उर्दूमें खास पुस्तके तैयार की गई हैं। मुसलमान आचार्या न मिलनेके कारण अभी एक गोरी महिलाको २०० रु० वनतपर नियुक्त किया गया है। इस स्कूलके लिए आजतक १३,००० रु० एकत्र किये गये हैं।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४६ भाषण प्रिटोरियाकी सभामें^१

प्रिटोरिया

३० जून, १९०७

श्री गांधीने कानूनका असर समझाते हुए कहा कि हर भारतीयको, चाहे वह गरीब हो या अमीर, स्वतन्त्र होना चाहिए। यह कानून [साम्राज्यीय] सरकारने मजूर कर लिया, इससे कुछ नहीं। भारतीय समाजके द्वारा मजूर होना अभी बाकी है।

१. एशियाई कानूनक प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिये श्री ईसप मियाँकी अध्यक्षतामें भारतीयोंकी एक सभा हुई थी। उसमें दिये गये गांधीजीके भाषणका यह सारांश है।

जबतक भारतीय समाज कानूनको मजूर नहीं करता तबतक वह पास माना ही नहीं जा सकता। यदि कोई बड़े या छोटे भारतीय कानूनकी गुलामीका पट्टा ले लेते ह तो उनका किसीको अनुकरण नहीं करना है। जो मुक्त रहेगे सो जीतेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

४७ पत्र 'रैड डेली मेल' को

जोहानिसबग

जुलाई १, १९०७

सेवामे

सम्पादक

['रैड डेली मेल']

महोदय

आपने एशियाई पजीयन अधिनियमके तथाकथित "अनाक्रमक प्रतिरोध" के सम्बन्धमे जा सोम्य और सदभावपूर्ण टिप्पणी की हे, उसकी आलोचना मुझे करनी पड रही हे जो, सम्भव हे, कृतघ्नता प्रतीत हो। भारतीय समाजको जो प्रतिरोध करना हे उसको म "तथा-कथित" कहता हूँ, क्योंकि वह मेरी सम्मतिमे वस्तुतः प्रतिरोध नहीं, बल्कि सामूहिक कष्ट-सहनकी नीति हे। अधिनियमके विनियमको पड लेनेपर भी आप इसको भावुकताकी बात समझते है।

यदि मेरे आठ वषके लडकेको एक ऐसे अधिकारीके सामने, जिसे उसने अपने जीवनमे शायद पहले कभी नहीं देखा, बिना किसी अपराधके, पहले अलग अलग और फिर एक साथ, अंगुलियो और अँगूठोके निशान देनेकी अत्याचारपूर्ण प्रक्रियासे गुजरनेको वाज्य किया जाये और मै पिताके नाते उस दृश्यको देखनेके बजाय गोलीसे मार दिया जाना अच्छा समझू तो क्या यह भावुकता हे? यदि म इस देशमे अपने अस्थिर निवासके मूल्यके रूपमे अपनी माका नाम और ऐसे ही दूसरे विवरण देना नामजूर करूँ तो क्या यह भावुकता है?

लॉड एलगिनको भले ही अपनी गद्दीदार कुर्सीपर बैठकर कलमके वजाय अँगूठेसे निशान बनानेमे कोई अतर न दिखाई दे, किन्तु मै जानता हूँ कि वे उस राष्ट्रके ह जो वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर किये गये आक्रमणका विरोध करनेके लिए एक सिरेसे दूसरे सिरे तक विद्रोह कर देगा और वे स्वयं पहले व्यक्ति होंगे, जो अपने हस्ताक्षरोके बलात अक्स किये जानेका भी चिल्लाकर विरोध करेगे। जो चीज चुभती है वह हे जबदस्ती, न कि अँगुलियोकी निशानी।

सरकारके मनमे हमे गिरानेकी कोई इच्छा नहीं है, यह बात तभी सत्य हो सकती है जब यह मान लिया जाये कि इस देशमे, जहाँ एशियाइयोके अतिरिक्त अय सबको स्वतन्त्रता प्राप्त हे, मेरे देशवासी पहले ही इतने गिरा दिये गये है कि वे उससे अधिक

गिरावटका अनुभव कर ही नहीं सकते। किन्तु यह समय तक करनेका नहीं है। वीर शासकापर, जो कथनीका नहीं, करनीका मूल्य समझते हैं, वीरता और ठोस कायकी ही प्रतिक्रिया हो सकती है।

जैसा आप कहते हैं, यदि प्रिटोरिया कमजार है और सरकारने “सापकी बुद्धिमे”, जिसका आप उसे श्रेय देते ह, अपने प्रति किसी भी विरोधका तोड़नेके लिए सबसे कमजार जगहको चुना है, और यदि इस अधिनियमके विरुद्ध आवाज उठानेवाला अकेला मैं और सम्भवतः मरे थोड़ेसे साथी कार्यकर्ता ही रह जाये, तब भी हम यह कह सकेंगे कि इस गिरावटको स्वीकार करनेमे हमारा कोई हिस्सा नहीं है। किन्तु प्रिटोरियाके सम्बन्धमे आपकी जो सम्मति है, उसे मैं नहीं मानता। कल स्थानीय मंत्री श्री हाजी हबीबके मकानपर ब्रिटिश भारतीयाकी जो आम सभा हुई थी उसमे एक वक्ता मैं भी था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मर देगवामिया द्वारा व्यक्त भावनाएँ उनके हृदयासे उद्भूत हुई हैं — और मेरा विश्वास है, बात ऐसी ही है — ता प्रिटोरियाका प्रत्येक भारतीय अनिवायत पुनः पजीयत करानेसे इनकार करेगा, फिर परिणाम चाह जा हा।

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति जब यह कहती है कि “स्थानीय सरकार इस सदेहकी पुष्टि करती है कि वह उग्रतम कानूनाका लादने और इस प्रकार ब्रिटिश भारतीयाका गिराने और अपमानित करनेके लिए व्यग्र है,” तब आप उसपर मुँह-फट भाषामें, असत्य नहीं ता आत्यन्तिक अत्युक्तिका आरोप लगात है। आत्यन्तिक अत्युक्ति या असत्य, चाह जिस बातका भी दोषी हानकी जाश्विम हो, मैं उसी कथनको दुहराता हूँ, और उसके समथतम आपक सम्मुख जानबूझकर किये गये अपमानका वह ताजा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जो प्रिटोरियाकी सभामे प्रकाशमे आया है। वहा एक धम-प्रचारकने मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेका एक कागज^१ दिखाया, जिसमे कहा गया था कि रेलकी यात्राके सम्भवतः धम-प्रचारकाको जो रियायत है वह ईसाई और यहूदी धम प्रचारकोके लिए ही है। धम-प्रचारककी इस सूचनासे सभामे दुःखद सनसनी फैल गई। क्या यह नया भेदभाव भा एशियाइयाकी भरमारके विरुद्ध आवश्यक चौकसी है?

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, २-७-१९०७

१ देखिए “प्रिटोरियाकी आम सभा”, पृष्ठ ८० ८२ ।

२ देखिए “आममें धी”, पृष्ठ ७१ ७२ ।

४८ जोहानिसबर्गके ताजे समाचार^१

जोहानिसबर्ग

बुधवारकी शाम, [जुलाई ३, १९०७]

नया प्रवासी विधेयक^२ पेश किया जा चुका है। इस विधेयकके अनुसार कोई भी अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति [ट्रान्सवालमे] प्रवेश कर सकता है, किन्तु भारतीय नहीं। जान पड़ता है कि जिनपर खूनी कानून लागू होता है, वे अंग्रेजी जाने या न जाने, दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा इस कानूनके अनुसार सरकार जिसे बुरा समझती है उसे जबर दस्ती निर्वासित कर सकती है और निर्वासित करनेका खर्च उसकी जायदादमे से ले सकती है। अब भारतीय अवश्य फंदेमे आये हैं। यह विधेयक पास होगा या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु इसमे शका नहीं कि ट्रान्सवालकी सरकार भारतीयोंको खदेड़ना चाहती है। मुझे आशा है कि हर भारतीय इज्जतके साथ यहासे जायेगा, बेइज्जती लेकर नहीं।

एशियाई भोजनालय

जोहानिसबर्गकी नगरपालिका प्रत्येक भारतीय भोजनगृहवालेके लिए यूरोपीय मैनेजर रखना अनिवार्य करना चाहती है।

फोक्सरस्टमे सभा

फोक्सरस्टमे मंगलवारको सभा हुई थी। श्री काछलिया सभापति थे। श्री गांधी, श्री भट तथा श्री काजी और श्री काछलियाके भाषण हुए। सबने जेल सम्बन्धी प्रस्तावपर दब रहना स्वीकार किया। उसी समय चंदा इकट्ठा किया गया। करीब २० पौंड चंदेके लिए नाम लिखवाये गये और ११ पौंड नकद मिले।

प्रिटोरिया

प्रिटोरियाके भारतीय बहुत जोर दिखा रहे हैं। अभीतक एक भारतीय भी नया अनुमतिपत्र लेने नहीं गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

१ यह “ हमारे जोहानिसबर्ग प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित ” रूपमें प्रकाशित किया गया था।

२ पाठक लिए देखिए परिशिष्ट ३।

४९ पत्र 'स्टार' को

जाहानिसमग
जुलाई ४, १९०३

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'
[जाहानिसमग]

महोदय,

आपने अपने पाठकोंका जो जानकारी दी है उससे भारतीय समाजको बहुत आश्चर्य हुआ है। आपने कहा है कि भारतीय लगभग किसी नियोग्यतासे पीड़ित नहीं है और अँगुलियाके निशान देनेके प्रश्नपर ता विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सिपाही अपनी पेंशन देनेसे पहले स्वेच्छामे अपने अँगूठोंके निशान देते हैं।

मैं साचता हूँ कि क्या आप अब प्रवासी विधेयकका, जो कल प्रकाशित किया गया है, समझन करगे और यह कहें कि, जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है वह कानून निर्दिष्ट है। एशियाइयोंका अत्यन्त चाशक बनाया गया है। किन्तु जो चालाकी इस विधेयकके निर्माताोंने दिखाई है वह, यदि अमानित भाषामें रहे तो, सबसे राजी मार ले जाती है। यदि खण्ड २ के उपखण्ड ४का मने ठीक तरह समझा है तो मेरा विश्वास है, उसने द्वारा एशियाई पजीयत अधिनियमके विरोध करनेवाला अनाक्रमक प्रतिरोधियोंको एक उत्तर दिया गया है और ट्रान्सवालक भारतीयोंमे आत्मसांस्कार अंगित भावनाका भी कुछ कुछ लिए राजकीय ठन्की प्रणाली स्थापित की गई है, क्योंकि उक्त खण्ड अतन्त एसा प्रयत्न एशियाई, जो नया पजीयत प्रमाणपत्र नहीं होगा, एक वर्जित प्रवासी है जो अत्यन्त वर्जित प्रवासीका जलकी मना दी जा सकती है, उसका बाद उस उपनिवेशमें जगदम्नी निराशा जा सकता है तथा उसका निवासनका यय उसकी सम्पत्ति, जो उपनिवेशमें होगी, वसूल कर लिया जायेगा। उस प्रकार मानन हुआ ही पनादा तरीकेमें वर्जित प्रवासीका निमाण करना है। जिस व्यक्तिन ट्रान्सवालका अपना दश बना लिया है, किन्तु जो अनिश्चित दण्ड भागकर अपने ऊपर लागू किसी कानूनका उचित या अनुचित विरोध करता है, वह व्यक्ति अपने अंगीकृत दशम कानूनक संरक्षणमें वचित कर दिया जायेगा। उसके अतिरिक्त यह खण्ड केवल 'एशियाई और दुर्गचार अधिनियम' का ही अमल करा सकता है, अर्थात् वेष्टाएँ, गुण्डे और वे एशियाई जो अपना सम्मान खानेमें उनहार करने हैं, एक ही श्रेणीमें रखे जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, इससे जो अपमान उद्दिष्ट है उसकी निरकुशता दिखानेके लिए, मैं जनताका ध्यान इस बातकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि यदि कोई भारतीय — उदाहरणार्थ, सर मचरजीको ही ले लीजिए — अत्यन्त कड़ी परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाये, और ट्रान्सवालमें

आना चाहे तो उसको अवश्य ही अपना और अपने अवयस्क बच्चोका पजीयन प्रमाणपत्र लेना होगा और यदि वह वजित प्रवासीकी श्रेणीमें आना और निष्कासित होना न चाहे तो उसके आठ सालसे अधिक आयुके जो बच्चे हो उन्हें भी अलग अलग और एक साथ अँगुलियोके निशान देने पडेगे। कहा यह जाता है कि पजीयन अधिनियम सिफ शिनाख्ती कारवाईके लिए है। एशियाई अधिनियम न होनेपर जो व्यक्ति अपनी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताके कारण ट्रान्सवालमे रहनेके अधिकारका दावा कर सकता है, उसकी शिनाख्त करानेका क्या कोई अर्थ है? वह चाहे उपनिवेशमे हो चाहे उसके बाहर, उसके किसी एक यूरोपीय भाषाके ज्ञानकी परीक्षा किसी भी समय की जा सकती है। तब क्या उसकी शिनाख्तके निशान उसके व्यक्तित्वमे ही समाहित नहीं है?

जनरल बोथाने तो, जब वे लंदनमे थे, सारे साम्राज्यके कल्याणकी इतनी चिन्ता प्रकट की थी और लाड ऐम्प्टहिलको आश्वासन दिया था कि सम्राटकी भारतीय प्रजाको नीचा दिखानेका उनका कोई इरादा नहीं है। उनके उन भाषणोका^१ क्या हुआ? क्या स्वशासनका अर्थ एशियाइयोकी समस्त स्वतन्त्रताके मनमाने अपहरणका परवाना है? सर जाज फेरारने प्रगतिवादी दलकी ओरसे बोलते हुए कहा था कि एशियाई पजीयन अधिनियमके पीछे बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी स्वीकृतिसे लाखो भारतीय अकारण ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध उत्तेजित हो जायेगे। फिर भी उन्होंने सरकारकी सहायताके लिए, बहुत ही बेमौके, सम्राट एडवर्डकी भारतीय प्रजाकी भावनाओको चोट पहुँचानेकी जोखिम उठाकर भी, एशियाई पजीयन अधिनियमका समर्थन किया। क्या प्रगतिवादी दल अपनी साम्राज्य-हितकी डींगोके बावजूद मेरे द्वारा बताई गई घणित धाराके रहते हुए इस प्रवास-विधेयकका समर्थन करेगा?

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ५-७-१९०७

५० आगमें घी

प्रिटोरियाकी आम सभाकी कारवाईका विवरण भेजते हुए हमारे प्रिटोरियाके सवाद-दाताने लिखा है कि मौलवी मुस्तियार अहमद द्वारा मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवे (सी० एस० ए० आर०)^१का एक पत्र पेश किया जानेपर बहुत सनसनी फैली। उस पत्रको हम एक बहुत जरूरी प्रलेख मानते हैं। वह इस तरह है

आपके २४ तारीखके पत्रके उत्तरमे, जिसमे ट्रान्सवालके मुस्लिम समाजकी धार्मिक आवश्यकताओकी पूर्ति करनेवाले एक मुल्लाके यात्रा सम्बन्धी खचका जिक्र है, मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि इस रेलवेमे धर्म प्रचारकोको दी जानेवाली रियायत ईसाई

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४६० ६१, ४८३।

२ देखिए 'पत्र रैड डेली मेल को' पृष्ठ ६७ ६८।

या यहूदी धर्मोंके अलावा दूसरे धर्मोंको नहीं दी जाती है, इसलिए मैं आपकी मांगी हुई विशेष सुविधाएँ देनेमें असमर्थ हूँ।

इसपर स्वयं मुख्य यातायात प्रबन्धकके हस्ताक्षर हैं। इससे, हमारी सम्मतिमें, न्यायपूर्ण व्यवहारकी, जिसका वचन जनरल बाथाने दिया था, सब आशाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस पत्रसे यह शोखी भी खत्म हो जाती है कि साम्राज्यके भीतर कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। दुभाग्यमें हम जाति-भेदके तो अभ्यस्त हो गये हैं। किन्तु एशियाई अधिनियमने एक धार्मिक भेदभाव करके पहल की है और रेलवे विभागने उनका अनुसरण किया है। ट्रान्सवालमें रहनेके इच्छुक भारतीय जानते हैं कि उन्हें अधिकारियोंसे क्या आशा रखनी है। हमारी समझमें नहीं आता कि जिन लोगोंका आधार ही धर्म है और जो—हिन्दू और मुसलमान दोनों—अपने धर्मपर आक्रमण होते ही विचलित हो उठते हैं, उन लोगोंकी धार्मिक भावनाओंके अकारण अपमानके इस नवीनतम उदाहरणका लाड एलगिन क्या औचित्य बतायेगे।

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५१ एक टेक

माननीय अमीर 'महाविभव' से 'महामहिम' सहज ही नहीं बन गये। उन्होंने सच्ची टेक रखी तब प्रतिष्ठा मिली और अंग्रेजोंने उनका स्वागत किया। वे भारतकी यात्रापर इस शर्तपर आये थे कि उनकी प्रतिष्ठाकी पूरी तरहसे रक्षा की जायेगी और सरकार कोई राजकीय विषय नहीं छेड़ेगी। उन्हें लाड कज़नने^१ भी आनेका निमन्त्रण दिया था, किन्तु उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया था। उसका कारण श्री मॉर्टन^२ अपने बजट-भाषणमें दिया है। काबुलमें भाषण करते समय उन्होंने कहा "इस समय भारत सरकारके अधिकारियोंने राजकीय विषयकी कोई बात नहीं छेड़ी। उन्होंने अपना वचन निभाया। इसलिए जब मेरी इच्छा हुई तब मैंने खुद होकर इस सम्बन्धमें बातचीत की। उसका उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। गॉड मिंटोका^३ निमन्त्रण सम्मतिपूर्ण था, इसलिए मैंने उस स्वीकार किया। दिल्ली दरबारके समय दिये गये आमन्त्रण और लाड मिंटोके आमन्त्रणमें बड़ा भेद था। इसीलिए मैंने दिल्ली दरबारमें न जानेका निश्चय किया था। मैंने सोचा था कि इतना बेहूदा आमन्त्रण स्वीकार करनेकी अपेक्षा मेरा राजपाट चला जाये, मैं भिखारी बन जाऊँ, मुझे प्राण देने पड़ें, यह सब सहन करनेको तैयार हूँ।" अपनी इसी टेकके कारण अमीरको मान मिला और लाड कज़नका पीछे हटना पड़ा।

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ५०५।

२ (१८५९-१९२५), भारतके वास्तराय और गवर्नर जनरल, १८९९-१९०५, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ५०।

३ (१८३८-१९२३), भारत-मन्त्री, १९०५-१०।

४ (१८४५-१९१४), भारतके वास्तराय और गवर्नर जनरल, १९०५-१०।

ट्रान्सवालके भारतीय समाजको इसी प्रकार सोचना चाहिए। “सबस्व चला जायेगा तब भी नया कानून मजूर नहीं करेगे” — यह टेक रखना आवश्यक है। इस कानूनकी धाराएँ प्रकाशित हुई हैं। उनका तजुमा हम इस अकमे दे रहे हैं। वे धाराएँ इतनी सरत और कठोर ह कि उनकी किसीको स्वप्नमे भी कल्पना नहीं हो सकती। जनरल बोथाने विलायतमे जो मीठी मीठी बातें की थी उनपर पानी फिर गया है। इससे हमें बहुत खुशी है। यदि इस जहरकी गोली रूपी कानूनपर चादीका वक चढ़ा हुआ होता तो भी भारतीय भुलावेमे आकर धोखा खा सकते थे। किंतु अब तो एक भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जो इस कानूनको स्वीकार करे।

इस कानूनके सामने झुकनेवाले भारतीयको क्या लाभ होगा, यह भी जरा हम देखें। एक तो यह कि वह अपने खुदाको भूलेगा, दूसरा यह कि उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो जायेगी, तीसरा यह कि उसे सारे भारतका शाप मिलेगा, चौथा यह कि उसके लिए बस्तीमे जानेकी नौबत आयेगी, और आखिर ट्रान्सवालमे कुत्तेकी जिदगी बितानी होगी। कानूनके सामने झुककर कौन भारतीय ऐसे लाभ भोगना चाहेगा? अब न झुकनेवालेकी भी बात ले। वह खुदासे डरनेवाला माना जायेगा, वह खुदाके साथ किये हुए इकरारका पालन करनेवाला माना जायेगा, शूर माना जायेगा। भारतीय उसका स्वागत करेंगे, जेल उसके लिए महल माना जायेगा। उसे ज्यादासे ज्यादा यदि कोई दुःख होगा तो यह कि उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी और अतमे शायद ट्रान्सवाल भी छोड़ना पड़े। यदि ट्रान्सवाल छोड़ना पड़ा तो क्या दूसरी जगह खुदा नहीं है? जिसे दात दिये हैं उसे चबेना देनेवाला मालिक हर जगह बैठा हुआ है। उस मालिकको खुशामद नहीं चाहिए। वह हमारे कानमे केवल यह कहता रहता है कि मुझपर भरोसा रख। यदि उसकी मधुर वाणी हमें सुनाई नहीं देती तो कानोके होते हुए भी हम बहरे हैं। यदि वह हमें अपने पास बैठा हुआ दिखाई नहीं देता तो आंखोंके होते हुए भी हम अंधे हैं।

यदि भारतीय समाज अपनी टेक निभायेगा तो हम मानते हैं कि कोई भी भारतीय बरबाद नहीं हो सकता। ट्रान्सवालके भारतीयोंकी तो बात ही दूर, सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको मुक्ति मिल जायेगी। क्योंकि भारतीय जनता अपनी ताकत पहचान जायेगी और बहादुर बोअरोको हमारी बहादुरीका पता चल जायेगा।

एक बार एक सिंह बचपनसे भेड़ोंके बीच पलनेके कारण अपना भान भूल गया और अपने आपको भेड़ ही मानने लग गया। किन्तु दूसरे सिंहोंका यूथ देखकर उसे अपना कुछ भान हो आया। यही स्थिति भारतीय सिंहकी समझनी चाहिए। बहुत समयसे हम अपना भान भूले, पामर बने बैठे हैं। यह भान करानेवाला समय आया है इसलिए

राखी पुरो विश्वास धनीनो^१ साचो ।
जवु^२ जेल, जेलने^३-जेल एम^४ उर राचो ।^५

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

१ स्वामीका । २ जाना है । ३ और । ४ ऐसा ।

५ ये पंक्तियाँ पुरस्कृत कविता ‘जेल-यात्रा’ की हैं !

५२ समितिकी सलाह

समितिके पाससे ट्रान्सवालके सम्बन्धमें आया हुआ तार हम प्रकाशित कर चुके हैं।^१ श्री रिचवे पत्रमें समझमें आ सकता है कि समितिके तारमें हमें जरा भी डरना नहीं है। समिति हमें बहुत भला पत्रा कहते तब भी जेठके सम्बन्धमें हमने जो बहुत ही सोच समझकर निणय किया है उसमें पीछे पैर नहीं खड़ा जा सकता। साहस करनेवालेको दूसरेकी सीख काम नहीं देती।

डा० जेम्सने ट्रान्सवालपर हमला किया तब किसीसे सीख नहीं ली थी। हमनेको ता लोग भूल गये, किन्तु उनकी बहादुरीकी आज भी प्रशंसा की जाती है। वे स्वयं इस समय बोथाके मित्र हैं और केपटा वारोपर चला रहे हैं।

इंग्लंडके प्रधान मंत्री सर हेनरी कैम्बेल बेनरमैनने बहुत ही विनयपूर्वक अंग्रेज महिलाओंको सलाह दी थी कि वे अपनी जेल जानेकी बात छोड़ दें। इन महिलाओंमें जनरल फ्रेचकी बूढ़ी बहन भी हैं।^२ किन्तु उन बहादुर महिलाओंने उस बुद्धिमान्तीकी सीखको माननेसे इनकार कर दिया। सताबिहारके अभावमें उन्हें जो बदनाम हो रही है उसे सर हेनरी क्या समझ सकते हैं? जब बहादुर अंग्रेज महिलाएं अपने नये अधिकार प्राप्त करनेकी लड़ाई किसीकी सीखकी परवाह किये बिना लड़ रही हैं, तब क्या भारतीय मद करने जाते हुए हकोंको — अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाकी लड़ाईको — भग्न कोई समिति या कोई महापुरुष सीख दें, छोड़ दें?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५३ कैसी दशा !

यदि ट्रान्सवालपर बादल छाये हैं तो नेटाल छूट जायेगा, सां बात नहीं। गोराली कालोपर चढ़ाई होती ही रहती है। अब नेटालकी सड़में ऐसा विवेक पेश हुआ है कि अपनी जमीन स्वयं जाननेवाला भारतीय अगर वह जमीन किसी दूसरे भारतीय या काफिरको जानने दे तो उसे उस जमीनपर गाराकी अपभवा दुगुना कर देना होगा। ऐसा इन्साफ ता दक्षिण आफ्रिकाने गारे ही कर सकत है। परन्तु गिरे हुएका ठाकर मारनेका रिवाज ता सदास चरुता आया है। ठमगिरे गिरे हुए भारतीय उठगे तभी उनके दुख मिटेगे। काफिरका लिखा पढ़ी जादि ता करनी ही होगी।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

१ देखिए “ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ५६ ६० ।

२ १९०५-८ ।

३ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३५४ ।

५४ नेटाल, तू जागता है या सोता ?

ट्रान्सवालके भारतीय नेटालके भारतीयोंका दरवाजा खटखटाकर उपयुक्त प्रश्न पूछ रहे हैं। ट्रान्सवालके भारतीय कहते हैं कि “हम केसरिया बाना पहनेगे और रणमें जूझेंगे।” तब नेटालके भारतीय भाई रणमें आहतोंकी सार सँभाल करेंगे या दूर रहेंगे ? इस प्रश्नका उत्तर प्रत्येक नेटालवासी भारतीयको अपने मनमें मोच लेना है।

यदि ट्रान्सवालकी मदद करनेमें ईमानदारी हो तो नेटालके भारतीयोंको भी अपनी टेक निभानी चाहिये। नेटालके नेताओंने ट्रान्सवालके भारतीयोंको हिम्मत बँवाई है वह तो पत्र और तार द्वारा। कहे और लिखे हुए शब्दोंपर चलनेका समय अब आया है। इसलिए हम नेटालके भारतीयोंको सावधान होनेकी सलाह देते हैं। नहीं तो सभी नेटालके बारेमें यही गायेंगे कि

बिना टेकवाला बहु बोली बोले
पछी आपसी टेक एके न पाले।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५५ खूनी कानून

खूनी धाराएँ

जाँ सोचा था वही हुआ। ‘ट्रान्सवाल गजट’ में ऐलान किया गया है कि जुलाई १ से नया कानून अमलमें आयेगा। इस कानूनके अंतर्गत जो धाराएँ बनाई गई हैं वे इतनी कठोर, खूनी हैं कि उनके अनुसार कोई भी भारतीय चल सकेगा, सो नहीं मालूम होता। उन धाराओंका सम्पूर्ण सारांश हम नीचे दे रहे हैं

- १ इस धारामें पथक पथक व्याख्याएँ दी गई हैं।
- २ एशियाईका पजीयनपत्र किस प्रकार रखा जाये, यह बताया है।
- ३ सालह वर्षसे अधिक आयुवाले व्यक्तिको पजीयनके लिए ‘ख’ फामके अनुसार आवेदन देना चाहिए। सोलह वर्षसे कम और आठसे अधिक आयुवाले लड़केको ‘ग’ फामके अनुसार आवेदन देना चाहिए।
- ४ प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको उपनिवेश सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्तिके पास उपस्थित होना होगा और उसे ‘ख’ फामके अनुसार अर्जीमें देने योग्य सारी हकीकत भरकर देनी होगी। इसीके साथ अपनी अर्जीके समथनमें यदि उसे अपना अनुमति-पत्र, तीन पौडवाला पजीयनपत्र तथा अन्य कोई दस्तावेज देने हो, तो देगा। आठ वर्षसे अधिक आयुवाले लड़केके आवेदनके लिए उसके पिता अथवा अभिभावकोंको अपने लड़केके साथ उपस्थित होना होगा और ऊपर बताये गये

दस्तावेज यदि हो तो उन्हें पेश करना होगा तथा 'ग' फाममे भरी जानेवाली बाने देनी होगी। उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित किये गये स्थानपर प्रत्येक अर्जी देनी होगी।

अर्जियाँ लेनेके लिए जिस व्यक्तिको नियुक्त किया जाये उसे अर्जी बनाकर आवेदकको रसीद देनी चाहिए और अर्जी पंजीयकके पास भेज देनी चाहिए।

५ यदि पंजीयक वयस्क व्यक्तिकी उपयुक्त तरीकेसे दी हुई अर्जीको खारिज कर दे तो उसे आवेदकके पास खारिज करनेकी सूचना भेजनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि न्यायाधीशके पास भेजनी चाहिए।

६ पंजीयनका प्रमाणपत्र 'फ' फामके अनुसार दिया जाये।

७ प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको जब भी उससे देखनेके लिए पंजीयनपत्र मागा जाये, दिखाना होगा, और पुलिसके माँगनेपर उसे निम्न जानकारी देनी होगी

(१) अपना पूरा नाम,

(२) उस समयका पता,

(३) अर्जी देनेके समयका पता,

(४) अपनी उम्र,

(५) अपने हस्ताक्षर, यदि उसे लिखना आता हो तो,

(६) और दोनों अँगूठाकी निशानियाँ, अथवा अँगूठे और अँगुलियोंकी निशानियाँ।

८ सोलह वर्षसे कम आयुवाले लड़केके पिता या अभिभावकको जब भी उससे माँगा जाये अपना प्रमाणपत्र दिखानेके अनिवार्य निम्न जानकारी देनी चाहिए

(१) अपना पूरा नाम।

(२) उस समयका पता।

(३) अर्जी देनेके समय उसके अभिभावकका पूरा नाम और उसका पता।

(४) उस बालककी आयु।

(५) और उस बालकके अँगूठेके निशान अथवा अँगूठे और अँगुलियोंकी निशानियाँ।

९ आठ वर्षसे कम आयुवाले लड़केके प्रमाणपत्रके लिए आवेदन देने समय अभिभावक या पिताको निम्न हकीकत देनी चाहिए,

(१) लड़केका पूरा नाम,

(२) उसकी आयु,

(३) उसका रिश्ता,

(४) उसका जन्मदिन,^१

(५) उसके ट्रान्सबालमे प्रविष्ट होनेकी तारीख।

१० खोये गये पंजीयनपत्रके लिए आवेदन^१ करने समय प्रत्येक एशियाई निम्नलिखित हकीकत पेश करे

१ मूल अंग्रेजी पाठमें है "प्रत्येकका जन्म-स्थान"।

२ मूल अंग्रेजीमें यह वाक्य दिया गया है "पंजीयन प्रमाणपत्रको नया करानेके लिए प्रार्थनापत्र देते समय"।

- (१) पजीयनपत्र क्रमांक,
 - (२) अपना पूरा नाम,
 - (३) अपना पता,
 - (४) और यदि बालकका पजीयापत्र खो गया हो तो उसका पूरा नाम,^१
 - (५) अपने अँगूठे और अँगुलियोंकी निशानियां,
 - (६) और यदि बालककी ओरसे अर्जी दी हो तो अपने अँगूठोंकी निशानी और बालकके अँगूठों तथा अँगुलियोंकी निशानियां।
- ११ व्यापारीका परवाना अथवा अन्य कोई परवाना लेते समय आवेदकको अधिकारियोंके समक्ष अपना पजीयनपत्र पेश करना होगा और इसके अतिरिक्त अधिकारी जिस प्रकार कह, उस प्रकारसे उसे अँगूठे तथा अँगुलियोंकी निशानियां देनी होगी।
- १२ यदि कोई एशियाई कुछ समयके लिए ट्रांसवालसे बाहर गया हो और उसकी ओरसे अन्य कोई एशियाई परवानेके लिए आवेदन करे तो उसे अधिकारियोंके पास निम्न बातें पेश करनी चाहिए,
- (१) अपना पजीयन पत्र,
 - (२) जिसके लिए अर्जी दी हो उसका पूरा नाम,
 - (३) उस एशियाईका उस समयका पता,
 - (४) उस व्यक्तिके दाहिने अँगूठेकी छाप लगा हुआ मुखत्यारनामा,
 - (५) और अपने दाहिने अँगूठेकी निशानी।
- १३ मुद्दती अनुमतिपत्र 'छ' फामके अनुसार दिया जाये।

फार्म ख

वयस्क व्यक्तिका आवेदनपत्र

पूरा नाम	कौम	
जाति या उपजाति	आयु	ऊँचाई
निवास स्थान	व्यवसाय	
शरीरके खास खास चिह्न		
जन्म देश		
ट्रांसवालमें पढ़ले-पढ़ल आनेकी तारीख		
मई १९०२ में कहाँ था		
पिताका नाम	माताका नाम	
पत्नीका नाम	कहाँ रहता है	
आठ वर्षसे कम उम्रके बच्चों आदिके नाम, आयु, निवास स्थान और रिश्ता	आवेदकके हस्ताक्षर	
	आवेदन प्राप्त करनेवालेके हस्ताक्षर	
	तारीख	कार्यालय

१ मूल अंग्रेजी पाठमें है “बालकका पूरा नाम तथा उसकी आयु (यदि सरक्षक किसी बालकके लिए प्रार्थनापत्र दे)”।

दाहिने हाथकी निशानियाँ

अंगूठा	पहली अँगुली	बिचला	तीसरी	अन्तिम अँगुली

ऊपरके अनुसार बायें हाथकी अलग अलग निशानियाँ

सम्मिलित निशानियाँ

बायें हाथकी चार पूरा अँगुलियोंका निशानी	दाहिने हाथकी चार पूरा अँगुलियोंका निशानी

वयस्क व्यक्तिकी निशानियाँ लेनेवालेका नाम

तारीख

फाम ग

बालकके लिए आवेदनपत्र

अभिभावकका विवरण

पूरा नाम
निवास स्थान
अभिभावकका रिश्ता
प्रमाणपत्र क्रमांक

जाति

बालकका विवरण

पूरा नाम
जाति या शाखा
पता
३१ मई १९०२ को कहाँ था
पिताका नाम
शरीरके खास खान चिह्न
जन्म-देश
टान्सवालमें आनेका तारीख

प्रजाति
आयु
व्यवसाय

माताका नाम

अभिभावकका
दाहिना अँगूठा

अभिभावकके हस्ताक्षर
बालकके हस्ताक्षर
आवेदनपत्र लेनेवालेके हस्ताक्षर
कार्यालय
तारीख

‘ख’ फामके अनुसार बालकके दाहिने तथा बायें हाथके अँगूठों तथा अँगुलियोंकी अलग अलग निशानियाँ और दाहिने तथा बायें हाथकी निशानी लेनेवाले अधिकारीके हस्ताक्षर

फार्म च

पजीयनपत्र

पूरा नाम
प्रजाति
वर्णन

आयु

ऊँचाई

दाहिना अँगूठा

पजीयकके हस्ताक्षर

तारीख

मालिकके हस्ताक्षर

फार्म छ^१

मुद्दती अनुमतिपत्र

सूचना

‘गजट’मे यह सूचना हे कि पहली जुलाईको प्रिटोरिया या उसके प्रदेशमे रहनेवाले एशियाईको अपने नये पजीयनपत्रके लिए जुलाई ३१, १९०७ स पहले रिचर्ड टेरेंस कोडोके पास ७०, चच स्ट्रीटमे आवेदनपत्र देना चाहिए।

श्री कोडी सोमवारमे शुक्रवार तक सबेरे ९ बजेसे शामके ४ बजे तक उपयुक्त स्थानपर रहेगे। और शनिवारको दोपहरके २ बजे तक रहेगे।

धाराओका प्रभाव

धाराओमे अनपेक्षित वाते ज्यादातर निम्न प्रकार दिखाई देती है

- (१) भारतम अपनी माके प्रति हिंदू और मुसलमान दोनो इतना अधिक आदर रखते है कि यदि उसका नाम कोई लेनेके लिए कहे तो कत्ल हो जाता हे। उस माताका नाम आवेदनपत्रोपर चडेगा।
- (२) यह स्वप्नमे भी खयाल नही किया गया था कि लडकोकी सब अँगुलियोकी निशानिया ली जायेगी। अब उनकी अठारह अँगुलियोकी निशानिया ली जायेगी। अनुवादकका अनुभव है कि नौ वषके कमजोर बालकको अनजान मनुष्य हाथ लगा दे तो वह रो पडता है। ऐसे कोमल भारतीय बालकोको अब जालिम हाथ लगेगा। उनकी अँगुलिया लगाई जायेगी और बाप बैठा हुआ देखेगा।
- (३) सब अँगुलियोकी निशानी एक बार ही नही दो बार देनी होगी। इकट्ठी और अलग-अलग।
- (४) पुलिसको अँगुलियोकी निशानी लेनेका आदेश है, बडे छोटे सबकी।
- (५) व्यापारी बाहर जाये और उसका मुनीम परवाना मागे तो उसके हाथमे व्यापारीके दाहिने अँगूठेकी निशानीवाला मुखत्यारनामा होना चाहिए, यह अपमानकी हद है। आगेसे भारतीय मुखत्यारनामेमे हस्ताक्षर पर्याप्त नही, अँगूठेकी निशानी चाहिए।
- (६) सारे आवेदनपत्र अधिकारी लिखेगे। वकील या एजेटसे कोई नही लिखवा सकेगा। सरसरी तौरसे देखनेपर यह धारा पैसा बचानेवाली है। किंतु गहराईसे देखनेपर

१ इस फार्मका विवरण उपर्युक्त च फार्मके अनुसार है।

शेरको सामने विठाकर खीर खिलानेके समान है। प्रौढ भारतीय भी अधिकारीके सामने घबरा जाते हैं तब दुबले पतले बालककी तो बात ही क्या की जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५६ प्रिटोरियाकी आम सभा^१

नया कानून पहली जुलाईमें प्रिटोरियामे अमलमें आनेवाला था। इसलिए वहां रविवार, ३० जूनका एक विराट आम सभा की गई थी। वहां जोहानिसबर्गसे खास खास भारतीय अपने खचसे गये थे। उनमें कायवाहक अव्यक्त श्री ईसप मिया, मौलवी साहब अहमद मुस्त्यार, श्री एम० एम० कुवाडिया, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी साले, श्री मकनजी, श्री झीणाभाई, श्री गुलावभाई कीकाभाई, श्री मोरारजी देसाई, श्री गुलावभाई पटेल, श्री भूला, श्री रणछोड नीछाभाई, श्री नादिरगाह कामा, श्री मुहम्मद इशाक, श्री खुशाल, श्री पीटर मूनलाइट, श्री नायडू, श्री ए० एस० पिल्ले, श्री गांधी वगैरह थे। प्रिटोरियाके लोगोमें श्री हाजी हबीबके अलावा वहांकी मसजिदके मौलवी साहब, श्री हाजी कासिम जूसब, श्री हाजी उस्मान, श्री काछलिया, श्री अली, श्री हाजी इब्राहीम, श्री गौरीशकर व्यास, श्री प्रभाशकर जोशी, श्री मोहनलाल जोशी, श्री उमरजी वगैरह कुल मिलाकर लगभग चार सौ भारतीय थे।

जोहानिसबर्गके प्रतिनिधियोंके खाने पीने, ठहरने आदिकी व्यवस्था श्री हाजी हबीब और श्री व्यासने की थी।

सभा ठीक तीन बजे शुरू होकर शामके सात बजे तक चलती रही थी। श्री हाजी हबीबने सबका स्वागत करते हुए कहा कि नया कानून अत्यन्त ही अत्याचारपूर्ण है। जबतक वह प्रकाशित नहीं हुआ था तबतक तो लगता था कि यदि उसकी धाराएँ ढगकी हों तो उसे स्वीकार भी किया जा सकता है। किन्तु धाराओंको देखनेके बाद तो यही लगा कि कानूनको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय समाजको एकताके साथ कानूनका विराट करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्री ईसप मियाँसे सभापतिका आसन ग्रहण करनेका निवेदन किया।

श्री ईसप मियाँने श्री हाजी हबीबका उपकार माना कि उन्होंने अपना मकान दिया। उन्होंने कहा कि कानून जहरी है। वह हमसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं अपना काम छोड़कर समाजकी सेवा करनेको तैयार हूँ। सभी भाइयोंको हिलमिलकर रहना है। आज तक हम झुकते आये हैं। किन्तु, अब वैसा नहीं हो सकता। दुनियामे माँका नाम कोई नहीं पूछता। केवल कयामतक दिन ही हमारा माँके नामसे परिचय दिया जायेगा। अब सरकार हमसे माँका नाम पूछनेवाली है। भारतीय समाज इस तरहकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री गांधीने यह समझाया कि कानूनका क्या असर होगा, और कहा कि हर भारतीयको — फिर वह गरीब हो या अमीर — स्वतन्त्र होना चाहिए। [साम्राज्य] सरकारने इस कानूनको

१ मूल गुजराती रिपोर्ट "इंडियन ओपिनियन"के रूपमें इन शीर्षकोंसे छपी थी, "प्रिटोरियाके भारतीयोंकी विराट आम सभा खूनी कानूनका जोरदार विरोध सब जेल्के लिए तैयार।"

मजूर कर लिया है, उससे कुछ नहीं हाता। अभी तो भारतीय समाज द्वारा उसकी मजूरी बाकी है।

जबतक भारतीय समाज इसे स्वीकार नहीं करता तबतक माना ही नहीं जा सकता कि यह कानून पास हो गया है। यदि कोई बड़े या छोटे भारतीय इस कानूनकी गुलामी स्वीकार कर ले तो भी दूसरोको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो स्वतंत्र रहेंगे वे जीतेगे।

मालवी साहब अहमद मुरत्यारने बड़े जोशसे भाषण देते हुए समझाया कि मुसलमान और हिंदू सबको हिल मिलकर चलना है। सच्चा मुसलमान तो वह है जो दीन और दुनिया दोनोंके काम सँभालता है। हजरत यूसुफ अबेसलामपर जब बला आई थी तब उन्होंने खुदासे प्रार्थना की थी कि हे खुदा, मुझे इस बलाकी अपक्षा जेल देना। किसी भी भारतीयको जुल्मी कानूनके सामने झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समितिको गाव गाव घूमकर लोगोको इस बातका भान कराना चाहिए। यदि ऐसी कोई समिति बनी तो मैं भी उसके साथ जानेको तैयार हूँ।

श्री नायडूने तमिल भाषामे समझाकर कहा कि मेरी जान चली जाये तब भी नये कानूनके सामने नहीं झुकूंगा।

श्री उमरजी सालेने भी भाषण करते हुए कहा कि सभी भारतीयोको हिलमिलकर चलना चाहिए ओर अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार करना चाहिए।

श्री एम० एस० कुवाडियाने पहले वक्ताआका समर्थन किया। श्री कामाने कहा कि यह कानून इतना खराब है कि इसके सामने एक भी भारतीय झुक नहीं सकता। मेरा सब कुछ चला जाये तब भी मैं इस कानूनको स्वीकार नहीं करूँगा।

इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि कोई भी भारतीय इस कानूनको स्वीकार कर, मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। यह कानून आजीवन कारावाससे भी बुरी सजा देता है। मौलवी साहबने स्वयं प्रस्तावका समर्थन किया और गाव गाव जानेके लिए अपनी उद्यतता दिखाई।

श्री मकनजीने कहा, मुझे आशा थी कि कानूनमे जरा सी भी गुंजाइश होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अब तो मैंने निश्चयकर लिया है कि कोई भी उसे स्वीकार करे, मैं नहीं करूँगा।

श्री हाजी इब्राहीमने भाषण देते हुए अन्तमे कहा कि यह कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री नूर मुहम्मद अय्यूबने कहा कि भारतीयोके लिए अपना जोश दिखानेका यह स्वर्ण अवसर है।

श्री इस्माइल जुम्मा, श्री मनजी नथू, श्री त्र्यम्बकलाल और श्री हाजी उस्मान हाजी अबाने भी ऐसे ही भाषण दिये।

श्री काछलियाने कहा कि नियानवे प्रतिशत सूरतियोके बारेमे तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वे जेल जायेगे।

श्री उमरजीने उनका समर्थन किया।

श्री गौरीशंकर व्यासने कहा कि ईमानदागोके लिए तो मितम्बर माहकी शपथ काफी बन्धनकारी है।

श्री नीमजी जानदजीने कहा कि कानून हर्गिज स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पिल्लेने भी जोशीला भाषण दिया।

श्री गुगुब रूद्र देसाइ, श्री खुगाल छीता, श्री गुलाम मुहम्मद ओर श्री मूसा मुतेमानने कहा कि यदि कोई आदमी अनुमतिपत्र कार्यालयम नायेगा तो वे उसे समझाकर राकगे।

श्री हाजी कामिमने कहा कि कानून भारतीय समाजका स्वीकार हो ही नहीं सक्ता।

मोहवी साहब अहमद मुख्तयारने कहा कि हम गुरुआका काम केवल नमाज पढाना ही नहीं, लोगोंके दुखमे पूरी तरह हाथ बटाना भी है। गाँरे ठाग हमारे हमका अपमान करना चाहत है, इसलिए वे रेल किरायेमे भेट करत है। रेलवेवालाने कहा है कि ईसाई और यहदी पादरी आवे किरायेपर रेलमे याना कर सकते है, किन्तु हिंदू और मुसलमान हम-गुरु नहीं कर सकते। भारतीय समाज इस प्रकारकी गुलामी अभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री ईसा मियाने अंतिम भाषण देते हुए श्री गुगुब रूद्र देसाईका उनकी हिम्मतके लिए अपनी शाल दी ओर कहा कि मैं अपना निजी काम छोडकर लाकमबाके लिए तैयार हूँ। इस समय प्रिटोरिया भारतीयपर जिम्मेदारी आई है। मुझे विश्वास है कि वे उस अच्छी तरह निभायेगे। श्री हाजी हाजीके आतिथ्यके ठीक साग भारतीय समाज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।

इस प्रकार बहुत रत्नाहके साथ काम पूरा हुआ और मान वज सभा समाप्त हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५७ भेट 'रैड डेली मेल' के प्रतिनिधिको

ट्रान्सवालके सरकारी 'गजट'मे प्रकाशित हुआ है कि १ जुलाईम एशियाई कानून लागू होगा। इस नय कानूनम सम्बन्धित वे धाराएँ भी प्रकाशित हुई हैं जिनके अनुसार सभी अँगुलियाकी अलग अलग और दकटठी छाप ली जायेगी। धाराओके प्रति भारतीयारा रूप जाननेके लिए 'रैड डेली मेल' के एक प्रतिनिधिने श्री गांधीमे भेट को श्री और तारीख २९के 'रैड डेली मेल'म निम्नलिखित विवरण प्रकाशित रखा है :

एशियाइयाक लिए बनाया गया जा नया कानून प्रकाशित हुआ है उसे मैं या मेरे साथी क्यापि स्वीकार नहीं करगे। किन्तु कानूनमे जा अंतिम सजा बढी गई है उसे भोगे। इस कानूनका कोई भी स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। मुझे और 'इंडियन ओपिनियन'म सम्पादकको जा पत्र प्राप्त हुए हैं उनम मालूम हाता है कि ट्रान्सवालकी भारतीय आवादीम म लगभग ५० प्रतिशत व्यक्ति कानूनका विरोध करेंगे। मैंने अभीतक एक भी ऐसा भारतीय नहीं देखा जो कानूनका ठीक समझता हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस दशका छाडकर चले जायेगे। किन्तु ऐसा किसीने नहीं कहा कि हम नया पजीयनपत्र लेगे। भारतीयामे बहुत ही रोष फैला हुआ है और

१ इसके बाद जो विवरण दिया गया है वह "भेट 'रैड डेली मेल'को", पृष्ठ ६० ६१ का सारांश है।

कमसे कम ६,००० व्यक्ति नया पजीयनपत्र लेनेसे इनकार करेगे। यदि सरकार उनपर मुकदमा चलायेगी तो वे लोग जेल जायेंगे, भले उससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े। लेकिन वे स्वाभिमानके लिए अपना सबस्व योछावर करनेको तत्पर हैं। हमें लगता है कि जब हमारे सम्बन्धमें कानून बनानेमें हमें बोलनेका अधिकार नहीं है, तब हमारे लिए एक ही उपाय शेष रह जाता है कि किसी भी कानूनके सामने घुटने न टेके जायें।

कहा गया है कि कानून नरम है। किंतु मुझे कहना चाहिए कि मने बहुतेरे उपनिवेशोंके कानून पठे हैं, लेकिन एक भी उपनिवेशमें इस कानूनके समान अपमान जनक ओर कलंकित करनेवाला कानून नहीं देखा। एम्पायर नाटकघरवाली सभामें दो हजारके लगभग लोग उपस्थित थे और उन सबने सबसम्मतिसे शपथ ली थी कि वे कभी भी अनिवाय पजीयन नहीं करवायेंगे। मुझे आशा है कि लोग उस शपथका अवश्य पालन करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

बहुत समयसे भारतीय जिनका रास्ता देख रहे थे वे नियम प्रकाशित हो गये हैं। “जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बड, वैसी जड”, इस कहावतके अनुसार जैसा कानून है वैसे ही उसके नियम हैं। जो लोग नियमोंमें कुछ नरमीकी आशा रखते थे, उनकी वह आशा भग्न हो गई है। मैं स्वयं इसलिए बहुत खुश हूँ कि नियम अनपेक्षित रूपमें सरत हैं। इससे प्रत्येक भारतीय दृढ़ हो गया है और अब तो सब कहने लगे हैं कि जेलके बिना चारा नहीं है।

घासमें सॉप

अंग्रेजीमें कहावत है कि हरी घासमें प्रायः हरे साप होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। वे काटते हैं तभी उनकी उपस्थितिका ज्ञान होता है। यह कानून भी वैसा ही है। इसमें कुछ साप छिपे हुए थे, जिनका पता मुझे अभी लगा है। इन नियमोंको मैंने पहले भी पढ़ा था। उस वक्त मुझे इसके कुछ प्रभावोंका ज्ञान नहीं हो सका था। मैं समझता था कि जबतक नया अनुमति पत्र — गुलामीका पट्टा — नहीं लिया जाता तबतक किसीसे पूछताछ करना सम्भव नहीं है। अब विचार करनेपर देखता हूँ कि इसमें पुलिसको जो सत्ता दी गई है उसके अनुसार वह चाहे जिस भारतीयसे अँगुलियोंकी निशानी माग सकती है और उसकी वशावली पूछ सकती है, और वह भी जितनी बार चाहे उतनी बार। इस सापसे डरकर चलना है। और यदि सरकारने उस चाबीको ऐंठा तो उससे भारतीय समाज शायद परेशान हो जायेगा। रास्ता सीधा है। किसी भारतीयको किसी भी तरह अँगुलियोंकी निशानी देनी ही नहीं है। इतने दिन अँगूठा लगाते रहे। किंतु अँगूठा लगाना भी अनिवाय हो गया है, इसलिए उसे लगानेसे भी इनकार कर देना चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा? उत्तर है

जेल। जेलका विचार प्रत्येक भारतीयक लिए सामान्य बन जाना चाहिए। पुलिस यदि प्रश्न पूछती है अथवा निगानी मांगती है और उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो नये कानूनके अनुसार उसकी सजा जेल अथवा जुर्माना है। जुमाना तो देना ही नहीं है। इसलिए जेल ही बची। मरी मलाह यह भी है कि फाक्सस्टसे आनेवाले किसी भी भारतीयका अब पुलिसको जगूठ या जगुलियोकी निशानी नहीं देनी चाहिए। परिणामस्वरूप यदि उस मजिस्ट्रेट पाम ल जाये, तो वहां [अपना अधिकार] सिद्ध कर देना चाहिए, और उतनेपर भी मजिस्ट्रेट उस जेल में तो वह भागी जाय। किन्तु यह लडाइ केवल सच्चे लागाक लिए है। जिनके पाम अपन अगूठकी निशानीवाल अनुमतिपत्र है, उहीपर यह बात लागू होती है। इसमें हिम्मत बनी चाहिए। किन्तु उस रखना है और रखेगा।

दूसरा साप

यह तो एक साप हुआ। दूसरा साप परवासे सम्बन्धित है। मैं मानता था कि परवानक सम्बन्धमें अँगुलियाके निशान लगवानेका काम जनवरीमें शुरू होगा। किन्तु अब देखना है कि वह आजसे ही शुरू है। अतः यदि कोई परवाना लेने जायेगा तो उससे अँगुलियाकी निशानी माँगी जा सकती है। किन्तु यह बात राजस्व-अधिकारियोंका भी मालूम नहीं हुई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि सब भारतीयोंने अपना अपना परवाना ले लिया होगा। लेकिन इस प्रकार हम वक्तक चल सकेंगे? सरकारन जगह जगह अँगुलियाकी बान लागू की है। अतः अब बहुत ही सतर्क होकर चलना है। मैं यह मानता था कि हर बड़ी दूकान पीछे एक व्यक्ति कानूनके निगाहके लिए अनुमतिपत्र लेकर बैठ सकता है। लेकिन गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर देखना है कि एक व्यक्ति व्यापार कर सकता, ऐसी आशा करना दुराशा मात्र है। इसलिए मुझे यह देना चाहिए, आवश्यक ही तो व्यापारियोंके लिए व्यापारका लालच छान देना ठीक होगा। दशक लिए, अपने आत्मसम्मानके लिए, व्यापारको छोड़ देनेके लिए तत्पर रहनेमें एन वक्तपर घबराहट नहीं होगी। इसका अलावा व्यापारके लिए भी अँगुलियोकी निगानी दफ्तर कैदी बनना ठीक नहीं मालूम होता। सुन्दर और एकमात्र रास्ता यही है कि गदापर पूरा भरोसा रखकर दश-द्वितीमें सब-कुछ कुर्बान कर दिया जाये। विजयके लिए हममें इतना निमल साहस होना चाहिए।

प्रिटोरियाके लिए अवसर

गुलामीका पट्टा देना पहले प्रिटोरियामें शुरू हुआ है। उमर्गाह प्रिटोरियापर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। साथ ही बहादुरी दिखानेका अवसर भी उसके हाथ आया है। सारे भारतीय यही चाहते और खुशामें यही प्रायना करने हैं कि प्रिटोरिया वही करे जो उस शोभा दे।

‘डेली मेल’ की टीका

पिछले शुक्रवारको [रैंड] ‘डेली मेल’के एक सवाददाताने श्री गांधीसे मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त की।^१ श्री गांधीने बताया कि कमसे-कम ६,००० भारतीय तो निश्चय जेल जायेंगे। भारतीय समाजने खुदाकी शपथ ली है। उससे वह विमुख नहीं हो सकता। कानूनका विरोध करनेमें बेवफाई नहीं होगी। कानूनका विरोध करके भारतीय समाज केवल अपनी टेक व

आत्मप्रतिष्ठा रखना चाहता है। इस तरह विरोध करनेसे छुटकारा कैसे होगा, यह कहा नहीं जा सकता, किंतु बहादुर उपनिवेशियोंको भारतीयोंकी बहादुरीका पता चल जायेगा। यदि वैसा न हो तब भी भारतीय समाज जेल जायेगा और आखिर ट्रांसवाल छोड़कर चला जायेगा, किंतु गुलामीकी हालतमें यहा नहीं रहेगा।

इसपर टीका करते हुए 'डेली मेल' सहानुभूति व्यक्त करता है और कहता है कि भारतीय समाजको कानून स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सरकारका उद्देश्य अपमान करना नहीं है। अँगुलिया लगवानेमें सरकारका उद्देश्य दूसरे भारतीयोंको आनेसे रोकना है। इसीके साथ 'डेली मेल' का सवाददाता लिखता है कि सरकारने जान बूझकर पहले प्रिटोरियाको लिया है, क्योंकि वह सबसे निबल है, इसलिए वहाके भारतीय तो निश्चय ही नया पजीयनपत्र ले लेंगे, और तब दूसरे तो अपने आप लेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रिटोरिया इस चुनौतीको झेल लेगा और बहादुरी दिखायेगा।

श्री गांधीका उत्तर

'डेली मेल'के उपर्युक्त पत्रका श्री गांधीने नीचे लिखा उत्तर दिया है ^१

'स्टार' की टीका

'स्टार' पत्रने बहुत टीका की है और उसे डर भी लग रहा है, इसलिए वह लिखता है कि भारतीय समाजको दस अँगुलियोंकी निशानी देनेके सिवा और कोई कष्ट नहीं है। फ्रीड्डापसे बिना हर्जाना दिये उन्हें कोई नहीं निकालेगा। ट्राममें उन्हें छूट है ही, और अँगुलियोंकी निशानी तो भारतीय सिपाही भारतमें भी देते हैं।

स्पष्ट ही यह सब सरासर झूठ है। फ्रीड्डापमें हर्जाना मिले तबकी बात तब, ट्राममें भारतीयोंको अभी तो धक्के दिये जाते हैं, और भारतीय स्वेच्छापूर्वक अँगुलियोंकी निशानी दे और अपढ सिपाही व्यापारीसे जबरदस्ती अँगुलिया लगवाये, इन दोनोंमें अंतर नहीं है, यह बात तो 'स्टार' ही कह सकता है। किंतु 'मेल' और 'स्टार' दोनोंकी टीकाओंसे मालूम होता है कि भारतीय कौमकी लड़ाईकी तैयारीसे डर पैदा हो गया है। तब, भारतीय समाज यदि सच्ची बहादुरी बताता है तो क्या नहीं कर सकता ?

नेटाल कांग्रेसकी सहानुभूति

नेटाल कांग्रेसकी ओरसे भारतीय समाजके नाम एक तार आया है, जिसमें जेलके निणयपर डटे रहकर अपनी टेक बनाये रखने और आर्थिक सहायता देनेके बारेमें कहा गया है। यह सहानुभूति बहुत कामकी है। लेकिन समय ऐसा है कि जो आर्थिक सहायता देनी हो वह अभी पहुँच जानी चाहिए। भारतीय समाज यदि सचमुच पुरुषाथ दिखाता है तो निस्सन्देह पैसैकी बहुत जरूरत होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

१ इसके बाद गांधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मूलके लिए देखिए "पत्र 'रेड डेली मेल' की पृष्ठ ६७ ६८।

५९ पत्र 'रैंड डेली मेल' को

जाहानिसबाग,
जुलाई ६, १९०७

सेवामे

सम्पादक

['रैंड डेली मेल']

महादय,

मैं विश्वास करता हूँ, एशियाई प्रश्नकी पुनर् चर्चा करनेके लिए मझे क्षमा याचनाकी आवश्यकता नहीं है।

मैंने आपके भेदकतामें यह नहीं कहा था कि "अनाक्रमक प्रतिरोध" मेरे देशवासियोंके लिए एक नया मार्ग है। मैंने यह कहा था कि हम पीढ़ियोंमें, याम तौरमें बने पैमानेपर, इसका अभ्यास नहीं रहा है, इसलिए मैं इसके परिणामक सम्बन्धमें पहलमें कुछ नहीं कह सकता। मुझे, व्यक्तिगत रूपमें, यह तयकर गव होता है कि सामाजिक हितके लिए कष्ट सहनकी क्षमता केवल सुप्त पत्नी श्री और परिस्थितियोंके दबावमें वह पुनः शीघ्रतामें क्रियाशील होती जा रही है। धरना भारतीय मानसके लिए कतई नई वस्तु नहीं है। भारतमें विभिन्न जातियोंका जो जाल फैला हुआ है वह हम अस्त्रका उपयोग और मूल्य प्रदर्शित करनेवाला है, बशर्ते कि उसका उचित उपयोग किया जाये। आज भी सामाजिक बहिष्कार और जातीय बहिष्कार दो बहुत शक्तिशाली अस्त्रोंका प्रयोग भारतमें किया जाता है, किन्तु दुर्भाग्यवश छोटे मोटे मामलोंमें ही। और यदि अब पंजीयन अधिनियमके कारण मेरे देशवासी इस भयंकर अस्त्रका प्रयोग एक ऊँच उद्देश्यके लिए करना जान सकेंगे तो लॉर्ड एलगिन और ट्रान्सवालकी सरकार दाना ही मेरे देशवासियोंकी क्रतुजताने पात्र होगे।

इसलिए भारतीय धरनेदार अमाश्रण (उनके लिए अमाश्रण) आश्रय और सहमति दिनाकर अपन अज्ञानी और निर्बल दश बन्धुओंको कृतव्यपन दिवानेका प्रयत्न कर रहे हैं ता, मचमुच, इसमें कोई अनायास नहीं है। इसके साथ ही आज पश्चिमी और पूर्वी, या या कहिए कि भारतीय धरनेदारोंमें, उतना ही अंतर है जितना प्रकट पूर्व और पश्चिममें है। आतंक फैलानेकी हमारी कार्य दृष्टि नहीं है। हम प्रहमती डकड़ जबरदस्ती मनवाना नहीं चाहते, किन्तु मक्ति-गनाकी अदम्य बालाओंकी भांति, अपन नम्रतापूर्ण ढंगमें, समझाने

१ यह "भारतीयोंका धरना" शायकने प्रकाशित हुआ था और १३-७-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

२ देखिए "मेंट 'रैंड डेली मेल' को", पृष्ठ ६० ६१।

३ सन् १८६५ में विलियम ब्यू द्वारा लन्दनमें स्थापित एक धार्मिक संगठन, जिसे "साल्वेशन आर्मी" कहा जाता था। बादमें संगठनने धर्म-सैनिक रूप ले लिया था। मूलतः यह ईसाई धर्मके सिद्धान्तोंसे सहमत था, लेकिन इसके उपदेश-आदेश व्यावहारिक और सीधे-सादे होते थे। उनमें दूसरोंकी मुक्तिके लिए कष्ट-सहन तथा आत्मबलिदानपर जोर दिया जाता था।

बुझानेकी अपनी समस्त सम्भव शक्तिको काममें लाकर, हम उन लोगोको, जो जानते नहीं, एशियाई पजीयन अधिनियमके उस रूपसे परिचित कराना जरूर चाहते हैं, जिसे ठीक माना जाता है। इसके बाद यह बात उही लोगोपर छोड़ दी जाती है कि वे हमारी सलाहको मानें या इस अपमानजनक कानूनको स्वीकार कर इस देशमें दीन हीन जीवन व्यतीत करनेके लिए अपने आपको बेच दें। जैसा मैंने पहले कहा है, यदि उपनिवेशियोको मालूम हो जाये कि इस कानूनका अर्थ क्या है तो वे स्वयं इस कानूनको माननेवाले भारतीयोको ठोकर मारने और घणा करने योग्य कुत्ते कहकर पुकारेंगे।

भारतमें अँगुलियोके निशानोके प्रयोगके सम्बन्धमें आपने श्री हेनरीके कथनको — मेरा खयाल है, भारतीयोके हितको ही दृष्टिगत करके — उद्धृत किया है। किंतु हमने उनके सत्प्रयोगसे कभी इनकार नहीं किया। मेरा और मेरे देशवासियोका विरोध तो इस प्रथाके दुरुपयोगके प्रति है।

आप आशा करते हैं कि मेरे देशवासियोमें समझ आ जायेगी और वे इस कानूनको मान लेंगे। इसके विपरीत मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरे देशवासी उपयुक्त साहस करेंगे और अपना सम्मान और स्वाभिमान खोनेके बजाय अपने सवस्वका त्याग करनेके लिए तैयार हो जायेंगे तो आप अपने विचार बदलेंगे और उन्हें अपनी बातके पक्के मानकर उनका आदर करेंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि भारतीयोंने ईश्वरको साक्षी बनाकर शपथ ली है कि वे इस कानूनको न मानेंगे। 'यायालयमें ली गई झूठी शपथका प्रायश्चित्त न्यायाधीशके दिये हुए दण्डको भागनेसे हो सकता है। किंतु जो परम यायाधीश कभी भूल नहीं करता उसके सामने झूठी शपथ लेनेका क्या प्रायश्चित्त हो सकता है? यदि हम उसके सामने ली हुई शपथ झूठी कर देंगे तो सचमुच हम किसी भी सभ्य समाजमें रहनेके अयोग्य होंगे, और पुराने जमानेकी चाण्डाल बस्तिया ही हमारे लिए उचित और उपयुक्त स्थान होंगी।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

रड डेली मेल, ९-७-१९०७

६० पत्र 'स्टार' को

पो० ऑ० वाक्स ५७

प्रिटोरिया

जुलाई ७, १९०३

सेवामे

सम्पादक

'स्टार'

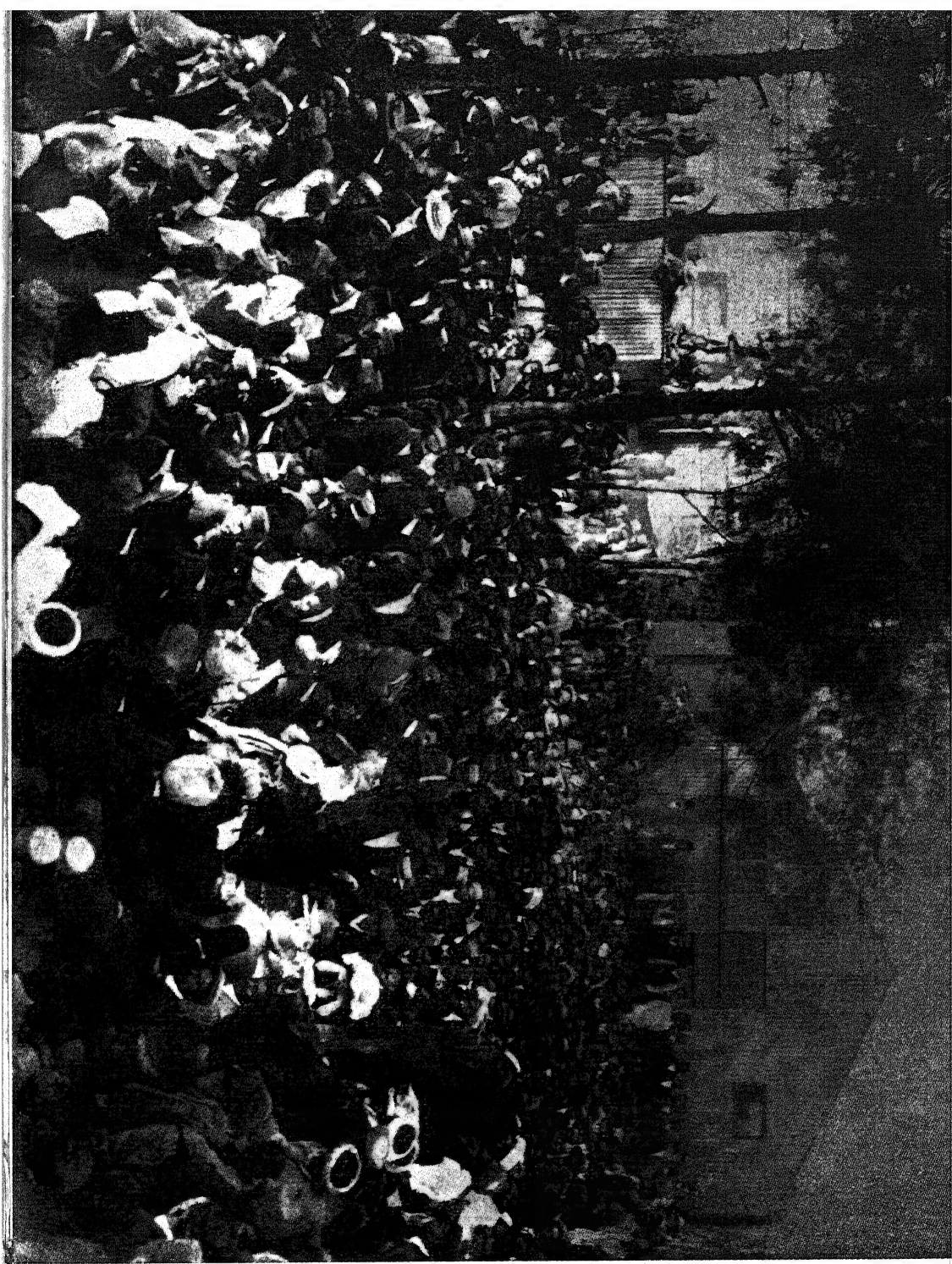
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपके प्रिटोरियाके सवाददाताने भारतीय समाजको यह कहकर उचित श्रेय दिया है कि ब्रिटिश भारतीयोंने इस उपनिवेशमें एशियाई पजीयन अधिनियमका स्वीकार न करनेका जो सघष आरम्भ किया है उससे "किसी गम्भीर उत्पातकी आशका नहीं है"। महान्यायवादीने भी यह कहकर हमारी बड़ाई ही की है कि उन्हें कानूनके पालन भारतीयोंसे कानूनके विरोधकी आशा नहीं थी। अतएव केवल यह है कि जहाँ कानूनके पालनकी सहज बुद्धि दगो और स्थूल प्रतिग्राहका असम्भव कर देती है, वहाँ उसका अर्थ यह नहीं होता कि कानूनको कितना ही अलचिक्कर हाथोंपर भी स्वीकार कर लिया जाये। वह सहज बुद्धि हमें बताती है कि अगर हम कानून द्वारा लादा गया जआ सहन न कर सकें तो हमें कानून भंग करनेके परिणामोंको शान्तिपूर्ण गौरव और सम्पणके भावमें सहन करना चाहिए।

आपके सवाददाताने धमकी दी है कि यदि मेरे देशवासियोंने अपना रवैया न बदला तो दण्ड विधानकी धाराएँ कड़ाईसे लागू की जायेगी और उन्हें निष्कासित कर दिया जायेगा। यह धमकी अनावश्यक थी, क्योंकि हमने इस कानून भंगके परिणामोंको सोच समझ लिया है। पजीयन अधिनियम द्वारा, जिसमें समूचे समाजपर अपराधी होनेकी ठाप रग जाती है, बलान लादी गई दासताकी तुलनामें जेठ हमें तनिक भी भयभीत नहीं करती। जिस हमें अपना घर समझना मिलाया गया वही कुत्तेकी जिन्दगी बगर करनेके मुकाबले ताँ देश निराला एक मनपसंद राहण हागी। यदि इस कानूनका हमपर उतना ही भयकर असर पड़ता है जितना हम बताते हैं ता हम जितना अधिक प्रलिदान करेंगे, उतना ही कम होगा।

हमें साम्राज्य भावना और साम्राज्यके सब समाजी सम्पत्तिका अनाम्ना अनुभव हो रहा है। यह माना जाता है कि साम्राज्यका हाथ मलबानाम निबलकी रक्षा करेगा। अब ट्रान्सवालके भारतीयोंका यह देखना है कि वह हाथ निबल भारतीयोंकी सबूत गोरोम — अंग्रेजों और दूसरोंसे — रक्षा करता है या नहीं, अथवा उसका उपयोग दुबारा और असहायोंको कुचलनेमें अत्याचारीके हाथोंको मजबूत करनेके लिए किया जायेगा। इस शब्दका प्रयोग करनेके लिए क्षमा करें, किन्तु क्या हमारी प्रत्येक भावनाकी आर हमारे धर्मोंकी अवहेलना करना अत्याचार नहीं है, क्योंकि यह प्रवासको नियन्त्रित करनेका प्रश्न नहीं है? पुनः पजीयनके सिद्धान्तको हमने मान लिया है, उसकी विधिपर हम तीव्र रोष प्रकट करते हैं। किन्तु



प्रिटोरियामें आम सभा

exceedingly well there.

I have written to Mr. West about jobs. The Customs Forms, as I have said to Mr. West, are to be sent to the address in your possession of Ibrahim Mahomed. He is one of the subscribers.

42.4674
Lm 383

I am certain that it is a short-sighted policy not to print Hindi. We are really not even using our capital. "Ramayana" is bound to sell, and, in my opinion, it will be a work of very considerable merit, for the simple reason that thousands of people who cannot possibly study the whole work will gladly avail themselves of the condensation. If, therefore, a good man is available, you should certainly not hesitate to incur the expense. The reasoning which tells you that, according to the expenses here, the book will be dear is faulty to a degree. It should be plain to us that, if the expenses are high, the prices charged are correspondingly high. The term "high", therefore, is merely relative. The Bhagavat-Gita, which we would issue in India for one Anna, we charge one shilling for, because the expenses were comparatively high. I am perfectly certain that, whenever we think of having things done cheaply outside the country of our adoption, we bring into play the ordinary weakness, namely, to drive the hardest bargain possible, and it is for that reason that I have condemned in my mind the idea of having the South African book printed in Bombay, and I feel this so keenly, that I have not yet summoned up sufficient zeal for writing out the book. I would ask you to reason this thing out for yourself. Never mind whether we employ an extra hand or not and whether we publish the book or not; that is a matter of detail. The first thing is to lay down the principle. If we cannot enforce it, or if we have not sufficient courage to do it, then we cease to worry about it, and cease to think of enlarging the scope of our work. If you need money, please let me know in time.

Yours sincerely,

सरकार जान बझकर हमे अपमानित करना चाहती है। यदि भारतीय इस कानूनको सहन करनेके बजाय अपनी भौतिक सम्पत्तिको खोनेके लिए तैयार ह तो क्या उनको दोष दिया जायेगा ? समचा गोरा ट्रान्सवाल हमारे विरुद्ध हे तो ईश्वर हमारे साथ है।

आपका आदि,

हाजी हबीब

मन्त्री,

ब्रिटिश भारतीय समिति, प्रिटोरिया

[अंग्रेजीमें]

स्टार, ९-७-१९०७

६१ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सोमवार [जुलाई ८, १९०७]

धन्य प्रिटोरिया !

प्रिटोरियाने तो हृद कर दी। वहापर जिन लोगोसे शायद ही किसीको कोई हिम्मतकी आशा थी, उन लोगोने भयानक दुख उठाकर तथा अपना सब कुछ छोडकर लोकसेवा शुरू की है और सभी, किस प्रकार लाज रहे, इसके सिवा कुछ नहीं माचते।

स्वयसेवकोपर न्योछावर जाऊँ !

स्वयसेवको उफ धरनेदारो उऊ चौकीदारो उऊ देशसेवकाने तो अपना नूर चमका दिया है। ट्रान्सवालके भारतीयोके इतिहासमे उनका नाम अमर रहेगा। वे अपना सारा समय केवल धरना देनेमे बिताते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं

सवश्री ए० एम० काछलिया, गौरीशकर प्राणशकर व्यास, गुलाम मुहम्मद, अब्दुल रशीद, कासिम सिद्धू, खुशाल छीता, मेमन इब्राहीम नूर, गोविन्द प्राग, हुसन बीबा, मुहम्मद वली, अर्देगर फरामजी, चाउल बेग, गुलाब रुद्र देसाई, मूसा सुलेमान और इब्राहीम नूर।

इतने देशभक्त बारी बारीसे सारे दिन अनुमतिपत्र कार्यालयके आसपास फिरते रहते हैं और जो काई भारतीय कार्यालयके अन्दर जाता हे उसे विनयपूर्वक समझाकर रोकते हैं। वे इस समय अपना कामधंधा छोडकर केवल देश-सेवापर तुले हुए ह। चाहे जैसी आफत आये, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। वे अपने कामके चाहे जसे परिणाम झेलनेको तयार हैं। जहा इतनी देशभक्ति हो वहा यदि अन्तमे जीत हो तो उसमे आश्चर्य कौन-ना ?

इस बहादुरीका सबक

स्वयसेवकाके इस कायका अनुकरण ट्रान्सवालके प्रत्येक गावको करना चाहिए। आज प्रिटोरियामे जो कुछ हो रहा है वह ट्रान्सवालके प्रत्येक गावमे हो सकता है। कुछ समयमे पजीयनधनकी अर्जी देनेके लिए प्रत्येक गावमे अधिकारियोकी नियुक्ति हो जायेगी। उस समय प्रिटोरियामे सबक लेकर हर गावके भारतीयोको स्वयसेवक खोजने होंगे। मेरी रायमे तो वे बाढ आनेके पहले ही बाध बाध ले और स्वयसेवक तैयार कर ले। जिनके लिए सम्भव हो

वे प्रिटोरिया जाकर यह देख आय कि तिननी तेजीसे काम किया जा रहा है। अनुमतिपत्र-कार्यालयका बहिष्कार यदि ठीक तरहसे किया जा सके तो बादकी लड़ाई बहुत आसान हो सकती है।

व्यापारियोंको सलाह

मैं सुना है कि कुछ व्यापारियों, जो विलायत संग्रह जगहाम मात्र मगवाने हैं, नये कानूनके कारण माल मँगवाना बंद कर दिया है। वे लोग अन्यवादके पात्र हैं। जान पड़ता है, उन्होंने जेलका कष्ट झेलनेकी पूरी तैयारी कर ली है। मज्र लगता है कि इस प्रकार यदि हर व्यापारी अपने लेनदारको लिख भेजे या तार भेज दे तो बहुत लाभ हो सकता है। एक तो यह हागा कि स्वयं व्यापारीमें बहुत हिम्मत आ जायेगी और, दूसरे, यूरोपके व्यापारी डरकर स्वयं भी हमारे लिए काम करने लग जायेंगे। यह सब काम वही व्यापारी कर सकेंगे जिनपर देशप्रेमका रंग चढ़ा हो, जिन्होंने कानूनमें होनेवाले नुकसानकी पूरी कल्पना हाँ गर्ई हो तथा जिन्हें खुदापर पूरा भरोसा हो।

प्रवासी विधेयक

इस विधेयकके सम्बन्धमें श्री गांधीने 'स्टार' में यह पत्र^१ लिखा है

फेरीवालोंके लिए कानून

फेरीवालोंके जिन नियमोंके सम्बन्धमें मैं पहले लिख चुका हूँ, वे पास हो चुके हैं। अब जुर्रताना किया जानेके पहले जाहानिसवगके फेरीवालोंका चेत जाना चाहिए। पिछले अकोंमें उन नियमोंको देख लिया जाये।

भारतीयकी गिरफ्तारी

पॉपेफ्टूमसे तार द्वारा समाचार मिला है कि वहाके हाजी उमरको, उनपर धोखेबाजी और दूकानमें आग लगानेका इलजाम लगाकर, गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जमानत १,५०० पीड ठहराई गई है।

मगलवार

खूनी कानूनके सम्बन्धमें विशेष समाचार

'रैंड डेली मेल' तथा 'रीडर' में बड़े-बड़े लेख आने लगे हैं। उनमें बताया गया है कि जाहानिसवगक भारतीय दबाव डालते हैं, इसलिए प्रिटोरियामें कोई पजीयन नहीं करवाना। उन अखबारवातने यह भी कहा है कि जलाईके अन्तिम दिनामें सब जाकर छाप लगा आयेंगे हम आया है कि प्रिटोरियाके भारतीय दृढ़ रहकर इस इलजामको झूठा साबित कर देंगे। यदि अन्तिम दिनामें लोग टिड्डीके समान प्रिटोरियाके दफ्तरपर टूट पड़े तो सब किया करायें धर्ममें मिर जायेंगा।

इसपर विचार

भारतीय समाजको इस समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बहुत जगहोंसे मैं यह भी सुनता हूँ कि नेताओंके गिरफ्तार होते ही लोग डरके मारे पजीयन करवा लेंगे।

१ इसके बाद गांधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मूलके लिख देखिए "पत्र 'स्टार' को", पृष्ठ ७० ७१।

यदि ऐसा होना हो तो “लेने गई पूत, खो आई भरतार” वाली कहावत चरिताथ हो जायेगी। यह समय नेता या किसी दूसरेपर निर्भर रहनेका नहीं है। सबको अपनी अपनी हिम्मतपर निर्भर रहना है। इस मामलेमें वकील या किसी औरका काम भी नहीं है। हम सब होलीमें पड़े हुए हैं। वहां हमें एक दूसरेकी ओर नहीं देखना है। मैंने सुना है कि कुछ ही दिनोंमें श्री गा-रीको गिरफ्तार किया जायेगा और सम्भव है, नेताओंमें में भी किसी एकको। यदि ऐसा हो तो लोगोंको घबड़ानेके बजाय खुश होना चाहिए और उनके जेल जानेसे लोगोंको ज्यादा हिम्मत आनी चाहिए। हकीकत यह है कि अब हम भेड़ नहीं, बल्कि स्वतंत्र हैं और किसीपर निर्भर नहीं रहना चाहते। जेल डरकी चीज नहीं है, यह जब मनमें समा जायेगा तभी मामला मुकामपर आयेगा। सबकी ढाल एक खुदा है, और उस ढालको लेकर रणमें जूझना है, यही सबको मनमें रखना चाहिए।

“दूसरे लेगे तो मैं लूंगा”

बहुतेरे गोरे भारतीयोंको सीख देने लगे हैं। वे पूछते हैं आप क्या करेंगे? उत्तरमें बहुत से भारतीय कहते हैं — “हमारे नेता जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे।” कोई कहते हैं — “दूसरे करेंगे वैसा करेंगे।” ये शब्द कायरोंके हैं और इसलिए इनसे नुकसान है। सभी लोगोंको यह उत्तर देना चाहिए कि “मुझे कानून पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने खुदाकी शपथ ली है, इसलिए भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यह कानून मुझे गुलाम बनाता है, इसलिए उसके बजाय मैं जेलको ज्यादा अच्छा मानता हूँ।” जो ऐसा उत्तर नहीं दे सकता वह आखिर पार भी नहीं हो सकता। दूसरेके तबके सहारे पार नहीं हुआ जाता। अपने बलपर पार होना है। मैं धूल खाऊँ तो क्या पाठक भी खायेगे? मैं गड़हेमें गिरूँ तो क्या पाठक भी उसमें गिरेंगे? मैं अपना धम छोड़ू तो क्या पाठक भी छोड़ देंगे? मैं अपनी माका अपमान सहन करूँ, अपने लड़केको चोर बनाऊँ और अपनी तथा अपने लड़केकी अँगुलिया काटकर द तो क्या पाठक भी वैसा करेंगे? सभी यही कहेंगे कि कभी नहीं। वैसा ही जोश रखकर उत्तर देना है कि “दूसरे क्या करते हैं, इसकी परवाह नहीं। हम तो कानूनके सामने घुटने बिल्कुल नहीं टेकेगे।” इतना सीधा और स्पष्ट उत्तर सब नहीं देते, इसीलिए अखबार इस प्रकारकी टीका करते हैं कि हम आज तो उत्साह दिखा रहे हैं किन्तु आखिर घुटने टेक देंगे। इन सब बातोंपर प्रत्येकको विचार करना चाहिए। यह समय डरका नहीं है, न कुछ छिपानेका है। हमें न कुछ छिपाकर रखना है, न छिपकर रहना है। जिस प्रकार सूरज अपना तेज प्रकट करता है, उसी प्रकार हमें अपना हिम्मत-रूपी सूर्य प्रकट करना है।

चीनियोंका जोर

चीनियोंने पिछले रविवारको सभा की थी। उसमें श्री पोलकको बुलाया गया था। श्री पोलक द्वारा सारी बातें समझा दी जानेके बाद उन लोगोंने फिरसे अपने निणयको पुष्ट किया कि कोई भी चीनी नये कानूनके सामने नहीं झुकेगा और यदि झुका तो उसे समाजसे बाहर कर दिया जायेगा।

एशियाई भोजनालय

जोहानिसबगकी नगर परिषद ऐसा कानून बनाना चाहती है कि एशियाई भोजनालयोंके प्रबंधक गोरे ही हो सकते हैं। तब क्या ट्रांसवालमें हिंदू मुसलमानोंके भोजनालयोंमें गोरे

परमेगे और भारतीय देखा करेगे ? यह सब गुलामीका पट्टा केनेवालापर लागू हांगा । मुक्त रहनवालाको कोई हाथ नहीं लगा सकता ।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६२ प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल विधानसभाको

जोहानिसबर्ग

जुलाई ९, १९०७

सेवामे

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण

ट्रान्सवाल विधानसभा

ट्रांसवाल ब्रिटिश भारतीय सभके कायवाहक अध्यक्षका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

१ ब्रिटिश भारतीय सभकी समितिक इच्छानुसार इस सदनके विचाराधीन प्रवासी प्रतिपत्रक विधेयकके सम्बन्धमें आपका प्रार्थी यह निवेदन करता है ।

२ उपर्युक्त सभ यद्यपि इस विधानके सिद्धांतका समर्थन करता है, तथापि उसकी नम्र सम्मतिमें भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार उसके निम्नलिखित कुछ पहलू गम्भीर रूपसे आपत्तिजनक हैं

- (क) यह विधेयक भारतीय भाषाओंको, जिनमें भारी मात्रामे साहित्य है, मायता नहीं देता ।
- (ख) यह उनके दावेको, जो पहले ट्रान्सवालके अधिवासी रह चुके हैं, मान्यता नहीं देता । (बहुत-से भारतीय, जिन्होंने १८९९ से पहले १८८६में सशोधित १८८५के कानून ३ के मातहत ३ पौंड इस देशमें बसनेके लिए अदा किये थे, लेकिन जो इस समय उपनिवेशसे बाहर हैं और जिन्हे शांति रक्षा अध्यादेशके मातहत अनुमतिपत्र नहीं मित्रे हैं, इस विधेयकके द्वारा इस देशमें तबतक पुन प्रवेश नहीं कर सकत जबतक कि उनमें शिक्षा सम्बन्धी वे योग्यताएँ न हों जिनके बारेमें इस विधेयकमें व्यवस्था की गई है) ।
- (ग) खण्ड २ की धारा ४, जैसा कि इस सभको समझाया गया है, उच्च शिक्षा प्राप्त ब्रिटिश भारतीयोंका भी, जबतक वे गशियाई पजीयन अधिनियमकी शर्तोंको पूरा नहीं करते, ट्रान्सवालमें प्रवेश करना प्राय असम्भव कर देती है । (सभकी नम्र रायमें विधेयक द्वारा जो शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाएँ लाजिमी करार दी गई हैं उनके पास कर लेनेके बाद किसी व्यक्तिका, उपनिवेशमें प्रवेश करनेके लिए, आगे और शिनाख्त देना कोई अर्थ नहीं रखता) ।

(घ) जैसा कि सघको समझाया गया है, धारा ४ ब्रिटिश भारतीयोंको अनैतिकता अव्यादेशके अंतगत आनेवाले लोगोंकी श्रेणीमें रख देती है और इसलिए ब्रिटिश भारतीय समाज इसे बहुत ही अपमानजनक समझता है।^१

(ङ) यह विधेयक, आशाके विपरीत, एशियाई पजीयन अविनियमको बरपा करता है।

३ यह सघ माननीय सदनका यान नम्रतापूर्वक इस बातकी तरफ खींचना चाहता है कि ब्रिटिश भारतीयोंका माननीय सदनमें प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए वे माननीय सदनसे आदरपूर्वक इस बातकी आशा रखते हैं कि वह उनकी बातपर विशेष गौर करेगा।

४ अंतमें, इस सघका विश्वास है कि इसके प्रार्थनापत्रपर उचित विचार किया जायेगा और जो राहत इन हालतामें दी जानी सम्भव हो, वह दी जायेगी। और 'याय तथा दया'के इस कायके लिए आपका प्रार्थी कृतव्य मानकर सदा दुआ करेगा, आदि।

मूसा इस्माइल मियाँ

कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

क्लोनियल आफिस रिकडस, सी० ओ० २९/१२२

६३ ट्रान्सवालका नया प्रवासी विधेयक

[जुलाई ११, १९०७के पूर्व]

यह विधेयक अभी कानून तो नहीं बना, फिर भी इसमें सरकारका इरादा व्यक्त हो जायेगा, इसलिए इसका संक्षिप्त विवरण हम नीचे दे रहे हैं

(१) इसके द्वारा अनुमतिपत्रका कानून [१९०३ का शान्ति रक्षा अध्यादेश] रद्द हो जाता है। किन्तु एशियाई-पजीयन कानूनके द्वारा जो सत्ता दी गई है, उसमें से कुछ भी इस विधेयकके द्वारा रद्द नहीं होती।

(२) नये विधेयकके लागू होनेकी तारीखसे जिन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं है वे लोग निम्नानुसार हैं

(क) जिन्हें किसी भी यूरोपीय भाषाका अच्छा ज्ञान न हो,

(ख) जिनके पास अपने निर्वाहके योग्य पैसा न हो,

(ग) वेश्या और उनके भडवे,

(घ) जो प्रवेशकर्ता उस कानूनकी अवहेलना करे जिसके द्वारा सरकार निवासित कर सकती है,

(ङ) पागल, कोढ़ी या छूतकी बीमारीवाले,

१ ट्रान्सवाल विधान सभाके सदस्य श्री विलियम हॉस्कने जिनकी माफत यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, मूल प्रार्थनापत्रसे यह अनुच्छेद निकाल दिया था।

- (च) जिनके बारेमें विलायत या दूसरी जगहमें सूचना मिली हो कि वे खतरनाक लोग हैं,
 (छ) जिन्हें सरकार राज्यका नुकसान पहुँचानेवाला मानती है,
 (ज) जिन्हें उपयुक्त मयादाओंके अनुसार प्रवेश करनेका हक हो उनकी पत्नी तथा वच्चापर यह विधेयक लागू नहीं होगा। इसी प्रकार काफिरा और यूरोपीय मजदूरोंपर भी।
- (३) इस कानूनका अमल लानेके लिए प्रवासी-कार्यालय खोला जायेगा।
 (४) इस कानूनका [दक्षिण आफ्रिकामें] अमल लानेके लिए गवर्नर दूसरे उपनिवेशोंके साथ इकरार कर सकेगा।
- (५) यदि कोई प्रतिबन्धित व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसपर १०० पाउंड जुमाना किया जायेगा अथवा ६ महीनेकी सजा दी जायेगी और निवासित किया जायेगा।
 (६) जो [१९०३ की] भड़वाड़की रागके अंतर्गत अपराध करेगा अथवा जो राज्यकी शान्ति भंग करनेवाला समझा जायेगा, उसे भी निवासित करनेका सरकारका अधिकार है।
 (७) जो व्यक्ति प्रतिबन्धित व्यक्तिका प्रवेश करनेमें मदद करेगा उस १०० पाउंड दण्ड अथवा ६ महीनेकी जलवा इकम दिया जायेगा।
 (८) प्रतिबन्धित व्यक्तिका परवाना या पट्टपर जमीन देनेका हक न होगा।
 (९) प्रतिबन्धित व्यक्तिके सम्पत्ति जानकारी मिलनपर उस त्रिना वारंट पकटा जा सकेगा।
 (१०) इस कानूनकी अनभिज्ञता वच्चाव नहीं मानी जायेगी।
 (११) जिस व्यक्तिका सीमा पार करना पड़े, उसमें निवालेका खर्च, उसकी उपनिवेशमें जो जायदाद होगी, उसमें से वसूल किया जायेगा।
 (१२) हाटलम जो आग आत है, होटल मास्टरका उन सबका नाम, देश, पता वगैरह दर्ज करना होगा। उस पुस्तिकाका जाँच करनेका सरकारको हक है।
 (१३) यदि किसी व्यक्तिपर प्रतिबन्ध नहीं है तो इसे सिद्ध करनेका दायित्व उस व्यक्तिपर है।
 (१४) हर मजिस्ट्रेटका सारी सजाएँ देनेका हक है।

विधेयकका अर्थ

यह विधेयक बड़ा भयंकर है। इसमें बड़ी सरकार राग रा सकती है। सरकारी तौरसे देखनेपर इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, किन्तु भीतर जहरके समान है। उसके द्वारा अनुमतिपत्र रहित निराश्रितका हक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जिनके पास अनुमतिपत्र है किन्तु नये कानूनके अनुसार जिन्होंने बदलवाये नहीं हैं, यदि वे लागू ट्रांसवालस बाहर जाते हैं तो उन्हें भी वापस आनेका अधिकार नहीं रहता।

पढ़े लिखे भारतीयोंका एक ओरसे अधिकार मिलता है किन्तु दूसरी ओरसे छिन जाता है। क्योंकि शिक्षणके आधारपर प्रवेश करनेवालाको खूनी कानूनके अनुसार आठ दिनके अन्दर अँगुलियाँ आदि लगाकर अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें निर्वासित कर दिया जायेगा।

अतः इस कानूनसे भारतीयोंको जरा भी लाभ होता सम्भव नहीं है।

हस्ताक्षरके लिए इस कानूनको लाड एलगिनके पास भेजना होगा। यदि यह हुआ तो भारतीय समाजको वहा [लंदनमें] टक्कर लेनी चाहिए। यह तो लिखा जा चुका, किन्तु इसके छपनेके पहले, यानी गुरुवार, तारीख ११ को, विधेयकके बारेमें ओर भी बातें मालूम होगी। वे सब दूसरे अकमें दी जा सकेंगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६४ पत्र छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबग

जुलाई ११, १९०७के पूर्व]^१

[चि० छगनलाल,]

तुम्हारा पत्र मिला। काजीके सम्बन्धमें तुमने जा लिखा वह मने ध्यानमें रख लिया है। श्री पोलक^२ प्रिटोरियासे अभी लौटे हैं। वहा उनका काम बहुत ही अच्छा रहा।

मैंने फुटकर ठपाईके बारेमें श्री वेस्टको^३ पत्र लिखा है। जैसा मैं उनसे कह चुका हूँ, इब्राहीम मुहम्मदका जो पता तुम्हारे पास है, चुगीके फाम उसपर भेजने है। वे ग्राहक हैं।

मुझे निश्चय है कि हिंदी न छापना अद्वर्दशितापूर्ण नीति है। हम दरअसल अपने मूल धनका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। 'रामायण' की बिक्री निश्चितरूपसे होगी और मेरी सम्मतिमें यह काय बड़ा मूल्यवान होगा। इसका सीधा सादा कारण यह है कि हजारों लोग, जो पूरी रचनाका अध्ययन नहीं कर सकते, इस सक्षिप्त संस्करणका लाभ प्रसन्नतापूर्वक उठायेंगे। इसलिए यदि कोई अच्छा आदमी मिले तो तुम्हें निश्चय ही खच करनेमें शिझकना न चाहिए। जिस तकसे तुम इस परिणामपर पहुँचते हो कि यहाकी लागतके अनुसार किताब महँगी होगी, वह एक हद तक गलत है। हमारे सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि खच अधिक आता है तो हम मूल्य भी उतना ही अधिक लेते हैं। यहा "अधिक" शब्द सापेक्ष है। जिस 'भगवद्गीता' को हम भारतमें एक आनेमें बेचते उसीका हम यहा एक शिलिंग लेते हैं, क्योंकि लागत अपेक्षाकृत अधिक है। मुझे पूरा निश्चय है कि हम, जिस देशमें रहते हैं,

१ स्पष्ट है गांधीजीने यह अपने ११ जुलाईके पत्रसे पूर्व लिखा था। अगला शीर्षक देखिए, जिसमें गांधीजीने रामायणके प्रकाशनके बारेमें लिखा है।

२ इंडियन ओपिनियनके सम्पादक और गांधीजीके साथी, देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ३५२, दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय १९, २३ ४५ और आत्मकथा भाग ४, अध्याय, १८, २१।

३ अल्बर्ट एच० वेस्ट, इंडियन ओपिनियनके मुद्रक और फीनिक्स आश्रमके निवासी, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५२, दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३, ४७ और आत्मकथा भाग ४ अध्याय १६, १८ आदि।

४ यह श्रीमती बेसेटके अनुवादके संस्करणका उल्लेख है जो १९०५ में प्रकाशित किया गया। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४५९।

जब भी उसमें बाहर कम गन्धम काम कराने का खयाल करते हैं, तब हम अत्यंत कमकर सोचवाजी करने की सामान्य दुबलता का परिचय देते हैं। इसी कारण मैंने अपने मनमें दक्षिण आफ्रिका की विनाश प्रश्न में ठगाने के विचार का पुनः माना है। और मैं उसका इतनी नाशनाश जनभय करता हूँ कि अभी तक विनाश लिखने याग्य उससे संचित नहीं कर पाया हूँ। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम खुद साच विचार कर यह खयाल अपने मनमें निवाल दो। हम अतिरिक्त आदमी नियंत्रित कर या न कर और विनाश ठाप या न ठाप उसकी चिन्ता मत करो, यह तो तफ्सील की बात है। पहली बात सिद्धान्त स्थिर करने की है। यदि हम उसका स्थापित नहीं कर सकते या ऐसा करने के लिए हममें पर्याप्त साहस नहीं है तो हम उसमें सम्मिलित चिन्ता करना ही ठाढ़ दो और अपने कार्य के क्षेत्र का बताने का विचार भी न करो। यदि तुम्हें रुपये की आवश्यकता हो तो मुझे समय पर सूचित करना।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिका फोटो नकल (एस० एन० ४६७४) से।

६५ पत्र छगनलाल गांधीको

जाहानिसबाग

जुलाई ११, १९०७

प्रिय छगनलाल,

मैं प्राणजी गडभाड दमाईरा पत्र साथ भेज रहा हूँ। यदि वह जरा भी वाञ्छनीय जान पड़े तो मरा सुझाव है कि तुम उसे ३ पौडपर परीक्षा की शतपर रख लो और गुजराती कमपर लगा दो, जिसमें कि तुम 'गमायण' का काम जारी रख सको। गुजराती विभागमें हमारे पास निश्चय ही कार्यक्षमता की कमी है। परन्तु मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ। हो सकता है कि वह मर्यादा अव्यावहारिक हो। इसलिए तुम जा सर्वात्तम समझो वहीं करना।

तुम्हारा शुभचिन्तक

मोहनदास^२

श्री कार्डिज कैम ठगन है आदि हकारत लिखना।*

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मरा अंग्रेजी टाईप प्रतिका फोटो नकल (एस० एन० ४७५७) से।

१ विचार था कि इंडियन ओपिनियन दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की सुसिद्धि पर एक पुस्तक प्रकाशित करे। देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४३०।

२ मूल प्रतिमें हस्ताक्षर गुजरातीमें हैं।

३ एक जर्मन थियॉसॉफिस्ट श्री गांधीजीके साथी बन गये थे। वे कुछ समय तक फीनिक्स स्कूलके प्रबन्धक रहे थे। उनका देहांत १९६० में सेवानाममें हुआ था।

४ मूल प्रतिमें यह पंक्ति गांधीजीकी गुजराती लिखावटमें है।

६६ भारतीयोंकी कसौटी

आजतक भारतीय समाजका मूल्यांकन नहीं हुआ। मुट्ठी बधी रही है और किसीने उसका अंदाजा नहीं लगाया। सामान्य विचार यह रहा है कि भारतीय निमाल्य और जीवन-रहित हैं।

किन्तु सौभाग्यसे अब ट्रांसवालमे भारतीयोंकी कसौटी हो रही है। यह अवसर लॉर्ड एलगिन, जनरल बोथा और उनके भाइयोंने दिया है। यह लिखते समय तो भारतीय कसौटीपर चढ़ चुके हैं। हम जो चिट्ठिया प्रकाशित करते हैं उनसे मालूम होता है कि प्रिटोरियाने, जिसे गोरे निबल मानते थे, एकाएक जोर दिखाया है। वहाँ एक भी भारतीयने खूनी चिट्ठी नहीं ली। एक मद्रासी गया था। किन्तु अँगुलियोंकी निशानीकी बात देखते ही उसने भी अर्जी फेंक दी और कहा “अँगुलिया तो मैं हर्गिज नहीं लगाऊँगा।” एक मद्रासी पोस्ट मास्टरने अपनी नाकरी छोड़ना मंजूर किया, किन्तु नया अनुमतिपत्र लेनेसे इनकार कर दिया। जहातक हमने सुना है, श्री चमनेके पजाबी नौकरने नया अनुमतिपत्र लेनेसे साफ इनकार कर दिया है। इस सबसे जाहिर होता है कि परीक्षाके समय भारतीय प्रजा कमजोर साबित होगी, सो बात नहीं।

जाको राखे साइया, मारि सकै नहि कोय। भारतीय समाज आस्तिक है, ईश्वरको माननेवाला है। वह ईश्वरपर भरोसा रखकर हाथमे लिया हुआ काम सहज ही पूरा कर सकेगा। कहा जाता है कि नरसिंह मेहताने^१ अपनी आस्थाकी बदौलत पसा न होते हुए भी ममेरा^२ चढाया था। पैगम्बर मूसाने खुदाकी मददसे महान सकटोका सामना करके दुश्मनोपर विजय प्राप्त की थी। वही जगत-कर्ता भारतीय समाजकी सहायता करेगा।

ट्रांसवालके भारतीयोपर इस समय हर भारतीयकी नजर है, और सब मुंह फाड़े यही प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय अपने उठाये हुए बीडेको बनाये रखेंगे या नहीं। प्रिटोरिया जवाब दे रहा है कि भारतीय समाज अब पीछे पैर रख ही नहीं सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

१ गुजरातके सुप्रसिद्ध सन्त कवि।

२ सतवाँसा पुत्रीके प्रथम गमके सातवें मासमें एक धार्मिक संस्कार होता है जिसे सतवाँसा कहते हैं। उस अवसरपर माता पिता पुत्रीको कुछ भेट देते हैं। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त नरसिंह मेहताकी सहायताके लिए एक यापारीका रूप धरकर आये थे।

६७ डबनका कर्तव्य

प्रिटोरियाके काम और वहांके भारतीय स्वयंसेवकाका जाग दबकर किस भारतीयको हप्स समाज न जाना होगा / गांधीजी देना आसान है। मच्छी शाखाशी ता इसमें है कि उनके समान काम करके लिया जाय। जिस प्रकार ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार किया जा रहा है, उसी प्रकार डबनमें भी किया जाना चाहिए। उस समय डबनमें एक भी भारतीय नहीं था। पवार आता दूसरे मकामी गिरनेसे समान है। ट्रान्सवालमें भारतीयोंका आज से बहिष्कारके लिए तैयार जाना है। जो भारतीय राम तौल ट्रान्सवालमें मदद करनेके लिए नहीं, फिर अपने कामके लिए आता है वह यहां आकर भारतीयोंका बल नहीं बढ़ाता बल्कि उठ उठ हमजोर बनता है। उसके अलावा चरि यह डबनके अनुमतिपत्र कार्यालयमें जानेके बाद ही ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सकता है। इसलिए यही माना जायगा कि बहिष्कारका भग हुआ है। किंतु यदि कोई भी भारतीय अनुमतिपत्र कार्यालयमें नहीं जाये ता डबनका अनुमतिपत्र कार्यालय चर नहीं सकता। इसलिए डबनमें भारतीयोंका प्रिटोरियाका अनुकरण करना चाहिए।

नटाल भारतय काश्मिर ट्रान्सवाल में जाका आर्थिक सहायता देनेके बारेमें लिखा है, मावजिनिक सभा करके जाय भरा है। चर उक्तता करनेकी बात भी हाथमें ली है। यह प्रशंसनीय है। उसके अलावा डबनके अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कारका काम भी हाथमें लेना जरूरी है। प्रतिकार तीन तरफ किया जा सकता है। एक तो डबनके कार्यालयपर धरना दिया जाय जिससे वहां कांड भगनाय न जा सके। दूसरे, ट्रान्सवालकी रेल पहुँचे तब वहाँ पर जातका जाँच का जाय कि वहाँ कौन भारतीय उतर रहा है, और वह नया अनुमतिपत्र लेकर जा रहा है या पुगना, यदि वह जेल जानेको तैयार न हो तो उसे रोकनेके लिए आज्ञा दी जाय। तीसरे इस बातकी व्यवस्था की जाये कि जहाजपर कोई भी भारतीय अग्निकाशी निशानी न दे। इस तरहसे डबनकी बड़ी सहायता होगी और गुप्तकार मिलनेमें शीघ्रता होगा।

[गुजराती]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६८ पूर्व ज्ञानमाला^१

ये पुस्तके अभी अभी अंग्रेजीमें छपी हैं। किसीने इनका गुजराती अनुवाद नहीं किया। किंतु ज्या ज्यो समय बीतेगा, हम इस प्रकारकी पुस्तकोंका सारांश देते जायंगे। इसी हतुसे पैगम्बरका जीवन चरित्र देना आरम्भ किया है।^२ इस बीच अंग्रेजी जाननेवाले उपयुक्त पुस्तके मँगवा सकते हैं।

सम्पादक
इंडियन ओपिनियन

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६९ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें^३

जोहानिसबाग
जुलाई १४, १९०७

श्री गांधीने उस तारीख तकके मामलोंकी स्थितिका सक्षेपमें सारांश दिया और नये कानूनकी अयायपूण धाराओंका अततक विरोध करनेके लिए अपने श्रोताओंको एक बार फिर प्रोत्साहित किया और कहा कि उहे किसी भी अवस्थामे दबावके कारण कदापि पुन पंजीयन नहीं कराना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

१ यह गांधीजीने नारवुडवासी एम० एच० उगतक १९ जून १९०७ के पत्रके उत्तरमें लिखा था। श्री उगतने पूर्वका ज्ञान (पृष्ठ ४२ ४३) का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा था गत १५ तारीखके अकमें पूर्वजु ज्ञान, जलालुद्दीन रुमी, कुरान शरीफनो सार, बुद्ध शिक्षा, जरथुस्त्रना शिक्षण आदि पुस्तकोंके सम्बन्धमें ध्यान दिलाकर उन्हें मँगानेकी जो सिफारिश की है वह शुभ है। परंतु हमारा समाज चूँकि कमोबेश गुजराती जाननेवाला है इसलिए मेरा खयाल है कि उपयुक्त पुस्तके गुजरातीमें हो तो थोड़ी बहुत खपेगी। आशा है आप खुलासा करेंगे।”

२ देखिए “पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा” पृष्ठ ५४ ५५।

३ गांधीजीने भारतीय वस्तीमें आयोजित हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें भाषण दिया था। यह उनके भाषणका सारांश है।

७० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सोमवार [जुलाइ १५, १९०७]

प्रिटोरियाकी टेक

अभा प्रिटोरियाका जास कायम है। उसकी टेक निभ रही है। दूसरा सप्ताह सकुशल बीत रहा है। काटी साहबका दूसरा सप्ताह भी "छट्टी" मिश्री और बहादुर धरनेदारो — स्वयंमवकाने अपना नाम उज्ज्वल कर दिया। गार दाता तल अगुली दबाये हैं और परेशान हैं कि 'यह क्या है' क्या हमारी ठाकर खानवाले भारतीय मूछापर ताव दे सकेंगे? " कोई कोई अंग्रेज औरत सज्जीके फरोवाशम पूछती है कि क्या व अनुमतिपत्र मग। बहादुर फेरीवाले साफ इनकार करते हैं। यदि यही जाग अन्ततक रहा तो भारतीय समाजका नाम ऊंचा चढ़ जायगा और नया कानून गलम लाटने लगगा। और इसका श्रेय प्रिटोरियाके भारतीयों और उनके धरनेदार स्वयंमवकाका है, यह बात सब एक स्वप्ने कट सकेंगे।

गॉरेकी झाररत

मैंत मुता है कि श्री स्टीफन फ्रजरका एक आदमी विशेष तौरसे गाँव-गाँव घूम रहा है। वह प्रत्येक भारतीयका भत्ताता है। पाठमवगके भारतीयोंको उसने इस तरह डराया है कि यदि भारतीय समाज श्री गांधीकी सलाह मानेगा और इस तरह कानूनके सामने नहीं झुकेगा तो वह बरबाद हो जायेगा, और उसका माल सरकार जब्त कर लेगी। जैसे-जैसे आखिरी दिन निकट आयेगा वम वैसे शत्रुता या स्वार्थी गोरो द्वारा निस्संदेह ऐसे षडयन्त्र रचे जायेंगे। मुझे कहना चाहिए कि एक व्यक्तिका झिडक देना हर भारतीयका कतव्य है। अभी जनानी सीख मुननका भी समय किसी भारतीयको नहीं है। सरकार माल जब्त कर लेगी, यह मरामर झूठ है। माल जब्त करनेका अधिकार उसे बिलकुल नहीं है। और बरबाद होनेके बारेमें तो हम जानते हैं कि हाजी हबीबने 'स्टार' को वैसी सूचना दे दी है। बात यह है कि बरबाद भल हो जाय, हमारी नाक बनी रहेगी और हम टेकवाले कहलायेंगे। अतः हम कानूनका विराध श्री गांधीकी सलाह मानकर करते हैं सो बात नहीं, हम तो अपनी मर्दानगीकी रक्षाके हनु विराध कर रहे हैं। यदि हम मद होंगे तो जहाँ ठाकर मारेगे वहाँ पैसा निकलेगा। किन्तु यदि मद हात हुआ भी औरत बन गये तो बचे खुच धनको भी बचाना मुश्किल होगा और वह धन भी खान दौड़ेगा। इगड्डवा पुराना राजा तीसरा रिचर्ड अपने सम्बन्धियोंका मारकर गद्दीपर बैठा था। किन्तु उसमें गद्दीका पचाया नहीं जा सका। सम्बन्धियोंका खूनमें सनी तलवारको हाथमें पकड़ते हुए वह बापना था और आखिर धुल धुलकर बुरी मौत मरा। ऐसा कौन भारतीय है जो अपने भाईकी बेदुज्जतीकी परवाह न करके पैसके लाभमें सबका काम बिगाड़ेगा? ऐसा व्यक्ति रिचर्डक समान धुल धुलकर पश्चात्तापमें ही मर जायेगा। ऐसे नाजुक समयमें गोरा मुँह लेकर और काला दिल रखकर यदि कोई सलाह दे तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय कौम उसे ठुकरा दे।

दो अन्य गोरे

श्री स्टीफेन फ्रेजरके आदमियोने उपयुक्त नालायकीकी बात कही है तो दूसरे दो गोरे, जिनका भारतीयोंके साथ बड़ा व्यापार है, सीधी बात करते हैं और स्वीकार करते हैं कि भारतीय समाजको प्रतिष्ठाकी खातिर तो जेलके निणयपर अटल रहना ही चाहिए। यदि सभी उसपर अटल रहे तो निस्सन्देह जीत होगी। कोई कहेगा कि इसमें “यदि” शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किन्तु “यदि” शब्द महत्वपूर्ण केवल कायरोको मालूम होगा। बहादुर तो दूसरोको भी बहादुर मानकर यही कहेगे कि इस बार भारतीय समाज निश्चय ही अपनी टेक निभायेगा।

जोहानिसबगमे सभा

हमीदिया इस्लामिया अजुमनके सभा भवनमे पिछले रविवारको एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। सभाका समय २-३० बजेका था। किन्तु उसके पहले ही भवन खचाखच भर गया था। जो भीतर न आ सके वे लोग बाहर थे। जर्मिस्टनके भी बहुत लोग आये थे। हाफिज अब्दुल सैयद अध्यक्ष पदपर आसीन थे। श्री फैन्सी द्वारा काय विवरण पढा जानेके बाद श्री गाधीने खूनी कानूनकी बातें समझाई। और बादमे जर्मिस्टनके श्री रामसुंदर पण्डितने एक सुंदर और जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जर्मिस्टनमे लोगोमे बहुत ही जोश है। और स्वयसेवक भी तैयार हैं। जैसा प्रिटोरियाने कर दिखाया है, वैसा ही जर्मिस्टन करेगा। प्रिटोरियामे स्वयसेवकोने बहुत ही स्वदेशाभिमान व्यक्त किया है। इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि इस कानूनको कोई भी एशियाई स्वीकार नहीं कर सकता। प्रिटोरियाकी सभामे उन्हें जिस जोशका दशन हुआ था, उसका उन्होंने वणन भी स्वयं सुनाया।

श्री नवाब खाने कहा कि नया कानून छोटे या बड़े किसी भी भारतीय द्वारा मजूर नहीं किया जा सकता। विलायतकी औरतोमे जब इतना जोश है तब भारतीय मद क्या जेल या किसी नुकसानसे डर सकता है? श्री अब्दुरहमानने कहा कि पाचेपस्टूमके भारतीय बहुत ही सतक हैं। स्टीफेन फ्रेजरके आदमीने मुझसे कहा कि स्टीफेन माल तभी उधार देगे जब मैं कानून स्वीकार करनेका वचन दूंगा। इसके उत्तरमे मैंने स्वयं कहा कि हजार स्टीफेन फ्रेजर भी माल उधार देना बंद कर देगे, तब भी मैं कानूनकी गुलामी मजूर नहीं करूंगा। पाचेपस्टूमके व्यापारी चाहे जितना नुकसान सहन करेगे, किन्तु इस जुल्मी कानूनके सामने नहीं झुकेगे।

श्री उमरजीने बहुत ही जोशीला भाषण दिया और “सतिया सत नव छोडिए” वाला दोहा सुनाया। फिर श्री शहाबुद्दीन और श्री कामाने कुछ प्रश्न पूछे और सभा समाप्त हुई। इस सभामे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसके मनमे कानूनको स्वीकार करनेकी जरा भी इच्छा हो। इस सभामे श्री पोलकने भी भाषण दिया, जिसमे प्रिटोरियाके जिस स्वयसेवकको उन्होंने स्वयं देखा था उसकी तारीफ की।

हुजूरियोकी सभा

श्री डेविड अर्नेस्टने ट्रान्सवाल फुटबाल सघके सदस्योकी बैठक एबनेजर विद्यालयमे बुलाई थी। उसमे लगभग ५० हुजूरियो उपस्थित हुए थे। वह बैठक सोमवारकी शामको

१ पूरा दोहा इस प्रकार है

सतिया सत नव छोडिये सत छोडे पत जाय ।

सतकी बाँधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय ॥

साठे तीन वजे हुई थी। श्री गांधीने उस बैठकमें कानून सम्बन्धी चीजें कही। उनके बाद श्री नायडूने वही बात तमिळ भाषामें कही। फिर श्री पाण्डने भाषण दिया। श्री पाण्डने कहा कि पुराने जमानेमें एक जानवर था। उसकी यह विशेषता थी कि यदि काट उसका भिर काटना तो बदरम दा भिर हो जाते थे। उस प्रकार जब उसका भिर कटना तब दा भिर रहते थे। इस बातका जब राजाका पता चला तब काट का उन्नाटन न था। भारतीयोंको उस समय तैसा ही करना है। उन्हें किसी नेतापर भरोसा करके नहीं चलना है। सभी नेता हैं यह समझना चाहिए और यदि सरकार एकका जठम बन करे तो बदरम दा व्यक्तियोंका गला बनने जेल या निर्वासन भागनेके ठीक तैयार रहना चाहिए। उस तरह हानेपर सरकार विना हार नहीं रह सकती। इंग्लैंडका समझना चाहिए कि वह नौकर हानेके पढ़े भद है। उस प्रकार सरकार समझकर नौकरोंका भय रख विना उन्हें दृढ़तापूर्वक कानूनका विरोध करना है।

सरकारी दुभाषिय श्री डेविन्ने कहा कि सरकारने उन्हें पजीयन करवानेके लिए कहा तो उन्होंने साफ उत्तर दे दिया।

इसके बाद श्री गांधीन प्रश्न पूछा कि हंगरीने अपने होकर बताया कि हमारी नौकरी जायेगी तब भी हममें से कोई पजीयन करवाने नहीं जायेगा। तीन पांच वजे सभा समाप्त हुई।

जर्मिस्टनमें सभा

जर्मिस्टनके भारतीय चीजें जान लिया रह है। पण्डित रामदास महाराज आगे रहकर बेधड़क काम करने हैं और राजाका समानान्तर। उन्होंने विशेष सभा करके यह प्रस्ताव पास किया है कि चाहे जितना जायिम चलाना पड़े, उनमें से कोई नये कानूनके सामने नहीं झुकेंगा। उस प्रस्तावमें दा सीमे ज्यादा व्यक्तियोंका हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा कुछ बहादुर लोग अंग्रेजोंका समान स्वयंसेवक बननेको भी निकल पड़े हैं।

प्रवासी कानून

प्रवासी विधेयका दो बार वाचन किया जा चुका है। श्री स्मट्सने विधेयके पेश किये जानेका उद्देश्य बताया था। उसमें श्री हॉस्केन, श्री लिडमे, श्री वाटसन, श्री नसर और श्री ह्यूडनाइड आदि सदस्योंने भाग लिया था। श्री हॉस्केनन भारतीयोंका पक्षम बालते हुए कहा कि नया विधेयक तो हममें शोभा दे सकता है। इस कानूनकी कुछ भागों तो अंग्रेजी राज्यमें हानी ही नहीं चाहिए।

सचकी अर्जी

इस विधेयकके विरोधमें सचने अर्जी दी है। वह अंग्रेजी विभागमें दी जा चुकी है। उसका सारांश इस प्रकार है

यह सच यद्यपि आरंजनपर प्रभुत्व रखनेकी नीतिक विरुद्ध नहीं है फिर भी नस्लतापूर्वक निम्न आपत्तियाँ पेश करता है, (क) इस विधेयकमें भारतकी एक भी भाषाको रीकार नहीं किया गया। (ख) ट्रान्सवालके पुराने निवासियोंके अधिकारोंकी यह विधेयक रक्षा नहीं करता,

१ ट्रान्सवालके निवासियोंका ।

२ देखिए “प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल विधान सभाको”, पृष्ठ ९२ ९३ ।

उदाहरणार्थ बहुतेरे भारतीयोंने ट्रा सवालमे रहनेके लिए बोअर सरकारको ३ पौंड दिये थे, किंतु उनमे से बहुतोंको अनुमतिपत्र नहीं मिले। ऐसे लोगोके हक, यदि उहे यूरोपीय भाषाका ज्ञान न हो तो, नष्ट हो जाते हैं। (ग) दूसरी धाराकी चौथी उपधाराके अनुसार जि हे कानूनन आनेका अधिकार है, ऐसे लोगोपर भी नया एशियाई कानून लागू होता है। इस तरह कानूनके लागू किये जानेका कुछ भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़े हुए लोगोकी पहचान तो उनका ज्ञान ही है। (घ) इसके अतिरिक्त उसी धाराके द्वारा भारतीय समाजको बेइया और भडवोकी श्रेणीमे रखा गया है। (ङ) पहले बहुत आश्वासन दिये गये थे किंतु उनके विपरीत इस विधेयकके द्वारा एशियाई पजीयन कानून कायम रहता है।

संसदको ध्यानमे रखना चाहिए कि एशियाई समाजके पास मताधिकार नहीं है और इसलिए उसकी अर्जीपर ध्यान देना उसका दुहरा कतव्य है। अतः सब प्रार्थना और आशा करता है कि उसकी अर्जीपर पूरा ध्यान दिया जायेगा तथा न्याय किया जायेगा।

यह अर्जी श्री हास्केनने पेश की है। समितिमे इस विधेयककी बुधवारको छानबीन की जायेगी। यह पत्र मैं सोमवारको लिख रहा हूँ। इसलिए कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, यह 'इंडियन ओपिनियन' के प्रकाशित होनेके पहले ही मालूम हो जायेगा।

जेलमे अखबार मिलेगा ?

एक भाईने यह प्रश्न किया है। उत्तरमे यही कहना है कि यह इस बातपर निर्भर है कि जेल किस प्रकारकी मिलती है। यदि कड़ी सजा मिली तो अखबार नहीं मिलेगा। किंतु हर कैदीसे उसके सगे सगवोंकी महीनेमे एक बार मिल सकेंगे। उन सगे सगवोंको मेरी सलाह है कि वे "इंडियन ओपिनियन" का सारांश याद करके जेल महलमे रमनेवाले भारतीयको सुना आये।

सुनवाई नहीं हुई

प्रिटोरियाके कुछ भाइयोंको यह लगा है कि स्थानीय सरकारसे कुछ माग करे और यदि वह दे दे तो जेलकी झड़टसे छूट जाये। किन्तु खुदा हमे पूरी तरह कमना चाहता है। इसलिए मागका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। उन लोगोंने श्री स्मट्ससे निम्नानुसार माग की थी

- (१) दस अँगुलिया न लगवाई जाये,
- (२) माका नाम छोड़ दिया जाये,
- (३) बडोका पजीयन किया जाये और बच्चोको परेशान न किया जाये,
- (४) काफिर पुलिस जाच नहीं कर सकेगी,
- (५) तुर्कीके ईसाई और मुसलमानके बीच भेदभाव किया गया है, वह समाप्त किया जाये,
- (६) आरेज रिबर कालोनीका नाम अनुमतिपत्रपर है, उसे रहने दिया जाये,
- (७) बच्चोकी उम्र कितनी है, इसे तय करना पजीयकके हाथमे नहीं, अदालतके हाथमे रखा जाये,
- (८) व्यापारीके नौकरोको आने-जानेके मियादी अनुमतिपत्र उदारतापूर्वक दिये जाने चाहिए,

(९) इसके बाद और कानून नहीं बनाया जायेगा, इसका आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री स्मट्सने लम्बा उत्तर दिया है। उसमें एक बड़ी खूबी है। मीठे शब्दोंमें कोई मर सकता है तो उसे मार डालना चाहते हैं। वे मांगके उत्तरमें कहते हैं कि यदि सभी भारतीय पजीयन करवा लगे तो माका नाम प्रतिलानेके लिए मजबूर नहीं किया जायेगा, काफिर पुलिस मिपाही अँगुलियाकी निशानी नहीं मागेगा — गान्धी अनमतिपत्र ता माग सकेगा, और कानून बनाया जायेगा या नहीं यह भारतीय समाजपर निर्भर है। यदि वह ठीक तरह कानूनके अनुसार चले तो स्मट्स भावना कहता है कि पायद ज्यादा सक्ती नहीं प्रगती जायेगी।

खून खौलता है

इस उत्तरका ब्योरा देते हुए मेरा खून खौलता है। अगर सीधे चलेगे तो ज्यादा सक्ती नहीं करेगे। इसका क्या मतलब हुआ? गान्धी कानूनके द्वारा हम जीते-जी मुर्दे बनाकर क्या अब मुर्दोंको ठाकर मारनेके लिए नया सुधार करेगे? देखनेकी बात यह है कि श्री स्मट्सन किसी भी बातमें अपनी हठ नहीं छोडी है। क्योंकि, माका नाम न दिया जाये, यह भी वह नहीं कहते। सभी भारतीय पजीयन करवा लगे, तब वह पत्रिका नाम प्रालाना या न बनाना हमारी इच्छा पर निर्भर है। काफिर पुलिस अँगुलियाकी निशानी नहीं माग सकती, पर पाम ता मांग ही सकेगी। यदि नया कानून स्वीकार कर लिया गया तो “ऊफ़ी पाम” का गीत भारतीयोंके सिर जडा ही भमझिण।

किन्तु ठीक हुआ

उस तरहका जुल्मी वार रेशममें लपट्टर किया गया, यह ठीक ही हुआ है। अब भारतीय समाज और भी ज्यादा जोर करेगा। जिन तरह खतरनाक कानूनोंके अन्तर्गत खतरनाक नियम ही बन सकते हैं, उसी प्रकार उसका उत्तर भी खतरनाक ही होगा। खतरनाक नियमोंसे भारतीय उत्तेजित हुए थे, किन्तु यह उत्तर उस उत्तेजनका और भी मजबूत कर देगा। खुदाको बीचमें खड़ा करके हमने कानूनका प्रतिष्ठा किया है। उसी खुदाका बीचमें खड़ा कर हम हिम्मत रखनी है।

सुधार

स्वयमेवकाममें एकन श्री ईमप मियाँका शाल उठाया था। एक सज्जन मूर्चित करन है कि उक्त व्यक्तिका नाम देनेमें मुझमें भल हुई है। मैं उनका आभार मानता हूँ। शाल श्री गुलाम मुहम्मदने उठाया था। मैं इसके लिए श्री गुलाम मुहम्मदसे माफी माँगता हूँ।

ट्रान्सवाल प्रवासी विधेयक^१

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक पण्डित दूसरी बार पढा गया। और खुदाको उसका तीसरा वाचन हुआ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

१ यह “विशेष तार द्वारा” भेजा गया था।

७१ पत्र उपनिवेश सचिवको

२५ व २६, कोट चेम्बर्स
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग
[जुलाई १६, १९०७^१]

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

मेरे सघकी समितिकी इच्छा है कि मैं सरकारका ध्यान सघके उस प्राथनापत्रकी^२ ओर आकृष्ट करूँ जो सघने प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके [विषयमे] माननीय विधान [सभा]^३की सेवामे प्रस्तुत किया है। इसमे जो मुद्दे उठाये गये हैं वे मेरे सघकी विनम्र रायमे उस समाजके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जिसका कि मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है। मेरे सघका खयाल है कि यदि प्राथनाके अनुसार राहत बख्शी गई तो भी विधेयकके सिद्धांत ज्योंके त्यों बने रहेंगे।

इस बातका कोई कारण मेरे सघकी समझमे नहीं आता कि सुशिक्षित भारतीयोंसे पजीयन अधिनियमका पालन करानेकी आवश्यकता क्यों है? जिन ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रान्सवालमे बसनेके लिए ३ पोंडका कर चुका दिया है, परंतु जिन्हें शांति रक्षा अव्यादेशके अन्तर्गत परवाने नहीं मिले हैं, उन्हें अपने अपनाये हुए देशमें लौटनेके अधिकारसे वंचित रखना बड़ा गम्भीर अयाय प्रतीत होता है।

इसलिए मेरे सघको भरोसा है कि सरकार उसकी प्राथनापर अनुकूल विचार करनेकी कृपा करेगी।

आपका आदि,
मूसा इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

१ यह पत्र इंडियन ओपिनियनमें बिना तारीखके छपा है, परंतु ट्रान्सवाल विधानसभाके अभिलेख संग्रहालयमें प्राप्त सरकारी कागजोंसे इसी तारीखका संकेत मिलता है।

२ देखिए “प्राथनापत्र ट्रान्सवाल विधानसभाकी” पृष्ठ ९२ ९३।

३ चौकोर कोष्ठकोमें दिये गये शब्दोंके पर्याय मूलमें नहीं हैं।

७२ घोर मान-हानि

ट्रा मंत्रालये एशियाई अधिनियमके प्रारम्भे आगे जा पत्र व्यवहार हुआ है और जा ठाड ऐम्बेस्डरकी मागपर सन्तमे पत्र किया गया है, जस हम प्राप्त हो गया है। ठाड सेन्ट्रोनने ठाड एन्ग्लिश वयान उम विज्ञानकी आर आरपित करनेके लिए निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये हैं

मुझे आशा है कि आप यथाशीघ्र मुझे यह सूचना दे सकेंगे कि महामहिमको यह सलाह नहीं दी जायेगी कि वे इस अधिनियमको अस्वीकृत करनेके अपने अधिकारका प्रयोग करें, जिससे अधिनियम तुरन्त असलमें आ सके और इस प्रकार गैर-कानूनी तौरपर एशियाइयाका टान्सवालमे आवजन, जो इस समय बड़े जोरोंके साथ बढ़ रहा है, रोका जा सके।

तिरछे अक्षर हमारे हैं।

हम यह कहनेमें जरा भी सकाच नहीं हैं कि गैरकानूनी आवजनके प्रारम्भे लाड सेल्बोनका ज़ोरदार कथन हमारी साफ और सच्ची मानताति है। ठाड महादयने एशियाइयाके गैरकानूनी आवजनके बारेमें अपने सामने पेश किये गये बयानाका निम्नकाच भावमें स्वीकार कर लिया है, हालांकि ये बयान एकतरफा ही हो सकत थे। भारतीयान कहा है कि एसा कोई आवजन नहीं हो रहा है। और उद्गार हमकी जाच करनेके लिए चलीनी भी दी है। लेकिन अभीतक कोई जाच नहीं की गई और फिर भी लाड सेल्बानन, अपन कथापर भारी दायित्वोका बोझ होनेपर भी, इस बसबत इल्जामपर अपने अधिकारकी मुहर लगा देना ठीक समझा है।

यह आराप सफ़्त ही झूठा है। अगर एसा दाखिला प्रत्यक्ष रूपमें होता रहा है तो ऐमे प्रवेशकर्ताका उपनिवेशमें रहने ही क्यों दिया गया? या ता लॉड महादयको सूचना देनेवाले ठाग यह जानते थे कि इस प्रकार किन लागाने प्रवेश किया है, या वे नहीं जानते थे। अगर वे जानते थे ता शांति रक्षा अ यद्देशके मानहत उनके पास सारे आवश्यक उपाय थे कि वे उन ठागाका अदायतेके सामन पेश करेंगे। इसलिए ठाड सेल्बानने जो ताहीन की है, वह इस बातका साबित करती है कि दक्षिण आफ्रिकाम, मिवाय अदालतके, वही भी एशियाइयाकी सच्ची मुनगाइ होना अगर असम्भव नहीं ता कितना कठिन है। और इस तरहके मामलेमें ता उनक लिए अदालत भी बन्द है। इसलिए उह चुप होकर बैठना पड़ता है और अपनी मुसीबतका यथाशक्ति हँसकर सहना पड़ता है।

जब हम ठाड एन्ग्लिश जरापर विचार करते हैं तब दखत है कि वह ब्रिटिश भारतीयोका निराशाम भर दनक लिए काफी है। उपनिवेशम त्रीन इस विधानको मजूरी इसलिए नहीं दी कि वे इस न्यायाचित समझते हैं, बल्कि इसलिए दी है कि इसके पीछे गारोंके अधिकारका बल है। तो इसका यही अर्थ हुआ कि यदि किसी उपनिवेशकी विज्ञानमभाका कोई भी कानून सर्वसम्मत हो तो साम्राज्य सरकार भी, बिना उस कानूनके औचित्य-अनौचित्यको

देखे उससे बँध जायेगी। और अगर यह मसला आलोचनासे परे है तो लाड एलगिनका यह वक्तव्य — कि “महामहिमकी सरकारकी अब भी यही राय है कि एशियाइयोपर इस समय जो पाबदिया लगी हुई है उनमें सशोबन करनेकी आवश्यकता है,” — एक सदिच्छामात्र है, जिससे ब्रिटिश भारतीय बहुत आशा नहीं रख सकते। ओर हो सकता है जबतक वह कानून, जिसके खिलाफ लड़नेके लिए ट्रान्सवालवासी गिगल-ने अपना सम्बन्ध दावपर लगा दिया है, उनके सामने एक कठोर वास्तविकता बनकर खड़ा हो तबतक यह इच्छा कभी फलित न हो। विनिमयमें सुधार करनेके लिए जनरल बोथाने जो वचन दिये हैं उनसे भारतीयोंका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। परन्तु प्रसंगवश यह बता दिया जाये कि जिस उग्र पूर्वग्रहसे स्थानीय सरकार ओतप्रोत है उसका ही यह एक लक्षण है कि जनरल अपने वचनको पूरा नहीं कर सके। उपनिवेश सरकारके विचारोंमें भारतीयोंकी भावनाओंका कोई महत्त्व नहीं है।

[अग्रेजासे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७३ ट्रान्सवाल प्रवासी-विधेयकपर बहस

ट्रान्सवालकी प्रिन्स मनामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके दूसरे वाचनपर जो विवाद हुआ, वह कई बातोंमें आखे खोल देनेवाला है। श्री स्मट्सने विधेयकको सदनमें बहुत ही मरसरी तोरपर पेश किया। माननीय महानुभावने ब्रिटिश भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले मुद्दोंको ठुजातक नहीं। उन्होंने उन बातोंका इस लायक भी नहीं समझा कि उनमें सदस्या या जनताको दिलचस्पी हो सकती है। उन्होंने इसे निश्चित मान लिया कि एशियाई पजीयन अधिनियमको ट्रान्सवालके कानूनका एक स्थायी अंग होना चाहिए। श्री डकनने इस विधानके पेश होने पर जो कुछ कहा था^१ उसके विपरीत, उन्होंने इसे भी निश्चित मान लिया कि जहातक एशियाई समुदायोंका सम्बन्ध है, प्रवासी विधेयक उसका स्थान लेनेके लिए नहीं, बल्कि उसकी कठोरतामें जो कमी रह गई थी उसको पूरा करनेके लिए बनाया गया है। उन्होंने सदस्योंको यह सूचित करनेका कष्ट नहीं किया कि इस विधेयक द्वारा सन १८८५ के कानून ३ की, जो बोअर सरकारको ३ पौड देनेवाले एशियाइयोंको निवास सम्बन्धी सरक्षणकी गारंटी देता था, अवहेलना होगी, और उन्हें इस वारामें कुछ भी आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं दी, जिसके अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त एशियाई भी उपनिवेशमें आनेपर एशियाई पजीयन अधिनियम द्वारा निश्चित अग्नि परीक्षामें से जबतक गुजर नहीं जाते तबतक वर्जित प्रवासी माने जायेंगे।

श्री नेसरके इस मन्त्र कथनके उत्तरमें, कि किसी व्यक्तिका बिना मुकदमा चलाये, उसके अपने ही खर्चसे उपनिवेशसे निकाल देनेका असाधारण अधिकार सरकारको देना बड़ी खतरनाक चीज होगी, श्री वाइबगने अत्यधिक रोष प्रकट किया। कि तु श्री वाइबगके उद्गाराको हम सिर्फ आम विस्मयजनित मूखता कह सकते हैं। यही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो वह बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। इस धारापर विचार करते हुए ओर सरकारसे उसपर दण्ड

१ देखिए खण्ड ६ पृष्ठ १५७। श्री पैट्रिक टर्नन १९०३ से १९०६ तक उपनिवेश सचिव थे।

रहनेका अनुरोध करने हुए उन्होंने भारतमें हुई हालकी घटनाओंका जिक्र किया। हम इस विवादके गुण-दापाकी चर्चामें नहीं पड़ना चाहते, परन्तु हम यह आशा रखते हैं कि श्री वाइबग जैसा एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ विधानमण्डलमें अपने आमनसे दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे ऐसे निहायत गैरजिम्मेदार तरीकेसे बात न करेगा। अगर उन्होंने भारतीय समस्याओंका विशेष अध्ययन न किया हा तो यह माफ जाहिर है कि वे सिफ उतना ही जान सकते हैं जितना समद्री तारों द्वारा भेजे गये पटनाआके सागरशासे समारको विदित हो पाता है। और अगर वे यह नहीं मानत कि सभी सरकारें भूत भ्रान्तियामें परे हैं तो उन्हें यह माननेका कोई हक नहीं है कि भारतीय नेताआका निवासित करनेकी अधिकाग्याकी कायवाही या तो अपने आपमें अच्छी थी या उसका कोई शान्तिजनक परिणाम हुआ है। शायद हम माननीय सदस्यकी अपेक्षा कुछ अधिक जाननेका दावा कर सकते हैं फिर भी ब्रिटिश साम्राज्यके उस भागमें जो घटनाएँ घट रही हैं उनके निकट सम्पकमें न होनेके कारण हमने कुछ न कहनेमें ही बुद्धिमानी समझी है।

श्री वाइबगने एक नामझी और की है कि उन्होंने भारतमें होनेवाली घटनाओंमें यह नतीजा निकाला कि ट्रांसवालमें आक्रामक प्रतिरोधके लिए भत्कानेवाले भारतीयाको निर्वासित करनेके लिए इस तारा द्वारा दिये गये अधिकार उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि उनमें विषयको समझनेकी क्षमता नहीं है। भारतकी घटनाओंको बगावतका रंग दिया गया है और उनका अर्थ ब्रिटिश राजके विरुद्ध विद्रोह लगाया गया है। ट्रांसवालके भारतीयोके धमयुद्धकी किसी भी विद्रोही आन्दोलनमें जग भी समानता नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि यह समुदाय अपनी नैतिक भावनाका नष्ट होने देनेके बजाय घोर शारीरिक फट सहन करनेका नैयार है। यह ट्रांसवालके भारतीयाका नाजरथके देवदूतके इस उपदेशपर चलनका प्रयत्न मात्र है कि “बुराईका विरोध न करो”।

नि सन्देह इस बातकी ब्रिटिश भारतीयोको जग भी परवाह नहीं कि श्री वाइबग सदनको उनके विरुद्ध भडका रहे हैं। वे किसी धमकीसे कतव्य विमुख होनेवाले नहीं हैं। उन्होंने बुरेसे-बुरा परिणाम पहले ही सोच लिया है। उनका साहस उद्देश्यकी पवित्रता और आत्मसम्मानको कायम न होने देनेके निश्चयमें पैदा हुआ है। हम श्री वाइबगके उदगाराकी चर्चा सिफ इसलिए कर रहे हैं कि हम उन्हें सच्चा, किन्तु गुमराह व्यक्ति मानते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि पूर्वग्रहपूर्ण वातावरणमें एक सन्तुलित मानस भी कैसा विचलित हो जाता है। विधानमण्डलमें सब सदस्योंमें अकेले श्री हास्केन ही ऐसा थे जिन्होंने श्री वाइबगके भाषणकी प्रतिशाधवन्तिकी जागरूक भूमना की। श्री हास्केनका यह कहनेमें कोई सकोच नहीं हुआ कि यह विधेयक रूसी या जर्मन इलाकमें ही सम्भव है ब्रिटिश भूमिपर नहीं। श्री वाइबग क्या जानें कि किसी विशेष वर्गके लोगोंका दमन करनेके लिए ग्रहण किये हुए निरंकुश अधिकार उलटकर उन लोगोंपर असर करते हैं, जिनके बारेमें स्वप्नमें भी नहीं सोचा जाता। परन्तु हमें आशा है कि शान्त होकर सोचनेपर उन्हें अपनी भूलपर पश्चत्ताप हुआ होगा।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७४ गिरमिटिया प्रवासी

हम इस सप्ताह उस महत्त्वपूर्ण पत्रको छाप सकते हैं जो भारतीय प्रवासी न्यास निकाय सचिवने गिरमिटिया भारतीयोंके मालिकोंको भेजा है। उसमें इन मजदूरोंको नेटालमें लानेके खर्चके सम्बन्धमें जानकारी दी गई है। यह कागज सवश्री इवान्स और राबिसनके देखने योग्य है, जिन्होंने पूरी तरह विचार करनेके बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि नेटालमें गिरमिटियोंका प्रवास बंद किया जाना चाहिए। हम चूँकि श्री हेगरको जानते हैं, इसलिए उनका उल्लेख इसी श्रेणीमें नहीं कर सकते। यद्यपि हम संयोगसे गिरमिटिया भारतीयोंका प्रवास बंद करनेके प्रयत्नमें उनसे सहमत हैं, किंतु हमारे हेतु एक नहीं हैं और भारतीय समाजका उस सदस्यसे बहुत कम सरोकार हो सकता है, जो उनकी मानहानि करनेमें तनिक भी सकोच नहीं करता, और जब उसे अपने कथनको सिद्ध करनेकी चुनौती दी जाती है तब उसमें उसे सिद्ध करनेकी या क्षमा मागनेकी मर्दानगी भी नहीं होती। श्री राइक्राफ्टने जो पत्र लिखा है उसमें यूरोपीयोंके दृष्टिकोणसे इन मजदूरोंका आब्रजन बंद करनेका प्रायः पूरा औचित्य बताया गया है। यह प्रत्यक्ष है कि मालिक उनको लानेका खर्च मुश्किलसे ही उठा सकते हैं। अनिवाय प्रत्यावर्तन, यदि भारत सरकार अपनी संरक्षकता छोड़कर ऐसी किसी शर्तको मान भी लेता, उनके लिए और अधिक बुरा होगा। यह बताया गया है कि १९०५ में मालिकोंने जहाँ मजदूरोंको लानेके खर्चमें केवल २० पौंड दिये वहाँ वास्तविक व्यय प्रति वयस्क पुरुषपर ३१ पौंड १० शिलिंग ९ पैसे आया। और, जैसे जैसे ३ पौंडी करके भारके कारण अधिकाधिक भारतीय बिना किरायेके भारत-वापसीका लाभ उठायेगे, वैसे वैसे यह खर्च बढ़ेगा ही। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोणसे गिरमिटिया मजदूरोंको लाना जितना जल्दी बंद कर दिया जाये, उतना ही दोनों पक्षोंके लिए अधिक अच्छा होगा।

[अग्रजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७५ जनरल स्मट्सका हठ

एशियाउ पजीयन अग्नियमक कारण सरकारन अपन आपका जिस गठन स्थितिम डाल दिया है, उसम निश्चयसे रिप प्रिटारियाके भारतीयाने उस एक मोहा आर दिया है। वह पत्र प्रहार लम्बा है और दुभाग्यवश हम उस जस उसका गामित करना असमर्थ है। पजीयन अग्नियमका अत्यन्त आपत्तिजनक गाराजक प्रारम्भ सम्बन्धित भारतीयों की लाने वृत्त ही उचित सृजाव दिया है। उपनिषद् सन्निधन प्रायः प्रत्येक प्राथमिक साफ साफ शब्दामे अस्वीकार कर दिया है। हम स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि सरकार उसमें भित्त कृत् कर भी नहीं सकती थी। हमारा रायम उस उस पत्रका यह अर्थ लगातक अधिकार था कि भारतीयोंम अपन जस सम्पत्ती प्रस्तावका कार्यान्वित करनेकी पर्याप्त शक्ति नहीं है। इसलिए सरकारने प्रत्यक्षतः उस अत्यन्त उचित पत्रका गठन अर्थ किया है। उसने अग्नियमक अनुरूप नियम स्वीकार कर दिया है, और प्रिटारिया भारतीयोंको अपना उत्तर उसी नीतिक अनुसार भेजा है। इस पत्र व्यवहारमे कुछ लाभ होगा, क्योंकि उसमे भारतीय समाजका अतिवाय पजीयन स्वीकार न करनेसे होनेवाले कष्टका सहन करनेका निश्चय दृढ़ होगा।

[अग्रजीम]

इण्डियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७६ द० आ० ब्रि० भा० समितिका काम

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति उस समय भी बड़ी सहनत कर रहा है। कुछ ही दिन पहले सर विलियम बुल और डा० रदरफोर्डने रायसभामे प्रश्न पूछा था। उसमे मालूम हो सकता है कि समितिने यद्यपि दो मालूम कानूनका विरोध न करनेकी सलाह दी है और भारतीय समाजने उस नहीं माना है फिर भी उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। समिति अपना काम कर रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। समितिकी प्रत्येक सहाय माननके लिए भारतीय समाज बाध नहीं है। समितिके सदस्य उदार हृदय हैं और वे अपना काम कर जाते हैं।

सर मन्त्रजी भायनगरी उनकी सावधानी और दूरगाम चरनेवाले व्यक्ति हैं कि उनकी अध्यक्षतामे समिति भारतीयोंका काम ठीक नहीं सकती। उसके अलावा श्री रिचर्ड लाड ऐम्प्टिल्लिक नाम का पत्र लिखा है उसमे माहम होता है कि वे समितिके सामने भारतीय विचारोंको साफ-साफ रखनेमें कभी सफल नहीं रहते।

डेलोगोआ-बे

सर विलियम बुलके प्रश्नामे डेलोगोआ बेके भारतीयोंको मालूम हो गया होगा कि उनका प्रश्न भी भुलाया नहीं गया है। 'इण्डियन ओपिनियन' में श्री कोठारीका पत्र प्रकाशित

किया गया तो उसके आधारपर सर विलियम बुलने तुरत भारतीयोपर होनवाले जुल्मोकी शिकायत की। हमे यहा कहना चाहिए कि डेलागाआ बेके भारतीयोकी ओरसे समितिका बिलकुल मदद नही दी गई है। उनपर इस समय ज्यादा मुसीबत नही हे, फिर भी हम मानते ह कि समितिके खचमे उहे हाथ बँटाना चाहिए।

रोडेशिया

जिस तरह डेलागाआ बे नही भुलाया गया, उसी तरह रोडेशियाका भी हआ हे। हमारे पाठकोको खयाल होगा कि भारतीयाके प्रति रोडेशिया परिषदके जा विचार थे उहे हमने इसी बीच प्रकाशित किया था। विलायत पहुँचते ही श्री रिचने उनका उपयोग किया हे और सम्भव है कि रोडेशियामे अधिक सरत कानन नही बन पायेगे। इस विषयमे विचार करते हुए सबको स्वीकार करना होगा कि क्या रोडेशिया और क्या डेलागाआ बे, दोनो देशोकी इज्जत वास्तवमे ट्रा सवालके भारतीयोकी लडाईपर निर्भर है। वे लाज रखेगे तो रहेगी, नही तो समिति या अय कोई ऐसी स्थितिमे नही रहेगा कि कुछ सहायता कर सके।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७७ लोबिटो-बे

हमारे सवाददाताने समाचार भेजा है कि लोबिटो बेके मजदूरोकी हालत बहुत बुरी है। उसके आधारपर हमने ग्रिफिय पेडीके एजेंटकी मारफत पूछताछ की। उसका नीचे लिखा उत्तर आया हे

रिपोर्ट बे-बुनियाद है। डाक्टरों सहायता बहुत मिल रही है। मजदूरोंके लिए विशेष चिकित्सालय और डाक्टरकी व्यवस्था है। यदि आवश्यक समझे तो आप नेटाल-सरकारसे कहियेगा कि जाच करनेके लिए किसी व्यक्तिको भेजे। मजदूरोंकी स्थिति अच्छी है। उहे सतोष है। पानी उत्तम है। खाद्य-सामग्री बहुत हे।

हमारे सवाददाता द्वारा भेजे गये समाचारमे और इसमे विरोध हे। हमारा सवाददाता बहुत ही सावधानीसे काम लेनेवाला और नि स्वाध व्यक्ति हे। इसलिए उसका समाचार बेकार नही है। हम दोनो समाचारोंको मिलाकर यह अथ करते है कि जब मजदूर वहा पहुँचे तब उन्हें बहुत कष्ट थे और वह समाचार हमारे सवाददाताको मिला। इस समय उनकी हालत उतनी खराब नही है। साधारणत वे सुखी होंगे। फिर भी इतना तय है कि अभी भागतीयोके लिये साहस करके वहा जानेका विचार करना बेकार हे। बेगुएला पहुँचने तक नि स देह बहुत कष्ट ह, और बेगुएला पहुँच जानेके बाद भी कोई स्वतन्त्र रहकर कुछ कारोबार कर सके, सो स्थिति अभी नही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-१७-९०७

७८ नेटालमें परवाने और टिकटका विधेयक

राजस्व परवानेक सम्बन्धमें कुछ सशोधन करनेके लिए एक विधेयक १२ जुलाईक नेटालक सरकारी 'गजट' में प्रकाशित हुआ है। उसमें से महत्त्वपूर्ण बात हम नीचे दे रहे हैं

- (१) १८९७का व्यापार कानून अबमें काफिर भोजनालयपर लागू होगा।
- (२) मजिस्ट्रेटके एक विभागमें फेरी लगानेका परवाना मिला हो तो उसका दूसरे विभागमें उपयोग नहीं किया जा सकता।
- (३) कोई फेरीवाला एक फामपर १२ घंटेमें ज्यादा नहीं ठहर सकता, और उम्मी जगह-पर चार दिन तक दूसरी बार नहीं जा सकता।
- (४) नगर परिषदमें परवानेपर उसकी कीमतके अगवा उसके दमवें हिस्सेके दूसरे टिकट लगाने हाने। वह दसवाँ हिस्सा परवानेवाला देगा और सरकारको मिलेगा।
- (५) विदेशी पढीके एजेंटका परवाना लेना होगा। और यदि नीलाम करनेवाला बैसा माल बचे ता उसे भी परवाना लेना होगा।
- (६) अपन व्यापारका परवाना लेते समय हर व्यक्ति, यदि उसक पास एजेसी हो तो, अधिकारीके सामने यह बात कहनेके लिए बाध्य है।
- (७) बतनी अथवा भारतीयका किरायकी रसीद दो हा ता उसक लिए अलगसे रसीद-बुक रखी जाये, उसपर क्रम मख्या डागि जाये और पन्नापर मुहर उभरी हुई होनी चाहिए। चिपकाइ हुई मुहरमें काम नहीं चलेगा।

यह विधेयक अभी कानून तो नहीं बना है, किन्तु माना जा सकता है कि कानून बन जायेगा। उसमें कुछ परिवर्तन होना सम्भव है, लेकिन बहुत छोटे मोटे यह सबपर लागू होता है, इसलिए इसका विरोध करना कठिन है। इस विधेयकका मतलब यह है कि उपनिवेशमें इस समय पैसकी तंगी है, इसलिए जहाँ-तहाँसे पैसा इकट्ठा किया जाये। गुस्सा आनेपर कुम्हार गधीके कान खींचना है, उसी प्रकार सरकारके पास पैसकी कमी है इसलिए उसने फेरीवाले जैसे गरीबापर हमला किया है। संक्षेपमें सारा दक्षिण आफ्रिका इस समय कगाल बन गया है। इसलिए सरकार पैसके लिए इधर-उधर भटक रही है। परवानाकी जो विभिन्न दर रखी गई है उन्हें हम इस समय नहीं दे रहे हैं, किन्तु यदि विधेयक पास हुआ तो आवश्यकता मालूम होनेपर प्रकाशित करेंगे। उपर्युक्त सारी उपधाराओंमें किरायेकी रसीदकी उपधारा भयकर है। उसक सम्बन्धमें लडाई लडनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७९ गिरमिटिया भारतीय

भारतीय प्रवासी यास निकाय (इंडियन इमिग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड)के सचिव श्री राइ क्राफ्टने गिरमिटिया भारतीयोंके मालिकोंके नाम जो पत्र लिखा है उसे हम अंग्रेजी विभागमें पूरा पूरा प्रकाशित कर रहे हैं। उससे पता चलता है कि भारतीय गिरमिटियोंको दाखिल करवानेका खर्च सेठोंको भारी पड़ता है और यदि भारतीय मजदूर अपने इकरारके वष पूरे हो जानेपर स्वदेश लौटते हैं तो बहुत ही ज्यादा खर्च हाता है। इससे श्री राइक्राफ्टका कहना है कि मजदूरोंको यदि बलात लौटा देनेका कानून बनाया गया तो सेठोंका नुकसान होनेकी सम्भावना है।

इस दृष्टिसे गिरमिटियोंके सेठोंकी हालत साफ छछदरकी सी हो गई है। अगर मजदूरोंको जाने दे तो उनके बर्मीठे बैठ जाये। यदि वे रोक ले ओर इधर उन मजदूरोंको भारत भेजनेका कानून बन जाये तो उन्हें बहुत ज्यादा खर्च उठाना होगा। इस सन्दर्भमें क्या किया जाये, यह एक जवरदस्त सवाल पैदा हो गया है। इस लड़ाईसे भारतीय मजदूरोंको किसी प्रकारका लाभ होनेका सम्भावना नहीं है। मजदूर न बुलाये जाये यह कहनेवाले ओर बुलाये जाये यह कहनेवाले दोनोंमें से किसीको भी भारतीयोंकी चिन्ता नहीं है। यदि भारतीय मजदूर और भी कम वेतनपर आये और गिरमिटिके अन्तमें चाहे उन्हें लौटना पड़े फिर भी कोई कुछ कहेगा सो बात नहीं। दोनों पक्ष प्रसन्न होंगे। भारतीय समाजका एक ही तरीकेसे लाभ हो सकता है और वह है, मजदूरोंको बुलाना बिल्कुल बंद हो। मजदूर यहां आकर गुलामीकी हालतमें अपना स्वाथ सिद्ध नहीं कर सकते, उनकी स्वतंत्र रहनेकी कोई स्थिति नहीं है। हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि गिरमिटियोंपर पड़नेवाले कष्टोंसे सारे भारतीय समाजको सहानुभूति हो रही है। यह हमारी जागृति का लक्षण है। इसलिए यदि हम अब एक कदम आगे बढ़कर गिरमिटिपर आनेवाले भारतीयोंको रोक सकें तो भारतीयोंकी गुलामी समाप्त होगी और इस समय दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजके जितने लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ राहत मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन २०-७-१९०७

८० भाषण नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें^१

उत्तर

जुलाई २० १९०७

तेरह वर्षाकी लड़ाईमें आजकी लड़ाई ही बड़ी आनमानकी है। इसलिए इसका परिणाम भी उतना ही भारी होना चाहिए। इस कानूनका सार दक्षिण आफ्रिकापर समान असर पड़ेगा। राडशिया ओर जमन आफ्रिकामें तो इसके छोटे उड ही हैं, किन्तु भारतमें भा इसका बुरा असर पहुँचे बिना नहीं रहगा। नटालके भारतीयोंका तो ज्यादा डरना है। [यहां १८ मई तथा ६ जुलाईके 'आपिनियन' में कुछ उदाहरण दिये गये थे]। गार कहते हैं कि भारतीय नागर ता मजूर हैं लेकिन स्वतंत्र भारतीय नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त अटक सार नचकेरा बैठते हैं। पोरबंदरके किसी गरीब हासिमका मामला मझे याद आता है। अपनी लगभग १०० रुपयेकी मौलूमी जमीन छिन जानके कारण वह प्रमर्गमें मरे पास आया। मने सहाइ दी कि १०० रुपयेकी जमीनक ठिग ५०० रुपयेपर पानी क्या फेरता है? उसने जवाब दिया कि मर पुरखाकी जमीन है। चाह जा हा, मैं उस वापस ठूंगा। मैं अपना पट्टा झग नहीं होने दूंगा। किन्तु ट्रान्सवालक सम्प्रभम ता कामका पट्टा है। एक है, उस जनरर दूसरा अपनी मर्जीक मुताबिक दना चाहत है। और वह भी कबल भारतीयोंका ही। उसक अगला पट्टा देने समय, जैसा नाटकमें देखा है, पाप, मा, पत्नी आदिक नाम तथा पहरे दम अंगरियाकी ओर उसक बाद आठकी ग्राप मागत है। उतना सब ठनेक ग्राप मर्जी हा ता मर्जीक अनुसार पट्टा देनेकी बात कहते हैं। ऐसी गुथामी कौन सहन करगा? तीन चार पाठ समानबाग आदमी जहाँ ठोकर मार वही अपना पेट भर सकता है, ता उतनी ग्रापी मी रखमक ठिग ट्रान्सवालमें बेइज्जतीके साथ रहना क्या पसंद करेगा? इसके अलावा ६०० पौंड समानवालको पैससे इज्जत प्यारी होती है। शायद गरीब अमीर सभी ठाग हजूरिय बनकर बेइज्जती सहन कर ले, लेकिन यदि उनके आठ-दस बपक लडकेपर जल्म हो ता वह उनमें कदापि सहन नहीं हागा। बाजर ठाग पट्टादुर है। उनका विरोध नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि व गलत दबमके सामने जकनर लिए वहे, यानी गुलाम बननेके ठिग वहे, ता इनकार किया जा सकता है। हम ठाग ग्राटे मिक्कर रूपमें जानते हैं। सच्चा मिक्का बननेका यह अच्छा अवसर है। यदि इस कमाटीपर सच्च उत्तर जाये ता दुनियाम कही भी रहनवाठ भारतीयोंका इसमें लाभ हागा। भारतमें आज बदर-न्याय हा रहा है। मुसलमान और हिंदू इन दो बिलियोंका लडाकर सरकार अपना काम बना रही है। यहाँ वह हालत नहीं है। दाना कौमें एक है, इसलिए हमारा साहस सफल होगा। इन सारी बातोंका विचार करके मिनम्बरकी मावजनिक सभामें^२ मैंने जेलकी सलाह दी। इसमें सबने खुदाको बीचमें रखकर हाथ ऊँच करके जेल जानेकी शपथ ली। उस दिनस आजतक की हकीकत सब जानते हैं। अब यदि शपथ नहीं निभाते हैं तो हम खुदाके चार माने जायेंगे। एकके बाद एक नये-नये कानून बनेगे, हम बिना पानीके माने जायेंगे। तबतक कुत्ताकी

१ नेटाल भारतीय कांग्रेसकी आम सभा शनिवारकी श्री दाउद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें हुई थी। उसमें एशियाई अधिनियमके फलितार्थपर गांधीजी बोले थे।

२ विक्टोरिया इंडियन थियेटर, बरबनमें २३ जुलाई १९०७ को खेला गया एक प्रहसन।

३ देखिये खण्ड ५, पृष्ठ ४३०-३४।

जिदगी रह गई। एक बार एक गोरी महिलाने कहा कि लात खानेवाला झल्लीवाला (बास्केटिया) मान अपमान क्या समझे? मैंने जवाब दिया कि एक बार यदि उसे यह हल्का पन महसूस हो गया तो फिर जिदगीभर पजीयन नहीं करवायेगा। इसका निश्चय करनेके लिए वह जो भी फेरीवाला उसके आगनमे आता उससे पूछती थी कि तू नया पजीयन करवायेगा या नहीं? उस महिलाको जवाब मिलता कि पजीयन नहीं करवाऊंगा। आज उसे मालूम हो गया है कि भारतीयोमे कुछ तो बहादुर है। इसलिए अब वह कहती है कि जब भारतीय जेलमे होंगे तब वह उनकी खबर लेती रहेगी और यथासम्भव सार सँभाल करती रहेगी। श्री हास्केन कहते हैं कि सारे भारतीय यदि जेल चले जाये तो सरकारकी ताकत नहीं कि फिर अँगुली उठाये। इससे हमे समझना चाहिए कि यदि हम टेक रखे, तो हमारा दिन निकला ही समझिए। इस समय तो हमारे प्रति यह खयाल है कि हम कोरे शोर मचानेवाले ह। इसलिए प्रवासी कानूनके खिलाफ की गई हमारी अपील रद्दीकी टाकरीमे फेक दी गई है। यह सब आपके सामने इसलिए कहना आवश्यक है कि इन उदाहरणोसे आप सीखे और तैयार रहे। आप और हम एक ही हैं, इसलिए यदि आप हमारे दुखमे हाथ बँटाये तो कोई नई बात नहीं होगी। बातें करके यानी प्रस्ताव पास करके तथा पत्र व्यवहार करके मदद दे, सो काफी नहीं है। खास मदद तो वह भीख मुझे देना है जिसके लिए मैं आया हूँ। ट्रांसवालमे सारे भारतीय चाहे जो नुकसान उठानेको तैयार हैं, तब आपको पैसेसे मदद करनेमे पीछे नहीं रहना है। आप उसमे कुछ अधिक नहीं कर रहे, बल्कि अपना फज अदा कर रहे हैं। बहुत-से लोग जब जेल चले जाये, तब उनके पीछे रहनेवालोका भरण पोषण आपको करना होगा। अतः पानी आनेके पहले बाव बाव लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप मदद करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८१ प्रार्थनापत्र^१ ट्रांसवाल विधान-परिषदको

जोहानिसबग

जुलाई २२, १९०७

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण

ट्रांसवाल विधान-परिषद

ट्रांसवाल ब्रिटिश भारतीय सघके कायवाहक अध्यक्ष ईसप इस्माइल मियाका प्राथनापत्र नम्र निवेदन है कि

१ आपका प्रार्थी ट्रांसवाल ब्रिटिश भारतीय सघका कायवाहक अध्यक्ष है।

२ उक्त सघ माननीय सदनसे उस विधेयकके सम्बन्धमे प्राथना करता है जो इस देशमे वर्जित प्रवासियो और अय लोगोके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाने, उनको देशसे निकाल बाहर करने और एक 'प्रवासी विभाग' स्थापित करने और कायम रखनेके उद्देश्यसे अब माननीय सदनके सम्मुख विचाराय प्रस्तुत है, या जल्दी ही प्रस्तुत किया जायेगा।

१ इसकी एक नकल ६६० टक्क्यु० रिचने १४ अगस्तको उप उपनिवेश मन्त्रीको भेजी थी। वह आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको (पृष्ठ १८३ ८८) के साथ भी सल्लय की गई थी।

३ प्रार्थी सघ जहा प्रवासपर प्रतिबन्ध लगानेके सिद्धा नकी पुष्टि करता है, वहा माननीय सदनका ध्यान सादर निम्न बातोकी ओर आकर्षित करता है

- (क) विधेयक एशियाई कानून संग्रान अग्रिनयमको स्थायित्व प्रदान करता है।
- (ख) उसमें किसी भी प्रमुख भारतीय भाषाका मायता नहीं दी गई है।
- (ग) उससे उन ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकार समाप्त हो जाते हैं जिन्होंने गत युद्धमें पूर्व ट्रान्सवाल्मे अधिवासका अधिकार प्राप्त करनेके लिए तीन पौंड दिये थे और जिनको, शरणार्थी होनेके कारण, शान्ति रक्षा अध्यादेशक अंतर्गत अनुमतिपत्र नहीं मिले है।
- (घ) उसकी प्राग २ की उपप्राग घ के द्वारा, वे भारतीय भी, जो गिन्ना-सम्बन्धी परीक्षा पास कर ल और अथवा वाजत न हो, एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत आ जाते हैं। (सादर निवेदन है कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त भारतीयोंका आगे गिन्नाखतकी आवश्यकता नहीं रहती।)

४ प्राग सघ सविनय निवेदन करता है कि ऊपर गिनार्दे गई आपत्तियाँ माननीय सदनके लिए विचारणीय हैं।

५ प्रार्थी सघ माननीय सदनका सादर स्मरण दिलाता है कि जिन समुदायोंका इस उपनिवेशकी ससदमें प्रतिनिधित्व नहीं है उनके हितोंकी रक्षा करना उसका विशिष्ट कर्तव्य है और प्रार्थी सघ एक ऐसे ही समुदायका प्रतिनिधित्व करता है।

६ प्रार्थी सघ इसी कारण सादर प्रार्थना करता है कि माननीय सदन जितनी सहायता उचित समझे उतनी दे। और उस कार्यके लिए हम क्रतज्ञ हागे, आदि, आदि।

[आपका आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ]
कायवाहक अथवा
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रजाम]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स सी० आ० २९१/१२२

८२ प्रार्थनापत्र नेटाल विधान-सभाको

डबन

जुलाई २५, १९०७

सेवामे

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण

नेटाल उपनिवेशकी विधान सभा

पीटरमरित्सबग

नेटाल भारतीय कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके रूपमे उसके अध्यक्ष और
सयुक्त मंत्रियोंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन हे कि,

- १ आपके प्रार्थी नेटाल भारतीय कांग्रेसके, अध्यक्ष और सयुक्त मंत्रियोंके रूपमे उसका प्रतिनिधित्व करते है।
- २ आपके प्रार्थियोंने गत २५वीं जूनके सरकारी 'गजट'मे प्रकाशित, भूमि कर लागू करनेवाला विधेयक पढा है।
- ३ आपके प्रार्थी इस सम्बन्धमे इस माननीय सदनका ध्यान आकृष्ट करते है और उस भेद भावका जो इस विधानमे, जहातक करकी दरका सम्बन्ध है यूरोपीय और भारतीय किरायेदारोके बीच किया जानेको हे विरोध करते है।
- ४ आपके प्रार्थियोंकी विनम्र सम्मतिमे उद्दिष्ट भेद जातिगत होनेके कारण ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अपमानजनक तो है ही, यह उनपर अनावश्यक कठिनाइया भी लाद देता है।
- ५ इसलिए आपके प्रार्थी नम्र निवेदन करते है कि यह माननीय सदन इस विधानमे ऐसा सशोधन करे कि उपयुक्त कठिनाई दूर हो जाये, और याय और दयाके इस कायके लिए आपके प्रार्थी कतव्य समझकर सदा दुआ करेगे, आदि।

दाउद मुहम्मद

दादा उस्मान

एम० सी० आंगलिया

[अंग्रेजीसे]

नेटाल आर्काइव्स पीटरमरित्सबग विधानसभाके बोर्ड्स ऐड प्रोसीडिंग्स, १९०७

८३ परवाना-कार्यालयके बहिष्कारका भित्तिपत्र^१

[प्रिटोरिया]

जुलाई २८, १९०७ के पूर्व]

बहिष्कार करो, परवाना कार्यालयका बहिष्कार करो। जेठ जाकर हम प्रतिगम नहीं करने, अपने सामूहिक नित आर आमसम्मानके लिए कान्त सहते हैं। ग़दशाहके प्रति उफ़ादारी ग़दशाहके ग़दशाहके प्रति उफ़ादारी चाहती है।

भारतीयों! स्वतंत्र हो!

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८४ प्रिटोरियाकी लड़ाई^२

जोहानिसबर्ग,

शुक्रवार, २ बजे

[जुलाई २६, १९०७]

अन्तिम समाचारमें मातूम हाता है कि अनमतिपत्र कार्यालयमें पजीयनके लिए अभीतक एक भी अर्जी नहीं दी गई है, परन्तु ऐसी अफवाह है कि अनमतिपत्र अधिकारी एक निजी मकानमें पजीयनके लिए रातका अर्जियाँ लेने लगे हैं।

शुक्रवारका दिनमें भारतीयोंकी एक सभा बुलाई गई थी। उसमें यह बताया गया कि कानूनके सामने न झुकनेके लिए हर वैधानिक रीतिमें समझानका प्रयत्न किया जायगा। उसके बाद सभी अपनी मर्जीका मतान्विक चर सकत ह। एक निजी मकानमें रात्रिके समय पजीयनके लिए अर्जियाँ दना और अनमतिपत्र अधिकारियोंका इस प्रकारमें चलना कठकनी वान है। सभा जेलके बाहरमें दृढ है तथा उसे उसाहमें काम कर रही है।

नगरके मुख्य स्थानमें सरकारने बहिष्कारके भित्तिपत्रको^३ उखड़वा डाला है। अनमतिपत्र कार्यालयके द्वारपर लगे हुए भित्तिपत्रन ग़ना मजा दिया। सरकारके यह पूछवानेपर कि भित्तिपत्र किसने बनाया है, उसकी सारी जिम्मेदारी श्री ग़ा सीने अपने मिर ठे ली है।

१ इस सन्देशके भित्तिपत्र बनावामक प्रतिरोध सघर्षके दिनोंमें प्रिटोरियामें लगाये गये थे। सरकारने उनको प्रमुख स्थानोंसे हटवा दिया था और उनके खेलकूदके सम्बन्धमें पूछताछ की थी। उनका उत्तरदायित्व गांधीजीने स्वीकार किया था। देखिए अगला शीर्षक।

२ यह 'विशेष तार द्वारा प्राप्त ताजा समाचार' शीर्षकसे प्रकाशित किया गया था।

३ देखिए पिछला शीर्षक।

तारीख ३१को विराट सभा होगी। सारे कारोबार बन्द रखने हैं। विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं। इसके लिए एक समय समिति नियुक्त की गई है। जैसा पहले कहा गया था, चार दिन तक दूकानें बन्द नहीं रखनी हैं। पजीयनपत्र ले लेनेकी अवधिका अंत निकट आ रहा है, इसलिए गम्भीरता हर क्षण बढ़ती जा रही है। महीना पूरा होनेसे पहले सम्भव है जानने योग्य कई नई-नई बातें सामने आये।

डबनके हमदद भाइयोकी ओरसे हिम्मत और मदद देनेके सम्बन्धमें ढेरके ढेर तार आये हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८५ “मानवजातिका विस्मय”

कहा जाता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति क्रूगरने^१ एक शक्तिशाली साम्राज्यके साथ असमान लड़ाई छेड़कर ‘मानवजातिको विस्मित कर दिया’ था। उहीके भूतपूर्व देशमें — यद्यपि वह अब नामभरको ब्रिटिश है — ट्रान्सवालके भारतीयों द्वारा इतिहास दोहराया जायेगा। लेकिन यह तुलना पूर्ण रूपसे सही नहीं है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एक रक्तरंजित युद्धमें लड़े थे। ट्रान्सवालके भारतीय एक बूढ़ खून गिराये बिना ही मानवजातिको विस्मित कर देंगे। हम बिना किसी अनादर भावके कहना चाहते हैं कि भारतीय भूतपूर्व राष्ट्रपतिसे भी अधिक करके दिखानेवाले ह। अपने सम्मानके लिए — कुछ लोग इसे निरी भावुकता कह सकते हैं — वे अपना सर्वस्व ‘योद्धावर करनेको तैयार हैं। उनका यह दान विधवाका सा श्रेष्ठ और अक्षय दान होगा।

बहुत से मित्र कहते हैं कि स्थानीय सरकार एशियाई अधिनियमको हर तरहसे लागू करनेपर तुली हुई है और उनकी बुरीसे-बुरी आशकाओके सही उतरनेकी सम्भावना है। भारतीय इसके जवाबमें कहते हैं कि वे इस सम्भावनाके लिए तैयार हैं। उन्हें जेल भेजेगे? वे तयार ह। उन्हें जबरदस्ती देश निकाला देगे? इसके लिए भी वे तैयार हैं। वे अपराधियोंकी तरह जिये और ईश्वरके सामने विश्वासघाती बने, इससे तो कुछ भी, यहातक कि — मौत भी ज्यादा अच्छी होगी।

हो सकता है कि वे गुमराह हो और उनका ध्येय वास्तवमें सही न हो। अगर ऐसा है तो वे फिर उसी उदाहरणका सहारा लेते हैं, जिसका हमने उल्लेख किया है, और जवाब देते हैं कि यद्यपि बहुत से लोगोके विचारसे भूतपूर्व राष्ट्रपति क्रूगरने ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध खड़े होकर बड़ी गलती की थी, तथापि उनमें अपने विश्वासोपर दब रहनेका साहस था इस लिए प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है। इतना ही काफी है कि वे एक ऐसे ध्येयके लिए लड़े जिसे वे सही समझते थे। लेकिन राष्ट्रपति पुरानी धर्म पुस्तिका (ओल्ड टेस्टामेंट) की प्रेरणाके अनुसार उसी पवित्र ग्रन्थके वीरोके आदर्शपर लड़े थे। भारतीय, जो इस देशमें ईमानदारीकी रोजीकी खोजमें आकर बसे ह और जिनके सामने नागरिक और सामाजिक विनाश मुह बाये खड़ा है, नई धर्म पुस्तिका (न्यू टेस्टामेंट)की प्रेरणासे लड़ रहे हैं। दुनियाके सबसे बड़े अनाक्रमक प्रतिरोधी कर्णावतार ईसा उनके आदर्श हैं। अगर ट्रान्सवालके शासक

उनके प्रस्तावोंको ठुकरा देते हैं, अगर उनके परम प्रभु सम्राट् एडवर्ड, महमूद गजनवीकी^१ तरह, उनकी रक्षा कर सकनेमें अपनेको असमर्थ घोषित करते हैं, तो इसमें उनका क्या बनता-बिगड़ता है? इसका ठुकराया गया, उन्हें चोरा और डाकुओंके साथ ऐसी मौतका भय दिखाकर जो उनके उत्पीड़काकी दृष्टिमें लज्जाजनक थी, उनमें ईश्वर निंदा करवानेका प्रयत्न किया गया, फिर भी क्या उन्होंने अतनक उसका विरोध नहीं किया? लेकिन काटाका ताज उस लहलुहान मस्तरूपर आज जितना फट रहा है उतना बढ़ियामें बढ़िया हीरामें जड़ा ताज भी किसी सम्राटके मस्तरूपर नहीं फटता। वे मरे इसमें शक नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वरके सच्चे भक्ताकी स्मृतिमें वे आज भी जीवित हैं, और उसके साथ वे चोर भी जीवित हैं, जिन्होंने उस वित्तमय नाजरवानामी आर उसके उपदेशोंको ग्रहण किया था।

इसी प्रकार, ट्रान्सवालमें भारतीय, अगर वे अपने परमात्माके प्रति सच्चे बने रहें तो अपनी उन सन्तानों और देशवासियोंकी स्मृतिमें जीवित रहेंगे, जो उनके इस क्षण भंगुर समारोहों को छुड़ जानेपर कह सकेंगे कि “हमारे बापदादाने राटीके एक टुकड़े के लिए हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया।”

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८६ श्री पारसी रुस्तमजीकी उदारता

श्री रुस्तमजीने^१, जिनका नाम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका बच्चा बच्चा जानता है, हमें एक मार्कैका पत्र गुजरातीमें लिखा है। उसका अनुवाद हम नीचे देते हैं

यद्यपि मैंने अक्सर ट्रान्सवालमें रहनेवाले अपने देशवासियोंकी दशाके बारेमें अपने विचार जनताके सामने प्रकट किये हैं, फिर भी शायद आप मुझे अपने पत्र द्वारा उह प्रकट करनेका मौका देंगे। ट्रान्सवालके भारतीय जिम संघमें लगे हुए हैं, उसमें फरका दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय भागीदार होगा। हम ठोग, जो उस देशमें बाहर हैं उनके शारीरिक कष्टोंमें सम्भवतः हिस्सा नहीं बँटा सकते। उन्हें सिर्फ जेलकी ही मसीबने नहीं अलसी पड़गी बल्कि बहुतेराका अपना सवस्व गँवा देना होगा। अगर हम जल नहीं जा सकते तो कमसे कम उनके उच्चादशका अनुकरण करके सवसाधारणकी भलाईमें अपनी माल मिल्कीयत तो कुर्बान कर ही सकते हैं। इसलिए मैं, पूरा नम्रताके साथ और ईश्वरका साक्षी रखकर, ट्रान्सवालमें रहनेवाले अपने देशवासियोंका सूचित करता हूँ कि मेरा यह आन्तरिक अभिलाषा है कि मैं उनके दुःखमें हाथ बटाऊँ, इसलिए आजमें इस दुनियामें माल मिल्कीयतके नामपर मेरे पास जा कुछ भी है वह सब तबतक ट्रान्सवालमें रहनेवाले मेरे देशवासियोंकी धरोहर होगी, जबतक कि इस संघर्षका अन्त न हो जायेगा। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकामें मेरे

१ सन् १९७ ई० में गजनीकी रक्षिण बैठनेके बाद उसने भारतपर १७ बार बढाई की, किन्तु अपनी विजयको स्थायी नहीं बना सका। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९०।

२. नेटालके प्रमुख भारतीय व्यापारी, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५।

बहुत से मित्र अपना कतव्य समझकर ट्रासाबलके भारतीयोंको इसी प्रकारकी आर्थिक सहायता देनेको तैयार हैं। सचमुच, प्रिटोरियाने हमारे दिलोको आशासे भर दिया है। हमें भरोसा है कि वहाँ बसनेवाले और ट्रान्सवालके दूसरे हिस्सोमें रहनेवाले हमारे देशवासी अपने सकल्पको अततक निबाहेगे।

इस पत्रसे सारी बातें स्वयं ही प्रकट हैं। हम तो सिर्फ अपनी रायके तौरपर इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग श्री रस्तमजीको जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इस वचनका अर्थ कितनी बड़ी ठोस सहायता है। यह ऐसा पत्र है जिससे प्रत्येक भारतीयका हृदय नये साहस और उमंगसे भर जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८७ श्री आदमजी मियाँखॉकी मृत्यु^१

गुलाम हुसैन मियाखा ऐड कंपनी, डबनकी पेढीके मालिक और नेटाल इंडियन कांग्रेसके उपसभापति श्री आदमजी मियाखाका, इसी महीनेकी २० तारीखको अहमदाबाद, भारतमें ४१ वर्षकी अपेक्षाकृत अल्पायुमें देहांत हो गया। श्री आदमजी गत फरवरीमें भारतकी यात्राको गये थे और डबनमें उनके भाईको उनके पत्र नियमित रूपमें मिल रहे थे। किंतु किसी गम्भीर बीमारीकी शिकायत नहीं मिली थी। श्री आदमजीने नेटालके भारतीय समाजकी बड़ी सेवाएँ की हैं और उनकी भलाईसे सम्बन्धित सभी मामलोमें उनकी योग्य तथा स्वेच्छाजनित सहायताकी कमी बहुत महसूस की जायेगी। गुजरातकी राजधानीमें गोटाकिनारीके व्यापारियोंके एक प्रसिद्ध घरानेमें जन्म लेकर, श्री आदमजी मियाखा अपने पिता और अपने भाई श्री गुलाम हुसैनके साथ १८ वर्षकी आयुमें, सन १८८४ में, दक्षिण आफ्रिकामें आकर बस गये थे। उनके अग्रेजी ज्ञानने भारतीयों और अनेक यूरोपीय मित्रोंके बीच प्रसिद्धि प्राप्त करनेमें उनकी बड़ी सहायता की थी। किंतु भारतीय सावजनिक मामलोसे उनका निकट सम्पर्क १८९६ से पहले नहीं हुआ था। कांग्रेसके तत्कालीन अवैतनिक मंत्रीके कुछ दिनोंके लिए अलग हो जानेपर श्री आदमजी, अपने काय और सुनहले गुणोंके कारण कांग्रेस द्वारा अवैतनिक मंत्रीके रूपमें काय करनेके लिए सवसम्पत्तिसे निर्वाचित हुए। उनके इस कायकालमें श्री अब्दुल करीम हाजी आदम झवेरीने बड़ी योग्यतापूर्वक उनकी सहायता की। श्री आदमजीने कांग्रेसकी पूँजीको १०० पौंडसे बढ़ाकर १,१०० पौंड कर दिया और १८९६ के अंतमें तथा १८९७ के आरम्भमें, जब प्रसिद्ध भारतीय विरोधी प्रदर्शन डबनमें हुआ तब श्री आदमजी अपने वैय, शान्ति और दृढ़तासे समाजकी गम्भीर कठिनाइयोंका सामना करनेमें सहायक हुए।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८८ आदमजी मियाँखाँका शोकजनक अवसान

ईश्वरकी गति गहन है। हमारे प्रसिद्ध नेता श्री आदमजी मियाँखाँको स्वदेश गये हुए केवल पाँच ही महीने हुए हैं। इनने हमें खबर आई है कि वे पीठके फाँटने २० दिन जीसकर रहकर २३^१ तारीखको अचानक अहमदाबादमें चल बसे। नेताजी और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागमें जा उनके नाम और काममें परिचित होंगे वे इस शोक समाचारमें दुःखी हुए बिना नहीं रहेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें ऐसा समय आता जा रहा है जहाँ देशमें उनकी आवश्यकता दिनादिन महसूस होगी। ऐसे समयमें श्री आदमजी मियाँखाँ जैसे एक दक्ष और जीउटवाले नेताके अवसानसे जा क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना मुश्किल है। उनका स्वदेशाभिमान और दूसरे मूल्यवान् सदगुण सर्वविदित हैं। कांग्रेसके कायदाहक मंत्रीके रूपमें तथा बादके मावजिनिक जीवनमें उन्होंने बुद्धि, शान्ति, तपस्या और आत्मबलिदान आदि सदगुणोंका जा परिचय दिया वह सब सबक लेने योग्य हैं। स्वदेश छोड़ने समय उनके सम्मानमें किये गये समारम्भामें उनकी शक्तिप्रियता प्रकट हुई थी। दक्षिण आफ्रिकाके कानून लिए भारतमें भी आज उठाने का उनका इरादा था। ऐसे लोकप्रियकारी सज्जनको केवल ८१ वर्षकी आयुमें मृत्यु हो जाना हमें बहुत दुःख है। हम हृदयमें चाहते हैं कि मतात्मा परमेश्वरका शान्ति मित्र, तथा उनपर श्रद्धा रखनेवालोंमें अनुरोध है कि वे उनका विधात सदगुणोंका अनुकरण करें।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

८९ खुदाई कानून

खूनी कानूनकी तारुत बननेका समय नजदीक आता जा रहा है। पहली जगन्तको सरकार क्या करती है, उसे देखनेके लिए हमें भारतीय चिन्तातुर रहना चाहिए। जेफ़रसन मानवमें चिन्ताके वजाय हिम्मतके साथ बैठना चाहिए। खूनी कानूनमें बचनेके लिए दूसरा चाल जितने दुःख भागने पड़े, उन्हीं सुख रूप समझना चाहिए, और हर भारतीयका यही मनाना चाहिए कि “मेरे भाइयोंका दुःख दूर करनेके लिए मुझे पहले जेल हो तो भले हैं।”

खूनी कानूनके सामने न झुकनेके कारणोंकी तो हम बहुत खानबीन कर चुके हैं। खूनी कानूनका विरोध करते हम खुदाई कानूनको मानते हैं, यह समझने जैसी बात है। खूनी कानूनके सामने झुकनेमें पाप है, उसी प्रकार खुदाई कानूनको भग करनेमें पाप है। खुदाई कानूनके सामने झुकनेवाला इस दुनियामें और दूसरी दुनियामें सुख भोगेगा। वह खुदाई कानून वहीना है? वह है सुख भागनेके पहले दुःख भोगना, और चूँकि परमात्ममें स्वायत्त है इसलिए दूसरेके लिए हम आत्मबलिदान करें, दुःख उठाएँ। उसके थोड़े उदाहरण लें

मिट्टी धूल बन जानेपर पानीके साथ मिलकर साग-सब्जी पैदा करती है, और साग-सब्जी अपने-आपका बलिदान करके प्राणि मात्रका पोषण करती है, प्राणी अपना बलिदान करके

अपने पीछे आनेवालेको सुख देता है। बच्चा पैदा होनेके पहले मा असह्य दुःख भोगती है और उस दुःखको भोगनेमें ही वह सुख मानती है। मा और बाप दोनों बच्चेके लालन-पालनमें कष्ट सहते हैं। जहाँ जहाँ कोमे और प्रजाएँ बसी हूँ वहाँ वहाँ उस उस प्रजा तथा उस उस कौमके लोगोने प्रजा हितमें दुःख सहन किये हैं। बुद्ध, ईसाके ६०० वर्ष पूर्व, जगल जगल भटकें, उन्होंने सर्वों गमीकी परवाह नहीं की, दुःख उठाया और ज्ञान प्राप्त करके लोक कल्याण किया। १९०० वर्ष पहले ईसा मसीहने ईसाई समाजकी मायताके अनुसार अपना जीवन लोगोको समर्पित करके बहुतसे अपमान और अर्थ दुःख सहन किये। मुहम्मद पैगम्बरने बहुत दुःख झेले। लोग उनकी जान लेनेको भी तयार हो गये थे। उसकी उम्हो परवाह नहीं की। इन सब महान और पवित्र पुरुषोने खुदाई कानूनके सामने झुककर मनुष्य समाजको सुख पहुँचाया। उन्होंने अपना स्वाथ नहीं देखा, बल्कि दूसरोके सुखमें अपना सुख माना।

राजनीतिक मामलोमें भी यही होता है। हैम्बन, टाइलर, क्रामबेल वगैरह अंग्रेज इंग्लैंडकी प्रजाके लिए अपना सबस्व बलिदान करनेको तयार हुए। उनकी सम्पत्ति लुटी, उनकी जान खतरमें पड़ी उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। इसीलिए अंग्रेज प्रजा आज इतने बड़े साम्राज्यपर राज्य कर रही है। ट्रान्सवालके शासनकर्ता राज्य भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देखते देखते बहुत दुःख उठाये हैं। मैजिनी अपने देश इटली के लिए निर्वासित हुआ। आज वह पूज्य है। वह इटलीका राष्ट्रनिर्माता माना जाता है। जाज वाशिंगटनने अपार मुसीबतें उठाकर अमेरिकाका निर्माण किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि सुखके पहले बिना दुःख भोगे काम नहीं चलता। लोक कल्याणके लिए मनुष्यको आजीवन दुःख भोगना पड़ता है।

और आगे चले। अपनी टेक छोड़ना और हमें जो मर्दानगीका गुण दिया गया है उसे छोड़ना, भी पाप है। यूसुफ अबेसलाम व्यभिचारसे बचनेके लिए जेल गया। इमाम हसन^१ और हुसैनने^२ यजीदकी^३ सत्ता स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसमें अधम था। अपनी टेक रखनेके लिए वे शहीद हुए। अपनी टेक रखनेके लिए भक्त प्रह्लादाने धधकते हुए खम्भेको हिम्मतके साथ पकड़ा था। बालक सुधवा खौलती हुई कड़ाईमें बिना विचार किये लपककर कूद पड़ा था। सत्यके लिए हरिश्चन्द्र नीचके घर बिका था। उसने राजपाट छोड़ा और स्त्री पुत्रका वियोग सहन किया। पिताके वचनके लिए रामचन्द्रने बनवास भोगा। और हकके लिए पाण्डव चौदह^४ वर्ष तक राजपाट छोड़कर वनमें भटके।

आज ट्रान्सवालमें ऐसे ही महान खुदाई कानूनको पालनेकी जिम्मेदारी भारतीय समाजके सिर आई है। यह समझकर हम अपने भाइयोको बधाई देते हैं। उनके हाथमें सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको मुक्त करनेका अवसर आया है। ऐसा महान सुख महान दुःख भोगे बिना कैसे मिल सकता है? हमारी अर्जी अब मानव समाजके पाम नहीं, खुदाके — ईश्वरके — पास है। वह चौबीस घंटे सारी बातें सुनता है। अर्जी सुननेके लिए हमें उससे समय नहीं मागना है, न कभी मागना ही पड़ता है। वह सबकी अर्जी एक साथ सुनता है। उसीपर भरोसा रखकर, निडर होकर, उसीका नाम स्मरण

१-२ ये अर्लीके पुत्र थे जो पैगम्बरकी पुत्री फातिमासे उत्पन्न हुए थे।

३ खलीफा, ६८०-८३। हुसैनने इसके खिलाफ बगावत की थी, किन्तु वे कर्बलामें पराजित हुए और मारे गये।

४ तेरह।

करते हुए अगस्त महीनेमें जो कुछ हो उसे सहन करनेके लिए हमारे भाई ट्रान्सवालमें तैयार रहे, यह हम अति पवित्र मनमें ईश्वरमें मागते हैं।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

१० अलीकी भूल

इस बार श्री रिचके पत्रके साथ श्री अलीने 'यायमूर्ति अमीर अलीके नाम जो पत्र भेजा है वह भी आया है।' सोना पत्र पढ़ने और विचार करने योग्य है। इन पत्रोंको प्रकाशित किया जाये या नहीं, हमारे लिए यह प्रश्न था। आखिर विचार करनेपर देखा कि देशहितके लिए हमें उसे प्रकाशित करना ही देना चाहिए। यह समय इतना नाजुक है कि किसी व्यक्तिके मतपर क्या असर होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यही सोचना है कि जनसाधारणका भला किस तरीकेसे हो।

हम मानते हैं कि श्री अलीने 'यायमूर्ति अमीर अलीके नाम पत्र' लिखनेमें उतावरी और भूल की है। समितिकी आरम्भमें वह पत्र, जिसमें जेल भिजवानेवाली लड़ाई न लड़नेकी सलाह दी गई थी, क्या आया, उसका कारण अब समझमें आ सकता है। श्री अलीने पत्रपरमें समितिने विचार किया कि हममें मतभेद है और यदि मतभेद है तो हाई भी व्यक्ति, जिसे पूरी बात न मालूम हो, यही सलाह देगा कि हम जेल भिजवानेवाली लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। वास्तवमें कोई मतभेद नहीं था, तब 'यायमूर्ति अमीर अलीका' उस पत्र लिखनेकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जनसंग्रहवाधामें मित्रोंके सम्प्रधान किमीन लापरवाही नहीं की, बल्कि ब्रिटिश भारतीय सघने पूरी मेहनत की। इतना करनेपर भी जब उन महाशयने मिलनेमें इनकार कर दिया तब उनमें एक लिखित निवेदन किया गया कि भारतीय समाजको माँग स्वीकार को जानी चाहिए।

सारे भारतीय व्यापारी मसलमान हैं और सभी फेंगेवाले हिन्दू, वगैरह टीकाको हम जहरी समझते हैं। ऐसी शब्द श्री अलीकी कलममें निकले, इसमें हम कौमकी बेइज्जती देखते हैं। ट्रान्सवालकी लड़ाई हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए एक समान है। दोनोंके हक डूबते हैं। और विचार करनेपर हम देख सकते हैं कि व्यापारियोंके बिना यह लड़ाई शांति भी नहीं दगी। भारतीयोंके पीछे ऐसा सूनी कानून लगा हुआ है कि जितने ज्यादा इज्जतदार उतनी ही ज्यादा मसीबत। जिस इज्जतकी जितनी ज्यादा परताह है, वह कानून उसके द्वारा उतना ही ज्यादा धिक्कारा जान योग्य है। अब हिन्दू मुसलमानका प्रश्न ही नहीं उठता। इतना ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकामें दोनों धर्मोंके बीच कोई बड़बुहाट नहीं है। कुल मिलाकर सब हिलमिलकर रहते हैं। इस स्थितिमें समितिका, जो उपयुक्त बातें लिखी गई हैं, उनका भारतीय कौमके लिए हम बहुत ही बुरा परिणाम देखते हैं। इसलिए यह पत्र छापकर तथा उसपर यह टीका करके हम सब भारतीयोंको चेतावनी देते हैं कि जब हमारे लिए स्वतन्त्र होनेका समय आया है तब कोई यह स्वप्नमें भी खयाल न करे कि हिन्दू और मुसलमानोंके बीच फूट है या फूट डालनी है।

इस विषयकी खुली चर्चा करके हम श्री अलीका दिल दुखाना नहीं चाहते। जिनका उनसे मतभेद हो उन्हें उनपर गुस्सा करनेके बजाय उनकी भूलके लिए उनपर दया करनी चाहिए। इसका मुरय्य हेतु यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सावजनिक काममें भाग ले उसे एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि चाहे जो हो, वह ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता जिससे सब लोगका नुकसान हो। साथ ही हम श्री अलीको सलाह देते हैं वे अपनी भूल ठीक करे।

उपयुक्त पत्रोंसे हम यह भी देख सकते हैं कि यदि श्री अलीका पत्र न जाता तो समितिकी ओरसे हमें रोका नहीं जाता। फिर भी समितिकी सलाह इस समय हमारे लिए बेकार है, यह बात हमारे लिए सदा याद रखने योग्य है। रणमें जानेवाले घरमें बैठनेवालोंकी सलाह नहीं सुन सकते। हमें अब अपने बलपर जूझना है। यदि यह कानून हमें पापस्वरूप जान पड़ता है तो हमें समिति या दूसरे कोई भी सलाह दे, हम पाप नहीं करने लगेंगे। हमें हिसाब समितिको नहीं, खुदाको देना है।

[गुजरातासे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

९१ केपके भारतीय

केप ससदका नया चुनाव, सम्भव है, कुछ ही समयमें ही जायेगा। केपके काले ओर गेहुँए लोग अपन मताधिकारका किस प्रकार उपयोग करेंगे, इस प्रश्नकी चर्चा हो रही है। यह चर्चा सिर्फ केपमें ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोंमें भी हो रही है। हमें जो-कुछ कहना है, वह विशेषकर भारतीय मतदाताओंके लिए है।

हम मानते हैं कि केपके भारतीय मतदाताओंने केप तथा अन्य जगहोंमें भारतीयोंकी स्थितिमें सुधार करनेका अवसर बहुत बार खोया है। प्रसंग आनेपर यदि मताधिकारका ठीक सा उपयोग न किया जा सके तो वह अधिकार किसी कामका नहीं। केपके काले लोग और भारतीय लोग यदि अपने मताधिकारकी कीमत समझें तो वे आज भी कई परिवर्तन करवा सकते हैं।

इस सम्बन्धमें पहले तो इतना याद रखना जरूरी है कि काले और भारतीय लोगोंके मत हमेशा एक ही पक्षमें गिरे, ऐसा कोई नियम नहीं है। दोनोंको अलग अलग प्रकारके हक चाहिए। दोनोंकी लड़ाई भिन्न प्रकारकी है। जैसे केपका प्रवासी कानून भारतीय समाजको रोकनेवाला है, उसका काले लोगोंपर कम प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार व्यापारका कानून केवल भारतीयोंपर ही असर करता है। इसके अलावा काले लोगोंकी जमभूमि दक्षिण आफ्रिका है, इसलिए उन्हें हमसे ज्यादा अधिकार हैं। १८५८ की घोषणाके कारण तथा भारतीयोंकी सभ्यता चूँकि बहुत पुरानी है इसलिए वे काले लोगोंकी अपेक्षा अधिक दृढ़ताके साथ अधिकार मांग सकते हैं। वैसे परस्पर लाभ दोनोंको है, इसलिए भारतीय समाज किस प्रकार मत दे, इसपर अलगसे विचार करना है।

दूसरी बात यह याद रखनी है कि मतदाता किसी एक या दूसरे पक्षको मत देनेके लिए बाँधा हुआ नहीं है। कभी-कभी तो यह होता है कि मत न देकर बहुत जबरदस्त असर डाला जा सकता है। हमें मालूम है कि डबनके इने गिने भारतीय मतदाताओंने एक बार मत

बिगुल न देनेका निणय किया था। उसका असर इतना हुआ था कि एक बड़े अधिकारीने उन्हें बुराकर कुछ आरामन दिये थे जोर उनका पालन भी किया गया था।

उपयुक्त दाता दाताको यानम रखकर हम कपटी स्थितिपर विचार कर सकन ह। कपम दा दल है। बौद्ध या डच, प्रगतिशील (प्राग्रेमिक) या ब्रिटिश और विद्वानों (फारन)। हमें स्वीकार करना होगा कि उन दाता दशम इस समय ता इतनी समानता है कि कठोर और कृडम क्या होगा? दाता एक ही कूचीसे रगे गये हैं। दातामन किमोका भी काठ व्यक्तिन प्रति स्नेह नहीं है। स्पर्धायी श्री राडमने^१ जो वचन दिया था उसपर प्रगतिशील दलन पाना फर दिया है। हम कपके भारतीय समाजका सलाह देते हैं कि व दाता पश्चात्क प्रमुखासे लिखकर पूछ कि व प्रबामी कानून तथा व्यापार कानूनम अमुक परिवर्तन कर सकन है या नहीं। जा वगटक और प्रामाणिकतापूर्वक साफ साफ बात कह, उन्हें मन दिये जाये। किन्तु यदि दाता स्पष्ट उत्तर देनेम आगे पीछे दर, व्यक्तिगत रूपम एक बात कह और सावजनिक रूपम दूसरी, ता वम कपटी रोगाका कतई उद्धार नहीं दिया जाये, और साफ कह दिया जाय कि गम्भी स्थितिम भारतीय समाज किमोका भी मन नहीं दगा।

उस तरह करनेम हम विश्वास हैं कि भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा प्रहेगी और दातामम एक दर, उस प्रार नहीं ता अगरी वार निश्चय ही वचन दगा। हमारी नेपके भारतीयाम प्राप्तता है कि उह उस प्रार अपने भठर लिए ही यह काम करना है। गार यदि उनक मित्र हा अथवा व पाच सात भागीयारा कुछ आराम दना चाहते ह ता उसकी व परवाह न कर। शितता जोर क्या माँगा जाये, उसका विचार दूसरी प्रार करण।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

९२. धर्मपर हमला

पाठशाळाग्राम हम भिखाया जाता है कि अंग्रेजी राज्यमे

जहर चरा गया, बैर चला गया और काला कहर भी चला गया। दूसरी जानिक लाग दशकी जानियामे मेलजोल करके इस समारम चल रहे हैं। दर लो, रास्ते चलनी हुई नेचारी प्ररीका भी काई पान नहीं पकड़ता। हे भारत, यह ईश्वरका उपकार मानकर अब तू खुशी मना।^१

परन्तु अब इस कविताको निम्न प्रकार बदलकर गाना चाहिए या गा सकने है

विषाकी भरमार हा गई है और बैर बढ़ता ही चला जा रहा है, दूसरी जानिक लाग दशक लागाम समारमे दुश्मनी करने चल रह है। देख लो, कोई भी

१ ऐफ्रीकांडर बॉड ।

२ (१८५३-१९०२), केप कालोनीक प्रधान मंत्री, १८९०-९६ ।

३ क्षेर गया ने वेर गया, बळी काळकिर गया करता,

पर नातीळा बातीळा थी, सप करी चाळे ससार ।

देख बिचारी बकरीनो पण, कोई न जाता पकड़े कान,

ये उपकार गणी ईश्वरनो पण, हरख हवे तुं हिन्दुस्तान ।

बेचारी बकरीके कान जबरदस्ती पकड़ लेता है। इस सबका विचार करके हे भारत, अब तू हिम्मतके साथ कुछ उपाय कर।^१

नेटाल रेलवेके मुरय प्रबन्धकका जो पत्र हमने देखा है उसपरसे हमें ऐसा विचार आ रहा है। उस पत्रमें मुरय प्रबन्धकने लिखा है कि अंग्रेजों अथवा गोरे पादरियोंको जैसे रियायती दरपर रेल टिकट दिये जाते हैं वैसी रियायत भारतीय पादरियोंको आइदा नहीं दी जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय पादरी हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई भी हो तब भी रियायती टिकट नहीं मिलेगा।

ट्रांसवालसे ये और एक कदम बढ़ गये। अब भारतके ईसाई भी गोरे ईसाइयोंसे पथक हो गये। इसे हम अच्छा शकुन मानते हैं। क्योंकि ऐसे दुखों और अपमानोंके कारण हम सारे भारतीय सदा एक दूसरेसे मिलकर रहेगे।

एक ओरसे देखनेपर श्री रासका पत्र थोथा है। दो-चार भारतीय पादरियोंको रियायती टिकट मिले तो क्या और न मिले तो क्या? किन्तु दूसरी ओरसे देखे तो यह मामला बड़ा गम्भीर है। दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंको हर प्रकारसे तिरस्कृत करके निकाल देनेकी जो तजवीज की जा रही है, उसके उदाहरणके रूपमें श्री रासके इस पत्रको मानकर उसका पूरे तौरसे विरोध करना चाहिए। भारतीय समाज और भारतीय धर्माका अपमान करनेमें यहांके गोरे जरा भी आगे पीछे नहीं देखते।

हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्बन्धमें मुस्लिम सघके अध्यक्ष श्री पीरन मुहम्मदने श्री रासको पत्र लिखा है और आवश्यक कदम उठाये हैं। श्री राससे सतोषप्रद उत्तर आनेकी सम्भावना है। यदि ऐसा हो तो भी उसमें फूलने जसी कोई बात नहीं।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुक्तिकी डोर ट्रांसवालके भारतीयोंके हाथमें है। वे यदि अपनी टेक बनाये रखकर जोर दिखायेंगे तो श्री रास और गोरे लोग भारतीयोंका अपमान करना भूल जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

- १ शेर बंधाने बेर बंधा बली कालाकेर बंधा करतार,
पर नातीला जातीला थी, बेर फरी चाले ससार।
देख बिचारी बकरीनो सङ्ग जोर करीने पकड़े फान,
पेवी रयाल करी हिम्मत थी उपाय कर तुं हिंदुस्तान।

९३ ईस्ट लन्दनको चेतावनी

इस्ट लन्दनक भारतीय एक गिगलमण्डल केप ठ गये थे। उसक नामके सम्बन्धमे विलायतक अखबारमे तार छपा ह। उसमे यह कहा गया ह कि 'कुछी भारतीय' के नियन्त्रणक लिय कानून बनाय जान चाहिए, इस बातका भारतीय समाज स्वीकार करता ह। किन्तु वह इज्जतदार भारतीयाके लिए छूटके विशेष कानूनकी माग करना हे। उसमे यह भा कहा गया हे कि जैम काफिराको छूटक पत्र मिलते है वैसे कुछ भारतीयाका भी दिये जाय।

हम नही मानत कि इस्ट लन्दनके भारतीयाने ऐसी कोई माग की होगी। हमारे दुमन ता ऐसी भूतकी प्रतीक्षाम हो बैठे हुए है। क्याकि हम यदि ऐसा भेदभावपूर्ण कानून मांग ठ ता वह ता जपन हाथा अपने पैरापर कुल्हाटी मार्गके समान हागा। अच्छे और बुर लागक बाच दुनियामे सदा ही अतर रहा हे, और रहगा। किन्तु अच्छे कौन और बुर बौन, नाच कौन और ऊच कौन, यह मर्यादा कानून नही नाय सकता। आज जा फेरी ठगाना हागा वह बल व्यापारी उन सकता ह। व्यापारी गरीब उन सकता है और नौकरी कर सकता है। यह होता ही रहता ह। उसमे 'कुछ' कौन कहलायेगा? भेद कैम रह सकता ह? ऐम भेद कौन कर सकता ह? गाँव आँखानीक हाथमे ऊँच या नीचवा टीरा लगान कौन जायगा? हम निश्चित माठूम हाता ह कि कानून भेद बरतकर कुछ भारतीयाका छूटक पत्र नही दे सकता। बसा करना अपने हाथा गुलामीको निमन्त्रण दनके समान हागा।

[गुजरातीमे]

इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९०३

९४ रूसका उदाहरण

हमार पाठकाका मालूम ह कि रूसके जारने ड्यूमा,^१ यानी ससद, की स्थापना की है। अग्रजी अग्रमराम अभी यह खबर प्रकाशित हुई है कि ड्यूमाके बहुतेरे सदस्य देशहितके लिए कैद अथवा निवासन भाग चुके है। इसलिए इस ससदका प्यारका नाम 'कैदियोंकी सभा' भी है। ड्यूमाके सदस्याक चुनावमे ठोगाने जेलस लौट हुए ठोगाका ज्यादा पसन्द किया। य कोई बिना पढे लिख या ग्रामीण नही, बल्कि विद्वान लाग है। कोई-कोई बडे वकील और चिकित्सक है। उनमे एक श्री गोबर्नाफ नामक सदस्य है। उन्हे मौत तक की सजा हुई थी। श्री सिम्ब्रमकका अनेक वर्षोंके लिए साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया था। ऐसे लोगोके चुने जानेसे रूसके शासक बहुत बार नाराज होते है। किन्तु सदस्य

१ इसकी स्थापना १९०५ में की गई थी। इसके सदस्य सीमित मताधिकारक आधारपर चुने गये थे। १९१७ में इसे तोड़ दिया गया था।

तथा उनके निर्वाचक इसकी परवाह नहीं करते। डीमिट्रिअस पर्लेशिन नामक एक सदस्य सरदार घरानेके हैं। उन्होंने दो वर्ष जेलकी सजा भोगी है। ऐसे हम अनेक नाम दे सकते हैं। किन्तु पाठकोके लिए उपयुक्त नाम काफी हैं। इतना और याद रखना है कि रूसकी जेले सचमुचमे कारागृह हैं। उनमे कोई सुविधा नहीं होती। इसके अलावा रूसमे सर्दी बहुत ही सख्त होती है। जेलर बड़े दुष्ट होते हैं। किन्तु ये बहादुर लोग जनताकी भलाईके लिए सब कष्ट सहते हैं। सर्दी गर्मीकी परवाह नहीं करते। उनके सम्राट खुश होंगे या नाराज, इसकी परवाह नहीं करते। किन्तु जिसमे उन्हें अपने देशका कल्याण दिखाई देता है उसे बेधडक किये जाते हैं। इतना होनेपर भी रूसी लोगोको स्वतंत्रता नहीं मिली, इससे वे घबडाते नहीं हैं। अपना कतव्य पूरा करते जा रहे हैं, और वह भी इस भावनासे कि आखिर वे नहीं नोग सके तो उनके बादमे आनेवाली पीढ़ी उनके कष्टोके लाभ भोगेगी और रूस स्वतंत्र होगा।

ऐसे बलवान स्वदेशाभिमानी पुरुषोके उदाहरण सामने रखकर, खुदाकी ओर मुह करके उसके नामको निरंतर अपने मनमे स्मरण करते हुए, ट्रान्सवालके भारतीय खूनी कानून रूपी वैतरणीको पार कर जायेगे, यह हमारी कामना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

९५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

खूनी कानून

इस अकके प्रकाशित होते समय जुलाईके चार दिन बाकी रहेगे। इसके बादके अकके लिए इस आशयके तार फीनिक्स भेजनेकी आशा करता हूँ कि नये पजीयनपत्र न लेनेके कारण सरकारने भारतीयोको पकडना शुरू कर दिया है। किन्तु यह मानना गलत न होगा कि जैसे मैं आशा कर रहा हूँ वैसे कुछ लोग डर भी रहे होंगे।

प्रिटोरियासे प्रार्थना

इस बीच प्रिटोरियाके भाइयोसे मैं विनती करता हूँ कि अबतक आपने अपनी और भारतीय कौमकी इज्जत रखी है, ऐसे ही अततक रखिए। मुझे विश्वास है कि प्रिटोरियामे एक भी ऐसा भारतीय नहीं निकलेगा जो आखिरी दिन अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी नरकसे कलकित होकर आयेगा। वहा कलकके सिवा और कुछ नहीं मिलना है। इसे ठीक मानकर मैं समझता हूँ कि कोई वहा स्वप्न मे भी जानेका विचार नहीं करेगा।

आगे क्या होगा ?

इस प्रश्नका मैं भिन्न-भिन्न अवसरोपर उत्तर दे चुका हूँ। किन्तु फिर भी देना ठीक समझता हूँ। जुलाईमे जो बहादुरी दिखाई गई वह एक प्रकारकी है। अगस्तकी बहादुरी दूसरे प्रकारकी है। जुलाईमे हमे घर सँभालकर बैठनेकी हिम्मत दिवानी थी। अगस्तमे हमे पकडकर जब न्यायाधीशके पास ले जायेगे तब हिम्मतसे जवाब देना है। अदालतका

नाम आते ही हम डरते हैं। हमें अदालतमें खड़ा किया जायेगा तब क्या होगा? उस समय हिम्मत रखना अधिक मुश्किल है, फिर भी विलकुल आवश्यक है।

पुलिस पकड़ेगी

पहले तो पहली अगस्तका किमी एक्का अथवा सभी भारतीयोंको नये पजीयनक लिए अर्जी न देनेके अपराधमें गिरफ्तार कर सकते हैं, सभी अपनी टेकका पता चर जायेगा।

जमानत न दी जाये

इस बार सभी भारतीयोंका याद रखना है कि गिरफ्तार किये जानेवाला जमानत देकर नहीं छूटना है, न किसीका छुड़वाना है। जेल महलकी तालीम यहीसे शुरू होगी। पकड़े गये भारतीयोंको उसी दिन या दूसरे दिन मजिस्ट्रेटके पास ले जाया जायेगा।

बचावका प्रश्न

सम्भावना यह है कि पजीयनकी अर्जी न देनेके सम्बन्धमें उसपर मुकदमा चलाया जायेगा। उस वक्त यदि वह व्यक्ति सच्चा अनुमतिपत्रवाला होगा या लप्का होगा, जिसे अनुमतिपत्रकी जरूरत नहीं हानी, तो उस व्यक्तिका श्री गांधी त्रिना शुल्कके बचाव करेंगे। वे तथा श्री ईसप मियाँ प्रयात दग कि भारतीय कौम शपथ और प्रस्तावके कारण नये कानूनक सामन न झुकनक लिए बँधी हुई है। अभियुक्तने वह प्रस्ताव स्वीकार किया है। और यदि किसीका सजा दी जानी चाहिए तो वह पहले सचक पदाधिकारियोंको दी जानी चाहिए। बादमें यदि अभियुक्तक लिए बयान देना आवश्यक हुआ तो उसे कहना है कि नया पजीयन करवानका उसका इरादा नहीं है, वह सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कौमक प्रस्तावका आदर करना है, बल्कि इसलिए कि उस खुदका कानून पसन्द नहीं है और इसलिए नया पजीयनपत्र लनेका इरादा नहीं है, किन्तु यदि सरकार जेल भेजेगी तो वह जेल जायेगा। जर्मनी भी वह नहीं देगा।

बचावका तरीका

उपर्युक्त बचाव किया जानेके कारण शायद ईसप मियाँ तथा श्री गांधीका पहले पकड़ा जाये और अभियुक्त छूट जाये। किन्तु यदि ऐसा न हो तो अदालत निश्चय ही अभियुक्तको सजा देगी। अदालतका जुरमाना करनेका अधिकार है। अतः शायद वह जुरमाना कर, और जुरमाना न देनेपर वह जलम भजा जाये।

जुरमाना न दिया जाये

यह विलकुल याद रखना चाहिए कि इस बार जुरमाना न देकर जेल जाना है। मेरी सलाह है कि कोई भी भारतीय पहली अगस्तसे अपनी जेबमें, जहाँतक सम्भव हो, पैसे न रखे और सोना तो कभी न रखे। लालच बुरी चीज है। जेलकी आदत न हानेके कारण जुरमानेकी आवाज सुनकर अभियुक्तके हाथ अनजाने जेबमें चले जायेंगे और उसकी नजर अपने दोस्तोंपर पड़ेगी। ऐसा हो तब भारतीयोंको मनमें तत्काल खुदासे माफी माँगकर सावधान हो जाना चाहिए और जेबमें से हाथ निकालकर गला साफ करके कहना चाहिए कि मुझे जुरमाना नहीं देना है। मैं कारावास भोगूँगा। साथमें यह भी याद रखा जाये कि विलायतकी

बूढ़ी और जवान औरतोंने आधे क्राउनका^१ जुर्माना देनेसे इनकार करके अधिकारके लिए कारावास पसन्द किया है।

दूसरे क्या करे ?

हम सामान्यतः मान ले कि सारे भारतीयोंको एक साथ तो पकड़ा ही नहीं जायेगा। अतः जेलके बाहर रहनेवाले क्या करे ? इसका उत्तर सरल है। जो भाई हिम्मत करके जेल गया है उसे बधाई दे, उसके सगे सम्बन्धियोंकी मदद करे और स्वयं डरकर पजीयन लेनेके लिए जानेके बजाय यह प्रार्थना करे कि दूसरी बार जेल जानेका सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो।

श्री गांधीको ही पहले पकड़ा जाये तो ?

ऐसा हो तो बचाव करनेका कोई काम नहीं रहता। उनपर मुकदमा चलेगा तब साफ हो जायेगा। और यदि उनके जेल जानेके बाद अथवा निर्वासित किये जानेके बाद भारतीय समाज कानूनका विरोध करनेवाले प्रस्तावपर डटा रहेगा तो तुरन्त ही नतीजा सामने आयेगा। चाहे जिस व्यक्तिको जेल हो, चाहे जिसका निर्वासन हो, भारतीय समाज दब बना रहेगा तभी आजतक की लड़ाईकी शान रहेगी।

यदि पजीयन पत्र लिये गये तो ?

किन्तु यदि भारतीय समाज डरकर पजीयन पत्र ले लेगा अथवा जुर्माना देकर जेलसे बच जायेगा तो आजतक की लड़ाईपर पानी फिर जायेगा। यह निश्चय हो जायेगा कि हमारा साहस मिथ्या था। और माना जायेगा कि नेता लोग केवल भडकानेका काम करते थे। आजतक जो चमक दमक दिखाई दे रही थी वह ऊपरी कलाई थी। वह कलाई खुल जायेगी और जाहिर हो जायेगा कि हम सच्चा सोना नहीं, बल्कि ताबा है और हमारी कीमत पाईके बराबर हो जायेगी।

सरकारके दूसरे हथियार

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि सरकार यह इलजाम लगानेके बजाय कि नये पजीयनके लिए अर्जी नहीं दी, दूसरे कदम भी उठा सकती है। जैसे मौजदा अनुमतिपत्र व पजीयनपत्र तो सबके रद्द हो गये हैं। इसलिए उनपर बिना अनुमतिपत्रके रहनेका आरोप लगाया जा सकता है। यदि यह आरोप लगाया जाये तो, जैसा मैंने पहलेके पत्रोमे कहा है, पहला मुकदमा चलते समय अभियुक्तको अमुक समयमे देश छोड़नेकी सूचना मिलेगी। उस अवधिमे यदि देश न छोड़े तो उसे कमसे कम एक महीनेकी सजा हो सकती है। इस प्रकार मुकदमा चले तब भी बचाव तो ऊपर लिखे अनुसार ही किया जायेगा। ऐसे मुकदमेकी सूचना मिलनेपर किसीको चले नहीं जाना है, बल्कि सूचनाकी अवधि पूरी करके गिरफ्तार होकर जेल जाना है।

क्या व्यापारी डरे ?

इसमे बड़े व्यापारियोंको डरना नहीं है। एक ही दूकानके सभी व्यक्तियोंका एक साथ पकड़ा जाना सम्भव नहीं है। दूकाने लुटवा दी जाये सो भी नहीं होगा। अधिकसे

अधिक नुकसान यही होगा कि कुछ दिन दूकान बन्द रहगी। इसके अलावा आर कुछ भी होना सम्भव नहीं। किन्तु सब व्यापारी अपना स्टॉक वगैरह ले रखे, इसमें बुद्धिमानी मानी जायेगी। इसका उद्देश्य केवल इतना ही कि लेनदार व्यापारी अधीर हो तो उनका हिस्सा तुरन्त साफ किया जा सके।

मण्डलोका कर्तव्य

इस बार ट्रांसवाल तथा ट्रांसवालके बाहरके मण्डल, जैसे मघ, काग्रेम, वगैरहमा कर्तव्य है कि सावजनिक तौरसे फिरसे सहानुभूतिके प्रस्ताव पास करे, गिरफ्तारगुदा व्यक्तिके पीछे रहनेवाले लोगोंकी सार-सँभाल करनेके लिए पैसे भेजे, और देश परदेशमें यथासम्भव इस आन्दोलनकी चर्चा करे।

‘संडे टाइम्स’ का प्रश्न

‘संडे टाइम्स’ के सम्पादकने कानूनपर टीका करते हुए पूछा है कि जिन लोगोंने अगस्त महीनेमें नया पजीयनपत्र न लिया हो उन्हें जेलमें बन्द करनेके लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है? क्या नये जेलखाने बनायेगी? यह प्रश्न मजाकके रूपमें पूछा गया है। किन्तु इसमें यह भी प्रकट होता है कि वे भारतीय समाजके आन्दोलनसे घबड़ा रहे हैं।

मिडलबर्गके भारतीय

मिडलबर्गके भारतीय वस्तीको बहाकी नगर परिषदने फिरसे निकालनेका प्रस्ताव किया है। उसका यह इरादा है कि किमी एक भारतीयपर मुकदमा चलाकर देख लिया जाये कि नगर-परिषदका अधिकार है या नहीं।

चेतावनी

कुछ भारतीयोंके मनमें यह विचार है कि यदि एक भी भारतीय नया अनुमतपत्र ले लें तो फिर दूसरेका रखना कठिन है। ऐसे सोचनेवाले, साफ हैं, लडाईको नहीं समझते। एक आदमी कुएँ गिरेगा या बुरा काम करेगा तो क्या उसके पीछे सारा समाज कुएँ जा गिरेगा या बुरा काम करने लगेगा? यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर नया कानून, जाकि बुरा है, भौड़ा है, कुएँस ज्यादा भयानक है, उसमें कैसे गिरा जा सकता है? इसके अलावा, यह मान लेना कि एक भी भारतीय गुलाम नहीं बनेगा बहुत ही ज्यादा अपेक्षा रखना है। यदि भारतीय समाजमें इतना जोश हो तो आज दक्षिण आफ्रिकामें या दूसरी किसी भी जगह उसका हलका दर्जा क्यों होगा? इतना याद रखना चाहिए कि इस लडाईमें हर भारतीयको अपनी स्वतंत्र बुद्धिका उपयोग करना है। एक-दूसरेके मुँहकी ओर नहीं देखना है। नया पजीयनपत्र कोई लड्डू नहीं है जिसे यदि एक छू ले तो दूसरे उसपर टूट पड़े। जबतक इस बातका ध्यान नहीं रखा जाता जबतक हमारी जीत कभी नहीं होगी। इसे अच्छी तरह लिख लें। मैं तो यह सलाह देता हूँ कि यदि कोई भारतीय अपनी नामर्दी या कमजोरी या अज्ञानके कारण नया पजीयनपत्र बिना लिये न रह सके तो उसे अपनी उस कमजोरीको मजूर करना चाहिए और दूसरेको वैसा न करनेकी सलाह देनी चाहिए तभी ठीक माना जायेगा।

प्रिटोरियाकी सभा

प्रिटोरियामे मंगलवार शामको विशेष सभा की गई थी। उसमे श्री रूज वकील भी हाजिर थे। उन्होने कहा कि जनरल स्मट्स यह जाननेके लिए आतुर ह कि उनके पत्रका क्या असर पडा। उन्हे वहम है कि भारतीय नेता जनरल स्मट्सके पत्र जाहिर नही करते। इसलिए सभाकी क्या राय है, यह जाहिर हो तो अच्छा। श्री गांधीने श्री रूजको 'इंडियन ओपिनियन' देकर बताया कि जनरल स्मट्सके पत्रका अथ प्रत्येक भारतीयके सामने पेश किया जा चुका है। वह श्री रूजने श्री स्मट्सको बतानेके लिए कहा। इस सभामे श्री गांधीके अलावा जोहानिसबर्गसे श्री ईसप मिया और श्री उमरजी सालेजी आये थे।

श्री गांधीने श्री स्मट्सके पत्रका अनुवाद करके सुनाया और सभाको सलाह दी कि कोई भी व्यक्ति नये कानूनके सामने हरगिज न झुके।

श्री हाजी हबीबने यह प्रस्ताव किया कि यदि जनरल स्मट्स श्री रूजके पत्रमे व्यक्त की गई मागको स्वीकार नही करेगे तो नया कानून कभी नही माना जायेगा। इसके अलावा उन्होने जनरल स्मट्सके साथका पत्र व्यवहार प्रकाशित करनेकी सूचना दी। श्री हाजी हबीबके प्रस्तावका श्री सूजने समर्थन किया। श्री अयूब बेग मुहम्मद तथा श्री उमरजीने भी समर्थन किया। श्री रूजने भाषण देते हुए बताया कि कानून स्वीकार किया जाना चाहिए और फिर जो माग करनी हो वह कायदेसे करनी चाहिए। इतना होनेपर भी श्री हाजी हबीबका प्रस्ताव सर्वानुमतिसे पास हुआ।

सभाने इतना जोर दिखाया है। फिर भी दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे स्थिति जरा गम्भीर होती जा रही है। अन्ततक सारा समाज सावधान रहेगा या नही, इस सम्बन्धमे तक-वितक होता रहता है।

इस समय सब भारतीयोको एक बात याद रखनी है कि चाहे जितने लोग नया अनुमतिपत्र ले, जिनमे हिम्मत है वे तो कभी न ले।

स्मट्सका इरादा

श्री स्मट्सने उत्तरमे कहा है कि तटवर्ती अनुमतिपत्र कार्यालयकी जरूरत है। इतने दिन तक अग्नेज सरकार हस्तक्षेप करती थी इसलिए पुराने डच कानूनोपर अमल नही होता था। अब अग्नेज सरकार हस्तक्षेप नही कर सकती। अत जो 'कुली' एक दफा बाहर जायेगा वह वापस न आ सके, इसके लिए तटवर्ती कार्यालयकी जरूरत है। इस तरहके जवाब होते हुए भी भारतीय समाज नये कानूनको स्वीकार करता है, तो उससे बुरा और क्या होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०७

९६ पत्र उपनिवेश-सचिवको'

प्रिटोरिया
जुलाई २७, १९०७

सेवामे

माननीय उपनिवेश सचिव

प्रिटोरिया

महोदय,

मेरी समितिका यह जानकर खेद हुआ है कि सरकारी कमचारी एशियाइयोंके पजीयनके आवेदनपत्र बहुत रातमे और व्यक्तिगत दूकानों या दूसरी जगहोंपर ले रहे हैं। मेरी समितिको यह भी पता चला है कि यह तरीका सरकारको दी गई इस आशयकी दरखास्तोंकी बिनापर अख्तियार किया गया है कि जो ब्रिटिश भारतीय अधिनियमके अन्तर्गत आवेदन दना चाहते हैं उनको मारपीट आदिकी धमकी दी जाती है।

मेरी समिति जहाँतक जानती है, समाजके किसी भी उत्तरदायी सदस्यने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है। समितिकी कारवाई अधिनियमकी धाराओंको स्वीकार करनेमे जो अप्रतिष्ठा और हानि है उसका बताकर जोरदार प्रचार करने तक ही सीमित है।

यह स्वीकार किया जायेगा कि स्वयमेवकोने सेवाव्रत ही निभाया है। मेरी समितिने खुलमुखुल्ला और जोरदार शब्दोंमे ब्रिटिश भारतीयोंको सूचित कर दिया है कि अगर कोई सदस्य आवेदन दना चाहता तो उसे किसी प्रकारकी हानि न पहुँचाई जायेगी, बल्कि यदि वह चाहेगा तो, पजीयन कार्यालय तक सुरक्षित पहुँचा दिया जायेगा।

समितिकी विनम्र रायमे, उन भारतीयाने, जिन्होंने गुप्त रूपसे और रातमे आवेदन दिये ह, ऐसा इसलिए किया है कि जिस बातको, समाजके दूसरे सदस्योंके साथ-साथ, उन्होंने भी अपने सम्मानके विरुद्ध माना है, उसको वे दूसरे ब्रिटिश भारतीयोंसे छिपा सके।

मेरी समितिकी विनम्र रायमे, दफ्तरके वक्तके बाद और निजी दूकानामे गुप्त रूपसे पजीयन कराना, यदि गैरकानूनी न भी हो, तो भी, गौरवास्पद नहीं माना जा सकता। कुछ भी हा मरी समिति सरकारका सादर आश्वासन देती है कि भारतीय समाज जिस सघटका अपने जीवन और मृत्युका सघटका मानता है उसम डगने धमकानेका या एमे उपायाका, या किसी भी तरह निन्दनीय माने जाये, आश्रय देनेका कोई विचार नहीं रखता।

आपका, आदि,
हाजी हबीब
अवैतनिक मंत्री,
ब्रिटिश भारतीय समिति

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९०७

१ स्ते अनुमानत गांधीजीने तैयार किया था।

९७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[जुलाई २९, १९०७]

नया कानून घोर विश्वासघात

मुझे लगता है कि जितने खेदके साथ मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूँ, उतने खेदसे मैंने शायद ही कोई चिट्ठी लिखी हो। मैं जो खबर देनवाला हूँ वह दू या नहीं, यह भी विचारणीय प्रश्न बन गया है। फिर भी मैं समझता हूँ कि, यदि हमें सत्यकी रक्षा करनी हो और बहादुर बनना हो तो प्रिटोरियाके भारतीय समाजमें जो एक घटना हो गई है उसका लेखा मुझे लेना ही होगा।

जुलाईका अन्तिम सप्ताह दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय समाजको बहुत याद रहेगा। जहाँ यह आशा थी कि हमारे जीतनेका समय साफ आ गया है, वहाँ भारतीय समाजके साथ विश्वासघात हुआ है और यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि जीत होगी भी या नहीं। बुधवार तारीख २४ को रातको १० बजेके बाद प्रिटोरिया स्टेशनपर अनायास इस धोखेकी खबर मिली। श्री गांधी आनेवाले थे और उन्हीं मिलनेके लिए श्री काछलिया, श्री व्यास, श्री बेग और दूसरे भारतीय हाजिर थे। उन्हें पता लगा कि श्री खमीसाकी दूकानमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसमें गोरे हैं, और दूकानके पास खुफिया पुलिस है। यह खबर पाते ही उपर्युक्त सज्जनोंने सोचा कि श्री खमीसाकी दूकानका दरवाजा खटखटाया जाये और यदि दरवाजा खुले और वहाँ नये कानूनके सामने झुकनेकी कोई कारवाई हो रही हो तो उन्हें समझाया जाये। श्री गांधीने दरवाजा खटखटाया। श्री व्यासने भी खटखटाया। एक व्यक्तित्वने आकर पूछा कौन है? श्री गांधीने जवाब दिया और अदर आनेकी इजाजत मागी। दरवाजा किसीने नहीं खोला। इस बीच खुफिया पुलिसका एक आदमी आया और उसने कुछ पूछताछ शुरू की। श्री बेगने आवेशसे जवाब दिया। फिर श्री गांधीने उससे बात की। इसपर उसने कहा “आप कानून जानते हैं। जो ठीक हो वह कीजियेगा।” यो कहकर वह चला गया। कुछ मिनट बाद वह और दूसरे दो अधिकारी आये। इस बीच श्री व्यास श्री हबीबको लेने गये थे। खुफियाने उपर्युक्त लोगोमें से प्रत्येकपर हाथ रखकर वहासे रास्ता नापनेको कहा। सब चले गये। सब समझ गये, श्री खमीसाकी दूकानमें जरूर कुछ दगा शुरू हुआ है।

सारी रात बहुतेरे भारतीय जागते रहे। गुरुवारको सवेरे सारे भारतीय समाजमें खल बली मच गई। गाव गाव पत्र और तार भेजे गये। कहा जाता है कि श्री खमीसाकी दूकानमें आधी रातको करीब बीस व्यक्तियोंने अपने हाथ और मुँह काले करके भारतीय समाजको बट्टा लगाया है।

इसमें दोष किसका ?

यह प्रश्न सब भारतीयोंके मनमें उठेगा। मैं स्वयं मानता हूँ कि जिन्होंने पंजीयनके लिए अर्जी दी है, उन्हें हम निर्दोष नहीं कह सकते। नया कानून अच्छा है और उसके

सामने झुकनेमें जरा भी अपमान नहीं है यह समझकर यदि वे खुले आम गुलामीका पट्टा लेनेके लिए अर्जी देने जाते तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। किन्तु उन्होंने बहुत ही लज्जाजनक काम करनेकी बात सोची और इसीलिए चोरीमें रातका अनुमतिपत्र लेना चाहा। इसमें सिद्ध होता है कि उन्हें अपने अपराधका पता था और इसलिए वे भारतीय समाजके प्रति अपराधी हैं। किन्तु जैसे उपयुक्त भारतीय दोषी हैं वैसे ही और उसमें भी ज्यादा दोषी अफ़्रीकागियोंका माना जा सकता है। ठागोकी दूकानोंमें जाकर रातको चोरीमें अर्जी देनेमें सिद्ध होता है कि वे लोगोंको नये कानूनके सामने झुकानेकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और यदि लागू न झुके, तो उन्हें डर है कि उनकी स्थितिको धक्का पहुँचेगा। यदि सरकार इस हद तक गिरती है और उसमें यदि ठोस गलतचले फँसते हैं तो उसमें आश्चर्य ही कौनसा?

जलेपर नमक

इस प्रकार चोरीसे पजीयन करनेका कारण यह बताया गया मातूम होता है कि भारतीय समितिने धमकी दी है कि जो लागू नये पजीयन पत्र लेगे उन्हें नुकसान पहुँचाया जायेगा। यह इल्जाम सरासर झूठ है। दगाबाज लोगोंने पजीयन पत्र लेनेके साथ ही अपनी निरुज्जता ढाकनेके लिए सारे समाजपर यह गलत आरोप लगाया है, और असत्य गढ़ा है।

हाजी हबीबका पत्र

यह इल्जाम सहन करके बैठा नहीं जा सकता, इसलिए श्री हाजी हबीबने उपनिवेश सचिवके नाम निम्नानुसार पत्र लिखा है^१

किन्तु धुरेमें से अच्छा

इस प्रकार विश्वासघात हुआ है फिर भी चूँकि भारतीय समाजकी लार्ड सच्ची है, इसलिए जान पड़ता है कि उसमें भला ही हुआ है। चोरीमें अनुमतिपत्र लेनेमें निर्दोष भावनामें जानेवाले एक अब्दुल करीम जमाल नामक भारतीय भी थे। उन्होंने भय तथा प्रलोभनके वशमें अनुमतिपत्रकी अर्जी दी थी। किन्तु चूँकि वे दगाबाज दलमें नहीं थे इसलिए उन्हें अर्जीमें झूठे तथ्य देनेके अपराधमें पकड़ लिया गया है। उन्हें १०० पौडकी जमानतपर छाड़ा गया है। उनपर मुकदमा चलेगा। इससे सारा प्रिटोरिया आतंकित हो गया है। भारतीय समझ गये हैं कि नये कानूनके अंतर्गत अनुमतिपत्रके लिए अर्जी देनेसे केवल यही डर नहीं है कि अनुमतिपत्र नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चे कैदीकी जेल भागनेका भी समय आ सकता है। श्री अब्दुल करीम जमालने अपराध किया या नहीं, यह बात अलग है। किन्तु इतना तो साफ है कि निरपराध लोगोंको घसीटनेमें भी देर नहीं लगेगी। यह कानून इतना भयकर है। और इस कानूनसे मुक्त रहनेमें ही प्रतिष्ठा और सुरक्षा है। यह मामला सबके लिए चेतावनी स्वरूप है। गुलामीका पट्टा लेनेके बाद भी कोई ट्रान्सवालमें रह ही सकेगा इस सम्बन्धमें कोई विश्वास नहीं दिला सकता।

“दया धर्मको मूल है”

इस प्रसिद्ध दोहेकी याद करके उन लोगोके साथ दया बरतनी चाहिए जिन्होंने भारतीय समाजके साथ विश्वासघात किया है। हमारे मनमें रोष आना स्वाभाविक है। किन्तु उस रोषको दबाकर हमें यही समझना चाहिए कि उन्होंने अज्ञानवश काला दाग लगाया है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि इस लड़ाईमें हमने किसी भी भारतीयपर हाथ उठाया अथवा किसीको नुकसान पहुँचाया तो उससे सारी लड़ाईको धक्का पहुँचेगा। इस विचारके सिलसिलेमें मुझे खेदपूर्वक बतलाना होगा कि श्री खमीसाने अपने प्रत्येक भारतीय देनदारके नाम सदेश भेजा है कि यदि वह सोमवारको सवेरे गुलामीके नये पट्टेके लिए अर्जी न दे तो उसपर जो रकम निकलती हो वह चुका दे। नहीं तो उसपर तत्काल समन्स जारी किया जायेगा। इससे खलबली मच गई है। किन्तु श्री ईसप मिया, श्री अस्वात, तथा श्री उमरजीने श्री खमीसाको समझाया, इसलिए उन्होंने अपनी सूचना वापस लेना स्वीकार कर लिया है।

सहानुभूतिके तारोकी वर्षा

प्रिटोरियामें प्रमुख भारतीयोके नाम तार आया ही करते हैं। कोई-कोई विश्वासघातकी सख्त टीका करते हैं। श्री पारसी रुस्तमजी तथा डबनके स्वयसेवकोने हर स्वयसेवकको बधाईके तार भेजे हैं। नाइयोकी ओरसे नाइयोके नाम दृढ़ रहनेके लिए तार आये हैं। उसी प्रकार बलेर, टौगाट, डेलागोआ बे, डडी, लेडीस्मिथ, एस्टकोट केप टाउन आदि विभिन्न स्थानों और विभिन्न व्यक्तियोंकी ओरसे तार आते ही रहते हैं।

आज सोमवारकी शाम तक किसी भी भारतीयने अनुमतिपत्र कार्यालयसे अनुमतिपत्र नहीं लिया।

हमीदिया सभा

जोहानिसबगकी हमीदिया इस्लामिया अजुमनके सभाभवनमें रविवारको एक भारी सभा हुई थी। उसमें बहुत उत्साह दिखाया गया था। श्री पोलकने सारी बातें समझाईं। इमाम अब्दुल कादिर बावजीर सभापति थे। मौलवी हाजी अब्दुल मुस्तारने एक लम्बा और प्रभावशाली भाषण दिया। उपयुक्त सभामें पजीयनपत्र लेनेवालोके कामको दगाबाजी और फन्देबाजी कहकर उसकी बहुत ही छीछालेदर की गई। श्री पोलकने बताया कि सम्भव है अब जोहानिसबगकी बारी आयेगी, इसलिए हमें स्वयसेवक नियुक्त कर देना चाहिए। फलतः कौन कौन लोग स्वयसेवक बननेको तैयार हैं, यह पूछा गया। इसपर नवाबखान जमालदार सबसे पहले आगे आये और उन्होंने जोशीला भाषण दिया। बादमें निम्नलिखित नाम दिये गये

मुहम्मद हुसैन, मीर अफजुलखान काबुली, नुरुद्दीन, इमामुद्दीन, जामाशाह, साहेबदीन, मूसा मुहम्मद, अलीभाई मुहम्मद, ईसप दासू, अलीभाई इस्माइल, उमर हसन, मूसा आन दजी, रामलगन, अली उमर, इस्माइल मुहम्मदशाह, मुहम्मद इस्माइल, सुलेमान आमद सूरती। इतने नाम आ जानेके बाद यह घोषित किया गया कि और नाम नहीं चाहिए। सभामें बहुत उत्साह था।

मद्रासियोंकी सभा

मद्रासियोंने उसी दिन शामको सभा की। उह भी श्री पोलकने ठीक तरहसे समझाया। लागाम बहुत उत्साह ओर जाश है। सब यही कहते हैं कि दूसरे लोग कुछ भी कर, वे स्वयं तो नये पजीयनपत्र ठेकर कठक लगाना कभी स्वीकार नहीं करगे। स्वयमेवकाके रूपमे सभामे श्री पी० के० नायडू, डब्ल्यू० जे० आर० नायडू, एस० मैथ्यूज, एम० लिंगम्, डी० एन० नायडू, एम० कुमार स्वामी, एम० जीरामामी, तम्ब्री नायडू, एम० पी० पडियाची, आर० के नायडू, आर० दण्डपाणि, के० रे० मामी, क० एन० दादशानी, जे० के० देमाई, वगैरह आगे आये थे।

डर्बनसे आनेवालोंको चेतावनी

फोक्समस्टमे एक भाईने सूचित किया है कि नेटालकी आगमे आनेवाले लोगके पजीयन-पत्र व अनुमतिपत्र अधिकारी ठे लेते हैं और फिर लोगाने कहते हैं कि वे अपने अनुमतिपत्र प्रिटोरियामे ले ले। यह बिल्कुल अनुचित है, और लागामे रखमे डालनेवाला तथा उन्हें अनुमति कार्यालयमे जानेके लिए मजबूर करनेवाला है। अतः सभी भारतीयोंको सूचना दी जाती है कि फिलहाल ट्रान्सवालमे कोई न आये। उपयुक्त बात नये कानूनसे निकलनी है। इसपरसे नये कानूनकी वागीकियापर विचार करना जरूरी है।

फ्रीडडॉपके भारतीय

फ्रीडडॉप अध्यादेश तुरन्त नहीं लागू किया जायेगा इतना ता निश्चित है। किन्तु यह न समझा जाये कि इसमे भारतीयोंका निश्चित लाभ हुआ है। क्योंकि वह अध्यादेश गोरे साहबोंको पसन्द नहीं है। इसका द्वारा जा अधिकार प्राप्त हो रह है उनसे पर्याप्त नहीं है, इसलिए अधिक मांगते हैं। वे अधिकार सरकारने देने स्वीकार किये हैं। इसीलिए अध्यादेश नया बनेगा। उसमे भी भारतीयोंके अधिकार सुरक्षित नहीं है। तृतीकी आवाज सुननेवाला कोई है ही नहीं। फ्रीड डॉपके डच गरीब हैं, फिर भी उह निर्वाचन अधिकार है, और व शमशेर बहादुर हैं। अतः उनके लिए सब कुछ किया जायेगा। भारतीयोंको मताधिकार भी नहीं है। गमगर ता देखी भी नहीं होगी। किन्तु यदि वे हिम्मतके साथ खूनी एगियाई अधिनियमको जेलरूपी अग्निम जरा दे ता उनकी कीमत जरूर हो सकती है। नहीं ता भारतीयोंके हक राम नाम बोल जायगे इसमे मुझे तो जरा भी शर नहीं।

लोकसभामें एशियाई कानून

स्थानीय अवधारामे ऐसा तार छपा है कि बड़ी ससम्मे सर विलियम बुलने ट्रान्सवालके भारतीयोंके सम्बन्धमे प्रश्न पूछा था। उत्तरमे श्री चर्चिलने सूचित किया कि ऐसा मालूम हुआ है कि पजीयनमे अंगुलियाकी गिनतीके सिवा कोई चारा नहीं है। लॉर्ड एलगिनने ट्रान्सवालके रुखपर खेद प्रकट किया किन्तु उन्हाने बताया कि ट्रान्सवालकी ओरसे यह हो जानेके बाद कि गिनाइतक इस तरीकेमे आपत्ति करने जैसी कुछ बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं फिरसे विचार करनेके लिए दबाव डाल सकंगा।

लॉर्ड एलगिनने खेद व्यक्त किया इसमे साफ मालूम होता है कि वे स्वयं इस कानूनको सख्त मानते हैं। अतः जब भारतीय जेल जायेंगे, उनकी सहानुभूति भारतीयोंकी ओर रहनी चाहिए।

रेलवेमे तकलीफ

ब्रिटिश भारतीय सघके कायवाहक मंत्री श्री पोलकके हस्ताक्षरसे निम्नलिखित पत्र रेलवे अधिकारीके पास भेजा गया है

सघके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी और श्री गुलाम मुहमदको एक तार मिला था। इसलिए जरूरी कारणसे उहे कल ४-४० की रेलसे प्रिटोरिया जाना था। किंतु उहे टिकट देनेसे इनकार कर दिया गया। मेरा सघ इसका निश्चय करनेको आतुर है कि कही रेलवे विभाग भारतीय समाजके आम हकोपर अब विशेष अकुश तो नहीं लगाना चाहता? इस सम्बन्धमे जाच पडताल करनेकी कृपा करे।

रेलगाडियोकी तकलीफोका यह ताजा उदाहरण साफ बताता हे कि अधिकारियोकी आख खोलनेके लिए किसी भी भारतीयको जेल जानेका अवसर हाथसे नहीं छोडना चाहिए। जबतक यह न दिखा दिया जायेगा कि भारतीयोमे पानी है तबतक सम्भव है, ये सारे कष्ट दिनोदिन घटनेके बजाय बढ़ते ही रहेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९०७

९८ भाषण प्रिटोरियामें

[प्रिटोरिया

जुलाई ३१, १९०७]

श्री गांधीने कहा कि श्री हॉस्केनने^१ अध्यादेशके बारेमें बहुत सी बातें समझाई ह। उन्होंने इस सफ्टके समय भारतीयोके साथ सहानुभूति भी प्रकटकी है। परंतु उनका खयाल है कि यद्यपि हमारे सघका आरम्भ सही विचारोसे हुआ है, तथापि हम गुमराह कर दिये गये ह, हमें अध्यादेशको मान लेना चाहिए, अर्थात् अध्यादेशके पीछे छिपी जबदस्ती तथा दसो अँगुलियोकी छापवाले हुक्मके सामने भारतीयोको अपना सर झुका देना चाहिए। श्री हॉस्केनने अपनी इस सलाहकी पुष्टिमे बहुत-सी दलीलें दी ह। उनमे से एक यह भी है कि जो बात अवश्यम्भावी है, उसे मान लेना चाहिए। श्री गांधीने आगे कहा म इस अवश्यम्भावी^२ बातकी दलीलको लेकर ही कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा खयाल है और म इस बातको बहुत गहराईसे महसूस करता हूँ कि न तो श्री हास्केन और न पश्चिमी जातिका कोई सदस्य यह समझ सकता है कि पूर्वके मानसमें 'अवश्यम्भावी' का वास्तविक अर्थ क्या है, और यह बात म अत्यंत नम्रताके साथ कह रहा हूँ। श्री हॉस्केनने हमें बताया है कि एशियाई पजीयन कानूनके पीछे गोरे निवासियोके लोकमतका

१ एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र देनेकी अन्तिम तारीख ३१ जुलाईको प्रिटोरियामें सारे ट्रान्सवाल्के ब्रिटिश भारतीयोकी एक सभा हुई थी। गांधीजीके भाषणकी तार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट ३-८-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें छपी थी यह उसकी पूरी रिपोर्ट है।

२ विलियम हॉस्केन जनरल बोथोके अनुरोधपर समामें आये थे और उन्होंने भारतीयोसे कहा था कि सरकार अध्यादेशको लागू करनेकी नीतिपर दृढ़ है।

३ देखिए 'श्री हॉस्केनकी अवश्यम्भावी', पृष्ठ १५१ ५२।

बल है, इसलिए उसको पलटा नहीं जा सकता। उसके सामने झुकना ही होगा। परन्तु मैं उसे अवश्यम्भावी नहीं मानता। अवश्यम्भावी तो यह है कि जिन ब्रिटिश भारतीयोंको इस देशमें मताधिकार नहीं है, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिनके प्राथनापत्र रद्दीकी टोकरीमें फेंक दिये जाते हैं और जिनके लिए विधान-सभामें एक आदमीने भी अपनी आवाज नहीं उठाई है — और तो और खुद श्री हाँस्केन भी जिनके पक्षमें एक शब्द नहीं कह सके, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें सुसंगठित और ठोस विरोधका मुकाबला करना पड़ेगा — वे भारतीय इस कानूनका विरोध करे। ऐसी स्थितिमें अवश्यम्भावी है, ईश्वरकी इच्छाके सामने ही अपना सर झुका देना। अगर उसकी यह इच्छा है कि पूरेके-पूरे १३,००० भारतीय अपने सवस्वका बलिदान कर दें, इस ससारमें हमें आर्थिक लाभ पहुँचानेवाली जो भी चीजें हूँ उन सबको छोड़ दें, तो भारतीयोंको इस नियतिके सामने सर झुकाना है। परन्तु इस अपमान और नीचे गिरानेवाले कानूनको हरगिज नहीं मानना है। श्री हाँस्केनके प्रति पूण आदर रखते हुए भी मेरा विचार है कि वे अपनी चमडीका रंग नहीं बदल सकते। और न ही वे इस देशमें रहनेवाले भारतीयोंको उनके जीवन-मरणके प्रश्नके सम्बन्धमें सलाह दे सकते हैं।

मैं इस देशमें तेरह वर्षसे रह रहा हूँ और अपने देशभाइयोंकी सेवा करता आया हूँ (करतल ध्वनि)। मैं अपने-आपको दक्षिण आफ्रिकाके शान्ति प्रेमियोंमें गिनता हूँ। और बहुत सोच विचार और सलाह-मशविरेके बाद ही मने यह धम-युद्ध छोड़ा, अपने देशभाइयोंको इसमें शामिल होनेकी सलाह दी। मने एशियाई कानूनकी एक एक धारा पढ़ी है और उपनिवेशके प्रायः सारे कानून भी पढ़ लिये हैं। उसके बाद ही मैं विचारपूर्वक इस निश्चयपर पहुँचा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस निणयको बदलूंगा, क्योंकि यदि एशियाई इस कानूनको मान लेते हैं तो उनकी स्थिति शुद्ध गुलामोंकी सी हो जायेगी। इससे जरा भी कम नहीं।

तो कैसे? जब मैं लन्दनमें था तब श्री हाँस्केनके देशभाइयोंको मैंने एक मिसाल सुनाई थी। मैंने कहा था, “यहाँ राह चलता हर आदमी एक रेशमका टोप पहनता है। अब मान लीजिए कि लन्दनमें इस आशयका एक कानून जारी किया जाता है कि हर अंग्रेजके लिए रेशमका टोप पहनना अनिवार्य होगा तो क्या सारा लन्दन टोप पहनना छोड़ नहीं देगा?” वहाँके मित्रोंके सामने मने यही स्थिति रखी थी। यह एक बहुत तुच्छ-सा उदाहरण है। यहाँ यह केवल एक प्रकारका टोप पहननेकी बात है। परन्तु अंग्रेज जाति अपनी स्वतन्त्रताको इतना कीमती समझती है कि यदि उसके अपने देशमें कोई ऐसी जबरदस्ती करनेवाला कानून बनाया जाये, फिर उसका उद्देश्य कुछ भी हो, तो हर अंग्रेज निश्चय ही उसका विरोध करेगा। दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न टोप जैसा छोटा नहीं है। यहाँ तो बाँहों और पेशानीपर गुलामीकी निशानी धारण करनेकी बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यह निशानी कदापि धारण न करें।

आपको यह सलाह देनेके लिए मैं अपने-आपको पूरी तरहसे जिम्मेवार मानता हूँ। परन्तु उसके साथ मैं यह कह देना चाहता हूँ, कि इस कानूनके पीछे छिपी मानहानिको मेरे भाई मेरी अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो इस कानूनकी उन सामियोंको जानता हूँ जो मेरे देशभाइयोंके पक्षमें जाती हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसे देशमें रहते हुए हमें कुछ पूर्वग्रहोंकी गुंजाइश तो रखनी ही पड़ेगी। इसलिए हमने कुछ अपमान और थोड़ी बेइज्जती चुपचाप बरदाश्त भी कर ली। परन्तु अब तो प्याला लबालब भर गया है। ब्रिटिश

भारतीय अब जान गये ह कि इस कानूनमें जो अपमान और गिरावट निहित हे उसे सहकर इस देशमें रहना अब हमारे लिए सम्भव नहीं है। हम खुद सोच विचारके बाद इस नतीजे तक पहुँचे ह कि अब हमारे लिए इस देशमें रहना सम्भव नहीं है। अगर कानूनके बारेमें मेरे देशभाइयोके ये विचार और ये भावनाएँ न हो तो म सबसे पहिले अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। म इस कानूनका पालन करूँगा और खुले तौरपर ऐलान कर दूंगा कि इस मामलेमें मुझसे भूल हो गई है और हम इस अध्यादेशके पात्र ह।

श्री ईसप मियाने सारी स्थिति बड़ी स्पष्टताके साथ हमारे सामने रखी है, अधिनियम और स्वेच्छया पजीयनका अंतर बताया है। अब सारी स्थिति हमारे सामने है। स्वेच्छया पजीयन करवानेसे और इस अध्यादेशके अतगत अनिवाय पजीयन करानेसे हमारी स्थिति कसी हो जायेगी, हम इन दोनों तस्वीरोकी कल्पना कर ले। इस कानूनकी तफसीलोमें जाना मेरा काम नहीं है। परंतु मौलवी साहबने हमें समझानेके लिए एक दो मिसाले बताई ह। श्री हाँस्केन मौलवी साहबकी भाषा नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने समझ लिया कि वे कोई निजी शिकायत सुना रहे ह। परंतु जो लोग कौमकी सेवा करना चाहते ह उनके लिए निजी शिकायत जसी कोई चीज ही नहीं हो सकती। मौलवी साहबने तो कहा था कि वह कानून घणके लायक है। और म पूरी नम्रता, किंतु और भी अधिक जोरके साथ कहता हूँ कि वह अत्यंत घणित और अपमानजनक है और मुसलमानों और ईसाइयोंमें भेद करता है। तुर्कोंके मुसलमानोंपर तो वह लागू किया जा रहा है, परंतु वहाके ईसाइयों और यहूदियोंको उससे भुक्त रखा गया है। मैं ऐसे किसी तुर्क मुसलमानको नहीं जानता जिसका तुर्किस्तानके किसी ईसाई या यहूदीसे कोई झगडा हो। इस अपमानको, इस कडवी घटको, पीना तो उनके लिए भी मुश्किल है।

परंतु मान लीजिये कि इस देशमें किसी तरह अपना पेट पालनेके लिए हम इन सब बातोंको बरदाश्त कर लेते ह तो भी इसका क्या भरोसा कि हमारी माली हालत निश्चित रूपसे सुधर ही जायेगी, और हमारे जो अधिकार पहले ही से छिन गये है वे हमें वापस मिल जायेगे? कहीं कुछ गौण फेरफार कर भी दिये जायें तो भी हमसे सम्पत्तिका अधिकार छिन ही जायेगा, अलग बस्तियोंमें भी रहना होगा, और पता नहीं क्या क्या हो। इन सारी परिस्थितियोंका सामना हमें करना है। इसीलिए म अपने देशभाइयोंको सलाह देता हूँ कि वे इस अधिनियमको न मानें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१९ प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभाके प्रस्ताव^१

[प्रिटोरिया

जुलाई ३१, १९०७]

प्रस्ताव १ प्रिटोरियाम की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा अत्यन्त खदक साय उल्लेख करती है कि भारतीय समाजम कुछ ऐसा ठाग पाये गय ह, जिन्हान अपने आपका और अपना परम्पराका बिलकुल भुला दिया है और जा, भलीभाँति यह जानते हुए भी कि एशियाई कानून मशायन अनियमितका पालन करना कितना अपमानास्पद है, पहले गुप्त रूपसे और फिर खुलमखुल्ला, उसके अतगत प्रमाणपत्राके लिए आवेदन करते हैं।

प्रस्ताव २ प्रिटोरियाम की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा एशियाई कानून मशायन अनियमितके अरीन न हानेपर और उसक अरीन न होनेके गम्भीर परिणामाका सामना करनेपर प्रिटोरियावासी भारतीयोंकी भारी ज़ुम्ह्याका बरादर दती है। और जिन साहसी भारतीयान इस अनियमितकी रागआक सम्बन्धम समाजक मददका सच्ची जानकारी देनेका पुण्यकाय करन अन्याय और अन्याचारका ऐसा लक्ष्यनीय सामना करनेकी स्थिति सम्भव बना दी है, उनका भी बधाई दती है।

प्रस्ताव ३ प्रिटोरियाम की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी इस सार्वजनिक सभाकी नम्र सम्मतिम अधिनियम अपने अभीष्ट उद्देश्यकी सिद्धिके लिए अनावश्यक है। इसलिए सभा प्राप्ता करती है कि सरकार कृपा करके अध्यक्ष भाषणम उल्लिखित स्वेच्छया पुन पजीयनके प्रस्तावको स्वीकार कर हमार समाजका इस अधिनियमक आग नही झुकनेसे हानराके राटमें न डाले।

प्रस्ताव ४ प्रिटोरियाम की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा अध्यक्षको अधिकार दती है कि वे पहलेक तीन प्रस्ताव सरकारका भेज दे।

[अंग्रेजीम]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१००७

१ यद्यपि इन प्रस्तावोंकी भारतीय समाजके विभिन्न प्रवक्ताओंने प्रस्तुत और अनुमोदित किया था, फिर भी यह स्पष्ट है कि ये गांधीजीने तैयार किये थे।

१०० भेट 'रैड डेली मेल' को

[प्रिटोरिया]

जुलाई ३१, १९०७]

यदि सरकार स्वेच्छया पजीयनके लिए कुछ काल, उदाहरणार्थ दो मासका, देनेके लिए तैयार हो जाये तो भारतीयोका बहुमत इन शर्तको मान लेगा, यद्यपि अँगुलियोके निशान देनेका तरीका फिर भी मुश्किल पदा करेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक गम्भीर बाधा है, और उनकी राय थी कि भारतीयोकी शर्तें तभी मानी जायेगी जब वे, या उनमें से बहुतसे, अध्यादेशके अतगत कष्ट सहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

रैड डेली मेल, १-८-१९०७

१०१ ट्रान्सवालकी लडाई

जुलाई महीना पूरा हो गया है। ट्रान्सवाल और शायद सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके इतिहासमें यह सदैव महत्त्वपूर्ण समझा जायेगा। ३१ तारीखकी विराट सभा ऐसे महत्त्वपूर्ण महीनेके अन्तके लिये उचित पूर्णाहुति रही। यह देखकर हमें प्रसन्नता हुई है कि ट्रान्सवालके इस सम्मेलनमें, जिसमें हर जगहसे प्रतिनिधि आये थे, सर्वसम्मतिसे फिर उस अध्यादेशकी भत्सना की है। अर्थात् समूचा ट्रान्सवाल आज एक स्वरसे जेल, जेल और जेलके लिए तैयार खड़ा है, यद्यपि कुछ लोगोंने सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके भविष्यपर असर डालनेवाली इस लडाईके मूल्यको भुलाकर समाजके साथ दगा किया है। यह काय भारी देशद्रोहके समान है, यद्यपि ऐसे लोगोकी सख्या बहुत ही थोड़ी है, इसके अतिरिक्त उनमेंसे बहुतेरोको जो पछतावा और खेद हुआ है तथा एकाध हकदार व्यक्तिके अनुमतिपत्रको झूठा ठहरा कर उसकी जो दुदशा की गई है, हम आशा करेंगे कि उससे सचेत होकर ट्रान्सवालमें हर जगह जो भी डगमगाता रहा हो, वह दब हो जायेगा। प्रिटोरियाने जो कर दिखाया उससे भी बढ़िया अब पीट्सबर्ग और अय जिलोको करके दिखानेका समय आया है। और यदि ऐसा कर दिखाया तो इस लडाईका परिणाम एक ही होगा, और वह है विजय। इस समय प्रिटोरियाके बहादुर भाइयोसे हम इतना ही कहेंगे कि उन लोगोंने जुलाईमें जो कुछ करके दिखाया है उसे निभानेके लिए कारावास भोगने, सरकार चाहे तो कठोर कारावास भोगने, निर्वासित होने, सक्षेपमें, चाहे जो सहन करनेके लिए बेधडक तैयार रहना है। इस समय हम रण सग्रामके मध्यमें हैं। इसलिए पीछे मुड़कर देखनेका समय नहीं है। हमारी लडाई न्यायकी है, इसलिए स्वयं जगतका महान कर्ता हमारे पक्षमें है। अबतक की लडाईमें सरकारने नीचे उतरनेमें कोई कसर नहीं रखी है। यह विजय हमारी अबतक की दृढताका परिणाम है। और भी क्या नहीं किया जा सकता, यह हम कूत नहीं

१. समाके समाप्त हो जानेपर गांधीजीने एक भेट दी थी जिसकी यह संक्षिप्त रिपोर्ट है।

सकते। प्रिटोरियाने जो कुछ किया है, उसके लिए उसे हम हार्दिक बधाई देते हैं और खुदामे इवादन करते हैं कि वह सदा जेल जानेवागकी पीठपर रहें।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९०३

१०२ नेटालके भारतीयोंमें जागृति

हम बार बार नेटालके भारतीयोंमें जागृति देनेके लिए कहते आये हैं। हमें खुशीके साथ कहना चाहिए कि वे अब सोते हुए नहीं जान पड़ते। वे ट्रान्सवालके भारतीयोंको तन, मन, धनसे मदद देनेकी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसके अग्रगण्य लोगोंमें से श्री दाउद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, दादा उम्मात, इस्माइल गारा, डा० नानजी, डा० हीरा माणिक, वगैरह डनमें चढ़के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। श्री एम० सी० आंगलियाने अब्दुल कादिर, पीरन मुहम्मद, तैयब मूसाके साथ जाकर मैरिट्सबर्गमें दा ही दिनमें चन्देकी बहुत बड़ी रकम इकट्ठा की है। हममें सबके लकर नेटालके सब भारतीयोंको अपने अपने विभागमें शक्तिभर चन्दा इकट्ठा करना चाहिए। कांग्रेसके नेता जब यह कोशिश कर रहे हैं तब साधारण वर्गके लोग भी पीछे नहीं हैं, रेलवसे जोहानिसबर्ग जानवाले मुसाफिरोंका पता रखनेवाले तीन स्वयंसेवकोंने अलावा सबथी हुसेन दाउद (श्री दाउद मुहम्मदके लडके), यू० एम० गेलत, ज़रीफ़दाम बी० महता, रुकनुद्दीन तथा डी० के० गुप्तेने भी अपना सारा समय कांग्रेसका अर्पित किया है। अगर कुछ दिनोंमें दिन भर यहाँसे प्रिटोरियाको तार भेजे जाते रहें हैं। और वहाँक तारकी आनुगतामें प्रतीक्षा की जाती है। नेटालके भारतीयोंकी इस हमदर्दीमें ट्रान्सवालके भारतीयोंको समझना चाहिए कि यहाँ की लड़ाईमें वे अकेले नहीं हैं, बाहरके भारतीय भी तन-मन धनमें, निभयनापूर्वक उनके साथ खड़े हैं।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९०३

१०३ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[अगस्त ५, १९०७]

पीटर्सबर्गपर बला

अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी बला पीट्सबर्ग गई है। इस पत्रके छपते छपते मालूम हो जायेगा कि पीट्सबर्गके भारतीय सिंह हैं या सियार। यह पत्र सोमवारको लिख रहा हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि वे सिंह हैं। अनुमतिपत्र कार्यालय केवल ७ तारीखसे १० तारीख तक गुलामीका पट्टा देनेके लिए पीट्सबर्गमें रहेगा। यह मालूम होते ही वहाके नेता प्रिटोरिया जा पहुँचे। अत्यंत जागरूक सेक्रेटरी श्री हाजी हबीब जो कामसे जोहानिसबर्ग आये हुए थे तत्काल वापस प्रिटोरिया गये और उन्होंने पीट्सबर्गके नेताओंको उत्साह दिलाया। उन्होंने बीडा उठाया है कि पीट्सबर्गमें अनुमतिपत्र कार्यालयका बिल्कुल बहिष्कार होगा।

पीटर्सबर्गमें बला क्यों गई ?

यह प्रश्न सबके मनमें उठेगा। मुझे खेदपूर्वक कहना चाहिए, इसमें दोष पीट्सबर्गके भारतीय भाइयोंका है। वे ३१ जुलाईकी प्रसिद्ध सावजनिक सभामें नहीं आये। उनका भेजा हुआ तार कमजोर था और उस दिन जहा सारे ट्रान्सवालकी दूकानें — श्री खमीसा की दूकान भी — बंद रही, वहा पीट्सबर्गके भारतीयोंकी दूकानें खुली थी। इससे सामान्यतः सरकारने अनुमान लगाया कि पीट्सबर्गके भारतीय बहुत आसानीसे गलेमें गुलामीकी जजीर डाल लेंगे और खूनी पट्टा रूपी पजीयनपत्र ले लेंगे। इसके अलावा चूँकि श्री खमीसा और हाजी इब्राहीमने मेमन लोगोंके नामपर बट्टा लगाया है और, दूसरे, पीट्सबर्गमें मेमन लोगोंकी बस्ती है, इसलिए सरकारने सोचा कि पीट्सबर्गमें उनका गोला बारूद कामयाब हो जायेगा और भारतीय स्वतंत्रताका किला पीट्सबर्गमें ढह जायेगा।

किन्तु पीट्सबर्गकी जमात श्री खमीसा तथा हाजी इब्राहीमसे आदश ग्रहण करेगी, यह माननेमें सरकारने भूल की है। मैं मानता हूँ कि ये दोनों भारतीय भी अब पछताते हैं। उनके नये पजीयनपत्र उन्हें भारी पड़ गये हैं। यद्यपि भारतीय उनसे सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर रहे हैं और न वे उठे सताते हैं, फिर भी वे अब लज्जित हो गये हैं और उन्हें लोगोंके कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। इसलिए किसी भारतीयकी यह हिम्मत नहीं कि कोई उनका अनुकरण करे। इसके अलावा जाहिर तौरपर तो वे यही कहते दिखाई देते हैं कि “हमने तो हाथ और मुंह काले किये किन्तु हमारे जैसा दूसरे भारतीय न करे।”

प्रिटोरियाको रियायत

पीट्सबर्गके नोटिसमें सरकारने यह भी कहा है कि प्रिटोरियाके भारतीयोंको भी वहा नये पजीयनपत्र लेनेकी छूट है। इसे मैं बन्धन मानता हूँ। लालच बुरी चीज है। नये पजीयनपत्र लेना मैं अपराध मानता हूँ। प्रिटोरियाके भारतीयोंको इस अपराधमें फसानेके लिए सरकारने जो दरवाजा खोला है उसे छूट मानना गलत है। यह तो एक फंदा है। मैं तो विश्वासपूर्वक मानता हूँ कि उस प्रलोभनमें फँसनेके लिए कोई भी भारतीय प्रिटोरियासे नहीं जायेगा।

करीम जमालका मुकदमा

करीम जमालके मुकदमेसे भारतीय लोग नये कानूनके प्रति और भी ज्यादा सतक हो गये हैं। उसके सामने झुकना उन्हें नींद बेचकर जागरण मोल लेनेके समान साबूम हुआ है। श्री करीम जमालका मुकदमा वापस ठे लिया गया है। सरकारी वकीलन स्वीकार किया है कि यह मुकदमा भूलमे दायर हुआ था। इसमे श्री करीम जमालको क्या लाभ? उन्हें तो तन्त्रीफ उठानी ही पड़ी और धनकी बरगानी भी हुई। इस बरगानी और मुसीबतमे तग आकर उन्होंने पजीयतकी अर्जी वापस ठे की है। (इस सम्बन्धमे पजीयतके नाम लिखा हुआ पत्र दूसरी जगह दिया गया है। वह देखिए)।^१

इस पत्रसे सबको चेत जाना चाहिए कि यह कानून गरीब आदमीपर कितनी मुसीबत डाल सकता है।

एक गोरेकी निशानी लगानेके विरुद्ध लड़ाई

एक गोरेका चोरीके अभियागमे गिरफ्तार किया गया है। जेलका कानून ऐसा है कि जो भी व्यक्ति जेल जाये, वहाँ पुलिसका उसकी अँगुलियाकी निशानी लेनेका अधिकार है। इस अधिकारके कारण पुलिसने गोरेमे जलम अँगुलियाकी निशानी माँगी। गोरेने देनेसे इनकार किया। उसे मजिस्ट्रेट सामने खड़ा किया गया। फिर भी गोरेने निशानी लगानेमे साफ इनकार कर दिया। कानूनमे जबरदस्ती हाथ दवाकर निशानी लगवानेकी सत्ता तो है नहीं। इसलिए मजिस्ट्रेटने उस गोरेको तीन दिन अगरी काठरीमे बंद रखनेकी सजा दी। वह उसने बहादुरीमे भागी, किन्तु अँगुलियाकी निशानी देनेसे इनकार किया।

लडाईमे पेसेकी सहायता

बाँस बैकस श्री भटने सघका लिखा है कि वहाँ भारतीयाम बड़ी हिम्मत है और वह चढ़ा उगाह रहे हैं। कोई जेल जायगा तब यदि मदद की आवश्यकता हुई तो देगे। यह खबर बहुत ही सन्तोषजनक है। मुझे इस सम्बन्धमे कहना चाहिए कि नेटालमे जितना धन एकट्ठा हो वह काग्रमेके मन्त्रीका भेज दिया जाये। और इसी प्रकार जहाँ भी चढ़ा जमा हो, वह वहाँके सघका भेज दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पाम या गॉवमे ही किसी नेताके पास चढ़की रकम रखे रहगा तो आवश्यकताके समय उसे पहुँचाना कठिन हो जायेगा। ट्रान्सवालमे एक ही जगहमे पैसा माँगना पड़ — ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है। इस समय किमीका इसमे न बड़प्पन मानना चाहिए और न उसकी अपेक्षा रखनी चाहिए, बल्कि सबको अपना-अपना फज अदा करना चाहिए।

सार्वजनिक सभा

प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभा बहुत ही अच्छी रही। वह सकते हैं कि एम्पायर नाटकघरकी और गेड्टी नाटकघरकी सभा उसके सामने कुछ नहीं थी। इसके अलावा वह चूँकि मसजिद जैसे पवित्र स्थानके मैदानमे हुई, इसमे जान पड़ता है, भारतीय समाजको विजय निश्चय ही मिलेगी। इस सभामें “प्रिटोरिया न्यूज” के सम्पादक स्वयं उपस्थित थे, जब कि अन्य सभाओंमें केवल सवाददाता ही आते थे। पहली दो आम सभाओंमें यहाँके सदसद-सदस्य नहीं थे।

हाँस्केनकी उपस्थिति

इस सभामे प्रसिद्ध ससद सदस्य श्री हाँस्केन आये थे। श्री हाँस्केनके भाषणसे हमे उत्साहित होना चाहिए। उन्होंने जो सीख दी हे उसके अलावा वे और कुछ कह ही नहीं सकते। किन्तु वे इसलिए आये कि उहे जनरल बोधा, जनरल स्मटस और श्री हलने भेजा था। इससे मालूम होता है, सरकारपर जुलाई महीनेके कामका प्रभाव पडा हे। दो पक्ष लडते हैं तब सामान्यतः अततक दोनो अपनी अपनी तरफ खींचते ह। उसमे जिसका पक्ष सच्चा होता है और जो अततक जोर दिखाता हे वह विजयी होता है। अतः सरकार यदि यह सदेश भेजती हे कि कानूनमे सशोधन बिलकुल नहीं होगा और स्वेच्छया पजीयनकी बात स्वीकार नहीं की जायेगी, तो इसमे कोई आश्चय नहीं। आजतक हमारी बात कोई नहीं सुनता था। उसके बदले अब सरकारको सुननेकी इच्छा हुई, इसे विजयकी ओर पहला कदम मानना चाहिए।

दूसरे शुभ शकुन

जैसे मैं मसजिदकी सभा और श्री हाँस्केनकी उपस्थितिको अच्छे लक्षण मानता हूँ, वैसे ही श्री हाजी कासिमकी लाई हुई इस खबरको भी, कि सरकार तत्काल किसीको जेल भेजनेवाली नहीं हे, शुभ शकुन मानना होगा। वास्तवमे तो यह बिलकुल बेकार बात है। सरकार जितनी जल्दी हमपर हाथ डालेगी उतनी ही जल्दी फैसला होगा। किन्तु यह खबर सभाके दिन मिली इस सयोगको मैं अच्छा मानता हूँ। सबसे अच्छा शकुन तो यह हे कि कि ३१ तारीखको सबेरे विलायतसे तार मिला हे कि दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति सर हेनरी कैम्बेल बेनर मैनसे मिलनेकी तजवीज कर रही है। इस तारसे सबको प्रसन्नता हुई है। सबको सतोष हुआ है कि समिति हमे बिलकुल छोड देनेवाली तो नहीं है।

रायटरको तार

सभा समाप्त हो जानेके बाद प्रिटोरिया समितिने रायटरको लम्बा तार भेजा तथा एक तार सीधा समितिके नाम भेजा। इसमे लगभग ७ पौड खच हुए। तारके उत्तरमे समितिकी ओरसे सूचना मिली हे कि इस प्रश्नपर लोकसभामे बहस की जायेगी और ट्रान्सवालको जो पचास लाख पौडका कज चाहिए उसके सिलसिलेमे हमारा प्रश्न उठेगा। इससे आशा तो है कि हमे लाभ होगा, किन्तु ऐसी मददपर किसीको ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। इसमे यदि निराशा हो तो आश्चयकी कोई बात नहीं। मुख्य बात यह हे कि सब कुछ हमारे बलपर निर्भर है और यह निश्चय मानना चाहिए कि जेलके दरवाजेसे गुजरे बिना हमारा छुटकारा नहीं होगा।

और भी सहायता

श्री मोतीलाल दीवान लिखते हैं कि ट्रान्सवालके भारतीय आत्म बलिदान करके सेवा करनेको तैयार हैं। यदि कोई भारतीय जेल जाये तो वे उसके बाल बच्चोकी व्यवस्था करने और उसका स्वागत करनेके लिए चार्ल्सटाउन तक जानेको तैयार हैं। ऐसे उदाहरणोंसे हमे बहुत ही मदद मिलती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०४ तार सी० बर्डको

मक्युरी लन

[डवन]

अगस्त ८, १९०७

श्री सी० बर्ड,^१ सी० एम० जी०

पी० मै० बग^२

महामहिम सम्राटने आपको मान^३ प्रदान किया तदर्थ वग^३ देता हूँ।

गाधी

हस्तलिखित दफतरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ३८७७) से।

१०५ पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको

जोहानिमवग

अगस्त ८, १९०७

जनरल स्मट्सक निजी सचिव

प्रिटोरिया

महादय,

मुझ एकाधिक सूत्रास यह सूचना मिली है कि जनरल स्मट्सकी रायम एशियाई कानून सशोधन विधेयकके विरुद्ध आन्दोलनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मेरे कामको वे बहुत नापसन्द करते हैं। यदि इस आरोपका मतलब यह है कि मेरे देशवासी कानूनका विलकुल विरोध नहीं करते लेकिन मैं बेजबूरत उन्हें भडकाता हूँ, तो मैं इससे कतई इनकार करनेकी ग्पत्ता करता हूँ। दूसरी ओर, यदि इसका यह अर्थ है कि मैंने उनके भावाको प्रकट किया है और पूरी योग्यताके साथ उनके सामने ठीक ठीक यह रखनेका प्रयत्न किया है कि कानूनका क्या उद्देश्य है, तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि, चूँकि मेरे माता-पिताने मुझे व्यापक ढंगकी शिक्षा दी है और मैंने भी एक खास हद तक आधुनिक इतिहास पढ़ा है, इसलिए यदि मैं इतना भी नहीं करता तो अपने प्रति और अपने देशके प्रति सच्चा नहीं उतरूँगा।

श्री डी० विलियमसन अपने पेशेसे सम्बन्धित मेरे ताल्लुकात रहे हैं। इसलिए उनपर भरासा करक मैं उनसे निजी तौरपर मिला और कठिनाईका कोई हल ढूढनेके खयालसे मैंने उनसे गैर-सरकारी तौरपर दखल देनेके लिए कहा। उन्होंने जनरल स्मट्ससे मिलकर मुझे सूचित करनेका वचन दिया था। उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन मैं उनसे स्वयं फिर नहीं मिल सका। वे इस आशयका सन्देश अपने सचिवके पास छोड गये थे कि, यद्यपि उनसे मेरी

१. टान्सवाल उपनिवेश-सचिवके निजी सचिव।

२. पीट्समैरिस्सर्ग।

३. कम्पेनिशन ऑफ (दि थोर्बर ऑफ़) सेंट मास्केल पेंड सेंट जर्ज।

सुझाई हुई दिशामे किसी सहायताके मिलनेकी बहुत कम आशा है तथापि मुझे सीधा जनरल स्मट्ससे निवेदन करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि मैं सरकारकी सेवा करनेके लिए उतना ही उत्सुक हूँ जितना अपने देशवासियोंकी सेवा करनेके लिए। और मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और साम्राज्यके लिए भी महत्वका है। इसलिए मैं इसके साथ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सशोधनका एक जल्दीमे तैयार किया हुआ मसविदा सलग्न कर रहा हूँ। मेरी विनम्र रायमे इसमे सरकारका दृष्टिकोण पूरी तरहसे आ जाता है और इससे वह लाञ्छन भी मिट जाता है जो, सही या गलत मेरे देशवासियोंकी रायमे एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके आगे झुक जानेसे, उनपर लगता है।

मैंने दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको भेजे हुए जनरल स्मट्सके उत्तरका तारसे प्राप्त सार भेजा है। उन्होंने यह कहनेकी कृपा की है कि भारतीय समाजके नेताओंसे सहयोग करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुकाबला करनेका रुख अरितयार किया है। मैं आदरपूर्वक कहूँगा कि हमारे रुखमे मुकाबला करनेका भाव नहीं है, बल्कि ईश्वरकी इच्छा पर सब कुछ छोड़ देनेकी भावना है, क्योंकि उसके नामपर भारतीयोंने शपथ ली है कि वे अपने पौरुष और स्वाभिमानको नहीं छोड़ेंगे, जिसपर, उनकी रायमे, पजीयन अधिनियम द्वारा गम्भीर आक्रमण होता है।

मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ भेजा हुआ प्रस्ताव उसी भावनासे ग्रहण किया जायेगा जिस भावनासे वह पेश किया गया है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[सलग्न पत्र]

एशियाई पजीयन अधिनियम सम्बन्धी कठिनाई हल करनेके लिए प्रस्ताव

निवेदन है कि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक, जो अब भी वापस लिया जा सकता है और सशोधित किया जा सकता है, सम्पूर्ण कठिनाईको नीचे लिखे अनुसार दूर कर सकता है

१ विधेयकके खण्ड १ मे “किन्तु” से “दिये जा चुके हैं” तक छोड़ दिया जाये।

२ खण्ड २ मे निम्न बातें जोड़ दी जायें “वर्जित प्रवासी” शब्दके अन्तर्गत उन एशियाईयोका समावेश न होगा और उनसे वे पुरुष एशियाई न समझे जायेंगे जो इसकी उपधारा (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत आते हैं, इसके बावजूद कि इनसे उपखण्ड १ की शर्तें पूरी न हो सकती हो

(क) कोई भी एशियाई, जिसने नियमानुसार क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश १९०२ या उसके किसी सशोधनके अन्तर्गत दिये गये परवानेके द्वारा या १ सितम्बर १९०० और कथित अध्यादेशके पास होनेकी तारीखके बीच दिये गये परवाने द्वारा, जबतक वह परवाना जाली तौरपर लिया हुआ न हो, उपनिवेशमे आने और रहनेका उचित अधिकार प्राप्त किया हो, व्यवस्था की जाती है कि ऐसे परवानेमे किसी एशियाईको केवल सीमित समय तक इस उपनिवेशमे रहनेका अधिकार बताया गया हो तो वह इस उपखण्डके सशोधनके भीतर परवाना न समझा जायेगा,

(ख) कोई भी एशियाई जो इस उपनिवेशका निवासी हो और ३१ मई १९०२ को प्रत्यक्षत यहा रहा हो,

(ग) कोई भी एशियाई जो ३१ मई १९०२के बाद इस उपनिवेशमें उत्पन्न हुआ हो, किन्तु इस उपनिवेशमें १९०४ के श्रम आयात अध्यादेशके अंतर्गत लाये हुए किसी मजदूरका बच्चा न हो,

(घ) कोई भी एशियाई, जिसने ११ अक्तूबर १८९९ से पूर्व १८८६ में सशोधित रूपमें १८८५ के कानूनके अनुसार ३ पौंडकी रकम दे दी हो।

व्यवस्था की जाती है कि ऐसा एशियाई उस तारीखसे पूर्व, जिसे उपनिवेश-सचिव निश्चित करेगा, नियमके द्वारा, विहित फार्मके अनुसार अधिवासी प्रमाणपत्र ले लगा और यह व्यवस्था भी की जाती है कि १६ वर्षकी आयु तक के बच्चे इस धाराके अमलमें मुक्त होंगे, १६ वर्षके होनेपर वे अधिवासी-प्रमाणपत्र लेनेके लिए बाध्य होंगे जिससे वे पहले उल्लिखित छूटकी माँग कर सकें।

३ एशियाई शब्दका अर्थ होगा ऐसा कोई भी पुरुष जैसा कि १८८५ के कानून ३ की धारा १ में बताया गया है, किन्तु वह उपनिवेशमें १९०४ के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तर्गत लाया हुआ व्यक्ति न हो।

४ संसदके प्रस्ताव, १२ अगस्त १८८६ की धारा १४१९ और १० मई १८९० की धारा १०८ द्वारा सशोधित रूपमें १८८५ के कानून ३ की धारा २ का (ग) उपखण्ड और एशियाई कानून सशोधन अधिनियम इसके द्वारा रद्द किये जाते हैं।

५ उपखण्ड १५ में जोड़ा जाये। उपखण्डके अन्तर्गत अधिवासी प्रमाणपत्रके फार्म और उसके लिए प्राथनापत्र देनेकी विधि एवं वह समय जिसके भीतर १६ वर्षसे कम आयुका एशियाई बच्चा १६ वर्षका होनेपर अधिवासी प्रमाणपत्रके लिए प्राथनापत्र देगा, भी बताया जाये।

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ गांधीजीने गुजराती स्तम्भोंमें प्रस्तावको संक्षिप्त रूपमें दिया था और उसके मुख्य मुद्दे ये बताये थे यह निवेदन है कि प्रवासी-प्रतिबंधक विधेयकसे, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, समस्त कठिनाई निम्न प्रकार दूर की जा सकती है

(१) नया अधिनियम वापस ले लिया जाये।

(२) "निषिद्ध प्रवासी" शब्दोंमें निम्न कौनके छोटे सम्मिलित न होंगे, जिनके पास वैध परवाने हों और जो उनको बताये गये समयके भीतर बदलवा कर नये के लें।

(३) कोई एशियाई, जिसके पास कोई परवाना नहीं है, किन्तु जिसने ११ अक्तूबर १८९९ से पूर्व बच-सरकारको ३ पौंडकी रकम दे दी थी, बशर्ते कि ऐसा एशियाई उपनिवेश सचिव द्वारा नियत की जानेवाली तारीखसे पहले नियम द्वारा निश्चित फार्मके अनुसार अधिवासी प्रमाणपत्र के ले।

(४) अपने परवानोंकी बदलवानेकी यह बाध्यता सोलह वर्ष तक की आयुके बच्चोंपर लागू न हो। वे जब सोलह वर्षके हो जायें तब अधिवासी प्रमाणपत्र ले सकते हैं, ऐसा नियम कर दिया जाये।

(५) "एशियाई" शब्दमें सब एशियाईयोंका समावेश हो।

(६) ३ पौंडकी अदायगीसे सम्बन्धित उपधारा रद्द कर दी जाये।

(७) सरकारको अधिवासी प्रमाणपत्रके फार्म और उनके लिए प्राथनापत्र देनेकी विधि निश्चित करनेका अधिकार हो।

१०६ तार प्रिटोरिया समितिको^१

जोहानिसबग

[अगस्त १०, १९०७ के पूर्व]

[प्रिटोरिया समिति
ब्रिटिश भारतीय सघ
प्रिटोरिया]

सघ की समितिने तथा हाइडेलबग, पाचेफस्टूम, फ्रेनीखन (वेरीनिगिंग), मिडेलबग, क्रूगसडाप और अन्य शहरोके प्रतिनिवियोंने भी, अपनी बैठकमे दासताके प्रमाणपत्रोके लिए प्राथनापत्र देनेके समस्त विचारपर घणा व्यक्त की। बैठकने प्रिटोरियाके भारतीयोसे आग्रहपूर्वक अनुरोध किया कि वे अन्ततक मजबूत और वफादार रहे जिससे उनकी कायरता और स्वाथपरता उनके देश और देशवासियोंके प्रति विश्वासघातका कारण न बने। यदि सब मजबूत रहे, जीत हमारी है। प्रिटोरियाको सब भारतीयोके सम्मुख उत्साहवद्धक उदाहरण रखना है।

[ब्रि० भा० स०]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०७ श्री हॉस्केनकी “अवश्यम्भावी”

सारे दक्षिण आफ्रिकामे श्री हॉस्केन अश्वेत जातियोंके मित्र समझे जाते हैं। वे दक्षिण आफ्रिकाके उन गिने चुने लोगोमे से हैं जो अपने विचारोपर दब रहनेका साहस रखते हैं। इसलिए प्रिटोरियाके भारतीयोकी आम सभामे उन्होने जो बातें कही, वे बहुत ध्यान देने लायक हैं।

आइये, हम उनके बताये हुए सिद्धान्तका विश्लेषण करे। सिद्धांत यह है कि भारतीयोको प्राच्य जातीय होनेके नाते “अवश्यम्भावी” को मान्य करके उसके सामने सिर झुका देना चाहिए। इस शब्दसे श्री हास्केन यह समझाना चाहते हैं कि यह अधिनियम चूँकि ट्रान्सवालके गोरोकी मागपर स्थानीय ससदनने सवसम्मतिसे स्वीकार किया है, इसलिए इसे उन्हें ईश्वरीय विधानके समान समझना चाहिए। श्री हॉस्केनके इस प्रस्तावपर हम आपत्ति करनेके लिए विवश हैं। माननीय महानुभावने स्वीकार किया है कि वे स्वयं इस कानूनको पसंद नहीं करते और अगर उनके लिए सम्भव होता तो वे स्वयं भारतीयोकी प्राथना स्वीकार कर लेते। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि “अनाक्रामक प्रतिरोध” अपनी सच्ची शिकायतोको दूर करनेका सही

१ यह ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा भेजा गया था और इसका मसविदा अनुमानत गांधीजीने बनाया था।

तरीका है। इसलिए श्री हॉस्केनका यह कथन कि यह कानून ईश्वरीय कानूनके समान है, स्वयं उन्हींकी बातोमे कट जाता है। लेकिन हम तो इससे भी आगे जाते हैं। प्राच्य लोगोंके विचारानुसार कोई भी मानवीय कृत्य, जबतक कि वह वास्तवमे न्यायोचित न हो, दैवी होनहार नहीं समझा जाता। और जब-कभी कोई प्राच्य व्यक्ति किसी जाहिरा होनहारके सामने झुक जाता है तो उसके इस आचरणके पीछे हमेशा दैवी हाथकी मान्यताका भाव नहीं होता, बल्कि नीच स्वाथपरता होती है। तब आत्मा चाहती है, पर देह साथ नहीं देती।

वह कौन-सी बात है जिसे श्री हॉस्केन भारतीयोंसे करवाना चाहते हैं? क्या यह कि वे इस देशमें बने रहनेके लिए गुलामीके कानूनको मान ले? दूसरे शब्दामे, श्री हॉस्केन, जो ईश्वरके भक्त हैं, भारतीयोंका यह सलाह देना चाहते हैं कि वे पार्थिव लाभके लिए अपने पवित्र सकल्प और सम्मानका लात मार दें। हम उनके प्रभुकी भाषामे जवाब देते हैं, “तुम पहले ईश्वरके राज्य और सदाचारके पथकी खोज करो, फिर तुमको सब-कुछ मिल जायेगा।” हमारा विश्वास है कि इस निकम्मे कानूनका विरोध करके भारतीय “ईश्वरका राज्य” खोजेंगे।

श्री हॉस्केन कहते हैं कि शपथ बंधनकारी नहीं है क्योंकि वह गलतीमे ली गई है। लेकिन वह पवित्र घापणा तो भारतीयोंने बहुत साच विचार कर की है और उन्होंने इस कानूनका विरोध करने और कैद या उससे भी अधिक काट सहन करनेका जो निश्चय किया है वह केवल अपने ही सम्मानके लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजना और स्वदेशकी प्रतिष्ठाके लिए भी किया है।

इसलिए, हमें विश्वास है कि श्री हॉस्केन, असहायोंके प्रति अपने स्वाभाविक उत्साहके साथ, गशियाई-प्रश्नको समझनेका प्रयत्न करेंगे और हम निश्चय हैं कि भारतीय समुदायके सम्पूर्ण पक्षको मान लेंगे। वे सभामे सरकारकी ओरसे शान्तिदूत बनकर गये थे। हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अगर वे भारतीय दृष्टिकोणको ठीक ठीक समझ लेंगे तो एक सच्चे मध्यस्थका कतव्य पूरा करेंगे।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०८ श्री अलीका विरोध^१

श्री अलीने अखबारोको जो पत्र लिखा है उसकी तरफ हम ट्रान्सवाल सरकारका ध्यान खीचना चाहते हैं। पाठकोको याद होगा कि श्री अली उस शिष्टमण्डलके एक सदस्य थे जो लॉड एलगिनसे एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमें मिला था। 'रैड डेली मेल' उसे एक कटु विरोध कहता है, और वह है भी। शायद, श्री अलीका मामला असाधारण हो, लेकिन इससे यह साफ जाहिर है, ऐसा और किसी तरह जाहिर नहीं हो सकता था कि इस कानूनमें भारतीय समुदायको कितना कष्ट होनेवाला है। भारतीयोंकी आपत्तिको कोरी भावुकता कहकर दबा दिया गया है। श्री डकनने बिना यह जाने कि इस कानूनका मतलब क्या है, यह कहनेकी कृपा की है कि एशियाइयोंके एतराजको दबा देना चाहिए। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या श्री अलीने सिर्फ भावुकताके कारण ही यह रवैया अपनाया है? क्या भारतीय समुदायसे यह कहा जायेगा कि श्री अली एक मूलताभरी भावुकताके पीछे ही, कदाचित, भुखमरीका सामना करने जा रहे हैं? या लॉड एलगिनकी आखे खुलेगी कि आखिरकार, ब्रिटिश प्रजाको, भले ही वह भारतीय हो, जहा कही ब्रिटिश झंडा लहराता हो वहा वैयक्तिक स्वतंत्रता और सुरक्षाका अधिकार है?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०९ ट्रान्सवालके भारतीय

सरकारने पीटसबगके सम्बन्धमें जो सूचना प्रकाशित की है वह नि सन्देह नब्ब टटोलनेके लिए है और ऐसा लगता है कि सरकारको अब भी शक है कि एशियाई अधिनियमके खिलाफ जो विरोधकी भावना है, वह व्यापक और आम लोगोंमें फैली हुई है या सिर्फ मुटठी भर "आन्दोलनकारियों" तक सीमित है। इस दृष्टिसे पीटसबगकी सूचना "यायोचित" है। पीटसबगके भारतीयों द्वारा दिये गये जवाबसे जनरल स्मट्सके दिमागमें जो भी शका हो, वह दूर हो जानी चाहिए। पीटसबगके भारतीय अपने शहरमें पजीयन कार्यालयका भेजा जाना एक ऐसी आफत समझते हैं, जिससे बचना चाहिए। उन्होंने सरकारको प्राथनापत्र भेज कर जो बहादुरी दिखाई है, उसपर हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें और सारे ट्रान्सवालवासी भारतीयोंको भी, सावधान कर देना चाहते हैं कि सरकारने पूर्वग्रहोंकी जो अभेद्य दीवार उनके सामने खड़ी कर दी है, उसमें दरार करनेके लिए उन्हें बहुत ही कठिन और लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। खून बहाये बिना पापका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। ब्रिटिश भारतीयोंके लिए इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि जेल और निर्वासन तक के कष्ट भोगे बिना उन्हें आजादी नहीं मिल

सकती। जिन राहतोको पानेके लिए वे लड रहे हैं, उन्हें पानेसे पहले उन्हें अपने आपको उनके योग्य साबित करके दिखलाना होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११० अब क्या होगा ?

सावजनिक सभा' समाप्त हो गई। प्रिटोरियाने बहादुरी दिखाई। अगस्तके दिन बीन चले, लेकिन अभी तक किसीको पकड़ा नहीं गया। अब क्या होगा ? यह प्रश्न बहुत जगह किया जा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि प्रिटोरियाके नोटिसके आधारपर सरकारने कोई कदम उठानेका इरादा नहीं किया था। सरकारका यह इरादा जान पड़ता है कि ट्रान्सवालके सारे भारतीयोंको गुलामीका पट्टा लेनेका मौका मिल जानेके बाद ही जेल भेजना शुरू किया जाये। अब पीटमब्रगमे बहिष्कार सफल होना सम्भव है। इसलिए यदि दफ्तर कहीं खुल सकता है तो वह जोहानिसबगम ही, और वहाँ नोटिसकी अवधि पूरी हो जानेके बाद गिरफ्तारिया शुरू हांगी। जो खबरे मिली हैं उनसे मायूम होना है कि सरकार सबसे पहले नेताओंको गिरफ्तार करेगी। यह निणय ठीक माना जायेगा। यदि उसे यह सन्देह हो कि केवल नेताओंके बहकानेसे लोग नये कानूनका विरोध कर रह हैं, तो नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद भी यदि समाज दृढ़ रहे तो वह सदेह दूर हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१११. समितिकी लडाई

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने फिर कानून सम्बन्धी लडाई शुरू की है और इसमें कोई शक नहीं कि वह सावजनिक सभाका फल है। श्री चर्चिलने श्री राबटको जवाब देते हुए कहा है कि बड़ी सरकार मानती है, यह मामला बहुत ही गम्भीर हो गया है। बड़ी सरकारने लॉड सेल्बोनसे हमेशा तार भेजते रहनेको कहा है। और यह भी सूचित किया है कि वे ऐसी सब कारवाई करे, जिससे स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशके हकोको धक्का न पहुँचे।

उधर, श्री काक्सने^१ नोटिस दिया है कि यदि भारतीयोंके हकोकी रक्षा न की जा सके, तो ट्रान्सवालको पचास लाख पौण्ड कजकी सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

इन घटनाओंसे पता चलता है कि बड़ी सरकार ट्रान्सवालके भारतीयोंको छोड़ नहीं देगी। किन्तु इसमें खुली शत यह है कि ट्रान्सवालके भारतीय अपने आपको न छोड़े। उनकी जेल जानेकी शक्तिपर सब कुछ निर्भर है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११२ जनरल स्मट्सका उत्तर

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने जनरल बोथाके नाम जो पत्र भेजा था उसका उत्तर जनरल स्मट्सने दिया है। उसका सारांश 'स्टार' आदि समाचारपत्रोंको तार द्वारा प्राप्त हुआ है। यह उत्तर एक मास पुराना है, इसलिए इसे अधिक महत्व देनेकी जरूरत नहीं। इसके बाद तो बहुतसी घटनाएँ हो चुकी हैं, और उनका क्या प्रभाव पड़ा है यह अभी नहीं कहा जा सकता। परन्तु श्री स्मट्सका एक महीने पहलेका उत्तर बता रहा है कि यदि उनका वश चले तो वे एक भी भारतीयको नहीं रहने देंगे। भूमि सम्बन्धी अधिकार वे देंगे नहीं, अँगुलियोंकी छाप तो देनी ही है, ट्रामका कानून भारतीयोंके हितके लिए है, वैसी ही रेलवेकी बात है। तब फिर शेष क्या रहा? इतनेपर भी जनरल स्मट्स कह रहे हैं कि भारतीय नेतागण कानूनके सामने झुकना नहीं चाहते, इसलिए वे उन लोगोंकी सलाह नहीं लेना चाहते, यानी भारतीय समाजको किस प्रकार गुलाम बनाया जाये, इसे वे महानुभाव खुद अच्छी तरह जानते ह।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११३ अलीका पत्र

श्री अलीने समाचारपत्रोंको पत्र लिखा है, इसे हम उचित कदम समझते हैं। हम मानते हैं कि श्री अलीका मामला बहुत ठोस है। उसका प्रभाव विधायनमें और दक्षिण आफ्रिकामें पड़े बिना नहीं रहेगा। श्री अलीने समितिको जो पत्र^१ लिखा था उसमें हुई भूल दस पत्रके द्वारा कुछ मात्रामें सुधर जाती है। श्री अली केप जानेवाले हैं। वहाँ वे चाहे ता देश सेवा कर सकते हैं। केपके भारतीयाने ट्रान्सवालकी लडाईमें काफी भाग लेना शुरू किया है। उसे श्री अली बल दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि श्री अली केपमें पूरी तरह लडाई लडेगे और केपके भारतीय भाई उनमें सहायता प्राप्त करेंगे। इस सम्बन्धमें हमें इतना कहना चाहिए कि जो सहायता करनेके लिए तैयार है उन्हें जेलके प्रस्तावका समर्थन करना है, ट्रान्सवालको जोश दिलाना है और जिनपर मुम्वित आये उन्हें आर्थिक सहायता देनी है। इसमें भिन्न जो कुछ भी किया जायेगा वह सहायक होनेके बदले नुकसान करनेवाला हागा।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११४. हमारा कर्तव्य

हम इस अकमें दो पत्र ऐसे प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें उन लोगोंके नाम हैं जिन्होंने ३१ जुलाईको अपनी दूकानें बन्द नहीं की। इसके अलावा जिन्होंने प्रिटोरियामें गुलामीके पट्टेके लिए अर्जी दी थी उनके जो नाम हमारे पास पहुँचे हैं, उन्हें भी हम छाप रहे हैं। यह सब हमने अत्यन्त खेदके साथ प्रकाशित किया है। किन्तु हम समझते हैं कि जब एक महान लडाई लड़ी जा रही है तब हमें अपराधियाके नाम छिपाने नहीं चाहिए। उनमें से एकपर भी हमें रोष नहीं है। किन्तु हम मानते हैं कि नामोंको इस प्रकार प्रकाशित करके हम देशसेवा कर रहे हैं। इस समय जरूरत यह है कि सारे भारतीय पूरी ताकत पकड़ ले और स्वायत्तको छोड़ें। इसलिए कमजोर लोगोंके नाम प्रकाशित करनेमें हमारा उद्देश्य यह है कि दूसरे बलवान बनें। जिन लोगोंके नाम दिये गये हैं उन्हें कुछ सफाई देनी हो और वह संक्षेपमें हो तो उसे भी प्रकाशित किया जायेगा। जिन्हें अपनी भूल दिखाई दे और वे पश्चात्तापके पत्र लिखें तो उन्हें भी हम छापेंगे। वे भी हमारे ही देशके हैं, यह समझकर हमें उनके कल्याणकी इच्छा करनी है और आशा है, इसी तरह हमारे पाठक भी चाहेंगे। हमारी लडाईमें गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्वायत्त-भावना, मारपीट, ये सब निकम्मे ही नहीं, हानिकारक भी हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१ देखिये “अलीकी भूल”, पृष्ठ १२४ २५।

११५ केपके भारतीय

हम अपने २७ जुलाईके अकमे^१ लिख चुके हैं कि केपके भारतीयोंको क्या मागना चाहिए, इसपर बादमें विचार करेंगे। अब यहाँ विचार करें।

केपमें एक कष्ट तो प्रवासी कानूनका है। उसमें केपसे बाहर जानेवाले भारतीयोंपर एक वर्षकी अवधिका पास लेनेका बंधन है। यदि वे यह पास न ले और उन्हें अग्रेजी न आती हो तो वे वापस नहीं आ सकते। इस कानूनको हम बहुत ही सख्त मानते हैं। ऐसा अनुमतिपत्र लेना स्वतंत्र व्यक्तिका काम नहीं है। जिन्हें केपमें रहनेका हक है वे यदि एक बार परवाना ले ले तो वह हमेशा कायम रहना चाहिए। एक वर्षसे अधिक समय तक यदि कोई व्यापारी बाहर रहे तो क्या वह अपना व्यापार संभालनेके लिए केप वापस नहीं आ सकता ? इसलिए अवधिकी यह उपधारा निकल जानी चाहिए।

इसके अलावा मियादी पास लेनेवालोसे फोटो मागा जाता है। अंगुलियोंकी छापकी अपेक्षा फोटो देना हम अधिक लज्जाजनक मानते हैं। ऐसी धाराएँ खत्म की जानी चाहिए।

दूसरा कानून व्यापारी परवानेका है। इस सम्बन्धमें परवाना अधिकारीके फैसलेपर अन्ततः सर्वोच्च न्यायालयमें अपील करनेका हक होना चाहिए। फेरीवालोपर हर मुहल्लेके लिए अलग अलग परवाना लेनेका जो बंधन है, वह भी दूर होना चाहिए।

ईस्ट लंदनमें पैदल पटरियों तथा बस्तियोंके विशेष नियम हैं। उनमें परिवर्तन करनेके लिए कहा जाना चाहिए। शिक्षाके सम्बन्धमें भारतीय समाजको पूरी सुविधाएँ देनेके लिए हलचल की जानी चाहिए।

इतनी बातोंके बारेमें जो सवथा सन्तोषजनक उत्तर दे उन्हींको मत दिया जाये। यदि ऐसा कोई न मिले तो किसीको मत न दिया जाये। हम समझते हैं कि इसमें भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा है और ऐसा करना उसका कतव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११६ एस्टकोर्टकी अपील

एस्टकोर्टके भारतीयोंने नगरपालिका मताधिकारके सम्बन्धमें जा अपील दायर की थी, उसका निणय उनके पक्षमें हुआ है। उसके लिए हम एस्टकोर्टके भारतीय बंधुआका बधाई देते हैं। इस अपीलका यह निणय हुआ है कि भारतीय समाजको एस्टकोर्ट नगरपालिकाके चुनावमें मत देनेका अधिकार है। अब सवाल यही रह जाता है कि उसका लिये आवश्यक सम्पत्ति आवेदकाके पास है या नहीं। इस विषयमें बहुत फूलनेकी बात नहीं है, क्योंकि अभी नगरपालिका विधेयक तो विलायतमें वैसा ही विचारार्थीन है। परन्तु समितिके प्रयत्नसे मालूम होता है, उस विधेयकपर बड़ी सरकारकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। फिर भी जिन्होंने अर्जी दी है वे अपने नाम मतदाता सूचीमें दर्ज करवा दें। इसका अतिरिक्त और कोई कदम उठाना हम उचित नहीं समझते।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०३

११७ राँसका पत्र

नेटाल रेलवेका मुख्य प्रबंधक श्री राँसने भारतीय समाजका अँगूठा दिखा दिया है। इस पत्रके कारण हम भारतीय समाजका बधाई देते हैं। जैसे जैसे ये लोग हमारे धर्मोंका अधिकाधिक अपमान करेंगे, हमारे रंगका अधिकाधिक निरस्कार करेंगे वैसा-वैसा, यदि हम सच्चे होंगे तो, हम अधिक जार कर सकेंगे। जैसा पत्र श्री राँसने लिखा है वैसा पत्रोंसे हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। यदि हमें बाकायदा हक नहीं मिलते, तो हमारा धन हमें खाने दौड़ेगा। समझदार व्यक्तिके लिए उसका धन प्रतिष्ठाके बिना काँटेके समान बन जाता है। सहायके रेगिस्तानमें किसीकी जेबमें मोनेकी इटे हो, किन्तु पानीकी बूँद न मिले तो वे इँटे जहरके समान लगेंगी। उसी प्रकार इस देशमें बिना मानके हमारा धन जहरके समान बन जायेगा। श्री राँसके पत्रके आधारपर तत्काल कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हमारी रायमें इन प्रश्नोंका निणय ट्रान्सवालकी लड़ाईके परिणामपर निर्भर है। बहुत आज्ञा करनेसे हमारे मौलवियों, पादरियों और पुजारियोंको आधी कीमतमें टिकट मिल सकते हैं, किन्तु हमारा सामने यह प्रश्न नहीं है कि टिकट मिलेंगे या नहीं। सच्चा प्रश्न तो यह है कि गोरोंकी नजरोंमें हमारी कोई गिनती नहीं है, और यही बात नुकसानदेह है। गिनतीमें आनेका यही रास्ता है कि ट्रान्सवालके भारतीय अन्ततक — मृत्यु पयन्त — जूझे और प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तब हम बिना मताधिकारके भी मताधिकारी हो जायेंगे।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०३

११८ डर्बनकी कृषि-समितिका ओछापन

हमारे अंग्रेजी विभागमे एक भारतीय व्यापारीने लिखा है कि समितिो भारतीयोको डवन प्रदर्शनीकी प्रतियोगितामे भाग लेनेसे मना कर दिया हे। यह बात बहुत ही बुरी हे। गोरे भारतीयोके परिश्रमसे डरते है, यह हम जानते है। मालूम होता है, वे भारतीयोकी कुशलतासे भी डरते है और इसलिए नादमे बैठे हुए कुत्तेका अनुकरण करते जान पडते है। वे न खाते है और न खाने देते है। समितिके इस कामसे सिद्ध होता है कि इस समय हमारा एक ही कतव्य है और वह हे मान मर्यादा प्राप्त करना। यह बात अभी तो ट्रान्सवालके भारतीयोके हाथमे हे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

११९ उमर हाजी आमद झवेरी

जून १८ के 'अखबारे सोदागर'^१ से मालूम हाता हे कि श्री उमर झवेरीने बम्बईके किनारे-पर पैर रखते ही भारतकी सेवा शुरू कर दी है। उनके सम्मानमे श्री जगमोहनदास सामलदासने अपने बगलेमे समारोह किया था। उसमे श्री उमर झवेरीने^२ भारतीयोकी हालतका चित्र खीचा। इसके अलावा उसी अखबारमे सवाददाताने उनके साथ मुलाकातका विवरण भी दिया है। वह तीन कालमोमे छपा हे। उसमे दक्षिण आफ्रिकामे होनेवाले कष्टोका सारा विवरण दिया गया हे। उपायके रूपमे बताया गया है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय तीस करोड भारतीयोकी मददपर भरोसा रखते है। श्री उमर झवेरीने अपने भाषणमे देशके भलेके लिए बैरिस्टर बननेका अपना इरादा फिर व्यक्त किया।

इस सबपर टीका करते हुए 'अखबारे सौदागर' के सम्पादकने श्री उमर झवेरीकी मागका समर्थन किया है और भारतीय समाजसे मदद करनेकी सिफारिश की है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१ बम्बईसे प्रकाशित होनेवाली एक गुजराती पत्रिका।

२ भूतपूर्व सयुक्त अवैतनिक मंत्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७४ प।

१२० एक पारसी महिलाकी हिम्मत

श्रीमती भीकाईजी हस्तमजी के० आर० कामाने 'सोशियलॉजिस्ट' में एक पत्र लिखा था, जा 'जामे जमशेद' में उद्धृत किया गया है। उसके इन जारदार शब्दाकी ओर हम अपने ट्रान्सवालके पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैं

भारतके पुरुषों और महिलाओं, मर्ने शब्दापर ध्यान दो और इस पाप कमका सामना करो। यह एक पुरानी कहावत है कि जो अपनी आजादी खाता है वह अपने आधे सद्गुण खोता है। इसलिए आजादी, इन्साफ और सच्चाईके लिए लड़नेका बाहर निकल पड़ो। भारतके लोगो, अपने मनमें निश्चय करो कि ऐसी गुलामीमें जीनेके बजाय सारी जनता मर जाये, वही अच्छा। यदि आप गुलामीमें जीते हैं तो भारत, ईरान और अरबिस्तानके प्राचीन स्वर्ण युगकी बातें करना बेकार है। बहादुर राजपूतो, सिक्खो, पठानो, गुरखा, देशामिमानी मराठा और बंगालियो, चंचल पारसियो, बहादुर मुसलमानों और आखिरमें नन्न जैना और धैर्यवान तथा महान बहुसंख्यक जनसमाजकी सन्तान हिन्दुओ, अपने प्राचीन इतिहासके अनुसार जिदगी क्या नहीं बिताते? इस तरह गुलामीमें क्या जी रह हा? बाहर निकलो।

श्रीमती भीकाईजी कामाको राजनीतिक जीवनका २० वर्षका अनुभव है। वे इस समय पेरिसमें रहती हैं। उन्हें अपने देशके लिए दद है। उन्होंने ये शब्द यद्यपि भारतके प्रति कहे हैं, फिर भी इस समय तो ट्रान्सवालके भारतीयोंपर लागू हो रह ह।

[गुजरातीमें]

इडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१२१ भाषण' . हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें

जाहानिसबग

अगस्त ११, १९०७

हमीदिया इस्लामिया अजुमन लगभग दो महीनेमें हर हफ्ते बैठक बुलाकर लोगोंमें साहस और उत्साह भर रही है। प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभाके लिए प्रिटोरियावालोंकी मदद करनेके विचारसे एक विशेष ट्रेनका इन्तजाम करके लगभग छ सौ व्यक्ति वहाँ गये थे। अजुमनका समाजपर यह एहसान है। हम आशा करते हैं कि अजुमन हमेशा ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। यद्यपि प्रिटोरियामें कुछ लोगोंने पंजीयन करा लिया है, किन्तु वे पछता रहे हैं। इसलिए हमारी बाजी बिगड़ी नहीं है। प्रिटोरियावालोंने लाज रखी है और उनसे भी अधिक पीटर्स-

१ गांधीजीने हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी एक बैठकमें पंजीयन अधिनियम विरोधी आन्दोलनका विवरण दिया था। यह उन्हींके भाषणकी रिपोर्ट है।

बगवालोने अपना कतव्य किया है। वहा किसी भी सज्जनने पजीयन नही कराया, यह बवाईकी बात है। सरकार जहा जहा कमजोरी देखती है, वहा वहा पजीयन कार्यालयका भेज देती है। मुझे लगता है कि श्री चैमनेको शायद यह खबर भी मिली हो कि पीटसबगमे लोग कमजोर हैं और वे सावजनिक सभामे भी शामिल नहीं हुए। इसलिए कार्यालय वहा गया था, किंतु सौभाग्यसे श्री जुसब हाजी वली और दूसरे लोगोंने मिलकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वेच्छया पजीयन कराने देगी, तभी वे उसे मांगेंगे, नहीं तो भले ही वह उन्हें देश निकाला या जेल दे, वे इस जहरीले कानूनको नहीं गानेगे। अब सरकार शिथिल पड गई लगती है, क्योंकि पीटसबगकी जेलमे जो दो आदमो थे, उन्हें फुसलाकर अँगुलियोकी छाप ली गई है। यह बड़ी शमकी बात है।

‘जूटपोंसबग रिव्यू’ लिखता है कि भारतीय समाज चतुर और योग्य है। उसके साथ सोच विचार कर बताव किया जाना चाहिए। हमारी लदनकी समिति भी इस समय बड़ी मेहनत कर रही है। यह सावजनिक सभाओका फल है। इस प्रकार हमें सभी स्थानोंसे मदद मिलनी शुरू हो गई है। फिर भी, हमें इतना तो याद रखना ही चाहिए कि कुछ व्यक्तियोंको जेलमे तो जाना ही है और यह सम्भव है कि सरकार उनमें से पहले मुझे पकड़े। दूसरे नेताओके विषयमे ऐसा ही है। सरकार चाहे मुझे और दूसरे नेताओको पकड़े, किंतु यदि आप लोगाने जो हिम्मत की है उसे कायम रखा, तो अतमें हमारी जीत है ही। अधिकारी परवानोंके बारेमें धमकी देते हैं, किंतु यह उनकी गलती है। हम बिना परवानोंके व्यापार कर सकते हैं। इसके कारण वे हमपर जुर्माना कर सकते हैं और यदि हम जुर्माना न दें, तो हमें जेल भेज सकते हैं। किंतु परवाना कानूनमे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें देश निकाला दिया जा सके। इसलिए हमारे लिए इसमें डरनेकी भी कोई बात नहीं है। अब पजीयन कार्यालय पाचेपस्टूम और क्लाक्सडाप जायेगा। यदि वहाके लोगोंने बुलाया, तो हम जायेंगे, नहीं तो जाना आवश्यक नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१२२ तार^१ पीटर्सबर्गके भारतीयोंको

[जाहानिसबग]

अगस्त ११, १९०७]

अजुमन पीटर्सबर्गके भारतीयोंको उनके शानदार प्रेदाग नामा और वीरता के साथ डट रहनेपर बधाई देती है। यदि हम अतन्त्र न रहेंगे तो परमात्मा हमें सफलता प्रदान करेगा।

[हमीदिया इस्लामिया अजुमन]

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०७

१२३ तार पाँचेपस्ट्रूमके भारतीयोंको

[जाहानिसबग]

अगस्त ११, १९०७]

आशा है वहाँके भारतीय अनमतिपर कार्यालय स्वी मंगमागिने बचेंगे। उसका स्पष्ट हमारी राष्ट्रायताको भ्रष्ट और हमारे समुदाय पर आघात करना है।

[हमीदिया इस्लामिया अजुमन]

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०७

१ गांधीजी हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी समझमें, जो ११ अगस्तको हुई थी, शामिल हुए थे और बोले थे। इस समझमें तय हुआ था कि पीटर्सबर्ग और पाँचेपस्ट्रूमके भारतीयोंकी तार भेजे जाय (देखिए अगला शीर्षक)। अनुमानतः इन तारोंकी जिम्मेदारी गांधीजीपर थी।

१२४ पत्र 'रैंड डेली मेल' को

जोहानिसबग

अगस्त १२, १९०७

सेवामे

सम्पादक

[रैंड डेली मेल]

महोदय,

आपने एशियाई अभिनियमपर अपने विशेष लेखको इस उत्तेजक शीर्षकसे आरम्भ किया है "भारतीय कज नहीं चुकायेगे"। इस लेखकी सयत भाषा प्रकट करती है कि यह किसी बुरे इरादेसे नहीं लिखा गया है। साथ ही यदि आप तबतक । -- -- -- दीखनेवाली इस बातको छापनेसे हाथ रोके रहते, जबतक ब्रिटिश भारतीय समाजके नेताओसे मिल न लेते, त। यह आपके पाठकोकी अवश्य ही अधिक अच्छी और अधिक उपयोगी सेवा हुई होती। जाहिर है कि आपको उन नेताओकी राये मालूम नहीं है।

अब मुझे यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि, जहातक मैं जानता हूँ, एक भी प्रतिष्ठित भारतीय ऐसा नहीं है जिसने कभी इस आशयका बयान दिया हो कि प्रत्येक भारतीय "जो अनाक्रमक प्रतिरोधके कारण जेलमे जायेगा अथवा अपने व्यापार या फेरीके परवानेसे वंचित किया जायेगा, अपना ऋण चुकानेसे इनकार कर देगा।" यह हमारे सधषकी भावनाके सवथा विरुद्ध होता। हमने ईश्वरके ऊपर पूरा भरोसा करके स्वयं कष्ट सहन करनेकी दष्टिसे इस आंदोलनको आरम्भ किया है। इसलिए, अपने वाजिब कजसे इनकार करनेका विचार रखना और उसे देनेसे इनकार करना हमारे लिए दुष्टताकी बात होती। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हमारा विश्वास है कि जो कर्ज हम इस जिदगीमे अदा नहीं कर सकते वे दूसरे जन्ममे कठोर दण्डके साथ हमें चुकाने होंगे। कयामतके दिन हमें अपने पापोंका जवाब देना होगा और कज न चुकाना उन पापोंमे कोई छोटा पाप नहीं है।

हम अवश्य ही हर तरफसे जोर डालना चाहते हैं। हम बेशक शाही सरक्षण चाहते हैं और उपनिवेशियों और सरकारकी सहानुभूति भी उससे कम नहीं चाहते, परन्तु हम यह किसी ऐसे उपायसे नहीं प्राप्त करना चाहते जो बिलकुल स्वच्छ और प्रामाणिक न कहा जा सके। हम जिसे अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठापर अकारण आक्रमण मानते हैं उसके विरुद्ध हमारे बचावका केवल एक ही अस्त्र है कि हम दक्षिण आफ्रिकाके लागो और उस विशाल साम्राज्यके नागरिकोंको, जिसके अग होनेका गोरोके समान हमारा भी दावा है, दिखा दे कि जिसे हम हृदयसे महा अध्याय समझते हैं उसके लिए कष्ट उठानेकी मर्दानगी हममे है।

मैं अपने साथी व्यापारियोंसे, जिनसे जल्दीमे मैं मिल सकता था, मिला हूँ। वे ह — सवश्री एम० सी० कम्पनी, एंड कम्पनी, एम० एस० कुवाडिया, एम० ए० करोडिया ए० एफ० कमे एंड कम्पनी, आमद मूसाजी एंड कम्पनी, एम० पी० फैसी, मुहम्मद हुसैन एंड कम्पनी और जुसब इब्राहीम। ओर हम लोग पिछले महीनेसे अबतक लगभग १८,००० पौंड यहाकी और लन्दनकी

थोक व्यापारी फर्मों का चुकता कर चुके हैं। हममें से कुछने आकस्मिक जरूरतों की तैयारी करने के लिए अवधि में पहले ही अपने ऋण चुका दिये हैं। यह सत्य है कि हममें से बहुताने इस सघपके कारण अपने माल खरीदने के आदेश रद्द कर दिये हैं। उन थोक व्यापारी फर्मों के लिए और हमारे लिए उचित भी यही है। हमें अफसोस है कि हमारे ऐसा करने में उन थोक व्यापारी फर्मों का हमारे साथ साथ हानि उठानी पड़ेगी, परन्तु वह अनिवार्य है।

आपका, आदि

ईसप इस्माइल मियाँ

सुलेमान इस्माइल मियाँ व कम्पनी के प्रबन्धक साझे

और कायवाहक अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय मण

[अंग्रेजी में]

रड डेली मेल, १३-८-१९०७

१२५. पत्र जनरल स्मट्स के निजी सचिव को

जोहानिसबर्ग

अगस्त १५, १९०७

जनरल स्मट्स के निजी सचिव

प्रिटोरिया

महोदय,

आपने एशियाई कानून संशोधन अधिनियमक सम्बन्ध में मेरे / तारीख के पत्र के उत्तर में १४ तारीख का जो पत्र भेजा है, मुझे उसकी प्राप्ति स्वीकार करना सम्मान प्राप्त हुआ। मैं सम्बन्धित अधिनियम के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट रूप में बताने के लिए जनरल स्मट्स को धन्यवाद देता हूँ।

मेरी विनीत सम्मति में, मेरे सुझावे द्वारा संशोधन एशियाई कानून संशोधन अधिनियम का प्रधान मन्त्र का कार्यान्वित हो जायेगा, अर्थात् उनसे उपनिवेश में रहने के अधिकारी प्रत्येक एशियाई की शिनाख्त हो जायेगी।

१ जनरल स्मट्स के निजी सचिव ने गोपनीय रूप से लिखा था “ मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि श्री स्मट्स उन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जो आपने प्रवासी प्रतिबंधक विधेयक में रखे हैं, क्योंकि उस विधेयक में ऐसे संशोधनों से, यदि वे सम्भव हों तो, १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम के सब विधान बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे और इसके अतिरिक्त चूंकि विधेयक में इस स्तर पर इन संशोधनों को स्वीकार करना असम्भव है उपनिवेश-सचिव एशियाई कानून संशोधन अधिनियम की सब धाराओं को पूरी तरह बमल में लायेंगे और यदि इस देश के निवासी भारतीयों के प्रतिरोध से वे परिणाम निकलते हैं, जो इस समय उनके सामने गम्भीर रूप में प्रस्तुत नहीं हैं, तो इसमें दोष केवल उनका और उनके नेताओं का होगा।”

मैंने जनरलका ध्यान अधिनियमके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंकी गम्भीर घोषणाकी ओर आकर्षित किया, इसके लिए मैं कोई क्षमा-याचना नहीं करता। जहातक मैं अपने देशवासियोंको सलाह दे सकता हूँ, परिणाम जो भी हो, मेरे लिए उनको अपनी ऐसी विचारपूर्वक की गई घोषणाको त्याग देनेकी सलाह देना सम्भव नहीं है। और यदि ऐन वक्तपर जनरल स्मट्सके लिए अधिनियमके मतव्यको किसी प्रकार सीमित किये बिना उस घोषणाको मान लेना सम्भव हो तो मैं उनकी सहानुभूति और सहायताका प्रार्थी हूँ। मैंने अपने देशवासियोंको जो सलाह दी है उसपर चलनेके सम्भावित परिणामोंसे कभी अपनी आखे बंद नहीं की हूँ अर्थात् यदि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक उपनिवेशकी विधि संहितामें सम्मिलित हो जाये तो प्रत्येक भारतीयको जेल भेजा जा सकता है, व्यापारियों और फेरीदारोंके व्यापारिक परवाने छीने जा सकते हैं और नेताओंको निर्वासित किया जा सकता है। किन्तु मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अधिनियमका पालन करना उन सब जोखिमोंसे अधिक बुरा होगा जो उसका पालन न करनेसे उनपर आ सकती है।

मेरा यह पत्र व्यवहार जनरल स्मट्ससे व्यक्तिगत अनुरोधके रूपमें है और खानगी है, किन्तु चूँकि मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि सरकारके इरादे यथासम्भव मेरे देशवासियोंके सम्मुख व्यापक और यथाथ रूपमें रखे जाये, इसलिए यदि जनरल स्मट्सको कोई आपत्ति न हो तो मैं इस पत्र व्यवहारको प्रकाशित करना चाहूँगा।^१

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ यह २४-८-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था। देखिए “पत्र ‘इंडियन ओपिनियन को’”, पृष्ठ १७७।

१२६ भारतीय प्रस्तावका क्या अर्थ ?

अब अन्तर्निपत्र न्यायालय गांव गांव भटकता फिर रहा है। अंगरेजी ठाग घर घर दलालाके समान घूम रहा है। व ठागाका उद्देश्य और समझात है कि उह नय कानूनके अनुसार पजीयन पत्र देना चाहिए। उसके अलावा व उहने ठागाम ही पूछत है कि उनकी मांग क्या है। उसलाग यह जरूरी है कि स्वयमेव प्रत्येक भारतीयका पजीयनका अब समझा। हम स्वयंकर यकी है कि इस प्रकार ठागाही पराधा हो रही है। नय कानूनक बारेमें प्रत्येक भारतीयका पूरी और स्वतन्त्र वक्ता हानी चाहिए। हम आश्चर्य ठागाकी परीक्षामें नहीं, बल्कि तब हागा जब हम जवाब न दे सके। अब अब हम स्वच्छया पजीयनक अपर विचार कर।

कानूनके अनुसार सरकार ठागाका नय पजीयनपत्र देने के लिए विवश कर सकती है। इतना ही नहीं वह उन पजीयनपत्राका बार बार बदलवाने के लिए भी विवश कर सकती है। साथ ही वह ठागाम चाहें जरा अगठिया लगाना सकती है। उच्चारी अगठिया भी लगाना सकती है। और परधाना तब समय अगठिया लगा सकती है। संक्षेपमें नय कानूनकी मारी यानी उपधारण ठागू हो सकता है। यह हमें मजर नहीं है। उसका उद्देश्य हमें सरकारमें रहत है कि उसका शक दूर करने के लिए हम मौजदा अन्तर्निपत्र बदलनेका तैयार ह। उस प्रकार जो खुशियं पजीयनपत्र बदलवा व उनपर नया कानून ठाग नहीं हो सकता और न काउ उपधारण ही लागू हो सकती है। यानी हमें जगह जगह अगठियां नहीं लगानी पडगी। और यदि प्रत्येक भारतीय स्वच्छया पजीयनपत्र के तात्पनी साता प्रिट्ठर रद्द हो जायेगा। यदि कोई भारतीय गफलतमें या जान बूझकर अन्तर्निपत्र न बदलवाये तो केवल उसीपर नया कानून लागू हागा। उस प्रकार हमारी मांग और सरकारी कानूनमें जबरदस्त अन्तर है। सरकारी कानून तो गरीबी सवारी है। और उस सवारीमें भारतीय समाजकी फजीहत हानी है। हमारी मांग हागीकी सवारी है और उसमें हम वात्साही और मान भोगते हैं।

उस मांगके अलावा प्रिटरियाक कुछ ठागाने वकीलकी मागफत श्री स्मट्सका जा पत्र लिखा है उसपर जरा विचार कर। श्री स्मट्समें कुछ परिवर्तन करनेकी मांग की गई है। उसे हम महलाना कहत हैं। भगदरका साधारण फाग मानकर यदि कोई खरोच डालता है तो कभी-कभी जरूर ऊपर ऊपर सूख जाता है। उसमें भगदरका रागी कभी-कभी मान लेता है कि उसका राग मिट गया। किन्तु वास्तवमें भगदर तो भीतर ही भीतर काम करता रहता है और भ्रममें पडा हुआ रोगी थोड़ा दिनाम दूसरी जगह फाडा देगता है और जबतक वह भगदरका इलाज नहीं करता, फाड हाते और मिटते रहते हैं। यही बात हम उपयुक्त कागजके सम्बन्धमें समझते हैं। भगदरके रागरूपी इस कानूनके लिए दो चार चीजें निकाल देना कतई कोई इलाज नहीं है। यह केवल मन बहलावके लिए है और हम मानते हैं कि इससे आखिर अधिक दुख सहन करना होगा। इस भगदरी कानूनके लिए जबरदस्त शल्य प्रक्रिया किये बिना और कोई चारा नहीं है। यह बात प्रत्येक भारतीय को जाननी चाहिए। अब कानूनके बारेमें जब भी पूछताछ हो तो हमारी यही मांग होनी चाहिए कि कानून बिल्कुल रद्द किया जाये, यह हमें साफ तौरसे समझ लेना चाहिए। और यदि यह कानून रद्द हो तो

हम झूठ लोगोको छिपाना नहीं चाहते, यह सिद्ध करनेके लिए हम स्वेच्छया पजीयन करवाने को तैयार हैं, किन्तु उतना करवा लेनेके बाद हम अपनेपर कानूनका हमेशाका सिर दद नहीं रखना चाहते।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१२७ पीटर्सबर्गको बधाई

प्रिटोरियाने ठीक कर दिखाया। लेकिन पीटसबगने तो हृद कर दी। वहा एक भी “कल पगा या कल मुहा” नहीं निकला। अनुमतिपत्र कार्यालयका शत प्रतिशत बहिष्कार किया गया, और अनुमतिपत्र कार्यालयको बिना कलेवा, खाली पेट लौटा दिया गया। वह बला फिर पीटसबगमे कदम न रखे, इसके लिए सरकारके पास पहले ही आवेदन भेज दिया गया है कि हमे कार्यालय नहीं चाहिए। इससे अधिक कोई भी गाव नहीं कर सकता और इससे कम एक भी गावको करना नहीं चाहिए।

कैदमे पड़े हुए दो व्यक्तियोंका जबरदस्ती अनुमतिपत्र दिया गया उससे पीटसबगका सम्मान रत्ती भर भी नहीं घटता। देशमे अकाल आता हे तो अकाल पीडित लोग पेट भरनेके लिए अखाद्य वस्तुएँ खा जाते ह। भूखे कुत्ते पाखाना चाटते हैं। उसी तरह खूनी कानूनके अधिकारीने भक्ष्य न मिलनेपर जेलमे जाकर जबरदस्तीसे जो नया अनुमतिपत्र दिया उसमे उसने अकाल पीडितके समान ही काम किया है और वह बताता हे कि नये अनुमतिपत्र लेनेमे सम्मान नहीं बल्कि अपमान हे। हम पीटसबगके लोगोको बधाई देते हैं। उन्होने जुलाईकी अंतिम तारीखको दूकाने बाद न करनेका जो महान अपराध किया था वह इसके द्वारा धुल गया हे और वे बहादुर भारतीयोकी दूसरी पकितमे आ बैठे हैं। अपनी इस तरक्कीमे उहे यह याद रखना हे कि वास्तविक लड़ाई अब आनेवाली है। जेलमे जाने और यह दिखानेका समय चला आ रहा है कि धनसे मान व देश अधिक प्यारा है। उस समय भी, हमे आशा है, पीटसबग हिम्मतभरा उत्तर देगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१२८ हनुमानकी पूँछ

कहा जाता है कि ठका जलाये जानेके पहले जैसे जैसे वानर हनुमानजी आगे बढ़ते गये वग वग उनकी पूँछ खानग बनी गई थी। उसी प्रकार नये पंजीयनका दफ्तर भी जैसे-जैसे आगे बढ़ता है वैसा वैसा उसका खजन बढ़ता जा रहा है। प्रिंटारियाका नाटिम निकला तब प्रिंटारियाका मंत्र भानीया पंजीकृत होना था। कार्यालय मंत्र पीटमंत्र पहुँचा तब प्रिंटारियाको पीटमंत्रमंत्र पंजीकृत होकरा जगह पर मिठा। पात्रफुट्टमंत्र बहाने भानीया। मंत्रा प्रिंटारिया तब पाटमंत्रमंत्र भारतीय भी पंजीकृत हो सकने। और कलाकर्मकारम उपयुक्त तीन सहाराके भारतीयको गुलामीका पट्टा लनेका अवसर दिया जायगा। उस प्रकार पंजीयन कार्यालयकी पूँछ लम्बी होती जा रहा है। हम प्रिंटारियाका भावना प्रती महानभि व्यक्त करते हैं, क्योंकि जगतका कार्यालय आगिरी जगह पर नहीं पहुँचगा तबतक उनका पीड़ा नहीं छुटेगा। यह सजा रही उसलिय ता नहीं दी गई * कि प्रिंटारियामें गद्दार और मित्र हैं। किन्तु हनुमानजी और कार्यालयमंत्र मंत्र मंत्र *। हनुमानजीकी मछल पर जितना तल डाला गया तथा चीयडे लपटे गये उनभी ही ठकास ज्यादा जाग लगी किन्तु हनुमानजीका आँच नहीं लगी। पंजीयन कार्यालयका काम खनी वानुनका जमलमें लाना *। उसलिय उसकी यात्राम जा गर्मी पैदा होगी उसमें, सम्भव है मंत्र वानून और कार्यालय दाना जगह पर भस्म हो जायेगे, क्योंकि भारतीय समाज लगी लवाका जगह सम्भव नहीं है। भारतीय समाज निर्दोष है और जलानेवाका कानन दागी है।

[गजगतीस]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१२९ नेटालके व्यापारियोंको चेतावनी

नेटाल सरकारके 'गजट'में एक विधेयक प्रकाशित हुआ है। उसके पास हो जानेपर यदि कोई व्यापारी अपना दूकान रेचना चाहगा ता उसे 'गजट'में और अपने आसपास प्रकाशित होनवाक अयद्वारमें चौदह दिन पहले सूचना छपवानी होगी। नये परवाने लनेवाको भी वैसी ही सूचना छपवानी होगी। ये दोनों शर्तें कड़ी हैं, फिर भी भारतीय काम इनका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि ये सबपर लागू हानी ह। उसी विधेयकमें एक शर्त यह भी है यदि किसी वजहकी मीयाद पूरी हो गई हो और कोई विशेष इकगार न हो तो उसपर अदालत आठ प्रतिशतमें ज्यादा ब्याज नहीं दिला सकती। किसी व्यापारीने किसी चीजकी बहुत ज्यादा कीमत ली हो तो उसके कारण इकगार रद नहीं हो सकता। यह विधेयक सरकारी है और सम्भव है पास हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१३० धोखा ?

इस अककी बहुत-कुछ सामग्री लिखी जा चुकी थी तब हमने सुना कि प्रिटोरियाके गद्दारोकी जो सूची हमने प्रकाशित की है वह पूरी नहीं है। पिछले अकमे हमने कुछ मेमन लोगो और एक हिन्दूका नाम प्रकाशित^१ किया है। हमे अभी मालूम हुआ है कि उनमे कुछ कोकणी भी है। उनके नाम हम यहा दे रहे हैं^२

साथ ही हमने यह भी सुना है कि पीटसबगमे जेलके अन्दरके दो व्यक्ति ही नहीं तीन-चार और भी पजीकृत हुए हैं। यदि यह बात सच है तो बहुत खेदजनक है। समाजमे ऐसे लोग मौजूद जान पड़ते हैं जो काला मुह करनेके बाद भी मनुष्य होनेका पाखण्ड करते हैं। कोकणियोने प्रिटोरियामे साफ साफ कहा है कि एक भी कोकणीने अर्जी नहीं दी। पीटसबगमे तो उपनिवेश सचिवको जो अर्जी दी गई है उसमे उपर्युक्त चारो व्यक्ति शामिल हैं। इसलिए दगाबाजीके ये दोनो मामले बहुत बड़े माने जायेगे। सौभाग्यकी बात यही है कि ऐसे दगाबाज लोग बहुत थोड़े हैं। फिर भी समाजमे ऐसे लोग मौजूद हैं, इससे अच्छे लोगोको बहुत चेतकर चलना चाहिए। ये सब कुल्हाडीके बेटकी बात याद दिलाते हैं। इस समाजको ऐसे लोगोके द्वारा जितना नुकसान पहुँचेगा, उतना खूनी कानून या सरकारसे नहीं। जो खुले आम जाकर पजीयन करवायेगा वह एक प्रकारसे मद माना जायेगा। किंतु जो चोरीसे पजीयन करवाकर साहूकार बनेगा उसे हम कौनसी उपमा दे ?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१ देखिए “हमारा कर्तव्य”, पृष्ठ १५६ ।

२ मूलमें दिये गये नौ नाम यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं ।

१३१ मोरक्कोमें उपद्रव

मोरक्काम अभी हाथी मुलग रही है। रसूलीने आतक फैला रखा है। तेजियरमें लूटपाट मची है। बहुत ठग फल हा गये ह। दा मौ औरते गिरफ्तार की गई है। बलात्कार भी हा रहा है। यहदियाका ज्यादा नुकसान पहुँचा है। सामान्यकाम अधेर हा रहा है। ऐसे तार गायटरके आय है। गायटरने यह भी कहा है कि मोरक्काक मुठतानका कहना है कि यदि यूरोपीय सनाए आ जायेगी ता जितनी कामे उनक बाबूमे है व भी नहीं रहगी। इसमे कितना सच है यह हम नहीं जान सकते। कहा जाता है कि रसूलीन सर हनरी मैक्लीनका छाड दिया है। रसूलीके वारम एक जमन लेखकका कहना है कि वह तजम्बी और बहादुर योद्धा है। बचपनस उमे सबशी ठूटनकी आदत थी। कुछ समयके ठिग वह तजियरका सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। किन्तु अभी कुछ वर्षोंस लटर डकैतका काम कर रहा है। उसने बहुत-से गाराका पकड़ रखा है। वह मौतका साथ लेकर फिरता है और उसका कहना है कि उसकी मृत्यु किसीकी चाटस नहीं हानी चाहिए। रसूलीका मार्गका बहुत ठगान प्रयत्न किया है, किन्तु वह इतना सतक और फूर्तीठा है कि सजब हाथमे पच जाता है। हमे आशा है कि हम आग चठकर बनावग कि मोरक्काम कैसा अधेर हा रहा है। इससे हमारे पाठकका वहाँकी स्थिति और भी अच्छी तरह मात्म हा सकेगी।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३

१३२ हेगर साहबका नया कदम

हेगर साहब भारतीयोंक पीछे पड़े हुए है। एक बात समाप्त हुई ता दूसरी खड़ी ही है। अब वे महापय उन गरीब भारतीयोंक पेटपर लान मारना चाहते ह जा इनके कामसे रोजी कमाने हैं। वे समदमे ऐसा विधेयक पश करना चाहते हैं जिससे नेटालम कार्ड भी भारतीय किसी गारे अधिकारीकी देखरेखके बिना इनका काम कर ही न सके। यदि यह कानून अमलम आया ता कुछ भारतीयोंकी रोजी जाना सम्भव है। किन्तु आशा ता की जा सकनी है कि यह विधेयक मजूर नहीं होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३

१३३ कच्ची उम्रमे बीड़ी पीना रोकनेका कानून

कुछ ही दिन हुए नेटाल ससदमे उपयुक्त कानून पास हुआ है। उसका अनुवाद धारा-प्रति धारा नीचे दिया जाता है

(१) १६ वर्षसे कम उम्रके लोगोका तम्बाकू सिगरेट या सिगार पीना गर कानूनी माना जायेगा। [ऐसे लोगोके पास] तम्बाकू, चिलम सिगार, सिगरेट या सिगरेट होल्डर दिखाई दे तो गोरा पुलिस अधिकारी उसे जब्त करके सरकारको सौंप दे।

(२) पाठशालामे जानेवाले किसी बच्चेके पास उपयुक्त सिगरेट आदि जो भी चीजे मिलेगी, उहे पाठशालाका शिक्षक छीनकर उसके अभिभावकको सौंप देगा। यदि शालामे जानेवाले बच्चे तम्बाकू पीते मालूम होंगे तो उहे शालाके नियमके विरुद्ध काम करनेके अपराधमे दण्ड दिया जा सकेगा।

(३) माता पिता, अभिभावक या मालिककी चिटठी न हो तो १६ वर्षसे कम उम्रके बच्चेको तम्बाकू, सिगार या सिगरेट न दी जाये या न बेची जाये। चिटठी अथवा हुक्ममे यह लिखा होना चाहिए कि सिगरेट वगैरह चीजे १६ वर्षसे अधिक उम्रके लोगोके उपयोगके लिए हैं, और वे हम्ना तम्बाकूको सौंप दी जायेगी। इस तरहका लिखित पत्र प्राप्त हुए बिना १६ वर्षसे कम उम्रके बच्चोको सिगरेट वगैरह देना या बेचना गर कानूनी माना जायेगा। इस धाराके उल्लंघन करनेवालेको प्रति अपराधके लिए ५ पौंड तक जुर्मानेकी अथवा एक महीने तक की कैदकी सजा दी जा सकेगी।

(४) जो माता पिता, अभिभावक या मालिक न होते हुए भी १६ वर्षसे कम उम्रके लडकेको सिगरेट वगैरह खरीदने भेजेगा उसे ५ पौंड तक का जुर्माना अथवा एक महीने तक की सजा दी जा सकेगी।

(५) इस कानूनके सम्बन्धमे उम्रका प्रश्न खडा होनेपर अय सन्तोषजनक सबूतोके अभावमे अदालत व्यक्तिके चेहरेपर से उम्र निश्चित करेगी ओर वह ठीक मानी जायेगी।

(६) इस कानूनको १९०७ का धूम्रपान निरोधक कानून कहा जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन जोपिनियन, १७-८-१९०७

१३४ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पीटर्सबर्गकी बहार

पीट्सबर्गकी बहादुरीकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। अब धावा पाचेपस्टूम और क्लाक्सडापपर है। ये दोनों नगर पीट्सबर्गसे आगे बढ़ जायेंगे सो नहीं, किन्तु पीट्सबर्गसे कम तो किसीका करना ही नहीं है। पीट्सबर्गके जागमें अखबारा और रागाम खलबली मची हुई है। भागतीयोका उत्साह बढ़ गया है। पीट्सबर्ग हमारी सफलताका दा कदम आगे ले गया है। प्रिटोगियाके समान पीट्सबर्गमें भी स्वयमेवक बने थे। उनके नाम ये हैं

श्री हमराज, श्री ए० गोवल, श्री डी० एच० जुमा, श्री तैयब एन० मुहम्मद, श्री कामिम मुठेमान श्री ए० देसाई, श्री गुलाब नवा मुख्य स्वयमेवक श्री हामिम मुहम्मद काला।

ये बहादुर बधाईक पात्र हैं।

‘कलेवाकें बिना’

जोश भर तार बहुत-से भारतीयोंका भेजे गये थे। उनमें से एकने तुरन्त जवाब दिया है कि पजीयन कार्यालय पीट्सबर्गमें कलेवा बिना जायेगा, यानी उस कार्यालयका भक्ष्य भारतीय है, और भारतीय पजीयन न कराये तो कार्यालय भखा ही कहलायेगा। उसका उपवास टूट ही नहीं पाया, तो वह बिना कलेवेके गया इसके अलावा क्या माना जायेगा? जेलके अंदर पजीयनके लिए जा अर्जी दी गई है, उसे गिनतीमें नहीं लिया जा सकता।

पीटर्सबर्गकी तार

सध और हमीदिया अजुमनने बधाईका तार भेजा है। अजुमनने बधाई देते हुए कहा है “अगर हम आखिर तक जोर कायम रखेंगे तो खुदा हम फतह देगा।”

पॉचेपस्टूम और क्लार्क्सडॉर्फ

कार्यालय इन दोनों शहरोंमें इस सप्ताहके अन्ततक पहुँच जायेगा। इससे हमीदिया अजुमनने निम्नलिखित तार भेजा है

आशा है कि अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी महामारीसे आप मुक्त रहेंगे। उसके स्पशसे हमारे समाजको धब्बा लगता है और हमारी धर्म भावनाको चोट पहुँचती है।

इन दोनों जगहोंसे तारपर तार आये हैं कि दोनों स्थान बहुत दृढ़ हैं। नया पजीयनपत्र लेनेवाला कोई नहीं है। दोनों जगहोंके लोगोंका कहना है कि “हमें जोहानिसबर्गसे किसीकी मदद नहीं चाहिए। हम सब एम्पायर नाटकघरमें ली हुई शपथपर दृढ़ हैं।” हम चाहते हैं कि सारे भारतीय ऐसा जोश अन्ततक रखें।

१ देखिए “तार पीटर्सबर्गके भारतीयोंको”, पृष्ठ १३२।

२. देखिए “तार पॉचेपस्टूमके भारतीयोंको”, पृष्ठ १३२।

लडाईका असर

कह सकते हैं, आज तक की लडाईका असर अच्छा हुआ है। 'रड डेली मेल' में प्रकाशित हुआ है कि भारतीयोंपर गोरोका कज है। यदि भारतीय जेल गये अथवा उन्हें परवाना नहीं मिला तो वे वह रकम नहीं चुकायेगे। 'मेल' वाला यह उडती हुई बात लिख कर कहता है कि भारतीय नेताओंके विचारोंका कुछ पता नहीं है। इस खबरसे गोरे व्यापारी घबड़ाये जान पड़ते हैं। यह असर अच्छा मानना है। अब कोई भारतीयोंका मजाक नहीं उड़ाता बरिक् लोग मानते हैं कि मामला नाजुक है। 'मेल' वाले ने यह भी लिखा है कि भारतीय समाजको विलायतके कई बड़े-बड़े लोगोंकी मदद है। श्री रिच काम कर रहे हैं और लोक सभाके सौ सदस्योंने कहा है कि यदि भारतीयोंके साथ 'याय' नहीं किया गया तो ट्रान्सवालको जो ५०,००,००० पौंडकी सहायता दी जानेवाली है उसका विरोध किया जायेगा।

ईसप मियोंका जवाब

उपर्युक्त लेखका श्री ईसप मियाने निम्नानुसार जवाब दिया है ^१

'स्टार' की टीका

'स्टार' समाचारपत्रने 'डेली मेल' के लेखपर तुरन्त ही एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित की है। उसका सारांश निम्नानुसार है

ब्रिटिश भारतीय सघका अनाक्रमक प्रतिरोध अभीतक बहुत सफल रहा है। भारतीय नेता मानते हैं कि कानूनपर उसकी अन्तिम सीमा तक अमल नहीं किया जायेगा यानी जिहोने अनिवाय पजीयन कानूनके अन्तगत पजीयन न करवाया हो, उहे कैद या निर्वासित नहीं किया जायेगा। प्रलोभनमें आकर पजीयन करवानेवाले भारतीयोंकी सरया राजधानीमें ७० है। पीटसबग और जूटपान्सबगके भारतीयोंने पजीकृत होनेसे इनकार कर दिया है। पाचेफस्ट्रूम और क्लाक्सडॉपके लोगोंने भी इसी तरहका निणय जाहिर किया है। जोहानिसबगमें बहुत भारतीय हैं। उनमें कुछ धनवान हैं। उन सभीने कानूनका विरोध करनेका निणय किया है। सरकार जोहानिसबगमें कार्यालय खोलेगी या नहीं, इस विषयमें भारतीय अनेक अनुमान लगा रहे हैं। सरकार धीरे धीरे चल रही है। श्री चैमनेकी रिपोर्ट पहुँचनेपर निश्चित कदम उठाये जायेगे। जोहानिसबगमें सरकार कार्यालय न खोले, ऐसे लक्षण तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं।

देश छोड़नेका समय आ जाये तो उसके लिए भी भारतीय व्यापारी धीरे धीरे तैयारी करने लगे हैं। कामा और कम्पनी ('स्टार' द्वारा भूलसे लिखे अनुसार चैमने और कम्पनी) के बड़े साझेदार एक पारसी सज्जन श्री कामासे 'स्टार' का प्रतिनिधि मिला था। उस समय बताया गया कि उक्त कम्पनीने अपने विदेशोंके आडर रद कर दिये हैं, और स्टोक कम करना शुरू कर दिया है, जिससे जब भी उसे ठिकाने लगाना हो, आसानीसे लगाया जा सके। और यही बहुतसी जगहोंमें हो रहा है। एक सहयोगीने प्रकाशित किया है कि वे कजकी रकम चुकानेसे इनकार करते हैं। इस बातका भारतीय व्यापारियोंने पूरी जिम्मेदारीसे खण्डन किया है। एक व्यापारीने आज कुल ४३७ पौंडका

विठ चुकाया है। दूसरे व्यापारीन आज सबर ३०० पाउ दिया। रजकी रकम न ठोठानकी सहाय सधन नही दा। अबवारम उस तरहकी गन्त गन्तर उपनम उह आचय हुआ या।

अन्तानामक प्रतिगारक उस आदारनक नता प्रमिद्व भारतीय प्रमिद्व श्री मो० क० गांधी है। जान पडता है, सबमच ही उन्हान अपनी मनाका अच्छी तारीम दी है। सामान्यत भारतीय अ ननक उनके पीठ चरनको नयार हा गय है।

इस सभमे मिद्व हाता है कि भारतीयाने जा शक्ति दिया है उस फल लगन रगा है।

फ्रीडडॉप अध्यादेश

यह अध्यादेश अब ठिकाने लग गया है। पहला अध्यादेश रूपा गया है और नया पास किया गया है। उसके अनुसार भारतीयाना चार वर्ष तक नही निर्यात जा सकता और चार वर्ष बाद भी उह जो नकसान हागा उसका हजाना दिया जायगा। उस नकसानक लिए चार वर्षा नाटिम रहता हागा। उसम व्यापार और उद्योगिके नकसानका ता समावेश नही है, किन्तु बर हुए मरानाका कीमतका समावेश है। अतः अत मानना चाहिय कि फ्रीडडॉपके भारतीय व्यापारिका चार वर्षकी अवधि मित्री है। उस जीतका श्रेय श्री रिचका दिया जाना चाहिय। उहान विरायनम बहुत परिश्रम किया। उमीरा यह परिणाम है। सबर यही एक उपशारा है गट है कि चार वर्ष बाद नौरव वगव सिवा और काउ काउ राग नही रह सकग। किन्तु इस रद करना सम्भव नही है। श्री स्मथका उतर रूपा दिया जाय। लकिन चार वर्ष उधर हाता है 'जर मरुम जाय रिच कीर'। फिर भारतीय फ्रीडडॉपम भी रह जाय ता इसे दक्षिणाम मानाका यात समझ रना चाहिय।

एस० एस० कुवाडिया

स्वयंम स्वयं आई है कि सधन कापा यक्ष श्री एस० एस० कुवाडियाकी प नीका स्वयं-वास हा गया है। यह स्वयं म शक्ति के साथ प्रकाशित करना हूँ और श्री कुवाडियाक प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हूँ।

मुहम्मद ईसप राहरी

श्री मुहम्मद ईसप, जा हमीदिया इस्लामिया अजमनक सदस्य है उस मासके अन्तम हज करनेके लिए मक्का शरीफ जानवार है। उनकी मुगद पूरी हा यह मरी कामना है।

हमीदियाकी बैठक

हमीदिया इस्लामिया अजमन नये कानूनके सम्प्रदाम पूरी ताकतमे काम कर रही है। हर हफ्त बैठक बलाई जाती है जिसमे सभी कीमाक भारतीय भाग लेते है। पिछठ रविवारकी बैठकके अध्यक्ष हमाम अब्दुल कादिर थे। श्री गांधीन मारी हकीकत समझाई। उनके बाद ईसप मिया बाल। उन्हाने कहा कि इस मौकपर श्री गांधी जेल जाये या निर्वासित हा फिर भी लोगोको पूरी हिम्मतके साथ रहना चाहिय। धनकी भी जरूरत हागी। अतः जिनके पास धन हो उन्हें धन देना चाहिय। अन्तमे मौलवी अहमद मुख्तार तथा महाराज राममुन्दर पण्डितने

१ प्रतियोगितामें भेजी गई एक कविताका उद्धरण “केल-महलमें जायें हिन्दके द्वारे”। देखिए “नये कानूनसे सम्पत्ति पुरस्कृत कविता”, पृष्ठ ४७-४८।

विवचन किया और श्री आमद कुवाडियाने श्री पोलककी मेहनतके सम्बन्धमे दो शब्द कहे। इसके बाद अध्यक्ष महोदयने सभा बरखास्त की।

जेल जानेवालेके पीछे क्या होगा ?

इस प्रश्नका उत्तर मैं पहले भी इस चिट्ठी में दे चुका हूँ। किंतु फिर पूछा गया है, इसलिए देता हूँ। मेरी समझमें जो जेल जानेको तैयार बैठे हैं वे यथासम्भव सारी व्यवस्था कर ही लेंगे, यानी समाजपर उनका बोझ कम ही रहेगा। एक ही मुहल्ले या एक ही दूकानके सभी व्यक्ति एक साथ पकड़ लिये जायें तो तो नहीं होगा। यदि यह विचार ठीक हो तो गिरफ्तार किये जानेवालेके सगे सम्बन्धी या दोस्त उनके बाल बच्चों और जायदादकी रक्षा कर लेंगे। जो लोग दूसरे कानूनोंके अंतर्गत गिरफ्तार किये जाते हैं हमने देखा है, उनकी, इसी प्रकार व्यवस्थाकी जाती है। फिर भी इतना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति नये कानूनके अंतर्गत गिरफ्तार किया जायेगा उसकी सारसँभाल सच करेगा। उसके बाल बच्चे कहा हैं, तथा किस हालतमें है, उन्हें कोई देखनेवाला है या नहीं, सच इन बातोंकी जाच-पड़ताल करेगा और निर्वाहकी व्यवस्था करेगा। अतः नये कानूनके अंतर्गत गिरफ्तार किये जानेवाले व्यक्तिके लिए दुहरी मदद मौजूद है। जेल जानेवाले व्यक्तिकी मर्जीके मुताबिक उसकी दूकान तथा बाल बच्चोंकी व्यवस्था हो सकेगी। श्री पारसी हस्तमजी जैसे वीरोंने जो पत्र लिखे हैं ऐसे अवसरपर उनका लाभ हमें मिलेगा। इस लड़ाईमें हम सत्यके लिए मरनेवाले हैं। इसलिए कदम-कदमपर हमें खुदाकी मदद मिलेगी। ऐसी मदद वह खुद नीचे उतरकर नहीं करता, बल्कि इस सानके दिलमें बैठकर उससे परोपकारके रूपमें करवाता है। उपयुक्त प्रश्न उठते रहते हैं, इससे मालूम होता है कि हमने इतना बड़ा कौमी काम पहली बार हाथमें लिया है, इसलिए डर लग रहा है। यह बात समझमें आ सकती है। किंतु विचार करनेपर सब देख सकेंगे कि घबड़ाने जैसी कोई बात नहीं है। यह भी प्रश्न उठा है कि कहीं १३,००० भारतीयोंको एक साथ जेलमें भेज दे तो क्या होगा? फिर बाल बच्चोंकी सारसँभाल कौन करेगा? यह सवाल केवल डरके कारण ही उठता है। खुदापर तिल मात्र भी भरोसा रखनेवाला ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता, फिर भारतीय मानस, जो कि खुदा या ईश्वरसे सदा डरनेवाला है ऐसे प्रश्न कैसे उठा सकता है? १३,००० भारतीय एक साथ जेल जायें ऐसा शुभ अवसर एक तो आनेवाला नहीं है और यदि आ गया तो सबको मानना चाहिए कि उनके पीछे रहनेवालोंको सँभालनेवाला महबूब बड़ा है। इसके अलावा यदि उपयुक्त प्रश्न उठता है तो हम यह भी प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि भूकम्पमें सारेके सारे १३,००० भारतीय मर जायें तो उनके पीछे रहनेवालोंको कौन सँभालेगा? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो केवल उनके बाल बच्चे अथवा जायदाद अनाथ बन जायें। किंतु यदि अनाथ ही होना है तो उतनी देशसेवा हम क्यों न करें? यदि देशसेवा न करेंगे तो हमें इज्जत कैसे मिलेगी? देशकी सेवा किसे कहा जायेगा?

“प्रगटे जो दिलमा प्रेम प्राण शु^१ प्यारो
हिमतनी^२ मददे खुदा सदा छै^३ प्यारो”

१ क्या ।

२ की ।

३ है ।

एक बहादुर भारतीय

कलकत्ताकी ओरके बस्तावर नामक एक भारतीयको अनुमतिपत्र कार्यालयने अँगुली लगानेको कहा, किन्तु उसने इनकार कर दिया। फिर उसमें नये कानूनक अतगत अर्जी देनेको कहा गया। किन्तु उसने उसके लिए भी इनकार कर दिया। ऐसी हिम्मत प्रत्येक भारतीयमें होनी चाहिए।

लन्दनमें हलचल

नूनी कानूनके बारेमें लन्दनमें जोरसे हलचल हो रहा है। बहुतेरे सदस्य प्रश्न पूछते रहते हैं। एक प्रश्नके उत्तरमें श्री चर्चिलने कहा है कि कानूनके अमलक सम्बन्धमें बनी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस उत्तरसे मैं लोगमें कुछ घबडाहट दबता हूँ। किन्तु घबडानेका कारण नहीं है। क्योंकि, पहली बात तो यह है कि हम अपनी हिम्मतके बलपर लड़ रहे हैं। इसमें बड़ी सरकार दखल नहीं देगी। किन्तु हम जिसे खराब काम मानते हैं उसमें नगी करते। दूसरे, बड़ी सरकार भले कानूनके अमलमें हस्तक्षेप न करे। किन्तु कानूनके जुल्मके समय तो हस्तक्षेप किये बिना चल ही नहीं सकता। यदि हस्तक्षेप नहीं करेगी तो उसकी आबरू का कौडीकी हा जायेगी। और आखिर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जायेगा। अतः श्री चर्चिलके उत्तरका मैं यही अर्थ करता हूँ कि जाहिरा तौरमें वे चाह कुछ भी कर, किन्तु नाजुक समय आनेपर बिना हस्तक्षेप किये काम नहीं चलेगा। लेकिन नाजुक समयका अर्थ है हमारे जेल जानेके बादका समय।

चेत कर चलो

बुधवारका क्रूगसडापक श्री मुलेमान वाडीपर एक काफिरका शराब बेचनेका मुकदमा चला। दा गारा और दा काफिराने खुफिया पुलिसको यह प्रमाण दिया कि श्री मुलेमानने आधी बोतल शराब बेची थी। श्री स्टैगमान तथा श्री गांधी वकील थे। बहुत मेहनत की गई। बयानमें साबित हुआ कि शराब बेचना धर्मके विरुद्ध है। बैकके हिसाब नवीस और दूसरे गारोने बयान दिया कि श्री वाडी बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं। हकीकत भी ऐसी ही मालूम होती है कि श्री वाडीपर जाली मुकदमा चलाया गया है। वे निर्दोष हैं। फिर भी मजिस्ट्रेटने उन्हें दापी ठहराकर छ महीनेकी सजा दे दी है। श्री वाडीने अपील की है। नतीजा जो भी हाना होगा, होगा। लेकिन सभी भारतीयोंका चेतकर चलना चाहिए। गोरे और काफिर अपन स्वायत्तके लिए लोगका फौजानेमें हिचकनेवाले नहीं हैं। श्री वाडी निर्दोष हैं। अतः उनके लिए लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है। जेल जानेमें शम नहीं है, शम है अपराध करनेमें। वे बेकार खर्चमें पड़े, यह बुरा हुआ। और अनजान लोग बदनाम करते हैं सो अलग।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१३५ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को

जाहानिसबग

अगस्त १७, १९०७

सम्पादक

'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके बारेमे मेरे और जनरल स्मट्सके बीच जो पत्र व्यवहार^१ हुआ है उसकी प्रतिलिपि प्रकाशनके लिए इसके साथ भेजता हूँ। मेरी विनम्र रायमे इस प्रश्नमे स्थानीयसे अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। मैं आखिरी दम तक यह मानता रहूँगा कि उपनिवेशियोंकी मानवता उनके विद्वेषभावपर विजय प्राप्त करेगी और यदि मेरे देशवासियोने वे कष्ट सहन कर लिये, जिनका उन्होंने निश्चय किया है, तो उनकी माग न्यायपूर्ण मान ली जायेगी। लेकिन बात ऐसी हो या न हो, मैं केवल एक सलाह दे सकता हूँ, और वह है कि, हमे स्वाथ की पूर्ति करनेके बजाय निडर होकर अपनी शपथपूर्ण घोषणाको पूरा करनेमे लग जाना चाहिए।

इसलिए आवश्यक है कि जनरल स्मट्सने अपने पत्रमे जो जोरदार चेतावनी^२ दी है, उसको मेरे देशवासी समझे। शायद उस जनताके लिए, जिसके नामपर यह कानून पास किया गया है और लागू किया जा रहा है, यह जानना भी जरूरी है कि मैंने उसके बदलेमे जो सुझाव देनेका विनम्र साहस किया है उससे यह कठिनाई पूरी तरह हल हो सकती है। उससे उपनिवेशमे रहनेवाले प्रत्येक एशियाईकी शिंनारत हो जाती है और, एशियाई अधिनियमके विपरीत, उन एशियाईयोकी सरया हमेशाके लिए निश्चित हो जाती है जो (उन थोड़ेसे लोगोको छोडकर, जो प्रवासी विधेयककी शैक्षणिक धाराका लाभ उठानेके योग्य हो सकते हैं) उपनिवेशमे रहनेके अधिकारी होंगे। इसीलिए असली सवाल, जहातक मैं समझ सकता हूँ, अंगुलियोके निशानोका अथवा दूसरे व्यौरोका नहीं है, बल्कि मोटे रूपमे यह है कि सरकार भारतीयोकी भावनाओकी, यद्यपि उनको मत देनेका अधिकार नहीं है, कद्र करेगी या नहीं, या यदि सरकार भारतीयोकी भावनाकी कद्र नहीं करती तो भारतीय अपने ईश्वर और अपने प्रति सच्चे रहेंगे या नहीं और अपने सवस्व का बलिदान करेंगे या नहीं।

आपका आदि,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिए "पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको" पृष्ठ १४८४९ तथा १६४६५।

२ देखिए "पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको" पृष्ठ १६४ के साथ दी गई पादटिप्पणी।

१३६ पत्र 'स्टार' को

जानानिसवग

अगस्त १९, १९०७

सेवामे

सम्पादक

'स्टार'

[जानानिसवग]

महोदय,

आपने उस विषयका, जिसे आप एशियाउ कानून मशायन अधिनियमस सम्बन्धित मेरी 'याजना' कहत है, एक सम्पादकीय टिप्पणीसे गात्रागित किया है। किन्तु, ऐसा करते समय आपन उसे सरसरी तौरपर पढ़कर उसके और सर प्रति याय नहीं किया। सर मसविदमे बताई गई प्राग्राका प्रवासी विधेयकम शामिल कर लेनम सरकारका हर अनुमतिपत्र वापस लेन और उसक स्थानपर तासवाउके प्रत्यर वास्तविक एशियाउ निवासीका अधिवासी प्रमाणपत्र जारी करनेका कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यदि आप सर मसविदा दुवारा पढ़ ता देख्य कि उन प्रमाणपत्राक स्वरूपका त्रिनियमन सरकारपर छोड़ दिया गया है। अतः, अगुठियाक निगानाके प्रश्नका कभी त्रिवाद विषयक नहीं बनाया गया है, और न ही, जहाँतक सर सम्बन्ध है, यह कभी कार्ट बुनियादी सवाल रहा है। मुख्य आपत्ति विधेयकम निहित अनिवायता और उसक उस रुबक प्रति है जिसमे भारतीयन साथ जरायमपगा ठागाकी तरह बर्ताव करनेकी व आता है। सर द्वारा प्रस्तुत मसविदम सरकार उपनिवेशमे अशिमामाशिनारकी मांगक हक्दार एशियाउयाकी ठीक मख्या माउम कर सकेगी और ऐसे एशियाउयाकी शिनास्त भी पूरी तरह हो जायगी। मसविदा जिन बानाका डाड दता है व है एशियाई पजीयन अधिनियमस निर्दिष्ट विस्तृत तन्त्र और दण्ड विधान। मसविदा १६ प्रमस कम आयुक बच्चाका भी तबाहीम बचाता है और उस कण्टप्रद निरीक्षणका टाल देता है, जो पजीयन अधिनियमके अन्तगत अपक्षित शिनास्तक मिलमिलम आन-जाते कहीं भी किया जा सकता है। किन्तु मैं यह कह दूँ कि यह बच्चाक जागे प्रवशका निराकरण पूण रूपस कर देता है, क्याकि मसविदम यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिवासा प्रमाणपत्रापर १६ बपसे कम आयुवाल बच्चाकी मख्या लिखी जायगी और १६ बपक हानपर उह अधिवासी प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा। फिर भी यदि मरी योजनाका मदाप माना जाय ता कमसे कम प्रवासी विधेयकम शिनास्त सम्बन्धी विधान शामिल करनेके सिद्धान्तका ता मदाप नहीं माना जा सकता, और उन सारे दाषोका निराकरण किया जा सकता है जिनपर मरी निगाह नहीं पड़ी है। इसलिए, अब भी प्रश्न यही है कि महामहिमकी भारतीय प्रजाके कल्याणकी दृष्टिमे जनता इस वैकल्पिक प्रस्तावका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करेगी या नहीं।

१ यह २४-८-१९०७ क इंडियन ओपिनियनमे उद्धृत किया गया था।

२ यहाँ अन्तरल स्पट्सके निजी सचिवक नाम लिखे पत्रक साथ भेजे गये प्रस्तावकी भर सकेत किया गया है। देखिए पृष्ठ १४९ १०।

आपकी सम्पादकीय टिप्पणीके दूसरे हिस्सेके बारेमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि मेरे देशवासियोंको सम्मानास्पद दर्जेका आवासन [नहीं]^१ दिया गया तो, चाहे वे कितने ही गिरे हुए हों, अपने आत्माभिमानकी बलि देने और अपनी गम्भीर प्रतिज्ञाको तोड़नेके मुकाबले जेल, देश निकाला और उसी प्रकारकी अन्य विपत्तियाँ उनके लिए वरदान-स्वरूप होंगी। और एक बातके लिए मैं आपको जोर देकर आश्वस्त कर सकता हूँ कि ऐसा एक भी भारतीय नहीं है जो इस अधिनियमको अपने हृदय तलसे नापसंद नहीं करता। मैं उनमें से अधिकांश लोगोंको जानता हूँ जिन्होंने प्रिटोरियामें इस अधिनियमके अंतर्गत पजीयन स्वीकार किया है, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे इसे अपनी राष्ट्रीयता और ईश्वरके प्रति अपराध मानते हैं, और फिर भी उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि, उनके ही शब्दोंमें, उन्होंने पैसेकी कीमत प्रतिष्ठासे ज्यादा आकी।

आपका आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २०-८-१९०७

१३७ भारतीय मुसलमानोंसे अपील^३

जोहानिसवग
अगस्त १९, १९०७

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता मुसलमान व्यापारी और ट्रांसवाले हमीदिया इस्लामिया अजुमन के अध्यक्ष, मन्त्री और सदस्य, इसके द्वारा आपको उस स्थितिका खयाल कराना चाहते हैं, जो एशियाई कानून सशोधक विधेयकके अंतर्गत मुसलमान भारतीयोंकी हो जायेगी। हम माने लेते हैं कि अधिनियमके विरुद्ध हमारी जो मुख्य आपत्तियाँ हैं उनको आपने जान लिया है। किंतु हम आपका ध्यान विशेष रूपमें एक आपत्तिकी ओर आकर्षित करेंगे, जिसका प्रभाव हमपर मुसलमान होनेके नाते पड़ता है। यह वह खण्ड है जो तुर्कीके मुसलमानोंपर लागू होता है, जब कि तुर्कीके ईसाई और यहूदी उससे मुक्त हैं।

१ वह इस प्रकार था श्री गांधी और उनके सहयोगी नेताओंने यह माननेकी भयंकर भूल की है कि इंग्लिश रेंडिकल नानकफर्मिस्ट लोगोंसे उधार लिये हुए उनके दाँवपंचोका ब्रिटिश उदारदलीय सज्जन किसी भी हद तक जाकर समर्थन करेंगे। उन्होंने अब अपनी भूल देख ली है और इसलिए हमें भरोसा है कि वे अपने असंगत रवैयेंसे बाज आयेंगे, या कमसे कम भविष्यमें अपने देशभाइयोंके असंख्य हिस्सेको उसकी अपनी सामान्य बुद्धिकें सुताबिक चलनेके लिए छोड़ देंगे। अगर उसमें से ज्यादातर लोग कानूनीकी सुखालिप्त करना और उसके परिणाम — जिनमें व्यापार करनेके अधिकारोंका खाला भी शामिल है — भोगना पसन्द करें तो ट्रांसवाल सरकार कानूनी और नैतिक दृष्टिसे फसूरवार नहीं ठहरेगी।

२ इंडियन ओपिनियनके पाठमें यह गन्ध आया है। स्पष्ट है स्टारमें यह भूलसे छूट गया।

३ कदाचित् यह गांधीजी द्वारा लिखी गई थी क्योंकि वे इसको भारतमें प्रचारित कराना चाहते थे, देखिए 'पाठकोंकी सूचना' पृष्ठ १९० और 'हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र' पृष्ठ १९४।

वस्तुतः यह अभिनियम समस्त भारतीयापर लागू होता है, और इसीलिए हमका सम्पूर्ण समस्त भारतीय जनतामें है। किंतु यह मुसलमानोंपर दुहरी कठारतामें लागू होता है क्योंकि उसमें हमारे धर्मका विशेष रूपसे अपमान होता है, और दूसरी ओर अपक्ष भारतीय मुसलमानोंका आत्मसम्मानको अधिक आघात लगता है, क्योंकि वे समाजके अधिकारी नहीं और सम्मानित अंग हैं।

हम कह सकते हैं कि सीमाश्रम, दक्षिण आफ्रिका में मुसलमानों और हिन्दुओंका वाद विवाद भाव नहीं है। हम सब मित्ररूप भारतीयोंके रूपमें गान्धि और मित्रभावन रहते हैं, आपसमें स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, और अपने प्रति विद्वेष और अत्याचारमें मिलकर लड़ते लड़ती हैं। इसीलिए यदि हम उस शिकायतपर, जो हमें प्रभावित करती है, जोर देते हैं तो हम ऐसा केवल अपनी अनिश्चित स्थितिकी ओर समस्त भारतके मुसलमानोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिए करते हैं, ताकि हम अपने संघर्षमें आपकी अत्यंत सक्रिय सहायता प्राप्त कर सकें। और हम आपसे मुसलमानों और भारतीयोंके रूपमें यह प्रार्थना करनेका साहस करते हैं कि आप हमारा मामला सरकारी सम्मुख प्रस्तुत करके और अन्य तरीकामें भी, जिन्हें आप वाञ्छनीय समझें, हमारे साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करें। जब कि हम इंग्लैंडमें बहुत सहायता मिल रही है, तब हम वे गांधी उपनिवेशी भाई, जिनकी हमारे साथ सहानुभूति है, पूछते हैं कि हमारा देश भारत हमारे लिए क्या कर रहा है।

भारतीय

इमाम अब्दुल कादिर सालिम बावजोर (अध्यक्ष)

एम० पी० फैन्सी (मन्त्री)

इब्राहिम सालेजी कुवाडिया (कोषाध्यक्ष)

ईसप इस्माइल मियाँ (सरक्षक)

अब्दुल गनी, एम० सी० कमरुद्दीनकी पेढी (सरक्षक)

[और ३३ अन्य]

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०३

१३८ पत्र 'स्टार' को १

जोहानिसबग

अगस्त २०, १९०७

सेवामे

सम्पादक

'स्टार'

[जोहानिसबग]

म एक बार फिर, अनिच्छापूर्वक, आपके सोज-यका लाभ उठानेके लिए विवश हुआ हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने अब भी पूरी तरहसे मसविदेको^१ नहीं पढा है? मैंने जो सुझाव दिये हैं उनका अर्थ यह नहीं है कि एशियाई अधिनियमकी कुछ धाराओंको रद्द कर दिया जाये और इस प्रकार कुछ अंश तो उस अधिनियमसे और अधिकांश प्रवासी विधेयकसे रख लिये जाये, बल्कि यह है कि पहलेवाले अधिनियमका सवथा अत कर दिया जाये, क्योंकि, मेरी रायमे, मेरे प्रस्तावसे, मेरे देशवासियोंको बहुत नाराज किये बिना ही, उपनिवेशियोंको सब कुछ मिल जाता है। मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि मैंने और मेरे साथियोंने जो कुछ लिखा है, उसके लम्बे उद्धरणोंके अव्ययनका भार आपपर डालकर यह दिखाऊँ कि यद्यपि इस अत्यन्त आपत्तिजनक अधिनियममे अँगुलियोंके निशानोंका सवाल हमेशा एक बड़ी गम्भीर बात मानी गई है, तथापि जबतक उसका प्रयोग एक अनिवाय शतके रूपमे नहीं होगा तबतक यह प्रश्न कोई सर्वोपरि महत्त्वका विषय नहीं रहेगा। आपको यह भी आसानीसे याद आ जायेगा कि हमने स्वेच्छासे उन अनुमतिपत्रोंपर अँगुलियोंके निशान दिये थे, जो लाड मिलनरकी सूचनाके अनुसार जारी किये गये थे।^२ उस समय यह स्वेच्छासे करनेकी बात थी और वह भी सिर्फ एक अँगूठेका निशान लगानेकी। एशियाई अधिनियममे दसो अँगुलियोंके निशान देनेका प्रश्न है और वह भी एक बार नहीं, बल्कि जितनी बार अधिकारीगण लेना चाहे। यदि मैं अपने देशवासियोंको दसो अँगुलियोंके निशान स्वेच्छासे देनेकी सलाह दे भी दू तो मैं समझता हूँ कि मेरी सलाह तुरत अस्वीकार कर दी जायेगी। लेकिन मुझे और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। मुझे खेद है कि भारतीयोंके पक्षको अब भी गम्भीर और निर्विकार भावसे नहीं समझा जा रहा है। मेरे देशवासी केवल इतना कह सकते हैं कि भले ही सारा गोरा द्रात्सवाल हमारे विरुद्ध हो, ईश्वर अब भी हमारे साथ है।

आपका आदि,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २१-८-१९०७

१ यह बादमें २४-८-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

२ देखिए 'पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको', पृष्ठ १४८-४९।

३ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २२४-२१।

१३९ पत्र 'रैंड डेली मेल' को

[जाहानिसबाग]

अगस्त २०, १९०७

मेरामे

सम्पादक

'रैंड डेली मेल'

[जाहानिसबाग]

महादय,

जनरल स्मट्सका भेज मर प्रस्तावकी आपन सम्पादकीय टिप्पणी लिखकर मान प्रदान किया है, उसमे एगियार्ड आश्लीक सगह दी * कि वह अपने निश्चयपर और विचार कर, क्याकि वह निश्चय एक जायक क्षणम ओर गायर उस बातकी पूरी तरह समझ बिना किया गया है कि एक हम देगम, जहाँकी रहत उनी आवाता अर प्रार गारा की है, काननका संगठित विचार करता कितनी गम्भार बात *।" यह एक विचित्र बात है कि आप एक ऐसे सरूपका, जिसपर पिछर उस महीनास गार ह है "जायक क्षणम किया गया" समझत हैं।

फिर भी, मैं य चंद पक्तियाँ यह भाकूम करना लिए लिख रहा हूँ कि क्या आप जनताका बता सकते हैं कि 'काननका संगठित विचार करनेकी गम्भीरता' और "बहुत उनी अध प्रवर आवादी" के बीच क्या सम्भार है? क्या उस आशदीस ब्रिटिश भारतीयपर हमला कराया जायगा, क्याकि ब्रिटिश भारतीय ऐसे काननका माननेके लिए तैयार नहीं हैं जा उन्हें नामद बनानेवाला है।

आपका आदि,

मो० क० गाधो

[अग्नेजीम]

रैंड डेली मेल, २०-/-१९०७

१४० आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको^१

पो० ऑ० बाक्स ६५२२

जोहानिसबग

अगस्त २३ १९०७

सेवाम

परममाननीय उपनिवेश मन्त्री

लन्दन

साम्राज्य सरकारको ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीय सघके अव्यक्षका प्रार्थनापत्र सविनय निवेदन है कि

ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीय सघकी समिति ट्रांसवालकी ससद द्वारा पास किये गये प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके बारेमे महामहिमकी सरकारकी सेवामे सविनय निवेदन करती है कि

उक्त समितिने इस कानूनके बारेमे ट्रांसवाल ससदके दोनो भवनोके सम्मुख विनयपूर्वक अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इन प्रार्थनापत्रोको देखनेसे यह विषय और भी अच्छी तरहसे साफ हो जायेगा। इसलिए उक्त दोनो भवनोमे प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्रोकी नकले इस प्रार्थनापत्रके साथ नत्थी कर दी गई है। उनपर क तथा ख^३ चिह्न लगा दिये गये है।

उक्त समिति सविनय निवेदन करती है कि उक्त विधेयकपर निम्नलिखित कारणोसे एतराज किया जा सकता है

- (१) यह एशियाई कानून सशोधक अधिनियमको स्थायित्व प्रदान करता है।
- (२) यह उन भारतीयोके अधिवास अधिकारकी अवहेलना करता है जो ट्रांसवालमे युद्धसे पूर्व बस चुके थे और जिनमे से अनेक १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत अपने अधिवासके मूल्य स्वरूप तीन पौडकी रकम भी दे चुके है किन्तु अभीतक ट्रांसवाल नही लौट सके है। इसका कारण या तो यह है कि उनके प्रार्थनापत्र देनेपर भी उनको लौटनेके अनुमतिपत्र नही मिले है अथवा उन्होने शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अधीन ऐसे अनुमतिपत्रोके लिए प्रार्थनापत्र ही अबतक नही दिये है।
- (३) इसमे विधेयककी शतके अनुसार किसी भी भारतीय भाषाको शिक्षा सम्बन्धी योग्यताका अंग नही माना गया है।
- (४) इस विधेयकके खण्ड २ के उपखण्ड ४ के^१ अनुसार विधेयक द्वारा निश्चित शिक्षाकी परीक्षा पास करनेवाले भारतीयोपर भी एशियाई कानून सशोधन अध्यादेश लागू होता है।

१ यह आवेदनपत्र इंडियन ओपिनियन के ३१-८-१९०७ के अकमें और इसका गुजराती अनुवाद २४-८-१९०७ के अकमें छपा था।

२ ये पहले तिथि क्रमानुसार दिये जा चुके है, देखिए क्रमश 'प्रार्थनापत्र ट्रांसवाल विधानसभाको' पृष्ठ ९२ ९३ और 'प्रार्थनापत्र ट्रांसवाल विधान परिषद्को', पृष्ठ ११५ ११६।

३ देखिए आवेदनपत्रके साथ दिया गया परिशिष्ट 'ग'।

- (५) ट्रान्सवालमे पहलेसे बसे हुए भारतीय व्यापारियोंका उसके अंतर्गत यह सुविधा नहीं दी गई कि वे अपने विश्वासी क्लार्कों, सहायकों व घरानेवालोंका स्थायी रूपसे आहरण बलवा सकें।
- (६) उस विधेयकके खण्ड ६ के उपखण्ड ग द्वारा यह अतिरिक्त दिया गया है कि एशियाई कानून सशोधक अधिनियमका सीमाएं अनेकानेक प्रांतोंका पड़कर जवत्सनी निवासित किया जा सकगा।

उपर्युक्त विषयपर ढलीले

उक्त समिति अत्र एतदुक्तके उपर्युक्त कारणोंके कारण कमजोर चर्चा करनेकी मरिन्त अनुमति माँगती है।

प्रथम कारण

जैसा कि मन्त्रालयकी सरकारका पता है, एशियाई कानून सशोधक अधिनियम ट्रान्सवालमे रहनेवाले भारतीयोंमें अधिकसे अधिक सन्ताप पैदा कर रहा है, उसकी गत उस समाजके स्वाभिमानके लिए इतनी अपमानजनक तथा हानिप्रद महसूस की जा रही है कि उसके बहुतसे सदस्य उसके अधीन पजीयन स्वीकार करनेकी अपेक्षा अपनी समस्त सामाजिक मूल गुणोंका खोना जानका खतरा माल ठेकर भी उन्नतापूजक अपना पजीयन न करनेका दण्ड भुगतनेका तैयार है। पहले-पहल पता किये जानेपर इस विधानका अस्थायी रूप देनेकी बात थी और कहा गया कि उस एशियाईयोंके प्रवासके प्रारंभ में जनता द्वारा निर्वाचित सभाका अभीस नियम न माना जाये। साथ ही यह भी कहा गया था कि वर्तमान विचारधीन विधेयकको केवल इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि इस सम्बन्धमें कोई और कानून मोजद नहीं है। इस विधेयकका पहला खण्ड ही एशियाई कानून सशोधक अधिनियमका स्थायी बना देता है और शान्ति रक्षा अभ्यादेशकी शर्तोंको भी वहाँतक बनाये रखता है जहाँतक एशियाई कानून सशोधक अधिनियमके अन्तर्गत के लिए उसकी आवश्यकता पड़े।

दूसरा कारण

यह सबविदित है कि उद्युक्त भारतीय जो युद्ध आरम्भ होनेपर ट्रान्सवालमे चले गये थे, अपने अपनाये हुए दशमें अभीतक वापस नहीं आये हैं। इस दशमें बस जानेके उद्देश्यसे उनमेंसे अनेक पुरानी डच सरकारका ३ पीड दे चुके हैं। शान्ति रक्षा अभ्यादेशके कारण उनके अनुमति पत्र मिलनेके मागमें इतनी गम्भीर बाधाएँ खड़ी हो गई हैं — यद्यपि पराये यूरोपीय भी उन्हें माँगते ही पा जाते हैं — कि वे ट्रान्सवालमें अभीतक वापस नहीं आ सकें हैं। उनमें से कुछने तो अभी अजिया भी नहीं दी हैं। इन शरणार्थियोंको इस विधेयकके अनुसार कोई यूरोपीय भाषा न जाननेके कारण ट्रान्सवालमें बर्जित प्रवासी करार दे दिया जायेगा। यह निषेध निहित स्वायत्त रहनेवाले सुपात्र ब्रिटिश प्रजाजनके विरुद्ध बहुत सख्तीसे लागू किया जायेगा। इस प्रकार स्थायी निवासके अधिकारका मसूख करनेमें यह विधेयक केप उपनिवेशमें प्रचलित ऐसे कानूनसे आगे निकल जाता है।

तीसरा कारण

भारतीय भाषाओंको मान्यता देनेमें इनकार करके यह विधेयक अनुचित तथा अयायपूर्ण भाव उत्पन्न कर रहा है।

चौथा कारण

उक्त समितिकी नम्र सम्मतिमे खण्ड २ का उपखण्ड ४ अत्यन्त अस्पष्ट है और उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। तो भी यह स्पष्ट है कि वह, दूसरी बातोंके अलावा योग्य भारतीयोंको निशाना बनाता है। एशियाई कानून सशोधक अधिनियमकी शर्तोंको उनसे पूरा करानेका विधान करके वह जो कुछ एक हाथसे देता है उसे दूसरे हाथसे छुड़ा लेता है, क्योंकि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई भारतीय व्यापक शिक्षा पानेके बाद कभी इस अधिनियमकी शर्तोंको स्वीकार करेगा। ऐसे भारतीयोंको ऐसे अधिनियमका शिकार बनानेके लिए कोई दलील भी दिखाई नहीं देती जिसका उद्देश्य टासवालमे रहनेवाले भारतीयोंकी शिंनारत करना है, क्योंकि ऐसे भारतीय तो यूरोपीय भाषाके अपने ज्ञानके कारण अपने आप पहचानके चिह्न रखते ही हैं। एशियाई कानून सशोधक अधिनियम इसलिए जरूरी माना गया है कि इस उपनिवेशमे रहनेवाले अधिकांश एशियाइयोंको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। शिक्षित भारतीयोंसे इस अधिनियमका पालन कराना उक्त समितिकी नम्र सम्मतिमे उनका अकारण अपमान है, साथ ही वह भारतीयोंको इस विवेककी शिक्षा सम्बन्धी धाराके लाभसे वंचित करनेका अप्रत्यक्ष ढंग है।

पाँचवाँ कारण

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन भारतीयोंको टासवालमे रहनेका हक है उनको अपने अस्थायी सहायक बाहरसे बुला सकनेकी सुविधासे वंचित करना एक गम्भीर शिकायत है।

छठा कारण

मूल मसविदेमे खण्ड ६ का उपखण्ड (ग) नहीं था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ट्रान्सवालके भारतीय एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके बारेमे, जीवन मरणके युद्धमे लगे हुए हैं। अनुमान है कि हजारों भारतीय उक्त अधिनियमके सामने सिर झुकानेकी अपेक्षा जेलकी कठिनाइया सहनेको तैयार हैं। उनमेसे बहुतोंके लिए ट्रान्सवाल उनका अपना घर है, जहा वे ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाते हैं। उनको देशसे निकाल देना, शायद उनको भुखमरीका सामना करनेको — निश्चय ही, अपने भावी जीवनकी सम्भावनाओंको नष्ट कर देनेको विवश करना है। जहा एशियाई कानून सशोधक अधिनियमके अनुसार पजीयनका प्रमाणपत्र न लेनेपर उसे उपनिवेशसे निकल जानेकी सूचना दी जा सकती है, वही इस प्रकारकी सूचनाकी उपेक्षा करनेपर अपराधीको जेल भेजा जा सकता है। ऊपर जिस उपखण्ड (ग) का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार स्थानीय सरकारको यह अधिकार मिल जाता है कि वह एशियाई कानून सशोधक अधिनियमके अधीन दी गई सूचनाकी अवहेलना करनेवाले किसी भी व्यक्तिको उसीके खचपर जबरदस्ती पकड़कर देशसे बारह निकाल सके। इस प्रकार नम्रता-पूर्वक निवेदन किया जाता है कि उक्त खण्ड अपने आपमे न केवल एक निन्द्य नियम है वरन वह अत्यधिक अयायपूर्ण भी है, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष रूपसे एशियाई कानून सशोधक अधिनियममे इस तरहका परिवर्तन करता है जिससे सम्बन्धित व्यक्तियोंको बहुत ही असुविधा होगी। उक्त समितिको इस बातका विश्वास है कि यदि ऐसा सशोधन स्वयं इस अधिनियममे ही किया गया होता तो उसे शाही स्वीकृति नहीं मिलती। अतएव उक्त समितिको विश्वास है कि महामहिम सम्राट्की सरकार उक्त अधिनियमके अनुसार असाधारण अधिकार देनेवाले उक्त

उपखण्डको अपेक्षाकृत बहुत अधिक आपत्तिजनक मानेगी। इससे अलावा जबरदस्ती देश निकासनका यह असर होगा कि निर्वासितकी सम्पत्ति जप्त हो जायेगी। और उसमें यह व्यवस्था नहीं है कि निवासित व्यक्ति कहा भेज जायेगे। वेप और नटार ता ऐस यस्तिथयाका अपने यहां नहीं आने दगे। इसलिए उनका भगवा मरनक लिए जबरदस्ती भारत भजा जायेगा। अतएव इस तत्त्व अपराग (यदि इसे अपराग माना ही जाये) के लिय दिया जानाला वह निवासित दण्ड भयकर अपरागके लिए दिय हुए निवासित दण्डम कही अधिक बरा होगा, क्योंकि इस दूसरे निर्वासितमें अपराधीका कमसे कम निवास स्थान तथा भाजन ता दिया जाता है।

सामान्य बातें

उक्त समितिकी यह नम्र राय है कि देशपर ब्रिटिश अधिकार हानक समयस लगानार अबतक महामहिम सम्राटकी सरकारन भारतीयों के स्वतंत्रताकी उपशा की है अथवा उनपर स्थान नहीं दिया है क्योंकि वे निवृत्त थे। वह स्वार्थी ठागाकी चिल्लाहट ममान जुकती रही है, क्योंकि व प्रवृत्तान है। और ऐसा उसी भारतीयोंका बार बार दिये हुए रचना और आश्वासनाकी परगार न करन हुए किया है। साथ ही उक्त समिति विनयपूर्वक महामहिमकी सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि विमानसभाम भारतीयोंका लक्षमात्र भी प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया है, कि जब प्रायिकाकी जारम उस सम्मानित सदनका प्राथनापत्र दिया गया तब उसके पक्षम किसी सदस्यने एक शब्द तक नहीं कहा, और इस प्रकारके प्राथनापत्रका ऐसी ही गति विमान परिषदम भी हुई और उस दशाम जब कि — उसकी रचना ही — अथ ज्ञातक माय माय उन स्वार्थीकी रक्षा के लिए की गई है, जिनका बहुत् तथा निर्वाचित सदनम प्रतिनिधित्व न है। उक्त समिति विनयपूर्वक निवेदन करती है कि इन परिस्थितियाम ब्रिटिश भारतीयोंका यह अधिकार हाना चाहिए कि साम्राज्यकी वृद्धीय सत्ताक रूपमें महामहिमकी सरकारम उनका विशेष संरक्षण मिले।

प्रार्थना

अतएव उक्त समिति अनुनयपूर्ण प्रार्थना करती है कि उक्त विधेयकको अस्वीकार कर दिया जाय और महामहिमकी सरकार अपना प्रभाव डालकर उस विधेयकम ऐसा संशोधन कराय जिसमें एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके कारण महामहिम सम्राटकी भारतीय प्रजापर बुरा असर डालनेवाला भोजदा तनाव कम हो।

अतः अगर, जिस समाजकी प्रतिनिधित्व यह समिति है, उसका कष्ट निवारण करना महामहिमकी सरकारके लिए असम्भव प्रतीत हो ता उसकी नम्र रायमें उसके लिए साम्राज्यके अन्दर शान्ति बनाये रखनेकी दृष्टिमें यह अच्छा होगा कि सम्राटकी समस्त भारतीय प्रजाका द्वांसारायस हटा लिया जाय और उसके निहित तथा प्राप्त अधिकारोंका स्थानीय या साम्राज्यीय काषसे पूरा हरजाना दिया जाय।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतव्य मान कर, सदा दुआ करेंगे।

[आपका, आदि]

ईसप इस्माइल मियाँ

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ

परिशिष्ट ग

उपयुक्त प्रार्थनापत्रमें विवेकक जिन अशोकी चर्चा की गई है उनके उद्धरण नोचे दिये जाते हैं

खण्ड १ शांति रक्षा अध्यादेश, १९०३ को मसूख किया जाता है किंतु उसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी किसी मसूखीसे एशियाई कानून सशोधक अधिनियम १९०७ से मिले हुए उन अधिकारों अथवा अधिकार क्षेत्रपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियमको अमली जामा पहनानेके लिए दिये जा चुके हैं। परंतु उक्त अध्यादेश उस अधिनियमके सभी उद्देश्योंके लिए पूरी तरहसे अमलमें लाया जायेगा।

खण्ड २ उपखण्ड १ और ४ वर्जित प्रवासी से अभिप्राय यह है कि उसमें निम्नलिखित वर्गोंके उन व्यक्तियोंको शामिल किया जायेगा जो इस अधिनियमके लागू होनेके बाद उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी इच्छा करे या प्रवेश करे।

- १ कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशके अन्दर अथवा इसके बाहर नियमानुसार अधिकार प्राप्त अधिकारोंके समक्ष किसी यूरोपीय भाषाके अपर ज्ञानके कारण (इमला अथवा दूसरे प्रकारसे) किसी यूरोपीय भाषाके अक्षरोंमें इन उपनिवेशमें आनेके लिए प्रार्थनापत्र या कोई दस्तावेज जो उक्त अधिकारों चाहे लिखनेमें अथवा उसपर हस्ताक्षर करनेमें असमर्थ होगा। इसमें यह व्यवस्था है कि इस उपखण्डके उद्देश्यके लिए ग्रीक भाषाको यूरोपीय भाषा माना जायेगा।
- २ कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें प्रवेश करने अथवा प्रवेश करनेके प्रयत्नकी तारीखको किसी ऐसे कानूनके अधीन हो या प्रवेश करनेपर हो जाये जो उस तारीखको अमलमें हो और जिसके अनुसार उसको उस तारीखको या उसके बाद वहाँ पाये जानेपर उपनिवेशसे निकाला जा सके अथवा उसे उस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जा सके, चाहे वह ऐसे कानूनके विरुद्ध जेलकी सजा दी जानेपर या उसको शर्तोंका उल्लंघन करनेपर अथवा उसकी शर्तोंके अन्तर्गत और किसी कारण हो। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी सजा उस व्यक्तिको उस उपनिवेशके अलावा किसी और जगह किये हुए अपराधको करनेपर न दी गई हो जिसके लिए उसको बिना शर्त माफ कर दिया गया हो।

खण्ड ६ कोई व्यक्ति जो

- (क) इस अधिनियमके अमलमें आनेकी तारीखके बाद अनैतिकता अध्यादेश, १९०३ का तीसरी, नेरहवी या इक्कीसवी या उन धाराओंके किसी सशोधनका उल्लंघन करनेके कारण सजा पा चुका हो, या
- (ख) मंत्री द्वारा यहाँ रहनेपर इस उपनिवेशकी शान्ति, व्यवस्था और सुशासनके लिए माफ़ूल कारणोंसे खतरनाक माना गया हो, या
- (ग) किसी कानूनके अधीन इस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जानेपर उस आज्ञाका पालन करनेमें असमर्थ रहा हो, उसको मंत्रीके हाथसे निकाले हुए वारंटपर गिरफ्तार करके इस उपनिवेशसे निकाला जा सकता है और गिरफ्तार होनेके बाद निकाले जानेके समय तक ऐसी हिरासतमें रखा जा सकता है जिसे नियमों द्वारा निश्चित किया जाये। इसमें यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद (ख) के अधीन इस उपनिवेशसे ऐसे किसी व्यक्तिको नहीं निकाला जायेगा जबतक उसके बागमें राज्यपालकी आज्ञा न हो। इसमें यह व्यवस्था और है कि यदि इस प्रकार गिरफ्तार किये हुए किसी व्यक्तिकी गिरफ्तारीसे दस दिनोंके अन्दर अन्दर राज्यपालने उसके निर्वासनकी आज्ञा न दे दी तो उसे हिरासतसे छोड़ दिया जायेगा।

खण्ड ११ किसी व्यक्तिको जिसे इस अधिनियमके अन्तर्गत इस उपनिवेशसे निकाले जानेकी आज्ञा दी गई हो और किसी अन्य व्यक्तिको जिसे इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेमें सहायता करने या उस अधिनियमका उल्लंघन करनेके कारण खण्ड ७ के अन्तर्गत सजा दी गई हो वे सब खर्च देने पड़ेंगे जो सरकारको उसको उपनिवेश या दक्षिण आफ्रिकासे निकालनेमें उठाने पड़े हो अथवा उपनिवेशके अंदर

कहीं और हटाने तक नजरबन्द रखनेमें उठाने पड़े हों। विभागका एक अधिकारी इस प्रकारके खर्चोंकी मदों तथा उनका कुल योग बनाकर उसका एक प्रमाणपत्र बनायेगा। वह प्रमाणपत्र जिलाधिकारीके सामने उपस्थित किया जायेगा जा इसको उस व्यक्तिकी उपनिवेशके अन्तर्गत सम्पत्तिस उसी प्रकार वसूल करेगा जैसे सबाच्च यायालय द्वारा किये हुए निणयका इजरा किया जाता है। जिलाधिकारी ऐसी सम्पत्तिकी कुर्कीकी रकमको खर्जाका पास जमा कर देगा। राजाकी सरकारके उपयुक्त खर्च तथा कुर्कीके खर्चको उसमें से काटकर शेष रकम उस व्यक्तिक पास भेज देगा, जो सम्पत्तिका मालिक था, अथवा वह उस रकमको किसी ऐसे व्यक्तिका दे देगा, जिसे सम्पत्तिक मालिकने उस रकमका लेनक लिए सुझाव दिया हो।

[अंग्रेजीमें]

कलानियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २९१/१२२

१४१ तार द० आ० ब्रि० भा० समितिको^१

[जाहानिसबाग]

अगस्त २३, १९०७ के बाद

मेवाम

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

[लन्दन]

प्रवामी विषयक गांधी स्वीकृतिके लिए प्रेषित। प्रावनापत्र^२ चला गया। विषयक अधिवामी भारतीयोंके लिए अहितकर। स याप्रहियाका बलान् निवासनकी धारा विशेष रूपसे सम्मिलित। प्रावना है, अस्वीकार किया जाये या साम्राज्यीय काफन मुआवजा दिया जाये।

[ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अंग्रेजीमें]

कलानियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २९१/१००

१ पल० डब्ल्यू० रिचने यह तार अगस्त ३१ को उपनिवेश कार्यालयको भेज दिया था।

२. देखिय पिछला शीर्षक।

१४२ प्रस्तावित समझौता

ट्रांसवालके उपनिवेश सचिव और श्री गांधीके बीच हुए पत्र व्यवहारको हम अन्यत्र छाप रहे हैं।^१ यह बड़ी दयनीय बात है कि जनरल स्मट्सने श्री गांधीके सुझावको स्वीकार नहीं किया यद्यपि वह समाजके नामसे नहीं किया गया, फिर भी हमारा खयाल है कि यह दोनों दलोंको एक गम्भीर कठिनाईसे बाहर निकल आनेकी साफ राह देता है। जनरल स्मट्स कानूनको लागू करनेकी अपनी योग्यतापर पूरी तरहसे भरोसा रखते हैं और इसलिए श्री गांधीके प्रस्तावको अस्वीकार करते हैं। हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसे युक्तिसंगत हलको अस्वीकार कर देनेसे प्रकट होता है कि जनरल स्मट्स ट्रांसवालके भारतीयोंके बारेमें कितनी ओछी राय रखते हैं। तदनुसार हम सोचते हैं कि अब ट्रांसवालके भारतीयोंका पहलेसे कहीं अधिक कतव्य हो गया है कि वे अपने आखिरी दम तक कानूनके आगे न झुकनेके आंदोलनको जारी रखें। ट्रांसवालकी सरकारके दब निश्चयसे उन भारतीयोंकी कोई हानि नहीं हो सकती जो पहले ही से बड़ेसे बड़े त्यागके लिए तैयार हैं। न तो जेल और न निर्वासनसे उन भारतीयोंके दिलामे जरा भी डर पैदा होना चाहिये जो अपनी इज्जतको सबसे बड़ी चीज समझते हैं।

श्री गांधीने अपना मसविदा भेजते हुए एक खास मुद्दा उठाया है, अर्थात् क्या स्थानीय सरकार ट्रांसवालमें रहनेके हकदार भारतीयोंकी शिनारत करानेमें भारतीय समुदायकी इच्छा और भावनाओंको जान लेनेकी कृपा करेगी। जनरल स्मट्स कहते हैं, 'नहीं'। इसका जवाब देना अब भारतीयोंका काम है। अब यह उनकी मर्जीपर है कि वे ट्रांसवालमें एक सवथा अपमानभरा जीवन बिताये अथवा ब्रिटिश साम्राज्यके नागरिक और मानव गिने जानेके लिए एक सर्वोपरि प्रयत्न करें।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४३ खुले दिलकी सहानुभूति

ट्रान्सफाटीनर 'फुड' न एक सावजनिक सभा की है और ब्रिटिश भारतीयाका हार्दिक त्रतनता अर्जित की है। क्याकि जिस ढंगम हमारे ट्रान्सवालके भाइयान अपन आत्मसम्मानको ठस पहुँचानेवाले कानूनके प्रति अपनी घणा प्रकट की है, उसका 'फुड' न सहृदयतापूर्वक समर्थन किया है। 'फुड' ने उस विषयपर विचार करनेके लिए एक सम्पादकीय लग्नमाला छापकर अपने साहस और जनहितकी भावनाका परिचय दिया है। अन्तम वह इस परिणामपर पहुँचा है कि एक अपमानाजनक कानूनके बारेमे सत्याग्रह द्वारा अपनी नागरजगी जाहिर करके ब्रिटिश भारतीय जिलकुल ठीक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रान्सवालक सहयोगी 'फुड' के अथत्र प्रकाशित उद्गारापर ध्यान दें।

[अग्रेजीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०३

१४४ पाठकोको सूचना

हमारा इण्टिम 'उम समयक' इंडियन ओपिनियन' के गुजराती विभागकी कीमत नहीं आँकी जा सकती। इस कथनम अनिश्चयाकित मायम हो सकती है, फिर भी यह उचित है। टांसवालके भारतीय इस समय जबरनस्त सघप कर रहे हैं। यह पत्र सघपम पूरी तरह मदद देनेमे रत है। अब हम हमारे भारतीयोंको कतव्य मानते हैं कि वह सघपस सम्बन्धित प्रत्येक पक्षि पढ़ें। पढ़ कर उसका उपयोग करना है। पढ़नेक बाद पत्रका फव न दिया जाये। उस सँभालकर रखनेकी जरूरत है। कुछ लख और अनुवाद तो हम राग राग पढ़नेकी सिफारिश करते हैं। इसके अनिश्चित भागम हमारे प्रश्नकी चर्चा घर-घर होनी चाहिए। उसमे हमारे पाठक बहुत मदद कर सकते हैं। सब अपने मित्रोंका 'इंडियन ओपिनियन' की आवश्यक प्रतियाँ भेजकर पढ़नेके लिए कह सकते हैं तथा इस सम्बन्धम जितनी भी मदद दी जा सकती हो, माँग सकते हैं। इस अकम हमोदिया इस्लामिया अजुमनका मुसलमानाक नाम पत्र है। हम मानते हैं कि इस अककी सैकड़ा प्रतियाँ भग्न जानी चाहिए।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०३

१ इन्हें यहाँ नहीं दिया गया। देखिए "सच्चा मित्र", पृष्ठ १९३ भी।

२ देखिए "भारतीय मुसलमानोंसे अपील", पृष्ठ १७९-८०

१४५ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

यह समिति बहुत बड़ा काम कर रही है। फ्रीडोपवालोकी निभ गई सो केवल इसीकी मन्दसे। आज भी इसकी मदद मिलती रहती है। श्री रिचका श्रम अपार है। स्पष्ट ही इस समितिको अपने कामके लिए अधिक धनकी जरूरत है। ट्रान्सवालसे बहुत सा पैसा गया है। अभी वहासे ज्यादा भेजे जानेकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ट्रान्सवालकी लडाईं सारे दक्षिण आफ्रिकाकी लडाईं ह। अतः हम नेटाल भारतीय कांग्रेससे सिफारिश करते हैं कि वह ज्यादा पैसा भेजे। केपके भाइयोंने इस मामलेमें अपने कतव्यका जरा भी पालन नहीं किया। अब यदि वे, या डेलगोआ-ब्रेके भारतीय, थोड़ा चढ़ा करके भेजे तो अनुचित नहीं होगा, और यह सिद्ध हो जायेगा कि वे मदद देनेको तैयार हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४६ श्री गांधीकी सूचना

जनरल स्मट्सने श्री गांधीको जो पत्र लिखा है ओर उसपरसे जो प्रश्नोत्तर^१ हुए हैं उनकी चर्चा 'लीडर' तथा 'डेली मेल' में हो चुकी है। जनरल स्मट्सका पत्र साफ धमकी है। उनके पत्रसे मालूम होता है कि कानूनको अमलमें लाना बड़ा कठिन काम है। दस-बीस व्यक्तियोंको सजा दी जा सकती है, किंतु हजारों व्यक्तियोंको सजा देनेकी हिम्मत, बहादुर होते हुए भी, जनरल स्मट्स नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वे कहते हैं कि कानूनको पूरी तरह अमलमें लायेंगे। यदि यही बात थी तो आजतक क्यों बैठे रहे? प्रवासी कानूनमें क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? उनके अधिकारी नये पंजीयनपत्रकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? उनकी धौंस और व्यवहारमें बहुत फक पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो उत्तर दिया है उससे भिन्न उत्तर वे दे ही नहीं सकते। क्योंकि अभी तो, जबतक संग्राम चल रहा है, गालोपर तमाचे लगा लगा कर भी अपने मुहकी ललाई कायम रखनी पड़ती है। भारतीय समाज कसौटीपर खरा उतरे तब देखना होगा कि वे क्या कर सकते हैं।

अखबारोंकी टीकाओंसे भी मालूम होता है कि पहले जिस प्रकार वे गालियां देते या मजाक उड़ाते थे, वह सब बदल गया। अब धमकीका खेल शुरू हुआ है। अखबार समझा रहे हैं कि जनरल स्मट्स अपनी हठ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भारतीय समाजको अपने खुदाको छोड़ कर जनरल स्मट्सके गुलामीके कानूनकी शरण जाना होगा। 'डेली मेल' तो यह भी धमकी दे रहा है कि ट्रान्सवालमें जंगली काफिर बहुत रहते हैं, यह बात भारतीयोंको याद रखनी चाहिए।^२ इसे हम बुढ़ापेका सठियाना कहते हैं। कानूनको अमलमें लाते लाते गोरे बूढ़े हो गये हैं यह कहा

१ देखिए 'पत्र' जनरल स्मट्सके निजी सचिवकी पृष्ठ १४८ ४९ और १६४ ६५।

२ देखिए 'पत्र' 'रड डेली मेल' की पृष्ठ १८२।

जा सकता है, फिर भी उनकी आशा पूरी नहीं हुई। इसलिए अब वकवास शुरू हुई है। नहीं तो, हमारी लड़ाई जोर काफिराक बीच क्या सम्भव है? क्या हम भारतीय समाजपर आक्रमण करवाना है? ऐसा ग़ुन तो बिस्तरम लग हुएक मुहम ही निकल सकता है।

अकिन जनरल स्मटमक उत्तरम हमे जा एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए सा यह है कि ट्रांसवालके भारतीय दरअसर दृढ़ रहेंगे, अपन उनका त्याग करेंगे, जेलके दुख भागेंगे और निवासित हानमे अपनी प्रतिष्ठा समझेंगे, तभी हमारी जीत होगी। यह सारा बलिदान हम तभी कर सकेंगे जब खुदापर हमारा सच्चा भरोसा होगा। यानी, हिंदू या मुसलमान प्रत्येक भारतीयक लिए इमानपर बात आ टिकी है। इमान रूपी तलवार हर दुश्मनका काट सकेंगी, और वह ईमान हम बालकर नहीं, करक दिखाना है।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४७ क्या हम न्याय परिषदमें जा सकते हैं?

मगरमंड वुडने श्री शिवक नाम जा पत्र लिगा है वह पढ़न याग्य है। श्री वेस्ट वुड उच्च न्यायालयक न्यायाग्य है। उन्होंने प्रागट्ट हिमायती हैं। उनकी राय है कि भारतीय समाज [न्याय परिषद (प्रिवा कोन्सिल) में] प्रश्न उठा मानता है कि चकि नया कानून क्रिश्चियन विचारवागक विरुद्ध है इसलिए निरस्य है। यदि यह किया जा सकता है तो यह कदम निम्न दह उठाने याग्य है। किन्तु हम गेदपूर्वक कहना होगा कि इसमे कुछ गार नहीं। ट्रांसवालक पर उडे वकील इस विचारक विरुद्ध है। इसलिए मगरमंडकी रायक जागपर हम कोई आशा नहीं जांन सकन। भारतीयोंको मन्वी न्याय परिषद उनकी निम्नत है। उनकी सुनवाई करनेवाला करक खुदा है। और हम खुदाका भरोसा ही उनका जगदस्त वकील है। उसकी हिमायत कभी निफल नहीं हो सकती। इतना हानपर भी समाजकी सुविधाके लिए समितिका सूचित किया गया है कि वह विलायतक बडे वकीलकी राय लें। हमम धनकी जरूरत होगी। अन हमारे कथनानुसार यदि समितिका सहायता भरी जायेगी तो परीक्षणक मकदमा लडा जा सकता है या नहीं, इस शकका निराकरण किया जा सकता है।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४८ क्या नेटालमें खूनी कानून बन सकता है ?

हेगर साहबके प्रश्न करनेपर मूअर साहबने जवाब दिया है कि नेटाल सरकार भी नेटालमें ट्रान्सवालके समान ही कानून बनानेके सम्बन्धमें विचार करेगी। खूनी कानूनकी यही विशेषता है। उसकी बदबू केवल ट्रान्सवालमें ही नहीं, सड़ते हुए मुर्देकी बदबूके समान चारों ओर फैल रही है। इस हलचलसे निम्न बातें प्रकट होती हैं

- १ ट्रान्सवालके भारतीयोंपर बड़ी जिम्मेदारी है,
- २ यदि ट्रान्सवालके भारतीय पीछे हट गये तो फिर हर जगह ऐसा कानून बन जायेगा,
- ३ ओर ट्रान्सवालका सवाल सारे दक्षिण आफ्रिकाका है।

इसलिए ट्रान्सवालके भारतीयोंको हर सकट झेलकर दब रहना चाहिए और इस प्रश्नको अपना व्यक्तिगत प्रश्न मानकर अथ भारतीयोंकी पूरी मदद करनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४९ सच्चा मित्र^१

हम ब्लूमफॉर्टीनके 'फ्रेड' नामक अखबारसे एक लेखका अनुवाद दे रहे हैं। हमारी सलाह है कि उसे सब ध्यानपूर्वक पढ़ें। 'फ्रेड' का अर्थ मित्र होता है और इस अखबारने भारतीय कौमके मित्रका काम किया है। उसने जो लिखा है उससे विशेष अच्छा होना सम्भव नहीं है। उस अखबारका प्रभाव बहुत है और जैसा असर उसके सम्पादकके मनपर पड़ा है वैसा हजारों गोरोंके मनपर पड़ा है। किंतु अभी वे बोल नहीं रहे हैं। हम जब सच्चा रूप दिखायेंगे तब वे बोलने लगेंगे। 'फ्रेड' के लेखसे इतना समझना चाहिए कि भारतीय समाज यदि इस समय जरा भी पीछे हटा तो कौमकी बदनामी होगी और तीस करोड़ भारतीयोंकी कीमत तेरह हजार भारतीयोंपर से आकी जायेगी। 'फ्रेड' ने हर्जाना देनेकी बात उठाई है। सम्भव है, यह बात आगे भी उठे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिए "खुले दिलकी सद्मानुभूति", पृष्ठ १९० ।

१५० हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र

ट्रांसमार्ककी हमीदिया इस्लामिया अजुमनने भारतीय समरमाना और अजुमनाक नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। उसकी जरूर हम भारतीय अंग्रेजों और नवाजाका ध्यान आकर्षित करने हैं। ट्रांसमार्क भारतीय उनकी सम्भार लगाएंगे हैं कि उन्हें भारत का कान कान मदद दी जानी चाहिए। आज तक जिनकी मदद मिली है उनका काफी नहीं है। हमारा भाव स्पष्ट है कि प्रश्नाम उलझ हुआ है, अब उन्हें दूसरा नाम करने के लिए काम आरम्भ करना है। फिर भी हम आशा करते हैं कि वे हमारे लिए थोड़ा बहुत समय निकालेंगे।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०३

१५१ एस्टकोर्टकी अपील*

एस्टकोर्ट स्थानिक निरायन सम्राटकी याचिका पर अपील करने का प्रचार किया था। उस सर्वोच्च याचिका के ठण्डा पानी चालकर खत्म कर दिया है। सम्राटकी याचिका पर अपील करने के लिए जा अनमति नहीं चाहिए यह सर्वोच्च याचिका नहीं दी, इसलिए स्थानिक निरायनका पानी चला गया है। इससे लिए हम एस्टकोर्टके भारतीयोंको बधाई देने हैं।

[गुजरातीस]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०३

१५२ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पाँचेफस्टूम और क्लाक्सडॉप

पजीयन कार्यालय इन दोनो स्थानोसे जैसा गया था वैसा ही लौट आया है। पाँचेफस्टूमके अखबार लिखते हैं कि पजीयकोने सारा समय बीडी पीनेमे बिताया। एक कैदी तक पजीकृत नहीं हुआ। पाँचेफस्टूममे स्वयसेवक काममे लग गये थे। प्रिटोरियासे पीटसबग, पीटसबगसे पाँचेफस्टूम और पाँचेफस्टूमसे आगे क्लाक्सडॉप बढ़ गया है, क्योंकि क्लाक्सडापके भारतीयोंने स्वयसेवक भी नहीं रखे। बाहरसे भी उन्होंने किसीकी मदद नहीं ली। जो मदद दी गई उन्होंने उसे लेनेसे भी इनकार कर दिया। हर भारतीयने अपने आप ही पजीयन कार्यालयका बहिष्कार किया। इस प्रकार क्लाक्सडॉप सबसे आगे बढ़ गया। अब दूसरे गांव किससे आगे बढ़ेंगे? और यदि बढ़ना चाहेंगे तो किस तरह? इन दोनो जगहोपर तार^१ पहुँच गये थे। ओर उन्होंने उनके उत्तर भी दिये हैं। पाँचेफस्टूमके पुराने निवासी श्री ई० एन० पटेल दोनो जगहोपर पहुँच गये थे।

स्मट्सको भेजे गये पत्रपर टीका

श्री गाधीने जनरल स्मट्सके नाम जो पत्र लिखा है, वह प्रकाशित हो गया है और उसपर 'लीडर' और 'स्टार' ने टीका की है। दोनो अखबारोका कहना है कि जनरल स्मट्सके उत्तरको निर्णायक मानकर श्री गाधीको भारतीय समाजसे यह सिफारिश करनी चाहिए कि वह कानूनकी शरण हो जाये, नहीं तो उसे परेशान होना पड़ेगा। यह सीख तो ठीक ही है। किंतु ऐसा लिखनेवाले यह भूल जाते हैं कि भारतीय समाज जनरल स्मट्सके भरोसे नहीं बैठा है। उसका सरक्षक तो परमेश्वर है, जनरल स्मट्स नहीं, न ट्रान्सवालके गोरे ही। इन गोरोकी कानूनके वश करानेकी आतुरतासे मालूम होता है कि भारतीय समाजके विरोधसे ये डर रहे हैं।

जनरल स्मट्सका उत्तर

स्वयं जनरल स्मट्सका उत्तर भी एक ऐसी ही धमकी है, जिससे भारतीयोंको रत्ती भर भी नहीं डरना चाहिए। उनका काम हमसे किसी भी प्रकार कानून स्वीकार कराना है। इसलिए वे तरह तरहकी धमकिया दे रहे हैं। वे कहते हैं कि वे कानूनको पूरी तरह अमलमे लायेंगे। इसका क्या मतलब? कोई भी यह नहीं सोचता कि कानून पूरी तरह अमलमे नहीं लाया जायेगा। यह तो सभी जानते हैं कि कानूनकी एक भी उपधारा रद्द नहीं होगी, किन्तु प्रश्न यह है कि जो उसके वश नहीं होंगे उनपर वह किस प्रकार लागू किया जायेगा? उन्हें सजा देकर? यदि यह बात हो तो भारतीय कहते हैं कि उन्हें जेल या निर्वासनका डर नहीं है। डरनेवालोपर वह अवश्य लागू किया जा सकेगा, किन्तु उन्हें तो

मरा हुआ ही समझना चाहिए। हम जानते हैं कि यह उनपर लागू किया जायगा उसीलिए ता कहते हैं कि भारतीय महरबानी करके कानूनके सामन न झुक। किन्तु इतना ता म निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि तरह-तरह भारतीयोंका गिरफ्तार या निरासिन करना जनरल स्मटम या किसीम नहीं हो सकता। यह स्वाभाविक नियम है। हर कानून वही असरम आ सकता है जहा बहुत ठाग उसे माननेका तैयार हो। मैं यह कह सकता हूँ कि जहा सभी चोर हो वहाँ चोरी सम्बन्धी कानूनपर असर नहीं किया जा सकता। उदाहरणके लिए, भारतक कुछ हिस्सामें ठग कहलानेवाले ठाग ठगोका धमा करने हो, उन्हें किसी भी कानूनमें बशमें नहीं किया जा सका है। जब अपराधी लोग इस प्रकार मुक्त रह सकते हैं, तब भारतीय कौम जैम निर्दोष लोगोंका क्या हो सकता है ?

व्यापारियोंकी स्थिति

कुछ भारतीय विचारम पड़ गये हैं और बहुतम ठागाका शक है कि वे आखिर तक टिक सकेंगे या नहीं। यह समय ऐसा है कि जिसके पास जितना धन है उसकी पीडा भी उतनी ही अधिक है। प्रश्न यह है कि उनका माह कैसे ठूँ। उसमें अनिश्चित, गाने व्यापारी [उधार] माल दना बाद कर रहे हैं। इसे मैं ता एक अच्छा लक्षण मानता हूँ। इतने दिन तक ता गार भजक करत था और मानत थे कि भारतीय जल नहीं जायेंगे। अब वे समझने लगे हैं कि हमारा बाना सच्चा है। फिर भी भारतीय व्यापारी स्वयं क्या मानत हैं उसका विचार किया जाना चाहिए। गार व्यापारी यदि माह न दग तो क्या हागा ? यह एक प्रश्न है। इसका सीधा उत्तर यह है कि नये कानूनका मान लनपर भी यदि वे माह न द तो हम क्या करेंगे ? उस वकत ता ऐसा प्रश्न भी नहीं उठ सकता। तब फिर आज यह प्रश्न भी नहीं उठता। और वे माल न द तथा व्यापार न चरु अथवा व्यापारका कम करना पड़ तो इसमें बतई आश्चर्य नहीं। यदि कोई भारतीय यह मानता हो कि समाजके लिए बिना नुकसान उठाये कानून रद हो सकता है या बाइ भी लाभ हो सकता है तो वह बड़ी भूठ करता है। कष्ट या नुकसान उठानेके लिए ता हम बरु ही हैं। यदि वह हम आज खशोम नहो उठायेग, तो आखिर कानून द्वारा अपमानित होकर नुकसान उठानेके लिए बाध्य होता पड़ेगा। और उसके बाद जो हाल होना है उसका नुकसान भी उठाना ही हागा। ऐसी चिन्ता करनेवाला व्यक्ति बताता है कि उसने अभी शपथका अर्थ नहीं समझा है। जलक लिए तैयार रहनेवाले लोगोंका मालके न मिलनकी बिन्ना ही क्या हागी ? वास्तवमें उन्हें आजमें ही माल लेना अपने आप बाद कर दना चाहिए, जिसमें पाछ कष्ट न हो, कोई हकाबत न रहे, तथा लनदारोंकी रकम उनके पास पहुँच जाये। धनका त्याग किय बिना इज्जत नहीं मिलगी। और न यह कष्ट सह बिना रहत ही मिलेगी। जैसे-जैसे दिन गुजरग हम तरह-तरहके रग देखनेका मिलेंगे। कई धमकियाँ मिलेगी। बहुत नुकसान भी हागा। जैम खुद मरे बिना स्वग मिलनेवाला नहीं है, वैसे ही धन, जेल और निर्वासनकी जोखिम उठाये बिना नया कानून रद होनेवाला नहीं है।

मनिकका निवेदन

श्री मनिकने श्री स्मटससे निवेदन किया है कि भारतीय व्यापारियोंका अलग बस्तीमें खदेड़ने तथा उनका व्यापार घटानेके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। श्री स्मटसने जवाब दिया है कि नये कानूनका परिणाम जाने बिना दूसरे कौनसे कानून बनाये जायें, यह

कहा नहीं जा सकता। किन्तु इस निवेदनका जवाब मैं दे सकता हूँ। मान ले कि सारे भारतीय ट्रांसवालसे चले गये और साढ़े तीन कलमुड़े रह गये। उस हालतमें कलमुड़ोको तां हलके दर्जेका मानकर जैसे तैसे रहने दिया जायेगा, किन्तु उन्हें दूसरे लोगोको लानेकी अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि उन्हें कुत्तेकी तरह जीवन बिताने दिया जायेगा। और थोड़े दिनोंमें उनके पैर अपने आप ही उखड़ जायेंगे। अब मान ले कि बहुतेरे भारतीयोंने पैसेको प्यारा समझकर कानून स्वीकार कर लिया। तब बाज़ार तो उनके सिरपर खड़ा ही है। उस कानूनका कौन विरोध कर सकता है? यदि किसीने किया तो नक्का-खानेमें तूतीकी आवाज कौन सुनेगा? किन्तु यदि भारतीय बहुत बड़ी सरयासे कानूनके विरोधमें जुझे तो वे निस्सन्देह जहाँ चाहेंगे वहाँ इज्जतके साथ व्यापार कर सकेंगे, तथा कानून भी ऐसे बनाये जायेंगे जो सब गोरे काले व्यापारियोपर लागू हो। इसके अलावा भारतीय व्यापारी बहुत इज्जतके साथ रहेंगे।

निर्वासन कानून

प्रवास कानून दोनों ससदोंमें पास हो गया है। सम्भव है वह शुक्रवारके 'गजट' में प्रकाशित हो। वह अभी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्ताक्षरके लिए विलायत भेजा जायेगा। उसमें एक उपधारा ऐसी देखनेमें आती है कि जिन्हें नये कानूनके अतगत ट्रांसवालसे निर्वासित होनेकी सजा हो उन्हें सरकार जबरदस्ती निर्वासित कर सकती है। यह उपधारा नई है। इसके आधारपर जिस भारतीयको नोटिस मिलेगा उसे सरकार जबरदस्ती निकाल सकती है। यह नई परेशानी है। इस कानूनपर विलायतमें सही होगी या नहीं, कह नहीं सकते। किन्तु यदि हो गई तो निर्वासन कानून सबपर लागू हो सकता है। परन्तु इसका अर्थ विशेष कुछ नहीं है। यदि ट्रांसवालकी सरकार भारतीयोंको जबरदस्ती जेलमें बंद कर सकती है तो जबरदस्ती उनका निर्वासन भी कर सकती है। किन्तु मानना यही होगा कि यह धारा केवल नेताओपर ही लागू की जायेगी। ब्रिटिश भारतीय सभ इस कानूनके खिलाफ एक अर्जी^१ विलायत भेज रहा है और बहुत करके इस पत्रके छपनेके पहले ही वह रवाना कर दी जायेगी।

रस्टनबर्गसे

रस्टनबर्गसे तार आया है कि खुदाकी मेहरबानीसे सारे भारतीय पजीयन करवानेके खिलाफ दृढ़ हैं।

'स्टार' की पत्र

श्री गांधीने 'स्टार' की टीकाके सम्बन्धमें निम्नानुसार पत्र लिखा है^१

'स्टार'

श्री गांधीके इस पत्रपर 'स्टार' ने बहुत ही टीका की है और लिखा है कि अँगुलियोका निशान लगाना यदि मुख्य आपत्ति नहीं थी तो उसपर आज तक क्यों इतना जोर दिया गया? 'स्टार' का कहना है कि बच्चोका पजीयन न करने और पुलिस द्वारा कोने-कोने न पुछवाने या अँगुलिया न लगवानेसे बहुत भारतीय घुस आयेंगे, इसलिए श्री गांधीका मुझाव ठीक नहीं माना जा

१ देखिए "आवेदनपत्र उपनिवेश मंत्रीको", पृष्ठ १८३ ८८।

२ पाठके लिए देखिए "पत्र 'स्टार' को", पृष्ठ १७८ ७९।

सकता। इसपर श्री गांधीने और उत्तर दिया है कि अँगुलिया लगाना मुख्य आपत्ति तो नहीं, किन्तु आपत्तिजनक तो है ही। इसके अलावा अँगुलिया लगाना अनिवार्य हो ही नहीं सकता। लाड मिलनरक समयमें भारतीय समाजने स्वेच्छया एक अँगुठा लगाना स्वीकार किया था। भारतीय समाज इस अँगुलिया तो स्वेच्छापूर्वक भी नहीं लगायेगा। 'स्टार' ने निवेदनका ठीक तरहमें नहीं देया है। जबतक गार ठीक तरहमें छानबीन नहीं करते, तबतक समझौता हाँ ही नहीं सकता। किन्तु प्रत्येक गोरा काले भारतीय समाजके विरुद्ध हो तब भी गुदा तो उसके साथ है, और इतना काफी है।

संघकी बैठक

बुधवारको संघकी बैठक हुई थी। उसमें श्री ईसप मियाँ, श्री अब्दुल गनी, श्री नायडू, श्री शहाबुद्दीन, श्री अस्वान, श्री मालिम मुहम्मद, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी साले, श्री गुलाम मुहम्मद, श्री एम० पी० फैन्मी, श्री कन्नादिया, श्री मसा इमाकजी, श्री आई० ए० काजी, श्री अमीरुद्दीन, श्री बल्लभ राम, श्री अमरादास तथा अन्य उपस्थित थे। श्री गांधीने प्रवास विधेयक सम्बन्धी अर्जी पढ़ी तथा उस और उसके सम्बन्धमें तार^१ भेजनेकी अनुमति माँगी। श्री शहाबुद्दीनके प्रस्ताव और श्री फैन्मीके समर्थनमें अनुमति दी गई। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनके प्रस्ताव और श्री कुवाडियाके समर्थनमें श्री ईसप मियाँ स्थायी अध्यक्ष बनाय गये और इमाम अब्दुल कादिरके प्रस्ताव और श्री नायडूके समर्थनमें श्री पाठकका सहायक अवैतनिक मन्त्री नियुक्त किया गया।

श्री फैन्मीके प्रस्ताव और श्री उमरजी साहेब समर्थनमें निणय किया गया कि संघका हिस्सा हर माह, 'इन्डियन ओपिनियन' में प्रकाशित किया जाय।

अन्तिम तार

ठोक्सभाम ट्रान्सवालका कज दिये जानेके सम्बन्धमें प्रस्ताव किया गया था वह मजूर हो गया है। किन्तु उसपर टीका करते हुए सर चार्ल्स डिल्क, श्री लिटिलटन, श्री कॉक्स आदि सदस्योंने भारतीयोंका हानेवाला कटावके सम्बन्धमें बहुत कहा। श्री लिटिलटनने, जो पहल सचिव थे, कहा कि कज देने पर पहल बड़ी सरकारका कर्तव्य था कि वह भारतीयोंके हककी रक्षा करती। किन्तु उसमें वह चूक गई है। श्री कॉक्सने ठोक्सभामे सवाल उठाया है कि बड़ी सरकारको चाहिये कि वह डच सरकारको सलाह दे कि वह ट्रान्सवाल छोड़कर जानेवाले भारतीयोंको ५०,००,००० पौंडक इस ऋणमें हर्जाना दे। इस हलचलमें जान पड़ता है कि भारतीय यहाँ जितना जार दिखायेंगे विलायतमें उनके पक्षमें उतने ही ज्यादा ठोग होंगे।

[गुजरातीसे]

इन्डियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिय "एन 'स्टार'को", पृष्ठ १८१।

२ देखिय "तार ६० भा० वि० मा० समितिको", पृष्ठ १८८।

१५३ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त २८, १९०७]

[टाउन क्लक
जोहानिसबर्ग
महोदय,]

मेरे सबकी समितिने समाचारपत्रोमे सामान्य प्रयोजन समितिका यह सुझाव देखा है कि माग यातायात उपनियमोमे ऐसे सशोधन कर दिये जाये कि दूसरोके साथ-साथ, ब्रिटिश भारतीय भी प्रथम श्रेणीकी किरायेकी बगियोका उपयोग न कर सके। मेरी समिति यह कहनेकी धष्टता करती है कि ऐसा उपनियम ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध द्वेषपूर्ण भेद उत्पन्न करेगा, और उस समाजके लिए अनावश्यक रूपसे अपमानजनक होगा जिसका मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मुझे भरोसा है कि नगर परिषद सामान्य प्रयोजन समितिकी सिफारिशको स्वीकार न करेगी।

[आपका आदि
ईसप इस्माइल मियाँ]

अ यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५४ प्रवास-प्रार्थनापत्र

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघने ट्रान्सवालके प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके बारेमे जो २६ तारीखके 'गजट' मे इस रोककी धाराके साथ अधिनियमके रूपमे छपा है कि, "जबतक राज्यपाल 'गजट' मे यह घोषित न कर देगे कि महामहिमकी इच्छा उसे अस्वीकार करनेकी नही है, तबतक यह अधिनियम अमलमे न आयेगा," लॉर्ड एलगिनको अविलम्ब प्राथनापत्र^१ भेज दिया है। जबतक शाही मर्जीका पता न चले, रोककी धारामे कोई बल नही है। इसलिए लॉर्ड एलगिनके पास अब उस साम्राज्य सम्बन्धी भूलको सुधारनेका एक मौका है जो, हमारे विचारसे, उन्होंने महामहिमको एशियाई पजीयन अधिनियम स्वीकार करनेका परामश देनेमे की थी। प्राथनापत्रमे श्री ईसप इस्माइल मियाने सम्बद्ध कानूनके उत्पन्न होनेवाले हर मुद्देकी चर्चा की है। तो भी फिलहाल हम अपनी चर्चाको कानूनके उस पहलू तक ही सीमित रखना चाहते है, जिसका असर ट्रान्सवालमे बसे भारतीयोपर पडता है।

१ देखिए "आवेदनपत्र उपनिवेश मंत्रीको", पृष्ठ १८३ १८८।

हमें याद है कि श्री डक्कनने जोर देकर कहा था कि एगियाई पजीयन अधिनियमको इसलिए जरूरी समझा गया था कि उस समय कोई प्रवासी अ यादगार लागू नहीं था, और उसका फ़ैल एक अस्थायी कदम ही समझा जाना था। वह निस्सन्देह एगियाइयों के प्रवासके तथाकथित उत्तारका 'कनेक्टिंग एंड एक्स्टेंडिंग रेलवे' के तहत भाग था और, माननीय श्री कटिसे के गन्दामे, यह प्रवास रूपा उबार कमसे कम २०० व्यक्ति प्रतिमासका दरम आ रहा था। श्री डक्कन तथा श्री कटिसेने प्रस्तुत की यह एक अनाड़ी तारीफ़ है कि तत्कालीन उपनिवेश सचिवों प्रास्ताविक भाषणमें एक उपराद भी अतक पजीयन नहीं हुआ। और यन् भी कि एगियाई पजीयन अधिनियम अतक उगभग लागू ही नहीं हुआ। हाँ, उनका ज़रूर हुआ है कि पजीयन अधिकारों उन ठांवा के लिए एगियाई प्रांतियों के तत्कालीन उपनिवेशों में गढ़ने लगाते रहते हैं जो गड में उनके कथनानुसार, पजीयन अधिनियम प्रदान करता है। और यही वह अधिनियम है जिस विचारणीय विधान स्थायी बनाना है। और इस तरह जहां यह ट्रान्सवालक गार निवासियों को गति रक्षा अ यादेशमें मकत करता है, वही एगियाइयों की गढ़ने के फ़ैला और भी कम देता है।

उस प्रकार एगियाई देवत है कि गारी ब्रिटिश प्रजा के अधिक स्वतंत्रता देनेका अथ एगियाई ब्रिटिश प्रजा के अधिकारिक पात्रों को लगाना होता है। साम्राज्य के उस नये लाडले बच्चेका, दूसरे तथा अधिक पुराने स्थायी भागी उपनिवेशों के विपरीत, उन भारतीयों के अधिकारों का अपहरण करने दिया जा रहा है जो पुरानी डच सरकारों के तीन पीढ़ियों के कारण पहल में ही ट्रान्सवाल के स्थायी निवासी बन चुके हैं। क्योंकि, जसा ब्रिटिश भारतीय संघ का कहना है प्रवासी अधिनियम के मातहत केवल उही एगियाइयों के स्थायी निवासी होने का अधिकार माना जायेगा जो उस एगियाई अधिनियम के मताधिक पजीयन हाग।

सब ठाग उठाया गया यह आखिरी मुद्दा 'मस्ती' हमारे बतलाये हुए दूसरे दो मुद्दों के भी कान काटना है। इसमें हम बात की व्यवस्था की गई है कि जो ब्रिटिश भारतीय इस नये कानून के अनुसार पजीयन का प्रमाणपत्र न ठग उनका पकड़कर उपनिवेशों में जबदस्ती निकाला जा सकता है। अतः, प्रमाणपत्र लेना अतक एक गंभीर औपचारिकता है जिसमें गुलामी की बढ़ती बात आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जो ठाग पजीयन का प्रमाणपत्र नहीं लेते वे ट्रान्सवाल के निवासी नहीं हैं। वास्तव में एगियाई अधिनियम के विरुद्ध वीरतापूर्ण मोर्चा लेने वाले अधिकतर भारतीय इस उपनिवेशों के पुराने सम्मानित निवासी हैं। हमारे अध्यक्षों के तरह उनमें से कुछ तो बीस-बीस वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उनकी सभी सांसारिक सम्पत्ति, यहाँ तक कि, उनके परिवार, उनके पूजा स्थान तथा ऐसी प्रत्येक वस्तु भी, जिस वे ससार में प्रिय समझते हैं, इसी उपनिवेश में है। ये ही वे लोग हैं जो अपमानपूर्ण दस्तावेजों को लेने से इनकार करने का कारण अपने घरों में जबदस्ती निकाले जाने वाले हैं, और यह निर्वासन निर्वासितों के खर्चों से ही किया जायेगा, इससे ट्रान्सवाल सरकार पर उनको भोजन तथा निवास देने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं आयेगी। श्री मियाँ बख्शी कह सकते हैं कि यह निर्वासन घोर अपराधों के लिए दिये हुए निर्वासन दण्ड से भी बुरा होगा।

लॉर्ड एलगिन जो हमारे साथ सहानुभूतिकी घोषणा कर चुके हैं और वाइसराय रह चुके हैं, यदि महामहिम को इस प्रकार के कानून को स्वीकार करने का परामर्श देते हैं तो उससे

हमको दुःख और आश्चर्य होगा। वे कई बार कह चुके हैं कि उनको एशियाई अविनियम पसंद नहीं है। अब ट्रांसवाल सरकारसे निबटनेका सुनहरा मौका उनके हाथ लगा है। वे चाहे तो एशियाई अविनियमको मसूख करा सकते हैं। और पुनः पजीयन करानेके सिद्धांतको सुधरे हुए रूपमें प्रवासी अधिनियममें शामिल करा सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५५ केपके भारतीय^१

केप उपनिवेशके प्रवासी अधिनियम और व्यापारिक परवाना अधिनियमके अमलके बारेमें केप टाउनके ब्रिटिश भारतीय सघने केपकी ससदके सामने जो तकसगत निवेदनपत्र पेश किया है उसके लिए सघको बधाई दी जानी चाहिए। इस निवेदनपत्रमें जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनको उठानेमें कोई जल्दी नहीं की गई है और जैसा कि निवेदनकर्त्ताओंने ठीक ही कहा है, उनकी प्रार्थनाको केपके अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञाने तकसगत और 'यायोचित' समझा है। मिसालके तौरपर जिन ब्रिटिश भारतीयोंको वस प्रायद्वीपको छोड़कर बाहर जानेका मौका पड़ता है उन्हें अस्थायी अनुमतिपत्र देकर बाहर जाने देना किसी भी सूरतमें 'यायोचित' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस अनुमतिपत्रकी मियादके भीतर न लौटनेपर उनका आवास अधिकार छिन जाता है। इस प्रकार तो वे पाबंदीके साथ छूटे हुए कैदी हो जाते हैं और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रतापर बिल्कुल अनुचित और बेजा अक्रुश लग जाता है। और पुराने भारतीय फेरीवालोंसे बिना किसी कारणके उनके परवाने छिन लेना भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। हमें विश्वास है कि ब्रिटिश भारतीयोंने जो निवेदनपत्र भेजा है उसपर केप सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५६ लेडी स्मिथके व्यापारी^२

लेडीस्मिथका व्यापार सघ फिरसे उन ब्रिटिश भारतीयोंका सुराग लगा रहा है जिनको लेडीस्मिथ निकायने अयायपूर्वक परवाने छिनकर क्लिप रिवरके जिलेमें व्यापार करनेसे वंचित कर दिया है और जिनमें इतनी मजाल है कि वे बिना परवानोंके अपने जीविकोपाजनके लिए अपना व्यापार जारी रख रहे हैं। जब हम कहते हैं कि लेडीस्मिथका व्यापारसघ ही इन गरीब भारतीयोंके पीछे पड़ा हुआ है तब उसका इतना ही मतलब होता है कि यूरोपीय व्यापारी, जो अपने प्रतिस्पर्धीयोसे ईर्ष्या करते हैं उन्हे इस जिलेसे निकाल बाहर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकारकी तरफसे भी कुछ ऐसा समझौता हो गया है कि वह

१ देखिए 'केप टाउनके भारतीय' पृष्ठ २०६।

२ "लेडी स्मिथके परवाने", पृष्ठ २०४५ भी देखिए।

निर्दोष लोगोपर मुकुदमा चलानेकी मजरी न दकर लेडीस्मिथ निकायके आचरणपर अपनी नापसंदगी जाहिर करंगी। लेकिन यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि सघने कायवाही करनेके लिए सरकारपर दबाव डाला है। क्योंकि ऐसा मान्य पन्ता है कि महायाय्यादीने, अगर ये दाग बिना परवानाके व्यापार करना जारी रखें तो उनके गिराफ कायवाही करनेके लिए सरकारी एकोलवा अधिकार दे दिया है। नेटारके व्यापारी परवाना अनियमका अमल इस तरहका है कि साम्राज्य सरकारने उससे राहत देनेमें एक तरहमें अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है। भारत सरकार, जो निश्चय ही मशक़्तमान है अपने इस एकमात्र और कारगर उपायका, कि यदि भारतकी स्वतंत्र प्रजावाच्यनतम न्याय भी नहीं मिलता है तो गिरमिटिया भारतीय प्रवासका राह दिया जाये, उम्तमाल नहीं करती।

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५७ दादाभाई जयन्ती

भारतक पितामह दादाभाई नाराजीकी जयन्ती मितम्बर ४ का आ रही है। उनके इस पञ्चीपर रहनक दिनका अन्त निकल आता जा रहा है। ज्या ज्या दिन बीत रहे हैं, इन पितामहका तेज उठता जा रहा है। ऊन्दन उनके लिए अरण्य है। उस अरण्यमें दशके हिताथ व फकीरी लेकर रहते हैं। जिहासे विशयाम उनका दफ्तर दखा है व जानते हैं उनके दफ्तर और महीम कुछ भी अंतर नहीं। उसमें दो यशिन मुश्किल बैठ सकते हैं। उसमें बैठकर काल भारतीयक दुस्वाका राज अपने मिर लिये हुए है। तनी अधिक आय हा जानेपर भी उनमें एक नौजवान भारतीयमें अधिक काम करनेकी ताकत है। उनकी शीर्षायुकी कामना करते हुए हम परमेश्वरमें प्रार्थना करते हैं कि वह हम व हमारे इस पत्रके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सब लोगोंका उनके मिल हृदयक समान हृदय दे। अपने पाठकाय हमारा अनुरोध है कि इन सच्च पितामहका सच्चा स्मरण इसीमें है कि हम उनक दश प्रेमका अनुकरण करें। ट्रान्सवालके भारतीयका याद रखना चाहिए कि अगर दादाभाईने हमारे लिए जो टक रखी है वैसी ही टक हम भी रखें। हम मानते हैं कि उस दिन सभी भारतीय सघ मभा करक बधाईके तार भजेंगे। हम प्रत्येक जयन्तीपर दादाभाईका चित्र प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए अगले सप्ताह, अर्थात् जयन्ती बीतनेके बाद, पहला बार हम चित्र छापेंगे। आशा है सभी लोग उसे मढ़वा कर रखेंगे।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५८ बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता

इस समय जब कि बहुत लोगोकी नजर ट्रांसवालके भारतीयोकी ओर लगी हुई है, भारतीय समाजकी दुबलताकी सूचना मिली है। यह समय समाजके अंदर छिपी हुई गद्गरीको प्रकट करनेका है, उसे दबानेका नहीं। हम मानते हैं कि दबानेवाला देशद्रोही होगा।

भारतीय समाजमें मुख्यतः सूरती, मेमन, कोकणी, मुसलमान, पारसी तथा हिन्दू हैं। हमने जैसा सुना है उसके अनुसार मेमन लोगो तथा कोकणियोंका बहुत बड़ा हिस्सा कानूनकी इस लड़ाईमें पस्त-हिम्मत हो गया है। कहा जाता है कि वे अब कानून स्वीकार करनेके लिए उद्यत हैं। किंतु स्वीकार करनेके पहले वे कानूनमें सरकारसे कुछ सशोधन करवाना चाहते हैं। उन सशोधनोका मसिवदा हमने देखा है। उसको छापनेमें भी हमें शर्म महसूस होती है। उस मसविदेको हम अपने हाथों अपनी गुलामी मागनेका चिट्ठा मानते हैं। उसमें जो सशोधन मागे गये ह, वे सशोधन हैं ही नहीं। मागकी भाषा इतनी लचर है कि उसका अर्थ यही होता है कि भारतीय समाजके बहुतेरे अग्रणी नये कानूनके खिलाफ थे ही नहीं। अँगुलिया लगाना वे स्वीकार करते हैं। तुर्की मुसलमानोका अपमान हो उसमें उन्हें हज नहीं है। माग केवल इतनी की गई है कि अच्छे भारतीयोकी जाचके लिए खास व्यक्ति नियुक्त किये जायें और वे उनकी अँगुलिया खानगी तौरसे लगवायें। पुराने परवानेवाले यदि हस्ताक्षर कर सकें तो उनसे अँगुलिया न लगवाई जायें। मुद्दती अनुमतिपत्र जैसे आज दिये जाते ह वैसे दिये जायें और बच्चोकी अँगुलियोंकी निशानी १६ वर्षकी उम्र हो जानेके बाद ली जायें।

इन मागोमें एक भी माग ऐसी नहीं है कि जिसके लिए कानूनकी बात तो दूर रही, धाराओमें भी कहीं सशोधन करना पड़े। ऐसे पत्रोके जवाब में स्पटस साहब कह सकते हैं कि “बहुत अच्छा”। अर्थात् जो उस पत्रसे खुश हो वे तुरन्त गुलामीका पट्टा रूपी पजीयन पत्र ले लें। मसविदेमें यह भी कहा गया है कि कानूनके सामने भारतीय तो मोमके समान हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर या खुदाके अस्तित्वपर विश्वास करनेवालेके मुहसे यह बात निकल ही नहीं सकती। मनुष्य केवल खुदाके सामने ही मोम है।

हमें यह कहते खुशी होती है कि उपर्युक्त पत्र श्री स्मटसके नाम नहीं लिखा गया। न हम यही कहना चाहते हैं कि उस पत्रको मेमन, कोकणी या दूसरे किन्हीं भारतीयोंने मजूर किया है। इसे सावजनिक रूपसे प्रकट करनेका मतलब इतना ही है कि यह पौधा उगनेके साथ ही जला दिया गया है। फिर भी यह भरोसा नहीं कि अब और वैसा प्रयत्न नहीं किया जायेगा। डरा हुआ मनुष्य हवाको काटनेको तैयार हो जाता है। टेकडीसे लुढ़कनेपर डरके मारे कौन तिनकेकी ओर नहीं झपटता? ट्रांसवालमें कुछ लोग उसी तरहके तिनके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भारतीयोको हम सलाह देते हैं कि वे कानूनकी खीचतान करनेके बजाय तुरन्त उसकी शरण हो जायें और पजीयन करवा लें। उसमें उनका दोष अधिक नहीं माना जायेगा। किन्तु यदि वे ऐसे पत्र लिखवायेंगे जिनसे समाजको बट्टा लगता है, तो माना जायेगा कि उन्होंने श्री हाजी इब्राहीम और खमीसाकी अपेक्षा ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, और पहुँचायेंगे भी। श्री हाजी इब्राहीम तथा उनके साथियोंने डरके मारे तथा सह न सकनेके कारण काला मुह करवाया था। किन्तु जो उपर्युक्त पत्रके समान पत्र लिखवायेंगे वे अपना मुह काला करवानेके साथ साथ

समाजका भी कृतकित करगे। व यह सिद्ध कर देंगे कि भारतीय समाजकी लार्ड कानूनके विरुद्ध नहीं रहित नगण्य सभासनाक शिष्ट था। उपयुक्त पत्रम यह भी बताया गया है कि कुछ गणराज्य राजाका अन्तर गेप भारतीय पजीयत करवानेका उत्पटा रह है। यह कितना हस्यास्प. है।

इसक अन्तरा भारतीयकी आरम्भ उपयुक्त पत्र यदि जनरल स्मरसन पास भेजा गया तो उसम प्रयोगी तानतके सम्म रम जा अर्जी ली ग. = उस भी प्रका लगेगा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकी लडार्ड वेरार न जायेगी और भारतीय कौमका दिन दहाने लट शिया जायगा। उमरिण हमारी ग्याम तीरग प्रारना है कि जिस या जिस कौमका पजीयत करवाना हा वह अथवा वह कौम खजोम कराये किन्तु अपन साथ दूसरका न धमाते। किन्तु कुछ मेमन, या काकणी या शान बहुत हिंदू या सूती या पारसी नाक कटाने हैं ना उसक लिए सारे मेमन, या काकणी या हिंदू क्या नाक कटायेगे? क्या मेमनाम कार्द गेसा शर नहीं जा हिम्मतसे कह सक कि "और मेमन जाये ता जाय मै ता नहीं जाऊगा?" काकणी भी ऐसा ही क्यों नहीं कह सकत? क्या भारतीय दुर काममे दूसरकी होड करगे? किन्तु भेत्के समान हम अब भी एक एक करर स्टार्डम गिरनका तयार हा ना निश्चित मानिये कि गुठामीरा कानून नमार गिरपर भडा हुआ ही है।

[गुजरानीम]

इंडियन ओपिनियन, ३१-१-१९०७

१५९ लेडीस्मिथके परवाने

लेडीस्मिथक जिन भारतीयको परवाने नहीं मित्रे, उनपर फिर बादल छाये हैं। व लोग बिना परवानके व्यापार कर रह है इसलिए व्यापार मन्त्रने उनपर मुकदमा चलानकी सिफारिश की है और श्री लैंग्रिस्मरन उत्तर दिया है कि व लाग अगर अब भी राजगार करत रहेगे तो उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। कांग्रेसके नेताओंको इस प्रकारका आदवासन दिया गया था कि जा ठाग बिना परवानके व्यापार करगे उह रोका नहीं जायेगा। यह वचन न्याय बुद्धिसे दिया गया था। अब गाने जोर लगा रह हैं इसलिए न्यायबुद्धि दब गई है और सरकार जारके सामने झुककर दूकान बन्द करना चाहती है। भारतीयपर कैसी मुसीबतें आनेवाली हैं उसका हृबह दश्य इसम दिखाई दे रहा है। इन बादलोंको हटानेके तीन रास्ते हैं।

(१) शाही न्याय परिषद (प्रिवी कौंसिल) मे अपील की जाये।

(२) अगर वह अपील न की जा सके तो कांग्रेसके मुखिया बड़ी सरकारसे मुलाकात करे। यह उपाय पहले उपायके साथ-साथ किया जा सकता है।

(३) हिम्मतके साथ दूकाने खुली रखी जाये। मुकदमा चलनेपर जुर्माना न देकर माल कुर्क करने दिया जाये।

पहला उपाय तभी किया जा सकता है जब कांग्रेसके पास १,००० पाँड जमा हो जायें। दूसरा उपाय तो करना ही चाहिए। उससे हमेशाके लिए समस्या सुलझ जायेगी, सो बात नहीं। तीसरा उपाय सबसे सरल और अच्छा है। किन्तु उसे करना मर्दोंका काम है। वह किसीके सिन्धाने पढानेसे नहीं आता। अपनेमें जोश चाहिए। वह हो तो सब कुछ हो सकता है। इस

कानूनमे जेल नहीं है। केवल जुर्माना किया जा सकता है और जुमाना न देनेपर वह माल कुक करके वसूल किया जा सकता है। हमारी विशेष सलाह है कि भारतीय लोग यह मांग स्वीकार करे। डाक्टर रदरफोर्ड जैसे यह करते हैं और हम भी यही कर सकते हैं। किंतु ऐसे काममें दूसरेकी दी हुई हिम्मत बेकार है। मनके आदरसे प्रेरणा होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१६० “हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन-वृत्तान्त” क्यों बन्द हुआ ?

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए हमें खेद होता है। भारतीय समाज और खासकर मुस्लिम भाइयोंकी सेवा करनेके लिए अत्यंत शुद्ध बुद्धि एवं प्रेमसे हमने इस अनुवादका प्रकाशन शुरू किया था। गोरो द्वारा लिखे गये जीवन-चरित्रोमे वाशिंगटन इरविंग द्वारा लिखित यह जीवन चरित्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर मुहम्मद साहबकी खबिया बताई हैं। मुसलमान धर्मकी अच्छी बातें अच्छी तरह पेश की हैं। ऐसा हो या न हो, हम मानते हैं कि गोरे मुसलमान धर्मके बारेमें अथवा उसकी स्थापना करनेवालेके बारेमें क्या लिखत हूँ इसे जानना प्रत्येक मुसलमानका कतव्य है। इस अनुवादको प्रकाशित करनेमें हमारा उद्देश्य अपने उसी कतव्यका निर्वाह करना था। किंतु पाचवे प्रकरणमें दिये गये मुहम्मद साहबकी शादीके विवरणसे हमारे कुछ पाठकोंको ठेस लगी, और उन्होंने हमें सूचना दी कि हमें उस वृत्तांतका प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए। हमें यथासम्भव यही सिद्ध कर दिखाना है कि यह अखबार समाजका है। हमें किसी भी प्रकार, बिना जरूरतके किसीको चोट नहीं पहुँचाना है। इस लिए हमने ‘जीवनचरित्र’^१ देना बन्द कर दिया है और उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि एक तो उसके अनुवादमें बहुत मेहनतकी गई थी, और दूसरे अब हमारे पाठकोंको इरविंगकी सुन्दर पुस्तकको समझनेका अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसी खबरे भी पहुँच रही हैं कि बहुत लोग इसलिए नाराज हो गये हैं कि हमने जीवन चरित्र देना बन्द कर दिया है। ऐसे लोगोंसे हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि उन्हें उसका अनुवाद चाहिए तो हमें लिख भेजे।

१ गांधीजीके सेक्रेटरी महादेव देसाईने अपनी डायरीमें जुलाई २९ १९३२ को लिखा है

बापूने अपने दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव बताये। उन्होंने वाशिंगटन इरविंगकी पुस्तक लाइफ आफ द प्रॉफेट (पैगम्बरका जीवन-वृत्तान्त) पढ़ी थी और इंडियन ओपिनियनमें मुसलमान पाठकोंके लिए उसका सरल अनुवाद भी प्रकाशित करना शुरू किया था। लेकिन मुश्किलसे एकाध अध्याय ही छपा गया था कि मुसलमानोंने इस प्रकाशनका जोरसे विरोध करना शुरू कर दिया। इन अध्यायोंमें सिर्फ मूर्तिपूजा, अधविश्वास और उन बुरे रीतिरिवाजोंके विषयमें लिखा गया था, जो पैगम्बरके जन्मसे पूर्व अरबमें प्रचलित थे। परन्तु मुसलमान इसको भी सहन नहीं कर सके। बापूने यह समझानेका प्रयत्न किया कि ये अध्याय तो उन भारी बुराईयोंकी प्रस्तावना मात्रके हैं जिनसे लड़ने और जिन्हें दूर करनेके लिए पैगम्बरने जन्म लिया था। पर किसीने न सुनी। मुसलमानोंका कहना था ‘हमें पैगम्बरका ऐसा कोई जीवन वृत्तांत नहीं चाहिए।’ बादके जो अध्याय लिखे जा चुके थे और कपीज भी हो चुके थे उनका प्रकाशन रोक देना पड़ा। (महादेव देसाईकी डायरी (अंग्रेजी संस्करण), नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद १९५३, देखिए खण्ड १ पृष्ठ २५९)। ‘पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा’, पृष्ठ ५४-५५ भी देखिए।

यदि बहुत पाठकाकी इच्छा हुई तो जब हमारे छापाखानेका सुविधा होगी तब हम स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित करके उन प्रेमियाकी आशा पूर्ण करनेका प्रयत्न करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१६१ केप टाउनके भारतीय

ब्रिटिश भारतीय लीगकी अर्जी हम गत सप्ताह दे चुके हैं। उसमें बहुतसी महत्वपूर्ण मांगोंका समावेश हुआ जाता है। हम लीगको बर्दाई देने हैं। हम आशा हैं कि लीग उस कामके पीछे यत्नासम्भव शक्ति लगाकर परिणाम अच्छा लायेगी। केपके भारतीयोंका अधिकार प्राप्त करने और उनका सँभालनेके जितने अवसर हैं उतने औरके पास नहीं हैं। हमें यह भी आशा है कि मफीकिंग तथा ईस्ट लंदनके भारतीय लीग और मधमे मिलजुलकर काम करेंगे और सब मिलकर एक प्रबुद्धी निधि इकट्ठा कर लेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१६२ बहादुरी किसे कहा जाये ?

समाचारपत्रोंमें खबर है कि मूर आगाने, जो मुसलमान हैं, वासा-रेकाम बहुत ही बहादुरी दिखाई है।

अपने लडाईके नार लगाते हुए मूर भालेवाले फ्रेंच गाली और तोपवालापर छलांग भरकर चढ़ बैठ। उनपर छरों, गालियाँ और बमोंके टुकड़ोंकी वर्षा हो रही थी, किन्तु उन्होंने परवाह नहीं की। बहुत लोग घायल होकर गिर गये, फिर भी जितने बचे वे आगे बढ़ते गये और तोपोंके मुँह तक पहुँच गये। उसके बाद लौटे।

पाठक पूछेंगे कि तापके मुँहमें वापस कैसे लौटा जा सकता था ? बहादुरीकी यही खूबी है।

उन्होंने इतना जोश दिखाया कि फ्रेंच तोपचियोंका उन बहादुर लोगोपर तोप चलानेकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उनका स्वागत किया और 'हुर्र' का नारा लगाकर शाबाशी देनेके लिए तालियाँ बजाइ। बादमें बहादुर मिपाही सलाम करके वापस लौटे।

ऐसे बहादुरोंका अनुकरण सारी दुनिया कर सकती है। उनके गीत सब गा सकते हैं। किन्तु हमारे मुसलमान पाठकोंको इसमें खास तौरसे सबक लेना चाहिए। यदि इन मूर लोगोकी, जो जंगली माने जाते हैं, बहादुरीका सौवाँ हिस्सा भी हम ट्रान्सवालके भारतीयोंमें होगा तो हम निश्चय जीतेगें। इसमें मरना नहीं है, न मारना ही है। धनका त्याग करना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१६३ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नाइलस्टूम तथा रस्टनबर्ग

इन दोनों जगहासे पजीयन कार्यालय जसा गया वैसा ही लौटा हे। नाइलस्टूमवालोने तो एक दिन दूकाने भी बन्द रखी। एक भी व्यक्तिये पजीयन नहीं करवाया। दोनों स्थानोको ब्रिटिश भारतीय सघ और हमीदिया इस्लामिया अजुमनने बघाईके तार भेजे थे। यह सब बहुत ही शुभ मालूम हो रहा है। किंतु फिर भी इससे हमे फूलना नहीं है। पजीयन कार्यालयका बहिष्कार करना आसान हो गया है। लोगोको चाहे जहा पजीयन करवानेका अवसर दिया जा रहा हे, इसलिए बहिष्कारमे विशेष जाखिम उठानेकी बात नहीं रही। किंतु अन्तिम मुकाम और अन्तिम तारीखके आनेपर दौड़ मचती हे या नहीं यह देखना है। आजसे ही चर्चा चल रही हे कि तब गोटा ट्रिग्नम रखेगे या नहीं, और जा लोग हिम्मत रखेगे वे जेलका समय आनेपर भी दब रहेगे या नहीं।

रेलवेकी तकलीफ

श्री अब्दुल गनी तथा श्री गुलाम मुहम्मदको प्रिटोरिया जानेवाली शामकी ४-४० की गाडीमे जोहानिसबर्गसे जाने नहीं दिया गया था। इस सम्बन्धमे सघने जो कारवाई की थी वह समाप्त हो गई। मुख्य प्रबन्धकका कहना है कि उन्हें खेद है किन्तु गाडके डिब्बेमे भी उनके लिए जगह नहीं थी इसलिए उन्हें जाने नहीं दिया गया। जनरल स्मट्सका कहना है कि ये सारी अडचने भारतीयोके भलेके लिए ह। यह लडाई अब आगे नहीं चल सकती, क्योंकि भारतीय कौम इस समय कसौटीपर चढी हुई हे। यदि कसनेपर वह सोना साबित हुई तो रेलवे आदिकी तकलीफे अपने-आप समाप्त हो जायेगी। और यदि वह राँगा निकली, तो फिर रेलके टिकट मिले तब क्या और न मिले तब क्या?

अलीकी विदाई

श्री हाजी वजीर अली शनिवारको परिवार सहित केपकी आर बिदा हुए ह। उहे पहुँचानेके लिए श्री अब्दुल गनी, श्री शहाबुद्दीन हसन, श्री अमीरुद्दीन श्री गुलाम मुहम्मद, श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन, श्री चैपमन, श्री पोलक, श्री गांधी आदि उपस्थित थे। श्री अली तथा श्रीमती अली दोनोंकी आखोमे पानी आ गया था। श्री अलीके बिदाईके शब्द स्मरण रखने योग्य ह। उन्होने कहा — “मुझसे भूल हुई हो या न हुई हो, उसे दरगुजर कर दे। मनुष्य मात्र भूल करता आया है। किन्तु जितना म करता हूँ उतना यदि दूसरे भारतीय भाई करे तो पर्याप्त माना जायेगा।” ये शब्द दरअसल याद रखने लायक हैं। हम श्री अलीकी गलतीको भूल जाये। उन्होने कानूनको न मानकर ट्रान्सवाल छोड दिया यह शाबाशी देने योग्य हे। यदि इतना करनेके लिए भी बहुत भारतीय खडे हो जायेगे तो अन्तमे हमारी जीत होगी।

दिवालियेपनके दगेकी सजा

इस्माइल ईसा नामक एक निर्वाचिता कजदारपर फरवरी उत्सव था। उसका मुकदमा श्री डी विठियसका अन्ततम प्रिन्सिपल चला था। उसपर उत्सव या कि दिवांग निकलने वाला है इस बातका ज्ञातते हुए भी उसने अनस्ट एक्टकी पढीस तम्बाक खरीदा थी। इसपर उसे तीन माहकी सजा हुई है। यह मुकदमा भारतीयों के लिए उज्जाजनक है। हममें इतनी टेक रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक भी दिवांगिया न हो। किन्तु उसमें तो प्रिन्सिपलपनक साथ ही जाठमाजी भी दिखाई दी। ऐसे काममें भारतीयोंका मिलकुट दूर रहना चाहिए।

रस्टनबर्गका पत्र

रस्टनबर्ग समाज जो विजय प्रान्तकी, उसका प्रारम्भ मधुन नाम एक पत्र आया है। उसमें लिखा है कि कैप्टन चैमने भारतीयोंका समझाने का काम किया है। किन्तु समाज नेहनापुर में यही जवाब दिया कि पजीयन नहीं करवाना है। श्री चैमन भी गया था, किन्तु वह भा यही जवाब मिला। तब श्री प्राप्तिमान, श्री रहीम भाई, श्री प्रियाणिया, श्री मन्दी और श्री एम० ई० काजी स्वयम्बरू थे। दूकान आठ दिन बाद खो गई थी। श्री डी'माजा नामक पुनगीज भारतीयोंके पास श्री काजी गये थे। किन्तु पुनगीज भाईने पजीयन करवानेमें साफ इन्कार कर दिया।

फाक्सरस्ट तथा वॉकरस्टूमक पत्र

फाक्सरस्ट तथा वॉकरस्टूमक पत्र आया है। उनमें वहाँके नेताओंने लिखा है कि एक भी भारतीय अनुमतिपत्र नहीं लगा। सभीमें रहने जाते हैं।

विशेष अपमान

जाहानिसराय नगरपालिकामें अब यह हलचल हो रही है कि भारतीय, जानी या दूसरे काठ लोगोंका पहल दर्जेकी धारा गालाम न उठने दिया जाये। मधुन इस सूचनाके विराम पत्र लिखा है। किन्तु इस समय ऐसा होनाका कम सम्भावना है। नगराज केवल पजीयन कानूनका बज रहा है। उसमें अन्तम जा आवाज निकलनेगी उसीपर सब दारो मदद है।

[गजगतीमें]

इडियत ओपिनियन, ३१-८-१९०३

१६४ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर १, १९०७ के पूर्व]^१

[टाउन क्लक
जोहानिसबर्ग
महोदय,]

पहले दर्जेकी किरायेकी घोडा-गाडियोसे सम्बन्धित यातायात उपनियमोमे प्रस्तावित सशोधनके बारेमे अपने इसी मासकी २८ तारीखके पत्रके^२ सिलसिलेमे मुझे मालूम हुआ हे कि परिषद विशिष्ट व्यवसायाके लोगोको भले ही वे रगदार व्यक्ति हो, पहले दर्जेकी घोडा गाडियोके उपयोग सम्बन्धी अयोग्यतासे मुक्त रखना चाहती हे।

मेरा सघ सम्मानपूर्वक निवेदन करता ह कि इस प्रकारकी छूट सराही जानेके बजाय जलेपर नमक ही छिडकेगी, क्योकि यदि किसी व्यक्तिके वस्त्रो और सामान्य व्यवहारको छोड दे तो यह समझना कठिन हे कि गाडीवान विशिष्ट व्यवसायो और दूसरे लोगोमे कैसे अंतर करेगा, और मेरे सघको यह निश्चित प्रतीत होता हे कि कोई आत्मसम्मानी व्यक्ति ऐसे अधिकारका लाभ न उठायेगा जिसका उपयोग उसके उतने ही सम्मानित देशवासी नही कर सकते। इसलिए मेरा सघ यह आशा करता है कि नगर परिषद कृपाकरके मेरे पत्रोमे उल्लिखित सशोधनके सम्बन्धमे आगे कारवाई न करेगी।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१ 'इसी मासकी २८ तारीखके' हवालेसे प्रकट होता है कि यह पत्र अगस्तमें लिखा गया था।

२ देखिए " पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको , पृष्ठ १९९ ।

१६५ तार ^१ दादाभाई नौरोजीको

[उवन]

मिनस्वर ४, १९०७]

नेटाल भारतीय कांग्रेसकी भारतमें राष्ट्रपितामहका शुभ कामनाएँ। यह दिन बार बार आये। ईश्वर भारतीय प्रवीणका निर्घायु कर।

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१६६ भाषण डर्बनमें^२

[उवन]

मिनस्वर ४, १०७]

गांधीजीने सुझाया कि सारे दक्षिण आफ्रिका और ट्रान्सवालसे बाहरके भारतीय चंदा जमा करें और ऐसी किसी भी आकस्मिक आवश्यकताके लिए, जो ट्रान्सवालमें उठ सखी हो, कोष तयार करें तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी।

वक्तान भारतीय समाजके स्वेच्छया पजीयन करानेके प्रस्तावका और जनरल स्मट्सको भेजे अपने पत्रका भी अथ समझाया।'

[अंग्रेजीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१ यह दादाभाई नौरोजीके ८३ व अन्तिमदिनपर भेजा गया था। देखिए "भाषण कांग्रेसकी समामे", पृष्ठ २११-१३।

२ गांधीजीकी डर्बन यात्राके अवसरपर नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक विशेष बैठक बुलाई गई। अध्यक्ष श्री दाउद मुहम्मदकी किन्तीपर वे ट्रान्सवाल-मन्त्र्यकी तत्कालीन स्थितिके बारेमें बोले। उक्त बैठककी रिपोर्टके ये कुछ अंश हैं।

३ विस्तृत विवरणके लिए गुजरातीसे अनूदित अगला शीर्षक देखिए।

१६७ भाषण कांग्रेसकी सभामें

डबन

सितम्बर ४, १९०७

हमने जो लडाई शुरू की है वह बहुत ही भारी है, इसलिए उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि जीत गये तो भारतीयोंकी स्थिति ट्रांसवालमें ही क्या, नेटाल, केप, और भारतमें भी बहुत कुछ सुधर सकेगी। और यदि हमने मुंह फेरा तो उसका परिणाम भी उतना ही खराब होगा। नेटालमें श्री हेगर जैसा व्यक्ति ससदमें ट्रांसवालके पजीयन कानून जैसा कानून बनानेकी बात उठाये, केपमें फेरीवाले तथा दूकानदारोंको परवानोंकी तकलीफ हो, डेलागोआ बेमें नये नये कानून व प्रतिबन्ध लगाये जाये, रोडेशियामें भी भारतीयोंके लिए विशेष कानून बनाये जाये, और जमन [पूर्व] आफ्रिकामें भी भारतीयोंकी प्रतिष्ठा गिरानेका विचार हो — यह सब, यदि हम अपना पानी बतानेको तैयार हो, तो रक सकता है। ट्रांसवालमें जो करना उचित है, वह हो रहा है। लंदनकी समिति भी तेजीसे काम कर रही है। नेटालने भी कुछ मदद दी है। ३१ जुलाईको प्रिटोरियामें जो तार आये और उसके बाद हर प्रसंगपर दूसरे गावोंमें मण्डलो और व्यापारियोंको अलग अलग तार भेजे गये, उनका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ है। उसके लिए मैं और ट्रांसवालके भारतीय आपका आभार मानते हैं। मुझे मालूम है कि यहासे समितिने १०० पौंड विलायत भेजे ह। यह ठीक किया है। लेकिन नेटालको इसके बाद भी अभी बहुत करना है। यहासे अभी बहुत सा चंदा इकट्ठा किया जा सकता है। यहा मैं यह नहीं कहता कि इसी तरह दूसरे गावोंसे धन एकत्र करके ट्रांसवाल भेज दे, बल्कि मेरा कहना है कि उसे एकत्र करके जमा रखे, जिससे जल्दतक समय उसका उपयोग किया जा सके। ट्रांसवालके लोग भी चंदा एकत्र करके अपना हिस्सा देते ह। ब्रिटिश भारतीय सघ इस लडाईमें लगभग १५०० पौंड खर्च कर चुका है, और अब भी बहुत खर्च करना है। उसके पास आज केवल १०० पौंडके करीब ही है। ऐसी गरीब स्थितिमें लोग मुझसे बार-बार पूछा करते हैं कि सघ जेल जानेवालोंके बाल बच्चोंका भरण पोषण किस प्रकार कर सकेगा? इस सबका मेरे पास एक ही उत्तर है, और वह है कि हम सब खुदापर भरोसा रखनेवाले हैं, फिर यह सवाल क्यों उठायेगे कि अपने पत्नी-बच्चोंका क्या होगा। इतनेपर भी हमें अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिए। घर घर और गांव गांव जाकर चंदा इकट्ठा करना चाहिए। लोगोंको स्थितिसे परिचित कराना चाहिए। इससे वे खुशी खुशी चंदा देगे, और उन्हें इसकी जानकारी भी हो जायेगी कि नये कानूनसे हमारी कितनी अधम स्थिति होनेवाली है। मतलब यह कि हमें कुछ भी उठा नहीं रखना है। तभी हम खुदापर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हमें जितना भी करना है वह करना चाहिए और उसीके साथ हर प्रसंगपर खुदाकी इबादत करके अंत करणसे मागना चाहिए कि “हे खुदा! हे ईश्वर! हमारी न्यायकी अर्जीकी यदि यहा कही सुनवाई नहीं होती तो हमें तेरा तो पूरा भरोसा है। तेरे दरबारमें किसी भी काममें जरा

भा अयाय सहन नहीं हागा।" पिछले रविवारका हमीदिया अजुमन [की एक उठक] में मौलवी मुहम्मद मुल्तयार साहबन भी यहाँ कहा था कि हम तो अपना गिफ्टमण्डल अब खुलके देखाराम हा भजना हैं। पिछले रविवारका जमिस्नम जन्माष्टमीक उसवम यही विचार मारे हिन्दुआन एकत किया था। उस तरहका प्राथना सब कर सनत ह।

एक प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने बताया

स्वीडिशमें सम्प्रत्यस हम अभी जा मोका मिश ह उसर ठिग 'जापिनियन' क पिछले अरसे तीन माग सुनाय गय ह'। उनसम एक अपनाया जाना चाहिण। जिस मुनदमकी अपीठ हम एक दफा बिछायन ठ गये थ उसम और इसम अतर ह। इस मामलम हम निचायक समक्ष फरियाद कर सकन ह और यदि वहा सुनवाई न हा ता सम्राटकी याय परिपदम अपाठ कर सनत ह। ठकिन उसक लिए उनकी पूरी आवश्यकता है। हिस्मत रक्कर दूकान खाल दी जाय इस मै ज्यादा अच्छा समझता हूँ। ठकिन लवार्न शुरू करनेर बाद उस आगिर तह निभाना चाहिण। दूकानदार जुर्माना न द और अपन मालका बार बार नीचम टान द। जिन यापारियाका इस वष परवान मिश गय ह उह सरकारम अजा करनी चाहिण कि हमार भाउयापर इस तरह अयाय हाता ह ता हम भी अगर उप मिना परवानक दूकान खरी रयग। यदि उस तरह हिस्मत और दहनाक माय हम सम्प्रतिहा महान प्रतिज्ञात करेगे ता निश्चित ही जीतगे और तभा जा पस वमाय है और जा वमायग उसकी गिनता राणी नहीं ता चुनकी तरह जीयगे।

पररगापर प्रशम वायायम गवाहक अगूठक निगात रिय जान ह। यह कानूनक विरुद्ध है। प्रवास अरिआग अंगठेक निशान ठ सकता ह, यह कानूनम है ही नहीं। इसलिए इस विषयम यदि धीरज और तडनामे लडाई की गई ता यह प्रथा मिट जायेगी। यह प्रथा अभी गु हो रही है। इसा अदुरका फलत ही जरा देनेकी जरूरत है।

ट्रासवालमें कुछ लोग समझौता करके पजीकृत होना चाहते ह, इस सम्बधमें पूछे जानेपर श्री गांधीने बताया

प्रतिारग्याम कुछ समन सरकारम समझौता करक पजीकृत हाता चाहत ह। इस समझौतेम जरा भी लाभ नहीं है, रतिक नकमान ह। हमारी ठडाईक सच्च स्वरूपका जिन्दान समझ लिया है उह एस समझौतम सताप नहीं हागा। मघन इस समझौतक सम्बधम जा पत्र भजा है वही ठीक है। जिह नाममादम समझौतम सताप हाता हा वे समझौता करनक बजाय अभी हा पजीयनकी अर्गी दे ता उसम समाजकी लडाई खरी नहीं हागी।

नगरपालिका मताधिकारके कानूनको लॉर्ड एलगिनने नामजूर कर दिया है। यह खबर उसी दिनके अखबारमें प्रकाशित हुई थी। इसको समझाने हुए श्री गांधीने कहा

इस जीनका यश लन्दनकी समितिको है। यह कानून यहाँस बहुत ही पहल सम्राटकी स्वीकृतिके हतु बिलायन पहुँच गया था। यहाँ अबनक विचारगय पडा रहा। इसलिए कभी उसके रद होनेकी सम्भावना की जा सकनी थी। लेकिन समितिने परिश्रमपूर्वक जो लडाई की, उसे न करके यदि वह चुप बैठी रहती तो जो परिणाम हम आज देखते हैं वह नहीं होता। आशा है, अब हम सब मताधिकारका लाभ भोगेंगे।

एस्टकोटका निकाय श्री हाफिजीवाले मामलेमें सर्वोच्च न्यायालयके निणयके खिलाफ सम्राटकी न्याय परिषदमें अपील करनेके लिए अनुमति माँगना चाहता है, इसका खुलासा करते हुए श्री गाधीने कहा

निकाय अपील करनेकी अनुमति चाहता है। वह नहीं दी जा सकती। क्योंकि, उसमें खर्च ज्यादा होनेकी सम्भावना है और यह नहीं दीखता कि परिणाम कुछ होगा। फिर भी सम्राटकी न्याय परिषदमें अपील करनेकी अनुमति यदि कोई मागता है तो हम रुकावट नहीं डालेंगे।

इतने स्पष्टीकरणके बाद श्री गाधीने बताया कि आज भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी जयंती है। उसके सम्बन्धमें एक तार^१ सवेरे भेज दिया गया है। इस प्रसंगपर टोगाटके भारतीयोंने तार द्वारा सूचित किया कि हम दादाभाई नौरोजीकी दीर्घायुकी कामना करते हैं।

इसके बाद सब उठकर खड़े हुए और उन्होंने दादाभाईकी दीर्घायुके लिए कामना की तथा उनकी खुशहालीके लिए तीन नारे लगाये। रातके दस बजे सभा समाप्त हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१६८ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जोहानिसबग

सितम्बर ७, १९०७ के पूर्व]

[उपनिवेश-सचिव

प्रिटोरिया

महोदय,]

मेरे सघको विश्वस्त रूपसे पता चला है कि सरकार एशियाई पजीयन अधिनियमके अंतगत विलम्बित प्राथनापत्र लेनेसे पूर्व प्राथियोसे इस आशयके हलफनामे ले रही है कि उन्होंने अभीतक सघके कुछ सदस्योंके अनुचित दबावके कारण ये प्राथनापत्र नहीं दिये।

यदि मेरे सघको प्राप्त सूचना सत्य है, तो मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि जहातक मेरी जानकारी है, सघके किसी सदस्यने कभी कोई ऐसा दबाव नहीं डाला है, और मेरा सघ नम्रतापूर्वक प्राथना करता है कि यदि किसी व्यक्तिने ऐसा आरोप लगाया है, तो जिसपर आरोप लगाया गया है, उसे इस सम्बन्धमें उचित जानकारी देनेकी कृपा की जाये।

[आपका, आदि,

ईसप इस्माइल मियाँ

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१६९ सविनय अवज्ञाका धर्म^१

ऐसा लगता है कि ससदके दोनो सदनोंने जो यह विधेयक पास कर दिया है कि मृत पत्नीकी बहनसे विवाह करना बध है, उससे ससदीय कानून द्वारा स्थापित गिरजो (एस्टेब्लिश्ड चर्च) के पादरी एक प्रकारके सत्याग्रहियोंमें परिणत हो जायेंगे। कटरबरीके सर्वापरि पादरी (आक बिशप) ने आज एक सदेश भेजा है जिसमें पादरियोसे अनुरोध किया है कि यद्यपि इस प्रकारके सम्बन्ध देशके कानून द्वारा जायज करार दिये गये ह, वे मृत पत्नीकी बहनसे विवाह न करायें।

“डेली प्रेस”

उम विवादमें पत्नीकी ह्मांगें दृच्छा नहीं है कि मृत पत्नीकी बहनसे शादी करना सही दिगाम मृधार है या नहीं। हमने उपर्युक्त समद्री तार यह बतानेके लिए उत्पन्न किया है कि सत्याग्रह ग्राम परिमितिनाम अपनी शिनायते दूर रुगनेका एक सम्भाव्य उपाय है और कानूनपर चलनेवाला और गान्ति परगण राग अपनी अन्तरात्माका हनन किये बिना सिफ यही रास्ता अपना सकत है। गान्तिवम उगता ता यह है कि यदि उनमें कोई अन्तरात्मा है और वह किसी खास कानूनक खिलाफ बगबान करती है ता यह तरीका उन्हें अपनाता ही चाहिए। जवाबमें कहा जा सकता है कि ट्रान्सवालक ब्रिटिश भारतीया द्वारा किय गये और कटरबरीके आक बिशप द्वारा मृझाये गये सत्याग्रहमें बाई समानता नहीं है। हमारा यहाँ मतभेद है और हम दावा करत है कि अगर कटरबरीके आक बिशपके लिए मृत पत्नीकी बहनके रुष्ट निवारणवाले कानूनकी अवहलना करना वैध है ता ब्रिटिश भारतीयाके लिए तो यह और भी अधिक वैध है कि वे एशियाई पजीयन अधिनियमका माननेमें इनकार कर। अगर ऐसे पादरियाक लिए, जो शादी करनेमें इनकार करके कानूनको न मान, इस कानूनमें कोई सजा नहीं है तो यह उनका दुहारा कतव्य है कि वे कानूनका मान। लेकिन आक बिशप ता जान-बूझकर विपरीत मलाह दते हैं, क्योंकि वे एक ऊंचे कानूनकी ओर बढे हैं और वह है अन्तरात्माका कानून। सही या गलत, पर कृपामूर्ति आक बिशपका विश्वास है कि इस प्रकारकी शादियाके लिए इजिलमें कोई विधान नहीं है और समदने ऐसा कानून बनाकर ईश्वरीय कानूनको भग किया है। इस बातको बर्दाश्त करना पादरियोके लिए अधम होगा। दूसरे शब्दामें, आक बिशपन थारोकी इस बातको स्वीकार कर लिया है कि हमें प्रजा होनेसे पहले मनुष्य होना चाहिए और हमारी अन्तरात्माकी ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि हम किसी भी कानूनको, उसके पीछे जाहे जो ताकत या बहुमत हो, अन्धे होकर मान ले।

१ इस विषयपर गुजरातीमें यह और आगेके लेख लिखनेमें गांधीजीने अमेरिकी दार्शनिक, प्रकृतिवादी तथा ग्रंथकार हेनरी डेविड थोरो (१८१७-६२) के निबन्ध सविनय अवज्ञाका धर्म (ऑन द ड्यूटी ऑफ सिलिब्सि-ओबिडिएन्स) की सहायता ली थी। उक्त निबन्ध सर्वप्रथम १८४९ में ‘नागरिक शासनका प्रतिरोध’, (रेबिल्टैन्स टु सिलिब गवर्नमेंट) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी भी यही स्थिति है। वे कानूनपरायण हैं और अबतक उन्हें जो प्रमाणपत्र मिला हुआ है उसमें, इस एशियाई कानूनके मातहत पजीयन न करानेसे कोई कमी नहीं आयेगी, क्योंकि इसे उनकी अतरात्मा उनके पौरुषके लिए अपमानजनक और उनके धर्मके हकमें घणित समझकर अस्वीकार करती है। यह सम्भव है कि सत्याग्रहके सिद्धांतकी अतिकी जाये, लेकिन यह बात कानून माननेके सिद्धान्तपर भी उतनी ही लागू होती है। हम शब्दोंमें इस विभाजन रेखाको उतने सही तौरपर नहीं दे सकते जितना कि थोरोने अमरीकी सरकारके बारेमें बोलते हुए कहा था

अगर कोई मुझसे कहे कि यह [अमरीकी] सरकार बुरी है, क्योंकि यह अपने बन्दरगाहोंमें आनेवाले कुछ विदेशी वस्तुओंपर कर वसूल करती है तो, सम्भव है, मैं इस बारेमें कोई बखेड़ा न करूँ, क्योंकि मैं उन वस्तुओंके बगर काम चला सकता हूँ। सभी यन्त्रोंमें घषण^१ होता है [वैसे ही सब शासन यन्त्रोंमें भी होता है] और शायद इससे बुराईको कम करनेमें काफी सहायता मिलती है। बहरहाल, इसी बातको लेकर हलचल करना एक बहुत बुरी बात है। लेकिन, जब घषण अपने [शासन] यन्त्रपर हावी हो जाये और जुल्म और लूटका बोलबाला हो तब तो मैं यही कहूँगा कि हमें ऐसे [शासन-] यन्त्रकी अब जरूरत ही नहीं है।

एशियाई पजीयन अधिनियम ब्रिटिश भारतीयोंके लिए सिर्फ ऐसा कानून ही नहीं है जिसमें थोड़ी सी बुराई हो या, थोरोके शब्दोंमें, यह एक ऐसा यन्त्र है जिसमें घषण है, लेकिन यह तो बुराईको ही वैध बनाना है, या घषणका साधन बनाना है। इस तरह बुराईका विरोध करना एक ऐसा पवित्र कर्तव्य है, जिसकी ओरसे कोई भी मनुष्य निरपेक्ष भावसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है। और केंटरबरीके आर्क बिशपकी तरह ब्रिटिश भारतीयोंके लिए भी इस बातका फैसला उनकी अतरात्माको ही करना चाहिए, और उन्होंने फैसला कर भी लिया है, कि वे एशियाई कानूनको माने या न माने, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७० 'इंडियन ओपिनियन' का परिशिष्टाक

हमने गताक्रमे सूचित किया था कि हम इस अरुम माननीय दादाभाई नौरोजीका चित्र उनके जन्मदिवसके उपलक्ष्यमें दगे। उसके अनुसार पाठक उस अवसरे उनका चित्र देखेंगे। यह चित्र गत वर्ष, जब भारतके पितामह स्वदेश गये थे, लिया गया था और 'इंडिया' में छापा गया था। हमने यहाँ उसकी नक़ल की है। हमारी मलात्त है कि सब इसे मङ्गवाकर रखें। किन्तु हम इसकी सच्ची मङ्गवाई ता तब करूँगे जब यह हमारे हृदयमें अंकित हो जाये। कागजक टुकड़ा मङ्गवाकर रखने और उसके पीछे जो अर्थ छिपा है, उसका तनिक भी स्मरण न रखनेका नाम ही मूर्तिपूजा या वनपरस्ती माना जा सकता है। इस चित्रका अपने कमरेमें टांगनेका उद्देश्य मात्र यही है कि उसको देखकर हमें अपने कर्तव्यका नियत नया ज्ञान हाता रहे। दस समय दक्षिण आफ्रिकामें और उसे ही भारतमें ऐसी स्थिति है कि दादाभाई जैसे सैकड़ों वीर निरुद्ध आय ता भी पर्याप्त न होंगे। जनतक ऐसी शोग नहीं निकलते तबतक राजनीतिक और सामाजिक जीवनके अर्थ क्षेत्रमें हमारा उद्धार न होगा।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७१ सुस्वागतम्

नेटालके नये गवर्नर सर मैथ्यु नेथन आ गये हैं। उनकी उम्र पैतालीस वर्षकी है। वे अग्रिवाहिन हैं। वे यहूदी हैं और अपनी जातिके पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दक्षिण आफ्रिकामें गवर्नर नियुक्त किया गया है। कहा जाता है कि वे बड़े प्रेमी, परिश्रमी और अनुभवी हैं। हांगकाँगमें सभी कौमाका चित्र उन्हाने चरा लिया था। इस समय नेटालकी हालत बची खराब है। ऐसी परिस्थितिमें यद्यपि स्वराज्य प्राप्त उपनिवशमें व बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते, फिर भी अपनी एक मज्जनाचिन मलाहम और व्यक्तिगत आचरणमें बहुत सहायता कर सकते हैं। उनके सम्बन्धमें जो आगाएँ रखी गई हैं भगवान करे, वे सफल हों। उनके साथ उनकी बहन कुमारी नेथन भी हैं। वे गवर्नरके सामाजिक जीवनमें सम्बन्धित कार्य सम्भालती हैं और समाराहोके समय पत्नीका अभाव खटकने नहीं देती।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७२ अनाक्रामक प्रतिरोधके लाभ

एक स्मरणीय उदाहरण

आजकल आयर्लैंडवासी अपने हक प्राप्त करनेके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। वहाके कुछ नेता मानते हैं कि जैसे भारतीयोमे चमडीके रगका दोष है वैसे ही आयर्लैंडकी जनतामे भूमिका दोष है। इसलिए भारतीय प्रजा भारतमे ओर भारतके बाहर दुख उठाती है और अंग्रेजोसे हलके दर्जेकी गिनी जाती है। आयर्लैंडवासियोकी अपने देशमे तो काई गिनती नहीं है, क्योंकि अंग्रेज शासक उनपर जुल्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपना देश छोडकर बाहर जाते हैं अंग्रेजोके समान ही अधिकार भोगने लगते हैं। लोकसभामे आयर्लैंडके ८६ सदस्य हैं। फिर भी अंग्रेज लोग अपने स्वाथमे अधे होकर इतना जार दिखाते हैं कि आयरिश प्रतिनिधियोकी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आयर्लैंडके कुछ नेता सुनवाईका दूसरा रास्ता अरितयार करना चाहते हैं। उसका नाम 'सिन फेन' है। इसका यदि गुजरातीमे हूबहू अर्थ किया जाये तो उसे 'हमारा स्वदेशी आंदोलन' कहा जा सकता है। 'सिन फेन' दलका जोर दिनोदिन बढ रहा है। उसने अपने आंदोलनमे शान्तिपूर्ण प्रतिरोध या अनाक्रामक प्रतिरोधको मुख्य हथियार बनाया था। आजतक वे लोग मार काटकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देते थे। आयर्लैंडकी जनता किरायेदार है और मालिक अंग्रेज यानी परदेशी हैं। इसलिए किरायेदार प्रजा परदेशी मालिकको मारने-पीटनेकी तरकीब करती थी। किंतु अब यह निणय किया गया है कि लोगोको ऐसी तालीम दी जाये जिससे धीरे-धीरे ब्रिटिश लोकसभासे आयरिश सदस्य निकाल लिये जायें, आयर्लैंडकी अदालतोमे आयरिश लोगोके मुकदमे न जाये और असुविधाएँ होनेपर भी ब्रिटिश मालका उपयोग न किया जाये। इन्ही उपायोके साथ स्वदेशीका आंदोलन चलाया जाये, जिससे बिना युद्धके विवश होकर अंग्रेज या तो आयर्लैंडको स्वायत्त शासन दे दे या फिर आयर्लैंड छोडकर चले जाये और आयरिश प्रजा स्वतंत्र राज्य करने लगे।

इस आन्दोलनकी बुनियाद यरोपके दक्षिण आस्ट्रिया हंगरीमे पडी थी। आस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग देश थे। लेकिन हंगरी आस्ट्रियाके अधिकारमे था, जिससे उसे सदा ही आस्ट्रियाका शिकार बनना पडता था। इसलिए डिक नामक एक हंगेरियनने आस्ट्रियाको तग करनेके लिए लोगोमे यह विचार फैलाया कि आस्ट्रियाको कर न दिये जायें, आस्ट्रियाके अधिकारियोके यहा नौकरी न की जाये और आस्ट्रियाका नाम तक भुला दिया जाये। यद्यपि हंगेरियन बहुत ही निबल थे फिर भी इस बलके कारण अतमे आस्ट्रियाको उनके साथ याय करना पडा और अब हंगरी आस्ट्रियाके अधिकारमे नहीं माना जाता। वह अब आस्ट्रियाके मुकाबलेका राज्य है।

इन उदाहरणोंसे ट्रान्सवालवासियोको बहुत सबक लेना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहासमे जो बातें पहले की जा चुकी हैं, वही भारतीयोके सम्बन्धमे ट्रान्सवालमे की जानी

१ आयरिश भाषाके इस शब्दका अर्थ है 'हम ही', यह नाम १९०५ में प्रारम्भ हुआ उस आन्दोलनको दिया गया था, जो बादमें एक सावजनिक गणतन्त्रीय दलके रूपमें विकसित हुआ और जिसके प्रयासोंसे आयरिश फ्री स्टेटकी स्थापना हुई।

चाहिए। मालव यह कि हज़ारा लोगोका कोई कैद नहीं कर सकता, न निकाल सकता है। लेकिन कैद भागने या देशके बाहर निकाले जानेके लिए प्रत्येक भारतीयका तैयार रहना चाहिए। भारतीय जेठ भागने और देशके बाहर जानेको तैयार है, यह साबित करनेके लिए उनमें से कुछको जेल भागनी पड़ेगी और देशके बाहर भी जाना पड़ेगा। जिसके हिस्से देश निकाला अथवा जेठ आयेगी, विजय उसी भारतीयकी हुई, जिन्दगी उसीने जी, ऐसा माना जायेगा। उसका नाम अमर होगा और हमने अपने देशके प्रति शत प्रतिशत कर्तव्य निर्वह किया, यह माना जायेगा।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७३ प्रधानमन्त्रीके विचार

सर हेनरी कैम्पबेल वैनरमनने श्री रिचरड उत्तर भेजा है कि वे दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके गिरफ्तारमें नहीं मिलेंगे। उनके दिये हुए उत्तरका मागश रायटरने तारमें भेजा है। इस तारमें अनुसार प्रधानमन्त्रीने सूचित किया है कि वे ट्रांसवाल सरकारका तार चूके हैं कि नया कानून खराब है। किन्तु चूंकि अब ट्रांसवाल स्वतन्त्र है इसलिए वे उस अधिनियमको लागू करनेके सम्बन्धमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और तत्काल ट्रांसवालपर अधिक दबाव भी नहीं डाल सकते। उस उत्तरके लिए, जान पड़ता है, सर हेनरीने तुरन्त बीस दिन लिये हैं। इसका अर्थ हम यह लगाते हैं कि ट्रांसवालमें बड़ी सरकारके पास कोई सूझा नहीं है कि भारतीय समाज आखिरमें बिना जबरनस्तीके पञ्जीयन करवा लेगा। हम मानते हैं कि इसी तरह लिखनेमें जनरल स्मट्सको इस बातमें बड़ा मित्र है कि कुछ लोगोंने पञ्जीयन करा लिया है और दूसरे करनेको तैयार हैं। यदि हमारा अनुभव सही हो तो सर हेनरीके उत्तरमें निराश होनेका कोई कारण नहीं रहता। सर हेनरीके हस्तक्षेपका समय तब आयेगा जब हमारी मच्छी लड़ाई शुरू होगी जब भारतीय जेलमें जाने अथवा निर्वासित होनेपर भी दृढ़ रहेंगे और कानूनके सामने नहीं झुके। सर हेनरी अगर ऐसे समयमें भी हस्तक्षेप नहीं करते तो हम समझते हैं कि ब्रिटिश राज्यका सूय अस्त हो गया है। क्योंकि निर्दोष मनुष्यों पर अत्याचार हो और बड़ी सरकार उन्हें न बचाये तो साधारण बुद्धि कहती है कि ईश्वर उसके हाथमें सत्ता छीन लेगा। जो रक्षा न करे उसे राजा कैसे कहा जाये?

किन्तु सर हेनरी हस्तक्षेप कर या न करें, भारतीयोंकी लड़ाईका सम्बन्ध इससे ज्यादा नहीं है। इस बारकी लड़ाई आत्मबलकी लड़ाई है। जिस कानूनको हम इस समय हेय कर रहे हैं उसे बड़ी सरकारकी निबलता दबकर स्वीकार नहीं कर लेंगे। यदि असली समयपर बड़ी सरकार हाथपर हाथ धरे हमारी होली होती देखती रहती है तो उस हालतमें उपनिवेशमें भारतीय अपने बलपर ही रह सकते हैं, और यदि कैद आदिकी उपेक्षा करेंगे तो वे उपनिवेशसे तबाह होकर बुरी मौत मरेंगे, क्योंकि कुत्तेकी तरह जीनेको हम मौतकी अपेक्षा हेय समझते हैं।

सर हेनरीके पत्रपर विलायतके सुप्रसिद्ध 'पाल माल गजट'ने आलोचना की है कि सर हेनरीने भारतीयोंके अधिकार डुबानेमें कायरता और कमीनापन दिखाया है और इस कायरताका परिणाम बड़ी सरकारको भोगना पड़ेगा। इस प्रकारका तार जोहानिसबगके 'सडे टाइम्स'में छपा है। इससे माना जा सकता है कि विलायतमें जो लड़ाई चल रही है उसका अंत अभी आया नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७४ नेटाल नगरपालिका मताधिकार अधिनियम

इस बातको लेकर कि नेटालमें भारतीयोंको नगरपालिकाका मताधिकार मिलेगा या नहीं, बहुत दिनोंसे बहस मुवाहसा हो रहा है। अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका अभीतक निणय नहीं हो सका अब समाचारपत्रोंमें जो खबर छपी है उससे मालूम होता है कि लाड एलगिनने उक्त अधिनियम अस्वीकृत कर दिया है। कारण यह दिया गया है कि परवानोंकी बाबत नेटालकी सरकार तमा न जाना। सतुष्ट नहीं कर सकी। इसमें कोई सदेह नहीं है कि यह उत्तम निणय दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके अस्तित्व और उसके द्वारा चलाये गये जबरदस्त सघषका परिणाम है। हमारे पाठकोंको याद होगा कि कई बार श्री रिचने उक्त समितिकी ओरसे लाड एलगिनके नाम इस विधेयकको लेकर पत्र लिखे हैं। इस जीतमें कुछ खास खुश होने जैसी बात नहीं है। हम स्वयं नगरपालिकाओंके अधिकारकी प्राप्तिको महत्त्व नहीं देते। यदि हममें उस अधिकारको काममें लानेका ज्ञान या शक्ति न हो, तो बहुधा वह एक बोझ ही हो जाता है। कानूनकी दृष्टिसे गोरो और गेहुँए लोगोंको समान हक होनेपर भी उन दोनोंमें जो लोग अधिक उत्साही, शिक्षित, चतुर और परोपकारी बुद्धि रखनेवाले हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम आज अमेरिकामें देख सकते हैं, और उम्मी तरह केप उपनिवेशमें भी। केपमें भारतीय, वतनी और गोरे, तीनोंको एक जसा मताधिकार है, फिर भी भारतीय समाज दिनपर दिन पिछड़ता जा रहा है। मतरूपी बन्दूकपर जग लग गई है और गोरे व्यापारिक परवानोंके विषयमें जैसा चाहे, वैसा कानून बनाते रहते हैं। इसका पहला तात्पर्य हम यह समझते हैं कि भारतीय गरीब हो, चाहे अमीर उनके मनमें मनुष्यताकी तीव्र भावना पैदा होनी चाहिए। अपने समाजमें हकोंको अक्षुण्ण रखनेके लिए उनमें लड़ने अथवा अय रीतिसे कष्ट सहन करनेकी हिम्मत और शक्ति आना जरूरी है। इन गुणोंके हमारे बीच उत्पन्न होनेका समय आ गया है अथवा हमें उसकी प्रतीक्षा अभी वर्षों तक करनी पड़ेगी, यह बात ट्रान्सवालके भारतीयोंके कामसे प्रकट हो जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७५ डॉक्टर नडीकी पुस्तिका

डॉक्टर नडीने' नये कानूनने वारमे एक पुस्तिका लिखी है। उसका मूल्य एक शिलिंग रखा है। उसमें ठोड मर्यादा, श्री कर्टिस श्री चैमने, श्री काडी "यादिकी बनी निदा की गड है, और उमा प्रकार श्री गायीक विषयम भी लिखा गया है। उस मारी आराचनाका माराश यहा तना जल्दी नहीं जान पटना। उन्होंने उस पुस्तिकाम यन् मुद्राव दिया है कि नया कानून र्ण र्ण एक आयागर्न द्वारा भारतीय समाजक अधिकाराकी जांच करानेक बाद नया पजीयन कराया जाना चाहिए। उस गुणावम और स्वच्छया पजीयनने प्रस्तावम वार्ड जल्द नहीं है। इस हद तक डॉक्टर नडीकी पुस्तिका हमारे लिए सहायक हो सकता है। किन्तु इस पुस्तिकारा इतना ही अर्थ है, या कानूनका अमलम करने हुए मिक पजीयनपत्राका उत्तरनेकी मांग की गई है, यह ठीक ठीक स्पष्ट नहीं किया गया। किन्तु इस पुस्तिकाका कार्य महत्त्व हमें नहीं दिखाउ ट्ठा, क्योंकि हमें उसमें वार्ड नई बात दिखाई नहीं पडती। इसमें मिला श्री चैमने, नया श्री हाडीपर जा समठा किया गया है, उसमें उन्हें कार्य हानि पहुंचगी मसा भी नहीं जान पडता। उस पुस्तिकाम डॉक्टर नडीने स्वीकार किया है कि जेल जानेका प्रस्ताव ही भारतीय समाजक लिए लाभदायक है। डॉक्टर नडीने 'रैंड डेली मल' के आधारपर शिक्षित भारतीयाका अंगुठियाक निशान र्णनेकी शतम मुक्त करनकी सूचना निकलनेकी बात भी की है। किन्तु ऐसी सूचना ता कभी नहीं दी गई, और यदि आगे दी भी जाये ता उसमें कानून सम्प्रधी सघषरा अत हातकी सम्भावना नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ [मुद्राव^१] भी देखनेम आत है।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, ७-०-१९०३

१७६. कानूनका विरोध — एक कर्तव्य' [१]

अमेरिकामें बहुत बड़ पत्रे हनरी डेविड थारो नामक एक महापुरुष हो गये हैं। उनके लेख लाखा मनुष्य पडते व मरन करने ह नया ३५ उनका अनमरण करते हैं। थारो जो कहते उसपर आचरण भी करते थे, इसलिए उनके लेखका बहुत महत्त्व दिया जाता है। उन्होंने स्वयं अमेरिकाके विरोधमें अर्थात् अपने देशके विरोधमें कतव्य समझकर बहुत-कुछ लिखा है। अमेरिकाके लाग बहुतसे लोगोको गुलाम बनाकर रखते थे, इसे वे बड़ा पाप मानते थे। परन्तु इतना लिखकर ही वे मन्तोप नहीं कर लेने थे, बल्कि अमरीकी नागरिककी हैसियतसे इस रोजगारको रोकनेके लिए जो भी उपाय अस्तित्वाय करना उन्हें योग्य दिखाई देता उसे वे

१ डॉक्टर एडवर्ड नडी, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६० ६१ ।

२ इंडियन ओपिनियनकी जो प्रति उपलब्ध है उसमें गांधीजी द्वारा प्रयुक्त शब्द ठीक पड़ा नहीं जाता ।

३ इसमें तथा १४-९-१९०७ (पृष्ठ २३१ ३३) के दूसरे लेखमें गांधीजीने गुजराती पाठकोंके लिए हेनरी डेविड थारोके विचारोंका सरल रूपान्तर प्रस्तुत किया था ।

करते थे। उनमें से एक उपाय यह था कि जिस राज्यमें गुलामीका व्यापार चालू हो उस राज्यको कर न दिया जाये। जब उ होने अपना कर देना बन्द किया उन्हें जेलमें भेज दिया गया। जेलमें उनके मनमें जो विचार आये वे बहुत दृढ़ और स्वतन्त्र थे तथा पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुए हैं। उस पुस्तकके अंग्रेजी नामका भावाय हमने इस लेखके शीर्षकके रूपमें दिया है। इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिकामें गुलामी बन्द होनेका मुख्य कारण था थोरोका जेल जाना और जेलसे निकलनेके बाद उपयुक्त लेख सग्रह प्रकाशित करना। थोरोका अपने आचरण द्वारा पेश किया हुआ उदाहरण और उनके लेख दोनों ट्रांसवालके भारतीयोंपर इस समय बिलकुल यथार्थरूपमें लागू हो रहे हैं। इसलिए हम उनका साराश नीचे द रहे हैं।

मैं स्वीकार करता हूँ कि राज्यमें लोगोपर जितना कम शासन होगा उतना ही वह राज्य अच्छा है। अर्थात् राज्य शासन एक प्रकारका रोग है, और उस रोगसे प्रजा जितनी मुक्त रह सके उतना ही वह राज्य शासन प्रशसनीय है।

बहुतेरे लोगोका कहना है कि अमेरिकामें सेना न हो अथवा कम हो तो अच्छा रहे। यह बात ठीक है। किन्तु ऐसी बातें कहनेवालोका खयाल गलत है। उनका कथन यह है कि राज्य-शासन लाभदायक है। उसकी सेना ही नुकसान पहुँचानेवाली है। ये मूर्ख लोग यह नहीं समझते कि सेना राज्य शासनका शरीर है और उसके बिना उसका काम घड़ी भर भी नहीं निभ सकता। किन्तु हम स्वयं चूँकि राज्य शासनके मदमें अंधे हैं, इसलिए इस बातको नहीं देख सकते। सचमुच देखा जाये तो सेना एवं राज शासन दानोको हमने यानी प्रजाने ही बनाये रखा है।

इस तरह हम देखते हैं कि हम अपने आपसे ठगे जा रहे हैं। अमेरिकाका सविधान अमेरिकी जनताको स्वतन्त्र रखता अथवा स्वतन्त्रताकी तालीम देता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस राज्यको हम देख रहे हैं वह कुछ कुछ अमेरिकी जनताके गुण और दोषोका परिणाम है। अर्थात् यद्यपि हम सुसंस्कृत और होशियार हैं फिर भी राज्य-शासनके कारण हमारे विकासमें यूनता है।

इतना होनेपर भी मैं राज्यका उन्मूलन करना नहीं चाहता। परन्तु तत्काल तो अच्छी राज्य-व्यवस्था चाहता हूँ और ऐसी अपेक्षा रखना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। जिस देशमें सभी बातें बहुमतसे की जाती हैं वहाँ याय ही होता है यह मानना निराश्रम है। और इस भूलको न देख पानेके कारण बहुतेरे अयाय होते रहते हैं। अधिक मनुष्य जो काम करते हैं वह सही ही होता है, यह मायता एक बेकारका वहम है। क्या ऐसा राज्य नहीं हो सकता जहाँ बहुमतकी रायका पालन होनेके वजाय सत्यका ही पालन हो? क्या मनुष्यको अपनी रू अथवा आत्मा हमेशाके लिए शासकोके सुपुद कर देनी चाहिए? मैं तो यह कहता हूँ कि पहले हम मनुष्य हैं, और बादमें प्रजा। मुझे कानूनका आदर करनेके गुणका विकास करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं दीखती। सच्चेका आदर करनेकी आवश्यकता सदैव है। मुझसे केवल एक ही कर्तव्य अपनाया जा सकता है, और वह है कि जो सच्चा हो वही मैं कहूँ। कानूनके द्वारा मनुष्यको अधिक यायी बना हुआ मैंने कभी नहीं देखा। किन्तु मैंने यह तो देखा है — और अब भी देखता हूँ — कि सामान्य न्याय बुद्धिवाले मनुष्य अपने भोलेपनके कारण अयायके प्रसारके दूत बन जाते हैं। कानूनको बेहद सम्मान देनेका परिणाम हम सब लोग देखते हैं कि हम बदरो जैसे सैनिक बन जाते हैं और बिना कुछ पूछताछ किये यत्रके

समान, हमारा अधिकारी जैसा कहता है, वैसा करत रहत है। बहुत स ठाग इस कामका अपना पेशा बना लेते हैं। और फिर अमुक ठगाने वुरी है, यह निश्चित रूपसे समझते हुए भी वे लोग उगमे बढ़ पतते हैं। इन्हें क्या हम मनुष्य समझे या कमाऊक हाथका कुल्हाड़ा? तेसे लोग लकड़ान दुकडे अपना ईटने समान प्रत जाने हैं। तब उह आदर किस प्रकार दिया जा सकता है? उनका मल्य कुत्ते बिल्लीसे अधिक कैसे समझा जाये? फिर कुछ लोग काननके समथक बनत हैं, राजदूत बनते हैं, वकील बनत हैं। उह अपनी मुद्रिके द्वारा राज्यकी रक्षा करनेका धमण्ट रहता है। परन्तु मैं दग्नता हू कि वे बिना माच-विचार किय अनजानम शैनाकी भी सेवा करते हैं। जा अपनी याय-बुद्धिका कायम रखकर राज्यकी बागडोर अपने हाथमे रखत हैं, वे वास्तवम हमंशा राज्यका विराग करत हुए माऊम हात हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७७ डर्बनमें अंगुलियोकी छाप देनेका आतक

कुछ दिनाग चला चल रही है कि त्रायक रास्ते जा भारतीय अपन दश जाना चाहते हैं उह अत्रिवास प्रमाणपत्र देनेक पट्ट प्रवासी अधिकारी उनक गवाहाग जगूठे ठगवाना है। कुछका यह भी रहता है कि इस सम्बन्धम तथ्रमका जगणा करना चाहिए। एसा मानन अभी बना ता नहीं है, फिर भी, हम मानत हैं, उस तरहम उसका गुप्तान हो रही है। उस सम्बन्धमे कांग्रेस जा-कुछ भी मदद कर सकती है, उसम बहुत ज्यादा रागाका मद करना चाहिए। जब भी अंगूठे मांग जाते हैं लोग यदि अपनी गरज निकालनक त्राग द दत हैं, तो कांग्रेस उसका इलाज नहीं कर सकती। अधिवास प्रमाणपत्रके लिए आवश्यक प्रमाणके सम्बन्धमे निणय करनेका काम प्रवासी अधिकारीको दिया गया है। वह बिना अंगुलियोकी छाप लिये प्रमाणपत्र देनेमे इनकार भी कर सकता है। और यदि कोई आजिजीके साथ मांगे तो वह उसका गरजका लाभ उठाकर उसम अंगूठ ठगवा सकता है। यहां हम यह नहीं कहना चाहत कि उसका यह काम उचित या न्यायपूर्ण है, न हम यह कहना चाहते हैं कि अमुक परिस्थितिमे बाकायदा नहीं लडा जा सकता, बकि हमे यही कहना है कि इस तरहकी लडाईमें यदि हम जीत भी गये तब भी सम्भव है हार ही होगी। जबतक भारतीय झठा शपथ लेते रहेंगे और गलत तरीकेसे अधिवास प्रमाणपत्र लेनकी इच्छा रखग तबतक इस तरहक कष्ट हुआ ही करग। लेकिन इसपर ध्यान देनेकी आवश्यकता इस समय हम नहीं दिखाई दता। हम ना निश्चित रूपसे मानते हैं कि यदि ट्रान्सवालकी लडाईमें हमारे जीत होगी यानी भारतीय समाज अपनी शपथका निर्वाह करेगा और लाख कष्ट उठाकर भी खूनी कानूनकी शरण नहीं जायेगा, तो हमपर जुल्म करनेका जो पीधा ट्रान्सवालमे रोपा गया है, वह फूटते ही जल जायेगा। इसके बाद हम नहीं मानते कि कोई दूसरा उपनिवेश इस तरहके कानून बना सकेगा। बडी सरकारकी हालत सॉप-छछूदरकी-सी हो गई है। और यदि ट्रान्सवालमे हम अन्ततक जूझते रहे तो एलगिन साहब सम्राटको ऐसे कानूनपर सही करनेकी मलाह देना भूल जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अनुमतिपत्र कार्यालयरूपी महामारी अमुक गांव गई और वहासे बगर किसीको छूत लगाये मिट गई, भारतीय कैदियोंको नी उसकी छूत नहीं लगी। महामारीको भगानेवाले वैद्य (स्वयसेवक) उपस्थित थे। जहा सभी स्वस्थ थे वहा वैद्योकी जरूरत ही न पडी।

यह रिपोर्ट अब सामाय हो गई हे। इसलिए मैं स्टैडटन, हाइडेलबर्ग तथा फोक्सरस्टको इतनी जल्दी मुबारकबाद नहीं देता। अब हम इस बीमारीके आदी हो गये ह। इसकी दवा भी जानने लगे हैं। डबनसे सबको एक ही दवा मिलती रहती हे। ओर जहा दवासे या बिना दवाके सभी स्वस्थ हो वहा मुबारकबाद किसे दिया जाये? जहा सभी एक जसा काम करते हो वहा प्रशंसा किसकी की जाये? इसलिए म तो अब खुदाकी ही प्रशंसा करूंगा कि उसने आजतक इन सब गांववालोको अच्छी बुद्धि दी हे और सब एकदिली और हिम्मतसे अपने कतव्यपर डटे हुए हैं। लेकिन मुझे बार बार कहना चाहिए कि यद्यपि ऊपर बताया हुआ काम जरूरी हे, फिर भी उससे ज्यादा कीमती काम अभी करना बाकी हे। जो यह मानते हो कि हम बिना मुसीबत उठाये, बिना जेल गये, बिना देश निकाला भोगे केवल बहिष्कारके बलपर जीत जायेंगे तो यह बड़ी भूल हे। “दुख भोगे सुख होय” इस बातको हमे याद रखना हे। दुख भोगे बिना सुखकी कीमत भी नहां हो सकती। जिसो ठण्डका अनुभव न किया हो, उसे धूपकी कीमत कैसे मालूम होगी? यदि सभी ककर हीरे होते तो हीरोको कौन छूता?

हमीदिया अजुमन

यह अजुमन अपना काम बड़ी हिम्मतसे किये जा रही हे। मैं देखता हूं कि हम जिस युद्धमे लगे हैं, वह धमयुद्ध हे। ईमानकी बात आकर खडी हुई हे। मसजिदमे इबादत की जा रही हे कि “हे खुदा, हम यदि सच्चे हो तो हमारी मदद करना।” लोगोके सामने अब एक ही प्रश्न पेश किया जाता है। कानून चाहिए या ईमान? मौलवी साहब अहमद मुख्तयारने पिछले रविवारको इसी आशयका एक जोशीला भाषण दिया था। उन्होंने कुरान शरीफकी आयतो द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि मुसलमानोका एक यही कतव्य है कि अब वे केवल खुदासे ही अर्जी करे। सच्चा शिष्टमण्डल वही ले जाना हे। वह महान न्यायाधीश किसीका लिहाज नहीं करता, किसीकी शक्तके सामने नहीं झुकता। उसपर चमडीके रंगका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता। वह तो केवल दिलका रंग देखता है। जिसने उसे अपने पक्षमे रखा है, उसकी कभी हार नहीं होती। मेरी सिफारिश है कि मौलवी साहबके इन शब्दोको सभी भारतीय भाई अपने हृदयमे अंकित कर रखे।

जर्मिस्टनकी सभा

सनातन वेद धर्म सभाने जमाष्टमीके उत्सवके सिलसिलेमे सभा की गी। वहा भी यही आवाज सुनाई पडती थी। हिंदू बड़ी सरयामे आये थे। श्री गावी, श्री पोलक,

श्री मैकडायर भी उपस्थित थे। सभी हिंदुओंको महाराज रामसुंदर पण्डितजीने समझाया था कि आस्तिक हिंदू तो एशियाई कानूनको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस सभाको खत्रियो, बाबू तालेवतसिंह और खडेरियाकी ओरसे भेटे दी गई थी।

कुछ डरपोक भारतीय

कुछ डरपोक भारतीयोंकी आरसे प्रिटोरियाके एक वकीलकी मारफत जनरल स्मट्सको एक पत्र^१ लिखा गया है। मालूम हुआ है कि यदि सरकार थोड़ा-सा भी आश्वासन दे दे तो वे लोग फिसलनेको तैयार हैं। मेरा कहना है कि ऐसे पत्रोंसे हमारी लड़ाई कमजोर होती है। किंतु मैं यह नहीं मानता कि इससे अतमे नुकसान होगा। यदि भारतीय बड़ी सरयामे अपनी टेकपर डटे रहे तो आखिर हमें विजय मिलनी ही चाहिए। मैं यह भी कहता हूँ कि इस तरहके डरपोक पत्रोंके कारण हमें ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इसके अलावा, हमने जो तुच्छ माग की है उससे प्रकट होता है कि हमें सच्ची लड़ाइका भान नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय समाजकी नाक बनाये रखनेके लिए है, हमारे ईमानकी रक्षाके लिए है। यदि हम उसे रोटी कहे तो यह डरपोक पत्र उस रोटीके बदले रेत लेकर सतुष्ट होनेकी बात करता है। पुलिस सावजनिक तौरसे अनुमतिपत्र न देखे, या दस अँगुलियोंकी छापकी जगह सही करवाये तो इसमें यह नहीं माना जायेगा कि हम जीत गये या हमारी प्रतिष्ठा रह गई। वह घणित कानून तो रह ही जायेगा। इसका अर्थ केवल यही हुआ कि लोहेकी बेड़ीकी जगह किसी हलकी धातुकी बेड़ी पहनाई जायेगी। हमारी लड़ाई तो बेड़ी तोड़कर चूर चूर कर देनेके लिए है।

मेरी अर्जी

अब उपयुक्त पत्र तो गया। लेकिन उस पत्रको भेजनेवाले भाइयो और दूसरे भारतीयोंसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आपको धीरज न हो, आपसे अपना पैसा न छूटता हो तो आपको मेहरबानी करके बिना अर्जी कानूनकी शरण चले जाना चाहिए। इससे आपके द्वारा समाजका कम नुकसान होगा और आप स्वयं कम डरपोक कहलायेंगे। यदि सभी भारतीयोंकी बुद्धि पलट जाये और सबके सब डर जाये तब भी मैं तो यही सलाह देनेवाला हूँ।

पत्रका असर कैसे दूर हो ?

उपयुक्त पत्रसे होनेवाला नुकसान कम या दूर कैसे हो, इसका उपाय खोजे। इस पत्रमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारतीय सघ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सभी भारतीय शामिल नहीं ह। दरअसल यह बात है भी ठीक। इससे अब यह दिखाना सघका कतव्य हो गया कि सघके कितने लोग एकमत हैं। समय आनेपर 'पीतल है या सोना' यह अपने-आप साबित हो जायेगा। लेकिन सच्चे मनुष्यको अपनी सच्चाई ढाकनी नहीं पड़ती। इस विचारसे हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें श्री गांधीने सुझाया कि हम कानूनके पूरी तरह खिलाफ हैं, वह हमें मजूर नहीं है, ऐसी एक छोटी सी अर्जी हर भाषामें तयार करवाई जाये और उसपर सब भारतीयोंके हस्ताक्षर करवाये जाये। ऐसा करनेसे निःसंदेह लड़ाईको बहुत बल मिलेगा।

१ सर्वश्री स्टैगमान पसेलेन और रॉस द्वारा लिखा गया पत्र, देखिए “भीमकाय प्रार्थनापत्र”, पृष्ठ २३७-४०।

इस विचारको मौलवी साहब, श्री उमरजी साले वगैरह सज्जनोने स्वीकार किया। लेकिन एम० एस० कुवाडियाका मत विरुद्ध होनेसे इसे अगले रविवार तक मुलतवी रखा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले रविवारको यह सर्वानुमतिसे पास हो जायेगा। इसी खयालसे आप सबको नीचे लिखे अनुसार सूचना देनेकी अनुमति मागता हूँ। यदि प्रस्ताव मजूर होगा तो

- १ अर्जी हर गावमे भेजी जायेगी।
- २ हस्ताक्षर दो कागजोपर लिये जाये और हस्ताक्षरकर्ताका नाम, धधा और उसका पता दिया जाये।
- ३ हस्ताक्षर लेनेवाले भाईका नाम अर्जीके कोनेमे लिखा हो। यह हस्ताक्षर लेनेवालेकी गवाही होगी।
- ४ अर्जीको ठीक तरहसे पढाये बिना किसीसे हस्ताक्षर न लिये जाये।
- ५ अर्जीको साफ रखा जाये और जैसे जैसे मूल और प्रतिलिपि दोनोपर हस्ताक्षर होते जाये वे कागज सघको भेजे जाये।
- ६ इस अर्जीपर हस्ताक्षर करवानेका काम १० दिनमे समाप्त होना चाहिए।
- ७ हस्ताक्षर करवानेके लिए स्वयसेवक तैयार रखे जाये, जिससे समय बरबाद न हो।
- ८ इस अर्जीपर हस्ताक्षर करनेवालेका मन दृढ हो और वह अततक टिकना स्वीकार करे तब वह हस्ताक्षर करे।
- ९ यदि कुछ ही हस्ताक्षर होंगे तो यह अर्जी सरकारको भेजी ही नहीं जायेगी।
- १० इस सूचनाको देखते ही हर गाववाले अपने गावकी भारतीय आबादीकी सख्या तार या पत्रके द्वारा सघको सूचित कर देगे तो बहुत अच्छा होगा और समयकी बचत होगी।

यह अर्जी यदि सरकारको न भी भेजी जाये तो भी हस्ताक्षर लेनेसे हमे यह पता तो चल ही जायेगा कि लोगोमे सचाई और हिम्मत कितनी है। यदि ज्यादातर लोगोमे सचाई नहीं होगी तो हम हर्गिज नहीं जीतेगे। इसके साथ मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि एक दफा अर्जीकी बात उठाई जानेके बाद यदि हम उसे न भेजे तो उससे हमारी उतनी ही कमजोरी जाहिर होगी। लेकिन जो खुदापर भरोसा रखते हैं वे अपनी कमजोरी जाहिर होनेसे डरनेके बजाय खुश होते हैं। खरे और छोटे रुपयोके ढेरमे से छोटे रुपयोको निकाल डालनेमे बुद्धिमानी है। उतना बोझ कम उठाना होगा। ये सब बिलकुल सीधी बातें हैं। इसलिए तुरन्त ही समझमे आ जानी चाहिए।

हमारे कुकृत्य

हमीदियाकी पिछली सभा देखकर मुझे यह विचार आता है कि हमारी नामर्दीके साथ हमारे कुकृत्य भी प्रकट हो जायेगे। यह तो हो ही नहीं सकता कि कानूनके बारेमे एक तरफ तो हम खुदापर यकीन रखे और दूसरी तरफ लुच्चे और धोखेबाज रहे। हमारी लडाई इतनी शुद्ध है। प्रिटोरियामे एक हिंदू है। उसके सम्बन्धमे कहा जाता है कि उसने शराबकी दूकानमे एक भारतीयको इतनी बुरी तरह मारा कि वह बेसुध हो गया। मारनेवाले-पर अबतक मुकदमा नहीं चला है। इसका नतीजा क्या होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन उसने मारा है, यह बात सब जानते हैं। जोहानिसबर्गमे कुछ भारतीयोपर एक गरीब

भारतीयको लूटनेका आरोप है। भारतीय लुटा, इसमें तो कोई शक नहीं। जिनपर इल्जाम लगाया गया है, उनका निश्चित कहना है कि वे निर्दोष हैं। एक और भारतीय पकड़ा गया है। उसपर नकली सिक्के बनानेका आरोप है। इन घटनाओंसे यह सिद्ध होता है कि हमसे से कुछ लोगोमें चरित्रकी कमी है। इसप मियाने समितिमें भाषण देते हुए कहा कि इस तरहकी बातें होनी ही नहीं चाहिए। और दीवानी दावे तथा झगड़े हो तो उन्हें भी वकील या सरकारका खजाना भरे बिना अपने घरमें निबटा लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस बातपर बहुत ही सावधानीसे अमल किया जाना चाहिए। इस लड़ाइके परिणामस्वरूप यदि हम हिंदू मुसलमानका भेद भूल जायेंगे, आंतरिक झगड़े खत्म कर देंगे, और यदि हुए भी तो उन्हें घर ही घरमें निबटा लेंगे और दूसरे कुकर्म भी छोड़ देंगे, तो तेरह हजार भारतीयोंकी सारे ससारमें तारीफ होगी और उनके नाम खुदाकी बहीमें सदाके लिए दर्ज हो जायेंगे। एक भारतीय सिर्फ बदला लेनेके लिए ही दूसरे भारतीयपर दोषारोपण करता है, यह मामूली बात नहीं मानी जा सकती। एक आदमी दूसरेको पीटता है, यह कोई छोटी क्रूरता नहीं है। कोई भी भारतीय शराब पीता है, यह कम बेइज्जतीकी बात नहीं। जरासे प्रयाससे इन बुरी आदतोंको मिटाया जा सकता है। नये कानूनका खात्मा करनेके लिए इस गंदगीको दूर करना भी मैं जरूरी मानता हूँ।

पहले दर्जेकी बग्घी

जाटानिमवग नगरपालिका पहले दर्जेकी बग्घीमें भारतीयोंको न बठने देनेके लिए नियम बना रही है। उसके विरोधमें ईसप मियाने सख्त पत्र^१ लिखा है। उस नियममें अब और यह सुधार (या बिगाड़) किया जानेवाला है कि जो भारतीय वकील या डाक्टर हो वह उस बग्घीमें बैठ सकता है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय वकीलोंको गलेमें पटिया लगाकर पहले दर्जेकी गाड़ीमें बैठने जाना चाहिए? यदि वह ऐसा न करे तो गाड़ीवान उसे किस तरहसे पहचान सकेगा? वकील भले फटेहाल हो, फिर भी वह पहले दर्जेकी बग्घीमें बैठ सकता है, लेकिन अच्छी पोशाकवाला व्यक्ति, यदि वह वकील या डॉक्टर नहीं है तो नहीं बैठ सकता। इस बेहूदे सशोधनके विरोधमें श्री ईसप मियाने दूसरा पत्र^२ लिखकर कहा है कि इस तरहके सुधार करना जलेपर नमक छिड़कनेके समान है। ऐसे सशोधन भारतीय नहीं चाहते। नये पजीयन लेनेवाले इस कूड़ा प्रस्तावसे चौक जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१ देखिए “पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको”, पृष्ठ १९९।

२ देखिए “पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको”, पृष्ठ २०९।

१७९ पत्र ' एशियाई पजीयकको

[जोहानिसबग
सितम्बर ११, १९०७]

[सेवामे
एशियाई पजीयक]

महोदय,

सबश्री मुहम्मद इब्राहीम, बूसा कारा, करावली और इसा इस्माइलको पिछले महीनेकी २७ तारीखको शांति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत उपनिवेशसे चले जानेका १४ दिनका नोटिस मिला था। तदनुसार मेरे मुवक्किलोंने इस मासकी २ तारीखको डेलागोआ बेंके तीसरे दर्जेके टिकट खरीद लिए और इस प्रकार नोटिसोकी शर्तें पूरी करनेकी कारवाई की। किन्तु वे कोमाटीपूटमे हिरासतमे ले लिये गये और पुतगाली प्रदेशमे घुसनेसे रोक दिये गये। ट्रान्स वालकी सीमापर जो सार्जेंट था उसने डेलागोआ बेंमे उनका प्रवेश करानेका प्रत्यन किया, उसका कोई फल नहीं निकला। इसके बाद मेरे मुवक्किल कोमाटीपूटमे, जैसा वे कहते हैं, पांच दिन तक जेलमे रखे गये। उसके बाद सार्जेंट उनके लिए डबनके टिकट लाया। उनके डबन होकर गुजरनेके लिए नौरोहण पासोके प्राथनापत्र देनेपर उन्हें हुक्म हुआ कि वे ११ पौंड जमा करे और अपना टिकट जोहानिसबगमे खरीदे। मेरे मुवक्किल मुझे सूचित करते हैं कि वे बहुत गरीब ह, इसलिए वे न यह रुपया जमा कर सकते हैं और न जोहानिसबगमे अपने टिकट खरीद सकते हैं। उनके रेलवे टिकट मेरे पास हैं। यदि आप मुझे कृपा करके यह बता देंगे कि मेरे मुवक्किलोको अब क्या करना है तो मैं कृतज्ञ हूँगा। वे देशसे जानेके लिए बिल्कुल तैयार ह, बशर्तें कि उनके लिए व्यवस्था की जा सके। मैं नम्रतापूर्वक यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किलोको कोमाटीपूट जेलमे क्यों रखा गया।^१

[आपका, आदि,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २१९/१२१

१ यह १४-९-१९०७के इंडियन ओपिनियनमें छपा था। इसकी एक प्रतिलिपि श्री रिचने ७ अक्टूबरको भारत उपमन्त्रीको भेजी थी।

२ पजीयकने इसका उत्तर दिया था कि “चूँकि इन लोगोको कोई ऐसी जगह नहीं मालूम थी जहाँ वे रह सकें”, इसलिए उनको पुलिसकी कोठरीके उपयोगकी अनुमति दी गई थी, और पुलिसका यह कार्य बिल्कुल भारतीयोके हितमें था। आवश्यक व्यवस्था होनेपर ये लोग बादमें डबनको रवाना हो गये, देखिए “जोहानिसबगकी चिट्ठी”, पृष्ठ २७०।

१८० न घरके न घाटके

हम अत्र एक पत्र^१ छाप रहे ह जो एशियाइयोके पजीयकको उन कतिपय भारतीयोके बारेमे लिखा गया है, जो ट्रासवाल खाली कर देनेकी सूचना मिलनेपर और डेलगोआ बेमे प्रवेश करते हुए, बाहर निकाल दिये गये हैं। उन लोगोको ट्रासवालमे रहते हुए कमसे कम एक महीनेके कारावासकी सजा होनेका खतरा है। उनका कहना है कि वे इतने गरीब हैं कि नेटाल जानेके जहाजी-पासोके लिए रकमे जमा नहीं करा सकते। अब वे क्या करे? इसपर अपनी राय देनेसे पूर्व हम सरकारी जवाबके इतजारमे हैं। इसी बीच, जो तथ्य सामने आये हैं उनसे पता चलता है कि एशियाई पजीयन अविनियमका भारतीयोके लिए क्या मतलब है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८१ क्या दशा होगी?

यदि इतनी मेहनत करनेके बाद भारतीय कणधार तूफानी लहरोको देखकर जेलकी लडाईं रूपी नौका छोड़ देगे तो क्या दशा होगी, इसका उदाहरण श्री रिचकी ओरसे प्राप्त पत्रसे सब समझ सकेंगे। फिर भी यह किस तरह, इसपर विचार कर ले।

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिका हमपर विश्वास जम गया है। इसलिए वह समिति अब खुलेआम सहानुभूति बताने लगी है। समितिके नामसे श्री रिचने प्रधानमन्त्रीको पत्र^२ लिखा है। उसमे हम जो-कुछ माग रह ह उसका हू-ब-हू चित्र खींचा है। यह लडाईं मामूली फेरफारके लिए नहीं लड़ी जा रही है। लोहेकी बेडीपर जरा सा मुलम्मा चढानेके लिए हम पानीके समान पैसा नहीं बहा रहे हैं। श्री रिचने साफ कहा है कि कानून रद किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी जो मागे की ह उन्हें पाठक ध्यानपूर्वक देख ले। अब किनारेपर पहुँची हुई नौकाको यदि भारतीय कणधार छोड़ देगे तो उहे कितनी हाय लगेगी। वे भारतीयोके नामके — भारतीयोकी लाजके रखवाले हैं। उन्होने आगसे बाजी लगाई है। उसमे यदि थोडा बहुत चटका लगता है तो डरना नहीं चाहिए। डरेगा सो मरेगा।

‘सटरडे रिव्यू’ के सम्पादकने जो कुछ कहा है उसपर विचार करे। वह बहुत ही प्रभावशाली और पुराना अखबार है। वह यद्यपि अनुदार दलका है, फिर भी जोशके साथ लिखता है कि भारतीय समाजने कानूनके बश न होने और जेल जानेका जो प्रस्ताव पास किया है, वह ठीक है। अंग्रेजी राज्य उन्हें छोड़ दे तो यह बड़ी बदनामीकी बात होगी। यहाँतक पहुँच जानेके बाद क्या अब भारतीय नेता यह दिखायेंगे कि उनकी लडाईं ऊपर

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ देखिए परिशिष्ट ५।

ही ऊपर थी ? क्या अपने पैसेके लोभमे अंधे होकर वे हजारोके पेटमे भाले भोकेंगे और सारी प्रजाको जनानी और नकटी साबित करेंगे ?

‘नेशन’ बहुत स्वतन्त्र अखबार माना जाता है। उसका उदार दलपर पूरा प्रभाव है। उसके नाम एक परिचित लिखावटवाले अंग्रेजने लिखा है कि भारतमे जितनी हाय तोबा और नाराजी ट्रान्सवालके भारतीयोपर होनेवाले जुल्मोके कारण हो रही है उतनी और किसी बातसे नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि इस लड़ाईमे यदि भारतीय कायर बनेंगे तो वे भारतको नुकसान पहुँचायेंगे। ट्रान्सवालके भारतीयोंने जो निश्चय किया है और जिसके बारेमे इतना प्रचार हुआ है, वैसा पहले कभी भारतमे भी नहीं हुआ। अतः भारतीय नेताओंके लिए बहुत जरूरी है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८२ “कानूनके सामने मोम”

प्रिटोरिया आदि नगरोंके “अग्रणी भारतीयों” की ओरसे जो अर्जी^१ भेजी गई है उसे हम बहुत शम और अफसोसके साथ इस अकमे प्रकाशित कर रहे हैं। इस कदमको हम बहुत कमजोर मानते हैं, और इसका मुख्य दोष श्री हाजी कासिमको देते हैं। उनका नाम प्रत्येक भारतीय मण्डलमे आता रहता है इसलिए उसे प्रकाशित करनेमे हमे झिझक नहीं है, बल्कि प्रकाशित करना हम एक कतव्य समझते हैं। यद्यपि हम श्री हाजी कासिमको दोष दे रहे हैं फिर भी हम समझते हैं कि उनकी जैसी स्थितिके दूसरे भारतीय इस प्रकार कदापि न करते, सो नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनकी बदनामीको हम सभीकी बदनामी समझते हैं।

अर्जीकी भाषा दीनताभरी और गुलामोंको फबनेवाली है। हम “कानूनके सामने मोम” है इस प्रकारके शब्दोंका उपयोग करनेमे, हम समझते हैं, हमने खुदाके प्रति अपराध किया है। हमारी बागडोर थामनेवाला वह एक ही है, तब उसीको शोभा देनेवाली भाषा हम अत्याचारी शासकोंके लिए कैसे बरत सकते हैं ?

जो मांगे की गई है वे बेसिर-पैरकी है। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक लड़ाईको हमने समझा ही नहीं है। ऐसा ही लेख हम पहले भी दे चुके हैं।^२

अब हम श्री हाजी कासिम तथा उनके साथियोंसे इतना ही पूछते हैं कि क्या उनकी समझमे इतनी सी बात नहीं आती कि उनकी तुच्छ अर्जीके कारण भारतीयाकी प्रतिष्ठा घटती है और उनकी टोकको धक्का पहुँचता है ? यदि यह बात ठीक हो तो ऐसा काम करनेके बाद बचे हुए पैसेको वे किस कामका मानेंगे ? इसलिए अब भी यदि समय हो तो हमारी उनसे विनती है कि समाजकी भलाईके लिए वे अपना बलिदान दे। क्या जैसे सरकार भारतीयोंकी अर्जी नहीं सुनती श्री हाजी कासिमकी सरकार भी नहीं सुनेगी ?

१ यहाँ नहीं दी गई है।

देखिए जोहानिसबर्गकी चिट्ठी, पृष्ठ २२३ २६।

यदि ऐसा ही हो तो, श्री हाजी कासिमकी प्रजासे, यानी उनके शब्दोपर चलनेवाले भारतीयोसे, हमारा कहना है कि इस समय दूसरोकी ओर न देखकर अपनी ही हिम्मत और खुदापर नजर रखनी है। हरएकको किसी भी भारतीयका पक्ष न लेकर खुदाका पक्ष लेना है। उसीके हाथमे अपनी लाज और आबरू रखकर जमकर काम करना है। हमे आशा है कि प्रत्येक भारतीय स्वतंत्र रूपसे विचार करेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८३ रिचका प्रयास

श्री रिचने हृद कर दी है। उनका परिश्रम अगाध है। उन्होंने 'टाइम्स' के नाम एक पत्र लिखा था जो तारसे प्राप्त हुआ है। उसका अनुवाद^१ अयत्र दिया गया है। वह पढ़ने योग्य है।

एक ओरसे कोई-कोई भारतीय लडाई छोडकर ढीले पडने लगे है। दूसरी ओरसे श्री रिच और समिति हमारे लिए पूरी ताकतसे प्रयत्नरत है। श्री रिचके पत्रपर टीका करते हुए 'लदन टाइम्स' ने ट्रान्सवाल सरकारको जो कोडे लगाये है उनका प्रभाव होना ही चाहिए। विलायतमे जब इतने सुंदर ढंगसे लडाई की जा रही है तब ट्रान्सवालके भारतीयोको तो हिल मिलकर साहसके साथ खुदापर भरोसा रखकर अपने निणयको निबाहना ही है। यह स्पष्ट हिसाब है। हमारी प्रार्थना है कि इस बातको कोई भारतीय न भूले।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८४ भारतीयोकी परेशानी

चार भारतीयोको ट्रान्सवाल छोडनेका आदेश दिया गया था। डेलागोआ बे जाते हुए उनको ट्रान्सवालकी सीमासे आगे नही बढने दिया गया और जेलमे रखकर उन्हें बडा कष्ट पहुँचाया गया। इसके बारेमे श्री गांधीने पजीयकको पत्र^२ भेजा है। वह हमने अयत्र दिया है। ये लोग ट्रान्सवालसे बाहर जानेके लिए राजी ह, फिर भी जा नही सकते। यदि ट्रान्सवालमे रहते है तो एक महीनेकी जेलकी सजाके पात्र बनते ह। इस हालतमे वे क्या करे? भारतीयोको ढीला समझकर सरकार उन्हें परेशान करना चाहती है, इसके सिवा इसका और क्या अर्थ हो सकता है? एशियाई पजीयन कानूनको लागू करके सरकार क्या करना चाहती है यह इस मामलेसे साफ हो जाता है। क्या भारतीय लोग अब भी नरम रहकर यह सब सहन करते रहेगे?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१ यहाँ नही दिया गया।

२ देखिए "पत्र एशियाई पजीयकको", पृष्ठ २२७।

१८५ कानूनका विरोध — एक कर्तव्य [२]

इस शीर्षकसे थोरोके लेखका कुछ भाग^१ हम दे चुके हैं। शेष निम्न प्रकार है।
समझदार व्यक्ति मदकी तरह ही काम करेगा। दूसरेके हाथका खिलौना नहीं बनेगा। अमेरिकाके इस शासनको टिकाये रखनेका जो मनुष्य प्रयत्न करता है उसे नामद समझा जाये। जो राज्य गुलामोपर शासन करता है उसे मैं अपना राज्य नहीं मान सकता। जब बहुत अत्याचार हो तब अत्याचारी राज्यका मुकाबला करना मनुष्य जातिका अधिकार है। कुछ लोगोका कहना है कि अमेरिकाका वर्तमान शासन उतना अत्याचारी नहीं है। अर्थात् स्वयं उनपर आक्रमण नहीं हो रहा है। और यदि दूसरोपर हो रहा है, तो ऐसा कहनेवालोको इस बातकी परवाह नहीं है।

जिस प्रकार प्रत्येक यत्रमे थोडा बहुत जग^२ लगा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक शासनमे जग रहता है। उस जगको दूर करनेके लिए विरोध करनेकी आवश्यकता भले कभी न पड़े, परन्तु जब जग ही यत्र बन जाये, जब जुल्म ही कानूनका रूप ले ले तब वह राज्य मर्दोको बर्दाश्त नहीं हो सकता।

प्राण देना पड़े तब भी न्याय एव सत्यका पालन करना चाहिए। मैंने यदि डूबते हुए व्यक्तिसे तूबा छीन लिया हो, तो मुझे अपनी जान देनी पड़े तब भी वह तूबा उसे वापस देना चाहिए। उसी प्रकार यदि अमेरिकाका राज्य डूबता हो तब भी गुलामोको मुक्त किया जाना चाहिए।

हम कहा करते हैं कि किसी काममे सुधार करनेके लिए लोग हमेशा तैयार नहीं होते। परन्तु सुधार करनेमे हमेशा समय लगता है, क्योंकि सुधारक लोग, जो ज्यादा नहीं होते, एकदम बहादुर नहीं बन जाते। इस बातकी चिंता नहीं कि आपके जसे सभी मनुष्य भले नहीं बन सकते। किन्तु समाजमे कुछको तो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जिस प्रकार खमीरकी एक बूद सारी रोटीको खमीर चढा देती है, उसी प्रकार वे अपनी सात्विकता समाजपर चढा देते हैं। ऐसे तो हजारो हैं जो विचारसे गुलामीके विरुद्ध हैं परन्तु व्यवहार बिल्कुल उलटा करते हैं। वे सब वॉशिंगटनके वशज कहलाते हैं, परन्तु जेबमे हाथ डाले हुए मौज उड़ाते रहते हैं। अधिक किया तो अर्जिया और भाषण दे दिया करते हैं।

ससारमे सत्यके पीर — माननेवाले — तो हजारमे नौ सौ नियावे व्यक्ति होते हैं, आचरण करनेवाला एक ही होता है। किन्तु सत्यको माननेवालेसे सत्यका आचरण करने वालेका, भले वह एक हो तो भी, मूल्य अधिक होता है। खजानेकी रक्षा करनेवाले बहुतेरे खडे हों तो भी वे उसमे से एक पाई भी नहीं दे सकते, जबकि मालिक एक ही हो तो वह सारा खजाना लुटा सकता है।

मनुष्य सत्यके पक्षमे मत दे तो वह सत्यका आचरण करनेके बराबर नहीं है। जब बहुत से लोग गुलामी रद्द करनेके लिए मत दे तब यह समझिये कि गुलामी रद्द करना

१ देखिये “कानूनका विरोध — एक कर्तव्य [१]”, पृष्ठ २२० २२।

२ गांधीजीने ‘फिक्शन’ (वर्षण)के लिए इस शब्दका प्रयोग किया है। देखिये उद्धरण, “सक्रिय अवज्ञाका धर्म”, पृष्ठ २१५।

शेष रहा ही नहीं। उससे यह समझना चाहिए कि रद्द करनेवाले सच्चे व्यक्ति उसकी नींव पहले ही डाल चुके थे।

मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक मनुष्यको जहा कही भी झूठ दीख पड़े, उसे दूर करना ही चाहिए। किन्तु इतना मैं निश्चित रूपसे कहता हूँ कि उसे स्वयं तो असत्यमे हाथ बँटाना ही न चाहिए। निश्चय कर लेनेके बाद जबतक मनुष्य मात्र उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तबतक उसमें क्या मजा आयेगा?

यदि कोई मेरा माल चुराकर ले जाता है, तो मैं यह कहकर नहीं बैठा रहता कि यह चोरी हुई सो ठीक नहीं हुआ, बल्कि चुराये गये मालको वापस प्राप्त करने और दुबारा चोरी न हो इसके लिए प्रयत्न करता हूँ। जो मनुष्य अपने कथनके अनुसार आचरण करता है वह और ही प्रकारका बनता है। वह न देशकी परवाह करता है, न सगे सम्बन्धीकी परवाह करता है, न मित्रोकी, बल्कि सत्यकी सेवा करते हुए उपर्युक्त सभी लोगोकी सेवा करता है।

हम स्वीकार करते हैं कि कानून अत्याचारपूर्ण है। क्या हम उसका विरोध करेंगे? साधारणतया लोग कहते हैं कि जब बहुमत उन कानूनोंको नापसन्द करेगा तब वे रद्द होंगे। उनका कहना है कि यदि वे विरोध करें तो कानूनसे होनेवाली बुराईकी अपेक्षा विरोधसे उत्पन्न बुराई अधिक बुरी होगी। किन्तु वैसा हो तो वह दोष विरोध करनेवालेका नहीं है, अधिकारीका है।

मैं बेखटके कह सकता हूँ कि मैसाच्युसेट्समें गुलामीके विरुद्ध, भले वह एक ही मनुष्य हो, उसे गुलामीको बनाये रखनेमें कर देकर अथवा और किसी भी तरहसे मदद नहीं करनी चाहिए। दूसरे उसकी राय नहीं अपनाते तबतक उसे खराब काम नहीं करते रहना चाहिए। क्योंकि वह अकेला नहीं है। खुदा सदा उसके साथ है। यदि मैं दूसरोकी अपेक्षा सच्चा हूँ तो मैं उन सभीकी तुलनामें बढकर हूँ। मुझे हर वर्ष एक बार इस राज्यका अनुभव होता है। मेरे पास कर लेनेवाला आता है। उस समय मुझे कर देनेसे इनकार कर ही देना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि इस मैसाच्युसेट्समें एक ही सच्चा वीर गुलामीके विरोधके निमित्त कर न देकर जेल जाये तो उसी दिनसे गुलामीकी बेड़ी टूटने लग जायेगी। जो चीज सही तरीकेसे की जाये उसे ही वास्तविक रूपमें सफल माना जायेगा। किन्तु हम तो लम्बी लम्बी बातें करके माने लेते हैं कि बातें करना ही हमारा काम है। गुलामी समाप्त करनेके आन्दोलनका समर्थन करनेवाले बहुतसे समाचारपत्र हैं, परन्तु उनमें मदद एक भी नहीं है।

जिस राज्यमें लोगोको गलत आधारपर जेलमें रखा जाता है उस राज्यमें न्यायी और भले लोगोका घर जेल है। इसलिए मैसाच्युसेट्समें भले मनुष्योको आज जेलमें होना चाहिए। जिस राज्यमें गुलामीकी प्रथा हो वहा मनुष्य जेलमें ही स्वतन्त्र है। वही उसकी प्रतिष्ठा है। जो लोग यह मानते हैं कि भले मनुष्य यदि जेल चले जायेंगे तो पीछे अन्यायके विरोधमें आन्दोलन करनेके लिए कोई नहीं रहगा, उन्हें पता नहीं है कि आन्दोलन किस प्रकार चलता है, न उन्हें इस बातका ही भान है कि सत्य असत्यसे कितना जोरदार होता है। जेल भोगनेवाले तथा अन्यायके जुल्मका अनुभव करनेवाले जेलमें रहकर जितना काम कर सकेंगे उतना जेलसे बाहर रहकर नहीं कर सकते। विरुद्ध राय रखनेवाले थोड़ेसे लोग जबतक दूसरी रायके बहुजन समाजके साथ घुलते मिलते रहेंगे तबतक उन्हें विरुद्ध विचारके नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो अपनी सारी शक्ति विरुद्ध गति पैदा करनेमें लगानी चाहिए।

मैं अपने पड़ोसियोंसे बातचीत करता हूँ तो उनके कथनसे पता चलता है कि उन्हें भय है, यदि वे विरोध करे तो उनका सब कुछ चला जायेगा और उनके पत्नी बच्चे दर दरकी ठोकरे खायेगे। यदि मुझे स्वयं अपने लिए या अपने परिवारके लिए राज्यपर निर्भर रहना पड़े तो मैं निराश हो जाऊँगा।

मुझे लगता है कि अत्याचारी राज्यके सामने झुकना लज्जाजनक है। उसका विरोध करना आसान और अच्छा है। आज छ वर्षसे मैंने कर नहीं दिया। इस कारण एक बार एक रातके लिए मुझे जेलमें रखा गया था। मैंने जब इस कैदखानेकी दीवारों और लोहेके दरवाजोंको ध्यानसे देखा तब मुझे राज्यकी मूल्यताका अनुमान हुआ। क्योंकि मुझे कैद करनेवालोंकी तो यही धारणा होगी कि मैं केवल हड्डी और मांसका बना हुआ हूँ। वे मूल्य यह नहीं जानते कि मैं दीवारोंसे घिरा हुआ होनेपर भी औरोंकी अपेक्षा मुक्त हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैं कैदमें हूँ। मुझे तो यही लगा कि जो बाहर है उहीकी स्थिति कैदीकी है। वे मुझ तक नहीं पहुँच सके इसलिए उन्होंने मेरे शरीरको सजा दी। ऐसा करनेसे मैं अधिक मुक्त हो गया और राज्य-शासनके प्रति मेरे विचार और भी भयकर बन गये। मैंने देखा कि छोटे बालक जब किसी मनुष्यका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तब उसके कुत्तेको सताते हैं। उसी प्रकार राज्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए मेरे शरीरको तकलीफ देता है।

मैंने यह भी देखा कि शरीरको तकलीफ देनेमें भी राज्य डरता था। इसलिए राज्यके प्रति मेरे मनमें जो कुछ सम्मान था वह चला गया।^१

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अभागे भारतीय

भारतीय जहाँ भी हो वही उनकी दुदशा है। अभी अमेरिकासे आवाज आई है कि वाशिंगटनमें काम करनेवाले मजदूर भारतीयोंकी नामद गोरोंने पिटाई की है। उनमें से चार भारतीय जरमी हुए ह और शेषमें भगदड़ मची हुई है। मारनेवाले इन गोरोंको मैं नामद मानता हूँ। क्योंकि, उनमें से हजारों लोग निरपराध मजदूरोंपर चढ़ दौड़े, यह कोई बड़ा दुरीका काम नहीं माना जायेगा। जो अपनेसे कमजोरपर जुल्म करता है वह नामद है। हमारी कहावत है कि कुम्हार नाराज होता है तो गधेके कान उमेठता है। ये नामद गोरों भी वैसे ही हैं। ये लोग चूँकि उन गोरोंका कुछ नहीं कर सकते जो इन भारतीयोंको नौकर रखते हैं, इसलिए नौकरोपर अत्याचार करते ह। बहादुर तो उसे ही कहेंगे जो अपनेसे ज्यादा बलवानका मुकाबला करता है।

वाशिंगटनके महापौरने भारतीय मजदूरोंसे कहलवाया है कि वे उनकी रक्षा करेंगे, वे अब खुशीसे अपनी नौकरियोंपर वापस चले जायें। उन्होंने इन मजदूरोंकी रक्षाके लिए विशेष

१ इसके बाद यह सम्पादकीय टिप्पणी दी गई थी 'चाटू तथा गताक्रमें आया हुआ यह लेख पुस्तिकाके रूपमें आगामी सप्ताहमें प्रकाशित होगा। मूल्य ६ पैसे, डाकाखच सहित ७ पैसे।'

पुलिस तैनात की है। इससे महापौर महोदयकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह भी खबर मिली है कि इग्लैंडका वैदेशिक विभाग भी उनकी सार-सँभाल करता है।

इस हमलेका अर्थ इतना ही होता है कि भारतीय स्वयं बहादुर होंगे तभी विदेशोंमें निभा सकेंगे। गोरे तो हमेशा लाते मारते ही रहेंगे और उनसे बड़ी या दूसरी कोई सरकार उन्हें बचानेवाली नहीं है। जो भीरु होकर बैठ जायेंगे, उनकी खुदा भी सहायता नहीं करता। हम यदि शेर चीतोंके बीच बसे तो दो ही बातें हो सकती हैं। सच्ची हिम्मत तो यह कहलायेगी कि उनसे डरा न जाये। शेर-चीतोंको भी भगवानने पदा किया है। उनकी ओरसे निभय वही रह सकते हैं जो सच्चे बहादुर हैं, या फिर जो सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त अपनी भक्ति द्वारा लम्बे समयमें यह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे वगकी हिम्मत है—शेर चीतोंके सामने हथियार लेकर खड़े होना। उसमें भी शरीरकी जोखिम तो उठानी पड़ती ही है। गोरोके बीच बसनेवालोंकी स्थिति ऐसी ही है, और आगे भी ऐसी ही रहेगी। जिन लोगोंको इसका भय हो, उन्हें अपने पेटके लिए परदेश नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें साधारणतः दूसरे वगकी हिम्मतकी जरूरत है। श्रीमती एनी बेसेंटी^१ नीतिके अनुसार छोटे बड़े सभी भारतीयोंको कुश्ती आदि व्यायाम सीखकर शरीरसे स्वस्थ बनना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हमारे मनमें स्वाभिमानकी भावना जागे और हम भी मद हैं इसका भान हो।

पोलकका पत्र

‘स्टार’ समाचारपत्रमें एक अंग्रेजी लिखनेवाले भाईने लिखा है कि भारतीय व्यापारी कुल मिलाकर और दूसरोंकी तुलनामें विश्वसनीय हैं। इसलिए उन्हें गोरे व्यापारी रकम दिया करते हैं। लेकिन इस पत्र लेखकने यह भी कहा है कि चूँकि भारतीय व्यापारियोंके पैसोंका उपयोग ट्रान्सवालमें नहीं होता इसलिए उन्हें निकालकर बाहर कर देना चाहिए। इसके उत्तरमें श्री पोलकने एक लम्बा पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीयोंको भूमि सम्बन्धी और दूसरे अधिकार नहीं हैं इसलिए उनके पैसोंका ज्यादा उपयोग इस देशमें नहीं होता। उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि पांचेफस्टूमके अग्निकाण्डके समय जो चढ़ा एकत्रित किया गया था उसमें मदद देनेके लिए भारतीयोंने क्या कहा था। समूचे भारतीय प्रश्नकी उन्होंने अच्छे ढंगसे चर्चा भी की है।

पजीयन कार्यालय

पजीयन कार्यालयकी यात्रा होती ही रहती है। दूसरे गांवोंको अब बधाई देनेकी भी आवश्यकता नहीं रही। सबत्र एक ही हलचल चल रही है। सभी लोग अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार कर रहे हैं। यह कदम सही रहा है। इसमें अब ज्यादा हिम्मत करनेकी जरूरत नहीं। जो अंतिम कसौटीपर खरे उतरेंगे वे बधाईके पात्र होंगे।

अफवाहे

आये दिन तरह तरहकी अफवाहे उडा करती हैं। कोई कहता है मेमनोंने पजीयनपत्र ले लिये हैं, कोई कहता है कोकणी कायर हो गये हैं, फिर कोई कहता है कि प्रिटोरियामें

१ एनी बेसेंटी, (१८४७-१९३३) सुप्रसिद्ध थियोसफिस्ट, १९१७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी अध्यक्ष, ‘रिलीजस प्रॉब्लेम इन इंडिया’ (भारतकी धार्मिक समस्या) तथा अन्य पुस्तकोंकी लेखिका।

सूरती मुसलमानो और हिन्दुओमे काला टीका लगवानेकी हलचल हो रही है। कसौटीका समय जैसे जैसे नजदीक आयेगा, वैसे वैसे ये अफवाहे उडती ही रहेंगी। डरपोक अपने डरकी छूत दूसरेको लगा देते हैं।

बेहूदा धमकी

देखनेमे आता है कि हममे ऐसे भी भारतीय हैं जो अपने घरवालोसे नाराज होते हैं तो कहते हैं “यदि तू अमुक काम नहीं करेगा तो मैं पजीकृत हो जाऊँगा।” ऐसी धमकीपर हँसना और रोना दोनों आ सकते हैं। मेरे लिए यदि तुम कुछ न करोगे तो मैं गढेमे गिर पडूँगा। इसमे तुम्हारा क्या बिगडेगा सो समझमे नहीं आता। इसलिए जिन्हे ऐसी धमकी दी जाये वे उन शूरवीरो’से साफ कह दे कि गुलामीके कार्यालयका दरवाजा सदा ही खुला है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ कि जो अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं वे पजीकृत हो जाये। इससे सच्चे शत प्रतिशत सच्चे उतरेंगे। ‘ब्लूमफॉर्टीन फ्रेड’ नामक पत्रने सच कहा है कि ट्रान्सवालके जहरी कानूनके सामने कायर झुक जायेगे और मद खुले सिर जूझेगे। हमने जेल सम्बन्धी पुरस्कृत गीतमे देखा है कि “क्या हम चोर, चुगलखोर, ठग, बदमाश बनकर रहे?” मुझे अत्यंत ही खेदपूर्वक कहना पडता है कि वह समय आ रहा है जब कानूनकी शरण जानेवालोकी कतार यही मानी जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८७ पत्र डब्ल्यू० वी० हलस्टेनको

[जोहानिसबग]

सितम्बर १७, १९०७

सर विलियम वॉन हलस्टेन, ससद-सदस्य

पो० आ० बॉक्स ४६

जोहानिसबग

महोदय,

गत १४ तारीखको ब्रिटिश भारतीय सघके अवतनिक सहायक मन्त्रीने जो पत्र आपकी सेवामे भेजा था, उसके बारेमे आपके गत १६ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

मेरा सघ जिस समाजका प्रतिनिधि है उसको आपने यह सलाह देनेकी कृपा की है कि वह इस उपनिवेशके कानूनोंके पालन करनेमे सहायता करे। मैं इस सत्यकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभीतक इस समाजने वैसा ही किया है और तबतक वैसा ही बराबर करता रहेगा, जबतक कि ऐसे कानून उस समाजकी धार्मिक भावनाओको ठेस नहीं

पहुँचाते और उसका अकारण अपमान नहीं करते। एशियाई पजीयन अधिनियमके बारेमें ब्रिटिश भारतीयोंको मेरे सघने बेशक यह सलाह दी है कि वे उसके आगे न झुके, क्योंकि, मेरी नम्र रायमें, उनका प्रथम कृतव्य यह है कि वे उस उच्चतर धर्मके आगे सिर झुकाये जो मानव जातिको आत्मसम्मान और सच्चाई तथा गम्भीरतासे की हुई घोरणाओका आदर करनेका आदेश देता है। पजीयन अधिनियमको स्वीकार करनेसे, मेरी रायमें, भारतीयोंकी सारी मर्दानगी छिन जाती है और वे नास्तिक बनते हैं, और इस बुनियादी सवालकी ओर आपका ध्यान दिलानेके विचारसे ही १४ तारीखका पत्र आपकी सेवामें भेजा गया था। किसी जिम्मेदार ब्रिटिश भारतीयके लिए अँगुलियोंके निशान देनेसे बचनेके लिए समाजको जीवन मरणके सघषमें उतर पडने और समस्त सासारिक सम्पत्तिका त्याग कर देनेकी सलाह देना लडकपन होगा।

मेरे सघको उस धमकीका पूरा पता है, जिसका आपने अपने भाषणमें, जो इस पत्र-व्यवहारका विषय है, इस्तेमाल करना उचित समझा है और जिसे आपने अपने इस पत्रमें भी दुहराया है। लेकिन मैं यह कहनेके लिए क्षमा चाहता हूँ कि उस धमकीका उन लोगोपर कोई असर नहीं होगा जिन्होंने अपने-आपसे यह सत्य कभी नहीं छिपाया कि सरकार कानून पालन करानेकी शक्ति ही नहीं रखती बल्कि कह भी चुकी है कि वह पालन करायेगी। कानूनका इस तरह अमल कराना उसके लिए श्रेयस्कर होगा अथवा मेरे देशवासी यदि दड रहे तो अकारण कष्ट सहन करनेके कारण यह सारा श्रेय उन्हीको मिलेगा, यह ऐसा प्रश्न है जिसे भावी सततिके निणयके लिए बखूबी छोडा जा सकता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

मो० क० गांधी

अवैतनिक मन्त्री

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

१८८ तार गो० कृ० गोखलेको

[जोहानिसबग,
सितम्बर २१, १९०७ के पूर्व]

[सेवामे
गो० कृ० गोखले^१
कलकत्ता]

तारके^२ लिए ब्रिटिश भारतीय सघका धन्यवाद। बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रतिष्ठा, धर्म और गम्भीरतापूर्वक ली गई शपथको रखनेके लिए अतत्क लड़गे। जितनी सहानुभूति मिल सके सब चाहिए। सब दलोकी सवसम्मत स्वीकृति और सहायता मागते हैं। सघष अबाध प्रवेशका नहीं, बल्कि जो यहा रहने ओर आनेके अधिकारी हैं उनके आत्मसम्मानका है।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१८९ भीमकाय प्रार्थनापत्र^३

[जोहानिसबग
सितम्बर २१, १९०७ के पूर्व]

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर कर्ता ट्रान्सवालवासी भारतीय उस पत्रसे अपना पूरा मतभेद प्रकट करते हैं जो आपको प्रिटोरिया, पीटसबग, स्टैंडटन और मिडलबर्गके कुछ प्रमुख भारतीयोंकी ओरसे स्टैंगमैन एसेलेन और रूजकी पेटीने ३० अगस्त १९०७ को एशियाई कानून सशोधक विधेयक सख्या २ सन १९०७ के सम्बन्धमे भेजा है।

१ महान भारतीय राजनीतिज्ञ माननीय गोपाल कृष्ण गोखले (१८६६-१९१५) । देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७-१८ ।

२ देखिए ' भारतसे कुसुक ', पृष्ठ २४३ ४४ ।

३ हस्ताक्षरोंके लिए यह प्रार्थनापत्र हिन्दी, गुजराती, तमिल तथा अग्रेजीमें प्रसारित किया गया था ऐसा प्रतीत होता है । यह वस्तुतः १ नवम्बरको ४५५२ भारतीयोंके हस्ताक्षर करवानेके बाद दिया गया था, देखिए " पत्र उपनिवेश सचिवको ", पृष्ठ ३२० २१ ।

हम सादर निवेदन करते हैं कि जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका प्रतिकार केवल इस अधिनियमको पूरी तरह रद्द करनेसे ही हो सकता है, उससे कम किसी कार-वाईसे नहीं। हमारी विनीत सम्मतिमें अधिनियम हमारे आत्मसम्मानको गिराने तथा हमारे धर्मोपर प्रहार करनेवाला है और इसको खतरनाक मुजरिमोंके सम्बन्धमें ही लागू करनेका खयाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने जो गम्भीर शपथ ली है उसके कारण हमारे लिए, साम्राज्यके सच्चे नागरिकों और ईश्वरसे भय करनेवाले लोगोंके रूपमें, अधिनियमके विधानके सम्मुख न झुकना आवश्यक हो गया है, भले ही हमें इसके परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतने पड़े, और जो, हम समझते हैं, जेल, निर्वासन, और हमारी जायदादकी बरबादी या जप्ती या इनमें से कोई भी हो सकते हैं।

हमने यह ऊपरकी बात इसलिए नहीं कही है कि हम बड़े पैमानेपर ब्रिटिश भारतीयोंके गुप्त प्रवेशके आरोपोंकी जांच कराना नहीं चाहते, या उन कागजातोंको पास रखनेसे इनकार करते हैं जिनसे सरकारकी सम्मतिमें हमारी काफी शिंनारत हो सकती है।

इसलिए हम सादर प्रार्थना करते हैं कि सरकार कृपा करके ट्रांसवालके भारतीयोंको मनुष्याके रूपमें और इस स्वतंत्र एवं स्वशासित उपनिवेशके योग्य नागरिकोंके रूपमें मायता दे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,

उक्त प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर प्राप्त करनेके सम्बन्धमें निर्देश

- १ सब हस्ताक्षर स्याहीसे किये जायें।
- २ प्रत्येक कागजपर ५० व्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंकी जगह है। इसलिए प्रत्येक कागजपर ५० से अधिक व्यक्तियोंके हस्ताक्षर न लिये जायें।
- ३ हस्ताक्षर दो प्रतियोंपर लिये जायें।
- ४ पतेके खानेमें गलीकी और जहा सम्भव हो बाडेकी क्रम-सरया दे। जिस शहरमें हस्ताक्षर कराये जायें उसका नाम केवल एक बार दिया जा सकता है।
- ५ कागजको मैला न होने देनेकी बहुत सावधानी रखी जायें।
- ६ हस्ताक्षर यथासम्भव ऐसे किये जायें कि वे स्पष्ट पढ़े जा सकें। जो नाम अंग्रेजीमें न हों, उनको हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति नीचे अंग्रेजीमें लिख दे। जहा हस्ताक्षरकर्ता केवल गुणाका चिह्न लगायें वहा हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति उस गुणाके चिह्नकी साक्षी दे।
- ७ हस्ताक्षरकर्ताको प्रार्थनापत्र पढाये बिना, या यदि वह कोई भाषा न पढ़ सकता हो तो उसको पढ़कर सुनाये बिना, हस्ताक्षर कदापि न कराये जायें।
- ८ हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति कागजके नीचे अपने हस्ताक्षरोंके लिए खिंची हुई रेखापर हस्ताक्षर करे।
- ९ दोनों प्रतियां यथासम्भव शीघ्र मन्त्री, ब्रिटिश भारतीय सघ बॉक्स ६५२२, जोहानिसबर्गको भेज दी जायें।

- १० सब हस्ताक्षर अधिकसे अधिक ३० सितम्बर तक भेज दिये जाये।
- ११ लोगोपर कोई दबाव न डाला जाये और जो बिलकुल अततक अधिनियमको न माननेके निश्चयका पालन करनेके लिए तैयार न हो, उसको हस्ताक्षर करनेकी आवश्यकता नहीं है।
- १२ कागजोकी घड़ी बनाई न जाये, बल्कि वे पुलिन्दा बनाकर रखे जाये और पुलिन्देके रूपमें ही भजे भी जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९० भीमकाय प्रार्थनापत्र

ट्रांसवालके भारतीय सरकारको एक भीमकाय प्रार्थनापत्र देनेका आयोजन करनेके लिए बधाईके पात्र है। पिछले सप्ताह दुर्भाग्यसे हमें जो पत्र^१ उद्धृत करना पड़ा था, उसका यह पूरा जवाब है। प्रार्थियोंने हमेशाके लिए मुरय मुद्देको, जहातक सम्भव हो सका है, संक्षेपमें लिपिबद्ध कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कि तु आदरपूर्ण भाषामें स्थानीय सरकारको आगाह कर दिया है कि सिवा एशियाई पजीयन कानूनको वापस लेनेके किसी और तरह इस मुसीबतसे पार पा जाना सम्भव नहीं है। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि कानूनको वापस लेनेकी दरखास्तका यह मतलब नहीं है कि वे एशियाइयोंके चोरीसे भर आनेके इल्जामकी जाचसे डरते हैं। और न वे उन अनुमतिपत्रोंको, जो इस समय उनके पास ह, बदलनेसे इनकार ही करते हैं। इसलिए बुनियादी मुद्दा यह है कि भारतीय लोग साम्राज्यके आत्माभिमानी नागरिक स्वीकार किये जाये या नहीं। हमारे सहयोगी 'स्टार'ने अभी उस दिन भारतीयोंको ताना दिया था कि उन्होंने अपने इंग्लैंडके मित्रोंको आदोलनके सही मुद्देसे गुमराह कर दिया है, और उसने बताया था कि ब्रिटिश भारतीय सिर्फ अँगुलियोंके निशान देनेके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब 'स्टार'ने यह लिखा था लगभग तभी श्री रिचने, जो दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके अथक परिश्रम करनेवाले मंत्री हैं, इस बारेमें लकाशायर डेली पोस्ट' को एक पत्र लिखा था। उसमें से निम्नलिखित अंश हम यहां दे रहे हैं

बेशक यह सच है कि एशियाई पजीयन कानून यह चाहता है कि ब्रिटिश भारतीय और अय एशियाई शिनाख्तके लिए पजीयन कराये। और इस कानूनको लागू करनेकी शर्तमें दसो अँगुलियोंके निशानोंका देना भी शामिल है, जो एक ऐसी एह्तियात है जिसका सम्बन्ध पूर्ण रूपसे अपराधियोंसे है। लेकिन इस कानूनकी वजहसे ट्रांसवालके हमारे भारतीय साथियोंको जिस अपमानका बोझ उठाना पड़ता है उसे पूरी तरहसे समझनेके लिए यह जान लेना जरूरी है कि यह खास अपमान एक सयोगमात्र है और अगर हम उस बड़े सिद्धांतसे इसकी तुलना करें जिसके अनुसार साम्राज्यकी सभ्य प्रजा होनेके नाते ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीय समाजको सभ्य व्यवहार पानेका अधिकार है, तो यह इतनी महत्त्वकी नहीं प्रतीत होगी। और इस कारण भारतीय उन मौलिक

१ यह संकेत सर्वश्री स्टैग्मान, एसेलेन और रूज द्वारा लिखे गये पत्रकी ओर है। देखिए पिछला शीर्षक।

अधिकारोमे दस्तदाजी और उनके छिननेकी आशका होनेपर अपने शासकोसे उनकी रक्षाकी आशा रखते ह ।

भारतीयोका दावा इससे अविक स्पष्ट भाषामे पेश नहीं किया जा सकता ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन आपिनियन, २१-९-१९०७

१९१ वीनेन परवानेकी अपील

ऐसा कभी कभी ही होता है कि व्यापारिक परवाना अधिकारियो और परवाना निकायके निणयोसे हम सहमत हो सके, लेकिन हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री भायातका मामला^१ कठिन था तब भी परवाना अधिकारी और निकायका निणय सिद्धांत रूपमे निर्दोष था । परवाना अधिकारी श्री इग्रामने अपने निणयके पक्षमे पूरी और स्पष्ट दलीले दी थी और हमे भी उनके इस कथनपर विश्वास है कि अगर प्रजातिकी दृष्टिसे स्थिति इससे उलटी होती तो भी उनका निणय यही होता । उपनिवेशमे जिस पूर्वग्रहका बोलबाला है उसको देखते हुए हमारे देशवासियोको यह बात पक्की तरह समझ लेनी चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकामे नहीं तो कमसे-कम नेटालमे उनके लिए अबाध व्यापारकी सहूलियते मिलना असम्भव है । हमारी रायमें कमसे कम जिस सुविधाका आश्वासन दिया जा सकता है, और जिसपर किसी भी कीमतपर जोर देना चाहिए, वह यह है कि मौजूदा परवानोकी पवित्र वस्तुकी भांति हिफाजत की जाये, लेकिन नई अर्जियोके बारेमे, जसी कि हमारी समझमे श्री भायातकी अर्जी थी, यही कह सकते हैं कि स्थानीय लोकमत, परवानोके वितरण और माग तथा उसकी पूर्तिकी मात्रासे परवाना अधिकारीको बहुत कुछ मागदशन मिलना चाहिए । इसमे शक नहीं कि कानूनकी सहायताके बिना भी किसी जातिके लिए यह छूट है कि वह किसी भी वग या कितने ही व्यापारियो या दूसरोका, जिन्हे वह नहीं चाहती, बहिष्कार कर दे । लेकिन जब द्वेषकी आगको भडकानेके लिए कानूनकी मदद ली जाती है, तब बहिष्कार असहनीय हो जाता है और उस बुराईको दूर करनेके लिए और मजबूत हाथोकी जरूरत होती है । साथ ही, श्री भायातके जैसे मामले बिना सहानुभूति उत्पन्न किये नहीं रह सकते । यहा एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है, जिसका सब वर्गोंके लोग आदर करते हैं, जो एक लम्बे अर्सेसे योग्य व्यापारी रहा है, जिसने ब्रिटिश सरकारकी, उसी प्रदेशमे जिसमे वह व्यापारी-परवाना चाहते हैं, काफी मदद की है और ऐसी कोई नैतिक या आर्थिक बात नहीं है, जिसकी बिनापर उसकी अर्जी नामजूर कर दी जाये । लेकिन जहा विरोधी स्वाथ उठ खड़े होंगे और जहा निजी स्वाथको सामने रखकर कोई खास नीति अपनाई जायेगी, वहा ऐसे कठिन मामले हमेशा होते रहेंगे । इसलिए इसके शिकार होनेवाले लोगोके लिए यही दूरदर्शिता है कि वे वस्तुस्थितिको पहचाने और अपनी ताकतको इस तरह साधे कि अपने मौजूदा अधिकार और आत्मसम्मानके अपहरणका मुकाबला कर सके ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९२ ट्रान्सवालकी लडाई

इस बार हमने श्री रिच द्वारा भेजे गये पत्रोका अनुवाद दिया है। उसपर प्रत्येक पाठकको पूरा ध्यान देना चाहिए। विलायतके नये कानूनके सम्बन्धमें बहुत बड़ी लडाई चल रही है। इस लडाईकी जड़में केवल भारतीयोका साहस है। विलायतके मुख्य व्यक्तियोंको कुछ कुछ भरोसा होने लगा है कि भारतीय जो कुछ कह रहे हैं उसे करेगे भी। ऋण विधेयक (लोन बिल) के समय भारतीय सवालोकों लेकर जैसी चर्चा हुई वैसी चर्चा हमने कभी नहीं देखी। यदि हम कहें कि दोनों पक्षोंके अधिकारोंके सम्बन्धमें इतने जोशसे बोलनेका पिछले पचास वर्षोंमें यह पहला उदाहरण है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। श्री लिटिलटन अनुदार दलके नेता हैं। वे कभी उपनिवेश मंत्री थे। उन्होंने बहुत ही जोशसे हमारे हकोंका समर्थन किया था। सर चार्ल्स डिल्क सुविख्यात उदारदलीय सदस्य हैं। एक बार उनके प्रधान मंत्री बननेकी सम्भावना थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ी सरकारको बीचमें आना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री बोनरला, श्री काक्स, श्री ओ० ग्रेडी आदि सदस्योंने जो भाषण दिये वे सब हमें प्रोत्साहित करनेवाले हैं।

समाचारपत्रोंको देखा जाये तो 'लंदन टाइम्स', 'याकशायर पास्ट', 'आब्जर्वर', और 'पाल माल गजट' आदि समाचारपत्रोंने हमारे पक्षमें सरत लेख लिखे हैं। सर चार्ल्स ब्रूसने तो हृदय कर दी है। उन्होंने बड़ी सरकारको जबरदस्त तमाचा लगाया है।

भारतीय समाजने पजीयन कार्यालयका बहिष्कार किया है। उतने ही से यदि यह सब हुआ है तो जब भारतीय जुल्मी तरीकेसे जेल ले जाये जायेंगे तब क्या विलायत भरमें शोर न मच जायेगा? फिर, सर हेनरीके उत्तरपर विचार करे तो भी स्पष्ट है कि उन्होंने बीचमें पड़नेसे इनकार नहीं किया है, बल्कि इतना कहा है कि फिलहाल वैसा समय नहीं आया है। इसका अर्थ यही होगा कि भारतीय समाज यदि आखिरतक जोर कायम रखकर जेल या निर्वासनका कष्ट सहन करेगा, तो बड़ी सरकार चुप नहीं बैठेगी। इन लक्षणोंसे भी, जिन्हें सरसरी तोरसे देखनेवाला व्यक्ति भी देख सकता है, यदि हम न समझे और हिम्मत न रखें तो हमारी जितनी बेइज्जती की जाये उतनी कम है। इसीके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि हम इस लडाईको अब छोड़ देंगे तो जो शक्ति हमारे पक्षमें लगाई जा रही है वही शक्ति हमारे विरोधमें लगाई जायेगी। हमें इसमें खुदाका हाथ दिखाई दे रहा है। खुदा सदैव मनुष्य अथवा अय साधनोंके द्वारा ही मदद करता है। अतः भारतीयों जागते रहो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९३ नेटालका परवाना कानून

वीनेनमे श्री भायातने परवाना निकायके सम्मुख परवानेके लिए अपील^१ की थी। खेद है कि उसमे वे हार गये। श्री भायातका मुकदमा बड़ा मजबूत था। वे वसीलेवाले व्यापारी हैं। लडाईमे उन्होंने सरकारको सहायता दी थी। उनके पास दोलत है। ऐसे व्यक्तिको, यह हो ही नहीं सकता कि किसी भी कानूनके अतगत, परवाना न मिले।

फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि परवाना निकायका निणय वतमान परिस्थितिको देखते हुए अयायी नहीं माना जा सकता। हम लोगोको इतना याद रखना जरूरी है कि नेटाल अथवा दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाज बिलकुल स्वतंत्रतासे व्यापार नहीं कर सकता। परवाना-अधिकारी आसपासके लोगोकी मनोदशाको और व्यापारियोकी सस्याको देखकर भारतीय व्यापारीको परवाना दे अथवा न दे, वतमान स्थितिमे इसका विरोध करना निरर्थक है। समझदार मनुष्यका काम यह है कि परिस्थितिपर विचार करके कदम उठाये, और अपने आसपास जो घटनाएँ घटे उनका खयाल रखे। भारतीय समाजपर बहुतेरी आफते टूट रही हैं। उनमे से किसको अधिक महत्त्व दिया जाये यह पहले ही निश्चित कर लेनेकी बात है। हमारे लिए इस समय मुरय आवश्यकता प्रतिष्ठा की है। वह मिलेगी, तो ओर सब आसानीसे मिल जायेगा। प्रतिष्ठाकी रक्षा करते हुए जिन अधिकारोका इस समय हम उपभोग कर रहे हैं उन्हें हमें बनाये रखना चाहिए। इसलिए इस समय जो परवाने वापस लिए गये हैं उनपर डटे रहे, ओर अन्य हानि सहन करके एव जेलमे जाकर भी मौजूदा परवानोको कायम रखे। यदि भारतीय समाज इतना प्रयास करेगा, तो हमें भरोसा है कि नये परवानोका माग अपने आप निकल आयेगा। जबतक हमें कायर समझा जाता है, हमारी निश्चित राय है कि हमारे अय प्रयत्नोका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि नये परवाने मिलेंगे ही नहीं। जहा परवाना अधिकारी दयालु होंगे, अथवा जहा गोरे खिलाफ न होंगे वहा नि सदेह नये परवाने मिलते रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि मित्रता या प्रीति वहा नहीं हो सकती जहा एक पक्ष दूसरेको नीचा समझता है। इसलिए पहला प्रयत्न यह करना होगा कि अपनी प्रतिष्ठाको बनाये रखकर हम मद बने।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९४ भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय

श्री शेलतने कुछ दिनों तक बड़े मनोयोगके साथ पुस्तकालयकी देखरेख की और अब दूसरी जगह जानेके कारण इस्तीफा दिया है। उनकी जगहकी पूर्ति श्री तार मुहम्मद सुमारने की है, और श्री जूसब उस्मानने उनकी सहायता करना स्वीकार किया है। हम इन दोनोंको बधाई देते हैं। समाजसे बिना कुछ लिए सामाजिक काम करनेवाले बहुतसे लोग सामने आने चाहिए। यह हमारी कमजोरीका लक्षण है कि हमें यह खयाल बना रहता है कि अमुक व्यक्तिके चले जानेके बाद काम किस तरहसे चलाया जा सकेगा। श्रम करने और नियमित रहनेकी दृष्टिसे श्री दीवानकी जगह भरना बहुत कठिन बात है, फिर भी हम आशा करते हैं कि श्री तार मुहम्मद तथा श्री जूसब उस्मानने जो काम लिया है, उसे वे पूरे मनो योगके साथ करेंगे।

पुस्तकालय शिक्षणका एक प्रतीक है। यह सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि उससे बहुत लाभ होता है, इसलिए इस पुस्तकालयको चलाते रहना हरएक भारतीयका कतव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९५ भारतसे कुमुक

माननीय प्रोफेसर गोखलेका समुद्री तार

माननीय प्रोफेसर गोखलेका नीचे लिखा समुद्री तार जोहानिसबग ब्रिटिश भारतीय सघके नाम आया, सो हमें प्रकाशनाथ प्राप्त हुआ है

आपकी लडाईं मैं सतत देखता रहता हूँ। चिंतातुर होकर मन उधर ही लगा रहता है। अत्यंत सहानुभूति है। लडाईंकी तारीफ करता हूँ। दढ़ मनसे खुदाकी मर्जीपर भरोसा रखना।

माननीय प्रोफेसर गोखलेको हर भारतीय देशभक्त जानता है। वे भारतके केन्द्रीय विधान-मण्डलके सदस्य हैं। उनके तारसे प्रत्येक भारतीयको लाख गुना और जोश आना चाहिए। प्रोफेसर गोखलेने तार भेजा है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब सारे भारतमें रग जमेगा और भारत पूर्ण रूपसे मदद करेगा।

तारका उत्तर

तार मिलते ही ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठक बुलाई गई। उसमें श्री ईसप मिया, श्री कुवाडिया, श्री अहमद मूसाजी, श्री फैसी, श्री उमरजी साले, इमाम अब्दुल कादिर,

श्री मुहम्मद आदमजी, श्री अली उमर, श्री अहमद हलीम, श्री कासिम मूसा, श्री अलीभाई आकुजी, श्री शाह, श्री मूसाजी अहमद, श्री दाऊद इस्माइल, श्री अहमद ईसे, श्री इस्माइल सुलेमान, श्री डाह्या रामा, श्री कामा और श्री मोमण्यात उपस्थित थे। प्रोफेसर गोखलेको निम्न तार^१ भेजनेका प्रस्ताव सबसम्मतिसे स्वीकार किया गया

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९६ अंगूठा निशानीका कानून

इसमे ओर ट्रासवालके कायदेमे हाथी और घोडे जैसा अंतर हे।^१

सम्पादक

इंडियन ओपिनियन

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१ यहाँ तार गो० कृ० गोखलेको का अनुवाद दिया गया है देखिए पृष्ठ २३७।

२ गांधीजीने यह वाक्य गुजराती सा ध्य दैनिक समाचारपत्र साक्ष वर्तमानसे निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करते हुए लिखा था

बम्बईमें अंगूठा निशानी

‘बम्बई गजट’ के पाठकोक विचार स्तम्भमें एक शिकायत की गई थी और वह हमने अपने पत्रमें उद्धृत की थी। शिकायत यह थी कि उच्च न्यायालयके पजीयन विभागको लक्ष्यमें रखकर एक कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार सब गैर यूरोपीयोंको अंगूठेकी निशानी देना आवश्यक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिकायत निराधार है। यह कानूनकी उस प्रतिसे प्रकट हो जाता है जिसे सरकारने व्यवस्थापिका परिषद्में श्री ओ० पी० दीक्षितके प्रश्न करनेपर अवलोकनार्थ भेजकर रखा है। इस कानूनके अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति किसी किसके दस्तावेजको इस विभागमें पजीयत कराना चाहता है तो उसे उस दस्तावेजपर सीधे हाथके अंगूठेकी निशानी लगानी होगी और अंगूठा निशानीकी सरकारी पत्रिकाओं में भी निशानी देनी होगी। इस सम्बन्धमें निम्न नियम बनाये गये हैं

(१) दस्तावेजको पजीयत करानेवाला व्यक्ति शिक्षित और पजीयकका परिचित व्यक्ति हो तो उसकी अंगूठा निशानी नही ली जायेगी।

(२) जो दस्तावेजका पजीयन कराये वह कोई यूरोपीय महिला हो या कोई ऐसा सज्जन या सम्मानित व्यक्ति हो जिसकी शिनाख्तके बारेमें कोई शक न हो सके तो अंगूठा निशानीकी आवश्यकता न होगी।

(३) जिन व्यक्तियोंके दायें हाथके अंगूठेका उपयोग किसी कारण नहीं हो सकता उनको बायें हाथके अंगूठेकी या वह सम्भव न हो तो किसी अंगुलीकी ही निशानी देनी होगी।

(४) यह निशानी पजीयकके सामने ली जायेगी।

१९७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

कूगसडॉप और जीरस्टने दूसरे शहरोंके समान ही कर दिखाया है। मैं कहना चाहता था कि उन्होंने भी वसी ही बहादुरी बताई है। लेकिन यदि बहादुरी शब्दका प्रयोग हम बहिष्कारके लिए करेंगे तो जब सच्चे बहिष्कारका समय आयेगा तब कौन-सा शब्द काममें लायेगे? हम सब जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक गावमें गुलामीका टोका नहीं लगवाता तो दूसरे किसी गावमें लगवा सकता है। काला टोका किसीको भी प्यारा नहीं लग सकता। इसलिए सब राह देखते बैठ सकते हैं कि देखे, जोहानिसबर्ग क्या करता है। इस तरहकी प्रतीक्षामें यदि अधिकांश लोग बैठें होंगे तो हमारे पापका घड़ा अवश्य फूट जायेगा और उसके नीचे भारतीय कुचल जायेगा। जोहानिसबर्ग चाहे कुछ भी करे लेकिन जो आजतक हिम्मत रखकर बैठे ह, वे आखिरतक बैठे रहेंगे तभी ठीक होगा। इसलिए कूगसडॉप और जीरस्ट यद्यपि अपनी दड़ताके लिए अन्वयादके पात्र हैं, फिर भी उनकी और सबकी सच्ची कसौटी अब होनेवाली है।

बाकी कौन रहा?

बॉक्सबर्गमें कार्यालय १७, १८, १९ और २० को रहेगा। जर्मिस्टनमें २४, २५, २६ और २७ को तथा बेनोनीमें १७, १८, १९ और २० को। इन जगहोंपर सरकारकी कृपा मालूम होती है। क्योंकि, हर जगह भारतीयोंको गुलामीका पट्टा लेनेके लिए चार दिन मिलेंगे। लेकिन इन स्थानोंके भारतीय सचेत ह। इसलिए ऐसा नहीं मालूम होता कि उनमें से कोई अन्यायी पट्टे लेने जायेगा। बॉक्सबर्ग और जर्मिस्टनमें सभाएँ भी की जा चुकी हैं और सभीने हाथ काला करनेका विरोध किया है। इसलिए अधिकारियोंकी “छुट्टीमें” अब भी खलल पड़ना सम्भव नहीं दीखता।

क्या हवा बदली है?

आजतक हर जगह श्री चैमने श्री जेम्स कोडी श्री रिचर्ड कोडी तथा श्री स्वीट हवा खाने गये थे। अब चौकड़ी बदली है। ब्लूमहॉफ, वुलमरनस्टाड, लिखतनबर्ग, पीट रिट्फि, अरमीलो, करोलीना, और बेथलमें ये लोग नहीं जायेंगे। वहाके लिए दूसरे साहब नियुक्त हुए हैं। हर जगह १७, १८ व १९ तारीखको नये अधिकारी हाजिर रहेंगे। ब्लूमहाफमें श्री हल, वुलमरनस्टाडमें श्री हॉग, लिखतनबर्गमें श्री ज्यूटा पीट रिट्फिमें श्री लेवी, अरमीलोमें श्री केरसवील कैरोलीनामें श्री जॉन और बेथलमें श्री बैंगले नियुक्त किये गये हैं। यह क्यों किया गया, इस सम्बन्धमें मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता। स्पष्ट कारण तो यह मालूम होता है कि वहा भारतीयोंकी सरया ज्यादा नहीं है। दूसरे, ये जगहें अलग अलग हैं और यदि उपर्युक्त चौकड़ीको सब जगह घुमाया जाये तो जोहानिसबर्गपर अक्तूबर महीनेमें धावा नहीं किया जा सकता।

जोहानिसबर्ग पकड़मे आया

जोहानिसबर्गपर १ अक्टूबरको चढाई होगी। यहा त्रिमूर्तिको नियुक्त किया गया है। दो तो कोडी है और तीसरे स्वीट साहब। इसलिए जो जोहानिसबर्ग आजतक शेखी मारता आया है, उसकी परीक्षाका समय नजदीक आ गया है। श्री गांधीने प्रिटोरियामे शेखी मारी थी कि कार्यालय पहले जोहानिसबर्गमे आया होता तो ठीक होता।^१ श्री ईसप मिया और श्री कुवाडियाने भी ऐसा ही कहा था। इसके अलावा श्री ईसप मियाने तो श्री रूसको एक जोरदार पत्र भी लिखा है कि “नेताओ” की ओरसे श्री रूसने जो बेहदा पत्र लिखा है उससे सघका और खासकर जोहानिसबर्गका कुछ भी सम्भव नहीं है। जोहानिसबर्ग सघका के द्रीय स्थान है। वहाके भारतीयोने काननके विरोधमे बहुत-कुछ कहा है। वही एम्पायर और गेटी नाटकघरोमे दो सभाएँ हुई है।^२ इतना सब होनेके बाद भी क्या जोहानिसबर्ग हार जायेगा? लेकिन अभी तो बडी देर है। एक पूरा महीना सामने है। प्रिटोरियामे अन्तिम दिनोंमे ही लोग फिसले थे। इसलिए जोहानिसबर्गमे अक्टूबरके तीन सप्ताह तो आसानीसे निकल जाना सम्भव है। लेकिन यदि अन्तिम सप्ताह भी ऐसा ही निकल जाये और एक भी भारतीय पजीयन कार्यालयका नाम न ले तो? इसका जवाब देना जरा मुश्किल है। भैस अभी तो जगलमे ही है तब इधर सौदेकी बात कसी? लेकिन मैं इतना अनुमान तो कर सकता हूँ कि यदि जोहानिसबर्ग पूण बहिष्कार कर सका तो सरकारको कुछ तो विश्वास हो ही जायेगा कि हम आखिरी दम तक लडाई चालू रखना चाहते हैं। हमे यह अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए कि यह लडाई हमारी सचाई साबित करनेके लिए है। आज सरकार या किसीको भी यह विश्वास नहीं है कि हम सच्ची हिम्मतसे लड़ रहे हैं। और जबतक हमारे बीच श्री शेख अहमद इशाक जैसे दोनो ओर ढोल बजानेवाले मौजूद हैं, तबतक विश्वास कैसे हो सकता है?

पीटर्सबर्गके ‘बहादुर’

श्री शेख मुहम्मद इशाककी बात करते समय ही मुझे दूसरी खबर मिली है। वह भी मैं पाठकोके सामने रखता हूँ। पीटर्सबर्गसे जिन चार ‘बहादुर’ भारतीयोने गुलामीका पट्टा ले लिया है उसके नाम हैं।^३ वहीसे ८६ भारतीयोके हस्ताक्षरोके साथ जो अर्जी भेजी गई थी, मालूम हुआ है, उसपर भी इन चारो महाशयोने हस्ताक्षर किये थे। जबतक यह होता रहे तबतक सरकार किस भारतीयका विश्वास कर सकती है? हम अर्जीमे जो कुछ लिखते हैं उसे सच्चा कैसे माना जा सकता है? यह भी सुननेमे आया है कि इन महाशयोसे कुछ हलफनामे भी लिये गये हैं। इस तरहकी गप्पे तो बहुतसी हैं। कोई कहता है कि उन्होने यह लिखवाया है कि उहे श्री गांधीने रोका था, इसलिए उन्होने गुलामीकी अर्जी नहीं भेजी। कोई कहता है कि उन्होने अपने समाजकी शमके मारे अर्जी नहीं दी। यदि यह सच है तो इन हलफनामे देने-वालोको सोचना चाहिए कि क्या उस डर और शमको वे अब नहीं महसूस करते? इस सबके बावजूद डरपोक विरोधी दलमे भी जा घुसे तो उससे कुछ नहीं बिगडेगा। यह लडाई ऐसी है कि इसके द्वारा डरपोक बहादुरसे अलग दिखने लगेंगे। इसके अलावा यह भी मालूम हो

१ देखिए “भाषण प्रिटोरियामे”, पृष्ठ १३९-४१।

२ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४११-२३।

३ यहाँ मूलमें चार नाम हैं।

जायेगा कि हमे वास्तवमे कौनसा रोग है? आजतक जिस तापमापक यंत्रसे गर्मी नापी जाती थी उससे गर्मीका ठीक पता नही चलता था। जेलरूपी तापमापक लगनेसे सबके तापमानका पता चल जायेगा।

इन सब नामोको देते और टीका करते हुए मुझे बहुत दुःख होता है। क्योंकि मेरे भाइयोकी शम मेरी शम है। मेरे भाई यदि चोरी करते ह तो उसका कलक मुझे लगेगा ही। हमारे ही भाइयोकी गलतीसे हमे सारे दक्षिण आफ्रिकामे कष्ट भोगना पड रहा है। कुछ भारतीय गदे रहते ह, उससे सबको दुःख उठाना पडता है। कुछ कजूस ह, तो उसका दाप भी सबपर आता है। कुछ चोरीसे प्रवेश करते ह, इसलिए नया कानून बना है, और उसका परिणाम हम सबको भोगना पड रहा है। यह अवसर इतना गम्भीर है कि इस समय अपने दोषोको छिपानेमे पाप है। हममे जो सडाध हो वह जब ऊपर आ जायेगी तभी हम ठिकाने लगेगे। हमारी चाशनी पक रही है। उसमे गदगी ऊपर आनी ही चाहिए। यदि गन्दगीको हम दबा देगे तो उबल जानेके बाद सारी चाशनी बिगड जायेगी। इसलिए मेरे नाम प्रकाशित करनेसे यदि किसीको गुस्सा आये तो मै उसके लिए माफी मागता हूँ। मुझे अपना यह कतव्य तो निभाना ही पडेगा।

पीटसबर्गके चार साहव गुलामीके पट्टे लेनेको टूट पडे तो मेफेकिगके श्री कासिम हाजी तारको लगा कि वे रह गये। अब वे भी पिघल गये हैं। तब फिर डबनके लजारस (तमिल) और जोजफ (तमिल)की तो बात ही क्या? ये दोनो तमिल भाई भी पजीयनका कलक लगवा चुके हैं।

पजीयन कार्यालयकी बेचैनी

भारतीय लोग गुलामीका थोडा बहुत दाग लगवा लेते हैं, इसलिए पजीयन कार्यालय बेचैन हो रहा है। बारबटनमे एक भारतीयके पास एक भूतपूर्व अधिकारीका दिया हुआ झूठा अनुमतिपत्र था। उससे वह पकडा गया। वह छ महीनेकी जेल काट रहा है। बारबटनसे कोरा न जाना पडे इसलिए उस जेलवासीसे अर्जी ली गई है। हम पूछ सकते हैं कि ऐसे व्यक्तिसे अर्जी लेनेके पीछे क्या हेतु होगा? जिसके पास अनुमतिपत्र नही है, जिसे रखनेका हक नही है, क्या ऐसे व्यक्तिकी अर्जी लेकर उसका पजीयन किया जायेगा? या फिर 'ब्लूमफॉटिनके मित्र' ['द फ्रेड ऑफ ब्लूमफॉटिन'] के कहे अनुसार सरकार जेलवासी भारतीयोको ट्रासवालमे रखकर, हकदार और पुराने निवासियोको निकाल देना चाहती है? देखना है कि ट्रासवालकी सरकार हकदारके हकोको कैसे डुबाती है।

अँगुलियोकी निशानीका नया कानून

इस बारके 'गजट'मे इस आशयका कानून प्रकाशित किया गया है कि जिस व्यक्तिको जेलमे रखा गया हो, वह यदि गवाही दे या दीवानी मामलेके सिलसिलेमे सजा न भोग रहा हो तो, अधिकारी अपनी मर्जीके मुताबिक उसका फोटो, उसकी अँगुलियोकी निशानी, और उसका नाम वगैरह ले सकते हैं। इस सम्बन्धमे यहाके 'यायालयमे' इस तरहका एक मुकदमा चल चुका है और उसीपर से यह कानून बनाया गया है। इससे भारतीयोका विशेष सम्बन्ध नही है। लेकिन इससे मालूम होता है कि ऐसा कानून फोजदारी अपराधोपर लागू किया जा सकता है।

क्या स्त्रियोंके अँगूठे लिये जा सकते हैं ?

फोक्सरस्टसे श्री मूसा इबाहीम मसूर लिखते हैं कि एक भारतीय स्त्रीसे पुलिसने अनुमतिपा मागा। वह उसने दिखा दिया। फिर उससे अँगूठेकी निशानी मागी गई। वह भी उसी अपने सेठके हुक्मसे दे दी। उस स्त्रीने अनुमतिपत्र कहासे दिया, यह समझमे नहीं आया। स्त्रियोंकी अँगूठा निशानी लेनेका पुलिसको बिल्कुल अधिकार न था। पूनियाके मामलेमें^१ निणय हो चुका है कि स्त्रियोंको अनुमतिपत्रकी जरूरत नहीं है। इस सम्बन्धमे दूसरी कार-वाई करनेकी आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन जहा इस प्रकार होता हो वहा चेतावनी देना ठीक है।

नुकसान कैसे सहन हो ?

मुझसे कहा गया है कि नये कानूनकी लड़ाईमे जो नुकसान होगा वह किस प्रकार सहन किया जाये, इस सवालका मैं जवाब दूँ। पहले तो जिसे हम नुकसान मानते हैं वह नुकसान नहीं, बल्कि फायदा है। हम सौ रुपयेकी गाडी लेते हैं तो उसे नुकसान नहीं मानते, बल्कि यह कहते हैं कि हमने अपने पैसेके बदलेमे यह चीज मिली है। उसी प्रकार हमने अपने पैसे देकर अपने हक खरीदने हैं। जिसे यह विश्वास हो कि ये हक मिलेंगे ही, वह पैसे देनेमे हिचकेगा नहीं। क्योंकि उसे अपने पैसेका बदला मिलनेका भरोसा है। यह ठीक है कि किसी-किसीको यह भरोसा नहीं होगा कि उसे हक मिलेंगे ही। किंतु फिलहाल तो ऐसे व्यक्ति भी पैसे छोड़ेंगे ही, और सो भी हकीकी आशामे ही। हम व्यापारमे सदा ही ऐसी जोखिम उठाते हैं। सट्टेमे हार जाते हैं, तो उससे व्यापार बंद नहीं कर देते। इस कुजीको याद रखकर यदि हम लड़ाईमे शामिल होंगे तो नुकसानकी बात नहीं करेंगे। महत्त्वकी बात यह है कि हककी लड़ाई समाजके लिए है, लेकिन सुकुचित मनके कारण हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि समाजका फायदा हमारा फायदा है। इसके अलावा और भी विचार करें तो देखेंगे कि जेमिसनके हमलेके^२ समय भारतीय अपने पैसे खो बैठे थे, और वैसा ही लड़ाईके^३ समय हुआ था। किंतु वह लाचारीके कारण हुआ था, इसलिए किसीने विचार नहीं किया। तब क्या अब पैसेकी जोखिमके कारण समाजके भलेकी लड़ाई हम छोड़ दें ?

अखबार पढ़कर क्या करें ?

इस सवालका जवाब देनेके लिए भी मुझसे कहा गया है। मेरी रायमे तो 'ओपिनियन' इस समय इतना महत्त्वपूर्ण है कि हरएकको उसकी फाइल रखनी चाहिए। लेकिन जिहे फाइल रखनेका शौक न हो, या जिहे आलस्य आता हो, ऐसे लोगोंको अखबार पढ़कर तुरन्त ही अपने सगे-सम्बन्धियोंको भेज देना चाहिए। यह आवश्यक है। क्योंकि भारतमे हमारी वास्तविक स्थिति जाहिर करनेका यही सरल और सस्ता उपाय है।

हलफनामा कैसा होता है ?

जो बहादुर 'पियानो बजाने' [अँगुलियोंकी छाप देने] के लिए पजीयन कार्यालयमे प्रिटोरिया जाते हैं उनसे हलफनामे लिये जाते हैं। उन हलफनामोका सारांश मेरे हाथ

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६३-६४ और खण्ड ६ पृष्ठ १२६।

२ दिसम्बर १८९५ में, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१८।

३ १८९९-१९०२ का बोअर युद्ध, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३७३।

लगा है। उसमें निम्नलिखित शब्द होते हैं “श्री गांधीके सिखानेसे, और एशियाइयोंने पजीयनपत्र नहीं लिये इससे, मैं जुलाई महीनेमें नये पजीयनपत्र लेने नहीं आया। क्योंकि मुझे डर लगता था। अब मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे पजीयित कीजिए।” इस प्रकारके कागजपर सही करनेकी किसी भारतीयकी कैसे हिम्मत हुई, समझमें नहीं आता। इससे पजीयन कार्यालयको क्या फायदा होता है सो भी मालूम नहीं होता। चाहे जो हो, लेकिन क्या अब वह डर मिट गया है? श्री गांधीकी सीख तो आज भी वैसी ही है, ओर उनका कहना है कि आखिरी दम तक वैसी ही रहेगी। भारतीय समाजका विचार भी अभी अटल है। लेकिन जिसे गुलामीका पट्टा लेना है उससे दलील किस प्रकार की जाये?

भीमकाय प्रार्थनापत्र

भीमकाय प्रार्थनापत्रकी^१ नकल और सूचना इसके साथ भेज रहा हूँ। इसके अनुसार अर्जी तेजीसे तैयार होनी चाहिए, जिससे ऊपर बताये हुए हलफनामे जादि खत्म हो जाये। जिसे सही करनेके लिए अर्जी न मिले वह मन्त्रीसे लिखकर माँगवाले। यहा मुझे जो एक उदाहरण याद आ रहा है, वह देता हूँ। सन १८९४ में जब मताधिकार विधेयक नेटालमें लागू किया गया था तब १०,००० भारतीयोंके हस्ताक्षरयुक्त एक अर्जी लाड रिपनको भेजी गई थी^२ और तब वह विधेयक रद्द किया गया था। इस बातको याद रखे। दूसरी बात यह कि तब अर्जीपर हस्ताक्षर लेनेके लिए सब बड़े बड़े लोग निकल पड़े थे, ओर पन्द्रह दिनमें सारे हस्ताक्षर हो गये थे। किंतु जब यह मालूम हुआ कि उसकी दा प्रतिया चाहिए तो बीस स्वयंसेवकोंने बैठकर रातोंरात नकल तैयार की थी। नेटालकी लडाई उस लडाईके सामने कुछ नहीं है। इस अर्जीमें हस्ताक्षर कर्वानेके लिए निश्चय ही बहुत समर्थ व्यक्तियों और स्वयंसेवकोंकी जरूरत है। अर्जीपर हस्ताक्षर लेकर ३० के पहले उसे पहुँच जाना चाहिए। मुझे तभी लाभ दिखाई देता है। आशा है कि कमसे-कम १०,००० भारतीयोंके हस्ताक्षर हो जायेंगे।

माननीय प्रोफेसर गोखलेके तारके सम्बन्धमें सघकी बैठक हुई थी। उसमें यह प्रस्ताव भी हुआ था कि अर्जी सब जगह भेजी जाये। श्री कुवाडिया, श्री कामा, श्री फैन्सी, इमाम अब्दुल कादिर और श्री शाहने अध्यक्ष महोदयके बाद भाषण दिये थे।

एक प्रसिद्ध अंग्रेज बहनका पत्र

नीति सुधारक मण्डलकी एक प्रसिद्ध बहन^३ विलायतसे लिखती है

२७ जुलाईका ‘इंडियन ओपिनियन’ मैंने अभी पढा। अब तो मुझसे आपको सहानुभूतिका पत्र लिखे बिना नहीं रहा जा सकता। जब-जब मैंने अखबार पढा है, मेरा मन भर आया है। मैं आपकी लडाईको जबरदस्त और पवित्र मानती हूँ। और जिस ढंगसे आप लिखते, बोलते और चलते हैं उससे मुझे पूरी हमदर्दी है। जिस हिम्मतसे आप लोग वहा आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ।

१ देखिए “भीमकाय प्रार्थनापत्र” पृष्ठ २३९-४०।

२ देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-२८।

३ फ्लोरेंस विंटरबोर्डम।

छूटे हुए स्वयंसेवक

श्री मुहम्मद इस्माइल कानमिया लिखते हैं कि हमीदिया अजुमनमे उन्होंने अपना नाम दिया था लेकिन फिर भी वह 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित नहीं हुआ। इसमें वे दुखी हैं। वह नाम क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, इसका कारण तो सम्पादक और रिपोर्ट भेजनेवाले भाड़ जाने। कामकी भौडमें जब सब व्यस्त हो, और ऐसा कोई नाम छूट जाये तो उसे दरगुजर करना चाहिए। लेकिन श्री मुहम्मद इस्माइलको उनके उत्साहके लिए शाबाशी देनी चाहिए। मुझे आशा है कि ऐसा ही जोश दूसरे भी रखेंगे। जोशकी कीमत काम करते समय होगी, इस बातको सभी भारतीय याद रखें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९८ पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको

जोहानिसबग

सितम्बर २१, १९०७

निजी सचिव

परममाननीय प्रधानमन्त्री

प्रिटोरिया

महोदय

मेरे सचकी समितिकी यह इच्छा है कि मैं प्रधानमन्त्रीका ध्यान समाचारपत्रोंमें प्रकाशित निम्नलिखित समाचारकी ओर आकर्षित करूँ—

उन्होंने खेत प्रकट किया कि एशियाई अँगुलियोंका निशान देने जसी तुच्छ बातका बहाना करके पजीयनका विरोध कर रहे हैं। यह गोरे लोगोंके लिए लागू किया गया था और मैं नहीं समझता कि इस नियमसे किसी को भी कष्ट होगा।

अगर यह रिपोर्ट ठीक है तो मैं परममाननीय महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेकी धष्टता करता हूँ कि पजीयन अधिनियमके विरोधका मुख्य कारण अँगुलियोंके निशान कभी नहीं रहे हैं। यद्यपि इस अधिनियमके बारेमें बहुतसे एतराजोंमें यह भी निःसन्देह एक गम्भीर बात है, फिर भी मेरा सघ इस बातको खुले दिलसे मजूर करता है कि अपने आपमें अकेली यही बात उस बड़े भारी असतोषका उचित कारण कदापि नहीं हो सकती, जिसे इस अधिनियमने जन्म दिया है। जिन कारणोंसे आपत्तियाँ की जाती हैं, उन्हें मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ

१ यह महामहिमके प्रतिनिधियोंकी पिछली घोषणाओंके स्पष्ट रूपसे विरुद्ध है।

२ यह ब्रिटिश एशियाइयों तथा अन्य एशियाइयोंके बीच कोई भेद स्वीकार नहीं करता।

- ३ यह ब्रिटिश भारतीयोंका दर्जा दक्षिण आफ्रिकाकी वतनी और रगदार जातियोंसे भी नीचा कर देता है।
- ४ यह ट्रांसवालके भारतीयोंकी स्थिति, जैसी १८८५ के कानून ३ के अंतर्गत बोअर शासन कालमें थी, उससे भी बुरी कर देता है।
- ५ यह परवानों तथा जासूसीकी एक ऐसी प्रणाली चलाता है, जिसका अस्तित्व और किसी भी ब्रिटिश इलाकेमें नहीं है।
- ६ जिन जातियोंपर इसे लागू किया गया है, उनको यह अपराधी अथवा सदिग्ध करार दे देता है।
- ७ भारतीयोंके तथाकथित अनधिकार प्रवाससे इनकार किया जाता है।
- ८ यदि ऐसे इनकारको स्वीकार नहीं किया जाता तो इस दमनकारी तथा अनावश्यक विधानको अमलमें लानेसे पहले ब्रिटिशों द्वारा इसकी अदालती और खुली जांच होनी चाहिए।
- ९ अय प्रकारसे भी यह विधान ब्रिटिश परम्पराके विरुद्ध है और निर्दोष ब्रिटिश प्रजाजनोकी स्वतंत्रतापर अनावश्यक पाबंदी लगाता है और ट्रांसवालके भारतीयोंको अनिवाय रूपसे देश छोड़कर चले जानेका निमन्त्रण देता है।

इस तरह यह ध्यान देनेकी बात है कि इस कानूनको जब पिछले वर्ष पहले पहल पेश किया गया था तब उसपर मुख्य आपत्तियोंमें जँगुलियोंके निशानोंका जिक्र तक नहीं था। मेरी नज़र रायमें इस अधिनियममें शुरूसे आखिरतक अपराधीपनकी बू आती है और इसके सामने सिर झुका देनेसे ट्रांसवालके भारतीयोंका जीवन असहनीय बन जायेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
ईसप इस्माइल मिया
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

१९९ पत्र जे० ए० नेसरको

[जोहानिसबग
सितम्बर १४, १९०७]

[श्री जे० ए० नेसर, ससद-सदस्य
पो० आ० बाक्स २२
क्लाक्सडाप]

प्रिय महोदय,

खबर हे कि आपने एशियाई अधिनियमके बारेमे नीचे लिखे विचार प्रकट किये हैं

एशियाइयोके बारेमे यह कानून बहुत जरूरी हे। अंगुलियोके निशान लेनेके बारेमे भारतीयोके एतराजोको म समझ नही सकता, क्योंकि उसमे कुछ भी पतनकारी नही है। इसका म एक ही कारण समझ सकता हूँ कि भारतीय अपनी बिरादरीके उन लोगोको बचाना चाहते ह, जो गरकालूनी ढंगसे द्रासवालमे आये ह और अब भी आ रहे ह।

मेरे सघको खेद हे कि आपने एशियाई अधिनियमपर भारतीय समाजके एतराजोको समझनेका कष्ट नही किया। म अपने सघकी ओरसे जनरल बोयाको भेजे हुए पत्रकी^१ जोर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे सघको रायमे यह अधिनियम केवल सारी पुरुषोचित भावनाओको ही चोट नही पहुँचाता, बल्कि भारतके महान वर्गोका अपमान भी करता है।

मेरे सघको इस बातपर आश्चय है कि आप उस समाजपर, जिसकी नुमाइ दगी मेरा सघ करता हे, यह दोष लगाना उचित समझते हैं कि वह उपनिवेशमे अवैय रीतिमे आनवाले लोगोको बचानेकी इच्छा रखता है। मुझे विश्वास है कि आप यह नही सोचते होंगे कि ब्रिटिश भारतीय समाज अपराबिरायोकी रक्षाके लिए वह सब कुछ बलिदान करनेको तैयार है, जो उसे प्यारा है। इसके अलावा, ब्रिटिश भारतीयोके स्वेच्छया पजीयन सिद्धान्तको मान लेनेसे ही जाहिर होता हे कि भारतीय समाजके लिए अपराधियोको बचाना सम्भव नही है।

[आपका आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[सितम्बर २५, १९०७]

प्लेग-कार्यालयका दौरा

अनुमतिपत्र कार्यालय — मैं भूला, 'प्लेग कार्यालय' — बॉक्सबगका चक्कर लगा आया, कि तु एक कैदीके सिवा और कोई भक्ष्य उसे नहीं मिला। 'लीडर' तथा [रैड] 'डेली मेल' के सवाददाता लिखते हैं कि वहाके भारतीयोमे बड़ा जोश है। उनके धररनेदार मजबूत हैं और कार्यालयमे जानेवाले भारतीयको समझाते हैं। कुछ भारतीय कार्यालयके खुलनेतक पहुँच भी गये थे। लेकिन, उन्होंने जब देखा कि क्या हाल होगा तब वे बिना नाक कटाये वापस हो गये। यह पत्र छपेगा, तबतक जर्मिस्टनमे भी कार्यालय पहुँच जायेगा। लेकिन वहा भी किसीके जानेकी बिलकुल सम्भावना नहीं है।

हमीदियाकी सभा

जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जोहानिसबगमे 'प्लेग' के आनेका समय नजदीक आता जा रहा है। इसलिए रविवारको हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी एक जबरदस्त सभा हुई थी। सभाभवन खचाखच भर गया था। इमाम अब्दुल कादिर अध्यक्ष थे। श्री गांधीने बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जाका तार^१ पढ़कर सुनाया और सारी बातें समझाई। [उन्होंने कहा,] बड़ी अर्जीमे तेजीसे हस्ताक्षर करवानेकी जरूरत है। उसके लिए स्वयंसेवक नियुक्त किये जाने चाहिए। पजीयन कार्यालयके लिए जो स्वयंसेवक नियुक्त किये गये हैं, उन्हें बहुत ही सावधानी और धीरजसे काम करना चाहिए। किसीको डाटकर कहना या किसीपर हाथ चलाना स्वयंसेवकोका काम नहीं है। श्री गिब्सनसे श्री ईसप मियाकी जो बातचीत हुई थी वह उन्होंने सुनाई और कहा कि श्री गिब्सन और दूसरे गोरे जो कुछ भी कहे, उसे हम बिलकुल न माने। मौलवी साहब अहमद मुरत्यारने जोशीला भाषण दिया और कुरान शरीफमे से आयते सुनाई, जिनका अर्थ यह है कि ईमानदारको खुदाके दुश्मन या अपने दुश्मनपर एतबार नहीं करना चाहिए। इस समय गोरे दुश्मनका काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी पजीयित होने वगैरहकी सलाहपर बिलकुल भरोसा न किया जाये। उन्होंने आगे कहा हजरत मूसा जसे पैगम्बरको अपने लगभग एक लाख आदमियोंके साथ बारह वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ा था। उसके बाद ही उन्हें सुख मिला। उसी तरह भारतीय कौमको भी कष्ट उठानेके बाद ही सुख मिलेगा। फिर, पैगम्बर मूसाने खुदापर यकीन रखकर ही फीरोजपर चढ़ाई की थी। उसी तरह यह भारतीय कौम भी खुदाके ऊपर यकीन रखकर ही अपनी शपथका निर्वाह कर सकेगी। नाम, इज्जत और ईमानके लिए सारा धन भी खोना पड़े तो क्या हुआ? इसके बाद अध्यक्ष महोदयने कहा कि भारतसे आज प्रोफेसर गोखले, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महापुरुष हमें उत्साह-

१ (१८४८-१९२५), वक्ता और राजनीतिज्ञ, सन् १८९५ और १९०२ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष। देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९३ ९४।

२ देखिए पृष्ठ २५४ और तार सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको", पृष्ठ २५६।

भरे तार भेज रहे हैं। यदि अन्तिम समयमें हम अपनी बाजी बिगाड़ देंगे तो हमें सारे भारतकी लानत सहनी पड़ेगी। इस सभामें यह भी जाहिर किया गया कि ट्रान्सवालमें रहने-वाली तुर्कीकी मुसलमान प्रजाने अर्जी देनेका इरादा किया है। श्री नवाबखाने^१ स्वयंसेवकोंके सम्बन्धमें भाषण दिया। क्लक्सडॉपसे श्री पटेल आये थे। उन्होंने कहा कि क्लक्सडॉपसे हस्ताक्षर आ जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। श्री अस्वातने कहा, रोजेका महीना अनुमतिपत्रके महीनेमें ही आ रहा है। इसलिए यह न हो कि मुसलमान एक ओर तो रोजा रखें और दूसरी ओर हाथ मुँह काले करके ईमान गँवायें। इस बातका ध्यान रखना है।

सरकारकी चिन्ता

सरकार बहुत चिन्ता दिखा रही है कि भारतीय लोग पजीयित हो जायें। इस बातसे हमें डरना भी चाहिए और हिम्मत भी लेनी चाहिए। डरने जैसी बात यह है कि सरकार जिस बातके लिए इतनी चिन्ता दिखा रही है वह हमें नहीं करनी है। हिम्मत इसलिए कि सरकारकी चिन्ता उसका भय भी व्यक्त करती है। सरकार चाहे कितने ही कठोर दिलकी हो, फिर भी यह नहीं हो सकता कि सारे भारतीयोंको देश निकाला दे दे या उनके परवाने छीन ले। सरकारने बेलफास्टके मजिस्ट्रेटको जो पत्र भेजा है उसकी प्रतिलिपि श्री सालूजीने भेजी है। उससे मालूम होता है कि मजिस्ट्रेट हर भारतीयको सूचना देगा कि जो लोग पजीयित न हुए हों वे जोहानिसबग जाकर अक्टूबर महीनेमें गुआमीका चिटठा लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा भीरुता और किसे कहा जाये?

बोथा साहबकी गलतफहमी

बोथा साहबका कहना है कि अँगुलियोंकी छाप देनेके लिए भारतीय समाज इतना लड़ रहा है, यह तो ठीक नहीं। इससे भी यही मालूम होता है कि यदि भारतीय दब रहे तो सरकार क्या करेगी, वह स्वयं नहीं जानती। लेकिन फिर भी इस गलतफहमीको दूर करनेके लिए श्री ईसप मियाने सघकी ओरसे नीचे लिखा पत्र^२ भेजा है

बाबू सुरेन्द्रनाथका तार

बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका कलकत्तेसे यह तार आया है

“बंगालको आपके कष्टों और लड़ाईके प्रति सहानुभूति है और वह आपकी विजय चाहता है।”

इस तारसे बहुत ही हर्ष हो रहा है। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको बंगाली विद्यार्थी पूजते हैं। आज २५ वर्षसे वे भारतीयोंके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भारतीय प्रशासन सेवाके लगभग पहले भारतीय सदस्य हैं। वे रिपन कॉलेजके आचार्य और ‘बंगाली’ नामक प्रसिद्ध पत्रके मालिक हैं। कलकत्तेके ब्रिटिश भारतीय सघके वे कई वर्षोंसे मंत्री हैं। पुना और अहमदाबादमें जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तब वे अध्यक्ष थे। भारतमें उनके जैसे भाषण देनेवाले कुछ ही लोग होंगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि दस हजार आदमियोंकी

१ मूलमें नवाबदाख है।

२ यहाँ मूलमें ‘पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको’, का अनुवाद है देखिए पृष्ठ २५०-५१।

सभामे भी वह सब ओर पहुँच जाती है। स्वदेशी आंदोलनमें^१ उन्होंने बड़ा काम किया है। भारतसे ऐसे तार आने लगे हैं, इसे शुभ चिह्न मानना होगा।

गद्दारोका सघ

इन भाई साहबोंकी सरयामे कुछ न कुछ वद्धि होती जा रही है। सवश्री^२ पवित्र हो चुके हैं। मुझे लगता है इन लोगोंको जनाना लिबास पहिन लेना चाहिए।

श्री स्टॉकेन्स्ट्रूम

हाइडेलबर्गमे भाषण देते हुए श्री स्टॉकेन्स्ट्रूमने कहा है कि भारतीय यदि पजीयित नहीं होते हैं तो उन्हें परवाने नहीं दिये जायेंगे। कलाई खुल चुकी है। पहले जेल थी। जेल मिटकर देश-निकाला हुआ। अब परवानेकी बात चल रही है। भारतीय जब परवानेका डर छोड़ देगे तब बोथा साहब क्या करेंगे?

श्री नेसर

क्लाक्सडॉपमे श्री नेसरने श्री स्टॉकेन्स्ट्रूमकी तरह भाषण दिया है। वे अँगुलीकी निशानीकी लड़ाईका खण्डन करते हुए कहते हैं कि भारतीय कोम गैर कानूनी तौरसे आये हुए लोगोंको बचानेके लिए लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय कौम लड़ाई ही करती रहेगी, तो सरकार उनके व्यापारी-परवाने बंद कर देगी। धमकी तो सुन ली। लेकिन भोकनेवाला कुत्ता काटता नहीं। इस कहावतके अनुसार, जैसे जैसे धमकिया दी जा रही हैं वैसे वैसे भारतीय समाज निभय होता जा रहा है। लेकिन श्री नेसर जैसे व्यक्तिकी नादानी विचार करने योग्य है। अभीतक इसी बातका प्रचार चल रहा है कि हम अँगुलियोंकी निशानीके लिए ही लड़ रहे हैं। इसलिए श्री ईसप मियाने नीचे लिखे अनुसार जवाब^३ भेजा है।

विलियम वॉन हलस्टेन

सर विलियम वॉन हलस्टेनने एक भाषणमे कहा था कि भारतीय सिर्फ अँगुलियोंकी निशानीके विरोधमे आन्दोलन कर रहे हैं। इसपर ब्रिटिश भारतीय सघके मंत्रीने इस ओर उनका ध्यान खींचते हुए इस प्रकार लिखा है^४

भारतीयोंकी लड़ाई सिर्फ अँगुलियोंकी निशानीके खिलाफ नहीं, बल्कि समूचे कानूनके खिलाफ है। इस कानूनको अनिवार्य रूपमे स्वीकार करनेमे भारतीय अपनी गुलामी मानता है, और अपनी उस गुलामीसे छूटनेके लिए — न कि सिर्फ अँगुलियोंकी निशानीसे बचनेके लिए — वह अपना सबस्व होम देनेको तैयार है। सरकारने धमकिया देना शुरू किया है इस बातको भी हम जानते हैं। ऐसे कानूनको अमलमे लानेसे सरकारका नाम होगा, या दुख भोगकर भी कानूनका विरोध करके दुनियामे भारतीयोंका नाम होगा यह तो अभी देखना है।

१ विदेशी मालके (खासतौरसे कपड़ेके) बहिष्कारका आन्दोलन।

२ यहाँ मूलमें पाच नाम दिये गये हैं।

३ देखिए “पत्र जे० ए० नेसरको” पृष्ठ २५२।

४ देखिए “पत्र डब्ल्यू० वी० हलस्टेनको”, पृष्ठ २३५ ३६।

भूल सुधार

पीटसबगके बहादुरोकी मैंने टीका की है। उसके बारेमें पीटसबगके एक प्रतिष्ठित सज्जन लिखते हैं कि जिन साहबोंके नाम मैंने दिये हैं उनके हस्ताक्षर पीटसबगकी प्रसिद्ध अर्जीमें नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वे बाहर गये हुए थे। अतः मुझे अपनी गलतीके लिए खेद है। इसके साथ यह भी कह दूँ कि जिन साहबोंने अपने हाथ काले किये हैं, उनका अपराध यद्यपि अक्षम्य है, फिर भी वह जितना बड़ा दीखता था उतना नहीं है। उपयुक्त पत्रका मैं यह अर्थ करनेकी अनुमति लेता हूँ कि जिन्होंने अर्जीपर हस्ताक्षर कर दिये हैं वे तो इस गुलामीके पट्टेको छुएँगे तक नहीं।

जर्मिस्टनमे युद्ध

जर्मिस्टनमे पजीयन कार्यालयने काम शुरू किया है। इससे वहाके भारतीयोंमें बड़ा जोश है। आज (बुधवार) तक उन्होंने काम-धन्दा छोड़ रखा है और सब स्वयंसेवकका काम कर रहे हैं। जर्मिस्टनके एक भी व्यक्तिने अर्जी नहीं दी। होटलके हजरियोने भी इनकार कर दिया है। केवल प्रिटोरियाका कासिम नामक एक मद्रासी धरनेदारोकी बातको न मानते हुए पजीयित हुआ है। पाच मेमन आये थे। लेकिन उन्होंने धरनेदारोकी बात मानकर पिआनो बजाने [अर्थात् पजीयन करवाने] का अपना विचार छोड़ दिया। जर्मिस्टनमे स्वयंसेवकोको आवश्यकतासे अधिक उत्साह बतलानेके कारण शांत करना पड़ा था। अब वहा सिर्फ उतने ही लोग काम करत ह जितने जरूरी हैं और सौ भी नम्रता और धीरजके साथ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०१ तार ' सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको

[जोहानिसबग,

सितम्बर २५, १९०७ के बाद]

भारतीयोंका धन्यवाद। कतव्य पूरा करेगे।

[त्रिभास]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०२ भारतसे सहायता

ट्रांसवालवासी भारतीयोंके प्रति उनके जीवन-मरण सघषमे सहानुभूति दिखानेमे माननीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने माननीय प्रोफेसर गोखलेका तत्काल अनुकरण किया है। भारतकी जनताके इन विश्वासपात्र प्रतिनिधियोंके समुद्री तार पाना कोई छोटी बात नहीं है। दोनोंने भारतके लिए अपना जीवनोत्सर्ग कर दिया है और दोनोंका भारतमे अनुपम प्रभाव है। इसलिए, यह सोचना उचित ही है कि ट्रांसवालके भारतीयोंका सवाल भारतीय राजनीतिमे जल्दी ही अत्यन्त प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगा। उस दिन लाड ऐम्स्टहिलने ठीक ही कहा था कि भारतीयोंकी भावनाको जितना गहरा आघात दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टोंने पहुँचाया है, उतना किसी और चीजने नहीं पहुँचाया। भारतसे जो प्रोत्साहन मिला है उसकी हमें आवश्यकता है। इस सवालपर भारतमे कोई दलबन्दी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हिन्दू मुसलमान, पारसी और ईसाई — सब समानरूपसे ट्रांसवालके भारतीयोंकी अत्यन्त दुःखपूर्ण और अपमानजनक परिस्थितिका अनुभव करते हैं। आग्ल भारतीयोंकी राय भी उतनी ही ठोस है जितनी कि भारतीयोंकी। इस व्यवहारके खिलाफ किसीने इतनी सख्तीसे नहीं कहा जितना कि कलकत्तेके 'इंग्लिशमैन' और बम्बईके 'टाइम्स आफ इंडिया' ने कहा है। इसलिए आवश्यकता इस बातकी है कि भारतकी तमाम सस्थाओं और लोकमतके मुख्य पत्रोंकी शक्ति केन्द्रित करके लाड मिटोपर पूरा जोर डाला जाये तब भारतीय सवाल 'यायोचित और मानवोचित सिद्धान्तोंके अनुसार हल हुए बिना नहीं रह सकता।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०३ धरनेदारोंका कर्तव्य

जोहानिसबर्गके भारतीयोंको जल्दी ही अपना जीवट दिखाना होगा। इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि एशियाई कानूनके प्रति अंतिम कदम क्या उठाया जाये। इसका निणय बहुत-कुछ इस बातसे होगा कि पजीयन दफ्तर द्वारा जोहानिसबर्गके एशियाइयोंको पजीयित करनेके प्रयत्नका क्या परिणाम निकलता है। ट्रांसवालकी एशियाई आबादीका प्रायः आधा भाग जोहानिसबर्गमे है। सभी विभिन्न एशियाई जातियोंके लोग भी बड़ी सरयामे जोहानिसबर्गमे हैं और अगर वे एशियाई कानूनके विरोधमे दब रहे तो इससे स्थानीय सरकारको गम्भीरतासे सोचनेके लिए जरूर कुछ मसाला मिल जायेगा। चाहे जितनी धमकियाँ क्यों न दी जाये, पर आजकल जब कि रुपयेकी इतनी तंगी है, जेलकी इमारते बनाना कोई हँसी-खेल नहीं है। हजारों निर्दोष लोगोंको निर्वासित करना भी व्यावहारिक राजनीति नहीं होगी, क्योंकि इससे बोथा और स्मट्स जैसे जनरलोंकी अन्तरात्मा भी प्रभावित होगी। इस प्रकार, अब हमें एशियाई परवानोंके रद्द करनेकी धमकियोंका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यह बात सम्भव ७-१७

हो तो सरकार अपने आपको मूख साबित करेगी, क्योंकि इस प्रकार इससे एशियाइयोंकी बहुत बड़ी सरया अछूती रह जायेगी। इसलिए जोहानिसबगके एशियाई जो भी कदम उठायेगे उसीसे इस प्रश्नका बहुत कुछ निणय होगा। अत जोहानिसबगके प्रमुख भारतीयों ओर दूसरे प्रमुख एशियाइयोंके कंधोपर जो जिम्मेवारी है, वह बड़ी गम्भीर और महान है।

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि अबतक भारतीय धरना देनेवालों या सेवाव्रतियोंके प्रयत्नसे ही पजीयन दफ्तरका बहिष्कार इतना सफल रहा है। उन्होंने अपना काम शान्ति, दबता और शिष्टताके साथ किया है। जोहानिसबगमे बहुतसे गडबडी पैदा करनेवाले तत्त्व हैं। जिन्होंने सेवा काय करनेका बीडा उठाया है, उनमे कुछ लोग आगके गोले हैं। फिर, जोहानिसबगमे सभी वर्गोंके लोग रहते हैं। इसलिए हम भारतीय स्वयसेवकोंको आगाह करते हैं कि वे किसी तरह जल्दबाजी या क्रोध न दिखाये। शारीरिक हिंसासे पूरा पूरा बचा जाये और इसी तरह सरत भाषा भी इस्तेमाल न की जाये। जो लोग एशियाई अविनियमके जुएको टालनेके लिए चिंतित हैं, उहे इस बातकी भी फिक्र करनी चाहिए कि वे नासमझी-भरी धौंस और धमकियोंके रूपमें कहीं उससे भारी जुआ न लाद ले। अगर भारतीयोंको इस बातका विश्वास है कि यह कानून उनको गिराता है और उनके पौरुषका हरण करता है तो उन्हें सिर्फ यही करना चाहिए कि वे इस दृष्टिकोणको उन दूसरोंके सामने रखे जो इसे नहीं जानते। ऐसा करते ही उनका कतव्य समाप्त हो जाता है। फिर वे इसे पजीयन करवानेवाले भावी आवेदनकर्तापर छोड़ दे कि वह इसमे से क्या चुनाव करता है। अगर वह इस कानूनकी गुलाम बनानेवाली शर्तोंको माननेके लिए रजामंद होता है तो यह उसीकी हानि है, न कि समाजकी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०४ जनरल बोथा और एशियाई कानून

यह देखकर बेचैनी होती है कि ट्रान्सवालके प्रधानमन्त्री, जिन्हें अपनी स्मरणीय लदन-यात्रामे सेमिल होटलमे मिलनेवाले भारतीय शिष्टमण्डलसे मीठी और नम्रतापूर्ण बातें कहनेमें कोई सकोच नहीं हुआ था, अभीतक यह नहीं जानते कि एशियाइयोंके सवषका वास्तविक आधार क्या है। उनका खयाल है, और वह ठीक ही है, कि ट्रान्सवालके एशियाइयोंने सिर्फ अँगुलियोंके निशानोंके बारेमें जो भारी आदोलन चला रखा है, उसका कोई उचित कारण नहीं हो सकता। किंतु जनरल बोथाका यह विश्वास, कि आदोलनका आधार सिर्फ अँगुलियोंके निशानोंपर होनवाली आपत्ति ही है, बताता है कि वे भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें कितने अज्ञानमें ह। जब सन् १९०६ मे यह कानून पहली बार विचारके लिए पेश किया गया तब इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय सभने कुछ आपत्तियाँ लेखबद्धकी थी। उनमें से कुछ तत्परतासे जनरल बोथाको भेज दी गई ह। हमारे बहादुर जनरलने यह देखनेका कष्ट भी नहीं उठाया कि यदि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी आपत्तियाँ अँगुलियोंके

निशान देने तक ही सीमित होती तो क्या वे विश्वव्यापी सहानुभूति प्राप्त कर सकते थे। ट्रान्सवालके राजनयिकोंको उन बहुत ही गम्भीर मुद्दोंकी उपेक्षा करनेमें सुविधा हो सकती है, जो भारतीय समाजमें अपनी धार्मिक भावनाओं, अपने दर्जों और अपमानजनक वर्गीय विधानके सम्बन्धमें उठाये हैं। किन्तु ऐसी चिर अभ्यस्त उपेक्षासे अतमें एशियाइयोंका गहरा क्षोभ बढ़ेगा एवं उनका विरोध और भी कड़ा होगा। अब उनका साहस निराशासे उत्पन्न साहस है। वे अपने सवस्वके अपहरणके अभ्यस्त हो गये हैं। इसलिए, ट्रान्सवालकी सरकारके लिए बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इसीमें होगी कि वह कमसे कम भारतीयोंकी आपत्तियोंपर उनके गुण दोषोंकी दृष्टिसे तो विचार करे और उनकी ओरसे अपनी आंखें बंद न करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०५ भारतीय फेरीवालोंके खिलाफ लड़ाई

नेटालकी विधानसभामें फेरीवालोंके परवानोंकी फीस बढ़ानेके प्रस्तावपर जो बहस हुई, वह बड़ी ज्ञानवर्धक है। नेटालके फेरीवालोंपर लगनेवाली इस भारी फीसकी किसीने परवाह नहीं की, क्योंकि फेरी करके रोजी कमानेका काम अधिकांशतः एशियाइयोंके हाथमें है और, जैसा कि 'याय मन्त्रीने कहा, "इस देशमें फेरी लगानेका धंधा श्वेत जातिके लोगोंके योग्य नहीं है।" रगदार जातियोंके लोगोंसे ताल्लुक रखनेवाले सवालपर इसी तरीकेसे बहस करते हुए एशियाइयोंके परम विरोधी श्री हैगरने प्रस्ताव रखा है कि "सावजनिक हितमें यह बात अवाञ्छनीय है कि नेटाल गवर्नमेंट रेल प्रणालीमें जिन पदोंपर साधारणतः गोरे लोग काम करते हैं, उनपर एशियाइयोंको नियुक्त किया जाये।" सच पूछा जाये तो इस महान विधानसभा सदस्यको "सावजनिक हित" के बजाय "श्वेत जातिके हित" कहना था। यह भी बता दिया जाये कि यह प्रस्ताव रेलवे और बन्दरगाह मन्त्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने कहा कि अगर मैं "कुलियों"को, जिस नामसे वे रेलगाड़ियोंका माग बदलनेवाले भारतीय कमचारियोंको पुकारते हैं, लात मारकर निकाल बाहर नहीं करता तो इसका कारण यह है कि मुझे सदनके सदस्योंसे छँटनीके बारेमें आदेश प्राप्त है। इस प्रकार इन दोनों अवस्थाओंमें इतना भी नहीं किया गया कि भारतीय फेरीवालों और भारतीय रेलवे कमचारियोंके यदि कोई दावे थे तो उनकी जांच कर ली जाती। जहातक उपनिवेशोंका ताल्लुक है, "ब्रिटिश प्रजा होनेका" सिद्धान्त थोथा साबित हो चुका है। उपनिवेशी इस पुराने ब्रिटिश झण्डेके सम्बन्धमें मिलनेवाले सारे लाभ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन उस झण्डेको अपनानेसे जो असुविधाएँ और जिम्मेदारियाँ आती हैं उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०६ हमारा परिशिष्ट

इस बार हम प्रिटोरियाके बहादुर स्वयसेवकाकी तस्वीरे दे रहे हैं। कुछ सज्जनोंके विचारकी कद्र करके हमने आजतक यह परिशिष्ट नहीं निकाला था। लेकिन हम मानते हैं कि इससे हमने प्रिटोरियाके स्वयसेवकोंके साथ आयाय किया है। हमारी निश्चित राय है कि यदि ये स्वयसेवक बाहर न निकलते और यदि इन्होंने धीरज, मिठास तथा हिम्मतका आदर्श न खड़ा किया होता तो यह लड़ाई यहातक नहीं पहुँच सकती थी।

अब जोहानिसबर्गकी बारी आई है। इस समय इस परिशिष्टको प्रकाशित करना हमने अपना कर्तव्य समझा है। जोहानिसबर्ग यदि इन युवकोंका अनुकरण करेगा, शांति और नम्रतासे काम लेगा, तो हम समझेंगे कि हमारी लड़ाईका अंत निकट आ गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०७ स्वयसेवकोंका कर्तव्य

ट्रांसवालकी लड़ाईमें हमने देखा है कि स्वयसेवकों (वॉलंटियस) ने चाहे हम उन्हें स्वयसेवक, धरनेदार (पिकेट), सेवाव्रती (मिशनरी) या चौकीदार, किसी नामसे पुकारें—बहुत बढ़िया काम किया। उनकी सहायताके बिना कुछ भी हो नहीं सकता था। इस लड़ाईका श्रेय सचमुच प्रिटोरियाके धरनेदारोंको देना चाहिए। उन्होंने धीरज, मधुरता और हिम्मतका जो उदाहरण पेश किया, उसका अनुकरण प्रत्येक स्थानपर होता आ रहा है।

अब जोहानिसबर्ग शेष रहा है। इस शहरमें हर तरहके भारतीय रहते हैं। कोई ऐसे भी होंगे जिन्हें लाज शर्म न हो। ऐसे लोग पजीयनपत्र लेने जायें तो उसमें आश्चर्य नहीं माना जा सकता। फिर, यह भी हो सकता है कि कोई दूसरे शहरोंसे हाथ मुह काले करवाने आ जायें। इन सबको धरनेदार कैसे सँभालेंगे? यदि कोई भारतीय अपने हाथ काले करनेके लिए जायेगा तो साधारणतया हमारे मनमें उसके प्रति तिरस्कार पदा होगा। परन्तु तिरस्कारके बदले उसपर दया करना हमें अधिक शोभा देगा।

चौकीदारका काम पहरा देनेका है, हमला करनेका नहीं। यदि जोहानिसबर्गमें पजीयन करवानेके लिए जानेवालोपर हमला किया गया तो हम निःसकोच कहते हैं कि किनारे लगी हुई नैया डूब जायेगी। हमारी सारी लड़ाई कष्ट सहन करनेकी है किसीको कष्ट देनेकी नहीं, फिर चाहे वह भारतीय हो या ग़ोरा हो। यह बात प्रत्येक चौकीदारको बहुत सावधानीसे याद रखनी चाहिए। गलती करनेवालोको समझाना, उनसे बिनती करना, उनकी आजिजी करना हमारा काम है। इसपर भी उहे यदि दासता ग्रहण करनी हो तो उहे छूट दे देनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उहे कानूनके अत्याचारसे बचाकर अपने अत्याचारसे दबायें तो उसमें हमें कुछ भी लाभ नहीं दिखाई देता। हम अपने लिए जितनी स्वतंत्रता चाहते हैं उतनी ही दूसरोंको भी दे, यह हमारा कर्तव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०८ क्या भारत जाग गया ?^१

माननीय प्रोफेसर गोखले तथा माननीय बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके समुद्री तारोसे हमें जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। ये दोनों महानुभाव केवल सहानुभूतिके तार भेजकर बैठे रहे, सो बात नहीं। इनके तारोसे मालूम होता है कि भारतसे हमें अब पर्याप्त सहायता मिलेगी। इसका बहुत गहरा अर्थ हो सकता है। ट्रांसवालका प्रश्न छोटा नहीं रहेगा। उसकी चर्चा सारी दुनियामें होगी। भारतसे अर्जिया भेजी जायेगी, और वहा सभाएँ होगी। मेरी यह मायता निराधार नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बड़ी सरकार बठी नहीं रह सकती। लाड एम्प्टहिल महोदय कह चुके हैं कि ट्रांसवालके सवालसे भारतको जितनी ठेस लगी है उतनी अर्थ किसी बातसे नहीं लगी। हर जगह शोर मचा है। तब भारतको नाराज करनेका इतना जबरदस्त कारण [साम्राज्य] सरकार कैसे रहने दे सकती है ?

इतनी सहायता मिलनेका कारण एक ही है। वह है, भारतीयोंकी हिम्मत। आजतक हमने एक होकर जोर दिखाया है। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमें बहुत ही प्रतिष्ठा मिली है। उसकी रक्षा करना अब ट्रांसवालके भारतीयोंके हाथ है। और ट्रांसवालके भारतीयोंकी दृष्टि अब जोहानिसबगपर है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०९ “बीच रुई जरि जाय”

कहावत है कि “लडे लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय”। नेटालमें गोरोके दो पक्ष खीचा-तानी करते हैं, जिसका परिणाम भारतीय मजदूरोंको भोगना पड़ रहा है। हैगर साहब और उनके जैसा विचार रखनेवाले गोरोका कहना है कि रेलवे लाइन पार करनेकी चौकियोंपरसे भारतीय कुलियोंको हटाकर गोरोको रखना चाहिए। यह नहीं माना जा सकता कि हैगर साहब यह हलचल किसी विशेष परोपकार बुद्धिसे कर रहे हैं। उनका विचार तो जैसे-तैसे आगे बढ़ना है। नेटालकी सरकार जानती है कि भारतीय मजदूरोंको चालू रोजीसे वचित करके ऊँची तनख्वाहवाले गोरोको रखना ठीक न होगा। लेकिन, वह अपनी इस प्रामाणिकताको प्रकट करनेमें झेपती है, इसलिए कहती है कि जहा भी भारतीय मजदूरोंको अलग किया जा सकेगा, वहा किया जायेगा। यह मनसूबा यदि कार्यावित किया गया तो इसके परिणामकी दोमे से किसी भी पक्षको परवाह नहीं है। इसको वे लोग “सुधार” कहते हैं। यदि सच्ची शिक्षा और सुधार इसीका नाम हो तो हम चाहते हैं कि भारतीय इस बलासे छूट जाये, यही अच्छा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

१ देखिए “भारतसे सहायता”, पृष्ठ २५७।

२१० मिस्त्रमे स्वराज्यका आन्दोलन

‘रैड डेली मेल’ के एक पत्रसे मालूम होता है कि मिस्त्रमे स्वराज्यके आन्दोलनने एकदम बड़ा रूप ले लिया है। कहा जाता है कि यह मुस्तफा कामेलपाशाके^१ कामका प्रभाव है। मिस्त्र ससदके उमराव सदस्योंमे से लगभग ११६ सदस्योंने स्वराज्यके लिए प्रस्ताव किया है। उनका कहना है कि वे अंग्रेजोंकी मदद लेनेसे इनकार नहीं करते। लेकिन राज्यकी लगाम वे अपने ही हाथोंमे रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोक शिक्षण विभाग पूरी तरहसे जनताके ही हाथोंमे होना चाहिए। मुस्तफा कामेलपाशा कहते हैं कि यदि अंग्रेज सरकार इतना अधिकार दोस्तीसे और प्रेमपूर्वक न दे तो मिस्त्रकी जनता लड़कर ले लेगी, लेकिन अब मिस्त्र पराधीन नहीं रहेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२११ पत्र जे० ए० नेसरको

[जोहानिसबग]

सितम्बर २८, १९०७

श्री जे० ए० नेसर, ससद-सदस्य

पो० आ० बाक्स २२

क्लाक्सडॉप

महोदय,

आपका इस मासकी २७ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। आपके इस अत्यंत शिष्ट, स्पष्ट और पूरा पत्रके लिए मैं आपको अपने सचकी ओरसे धन्यवाद देता हूँ। भारतीय प्रश्नके ठीक तरहसे हल होनेमे सबसे बड़ी बाधा नि सदेह यह रही है कि लोक सेवक उसके प्रति अत्यंत उदासीन रहे और, इसलिए, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है।

आपने मेरे देशवासियोंके प्रति, जिनके हित इस देशमे निहित हैं, जो हमदर्दी जाहिर की है, उसके लिए मैं हृदयसे आभारी हूँ, और चूंकि यह लड़ाई पूरी तरह उन्हीं हितोंकी रक्षाके लिए है, इसलिए मुझे आपके रुखमे एक ऐसी बात दिखाई देती है, जिसपर हम सहमत हो सकते हैं।

मेरा सच न केवल भारतीयोंके सामूहिक आब्रजनपर की जानेवाली आपकी आपत्तिके साथ सहानुभूति रखता है, वरन् इस प्रकारके आब्रजनके विरुद्ध साधारण विद्वेषको ध्यानमे

रखते हुए उसने उसकी वैधताको स्वीकार किया है और इस उद्देश्यकी प्राप्ति के लिए सरकार के साथ सदा ही सहयोगकी तत्परता दिखाई है।

अब एशियाई अधिनियमपर उसके गुणावगुणकी दृष्टिसे विचार करने के लिए माग साफ है। मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेका साहस करता हूँ कि जब सितम्बर १९०६ मे अध्यादेशके मसविदेपर — उस समय यह अधिनियम इसी रूपमें था — एतराज किये गये थे, तब उनमें अँगुलियोंके निशानोका जिक्र तक नहीं था, यद्यपि उस समय यह पता चला था कि सरकार अँगुलियोंके निशानोपर जोर देना चाहती है। इसलिए यदि अँगुलियोंके निशानोके बदलेमें हस्ताक्षर रख दिये जाते तो मेरे सघका रुख किसी प्रकार भी नहीं बदलता। सारे अधिनियममें व्याप्त अनिवायताका डक ही भारतीय समाजको चोट पहुँचाता है और उसपर इतना भारी बोझा बना हुआ है। अँगुलियोंके निशानोसे किसीकी भी धार्मिक भावनाको चोट नहीं पहुँचती, किन्तु अधिनियममें जो तुर्की-ईसाइयो और तुर्की यहूदियोंके लिए छूट दी गई है वह बेशक धार्मिक भावनाओको उग्रतम चोट पहुँचानेवाली है।

यह अधिनियम अपनी विभिन्न शर्तोंके भग होनेपर कठोर दण्डोंसे भरा पड़ा है, किन्तु विरोध सजा या उसकी सख्तीका नहीं किया जाता, बल्कि उसके अदर छिपी हुई इस धारणाका किया जाता है कि भारतीयोका वगका वग अपने गलत नाम बतानेकी जालसाजी करनेमें तथा धोखाधडीसे अनुमतिपत्रोंकी अदलाबदली करने और देशके अदर अनधिकृत प्रवासियोंको लानेमें समर्थ है। और मैं समझता हूँ, कि यह विरोध ठीक ही है। जब कभी किसी देशमें किसी विशेष अपराधके लिए असाधारण सजाओका विधान किया जाता है, तब, जैसा कि आप जानते हैं, यह मान लिया जाता है कि उस देशमें इस अपराधका अस्तित्व सब-साधारण रूपमें है। इस बातको भली भाँति जानते हुए कि ब्रिटिश-भारतीय, वगके रूपमें ऊपर बताये हुए अपराध नहीं करते, वे उस धारणाके, जिसे यह अधिनियम मौन रूपसे तथा विधि निर्माता खुलेआम उनका अपराध बतला रहे हैं, परिहारके लिए दिलेरीसे सघष कर रहे हैं। इसके अलावा, यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि यह कानून एक घृणित ढगका वग कानून है। यह भारतीयोको मलायी लोगोकी, जिनके साथ उनके नजदीकी रिश्ते हैं, केपके रगदार लोगोकी, जिनके निकट सम्पर्कमें वे आते ह, और काफिर जातियोंकी भी, जिनको वे बहुत बड़ी सख्यामें नौकर रखते हैं, निगाहमें गिराता है। जब कि इन तीनोंको उपनिवेशके अय निवासियोंके साथ उनकी व्यक्तिगत आजादीपर ऐसी पाबन्दियोंसे छूट दी गई है, एशियाइयोको ही विशेष रूपसे पाबन्दियोंके लिए छोट लिया गया है।

आपके अंतिम एतराजका स्वभावतः साफ जवाब यह है कि भय एशियाइयोकी प्रति-योगितासे है, रगदार जातियोंकी प्रतियोगितासे नहीं। इस तथ्यको जानते हुए ही मेरे सघने यह प्रस्ताव किया था कि अनिवाय विधानके बदलेमें स्वेच्छया शिनारत या पजीयनका विधान किया जाये। इस प्रकारके स्वेच्छया पजीयनसे शेष समाजसे अलग कर दिये जानेपर भी भारतीयोका अपमान नहीं होगा, यूरोपीयोके एतराजोका पूरा समाधान हो जायेगा, और निहित अधिकारोकी रक्षा होगी। आप यह सोचते हुए मालूम होते हैं कि स्वेच्छया पजीयनसे बेईमान भारतीय साफ बच जायेंगे। उनके अस्तित्वसे मैं इनकार नहीं करता। किन्तु मेरा निवेदन है कि आपका यह खयाल गलत है। प्रस्तावके अंतर्गत सरकारसे यह कह दिया गया है कि स्वेच्छया पजीयनके अनुसार दोनो पक्षोंकी सहमतिसे एक छोटा सा विधेयक पास करके

इस कानूनको उन लोगोपर लागू किया जा सकता है जो अपने आप पजीयन न कराये। नि सदेह, एक निश्चित समयपर सभी भारतीयो या एशियाइयोकी एक साथ जाच की जा सकती है, और जिनके पास पहचानके नये प्रमाणपत्र न मिले उनको शांति रक्षा अध्यादेशके अधीन उपनिवेशसे निकाला जा सकता है, या शांति रक्षा अध्यादेशके बदलेमे एक आम प्रवासी कानून पास करके उसके अधीन उहे निकाला जा सकता है।

म आपका समय अधिक न लेते हुए केवल यह कहकर अपने वक्तव्यको समाप्त करूंगा कि जहा मेरे देशवासियोने ईमानदारीसे यूरोपीयो द्वारा उठाये हुए माकूल एतराजोकी जाच करके उनको पूरा करनेका प्रयत्न किया है, वहा यूरोपीय सामूहिक रूपमे उसका उसी रूपमे उत्तर देनेमे पूणतया असफल रहे है और भारतीय स्थितिकी जाच करनेकी परवाह किये बिना अपनी विद्वेषपूण विरोधी नीतिपर अडे रहे है। चूकि आप अपने पेशेके कारण ब्रिटिश भारतीयोसे अत्यधिक सम्बन्धित रहे है, इसलिए मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने-आपको हमारी स्थितिमे रखे और सारी बातोपर हमारे दृष्टिकोणसे विचार करे और देखे कि क्या थोडे बैय तथा कुछ सहयोगसे एक माकूल समझौता होना सम्भव नही हे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सच

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१२ पत्र.' 'रेड डेली मेल' को

[जर्मिस्टन]
सितम्बर, २८, [१९०७]

सेवामे
सम्पादक
['रेड डेली मेल'
जोहानिसबग]
महोदय,

आपके सवाददाताने जनताको सूचित किया है कि जर्मिस्टनमे भारतीय धरनेदारोके डराने धमकानेसे ही वहाके बहुतसे भारतीयोने अपना पजीयन नही कराया। मै प्रधान धरने दारकी हैसियतसे कहना चाहता हू कि आपको दी गई सूचना बिलकुल गलत है। मै आपको सूचित कर दू कि वास्तवमे दो दिन तक जर्मिस्टनकी तमाम भारतीय आबादी धरना देती रही थी, क्योकि उन सभी लोगोने काम बन्द कर दिया था। इस कानूनके विरुद्ध उनका उत्साह और इसके प्रति उनका विरोध ऐसा ही जोरदार था। जब नियुक्त धरनेदारोने अन्य भारतीयोको समझाया तभी उन्होने अपना काम फिर आरम्भ किया।

१ इसका मसविदा अनुमानत गांधीजीने तैयार किया था।

किन्तु यह बिल्कुल सच है कि दूसरे स्थानोंसे कुछ भारतीय जर्मिस्टनमें पजीयन करानेके लिए आये थे और उन्होंने जर्मिस्टनके धरनेदारोंका मैत्रीपूर्ण विरोध और तक सुना और वे अपने आपको और अपने समाजको झुकाये बिना लौट गये। किन्तु जहाँ ऐसा उचित तक कारगर नहीं हुआ, वहाँ कड़ी हिदायत दे दी गई थी कि जो लोग कानून द्वारा लादी गई दासताको स्वीकार करना चाहें, उनको स्वयं साथ जाकर पहुँचा दिया जाये, और ऐसा बाक्सबगसे आये हुए एक भारतीय जोसफ बहादुरके मामलेमें किया भी गया।

हमारी लड़ाईमें हमें डराने धमकानेकी आवश्यकता नहीं होती। जो लोग अधिनियमको और उसके सब परिणामोंको समझते हैं वे अपने आप इस दासताको स्वीकार करनेसे हाथ खींच लेते हैं, इसमें अपवाद तभी होता है जब वे अपने स्वाथके कारण अपनी आत्म-सम्मानकी भावनाको भुला देते हैं। मैं आपके असख्य पाठकोंकी जानकारीके लिए बता दूँ कि अस्पताली नौकरो और मजदूरों तक ने नौकरीसे बरखास्त कर दिये जानेकी धमकियोंके बावजूद अपना पजीयन करानेसे इनकार कर दिया, और उनके मालिकापर उनकी इस सम्मानजनक इनकारीका ऐसा स्पष्ट प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उन धमकियोंको वापस ले लिया।

आपका, आदि,

रामसुन्दर पण्डित

प्रधान जर्मिस्टन धरनेदार

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, ३-१०-१९०७

२१३ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें

जोहानिसबग

[सितम्बर २९, १९०७]

मैं आज अजुमनकी बैठकमें आया हूँ, किन्तु मुझे कुछ खास नहीं कहना है। श्री बेगका पत्र आया है, अगर जरूरत हो तो वे धरनेदारके रूपमें मदद देनेके लिए तैयार हैं। जर्मिस्टनके भारतीय भाइयोंने जो बहादुरी दिखाई थी, उससे जोहानिसबगके भारतीयोंको सबक लेना चाहिए। श्री रामसुन्दर पण्डित उस विषयमें बतायेंगे। यहाँके धरनेदारोंको अपना कतव्य अच्छी तरह करना चाहिए, जैसे बने वैसे लोगोंको समझाना चाहिए। किसीके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि बाहरके कोई आये तो उनके साथ धीरजसे काम लिया जाये।

प्रिटोरियाकी अर्जीके बारेमें मुझे अभी इतनी ही खबर मिली है कि सरकार अनुमति-पत्रोंकी जाँचके लिए निरीक्षक रखेगी। श्री कोडीने ट्रान्सवालसे निकाल देनेकी धमकी दी है, पर श्री पण्डित बड़े जोरमें हैं। सरकार यदि इन्हींको गिरफ्तार करे तो अच्छा। जोहानिसबगमें हस्ताक्षरोंका काम तेजीसे हो, यह जरूरी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१४ प्रार्थनापत्र ' तुर्कीके महा वाणिज्य-दूतको

[जोहानिसबग
अक्टूबर ५, १९०७ के पूर्व]

महोदय,

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जोहानिसबगवासी और तुर्कीके महामहिम सुल्तानके वफादार मुसलमान प्रजाजन, इसके द्वारा आपका ध्यान एशियाई पजीयन-अधिनियमकी ओर आकर्षित करते हैं। इस अधिनियमके अतगत तुक साम्राज्यकी मुसलमान प्रजाको पजीयन कराना पड़ता है। हमारी विनीत सम्मतिमें, यह अधिनियम अपमानजनक है और इससे तुर्कीके मुसलमानोंका विशेष रूपसे तिरस्कार होता है, क्योंकि इससे तुक साम्राज्यके मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रजाजनोमें भेदभाव किया जाता है, जिससे मुस्लिम प्रजाजनोकी हानि होती है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप कृपा करके स्थानीय सरकारसे आवश्यक निवेदन करेंगे और इस प्रार्थनापत्रकी प्रतिलिपि महामहिम सम्राटके सम्मुख प्रस्तुत करनेके लिए भेजेंगे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
सैयद मुस्तफा अहमद जैल
[और तुर्कीके १९ अय मुसलमान]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१५ जॉर्ज गॉडफ्रे

श्री सुमान गॉडफ्रे और श्रीमती गॉडफ्रे अपने तृतीय पुत्रके इंग्लैंडसे उदार सांस्कारिक शिक्षा प्राप्त करके लौटनेपर और भी बधाईके पात्र हैं। अपने दो पुत्रोंको बैरिस्टर और एकको डाक्टर बनाकर किन्हीं भी माता-पिताको गव होगा, फिर उनके दूसरे बच्चे भी अभी स्कूलोमें पढ़ रहे हैं। श्री जॉर्ज गॉडफ्रे अपनी शिक्षा निर्विघ्न समाप्त करके सकुशल लौट आये हैं और उन्हें अपने मित्रों तथा देशवासियोंका स्वागत सत्कार प्राप्त हुआ है, अतः वे बखूबी अपने आपको कृतकाय मान सकते हैं। परन्तु शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओंका महत्त्व बढ़ा चढ़ाकर बतानेको हमारा जी नहीं चाहता। जनताके लिए यह जानना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा भव्य लाभ अपनी शान शौकत बढ़ाने और जन सचयके काम आयेगा या राष्ट्रकी सेवामें अपण होगा। और इस उपयुक्त प्रश्नके उत्तरकी अपेक्षा हम श्री गॉडफ्रेके वादोसे नहीं, उनके जीवनक्रमसे करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

१ सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीने बनाया था। देखिए “जोहानिसबगकी चिट्ठी”, पृष्ठ २७०।

२ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ६।

२१६ गरीब किन्तु बहादुर भारतीय

कुछ गरीब भारतीय अपनी नौकरी छोड़कर भिखारी बन जानेको तयार हैं, किन्तु वे खूनी कानूनके सामने न झुकेंगे। यह बात हम अपनी जर्मिस्टनकी रिपोर्टमें दे चुके हैं। जिन भाइयोंने हिम्मतसे कानूनको ठुकराया है वे गरीब हैं, यह देखकर हम खुशीसे उछल तो नहीं पड़ते, फिर भी हम उन्हें नर वीर मानते हैं, और यदि कानूनके मामलेमें हम जीते तो उसका यश बहुत कुछ ऐसे गरीबोंको ही मिलेगा। व्यापारियोंमें जो लोग ढीले पड़ गये हैं उन्हें हम याद दिलाते हैं कि उनके व्यापारके प्रति [गोरोकी] ईर्ष्याके कारण ही सारे भारतीय समाजको दुःख उठाना पड़ रहा है। यह कानून मुरयत उन्हीं लोगोंके लिए शमनाक है। अतः उनके लिए लाजिमी है कि वे अपनी आबरूके लिए नहीं, तो देशके लिए ही अपनी टेक रखें।

परवानेके बिना व्यापारीका काम कैसे चलेगा, यह सवाल बहुत उठता है। लेकिन नौकरीसे अलग किये हुए भारतीयोंका क्या हाल होगा, यह सवाल ज्यादा भयंकर है। नौकरीको बचाना हम ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानते हैं। फिर भी हमारा कहना है कि कानूनके सामने घुटने टेकनेके बजाय नौकरी छोड़कर भूख सहन करना नौकरीके लिए अधिक अच्छा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१७. भारतीय मतदाता

“मतदाता” (वोटर) नामसे लिखनेवाले एक भारतीयका पत्र हम इस अकमें छाप रहे हैं। “मतदाता” ने जो सवाल उठाया है वह ऊपर ऊपर देखनेमें ठीक लगता है। यदि लेडी स्मिथ या डबनमें भारतीय मतदाता होते तो नगरपालिकाके सदस्य परवाने छीन नहीं लेते, यह दलील एक ही शतपर ठीक है कि मताधिकारका उपयोग करनेमें भारतीय लोग गोरोके मुकाबलेके हों। हमारा कहना है कि भारतीय ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें स्वतंत्रताका जोश नहीं है। केपमें बहुतेरे मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारका उपयोग नहीं किया। हमारे पाठकोंको याद होगा कि बम्बई जैसे शहरमें भी चुनाव दलोंने अपना स्वॉग रचा था, फिर नेटालकी तो बात ही क्या? हमें विश्वास है कि जबतक भारतीय समाजमें पश्चिमकी सच्ची शिक्षाका प्रवेश नहीं होता, तबतक हममें वह जोश नहीं आयेगा और तबतक मत-रूपी हथियार बेकार है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मताधिकार खो दिया जाये। मताधिकारसे वंचित करनेकी कारवाईके खिलाफ हमने सख्त लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम मताधिकारका उपयोग करने जाये तो वह खो जायेगा। किन्तु यदि रह जाये तो हम अवसर आनेपर उसका उपयोग कर सकते हैं। यह तलवार अभी तो म्यानमें ही शोभा देने लायक है। लेकिन लेडीस्मिथके परवानोंका

पहला ओर सरल उपाय यह है कि बिना परवानेके व्यापार किया जाये। लोगोमे जबतक इतना जोश नही आ जाता तबतक हम मताधिकारकी बात बेकार समझते है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१८ केपमें सघ

केपका सघ श्री नूरुद्दीनकी अध्यक्षतामे जोर पकडता दीखता है। उसकी बैठककी काय वाही^१ हमने दी हे। वह पढने लायक है। जिस जोशसे यह सघ चल रहा है, उसी जोशसे यदि सावजनिक काम हो, तो खूबी मालूम होगी। नेताओको यह याद रखना चाहिए कि यह समय अधिकार भोगनेका नही, लोक सेवा करनेका है। तभी हमारे आसपास जो आग सुलग रही है, वह ठडी होगी।

केपमे दो मण्डल एक ही जगह ह, सभा (लीग) ओर सघ (असोसिएशन)। हम देखते है कि इन दोनो मण्डलोके बीच गलत होड चल रही है। हमारी सलाह है कि दोनो मिलकर काम करे।

सघको हम याद दिलाना चाहते ह कि उसके सदस्योने लदन समितिके प्रति अपने कतव्यका पाला नही किया। केपकी ओरसे ५० पौड आनेकी सम्भावना थी। परन्तु वह रकम आजतक नही मिली। समिति बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और कामके हिसाबसे खच भी होगा ही। उस खचमे मदद देना दक्षिण आफ्रिकाके सभी भारतीयोका कतव्य है। हम आशा करते है कि सघ यह काम उठा लेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जनरल बोथाकी वर्षगांठ

जनरल बोथाका जन्म-दिन शुक्रवारको था, इसलिए सघ और हमीदिया इस्लामिया अजुमनने बधाईके तार भेजे थे। गोरोकी ओरसे उन्हे एक बडी भेट अर्पित की गई थी। इन तारोका भेजा जाना भारतीय प्रजाके विवेकका सूचक है। हमारे तारोसे यह सिद्ध होता है कि वे हमारे साथ याय करे या न करे, हम अपना विवेक नही खोते।

हमीदिया अजुमनकी बैठक

नियमानुसार इस अजुमनकी बैठक रविवारको हुई थी। सभा भवन खचाखच भर गया था। यदि कानूनकी लडाई सफल हुई तो उसका श्रेय अधिकतर अजुमनको ही प्राप्त होगा। मैने यहा “यदि” शब्दका उपयोग किया है, उससे किसीको डरना नही चाहिए। “यदि” का

उपयोग मैंने इसलिए किया है कि इतनी बड़ी लड़ाईमें भारतीय प्रजा अततक अपनी एकताको कायम रखकर कानूनका विरोध करती रहेगी, इसमें सामान्यतः शंका बनी रहती है। क्योंकि इस जमानेमें हमारे लिए यह नया कदम है। हमारे मनमें इस वहमने गहरी जड़े जमा रखी हैं कि कानूनकी मुखालफत नहीं की जा सकती। यदि यह वहम निकल जाये तो उसे कम उत्कष नहीं कहा जायेगा। यदि हम अततक कानूनको माननेसे इनकार करते रहे तो यही माना जायेगा कि हम छोटे छोटे थोरो बन गये हैं। थोरो कौन हैं, इसे 'ओपिनियन' के पाठक अब जानते ही होंगे।

अब हम फिर सभाका विषय ले। सभामें इमाम अब्दुल कादिर सभापतिके आसनपर विराजमान थे। मौलवी साहब मुहम्मद मुख्त्यारने प्रभावशाली भाषण दिया और जोशीले शेर पढ़कर सुनाये, जो सभी भारतीयोंपर लागू होते हैं। उनके बाद श्री रामसुंदर पण्डितने भाषण दिया। उसमें उन्होंने जर्मिस्टनकी लड़ाईका बयान किया और बताया कि उनके अनुमतिपत्रकी अवधि ३० तारीखको समाप्त हो रही है फिर भी लोगोंकी मागपर उन्होंने यहाँ रहना स्वीकार किया है। सरकार उनके अनुमतिपत्रकी अवधि नहीं बढ़ायेगी, तब भी यही रहकर वे जेल भोगेंगे। अपने कनव्यका पालन करनेमें चूकेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मिस्टनके स्वयंसेवक जोहानिसबगमें मदद देनेको तैयार हैं। श्री गांधीने बताया कि धरनेदारोंकी मददके सम्बन्धमें प्रिटोरियासे श्री बेगका पत्र आया है। श्री उमरजी सालेने जोर देकर कहा कि मुसीबत आनेपर भी वे नये कानूनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। नये कानूनके सम्बन्धमें 'गुजराती' पत्रमें एक लेख छपा था। श्री इब्राहीम कुवाडियाने वह पढ़कर सुनाया। श्री वल्लभ भाईने कहा कि कुर्मियो (कुनवियो) में से एक भी हिन्दू पीछे नहीं रहेगा। अर्जीपर करीब करीब सभी हिन्दुओंने हस्ताक्षर कर दिये हैं। श्री नवाब खाने भी भाषण दिया। सभापति महोदयने श्री बेग और श्री रामसुंदर पण्डितके तत्परता दिखाने और श्री पण्डितके जोशके लिए आभार माना। नेताओंको अर्जीपर हस्ताक्षर पूरे करवानेकी प्रेरणा देकर बैठक समाप्त हुई।

चीनियोंकी सभा

चीनी सभकी सभा भी इसी रविवारको हुई थी। उनका सभा भवन भी खचाखच भर गया था। श्री क्विन सभापति थे। श्री गांधीने कानूनके बारेमें सारी बातें समझाई और कहा कि चीनी लोग डटकर कानूनका विरोध करें।

नये कानूनके आधारपर मुकदमा

ईलू मथु नामक एक मद्रासीने नये कानूनके अतगत गुलामीका पट्टा लेनेके लिए अर्जी दी है। उसकी अर्जी ठीक न होनेके कारण पजीयकने कानूनके अनुसार प्रिटोरिया न्यायालयमें नोटिस लगवाया है कि उसे नया पजीयनपत्र न दिया जाये और वह न्यायालयमें आकर जवाब दे। कच्ची मिट्टीके घड़ोंको याद रखना चाहिए कि नये पजीयनपत्र लेनेवालोंका यही हाल होगा।

“भारतीयोंका बहिष्कार करो”

प्रिटोरियामें महिला-मण्डली इस तरहकी आवाज उठा रही है। इन महिलाओंने प्रस्ताव किया है कि भारतीय फेरीवाले और भारतीय व्यापारियोंसे किसी तरहका व्यवहार न रखनेके

सम्बन्धमे गोरी महिलाएँ आदोलन करे और गोरोसे ही माल ले। वास्तवमे हमे नये कानूनकी अपेक्षा ऐसी हलचलसे डरना चाहिए। यदि गोरे लोग भारतीयोसे सम्बन्ध तोड़ ले तो बिना कानूनके हमे यहासे जाना पडेगा। इस परिस्थितिको रोकनेका एक उपाय यही हे कि भारतीय समाज परिश्रमी बने और प्रामाणिकता बनाये रखे। साथ ही मेरा तो यह भी खयाल है कि इस समय हम जो हिम्मत दिखा रहे ह उससे खुश होनेवाली महिलाएँ नि सदेह व्यापार चालू रखेगी। किन्तु यदि हमने नामर्दी दिखाई तो वे भी तिरस्कारपूर्वक हमे छोड़ देगी। मेरी इस बातका यदि फेरीवालोको अनुभव हुआ हो तो वे समथन कर सकेगे।

कोमाटीपूरसे लौटे हुए भारतीय

इन चार भारतीयोके बारेमे श्री चैमनेको जो पत्र लिखा गया था^१ उसके उत्तरमे वे लिखते ह

मुहम्मद इब्राहीम, मूसा कारा, कारा वली और ईसा इस्माइल, इन चारोने पुतगीज देशसे होकर [ट्रांसवालमे] प्रवेश किया, इसलिए इ हे रोक दिया गया था। जहाजके टिकट नहीं थे, इसलिए इ हे डेलागोआ बे नहीं जाने दिया गया। इनके पास रहनेकी जगह न होनेके कारण जाचके समयके लिए पुलिसने एक कोठरी दी थी जो केवल गुजर-भरके लिए थी। इन लोगोको ट्रांसवालमे आनेका हक नहीं हे। इसलिए अब इन्हें चले जाना चाहिए, नहीं तो मुकदमा चलाया जायेगा।

इन चार “बहादुरोने” डबनके टिकट ले लिये हैं। इसलिए अब ये चैमने साहबको विशेष तकलीफ नहीं देगे, न अब विशेष टीकाका कारण ही रहा है।

तुर्कीकी प्रजा

जोहानिसबगमे रहनेवाले तुर्कीके कुछ मुसलमानोने मौलवी साहब अहमदकी मददसे तुर्कीके वाणिज्य दूतको एक अर्जी भेजी है। उसमे बीस व्यक्तियोके हस्ताक्षर हैं। उसका अनुवाद निम्नानुसार है^२

इस अर्जीपर तुर्कीके बीस मुसलमानोने हस्ताक्षर किये हैं।

नेसरका पत्र

श्री ईसप मियाने श्री नेसरको पत्र लिखा था। उसका उत्तर नीचे लिखे अनुसार आया है^३

आपने जो रिपोर्ट दी है वह सही है। और उस वक्तके प्रत्येक शब्दपर मैं दृढ़ हूँ। जो एशियाई यहा नियमानुसार बसे हुए हैं उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है। उनके लिए मैं पहले न्यायालयमे लड़ चुका हूँ और भविष्यमे प्रत्येक योग्य प्रसंगपर लड़नेको तैयार हूँ। लेकिन एशियाइयोके प्रवेशको मैं और अधिक जारी रखनेमे असमथ हूँ। इस प्रवेशको रोकनेमे हर तरहकी मदद देनेका मैंने निश्चय किया है। आत्मरक्षाके

१ देखिए “पत्र एशियाई पजीयकको”, पृष्ठ २२७।

२ पाठके लिए देखिए “प्रार्थनापत्र तुर्कीके महा वाणिज्य-दूतको”, पृष्ठ २६६।

३ मूल पत्र ५-१०-१९०७के इंडियन ओपिनियनके अंग्रेजी विभागमें प्रकाशित किया गया था।

लिए उतना जरूरी है। अँगुलियोकी निशानीके सम्बन्धमें क्या आपत्ति हो सकती है, यह समझमें नहीं आता। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं मालूम होती। अँगुलियोकी निशानीसे किसीकी धार्मिक भावनाको किस तरह चोट पहुँच सकती है? आप स्वेच्छया पजीयनके बारेमें बहुत कह रहे हैं। लेकिन उसमें और अनिवाय पजीयनमें क्या अन्तर है, कृपया लिखें। स्वेच्छया पजीयनमें बेकार समय जायेगा। भले लोग तो पजीयन करवा लेंगे, लेकिन बदमाश तब भी बच जायेंगे। जैसे मैं यह नहीं कह सकता कि गोरे या उनके समाजका हरएक व्यक्ति ईमानदार है, वैसे ही आप भी यह नहीं कह सकते कि आपके भी सभी लोग ईमानदार हैं।

ईसप मियाँका उत्तर

इसपर श्री ईसप मियाने निम्नलिखित उत्तर दिया है^१

आपके विवेकपूर्ण और खुले दिलसे लिखे गये पत्रके लिए हमारा सघ कृतज्ञ है। भारतीय प्रश्नका निराकरण करनेमें मुख्य कठिनाई यह है कि गोरे नेता भारतीय प्रश्नकी वास्तविकतासे परिचित नहीं हैं।

इस उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयोंके प्रति आपकी सहानुभूतिके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। उन लोगोंके लिए ही यह लड़ाई है, इसलिए आपकी और हमारी लड़ाई मिलती जुलती है।

भारतीय बड़ी सख्यामें प्रवेश करें, इसपर आपने आपत्ति प्रकट की है, जिससे सघको सहानुभूति है। गोरे आब्रजनके विरुद्ध हैं, इसलिए इस आपत्तिके सम्बन्धमें हमें कुछ कहना नहीं है। और इस विषयमें सघ हमेशा सरकारको मदद देनेको तैयार है।

अब हम एशियाई कानूनके गुण दोषोंका विवेचन करें। सितम्बर १९०६ को जब एशियाई कानून बनाया गया था तब अँगुलियोकी निशानीकी बात नहीं थी। अँगुलियोकी निशानीकी जगह यदि हस्ताक्षरकी बात की जाती तो भी सघ कानूनका विरोध करता। हमें जो चीज चुभती है, और जिससे वेदना होती है वह यह है कि कानून हमें पजीकृत होनेके लिए मजबूर करता है। अँगुलियोकी निशानी देनेसे हमारी धार्मिक भावनापर चोट नहीं पहुँचती। किन्तु यह कानून तुर्कीके यहूदियों और ईसाइयोंपर लागू नहीं होता, इस धार्मिक भेदभावसे हमारी भावनाको चोट जरूर लगती है।

कानूनमें विधिवत् शर्तें बनाई गई हैं। उनके भग होनेपर हर बातके लिए सख्त सजा रखी गई है। ऐसी सजाओंसे कानून भरा हुआ है। लेकिन हम जो विरोध करते हैं, वह इसलिए कि आप भारतीय प्रजाके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो वह बदमाश समाज हो, ठग हो, उसने अनुमतिपत्रोंकी बदला बदलीका धधा ही उठा रखा हो और गैरकानूनी तरीकेसे लोगोंका प्रवेश कराता हो। भारतीय समाजका विरोध इससे है, और वह बिल्कुल वास्तविक है। सामान्यतः, सख्त सजाएँ रखनेका अर्थ ही यह होता है कि ऐसे अधम अपराध होते हैं। भारतीय समाज ऐसे अपराध करनेका धधा नहीं करता, और इसलिए बदमाशोंमें शरीक किये जानेपर वह उसके विरुद्ध लड़ता है। दूसरी बात यह भी याद रखनी चाहिए कि यह अधम कानून सिर्फ

१ मूल अंग्रेजी पत्रके हिन्दी अनुवादके लिए देखिए “पत्र जे० प० नेसरको”, पृष्ठ २६२-६४।

भारतीयोंके लिए ही बनाया गया है। मलायी लोगोके साथ बहुत से भारतीयोंका सम्बन्ध है, रगदार लोगोके साथ उनका स्नेहभाव है, काफ़िरोको वे अपने यहाँ नौकर रखते हैं। एशियाई कानून उपयुक्त सभी लोगोकी नज़रमें भारतीयोंको नीचे गिराता है। उपनिवेशमें दूसरे लोगो तथा मलायी, रगदार और काफ़िरोपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, सिर्फ़ भारतीयोंको उनकी बदनामी करनेके लिए अलग किया गया है।

अन्तिम आपत्तिका उत्तर एशियाई प्रतिस्पर्धाका डर है। यह स्पष्ट है। इस बातको मेरा सघ स्वीकार करता है और इसलिए कहता है कि हम स्वेच्छया पजीकृत होंगे, या अपनी अँगूठा निशानी या शिनारत देगे। इससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, गोरोका काम हो जायेगा और यहाँके निवासियोंको सरक्षण मिल जायेगा। आपकी यह मायता मालूम होती है कि स्वेच्छया पजीयनसे झूठे प्रवेशकर्त्ताओपर अकुश नहीं लगता। ऐसे लोगोके अस्तित्वको स्वीकार करनेसे मेरा सघ इनकार नहीं करता। लेकिन आप जो मानते हैं कि ऐसे लोग बच जायेगे, यह भूल है। क्योंकि जो स्वेच्छया पजीकृत नहीं होते उनपर आप नया कानून लागू कर सकते हैं। इसके अलावा एक निश्चित अवधिके बाद सबके प्रमाणपत्र एक साथ भी देखे जा सकते हैं। उस वक्त जिसके पास नया पजीयनपत्र न हो, उसे प्रवासी अधिनियमके अंतर्गत उपनिवेशके बाहर निकाला जा सकता है।

अतमें मैं इतना कहता हूँ कि उचित शिकायतोंके सम्बन्धमें मेरे देशभाइयोंने गोरोकी इच्छाके अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है, जबकि गोरोने भारतीयोंका असन्तोष दूर करनेके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आखे मूढ़कर भारतीयोंका विरोध करना ही अपना कतव्य समझा है। भारतीय क्या चाहते हैं, उन्होंने इसे जानने तक की परवाह नहीं की। आप अपने धंधेके कारण भारतीयोंके सम्पर्कमें काफ़ी आये हैं तो क्या आप जरा इस मामलेमें पडेगे? हमारी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्रश्नको देखेंगे? इस प्रकार छानबीन करके देखिए कि जरा धैर्य और परस्पर सहायतासे समझौता किया जा सकता है या नहीं।

झूठे गवाहोंकी सूचना

जोहानिसबगमें श्री वेडरबगके पास पांच भारतीयोंपर एक लूटका मुकदमा चला था। उसमें फरियादी तथा कुछ दूसरे भारतीयोंने जो गवाही दी वह मजिस्ट्रेटको झूठी मालूम हुई। इसपर उसने गवाहोंको फटकारा और अभियुक्तोंको बिना जाच किये छोड़ दिया। उसने खुली अदालतमें, जहाँ बहुत से भारतीय थे, सबसे कहा कि आजकल भारतीयोंमें झूठे मुकदमें बहुत होते हैं। यदि ऐसे मुकदमें फिर लाये गये तो झूठी गवाहीके लिए मुकदमा चलाया जायेगा। इस बातको प्रकाशित करते हुए मुझे दुःख होता है। लेकिन इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूँ। इस तरहके मुकदमोंसे भारतीयोंकी इज्जत जाती है, और हम दूसरोंकी नज़रमें गिरते हैं। मेरा खयाल है कि गवाह तो खिलाडियोंके हाथके मोहरे थे, सच्चे गुनहगार खिलाडी हैं। उनसे मुझे कहना है कि थोड़े से पैसोंके लालचमें गरीबोंको बरबाद करना और अपने साथ अपने समाजको भी कलंकित करना शोभा नहीं देता। झूठे मुकदमें बनाकर कमाई करनेके बजाय कमाईके और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं।

अनुमतिपत्र खो जानेपर क्या किया जाये ?

एक भाईने यह प्रश्न पूछा है। इसका उपाय आसान है। और वह है, बिना अनुमति-पत्रके घूमे-फिरे। जेलका डर रहा नहीं, इसलिए यदि मजिस्ट्रेटके पास खड़ा किया जाये तो बेधड़क जाये। जाँच होनेपर उन्हें छोड़ दिया जायेगा। अंतिम नोटिस निकल जानेके बाद वतमान अनुमतिपत्र खोयेके समान हो जायेगा, क्योंकि पुराना अनुमतिपत्र दिखानेसे कोई किसीको छोड़नेवाला नहीं है। इसलिए नये कानूनका विरोध करनेवाले अनुमतिपत्र खो जानेका डर क्यों रखे ?

नई बला

स्वण कानून (गोल्ड लॉ) के अन्तर्गत व्यापारका परवाना नहीं दिया जा सकता, इस तरहका एक मुकदमा चल रहा है। मेरा खयाल है, सरकार ऐसा मुकदमा चलाकर सरासर गलती कर रही है। यह मामला उच्च न्यायालयमे ले जाया जायेगा, इसलिए इसके बारेमे विशेष कहना अनावश्यक है। सरकार स्वण कानून लागू करना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस नये कानूनके सामने घुटने टेकनेवालोके लिए चैन नहीं है। लेकिन यदि यह खूनी कानून गया तो मेरे विचारमे स्वण-कानून अपने आप मर जायेगा।

स्मट्सका उत्तर

प्रिटोरियाके कुछ लोगोंने गुलामीकी अर्जी दी थी और श्री स्मट्सने उसका उत्तर भी ऐसा ही दिया है जो गुलामोको फबे। उन्होंने कहा है कि जो एशियाई कानूनके अनुसार चलेंगे उनकी बेडीकी जाँच काफिरोंकी जगह गोरे करेंगे। शेष बातें स्वीकार नहीं की जा सकती। सम्भव हुआ तो अगले सप्ताहमे उस उत्तरका पूरा अनुवाद दूंगा। वह जानने योग्य है। आशा है, उसके साथ जोहानिसबर्गके आंदोलनकी और भी महत्वपूर्ण बातें दूंगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२२० पत्र मगनलाल गाधीको

[जोहानिसबर्ग]

अक्टूबर ६, १९०७

चि० मगनलाल,

मने श्री बद्रीके^१ कागजपत्र अब खोज लिये हैं। उन्होंने श्री लोगनसे जो जायदाद खरीदी थी उसका पंजीयन हो चुका था और हस्तांतरणका दस्तावेज मेरे पास है। क्या वे यही चाहते थे ? पता लगाकर मुझे लिखो।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४७६७) से।

१ देखिए “जोहानिसबर्गकी चिट्ठी”, पृष्ठ २८४।

२ गांधीजीके एक मुवक्किल। देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४५०।

२२१ पत्र उपनिवेश सचिवको

जोहानिसबग

अक्टूबर ७, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरे सघकी समितिते मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपके उस भाषणके बारेमे आपको अत्यंत विनयपूर्वक कुछ शब्द लिखू जो आपने अपने निर्वाचकोके सामने दिया था और जिसमे आपने एशियाई कानून सशोधन अधिनियमका उल्लेख किया था। यदि पत्रोमे छपा हुआ विवरण ठीक है तो मेरी नम्र रायमे उसमे तथ्योंके सम्बन्धमे कई गलत बयानिया है।

मेरे सघको इस बातसे बहुत दुःख पहुँचा है कि आप एक ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदपर आसीन होकर भी मदीके कारणके बारेमे जन साधारणमे प्रचलित भ्रांतिका ही प्रचार करे। व्यापार करनेवाले इस बातको जोर देकर कह चुके हैं कि इस भारी मन्दीका कारण कुछ और है। कुछ भी हो, उसका प्रभाव भारतीयोपर उतना ही पडा है जितना यूरोपीयोपर।

मेरा सघ इस वक्तव्यका पूर्णतया खण्डन करता है कि इस समय उपनिवेशमे १५,००० भारतीय हैं। मेरे सघको अकोका जो विश्लेषण प्राप्त हुआ है, वह शीघ्र ही आपको भेज दिया जायेगा। उससे आपको पता चलेगा कि इस समय ट्रांसवालमे ७,००० से अधिक भारतीय नहीं हैं।

आपने यह कहनेकी कृपा की है कि पुराने कानूनके अतगत जो प्रमाणपत्र जारी किये गये थे उनकी दूसरी जाली प्रतिया तैयार करके उनको बेचा गया है और बम्बई, जोहानिसबग और डबनमे ऐसे स्थान मौजूद हैं जहा ऐसे जाली प्रमाणपत्र अमुक रकम देकर खरीदे जा सकते हैं। मेरा सघ आपके इस वक्तव्यका पूरी तरह खण्डन करता है और विनयपूर्वक निवेदन करता है कि इस मामलेकी सावजनिक जाच की जाये। किन्तु मेरे सघको इस बातका पता है कि पजीयन कार्यालयका एक मुशी जाली अनुमतिपत्रोका व्यवसाय करता था और उसने नि सदेह कुछ भारतीयोको, जिनको न तो अपनी राष्ट्रीयताका और न अपने सम्मानका ध्यान था, अपना साधन बनाया। परन्तु वह बात, आपने जनताके सामने जो कुछ रखा है उससे, बिल्कुल अलग है।

आपने यह भी कहनेकी कृपा की है कि भारतीयोने अँगुलियोके निशानोके कारण इस अधिनियमका विरोध किया है। मेरा सघ सरकारसे कई बार निवेदन कर चुका है कि भारतीयोके विरोधका मौलिक कारण अँगुलियोका निशान नहीं, बल्कि अनिवायताका सिद्धान्त तथा कानूनका वह सम्पूर्ण उद्देश्य है जो भारतीयोको अपराधी करार देता है। इस कानूनके खिलाफ जब पहले-पहल एतराज पेश किये गये थे तब अँगुलियोके निशानोका जिक्र तक नहीं किया गया था। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय ट्रांसवाल आये हैं उनसे भारतमे

कभी भी न तो अँगुलियोके और न ही अँगूठोके निशान लगवाये गये थे। भारतमे निश्चय ही कुछ मामलोमे अँगूठोके निशान लिये जाते ह, किंतु उनका सम्बन्ध अपराधोसे नहीं होता। अँगुलियोके निशान केवल अपराधियोसे अथवा उनसे ही लिये जाते हैं, जिनका अपराधोसे कोई सम्बन्ध होता है। अँगूठोका निशान जहा लिया जाता है वहा वह नियम केवल निरक्षरोपर ही लागू होता है।

मेरे सचको सरकारकी इस इच्छाका हमेशा ही पता रहा हे कि वह इस कानूनको पूरी तरह और कठोरतासे अमलमे लाना चाहती हे। किंतु मुझे एक बार फिर यह कहनेकी अनुमति दी जाये कि इस कानूनके सामने झुकने तथा सोच विचार कर की गई अपनी शपथको तोडनेसे हमारे समाजका जो पतन होगा, उसके मुकाबले कानूनका कठोरसे कठोर प्रशासन भी कुछ नहीं है। मेरा सच यह अनुभव करता है कि यद्यपि आपने यह घोषणा कर दी है कि आपने इस प्रश्नके भारतीय दृष्टिकोणका विशेष रूपसे अध्ययन किया है, फिर भी विरोधकी मूल भावना और साथ ही मेरे सच द्वारा उठाये हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दोपर आपने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया।

अन्तमे मैं इस बातको फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि भारतीयोके अत्यधिक सख्यामे आब्रजन तथा व्यापारमे अनियन्त्रित प्रतियोगिताके विरुद्ध आपके एतराजकी मेरे सघने सदा ही कद्र की हे। और समाजकी नेकनीयती प्रकट करनेकी दृष्टिसे उसने विनम्रतापूर्वक ऐसे प्रस्ताव पेश किये हैं, जिनसे दोनो एतराज दूर हो जाये। किन्तु, भारतीयोके लिए यह असम्भव हे कि वे इस कानूनको स्वीकार कर अपना रहा सहा सम्मान भी खो बैठे, क्योंकि यह कानून सही वस्तु-स्थितिसे अनभिज्ञताके कारण बनाया गया है, कायरूपमे एक हद तक दमनकारी है और मेरा सच जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है उसकी धार्मिक भावनाओको चोट पहुँचाता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२२ पत्र 'रैंड डेली मेल' को

जोहानिसबग

अक्टूबर ९, [१९०७]

सेवामे

सम्पादक

['रैंड डेली मेल']

जोहानिसबग]

महोदय,

आपने श्री सुलेमान मगा^१ तथा पूनिया^२ नामक एक भारतीय महिलाके, जिनके साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया था, मामलोको उत्साहपूर्वक उठा लेनेकी कृपा की थी। मैं आपका ध्यान एक तीसरे मामलेकी ओर आकर्षित करता हूँ, जो मेरे देखनेमें आया है। इस मामलेमें जो अकारण अपमान किया गया है, वह पहले दोनों मामलोसे अधिक नहीं, तो कम भी नहीं है।

श्री ए थनी पीटस जन्मत भारतीय ईसाई और नेटालके एक पुराने सरकारी नौकर ह। इस समय वे पीटरमरित्सबगके मुख्य न्यायाधीशकी अदालतमें दुभाषियेका काम कर रहे ह। रविवारकी बात है, वे शनिवारको पीटरमैरित्सबगसे चलनेवाली जोहानिसबग मेलसे जोहानिसबग जा रहे थे। उनके पास रियायती टिकट और रेलवेकी ओरसे मिला हुआ एक प्रमाणपत्र था, जिसमें उनके सरकारी पदका विवरण था। फोक्सरस्टमें जाच करनेवाले पुलिस-अधिकारीने उनसे कड़ी जिरह की। श्री पीटसने अपना अनुमतिपत्र दिखलाया, जो उन्हें भारतीयाके स्वेच्छया अँगूठा निशान देनेसे पहले दिया गया था। इससे अधिकारीको सन्तोष नहीं हुआ। अतः श्री पीटसने वह रियायती टिकट दिखलाया, जिसका मने उल्लेख किया है, अपने हस्ताक्षर देनेका प्रस्ताव किया, किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। और अधिकारीने उनका यह कहकर अपमान किया कि शायद आप और किसीका रियायती टिकट लेकर आये हैं। इसपर श्री पीटसने अपनी छड़ी तक दिखलाई, जिसपर उनके नामके प्रथम अक्षर अंकित थे। फिर, उन्होंने अपनी कमीज भी दिखलाई, जिसपर उनका पूरा नाम था। किन्तु यह भी सन्तोषजनक नहीं समझा गया। तब उन्होंने तीन दिन बाद लौटनेकी जमानतके लिए रुपया जमा करनेका प्रस्ताव किया, किन्तु अधिकारीने एक काफिर पुलिसको आज्ञा दी कि वह श्री पीटसको अक्षरशः डिव्बेसे बाहर घसीट ले। जब श्री पीटसको सार्जेंट मैसफील्डके सामने पेश किया गया तो उसने उस भयंकर गलतीको अनुभव करते हुए माफी मागी और उनको छोड़ दिया। लेकिन इतनेसे ही भला सन्तोष कैसे होता ? इस अपमानके अलावा उन्हें फोक्सरस्टमें, जहाँ वे किसीका जानते नहीं थे, लम्बी तथा थका देनेवाली प्रतीक्षा करनी पड़ी और साथ ही उनकी तीन दिनकी छोटी सी छुट्टीका भी बड़ा सा हिस्सा बेकार गया। श्री पीटस आज रातको नौकरीपर लौटेंगे। इस घटनाके बारेमें मुझे टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल यही कहना है कि इस देशमें

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २८८ ८९ और २९४।

२ वही, पृष्ठ ४६३ ६४।

यात्रा करनेमें भी अनेक सम्मानित भारतीयोंको जो-कुछ सहन करना पड़ता है, यह उसका एक नमूना है। यहा साधारण कानून बनानेका प्रश्न नहीं है, एशियाइयोंका बड़ी सख्यामें आनेका भी प्रश्न नहीं है, बल्कि मनुष्य और मनुष्यके बीचमें साधारण शिष्टता तथा 'यायका' प्रश्न है। अथवा, 'ग्लासगो हेरल्ड' में उस दिन लिखनेवाली श्रीमती वाँगलके शब्दोंमें, क्या रगदार चमड़ी होना ट्रान्सवालमें श्वेत लोगोंके विरुद्ध जुम है ?

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

रड डेली मेल, १०-१०-१९०७

२२३ केपके भारतीय

केपके सर्वोच्च न्यायालयमें प्रवासी कानूनसे उत्पन्न एक महत्त्वपूर्ण परीक्षाणात्मक मुकदमेकी सुनवाई हुई थी, जिसका विवरण^१ 'केप टाइम्स' ने प्रकाशित किया था। कुछ विलम्ब हो जानेपर भी हम उसे इस अकमें अग्रत उद्धृत कर रहे हैं। केपकी ससदमें जब प्रवासी अधिनियम पास किया जा रहा था उस समय वहाके प्रमुख भारतीयोंने जो सुस्ती दिखाई उसपर हम पहले भी खेद प्रकट कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि फरियाद की जाती तो इस प्रकारके कानूनमें निश्चय ही काफी सशोधन कर दिया जाता। यद्यपि मुकदमेके तथ्योंको उक्त विवरणमें पूरी तरहसे दिया गया है, तथापि हम दुबारा उनको यहां दे रहे हैं। केपमें बसा हुआ एक भारतीय, जिसकी वहा कुछ जमीन जायदाद थी, और जो १८९७ से वहा सामान्य विक्रेताका रोजगार करता था, भारत जाना चाहता था, और भारतसे लौटते समय होनेवाली असुविधासे बचनेके इरादेसे एक निश्चित अवधि तक उस उपनिवेशसे अनुपस्थित रहनेका अनुमतिपत्र चाहता था। प्रवासी अधिकारीने ऐसा अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया और ऐसा अनुमतिपत्र देना चाहा जिसकी अवधिका निश्चय वह स्वयं करता। यहा प्रश्न यह नहीं है कि प्रवासी-अधिकारीका निणय उचित था या नहीं, क्योंकि एक ओरसे अधिकार पानेका तथा दूसरी ओरसे उसे न देनेका प्रयत्न किया जा रहा था। प्रवासी अधिकारीका कहना था कि एक एशियाईको उपनिवेशसे अनुपस्थित रहनेका अनुमतिपत्र देना एक रियायत है। किन्तु एशियाईका कहना था कि यह उसका अधिकार है। अब सर्वोच्च न्यायालयने यह निणय दिया है कि कानूनके अनुसार एशियाइयोंको अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र पानेका निहित अधिकार नहीं है। सारांश यह कि यह मामला निरा स्वाग है, क्योंकि इससे एशियाइयोंको दासताकी अवस्थामें पहुँचा दिया गया है, जिसके लिए वहाके प्रमुख भारतीयोंके अलावा और किसीको दोष नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, दलीलोंमें उठाया गया सबसे दिलचस्प मुद्दा अनिश्चित ही छोड़ दिया गया है। प्रवासी अधिनियमकी पहली धारा १९०२ के प्रवासी अधिनियमके द्वारा दिये गये अधिकारोंकी रक्षा करती हुई

मालूम होती है, जिसे उक्त अधिनियमने मसूख कर दिया है। इसमें कहा गया है कि

इस मसूखीका इस अधिनियमके लागू होनेके समय पूरे किये गये अथवा शुरू किये गये कामो, किहीं अधिकारो, सुविधाओ या प्राप्त सरक्षणो, किही सजाओ या देनदारियोकी जिम्मेदारी, किही वतमान नियोग्यताओ, किसी किये हुए अपराध अथवा की हुई कायवाहीपर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

इधर, १९०२ का अधिनियम ४७ दक्षिण आफ्रिकामे आकर बसनेवाले दूसरे लोगोके साथ एशियाइयोके अधिकारोकी भी रक्षा करता था। इससे ऐसा लगता है कि १९०२ से पहले केपमे, या दक्षिण आफ्रिकामे भी, बस जानेवाले भारतीयोके अधिकारोपर १९०६ के अधिनियमका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। 'यायमूर्ति' मैसडापने साफ कहा कि उस भारतीयके सम्बन्धमे ही यह मुद्दा उठाया जा सकता है और उसका फैसला किया जा सकता है जो १९०२ से पूर्व केपका निवासी रहा हो और अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र लिये बिना केपसे बाहर जाकर फिर वहा वापस आये। यह बहुत ही सहज है और हमारा विश्वास है कि केपमे रहनेवाले भारतीय अपने इस अधिकारकी परीक्षा करा लेनेमे समय न खोयेंगे। अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र जारी करनेकी प्रथा अत्यधिक दमनकारी है, और वह नि सदेह उस स्वतन्त्रतामे हस्तक्षेप करती है, जिसका हर आजाद आदमीको अधिकार है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२४ 'इंडियन ओपिनियन' के बारेमें

हमारे पाठकोने देखा होगा कि हम गुजरातीमे पहले चार पष्ठ देते थे, फिर आठ हुए, उसके बाद बारहपर पहुँचे, और कुछ सप्ताहसे तेरह, चौदह और पंद्रह पष्ठ चल रहे हैं। अब हमने हमेशा सोलह पष्ठ देनेका इरादा किया है। सम्भव है, कभी किसी असुविधाके कारण इतने न दिये जा सके। इस तरह कलेवर बढ़ानेसे खर्च बढ़ता जाता है। फिर भी हम विचार बदलनेवाले नहीं ह, क्योंकि हमारा हेतु सेवा करके अपनी रोटी कमाना है। मुरय उद्देश्य है सेवा करना। कमाई उसके बाद है। 'इंडियन ओपिनियन' जबसे शुरू हुआ है^१ तबसे आजतक इससे मालदार बननेका लक्ष्य न तो किसीका रहा, और न आगे रहेगा। इसलिए आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही पाठकोको फायदा पहुँचे, इसकी हम व्यवस्था करना चाहते हैं। इस पत्रमे काम करनेवालोकी आमदनी एक सीमा तक पहुँचनेके बाद जो-कुछ भी रकम बच रहेगी, और ऐसी बचतका समय आयेगा तो, वह सब रकम सावजनिक कायमे खर्च की जायेगी।

हमारी निश्चित मान्यता है कि 'इंडियन ओपिनियन' की बिक्रीमे जितनी वृद्धि होगी, उतनी ही हमारी शिक्षा और स्वाभिमानमे वृद्धि होगी। फिलहाल 'इंडियन ओपिनियन' के ग्राहक सिर्फ ग्यारह सौ हैं, यद्यपि उसके पाठकोकी संख्या बहुत ज्यादा है। यदि सभी पाठक

अपनी अपनी प्रति ले तो 'ओपिनियन' आज जितनी सेवा कर रहा है उससे तिगुनी ज्यादा सेवा कर सकता है। हम जिस तरह पण्डसख्या बढ़ाते हैं उसीके अनुपातमें प्रोत्साहन भी चाहते हैं, यह ज्यादा तो नहीं माना जायगा। जो इस पत्रकी कीमत पूरी तरहसे जानते हैं, वे यदि एक एक ग्राहक बना दे तो भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और पण्ड बढ़ानेसे जो खर्च बढ़ता है, उसमें मदद मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२५ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

इस समितिको अब एक वर्ष पूरा हो रहा है।^१ इसे दूसरे वर्ष चालू रखा जाये या नहीं, यह दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर निर्भर है। श्री रिचने यह सवाल उठाया है। उनके पत्रकी ओर हम प्रत्येक भारतीयका ध्यान खींचते हैं।

समितिने काम बहुत किया है और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ है, इस बातको प्रत्येक भारतीय समझ सकता है। अभी हमारी नाव बीच समुद्रमें है। इस बीच समितिको तोड़ना हम नावको डुबानेके समान मानते हैं।

समितिके कामसे केवल ट्रान्सवालको ही नहीं, समूचे दक्षिण आफ्रिकाको लाभ है। फ्रीडोमके कानूनका लाभ केवल जोहानिसबर्ग ही भोगेगा सो बात नहीं। उस कानूनमें जो परिवर्तन हुआ और जनमतपर जो असर पड़ा है उसका लाभ सबके लिए समझना चाहिए। नये कानूनकी लड़ाईकी सफलतामें समस्त भारतीयोंका लाभ समाया हुआ है। समितिने बस इतना ही नहीं किया है। नेटालका नगरपालिका कानून रद्द सा है। उसका श्रेय समिति ही ले सकती है। परवानेके सम्बन्धमें समिति अभी लड़ रही है। डेलागोआ बेंके बारेमें, हमारा विचार है, समितिकी लिखा-पढ़ीका असर हुआ है। और यदि केपके भारतीयोंकी नींद खुल जाये तो उनके कानूनके लिए भी समिति लड़ सकती है।

समितिमें कई प्रसिद्ध लोग हैं। लेकिन यदि उसका काम करनेवाले श्री रिच न हो तो वह चल ही नहीं सकती। सर मचरजी भावनगरी बहुत परिश्रम करते हैं। परन्तु यह काम उनके बहुत से कामोंमें एक है। श्री रिचका तो सारा समय समितिके काममें ही जाता है। इसलिए उनके बिना समितिको चलाना मुश्किल होगा। उनका दक्षिण आफ्रिका लौट आनेका समय आ गया है, फिर भी जान पड़ता है कि वे वहां रुकनेमें खुश हैं।

अब खर्चके सम्बन्धमें विचार करें। समितिकी स्थापनाके समय हमने कमसे कम ३०० पौंड खर्चका अनुमान लगाया था। लेकिन काम इतना बढ़ गया कि समितिको जो ५०० पौंड भेजे गये वे भी कम पड़े। इतने खर्चमें भी काम इसलिए चल गया कि श्री रिचने नाममात्रको वेतन लिया है। वे तो वह भी न लेते, लेकिन उनके लिए और कोई चारा नहीं था। अब हमें उनका पूरा खर्च उठाना चाहिए। यानी उनके हिसाबसे एक वर्षका खर्च १,००० पौंड होगा। यदि समिति पूरी ताकतसे एक वर्ष काम करे तो ५०० पौंड उसके लिए मानना चाहिए

१ यह नवम्बर, १९०६ में स्थापित की गई थी, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २४३ ४४।

और ५०० पौड श्री रिचको देनेके लिए। इस तरह हिसाब लगानेसे १,००० पौड होते हैं। फुटकर खचमे कटौती की जा सकती है, किन्तु श्री रिचके खचमे नहीं, क्योंकि उतना खच तो विलायतमे सहज ही हो जाता है।

यह प्रश्न हर भारतीयके लिए विचार करने योग्य और हर सघके लिए हाथमे लेने योग्य है। समितिका खच दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक हिस्सेसे पूरा किया जाना चाहिए।

यदि केप, रोडेशिया, डेलागोआ बे, नेटाल और ट्रांसवाल मिलकर इतना खच उठा ले तो अधिक नहीं होगा। इतना खच किया जानेपर भी सामायत ऐसी समिति, और ऐसा काम मिल नहीं सकता। श्री रिच समितिके कामको वेतन भोगी नौकरकी तरह नहीं, बल्कि अपना काम समझकर करते हैं, इसलिए उपयुक्त रकमसे काम चल सकता है।

इस सम्बन्धमे पाठकोके जो भी विचार सक्षेपमे आयेंगे, उन्हें प्रकाशित किया जायेगा। यदि कोई इस सम्बन्धमे पैसे भेजना चाहे तो हम स्वीकार करेंगे। भेजनेवालोको आखिरमे सघकी रसीद मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२६ स्मट्सका भाषण

श्री स्मट्सने प्रिटोरियामे जो भाषण दिया उसका पूरा अनुवाद हमने अपनी जोहानिस-बर्गकी चिट्ठीमे दिया है। वह बहुत ही पढ़ने व विचार करने योग्य है। श्री स्मट्स बड़े गवसे बोले ह। किन्तु ईश्वर किसीका गव टिकने नहीं देता। वही हाल श्री स्मट्सके गवका होना सम्भव है।

उन्होंने जितना गव किया है उतना ही उनका अज्ञान है। श्री ईसप मियाने उन्हें समुचित उत्तर दे दिया है, यह देखकर हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री स्मट्स ऐसे बोलते ह, मानो ब्रिटिश सरकारकी उनके मनमे कोई बिसात नहीं। उनके इन शब्दोका, सम्भव है, उदारदलीय पक्ष भी विरोध करेगा — यद्यपि हमे इसकी कुछ भी परवाह नहीं कि वह पक्ष उनका विरोध करता है या नहीं करता।

श्री स्मट्सके अज्ञानके उदाहरण ले। उनका कहना है कि हम लोग अँगुलियोकी छापके सम्बन्धमे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात बिल्कुल बेहूदा है। यह ठीक है कि अँगुलियोकी छापकी बात भी एक प्रश्न है, लेकिन हमारी लड़ाई उसीपर आधारित नहीं है। लड़ाईका मुख्य कारण यह है कि यह कानून हमे अपराधी और झूठा मानकर हमारे व्यक्तित्वपर हमला करता है, हमे गोरे तथा अय काले लोगोके सामने गिराता है और निर्माल्य समझकर हमे कुचल देना चाहता है। इन सब बातोको नजरअंदाज कर, केवल अँगुलियोकी छापकी बातपर जोर देकर, श्री स्मट्स हमारा मजाक उड़ाते हैं और गोरोको हसाते हैं। इस असत्य तथा अन्य आरोपोका श्री ईसप मिया तीखे शब्दोमे श्री स्मट्सको जवाब दे चुके हैं। उन्होंने हमपर यह आरोप लगाया है कि बम्बई, जोहानिसबर्ग तथा डबनमे झूठे अनुमतिपत्र बेचनेके लिए भारतीय कार्यालय चल रहे हैं। यह छोटी मोटी बात नहीं है।

परन्तु हमारे लिए श्री स्मट्सकी इस सरासर झूठकी अपेक्षा उनके विचार अधिक समझ लेने योग्य है। श्री स्मट्सके कथनसे हम समझ सकते हैं कि यह सारा आक्रमण व्यापारियोपर है। भारतीय व्यापारी उनकी आखोमे खटकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे व्यापारियोकी बस्तीमे ही भेजेगे। चाहे जितनी मुसीबते भोगनी पडे, वे ट्रांसवाल केवल गोरोके लिए ही रखना चाहते हैं। इस समयकी व्यापारिक मन्दीका दोष भारतीय व्यापारियोपर थोप रहे हैं, और जबतक भारतीय व्यापारियोकी जडे नहीं उखाड देगे तबतक वे चैन नहीं लेगे। वे समझते हैं कि यदि हम लोग इस कानूनको मान ले तो फिर उहे जो कुछ करना हो वह कर सकेगे। जबरदस्त टक्कर लेकर और शपथे खाकर यदि हम सो जाये तो फिर लात मारना आसान है। इससे खासकर व्यापारियोको समझ लेना चाहिए कि यदि व्यापारीपजीवन करवायेगे तो उनका दोहरा नुकसान होगा। उनकी प्रतिष्ठा जायेगी, उहे भारतीय धिक्कारेगे और हाथ मुँह घिसनेके बाद भी उन्हें बस्तीमे जाकर बरबाद होना पडेगा। यदि वे दृढ रहकर लडेगे तो उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और प्रतिष्ठा ही सच्चा धन है। इतना ही नहीं, दृढ रहनेसे लडाई जीतनेकी पूरी सम्भावना है। अर्थात् उनका व्यापार बच जायेगा। बचनेका एक ही रास्ता है और वह है कानूनके खिलाफ जूझना। अन्यथा हम आजसे ही मरे हुए हैं।

फिर, श्री स्मट्सके शब्दोको हम धमकीके रूपमे ही लेते ह। जो करता है वह बकता नहीं। काटनेवाला कुत्ता भौकता नहीं। फन उठानेवाला साप डसता नहीं केवल फुफकारता है। श्री स्मट्स एक ओर तो कहते हैं कि दिसम्बर महीनेमे प्रत्येक भारतीयको निर्वासित करेगे, दूसरी ओर कहते ह कि जनवरीमे परवाने छीनकर दूकाने बन्द कर देगे। इसमे सच क्या है? यदि दिसम्बरमे सबको निकाल बाहर करेगे तो फिर दुकाने किसकी बंद करेगे? ऐसे शब्द तो क्रोधका मारा पागल मनुष्य ही बोलेगा। फिर, निर्वासित करनेकी सत्ता तो उनके हाथमे आई नहीं है, पहले ही निर्वासित करनेकी धौंस दे रहे हैं। इसे हम बच्चोका खेल समझते हैं। आखिर निर्वासित करे और जेलमे बंद कर दे, इसका डर उसे क्यों लगेगा जिसने अपनी प्रतिष्ठाको श्रेयस्कर माना है? और अन्तमे भारतीय समाजको खुदापर भरोसा है, इसलिए वह हजार स्मट्सोसे भी नहीं डरेगा।

श्री स्मट्स एक ही बातकी रट लगाये जा रहे ह, किन्तु दूसरी ओर, हम देख रहे ह कि, इंग्लैडमे हमारा समर्थन बढ़ता जा रहा है। मंगलवारके तारोसे ज्ञात होता है कि काले मनुष्योकी सरक्षक समिति और नैतिक समिति सघने मिलकर प्रस्ताव किया है कि एशियाई कानून बुरा है और इस सम्बन्धमे भारतीय सरकार, उपनिवेश मन्त्रालय तथा ट्रांसवालकी सरकारको नरमीसे काम लेना है। ये सब समितिया और सारे ससारके समाचारपत्र हमारे पक्षमे ह। इसके सामने श्री स्मट्स चाहे जितना जोर करे और चाहे जितना धमण्ड करे, उनसे क्या होना है? जिसका खुदा रक्षक है उसका भक्षण किस इन्सानके बूतेका है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२७ वाईबर्गका भाषण

श्री वाईबर्गने ब्लूमफाटीनमे जो भाषण दिया है उसका साराश^१ हमने अयत्र दिया है। श्री वाईबर्गने कहा है कि गोरोको यदि उन्नति करनी है तो काले लोगोको बिलकुल अलग देशमे रखा जाये, जिससे गोरोका कालोसे जरा भी ससग न हो। यह कहना आवश्यक नहीं है कि काले लोगोको अलग निकाल देनेमे एशियाइयोका अलग किया जाना भी शामिल है। श्री वाईबर्गके शब्दोमे ऐसा अर्थ समाया हुआ है। भारतीय लोग गोरोसे अधिक सभ्य ही नहीं हैं, उनसे बहुत ही प्राचीन सभ्यताका दावा करते हैं। श्री वाईबर्गको स्वाथवश इस बातका खयाल तक नहीं। इसलिए स्पष्ट रूपसे कहा जाये तो इसका अर्थ यह होता है कि यदि श्री वाईबर्गका वश हो तो कल सबेरे वे भारतीयोको अकेले रहनेके लिए रवाना कर देगे। वे या उनके अर्थ साथी इस कामको कर सकेंगे या नहीं, यह बहुत कुछ इसपर निर्भर है कि भारतीय इस समय कितना बल दिखाते हैं। यदि वर्तमान लडाईमे भारतीय पीछे हट गये तो गोरो उन्हें बेदम समझकर अलग रहनेके लिए निकाल देगे, इसकी भनक अभीसे सुनाई पड रही है। तब क्या भारतीय इस स्थितिको समझकर सतक नहीं रहेंगे? एक ओर श्री स्मट्सने कहा है कि कानूनके सामने नहीं झुकोगे तो यह करेगे और वह करेगे, दूसरी ओर श्री वाईबर्गने चेतावनी दी है, यद्यपि घुमा फिराकर, कि यदि हम कानूनके सामने झुक गये (अर्थात् निर्माल्य ह, इसका निश्चय होने दिया) तो हमे अलग रहनेके लिए निकाल देनेमे कुछ भी देर नहीं लगेगी। श्री स्मट्सकी धमकीसे यदि कोई डर गया हो तो उसके लिए श्री वाईबर्गके शब्द कम ध्यान देने योग्य नहीं हैं। उपाय केवल एक ही है, और वह है कि भारतीय इस लडाईमे अटल रहकर अपना पानी दिखा दे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२८ केपके भारतीय

केपका प्रवासी कानून ज्यो-ज्यो हम पढ़ते हैं त्यो-त्यो उसके लिए हम केपके भारतीय नेताओको दोषका पात्र समझते हैं। फ्राईबर्गके श्री धारशीकी ओरसे जो मुकदमा चलाया गया था उसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका आवश्यक विवरण हमने अंग्रेजीमे दिया है और उसपर टिप्पणी भी लिखी है।^२ यहा उसकी उतनी ही हकीकत दे रहे हैं जितनी समझमे आ सके।

श्री वारशी १८९७ से केपमे व्यापार करते हैं। उन्होंने भारत जानेके लिए अठारह महीनेकी अवधि वाला अनुमतिपत्र मागा। अधिकारीने वह अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया और एक वर्षकी अवधिका अनुमतिपत्र देनेकी रजामंदी दिखाई। श्री धारशीने अधिकारके आधारपर अनुमतिपत्रकी माग की। अधिकारीने कहा कि उन्हें अधिकार कुछ भी नहीं है। अनुमतिपत्र देना या न देना अधिकारीपर निर्भर है। इसपर श्री धारशीने अदालतमे मुकदमा दायर किया।

१ यहाँ नहीं दिया गया।

२ देखिए “केपके भारतीय”, पृष्ठ २७७-७८।

सर्वोच्च न्यायालयने श्री धारशीकी अर्जी नामजूर कर दी और निणय दिया कि भारतीय लोग अनुमतिपत्र देनेके लिए अधिकारीको बाध्य नहीं कर सकते।

इस फैसलेका अर्थ यह हुआ कि केप छोड़कर यदि कोई भारतीय बिना स्वीकृतिके जाता है तो लौटकर नहीं आ सकता। अनुमतिपत्र देनेकी सत्ता अधिकारीके हाथमें रहनेके कारण भारतीय सदाके लिए केपमें पराधीन हो गये। इस समय अनुमतिपत्र सभीको दिया जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु अनुमतिपत्र लेना पड़ता है, यही जुल्मकी बात है। ऐसा कानून कही नहीं है। नेटालमें एक बार प्रमाणपत्र मिलता है, वह हमेशाके लिए पर्याप्त होता है। ट्रान्सवालमें भी जो प्रमाणपत्र देना चाहते हैं वह एक बारका है। केपसे जब कोई भारतीय जाना चाहे तब उसे अनुमतिपत्र लेना चाहिए। यदि वह न ले और उसे अग्रेजी न आती हो तो वह वापस नहीं आ सकता। इस कानूनको हम अत्यन्त अत्याचारपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा, इस अनुमतिपत्रके लिए एक पौड शुल्क और लगता है। इसमें और गुलामीमें अधिक अन्तर नहीं है। केपसे अनुमतिके बिना क्यों नहीं जाया जा सकता ?

अब भी उपाय है। एक तो यह कि केपके नेता जबरदस्त आंदोलन करके कानूनमें परिवर्तन कराये। दूसरा यह कि केपके चुनावोंके समय वे अपनी ताकत बताये। इस कानूनमें और एक डक है, यह भी स्मरण रखनेकी बात है। प्रत्येक भारतीयके लिए अपना फोटो देना अनिवार्य है। कुछ लोगोंसे फोटो नहीं लिये जाते। इससे उन्हें फूलना नहीं है। बसीलेवाले व्यक्ति यदि छूट जाते हैं तो उससे भारतीय समाजको क्या लाभ ? उससे हमारी प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं होती।

जो तीसरा माग है उसपर भी विचार कर ले। उपयुक्त मुकदमेकी दलीलके समय एक प्रश्न यह उठा था कि १९०२ से पहले केपमें बसे हुए भारतीयोंपर १९०६ का कानून लागू नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न मुकदमेमें नहीं उठा था, इसलिए न्यायालयने इसके सम्बन्धमें निणय नहीं दिया और कह दिया कि जब ऐसा मुकदमा आयेगा तब न्यायालय देख लेगा। १९०२ के कानूनके अनुसार दक्षिण आफ्रिकामें बसनेवाले प्रत्येक भारतीयको केपमें न जानेका अधिकार था। इससे यह समझा जाता है कि १९०२ के पहलेसे बसे हुए भारतीयोंपर १९०६ का कानून लागू नहीं होना चाहिए। यदि यह दलील ठीक है तो ऐसे भारतीयोंके लिए अनुमतिपत्रकी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकारका मुकदमा न्यायालयमें लानेके लिए १९०२ के पूर्वसे बसनेवाले भारतीयोंको केपसे बाहर जाकर वापस आनेका प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रवासी अधिकारी उसपर रोक लगाये, तो उपयुक्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयमें उठाया जा सकता है। यह प्रश्न उठाने योग्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस प्रकार केपके भारतीय तीन माग अपना सकते हैं और हमें आशा है कि वे तीनों माग अपनायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

स्मट्सने दुच्चे पत्रका उत्तर दिया

मै कह चुका हूँ कि श्री स्मट्सने उस पत्रका उत्तर दे दिया है, जो श्री रूजने कुछ भारतीय नेताओकी ओरसे लिखा था। अब उस उत्तरका अनुवाद दे रहा हूँ^१।

नये कानूनके अन्तर्गत बनाये गये नियमोके सम्बन्धमे आपका ३० अगस्तका पत्र मुझे मिला। ट्रान्सवालमे रहनेवाले एशियाई लोग कानूनके सामने झुक जायेगे तो उन भारतीयोके अनुमतिपत्र जाचनेके लिए, जिनपर कोई सन्देह नही है तथा जिहोने कोई अपराध नही किया, खास तौरसे चुने हुए कुछ गोरे अधिकारी नियुक्त किये जायेगे।

परवाना देनेवाले कारकुनको इसकी जाच करनेका अधिकार नही दिया जा सकता कि अजदारोके अनुमतिपत्र सच्चे है या झूठे। परवाना अधिकारीके समक्ष पजीयन पत्र पेश करना होगा और केवल दाहिने हाथके अँगूठेकी निशानी देनी होगी। वह निशानी पजीयकके पास भेजी जायेगी। यदि वह पहलेकी निशानीसे मिल गई, तो फिर विशेष जाच नही की जायेगी।

गुमास्तोको मियादी अनुमतिपत्रोके द्वारा बुलानेके बारेमे अपने विचार पहले व्यक्त कर चुका हूँ। उनमे परिवर्तन नही किया जा सकता।

माता पिताओसे उनके बच्चे अलग कर देनेका इरादा नही है। और सोलह वर्षसे कम उम्रके बालकोको बाहर भेजनेका हुक्म नही दिया जा सकता। लेकिन पिता या अभिभावकको कानूनके अनुसार बालकका हुलिया, अँगुलियोकी निशानी आदिका नियम पालना होगा।

चीनी राजदूत आदिके अँगुलियोके निशान नही लेनेका नियम है। उनके सिवा इस नियमसे किसीको मुक्त नही किया जा सकता।

‘जैसी बोनी वैसी कटनी’

इस कहावतके अनुसार जिन साहबोने श्री स्मट्सको पत्र लिखवाया था उहे उपयुक्त ही उत्तर मिला है। यह उत्तर बताता है कि श्री स्मट्सने एक भी बात नही मानी, गोरे अनुमति पत्र निरीक्षक भी तभी मिलेगे जब सभी भारतीय पजीकृत होना स्वीकार करेगे, कुछ खास लोगोके पजीकृत हो जानेसे काम नही चलेगा। यदि मै अपने हाथ काले करता हूँ तो मुझे तो कहना चाहिए कि मेरा पजीयनपत्र काला देखे या गोरा, उसमे कुछ भी फक नही पडता। काला आदमी देखे तो शायद कुछ विवेक भी बरत सकता है, लेकिन किसी गोरे अधिकारीने गुलामोके प्रति विवेक बरता हो और उसका कोई उदाहरण हो तो कृपया पाठक मेरे पास भेजे, जिससे इस पत्रमे उन गोरे साहबका नाम जितना भी अमर किया जा सकेगा, करूँगा।

शेष मागोके लिए श्री स्मटस साहबने साफ इनकार कर दिया है, और वह भी गुलामी लेनेवालेको फबे वैसी भाषामे। कुछ मागे बेकार है, यह भी उन्होंने कह दिया है। जैसे, बालकोके सम्बन्धमे। स्मटस साहब चाहे तो भी नये कानूनमे परिवर्तन किये बिना १६ वर्षसे कम उम्रवाले बालकपर हाथ नहीं उठा सकते। बालक यदि अँगुलियोंकी भी निशानी न दे तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो पिता अपने लडकेको गुलामीका ककहरा बचपनमे न सिखाये उसके लिए सजा है। गुलामोके बालक स्वतन्त्र मिजाजके हो, यह सरकारको कैसे वरदास्त हो सकता है? अग्रेजोके बालक आठ वर्षकी उम्रसे कवायद सीखते और बंदूके उठाते हैं। लेकिन हम तो गुलाम ठहरे। इसलिए हमारे बालकोको गुलामीकी तालीम ही दी जा सकती है। जैसा बाप वैसा बेटा, यह तो चला ही आ रहा है, और चलेगा भी। अब इस जवाबके बारेमे और अधिक क्या कहूँ? सिफ इतना ही कहना काफी है कि इस काले पत्रसे कही प्रिटोरियाके भाइयोमे जान आ जाये तो वे अब भी अपने धनका मोह छोड़कर कुछ जोशके साथ श्री स्मटसको अनुरूप उत्तर देगे तथा अपनी गलती सुधार कर, भारतीय प्रजा जो आंदोलन कर रही है, उसमे पूरी ताकतसे शामिल होंगे। वास्तवमे श्री स्मटसका पत्र प्रत्येक भारतीयमे जोश भरनेवाला है। उस पढनेके बाद प्रत्येक भारतीयको लगना चाहिए कि “यदि श्री स्मटसको अपने पत्रमे लिखी शर्तोंपर ही ट्रांसवालमे रहने देना हो, तो मुझे ट्रांसवाल नहीं चाहिए। अन्न-जल देनेवाला खुदा महान है। वह सूखा टुकड़ा कहीं भी देगा।” यह जोश आ जाये तो कैसा रग जमता है, यह देखनेवाले देखेंगे। नर रत्न थोरोके समान उनके लिए जेल महल ही बन जायेगी और जेलमे पड़े हुए भारतीयोकी पुकार श्री स्मटसको दहला देगी।

हाजी कासिमका स्पष्टीकरण

श्री रूजके पत्रका उत्तरदायित्व श्री हाजी कासिमके ऊपर डाला गया है। इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ अन्याय माना है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है, जिसे मैं समाजके समक्ष रख रहा हूँ। श्री हाजी कासिम लिखते हैं

जो अर्जी उपनिवेश-सचिवको दी गई वह कुछ लोगोने मिलकर दी थी। अर्जीकी भाषा नम्र रखनेका कारण यह नहीं था कि मैंने वैसा करनेको कहा था, बल्कि वकीलकी वैसी सलाह थी और हमे भी सरकारसे नम्रतापूर्ण अर्जी करना ठीक मालूम हुआ था। इसके अलावा नम्रतापूर्ण अर्जी करनेसे सरकार हमारी मागकी पूर्ति करेगी, यह सोचकर ही हम सब भाई उसमे शामिल हुए थे, और सबने अपनी सम्मति दी थी। वह अर्जी खासकर मैंने ही भिजवाई हो, सो बात नहीं। ‘इंडियन ओपिनियन’ मे मुझपर व्यथ ही दोष मठा जाता है। वह सरासर गलत है। पजीकृत होना या न होना, यह सबकी अपनी इच्छापर निर्भर है। किसीने आपको गलत लिखा होगा। उसके आधारपर अखबारमे गलत तरीकेसे मेरा नाम प्रकाशित करना ठीक नहीं। मने स्वयं पहले ही ब्रिटिश भारतीय सघके नेताओसे जाहिरा कहा है कि जहातक खुदा हिम्मत देगा वहा तक सब भाइयोके साथ चलता रहूँगा और यदि हिम्मत टूट गई, तो भी भाइयोकी सलाह और मददसे ही जो कुछ करना उचित होगा, करूँगा।

यदि मुझपर यह आरोप लगाया जाता कि अर्जी देनेमे जो लोग शामिल थे मैंने उनका साथ दिया तो वह बिल्कुल अलग बात है। वास्तवमे मैं नरम प्रकृतिका आदमी हूँ, और मानता हूँ कि सरकारसे समझौता करके चलनेवाला पक्ष अक्लमन्द है। यह

मानकर ही मैं इस अर्जीमें शामिल हुआ। क्योंकि औरोकी तरह मैं भी मानता हूँ कि कानून रद्द नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर रास्ता यही था कि सरकारसे समझौता करके उसमें परिवर्तन कराये जाये, और इस तरह समझौतेसे काम चलाया जाये। ब्रिटिश भारतीय सघका आंदोलन सच्चा है। उससे मेरी पूरी सहानुभूति है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा सघकी पूरी मदद करे।

स्मट्स साहबका भाषण

स्मट्स साहबने अपने मतदाताओके समक्ष भाषण^१ दिया है। उसमें उन्होंने नये कानूनपर भी टीका की है। उसका अनुवाद नीचे देता हूँ

एक दूसरा एशियाई प्रश्न भी है, और वह है ट्रांसवालमें रहनेवाले भारतीय और चीनियोंके बारेमें। दक्षिण आफ्रिकाकी स्थायी आबादीको तोड़नेवाले ये लोग हैं। पुराने राज्यमें यदि भारतीय १८८५ के कानूनके अनुसार पजीकृत होकर निर्धारित रकम न देते तो रह नहीं सकते थे। सभी भारतीयोंका उस कानूनके अंतर्गत पजीयन किया जाता था। उन्होंने व्यापारमें प्रतिस्पर्धा की, इसलिए डच ससदने निणय किया था कि उन्हें 'बाजार' में ही व्यापार करनेकी अनुमति दी जाये। लेकिन ब्रिटिश सरकार बीचमें आई और उसने कहा कि ये लोग ब्रिटिश प्रजा हैं और लंदन समझौतेके अनुसार सारी ब्रिटिश प्रजाके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए 'बाजार'का कानून अमलमें नहीं आ सका। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय व्यापारी सब जगह फ़ैल गये। वे बिना परवानेके व्यापार करने लगे और, इसलिए, गोरे व्यापारियोंसे उनकी स्थिति अच्छी हो गई। इतनी खराब हालत थी, फिर भी ब्रिटिश सरकारकी लिखा पढीके कारण लडाईके पूर्व तक चलती रही। उसका नतीजा आप प्रिन्सले स्ट्रीट, पीट्सबर्ग, पाचेफ़स्ट्रूम और दूसरी जगहोंमें देख सकते हैं। इन जगहोंका व्यापार भारतीयोंके हाथमें है। लोग पूछा करते हैं कि देशमें भुखमरी क्यों आई? व्यापार क्यों बैठ गया है?

इसका एक कारण भारतीय व्यापार है। जैसा नेटालमें हो रहा है वैसा ही भारतीय प्रजा यहां भी करना चाहती है। वह सब व्यापार ले लेना चाहती है। उसका इलाज हमने किया है। उसके लिए हमने पजीयन कानून पास किया है। उस कानूनको पास करते समय किसी सदस्यने उसका विरोध नहीं किया। मैं जानता हूँ कि इस कानूनके मागमें अडचने आयेगी, इसलिए यह क्या है, इसके बारेमें कहना चाहता हूँ। यहां भारतीय अधिक सख्यामें हैं, इसलिए हमने कानूनको सरत बनाया है। ट्रांसवालमें १५,००० भारतीय और १२,०० चीनी व्यापारी हैं। पहलेके कानूनके आधारपर दिये गये प्रमाणपत्रोंकी जाली प्रतिया निकाली जाती हैं और बिकती हैं। बम्बई, जोहानिसबर्ग और डबनमें ऐसे स्थान हैं जहासे ऐसे जाली प्रमाणपत्र अमुक कीमत देनेपर प्राप्त किये जा सकते हैं। और भारतीय भारतीयोंके बीचका अन्तर जाना नहीं जा सकता, इसलिए अँगलियोंकी निशानी लेकर पजीयन करनेका निणय किया गया है। भारतीय प्रजा इसे

१ भाषणकी मूल अंग्रेजी रिपोर्ट १२-१०-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुई थी। देखिए स्मट्सका भाषण", पृष्ठ २८० ८१ भी।

अपमानजनक मानती है। (हँसी)। भारतीयोंका शिष्टमण्डल ब्रिटिश सरकारके पास गया था। लेकिन फिर भी बड़ी सरकारने इस कानूनको मजूर कर दिया है। भारतीयोंकी दलीलको मैंने स्वयं देखा है। उसमें क्या है? उन्हीं लोगोंको भारत छोड़नेके पहले अँगुलियोंकी निशानी देनी पड़ती है। पेशनयाफ्ता सिपाही या अधिकारी अँगुलियोंकी निशानी देनेके बाद ही पेशन प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय शिष्टमण्डलके इंग्लैंड जानेपर ये सारी बातें प्रकट हुईं। भारतीय सोचते हैं कि वे सरकारको बेवकूफ बना देंगे, लेकिन कुछ ही समयमें उनका भ्रम दूर हो जायेगा।

भारतीयोंको पजीकृत होनेके लिए समय दिया गया है। सरकारको मालूम हुआ है कि पजीयन कार्यालयके पास धरना दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत कम लोग पजीकृत होते हैं। किन्तु यह कह देना उचित होगा कि हर चीजकी सीमा होती है। कानून सरतीसे अमलमें लाया जायेगा और जो भारतीय अवधिके अंदर पजीकृत नहीं होंगे उन्हें निर्वासित किया जायेगा। नया नोटिस निकाला जा चुका है कि जिनके पास पजीयनपत्र नहीं है, उन्हें दिसम्बरके बाद परवाने नहीं दिये जायेंगे और सारी दूकानें बन्द होगी। (तालियाँ)। भारतीय मानते हैं कि आखिर सरकार ढीली पड़ जायेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बिल्कुल ढीली नहीं पड़ना चाहती। मैं भारतीयोंको चेतावनी देता हूँ कि हम कानूनको बराबर अमलमें लायेंगे। मुझे आशा है कि अखबारवाले स्पष्ट कर देंगे कि दिसम्बर ३१ के बाद हमेशाके लिए दरवाजे बंद हो जायेंगे। मेरा भारतीयोंसे कोई झगडा नहीं। हम उनपर जुल्म करना नहीं चाहते हैं। हम तो आनेवाले भारतीयोंको रोकना चाहते हैं और इस मुल्कको गोरोंका मुल्क बनाना चाहते हैं। चाहे जो भी कठिनाइयाँ आये, इसके लिए हम कृतनिश्चय हैं और इससे हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। (खूब तालियाँ)।

ईसप मियाँका उत्तर

श्री ईसप मियाने इस भाषणका जवाब दिया है। उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है^१

सघकी बैठक

पिछले रविवारको हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी अनुमतिसे अजुमनके सभा-भवनमें सघकी बैठक हुई थी। श्री ईसप मिया सभापति थे। सभा भवन खचाखच भर गया था। चीनी सघके प्रमुख श्री क्विन और दूसरे चीनी भी उपस्थित थे। श्री ईसप मियाके भाषणके बाद श्री गांधीने धरनेदारोंके सम्बन्धमें कहा कि उहे बिल्कुल नम्रता बरतनी चाहिए। धरनेदार कभी एक जगह घेरा बनाकर न खड़े रहे। वे सिपाहीके समान हैं। और सिपाहीका काम यह है कि जो हुक्म दिया जाये उसके अनुसार बताव करे, नियमोंका निर्वाह करे और अपनी जगहसे कहीं न जाये। सिपाहीको अपनेसे बड़ेके अनुशासनमें भी रहना चाहिए। जिन धरने-दारोंके नाम श्री गांधीके पास होंगे, वे यदि अपने कतव्यका पालन करते हुए गिरफ्तार किये गये तो उनका बचाव श्री गांधी करेंगे। लेकिन यदि उन्हें जुर्माना हो तो जुर्माना न देकर उन्हें जेल जाना है। बुरा बर्ताव करनेवाले अथवा मारपीट करनेवाले स्वयंसेवकोंका बचाव

बिल्कुल नहीं किया जायेगा। इसके बाद श्री गांधीने दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको बनाये रखनेके सम्बन्धमे समझाया और श्री रिचके पत्रकी बाते कही। बादमे इमाम अब्दुल कादिर, श्री टी० नायडू, श्री अब्दुल रहमान (पॉन्चेफस्टूमवाले), श्री नवाबखा, श्री कुवाडिया श्री अली मुहम्मद, श्री जोजेफ, श्री उमरजी साले आदिके भाषण हुए। उन्होंने कहा कि समिति तो कायम ही रहनी चाहिए। श्री जोजेफने प्रश्न किया कि जो नौकरीसे अलग कर दिये जायेंगे उनका क्या होगा। इसके उत्तरमे श्री गांधीने कहा कि जेल जाने तक जो तकलीफें होगी वे तो सबको उठानी हैं। नौकरीवालेको यदि इज्जतकी परवाह होगी तो वह नौकरीकी परवाह नहीं करेगा। नौकरी एक जगहसे दूसरी जगह मिल सकती है, लेकिन गई हुई इज्जत नहीं मिल सकती। देशके सामने नौकरीकी क्या कीमत? परवानेके नोटिसके सम्बन्धमे पूछे गये श्री कुवाडियाके प्रश्नके उत्तरमे श्री गांधीने कहा कि परवाना न मिले तो जेल जाना ही ठीक है। लेकिन परवानेके बिना व्यापार करनेमे कोई हज्र नहीं। फिर भी यदि भारतीय प्रजा डर जाये तो परीक्षात्मक मुकदमा दायर किया जा सकता है। उसमे धनकी जरूरत होगी।

धरनेदारोकी बैठक

उपर्युक्त बैठकके पहले धरनेदारोकी एक अलग बैठक हुई थी। उसमे बड़ी हिम्मतसे काम किया गया। हर स्टेशन और वान ब्रेडिस चौककी जाच करनेके लिए आदमी नियुक्त किये गये थे। हरएकके लिए फीता बनवाया गया है जिससे धरनेदारोको तुरंत पहचाना जा सकता है। धरनेदारोके नामोमे थोडा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी मैं नाम नहीं देना चाहता। क्योंकि बादमे और भी परिवर्तन हो सकता है। महीना पूरा होनेपर जितने लोगोने काम किया होगा, उतने नाम दे दूंगा। पिछली बार जो नाम दिये गये ह, उनमे दो नामो से एक ही व्यक्तिका बोध होता है। उहे नरोत्तम अमथाभाई पटेल वाझवाला और नाराणजी करसनजी देसाई छीनावाला समझा जाये।

क्रूगर्सडॉर्फके भारतीयोकी सूचना

मैं देखता हूँ कि, क्रूगर्सडॉर्फके भारतीय अब भी 'रैड डेली मेल'के सवाददातासे काम लेते रहते हैं। उन्होंने अँगुलियोकी निशानीपर बहुत जोर दे रखा है। लेकिन हमे समझना चाहिए कि वह कानून हमे अस्वीकार इसलिए है कि वह हमपर ही लागू होता है, और हमे अपराधी साबित करता है। ऐसे भारतीयोको 'इंडियन ओपिनियन'के पिछले अंक देखकर सारी बाते जान लेनी चाहिए।

फेरीवालोका मुकदमा

बॉक्सबगमे फेरीवालोपर मुकदमा चल रहा है। उसमे मजिस्ट्रेटको इस विषयपर निणय देना है कि यदि कोई फेरीवाला किसीके निजी मकानके सामने २० मिनटसे ज्यादा रुके तो वह अपराध है या नहीं। मजिस्ट्रेटका रुख एक फेरीवालेकी ओर था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया है। नये कानूनके सम्बन्धमे भी ऐसा ही होना सम्भव है।

धरनेदार गिरफ्तार

श्री भाणा छीनिया नामक एक धरनेदारको पुलिसने यह आरोप लगाकर पकड़ लिया था कि वह पदल पटरीपर खड़े होकर आने जानेवाले लोगोके मागमे रुकावट डालता था। वह

मुकदमा श्री क्रासके सामने चला। श्री गांधीने निशुल्क पैरवी की और मजिस्ट्रेटने उसे निर्दोष ठहराकर छोड़ दिया। तैयारी इतनी थी कि यदि उसपर जुर्माना किया जाता तो वह जुर्माना न देकर जेल जाता। इससे कोई यह न समझ ले कि चाहे जिस पैदल पटरीपर खड़ा रहा जा सकता है। श्री भाणाके छूटनेका कारण यह था कि उनके खड़े रहनेसे दूसरे राहगीरोंको रुकावट नहीं होती थी। सरल तरीका यह है कि यदि पुलिस किसी जगह खड़े रहनेको मना करे तो दूसरी जगह जाकर खड़े हो जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२३० द० आ० ब्रि० भा० समितिको पत्र^१

[जोहानिसबग

अक्टूबर १४, १९०७के पूर्व]

आप जान्तेसे सूचित कर सकते हैं कि सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनके नाम जो पत्र भेजा गया हे वह यहांके भारतीय समाजके विचारोंको ठीक व्यक्त करता हे और यदि जो अनुमति मागी जा रही हे वह प्रदान की गई तो भारतीय निश्चय ही महसूस करेंगे कि वे साम्राज्यके अग समने जा रहे ह। आज तो वे नि सदेह अनुभव करते हैं कि वे सौतेली सताने हैं।

[मो० क० गांधी]

[श्री एल० डब्ल्यू० रिच

२८, क्वीन ऐस चेम्बर्स

ब्राडवे, वेस्ट मि स्टर्

लन्दन, एस० डब्ल्यू०]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २९१/१२२

१ एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके मंत्री एल० डब्ल्यू० रिचने १४ अगस्तको ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनके नाम एक पत्र भेजा था (देखिए परिशिष्ट ५)। सरकारी उत्तरमें, दूसरे विषयोंके साथ-साथ कहा गया था 'प्रधानमन्त्रीको ज्ञात नहीं है कि स्वयं टान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंने जो रुख अपनाया है वह इन प्रस्तावों द्वारा सही सही व्यक्त होता है या नहीं।' जाहिर है कि यह गांधीजीको सूचित किया गया था। रिचने प्रधानमन्त्रीके नाम अपने १४ अक्टूबरके पत्रमें उपयुक्तको, 'टान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक मंत्रीसे प्राप्त एक पत्र' के रूपमें उद्धृत किया था। मूल उपलब्ध नहीं है।

२३१ पत्र मगनलाल गाधीको

[जोहानिसबग]

अक्तूबर १४, १९०७

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। श्री बट्टीसे कहना कि मैंने उन फीसोको बहुत सावधानीसे दज किया है। वे अनुपस्थित थे, इसलिए उनके लिए लिखे गये बहुत-से पत्रोका मैंने कुछ नहीं लिया। फिर भी उनसे कहना कि वे मेरी लगाई हुई फीसोकी कोई भी रकम काट सकते हैं। मैं उनका निणय स्वीकार कर लूंगा। जहातक उनके कागजोका सम्बन्ध है, मैं इस मामलेमे विचार कर रहा हूँ। मेरे बिलके विषयमे तुम उनसे बहुत स्पष्ट बात कर सकते हो। मनमाने ढंगसे फीस लेकर मैं कभी उनके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ, ऐसा वे सोचे तो मुझे उनके लिए अफसोस होगा। मैं चाहूँगा कि वे हर मदको देख जाये और जो उनको अनुचित लगे उसके आगे काटेका निशान लगा दे।

बैटवारेका जो हिसाब श्रीमती डोमनने भेजा है वह मुझे मिल गया है।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजो प्रति (एस० एन० ४७६९) से।

२३२ पत्र पुलिस कमिश्नरको

[जोहानिसबग]

१५ अक्तूबर, १९०७

पुलिस कमिश्नर

जोहानिसबग

महोदय,

सयोगसे उस समय मैं अदालतम मौजूद था, जब श्री अलेक्जैंडरने अपने दो भारतीय मुवक्किलोकी ओरसे कहा था कि वे वान ब्रैडिस स्कवेयरके धरनेदारोसे डरते हैं और इसी कारण उन्होंने पजीयन प्रमाणपत्रके लिए प्राथनापत्र नहीं दिये। मने इस बयानका तब भी खण्डन किया था और अब भी करता हूँ। नि सदेह पजीयन कार्यालयमे जानेवालोपर कुछ भारतीय नजर रखते हैं। ऐसा वे उनको यह समझानेके खयालसे करते हैं कि एशियाई कानून सशोधन अधिनियमको मान लेनेपर उनकी स्थिति कैसी हो जायगी। साथ ही वे अपना प्रभाव डालकर उनको कार्यालयमे जानेसे रोकते भी हैं। किंतु इस प्रकार समझानेपर भी यदि कोई कार्यालयमे जाना चाहता है, तो उसको बिलकुल तग नहीं किया जाता। श्री अलेक्जैंडर जब मजिस्ट्रेटके सामने बयान दे रहे थे तब ऐसा एक मामला हुआ था। एक

नौजवान भारतीय अपना पजीयन कराना चाहता था। वह अपनी मालकिनके साथ था और उसे किसीने नहीं रोका। कुछ समय पहले एक और भारतीय भी वान ब्रैडिस स्कवेयरके पजीयन कार्यालयमें इसी तरह गया था। मैं आपके सामने यह तथ्य इसलिए पेश कर रहा हूँ कि श्री अलेक्जेंडरने यह सुझाव दिया था कि उनके मुक्किलोको पुलिस सुरक्षा दी जाये। और वास्तवमें मुझे बतलाया गया कि उनको पुलिस-सुरक्षा मिल भी गई थी।

अपने सघकी ओरसे मैं यह आश्वासन देनेकी धष्टता करता हूँ कि ब्रिटिश भारतीय सघ किसी डराने धमकानेकी बातका समर्थन नहीं करेगा और मेरा सघ इस बातका पूरा खयाल रखेगा कि पजीयन कार्यालयमें जानेके इच्छुक किसी भी आदमीको सघसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति तंग न करे। जहातक मुझे पता है, मुझे इस बातका यकीन है कि श्री अलेक्जेंडरको उनके मुक्किलोने गलत खबर दी, क्योंकि उहे किसी प्रकारकी शारीरिक हानिकी अपेक्षा भारतीय जनमतका अधिक भय था।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

मो० क० गांधी

अवैतनिक मंत्री,

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३३ पत्र 'स्टार' को

जोहानिसबग

अक्तूबर १८, १९०७

सेवामें

सम्पादक

'स्टार'

[जोहानिसबग]

महोदय,

भारतीय धरनेदार पूणतया निर्दोष हैं, फिर भी बिना लेशमात्र प्रमाणके उनपर यह दोष लगाया जा रहा है कि वे उन लोगोको डराते धमकाते हैं जो पजीयन प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं। इसलिए कृपा होगी, यदि आप मुझे इस आरोपके थोथेपन और साथ ही उस जवाबी धमकीकी ओर भी, जो एक वास्तविकता है, जनताका ध्यान आकर्षित करनेकी सुविधा दें।

कल एक ऐसा मामला हुआ जिसमें धरनेदारोंने पीटसबगसे आये तीन भारतीयोके साथ रक्षक दल भेजनेकी रजामंदी जाहिर की कि तु वह अस्वीकृत कर दी गई। बात दरअसल यह

हे कि आतंककी कहानिया गढकर और पुलिस सुरक्षाकी माग करके धरनेदारोकी बदनामी करनेकी कोशिश की जा रही हे। लेकिन, हमारे अपने “राष्ट्रीय चर” भी ह और, नि सदेह, वे अपनी सरयामे वद्धि करना चाहते हैं। धमकीका आरोप इसी उद्देश्यसे अपनाया गया एक तरीका है। यदि इस आरोपमे कोई सचाई हे तो किसीपर मुकदमा क्यों नही चलाया गया हे? इसे साबित करना तो सबसे आसान बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धमकिया वान ब्रडिस स्ववेयरमे, आते जाते सकडो लोगोकी उपस्थितिमे, दिन दहाडे दी जाती है।

जहातक जवाबी धमकीकी बात है, अनेक भारतीयोका विश्वास हे कि जिन भारतीयोके पास अनुमतिपत्र है — चाहे वे कप्तान हेमिल्टन फाउलके दिये हुए हो या श्री चैमनेके — वे पजीयन अधिनियमके आगे न झुकनेके कारण अब सरकारी दबावसे बर्खास्त किये जा रहे हैं। ऐसा दबाव हो या न हो, मेरे सामने जर्मिस्टनके मुरय मेटकी एक चिटठी पडी हे, जिसमे इस सूचनाकी पुष्टि की गई है कि नौ भारतीय इसलिए बर्खास्त कर दिये गये कि उन्होने नये अधिनियमके अधीन पजीयन करानेके लिए प्राथनापत्र नही दिये। यह देखते हुए कि जनरल स्मट्स इस बातमे खुद ही अगुआ बने हुए हैं, इस घटनासे कोई आश्चर्य नही होता। उन्होने सभी तरहकी सजाओकी धमकी दी है — और जि हे देश-निकालेकी धमकी दी गई है उहीको परवाने छीन लेनेकी भी धमकी दी गई है। समझमे नही आता कि दोनो सजाएँ एक साथ कसे दी जा सकती ह। प्रवास अधिनियमके बिना जबदस्ती देश-निकाला मुमकिन नही हे, और प्रवासी अधिनियमपर अभी शाही मजूरी मिलनी बाकी है। भारतीय यायपूण युद्धसे नही डरते, और जहातक मै समझ पाया हूँ, वे अन्यायपूण युद्धके लिए भी तयार हैं, यद्यपि वह सवथासे अ-ब्रिटिश होगा। भारतीयोको गुलामीके चिट्ठे लेनेपर मजबूर करनेके लिए यरोपीय मालिकोकी सहायता क्यों ली जानी चाहिए? अबतक अनेक मालिकोने इस प्रकारके दबावका विरोध किया है और भारतीयोको अपनी नौकरीसे निकालनेसे साफ इनकार कर दिया है। यह दोनोके लिए श्रेयकी बात है — मालिकोके लिए इसलिए कि वे अनैतिक रूपमे चोट करनेकी प्रक्रियामे भाग नही लेना चाहते, और भारतीयोके लिए इसलिए कि वे इतने उपयोगी तथा स्वामिभक्त सेवक हैं कि उनको बर्खास्त नही किया जा सकता।

मुझे अभी पता लगा हे कि जिन चार भारतीयोकी ओरसे कहा गया था कि उनको धमकी दी गई हे और जिनके बारेमे यह मान लिया गया था कि उनके पास अनुमतिपत्र नही है, उहे आज छोड दिया गया और खुली अदालतमे यह भरोसा दिलाया गया कि उहे पजीयन प्रमाणपत्र मिल जायेगे। गुलामोको तो उनके पट्टे मिलने ही चाहिए। मेरे विचारमे जिनके पास पुराने डच पास ह — और कहा जाता हे, इन लोगोके पास ह — उनके साथ भी वसा ही बरताव किया जाना चाहिए, जसा शांति रक्षा अध्यादेशके अतगत अनुमतिपत्र लेनेवालोके साथ किया जाता है। लेकिन सभी जानते हैं कि श्री जाडनको ऐसे सभी आदमियाको उपनिवेश खाली करके चले जानेका आदेश देनेके कष्टप्रद कतव्यका पालन करना पडा था। ऐसे एक आदमीको उसी दिन आदेश मिला जिस दिन उपयुक्त चार आदमियोने यह कहा था कि वे नये पजीयन प्रमाणपत्रोके लिए दर्खास्त देगे। इस प्रकार जनरल स्मट्स वास्तवमे अवैध निवासियोमे से वैध निवासियोकी तलाश कर रहे ह। ये अवध निवासी पजीयन अधिनियमके अनुसार वाञ्छित लोग बन जायेगे, क्योंकि वे उसके अतगत प्रमाणपत्रोके लिए

प्राथनापत्र दे देगे और दूसरे लोग सासारिक समझिसे अपनी मनुष्यताका मूल्य अधिक लगानेके कारण अवैध निवासी बना दिये जायेगे।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, १९-१०-१९०७

२३४ रिचकी सेवाएँ

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके एक सदस्य श्री रिचके बारेमे इस प्रकार लिखते हैं

इस योग्य, सक्षम तथा स्वाथत्यागी पुरुषके भगीरथ काय और लगनके लिए भारतीय समाज जितनी कृतज्ञता और प्रशंसाभाव प्रकट करे, थोडा ही होगा।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय न केवल ऊपर प्रयुक्त प्रत्येक विशेषणका समर्थन करते हैं, बल्कि वे यह भी अनुभव करते हैं कि उनकी सेवाएँ जितनी मूल्यवान आज हैं उतनी और कभी नहीं हो सकती। ट्रांसवालके भारतीय एक ऐसे सघषमे लगे हुए ह, जैसा इस पीढीमे फिर कभी नहीं होगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि लाड ऐम्प्टहिल ट्रांसवालमे भारतीयोंके कष्टोंको दूर करनेके जो प्रयत्न कर रहे हैं उनमे उहे सतत जागरूक तथा अथक परिश्रमी श्री रिचकी सहायता मिलती रहे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३५ जनरल बोथाका अनुकरण

यद्यपि ट्रांसवालमे भारतीय समाज बहुत जोर दिखा रहा है, फिर भी भीतर ही भीतर यह डर बना हुआ है कि अंत कैसा होगा। इतना तो स्पष्ट है कि इस तरहका डर रखने वालेको सत्य, और खुदा या ईश्वरपर कम भरोसा है। इस कारण या और किसी कारणसे हम डर रखनेवालेके सामने ट्रांसवालके वर्तमान राज्यकर्ताओंका उदाहरण पेश करते हैं। पाठकोंको याद होगा कि ट्रांसवालके गोरोंको जब स्वराज्य मिला उसके पहले ही श्री लिटिलटनने लाड मिलनरकी सलाहसे आधा स्वराज्य दे दिया। उसमे जनरल बोथा जनरल स्मट्स वगैरह काम कर सकते थे। लेकिन उतने अधिकारोंको अपर्याप्त मानकर जनरल बोथाने लाड मिलनरको लिखा था कि “हमारा विचार आपके राज्य शासनमे हिस्सा लेनेका बिलकुल नहीं है। हमें जो सविधान दिया गया है उसे हम सन्तोषजनक नहीं मानते।” लाड मिलनर इसपर चिढ़ गये। वाडरर सभाभवनमे भारी सभा हुई। उसमे लाड मिलनरने भाषण दिया और

जनरल बोथाको धमकी दी कि यदि बोअर लोग राज्य संचालनमें भाग नहीं लेंगे तो उनके बिना ही राज्य चलाया जायेगा। जनरल बोथा ऐसी धमकीसे डरे नहीं। अब नतीजा यह हुआ कि बोअर लोगोंको पूर्ण स्वराज्य मिल गया है। यह उदाहरण महान बहिष्कारका है। बोथाने बहिष्कार किया और विजय प्राप्त की।

इस उदाहरणमें हमें इतना याद रखना चाहिए कि बोअर अधिक अधिकार माग रहे थे। अधिक अधिकार नहीं मिले, इसलिए वे बहिष्कारपर आमादा हुए। हम ज्यादा अधिकार नहीं मागते, बल्कि हमपर गुलामीका जो जुआ रखा जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारे लिए डरनेकी क्या बात है? बोथाका बहिष्कार सफल हुआ, क्योंकि उनमें पूरी हिम्मत थी, और लाड मिलनरको विश्वास हो गया था कि वे राज्य संचालनमें भाग न लेनेकी निरी धमकी नहीं दे रहे हैं बल्कि बात सत्य है। हमारी लड़ाईका अबतक जनरल स्मट्सपर यह प्रभाव नहीं पड़ा कि भारतीयोंका जोर पूरा और सच्चा है। हम आशा करते हैं कि जनरल बोथाका उदाहरण लेकर भारतीय जनता अन्ततक उत्साह कायम रखेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३६ पीटर्सके मुकदमेसे लेने योग्य सीख

श्री पीट्सको फोक्सरस्टमें मुसीबत क्यों उठानी पड़ी? यह प्रश्न प्रत्येक भारतीयके मनमें उठना चाहिए। यदि कोई गोरा अच्छे कपड़े पहनकर प्रथम या द्वितीय श्रेणीमें यात्रा कर रहा हो तो अनुमान यह किया जायेगा कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा फिर वास्तवमें भले वह जबरदस्त अपराधी ही क्यों न हो। काली चमड़ीवाला व्यक्ति भले प्रतिष्ठित हो, उसके बारेमें अनुमान यह किया जायेगा कि वह ठग ही होगा। श्री पीट्सके सम्बन्धमें ऐसा ही हुआ है। जाच-अधिकारीने मान लिया कि श्री पीट्सके पास झूठा अनुमतिपत्र होना चाहिए। उसमें अधिकारीका अधिक दोष नहीं है। दोष सरकारका है। भारतीयोंको झूठे समझकर उसने खूनी कानून पास किया है। जाच अधिकारीने उसका अनुसरण किया। इस प्रकार आज भारतीयोंका सम्मान नहीं है। किंतु यदि भारतीय समाज खूनी कानूनके सामने झुक जाये तो फिर प्रतिष्ठा तो एक ओर रही यदि गोरे बिना ठोकरके भारतीयसे बात न करे तो उसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। ऐसे ठोस कारणोंको लेकर भारतीय समाज कानूनका विरोध कर रहा है, उसकी लड़ाई किसी धारा या अँगुलियोंकी निशानीके खिलाफ नहीं है। जहापर कानूनकी जड़ ही खराब है, वहा उसकी शाखाओंका विरोध करनेसे क्या होगा? जड़पर कुल्हाड़ी मारनेकी आवश्यकता है, और वह कुल्हाड़ी है भारतीयोंकी हिम्मत तथा उनकी मर्दानगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३७ रिचकी सेवाएँ

श्री रिचने भारतीय समाजकी सेवामे हृद कर दी। समितिके एक सदस्य लिखते हैं

म लदन समितिका उल्लेख करता हूँ तब आप उसे श्री रिचका उल्लेख समझे। इस समझदार, परोपकारी और आत्मत्यागी व्यक्तिका भारतीय समाज कभी पूरा अहसान नहीं मान सकेगा। म मानता हूँ कि यदि आप समितिको बचाये रखेंगे और श्री रिचको फिलहाल लदनमे रहने देंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। म समझता हूँ कि खासकर समितिकी उपस्थितिके कारण ही ट्रान्सवाल सरकारके पैर ढीले हो गये ह। यदि समितिको अधिक खर्च करनेकी अनुमति हो तो वह बहुत ही काम कर सकती है।

इन शब्दोमे हमे कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम होती। हमे यह देखना है कि ऐसी मूल्यवान सेवाको हम धनकी कमीके कारण छोड़ न दें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३८ ट्रान्सवालमे दूकान बन्द करनेके समयका कानून

नेटालके समान ट्रान्सवालमे दूकाने बन्द करनेके सम्बन्धमे कानून बनेगा यह सब जानते थे। वह कानून अब प्रकाशित हुआ है और उसके आवश्यक अंशका अनुवाद हम अद्यतन दे रहे हैं। हम ट्रान्सवालके भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोसे सिफारिश करते हैं कि वे उन धाराओको पूरी सावधानीसे पढ़ें। उनसे भारतीय व्यापारको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। परन्तु वह बरदाश्त कर लेने जैसा है। प्रत्येक व्यापारी ओर फेरीवालेसे हमारा अनुरोध है कि वह इन कानूनोंका पूरा पूरा आदर करें। ऐसी बातोमे यदि भारतीय कानून भंग करते हैं तो वे लोगोकी नजरोपर चढ़ जाते ह, और हमारे दुश्मनोको हमारे विरुद्ध हथियार मिल जाते हैं। जहा सभीको एक जैसे समयपर बन्द करनेका आदेश हो वहा किसीके लिए भी अपनी दूकान अधिक समय तक खुली रखनेकी गुंजाइश नहीं रहती।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमीदिया अजुमनकी सभा

इस अजुमनका जोर बढ़ता जा रहा है। लोगोका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, और हिंदू मुसलमान सभीकी एक स्वरसे माग है कि काननको मिटाया जाये। रविवारको इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। मौलवी साहब और दरवेश साहबने बहुत विस्तारसे भाषण दिये। श्री कुवाडिया, श्री उमरजी साले वगैरह भी बोले। श्री एच० ए० कुवाडिया तथा दूसरे सज्जनोने विषय छेड़ा कि श्री एस० हेल्ने हाथ मुड़ काले करके पजीयनके लिए अर्जी दी, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाये। इसे सारी सभाने स्वीकार किया। इसपर अजुमनने सलाह दी है कि श्री हेल्से सारा व्यवहार बन्द किया जाये, उनके नौकर नोटिस देकर नौकरी छोड़ दे और दूसरे भारतीय उनसे किसी प्रकारका लेन देन न करे। इसके बाद क्लक्सडाप अजुमनके एक सदस्य श्री दावजी पटेलने, जो देश जा रहे थे, अपना सारा बकाया चढ़ा चुकाया और उनके देशमें रहनेकी अवधिमें भी उनकी सदस्यता कायम रहे, इसलिए १० शिलिंग और जमा कर दिये। इसके बाद अजुमनकी ओरसे उन्हें चादीका एक पदक भेंट किया गया। कुछ लोगोने उनकी तारीफमें भाषण दिये। श्री दावजी पटेल स्वदेशके लिए रवाना हो चुके हैं।

दूसरे दिन सोमवारको श्री हेल् श्री गांधीके दफ्तरमें पजीयन अर्जीके सम्बन्धमें स्वयं खेद प्रकट करनेके लिए आये। धरनेदारोको तुरंत इसकी खबर मिल गई और उन्होंने श्री गांधीके नाम निम्नलिखित सूचना भेजी “यदि श्री हेल् भविष्यमें आपके दफ्तरमें आये तो, निश्चित समझिए, आपका भी बहिष्कार किया जायेगा।”

इसके उत्तरमें श्री गांधीने अपना कतव्य बजानेके लिए धरनेदारोका उपकार माना है और उन्हें शाबासी दी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा उत्साह सभी भारतीय सदा रखे। श्री हेल् यदि नियमानुसार माफी मागे और पश्चात्ताप करे तो माफ करना चाहिए या नहीं, इसका इस उत्साहसे कोई सम्बन्ध नहीं है। की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना और आये हुए कतव्यका निर्वाह करना समझने और अमल करनेकी बात है। जबतक श्री हेल्को माफ नहीं किया गया, तबतक उपयुक्त काय करना धरनेदारोका कतव्य था।

रामसुन्दर पण्डितका मुकद्दमा

श्री रामसुन्दर पण्डितके पास उनकी हिम्मतके लिए हर जगहसे बधाईके तार आ रहे हैं। उनमें हिम्मत है और जर्मिस्टनके सारे भारतीय उन्हें हिम्मत दिला रहे हैं। उन्हें अभीतक पकड़ा नहीं गया है। और जैसे श्री अब्दुल कादिर कोकाटीको नहीं पकड़ा जा सका वैसे ही यदि श्री पण्डितको भी न पकड़ा जा सके तो कोई आश्चर्य नहीं। इस सम्बन्धमें शुक्रवार तक जो भी होगा उसका तार भेजूंगा।

पीटर्सका मुकद्दमा

श्री ऐथनी पीटसपर जो अत्याचार हुआ उसकी चर्चा अब भी चल रही है। जिस सिपाहीने उनपर अत्याचार किया वह अब बदल गया है और कहता है, उसने उनके

इंडियन ओपिनियन, परिशिष्ट

२८ सितम्बर, १९०७

प्रिटोरियामें भारतीय सत्याग्रही

Supplement to INDIAN OPINION,
28th September, 1907.

Indian Passive Resistance Volunteers in Pretoria.



IBRAHIM NOOR इब्राहिम नूर	GOVIND PRAG गोविंद प्राग	GOULAB RUDRA DESAI गुलाब रुद्र देसाई	MOOSA SULIMAN मूसा सुलेमान	HOUSEN BIA हुसेन बिया	VALI M वली म
A. J. C. BEE ए० एफ० सी० बेग	BABU GANGARAM बाबू गंगाराम	GOULAM MAHOMED ABDUL RASHID गुलाम मुहम्मद अब्दुल रशीद	KHOOSHA SITA खुश सती	AMJED M. CAHAGIA अहमद एम० काछलिया	जी० पी०

इब्राहिम नूर गोविन्द प्राग गुलाब रुद्र देसाई मूसा सुलेमान हुसेन बिया वली
ए० एफ० सी० बेग बाबू गंगाराम गुलाम मुहम्मद अब्दुल रशीद अहमद एम० काछलिया जी० पी०

PASSIVE RESISTERS.

—*Jan 25/10/07*
on Von Brandis Square.

Gandhi's Explanation.

THE EDITOR, OF "THE STAR."

regret that I have to trespass
your courtesy again with reference
Asiatic Registration Act. Your
of to-day's happenings on Von
Square bears evident traces of in-

s by the description of Indian
as "pickets of coolies" as merely
brant description of inoffensive and
able men.

I maintain that neither the pickets
y other Indians have exceeded the
of moral suasion in preventing regis-
. The Indian referred to by your
er was in the witness-box to-day,
ertainly said that there was no
ation. He was taken hold of by
m, and, when he said that he want-
go to the registration office, he was
d to go. That was his own evidence,
orated by his co-registrant and the
d. I do not know whether this can
stretch of imagination be described
oughly collared outside the office."
men—there were two Indians—who

were met by the accused Indian, who, by
the way, was not a picket, did not know
what the law was. All they knew was
that they got a letter from their master
to go to some office in Johannesburg to
sign. Why should any exception be taken
to people at least informing such men of
the trap into which they were about to
fall? The opinion of the registration
officer that Dr. Mathey's client must have
been intimidated because he did not ap-
pear to register may, perhaps, be counter-
balanced by another and more probable
opinion—that the client has listened to the
remonstrances of his friends, and not been
intimidated. I am free to admit that
there are many Indians who, but for the
pickets, would allow themselves to be
registered. The real thing they fear is
not intimidation but Indian public opinion.
These are men who know the law to be
bad, but who cannot rise superior to their
worldly ambition, and they would un-
doubtedly register if there were no pickets.
To mention the priest case in connection
with the matter betrays either very great
ignorance or equally great prejudice on
the part of your reporter, because that
case was entirely a religious quarrel, and
the priest who was assaulted, in giving
his evidence, himself expressed exceeding
regret that he had ever filed his affidavit.
I do not wish to defend the Dervish who
committed the assault, but I fancy that
all communities have such men and all
are proud of them. They do not live for
a nationality but for a principle.—I am
etc.,

M. K. GANDHI.

Johannesburg, October 24.

“स्टार” को पत्र

(देखिए पृष्ठ ३०१-०२)

साथ कुछ नहीं किया था। अब श्री पीटसका हलफनामा मँगवाया गया है। मुकदमा और चलेगा।

ईलू मुथुका मुकदमा

ईलू मुथुका मुकदमा बहुत ही जानने योग्य है। उसके सम्बन्धमें श्री व्यास द्वारा लिखा हुआ एक प्रभावशाली पत्र मैं नीचे दे रहा हूँ

मजिस्ट्रेटकी ओरसे ईलू मुथुको दो दिनमें चले जानेका आदेश मिला है। उसे १८९७ में यहा बुलाया गया था। लडाईके पहले वह जोहानिसबर्गमें कुककी खेतीपर काम करता था। एक माह उसने राबिसन खानमें काम किया था। कुछ दिन हुए उसे बुलुवायोके पागलखानेमें रख दिया गया था, परंतु डाक्टरने हवा पानी बदलनेके लिए यहाके अस्पतालमें भेज दिया। पजीयकके आदेशसे पागलखानेका सिपाही उसे पजीयकके कार्यालयमें ले गया। वहा उससे उसका सारा हाल पूछा गया, जो उसने ऊपरके अनुसार बताया। अंतमें पजीयक महोदयने उसे देश छोड़नेका नोटिस दिया, जिसका परिणाम उपयुक्त हुआ है। ईलू मुथुका दिमाग अभी फिरा हुआ ही है। उसके पास तीन लुगियोके अलावा कुछ नहीं है। भाडापत्तीके लिए पजीयकने अँगूठा दिखा दिया है। मजिस्ट्रेटका कहना है कि यह हमारा काम नहीं है। पागलखानेसे भी रखसतनामा दे दिया गया है।

यह मुकदमा बहुत ही त्रासदायक है। ईलू मुथु भिखारी है। यहाका पुराना रहनेवाला है। यदि वह पजीयनके लिए अर्जी न देता, तो उसे कोई नहीं बुलाता। उससे जबरदस्ती अर्जी दिलवाई गई और अब उसे नोटिस मिला है कि वह देश छोड़कर चला जाये। कहा जाये? पैसे कहासे लाये? किस कारणसे जाये? जिस कानूनके द्वारा ऐसा जुल्म हो उसके सामने यदि कोई भारतीय घुटने टेकेगा तो उससे भारतीय प्रजा भी पूछेगी और खुदा भी पूछेगा। बिना अनुमतिपत्रवाले यदि पजीयनके लिए अर्जी देगे तो उनका भी ईलू मुथु जैसा ही हाल होगा और वैसा किया जाना उचित भी है। उनकी सुरक्षा अँगुलिया घिसनेमें नहीं, बल्कि ट्रासवाल छोड़नेमें है। और यदि उनका मामला मजबूत हो तो जेल जानेमें है। अब जेल भले और सच्चे लोगोंके लिए है।

चीनियोकी एकता

यहाके बड़े व्यापारी हार्विन और पेटसन चीनियोसे बहुत व्यापार करते हैं। वे हर महीने लगभग ५,००० पौडका माल उधार देते हैं। चीनियोको उन्होंने नोटिस दिया कि यदि वे नये पजीयनपत्र न लगे तो उन्हें माल उधार देना बंद कर दिया जायेगा। इसपर चीनियोने डरनेके बजाय ज्यादा हिम्मत की। उन्होंने कहा “हमारे बिल दीजिए। हम आपके पैसे चुका देना चाहते हैं। आपके मालकी हमें जरूरत नहीं। हम आपके साथ कारोबार बन्द करेंगे।”

यह सुनकर हार्विन साहब शांत हो गये। उन्होंने चीनियोसे माफी मागी और स्वीकार किया कि भविष्यमें पजीयनपत्र या हिसाबके सम्बन्धमें कोई बात नहीं की जायेगी। हमारे व्यापारियोको कुछ गोरे व्यापारी धमकाते हैं तो वे डर जाते हैं, और जैसे उनके गुलाम हो, पजीयनपत्र लेनेको तैयार हो जाते हैं। उस समय यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कानूनके आगे घुटने न टेकनेकी शपथ ली है।

धरनेदारोका काम

धरनेदार बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और इसमें शक नहीं कि उनके प्रयत्नोसे बहुतेरे कमजोर भारतीय एक जाते हैं। पाक, फोडूजबग, ब्रामफाटीन डानफाटीन और जेपी स्टेशनपर धरनेदार बठते हैं। वैसे ही, अनुमतिपत्र कार्यालयके आसपास भी। इस व्यवस्थाके कारण रडीपूटसे आनेवाले तीन भारतीय मजदूर हाथ आये थे। उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारीने जबरदस्ती पजीयन करवानेके लिए भेजा था। धरनेदारोसे भेट होनेपर उन्हें समझाया गया, इसपर वे यह कहकर वापस चले गये कि नौकरी छोड़ देगे मगर नये पजीयनपत्र नहीं लेगे।

इमाम कमाली लोगोको गुमराह करते हैं और बीचमे पडते ह, इससे लोगोमे बहुत क्षोभ और खेद पैदा हो गया है। इमाम कमाली भारतीय नहीं, मलायी हैं, इसलिए सबको यही लगता है कि उहे भारतीय मामलेमे दखल नहीं देना चाहिए।

भीमकाय प्रार्थनापत्र^१

यह प्रार्थनापत्र अभीतक सरकारके पास नहीं गया है। एक दो जगहसे फाम सही होकर नहीं आये हैं, इसलिए रुका हुआ है। इसमें लगभग सभी प्रमुख भारतीयोंके हस्ताक्षर हो चुके हैं। श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी हबीब, श्री ईसप मिया, श्री दादाभाई, श्री कुवाडिया वगैरह सज्जनोके हस्ताक्षर हैं। विशेष समाचार अगले सप्ताह देनेकी आशा करता हू।

मोहलत मिलेगी या नहीं ?

यदि दिसम्बरमे लोगोपर प्रहार हो और उहे मजिस्ट्रेटके समक्ष खड़ा किया जाये तो मोहलत मिलेगी या नहीं ? यह प्रश्न पूछा गया है। नये पजीयनपत्र न लेनेके कारण यदि किसीको मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया जाये, तो वह जानेके लिए मोहलत माग सकता है। कितनी मोहलत दी जाये, यह मजिस्ट्रेटके हाथमे है। यानी वह एक घटेसे एक वर्ष तक की या इससे भी ज्यादा मोहलत दे सकता है। लम्बी मोहलत देगा ही यह मैं नहीं कहता, परन्तु इसमें शक नहीं कि उसे लम्बी मोहलत देनेका अधिकार प्राप्त है। फिर भी मैं जानता हूँ कि इस तरह मोहलत मागनेमे हीनता है। और मैं किसीको इसकी सलाह नहीं दे सकता। जो जेलसे डरकर अपना कारोबार समेटना चाहे वे कुछ मोहलत माग सकते हैं और मैं नहीं समझता कि थोड़ी बहुत मोहलत देनेसे भी मजिस्ट्रेट इनकार करेगा। ये सब बातें हरएक मुकदमेपर, मजिस्ट्रेटपर और समयपर निर्भर ह।

ईसप मियाँका शोक

श्री ईसप मियाकी पत्नीका प्रसूतिकी बीमारीसे शुक्रवारकी रातको देहात हो गया। उससे बड़ा शोक फैल गया है। श्री ईसप मियाका इरादा अपनी पत्नीको लेकर हज करने जानेका था। किन्तु उन्हें खूनी कानूनकी लडाईके कारण रुक जाना पडा। इसी बीच यह खेदजनक घटना हो गई। इससे उहे बहुत दुःख हुआ है। खुदा श्री ईसप मियाको हिम्मत बख्शे, यह मेरी प्रार्थना है।

बेगका पत्र

श्री बेग अखबारोमे जोरसे लिखा करते हैं। प्रिटोरिया यूजमे उन्होंने श्री स्मट्सके भाषणके उत्तरमे लम्बा पत्र लिखा ओर श्री स्मट्सको उनकी बातोंका अनौचित्य दिखा दिया

है। श्री ब्रिटलबैकने भी उसी अखबारमे लम्बा पत्र लिखा है। उसमे ट्रान्सवालकी सरकारको फटकारा है। श्री बेगका एक पत्र 'लीडर' मे भी प्रकाशित हुआ है।

‘सडे टाइम्स’

अनाक्रामक प्रतिरोधके बादसे यह अखबार हर सप्ताह कोई न कोई चित्र छपा करता है। इस बार जो चित्र छपा है उसमे बिना काम मुफ्तकी तनरवाह लेनेवाले पजीयन अधि कारियोके दफ्तरका दृश्य है। उसके परिचयमे सम्पादकने लिखा है सरकारको चाहिए कि वह “कुलियो” को जरूर बाहर निकाल दे।

हाजी हबीब

श्री हाजी हबीब डबनसे प्रिटोरिया आ गये हैं।

सारा नवम्बर क्यों कोरा रखा गया ?

बहुत से लोगोने मुझसे पूछा है कि क्या सरकारको इतनी भूख लगी है कि वह सारा नवम्बर खा जायेगी ? जब भारतीयोपर मुकदमा ही चलाना है तो क्यों पहली नवम्बरसे शुरू नहीं करती ? जान पड़ता है कि ये प्रश्न करनेवाले भाई ‘इंडियन ओपिनियन’ ठीक तरहसे नहीं पढ़ते। नहीं तो, जहां मैंने नोटिसके बारेमे समझाया है वही यह बात भी आ गई है। अब मैं पाठकोको सलाह देता हूँ कि वे ‘इंडियन ओपिनियन’ बहुत ध्यानसे पढ़ा करे। उसे पढ़नेमे बहुत दिन नहीं लगते। और मुझे विश्वास है कि उसमे जानने योग्य कुछ-न कुछ तो उन्हें मिलेगा ही। इतना कह देनेके बाद अब मैं प्रश्नका उत्तर देता हूँ। जो नोटिस निकाले गये हैं उनके अनुसार जिन लोगोके पास पहली दिसम्बरसे नये पजीयनपत्र नहीं होंगे, उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। सारा अक्तूबर महीना पजीयनपत्रोकी अर्जी लेनेमे बीतेगा। अर्जी प्राप्त होते ही पजीयक महोदय उसका फैसला नहीं कर देते। अर्जी प्राप्त होनेके बाद जाच करनेका उहे अधिकार है। जाच करनेके लिए उहे कुछ समय चाहिए ही। सरकारने अर्जियोकी जाच करनेके लिए चैमने साहबको नवम्बर महीना दिया है। इस बीच जिसने गुलामीकी अर्जी दी होगी, उसे गुलामीका पुरस्कार मिलेगा या नहीं, इसका फैसला होगा। अर्थात् दिसम्बर महीनेमे सबके पास पजीयनपत्र हो, यह व्यवस्था हो गई। कोई पूछ सकता है कि भारतीय समाजने जब बहिष्कार किया है तब एक महीना और क्यों दिया गया ? इसका उत्तर यह है कि सरकार बहिष्कारकी ओर ध्यान नहीं दे सकती। कही ३१ अक्तूबरको आसमान फट पड़े और पजीयन कार्यालयमे अर्जियोकी वर्षा हो जाये, तो उन अर्जियोका फैसला करनेके लिए पजीयकको समय तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए दुर्भाग्यसे नवम्बरकी खाई पड़ी है।

धरनेदारोकी आफत

मंगलवारको वकील श्री अलेक्जेंडर और श्री डी'विलियसके पास दो दो कोकणी मुवक्किल थे। उनपर बिना अनुमतिपत्रके रहनेका आरोप था। दोनो वकीलोने श्री जाडनसे कहा कि इन कोकणियोको धरनेदार डराते हैं, इसलिए ये पजीयन कार्यालयमे नहीं जा सके। ये जानेको तैयार हैं। श्री अलेक्जेंडरने कहा कि अदालतको धरनेदारोको हटाना चाहिए। इसपर श्री गाधीने, जो वहाँ मौजूद थे, कहा कि धरनेदार बिलकुल धमकी नहीं देते और यदि कोकणियोका पजीयन कार्यालयमे जानेका विचार हो तो मैं स्वयं उहे ले जाऊँगा। यह बात

सम्भव है कि पुलिस अब आयुक्त (कमिश्नर) के पास जायेगी। इससे सघके मन्त्रीकी ओरसे पुलिस आयुक्तको निम्नानुसार पत्र लिखा गया है।^१

इस किस्सेसे धरनेदारोको ध्यान रखना है कि वे बहुत शांतिसे काम करे। धरनेदारोका काम लोगोको समझानेके सिवा और कुछ नहीं है और जब उनके साथ पुलिस हो तब तो किसीको बीचमे बिलकुल ही नहीं पडना चाहिए। जो लोग गुलाम बनना ही चाहे, उहे किसीको रोकनेकी जरूरत नहीं है। ऐसे भी भारतीय मौजूद हैं जो कहते हैं कि धरनेदार धमकाते हैं। इससे मैं लज्जित हूँ और मानता हूँ कि हमारा कितना दुर्भाग्य है। हर भारतीयको समझा दिया गया है कि यदि उसे हाथ घिसना ही हो तो धरनेदार स्वयं उसे ले जायेगे। इस चिट्ठीके छपनेके बाद अक्तूबरके और भी बारह दिन बचेगे। इतने दिनोंमे बहुत रग देखनेको मिलेगा। जोहानिसबगके प्रत्येक भारतीय व धरनेदारको मर्दानगी, ओर साथ ही धीरज, नम्रता और मिठास दिखाना है। सामान्य लोगोका काम है कि वे पजीयन कार्यालयका बहिष्कार करे। नेताओका काम है कि वे समझ व हिम्मत दे, और अपने पैसोका त्याग करे। और धरनेदारोका काम है कि वे धीरजसे अपना फज अदा करे। उनके दबावकी जरूरत नहीं है, उनकी हाजिरीकी जरूरत है। हर स्टेशन और हर जगह, जहासे भारतीयोका आना सम्भव हो, धरनेदार होने चाहिए। यदि धरनेदारको सरकार गिरफ्तार करे तो डरना नहीं है। यदि कोई धरना देते हुए पकडा जाये तो उसे याद रखना चाहिए कि जमानत नहीं देना है। और यदि सजा दी जाये तो जुमाना न देकर जेल जाना है।

नौकरी छोड़ी लेकिन हाथ नहीं धिसे

श्री मुरगन, श्री अरमुगम, श्री हेरी, श्री व्यकटापन, श्री मुथु, मिट्टीके बरतनोके कारखानेमे काम करते थे। उन्हें हुक्म दिया गया कि उहे पजीयन न करवाना हो तो नौकरी छोड दे। उन्होने नौकरी छोड दी, किंतु हाथ नहीं धिसे। ऐसा उत्साह हर भारतीयमे होना चाहिए। इन लोगोको मैं हीरा समझता हूँ।

नामर्द पदार्थानि हो गये

चार नामर्द कहीसे आये थे। वे पर्देवाली गाडीमे बैठकर पजीयन कार्यालयमे घुस गये और वहा उन्होने अपने हाथ धिसाये। बुधवारको इस तरह चार आदमियोने जोहानिसबग कार्यालयमे अपनी इज्जत बेचकर स्वयं गुलामीका रुक्का लेनेके लिए अर्जी दी।

चेतो ! चेतो ! चेतो !

पजीयन कार्यालय चाहे जिस तरहसे भारतीयोको पजीकृत करना चाहता है। मुझे आशा है कि इसका अर्थ प्रत्येक भारतीय समझ जायेगा। श्री स्मट्स जानते हैं कि यदि भारतीय मजबूत रहे तो किसीको बलात जेल भेजकर पजीकृत नहीं किया जा सकता। परवानेकी तकलीफ भी हजारो भारतीयोको नहीं दे सकते और इसलिए आखिर उन्हें कानून रद करना ही होगा। इस बातको ठीक समझकर हर भारतीयको चेतना चाहिए और हिम्मतसे काम लेना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२४० पत्र 'स्टार' को

जोहानिसबग

अक्टूबर २४, १९०७

सेवामे

सम्पादक

'स्टार'

[जोहानिसबग]

महोदय,

मुझे खेद है कि एशियाई पजीयन अधिनियमके बारेमे आपके सौजन्यका लाभ पुन उठा रहा हूँ। आपने वान ब्रैडिस स्ववेयरकी आजकी घटनाओकी जो रिपोर्ट दी है उसमे इसके साफ चिह्न दिखाई देते हैं कि वह किसीके उकसानेसे लिखी गई है।

इस बातको तो मैं नजरअन्दाज किये देता हूँ कि भारतीय धरनेदारोको "कुलियोके धरनेदार" कहा गया है, क्योंकि यह निर्दोष और प्रतिष्ठित व्यक्तियोका ज्ञानशूय चित्रण है।

मेरा अब भी यह खयाल है कि पजीयनको रोकनेके लिए न तो धरनेदार और न ही कोई अय भारतीय नतिक रूपसे समझाने बुझानेकी सीमासे आगे बढे हैं। जिस भारतीयका आपके सवाददाताने उल्लेख किया है वह आज अदालतमे गवाही दे रहा था, और उसने निश्चय ही यह कहा है कि उसे किसी प्रकार परेशान नहीं किया गया। उसकी बाह पकड ली गई थी और जब उसने कहा कि वह पजीयन कार्यालयमे जाना चाहता है तो उसे जाने दिया गया। यह उसका अपना ही साक्ष्य था और उसकी पुष्टि उसके पजीयन करानेवाले साथी तथा अभियुक्तने भी की। मैं नहीं जानता कि इसे किसी प्रकार कल्पनाकी खीचातानसे भी "दफ्तरके बाहर बुरी तरह गरदनिया देना" कहा जा सकता है। मैं प्रसंगवश कहूँ कि जिस भारतीय अभियुक्तने उन लोगोको — वे दो भारतीय थे — रोका था, वह कोई धरनेदार नहीं था, और उन दोनोको भी पता नहीं था कि कानून क्या है। वे बस इतना ही जानते थे कि उनके मालिकने एक पत्र देकर कहा कि वे जोहानिसबगके अमुक कार्यालयमे जाकर हस्ताक्षर कर आये। यदि कोई ऐसे आदमियोको कमसे कम इतना बता दे कि वे किस जालमे फँसने जा रहे हैं तो इसपर किसी प्रकारकी आपत्ति क्या होनी चाहिए? डाक्टर मेथेका आदमी पजीयन नहीं कराने पहुँचा, और पजीयन अधिकारी मान बैठे कि उसे अवश्य ही डराया धमकाया गया होगा। लेकिन उनकी इस धारणा जसी ही वजनी और अधिक सम्भावित तो यह बात भी हो सकती है कि उसने अपने मित्रोके उलाहनेपर ध्यान दिया, और उसे डराया नहीं गया। मैं इस बातको खुले दिलसे मजूर करता हूँ कि यदि धरना नहीं दिया जाता तो बहुतसे भारतीय पजीयन करा लेते। वास्तवमे वे जिस बातसे डरते हैं वह धौस धमकी नहीं है, बल्कि भारतीय जनमत है। वे ऐसे आदमी हैं जो जानते

हैं कि कानून बुरा है, फिर भी अपनी सासारिक अभिलाषाओंसे ऊपर नहीं उठ सकते, और यदि धरनेदार न होते तो वे पजीयन जरूर करा लेते। इस सम्बन्धमें मुल्लाके मामलेका उल्लेख या तो आपके सवाददाताका घोर अज्ञान या वैसा ही भारी पूर्वग्रह प्रकट करता है, क्योंकि यह मामला पूरी तरहसे वार्मिक झगडेका था और जिस मुल्लापर हमला किया गया था उसने अपनी गवाहीमें अपने हलफिया बयान देनेपर भारी खेद प्रकट किया था। मैं हमला करनेवाले फकीरकी ओरसे कोई सफाई देना नहीं चाहता। किंतु मैं समझता हूँ कि सभी समुदायोंमें ऐसे आदमी होते हैं, और सम्बंधित समुदायके लोग उनपर गव करते हैं। वे किसी राष्ट्रीयताके लिए नहीं, बल्कि एक सिद्धांतके लिए जीते हैं।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २५-१०-१९०७

२४१ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबग
अक्तूबर २६, १९०७ के पूव]

[सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबग]

महोदय,

एशियाई अनाक्रमक प्रतिरोधियोंकी कथित धमकियोंके सम्बन्धमें आपने जो सयत अग्रलेख लिखा है उसके लिए मेरा सच आपका आभारी है। भारतीय आंदोलनमें किसी भी प्रकारकी हिंसाके प्रयोगके विरुद्ध आपने जो-कुछ कहा है उसके प्रत्येक शब्दका समर्थन करनेमें हमें कोई सकोच नहीं हो सकता। एशियाई अधिनियमके बारेमें हमारा लक्ष्य हमेशा यह रहा है कि स्वयं कष्ट भोगकर, न कि दूसरोंको दुःख पहुँचाकर न्याय प्राप्त करें।

आपके स्तम्भोंमें जो अनुच्छेद प्रकाशित हुआ है वह स्पष्ट ही किसीकी प्रेरणासे लिखा गया है। आतंक-राज्यका अस्तित्व अस्वीकार करनेमें मुझे कोई सकोच नहीं है। यह बात दूसरी है, अगर अधिनियमके विरुद्ध ट्रान्सवालवासी समस्त भारतीय जनतामें व्याप्त अत्यन्त प्रबल भावनाने उन भारतीयोंके बीच आतंक फला रखा हो जो अपने आपको समाजके अलग कर इस अधिनियमके अनुसार प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं, और सो भी इसलिए नहीं कि उनको यह प्रणाली पसन्द है, बल्कि इसलिए कि वे पैसोंको प्रतिष्ठासे बढ़कर मानते हैं। मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि अनेक एशियाई अपना पजीयन करानेकी पूरी इच्छासे ही अपने कामकी जगहोंसे निकले थे, लेकिन बादमें उन्होंने उन चौकस धरनेदारोंके समर्थाने बुयानेपर ऐसा न करनेका फैसला किया। धरनेदारोंने पजीयन करानेवालोंके सामने कानूनका सही रूप खोलकर रख देनेकी

कारगर दलीलसे काम लिया और उनके मस्तिष्कसे उन सूक्ष्म प्रलोभनोंको निकाल दिया जो पजीयनके पुरस्कारस्वरूप उनके सामने प्रस्तुत किये गये थे। सरकार पजीयन करानेके लिए समाजको बहकानेके जो घोर प्रयत्न कर रही है उनके बारेमें जनताको कोई जानकारी नहीं हो सकती। धरनेदारोंने कभी भी धमकियोंसे काम नहीं लिया और समाजके जिम्मेदार लोग उन धरनेदारोंकी गतिविधियोंपर बराबर नजर रखते ह।

दुर्भाग्यवश, एक मुल्लापर आक्रमण किया जानेकी सूचना सच है, किन्तु उसपर कई भारतीयोंने मिलकर हमला नहीं किया था। वास्तविक घटना इस प्रकार है उक्त मुल्ला भारतीय नहीं, बल्कि एक मलायी है। हमारे बीच एक फकीर है, जो पैगम्बरका पक्का भक्त है। वह अपना पूरा वक्त तीनों मस्जिदोंमें से किसी न किसीमें गुजारता है और जब कभी वह ठीक समझता है, एक खानमें पत्थर तोड़नेका काम करके, अपनी रोटी कमाता है। वह किसीकी नहीं सुनता और शायद दक्षिण आफ्रिकामें सबसे ज्यादा आजाद तबीयतका आदमी है। उसे और उसकी सादी जिन्दगीको देखनेवाला हर आदमी उसकी इज्जत करता है। जब उसने यह सुना कि इस मलायी मुल्लाने भारतीयोंको, विशेषकर भारतीय मुसलमानोंको, अपनी शपथकी पवित्रता भग करके कानूनके आगे झुकनेको प्रोत्साहित किया है तब वह गुस्सेसे भर गया। वह इरादतन मलायी मस्जिदमें जा पहुँचा, उक्त मुल्लासे मिला और उसके साथ प्हस मुबाहसा करने लगा। उसने कुरानकी एक आयतका उदाहरण देते हुए मुल्लाको यह समझाया कि कमसे-कम उसे तो भारतीय मामलोंमें दखल देने और लोगोंको कुरानकी तालीमसे मुकर जानेके लिए फुसलानेसे दूर ही रहना चाहिए, खास तौरपर इसलिए कि वह भारतीय नहीं है। फिर तू-तू मैं मैं की नौबत आ गई, जिसका परिणाम हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमण। आप इस बातको स्वीकार करेंगे कि इस मामलेकी जिम्मेदारी भारतीयोंपर डालना नितान्त अनुचित है। हममें से अनेकने उस फकीरको समझानेकी कोशिश और उससे सयम बरतनेके लिए अनुनय विनय की है, किन्तु वह अपने व अपने खुदाके बीच किसीकी दस्त-दाजी मुनासिब नहीं मानता। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उसके लिए घर और जेल बराबर हैं। और दलील दी जानेपर उसने कहा कि वह अदालतके सामने जाकर अपने कायका औचित्य सिद्ध करनेके लिए बिलकुल तैयार है।

जहातक कुत्तोंको जहर देनेका मामला है, वह इल्जाम शरारत भरा है। मने बड़ी सावधानीसे जाच की है, लेकिन मुझे जहर देने और कुत्तोंके मालिकके पजीयनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं मिल सका। पिछले दिनों भारतीयोंके अनेक कुत्तोंको जहर दिया गया है। आम तौरपर ऐसा खयाल है कि काम चोरोका है, जो इन कुत्तोंके भौकनेके कारण पकड़े जानेसे बचना चाहते थे। अगर भारतीय-गद्दारोंके साथ होनेवाली हरएक दुष्टटनाको भारतीय अनाक्रामक प्रति-रोधियोंके मत्थे मढा जायेगा तो यह बड़ी भयंकर बात होगी। महोदय, आप विश्वास कीजिए, अल्पसंख्यकोंको बहुसंख्यक भारतीयोंकी इच्छाके सामने झुकानेके लिए किसी आपत्तिजनक तरीकेको अपनानेकी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम, जो अपने आचार-व्यवहारमें स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इसीलिए एशियाई अधिनियमको माननेसे इनकार करते हैं उन दूसरे आदिमियोंपर पाबन्दी लगा भी कैसे सकते हैं जो हमारे जैसा नहीं सोचते? हम, जो अपने लिए स्वतंत्रता तथा आत्मसम्मानका दावा करते हैं, अगर दूसरोंको उतनी ही स्वतंत्रता देनेसे इनकार करते हैं तो अपने आदर्शोंके प्रति झूठे साबित होंगे।

और जहातक आपके सवाददाता द्वारा उल्लिखित सागर तटपर बसे नगरके हिन्दू पुजारी की बात है, जर्मिस्टनमे निश्चय ही दगा नहीं हुआ है। यह बिल्कुल सच है कि उक्त पुजारीने उपनिवेशके अय हर पुजारीकी तरह ही, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, एक ऐसे प्रश्नमे दिलचस्पी ली है जो पूरे भारतीय समुदायके कल्याणसे सम्बन्धित है। अपने धर्मसे प्रेम करनेवाले किसी भी भारतीयका आचरण इससे भिन्न नहीं होगा। क्या ऐसे मामलेमे, जिसमे ईश्वर और कुबेरमे से एकको चुनना हो, एक पुजारी अपने श्रोताओंसे यह अनुरोध नहीं कर सकता कि वह कुबेरकी ओर देखनेकी अपेक्षा ईश्वरकी ओर देखे ?

[आपका, आदि,
ईसप इस्माइस मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४२ स्वर्गीय श्री अलेक्जेंडर

डबनके भूतपूर्व मुख्य पुलिस अधिकारीकी^१ मृत्युके समाचारसे वहाके पूरे समाजको दुःख आघात पहुँचा है। जरसीके लिए रवाना होते समय श्री अलेक्जेंडरका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और यह आशा की जाती थी कि वे अभी अनेक वर्षोंतक जीवित रहकर सु-अर्जित विश्रामका उपभोग करेंगे। इस बातको याद कर अत्यधिक कष्ट होता है कि डबन नगरके सर्वोच्च पुलिस अधिकारीको जो थैली भेट की गई थी वह ठीक ऐसे समयपर मिली थी कि उससे वे घर जा सके। वे डबनकी सवसमाजी आबादीके इतने प्यारे हो गये थे कि उसको बहुत समय तक याद आते रहेगे। हम उनकी विधवाकी इस क्षतिमे हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। दरअसल तो यह समाजकी भी क्षति है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४३ अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके लिए^१

राजकीय आवश्यकताका सिद्धांत, ईश्वरीय नियमका उल्लंघन करनेके लिए केवल उहीं लोगोंको बाँध सकता है जो सासारिक लाभोंकी प्राप्तिके लिए अमायको भी माय करनेकी कोशिश करते हैं। किंतु एक ईसाई, जो ईसा मसीहकी शिक्षाके अनुसार आचरण करनेसे मोक्ष पानेमें सच्चा विश्वास रखता है, उस सिद्धांतको कोई महत्त्व नहीं दे सकता। — टॉल्स्टाय

डेविड थोरो एक महान लेखक, दार्शनिक, कवि और साथ ही अत्यंत व्यावहारिक पुरुष भी था। अर्थात् वह ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता था जिसपर वह स्वयं आचरण करनेके लिए तैयार न हो। वह अमरीकाके महानतम और सबसे सदाचारी व्यक्तियोंमें से एक था। दासता उन्मूलन आंदोलनके समय उसने “सविनय अवज्ञाके कतव्य” के बारेमें अपना प्रसिद्ध निबंध लिखा था। अपने सिद्धांतों तथा पीड़ित मावनताके लिए वह जेल भी गया। इसलिए उसका निबंध कष्ट सहन द्वारा पवित्र हो चुका है। इसके अलावा वह हमेशाके लिए रचा गया है। उसकी पैनी दलीलोंका जवाब नहीं दिया जा सकता। जिन एशियाई अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके मूक कण्ठकी कहानी अब समस्त सभ्य ससारके कानों तक पहुँच चुकी है उनके लिए अक्टूबरका महीना कण्ठकर प्रलोभनोंसे पूर्ण था — इसी महीनेके अंतिम सप्ताहमें हम थोरोके निबंधसे कुछ उद्धरण नीचे दे रहे हैं। मूल निबंध एक जेबी पुस्तकके तीस पष्ठोंसे कुछ अधिक है। इस पुस्तकको श्री ऑथर सी० फीफील्ड, ४४ फ्लीट स्ट्रीट, लंदन, ने अपने ‘सादा जीवन’ नामक सुंदर पुस्तकमालामें प्रकाशित किया है। इसका मूल्य तीन पैसे है।

उद्धरण

म इस आदेश वाक्यको हृदयसे स्वीकार करता हूँ कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो कमसे कम शासन करती है, और मैं चाहता हूँ कि इसपर जल्दी और ढगसे अमल किया जाये। अमलमें उसका अंतिम रूप यह हो जाता है और इसपर भी मेरा विश्वास है “वही सरकार सबसे अच्छी है, जो बिल्कुल शासन नहीं करती,” और जब मनुष्य इसके लिए तैयार हो तो वे ऐसी ही सरकार बनायेंगे। सरकार अधिकसे अधिक एक काय-साधक संस्था है, किंतु प्रायः बहुतेरी सरकारें और कभी कभी सभी सरकारें काय-साधक नहीं होती।

आखिरकार, जब सत्ता एक बार जनताके हाथों चली जाती है तब बहुसंख्यकोंको जो शासन करने दिया जाता है, और वह भी लम्बे अंसे तक के लिए, सो इसलिए नहीं कि उनके सही रास्ते जानेकी अधिकसे-अधिक सम्भावना रहती है और न ही इसलिए कि वह अल्पसंख्यकोंको सर्वाधिक उचित जान पड़ता है, बल्कि इसलिए कि

१ अनाक्रामक प्रतिरोधके सिद्धान्तमें गांधीजीकी जो दिलचस्पी थी वह बादमें इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित एक घोषणाके रूपमें यत्न हुई। घोषणामें उक्त विषयसे सम्बन्धित निबंध माँगे गये थे। देखिए परिशिष्ट ६।

वे अधिक बलवान होते ह। लेकिन जो सरकार हर बातमें बहुसरयकोकी ही सुनती हो वह यायपर आधारित नहीं हो सकती, उस सीमा तक भी नहीं जिस सीमा तक लोग वैसा समझते ह।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४४ राष्ट्र-पितामह

हमारे पाठकोको यह जानकर दुःख होगा कि श्री दादाभाई नोरोजी अचानक बीमार पड़ जानेके कारण, उस शानदार विदाई भोजमें उपस्थित न हो सके जो उनके सम्मानमें दिया गया था। अभी मुझे 'इंडिया' पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उस समारोहका पूरा विवरण छपा है। उससे ज्ञात होता है कि समारोहमें सभी राजनीतिक विचारोंके लोगोंने भाग लिया था। किसी समुद्री तारके न आनेसे जान पड़ता है कि राष्ट्र-पितामहकी तबीयत अब अच्छी हो गई है और उनके सयमी, तपस्वी तथा निग्रही जीवनने, जिसका सर मचरजीने इतनी वाग्मितासे वर्णन किया, उनका अच्छा साथ दिया है। हमें आशा है कि जिस देशको वे इतना अधिक प्यार करते हैं उसके लिए वे दीर्घकाल तक जीवित रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४५ मेमन लोगोकी विपरीत बुद्धि

हममें एक कहावत है, विनाश कालमें बुद्धि विपरीत हो जाती है। यही हाल द्रासवालोंके मेमन लोगोका हो गया है। उनमें गुलामीका पट्टा न लेनेवाले बहुत कम लोग बचे होंगे। जो बचे हैं उन्हें हम सिहके समान मानते हैं। जिन्होंने दुमति बरती है उन्हें चोट पहुँचानेके लिए हम यह लेख नहीं लिख रहे, बल्कि इसलिए लिख रहे हैं कि उनके बुरे कामसे दूसरे भारतीय अच्छा सबक लें।

मेमन लोगोंने पजीयनपत्र ले लिये हैं, इससे दूसरी कौमोको डरना नहीं चाहिए। डरना बेहिम्मतकी निशानी है। कोई यह न समझ ले कि चूँकि मेमन लोगोंने खूनी कानूनके चिट्ठे ले लिये, इसलिए वे ट्रान्सवालमें सुखसे व्यापार करेंगे और ज्यादा कमायेंगे, तथा दूसरे भारतीयोंको भागना पड़ेगा। वास्तवमें जहाँ थोड़े से मेमन गुलाम बन गये हैं, वहाँ सैकड़ों भारतीय मुक्त हैं। इस बातको समझकर हमें खुदाकी बदगी करनी चाहिए। जो यह आशा करते हैं कि गुलामीका पट्टा लेनेके बाद मेमन सुखसे व्यापार कर सकेंगे उन्हें हम नासमझ मानते हैं। और यदि दूसरे भारतीयोंको द्रासवाल छोड़ना पड़ा तो मेमन लोगोको जो ठोकरें पड़ेगी वह गोरे तो देख ही पायेंगे। उनकी स्थितिकी कल्पना करके हमें कँपकँपी छूटती है।

लेकिन हम मानते हैं कि यदि दूसरे भारतीयोंका अच्छा-खासा भाग दब रहकर जेल जानेको तैयार रहा तो किसीको ट्रान्सवाल नहीं छोड़ना पड़ेगा। सभी हकदार भारतीय शान्तिपूर्वक ट्रान्सवालमें रह सकेंगे और नया कानून रद हो जायेगा। जो लोग मानते हैं कि वह रद नहीं होगा उन्हें, हम समझते हैं, खुदाकी सचाई और उसके अति पवित्र यायपर भरोसा नहीं है। इसलिए हम शेष भारतीयोंसे प्रार्थना करते हैं कि “आप भारतकी नाक रखे, सारी तकलीफें उठाये, किन्तु कानूनके सामने न झुके।” ‘कुरान शरीफ’ के अन्तिम सूरेमें जो कहा गया है उसके अंग्रेजी अनुवादका गुजराती भाषांतर हम नीचे दे रहे हैं

कहो कि मैं उस खुदाकी शरण जाता हूँ जो सारे आलमका बादशाह है। वह मुझे शैतानके, दुष्टोंके तथा मनुष्योंके पजेसे बचायेगा।

ये शब्द हर भारतीयको अकित कर लेने चाहिए। अभी कायरोके पजोंसे बचनेका समय है। उपयुक्त आयत हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबपर लागू होती है। सत्य तो एक ही है और खुदा भी सबका एक ही है। “आकार पानेपर नाम रूप भिन्न है, सोना तो अतम सोना ही है।”

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४६ ट्रान्सवालके भारतीयोंका कर्तव्य

इस शीषकसे हम कई बार लिख चुके हैं तथा और भी कई बार लिखना पड़ेगा। हमने श्री रिचका पत्र और सलग्न पत्रोंका अनुवाद करके दिया है। हम ट्रान्सवालके प्रत्येक भारतीयसे उसे पढ़नेका अनुरोध करते हैं। समितिका हर सदस्य उनके साथ है। हमोदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र भी श्री मालें तक पहुँच गया है। उस पत्रकी चर्चा विलायतमें हो रही है। सर जॉज बडबुड भारतके बहुत ही समझदार, पुराने और जाने-माने सेवक हैं। उनका बहुत समय भारतीय परिषदकी नौकरीमें बीता है। उन्होंने लिखा है कि भारतीयोंकी लड़ाई उचित है। इसमेंसे कुछ भारतीयोंको कमजोर देखकर श्री रिच सोच विचारमें पड़ जाते हैं। मतलब यह कि समिति चाहती है कि हमें लड़ाई अततक लड़नी चाहिए। अपनी लड़ाईका इस तरह प्रचार करनेके बाद जो भारतीय अपने स्वाथ या पैसेके लोभके कारण डरकर कानूनकी शरण चला जाये उसे हम अपना और अपने देशका दुश्मन मानते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

१ सुप्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहताके एक मंजनसे। इन्हीकी एक रचना ‘वैष्णव जन तो’ बादमें गांधीजीकी प्रिय प्रार्थना हुई। इस मंजनमें सच्चे ईश्वर भक्तके लक्षणोंका वर्णन है।

२४७ लेडीस्मिथके भारतीय व्यापारी

लेडीस्मिथ तालुकेमे बारह भारतीय दूकाने बंद हो गई ह। इस खबरको हम बहुत ही बुरा मानते हैं। इन व्यापारियोने परवानेके लिए फिर अर्जी दी थी। कि तु उहे परवाने नही मिले, उलटे सूचना मिली कि यदि दूकाने बंद न होगी तो मुकदमे चलाये जायेगे। इस सूचनासे डरकर व्यापारियोने दूकाने बंद कर दी हैं। हमारी तो खास तोरसे सलाह हे कि अब भी वे अपनी दूकाने हिम्मतसे खुली रखे ओर व्यापार करे। बिना परवानेके व्यापार करनेपर यदि सरकार मुकदमा चलाये तो चलाने दिया जाये। मुकदमा चलनेपर यदि जुर्माना हो तो वह न दिया जाये। इसपर माल नीलाम होगा। हमारी राय हे कि इस तरह माल नीलाम होने दिया जाये। इसमे हिम्मतकी जरूरत हे। लेकिन यदि मद हिम्मत न दिखायेगे तो कौन दिखायेगा ? कोई कहेगा कि माल नीलाम होगा तो लोग बर्बाद हो जायेगे। तो क्या दूकान बन्द होनेसे लोग बर्बाद नही होंगे ? सरकार एक वक्त माल नीलाम करेगी, क्या हमेशा करेगी ? सरकार एक व्यापारी-पर मुकदमा चलायेगी, क्या सबपर चलायेगी ? ओर यदि ऐसा करेगी तो क्या बड़ी सरकार हस्तक्षेप न करेगी ? बड़ी सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये बिना काम न होगा। यदि उसे हस्तक्षेप करना ही नही हे तो उसका भी अनुभव हो जाना चाहिए। यदि भारतीय प्रजा एकताके साथ लड़ाई लडेगी तो हमे विश्वास है कि नेटालका व्यापारी कानून रद्द होकर रहेगा। डबनके नेताआसे हमारी सिफारिश हे कि वे लेडीस्मिथके व्यापारियोसे मिलकर एकताके साथ लड़ाई लडनका निश्चय करे। यह आवश्यक हे। हमारा दब मत हे कि इसमे हिम्मतकी जितनी जरूरत हे, उतनी पसेकी नही। इस तरहकी लड़ाई लडनेकी हिम्मत रखनेवालेको इतना याद रखना चाहिए कि (१) लड़ाई पुराने भण्डारोके सम्बन्धमे लडी जा सकती हे, (२) दूकाने साफ होनी चाहिए, (३) दूकानदारोपर कलक न होना चाहिए। ऐसे दुकानदार हिलमिलकर लडेगे तो सिवा जीतके और कोई परिणाम हो ही नही सकता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४८ भारतके राष्ट्र-पितामह

पूज्य दादाभाई नोरोजी इस समय विलायतमें ह । अपनी अति वृद्धावस्था तथा बीमारीके कारण उन्होंने अपनी उत्तरावस्था देशमें वितानी चाही । इसलिए उनके सम्मानमें लन्दनमें बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था । दुर्भाग्यसे उसी दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया । वे सम्मेलनमें नहीं जा पाये और उनका स्वदेश लाटना भी रह गया । यह समाचार विलायतसे पिउली डाकसे आया है । इस प्रसंगको अब लगभग एक महीना होने जा रहा है । आजतक कोई तार नहीं आया है । इसमें माना जा सकता है कि भारतके पितामह अभी सकुशल ह और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा । आगामी डाकसे विशेष समाचार प्राप्त होने चाहिए । इस बीच हम सबको ईश्वरसे यह प्रार्थना करनी है कि वह पितामहको दीर्घायु करे ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२४९ स्वर्गीय अधीक्षक अलेक्जैंडर

सुपरिटेण्डेंट अलेक्जैंडरका इंग्लैंडमें देहावसान हो गया यह तार समाचारपत्रोंमें छपा है । यह समाचार हमारे लिए बड़ा खेदजनक है और हम मानते हैं कि इससे प्रत्येक भारतीयको खेद होगा । सुपरिटेण्डेंट अलेक्जैंडरने भारतीयोंके प्रति कृपालु दृष्टि रखी थी । इस अवसरपर स्मरण किया जा सकता है कि भारतीय समाजकी ओरसे उन्हें जो थेली मिली थी, वह इंग्लैंड जानेंमें उन्हें बड़ी काम आई थी । श्री अलेक्जैंडर अपने पीछे अपनी पत्नी छोड़ गये ह । हमारी उनसे सहानुभूति है ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

२५० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमीदिया अजुमनकी सभा

हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी बैठक नियमानुसार गत रविवारको हुई थी। सभा भवन खचाखच भर गया था और लोगोमे बहुत ही जोश था। इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। श्री रामसुन्दर पण्डितने जोशीला भाषण दिया और रेलवे सेवामे लगे भारतीयोके साथकी भेटका बयान किया। मौलवी साहब अहमद मुरत्यारने 'कुरान शरीफ' की आयत सुनाकर बताया कि खुदाकी कसम खानेके बाद मुसलमान कानूनके सामने झुक ही नहीं सकते। उन्होने कहा कि श्री हेलूके नौकर यदि उहे प्रोत्साहन दे तो उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। समाजके आदमीको समाजके अदर गदगी फैलाने नहीं दी जा सकती।

श्री गांधीने प्रिटोरियासे आया हुआ हाजी हबीबका पत्र और क्लाक्सडापके पत्र पढ़कर सुनाये और कहा कि किसीको बहिष्कारकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि बात निकले ही तो फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए।

श्री अली भाई आकूजीने कहा कि यदि सभी गद्दाराका बहिष्कार किया जाना तय हो, तो वे स्वयं श्री हेलूके कानमिया लोगोको खींच लेनेकी तजवीज करेगे। श्री एम० एस० कुवाडियाने कहा कि श्री हाजी हबीबने लिखा है कि जोहानिसबर्गके नेताओमे से कोई एक चोरीसे पजीकृत हो गया है। किन्तु मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होने सभी गद्दारोका बहिष्कार करनेकी बात पसन्द की। उन्हें ५० पौडका लाभ होनेकी सम्भावना थी। फिर भी जब एस० बुचरने यह सूचना भेजी कि पजीकृत हो जाओ तो आटा भेजूगा, तब उन्होने आटा लेनेसे साफ इनकार करके नुकसान उठाना मजूर किया।

श्री उमरजी सालेने बहिष्कारका समर्थन किया। श्री इब्राहीम कुवाडियाने 'अल इस्लाम' का 'अनुमतिपत्रका पियानो' (परमिट पियानो) लेख और कविता पढ़कर सुनाई। मौलवी साहबने फिरसे उठकर निवेदन किया कि हमीदिया इस्लामिया अजुमनको राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्षके पास इस कानून सम्बन्धी लडाईके बारेमे लिखना चाहिए। यूरोपकी ओर जानेवाले जमन लाइनके जहाजोके लिए पहले, दूसरे और तीसरे दर्जेके टिकट नहीं मिलते, इस सम्बन्धमे समाजकी ओरसे कुछ किया जाना चाहिए। बहिष्कारका रास्ता सरल है।

श्री इब्राहीम कुवाडियाने कांग्रेसको पत्र लिखनेके सम्बन्धमे मौलवी साहबके निवेदनका समर्थन किया। बादमे कुछ और सज्जनोने भाषण दिये, और अन्तमे अध्यक्ष महोदयके भाषणके बाद सभा समाप्त हुई।

मद्रासियोकी सभा

मार्केट स्ट्रीटमे मद्रासियोकी सभा हुई थी। लगभग सौ व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। श्री गांधीने उन्हें सारी हकीकत समझाई और सबने कानूनके विरोधमे अतत्क दृढ़ रहनेका निश्चय किया।

‘ट्रान्सवाल लीडर’ में लेख

पिछले शनिवारके ‘ट्रान्सवाल लीडर’ में सवाद हे कि जान पडता है, भारतीय समाजका जोर घट रहा है, क्योंकि कुछ भारतीयोंने एक इमामको इस कारण पीटा कि वह एक भारतीयको अनुमतिपत्र कार्यालयमें ले गया था, उस भारतीयके कुत्तेको जहर दे दिया जिसने अनुमतिपत्र लिया, और जर्मिस्टनके हिंदू पुरोहितने जर्मिस्टनमें उपद्रव खडा कर दिया। इसपर टीका करते हुए ‘लीडर’ कहता हे कि यद्यपि मारपीट वगैरहमें भारतीय नेता शामिल नहीं होंगे, फिर भी भारतीय समाजके कोई भी व्यक्ति मारपीट वगैरहके काम करेंगे तो उनकी ओर किमीकी सहानुभूति नहीं रहेगी और उनका नुकसान होगा।

ईसप मियाँका पत्र

इसके जवाबमें श्री ईसप मियाने निम्न पत्र^१ लिखा हे
महोदय,

अनाक्रमक प्रतिरोधी डराने धमकानेका काम करते हैं, इस तथाकथित बातपर आपने जो नम्रतापूर्ण टीका की हे उसके लिए मेरा सघ आभारी है।

किंतु आपके पत्रमें प्रकाशित विवरण द्वेषभरा मालूम होता है। इस बातसे इनकार करनेमें मुझे जरा भी सकोच नहीं ह कि लोगोको डरा-धमकाकर उनमें आतक पैदा किया गया हे। पजीयनको अच्छा न समझनेपर भी पैसेके लोभमें फँसकर कुछ लोग पजीकृत होना चाहते होंगे। किंतु उमसे उहे सारे समाजसे बहिष्कृत होना पडेगा, और इसलिए काननके खिलाफ सारे मजाजमें जो तिरस्कार फैला हुआ हे उसे यदि बहिष्कृत होनेवाले लोग आतक मानकर डरते हो तो उससे मैं इनकार नहीं करता। यह सही है कि कुछ पजीकृत होने जा रहे ये और बादमें नहीं हुए। इसका कारण यह हे कि धरनेदारोंने मिलकर जब उहे कानूनकी गुलामीका अथ समझाया और लालचकी बुराई स्पष्ट कर दी तभी उन्होंने पजीकृत न होनेका निश्चय कर लिया था। भारतीय समाजको पजीयनके लिए फूसलानेमें सरकार कितना अथरु परिश्रम कर रही है, इसे लोग नहीं जानते। धरनेदाराने कभी भी धमकीका उपयोग नहीं किया। भारतीय समाजके जिम्मेदार लोग उनकी गतिविधिपर निगरानी रखते ह।

दुर्भाग्यसे यह सच हे कि एक इमामपर हमला हुआ, किन्तु भारतीयोकी टुकडीने हमला नहीं किया था। हकीकत इस प्रकार है

उक्त इमाम भारतीय नहीं, बल्कि मलायी है। हम लोगोमें एक दरवेश साहब है। धमके मामलेमें वे बहुत ही कट्टर हैं। वे अपना सब समय मसजिदमें बिताते हैं। और राटीके लिए, जब इच्छा होती है, खानोपर पत्थर तोडनेका काम करते हैं। वे किसीकी बात नहीं सुनते और सारे दक्षिण आफ्रिकामे शायद सबसे स्वतन्त्र मिजाजके हैं। जिन्होंने उन्हें और उनकी सादगीको देखा है वे उनका आदर करते हैं। उन्हें जब मालूम हुआ कि सदर मलायी इमाम भारतीय मुसलमानोको अपनी पवित्र शपथ तोडनेको बहका रहा है, उनका खून खौल उठा। वे जानबूझकर मलायी मसजिदमें गये और इमामसे

१ मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए “पत्र ‘ट्रान्सवाल लीडर’ को”, पृष्ठ ३०२-०४।

मिलकर उन्होंने उससे वादविवाद किया। उन्होंने इमामको विश्वास दिलानेके लिए कुरानकी एक आयत सुनाई और कहा “आप तो इमाम हैं, इसके अलावा आप भारतीय नहीं, मलायी हैं, आपको भारतीय मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इमाम होकर कुरानकी आयतको तोड़नेके लिए लोगोंको नहीं बहकाना चाहिए।” समझाते समझाते दोनों गरम हो गये, बोलचाल शुरू हुई और उससे मारपीट हो गई। इस प्रकार यह घटना घटी। इसमें भारतीयोंपर खतरनाक होनेका आरोप लगाना बहुत ही अनुचित होगा। हममें से बहुतेरोंने दरवेश साहबको समझाया तथा शांत होनेके लिए उनसे मित्रता की। लेकिन उनका कहना है कि खुदा ओंग मेरे बीच किसीको नहीं आना चाहिए। कहनेकी जरूरत नहीं कि उनके लिए घर और जेलखाना दोनों एक जैसे हैं। उन्हें समझाया गया तो उन्होंने कहा है कि मैं अदालतमें जाकर अपनी बात समझानेकी तैयार हूँ।

कुत्तेको जहर देनेका आरोप लगाना निंदयतापूर्ण है। मैंने इस बातकी बहुत ही बारीकीसे जाच की है। लेकिन कुत्तेको जहर देने और उसके मालिकके पजीकृत होनेमें कोई सम्बंध नहीं है। लोग मानते हैं कि कुत्तेके भौकनेके कारण पकड़े जानेसे बचनेके लिए किसी चोरने वैसा किया होगा। किसी भारतीय गद्दारका नुकसान हो और उसका दोष आप अनाक्रामक प्रतिरोधीके सिर थोपे तब तो बड़ी भयंकर बात होगी। नहीं महोदय, बहुसरयक भारतीयोंकी इच्छाका पालन करनेके लिए अल्पसरयकोको लाचार करनेके अनुचित उपाय काममें लानेका हमारा जरा भी इरादा नहीं है। जैसे हम स्वतंत्र रहनेके लिए कानूनके वश नहीं होते, उसी तरह दूसरोंके अपनी इच्छाके अनुसार चलनेकी स्वतंत्रता भोगनेमें हम आड़े आना नहीं चाहते।

जर्मिस्टनके हिंदू धर्मगुरुके सम्बंधमें आपके सवाददाताने जैसा लिखा है वैसी कोई घटना नहीं घटी। हा, यह बात बिल्कुल ठीक है कि उक्त धर्मगुरु कानूनके मामलेमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। ओर ऐसा तो इस उपनिवेशके सभी हिंदू व मुसलमान धर्मगुरु करते हैं क्योंकि यह सवाल समस्त भारतीय समाजपर लागू होता है। यदि भारतीयोंको अपना धर्म प्यारा हो तो उनसे लड़ाईमें उत्साह दिखाये बिना रहा ही नहीं जा सकता। जहां यह विकल्प खड़ा हो कि इन्सान रहे या हैवान बने, वहां अपनी इंसानियतको कायम रखनेकी सलाह क्या धर्मगुरु नहीं दे सकता?

इस किस्सेपर टीका

यह किस्सा बहुत ही विचार करने योग्य है। इमाम कमाली तथा श्री हेलूने पजीयन अधिकारीसे बहुत बड़ा चढ़ाकर झूठी बातें कही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ईसप मियाने सिद्ध कर दिया है कि बहुत से भारतीयोंके मारपीट करनेकी बात बिल्कुल झूठी है। फकीरकी पिटाईकी जिम्मेदारी भारतीय कौमपर डालना बिल्कुल गलत है। श्री हेलूके कुत्तेको किसी भी भारतीयने जहर दिया होगा यह बिल्कुल असम्भव है। लेकिन इस उदाहरणसे इतनी बात बिल्कुल समझ ली जानी चाहिए कि हमारी लड़ाईमें मारपीटके लिए कोई स्थान नहीं है। मारपीट करके हमें विजय प्राप्त करना नहीं है। और जो खुदापर भरोसा रखकर लड़ते हैं उन्हें मारपीट आदिके साधनोंकी आवश्यकता होती ही नहीं। मैं तो किसी भी दिन नहीं मानगा कि सत्यकी हार हो सकती है। भारतीयोंका मामला बिल्कुल सच्चा है, इसलिए हमें निभय होकर रहना

चाहिए। जो खूनी कानूनके सामने घुटने टेकेगे उनके नये पजीयनपत्र उनके लिए ही कच्चे पारेकी तरह फूट निकलेंगे और फिर वे हाथ मलते रह जायेंगे।

धरनेदारोके बारेमे पुलिस आयुक्तका पत्र

पाठकोको याद होगा कि धरनेदार बिल्कुल बल प्रयोग नहीं करते, ऐसा एक पत्र लिखा गया था। पुलिस आयुक्तने उसका जबाब निम्नानुसार दिया है ^१

इस विषयमे कि आपके सघने वान ब्रैडिस स्कवेयरमे अपने धरनेदार तैनात कर रखे हैं, आपका पत्र मिला। आप विश्वास दिलाते हैं कि पजीयन कराने वालोको कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा। इसमे मुझे खुशी हुई है। मैं आशा करता हूँ कि उसके अनुसार आपकी कोशिश जारी रहगी।

इस पत्रसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि धरनेदार नियुक्त करनेमे दोष नहीं है। यदि वे हाथ चलाये या धमकी दे तो उसमे दोष है।

जनवरीमे परवाने बन्द ?

यह सूचना 'गजट' मे आ गई है कि जो पजीयन नहीं करवायेगे उन्हें जनवरीमे परवाने नहीं दिये जायेंगे। फिर भी हर शहरमे मुख्य भारतीयोको लिखित सूचना दी जा रही है कि यदि वे ३१ अक्टूबरके पहले नये पजीयनके लिए अर्जी नहीं दे देगे, तो फिर नहीं दे सकेंगे और जनवरीमे परवाने भी नहीं मिलेंगे। इस तरहकी सूचना देकर रसीद भी ली जाती है। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट है कि सरकार स्वयं डर गई है कि यदि भारतीय समाज कानूनके सामने नहीं झुकता तो फिर उसका कुछ भी बिगाडा नहीं जा सकता। इसलिए अब गडबडी शुरू की गई है और सरकार धमकी देकर या फुसलाकर गुलामीका पट्टा दिलवाना चाहती है। इस तरहके चिह्न दिखाइ दे रहे हैं फिर भी ऐसे भारतीय मौजूद हैं जो अब भी नहीं चेतते और पैसेके मोहमे फँसकर पतंगोके समान खूनी कानूनरूपी चिरागपर कूद पडते हैं, ओर जल मरते हैं। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे भारतीय इन चिह्नोंसे सचेत होकर अन्ततक मजबूत रहेंगे।

जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन^२

मौलवी साहबने हमीदिया सभामे कहा था कि इस कम्पनीके यूरोपकी ओर जानेवाले जहाजोके लिए भारतीयोको छत (डेक) के सिवा दूसरे स्थानोके टिकट नहीं मिलते। यह मामूली बात नहीं है। इस विषयमे कुछ समयसे विवाद चला आ रहा है। मौलवी साहबके कथनानुसार इसमे मुख्य तकलीफ हाजियोको हो सकती है। उपाय बहुत ही सीधा है। एक तो यह कि लाइनमे भिन्न भिन्न जगहोपर जो भारतीय एजेंट हैं वे ठीक प्रबंध करे, दूसरा उपाय सीधे बहिष्कारका है। इस लाइनको भारतीय यात्रियोसे बहुत ही आमदनी होती है। यदि भारतीय यात्रियोके साथ जानवरके समान व्यवहार होता रहा तो वह आमदनी बन्द हो सकती है। उसके लिए भारतीयोमे भारी पैमानेपर प्रयास किया जाना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कम्पनी तथा दूसरी कम्पनियोके साथ व्यवस्था की जा सकती है तथा पहले मुगल लाइनके जो जहाज आते थे वे फिरसे शुरू किये जा सकते हैं। ऐसे कई उपाय हैं।

१ मूल अंग्रेजी पत्र २६-१०-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था।

२ देखिए जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन, ४२४ २५ भी।

‘स्टार’ को पत्र

भारतीय धरनेदारोपर जो धमकीका इल्जाम लगाया गया है वह तो बिल्कुल झूठ है। लेकिन यह सच है कि कुछ गोरे लोग अधिकारियोंकी सिखावनसे भारतीयोंको परेशान करते हैं और गुलामीका पट्टा लेनेके लिए धमकिया देते हैं। इसपर श्री गांधीने ‘स्टार’ को निम्न पत्र^१ लिखा है

महोदय, जो पजीकृत होना चाहते हैं उन्हें डरानेका आरोप सवथा निर्दोष धरनेदारोपर बिना किसी सबूतके लगाया जाता है। इस आरोपके खोखलेपनकी ओर तथा पजीकृत न होनेवालोंको जो सचमुच डराया-धमकाया जा रहा है उसकी ओर मैं लोगोका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

कलकी बात है। उसमें पीटसबगसे आये हुए तीन भारतीयोंको धरनेदारोंने स्वयं पजीयन कार्यालयमें ले जानेको कहा था। किन्तु वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी धरनेदारोको बदनाम करनेके लिए यह ढोंग रचा जा रहा है कि डर लगता है। इस आधारपर पुलिसका संरक्षण प्राप्त करनेके प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। यदि इस आरोपमें कुछ भी सचाई है तो फिर अभीतक किसीपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? यदि वह सच ही है तो उसे सिद्ध करना सबसे आसान काम है। क्योंकि यदि डराने धमकानेका काम होता होगा तो वह तो ब्रैडिश स्क्वेयरमें सरेआम सैकड़ों राहगीरोंके सामने होता होगा।

अब मैं इस विषयकी बात कहूँगा कि जो लोग पजीयन नहीं करवाना चाहते उन्हें धमकी दी जाती है। बहुतेरे भारतीयोंको लगता है कि जिनके पास कैप्टन फाउल अथवा श्री चैमने द्वारा दिये गये अनुमतिपत्र हैं उन्हें, नये पजीयनपत्र न लेनेके कारण, आड़े टेढ़े तरीकोसे अधिकारीवगका दबाव पड़नेके कारण नौकरीसे अलग कर दिया जाता है। जर्मिस्टनमें भारतीयोंको नये कानूनके मुताबिक पजीकृत न होनेके कारण नौकरीसे अलग कर दिया गया है। यह बात सच है — इस आशयका एक पत्र जर्मिस्टनके मुख्य धरनेदारके पाससे मुझे मिला है। दबावकी बात सच है या झूठ, यह उपयुक्त पत्रसे मालूम हो सकता है। इससे हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं जनरल स्मट्सने इस प्रकारकी धमकिया देनेमें पहल की है। उन्होंने हर प्रकारकी सजाकी धमकिया दी है। वे निर्वासित करने और परवाना छीनने — दोनों प्रकारकी सजाएँ एक साथ देनेको कह चुके हैं। ये दोनों सजाएँ एक ही व्यक्तिको एक साथ कैसे दी जा सकती हैं, यह मेरी समझमें तो नहीं आता। प्रवासी कानूनके बिना निर्वासित करना सम्भव नहीं है, और उस कानूनको मजूरी तो अभी मिलनी ही बाकी है। भारतीय शुद्ध लडाईसे नहीं डरते, और जैसा मैं देख रहा हूँ, यदि सरकार अशुद्ध लडाई लड़ना चाहेगी तो उसमें जूझनेको भी वे तैयार हैं। लेकिन सरकारका ऐसा करना तो अग्रेजोंके लिए अशोभनीय है। गुलामीके प्रमाणपत्रके लिए भारतीयोंपर जोरो-जबदस्ती करनेमें गोरे मालिकोंकी मदद क्यों ली जानी चाहिए? बहुत मालिकोंने ऐसे दबावका विरोध किया है और अपने भारतीय नौकरोको बर्खास्त करनेसे साफ इनकार कर दिया है। इसके लिए दोनों आदरके पात्र हैं — मालिक

इसलिए कि वे दगाबाजीमें शामिल नहीं होना चाहते, और भारतीय नौकर इसलिए कि वे इतने लायक और नमकहलाल ह कि उनके मालिक उन्हें छोड़ नहीं सकते।

मुझे अभी ही मालूम हुआ है कि जिन चार भारतीयोंकी ओरसे यह कहा गया था कि उन्हें धमकी दी गई है और जिनके पास अनुमतिपत्र बिलकुल थे ही नहीं, वे आज छूट गये ह, और उन्हें भरी अदालतमें विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें पजीयन प्रमाणपत्र मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि गुलामोंको नये पजीयन प्रमाणपत्र रूपी पट्टे मिलने ही चाहिए। मेरी रायमें जिन लोगोंके पास पुराने डच पास हा (जैसा कि कहा गया है, चार व्यक्तियोंके पास है) उन्हें शांति-रक्षा अध्यादेशके अनुसार दिये हुए अनुमतिपत्रवालोंके समान मानना चाहिए। लेकिन यह सब जानते हैं कि उन लोगोंको तो श्री जाडनने उपनिवेश छोड़कर जानेके लिए नोटिस दिया था। जिस दिन उपयुक्त चार व्यक्तियोंने नये पजीयनपत्र लेनेके लिए अर्जी देनेको कहा उसी दिन उन जैसे पासवाले एक भारतीयको नोटिस मिला था। इसलिए जान पड़ता है कि जनरल स्मट्स इस खोजमें लगे ह कि कोन कायदेके मुताबिक रह रहा है और कौन बेकायदे।

चिदेसे सहायता

चिदेके भारतीयोंने सहानुभूतिके तार ही नहीं साथमें पैसे भी भेजे हैं। चिदेसे श्री इब्राहीम हाजी सुलेमान सघके नाम निम्नानुसार लिखते हैं^१

वहाकी मुसीबतोंमें हमारी पूरी सहानुभूति व्यक्त करनेवाला २२ अगस्तका हमारा तार आपको मिला होगा। हमें आशा है कि हमारे भाई अततक उत्साह कायम रखेंगे।

२१ तारीखको हमारी सभा हुई थी। उसका विवरण न देकर मैं इतना ही सूचित करता हूँ कि उस सभामें बहुत से भारतीय उपस्थित हुए थे और उत्साह बहुत था।

हमने उसी समय चंदा भी वसूल किया और कुल मिलाकर ३३ पौंड १५ शिलिंग ९ पेस जमा हुए। यह रकम यद्यपि हम बहुत कम मानते ह, फिर भी आपको भेज रहे हैं। स्वीकार करे।

चंदा देनेवालोंके नाम इसके साथ भेज रहा हूँ। बहुत से लोगोंकी सलाह है कि इस सूचीको 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित किया जाये। यह सूचना इसलिए नहीं दी गई कि वे अपना नाम अखबारमें देखना चाहते हैं बल्कि इस आशासे दी गई है कि इसे देखकर दूसरे लोग भी मदद करेंगे।

यह मांग ऐसी नहीं कि जिसे साफ नामजूर कर दिया जाये। इसलिए वह सूची खुशी खुशी प्रकाशनके लिए भेज रहा हूँ। चंदा देनेवालोंके नाम इस प्रकार ह^२

चिदेके सघको आभारका पत्र भेज दिया गया है।

१ मूल अंग्रेजी पत्र २६-१०-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया था।

२ इसके बाद मूलमें ४६ नामोंकी सूची दी गई थी, जो यहाँ नहीं दी जा रही है।

एक कुत्तेकी बहादुरी

यहाके धरनेदारोने एक प्रसिद्ध चित्रकारका बनाया चित्र खरीदा हे। वह बहुत ही प्रभावोत्पादक और हर भारतीयको जोश दिलानेवाला हे। उसमे एक कुत्ते ओर दो बालिकाओका दश्य हे। बालिकाओने जूते उतार दिये है ओर उनमेसे एक कुत्तेको रस्सी बाव कर खीचती हे और दूसरी उसे धक्का देती हे। लेकिन वह बहादुर अपनी जगहसे टससे मस नही होता। इसका नाम हे अनाक्रामक प्रतिरोध [पैसिव रेजिस्टेस]। चित्रकारने भी इस चित्रको अनाक्रामक प्रतिरोधी कहा है। वह कुत्ता इतना बलवान चित्रित किया गया हे कि यदि काटना चाहे तो काट सकता हे। लडकिया हठीली तो है कि तु वचिचया है। लेकिन कुत्ता सिफ अपनी जगह नही छोडना चाहता। वह कहता हे “मै तुम्हारा गुलाम कदापि नही बन सकता। तुम मुझे रस्सीसे खीचो या धक्के मारो, पर म नही हटूंगा। स्वेच्छासे तुम्हारे साथ चलू तो बात अलग हे। तुम्हारी जवदस्ती नही चलेगी। न मै ही तुमपर कोई बल प्रयोग करूँगा।” भारतीयोकी लडाई इसी प्रकारकी है। हमे किसीपर बल प्रयोग नही करना हे। लेकिन हमने जो प्रतिज्ञा की हे उसे भी नही छोडना हे।

गद्दारीकी सूची

आजतकके गद्दारीकी — उहे काले पैरवाले कलमुहे, पियानो बजानेवाले, कुछ भी कहिए — जो सूची मेरे हाथमे आई हे, वह यहा दे रहा हूँ^१

इस सूचीको प्रकाशित करते हुए मझे शम आती है। लेकिन कतव्य समझकर, शमको दबाकर, प्रकाशित कर रहा हूँ। इनमे से श्री हासिम मुहम्मद पीटसबगमे मुख्य धरनेदार थे। उन्होने कलक लगवाया, यह कम खेदकी बात नही है। इनमे पहल करनेवाले श्री अबू ऐयबजी माने जाते है। लेकिन वे श्री खमीसाकी शतरजकी वाजीमे एक प्यादे थे। उहे क्या दोष दिया जाये? ये महागय इतने शरमाते थे कि इहोने पहले नम्बरका पजीयन लेनेमे आनाकानी की। इसलिए पजीयन अविकारिने इहे १२७ वा नम्बर दिया। इतनी बेहूदगी होते हुए भी भारतीय डरता है, यही हमारी अधमताका चिह्न हे। इस सूचीसे मालूम होता हे कि पजीयन करवानेवालामे मुरयत मेमन लोग है। कुछ कोकणी है और शेषमे एक गुजराती हिन्दू ओर दो तीन मद्रासी है। इसमे श्री हेलू और दूसरे चार-पाच कोकणी आदिके, जो जोहानिसबगमे अर्जी दे चुके है नाम नही है। अब ज्यादा दिन नही ह। बाजे-गाजेके साथ बरात मडवेमे पहुच जायेगी। उपयुक्त सूची बडी मुश्किलसे मिली है। प्रिटोरियाके व्यापार सघको वह मेहरबानीके तौरपर दी गई थी। लेकिन जहा बात एक कानसे दूसरे कानपर जाती है कि हवामे उडने लगती हे वहा यदि सघको लिखित सूची मिले और वहासे दूसरेके पास चली जाये तो उसमे आश्चय कोन-सा? और यदि दूसरेको मिलती है तो फिर बेचारे ‘इंडियन ओपिनियन’ का क्या दोष? इसपर यदि कोई यह माने कि ये नाम मुझे व्यापार सघसे मिले है तो यह उसकी भूल होगी। कहासे मिले, इसे जाननेकी इच्छावालेको फिलहाल तो हवा खानी पडेगी।

क्लाक्सर्टडॉर्फका अखबार

यह अखबार कानूनके बारेमे जो आलोचना करता हे उसे देखकर हँसी आती हे। उसने कहा कि श्री गांधी जैसे उपद्रवी आदमीका क्या लगता हे? वह तो थैली उठाकर दूसरी

जगह जा बैठेगा। लेकिन जिनके धन दौलत है उहे तो गुलाम बन ही जाना चाहिए। क्याकि सरकार तो कह ही चुकी है कि भारतीयाको निर्वासित कर दिया जायेगा, ओर उन्हे परवाने भी नही दिये जायेगे। क्लाक्सडायके अखबारके सम्पादकने यह सीख आप्त जनकी तरह दी है। सम्पादक महोदय यह भूल जाते है कि लोग सम्पत्ति गुलाम बननेके लिए नही बल्कि आजाद रहनेके लिए रखते है। कटार म्यानमे रखी हुई तो शाभा बढाती है, किन्तु यदि छातीमे खास ली जाये तो मौत हो जाती है, उसी प्रकार सम्पत्ति इज्जतदार आदमीको ही शोभा देती है। गुलामके लिए तो वह छातीमे खोसी हुई कटार है। जिन्होंने सम्पत्ति कमाई है उन्हे उसे बबाद करनेका हक है। ओर भारतीय समाज उन्ही हकोको बरत रहा है। यह सयानेपनकी शिक्षा देनेवाले गोरे अपने देश और सम्मानके लिए कई बार स्वय अपनी सम्पत्ति गँवा चुके ह। और उन्होंने उतनी ही आसानीसे फिर कमा भी ली है। अब यदि अपने सम्मान और धमके लिए भारतीय समाज अपनी सम्पत्तिको लात मारता है तो उसमे आश्चर्य कोन सा ?

बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा

मैं लिख चुका हूँ कि श्री दुलभ वीराका परवाना सम्बन्धी मुकदमा रूडीपूटमे चला था। उसमे मजिस्ट्रेटने यद्यपि श्री दुलभ वीराके प्रति सहानुभूति व्यक्त की, फिर भी फैसला उसके विरुद्ध दिया। मुकदमा दो व्यक्तियोंपर था। एक उनपर और दूसरे उनके नौकरपर। श्री दुलभ वीराके पास परवाना नही था। नौकरने माल बेचा था, इसलिए मुकदमा उसपर भी था। मजिस्ट्रेटने फसला दिया कि यद्यपि श्री दुलभ वीराको परवाना पानेका हक है, फिर भी चूकि आदाताने परवाना नही दिया, इसलिए उन्हे दूकान खोलनेका हक नही है। नौकरने चूकि माल बेचा था, इसलिए वह व्यापार हुआ, और इसलिए उसे भी गुनहगार ठहराया गया। नौकरको सजा नही दी गई। श्री दुलभ वीराको एक शिलिंग जुर्माना किया गया।

सर्वोच्च न्यायालयमे जो अपील की गई थी उसमे ये कारण बताये गये थे

(१) नौकरने माल बेचा, यह गुनाह नही है। कानून सिर्फ मालिकको ही गुनहगार ठहरा सकता है।

(२) श्री दुलभ वीराने परवानेके लिए अर्जी दी थी, किन्तु उनका हक होते हुए भी चूकि आदाताने परवाना नही दिया इसलिए उसमे श्री दुलभ वीराका दोष नही माना जा सकता। अतः, उनको दण्ड न दिया जाना चाहिए।

अदालतने अपीलका निणय यह किया कि बिना परवानेके व्यापार करनेवाले मालिकको कानून सजा देता है। वह नौकरको सजा नही दे सकता। इसलिए नौकर निर्दोष है। उसका कुछ नही हो सकता।

श्री दुलभ वीराको [न्यायालयके अनुसार] परवाना लिये बिना दूकान खुली रखनेका हक नही था। उहे आदाताको फिरसे अर्जी देनी चाहिए। उसके बाद यदि न्यायालयको मालूम होगा कि आदाता जान-बझकर परवाना नही दे रहा है, तो न्यायालय उसे खच दिलवायेगा और अजदारकी नुकसानीकी पूर्ति भी करवायेगा।

यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमे से कई रास्ते निकल सकते ह। यह ट्रान्सवालकी लडाईमे लोगोको बहुत हिम्मत देनेवाला है। बहुतेरे भारतीयोको डर है कि जनवरीमे परवाना नही मिला तो दूकाने बंद कर देनी चाहिए। किन्तु अब वह डर नही

रहा। सजा सिर्फ दूकानके मालिकको ही हो सकती है। कानूनमें दूकान बंद करनेका अधिकार नहीं है। और दूकानमें नोकर काम कर सकते हैं। इसलिए दूकान बंद करनेका प्रश्न नहीं रहता। सिर्फ दूकानके मालिकको जेलकी असुविधा (मेरे हिसाबसे सुविधा) भोगनी होगी। मैं इस फैसलेको बहुत कीमती मानता हूँ।

आदातासे हर्जाना और खर्च मिल सकता है, यह बात भी बहुत प्रोत्साहन देनेवाली है।

इस मुकदमेका फैसला मालूम हो जानेपर भी यदि कोई भारतीय व्यापारी डिगता है तो मानना होगा कि हम इस खूनी कानूनके योग्य ही हैं।

शाहजी साहबको दण्ड

इमाम कमालीने शाहजी साहबके खिलाफ मार पीट करनेकी फरियाद की थी। उस मुकदमेकी सुनवाई बुधवारको अदालतमें हुई थी। इमाम कमालीने उसमें बयान देते हुए कहा कि उन्होंने हलफनामा दिया, इसका उन्हें पछतावा है। कानूनके सम्बन्धमें दोनोंके बीच धर्म विवाद हुआ था और शाहजी साहबने डंडा मारा था। परन्तु अब वे नहीं चाहते कि इसपर कोई सजा दी जाये। शाहजी साहबने भी उपयुक्त मार पीटकी बातको स्वीकार किया। अदालत ठाठास भरी हुई थी। मजिस्ट्रेटने ५ पौंड जुर्माने या सात दिन जेलकी सजा दी। शाहजी साहबने जुर्माना देनेसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन श्री गुलाम कडोदियाने जबदस्ती वह दे दिया।

ब्रिटिश भारतीय सघकी समितिकी बैठक

सघ और भारतीय विरोधी कानून निधिकी बैठक बुधवारको बारह बजे हुई थी। श्री ईसप मिया अध्यक्ष थे। श्री गांधीने कहा कि अब समाजको श्री दुलभ वीराका मुकदमा हाथमें लेना चाहिए। दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको कायम रखनेकी व्यवस्था की जानी चाहिए और चूकि समाजकी स्थिति डावाडोल है इसलिए बेहतर होगा कि भारतीय विरोधी कानून निधिकी रकम उनके हाथमें रखनेका निणय किया जाये। श्री उमरजी, श्री नायडू, श्री आमद मसाजी और श्री फैसी उस सम्बन्धमें बोले और उसके बाद सर्वानुमतिसे निम्न प्रस्ताव पास किये गये

(१) दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको एक वर्ष चलाया जाये और नेटालसे पहले छ महीनेके लिए सहायता मांगी जाये।

(२) श्री दुलभ वीराका मुकदमा सघ आगे बढ़ाये तथा उसपर २० पौंड तक खर्च किया जाये।

(३) भारतीय विरोधी कानून निधिका हिसाब उठाकर वह रकम श्री गांधीके सुपुद की जाये।

और गद्दार

^१ ने पजीयनके लिए प्राथनापत्र दिये हैं। मुझे यह सूचना देते हुए खेद है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

१ मूलमें यहाँ चार नाम दिये गये हैं।

२५१ पत्र सर विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबग

अक्तूबर ३१, १९०७ के पूर्व]

सेवामे

सर विलियम वेडरबर्न

अध्यक्ष

ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय महासभा

लन्दन

[महोदय,]

एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमे जो नाजुक स्थिति यहा उत्पन्न हो रही हे उसकी ओर मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पजीयनके लिए अंतिम तिथि आगामी ३० नवम्बर हे। उसके पश्चात, विशेष मामलोको छोडकर, कानूनके अंतगत दिये जानेवाले पजीयन प्रमाणपत्रोके लिए भेजी गई अजियोको सरकार स्वीकार नही करेगी। मेमन समाजको छोडकर, भारतीय सामान्यतः पजीयन कार्यालयमे नही गये है, और १३,००० अनुमतिपत्र-स्वामियोमे से केवल २५० ने ही कानूनकी अधीनता स्वीकार करनेके सम्बन्धमे प्राथनापत्र भेजे है। इसमे भावनाकी तीव्रता प्रकट होती है। राहत पानेका हमारे पास यह तरीका है कि कानूनको भंग करनेके सब परिणामोको सहन किया जाये। सम्भव हे, कुछको, जो बहुत बडे व्यापारी ह अपना सबस्व बलिदान करना पडे। उनमे से बहुतेरे तो इस दुखका अभी ही अनुभव कर रहे है, क्योंकि यूरोपीय थोक विक्रेताओने भारतीय व्यापारियोको, यदि वे पजीयन प्रमाणपत्र पेश न कर सके, उधार माल देना बन्द कर दिया हे। गरीब भारतीय अपनी नौकरियोसे हाथ धो बैठे है, और तब भी कानूनके प्रति वही विरोध और वही दडता बनी हुई हे।

मेरे सघकी रायमे यह प्रश्न साम्राज्यीय महत्त्वकी दृष्टिसे प्रथम श्रेणीका तथा भारतके लिए राष्ट्रीय महत्त्वका है। अतएव मेरा सघ आशा करता हे कि यह मामला कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमे उत्साहके साथ उठाया जायेगा और भारतकी सवसाधारण जनता भी इस प्रश्नपर यथोचित ध्यान देगी। और इस उद्देश्यसे मेरा सघ सम्मानपूर्वक आपकी सक्रिय सहायुभूति और प्रोत्साहनके लिए अनुरोध करता है। मेरे सघको लगता है कि प्रत्येक भारतीय, आपके कांग्रेसी पदसे अलग, आपको भारतका एक सबसे बडा शुभचिन्तक मानता है। मै आशा करता हूँ कि हमारे इस वर्तमान सघषमे भी आप भारतमे भारतीय विचारका वैसा मागदशन करेगे जो वाञ्छनीय प्रतीत हो।

[आपका

ईसप इस्माइल मिया

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५२ पत्र उपनिवेश-सचिवको^१

जोहानिसबग
नवम्बर १ १९०७

सेवामे
उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,

मैं आपकी सेवामे डाक पासलसे एशियाई पजीयन कानूनके विषयमे ट्रान्सवाल भरके ब्रिटिश भारतीयोका प्राथनापत्र भेज रहा हूँ। साथमे अनुयाचकोको दी गई हिदायतोकी^२ एक प्रति भी हे।

कुछ भारतीयोने उक्त कानूनके अतगत बनाये गये विनियमोमे सशोबनकी माग करते हुए सरकारको एक पत्र लिखा था। जब —ने— फाम बाटे गये उस समय तक उस पत्रका कोई उत्तर नही आया था ओर न ही उसे वापस लिया गया था। लेकिन तबसे यद्यपि सवश्री स्टगमान, एसेलेन व रुजके मुवक्किलोको कोई सतोषजनक उत्तर नही मिला हे और फलत उन्होने अपना पत्र वापस भी ले लिया है तथापि मेरे सघकी समिति चाहती हे कि मैं उक्त प्राथनापत्र प्रेषित करूँ क्योंकि उसमे उसपर हस्ताक्षर करनेवाले लोगोकी भावनाएँ सन्निहित है। मेरे सघकी नम्र सम्मतिमे, प्राथनापत्र उसके द्वारा अपनाये गये रुखका औचित्य पूरा पूरा सिद्ध कर देता हे, और उससे यह प्रकट होता है कि वह उपनिवेशमे रहनेवाले भारतीयोके भारी बहुमतका प्रतिनिधित्व करता हे। प्राथनापत्र कुछ दिनोंसे तैयार पडा था, लेकिन सघने इसे पेश करना रोक रखा, क्योंकि वह पजीयन-कार्यालयके जोहानिसबगमे खुले रहनेकी अवधिमे समाजकी गतिविधियोकी परख करना चाहता था।

प्राथनापत्रपर ४,५२२ हस्ताक्षर है, और वे हस्ताक्षरकर्ता ट्रान्सवालके २९ नगरो, गावो और जिलोमे से है। केद्रोके अनुसार विश्लेषण इस प्रकार हे जोहानिसबग, २०८५, यूक्लेयर, १०८, रूडीपुट, १३६, क्रूगसडॉप, १७९, जर्मिस्टन, ३००, बाक्सबग १२९, बिनोनी, ९१, माडरफॉटीन, ५१, प्रिटोरिया, ५७७, पीटसबग और स्पेलोनकेन ९०, वेरीनिगिंग, ७३, हाइडेलबग, ६६, बैलफर, १४, स्टैडन, १२३, फोक्सरस्ट, ३६, वाक्स्ट्रूम, १२, पीट रिटीफ, ३, बेथाल, १८, मिडलबग, २९, बेलफास्ट, मेकाडोडाप और वाटरवाल, २१, बाबटन, ६८, पाचेपस्ट्रूम, ११४, वेन्टसडाप, १२, क्लाक्सडाप, ४१, क्रिश्चियाना, २४, लिखतनबग, ७, जीरस्ट, ५९, रस्टनबग, ५४, अरमीलो, २।

ट्रान्सवालमे भारतके हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी ह, तथा मुसलमान तीन हिस्सोमे बँटे हुए है सूरती, कोकणी तथा मेमन। उसी प्रकार हिंदू भी गुजराती, मद्रासी

१ नवम्बर २, १९०७ के इंडियन ओपिनियनमें इस पत्रका सारांश प्रकाशित किया गया था।

२ देखिए 'भीमकाय प्रार्थनापत्र', पृष्ठ २३७-३८।

और उत्तरके, जिन्हे साधारणतया कलकतिया कहते हैं, रूपमे विभक्त हैं। सिखो ओर पठानोका अलग वर्गीकरण न करना पड़े इस विचारसे यदि हिंदू हैं तो उन्हें उत्तरी लोगोमे और मुसलमान हैं तो सूरती लोगोमे शामिल कर लिया गया है। ईसाइयोका अलगसे वर्गीकरण नहीं किया गया, क्योंकि एक तो लगभग वे सबके-सब मद्रासी हैं और, दूसरे, वे कुल मिलाकर २०० से अधिक नहीं हैं। अतः, धर्म और प्रातके हिसाबसे वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है सूरती, १,४७६, कोकणी, १४१, मेमन, १४०, गुजराती हिंदू, १,६००, मद्रासी, ९९१, उत्तरी, १५७, पारसी, १७।

मैं यह भी कह दूँ कि मेमनोको छोड़कर शायद ही कोई हस्ताक्षर देनेसे रहे हो, किन्तु हस्ताक्षरोकी अनुयाचनाक लिए हमें जितना समय मिला था उसमे ट्रान्सवालके कोने अंतरोके हिस्से — जैसे फारम आदिमे बसे हुए हर भारतीय तक पहुँच पाना मेरे सघके बूतेसे बाहरकी बात थी। अनुयाचकोने — जिनमे सब जिम्मेदार ओर प्रातिनिधिक व्यक्ति हैं — खबर दी है कि समाजको जो सघप करना पड़ रहा है उसके कारण भारतीय एक बड़ी तादादमे ट्रान्सवाल छोड़कर जा चुके हैं। सभी मानते हैं कि शांति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत ब्रिटिश भारतीयोको १३,००० अनुमतिपत्र दिये गये हैं, और जब गत वर्ष सितम्बर मासमे दुर्भाग्यसे यह सघप शुरू हुआ तब लगभग इतने ही भारतीय ट्रान्सवालमे रहते थे। आज मेरे सघको प्राप्त जानकारीके अनुसार ट्रान्सवालमे ८००० से अधिक ब्रिटिश भारतीय नहीं हैं, बल्कि यह सरया, सम्भवतः, ८,००० की अपेक्षा ७,००० के अधिक करीब है। मेरे सघको यह ज्ञात है कि थोक व्यापारियोके दबाव डालने या ऐसे ही दूसरे कारणोसे कुछ मेमनो ओर अय लोगाने, जिनकी सख्या ३० स अधिक नहीं है, दस्तखत वापस ले लिये हैं और कानूनके अंतगत पजीयनकी दररवास्त की है। इसके अतिरिक्त मेरे सघ द्वारा प्राप्त जानकारीके अनुसार जिस अवधि तक — अर्थात् १ जुलाईसे ३१ अक्टूबर तक — पजीयन चलता रहा, उसमे सारे ट्रान्सवालमे ३५० से ज्यादा भारतीयोंने पजीयनके लिए दरखास्त नहीं की है, और इन प्राथियोमे से ९५ प्रतिशत मेमन हैं।

अन्तमे मेरा सघ सरकारका ध्यान एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध उस समाजकी तीव्र भावनाकी ओर आकर्षित करता है जिसका कि मेरा सघ प्रतिनिधि है। समाजको इसके प्रति जो रुख अस्तित्वार करना पड़ा है उसमे उसका इरादा सरकार अथवा देशके कानूनको अमान्य करनेका नहीं रहा है। बल्कि बात यह है कि इस कानून द्वारा समाजपर जो ज्यादाती की गई है उसकी अनुभूति तथा कानूनके समस्त निहित अर्थोंने भारतीयोको वे मुसीबते झेलनेके लिए तैयार हो जाओपर मजबूर कर दिया है, जो अनाक्रमक प्रतिरोधके लिए, जिस रूपमे ब्रिटिश भारतीयोंने उसे समझा है, उन्हें झेलनी पड़ेगी।

[आपका, आदि

ईसप मियाँ

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, २-११-१९०७

२५३ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबर्ग]

नवम्बर १, [१९०७]

[सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबर्ग]

महोदय,

अपने आजके अकेले अग्रलेखमें आपने ब्रिटिश भारतीय सघपर एशियाई पजीयन अधि नियमके बारेमें यह वक्तव्य देनेका आरोप लगाया है कि जिन चार सौ व्यक्तियोंने अपना पजीयन करवाया है, उन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका कोई अधिकार नहीं है। सघके किसी पदाधिकारी द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जानेका मुझे कोई पता नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ धरनेदारोंने कतिपय ऐसे वक्तव्य दिये थे लेकिन यह केवल दुःसाहस था। मुख्य धरनेदार श्री नायडूने तत्काल इसका सुधार कर दिया था। लेकिन भूल-सुधारका प्रकाशन आपकी रिपोर्टमें नहीं किया गया। सघने जो अधिकृत वक्तव्य दिया था वह यह है कि कमसे-कम ऐसे चार व्यक्तियोंने, जिन्हें कानूनकी सरकारी व्याख्याके अनुसार इस देशमें रहनेका अधिकार नहीं है, पजीयन-प्रमाणपत्रके लिए अर्जिया दी हैं और, कदाचित्, उन्हें प्रमाणपत्र मिल भी गये हैं, सघ तो इन लोगोंको भी प्रमाणपत्रके अधिकारी नहीं समझता।

यदि सरकार अर्जिया लेनेके लिए दफ्तर खुला रखती है तो मुझे विनयपूर्वक इस बातसे इनकार करना होगा कि यह कोई भलमनसाहत भरी रियायत है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयोंकी रायमें सरकार द्वारा अपनी कमजोरीको मजूर करना होगा। ब्रिटिश भारतीय सघने अत्यन्त नम्रतापूर्वक तथा उच्चतर प्रेरणाके वशीभूत होकर सरकारको चुनौती दी है कि वह जितना बुरा कर सके, कर ले। हमें पजीयनकी चिकोटियोंकी जरूरत नहीं है और यदि धरनेदारोंकी सतकताने भारतीयोंको उस चीजसे दूर रखा है जो उनकी नजरोमें एक सकटका मूल है, तो यह सतकता प्रिटोरियामें भी बरती जायेगी।

आप पूछते हैं कि उस दशामें भारतीय विरोधसे क्या लाभ हो सकता है, जब कि जनरल स्मट्स धौस धमकी दे रहे हैं और साम्राज्य सरकार हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर रही है। जहातक मुझे पता है, भारतीयोंका अंतिम उपायके रूपमें न डाउनिंग स्ट्रीटके हस्तक्षेपमें विश्वास है और न ही जनरल स्मट्स द्वारा मानवताके सिद्धान्तके स्वीकार किये जानेमें। यद्यपि भारतीय समाज आज जो प्रयास कर रहा है, वह यदि सफल हो गया तो, निःसंदेह, भारतीयोंको उपनिवेशमें एक प्रतिष्ठा प्राप्त होनेकी आशा है, तथापि उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि इस युद्धमें उनका सवस्व नष्ट हो जा सकता है। किन्तु अगर ऐसा हो जाये, जिसका मुझे यकीन नहीं है, तो कमसे-कम उन्हें आत्म लाभ तो अवश्य ही होगा। और यदि उस लाभको तराजूके एक पलडेमें रखकर, दूसरे पलडेमें उस सम्पूर्ण लाभको रखा जाये

जो जनरल स्मट्स तथा उनका अधिनियम भारतीय समाजको दे सकता है, तो मुझे अपने देशवासियोंसे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं होगी कि वे किसी भी कीमतपर दूसरे लाभको लेनेसे इनकार कर दें। और तब आप देखेंगे कि कानून द्वारा मिलनेवाली सारी सुविधाओंको तो हम प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक या उसमें भी सख्त कोई और कानून हमारे समाजको इस सीधे और तग रास्तेसे नहीं हटा सकेगा। यदि उसने हटा दिया, और मैं यह नहीं कहता कि वह ऐसा नहीं करेगा, तो प्रत्येक भारतीय जानता है कि दोनों ओर खार्ई है।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, २-११-१९०७

२५४ पत्र सर विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २, १९०७के पूर्व]

सेवामें
सर विलियम वेडरबर्न
अध्यक्ष,
ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय महासभा
लंदन

[महोदय,]

एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्प्र वमें मेरा सघ बड़ी सरगर्मीसे काम कर रहा है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारे अपने बीच कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। विभिन्न प्रांतोंके हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई — सब मिलजुलकर सबके हितके लिए काम करते हैं। कुछ बातोंमें एशियाई पजीयन अधिनियम भारतीय मुसलमानोंको विशेष रूपसे प्रभावित करता है। हमने सभी दलों और वर्गोंसे अपील की है, अतः मेरा सघ आपको इरलैंडमें भारतीय राष्ट्रीय महासभाका प्रतिनिधि मानकर आपसे भी अपील करता है तथा विश्वास करता है कि ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियमको, सामान्य दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नोंसे पृथक्, कांग्रेसके समक्ष विचाराय प्रस्तुत प्रश्नोंमें प्रमुखता प्रदान की जायेगी। जैसा कि आपको विदित है, ट्रान्सवालकी विशेष कठिनाइयोंका सामना करनेके लिए हमने जो माग अपनाया है उसे शायद साहसिक ही कहा जा सकता है। दक्षिण आफ्रिकामें दूसरे कानूनोंको बर्दाश्त किया जा सकता है और अबतक उनको बर्दाश्त किया भी गया है, परन्तु ट्रान्सवाल कानून तो असह्य है। दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे कानूनोंके अंतर्गत भारतीयोंने उनके आगे झुकनेके बजाय उनका विरोध करके अपना सबस्व गँवा देनेकी प्रेरणाका अनुभव नहीं किया,

लेकिन ट्रांसवाल कानूनके अंतगत यह कदम नितांत आवश्यक समझा गया है और हो भी गया है। दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे कानून हमें सामान्य रूपसे धनोपाजनके साधनोंसे वंचित करते हैं, ट्रांसवाल पजीयन अविनियम हमें पुसत्वहीन बनाता है और हमें लगभग गुलामीकी स्थितिमें पहुँचा देता है। और चूँकि यह प्रश्न मुसलमानोंको खास तौरसे प्रभावित करता है, इसलिए यदि राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रांसवालके मामलेको विशेष महत्त्व दे तो यह उसके लिए, शायद, शोभनीय ही होगा। कदाचित् दिसम्बर मासके अंततक बहुत से भारतीय एक सिद्धान्तके लिए कारावासका दण्ड भी पा चुकेगे, और इस प्रकार महासभाका अधिवेशन प्रारम्भ होने तक बहुत ही नाजुक हालत पैदा हो जायेगी।

[आपका, आदि,

इमाम अब्दुल कादिर सालम बावजीर

कायवाहक अध्यक्ष

हमीदिया इस्लामिया अजुमन]

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५५. जनरल स्मट्सकी बहादुरी (?)

बहुतेरे भारतीय ओरतो जैसे डर गये हैं कि जनरल स्मट्स तो ऐसे हैं कि जो कहा है वह करेंगे ही। गत सप्ताह हम यह सूचित कर चुके हैं कि उन्होंने दूकानें बन्द करनेके सम्बन्धमें कानून बनाया और लगे हाथ वापस ले लिया। वह कानून एक सप्ताह भर 'गजट' में रहा था, इसी बीच बहुतेरे गोरे दूकानदारोंने उसका विरोध किया और जनरल स्मट्स ठंडे पड़ गये। उन्होंने प्रकाशित करनेके दस दिनोंके अंदर ही उस कानूनको खींच लिया। इसी प्रकार उन्होंने बीयर विधेयक (बीयर बिल) तथा काफ़िरो-सम्बन्धी कानून वापस लिये थे। दूकान सम्बन्धी कानून उन्होंने ट्रांसवालके गोरोके भयसे वापस लिया था, और दूसरे दो कानून इसलिए वापस लिये थे कि इंग्लैंडमें उनका घोर विरोध हुआ था।

भारतीय भाइयोंको ये तीन उदाहरण अच्छी तरह याद रखने चाहिए। उसका तात्पर्य यह है कि बहादुरसे तो जनरल स्मट्स डरते हैं। किंतु जिस प्रकार कोई डरपोक पति अपनी पत्नीपर पूरी बहादुरी दिखाता है उसी प्रकार जनरल स्मट्स भी उन्हीं लोगोपर बहादुरी बताते हैं जो उनसे डरते हैं, अर्थात् जो स्त्री जैसे हैं। उन्हें गोरे व्यापारियोंसे डरना पड़ता है, क्योंकि उनकी सत्ता गोरोपर अवलम्बित है। वे भारतीयोंसे क्यों डरने लगे? भारतीयोंका रूप तो स्त्रियोंके समान दिनमें दस बार बदलता है। वही भारतीय धरना देनेवाला बनता है और वही गुलामीका पट्टा लेता है, वही कानूनका विरोध करनेके लिए अध्यक्ष पद ग्रहण करता है और वही हलफनामा देकर गुलामीकी साड़ी पहनता है, वही एक कलमसे हस्ताक्षर करता है कि खुदाकी कसम मैं कानून स्वीकार नहीं करूँगा, और दूसरी कलमसे कहता है कि मुझे गुलामी तो चाहिए ही। अब बताइए, जनरल स्मट्स क्यों डरेंगे? एक गुजाइश अब भी है सही। वह है, जो भारतीय अभीतक फिसले नहीं हैं वे अततक, बरबाद

होनेपर भी, जनरल स्मट्ससे जूझते रहे। फिर देखेंगे कि बीयर विधेयक-जैसी दशा खूनी कानूनकी होती है या नहीं। जगके बिना रग जगतमें कहीं भी नहीं जमा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५६ सच्ची मित्रता

नि सदेह ब्लूमफॉर्डीनके 'मित्र (फ्रेड)' की हमारे प्रति सच्ची मित्रता है। 'फ्रेड' के सम्पादकने अपने २४ तारीखके अकमें एशियाई कानूनपर कड़ी टीका की है। उसमें बताया है कि जो भारतीय विरोध करते हैं उन्हें बयबाद दिया जाना चाहिए। कुछ भारतीय डरके मारे पजीयन करवा ले तो उससे कुछ भी नहीं बनता। किन्तु जो विरोध करते हैं अथवा देश छोड़कर चले जाते हैं वे सिद्ध करते हैं कि कानून बुरा है।

'फ्रेड'के सम्पादकने ट्रांसवाल सरकारको सलाह दी है कि उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यदि एशियाईको निकाल बाहर करना हो तो उसके लिए लाजमी है कि वह उन्हें हर्जाना दे। हम अपने पाठकोंसे सारा लेख पढ़नेका अनुरोध करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५७ ब्लूमफॉर्डीनका 'मित्र' फिर भारतीयोंकी सहायतापर

“कानून नासमझी-भरा और अन्यायपूर्ण है”

ब्लूमफॉर्डीन 'फ्रेड'के २४ तारीखके अकमें ट्रांसवाल भारतीयोंके समर्थनमें एक अग्रलेख निम्न प्रकार है

प्रिटोरियासे खबर मिली है कि सरकारको लग रहा है, भारतीयोंका अनाक्रामक प्रतिरोध अपने-आप ही टूटने लगा है। इस मायताका कारण यह बताया गया कि प्रिटोरियामें लगभग ४८ भारतीय पजीकृत हो चुके हैं, जिनमें कुछ तो समाजके बहुत ही माने हुए लोग हैं। परंतु जोहानिसबर्गमें, जो कि भारतीयोंका प्रबान केन्द्र है, केवल १६ व्यक्तियोंने पजीयन करवाया है, जिनमें एक व्यक्ति स्थानीय है और अथ बाहरके गाँवोंके हैं। हमारा खयाल है कि इन आकड़ोंकी अपेक्षा नीचेकी बातमें अधिक अथ समाया हुआ है। मालूम हुआ है, कल सवेरे डबनसे लगभग १०० भारतीय, जो ट्रांसवालके ही होने चाहिए, भारतके लिए रवाना होनेवाले हैं।

१ ऐसा लगता है कि यह लेख प्रकाशित होनेसे कमसे कम दो दिन पहले अवतूबरमें, लिखा गया था।

२ देखिए अगला शीर्षक।

भारतीयोंमें भी थोड़े बहुत नामर्द

यदि जुल्मपर जुल्म करके परेशान किया जाये तो फिर भारतीयोंमें भी थोड़े बहुत नामर्द निकल ही आयेगे। ऐसा तो गोरे हो या काले, सबमें होता है। जिस कानूनको स्वयं ही अपमानजनक और अत्याचारपूर्ण मानते हैं उसके सामने डरके मारे यदि ४० या ५० भारतीय झुक जाते हैं तो इससे हमें कुछ भी नहीं लगता। हमें जो बात खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य लगती है, सो यह है कि डर जानेवालोंकी अपेक्षा आत्मसम्मानके हेतु देश छोड़कर जानेवालोंकी संख्या बहुत अधिक है। ट्रान्सवाल सरकारने जो धंधा अस्तित्वार किया है उसमें नैतिकता नहीं है। ऐसे कारोबारको मूखता पूर्ण कहना चाहिए। जिन ब्रिटिश भारतीयोंने कानूनका विरोध किया है उनको ट्रान्सवालमें बसनेका पूरा वैधानिक अधिकार है, जिसमें कोई सन्देह नहीं। यह हक उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे लम्बे समयसे यहाँ रहते आ रहे हैं। सरकारने निश्चय किया है कि यदि वे अब आगे ओर भी उस अधिकारका उपभोग करना चाहते हों तो उन्हें इस कानूनके सामने झुकना होगा — एक ऐसे कानूनके सामने जो उन्हें आवारे और लफंगेका खिताब देता है। हमें तो नहीं लगता कि सरकारको ऐसा करनेका जरा भी अधिकार है। सब जानते हैं कि ट्रान्सवालमें अँगुलियोंकी छाप लेकर पंजीयन करनेकी व्यवस्था केवल कैदियों और चीनी गिरमिटियोंपर ही लागू होती है। किसीको शायद यह लगे कि भारतीय भी हलके दर्जेके लोग हैं, इसलिए उनपर भी यह पंजीयन लागू किया जा सकता है। मान लें कि वे हलके दर्जेके हैं, तो क्या अपना ऊँचा दर्जा दिखानेके लिए उनपर जुल्म किया जाये ?

भारतीय निम्न कोटिके है ?

परन्तु कौन कहता है कि भारतीय हलके दर्जेके हैं ? हमारी भारतीय सेनामें ऐसी टुकड़ियाँ हैं जो गोरी सेनाकी चुनिदासे चुनिदा टुकड़ीके समकक्ष मानी जाती हैं। हमारे विश्वविद्यालयोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ पारितोषिकोंको भारतीय विद्यार्थी बार बार जीतते हैं। तत्त्वज्ञान और ऐसी ही अग्र विद्याओंमें एशियाइयोंके सामने यूरोपीय केवल बच्चोंके समान हैं। यदि व्यापार वाणिज्यकी योग्यताके आधारपर परीक्षा करे तो कुल मिलाकर स्पर्धामें एशियाईको गोरा कभी हरा नहीं सकता। ट्रान्सवालमें जिस ढंगसे भारतीयोंको रखा जा रहा है उससे हम निःसन्देह कह सकते हैं कि उसका यथार्थ कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। हाँ, युद्ध विद्यामें निःसन्देह गोरे लोग एशियाइयोंसे बढ़कर हैं।

यह विशेषता कितने दिन निभेगी ?

परन्तु यह विशेषता कितने दिन निभेगी, इस विषयमें गोरे राजनीतिज्ञ बड़े चिंतित हैं। सम्भव है कि एशियाके असंख्य लोग अपनी शताब्दियोंकी निद्रासे कुछ ही वर्षोंमें जाग जायेंगे और पश्चिमके लोगोंको पछाड़ देंगे। पहले भी एक नहीं, कई बार वे पश्चिमको पछाड़ चुके हैं। वे जगे नहीं, यह अलग बात है। किन्तु उन्हें जगानेके लिए

ट्रांसवाल सरकार तो अपनी ओरसे जितना बन पाया, कर चुकी है। ट्रान्सवाल सरकारके जुल्मोंके कारण जिन भारतीयोंको भारत वापस लोटना पड़ेगा उन सबके मनमें ऐसा घाव हो जायेगा जो कभी भर नहीं सकता। और तब यदि ऐसा प्रत्येक मनुष्य आंदोलनकारी बन जाये और गोरोंके राज्यके विरुद्ध लोगोंको उभाड़े तो उसमें कहना ही क्या है? यह हम जानते हैं कि ट्रान्सवाल बड़ी सरकारकी चिंताओंमें वृद्धि करना नहीं चाहता था, फिर भी कोई इनकार न कर सकेगा कि ट्रान्सवालने अपना एशियाई प्रश्न ऐसे ढंगसे निपटाना शुरू किया है कि उससे बड़ी सरकारकी एशियाई प्रश्न विषयक मुसीबतमें वृद्धि हुए बिना रह ही नहीं सकती।

नासमझी भरा और अन्यायपूर्ण कानून

अतः, हम पजीयन कानूनको नासमझी भरा और अन्यायपूर्ण मानते हैं। हम यह नहीं मानते कि भारतीय सरकारके दबावमें आकर बड़ी सरकार ट्रान्सवाल सरकारपर जोर डालेगी और एशियाई कानूनमें संशोधन करनेके लिए कहेगी अथवा, (जसा कि कुछ लोगोंको डर है), शायद यह कहेगी कि हमारे देशमें भारतीयोंको आने दिया जाये। इंग्लैंड उपनिवेशोंके बतावको बहुत ही सहन करता है, उसके निजी लाभको आचर रही हो तो भी वह उपनिवेशोंको उनकी इच्छाके अनुसार चलने देता है। और न वह अपने व्ययसे और अपनी नौसेना द्वारा उपनिवेशोंका संरक्षण करनेका उत्तरदायित्व अपने सिरसे उतार फेंकता है। ट्रान्सवाल यह सब स्वीकार करता है। जनरल बोथार्डकी सरकार यद्यपि बड़ी सरकारके प्रति मंत्रीभाव रखती है, फिर भी एशियाईयोंके प्रति उन्होंने जो नीति अपना रखी है उसके कारण उनके इंग्लैंडके मित्र उलझनमें पड़ गये हैं। तो क्या कोई अच्छा माग नहीं है?

अच्छा मार्ग

इतना कहनेके बाद अब हम उचित माग सुझाते हैं। पहला यह है कि ऐसा कानून बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा नये आनेवालोंको आनेसे रोक दिया जा सके। दूसरा यह है कि ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं जिन्हें उन सारे एशियाईयोंको पालना होगा जो ट्रान्सवालमें रहना चाहते हैं। यदि कोई एशियाई ऐसे कानूनका पालन करनेकी अपेक्षा ट्रान्सवाल छोड़ना पसंद करे और यह सिद्ध कर दे कि छोड़नेसे उसे हानि होती है तो उसे पूरा हर्जाना दिया जाना चाहिए। मान लें कि इस तरह ट्रान्सवालके सभी भारतीय जाना चाहें तो भी उनके हक खरीदनेमें हमें जो खर्च आयेगा वह किसी भारतीय बलवेके खर्चसे कम ही होगा। फिर इस सवालके उचित निराकरणमें मदद देनेके लिए इस प्रकारके खर्चमें बड़ी सरकार भी योग तो देगी ही। भारतीयोंकी परेशानियां भी बोअर युद्धका एक कारण हैं, इस कथनके लिए स्वयं बड़ी सरकार जिम्मेदार है। फिर, यदि दक्षिण आफ्रिकाको एक करना है तो सभीको एशियाई प्रश्न तो उठा ही लेना होगा। इसमें नेटालका विशेष सम्बन्ध है, क्योंकि उसका काम भारतीय मजदूरोंके बिना चल नहीं सकता। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नेटालके लिए माग यह है कि वह भारतीयोंके लिए एक अलग ही हिस्सा निश्चित कर दे। उस हिस्सेमें भारतीयोंको गोरोंके बराबर ही अधिकार होंगे। तब उहे उससे

कुछ अफवाहे

एक ऐसी बात उड़ी है कि श्री गांधीने जोहानिसबगके बहुत से प्रमुखोंको गुप्त रूपसे पजीकृत करा दिया है और खुद भी हो गये हैं। पाठक खुद समझ लें कि इसको कितना महत्त्व दिया जा सकता है। अफवाह तो यह भी है कि इस बातको उत्तेजन जनरल स्मट्सने दिया है। यदि ऐसी बात हो तो यही कहना होगा कि जनरल स्मट्स डरके मारे नाहक हाथ-पाव पटक रहे हैं।

दूसरी गप्प यह उड़ी है कि जनरल स्मट्स दिसम्बरमें अ पजीकृत लोगोंको निश्चित रूपसे गाडीमें बिठा देगे। उन्होंने नेटालके मंत्रीके साथ यह व्यवस्था कर ली है कि गाडी बदर गाहपर पहुँचाई जायेगी और वहासे उन्हें बालाबाला स्टीमरमें भरकर भारत पहुँचा दिया जायेगा। यह बात बेबुनियाद है क्योंकि झूठ है। जबरदस्ती देशनिकाला देनेका कानून अभी पास नहीं हुआ है। श्री लेनड राय दे चुके हैं कि ऐसा एक भी कानून ट्रान्सवालमें नहीं है जिसकी रूसे पजीयन न करानेवाले भारतीयको जबरदस्ती निर्वासित किया जा सके। इसके अलावा यह भी सोचना चाहिए कि यदि ऐसी सत्ता खूनो कानूनमें होती तो सरकार प्रवासी विधेयकमें वह वारा विशेष तौरसे न रखती। इतनी बात निश्चय है कि सरकारको जबरदस्ती निर्वासित करनेका अधिकार नहीं है। फिर, जिन्हें नेटालमें रहनेका हक है उन्हें जहाजमें जबर दस्ती कौन बिठा सकता है?

तीसरी गप्प यह है कि जोहानिसबगके बहुतसे भारतीयोंने पजीयन करवा लिया है। इसपर अरमीलो, क्लाक्सडॉप और पाचेप्स्ट्रूमसे अगुवा लोग पता लगानेके लिए यहा आ गये हैं। यहा स्थितिको देखकर उन्हें हिम्मत बँधी है। श्री हेलू श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन, श्री अब्दुल गफर और दूसरे दो या तीन व्यक्तियोंके सिवा जोहानिसबगके किसी भी व्यक्तिके पजीयन नहीं कराया। और अ य शहरोके सिफ पन्द्रह लोग आकर यह कालिख लगवा गये हैं। इस सारी स्थितिसे उपर्युक्त नेता खुश हुए हैं और कानूनका विरोध करनेका उनमें फिरसे पूरा उत्साह भर आया है।

प्रिटोरिया कमजोर

यह जो डर था कि प्रिटोरिया सबसे कमजोर है वह अब सच्चा साबित हो चुका है। अधिकतर वहीके लोक पजीकृत हुए हैं। मेमन तो सभी पजीकृत हो चुके। इससे दूसरी जातियोंमें भी खलबली मची है और यही विचार हो रहा है कि दूसरे क्या करें। किंतु इसमें विचार किसलिए किया जा रहा है यह समझमें नहीं आता। कानून बुरा है और उसका विरोध करनेकी हमने शपथ ली है, इतना प्रत्येक व्यक्तिके लिए काफी होना चाहिए।

खेदजनक घटना

शाहजी साहबने इमाम कमालीके ऊपर हाथ डाला, यह खबर तो अभी ताजी ही है। इस बीच उनका हाथ श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनके ऊपर पड़ चुका है। सोमवारको लगभग दस बजे श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन मार्केट स्क्वेयरमें थे। इतनेमें शाहजी साहबने आकर उनको पजीयन करानेपर उलाहना दिया और पीटा। उनकी उँगलीमें खासा जरम आया। वहा जो यहूदी मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव कर दिया, अथवा ज्यादा चोट लगती। इससे हाहाकार मच रहा है। मभीको इसमें खेद होता है। श्री ईसप मिया और श्री गांधी श्री मुहम्मद

शहाबुद्दीनके पास सहानुभूति प्रकट करनेके लिए गए थे। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनने शाहजी साहबके विरुद्ध कोई कारवाई न करनेका निश्चय किया है। फिर भी जब पुलिस कमिश्नरको इस बातकी खबर मिली तो उन्होंने उसके सम्बन्धमें पूछताछ की है। उन्होंने श्री शहाबुद्दीनका बयान मँगवाया है। श्री शहाबुद्दीनने उसपर हस्ताक्षर करनेमें इनकार कर दिया है। नेतागण शाहजी साहबको समझा रहे हैं। इस घटनासे सभीको दुःख हुआ है।

मैं अनेक बार इस चिट्ठीमें लिख चुका हूँ कि यदि इस लड़ाईके दौरान कौममें मारपीट हुई तो हमारा जीतना कठिन है। यह लड़ाई मारपीटकी नहीं है। जो “पियानो बजाता”^१ है उसका बचाव नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग देशद्रोही हैं इसमें शक नहीं। किन्तु उनको नम्रतासे और तकसे समझाना है। परन्तु यदि वे न माने तो उनको मारनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। उसमें भारी नुकसान है। शाहजी साहबको कोई कुछ कह नहीं सकता। उनकी बात ही “यारी” है। किन्तु सभी भारतीयोंको सोचना चाहिए कि यह काम प्रत्येक भारतीयकी हिम्मतसे पूरा हो सकता है। मारपीटसे कदापि नहीं। जिनको कानूनसे बेइज्जती नहीं मालूम होती वे यदि अपना पजीयन भी करा देंगे तो उसमें क्या होना जाना है? मैं तो मानता हूँ कि जबतक समाजका बड़ा हिस्सा दब रहेगा तबतक कुछ नहीं होगा।

कुछ प्रश्न

सवाल उठाया गया है कि मालिककी गैरहाजिरीमें मैनेजरको परवाना मिल सकता है या नहीं। इस सवालका जवाब सर्वोच्च न्यायालयसे राम मकनके मुकदमेमें मिल चुका है। सो यह है कि परवाना मिल सकता है। यह सवाल भी उठा है कि यहाँके निवासी भारतीयोंको नये कानूनके अनुसार मुख्तयारनामपर अँगूठा लगाना चाहिए या नहीं। यह तो स्पष्ट है कि उसपर तो लगाना चाहिए। ये सारे सवाल उनके लिए हैं जिनको कानून स्वीकार करना हो। जिन्हें कानूनके सामने न झुकना हो वे तो बिना परवानेके व्यापार करते हुए लडेंगे और अन्तमें कानूनको रद्द करायेगे।

गद्दारोंकी सख्यामें वृद्धि

मैं पिछली बार जो सूची^२ भेज चुका हूँ उसमें अब जो वृद्धि हुई है, वह दुःखके साथ यहाँ दे रहा हूँ

[प्रिटोरियासे २७, पीटसबर्गसे २१ पाचेपस्ट्रूमसे १२, मिडेलबर्गसे ४, जोहानिसबर्गसे ५, और लुई ट्रिचाट, जीरस्ट मेफिकिंग और क्रिश्चियाना — प्रत्येकसे १।]^३

भारतीय कांग्रेसकी लन्दन समितिको पत्र

सर विलियम वेडरबन कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके प्रमुख हैं। श्री ईसप मिया तथा इमाम अब्दुल कादिरने उन्हें पत्र^४ लिखे हैं कि आगामी कांग्रेसमें इस कानूनके सम्बन्धमें बात जरूर उठाई जाये।

१ अंगुलियोंकी छाप देनेपर “यस्यैतमक” शब्द प्रयोग।

२ देखिए जोहानिसबर्गकी चिट्ठी, पृष्ठ ३१६।

३ यहाँ गांधीजीने विभिन्न स्थानोंके गद्दारोंके नाम दिये थे जिन्हें इस रूपमें सक्षिप्त कर दिया गया है।

४ देखिए पत्र सर विलियम वेडरबनको, पृष्ठ ३१९ और ३२३-२४।

बहादुर मुलतानी व्यापारी

“स्टार” में निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित हुआ है

“अनाक्रामक प्रतिरोधी पजीयन नहीं करायेंगे। माट्टी फीता ‘टेनेरीफ’ माल, जापानी और भारतीय रेशम आदि-जादि नीलाम करना है।”

यह विज्ञापन एक बहादुर मुलतानी व्यापारी ने प्रकाशित कराया है। वह पजीयन की अपेक्षा जेल जाना ज्यादा अच्छा मानता है। यह कदम व्यवसाय में निवृत्त होकर सरकार जो भी करे उसको बर्दाश्त करने की तैयारी के तोर पर है।

अधिकारियों की व्यर्थ दौड़ धूप

अधिकारीगण अर्जिया लेने के लिए इतनी बेकार दौड़ मूक रहे हैं कि उनका व्यवहार हास्यास्पद हो जाता है। इसका एक उदाहरण पिछले सप्ताह गिरफ्तार किये गये दो चीनी बरनेदारों के मामले से मिलता है। अदालत में यह बयान दिया गया था कि पुलिस के एक सिपाही ने (जो पजीयन अधिकारी के हाथ का हथियार बन गया था), दो जुदा जुदा वक्तों पर एक चीनी बरनेदार को गाली दी थी और उसके ऊपर हाथ आजमाने का प्रयत्न भी किया था। यायावी शाने अभियंता को निरपराध मानकर छोड़ दिया। इस मुकदमे के दौरान में प्रकट हुए गोरों का व्यवहार और चीनिया की चतुरता को देखकर बहुत से गोरों का हृदय अनाक्रामक प्रतिरोधियों की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहा।

[गुजराती से]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२६० पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को

जोहानिसबग

नवम्बर ४ १९०७

[श्री रासबिहारी घोष]

निर्वाचित अध्यक्ष,

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

श्रीमान,]

मैं आपका तथा कांग्रेस का ध्यान ट्रांसवाल में एशियाई पजीयन अविनियम को लेकर भारतीयों की जो नाजुक स्थिति हो गई है उसकी ओर आकर्षित करता हूँ। ब्रिटिश भारतीयों को सूचना दी गई है कि उस घणित कानून के अन्तर्गत पजीया सम्बन्धी प्राथनापत्र लेने की अंतिम तारीख ३० नवम्बर है। उसके बाद खास मामलों के अलावा सरकार पजीयन का कोई प्राथनापत्र नहीं लेगी। सम्भवत आपको यह पहले ही पता चल गया होगा कि समाज के कुछ थोड़े से आदमियों के अलावा समूची भारतीय जनताने इस कानून के अंतर्गत पजीयन कराने से इनकार कर दिया है। मेरे सघ का दावा है कि १३,००० अनुमतिपत्र वारियों में से पजीयन कराने के

लिए अबतक ३५० से अधिक भारतीयोंने अर्जिया नही दी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मामलेमे भावना कितनी तीव्र है।

आपको पता लग गया होगा कि हमपर जो अयाय हुआ हे उसको दूर करानेके लिए हमने अनाक्रामक प्रतिरायका रास्ता अपनाया हे। हमने कानून तोडनेके सभी नतीजोको सहन करनेका निश्चय किया हे। हममे से अनेक लोग अभी ही बडे बडे नुकसान उठा चुके हैं, जोर आगे भी बहुत-से लोगोको सवस्व गंवाना पडेगा। यहातक कि कइ यूरोपीय योक व्यापारियाने भारतीय व्यापारियोको, जबतक वे नये कानूनके अनुसार पजीयन प्रमाणपत्र नही दिखलाते उधार देना बंद कर दिया हे। नोकर या मजदूरके रूपमे काम करनेवाले ओक भारतीयोंने पजीयन करानेके बजाय अपने मालिका द्वारा नोकरीस निकाल दिया जाना मजूर कर लिया हे।

जैसा कि आप भली भाति जानते हैं, ट्रान्सवालके भारतीय समाजमे मुसलमान, हिंदू, इसाई और पारसी, मद्रासी, गुजराती, सिख, पठान, हिंदी-भापी ओर कलकत्तेके लोग — सभी शामिल हैं। इस अयायपूर्ण कानूनका विरोध करनेमे सब कबसे क्या मिलाकर खडे हैं, क्योंकि इससे हर भारतीयकी धन दोलत छिा जानेका भय हे ओर जिस आत्म-सम्मानको उसने पिछले दमनकारी कानूनसे बडी कठिनाइस बचाया हे उसके पुन नष्ट हो जानेका खतरा है।

मेरा सच इस समय कांग्रेसकी सेजामे इस आशासे निवेदन कर रहा हे कि ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियमको कांग्रेसके विचारणीय विषयामे प्रमुखता प्राप्त हो सके ओर वर, सामान्य दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नसे पथक, उसके कार्यक्रमोका मुरय विषय बन सके। आज ट्रान्सवालमे भारतीयोकी भयानक स्थितिके सिवाय दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी ओर कोई प्रश्न नही हे। जो-कुछ आज हमारे ऊपर बीत रहा हे वही कल दक्षिण आफ्रिका भरमे हमारे भाइयोपर बीतेगा। बल्कि, हमारे विचारमे, हमारा प्रश्न साम्राज्यके लिए सबसे अधिक महत्त्वका और भारतके लिए राष्ट्रीय महत्त्वका हे, क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेश हमारे विरुद्ध जो कुछ करनेमे यहा कामयाब हो जायेगे, साम्राज्यके दूसरे उपनिवेश उसीको अयत्र बसे हुए हमारे भाइयोके विरुद्ध आजमायेगे। यह कहा जा सकता हे कि ट्रान्सवालमे विशेष कठिनाईका सामना करनेके लिए हम लोग बीरोचित माग अपना रहे हैं, किंतु हम अपने आपको इस दशमे अपनी मातृ-भूमिका प्रतिनिधि मानते हैं, ओग देशभक्त भारतीयोके रूपमे हमारे लिए अपनी जाति तथा राष्ट्रके सम्मानके अपमानको पी सकना असम्भव हे। दक्षिण आफ्रिकामे इन बातोको लेकर हमपर किसी और कानूनने इतनी भीषणतासे प्रहार नही किया, लेकिन ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियम तो असह्य है। दक्षिण आफ्रिकाके अय सभी कानून आम तौरपर हमे धन-पाप्तिके साधनोसे वचित करते ह। ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियम तो हमे अपने पौरुषसे ही वचित कर देता है और हमे गुलामीके दर्जेपर पहुँचा देता हे। दिसम्बरके अन्ततक सम्भवत अनेक भारतीय एक सिद्धान्तके लिए जेलके कष्ट सह चुके होंगे और पहली जनवरीको उन भारतीयोको व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर दिया जायेगा जिन्होंने नये कानूनके अनुसार अपना पजीयन करानेसे इनकार कर दिया ह। इस प्रकार कांग्रेसका अधिवेशन आरम्भ होनेतक परिस्थिति अत्यंत नाजुक हो जायेगा। हमारी मायता हे कि हमारे अनाक्रामक प्रतिरोध आंदोलनको सभी धार्मिक व्यक्तियो, सभी सच्चे देशभक्तो और सभी ईमानदार ओर

विवेकशील व्यक्तियोंका समर्थन मिलना चाहिए। इस आंदोलनमें ऐसी शक्ति निहित है कि हमारे प्रतिरोध न करने और खुशीसे कष्ट सहनके कारण ही हमारे विरोधियोंको हमारा आदर करना पड़ेगा। इस विरोधके बारेमें हमारा सकल्प इसलिए और भी दृढ़ है कि हमारे खयालसे इस उपनिवेशमें छोटे पमानेपर हमारा यह प्रयोग सफल हो या असफल, किंतु प्रत्येक अत्याचार-पीडित जनता, प्रत्येक अत्याचार-पीडित व्यक्ति इसका अनुकरण कर सकेगा, क्योंकि अत्याचारी दूर करानेके लिए इससे अधिक विश्वस्त और सम्मानपूर्ण अस्त्र आजतक नहीं अपनाया गया।

[ईसप इस्माइल मियाँ

अध्यक्ष,

ब्रिटिश भारतीय संघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६१ पत्र अखबारोंको^१

[जोहानिसबग

नवम्बर ६, १९०७]

[महोदय,]

आपने अपने पत्रके आजके अंकमें एक वक्तव्य प्रकाशित किया है। आशयतः, वह वक्तव्य एशियाई अधिनियम संशोधन कानूनके प्रशासनके सम्बन्धमें आपके प्रिटोरिया-स्थित सवाद दाताको दिया गया सरकारके वर्तमान रुखका अधिकृत स्पष्टीकरण है। लेकिन मेरे संघको यह देखकर खेद हुआ है कि उस वक्तव्यमें इतनी अधिक गलतफहमियाँ तथा गलतबयानियाँ हैं कि लगता है, शायद आपका सवाददाता उस स्पष्टीकरणकी तफसीलोंको, जो उपनिवेश सचिवके दफ्तरसे जारी किया गया था, समझ ही नहीं सका। अपने संघकी ओरसे मैं उसमें दिये हुए कुछ तथ्योंका परीक्षण करनेके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ।

पहली बात उसमें यह कही गई है कि भारतीय समाजकी ओरसे उपनिवेश सचिवको ऐसे प्रार्थनापत्र दिये गये हैं जिनका उद्देश्य कानूनके प्रांगण में विनियमोंमें कुछ सुधार कराना है। मेरा संघ इस बातका पूर्णतः खण्डन करता है। तथ्य ये हैं ३० अगस्तको सवध्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजने विनियमोंमें कुछ संशोधन करानेकी दृष्टिसे “प्रिटोरिया, स्टैंडटन, पीटसबग और मिडेलबर्गके कुछ प्रमुख भारतीयों” की ओरसे माननीय उपनिवेश सचिवको एक प्रार्थनापत्र दिया था। सवध्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजके मुवक्किल यह दिखलाना चाहते थे कि वे बहुत-से प्रतिनिधि भारतीयोंकी ओरसे बात कर रहे हैं। मेरे संघने इन तथ्योंका पता चलते ही प्रिटोरियाके इन सॉलिसिटर्सको एक पत्र लिखकर इस बातका खण्डन किया कि उन

लोगोंको भारतीय समाजकी तरफसे और, इसलिए, मेरे सचकी ओरसे बोलनेका अधिकार है। ऊपर मैंने जिस पत्रका हवाला दिया है उसकी भाषा यह सिद्ध करनेके लिए काफी है कि सरकारको जो प्रार्थनापत्र भेजे गये वे कुछ व्यक्तियोंने अपनी निजी हिसियतसे भेजे थे, और अबतक उनमें से अधिकतर व्यक्तियोंका पजीयन हो चुका है। इन प्रार्थनापत्रोंके उत्तरमें माननीय उपनिवेश सचिवने प्रार्थियोंका सूचित किया था कि वे उनकी प्रार्थना स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने विनियमोंमें कुछ छोटे छोटे संशोधन कर दिये थे जिनका लगभग कोई मूल्य नहीं था। प्रिटोरियाके सालिसिटरोने जिन लोगोंकी ओरसे यह काम किया था वे इस उत्तरसे इतने असन्तुष्ट हो गये थे कि उन्होंने सक्ली स्टैगमान, एसेलेन व रूजकी मारफत इस आशयका उत्तर भेजा कि वे अपने ३० अगस्तके पत्रमें की गई प्रार्थनाको वापस लेना चाहते हैं, और माननीय उपनिवेश सचिवने जो सुविधाएँ देनेकी कृपा की हो उन्हें वे चाहें तो वापस ले लें। इस प्रकार यह साफ है कि भारतीय समाजने विनियमोंके मामलेमें माननीय उपनिवेश सचिवके पास कोई प्रार्थनापत्र नहीं भेजा, और जो प्रार्थनापत्र भेजे गये वे कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा भेजे गये, तथा उन्हें भी उन्होंने पिछले महीनेकी १२ तारीखके पत्र द्वारा वापस ले लिया है।

अपने सचकी ओरसे मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह आरोप बिल्कुल गलत है कि भारतीय समाजने अब वह रुख अपनाया है कि जिसको अपनाते, आंदोलनकी प्रारम्भिक स्थितिमें, उसे साहस नहीं था। अगर उपनिवेश सचिवके विभागको इस बातका पता नहीं है कि इस कानूनका अनाक्रमक प्रतिरोध सितम्बर १९०६ से ही किया जा रहा है तो समझना चाहिए कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अनाक्रमक प्रतिरोधकी शपथ जोहानिसबर्गकी साव-जनिक सभामें उसी माह ली गई थी और एशियाइयोंका पजीयक खुद वहाँ मौजूद था। अधिनियमके मातहत बनाये गये विनियमोंके सवालमें किसी तरह भी पडनेसे मेरे सचने बराबर इनकार किया है। मेरे सचने स्वयं इस अधिनियमकी वैधताको आरम्भसे ही नहीं माना है, इसलिए यदि वह इसके छोटे मोटे ब्यौरेमें जाता तो यह उसकी शानके बहुत खिलाफ होता। मेरे सचने जब इन नियमोंके अस्तित्वकी ही उपेक्षा की है तो यह किसी तरह नहीं कहा जा सकता कि उसने उन कथित संशोधनोंका खण्डन किया होगा जो माननीय उपनिवेश-सचिवने समाजकी तथाकथित प्रार्थनापर ब्रिटिश भारतीयोंके हकमें किये थे। यह मान बैठना बिल्कुल गलत है कि मेरे सच और भारतीय समाजने अनाक्रमक प्रतिरोधका जो आंदोलन छेड़ा है वह पजीयनकी घोषणा होनेपर पिछले जुलाई मासमें शुरू किया गया। हमने तो पिछले साल आंदोलन छेड़नेके समयसे ही इस अधिनियमको पूरी तरह रद्द करनेकी माग कर रखी है।

मेरे सचने माननीय उपनिवेश सचिवको अभी हालमें जो प्रार्थनापत्र भेजा है उसके बारेमें एक गौण प्रश्न उठाया गया है। इस प्रार्थनापत्रमें और बातोंके साथ साथ यह भी लिखा गया था कि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले अपनेको उस पत्रसे पूर्णतया असम्बद्ध घोषित करते हैं जो सक्ली स्टैगमान, एसेलेन व रूजने अपने मुक्किलोंकी ओरसे माननीय उपनिवेश सचिवको दिया था। इस प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर करनेवालोंने विनयपूर्वक यह भी कहा था कि जो कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई हैं वे इस अधिनियमको बिल्कुल रद्द कर देनेसे ही दूर हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं थी। आपके सवाददाताको सरकारी सूचना देनेवालेका

मशा यह जाहिर करना था कि माननीय उपनिवेश-सचिवने पिछले सितम्बरके अपने पत्र द्वारा विनियमोमे जो मामूली सुधार सूचित किये थे उनके कारण भारतीय समाजने एक कथित रियायतका फायदा उठाया और इस अर्जीको इसलिए घुमाया कि जो काय नि सदेह कृपाका समझा जाना चाहिए था उससे और फायदा उठाया जाये। तथ्य तो यह है कि जैसे ही मेरे सघको इस बातका पता चला कि सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजका ३० अगस्तका पत्र उपनिवेश सचिवको भेजा गया है, मेरे सघने पाच विभिन्न भाषाओमे प्राथनापत्रके फाम जारी किये जोर उनको सारे उपनिवेशमे भेज दिया। यह सितम्बरके आरम्भकी बात है। सितम्बरके अततक जब माननीय उपनिवेश सचिवका उत्तर प्रिटोरियाके सोलिसिटरोके पास आया, वे सभी फाम ठीक तरहसे भरकर मेरे सघको लौटाये जा चुके थे। लेकिन चूकि पजीयनका काम अतमे जोहानिसबगमे होना था ओर इस कामके लिए आखिरी महिना अक्तूबर था, मेरे सघने यह तय किया कि अक्तूबरके अततक दररवास्तको रोक लिया जाये, जिससे सरकारके सामने एशियाई कानून सशोधन नियमके विरोधमे भारतीय समाजकी एकताका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया जा सके, ओर यह काम सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजके मुक्किलोका पत्र १२ अक्तूबरको वापस ले लिया जानेके बावजूद किया गया।

अब म पजीयनकी अवधिको नवम्बरके अततक बढानेके सवालकी सक्षेपमे चर्चा करूंगा। मेरा सघ इस बातको जोर देकर कहता है कि यह फसला अतिम क्षणमे किया गया था ओर मेरे सघके इस कथनका समथन वे वक्तव्य करते हैं जो मन्त्रि परिषदके कमसे कम तीन मन्त्रियो द्वारा किये गये थे। यदि इसकी ओर पुष्टिकी जरूरत हो तो वह उस परिपत्रसे हो जायेगी जो १६ अक्तूबरको उपनिवेश सचिवके दफतरसे उपनिवेश-भरके आवासी मजिस्ट्रेटोके पास भेजा गया था और जिसपर एशियाई पजीयकके हस्ताक्षर थे। उसमे कहा गया था कि आवासी मजिस्ट्रेट एशियाइयोको सूचना दे दे कि “निश्चय किया गया है, पजीयनके लिए प्राथना पत्र देनेकी अवधि, जो ३१ अक्तूबरको समाप्त होती है, आगे नहीं बढाई जा सकती”, और विभिन्न जिलोमे रहनेवाले सभी एशियाइयोको इस बातकी सूचना दे दी जाये कि वे पजीयनके लिए प्राथनापत्र ३१ अक्तूबरको या उससे पहले जोहानिसबग स्थित वान ब्रैडिश स्कवेयरके पुराने डच गिरजाघरमे दे। ये सूचनाएँ बहुत स्पष्ट थी। और यह साफ जाहिर है कि माननीय उपनिवेश सचिवने जब यह देखा कि सम्पूर्ण ट्रान्सवालसे २५ से अधिक प्राथनापत्र जोहानिसबगमे नहीं आये हैं तब उन्होने, अन्तिम क्षणमे, प्राथनापत्र देनेकी अवधिको एक मास और बढानेका निश्चय किया। इस तरह यह बात ध्यान देनेकी है कि पिछली ४ तारीखके ‘गजट’ मे प्रकाशित हुई क्रम-संख्या १९०७ की सरकारी विज्ञप्तिमे उस अवधिको बढानेकी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमे पहलेसे पजीयन न करानेवाले एशियाई नये कानूनके अनुसार पजीयनके लिए प्राथनापत्र दे सकते थे।

आखिरमे मेरा सघ एक और बातकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। प्रत्येक नगरके निवासी एशियाइयोके उसी नगरमे अर्जी देनेकी अवधि निश्चित करनेके बजाय यह विज्ञप्ति निकाल दी गई कि जिन नगरोका दौरा पजीयन अधिकारी कर चुके ह उन नगरोके एशियाइयोने यदि पहले अर्जिया न दी हो तो वे नव-विज्ञापित नगरमे अर्जिया दे सकते ह। और चूकि जोहानिसबग वह अन्तिम विज्ञापित स्थान था, जहा ट्रान्सवाल-भरके एशियाई अपना पजीयन करा सकते थे, तथा अन्य किसी स्थानपर नहीं, इसलिए मेरा सघ पजीयक-

कार्यालयके अफसरोपर यह आरोप लगाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कायरोसे गुप्त रूपसे प्रिटोरियामे प्राथनापत्र लिये, जिन्होंने जाली तरीकेसे झूठे हलफनामे पेश किये और झूठे बयान दिये कि कुछ व्यक्तियोंके, जिनके नाम नहीं बताये गये, डराने वमकानेसे वे पहले प्राथनापत्र नहीं दे सके थे। मेरा सघ एक बार फिर यह बतला देना चाहता है कि भारतीय लोग इस युद्धमें निश्छल रूपसे लड़ रहे हैं, अतएव उनको धोखे या असत्यका आश्रय लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीयोंके विरुद्ध यह कहा गया है कि वे, दूसरे सभी प्राच्य लागोंके समान, दुरगी चाल चलते हैं, जिसके लिए 'प्राच्य' शब्दका प्रयोग किया गया है। आपके सवाददाताके तारमें तथ्योंको जिस विचित्र ढंगसे तोड़ा मरोड़ा गया है उसका चित्रण करना बहुत कठिन है।

[आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६२ श्री लैबिस्टर

श्री लैबिस्टरके दुःखद अवसानसे नेटाल और भी दरिद्र हो गया है। श्री लैबिस्टरके रूपमें नेटालके वकील सघका एक चतुर तथा प्रसन्नचित्त सदस्य सरकारका एक विश्वस्त सेवक और भारतीयोंका एक सच्चा मित्र उठ गया। यायाधीशोंने उन्हें जो श्रद्धाजलि अर्पित की उसके वे योग्य पात्र थे। जब वे नगर परिषद्के सदस्य थे, तब विक्रेता परवाना अधिनियमके सम्बन्धमें उन्होंने जो वीरतापूर्ण रुख अपनाया था^१ उसके लिए भारतीय सदा उन्हें कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि जनताको इस बातका पता नहीं, किन्तु वे श्री लैबिस्टर ही थे जिन्होंने भारतीयोंके प्रवेशको नियमित करनेके बारेमें अपनी नीतिपर दृढ़ रहते हुए भी अपनी व्यवहार कुशलतासे अनेक भारतीय व्यापारियोंको बरबादीसे बचाया था, क्योंकि उन्होंने उन भारतीयोंपर मुकदमा चलानेसे इनकार कर दिया था जिनके परवाने उनके पुराने व्यापारी होते हुए भी, व्यापारिक ईर्ष्याके कारण छीन लिये गये थे।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६३. ईद मुबारक

हम कामना करते हैं कि हमारे मुसलमान पाठको को ईद मुबारक हो । मनुष्य बहुत बातों की कामना करता है, किन्तु सारी कामनाएँ पूरी नहीं हो सकती । इसी प्रकार यद्यपि हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक हो, फिर भी जितना हमें ज्ञान है उसके अनुसार खुदाई नियम तो यह है कि जिसने रमजान शरीफ का उच्च तरीके से पालन किया हो उसी को ईद का फल मिल सकता है । हमने तो यह पढ़ा और देखा है कि केवल रोजा रखने से यह नहीं माना जा सकता कि रमजान शरीफ का पालन हो गया । रोजा तो मन तथा शरीर दोनों से रखा जाना चाहिए । यानी अथ महीने में नहीं तो कम से कम रमजान के महीने में पूरी तरह से नीति के नियमों का निवाह करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और क्राधमात्र का त्याग करना चाहिए । जिसने इतना किया होगा उसके लिए हमारी कामना विशेष रूप से सफल हो सकेगी, ऐसी हमारी धारणा है ।

[गुजराती से]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६४ नया वर्ष शुभ हो

जैसे हमने अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबादी दी है, वैसे ही हम अपने हिंदू पाठकों के लिए कामना करते हैं कि उन्हें नया वर्ष फले । नया वर्ष शुरू होने के बाद यह हमारा पहला अंक है । हम देखते हैं कि ट्रान्सवाल में जोर, सच कहा जाये तो, सारे दक्षिण आफ्रिका में भारतीय प्रजा कष्ट भोग रही है । उन कष्टों के परिणामस्वरूप लोगों में जैसे स्वदेशाभिमान का उत्साह बढ़ा है, वैसे ही उनकी दृष्टि देश की ओर ज्यादा गई है, और धर्म की ओर भी कुछ झुकाव हुआ है ।

हिंदू हिंदू धर्म की ओर अधिक आकर्षित दिखाई देते हैं मुसलमान इस्लाम की ओर और दूसरे भारतीय अपने अपने धर्मों की ओर । यही ठीक भी है । हमारा दृढ़ मत है कि यदि भारत का कल्याण होना होगा तो इसी माग से होगा । हर धर्मवाले यदि अपने-अपने धर्म का सच्चा रहस्य समझ जाये, तो आपस में द्वेष कर ही नहीं सकते । जलालुद्दीन रूमी के कहे अनुसार, या जैसा श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा है उसके अनुसार नदियां बहुत हैं और अलग अलग दिखाई देती हैं, फिर भी सब का मिलाप समुद्र में होता है । उसी प्रकार धर्म भले ही बहुत हों, फिर भी सब का सच्चा उद्देश्य एक ही है, खुदा या ईश्वर का दर्शन कराना । अतः उद्देश्य की दृष्टि से धर्मों में भेद नहीं है । हम लिखते हुए ऊपर कह गये हैं कि भारतीयों का नया वर्ष फलीभूत हो । किन्तु जैसे ईद कुछ शतों का निवाह करने पर ही मुबारक हो सकती है — यह साफ मालूम होता है, उसी प्रकार नया वर्ष भी अमुक शतों पर ही फल सकता है । इतना कहने के बाद इस सम्बन्ध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वे शत कौन-सी हैं ।

[गुजराती से]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६५ समझदारके लिए इशारा

हममें एक कहावत है कि समझदारके लिए इशारा काफी है। चारा ओर जो लक्षण दिखाई दे रहे ह उनसे यही प्रकट होता कि यदि भारतीय समाज आखिरतक लडता रहा तो जीतेगा। जीता हुआ तो आज ही है। किन्तु प्रतिष्ठापूवक ट्रासवालमे रह सकेगा। 'फ्रैड' का लेख हम देख चुके ह।^१ अबधि नवम्बर तक बढा दी गई है, यह हम देखते हैं। इससे सरकारकी कमजोरी प्रकट होती है। जो गोरे पहले भारतीय प्रश्नकी बात शायद ही कभी करते थे व अब उसीकी बात करते रहते हैं। 'लीडर' जैसा अखबार सरकारको चेतावनी दे रहा है कि वह वीरज रखे, ब्रिटिश नीतिको याद करे, अपनी जिम्मेदारी समझे और भारतीयोंके साथ न्याय करे।

जैसे एक ओरसे ये सब शकुन दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही दूसरी ओरसे सच्ची कसौटीका समय नजदीक आता जा रहा है। बोलनेमे हम हमेशा होशियार कहलाये हैं। आरम्भ-शूर भी कहलाये हैं। अब अन्तिम समयमे हम ठिकानेपर रहेगे या नहीं, यह देखना है। यदि आखिरी ताकत नहीं लगायेगे तो आजतकके किये करायेपर पानी फिर जायेगा। जो लडाई भारतीयोंके बिना मागे हाथ आ गई है, वैसी फिर आनेवाली नहीं है। लक्ष्मी जब तिलक लगाने आई है तब यदि भारतीय मुह छिपायेगे तो फिर कभी ऐसा मोका हाथ नहीं आयेगा। लडाई जोखिम है भी और नहीं भी। जो पैसेसे चिपटे हुए हैं, उन्हें सहज ही जोखिम मालूम होगी। किन्तु जो सिफ देशके सेवक हैं, जो टेकवाले ह, उनके लिए तो जोखिम रत्ती भर भी नहीं है। कानून उनके लिए है ही नहीं। कानूनके खिलाफ जूझनेपर भी यदि वह रह जाये तो इसमे उनकी हार नहीं होगी। व परीक्षामे सौ टका खरे उतरेगे और जहा जायेगे वही उनका मूल्य ऊँचा होगा। इतना जोश रखे बिना जीत हो ही नहीं सकती। जो सिरपर कफन बाध कर जाते हैं वे ही जीत कर आते हैं। इस लडाईमे सच्चा सहारा खुदा — ईश्वर — का है। उसके सामने कोई शत नहीं रखी जा सकती। शत रखनेके बाद भरोसा नहीं रखा जा सकता। इस विचारको ठीक मानकर भारतीय समाज अन्ततक एक टेकवाला बना रहे, यही हमारी ईश्वरसे प्रार्थना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६६ बढाई गई अवधि

ट्रान्सवाल सरकारने 'पियानो बजाने' की अवधि बढा दी है, सो क्यों ? इस प्रश्नका उत्तर सरकारी नोटिसमें ही है "सरकारके सामने यह बात पहुँची है कि डर या अग्र कारणोंसे भारतीय पजीयनके लिए अर्जी नहीं दे सके।" इसलिए अवधि बढाई गई है। सरकारके पास इस प्रकारकी अर्जी भेजनेवाले भारतीयको क्या कहा जाये ? क्या उसे भारतीय कहा जा सकता है ? उसे मनुष्य कहा जा सकता है ? अर्जी भेजनेवाला जानता है कि ऐसा करके उसने एक बहुत बडे झूठका काम किया है। कोई भी व्यक्ति डर नहीं दिखाता और यदि डर दिखाया ही हो तो क्या वह अब बद है ? धरनेदार अपना काम करते ही रहेंगे। समझानेवाले समझाते ही रहेंगे। फिर यदि अक्टूबरमें डरके कारण नहीं जाया जा सका तो नवम्बरमें कैसे जाया जायेगा ? यदि मियाद मागनी ही थी तो सीधे रास्ते मागी जा सकती थी। मियाद न मिल सकती तो भी जिहे मुह काला करना होता वे तो कर ही सकते थे। फिर भी इस सम्बन्धमें कुछ भी कहना बेकार है। एक गलतीके पीछे हमेशा कई गलतियां हुआ करती ह। सरोवरका बाव टूट जाये तो दरार बढती ही जाती है। पजीयनपत्र लेना गुनाह है, इसे लेनेवाला समझता है। इसलिए वह दूसरे अपराध करनेसे शरमाता नहीं, न डरता ही है। इतनी जधम स्थिति खूनी कानूनके सामने झुकनेवालेकी हो जाती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमादिया इस्लामिया अजुमन

हमादिया इस्लामिया अजुमनकी बैठक नियमानुसार रविवारको हुई थी। बहुत लोग उपस्थित थे। इमाम अब्दुल कादिर अध्यक्ष थे। श्री मुहम्मदखाने श्री हाजी हबीबका पत्र पढकर सुनाया। वह पत्र प्रिटोरियाकी अजुमनकी ओरसे आया था, और उसमें इस अजुमनको इसके कामके सम्बन्धमें ओर धरनेदारोंको उनकी बहादुरीके सम्बन्धमें बधाई दी गई थी। बादमें श्री गांधी श्री उमरजी साले तथा श्री एम० एस० कुवाडियाने कुछ बातें समझाई और यह विचार पेश किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सगे सम्बन्धियोंको लिखे कि नवम्बर महीनेमें कोई भी प्रिटोरिया न जाये, ओर यदि किसी कामसे जाना ही पडे तो भी पजीयन कार्यालयमें तो जाये ही नहीं। इस बातको सबने स्वीकार किया।

चीनियोंकी सभा

चीनियोंकी अपनी सभा हर रविवारको होती है। इस बार चीनी वाणिज्य दूत उपस्थित थे। श्री गांधीको विशेष तौर से बुलाया गया था। उन्होंने नवम्बरकी बात सुनाई और सभाने प्रिटोरियाको चीनी स्वयसेवक भेजनेकी व्यवस्था की।

नवम्बरमे “महामारी”

सबको डर था महामारी स्वरूप पजीयन कार्यालय शायद नवम्बरमे खुलेगा। हमने पिछले सप्ताहके ‘इंडियन ओपिनियन’ में देख लिया कि यह सत्य निकला। इस तरह कार्यालय खोलकर सरकारने साफ अपनी कमजोरी बताइ है। यदि जारल स्मटममे भारतीयोको देश निकाला देनेकी हिम्मत होती तो वे नवम्बरमे अर्जी देनेकी मोहलत कभी न देते। कहा गया अक्तूबरका वह नोटिस जिसमे लिखा गया था कि इस महीनेकी ३१ तारीखक बाद किमीका पजीयन नहीं किया जायेगा? कहा गये गाव गावको लिखे वे पत्र जिनम सूचित किया गया था कि सबके लिए अक्तूबरमे अर्जी देनेका अंतिम मोका है? हम बताया — समझाया — जाता है कि जनरल स्मटम अपना हठ कभी नहीं छोडते। किंतु [‘इंडियन ओपिनियन’] सम्पादक महोदयने हमें बताया है कि स्मटस साहब तीन बार दवावके कारण अपना हठ छोड चुके हैं। अब फिर यह चौथी बार अक्तूबरका नोटिस छूटा है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि इस बार उहे किस बातका डर था? इसका उत्तर सीधा है। उनपर बड़ी सरकारकी जोरसे निजी तौरपर यह दवाव होगा कि वे किसी भारतीयपर हाथ नहीं डाल सकते। यह अनुमान ठीक न हो तो शायद यह ठीक होगा कि श्री स्मटसको अपनी इज्जत जानेका डर लग रहा है। चीटीको कुचलनेमे हाथीको बहुत विचार करना पडता है। स्मटस साहब अपने मनमे हाथी हैं और हम चीटी हैं। इसलिए चीटीको कुचलनेमे शरम आती है।

कमजोरीका दूसरा उदाहरण

पिछले सप्ताह मैं बता चुका हूँ कि अफवाह ऐसी है कि श्री गांधीपर सबसे पहले बार किया जायेगा, और सबको निर्वासित करनेकी तैयारी की जा रही है। अब मेरे हाथमे इस प्रकारका पत्र आया है।

काछलिया और रूजके बीच हुई बातें

श्री काछलिया कहते हैं

श्री रूजके साथ मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाकी सरकारकी योजनाके अनुसार नेटाल सरकारने स्वीकृति दी है कि जब टान्सवाल सरकार लोगोको निर्वासित करेगी उस समय गाडीको बालाबाला बंदरगाहपर ले जाकर उहे सीधे जहाजपर चढा दिया जायेगा। फिर उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि श्री गांधीको तो निर्वासित करना सरकार तय कर चुकी है।

यदि श्री गांधीको सबसे पहले निर्वासित किया जाये तो उनके समान भाग्यवान और कौन होगा? और यदि वैसा हो तो भारतीय समाजम घबडाहट पदा होनेके बजाय हिम्मत ही पदा होगी। किन्तु इस प्रकार देश निकाला देनेकी सत्ता अभी तो ट्रान्सवालको प्राप्त नहीं है और उसे मिलनेमे देर लगेगी। श्री रूजकी कही बात सरकारको फूफा है यह साफ नजर आता है।

कैड्री और गुलामीकी चिट्ठी लेनेवालेमे क्या अन्तर है?

ऐसी खबर मिली है कि अठारह अँगुलीवाले कागज पजीयकके दफ्तरमे नहीं रहते। वे सब पुलिसके सुपुद कर दिये जाते हैं। जिस पुस्तकमे अपराधियोका नाम दर्ज रहता है, उसीमे इन

‘बहादुर’ भारतीयोंका नाम भी दज रहेगा। यानी हर प्रकारसे कानूनके सामने झुकनेवाला अपराधी सिद्ध हो जाता है। अतः केवल इतना ही है कि चोर तो चोरी करके अपराधी ठहरता है और गुलामीका चिट्ठा लेनेवाला भारतीय केवल अपनी नामर्दीके कारण गुनहगार माना जाता है। इन दोनोंमें अधिक खराब कौन है, इसका निणय पाठक स्वयं करे। अठारह अँगुलियोंकी याद करते हुए बचपनकी एक कविता याद आ जाती है ‘ऊँटके टेढ़े-मेढ़े शरीरमें अठारह बल होते हैं, बताओ उसे ढका जाये तो वह ढका कैसे रहे?’” ऐसा ही कुछ हाल अठारह अँगुलिया लगातेवाले भारतीयका भी माने।

पूछताछ बिना

देशमें जब वर्षा बहुत होती है तब हरी सब्जी सस्ती हो जाती है। उसी प्रकार इस समय पजीयन कार्यालयकी वर्षा हो रही है, इसलिए पजीयन पत्रोंका भाव सस्ता हो गया है। कहा जाता है कि लडकोको बिना पूछे ही पजीयक महोदय पजीकृत कर लेते हैं। इसमें मैं कोई दोष नहीं देख रहा हूँ। गुलाम बननेमें कहीं भी कठिनाई नहीं होती। परन्तु यह सब तो शिकारको पकड़नेके लिए लार टपक रही है, ऐसा समझकर इससे दूर रहना चाहिए। इस टीकाकी आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं कभी कभी सुनता हूँ कि “फला व्यक्ति पजीयन कराकर काम निकाल आया।” यह खयाल उसीको होता है जो कानून और हमारी लडाईको नहीं समझता। बाकायदा पजीकृत होनेमें लाभ हो तो हमारी लडाई गलत है और पजीयन करवाना कतव्य हो गया है ऐसा कहा जायेगा। किंतु पजीयन करवानेमें नुकसान है, पाप है, प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होना है, इसलिए हम पजीकृत नहीं होते। फिर, पजीयनपत्र लेनेमें “काम निकाल लिया”, यह कैसे कहा जा सकता है? हमारी लडाई मद बनने और मद बने रहनेकी है। फिर यदि कोई औरत बन जाये तो उसे हम “काम निकालना” क्यों समझे? हमें अपने मनमें इतना लिख रखना चाहिए कि जो पजीकृत नहीं हुए वे आजाद हैं और आजाद रहेंगे। और ट्रांसवालमें सम्मानपूर्वक रहा जा सकेगा तभी रहेंगे। तब जिन्होंने पजीयन करवाया है उन्होंने तो अखण्ड गुलामी स्वीकार की है।

‘ट्रांसवाल लीडर’ द्वारा सहायता

जिस प्रकार ब्लूमफ़ॉर्टीनका ‘फ्रेड’ मदद कर रहा है, उसी प्रकार ट्रांसवालके अखबार भी आखिर मदद करने लगेंगे, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहुत-से गोरे तो सहानुभूति दिखाने लगे हैं। अखबार हमारी मदद करे या न करे, ‘लीडर’ ने अपने सोमवारके अकमे जो लेख लिखा है वह हमें हिम्मत बँधाने लायक है। उसका सारांश नीचे देता हूँ

कैसे ?

कुछ भारतीयोंकी मागके कारण सरकारने पजीयनकी अर्जीके लिए एक महीनेकी अवधि और बढ़ाई है। महीना बीत जानेपर सरकार क्या करेगी, यह नहीं बताया गया। अवधि बढ़ानेका प्रस्ताव बहुत ही देरसे किया गया होगा, क्योंकि नोटिस दिया जानेके एक दिन पहले ही श्री सॉलोमनने घोषित किया था कि अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी। क्या आखिरी घड़ी तक इस निणयका पता नहीं चला था? भारतीयोंकी अवधि बढ़ाने

सम्बन्धी सारी अजिया शुक्रवारके दिन ही भेजी गई थी। सरकारकी इस मेहरबानीके लिए किन्हीं प्रमुख एशियाइयोने एहसान माना हो तो उनके नाम प्रकाशित किये जाये। इससे दूसरोपर भी उसका असर पड़ेगा। हमारा खयाल है कि ऐमा आभार किसीने नहीं माना और प्रमुख तो विरोधपर दब ही है। उनका यह भी कहना है कि सरकारको देश निकाला देनेका अधिकार है ही नहीं। वे अपने समथनमे श्री गेनडकी राय पश करते ह।

इसके अतिरिक्त, श्री रेमड वेस्ट जैसे योग्य व्यक्ति भी मानते हैं कि कानून ब्रिटिश नीतिके विपरीत है। सरकार यदि प्रवासी अधिनियमपर भरोसा रखती हो तो क्या वह मानती ह कि भारतीय समाज उस कानूनको मन्नाटकी 'याय परिषद तक नहीं ले जायेगा? फिर, यदि सरकारको निर्वासित करनेकी सत्ता मिल जाये तो उस सत्ताके बलपर उसे भारतीयोको भारतमे भेज देना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या भारत सरकार उसमे हस्तक्षेप नहीं करेगी? मोटे तौरमे देखे तो मालूम होता है कि श्री हास्केनके सिवा सभी गोरे भारतीयोके विरुद्ध हैं। किन्तु गहराईसे देखनेपर मालूम होता ह कि एशियाइयाको निकाल भगानेका सरल रास्ता गोरे ग्रहण नहीं करते। यदि वे भारतीयोसे 'यवहार बद कर दे ता भारतीय कैसे रह सकते हैं? भारतीय नौकर पजीयनपत्र ले या न ले इसपर उनके गोरे मालिक कोई आपत्ति नहीं करते। कोई यह नहीं कह सकता कि भारतीयोका विरोध सामाय गोरे करने हैं। अत वास्तविक स्थिति प्रेक्षकको एकदम मालम नहीं हो सकती। यह सवाल बड़ा उलझन भरा जान पड़ता है। इसलिए यदि इसपर फिरसे विचार करना आवश्यक हो तो सभी बड़े लोगोका निष्पक्ष तरीकेसे विचार करना चाहिए। जनरल स्मट्स और श्री गावीको एक बहुत ही कठिन प्रश्नका हल खोजना है। मुसाफिरीकी सुविधाओके बारेमे पूव और पश्चिमके सम्बन्धोमे बहुत ही परिवर्तन हुआ है। एशियाई जो पहले यात्राएँ नहीं करते थे अब निकलने लगे ह। वे मितव्ययी और विनयी हैं। वे इतनी सादगीसे रहते हैं कि उतनी सादगी यूरोपीयोसे नहीं निभ सकती। हम उनके देशमे जाते ह। किन्तु उनके हजारोकी जगह हमारे जानेवाले लोग अँगुलियोपर गिने जा सकते हैं। और जब उनका वश चलता है, वे उन्हे जानेसे रोकते हैं। किन्तु एशियाई स्वय स्वीकार करते हैं कि ट्रांसवालमे भारतीयोको बे रोकटोक नहीं आने देना चाहिए। यहाके गोरे स्वीकार करते हैं कि जो भारतीय यहा आ गये हैं और हकदार हैं, उनके साथ 'याय होना चाहिए। अत यह प्रश्न रहता है कि दूसरोको आनेसे किस प्रकार रोका जाये। एशियाइयोका कहना है कि सरकारने जो तरीका निकाला है वह अनुचित और हल्के दर्जेका है। क्या सरकारने सभी तरीके आजमा कर देख लिये हैं? हस्ताक्षरोसे फोटोसे, या ऐसे ही तरीकोसे काम नहीं चलेगा? भारतीय तौर तरीके समझनेवालोके साथ सरकारने मशविरा किया है? यदि सरकारको मदद चाहिए तो बहुत लोग मदद करेगे। यदि उठाये हुए कदम वापस लेने पडे तो हमे आशा है कि सरकार प्रतिष्ठाका खयाल करके आगा पीछा नहीं करेगी। यूरोपीय और अधिक एशियाइयोको आनेसे रोकना चाहते हैं किन्तु साथ ही यह भी चाहते हैं कि ट्रांसवाल ब्रिटिश राज्यका अग है, इसे न भूला जाये। सरकारको हमारी परम्परासे चली आ रही 'यायीकी 'याय बुद्धिको कायम रखना चाहिए। यदि सरकार

अयाय करेगी और वह भी निरपराध और निबलोके साथ तो उसकी राजनीतिको बट्टा लगेगा और सरकार हार जायेगी।

इस सुंदर लेखमें केवल एक ही भूल यह है कि 'लीडर' का लेखक मानता है, लडाई केवल अंगुलियोंकी निशानी लेने देनेके सम्भवमें ही है। इस भूलसे कुछ नहीं बिगड़ता। 'लीडर' जसा अखबार सरकारको पीछे हटने और याय करनेकी सलाह देता है, इससे प्रकट होता है कि हवाका रुख बल्लनेपर आ गया है। प्रश्न केवल यह है कि भारतीयोंको अब जो जोर दिखाना है, वह दिखायेंगे या बठे रहेंगे?

नाइयोकी चेतावनी

जोहानिसबग नगरपालिकाने नाइयोके लिए नियम बनानेका प्रस्ताव किया है। और चूकि नियमोका पास हो जाना सम्भव है इसलिए उनका साराश नीचे देता हूँ

१ नाई अपनी दूकाने बिल्कुल साफ रखे। उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उनमें हवा आ जा सके।

२ बाल काटनेके यत्र, कैंची, उस्तरे कपड़े और ब्रश हमेशा साफ रखे जाने चाहिए।

३ हजामत करते समय नाईको झग्गा पहनना चाहिए। वह झग्गा गले तक पहुँचना चाहिए। नाईको अपने हाथ अच्छी तरह साफ रखने चाहिए।

४ स्वयं नाईको या उसके नौकरको कोई चम रोग या सक्कामक रोग हो तो वह हजामत न बनाये।

५ जनवरीकी पहली तारीखके बाद नाईकी हर दूकान पंजीकृत होनी चाहिए। परिषद यह पंजीयन मुफ्त करेगी।

६ सफाई निरीक्षक या डाक्टरको किसी भी नाईकी दूकानमें प्रवेश करनेका हक है।

इन नियमोकी एक प्रति प्रत्येक नाईकी दूकानमें लगाई जाये। परिषदने निम्न बातोंकी सिफारिश की है

१ हर मेजपर काच, सगमरमर, स्लेट या जस्तेका पतरा बिछा होना चाहिए।

२ हर ग्राहकके लिए साफ रूमाल काममें लाया जाये और सिर टिकानेकी जगह हर बार साफ रूमाल अथवा साफ कागज रखा जाये।

३ हजामत बनानेके लिए दो ब्रश रखे जाये। उन्हें कृमिनाशक पानीमें रखा जाये और पानीमें रखे हुए ब्रशका उपयोग किया जाये।

४ साबुनका पानी, पाउडर या साबुनकी लम्बी टिकियाका उपयोग करना चाहिए।

५ उस्तरेको साफ कागजपर घिसा जाये और उस्तरा तथा दूसरे औजारोको काममें लानेके बाद चार पांच मिनट तक जन्तुनाशक पानी में रखा जाये। दो छोटे चम्मच-भर सीलिव^१ या केरोल^२ एक क्वाट पानीमें मिलाकर जन्तुनाशक पानी तैयार किया जाये। या इतने ही पानीमें इजॉलके तीन चम्मच डाले जाये।

१ २ ये कृमि नाशक दवाओंके व्यापारिक नाम मालूम होते हैं।

६ हजामत बनानेके बाद फिटकरीकी गुल्लोका उपयोग न किया जाये, बल्कि फुहारी या साफ रुईको गीला करके उपयोगमे लाया जाये।

७ स्पञ्जका बिलकुल उपयोग न किया जाये, बल्कि उसकी जगह रुई आदिका उपयोग किया जाये।

८ पाउडर लगानेके फूलकी जगह रुईका उपयोग किया जाये।

९ ब्रशके बाल सफे होने चाहिए जोर उसे दिनमे एक बार पानी साबुन ओर साडेमे धोया जाना चाहिए।

१० बाल वारीक काटते समय गन्धेपर गिरते हैं। उन बागको हज्जाम मुहमे फूक कर न उड़ाये, बल्कि झाड़ दे।

११ कटे हुए बाल झाड़कर एक कानेमे लगानेके बजाय किसी तस्कनवाटे बतनमे रखे जाये।

उपर्युक्त नियम तथा सूचनाएँ सभी नाइयोको ध्यानमे रखनी चाहिए। इन नियमोंके अनुसार जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको दण्ड हागा इतना ही नहीं, बल्कि हमे यत् भी स्वाकार करना चाहिए कि इतनी सफाई रखना प्रत्येक नाइका कतव्य है। देशमे नाइयोकी लापरवाही अथवा गदगीसे परस्पर छून लगनेके कारण दाद, खुजली आदि बीमारिया होती हैं। जो नाई उपयुक्त नियमोंके अनुसार चलेगे उनका फायदा होगा और माना जायेगा कि उन्होंने सच्ची एवं आवश्यक तालीम ले ली है। इसमे खचकी नहीं, इच्छाकी जरूरत है।

सरकारी स्पष्टीकरण

नवम्बरका नोटिस आगे क्यों बढ़ाया गया, इसके बारेमे सरकारने स्पष्टीकरण किया है। वह स्पष्टीकरण ही सरकारको दोषी साबित करता है। सरकारको यदि डर नहीं था तो नवम्बर तक अवधि बढ़ानेकी क्या जरूरत थी? सरकारने कारण बताया है कि नवम्बरमे बिलकुल काम ही न था इसलिए एशियाइयोपर मेहरबानी की। यह बात तथ्यानुरूप नहीं है। क्योंकि नवम्बरमे गिरफ्तारिया नहीं करनी ह, यह सरकारको मालूम था। फिर यदि ऐसा ही था तो घर घर सिपाही क्यों भेजे गये? यह भी देखना है कि सरकारने अब भारतीयोंकी अर्जीकी बात छोड़ दी है। इस विचित्र स्पष्टीकरणका उद्देश्य 'लीडर' के लेखका जवाब देना है। 'लीडर' ने, जिन जिन 'मुखियो' ने अर्जी दी है, उनके नाम मागे हैं, किन्तु ऐसे नाम तो हैं ही नहीं। इसलिए सरकार दे कहासे? अतमे सरकार स्पष्टीकरणमे कहती है कि दिसम्बरसे तो कानून अमलमे आयेगा ही। यह चेतावनी कितनी बार दी जायेगी? बहुत बार 'भेडिया आया' का शोर मचाया जानेके कारण जैसे गडरिये निभय हो गये थे, वैसे ही भारतीयोंका समाज भी निभर हो गया है। यहातक कि जब दरअसल भेडिया आया था तब किसी गडरियेने नहीं माना कि भेडिया आया है। किन्तु सच्चा कानून रूपी भेडिया आयेगा तब भी भारतीय डरे, इसके लिए कोई कारण नहीं मालूम होता। क्योंकि जेल या देश-निकाला रूपी भेडियोको तो भारतीय-समाज फाड़कर खा गया है। इसलिए सरकारका भेडिया भले आना रहे।

गोरे नरम होने लगे हैं

'रैड डेली मेल' मे समाचार है कि श्री गांधी और दूसरे भारतीयोंने प्रिटोरियाकी साव जनिक सभामे साफ कहा है कि भारतीय समाज अँगुलिया लगाना कभी स्वीकार नहीं करेगा।

इस बातसे ट्रांसवालके भारतीयोंमें अधिक उत्साह पदा होगा। क्योंकि अब सरकार तथा गोरे सोचमें पड़ गये हैं कि किस प्रकार यह उलझन भरी समस्या हल हो, और इसलिए हम क्या चाहते हैं इसे समझनेका प्रयत्न करते हैं। अँगुलिया लगानेकी ओर यद्यपि हमने बहुत ही तिरस्कार दिखाया है और अँगुलिया लगानेकी शतके कारण हमारी लड़ाईको बल मिला है, फिर भी सबसे बातचीत करते समय हमें इतना अवश्य कहना चाहिए कि यह लड़ाई इस बातकी नहीं है कि अँगुलिया ली जाये या न ली जाये, बल्कि भारतीयोंकी प्रतिष्ठाकी है। सरकार हमें पछाड़ना चाहती है और हम पछाड़े जाना नहीं चाहते। सरकारने हमें गुलाम बनानेके लिए कानून बनाया है और उस कानूनको मरने तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह लड़ाई इस प्रकारकी है।

पीटर्सबर्गकी ओरसे पश्चात्ताप

पीटर्सबर्गसे श्री गनी इस्माइल और श्री हासिम मुहम्मद काला लिखते हैं कि नये पजीयन पत्रके लिए जोहानिसबर्गमें अर्जी देनेके बाद दोनोंको पश्चात्ताप हो रहा है। उस पश्चात्तापकी सीमा नहीं रहती। कानूनके लागू हो जानपर उनकी क्या हालत होगी, इसे सोचकर उनका दिल फटने लगता है। ये शब्द उन दोनों भारतीयोंके हैं। उन्होंने विशेष यह लिखा है कि उन्हें केवल पहुँच मिली है गुलामीकी चिट्ठी नहीं मिली। अर्जी वापस लेनेका यदि कोई उपाय हो तो वे जानना चाहते हैं। यदि अर्जी वापस लेनी हो तो मैं कह सकता हूँ कि वह बात अत्यंत सरल है। जिस प्रकार श्री चेनटाग (पजीकृत चीनी) ने पजीयनपत्र फेंक दिया था, उसी प्रकार उन्हें भी अपनी अर्जी वापस ले लेनी चाहिए। यदि खूनी पजीयनपत्र न लेना हो, तो माग बहुत ही सरल है। पजीयनपत्र लेनेके लिए प्रिटोरियाकी यात्रा फिर करनी होगी और पजीयनपत्रोंपर अँगूठेकी निशानी देनी होगी। इन दोनों बातोंके लिए वे साफ इनकार कर सकते हैं। इस तरह वे मुक्त रह सकेंगे। पजीयनपत्र लेने जानेके लिए वे बंधे हुए नहीं हैं और यदि न जाये तो सहज ही बिना गुलामीके चिट्ठेके रह सकेंगे। मुझे आशा है कि यह पश्चात्ताप वास्तविक है, केवल ऊपरी भावावेश नहीं है। और यदि वह वास्तविक ही होगा तो इससे दूसरे भारतीयोंको भी बल मिलेगा। इन दोनोंको मेरी सलाह है कि वे श्री शेख मुहम्मद इशाकका उदाहरण याद रखें।

कायरका प्रेम शत्रुता है

मुझे खबर मिली है कि श्री इस्माइल हाजी आमद कोडथाने मेफिकिंगसे जुलाईमें मेमन लोगोके नाम तार भेजकर हिम्मत दिलाई थी कि वे दृढ़ रहे और अपना मुँह काला न करें। यही भाई प्रिटोरियामें पधारकर और गुलामीका पट्टा लेकर इस पत्रमें “अमर” हो गये हैं। ऐसे बड़े-छा प्रोत्साहनके लिए तार देते रहे तो ऐसे तारोंसे किसे और कैसे जोश आ सकता है? यह उदाहरण बाहरके सभी भारतीयोंके लिए नोट करने योग्य है। श्री अली खमीसा गुलाम बननेके पहले बहुत बार जो बातें किया करते थे, वे याद रखने योग्य हैं। जब प्रिटोरियाके बाहरका कोई व्यक्ति हिम्मत रखनेके लिए कहता तो वे कहते थे कि जो इस सघषमें शामिल नहीं है वह मिट्टी है [इसलिए उसे उपदेश नहीं देना चाहिए]। और

डबनसे तार भेजनेवाले भाइयोको यह बात याद रखनी है, और याद रखना है कि कहीं “मिट्टी” की बूल न बन जाये।^१

ईसप मियाँका सख्त जवाब

श्री ईसप मियाने जनरल स्मट्सके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें ‘लीडर’ और ‘स्टार’ को सख्त पत्र लिखा है। उसका अनुवाद अगले सप्ताह दूंगा। उसमें सिद्ध कर दिया गया है कि सरकारके झूठकी तो सीमा ही नहीं रही।

ठीक हुआ है

जोहानिसबगमें जिन लोगोंने गुलामीके पट्टेके लिए अर्जी दी थी उनमें से एक कोकणी और एक मद्रासीको देश छोड़नेकी सूचना मिल चुकी है।

दयालजीको कैदकी सजा और उसकी अपील

दयालजी प्रागजी देसाईपर गोविंदको मारनेके सम्बन्धमें मुकदमा चला था। प्रिटोरिया अदालतने उसका फमला दे दिया है। उसमें उन्हें ४ महीनेकी सरत सजा मिली है। उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है।

गद्दार

पिछले शनिवार तक पजीयन करानेवालोंकी सूची प्रिटोरियासे [३०] पीटसबगसे [१६] लुई ट्रिचडटसे [३] मिडेलबगसे [३] पाचेफस्ट्रमसे [४], स्टैडटनसे [५] और जोहानिसबगसे [१]।

एक दयनीय मामला

मिराडा नामक पोर्तुगीज भारतीयको बगैर अनुमतिपत्रका समझकर १० अक्टूबरके पहले ट्रान्सवाल छोड़नेका हुक्म मिला था। उस मीयादके बीत जानेके कारण पिछले शनिवारको फिर उसे अदालतमें खड़ा किया गया। अभियुक्तने बताया कि उसके पास ट्रान्सवालसे बाहर जानेके लिए पैसे नहीं हैं, तो कैसे जाये? यायाधीशने अभियुक्तको दोषी ठहराकर एक महीनेकी सरत कैदकी सजा दी। और कैद पूरी होनेके बाद सात दिनमें देश छोड़नेका आदेश दिया, और यदि वह न छोड़े तो छ महीनेकी दूसरी कैदकी सजा सुनाई। यह मुकदमा वास्तवमें दयाजनक है। अब उस व्यक्तिको सरकारके सिर चढ़कर बार बार जेल भोगनी चाहिए। तभी सरकारकी अक्ल ठिकाने आयेगी। कहना आवश्यक नहीं कि यदि यह लड़ाई अन्ततक लड़कर सरकारको थका न दिया जायेगा तो ऐसे दु ख ट्रांसवालके भारतीयोंके भाग्यमें हमेशाके लिए जड़ दिये जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

१ मूल गुजरातीमें “माटी” शब्द आया है जिसका अर्थ बहादुर भी होता है। उस दृष्टिसे इन दो वाक्योंका अर्थ यह भी हो सकता है “जो सधसे दूर हैं वे अपनेको बहादुर ही समझते हैं। डबनसे तार भेजने वाले भाइयोंको यह बात याद रखनी है और याद रखना है कि अक्सर आनेपर कहीं उनकी बहादुरीका दिवाला न निकल जाये।

२६८ पत्र 'ट्रांसवाल लीडर' को

जोहानिसबर्गके 'लीडर' में श्री गांधीका एक पत्र प्रकाशित हुआ है वह इस प्रकार है'
महोदय,

आपने अपने आजके अकमे लिखा है कि जो ४०० के करीब भारतीय पजीकृत हुए हैं उन सभको ट्रांसवालमें रहनेका कुछ अधिकार नहीं है, ऐसा ब्रिटिश भारतीय सभने कहा है। परंतु मुझे कहना चाहिए कि सभके किसी पदाधिकारीने ऐसा कहा हो — यह मेरी जानकारीमें नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि हमारे बरनेदारोंमें से किसीने ऐसा कुछ कहा था, परंतु वह केवल शेखी मारनेके लिए था। यह बात कही गई अभी धरनेदारोंके मुखिया श्री पी० नायडूने उसे ठीक कर दिया था। परंतु वह समाचार आपके अखबारमें नहीं छपा। सभके पदाधिकारीकी ओरसे जो बात कही गई है सो यह है कि, सरकारने कानूनका जो अर्थ किया है उसके अनुसार जिन्हें यहां रहनेका कुछ भी अधिकार नहीं है ऐसे कमसे कम चार व्यक्तियोंने पजीयनके लिए अर्जी दी है, और सम्भवतः उनको पजीयनपत्र प्राप्त भी हो गये हैं। सभ यह नहीं मानता कि इन लोगोंको पजीयनपत्रका अधिकार नहीं है।

अर्जिया लेनेके लिए सरकार अब भी कार्यालय चालू रखना चाहती हो तो वह कोई मेहरबानी कर रही है, इसे माननेसे मैं आदरपूर्वक इनकार करता हूँ। क्योंकि इससे तो अधिकांश भारतीय केवल यही समझेंगे कि इसमें सरकारकी निबलता ही प्रदर्शित होती है। भारतीयोंने बहुत ही शालीनतासे खुदाके नामपर ली हुई शपथकी खातिर बता दिया है कि सरकारसे जो भी बने, कर ले, किंतु पजीयनकी परेशानी हमें नहीं चाहिए। कहा गया है कि बरनेदारोंके कारण भारतीय 'प्लेग' कार्यालयमें नहीं जा पाये हैं और इसी कारण अवधि बढ़ाई गई है। परंतु धरनेदार तो अब भी प्रिटोरियामें निगरानी रखेंगे ही।

आप यह कह रहे हैं कि जनरल स्मट्सने धमकिया दी है और बड़ी सरकारने हस्तक्षेप करनेसे फिलहाल इनकार कर दिया है, इसलिए भारतीयोंके विरोध करनेसे क्या लाभ है। परंतु भारतीयोंकी लड़ाई बड़ी सरकारके हस्तक्षेप अथवा जनरल स्मट्सकी दयापर निर्भर नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय समाजने जो लड़ाई छेड़ रखी है वह सफल हुई तो अनुमान है कि उपनिवेशोंमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी। किंतु वे यह भी जानते हैं कि लड़ाईमें उन्हें सबस्व खोना पड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा तो नहीं, किंतु हुआ भी तो भारतीय अग्निमें तपे हुए सोनेकी तरह निखर उठेंगे। यह एक लाभ ही है। मैं निस्कोच कहता हूँ कि श्री स्मट्स और उनका कानून दोनों मिलकर भारतीय समाजको जो कुछ देंगे उसकी तुलनामें भारतीय समाजके लिए उपयुक्त लाभ बेहतर है। उस समय आपको भी पता चल जायेगा कि प्रवासी कानूनसे उसे स्वीकृति प्राप्त हुई तो, अथवा अन्य चाहे जैसे, जुल्मी कानूनोंसे डर कर भारतीय समाज अपने ग्रहण किये हुए मागसे पीछे हटनेवाला नहीं है। यदि वह पीछे हट गया — और वह नहीं हटेगा, यह कहनेका जिम्मा मैं लेना नहीं चाहता — तो हर भारतीयको पता चल जायेगा कि ऐसा करना तो कड़ाहीसे निकलकर भट्टीमें गिरनेके समान है।

नवम्बर १ के 'लीडर' के लेखका तात्पर्य निम्न प्रकार था

अक्तूबर पूरा हो गया फिर भी ८,००० में से केवल ४०० के लगभग पजीकृत हुए हैं। और ये ४०० भी, ब्रिटिश भारतीय सघने बताया है, ऐसे हैं जिन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकार नहीं है। ट्रान्सवालमें १,१०० चीनी हैं। उनमें से केवल दोने ही पजीयन करवाया है और ये दो भी वणसकर हैं। इतने लोगोंने पजीयन नहीं करवाया फिर भी सरकार दूढ़ है। बरनेदारोंके द्वारा डराये धमकाये जानेके कारण पजीकृत होनेमें मुसीबतें थी यह देखते हुए सरकारने अवधि बढ़ा दी है। यह समझ और दयाका काम है। सही ढंगसे या फिर गलत ढंगसे भी जब कानून सरकारी पुस्तकमें चढ़ चुका है तब हमें यही अधिक उचित मालूम होता है कि भारतीयोंको उसके सामने झुक जाना चाहिए। प्रधानमन्त्रीने ससदमें हस्तक्षेप न करनेके सम्बन्धमें जो उत्तर दिया है और जनरल स्मट्सने जो कहा है वह जान लेनेके बाद भी भारतीय यदि और भी विरोध जारी रखते हैं तो उसमें क्या लाभ?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६९ पत्र जनरल स्मट्सको

जो भीमकाय प्राथनापत्र हस्ताक्षरयुक्त फार्मोंके साथ उपनिवेश सचिवके नाम भेजा गया है और उसके साथ ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री ईसप मियाने जो पत्र भेजा है, उन दोनोंका सारांश पिछले सप्ताहकी खबरोंमें छप चुका है। अब हम वह पूरा पत्र^१ नीचे दे रहे हैं

महोदय,

एशियाई कानूनके सम्बन्धमें ट्रान्सवालके भारतीयोंका एक भीमकाय प्राथनापत्र पोस्ट पासल द्वारा आपके पास भेज रहा हूँ। हस्ताक्षर करनेवालोंको जो सूचनाएँ दी गई थी उनकी प्रतिया भी साथ भेजता हूँ। ये फार्म हस्ताक्षरके लिए जब ट्रान्सवाल भेजे गये तब कुछ भारतीयोंकी ओरसे कानूनकी धाराओंमें परिवर्तन करनेके लिए सरकारको प्राथनापत्र दिया गया था। सरकारने उसका उत्तर नहीं दिया। और तबतक वह प्राथनापत्र भी वापस नहीं लिया गया था। बादमें श्री स्टगमान, एसेलन और रूजके मुवक्किलोंको सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने वह पत्र तो वापस ले लिया है, फिर भी मेरे सघकी समितिने मुझे प्राथनापत्र आपको भेज देनेका निर्देश किया है। क्योंकि, इससे आपको उसपर हस्ताक्षर करनेवालोंकी भावनाका पता लगेगा। मेरे सघकी नम्र रायमें सघने कानूनके खिलाफ जो रुख अपनाया है, उसके [औचित्यका] यह आवेदनपत्र एक जबरदस्त सबूत है, और इससे उपनिवेशके अधिकांश भारतीयोंके विचारोंका पता चल जाता है। यह आवेदनपत्र कुछ समय पहले तैयार हो गया था,

कि तु जोहानिसबगमे दफ्तर खुलनेपर समाजका रुख कैसा रहता हे, यह देखनेके लिए आजतक इसे भेजना स्थगित रखा गया था ।

इसपर कुल ४,५२२ हस्ताक्षर हुए हैं । वे इस प्रकार कुल २९ स्थानोंसे लिये गये हैं जोहानिसबग, २,०८५, न्यू क्लेअर, १०८, रुडीपूट, १३६, क्रूगसडाप, १७९, जर्मिस्टन, ३००, बाक्सबग, १२९, बेनोनी, ९१, माडरफॉटीन, ५१, प्रिटोरिया, ५७७, पीटसबग तथा स्पेलोनकेन ८०, वेरिनिगिंग, ७३, हाइडेलबग, ६६, बालफर, १४, स्टैडटन, १२३, फोक्सरस्ट, ३६, वाकस्टूम १२, पीट रिटीफ, ३, बेथल, १८, मिडेलबग, २९, बेलफास्ट, मेकाडोडॉप तथा बाटरवाल, २१ बारबटन, ६८, पाचेपस्टूम, ११४, विटरडाप, १२, क्लाक्सडाप ४१, क्रिस्चियाना, २४, लिखतनबग, ७, जीरस्ट और मेरीको, ५९, रस्टेनबग, ५४, तथा अरमेलो, २ ।

वगके अनुसार हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं सूरती, १,४७६, कोकणी १४१, मेमन १८०, गुजराती हिंदू, १,६००, मद्रासी, ९९१, कलकतियाके नामसे परिचित (उत्तर भारतीय), १५७, पारसी, १७ । सिक्ख और पठानोमेसे हिंदुओंके हस्ताक्षर गुजराती हिंदुओंके साथ गिने गये ह तथा मुसलमानोंके हस्ताक्षर सूरतियोंके साथ गिने गये हैं । ऊपर ईसाइयोंका अलग वग नहीं बताया गया । वे लगभग २०० हैं और मद्रासियोंके साथ गिने गये हैं ।

मेमन लोगोंको छोड़कर शायद ही कोई कौम ऐसी बची हो, जिसने हस्ताक्षर न किये हो । एक तो समय बहुत कम था और दूसरे, भारतीय सारे द्रासवालके फार्ममे — कुछ एकमे, कुछ दूसरे फार्ममे — फँसे हुए हैं, इसलिए सघके कायकर्ता हस्ताक्षरके लिए बहुत लोगोंके पास पहुँच ही नहीं सके । हस्ताक्षर करानेवाले सभी इज्जतदार व्यक्ति थे । उन्होंने बताया हे कि बहुत जगहोंसे लोग यह देश छोड़कर भारतको रवाना हो गये हैं । सितम्बर १९०६ को लडाई शुरू हुई तब १३,००० भारतीय अनुमतिपत्र थे । सघको मालूम हुआ हे कि गुलाम बननेके बजाय देश छोड़ना ठीक समझनेके कारण इस समय ७-८ हजार बच रहे होंगे । बहुत करके तो ७,००० से बहुत ज्यादा न होंगे । मेमन लोगोंके अलावा जितने भी लोगाने पजीयन करवाया है, उनमे बहुतेरोपर गोरे मालिकोंने दबाव डाला था । सघको खबर मिली है कि १ जुलाईसे ३१ अक्टूबर तक ३५० से अधिक लोगोंने अर्जिया नहीं दी और उन अर्जी देनेवालोंमे ९५ प्रतिशत मेमन हैं ।

एशियाई कानूनके खिलाफ भारतीयोंमे कितनी कटुता पैदा हुई हे, उसकी ओर, आखिरमे, मेरा सघ आपका ध्यान आकर्षित करता है । भारतीय समाजने जो रुख ग्रहण किया है, वह सरकारको परेशान करनेके लिए नहीं, बल्कि उसे जो कष्ट हुआ है उसके सबूतके रूपमे है । कानूनसे भारतीयोंको इतनी तीव्र चोट लगी हे कि वे उसके सामने झुकनेके बजाय अनाक्रामक प्रतिरोध करके कष्ट सहनेको तैयार हो गये हैं ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२७० रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा^१

[जर्मिस्टन

नवम्बर ११, १९०७]

श्री गांधीने कहा कि यद्यपि वे मोहलतकी अर्जीका विरोध नहीं करना चाहते, तथापि अदालतको सूचित करते हैं कि जहातक श्री पण्डितका सम्बन्ध है, औचित्य-समर्थनके लिए अदालतके सामने तथ्य पेश करनेके अलावा और कोई सफाई पेश नहीं करनी है। श्री पण्डित स्वीकार करेगे कि वे बिना अनुमतिपत्रके उपनिवेशमें हैं। मेरे मुवक्किल इस बातके लिए अत्यंत उत्सुक हैं कि यह मामला जल्द समाप्त कर दिया जाये। कुछ भी हो, वे चार दिनसे हवालातमें बंद हैं और यद्यपि बीसियों भारतीयोंने उनकी जमानत लेनेकी तत्परता दिखाई है, श्री पण्डित जमानतपर छूटनेसे इनकार करते हैं। इसलिए श्री गांधीने सुझाया कि यदि इस मामलेमें मोहलत देना स्वीकार किया जाये तो भी पण्डितजी स्वयं अपने वचनपर छोड़ दिये जाये। इसे अदालतने स्वीकार कर लिया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२७१ भेंट . 'ट्रान्सवाल लीडर' को^२

[जर्मिस्टन

नवम्बर ११, १९०७]

श्री गांधीने मुझे बताया कि यह^३ भारतीयोंके — मुख्यतः मुसलमानोंके — धर्मके विरुद्ध है, क्योंकि इससे अधिनियमके अंतर्गत आनेवाले प्रत्येक एशियाईकी निजी स्वतंत्रता छिन जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह खुदाका बंदा होनेके बजाय अधिनियमके अंतर्गत नियुक्त अधिकारीका बंदा हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वरमें विश्वास करता है, वह ऐसे

१ रामसुन्दर पण्डित अपने अस्थायी अनुमतिपत्रकी अवधि पूरी होनेपर ट्रान्सवालमें गैरकानूनी ढंगसे दाखिल होने और रहनेके लिए ' ८ नवम्बरको गिरफ्तार किये गये थे । एशियाई मुद्दामेको सुझाया गया था कि उनकी गिरफ्तारीका भारतीयोंपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । एशियाई कानून मशौधन अधिनियमके अन्तर्गत चलाया जानेवाला यह पहला मुकदमा था और यह सहायक अधिवासों मजिस्ट्रेटकी अदालतमें दायर किया गया था । सरकारी वकीलोंने जब एशियाई पंजीयकोंको अदालतमें बुलानेके खयालसे मोहलत माँगी तब गांधीजीने यह दलील पेश की । देखिए दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय १८ भी ।

१२-११-१९०७ के ट्रान्सवाल लीडरकी एक रिपोर्टके अनुसार गांधीजीने कहा कि रामसुन्दर पण्डित ' अपने आपको सभी प्रकारसे निर्दोष समझते हैं तथा यह मुकदमा लड़नेको तैयार हैं और इसलिए जब भी बुलाये जायेंगे, अदालतके सामने जान्तेसे उपस्थित होंगे । '

२ ट्रान्सवाल लीडरके एक संवाददाताने रामसुन्दर पण्डितके मामलेकी पहली सुनवाईकी समाप्तिपर उनकी रिहार्डके बाद गांधीजीसे भेंट की थी ।

३ पंजीयन ।

अधिनियमको माननेका खयाल सपनेमे भी नही कर सकता, जिससे वह वास्तवमे दासतामे बँध जाता हो।

अब चूँकि सब भारतीय पजीयन अधिनियम अपने धर्मके विरुद्ध होनेके कारण उसे स्वीकार न करनेके लिए एक गम्भीर शपथके द्वारा बँधे हैं, इसलिए यहाँ धर्म अधिक प्रमुख रूपसे सामने आता है। जोर इसलिए यदि कोई भारतीय किसी ऐसे भौतिक लाभके लिए, जो उसे मिल सके, अधिनियमको स्वीकार करता है तो वह अपनी अंतरात्माका हनन करता है। फलतः उक्त पुरोहितने इस बातमे सक्रिय दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है कि लोग पजीयन न कराये और वे लौकिक सम्पदाको देखनेके बजाय पारलौकिक सम्पदाको देखे। यही कारण है कि जब जर्मिस्टनमे एशियाई पजीयन कार्यालय खुला था तब उन्होंने मुरय धरनेदारके रूपमे काय किया, जो विशुद्ध रूपसे समझाने-बुझानेसे सम्बन्ध रखता था।

[अंग्रेजीसे]

द्रासवाल लीडर, १२-११-१९०७

२७२ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा^१

[जर्मिस्टन

नवम्बर १४, १९०७]

श्री गांधी द्वारा जिरह करनेपर गवाहने^२ कहा कि समझौता यह था कि अभियुक्त तारीख २८ अगस्त १९०६ तक रहेगा। तबसे उसके अनुमतिपत्रकी अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि मुझे यह विश्वास दिलाया गया, और मने विश्वास किया भी, कि अभियुक्तको उपनिवेशमे जिस कायके सम्बन्धमे रहनेकी अनुमति दी गई है, वह यहाँ उसीको करेगा।

[गांधीजी] क्या आपके पास इसमे सन्देह करनेका कोई कारण है कि अभियुक्त धर्म-पुरोहित है और वही रहा है ?

[गवाह] यहाँ धर्म पुरोहित बहुत-से हैं और धर्म पुरोहित धर्मका प्रचार करते हैं। कोई पुरोहित ईसाई हो, या मुसलमान, या हिन्दू या किसी दूसरे धर्मका, जबतक वह अपने सिद्धांतका प्रचार करता रहता है तबतक, मेरे विचारमे, वह वाञ्छनीय है, किंतु जब वह अन्य सिद्धांतको — म नहीं कहूँगा, राजद्रोहका — प्रचार करता है और अपने लोगोको हिंसाके लिए भडकानेके तरीके अख्तियार करता है, तब वह उससे भिन्न व्यक्ति हो जाता है, जसा मने उसको उपनिवेशमे जानेकी अनुमति देते समय समझा था।

उन्होंने क्या प्रचार किया ?

क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है कि उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तोके अलावा किसी दूसरी बातका प्रचार किया ?

^१ देखिए 'रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा', पृष्ठ ३५१।

^२ एशियाई पजीयक मॉटफोर्ड चैमने।

मेरा विश्वास है कि उसने ऐसा प्रचार किया है, और इस विश्वासके आधारपर मने उसका अनुमतिपत्र नया करनेसे इनकार कर दिया है।

क्या आप कहते हैं, आपका विश्वास है कि उन्होंने पुरोहितके कतव्यसे भिन्न काय किया है ?
मने यह नहीं कहा।

आपने अभी कहा है कि आपके पास ऐसा माननेके कारण है कि वे धार्मिक सिद्धान्तासे भिन्न सिद्धान्तोका प्रचार कर रहे हैं। क्या आपके पास यह विश्वास करनेके पर्याप्त कारण है ?

मुझे गोरो और रगदार, दोनोंसे शिकायते मिली हैं।

क्या आपने उनको इन शिकायतोके सम्बन्धमे कभी चेतावनी दी है ?

निश्चय ही नहीं दी।

आपको शिकायते कब मिली ?

मुझे ठीक तारीखे याद नहीं आ रही, किंतु ये एशियाइयोके पजोयनके सम्बन्धमें थी।

क्या आप इन शिकायतोको पश कर सकते हैं ?

म पेश तो हर्गिज नहीं करूँगा।

तब, श्री चैमने, आप इन शिकायतोको पश करनेसे निश्चित रूपसे इनकार करते हैं ?

म आपको उन व्यक्तियोंके, जिन्होंने शिकायतें की हैं, नाम बतानेसे निश्चित रूपसे इनकार करता हूँ।

श्री गांधीके अनुरोधपर गवाहने पिछले २८ सितम्बरकी वह दरखास्त पेश की जो उसको जर्मिस्टनके भारतीयोंसे प्राप्त हुई थी और जिसमे उससे अभियुक्तके अनुमतिपत्रकी अवधि, जो समाप्त होनेवाली थी, बढ़ानेकी प्रार्थना की गई थी और कहा गया था कि अभियुक्त मात्र मन्दिरसे सम्बन्धित काममें लगा रहता है और अपने धार्मिक कर्तव्योका पालन करता है।

क्या आपने इस दरखास्तको अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़ानेके लिए पर्याप्त प्रेरणादायक नहीं समझा ?

नहीं, मुझे जो सूचनाएँ दी गई थीं उनको देखते हुए मने इसको पर्याप्त नहीं समझा।

आप मानते हैं कि अभियुक्तने जर्मिस्टनका हिंदू मन्दिर खरीदा है ?

म इस सम्बन्धमे कुछ नहीं जानता। वह यहां कुछ सप्ताहका अनुमतिपत्र लेकर आया था, और हमने उस अनुमतिपत्रकी अवधि एक वर्षसे अधिक समयके लिए बढ़ा दी, और म नहीं जानता कि उसने क्या किया।

और यदि यह नया अधिनियम न बना होता तो आप, कदाचित्, उसकी अवधि निरन्तर बढ़ाते जाते ?

बहुत सम्भव है, बढ़ाता जाता।

जब आप “राजद्रोह” की बात कहते हैं, आपका तात्पर्य क्या होता है ?

मने विशेष रूपसे कहा है कि मैं राजद्रोहकी बात नहीं कहता ।

तब उन्होंने अपने धार्मिक कृत्योंके अलावा कुछ किया, यह कहनेसे आपका अभिप्राय क्या है ? क्या आपका अभिप्राय यह है कि उन्होंने लोगोसे पञ्जीयन अधिनियमको न माननेके लिए कहा ?

म कल्पनापर आधारित प्रश्नोका उत्तर नहीं दे सकता ।

आप जानते हैं कि उन्होंने एशियाई अधिनियमको माननेके विरुद्ध प्रचार किया है । क्या यह उसका एक पहलू है ?

इसका उत्तर है “हाँ”, किंतु मेरी यह हाँ बिना शत नहीं है ।

क्या मुल्लाओके अनुमतिपत्रकी अवधि भी बढ़ाई गई है ?

हाँ, और ईसाई तथा दूसरे पुरोहितोके अनुमतिपत्रोकी भी ।

आपका आशय एशियाइयोसे है ?

जब म ईसाइयोकी बात करता हूँ तो, श्री गांधी, आपको समझना चाहिए कि मेरा तात्पर्य होता है असीरियाइयोसे ।

“यायाधीशने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि श्री गांधी क्या समझते हैं, बल्कि यह है कि अदालत क्या समझती है ।

श्री चैमनेके तरीके

गवाहने बताया कि जब कोई पुरोहित धर्म प्रचारके उद्देश्यसे द्रासवालमे प्रवेश करनेके अनुमतिपत्रके लिए प्राथनापत्र देता है, वे (श्री चैमने) उसके मागमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करते, किंतु असीरियाई और मुसलमान इतनी बड़ी संख्यामे आते हैं कि उनसे इनको अनुमतिपत्र देना सीमित करनेका अनुरोध किया गया है । सरकारको ऐसे पुरोहितोको अस्थायी अनुमतिपत्र देनेमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि अनुमतिपत्र जिन शर्तोंपर दिये गये हों उन्हें वे पूरा करें ।

क्या आपको उनके सम्बन्धमे जर्मिस्टनी भारतीयोसे कोई शिकायत मिली है ?

म समझता हूँ, “जर्मिस्टनी भारतीय” से आपका मतलब जर्मिस्टनवासी भारतीयोसे है ?

हां ।

तब मुझे उनसे ही शिकायत मिली है ।

क्या आपने शिकायतकी जाच की है ?

बेशक ।

क्या आपने कभी इन शिकायतोंके सम्बन्धमे अभियुक्तका उत्तर भी सुना है ?

नहीं, निश्चय ही नहीं ।

तो आपने उनका बयान सुने बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया ?

मुझे उनका पत्र मिला है। यह बात न भूलें।

तब उसे पेश कीजिए।

म पेश कर चुका हूँ।

किंतु वह पत्र शिकायतका उत्तर तो नहीं है ?

मैंने यह नहीं कहा कि वह उनका उत्तर है।

तब तो वही बात हुई जो मैंने कही, आपने सुनवाई किये बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया।

मने उनको कुछ शर्तोंके साथ ट्रांसवालमे आनेकी अनुमति दी थी। इन शर्तोंको उन्होंने नहीं निभाया।

क्या आपने कभी उनको इसकी सूचना दी ?

अब देता हूँ।

उनको फासी देनेके बाद ?

नहीं, फासी देनेके बाद नहीं। म इस आक्षेपको पसंद नहीं करता।

तब गवाहने गत ९ अक्टूबरका एक पत्र पढा जो उन्होंने अभियुक्तको तत्काल उपनिवेशसे चले जानेकी सूचना देते हुए लिखा था।

श्री गांधी इससे मेरे प्रश्नका उत्तर बिलकुल नहीं मिलता।

मेरा उत्तर यही है।

इसके बाद अभियोग पक्षकी कारवाई समाप्त हो गई ।

बचाव

सरकारी वकील अभियुक्तका धरनेदारोसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा ?

श्री गांधी म मानता हूँ कि वे मुख्य धरनेदार थे ।

तब श्री गांधीने अदालतको सम्बोधित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि कानून जैसा है उसके अनुसार सजा अवश्यम्भावी है, किंतु उन्होंने अनुरोध किया कि यह मामला ऐसा है जिसमे अदालतका मत व्यक्त करना आवश्यक है। उन्होंने “ताज बनाम भाभा” के मुकदमेकी नजीर दी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालयने शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध तीव्र मत व्यक्त किया था। उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किलपर मुकदमा इसलिए नहीं चलाया गया कि उनके पास अनुमतिपत्र नहीं ह, बल्कि, जैसा बिलकुल स्पष्ट है, इसलिए चलाया गया कि एशियाई अधिनियमके सम्बन्धमे उनके विचार तीव्र ह और उनको वे अपने देशवासियोंके सम्मुख रखनेमें सक्षमके नहीं ह। यदि यह अपराध हो तो भारतीयोंकी बहुसंख्या अभियुक्तके समान ही अपराधी है। उचित या अनुचित, रामसुन्दर पण्डितका विश्वास यह है कि इस अधिनियमके सम्बन्धमे सच्ची बातोंको अपने देशवासियोंके सम्मुख रखना धर्म-प्रचारकके रूपमे उनके कतव्योंका अंग है। धार्मिक आपत्ति अँगुलियोंके निशान देने और पत्नीका नाम

बतानेसे बहुत आगे जाती है। पण्डितजीने प्रचार किया है, क्योंकि प्रत्येक आत्मसम्मानी भारतीय की भाँति उनकी सम्मतिमें भी इस अधिनियमको माननेसे भारतीयोंके समस्त पुरुषोचित गुण चले जाते ह। मेरा खयाल है कि पण्डितजीने जो कुछ किया है उसको देखते हुए वे निदाके बजाय स्तुतिके पात्र ह। उन्होंने न्यायाधीशसे अभियुक्तके इस वक्तव्यपर विश्वास करनेका निवेदन किया कि जो शिकायतें कभी प्रकाशमें नहीं आईं और जिनके सम्बन्धमें अभियुक्तको मुकदमेके दिन तक कोई जानकारी नहीं थी, उनमें कोई सत्य नहीं है। अभियुक्त पजीयकके आदेशका उल्लंघन करनेके परिणामोंसे परिचित ह, किंतु उनके अपने ही शब्दोंमें, उनको एक उच्चतर कर्तव्यका आह्वान मिला है और उसी आह्वानपर वे इस 'यायालयके सम्मुख कैदकी या उससे भी बड़ी सजा भुगतनेके लिए उपस्थित हुए ह।'

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२७३ प्रस्ताव सार्वजनिक सभामें^२

[जर्मिस्टन

नवम्बर १४, १९०७]

एशियाई पजीयन अधिनियमके अंतगत एकमात्र हिंदू पुरोहित रामसुन्दर पण्डितको सजा सुनाई जानेके बाद जर्मिस्टनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सभा हुई। महामहिम सम्राटसे दमनके विरुद्ध, जिससे निर्दोष भारतीय पीड़ित हैं, संरक्षण प्राप्तिके लिए आवेदनका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पण्डितजीने सिद्धांतके बलिदानके बजाय जेल जाना स्वीकार किया है। हजारों इसके लिए तैयार ह।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

१ रामसुन्दर पण्डितको एक महीनेकी कैदकी सजा दी गई।

२ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा खत्म हो जानेपर गांधीजीने एक सार्वजनिक सभामें भाषण दिया, देखिए पृष्ठ ३६६-६७। प्रस्ताव एक तारके रूपमें लिखा गया था जो स्पष्टतया दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके माध्यमसे भेजा जानेवाला था और अनुमानत गांधीजीने ही इसे तैयार किया था। यह भी तय किया गया था कि पण्डितजीके परिवारके प्रति बर्खाश्ते तार भेजे जायें और दूसरे दिन दूकानें तथा सब कारखार स्थगित रखे जायें।

२७४ पत्र गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबग
नवम्बर १४, १९०७

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

इस पत्रका उद्देश्य श्री अमीरुद्दीन मुहम्मद हुसैन फजदारका^१ आपसे परिचय कराना है। ये, चार अन्य भारतीयोंके साथ, आगामी राष्ट्रीय कांग्रेसमें ट्रान्सवालके भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए नियुक्त हुए हैं। श्री फजदार ट्रान्सवालके सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं और यहाँ लम्बे अरसेसे रह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन्हे कांग्रेसके सामने हमारा मामला रखनेके लिय प्रत्येक सुविधा प्राप्त करानेकी कृपा करेंगे और अपनी सलाह तथा मागदशनका लाभ उठाने देंगे।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिका फोटो-नकल (जी० एन० ४१०८)से।

२७५ धरनेदारोंके विरुद्ध मुकदमा

[प्रिटोरिया
नवम्बर १५, १९०७]

गौरीशंकर व्यास, शरफुद्दीन, गोविन्द प्राग और फ्रक लछमनपर इसी १५ तारीखको यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मारपीट करने या जुर्मके लिए भडकानेका अपराध किया, क्योंकि १३ नवम्बर १९०७ को (या उसके आसपास) उसी जिलेके प्रिटोरिया नगरमें (या उसके आसपास) प्रत्येक और सब अभियुक्तोंने या उनमेंसे किसी-न-किसी ने अन्यायपूर्ण और अवैध रूपसे लछमन नामके एक भारतीयको, जो वहीं रहता है, पीटा, उहोने उसको वहीं घेर लिया और उसको अपनी (या किसी अयकी) इच्छाके अनुसार भारतीय पजीयन कार्यालयमें जानेसे रोका। उसी वक्त और उसी जगह प्रत्येक और सभी कथित अभियुक्तोंने या उनमेंसे किसी-न-किसीने अन्यायपूर्वक और गरकानूनी रूपसे उसको पजीयनका प्रार्थनापत्र, जिसे पेश करना सन् १९०७ के अधिनियम २ के खण्ड १, २ और ८ के अन्तर्गत आवश्यक है, न देनेके लिए यह धमकी देकर भडकाया कि यदि उसने पजीयन कराया तो उसको पीटा जायेगा तथा उसका मुँह काला कर दिया जायेगा। अभियुक्तोंने अपनेको निर्दोष बताया और और श्री गांधीने उनका बचाव किया। सरकारकी ओरसे श्री ग्राहमने पैरवी की। अदालत भारतीयोंसे खचाखच भरी थी और कई तो प्रवेश पा भी नहीं सके।

१ मूलमें 'वजिन्दार' शब्द आया है।

२ मूलमें 'अधिनियम २०/१९०७' है।

वादीने कहा कि अभियुक्तोने उससे पजीयन कार्यालयके बाहर बातकी थी और उसको सलाह दी थी कि हमारे लोग अनुमतिपत्र नहीं ले रहे ह इसलिए तुम भी उन लोगोसे सलाह कर लो जो तुमसे अधिक बुद्धिमान ह। अभियुक्तोने मुझसे मारपीट कभी नहीं की।

श्री ग्राहमने कहा कि गवाह [लछमन] को विरोधी गवाह माना जाये, किन्तु श्री गांधीने आपत्ति की। वह आपत्ति लिख ली गई और गवाहने कहा कि उसको रिपोर्ट लिखनेके दफ्तरमे ले जाया गया और श्री कोडीने उससे पूछा कि क्या अभियुक्तोने उसके साथ मारपीट की है। उसने कहा, “नहीं”। श्री कोडीने कहा कि उहोने अभियुक्तोको गिरफ्तार कर लिया है और गवाहने जब यह पूछा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो उसको बताया गया कि यह उसकी इच्छा थी। गवाहने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उसने कहा “ये मेरे देशवासी ह और गिरफ्तार नहीं किये जाने चाहिए। म पासके लिए आया था और जब मुझे पास मिल जायेगा, तब म चला जाऊंगा। उहोने मेरे साथ मारपीट नहीं की है।”

श्री गांधी यह प्रिटोरिया पास लेने आया, क्योंकि इससे एक गोरेने कहा था कि यदि यह पास न लेगा तो इसको निकाल दिया जायेगा। उस गोरेने इसके कागजात ले लिये थे और श्री कोडीको भेज दिये थे। यह विटबैकका धोबी है। यह अपने मनमे सरकारसे भयभीत है और इसीलिए यहां आया था। इसको पजीयन-कार्यालयमे दो गोरे ले गये थे, जो इसे स्टेशनपर मिले थे।

श्री गांधीके जिरह करनेपर एक गवाहने^१ कहा कि उसको सुपरिटेण्डेंट बेटसने लछमनसे स्टेशनपर मिलने और उसको पजीयन कार्यालयमे लाने एव यदि उसको (लछमनको) तग किया जाये तो उसकी खबर देनेकी हिदायत की थी। वह हिन्दुस्तानी अच्छी तरह जानता है। उसने कोई मारपीट होते नहीं देखा।

श्री ग्राहमने अपनी ओरसे मामला खत्म कर दिया और श्री गांधीने अभियुक्तोको तुरत बरी करनेकी माग की। श्री ग्राहमने कहा था कि वे मारपीटके आरोपकी पुष्टि नहीं कर सकते और उनको भडकानेके आरोपपर निभर रहना होगा। श्री गांधीने कहा कि मेरे सामने अब कोई मामला सफाईके लिए नहीं है।

श्री मेलर^२ (मुसकराते हुए) श्री ग्राहम, क्या आप इस आरोपको पुष्ट करेंगे ?

श्री ग्राहम वस्तुतः म इस आरोपपर जोर नहीं देता। मेरे खयालमे मामला काफी मजबूत नहीं है।

श्री मेलर उनसे कह दें कि वे बरी कर दिये गये^३।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

१ आल्फ्रेड एंडर्सन, केप्टीय जेलका सन्तरी। उसने गवाहीमे कहा था कि वह जेलके गवर्नरके निर्देशसे रेलवे स्टेशनपर गया था और वादीसे मिला था। वादीने उसे बताया कि वह पजीयन करानेके लिए आया है, किन्तु अभियुक्तोने उसको पीटनेकी धमकी दी है।

२ सहायक आवासी मजिस्ट्रेट।

३ इसके पश्चात् धरनेदारोंको मालाएँ पहनाई गईं और वे जुलूसमें श्री व्यासके घर ले जाये गये, जहाँ श्री ए० एम० काछलिया, मुख्य धरनेदार श्री एम० एल० देसाई, गांधीजी और अन्य लोगोंने धरनेदारोंके वीरतापूर्ण खूबी प्रशंसा करते हुए भाषण दिये।

२७६ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को^१

जोहानिसबग

नवम्बर १५, १९०७

सेवामे

सम्पादक

'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

क्या आप मुझे रामसुन्दर पण्डितके^२ मुकदमेके सिलसिलेमे सामने आये कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथ्योंको जनताके ध्यानमे लानेकी इजाजत देनेकी कृपा करेंगे ?

एशियाई पजीयकने स्वीकार किया कि यह उसके कार्यालयका नियम है कि पुरोहितको अस्थायी अनुमतिपत्र ही दिये जाये, लेकिन साथ ही यह मूक समझौता भी है कि जबतक वे अपनेको पुरोहिताई तक ही सीमित रखते हैं तबतक अनुमतित्रोकी अवधि, पजीयकके शब्दोमे, "जीवनके अन्ततक बढ़ाई जा सकती है।" आगे उसने यह बताया कि हिंदू पुरोहितने पुरोहिताईके अतिरिक्त कुछ और काम भी शुरू कर दिया, इसलिए पजीयकके विचारमे वह अवधि बढ़वानेके अधिकारका पात्र नहीं रह गया। बड़ी मुश्किलसे मैं समझ पाया कि इस "कुछ और" मे पुरोहित द्वारा एशियाई अधिनियमके विरुद्ध प्रचार भी शामिल था। उसकी अय "कुचालो" का भी एक बुधला सा हवाला दिया गया, लेकिन पजीयकने शिकायतको स्वरूप तथा शिकायत करनेवालोके नाम बतानेसे साफ इनकार कर दिया। उसने यह स्वीकार किया कि पुरोहितको अपने निदकोका मुकाबला करने या उनकी शिकायतको जवाब देनेका मौका कभी नहीं दिया गया। दूसरे शब्दोमे, उसकी बात सुने बिना ही उसे सजा दे दी गई। युद्ध-कालके अलावा ऐसे किसी मनमाने, अनुचित तथा अयायपूर्ण कायका उदाहरण मुझे नहीं मिलता। इस कानूनके अन्तगत एक ऐसे व्यक्तिको, जो — जैसा कि उसने गवाहीके कठघरेमे खड़े होकर स्वीकार किया — उक्त कानूनके विषयमे कुछ नहीं जानता और फलत गवाहीको तोल सकनेमे सवथा असमर्थ है तथा जिसे राजद्रोह और वैयक्तिक स्वतंत्रतापर चोट करनेवाले कानून-विशेषके सादर तथा वीरतापूर्ण विरोधमे कोई फक नहीं दिखाई देता, स्वतंत्र तथा निरीह ब्रिटिश प्रजाजनोंपर असीम सत्ता प्राप्त है। वह किन शर्तोपर धम प्रचारकोको इस देशमे रहने देगा, यह उसकी मर्जीपर निर्भर है, और अगर कही वह उनसे नाराज हो गया तो उसे अधिकार है कि वह लगभग तत्काल मन्दिरको बंद कर सम्बंधित समुदायोको धार्मिक समाधानसे वंचित कर दे।

और फिर भी एशियाइयोसे प्रायः पूछा जाता है कि वे एक इतने सीधे सादे कानूनका, जिसका एकमात्र उद्देश्य उपनिवेशमे रहनेवालोकी पहचान करना है, विरोध क्यों करते हैं।

श्री लिअग क्विनने जनताका ध्यान एक शोकजनक घटनाकी ओर आकर्षित किया है। बहस्पतिवारको जर्मिस्टनमे जो कुछ हुआ वह इतना भारी काण्ड था कि मजिस्ट्रेटको कहना

१ इस पत्रका गुजराती अनुवाद २३-११-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें छपा था।

२ देखिए पृष्ठ ३५२-५६।

पडा कि वह अभियुक्तसे सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। किन्तु, 'यायालय लाचार था और एक निरीह व्यक्तिको अफसरके पूर्वग्रह, अज्ञान, अयोग्यता तथा उद्धतताकी वेदीपर—ऐसे दुगुणोकी वेदीपर जो निश्चय ही घोर रूपसे अ-ब्रिटिश है—बलिदान कर दिया गया।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२७७ कैक्सटन हॉलकी सभा

श्री अमीरअली तथा ब्रिटेनवासी मुसलमान ट्रान्सवालके भारतीय समाजके पक्षके समर्थनके लिए उसके धन्यवादके पात्र हैं। हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी ओरसे भारतीय मुसलमानोको एक सवसामाय पत्र^१ भेजनेका विचार सुंदर था। समुद्री तारोसे पता चलता है कि कायवाही उत्साहपूर्ण थी और सभामें अनेक प्रमुख यूरोपीयोने भाग लिया था। विचित्र संयोग है कि सभा ९ नवम्बरको, जो सम्राटका जन्म-दिवस है, हुई। अगर श्री अमीरअली और उनके श्रोताओको यह मालूम होता कि जिस समय वे ट्रान्सवालके पददलित भारतीयोके पक्षमें न्याय और मानवताकी मांग कर रहे थे, उस समय ट्रान्सवाल सरकार एक भारतीय पुरोहितको अपने अत्याचारका शिकार बना चुकी थी, तो न जाने उनकी भावना क्या होती? हमको रायटरसे पता चला है कि एशियाई अधिनियमकी भत्सनाके भाषणोके बीच बीचमें "शम शम" और "अबोभनीय" की आवाज गूज उठती थी। इस महत्वपूर्ण सभाकी अवहेलना करनेका एक तरीका यह है कि इसे स्थानीय स्थितिसे अनभिज्ञ लोगोकी राय कहकर टाल दिया जाये। एक दूसरा तरीका यह है कि इसे उस असतोषका प्रतीक मान लिया जाये जो हजार हजार भारतीयोके हृदयमें व्याप्त है। यदि इसे दूसरे दृष्टिकोणसे देखा जाये तो इस सभामें पास किये हुए प्रस्तावपर ट्रान्सवाल सरकारको हार्दिक और सहानुभूतिपूर्ण ढंगसे गौर करना चाहिए। किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि जबतक साम्राज्यीय सरकार कोई प्रभावकारी कारवाई नहीं करती, ट्रान्सवालके अधिकारी भारतीयोकी कही हुई हर बात अनसुनी कर देगे, चाहे वे भारतीय कितने भी प्रभावशाली तथा जानकार हो। कुछ भी हो, इस सभामें एक काम तो अवश्य ही किया है कि ससार भरके मुसलमान अब यह महसूस करने लगे हैं कि उनको महज अपने सहधर्मियोके प्रति ही सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और न महज उनके लिए ही काम करना चाहिए, बल्कि उनको अपना कायक्षेत्र हिंदुओ तक भी बढ़ाना चाहिए। यह एक अच्छा लक्षण है और इससे पता चलता है कि हम उस समयकी ओर बहुत शीघ्रतासे अग्रसर हो रहे हैं जब जाति तथा धर्मका विचार किये बिना मनुष्य मनुष्यके लिए काम करेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२७८ लाजपतरायकी रिहाई

ट्रान्सवालके भारतीयोंके लेने लायक सीख

लाला लाजपतराय तथा उनके सेनापति अजीतसिंह छूट गये हैं। देश निकाला तो भोगा, किन्तु पंजाबके जमीन सम्बन्धी कानूनको रद्द करवा दिया है। यह जीत अनाक्रामक प्रतिरोधकी सफलताका जबरदस्त सबूत है। यह ताजा उदाहरण सामने होते हुए भी क्या ट्रान्सवालके भारतीयोंमें किसीके डगमगाते रहनेके लिए कारण रहेगा? हम आशा करते हैं कि कदापि नहीं रहेगा। उल्टे, जिन्होंने अर्जी दी है वे भी यदि लाजपतकी जीतका अर्थ समझ सकेंगे, तो अर्जी वापस लेनेका अवसर, यानी नये पंजीयनपत्र लेने न जानेका अवसर, होनेपर उसे चूकेंगे नहीं। क्योंकि यह तो सब स्वीकार करते हैं कि एशियाई कानून खराब है। पंजीकृत होनेवाले केवल स्वाथसे अच्छे होकर तथा जेलसे डरकर इस गुलामीके चक्रमें फँसे हैं। लाजपतकी विजय बताती है कि डरनेवाले औरते हैं और हारे हुए हैं, जबकि लड़नेवाले मद और जीते हुए हैं। आजकल जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उनसे भी यह प्रकट होता है कि लड़नेवाले जीते हुए हैं। शत केवल यह है कि लड़ना हो तो, जेल और देश निकाला भोग कर भी अततक लड़े, और लाजपतका उदाहरण भी यही बताता है। इसलिए ट्रान्सवालके भारतीय “हिंदके लाला” के देश-निकालेसे आवश्यक सबक लेंगे और उसके अनुसार आचरण करनेके लिए छाती तानकर तैयार रहेंगे तो हम बिना किसी सकोचके कहते हैं कि उन्हें विजय अवश्य मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२७९ सम्राटकी सालगिरह

हम मानते हैं कि महाराज एडवडको उनकी सालगिरहपर भारतीयोंकी ओरसे मुबारक-बादीका तार भेजा गया सो ठीक हुआ। हम सच्ची प्रजा हैं। विवेक हमारी हड्डियोंमें रमता है। यदि तार न जाता तो माना जाता कि हम विवेकको भूल गये हैं। उसमें हमने गलत खुशामद नहीं की। हमने फायदेके लालचसे तार नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा है कि सम्राटकी मंगल कामना करना हम अपना कतव्य समझते हैं।

फिर भी ऐसा तार क्यों भेजा जाये? हमें सालगिरहके दिन तीन भेदे प्राप्त हुईं। रामसुंदर पण्डित व्यर्थ पकड़े गये। इसमें धमकी हानि हुई। वे हिन्दू हैं, फिर भी धक्का पूरे समाजको लगा है। हजके लिए जानेको पारपत्र (पासपोर्ट) नहीं मिलते। जोहानिसबग आदिमें परवाने नहीं मिलते। मतलब यह कि जब सभी खुशी मना रहे हैं तब भारतीयोंके लिए शोक मनाने जैसा रहा। तब भी क्या हम सालगिरहका तार भेजे?

कांग्रेसके भूतपूर्व तीन अध्यक्षोंके मनमें यह विचार उठा, और वह ठीक ही उठा। उन्होंने कहा कि यदि तार भेजना ही हो तो हमें उपर्युक्त दुःख भी साथमें रोना चाहिए।

उन्होंने जो इस तरह आपत्ति की है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारी भावनाओंको कितनी ठेस पहुँची है, यह उसका चिह्न है। इतना होनेपर भी यह गुस्सेकी निशानी है। हमें जो दुःख है, उसमें महाराजका दोष नहीं है। इलाज हमारे हाथमें है। दुःख आया है तो इलाज भी होगा। वह इलाज ट्रान्सवालके भारतीयोंके हाथ है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८० लन्दनमें मुसलमानोंकी सभा

अखबारोंमें तार छपा है कि यह सभा ९ नवम्बरको लन्दनमें हुई। यह कोई मामूली समाचार नहीं है। न्यायमूर्ति अमीरअली सभाके अध्यक्ष थे। कई गोरे उपस्थित थे। नये कानूनसे और कोई लाभ न हो तो न सही, हिन्दू-मुसलमानके बीच मेल तो अवश्य बढेगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सभामें यह साफ कहा गया है कि हिंदुओंके लिए भी मुसलमान हक मांगेंगे। जो मुसलमान इकट्ठे हुए थे, वे केवल भारतके ही नहीं थे। भारतके मुसलमान हिंदुओंके लिए अधिकार मांगें, तो यह उनका कर्तव्य ही है, क्योंकि दोनों भारतकी सत्तान हैं। किन्तु विलायतमें रहनेवाले दूसरे देशोंके मुसलमान भी उसमें शामिल हुए, यह बहुत ही खुशीकी बात है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चन्दा

हर वर्ष हम कांग्रेसका चन्दा इकट्ठा करते हैं। वैसे ही इस वर्ष भी होगा। अब हमारी ओरसे प्रतिनिधि जानेवाले हैं, इसलिए आशा है कि कांग्रेस निधियोंके लिए बहुत से भारतीय हमें चन्दा भेजेंगे। हम उसकी प्राप्ति स्वीकार करेंगे। लगभग २५ पौंड तो जोहानिस बर्गमें जमा हो गये हैं। चन्दा देनेवालोंके नाम अगले सप्ताह प्रकाशित करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८२ बचे हुए मेमन

प्रिटोरियामे ४०, पीट्सबर्गमे २७, पाचेस्ट्रममे २०, पीट रिटीफमे ३, इस प्रकार लगभग १०० मेमन बच गये हैं। इन्हें हम वीर समझते हैं। उनसे हमारी यह छोटी सी प्रार्थना है कि अब हिम्मत न हारे और मेमन लोगोकी तथा भारतीय समाजकी नाक रखे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८३ पण्डितजीका जीवन-चरित्र

इतना शोर मचानेवाले भारतीयका इतिहास जाननेके लिए सभी भारतीय उत्सुक होंगे। इस अकमे हम उनका चित्र दे रहे हैं। रामसुंदर पण्डितकी आयु तीस वर्षकी है। उनके पिताजीका नाम कालिकाप्रसाद है। वे पुरोहिताई करते थे। पण्डितजीका जन्म बनारसमे हुआ था। बनारस संस्कृत पाठशालामे उन्होंने हिन्दी और संस्कृतका अध्ययन किया था। इधर नौ वर्षोंसे वे दक्षिण आफ्रिकामे पुरोहिताईका काम कर रहे हैं। उन्होंने नेटालमे विवाह किया है और उनकी सतानोमे ढाई वर्षका एक लड़का और एक वर्षकी एक लड़की है। उनके बाल-बच्चे ग्रेटाउनमे रहते हैं। सन १९०५मे पण्डितजी ट्रान्सवाल आये। उनके परिश्रमसे जर्मिस्टनमे मंदिर बना और सनातन धर्म सभाकी स्थापना हुई। एशियाई कानूनके सम्बन्धमे उनके कामको सब भारतीय जानते हैं। अतमे हम इतना ही चाहते हैं कि पण्डितजी दीर्घायु हो और निरन्तर समाज-सेवा करते रहे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८४ भारतके लालाजीने क्या किया ?

हम मानते हैं कि लाला लाजपतरायने तो देश-निकाला भोगकर सैर की है, क्योंकि उनकी मनोकामना फली है। उन्होंने पंजाबके भूमि-कानूनके विरुद्ध युद्ध मचाया, न कि अपनी सुख-सुविधाके लिए। वह कानून रद्द हो गया है। फिर लालाजी चाहे माडलेमे बसे या लाहौरमे, इसकी उनकी क्या परवाह हो सकती है? गम्भीरतापूर्वक बोलना बहुतेरोको आता है। परन्तु उन सबकी बातोंपर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जो कहा हुआ कर दिखाता है — बोले हुए वचनोका पालन करता है — उसके वचन पागलके समान हो तो भी सब सुनते हैं। इसी कारण लाला लाजपतरायके भाषणका साराश हम नीचे दे रहे हैं। इसमे नई बातें नहीं हैं। फिर भी चूंकि वे एक निर्वासित सेवकके विचार हैं इसलिए जानने योग्य हैं।

भाइयो, सरकारका कहना है कि यह (पंजाबकी) जमीन उसने दी है, इसलिए इसपर हमें उसका अधिकार मानना चाहिए। सवाल यह है कि सरकारको जमीन मिली

कहासे? यह जमीन और ऊपरका आकाश दोनों तो शुरूसे ही हैं। इसके स्वामी पहले हिंदू थे। बादमें मुसलमान आकर बस गये। हम हिंदू और मुसलमान उन दोनोंके उत्तराधिकारी हैं। तब सरकार हमें बताये कि वह इस जमीनको कैसे छीन सकती है। यह जमीन खुदाकी है। उसने हमें दी है। उसपर [शासन करनेवाला] बादशाह भले हो, परन्तु वह किसी बादशाहके नौकरकी नहीं है। ऊँची तनरवाह लेनेवाले अधिकारी हमारे राजा नहीं, बल्कि नौकर हैं। वे हमारा नमक खाते हैं।

हम सोते हुए सिंहके समान हैं। नींदमें देखकर कोई हमारी पूछ खीचता है, कोई हमपर थूकता है, किंतु यदि हम अपना रुतबा जानते हो तो हमें कोई नहीं सता सकता। हमारे दुश्मन हिंदू-मुसलमानके बीच बैर करवाना चाहते हैं, सिक्ख और हिंदुओंके बीच दरार डालना चाहते हैं। उनका बड़ेसे बड़ा हथियार है हमारे बीच फिसाद बनाये रखना। प्रत्येक वस्तुमें अपना अपना गुण रहता है। पानी बुझाता है। आग जलाती है। इसी प्रकार विदेशी शासकोंका गुण हममें फूट डालकर हमपर अपनी सत्ता कायम रखना है। हमारा गुण यह होना चाहिए कि हम उनके इस हेतुको असफल कर दे। हमारा कतव्य यह है कि हममें यदि कोई देशद्रोही हो तो उसको समाजसे निकाल दिया जाये। हमें वाइसरायके पास जाना चाहिए। इंग्लैंड जाना भी ठीक होगा। और यदि हम सच्चे हृदयसे मान ले कि अधिकारकी लड़ाईमें हमारे लिए मरना और जीना दोनों एक समान हैं, तो अधिकारी लोग तुरंत कह देंगे, “हा, यह भूमि तो आपकी ही है।”

इस ददका दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। हम सगठित बने और रहे, यही है। यदि सरकार किसीकी जमीन छीनकर जमीनका नया कानून स्वीकार करनेवाले व्यक्तिको देना चाहे, और कानूनको स्वीकार करके जमीन लेनेवाला वह व्यक्ति हममें से ही कोई हो तो उसे हम समाजका दुश्मन तथा दगाबाज समझे। सरकार यदि किसीकी जमीन छीनती है, तो दूसरोंके लिए यह शपथ लेना जरूरी है कि वे उस जमीनको नहीं लेंगे। हम मद बने, औरत नहीं। यदि आप अपनी शपथपर डटे रहेंगे तो आपको अजियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। जब आप अपने शास्त्रों अथवा कुरान शरीफकी शपथ लेंगे और आपसमें एकदूसरेके प्रति वफादार रहेंगे तब इस दुनियामें ऐसा कोई नहीं जो आपका अपमान कर सके।

भारतकी भूमि हिंदूके लिए स्वर्ग है मुसलमानके लिए बहिश्त है। हम करोड़ों मन अनाज पैदा करते हैं। फिर भी भारतकी सात करोड़ सन्तान हमेशा भूखी रहती है।

इस रोगका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करें। हजारों मनुष्य प्लेगसे सदा मरते हैं, किन्तु सच्ची मौत वह मरता है जो औरोंके लिए अपनी जान देता है फिर भले वह जेलमें दे या बाहर दे।

लालाजीने माडलेसे जो पत्र लिखा है वह हम आगामी सप्ताहमें प्रकाशित करेंगे। वह जानने योग्य है। अपने पाठकोसे हमारा अनुरोध है कि वे उपयुक्त लेखको बार बार पढ़ें तथा अपनी दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिपर इसे लागू करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८५ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा

जर्मिस्टनमे विराट सभा

हम पिछल सप्ताहके तारमे बता चुके ह कि रामसुन्दर पण्डित शुक्रवार ८ तारीखको बिना अनुमतिपत्रके ट्रासवालमे रहनेके कारण गिरफ्तार कर लिये गये हैं। वे शुक्रवारको सवेरे स्वयं जर्मिस्टनमे अदालतके सामने खड़े थे। उस समय खुफिया पुलिसके आदमीने उनका नाम पूछा और अनुमतिपत्र मागा। उन्होंने कहा, मेरे पास अनुमतिपत्र नहीं है। इसपर खुफियाने उहे उसी वक्त पकड़ लिया। श्री पोलकको मालूम हुआ तो वे तुरन्त जर्मिस्टन गये। श्री पण्डितसे जेलमे मिले। पूछनेपर श्री पण्डितने उत्तर दिया कि मुझे जमानतपर बिलकुल नहीं छूटना है। मैं जेलमें ही रहूँगा।

जेलमे जेलरने भी जमानतपर छूटनेके लिए उनपर बहुत दबाव डाला। किन्तु उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी कौमके लिए तथा अपने धर्मके लिए जेलमे ही रहूँगा।

जेलमे हालत

जेलमे हालत बहुत अच्छी थी। रहने, नहाने धोने आदिकी सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई थी। पण्डितजीके कथनानुसार, जब वे जेल गये थे तब उन्हें बुखार आता था। अब बिलकुल नहीं है। खाने पीनेकी व्यवस्था समाजकी ओरसे की गई थी और दूध तथा मेवा बराबर पहुँचाया जाता था। इन चीजाँके अलावा और कुछ खाने से उन्होंने इनकार कर दिया।

तारोकी वर्षा

जेलमे उनके पास बधाईके और हिम्मत बँधानेके बहुत-से तार आये। नेटाल भारतीय कांग्रेस, डबन इस्लामिया अजुमन, डबन मेमन समिति, हिंदू धर्म सभा (डबन), पारसी समिति (डबन), व्यास (प्रिटोरिया), सूरत हिन्दू सघ (डबन) के पाससे तार मिले। सभी तारोमे पण्डितजीको धर्म और भारतीय समाजकी लड़ाईके लिए जेल जानेपर मुबारकबादी दी गई।

सोमवारको मुकदमा

मजिस्ट्रेटके सामने सोमवारको मुकदमेकी सुनवाई होगी, इस आशासे बहुत सी जगहोसे नेता लोग आये थे। जोहानिसबर्गसे मौलवी साहब अहमद मुस्त्यार, श्री ईसप मिया, इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी सालेजी, श्री एम० एस० कुवाडिया, श्री जूसब इब्राहीम, श्री अहमद मूसाजी, श्री थम्बी नायडू, श्री पोलक, श्री मुहम्मद खा, श्री गुलाबभाई श्री भट, श्री नारायणजी, श्री नवाबखा, श्री अलीभाई आकुजी वगैरह आये थे। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री पिल्ले, श्री व्यास, श्री मणिभाई आदि थे। क्रूगसडॉपसे श्री वाजा, वेरीनिजिंगसे अस्वात वगैरह थे। पुकार होनेके पहले लगभग १५० भारतीय अदालतके दरवाजेपर हाजिर हो गये थे। बहुत-से लोगोके हाथोमे फूलोके हार वगैरह थे। साढ़े दस बजे श्री गांधीने खबर दी कि मुकदमा

स्थगित हो जायेगा, किंतु सम्भव है, श्री रामसुन्दर पण्डित बिना जमानतके छूट जायेंगे। इसलिए लोग सड़कपर आतुरतापूर्वक पण्डितजीका स्वागत करनेके लिए खड़े थे।

ठीक ग्यारह बजे पण्डितजीको अदालतमें लाया गया। उनके आते ही अदालत भारतीयोसे भर गई। सरकारी वकीलने मोहलत माँगी, जिससे प्रिटोरियासे श्री चैमने आ सके। श्री गांधीने कहा

“मेरे मुवक्किल चार दिनसे जेलमें हैं। वे जमानतपर नहीं छूटना चाहते। वे उपनिवेश छोड़कर जानेवाले नहीं हैं, बल्कि कानूनके अन्तगत सजा भोगेंगे। इसलिए मुकदमा आज ही चल सकता है। प्रिटोरियासे गवाहोंकी आवश्यकता नहीं है। इतनेपर भी यदि मुकदमेको स्थगित करना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मेरे मुवक्किलको बगैर जमानतके उनकी ही जिम्मेदारीपर छोड़ दिये जानेकी आज्ञा दे दी जाये।”

सरकारी वकीलने कहा कि बगैर जमानतके छोड़नेके बारेमें मैं अपनी सम्मति नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मामलेका ज्ञान नहीं है। श्री गांधीने कहा कि श्री पण्डित भागनेवाले नहीं हैं। भागे, यही तो सरकार चाहती है। फिर, ऐसे आदमीके लिए जमानत क्या हो सकती है, जो समाजके लिए ट्रासवालमें रहनेका अधिकार जताता हो और इसलिए सरकारके निकालनेपर भी निकलनेवाला न हो?

मजिस्ट्रेटने यह दलील स्वीकार की और पण्डितजीको उनकी जिम्मेदारीपर छोड़ दिया।

“हुर्रे” की आवाज

पण्डितजीके बाहर निकलते ही हुर्रेकी आवाजके साथ सैकड़ों लोगोंने उनका स्वागत किया। फूलोंकी वर्षा की गई और सबने हाथ मिलाये। बादमें बस्तीमें सभा करनेका निश्चय किया गया, इसलिए सब सनातन धर्म सभाके भवनकी ओर चल दिये।

सभा

सभामें श्री लाल बहादुरसिंह द्वारा प्रस्ताव किया जानेपर श्री मौलवी साहब अहमद मुख्तियार सभापतिके आसनपर विराजमान हुए। मेहमानोंको सभा भवनके अंदर बैठकर जमिस्टनके लोग बाहर खड़े रहे। मौलवी साहबने भाषण देते हुए कहा कि पण्डितजी बधाईके योग्य हैं। उन्होंने सारे भारतीय समाजकी सेवा की है। जेल सच्चा महल है, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया है। समय आनेपर मैं स्वयं भी जेल जानेको तैयार हूँ। मौलवियों और अमगुरुओंका कतव्य है कि ऐसे दुःखके समय वे लोग आगे बढें।

श्री इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि रामसुन्दर पण्डितके उदाहरणसे सबको बहुत हिम्मत बाधनी चाहिए।

श्री ईसप मियाने कहा कि सरकारसे किसीको जरा भी डरना नहीं चाहिए।

श्री गांधीने कहा कि अभी तो लडाईकी शुरुआत है। इसमें सबसे बड़ी जीत यह है कि हिन्दू-मुसलमान एक होकर सारे समाजके कामके लिए लड़ रहे हैं।

श्री अहमद मूसाजीने पण्डितजीकी तारीफ करते हुए कहा कि वे भी जान रहते पंजीयन नहीं करवायेंगे।

श्री मणिभाईने प्रिटोरिया हिंदू धर्म सभाकी ओरसे आभार माना।

श्री थम्बी नायडूने कहा, पण्डितजी जेल जायेंगे तभी खरा रंग जमेगा। उनके समान सबको करना है।

श्री कुवाडियाने कहा, हमे कोई डर नहीं है। सरकार पण्डितजीको कुछ करेगी, यह नहीं दिखाई देता।

श्री मुहम्मद खाने कहा, मैं स्वयं स्वयंसेवक हूँ, इसलिए जिन्होंने स्वयंसेवकका काम किया है उनपर मुझे गव है।

श्री उमरजीने निम्न लिखित गुजराती दोहा कहा

“हे मा, तू तीन प्रकारके लोगोको ही जन्म देना — दाताको, भक्तको या शूरको।
नहीं तो, तू बन्ध्या ही रहना। व्यथ ही अपना तेज क्यों खोती है?”^१

इस सूक्तके अनुसार, पण्डितजीकी माने शूर पण्डितजीको जन्म दिया है।

श्री अस्वातने कहा श्री पण्डितके उदाहरणसे सबको समझना चाहिए कि पजीयन कार्यालय एक जालके समान है। उसमे किसीको फँसना नहीं चाहिए।

श्री काल्लियाने पण्डितजीका आभार माना और कहा कि प्रिटोरियामे जितने लोग बचे हैं, वे कभी पजीकृत नहीं होंगे।

श्री अलीभाईने कहा कि अगर प्रिटोरियामे कानमिया स्वयंसेवक तयार नहीं होंगे तो वे स्वयं वहा खास तौरसे जायेगे।

श्री व्यासने बताया कि पण्डितजीकी हिम्मत खरी उतरी है। उन्होंने प्रिटोरियामे रहना स्वीकार किया था।

श्री लाल बहादुर सिंहने सब सज्जनोका आभार माना। श्री पोलकने कामना व्यक्त की कि अब पण्डितजीके बाद मौलवी साहबकी बारी आये।

इसके बाद मौलवी साहबने थोड़ी देर और भाषण देकर सभा समाप्त की।

अन्तमे सबको केले, सतरेका नाश्ता और चाय लेमोनेड वगैरह दिया गया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

बहादुर दर्जी और गोरा व्यापारी

यहाके दर्जियोकी मुसीबतका विवरण इस पत्रमे कुछ तो छप चुका है। किन्तु यह किस्सा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं और भी अधिक विवरण दे रहा हूँ। श्री टी० आलब्रेटने दर्जियोको निम्नानुसार पत्र लिखा है

उपनिवेश सचिवके पिछले भाषणसे मालूम होता है कि ट्रान्सवाल सरकारने भारतीयोके लिए अभी-अभी जो कानून बनाया है उसके सामने यदि भारतीय नहीं झुकेगे तो ट्रान्सवालकी सरकार परवाना नहीं देगी, कानूनके अनुसार उन्हें गिरफ्तार करेगी और जेल भेजेगी। और आप लोगोने कानूनके सामने न झुकनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिए मौजूदा प्रसंगसे बचनेके लिए हमे आपकी मददकी आवश्यकता है। अतः हमे खेदपूर्वक कहना चाहिए कि आपको हमारी दूकानसे जिस मालकी भी जरूरत पड़े वह आप नकद कीमत देकर ले तथा चालू खातेकी रकम दिसम्बरके पहले चुका दे।

१ ‘जननी जणजे ज्ञान जन, दाता भक्त का शूर। नहिं तर रहेजे बांझणी, रखे गुमावे नूर।’

इससे यह न समझो कि इसमें हमारा उद्देश्य कुछ ओर है। ईश्वर करे कि आपकी अव्यवस्थित स्थितिका परिणाम विजयपूर्ण निकले और समाधान हो जाये। उस हालतमें, हम चाहते हैं, हमारा जैसा व्यवहार चल रहा था वही फिरसे शुरू हो जाये।

आपने हमें व्यापार तथा लेनेदेनेमें जो सन्तोष दिया है उसके लिए हम आभारी हैं।

यह पत्र विनयपूर्ण है। इसमें अपमानका भाव नहीं है। फिर भी इसका अर्थ यही है कि यदि दर्जी पजीयन न करवाये तो उन्हें माल उधार नहीं मिलेगा। इससे दर्जी चिढ़ गये हैं। वे डरपोक होते तो डरके मारे पजीयन करवानेका विचार करते, किन्तु बहादुर हैं, इसलिए उन्होंने आलब्रेटके मालके सारे नमूने उसके यहाँ फेंक दिये और २१ व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे निम्नानुसार पत्र लिखा

निवेदन है कि आपका गुजरातीमें लिखा हुआ नोटिस हमें मिला। हम अत्यन्त खेदपूर्वक सूचित करते हैं कि आज, अर्थात् तारीख ७ नवम्बर १९०७, से हममें से कोई आपसे किसी भी प्रकारका लेनेदेन नहीं करना चाहता। हम आपसे एक पेनीका भी माल नहीं खरीदेंगे। कारण यह है कि हमने पजीयन न करवानेकी शपथ ली है। हम उसे, कितनी ही हानि क्यों न हो, कभी तोड़ना नहीं चाहते। आपका जो भी पैसा निकलता है, वह हम सुविधा होते ही चुका देंगे।

इससे आलब्रेट घबड़ाये। बहिष्कार मजबूतीसे जमा। उनकी दूकानपर यह देखनेके लिए एक धरनेदार बैठाया गया कि यदि उनकी दूकानसे कोई आदमी कपड़ा लेकर सीनेके लिए दे तो वे वह काम लेनेसे भी इनकार कर दें। इसपर श्री आलब्रेटने बहुत अनुनय विनय की और निम्नानुसार माफी मागी

हमने अंग्रेजी तथा गुजरातीमें अपने ग्राहकोंके नाम जो नोटिस भेजा था उसका उन्होंने यह अर्थ किया है कि हमने उन्हें पजीयन करानेको और, यदि पजीकृत न हो तो, केवल नकद व्यवहार करनेको कहा है। इस प्रकारका अर्थ करके वे चिढ़ गये हैं और हमारा बहिष्कार कर रहे हैं।

हमें शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनकी भावनाको चोट पहुँचानेका हमारा स्वप्नमें भी इरादा नहीं था। हम समझ सकते हैं कि कानूनके सामने झुकनेके लिए उनपर जरा भी दबाव डाला जाये तो उन्हें गुस्सा आ जायेगा। ब्रिटिश राज्यमें सबको अपनी मर्जीके अनुसार चलनेका अधिकार है। इसलिए हम अपना पत्र और अपनी माग बिना शर्त वापस लेते हैं, और आशा करते हैं कि भारतीय समाजकी जीत होगी और उसे न्याय प्राप्त होगा। हमारी भावना सच्ची है, यह दिखानेके लिए, और हम अपने ग्राहकोंको चाहते हैं, यह साबित करनेके लिए हम लडाईमें सहायता २५ पौडका चेक भेज रहे हैं।

हमें आशा है कि बहिष्कार बंद हो जायेगा। किन्तु वह तो केवल दर्जियोंकी मर्जीपर निर्भर है। बहिष्कारके समाप्त होनेपर हम पहलेके समान व्यापार करके खुश होंगे और उन्हें खुश करनेका प्रयत्न करेंगे। किन्तु हमारे पत्रका इस बातसे सम्बन्ध नहीं है। हमने जो भूल की है उसे सुधारनेके लिए, और हमारा इरादा किसीको चोट पहुँचानेका नहीं था इसलिए यह पत्र लिखा है। हमारा जो पावना है वह हमें आशा है, समयानुसार चुकाया जायेगा।

मेरी जानकारीमें ऐसा क्षमा-याचना पत्र कभी गोराकी ओरसे नहीं लिखा गया। मैं मानता हूँ कि यह विवेकपूर्ण ओर सन्तोषजनक है। यह उदाहरण दर्जियोंको मान प्रदान करनेवाला है, ओर सबके शिक्षा लेने योग्य है। गोरासे हम नहीं डरेगे ता वे माल देना बन्द कर देगे, सो बात नहीं। बद कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पैसे नहीं चाहिए? मैंने यह भी सुना है कि इस पेढीने पिछले पाच वर्षोंमें भारतीयोंके साथ ६०,००० पौडका व्यापार किया है, और उसमें से आजतक केवल २३ पौड ही खोये हैं। भारतीयोंमें प्रामाणिकता होगी तो माल घर बठे मिलगा।

मूसा इस्माइल मियाँ

श्री मूसा इस्माइल मिया हज करने गये हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उनके बड़े भाई श्री ईसप मिया समाजकी सेवा करनेका धम काय कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों भाइ इहलोक और परलोककी साधना कर रह हैं। वे सदा धमनिष्ठ रहे ओर कौमकी सेवा करते रहे। लाखों कमानेसे यह कमाई अधिक बड़ी है।

और दुगा ?

सुना है कि श्री खमीसाकी दूकानमें गुप्त तरीकेसे पजीयन पत्र दिये जाते हैं। ऐसे पजीयनपत्र नौ दिये जा चुके हैं। अर्जी नहीं ली जाती, परन्तु जिसने अर्जी दी हो उसे पजीयनपत्र दिया जाता है।

कानूने जान ली

एक चीनीने पजीयनपत्र लेनेके बाद शमके मारे आत्महत्या कर ली है। इससे त्रास फैल गया है। चीनी सघके प्रमुख श्री क्विनने अखबारोंमें निम्नानुसार पत्र लिखा है

एक चीनी द्वारा आत्महत्या की जानेकी खबर अखबारमें छपी है। उसे पढनेके पहले मेरे एक आदमीने मुझे एक पत्र दिया, जो चीनी भाषामें लिखा हुआ था तथा उसपर मरनेवालेके हस्ताक्षर थे। पत्रका अनुवाद इस प्रकार है

चाऊ क्वाईकी ओरसे चीनी सघके अध्यक्षको, १० नवम्बर १९०७

मैं इस दुनियाको छोडनेवाला हूँ। इसलिए मैंने आत्महत्या क्यों की, यह लोगोकी जानकारीके लिए प्रकट कर देना चाहिए। जबसे मैं दक्षिण आफ्रिका आया, घरेलू नौकरका काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने सेठके घर रहता हूँ। मेरी बोली दूसरे चीनियोंकी बोलीसे बिल्कुल भिन्न है। और मेरे देशबन्धुओंके साथ मेरा बहुत ही कम व्यवहार है। मेरे सेठने पजीयन करा लेनेकी सलाह दी थी। पहले मैंने पजीयन करानेसे इनकार किया। तब मेरे सेठने मुझे नौकरीसे बरखास्त करनेकी धमकी दी। नौकरी छूटनेका डर लगा इसलिए मुझे लाचारीसे पजीयन कराना पडा। किन्तु तबतक मुझे पजीयन करानेसे होनेवाली बर्बादीकी जानकारी नहीं थी। बादमें मेरे एक दोस्तने आकर मुझे सारी बातें समझाई और कानूनका चीनी अनुवाद मुझे पढाया। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी तो गुलामो जसी हालत हो जायेगी। गुलामी भोगना मेरे और मेरे देशबन्धुओंके लिए कलकरूप है। ये सारी बातें पजीयन करानेके पहले मुझे मालूम नहीं थी। किन्तु अब पछतावा करूँ तो बेकार है। मैं अपने देशभाइयोंको कौन सा मुह दिखाऊँ? मुझे आशा है कि मेरी भूलसे मेरे दूसरे देशभाई चेतने।

इसके बाद श्री क्विन इसपर निम्नानुसार टीका करते ह

इस पत्रको पढनेके बाद मुझे कितनी पीडा हुई होगी, उसकी आप कल्पना कर सकेंगे। तुरत ही मने अखबार पढा, तो मालूम हुआ था कि चाऊ क्वाईने जैसा कहा था वसा कर डाला। उसकी लाशके लिए मेरे सघने तुरत ही अर्जी दी और अभी मैं उसकी दफन क्रिया करमे आ रहा हूँ। उस क्रियाके समय लगभग ७० चीनी सदस्य उपस्थित थे।

मेरे समाजके इस आदमीको धमकी दी गई थी, इस आरोपको मैं बिलकुल गलत कहता हूँ और उसे बिलकुल महत्त्व नहीं दता। इस खेदजनक घटनाका अर्थ क्या हुआ? उसे खुले आम कहनेमे मुझे जरा भी सकोच नहीं है। ऐसे अवसरपर मेरा खून गरम हुए बिना नहीं रहता। इसलिए मैं सोच समझकर यह आरोप लगाता हूँ कि ट्रान्सवाल सरकारने निरपराध मनुष्यका खून करनेके समान काम किया हे, और इसका कारण केवल यही हे कि वह एशियाई था। एशियाई कानून पास हुआ तबसे हम बड़ी उलझनमे पड गये थे। और अब तो एशियाई कानूनने एक आदमीकी जान ले ली हे। जिस कानूनसे इतनी दुखदायी घटना हो सकती हे, क्या उसे ट्रांसवालके गोरे न्यायपूर्वक चला सकेंगे? अथवा, क्या ट्रांसवालके लोग अब भी कहेंगे कि एशियाई कानून कामका हे ट्रांसवालके गोरोकी रक्षाके लिए आवश्यक हे, और यदि एशियाई ऐसा मान लेते ह कि एशियाई कानूनसे उनका अपमान होता हे तो इससे हमारा क्या बिगडा? या, अब लोग ऐसा नहीं कहेंगे? पश्चिमके लोगोको हम सभ्य मानते हैं, अत वे ऐसा समझेंगे यह हम कैसे मान सकते हैं?

शाहजी साहब

शाहजी साहबका मुकदमा बुधवारको अदालतमे आया था। सैकडो भारतीय उपस्थित थे। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनने मुकदमा वापस लेनेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु वैसा हो नहीं सका। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उनका विचार फरियाद करनेका नहीं हे। धमका खण्डन करनेके कारण शाहजी साहबने मारा, किंतु वह उस मारको अपने बापकी मारके समान समझता है। अदालतने शाहजी साहबको चेतावनी देकर छोड दिया।

व्यास और दूसरे धरनेदार पकडे गये

श्री गोरीशकर व्यास, श्री लछमन तथा श्री शरफुद्दीन धरना देते हुए पकडे गये ह। उन सबको बिना जमानतके छोड दिया गया है। उन्होंने जमानत देकर छूटनेसे इनकार किया। मुकदमा १५ तारीखको होगा। प्रिटोरियामे शोरगुल मचा हुआ हे। सब जोशमे हैं। उनके लिए बधाईके तार गये हैं।

गोरोमे खलबली

गोरोमे अब खलबली मची हुई हे। कुछ गोरे सरकारके पास शिष्टमण्डल ले जाना चाहते हैं। विशेष खबर बादमे देनेकी आशा है।

कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि

श्री ईसप मियाकी अध्यक्षतामे बुधवारको ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठक हुई थी। बहुत से सदस्य उपस्थित थे। श्री फैसी, श्री कुवाडिया, श्री काछलिया, श्री अहमद मूसाजी, श्री मौलवी

साहब अहमद मुख्त्यार, इमाम अब्दुल कादिर ओर श्री गांधी आदिने भाषण दिये । बादमे श्री उमर हाजी आमद झवेरी, अमीरुद्दीन मुहम्मद हुसेन फजदार श्री हाजी इब्राहीम अहमद दीनदार, श्री अहमद सालेजी कुवाडिया, श्री सुलेमान मुदजी कासिम तथा श्री पीरन मुहम्मदको सूरत काग्रेसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया । उसी समय काग्रेसके चंदेकी वसूली शुरू की गई । श्री अमीरुद्दीनने भाषण देते हुए खूब प्रयत्न करनेका कहा ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८७ डबनमे दीवाली-महोत्सव

ग्रे स्ट्रीटमे श्री अब्दुल लतीफके मकानमे दीवालीका त्यौहार मनानेके लिए हिन्दुओका एक सम्मेलन हुआ । मकान अच्छी तरह राशनीसे सजाया गया था और वादक इत्यादि भी बुलाये गये थे । मुहूर्तके अनुसार सरस्वती-पूजन होनेके बाद केशवलाल महाराजने दीवाली-महात्म्य पढ़कर सुनाया । श्री अम्बालालजीने आशीर्वादनके श्लोक सुनाये । उसके बाद सम्मेलनकी समितिका एक शिष्टमण्डल श्री गांधीको लेनेके लिए स्टेशन गया । लगभग साढ़े सात बजे श्री गांधी आये । उनके साथ सेठ अब्दुल करीम रस्तमजी सेठ सेठ दाउद उस्मान इत्यादि भी पधारे थे । श्री अम्बारामने देश-सेवापर प्रभावशाली भाषण दिया । श्री गांधीने ट्रान्सवालके भारतीयोकी स्थिति बताते हुए कहा कि आज तो ट्रान्सवालमे भारतीयोकी होली है, ओर जब वे सघषमे जीतेगे तभी उनकी वास्तविक दीवाली कहलायेगी । श्री गांधीने ट्रान्सवालमे भारतीयोकी स्थितिका विस्तारसे चित्रण किया और उससे सभी श्रोताओमे गम्भीर भावना जाग्रत हुई । बादमे सेठ अब्दुल करीम श्री पारसी रस्तमजी आदिने भी भाषण दिये । उसके बाद ट्रान्सवालकी मददके लिए थाली घुमाई गई, जिसमे पाच पौडसे ऊपर रकम आई । तदुपरांत प्रसाद इत्यादि बांटा गया और फिर सगीतके बाद सभा विसर्जित हुई ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८८ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे

[जोहानिसबग
नवम्बर १७, १९०७]

इसके बाद श्री गांधीने डबनसे प्राप्त श्री हाजी हबीबका उत्साह देनेवाला पत्र पढ़ा। बादमे उन्होंने जेलके बारेमे, अखबार बेचनेवालोंकी हड़तालके बारेमे तथा प्रिटोरियाके धरनेदारोंके मुकदमेवाले लखमनके सम्बन्धमे हकीकत बताई। आगे उन्होंने कहा कि श्री हास्केन, जो प्रिटोरियाकी सभामे हमे समझानेके लिए आये थे, आज सरकारको समझानेकी तजवीज कर रहे हैं। नेटालक सेठ पीरन मुहम्मद इस जहाजसे भारत नहीं जा सके। श्री रिच विलायतमे बहुत श्रम कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिगत खर्चके लिए अनुमति देनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके लिए श्री फसी चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रत्येक सज्जनको चाहिए कि उन्हें यथा शक्ति चढ़ा दे। पण्डितजीके मुकदमेके बारेमे श्री स्मट्स फिरसे जांच कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कितनी डर गई है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२८९ पत्र भारतके वाइसरायको

डबन
नवम्बर १८, १९०७

सेवामे

परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय, [भारत

श्रीमान् लाड महादय,]

हम आपकी अनुमतिसे इसके साथ उन प्रस्तावों और तारकी प्रतिया भेज रहे हैं, जो रामसुन्दर पण्डित नामक एक हिन्दू पुरोहितके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कांग्रेस भवन, पाइन स्ट्रीट, डबनमे आयोजित आमसभामे सवसम्मतिसे पास और स्वीकृत किये गये हैं। रामसुन्दर पण्डितको ट्रान्सवालके जर्मिस्टन नगरमे नये एशियाई अध्यादेशके अंतगत एक मासकी सादी कैदकी सजा दी गई है।

इस अभियोगका याय-विरोधी रूप लॉर्ड महोदयके सम्मुख प्रत्यक्ष है और लाड महोदयकी व्यक्तिगत सहानुभूतिका विश्वास रखते हुए हम सादर निवेदन करते हैं कि भारत सरकार

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंको, जो तिरस्कृत और अपमानित किये जा रहे हैं, अपना सरक्षण और समर्थन दे। हमें विश्वास है कि हमारे निवेदनपर ध्यान दिया जायेगा।

आपके, आदि,

दादा उस्मान

एम० आगलिया

सयुक्त अवैतनिक मन्त्री,
नेटाल भारतीय कांग्रेस^१

[सलग्न पत्र]

गुरुवार, १४ नवम्बर, १९०७ के साथ नेटाल भारतीय कांग्रेसके तत्त्वावधानमें आयोजित भारतीयोंकी सावजनिक-सभामें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

नीचेके तारकी प्रति भी पास और स्वीकृत की गई। सभामें तय किया गया कि इसकी प्रतियाँ महामहिम सम्राट्के उपनिवेश मन्त्री और ट्रान्सवालके माननीय उपनिवेश सचिवको भेजी जाये।

प्रस्ताव सं० १ — वफादार ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति ट्रान्सवालका विधान मण्डल जो अयाय और कठोरता बरत रहा है उसको सुनकर नेटालकी भारतीय आबादीके प्रतिनिधि भारतीयोंकी इस सभाको गहरा दुःख हुआ है।

प्रस्ताव सं० २ — यह सद्यः निश्चय करता है कि रामसुन्दर पण्डित और उनके परिवारको सहानुभूतिके पत्र तथा तार भेजे जाये और अपने समाजकी आध्यात्मिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके निमित्त अपने लिए पुरोहितके अधिकार प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उन्होंने जो रुख अख्तियार किया है उसपर उनको बधाई दी जाये। आगे यह निश्चय किया जाता है कि नेटाल भरमें एक दिन कारोबार बन्द रखा जाये और इसको कायरूप देनेके लिए शनिवार, १६ तारीखको सब भारतीय दुकानें और व्यावसायिक स्थान बन्द रखे जाये, ताकि ट्रान्सवालमें भारतीयोंके ऊपर जो नियोग्यताएँ लगी हैं वे अधिक व्यावहारिक रूपमें दज हो सकें। यह सभा हिंदू समाजके साथ, उसके एक आध्यात्मिक नेता और मागदशकसे वचित कर दिये जानेपर, हादिक सहानुभूति प्रकट करती है और यह सोचकर दुःख अनुभव करती है कि कोई सरकार हिंदुओंको वार्षिक माग दशकसे वचित करके उनके धार्मिक कृत्यों और सस्कारोंके उचित सम्पादनमें परोक्ष रूपसे हस्तक्षेप करनेका अविवेक दिखाये। इन प्रस्तावोंकी प्रतिया उपनिवेश मन्त्री, ट्रान्सवाल-सरकार तथा ब्रिटेन और भारतके समाचारपत्रोंको भेजी जाये।

तार नेटालके भारतीय रामसुन्दर पण्डितकी गिरफ्तारी और सजाका सादर विरोध करते हैं। यह एक ब्रिटिश उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी निजी स्वतन्त्रता और उनके धर्ममें अनुचित हस्तक्षेप है। ब्रिटिश सरकारसे साम्राज्य हितके लिए हस्तक्षेपकी प्राथना है।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफिस रेकड्स जे० एंड पी०, ५९८/०८

२९० ट्रान्सवालके भारतीयोंको सूचना

जोहानिसबग

वाक्स ६५२२

नवम्बर १९, १९०७

सघके आकडोसे^१ सभी भारतीयोंने देखा होगा कि सघके पास इस समय बहुत कम पैसा है और सघष जबरदस्त है। यद्यपि बहुत-सा काम बिना दामके हो जाता है, फिर भी कुछ तो खच होना ही है, और होता है। तार दिये जाते हैं, सैकडो पत्र लिखे जाते हैं, बहुत सा टकनका काम होता है कुछ छपाई होती है और अखबारोमे खच होता है। ये सारे खच छोटे ह, फिर भी विचार करे तो कुल मिलाकर काफी खच हो जाता है।

बहुत से शहरोमे थोडा बहुत चंदा हुआ है, किंतु वह रकम सघको नहीं भेजी गई। जिनके पास रकम इकट्ठी हुई हो, उन्हें तथा दूसरे भारतीयोंको भी चाहिए कि जैसे बने वैसे, जल्दी ही रकम सघको भेज दे। यह हमारी प्रार्थना है। हरएकको बदस्तूर पहुँच भेजी जायेगी। हम आशा करते हैं कि इस विषयमे कोई ढील नहीं होगी। यदि पैसा व्यक्तिश भी भेजा गया, तो स्वीकार किया जायेगा। इतना ही।

ईसप मियाँ, अध्यक्ष

कुवाडिया, खजाची

मो० क० गाधी, मन्त्री

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९१ पत्र मणिलाल गाधीको

जोहानिसबग

नवम्बर २१, १९०७

प्रिय मणिलाल,

मेरा खयाल है, मने तुम्हे पहले कभी अग्रेजीमे नहीं लिखा। आज मुझे लाचारीसे गुजरातीके बजाय अग्रेजीमे लिखना पडता है। मैं आज 'रामायण' और सशोधित^२ 'गीता' भेज रहा हूँ। 'रामायण' की जिल्द ठीकसे बँधवा लो। ध्यान रखो कि वह फिर खराब न हो। किताबो और दूसरी चीजोंको^३, जो तुम्हारे पास हो, तुम्हे सावधानीसे काममे लाना सीखना चाहिए। अगली बार वहा जानेपर तुम्हारी परीक्षा लेकर सतोष प्राप्त करनेकी आशा रखता हूँ। तुम्हे जेलवाले भजन^४ जबानी याद होने चाहिए। मगनलालको चाहिए कि वे एक भजन

१ देखिए परिशिष्ट ७।

२ छन्दबद्ध ?

३ मूल अग्रेजीमें जो शब्द आया है उसका अर्थ होगा 'आसान चीज' या 'आसान बात'।

४ यह गुजरातीमें "जेलना काव्यो" शीर्षकसे छपा था।

मण्डली तैयार करे। ऐसे काममे यदा कदा थोडा समय लगा देनेमे कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। तुम उन्हें यह सुझाव दे सकते हो। यह पत्र उन्हें पढकर सुना दो। 'रामायण' का क्या उपयोग करनेका विचार है, सो लिखना। उसका अर्थ कौन बतायेगा, या तुम्हारा विचार^१ छ-दोको बिना समझे पढनेका है?

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मोहनदास

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८२) से
सौजन्य सुरशीलाबहन गांधी।

२९२ पत्र गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबग
नवम्बर २२, १९०७

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

मैंने आपके नाम श्री अमीरुद्दीन फजदारके हाथ एक पत्र^१ भेजा है। श्री फजदार ट्रान्सवालके एक प्रतिनिधिके रूपमे सूरत कांग्रेसमे भाग लेगे। क्या मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि हम यहा जिम सघपसे होकर गुजर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप हमने यह अनुभव किया है कि हम भारतीय पहले हैं और हिंदू, मुसलमान, तमिल पारसी आदि पीछे। आप यह भी देखेंगे कि हमारे सब प्रतिनिधि मुसलमान हैं। मुझे स्वयं इस बातसे प्रसन्नता है। और यह भी हो सकता है कि वहा कांग्रेसमे भाग लेनेवाले ऐसे बहुत से मुसलमान हो जायेंगे जिनके सम्बन्ध दक्षिण आफ्रिकासे रहे हैं। क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूँ कि आप उनके सम्बन्धमे दिलचस्पी ले और उनको पूरा आराम दे? हो सकता है, हिन्दू मुस्लिम एकता इस कांग्रेसकी एक विशेषताके रूपमे सामने आये। सघषके शेष समाचार आप समाचारपत्रोंसे जानते ही हैं।

आपका हृदयसे
मो० क० गांधी

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०९) से।

१ मूल अंग्रेजीमें यहाँ जो शब्द आये हैं उनका अर्थ होगा 'तुम्हारा उद्देश्य'।

२ देखिए "पत्र गो० कृ० गोखलेको" पृष्ठ ३५७।

२९३ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबर्ग

नवम्बर २३ १९०७ के पूव]

[सम्पादक

'ट्रान्सवाल लीडर'

जोहानिसबर्ग

महोदय,]

मुझे अपने साथी पुरोहित रामसुन्दर पण्डितके मुकदमेमे उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक खयाल मेरे दिमागमे जोरसे आया कि ट्रान्सवालके कानूनोमे जरूर ही कोई बुनियादी खराबी है। जैसा कि अब हर कोई जानता है, मैंने इमाम कमालीकी उस कार-वाईसे, जिसे मैंने कुरानकी हिदायतके खिलाफ समझा, गुस्सा होकर उसको पीटा था। मुझे इसपर ५ पौंड जुर्मानेकी या कदकी सजा दी गई। एक बेरहम दोस्तने, जो अपनी शराफतकी वजहसे अपनेको मेरा शागिद बताता है, जुर्माना दे दिया और मैं जेलसे बच गया। मैंने फिर मुहम्मद शहाबुद्दीनको पीटा, जिसने अपने बयानमे मजूर किया कि उसने अपनी कुरानकी कसम तोड़ी है और यह कहा कि उसको पीटनेमे मेरा खयाल वैसा ही था जैसा बापका बेटेके लिए होता है। इसलिए मुझे मेहरबान अदालतने यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि मुझे किसी भी वक्त सजाके लिए बुलाया जा सकता है।

रामसुन्दर पण्डितने, जहातक मैं जानता हूँ, और मैं उनके बारेमे कुछ जानता हूँ, कभी किसीको नहीं पीटा, फिर भी उनको एक महीनेकी कैदकी सजा दे दी गई, क्योंकि उनके पास — एक ब्रिटिश प्रजाके पास — कागजका वह टुकड़ा न था जिसमे उनको एक ब्रिटिश उपनिवेशमे अपने देशभाइयोकी धार्मिक आवश्यकताएँ पूरी करनेका अधिकार दिया गया होता।

मने हमेशा जैसा समझा है उसके मुताबिक यदि कोई आदमी जेलके लायक था तो वह मैं था, और फिर भी किसीके लिए यह सम्भव हो सका कि वह मेरे लिए उस चीजको खरीद ले जो उसकी नजरोमे मेरी आजादी थी, जब कि रामसुन्दर पण्डितको लाजिमी तौरपर एक महीनेके लिए उन लोगोके ससगसे, जिनसे उहे हर रोज मिलनेकी आदत थी, लगभग बिलकुल अलग कर दिया गया और उनके धार्मिक कामसे उनका सम्बन्ध तोड़ दिया गया। इस खयालसे मैं बिलकुल काँप उठता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं जेलमे हूँ और रामसुन्दर पण्डित आजाद है। खुदा उनको चैन और हिम्मत दे।

[आपका, आदि,
मुहम्मद शाह]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९४ पण्डितजीकी देश-सेवा

यही माना जायेगा कि रामसुंदर पण्डितने जेल जाकर जो सेवा की है वैसी सेवा जेलके बाहर रहनेवाले भारतीयोंने, फिर वे कितने ही बड़े क्यों न हों, नहीं की। पण्डितजीने हमारी स्वतंत्रताका दरवाजा खोल दिया है। उस रास्तेसे हम सब प्रवेश कर सकते हैं। कांग्रेसके अध्यक्षका कहना है कि पण्डितजीने जेल जाकर उसे पवित्र कर दिया है। यह बिलकुल ठीक है। जितने निरपराध लोग जेलमें जाते हैं उमें उतना ही पवित्र करते हैं।

पण्डितजी और उनके कुटुम्बको हम भाग्यशाली समझते हैं। उनका नाम आज सारे दक्षिण आफ्रिकामें गाया जा रहा है और भारतमें भी गाया जायेगा। यह सच्ची सेवाकी तासीर है। पण्डितजीने निडर होकर अपने जीवनका मुख देश-सेवापर 'योछावर' किया है। इसे हम सच्ची सेवा मानते हैं।

अब समाज क्या करेगा? इस प्रश्नका उत्तर एक ही है। पण्डितजीको जेल भेजनेके बाद जो भी व्यक्ति खूनी कानूनके सामने झुकेगा उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। हमने जो युद्ध छोड़ा है वह खेल नहीं है। यह कोई दाल भातका कौर नहीं है। जो विजय प्राप्त करनी है वह मामूली नहीं है। विजयके हिसाबसे हमें कष्ट भी उठाना होगा। सरकारको जबतक विश्वास नहीं हो जाता कि हम दृढ़ हैं, बाहरी दिखावा नहीं कर रहे हैं, तबतक और उतने लोगोंको जेल भोगना पड़ेगा।

निवासित करनेकी जो बात सरकार कर रही थी वह झूठ है, यह इस मामलेसे प्रकट हो गया है। डरे हुए भारतीयोंको यह बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिए।

पण्डितजीके मामलेसे सबसे बड़ा लाभ हमें यह दिखाई देता है कि हिंदू मुसलमान दोनों कौमोके बीच दृढ़ एकता हो गई है। हर व्यक्ति समझ गया है कि यह काम हम सारे भारतीयोंके लिए है। इस लड़ाईका और इस मामलेका यदि इतना ही फायदा माना जाये तो हम उसे काफी समझते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९५ धरनेदारोका मुकदमा

प्रिटोरियामें गिरफ्तार किये गये स्वयंसेवकोंके मुकदमेमें हमें अनपेक्षित विजय मिली है। उन्हें गवाही भी न देनी पड़ेगी, ऐसी आशा किसीको नहीं थी। इसके अलावा उस मुकदमेमें सरकारी गवाहने ही स्वीकार किया कि लछमनपर किसीने हाथ नहीं उठाया था। इस मुकदमेसे सिद्ध होता है कि सरकारका बल बिलकुल क्षीण हो गया है। इसीलिए वह हाथ पाव मार रही है। अब उसीके अखबार उसपर हँस रहे हैं।

धरनेदारोंने जो हिम्मत दिखाई है, आशा है वसी ही हिम्मत दूसरे भी दिखायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९६ कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि

ट्रांसवाल ब्रिटिश भारतीय सघने [भारतीय राष्ट्रीय] कांग्रेसमें प्रतिनिधि भेजनेका जो निणय किया है, वह उचित है। यहाके पाच प्रसिद्ध व्यापारी कांग्रेसमें जाकर पुकार करेगे, उसका अच्छा प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता। इसके अलावा वह पुकार होगी भी ठीक समयपर — यानी जब ट्रांसवालमें बहुत-से भारतीय जेलका मजा लूट रहे होंगे तब।

प्रतिनिधियोंपर जबरदस्त जिम्मेदारी है। उन्हें सारे भारतमें आवाज उठानी चाहिए। श्री अमीरुद्दीनपर, जो यहासे सब कुछ देखकर जा रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो जानेके बाद भी उन्हें बहुत काम करना है।

अगले अकमें हम श्री अमीरुद्दीनका फोटो देनेका विचार कर रहे हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९७ केपके भारतीय कब जागेगे ?

हम बार बार कह चुके हैं कि केपके भारतीयोंका जागना बहुत जरूरी है। केपमें भारतीय परवानेको रोकनेके लिए कितनी तजवीज की जा रही है, उसका विवरण हमने पिछले अकमें दिया था। उसके आवारपर हम केपके भारतीयोंसे एक बार फिर पूछते हैं कि आप कब तक सोते रहेंगे ? अभी कुछ ही समय पहले हमें कहना पड़ा था कि केपमें प्रवासी कानूनका जुल्म भारतीयोंकी लापरवाहीके कारण हो रहा है। उसके बाद वहा कुछ हलचल दिखाई पड़ी थी, लेकिन जान पड़ता है, वह फिर बद हो गई है। आव्रजनकी बीमारीका इलाज अभी हुआ ही नहीं था कि परवानेकी बीमारी घूर घूरकर देखने लगी है। हमें कहना पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालयमें जानेका हक छिन गया, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत-कुछ भारतीयोंपर है। उसके बारेमें नेटालकी हालत देखकर केपवालोंको सरत लड़ाई लड़नी चाहिए थी। किंतु वह नहीं हुआ, यह अफसोसकी बात है। कानून जब ससदमें था तब उन्हें नींद घेरे रही। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके मनमें यह बात बैठ जानी चाहिए कि इस देशमें आकर नीदमें पड़े रहनेसे काम नहीं चलेगा। हम हथियारबंद फौजके बीच पड़े हुए हैं। सभी लोग हमारे विरुद्ध हैं। हम आलस्यमें पड़े रहेंगे और अपने समाजको नहीं संभालेंगे तो भविष्यमें हमारा और हमारे समाजका बुरा हाल हो सकता है। इसलिए हम केपके भाइयोंसे एक बार फिर कहते हैं कि वे आजसे इस सम्बन्धमें सावधान हो जायें, नहीं तो जो दुश्मन हर रोज आपको सताया करते हैं तथा जो जड़मूलसे उखाड़नेपर तुले हैं वे आपको भी, जैसा ट्रांसवालमें आज हो रहा है, उस हालतमें न पहुँचा दे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा

एक प्रश्न उठाया गया है कि यह मुकदमा नये कानूनके अतगत चलाया गया था या पुरानेके अतगत। किन्तु इसका हल आसानीसे हो सकता है। उनके सम्मन्धमें ही नये कानूनकी १७ वी उपधाराका उल्लेख था, और यदि वह उपधारा लागू नहीं होती तो पण्डितजी का बचाव अ य तरीकेसे किया जा सकता था। इसके अलावा, इस “चिट्ठी” के पाठक जानते हैं कि पण्डितजीने अपने पत्रमें बताया था कि नये कानूनके अतगत वे मीयादी अनुमतिपत्र भी नहीं ले सकते। अतः मेरी रायमें यह मुकदमा नये कानूनके अतगत ही नहीं है। यही नहीं, यह हमें बहुत दृढ़ करनेवाला भी है। क्योंकि इसमें कानूनकी बहुत सी दलीलोका समावेश हो गया है, इसमें धमपर हमला हुआ है। इसके अलावा, यह भी जाहिर हो गया है कि अनुमतिपत्रकी अवधि न बढ़ानेका कारण कितनी बेहदगीसे भरा हुआ था। और चाहे जो कहे पण्डितजी एक नेता माने जाते ह, इसलिए नेतापर हाथ डाला गया है। फिर, वे धमगुरु ह, इसलिए किसीके बीचमें आनेवाले आदमी नहीं ह। इन सारी बातोंको देखते हुए साफ है कि यह मामला बहुत ही सवल है। गोरोंके मनपर भी ऐसी ही छाप पड़ी है।

‘प्रिटोरिया न्यूज’ की टीका

इसपर टीका करते हुए ‘प्रिटोरिया न्यूज’ लिखता है^१

पण्डितजीके अनुमतिपत्रकी मियाद न बढ़ाने तथा उसके द्वारा हिन्दुओंको धमगुरुसे वंचित करनेमें सरकारने कोई बुद्धिमानी नहीं बरती। सारी हकीकतको देखते हुए यदि श्री स्मट्स अपनी धमकीको पूरा करना चाहते हो तो भारतीय कौमको अपने धम गुरुओंकी जरूरत पड़ेगी। हमें लगता है कि सरकारने भूल की है। लोगोंको दुखी करना ठीक नहीं है। आज श्री पण्डितको दुख पाया हुआ कहा जा सकता है। उनका खयाल है कि उन्होंने जो किया है, वह उचित है। उनके सभी भाई उनका स्वागत करते हैं। ऐसा करनेमें सरकारको क्या लाभ हुआ, यह हमारी समझमें नहीं आता।

अब हमने देखा है कि पण्डितजीके मुकदमेसे गोरोंकी सहानुभूति भी भारतीयोंकी ओर खिंची है। वह मुकदमा इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि यहांके अखबारोंने उसे बहुत जगह दी है।

विशेष सहानुभूति

श्री फिलिप्स जोहानिसबर्गके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वे स्वयं पादरी हैं और पादरी समाजके प्रमुख ह। उन्होंने अखबारमें एक पत्र लिखा है। वह जानने योग्य है। उन्होंने भारतीयोंकी स्वेच्छया पञ्जीयन करवानेकी बातको स्वीकार किया है और सरकारसे स्वीकार करनेकी सिफारिश की है। वह पत्र हमने दूसरी जगह दिया है।^२

१ मूल अंग्रेजी टीका २३-११-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत की गई थी।

२ यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

इसके अलावा, श्री मकिटायरने 'लीडर' में लिखा है कि यहाँ दस अँगुलियोकी छाप तो केवल अपराधियोसे ही ली जाती है। और यदि सरकार दस अँगुलियोकी छापकी बात छोड़ दे तो उसे हर वर्ष ५०० पौडका लाभ होगा। इस प्रकार चारो ओरसे मदद मिलने लगी है। स्वेच्छया पजीयन स्वीकार हो और दस अँगुलियोकी बात रद्द हो जाये, तब तो मागा हुआ मिल गया, यही माना जायेगा।

प्रिटोरियाके धरनेदारोका मुकदमा

इस मुकदमेकी टीका करते हुए 'प्रिटोरिया न्यूज' लिखता है कि

यदि पण्डितजीके मुकदमेसे सरकारको नुकसान हुआ है, तो फिर धरनेदारोके मुकदमेसे और भी ज्यादा हुआ है। उस मुकदमेमें साफ कहा गया है कि धरनेदारोने तनिक भी धमकी नहीं दी, सरकार ही स्वयं लोगोको डराकर पजीकृत करती है। इन लक्षणोको देखते हुए भी यदि कोई भारतीय काला मुह करता है तो उसे भारतीय माना ही नहीं जा सकता।

हडताल

पण्डितजीको जेलकी सजा हो जानेके बाद ट्रांसवालमें सब जगह दूकाने बन्द रही। फेरीवालोंने फेरी नहीं लगाई। अखबार बेचनेवालोंने अखबार बेचना बन्द रखा और नुकसानकी परवाह नहीं की। मालिकोंने अखबार बेचनेवालोको दूसरे दिन अखबार देनेसे इनकार किया। ग्राहक नाराज हुए। आखिर अखबारवालोको ग्राहकोके नाम विनतीपत्र लिखना पडा, और अब भी कठिनाई पूरी तरह हल नहीं हुई। इस तरह जब एक ओर लोगोका सारा समुदाय कष्ट उठानेको तैयार हुआ तब ऑफटनमें श्री कमालखा नामक एक व्यापारीने अपनी दूकान खुली रखी। वैसे ही हाइडेलबर्गमें श्री खोटा, श्री अबुमिया कमरुद्दीन तथा श्री आदम मामूजी पटेलने अपनी अपनी दूकाने खुली रखी। इससे सारा भारतीय समाज बहुत ही क्षुब्ध हुआ है।

गद्दारोको शाबाशी

श्री खमीसा और उनके भाईबन्दके बारेमें मुझे कडवी बातें लिखनी पड़ी है। इस बार उनकी प्रशंसा करनेका अवसर मिला है, इसलिए मुझे खुशी है। श्री खमीसा और दूसरे सब लोगोने, जिन्होंने अपने हाथ मुह काले किये हैं, समाजके लिए दूकाने बन्द की थी। पीटसबर्गमें भी सबने वैसा ही किया। इस बातसे प्रकट होता है कि लकडी पीटनेसे पानी नहीं फटता। एक देशके आदमी एक दूसरेके बिलकुल विरोधी बन जाये, यह कभी नहीं हो सकता। स्वाथ रूपी जहर जब निकल जाता है तब कौमी हमदर्दी हुए बिना नहीं रहती।

चैमनेके चोचले

कुछ लोगोसे अच्छा काम हो ही नहीं पाता। श्री चैमनेकी इस समय ऐसी ही हालत है। किसी भी बहाने हमें परेशान करके वे भाईसाहब हमसे पजीयनपत्र लिवाना चाहते हैं। उनका नया चोचला यह है कि अब पोर्तुगीज राज्यके साथ उन्होंने व्यवस्था की है कि जिन्होंने पजीयनपत्र न लिया हो उन्हें परेशान किया जाये। पोर्तुगीज वाणिज्यदूतके कार्यालयमें यह नोटिस चिपकाया गया है कि डेलगोआ बं होकर भारत जानेवाले भारतीयोको डेलगोआ बं जानेका पास तभी मिलेगा जब वह नया पजीयनपत्र बतायेगा। और यदि नया पजीयनपत्र न दिखाये तो

भारतीय यह लिख दे कि वह भारतसे ट्रान्सवाल वापस नहीं आना चाहता। यह बात केवल परेशान करनेके लिए है। इससे प्रकट होता है कि चाहे जैसा प्रलोभन देकर भारतीयोंसे पजीयन पत्र लिवाना है। और कोई जोर चल नहीं सकता। डेलागोआ बेका पास न मिले तो भारतीयोंको धबडाना नहीं चाहिए। जिसे भारत जाना होगा, वह दूसरे रास्ते जा सकता है। फिर भी इस सम्बन्धमें कारवाई जारी है।

‘ट्रान्सवाल लीडर’ की सलाह

‘ट्रान्सवाल लीडर’ ने सलाह दी है कि सरकार भारतीय समाजके नेताओंसे मिले और उनसे परामर्श करके कानूनकी समस्याका हल निकाले। यदि सरकार वह हल नहीं निकालेगी तो बादमें पछताना होगा। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि ‘लीडर’ ट्रान्सवालका बहुत ही प्रभावशाली अखबार है।

शाहजी साहबकी बहादुरी

पण्डितजीके जेल जानेसे शाहजी साहबको बहुत ही दद हुआ है। इसलिए उन्होंने अखबारोंमें निम्नानुसार पत्र^१ लिखा है

महोदय, अपने भारतीय धर्मगुरुके मुकदमेके समय में अदालतमें था। उस समय मेरे मनमें यह विचार आया कि ट्रान्सवालके कानून कुछ ओघे हैं। आवेशके कारण मैंने इमाम कमालीको कुरानके फरमानका उल्लंघन करनेके कारण पीटा था। उसमें मुझे जेल अथवा ५ पौडके जुर्माने की सजा हुई थी। एक निदय मित्रने “मैं आपका शिष्य हूँ” कहकर जबरदस्ती ५ पौड भर दिये। इससे मुझे जेल भोगनेका मौका नहीं मिला। दूसरी बार मैंने श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनको मारा था। उसने बयान देते हुए स्वीकार किया कि उसने कुरानकी शपथ तोड़ी थी और इसीलिए मेरा मारना वैसा ही था जैसे बाप लडकेको मारता है। इससे दयालु यायालयने मुझे छोड़ दिया, किन्तु चेतावनी दी कि आगे ऐसा हुआ तो सजा होगी।

इस दृष्टिसे रामसुंदर पण्डितको बेकार ही एक महीनेकी सजा दी गई है। मैं उन्हें पहचानता हूँ। उन्होंने कभी किसीको कष्ट नहीं दिया। वे ब्रिटिश प्रजा हैं और ब्रिटिश उपनिवेशमें अपने सहधर्मियोंके धर्मसम्बन्धी कामकाज करते हैं। ऐसे व्यक्तिको ट्रान्सवालमें रहनेका एक कागजका टुकड़ा न होनेके कारण जेलमें डाला गया है।

मुझे तो लगता है कि यदि किसीको जेल दी जानी चाहिए तो वह मैं हूँ। फिर भी एक आदमीने बीचमें आकर जबरदस्ती पैसे देकर मुझे जेल नहीं भोगने दी। उधर, श्री रामसुंदर पण्डितको एक महीनेके लिए बन्द करके रखा जायेगा, उनके मित्र और सम्बन्धी उनसे नहीं मिल पायेगे, और वे धर्म-सम्बन्धी कार्य नहीं करा सकेंगे। इससे मेरा हृदय फटता है। मुझे जेल हो ओर श्री रामसुंदर पण्डित मुक्त हो तो कितना अच्छा। खुदा तू उन्हें बिल्कुल सुखी रखना और हिम्मत देना।

केप टाउनसे सहानुभूति

केप टाउनके आफ्रिकी भारतीय सघने [ब्रिटिश भारतीय] सघके नाम सहानुभूतिका तार भेजा है। उच्चायुक्तके नाम भी एक तार भेजा है कि उन्हें हस्तक्षेप करके भारतीयोंका कष्ट

दूर करना चाहिए तथा श्री रामसुन्दर पण्डितको छुड़ाना चाहिए। ऐसे तार कई जगहोंसे आये ह। तार भेजनेवाले सब लोगोंके नाम और तारोंका साराश अगले सप्ताह देनेकी आशा करता हूँ।

अमीरुद्दीनकी तार

श्री अमीरुद्दीनके साझी श्री अब्दुल गफूरने उन्हें निम्नानुसार तार भेजा है

आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। अपना फज हिम्मतके साथ निभाइये। आपसे बड़ी आशा रखते हैं। भारतकी प्रतिष्ठा यहाँकी लड़ाईपर निर्भर है। जबतक हम स्वतन्त्र नहीं हो जाते और हमारे बाल बच्चोंकी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं हो जाती तबतक आप आराम न ले।

पजीयन कार्यालयके बेकार प्रयत्न

लछमन नामक व्यक्तिका, जिसने धरनेदारोंके बारेमें बयान दिया था, गलत बयान देनेके अपराधमें गिरफ्तार किया गया था। वास्तवमें मामला तो कुछ था नहीं। इसलिए छोड़ दिया गया। किन्तु लछमनका मामला बताता है कि जो भारतीय पजीकृत होने जायेंगे वे अपने समाजको कलकित करेंगे, अपने भाइयोंको गढ़में उतारेंगे और हो सकता है कि स्वयं भी न उबरें। करीम जमालका मामला जिस तरहका था वैसा ही लछमनका भी हो गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९९ भाषण : हमीदिया अजुमनकी सभामें

[जोहानिसबग]

नवम्बर २४, १९०७]

श्री गांधीने प्रतिनिधियोंकी याग्यताकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेसमें भाषण करनेवाले अल्प लोग हैं, इसलिए इस समय अधिक व्यय करनेकी आवश्यकता न होगी। पैसेकी तंगीके कारण अधिक प्रतिनिधियोंकी नामजदगी स्थगित रखनी पड़ेगी। समय भी कम है। पजाबियों और पठानोंके सम्बन्धमें कुछ समयमें लॉर्ड सेल्बोनको पत्र लिखा जायेगा। श्री गांधीने तुर्कोंको दब रहनेकी सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोरोकी सभा हुई थी। उसके विवरणसे जान पड़ता है कि सरकार शिथिल हो गई है। यदि भारतीय समाज दब रहा तो सभी गोरे हमारे पक्षमें हो जायेंगे। गोरोका शिष्टमण्डल दिसम्बरमें जायेगा। भारतीय अन्ततक डटे रहेंगे, इसमें सरकारको सन्देह है। किन्तु, श्री गांधीने तकपूर्वक समझाया, जो साहसपूर्वक और परमात्मामें विश्वास रखकर प्रयत्न करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। उन्होंने प्रिटोरियाके धरनेदारोंकी वीरताके बारेमें बोलते हुए कहा कि मेजर फ्यूज उनसे हर दिन ही मिलते रहते हैं। मेजर कोडी आदि उनको उलटा समझाते हैं, किन्तु वे मानते नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनके लिए चुने गये प्रतिनिधि ।

३०० प्रार्थनापत्र गायकवाडको^१

[जाहानिसबग]

नवम्बर २५ १९०७

सेवामे

महाविभव गायकवाड [बडोदा]

१ आपके प्रार्थी महाविभवकी प्रजा है और ईमानदारीसे कमाने खानेके लिए ट्रांसवालमे आकर बसे ह ।

२ ट्रांसवालमे आपके प्रार्थियोमे से अधिकतरके बडे बडे हित दावपर चडे ह ।

३ आपके प्रार्थी आप महाविभवका ध्यान ट्रांसवाल ससद द्वारा पास किये गये एशियाई कानून सशोधन अधिनियमकी ओर सादर आकर्षित करते ह ।

४ आपके प्रार्थी, जैसा कि कदाचित महाविभवको विदित होगा, रक्षित ब्रिटिश प्रजाके रूपमे ट्रांसवालके अन्य ब्रिटिश भारतीयोके साथ मिलकर, साम्राज्य सरकारको निवेदन भेज चुके ह ।

५ आपके प्रार्थी इसके साथ उस प्राथनापत्रकी एक प्रति सलग्न कर रहे है जा उन्हाने परममाननीय उपनिवेश-मन्त्रीको इस अधिनियमके सम्बन्धमे भेजा हे ओर जिसमे सब आपत्तियोका विवरण दिया गया हे ।

६ चूकि साम्राज्य सरकारने हस्तक्षेप करनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया हे और चूकि उक्त कानून असामाय रूपसे तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक हे, तथा चकि प्रार्थी एक गम्भीर शपथसे इस अधिनियमको न माननेके लिए बँधे हुए है, इसलिए उन्होने अनाक्रामक प्रतिरोधके नामसे ज्ञात धमयुद्ध छेड दिया हे आर अपने सवस्वको दावपर चढा दिया हे । स्थानीय सरकारने जेल भेजने, निर्वासित करने और अन्य सजाएँ देनेकी धमकी दी है जिनमे से सभी, आपके प्रार्थियोके विचारमे, उक्त अधिनियमके जुएकी तुलनामे सह्य और झेल लेने योग्य ह ।

७ आपके प्रार्थियोकी विनीत सम्मतिमे आप महाविभवकी सहानुभूति और सक्रिय हस्तक्षेपसे साम्राज्य सरकारको, और भारत सरकारको भी, बल मिलेगा तथा प्रार्थियोको बहुत हिम्मत बँधेगी ।

८ इसलिए आपके प्रार्थी सादर विश्वास करते है कि श्रीमान उनको किसी भी वाञ्छनीय तरीकेसे अपना संरक्षण प्रदान करेगे, और याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी कतव्य मानकर सदा दुआ करेगे, आदि ।

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्डस सी० ओ० २९१/१२२

१ यह ' महाविभव गायकवाडकी ट्रांसवालवासी प्रजाने ' भेजा था और ३०-११-१९०७के इंडियन ओपिनियनमे प्रकाशित किया गया था । इस प्रार्थनापत्रकी एक प्रति श्री एल० डब्ल्यू० रिचने २३ दिसम्बर १९०७को उपनिवेश-उपमन्त्रीको भेजी थी ।

३०१ प्रार्थनापत्र उच्चायुक्तको^१

[जोहानिसबग

नवम्बर २६, १९०७ के पूव]

सेवामे

परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त, दक्षिण आफ्रिका

निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ताओका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन हे कि,

१ आपके प्रार्थी पुराने भारतीय सनिक है। हममे ४३ पजाबी मुसलमान, १३ सिख तथा ५४ पठान है।

२ आपके सभी प्रार्थी ब्रिटिश प्रजाजन है, और उनमे से अविकाशको इस उपनिवेशमे गत युद्धके समय परिवहन दलोके रूपमे लाया गया था। प्रार्थियोके दक्षिण आफ्रिकामे आनेपर उनके अफसरोंने उनसे कहा था कि युद्ध समाप्त होनेपर आप दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमे बस सकेगे और आपको इज्जतके साथ रोजगार मिलेगा।

३ आपके प्रार्थियोमे से कुछ चित्रालकी चढाईमे^२, तीरा युद्धमे^३ ओर दूसरी लडाइयोमे ब्रिटिश सरकार की ओरसे लडे है।

४ आपके प्रार्थियोमे से अधिकाशके पास शान्ति रक्षा अध्यादेश और १८८५ के कानून ३के अनुसार जारी किये हुए अनुमतिपत्र तथा पजीयन प्रमाणपत्र है। प्रार्थी ट्रान्सवालके युद्ध पूव कालके बाशिदे नही ह, बल्कि उनको ये अनुमतिपत्र उनके अपने अपने अफसरोंसे मिले हुए विमुक्ति प्रमाणपत्रोंके बदलेमे दिये गये है।

५ कुछको छोडकर इस समय हममे से सभी बेरोजगार है। इसकी वजह ज्यादातर एशियाई पजीयन कानूनके खिलाफ चलनेवाला सघष हे। कुछको उनके मालिकोंने पजीयन न करानेकी वजहसे नौकरीसे अलग कर दिया है, दूसरोके नौकरीकी अर्जी देनेपर उनसे कहा गया है कि अगर वे नय कानूनके मुताबिक अपना पजीयन करा ले तो उनको नौकरी दी जा सकती है।

६ आपके प्रार्थियोकी नम्र रायमे उनके लिए एशियाई कानूनके सामने सिर झुकाना मुमकिन नही है, क्योंकि इससे उनको इतना अधिक अपमान सहना पडता है, जिसका अनुभव उनको भारतमे पहले कभी नही हुआ। और यह उनको ऐसी हालतमे पहुँचा देता है, जो उनके आत्मसम्मान और सैनिक मर्यादाके अनुरूप नही है।

७ आपके प्रार्थी किसी भी अधिकारीके सामने, जिसे मुकरर किया जाये, यह गवाही देनेको तैयार है कि उन्होंने राजभक्त ब्रिटिश प्रजाजनोके रूपमे साम्राज्यकी सेवा की हे।

१ यह प्रार्थनापत्र गांधीजीने ११५ सेवा निवृत्त भारतीय सैनिकोंकी ओरसे ७ दिसम्बर १९०७ को उच्चायुक्तके नाम लिखे अपने पत्रके (पृष्ठ ४०९) साथ उहाँ भेज दिया था। श्री एल० डब्ल्यू० रिचने दिसम्बर २३, १९०७ को इसकी एक प्रति उपनिवेश-उपमन्त्रीके पास भेजी थी।

२ १८९५ में।

३ १८९७-९८ में।

८ आपके प्रार्थियोंका भारत लौटना और वहा जाकर अपने गुजारेका कोई जरिया खोजना सम्भव नहीं है।

९ आप दक्षिण आफ्रिकामे बड़ी सरकारके हितोके न्यासी तथा उच्चायुक्त हैं। अतः, इस हेतियतसे, हम विनयपूर्वक आपसे रक्षा पानेके अधिकारका दावा करते हैं।

१० इसलिए आपके प्रार्थी विनयपूर्वक निवेदन करते हैं कि परमश्रेष्ठ हम लोगोको इस प्रकारकी राहत दिलाये जो ऐसी परिस्थितिमे सम्भव हो। और याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य मानकर, सदा दुआ करेंगे।

[आपका, आदि,
नवाबखाँ
फजले इलाही]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० २९१/१२२

३०२ पत्र अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षको

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २६, १९०७ के पूर्व]

[अध्यक्ष
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
कलकत्ता
महोदय,]

मेरा अजुमन एशियाई पजीयन कानूनको लेकर ट्रान्सवालके अय भारतीय सगठनोंके साथ-साथ, जिस सघषमे लगा हुआ है उसके सिलसिलेमे उसने मुझे आपसे कुछ निवेदन करनेको कहा है।

मुझे यकीन है कि भारतीय मुसलमानोंके नाम हमीदिया इस्लामिया अजुमनने जो गश्ती चिट्ठी^१ भेजी है उसे आप देख चुके होंगे। हमने सभी भारतीय सगठनोंसे उनके स्थानीय राजनीतिक विचार भेदका खयाल किये बिना, निवेदन किया है। एशियाई कानूनके अन्तगत ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके प्रश्नपर उनमे किसी प्रकारका मतभेद नहीं है, और खयाल यह है कि हमारे साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है उसका मिलजुल कर जोरदार विरोध किया जाये।

१ देखिए “भारतीय मुसलमानोंसे अपील” पृष्ठ १७९ ८०।

अतः, मेरा अजुमन इस बातका भरोसा करनेकी हिम्मत करता है कि आप ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीयोंके एक हकमे लीगकी सहानुभूति हासिल करानेकी कृपा करेंगे।

[आपका, आदि,

इमाम अब्दुल कादिर सलीम बावजीर

कायवाहक अध्यक्ष

हमीदिया इस्लामिया अजुमन]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[मंगलवार, नवम्बर २६, १९०७]

सघका हिसाब

सघका हिसाब^१ सावजनिक सूचनाओंके साथ दिया गया है। उसकी ओर ट्रांसवालके भारतीयोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उससे मालूम होगा कि अब सघके पास केवल १४० पौ० १८ शिलिंग १ पैस बचा है। उसमें भी २५ पौड तो श्री आलब्रेटके दिये हुए हैं। सघने जबरदस्त काम उठाया है, किन्तु उस हिसाबसे पैसा कुछ भी नहीं है। इस सघकी तरह कम खर्चीसे किसी दूसरे सगठनका काम चलता हो, सो हमें नहीं मालूम। उसका चालू खर्च १० पौडके अन्दर है। किन्तु अब तार आदिका खर्च बढ़ेगा। किराया कुछ लगता नहीं है। कोई फालतू खर्च नहीं है। खर्चका बहुत कुछ बोझ जोहानिसबर्गपर है। रस्टेनबर्गका अनुकरण दूसरे शहर करे तो भी सघको कुछ मदद मिल सकती है। रस्टेनबर्गसे हालमें ही १५ पौडकी सहायता प्राप्त हुई है। इससे दूसरे शहरोंको सबक लेना चाहिए।

वह हमें कैसे घेरती है

मैं बता चुका हूँ कि चैमने साहब पूरी व्यवस्था कर चुके हैं कि डेलागोआ वे जानेमें भारतीयोंको मुसीबतें हों। अब फोक्सरस्टपर मुसीबत आई जान पड़ती है। सुना है कि जो भारतीय नेटाल होकर जाना चाहें, उनके अनुमतिपत्रोंकी जाच फोक्सरस्ट या चार्ल्सटाउनमें की जायेगी, उनके अँगूठोंकी छाप ली जायेगी और तब उन्हें आगे बढ़ने दिया जायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि सघषके समयमें भारत जानेवालोंका नाम दर्ज रहे और जब वे वापस आये तब उन्हें परेशान किया जाये। इस सम्बन्धमें मुझे सूचित करना है, कि ट्रांसवाल छोड़ते समय कोई भी अनुमतिपत्र बतलानेके लिए बँधा हुआ नहीं है। किसीको अँगूठोंकी निशानी भी नहीं देनी है। इन दोमें से एक भी बात अपराध नहीं है। किन्तु यदि सरकार हैरान करना चाहें तो उसे उसका मौका नहीं देना है। ये सब लडाईके बीचके हंगामे हैं। इसलिए किसीको डरना नहीं चाहिए और न हमारे सामने यह सवाल ही उठाना चाहिए कि अब क्या होगा।

बहादुरीका उदाहरण

श्री मुहम्मद मूसा पारेख न्यूकैसिलसे लिखते हैं कि वे स्वयं खास तौरसे कानूनका विरोध करनेके लिए ही दिसम्बरके शुरू होनेक पहले वाकरस्ट्रूममे आकर बैठेगे। उन्होंने यह भी लिखा है

ऐसे हजारों पजीयन दफ्तर खुले तो भी क्या? जिसने एक बार सच्चे दिलसे खुदा और उसके रसूलको सत्य मानकर शपथ ली हो वह हर्गिज गुलामीका टोकरा नहीं उठा सकता।

मेरी कामना है कि यह जोश श्री पारेख और सभी भारतीयोंमे अन्ततक रहे।

एशियाई भोजनालय

पाठकोको याद होगा, कि इन भोजनालयोंके नियमोंमे नगरपालिकाने यही तय किया था कि मनेजर गोरा आदमी होना चाहिए। उसपर सघने अर्जी दी थी। अब सरकारने उसमे परिवर्तन करनेका आदेश दिया है और उसे नगरपालिकाने स्वीकार किया है।

बग्घीके नियम

बहुत समयसे बात चल रही है कि ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे पहले दर्जेकी बग्घीमे काले आदमी न बैठ सके। अब नगरपालिकाने ऐसा नियम पास कर दिया है। उसमे कहा गया है कि काला बैरिस्टर या डॉक्टर उसमे बैठ सकेगा। अर्थात् शराबके नशेमे चूर या फटेहाल काला वकील या डाक्टर तो पहले दर्जेकी गाडीमे बैठ सकता है, किन्तु अच्छे कपड़े पहननेवाला लखपति भारतीय व्यापारी नहीं बैठ सकता। और भी विशेषता यह है कि वकील तो बैठ सकता है किन्तु उसकी पत्नी या लडका नहीं बैठ सकता। इस नियमके बनाने-वालेकी मूखताकी सीमा नहीं है। सघने इस कानूनके खिलाफ सरकारके पास अर्जी भेजी है।

स्टैगरके भारतीयोंका प्रस्ताव

रामसुन्दर पण्डितके जेल जानेके सम्बन्धमे कई जगह सभाएँ हुई और प्रस्ताव पास किये गये हैं। वैसा ही स्टैगरमे हुआ है। श्री दाउद मुहम्मद सीदत, श्री अहमद मूसा मेतर, श्री मणिलाल चतुरभाई पटेल, तथा श्री अहमद मीठाके हस्ताक्षरसे सहानुभूतिके प्रस्ताव सघको प्राप्त हुए हैं।

सभी तार भेजनेवालों और प्रस्ताव पास करनेवालोंको सघ आभार सूचक पत्र नहीं भेज सका, क्योंकि वह लगभग असम्भव था। तथा, जहा सब लोग देशके कष्टोंसे उद्विग्न हो एव अपना कतव्य समझ कर कोई काम करते हो वहा उपकार माननेकी जरूरत भी नहीं होती। यह अवसर एक दूसरेके गुण गानेका या उपकार माननेका नहीं है। किये हुए कतव्यका ज्ञान ही उपकार मानना है।

खोलवाड मदरसा

श्री गुलाम मुहम्मद आजम बम्बईसे लिखते हैं कि उन्हें ९२१ पौंड १० शिलिंग मिले हैं। वे उस रकमसे [मदरेसेके लिए] मकान खरीदनेकी तजबीज कर रहे हैं। किन्तु उन्होंने लिखा है कि रकम इतनी कम है कि उसमे अच्छा मकान मिलना मुश्किल है। उन्हें यास पत्र और मुख्तारनामा भी मिल गया है।

खानवाले क्षेत्रमें परवाने

जोहानिसबग आदि जगहोपर स्वण कानूनके अतगत सरकारने परवाने देनेसे इनकार किया था और यह स्थिति पैदा हो गई थी कि मुकदमा लड़ना होगा। किन्तु अब फिर सरकारी जवाब आ गया है कि नये कानूनकी लड़ाईके कारण सरकार इस सम्बन्धमें लड़ाई करना नहीं चाहती और जो परवाना मागेगा उसे दिया जायेगा। यह जवाब समझने योग्य है। ऐसा मुकदमा लड़नेमें सरकारको बदनामीका डर लगता है। क्या ७,००० लोगोंको कैद करते हुए बदनामीका डर नहीं लगेगा ?

कोकणियोंकी सभा

खुद सब दूढ़ हैं, या नहीं यह देखनेके लिए पिछले रविवारको कोकणियोंकी एक सभा हुई थी। हमीदिया इस्लामिया अजुमनके सभा भवनमें सब एकत्र हुए थे। श्री मालिम मुहम्मद सभाके अध्यक्ष थे। श्री अब्दुल गनीने अपने भाषणमें कहा था कि वे स्वयं बिलकुल दूढ़ रहेंगे। जिस शपथको दिलवानेमें वे स्वयं शामिल थे, उसे वे तोड़नेवाले नहीं ह। श्री इस्माइल खा, श्री शहाबुद्दीन हसन, श्री हसन मिया (रूडीपूटके), श्री अब्दुल गफूर आदि सज्जनोंने भाषण दिये और सभामें सबने यही राय व्यक्त की कि चाहे जितनी रकामें आये, फिर भी कानूनके सामने नहीं झुकना है। यह सवाल उठनेपर कि दूकानके हर व्यक्तिको पजीकृत होना चाहिए या नहीं, यही निणय हुआ कि वैसा करनेकी कोई जरूरत नहीं है।

कांग्रेसका चन्द्रा

[भारतीय] राष्ट्रीय कांग्रेसके चंदेमें यहाँ ५० पौंडसे ज्यादा रकम इकट्ठी हुई है। और भी इकट्ठा होनेकी सम्भावना है। सूची अगले सप्ताह भेजूंगा। उपयुक्त रकममें से अभी तो २५ पौंड श्री अमीरुद्दीनको भेजे गये हैं। यदि अधिक रकमकी आवश्यकता मालूम हुई तो ५० पौंड तक भेजनेका निणय हुआ है। प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें यहाँसे भारतको जो समुद्री तार भेजे गये हैं, उनका खर्च भी हुआ है। यह हिसाब प्रकाशित किया जायेगा।

डेलगोआ-वेमें भारतीयोंकी सुस्ती

यहाँके अखबारोंसे मालूम होता है कि डेलगोआ बंके भारतीय यदि नहीं चेतेंगे तो उनका बुरा हाल होगा। वहाँके व्यापार मण्डल (चेम्बर) ने निश्चय किया है कि अब भारतीय सदस्य मत नहीं दे सकते। वहाँके भारतीय यदि यह सब चुपचाप सहते बैठे रहेंगे तो बहुत ही बदनामी होगी। इसके अलावा, वहाँ ट्रांसवालसे जानेवालोंको तग करनेकी तजवीज भी की जा रही है। इन सब बातोंको लेकर डेलगोआ बंके भारतीयोंमें यदि कुछ पानी आ जाये तो अच्छा होगा। वहाँके सेठोंसे सम्बद्ध सभी भारतीयोंको हम जोरोंसे सलाह देते हैं कि उनसे जितना भी लिखा जा सके उतना लिखें।

गायकवाडकी याचिका

महाराजा श्री सयाजीरावको उनकी प्रजाने नये कानूनके बारेमें निम्नानुसार याचिका दी है। उसमें लगभग १५० हस्ताक्षर हुए हैं।^१

इसम्बरमे क्या किया जाये ?

इस प्रश्नका उत्तर पढ़नेके लिए बहुतेरे पाठक उत्सुक होंगे। मेरी चिट्ठीमें यह प्रश्न अंतिम रखा गया है, किन्तु इसकी आवश्यकता पहली है। क्या किया जाये, इसका विचार करनेके पहले क्या हो सकेगा, इसपर विचार करे।

क्या हो सकता है

हमने देखा कि सरकारको शरीरसे पकड़ कर निर्वासित करनेकी सत्ता तो नहीं है। फिर जेल भोजना ही बाकी रहा। कानूनके आठवे खण्डके अनुसार हर भारतीयसे पुलिस नया पजीयनपत्र माग सकती है। उसके न होनेपर वह उसे मजिस्ट्रेटके सामने ले जायेगी। वहा उसे सूचना दी जायेगी कि निश्चित अवधिके अंदर देश छोड़ दे। उस आदेशका पालन न करनेपर उसे फिर पकड़ा जायेगा और उसे छ महीने तक की जेलकी सजा दी जा सकेगी। इस उपपाराके अनुसार मुकदमा चलनेपर अदालतको जुर्माना करनेका अधिकार नहीं है। कानूनको पढ़नेसे मालूम होगा कि अदालत पजीयनके लिए अर्जी देनेका हुक्म दे सकती है। इस प्रकार मुकदमा न चलाकर सरकार यह मुकदमा भी दायर कर सकती है कि अर्जी क्या नहीं दी गई। अर्जी न देनेके अपराधकी सजा १०० पाँड जुर्माना या जेल है। ऐसा व्यवहार सरकार प्रत्येक भारतीयके साथ कर सकती है। यानी प्रत्येक भारतीयको जेल भेज सकती है। किन्तु कर सकने और करनेमें बहुत अंतर है। सरकार प्रत्येक भारतीयको पकड़े और जेलमें बंद करे इसे मैं लगभग असम्भव मानकर छोड़ देता हूँ। किन्तु कुछ भारतीयोंको तो जहर पकड़ेगी।

कुछ गिरफ्तारियाँ जरूर

मेरा अनुमान है कि पहले झपाटेमें अधिकसे अधिक सोके करीब भारतीय पकड़े जायेगे।

कितना पानी है ?

और हममें कितना पानी है यह देखनेके लिए, सम्भव है, गाव गावसे थोड़े भारतीय पकड़े जाये। यदि ऐसा हो तो हमारी लड़ाईका अंत जल्दी होगा। यदि गाव-गावसे गिरफ्तारी की जाये तो किसीको घबड़ाना नहीं चाहिए। वैसा होगा तो श्री गांधीके लिए प्रत्येक गाव जाना सम्भव नहीं होगा, और न उसकी जरूरत ही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये उसके सम्बन्धमें सघ (विआस) को जोहानिसबर्ग तार भेजा जाये।

जमानतकी अर्जी नहीं

गिरफ्तार किये जानेवाले व्यक्तिको जमानतपर नहीं छूटना है। वकील भी नहीं करना है। जिस दिन अदालतमें पेश किया जाये उसे कहना चाहिए

म कानूनका विरोधी हूँ। मैं ट्रान्सवालका सच्चा निवासी हूँ। मेरे पास सच्चा अनुमतिपत्र है। कानूनसे हमारी मनुष्यता जाती है। उससे हमारा धर्म भी जाता है। इसलिए मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। हमारी सारी कौम उसके खिलाफ है। यदि सरकार मुझे चले जानेका नोटिस देगी तो वह भी माना नहीं जायेगा। इसलिए मुझे जो सजा देनी हो वह अभी ही दीजिए। और यदि नोटिस देना ही हो तो जितने थोड़े समयका दिया जा सके उतने थोड़े समयका दीजिए।

इतना अपन-आप या दुभाषियेकी मारफत कहा जाये।

नोटिस ही मिलेगा

इसपर बहुत करके तो नोटिस ही मिलेगा । उसकी अवधि समाप्त हो जानेपर भी वकीलकी जरूरत नहीं है । अवधि समाप्त होने तक तो वह व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा । इस बीच उसे अपनी कुछ व्यवस्था करनी हो तो करे ।

नोटिस पूरा होनेपर

नोटिस पूरा हो जानेके बाद वह फिर पकड़ा जायेगा । इस समय कुछ अधिक बयान नहीं देना है । केवल इतना कहना है कि “मैंने पहले जो कहा है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना ।” उसके बाद जो सजा मिले उसे भोगा जाये । जो लोग बाहर रहे, उन्हें सजाके सम्बन्धमें तुरन्त तार करना चाहिए । सजा प्राप्त व्यक्तिके बाल बच्चे हैं या नहीं, वे कहा हैं, उसके भरण-पोषणका बोझ उस व्यक्तिके समाजपर डाला है या उसके पास पैसे हैं वगैरा बातें तारमें लिखी जायें ।

इतना याद रखना चाहिए कि जिसके बारेमें उचित मालूम होगा, उसके बाल बच्चोंका भरण पोषण जेलसे छूटने तक समाज करेगा । अच्छी बात तो यह है कि हर जगह लोग अपने अपने आदमियोंका बोझ उठा ले, जैसे रामसुंदर पण्डितके बाल बच्चोंका बोझ जर्मिस्टनके भार तीयोंने उठाया है । किन्तु यदि वैसा न हो सके तो सघ तो व्यवस्था करेगा ही ।

यदि जोहानिसबगमें गिरफ्तार नहीं किया गया और रोक टोक न की गई तो श्री गांधी बिना शुल्कके वहां जायेंगे, जहां भारतीय (सच्चे अधिवासी) गिरफ्तार किये गये होंगे । उनका किराया यदि वह गांव दे तो इसमें उसकी शोभा होगी, किन्तु यदि वहांसे गाड़ी किराया न मिले, तो सघ देगा और श्री गांधी वहां पहुँचेंगे ।

जेल जानेवालेके व्यापारके बारेमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । उस व्यक्तिके अपने व्यापारके बारेमें पहलेसे बन्दोबस्त कर रखा होगा । सरकार किसीकी दूकानको बन्द नहीं कर सकती । जुर्माना वसूल करनेके लिए वह माल नीलाम कर दे, सो भी नहीं होगा । एक ही दूकानके सभी व्यक्ति एक ही साथ पकड़ लिये जायें, यह भी बहुत सम्भव नहीं दीखता । जेलमें बैठे बैठे भी वह आदमी अपने कामकी कुछ व्यवस्था कर सकता है, किसीको लिख सकता है या सन्देश भेज सकता है ।

बाहरवाले क्या करें ?

एक या अधिक लोगोंको जेलमें भेजकर दूसरे बैठे रहे, यह सरल रास्ता है । किन्तु इससे घबड़ाहट पदा हो और हमें भी गिरफ्तार किया जायेगा इस दहशतसे कोई पजीयन करानेको दौड़ पड़े, तो वह देशका दुश्मन माना जायेगा और उसके द्वारा भारतीयोंके नामको बढ़ा लगेगा ।

खरी कसौटी

खरी कसौटी इसीमें होगी कि नेताओंके जेलमें चले जानेपर भी लोग घबड़ाये नहीं, बल्कि जोर दिखायें और कानूनको न मानें । इतना जब साफ तौरसे साबित हो जायेगा तभी कानून रद्द होगा । यह हम खूब याद रखें ।

दो दिसम्बरको

दिसम्बरकी २ तारीखको भारतीयको अपने घरोंमें घुसकर नहीं बैठना है। फेरीवालोंको डर कर फेरी बंद करनेके बजाय निभयतापूर्वक बाहर निकल कर अपने धंधेमें लगना चाहिए। उस दिन और उसके बादके दिनोमें कुछ नहीं है यह समझकर हमेशाकी तरह काम करते रहना है। यह लडाई आजादीके लिए है। इसलिए कदम कदमपर हिम्मतकी आवश्यकता है। इसके बिना सफल होना सम्भव नहीं है।

हेलूने फिर मुँह फेरा

श्री हेलूने अपना मुँह काला किया इसके लिए उन्होंने मस्जिदमें माफी मागी है और पजीयकको निम्नानुसार पत्र^१ लिखा है

मैं १२ अक्तूबरको प्राप्त अपना पजीयनपत्र सादर वापस भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा करके मैं नये कानूनका जुआ उतार नहीं सकता, फिर भी जिन परिस्थितियोंमें मैं हूँ, उनमें जब मैं पजीयन कराने गया तब मेरे मनमें परस्पर-विरोधी भावनाएँ जोर कर रही थी। एक और तो मेरा लेनदार मुझे कानूनके सामने झुकनेके लिए विवश कर रहा था, और यदि मैं न झुकू तो मेरा माल कुक कर देनेकी धमकी दे रहा था, दूसरी ओर कानूनके सामने झुकनेकी मेरी बेशर्मीका खयाल मुझे आ रहा था। मैंने बेशर्मीका पूरा अनुमान नहीं लगाया और धमकीके वश हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन बेकार हो गया है।

मेरे देशभाई और सहधर्मी मुझे छोड़ रहे हैं। मेरी बहन और अन्य सगे सम्बन्धी मेरा तिरस्कार करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी ली हुई शपथ तोड़ी है, इसलिए मैं अपने कुटुम्बमें रहने योग्य नहीं हूँ। मेरी जायदाद तो शायद मेरे पास रहेगी। किन्तु मैं देखता हूँ कि मेरे सगे सम्बन्धी और देशवासी भाई यदि मुझे छोड़ देते हैं तो वह जायदाद मेरे लिए बोझ रूप ही होगी। ३१ जुलाईको प्रिटोरियामें आम सभा हुई थी तब जिन मेमन लोगोंने पैसेके मोहमें अपनी ली हुई शपथ भग करके कानूनकी गुलामी स्वीकार की थी, उनके खिलाफ सख्त बोलनेवाला केवल मैं ही एक था। किन्तु जब उसी पैसेका लोभ मुझे हुआ तब मैं भी फिसल गया। जो हो गया उसे तो मिटाया नहीं जा सकता। किन्तु यह पजीयनपत्र आपको भेजकर मैं अपने आपको कुछ हदतक निष्कलंक करनेका सतोष मान लेता हूँ।

अंतमें मैं इतनी ही आशा करता हूँ कि मेरा उदाहरण मेरे भाइयोंके लिए चेतावनी स्वरूप हो जायेगा। और जबतक आपके दफ्तरका काम नये कानूनपर अमल करवाना रहेगा तबतक वे आपके दफ्तरकी ओर देखेंगे भी नहीं।

इसके अलावा श्री हेलूने उपयुक्त पत्र अखबारोंमें भेजते हुए यह भी लिखा है कि उनके कुत्तेको जहर देनेकी जो बात अखबारोंमें प्रकाशित हुई है, वह झूठ है।

हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षके नाम इस अजुमनने निम्नलिखित पत्र^१ भेजा है

मेरा अजुमन एशियाई कानूनकी ओर आपका ध्यान खींचता है। अजुमनने भारतीय मुसलमानोंको जो पत्र लिखा है, उसे आप जानते ही होंगे। हमने राजकीय विषयमें उतरे बिना सभी प्रकारके सगठनोंके सामने अपनी फरियाद पेश की है। इस विषयमें मतभेद नहीं है। इससे हम चाहते हैं, कि इस सम्बन्धमें सभी सगठनोंकी ओरसे एक स्वरसे पुकार की जाये। इसलिए मेरा अजुमन आशा करता है कि अखिल भारत मुस्लिम लीग इस सम्बन्धमें आवाज उठायेगी।

गोरेके शिष्टमण्डलका क्या हुआ ?

कुछ गोरे सरकारके पास शिष्टमण्डल ले जाना चाहते थे, यह खबर मैं दे चुका हूँ। शिष्टमण्डल अभी तक गया नहीं, इससे कुछ भारतीय अधीर हो गये हैं। मुझे कहना चाहिए कि यह अधीरता भीरुताका लक्षण है। शिष्टमण्डल जाये तो क्या और न जाये तो क्या ? हम तो अपनी हिम्मतपर निर्भर हैं। इतनेपर भी भीरुओंको हिम्मत देनेके लिए मैं खबर देता हूँ कि शिष्टमण्डलके लिए तैयारी हो रही है। वह केवल यह देखनेके लिए आतुर है कि हममें कितना पानी है। दिसम्बरके पहले यह मालूम हो जानेकी सम्भावना नहीं है, इसलिए शिष्टमण्डल नहीं गया। फिर भी जो लोग बाहरकी मददके बलपर ही टिके हुए हैं, वे यदि निराश हो तो आश्चर्य नहीं।

एक धरनेदारका मामला

श्री पी० के० नायडू एक बरना देनेवाले स्वयंसेवक थे। उनकी एक मद्रासीसे पजीयनपत्रके सम्बन्धमें तकरार हो गई थी। मद्रासीने पजीयनपत्र ले लिया था, इसलिए श्री नायडूने उसे पीटा था। श्री नायडूके मुकदमेकी सुनवाई (मगलवारको) हुई। उनको १० पौंड जुर्माना हुआ। वह जुर्माना उनके मित्रोंने दे दिया। इस सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटने टीका करते हुए कहा कि यह मामला पजीयनके सम्बन्धमें है, इसलिए सच देखा जाये तो उसे जुर्मानेके बजाय जेलकी सजा दी जानी चाहिए। मुझे स्वयं तो श्री नायडूसे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे मामलासे हमारा ही नुकसान होता है। मारपीटकी बात इस लड़ाईमें है ही नहीं। इसके अलावा जुर्माना देकर छूटनेको मैं और भी खराब मानता हूँ। जुर्माना सगे सम्बन्धियोंने दिया, यह उन लोगोंके लिए भी बदनामीकी बात है। जो मारपीट करके या दबाव डालकर लोगोंको पजीकृत होनेसे रोकनेकी बात सोचते हैं, वे इस भव्य धार्मिक स्वदेश हितकी लड़ाईको समझते ही नहीं।

पजाबियोंकी याचिका

पजाबियोंने लाड सेल्बोनके पास जो याचिका भेजी^२ है उसका अनुवाद निम्नानुसार है,

हम पुराने भारतीय सैनिक हैं। हममें ४३ पजाबी मुसलमान, १३ सिख, तथा ५४ पठान हैं। हम सब ब्रिटिश प्रजा हैं। हमें बोअर युद्धके समय यहा लाया गया था।

१ वहाँ पत्रका सारांश मात्र दिया गया है। मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए “पत्र अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षको”, देखिए पृष्ठ ३८५ ८६।

२, मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए “प्रार्थनापत्र उच्चायुक्तों”, पृष्ठ ३८४ ८५।

जब हम दक्षिण आफ्रिकामे आये, हमारे अधिकारियोने कहा था कि लडाईके बाद आप लोग ट्रान्सवालमे चाहे जिस हिस्सेमे रह सकेंगे ।

हमसे से कुछ लोग चित्रालकी चढाई, तीरा मुहिम और दूसरी लडाइयोमे ब्रिटिश सरकारकी ओरसे लडे हैं ।

हमसे से बहुत लोग एशियाई कानून सम्बन्धी लडाईके कारण अभी बेकार ह । कुछ लोगोको पजीकृत न होनेके कारण नौकरीसे बरखास्त हाना पडा है । कुछ लोगोसे यह कहा गया है कि नये कानूनके अन्तगत पजीकृत हो जाओ तो नौकरी मिलेगी ।

किन्तु हमारी नम्र रायमे एशियाई कानूनके सामने झुकना हमारे लिए असम्भव है । क्योंकि उस तरहका अपमान हमने कभी नहीं भोगा । हम सैनिक होकर अपनी इज्जत और दर्जा क्यों गँवाये ?

भारत लौटना अब हमारे लिए सम्भव नहीं है ।

इसलिए आदरपूर्वक निवेदन करते ह कि आप दक्षिण आफ्रिकामे बड़ी सरकारके न्यासीके समान हैं अतः आपको हम संरक्षण देना चाहिए ।

इसलिए हम आशा करते हैं कि आप हमें यथासम्भव संरक्षण प्रदान करेंगे ।

चीनीकी मृत्युपर शोक सभा

[बुधवार]

एक चीनीने आत्मघात किया था । उसकी स्मृतिमे चीनी सघने आज (बुधवारको) एक सभा की थी । इस सभाको देखनेवालेके मनमे चीनियोंके प्रति सदविचार आये बिना रह ही नहीं सकते । इन लोगोंने अपना सुन्दर सभा-भवन काले कपडोसे सजा दिया था । उसमे एक ओर मृत चीनीकी तसवीर रखी थी । बीचमे धरना देनेवाले स्वयंसेवक खडे थे । आसपास कुर्सिया रखी गई थी, जिनपर आमन्त्रित लोगोको बैठाया गया था । लगभग एक हजार चीनी अपने हाथोमे फूलकी मालाएँ लिये बहुत धीरे-धीरे तसवीरके पास गये और मतात्माके लिए दुवा मागते हुए दूसरे दरवाजेसे निकल गये । ये सब लोग बहुत ही साफ-सुथरे कपडे पहनकर आये थे । बादमे उन्होने चीनी भाषामे मर्सिया गाया । मर्सिया गा चुकनेके बाद दूसरे सभा कक्षमे सभा हुई । सभा कक्ष पूरा भर गया था । वहा उनके प्रमुख श्री क्विनने चीनी और अंग्रेजीमे भाषण दिया । फिर श्री गांधी और श्री पोलकने कानूनके बारेमे समझाया, और बैठक समाप्त हुई । उनकी एकता, उनका साफ सुथरापन और उनकी हिम्मत, तीनों बातें हमारे लिए अनुकरणीय हैं ।

प्रिटोरियामे मारपीट

श्री हाजी इब्राहीम एक गद्दार है । उहे एक पठान श्री बनुतखानने मारा था । उस पठानपर मुकदमा चल रहा है । उसकी पूरी खबर अभी नहीं मिली है । दिखाई यह पडता है कि पजीयन पत्र लेने ओर शपथ तोडनेके कारण बनुतखानने हाजी इब्राहीमको लकड़ी मारी । इसपर हाजी इब्राहीमने उसे पछाड दिया और वह उसपर चढ बैठा । बनुतखानने छूटनेके लिए उसका गाल नोच लिया । बनुतखानकी जमानत पहले १०० पौड रखी गई थी क्योंकि श्री चैमनेने खबर दी थी कि उसने उहे भी धमकी दी थी । किन्तु आधा मुकदमा हो जानेपर जमानत ५० पौड कर दी गई थी । मजिस्ट्रेटने बनुतखानको २० पौड जुर्माना किया है और वह रकम उसने दे दी है ।

मणिलाल देसाईका पत्र

प्रिटोरियाके मुख्य धरनेदार श्री मणिलाल देसाईने अखबारोको पत्र लिखा है कि धरना देनेवाले मारपीट बिलकुल नहीं करते, न बल-प्रयोग करते हैं। वे बहुत ही धीरे और प्रेमसे कानूनकी वारीकिया समझाते हैं तथा उससे होनेवाली अड़चनोका बयान करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०४ भाषण चीनी सघमें^१

[जोहानिसबग

नवम्बर २७, १९०७]

उहोने कहा कि ऐसे अवसरपर इस अधिनियमपर विचार करना धमभ्रष्टाका काय जसा लगता है, परन्तु चूँकि अध्यक्षने एक उदाहरण^१ उपस्थित कर दिया है, मुझे उसका अनुसरण करना ही है, और विशेषकर इसलिए कि जिस सस्कारमे हम लोगोने अभी हालमे भाग लिया है वह इस अधिनियमसे इतना अधिक सम्बद्ध है। मने प्राय यह आक्षेप सुना है कि चीनी लोग मानव-जीवनकी वसी कद्र नहीं करते जसी कि अय लोग करते हैं। परन्तु यदि मुझे इस सम्बन्धमे कभी कोई भ्रम था तो वह आज अपराह्णमे मने जो-कुछ देखा, उससे दूर हो गया है। अच्छा होता, यदि जनरल स्मट्सने उस महान सस्कारको देखा होता जिसमे हम लोगोने भाग लिया था। मेरा विचार है, उस दशामे जनरल स्मट्सने यह कहनेसे पहले, कि उहोने अपना चरण जहाँ रोपा है उसे वे वहीं रोपे रहेगे, दुबारा सोचा होता। एशियाई अधिनियमसे लडनेकी सलाह मैने दी और म अब भी महसूस करता हूँ कि मने वही किया है जो ठीक, उचित और न्यायानुकूल है। मने अपने देशवासियोको वह सलाह दी है और मुझे आपको भी, साथी एशियाइयोके रूपमें, वही सलाह देनेमें कोई हिचक नहीं है। मैने ब्रिटिश प्रजाजनो और गैर-ब्रिटिश प्रजाजनोके बीच एक रेखा खींचनेका कठिन और सुवीघ प्रयास किया। मैने यहाकी सरकारसे, और साम्राज्यीय सरकारसे भी, जोरोसे प्रार्थनाएँ कीं कि कमसे कम ब्रिटिश प्रजाजनो और अन्य एशियाइयोमे कुछ भेद तो किया ही जाना चाहिए। साम्राज्यीय सरकार और स्थानीय सरकार, दोनोने जोरके साथ उत्तर दिया, “नहीं”। और यद्यपि मने अपने देशवासियोके लिए और स्वयं अपने लिए उन सब अधिकारोकी माँग की जो ब्रिटिश प्रजाजनोको समुचित रूपसे प्राप्त होने चाहिए, तथापि वह माँग शीघ्रतासे ठुकरा दी गई और ब्रिटिश भारतीय तथा अन्य एशियाई एक ही श्रेणीमे रख दिये गये।

१ चाउ क्वाई नामक एक चीनीने पजीयनके सामने झुकनेसे होनेवाले अपमानका अनुभव करके आत्म हत्या कर ली थी। उनकी स्मृतिमें एक सभा हुई। चीनी सघके अध्यक्ष श्री विवनने गांधीजीको इस सभामें भाषण देनेके लिए आमंत्रित किया था।

२ उन्होने श्रोताओकी एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके छोड़े जानेका विरोध करनेके लिए प्रोत्साहित किया था।

मुसीबतने हमें इस सघषमें अजीब हम बिस्तर बना दिया है। यह सवथा सत्य है कि इस स्थितिके बावजूद ब्रिटिश भारतीय अब भी किसी न-किसी प्रकार ब्रिटिश प्रजावाली भावना-से चिपके हैं और उनका विचार है कि किसी-न-किसी दिन वे इस दलीलको फलीभूत करनेमें समर्थ हो जायेंगे। जहाँतक इस बातका सम्बन्ध है, चीनी सघष ब्रिटिश भारतीय सघषसे भिन्न है, परन्तु जहाँतक इस काले कानूनके परिणामोका सम्बन्ध है, चीनी सघष ब्रिटिश भारतीयोके सघष जसा ही है, और चूकि यह कानून दोनोको समान रूपसे पीसता है, इसलिए दोनो उससे लड रहे ह। यदि एशियाई अधिनियमके रद किये जानेके बारेमें कोई औचित्य ढूँढा जाये तो मेरी रायमें इसके दो उदाहरण दिये जा सकते ह। महत्त्वकी दष्टिसे निश्चय ही पहला है, आप चीनी श्रोताओके एक देशभाईकी मृत्यु। आपके देशभाईने, जिसे वह गलती समझता था, उसके लिए आत्म-बलिदान किया है। यह दिखानेका एक क्षुद्र प्रयत्न किया गया है कि उस आदमीने अय कारणोसे अपनी जान दी। परन्तु यह स्पष्ट तथ्य है कि उस आदमीने इस काले, क्षुद्र एशियाई अधिनियमके कारण अपने प्राण दिये। दूसरा उदाहरण, जिसका उहोने उल्लेख किया, स्वय (वक्ताके) अपने देशभाइयोमें से एकका था। [उन्होंने कहा,] एक ऐसे आदमीको, जो कि पूणतया निर्दोष था और अपना जीवन अपनी समझके अनुसार सर्वोत्तम ढंगसे बितानेका प्रयत्न कर रहा था तथा अपने देशवासियोकी आध्यात्मिक आवश्यकताओकी पूर्ति कर रहा था, जेल भेजा गया और वह आज भी मात्र इसी एशियाई अधि नियमके कारण जोहानिसबगमें अबहेलित है।^१ सब तरहके अभियोग उसके विरुद्ध लगाये गये ह और उन राजद्रोहात्मक अभियोगोके लिए रचमात्र भी सबूत नहीं है। म केवल इतना ही कह सकता हूँ कि चीनी और ब्रिटिश भारतीय, यदि वे अपने प्रति ईमानदार ह, अपने देश वासियोके प्रति ईमानदार है और अपने सम्मानको अय सारी चीजोसे मूल्यवान समझते ह तो, वे उस अधिनियमको, जो अभी ही उनपर इतनी ज्यादाती कर चुका है, कभी सिर नहीं झुका सकते। यह सघष एक नतिक और धार्मिक सघष है। उहोने श्रोताओको स्मरण दिलाया कि सदाचार अपना पारितोषिक स्वय है और कहा कि यदि यह युरोपीयो और एशियाइयोके परस्पर विरोधी अधिकारोका प्रश्न होता तो सरकारने जो खल अस्तित्वार किया है वह म समझ सकता था। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह युरोपीयो और एशियाइयोके बीचका सघष नहीं है। जनरल स्मट्सके बहुत दृढ़ होनेकी ख्याति है और वे ऐसे ह भी, परन्तु जहाँतक एशियाइयोका सम्बन्ध है, उस ताकतका सबूत मिलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा है कि वे [ट्रान्सवाल सरकारके सत्ताधारी लोग] तेरह हजार ब्रिटिश भारतीयो और तेरह सौ चीनियोकी आत्माकी पुकार नहीं सुन रहे ह और उहोने एक ऐसे कामको करनेके लिए अत्यन्त सडियल रास्ता चुना है जो बहुत पहले ही अच्छे तरीकेसे किया जा सकता था। दूसरी दिसम्बरके बाद उनकी स्वतंत्रता उनकी न रहेगी, परन्तु वे गिरफ्तार हो या नहीं, वे अपने सामने उस मृत व्यक्तिकी भावनाको रखेंगे और इस सघषमें याद रखेंगे कि सदाचार अपना पारितोषिक स्वय है।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन ७-१२-१९०७

३०५ हम विरोध क्यों करते हैं

पिछले पन्द्रह महीनोमें मुश्किलसे ऐसा कोई सप्ताह गुजरा होगा जब इन पष्ठोमें एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध कोई वक्तव्य प्रकाशित न हुआ हो। और तब भी इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांश यूरोपीय तथा अनेक भारतीय भी यह नहीं बता सकेंगे कि महज पञ्जीयन कानूनका इतना तीव्र तथा सतत विरोध क्यों किया जाना चाहिए। कुछ लोगोका कहना है कि अधिनियम इसलिए आपत्तिजनक है कि उसके अनुसार एशियाइयो और उनके आठ सालसे ऊपरकी आयुवाले बच्चोको अपनी अँगुलियोके निशान देने पड़ते हैं, जब कि कुछ अन्य लोगोकी आपत्ति इस बातपर आधारित है कि यह एशियाइयोको परेशान करनेके असीम अधिकार दे देता है। हम इन आपत्तियोका महत्त्व कम नहीं आकते, लेकिन हमको यह स्वीकार करनेमें तनिक भी सकोच नहीं है कि अपने आपमें ये आपत्तियां नगण्य हैं और कमसे-कम उस बलिदानके योग्य तो नहीं ही हैं, जिसकी भारतीयोंने शपथ ली है।

तब यह जी तोड़ सघष किसलिए ? इसका उत्तर यह है कि यदि इस अधिनियमको उन घटनाओके सद्वर्णन पढा जाये जो इसके पूर्व घटित हुई और जिहोंने इसको जन्म दिया, तो ज्ञात होगा कि यह एक ऐसा कानून है जो भारतीयोको आदमी मानता ही नहीं है, जब कि भारतीय भी जीवनकी सभी सारभूत बातोंमें उतने ही सम्य होनेका दावा करते हैं जितने कि स्वयं कानून निर्माता। यह अधिनियम एक ओर तो ट्रांसवाल सरकारको यह अधिकार देता है कि वह भारतीयोके साथ, उनके विचारों और भावनाओकी कोई परवाह किये बिना, जैसा चाहे वैसा बरताव कर सकती है। दूसरी ओर सरकार इस बातसे मुक्त होती है कि उसे ऐसा कोई सहज अधिकार प्राप्त है, विशेषकर उस दशामें जब कि उसके क्रिया कलापोका सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कम करने अथवा उसपर आघात करनेसे हो।

यदि हमसे यह बतानेको कहा जाये कि सरकारका ऐसा कोई मतव्य या दावा अधिनियमकी किस धारासे प्रकट होता है तो अपनेको भावुकताके आरोपका भागी बनाये बिना किसी एक विशेष धारापर अँगुली रखना, शायद मुश्किल होगा। जिस प्रकार यह बताना सम्भव नहीं है कि अफीमके किस खास कणमें विष है, उसी प्रकार, शायद, यह बताना भी असम्भव है कि अधिनियममें यह विष कहा व्याप्त है। किन्तु किसी भी आत्माभिमानी एशियाईके लिए पूराका पूरा अधिनियम, निःसन्देह, विषसे भरा हुआ है और ऊपर बताई हुई छोटी छोटी बातोंको एक साथ मिलाकर देखनेसे यह तथ्य बिल्कुल साफ हो जाता है। इस अधिनियमके सामान्य प्रभावको केवल अनुभव किया जा सकता है उसे शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जनताने जिस भयंकर भावनाको अनजाने ही, किन्तु सचमुच सदा अनुभव किया है उसको प्रकट करनेके लिए प्रतीकोका उपयोग किया है। इस अधिनियमके प्रशासनके लिए किये गये प्रयत्नोंके सिलसिलेमें जो कुछ घटित हुआ — उदाहरणार्थ, करीम जमालपर व्यथ ही मुकदमा चलाना, प्रार्थियोकी गुप्त जाच करना, भारतीय पुजारीके मुकदमेमें चौका देनेवाले रहस्योद्घाटन — वह भारतीय जनता द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोणको भयंकर रूपसे पुष्ट करता है और उसे सवथा उचित ठहराता है।

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उसके बाद यह दिखाना, शायद, अनावश्यक है कि इसमें धार्मिक आपत्ति कहा है, किन्तु इसकी अधिक बारीकीसे जांच करना, सम्भवतः आवश्यक है, क्योंकि सदभाव रखनेवाले मित्रोंने भी यह प्रश्न किया है। उच्चतम दृष्टिकोणसे परखते हुए हम उस कारगर दलीलसे काम नहीं लेगे जो तुक मुसलमाना तथा अथ तुक प्रजाजनोके बीच किये जानेवाले मनमाने और द्वेषजनक भेदभावके रूपमें हमें प्राप्त है, कि तु हम धमात्मा पुरुषोंके सामने अपनी दलील एक सीधे सादे प्रश्नके रूपमें रखेंगे यदि यह सच हो कि भारतीय लोग शुद्ध अन्तःकरणसे यह मानते हैं कि अविनियम उनको पौरुषहीन बनाता है, उनको गिराता है, उनको प्रायः दास बना देता है तो क्या जो मनुष्यताके दर्जेसे कम हैं वे कभी परमात्माकी पूजा कर सकते हैं ? क्या वे मनुष्य, जो कानून विशेषके घातक परिणामाको अच्छी तरह जानते हुए भी उसे मात्र स्वाथपरता तथा सासारिक समृद्धिके क्षुद्र उद्देश्योंसे स्वीकार कर लेते हैं, कभी परमात्माकी सेवा कर सकते हैं ?

इस दृष्टिसे देखनेपर यह साफ हो जाता है कि यह सघष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुट्ठी भर आदमी, जिनको आम तौरपर कोई खास बहादुर नहीं समझा जाता, अपनेसे अधिक शक्तिशाली और असीम सत्ता सम्पन्न सरकारके विरुद्ध सघष कर रहे हैं। क्या वे कामयाब हो सकते हैं ? हम जोर देकर कहते हैं, हाँ— बशर्ते कि वे, जैसा अबतक करते आये हैं, अभिप्रेत परिणामके अनुपातमें ही महान बलिदान करनेको इच्छुक और प्रस्तुत हों।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०६. हम कानूनके विरुद्ध क्यों हैं ?

इस प्रश्नके उत्तरमें आज बारह महीनोंसे कुछ-न-कुछ लिखा जाता रहा है। इतना होनेपर भी हमें डर है कि लडाईकी जड़ इतनी गहरी है कि इने गिने भारतीय ही उसे ठीक तरहसे समझते हैं। यह आशा की जा सकती है कि अब सच्चे खेलका प्रसंग आ पहुँचा है। हमें उम्मीद है कि सरकार डरी हुई है तो भी सोके लगभग भारतीयोंपर हाथ डालेगी ही। यदि न डाले तो हमें सचमुच खेद होगा। यो कहना सरसरी तोरसे देखनेपर कदाचित् उचित न माना जाये, फिर भी हम अपने कथनको 'यायोचित समझते हैं, क्योंकि हमारी कसौटीका समय आ गया है। लोग जोशमें हैं। इस अवसरमें चुका कर सरकार हमारा डका नहीं बजने देगी। इसलिए फिर ऐसा अवसर और नहीं आनेवाला है। युद्धमें पहुँचा हुआ योद्धा बिना लडाई किये लौटनेपर जिस प्रकार निराश हो जाता है, ट्रांसवालके भारतीयोंकी इस समय वैसी ही दशा है। इसलिए, और कुछ नहीं, तो सौके लगभग भारतीय जेल जाये तभी लडाई जमी मानी जायेगी। यह समाचारपत्र ट्रान्सवालके पाठकोंके हाथमें पहली या दूसरी दिसम्बर तक ही पहुँच पायेगा। उस समय बहादुर लोग इस विचारसे आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि हम पहले रणमें जाये, अर्थात् बिना अपराधके पकड़ लिये जाये। और कायर घरमें दुबक कर 'हाय, पकड़ लगे तो' इस डरके मारे बिन मोतके 'मरे। मरे।' कर रहे होंगे। और दोगलोंके भाग्यमें तो ऐसे देश-प्रेमका अवसर होगा ही कहासे ? कायर और बहादुर दोनोंके लिए दो

दिसम्बरका अवसर हम भव्य मानते हैं। डरपोकोको भी वयवाद देते हैं। क्योंकि, डरते रहनेपर भी देशके हितका खयाल करके उन्होंने पजीयन करवाकर अपने नामपर बट्टा नहीं लगने दिया।

ऐसा हम किस हेतुसे लिख रहे हैं? भारतीय समाजपर ऐसा कौन-सा भारी काम आ पड़ा है? कानूनका विरोध क्यों कर रहे हैं? अब इन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करे। बहुतेरे लोगोका खयाल है कि लडाईं इसलिए चल रही है कि हमें दस अँगुलियोंकी निशानी देनेमें आपत्ति है। कुछ लोगोकी आपत्तिका केवल इसीमें समावेश हो जाता है कि उहे मा और स्त्रीका नाम देना पड़ता है। फिर, कुछ लोगोका कहना है कि पुलिस घर-घरमें जाच करेगी यह तकलीफकी बात है। यह भी सच है कि ये सारी बातें अपमानजनक हैं। दस अँगुलियोंकी निशानी केवल चोर ही देते हैं। अपमान करनेके हेतु पवित्र माका नाम लेनेके लिए कहनेपर कमरसे तलवारे निकल पड़ी हैं। सदिग्ध समझकर पुलिसने किसीसे पास मांगा तो अपमानसे जले भुने उस मनुष्यका घूसा खाकर पुलिसको धूल चाटनी पड़ी है। इतनेपर भी यदि कोई कतव्य रूपसे नहीं बल्कि विवेकपूर्वक अँगुलियोंकी निशानी देनेके लिए कहे और हम दें तो उसमें विशेष दुःख नहीं है। जिस प्रकार माला फेरकर ईश्वर — खुदाका नाम हम लेते हैं उसी प्रकार खुशी-खुशी हम माका नाम लेंगे। मतलब यह कि उपयुक्त बातें अपमान करनेके इरादेसे दाखिलकी गई हैं, इसीलिए आपत्तिजनक हैं। मूलतः उनसे हमें आपत्ति नहीं है। सभी पीले मनुष्य पीलियाके रोगी नहीं होते। परन्तु साधारणतया अस्थिपज्जर जैसे शरीरमें हम पीलापन देखेंगे तब हम मान लेंगे — उस शरीरमें पीलियाका रोग है। वैद्य पीलेपनका इलाज नहीं करेगा, बल्कि पीलिया रोगका इलाज करेगा।

तब कानूनमें पीलिया कहा है, यह देखना है। पीलापन देख लिया। पीलिया तो यह है कि इस कानूनको बनाकर गोरे लोग यह बताना चाहते हैं कि एशियाई लोग मनुष्य नहीं, पशु हैं, स्वतंत्र नहीं, गुलाम हैं, गोरोकी बराबरीके नहीं, उनसे हलके दर्जेके हैं, उनपर जो कुछ हो वह सहन करनेके लिए जमे हैं, उन्हें सिर उठानेका — विरोध करनेका अधिकार नहीं है, वे मद नहीं, नामद हैं। अँगुलियोंकी निशानी आदि लक्षणोंसे यह स्थिति — पीलिया — प्रकट हो रही है। कानून जो-कुछ करवाना चाहता है वह जबरदस्ती करवाना चाहता है। वह भारतीयोंको, जो कि साहूकार हैं, चोर ठहराता है। हमें चोर ठहराकर तथा हमारे बच्चोंको भी चोर मान कर उन्हें अशोभनीय तरीकेसे परेशान करता है और उनमें डर पैदा करता है। हमारे देशमें बालकोंको जैसे “हौवा आया” यह कहकर बचपनसे डरा देते हैं, उसी प्रकार उन्हें यहा भी डरानेके लिए यह कानून है। हमसे कोई पूछे कि यह सब कानूनकी किस धारामें है तो वह बताना कठिन हो जायेगा। धतूरेके फूल देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसमें जहर किस जगह है। उसकी परीक्षा जैसे खानेपर होती है उसी प्रकार इस कानूनको समझा जाये। इस सारे कानूनको पढ़नेवाला और समझनेवाला मद हो तो उसके रोगटे खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। यह भारतीयोंका पानी उतार देता है। और बिना पानीकी तलवार जैसे निकम्मी हो जाती है वैसे ही इस कानूनको स्वीकार करनेवाला भारतीय मदकी श्रेणीसे निकल जाता है।

अब कोई कहेगा कि धर्म-सम्बन्धी आपत्ति क्या है? यह तुर्कीके मुसलमानोंपर लागू होता है और ईसाइयों तथा यहूदियोंको छोड़ देता है। इस बातको हम भले छोड़ दें, परन्तु यह कानून यदि हमारा अपमान करनेवाला हो और हमें जानवरकी भाँति रखनेवाला हो तो हम यह सवाल करते हैं कि क्या जानवर कभी खुदाको पहचानता है? क्या वह धर्म समझता है?

वास्तवमे यह कानून एशियाई और गोरोके बीचका युद्ध है। गोरे कहते हैं, “ हम एशियाइयोको केवल यत्रके समान अपनी गधा-मजूरी करवानेके लिए ही रखेंगे। ” भारतीय लोग ट्रान्सवालमे कानूनका विरोध करके कहते हैं, “ हम रहेंगे, तो स्वतंत्र मदके रूपमे और सामान्य व्यवहारमे बराबरीवालोके रूपमे रहेंगे ? ” वास्तवमे कानूनका मतलब यही है। ऐसी लड़ाईमे बलवानसे टक्कर लेकर जीतना कठिन और सरल दोनों है। कठिन इसलिए कि बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। सरल इसलिए कि मनुष्य देशकी भलाईके लिए, समाजके कल्याणके लिए कष्ट उठानेमे सुख मानता है।

मैं बिना किसी हिचकिचाहटके कहूँगा कि जा मनुष्य यह प्रश्न करता है कि बलवान ओर सब प्रकारसे — धनसे, शरीरसे, शस्त्रसे समथ गोरोके मुकाबलेमे मुट्ठीभर भारतीय कैसे जीतेगे, उसको खुदापर पूरा भरोसा नहीं है। हम कैसे भूल जायेंगे कि —

जनम्या ते मरवा माट हिमत नहीं हारो,

समरथ छे मालिक साथ, रहम करनारो।

फिर, समथ हानेपर भी जब कोई अत्याचार करता है तब क्या होता है यह हमें बताया गया है

कहा मनसूर खुदा मैं हूँ यू ही कहता था आलम को।

गया सूली प चढनेको, तेरा दुश्वार जीना है॥

इस लड़ाईमे हमारी जीतके लिए एक ही शत है, सो यह कि हमारी हिम्मत सच्ची होनी चाहिए। हमारी मुसीबत उठानेकी शक्तिरूपी तलवार लकड़ीकी नहीं, बल्कि पानी चढ़ी फौलाद की होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०७ हमारा परिशिष्ट

श्री अमीरुद्दीन फजदारका स्वदेश लौटनेका प्रसंग आया इसलिए [भारतीय राष्ट्रीय] कांग्रेसके प्रतिनिधिकी बात चली थी। श्री अमीरुद्दीनने शुरूसे ही कानूनके खिलाफ चुस्तीसे जोश बताया था। इसलिए जब उनके स्वदेश जानेकी बात हुई तब उनसे कुछ मित्रोंने पूछा कि वे स्वयं प्रतिनिधि बनेगे या नहीं। श्री अमीरुद्दीनने तुरंत ही बीड़ा उठा लिया। वे यह कह कर गये हैं कि भारतमे पहला काम वे यही करेंगे। इस बार हम उनका चित्र प्रकाशित कर रहे हैं।

श्री अमीरुद्दीनकी आयु छत्तीस वर्ष है। उनके मातापिता जमींदार थे। इसीलिए उनका आस्पद फजदार है। वे प्रसिद्ध झटाम परिवारके हैं। सन १८८८ मे पहले पहल ट्रान्सवाल आये तब अहमद कासिम कमरुद्दीनकी प्रसिद्ध पेढीमे मुशीके रूपमे बहाल हुए। १८९३ तक उनके यहां नोकरी करनेके बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। उनकी पेढीका नाम है

मुहम्मद हुसैन कम्पनी। बहुतेरे गोरोंने उन्हें माल न देनेका डर दिखाकर पजीयन करवानेके लिए प्रलोभन दिया। लेकिन उन्होंने अपनी एक ही टेक रखी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०८ खूनी कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम

हम इस अकमे नया कानून तथा उसके अतगत बनाये गये विनियमोंका अंग्रेजी और गुजराती रूपांतर दे रहे हैं। हम गुजराती अनुवाद पहले भी दे चुके हैं^१। इस बारका अनुवाद कुछ विस्तारसे किया है। अब उसके साथ-साथ शांति रक्षा अध्यादेशके खण्ड भी दिये जा रहे हैं। इसके सिवा इस अकमे दूसरी महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इसलिए यह अक प्रत्येक भारतीयको ध्यानसे पढ़ना और सँभालकर रखना चाहिए। हम यह जानते हैं कि नया कानून और उसके विनियम ही कानूनके विरोधमें सर्वश्रेष्ठ दलीलें हैं। इसलिए यह कानून तथा इसके विनियम हम पुस्तकके रूपमें गुजराती तथा अंग्रेजीमें भी प्रकाशित कर रहे हैं। उसकी कीमत ६ पैसे रखी गई है। हमें विश्वास है कि भारतमें भी यह अक तथा इस कानूनकी पुस्तिका घर-घरमें पहुँचेंगी।

- १ १८८५ का कानून ३ निम्न परिवर्तनके साथ कायम रहेगा।
- २ एशियाई, यानी कोई भी भारतीय कुली अथवा तुर्कीकी मुसलमान प्रजा। इसमें मलायियो और गिरमिटमें आये हुए चीनियोंका समावेश नहीं होता। (इसके अलावा, पजीयन अधिकारी आदिकी व्याख्या दी गई है। उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।)
- ३ ट्रांसवालमें वैध रूपसे रहनेवाले प्रत्येक एशियाईको पजीकृत हो जाना चाहिए। इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा।

निम्न व्यक्ति ट्रांसवालमें वैध रूपसे रहनेवाले एशियाई माने जायँगे।

- (क) जिस एशियाईको अनुमतिपत्र कानूनके अतगत अनुमति मिली हो, बशर्ते कि वह अनुमतिपत्र धोखेसे अथवा गलत ढंगसे प्राप्त किया गया न हो। (मुद्दती अनुमतिपत्रोंका समावेश इसमें नहीं होता।)
- (ख) प्रत्येक एशियाई जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वी तारीखको ट्रांसवालमें रहा हो।
- (ग) जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वी तारीखके पश्चात् ट्रांसवालमें जमा हो।

- ४ प्रत्येक एशियाई, जो इस कानूनके अमलमें आनेकी तारीखको ट्रांसवालमें मौजूद हो, उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई तारीखसे पहले निर्धारित स्थानपर निर्धारित अधिकारीके यहाँ पजीयनके लिए आवेदनपत्र दे। कानूनके अमलमें लाये जानेकी तारीखके बाद ट्रांसवालमें प्रवेश करनेवाला प्रत्येक एशियाई, यदि उसने इस कानूनके

अतगत नया पजीयनपत्र न लिया हो, तो, पजीयनके लिए अपना आवेदनपत्र प्रविष्ट होनेके आठ दिनके अन्दर भेज दे। परन्तु

(क) इस धाराके अनुसार आठ वर्षसे कम उम्रके बालकके लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है।

(ख) आठ वर्षसे सोलह वर्ष तक के बालकके लिए उसका अभिभावक पजीयनका आवेदनपत्र दे। और अगर वैसे आवेदनपत्र न दिया गया हो तो सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद बालक स्वयं दे।

५ पजीयक वैध रूपसे रहनेवाले एशियाईके आवेदनपर ध्यान देगा। पजीयक उपर्युक्त एशियाईको तथा जिसे वह माय करे ऐसे एशियाईको पजीयनपत्र दे।

यदि पजीयन अधिकारी किसी एशियाईके आवेदनको अस्वीकृत कर दे, तो उस एशियाईको न्यायाधीशके समक्ष उपस्थित होनेके लिए वह कमसे कम १४ दिनका नोटिस दे, और यदि निश्चित तारीखपर वह उपस्थित न हो, अथवा उपस्थित रहते हुए भी न्यायाधीशको अपने ट्रान्सवालमे रहनेके अधिकारके सम्बन्धमे सन्तुष्ट न कर सके और वह १६ वर्षकी आयुका हो तो, उसे न्यायाधीश ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दे। और इस हुक्मपर १९०३ के शांति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ६, ७ और ८ लागू होंगे। यदि न्यायाधीशको विश्वास हो जाये कि उपर्युक्त एशियाई वैध निवासी है तो उसे पजीयन अधिकारीको पजीयनपत्र देनेका आदेश देना चाहिए।

६ जो एशियाई आठ वर्षसे कम आयुके किसी बालकका अभिभावक हो, उसे अपना आवेदनपत्र देते समय कानूनके अनुसार पजीयन अधिकारीको उस बालकका विवरण और हुलिया दना चाहिए। यदि उस व्यक्तिका आवेदन स्वीकृत किया गया तो उसके पजीयनपत्रपर वह विवरण और हुलिया लिख दिया जायेगा। फिर, उस बालकको आठ वर्षकी उम्र हो जानेपर एक वर्षके अन्दर पजीकृत करनेके लिए वह अपने जिला न्यायाधीशके मारफत दुबारा अर्जी दे।

ट्रान्सवालमे जन्मे हुए बालकका एशियाई अभिभावक बालककी आठ वर्षकी आयु होनेपर एक वर्षके अंदर उसे पजीकृत करनेके लिए अर्जी दे।

(क) यदि अभिभावक उक्त प्रकारसे आवेदन न दे तो पजीयन अधिकारी या न्यायाधीश जो समय निश्चित करे उस समय अभिभावक अर्जी दे।

(ख) यदि अभिभावक आवेदन न दे, अथवा आवेदन दिया गया हो किन्तु अस्वीकृत हो गया हो, तो १६ वर्षकी आयु हो जानेपर वह बालक स्वयं एक सालके अंदर आवेदन करे। जिस न्यायाधीशके पास ऐसा आवेदनपत्र पहुँचे वह उस आवेदनके साथ सभी कागज पजीयकको भेज दे और यदि पजीयक ठीक समझे तो, आवेदकको पजीयनपत्र दे दे।

७ अभिभावकने उपर्युक्त प्रकारसे आठ वर्षके बालकका नाम और हुलिया दर्ज न कराया हो और आठ वर्षके बाद बालकका पजीयनपत्र न लिया हो तो १६ वर्षकी उम्र हो जानेपर बालक स्वयं एक महीनेके अन्दर आवेदन करे। और पजीयकको उचित मालूम हो तो वह उसका पजीयन कर दे।

- ८ इस कानूनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने या बालकके पजीयनके लिए उपर्युक्त ढंगसे आवेदन नहीं देगा तो उसपर १०० पौड तक जुर्माना होगा, और जुर्माना न देनेपर उसे तीन महीने तक की कड़ी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सोलह वर्षसे कम आयुवाले एशियाईको ट्रांसवालमे लायेगा, जो यहाका वैध निवासी न हो, और जो व्यक्ति उस लडकेको नौकर रखेगा, वे दोनों अपराधी समझे जायेंगे, और उन्हें उपयुक्त प्रकारसे सजा दी जायेगी, यदि ऐसे व्यक्ति एशियाई हुए तो उनका पजीयन खारिज कर दिया जायेगा और उन्हें ट्रांसवाल छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा। यदि वे ट्रांसवाल नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें कानूनके मुताबिक जुर्माने या जेलकी सजा दी जायेगी, और शांति-रक्षा अध्यादेशके खण्ड ६, ७ और ८ उसपर लागू होंगे।

सोलह वर्षसे ज्यादा उम्रवाला जो भी एशियाई उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई अवधिके पश्चात् ट्रांसवालमे बिना पजीयनके पाया जायेगा उसे ट्रांसवाल छोड़नेका आदेश दिया जायेगा और यदि वह ट्रांसवाल नहीं छोड़ेगा तो उसे जुमाने अथवा कदकी सजा होगी।

उपयुक्त प्रकारसे पजीयनरहित एशियाई पजीयनका आवेदन न देनेका न्यायालयको सन्तोषप्रद कारण बतायेगा तो उसे न्यायाधीश आवेदन करनेके लिए मोहलत दे सकता है। और उस अवधिमे यदि वह पजीयन न कराये तो उसे फिर ट्रांसवाल छोड़ने या सजा भोगनेका आदेश दिया जायेगा।

- ९ सोलह वर्षकी आयुवाला जो कोई एशियाई ट्रांसवालमे प्रवेश करेगा अथवा रहता होगा उसे कोई भी पुलिस या उपनिवेश सचिव द्वारा आदिष्ट व्यक्ति पजीयनपत्र दिखानेके लिए कह सकेगा, और इस कानूनकी धाराओके अनुसार निर्धारित विवरण तथा हुलिया माग सकेगा।

सोलह वर्षसे कम उम्रवाले एशियाईका अभिभावक उस बालकका पजीयनपत्र दिखाने और विवरण तथा हुलिया प्रस्तुत करनेके लिए उपयुक्त प्रकारसे बाध्य है।

- १० जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके अनुसार प्राप्त किया हुआ नया पजीयन पत्र होगा उसे ट्रांसवालमे रहने और प्रवेश करनेका हक है। किन्तु जिसे शांति-रक्षा अध्यादेशके खण्ड १० के अन्तर्गत हुक्म मिला हो, उसे यह हक नहीं है।
- ११ जिस व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्तिका पजीयनपत्र अथवा मियादी अनुमतिपत्र मिले उसे सारे दस्तावेज तत्काल पजीयकके पास भेज देने चाहिए। यदि वह नहीं भेजेगा तो उसका ५० पौड तक जुर्मानेकी अथवा एक महीनेकी कड़ी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।
- १२ जिस व्यक्तिका पजीयनपत्र खो जाये उसे तुरन्त नये पजीयनपत्रके लिए अर्जी देनी चाहिए। उस अर्जीमे कानूनके मुताबिक सारा विवरण दिया जाये और उसपर पांच शिल्लिकके टिकट लगाये जाये।
- १३ 'गजट' मे निर्धारित की गई तारीखके पश्चात् किसी भी एशियाईको राजस्व या नगरपालिका कानूनके अनुसार तबतक परवाना नहीं दिया जायेगा जबतक वह अपना पजीयनपत्र न दिखाये तथा माँगी हुई हकीकत व हुलिया न दे दे।

- १४ किसी भी एशियाईकी आयुका प्रश्न खड़ा होनेपर यदि वह प्रमाणोंके साथ आर कोई आयु सिद्ध न कर सके तो पजीयक द्वारा निश्चित की हुई आयु ही सही मानी जायेगी।
- १५ इस कानूनके अन्तर्गत जो हलफनामा देना पड़ेगा उसपर टिकटकी आवश्यकता नहीं है।
- १६ जो व्यक्ति पजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें कुछ धोखा देगा, अथवा झूठ बोलेगा, अथवा दूसरे व्यक्तिको झूठ बोलनेके लिए प्रोत्साहन देगा या सहायता करेगा, अथवा जाली पजीयनपत्र काममें लायेगा, अथवा वैसा पजीयनपत्र दूसराको काममें लानेके लिए देगा, उसपर ५०० पौंड तक जुर्माना होगा, अथवा दस वर्ष तक की कड़ी या सादी कैदकी सजा होगी।
- १७ उपनिवेश सचिव अपनी इच्छानुसार किसी भी एशियाईको मुद्दती अनुमतिपत्र दे सकते हैं। उस अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त हो जानेपर वह व्यक्ति बिना अनुमतिपत्रका माना जायेगा। फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसपर शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ७, ८ और ९ लागू होंगे, और उस कानूनकी रूसे उसे उपनिवेश छोड़नेका हुक्म हो गया है, ऐसा मानकर सजा दी जायेगी। आजतक ऐसे जितने भी अनुमतिपत्र दिये जा चुके हैं उन सबपर यह कानून लागू समझा जायेगा। मियादी अनुमतिपत्रवालेको शराबकी छूट मिल सकती है। अलावा इसके, जिन एशियाइयोंपर यह कानून लागू नहीं होता, उन्हें भी उपनिवेश सचिव शराबकी छूट दे सकते हैं।
- १८ गवर्नर निम्न लिखित कामोंके लिए नियम बना सकते हैं
 - (१) पजीयनपत्र किस प्रकारका रखा जाये।
 - (२) पजीयनपत्रके लिए अर्जी किस प्रकार की जाये, किस रूपमें दी जाये, उसमें दी जानेवाली हकीकतें क्या हों, हुलियामें क्या-क्या लिखा जाये।
 - (३) पजीयन प्रमाणपत्र किस प्रकारका लिया जाये।
 - (४) जाठ वर्षसे कम आयुवाले बालकका अभिभावक, वह एशियाई जिससे खण्ड ९ के अनुसार पजीयनपत्र मांगा जाये, खोये हुए पजीयनपत्रकी प्रतिलिपि मागनेवाला एशियाई तथा व्यापारिक परवानेके लिए अर्जी देनेवाला कोई भी एशियाई क्या क्या हकीकतें, और कौन कौनसा हुलिया दे।
 - (५) खण्ड १७ के अनुसार किस प्रकार अनुमतिपत्र दिया जाये।
- १९ प्रत्येक एशियाई अथवा एशियाईके अभिभावकपर, यदि वह अपने लिए ऊपर निर्दिष्ट की गई बातें नहीं करता, और यदि इसके लिए कोई अन्य सजा निर्धारित नहीं की गई है, १०० पौंड तक जुर्माना किया जायेगा अथवा उसे तीन महीने तक का सपरिग्रम या सादा कारावास दिया जायेगा।
- २० चीनियोंसे सम्बन्धित नौकरीका कानून [श्रम आयात अध्यादेश] एशियाइयोंपर लागू नहीं होगा।
- २१ १८८५ के कानूनकी तारीखसे पहले यदि किसी एशियाईने अपने नामपर जमीन खरीदी होगी तो उसके उत्तराधिकारीको वह जमीन पानेका अधिकार होगा।
- २२ जबतक सम्राट् स्वीकृति न दे और वह स्वीकृति 'गजट' में प्रकाशित न हो जाये तबतक यह कानून अमल नहीं आयेगा।

नये कानूनमें उल्लिखित १९०३ के शान्ति-रक्षा अध्यादेशके कुछ खण्ड

- ६ जो व्यक्ति पंजीयन न होनेके कारण गिरफ्तार किया जायेगा उसे सीधे मजिस्ट्रेटके पास ले जाया जाये। और यदि वह व्यक्ति उपनिवेशमें रहनेका अपना हक साबित न कर सके, तो उसे मजिस्ट्रेट अपनी मर्जीके मुताबिक निश्चित अवधिके भीतर उपनिवेश छोड़नेका नोटिस दे। परन्तु यदि वह व्यक्ति यह बता सके कि उसके पास अनुमतिपत्र है, किन्तु उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता, अथवा यह बता सके कि वह उस वगका व्यक्ति है जिसे अनुमतिपत्र रखनेकी आवश्यकता नहीं है, तो बादमें अधिक प्रमाण पेश करनेके लिए मजिस्ट्रेट उसकी जमानत लेकर उसे छोड़ सकता है। यदि वह जमानतकी शर्तें तोड़े, तो जमानतपत्रके मुताबिक उसका पसा जस्त कर लिया जायेगा।
- ७ जिस व्यक्तिको उपनिवेश छोड़नेका हुक्म दिया गया हो, पर उसने उपनिवेश नहीं छोड़ा हो, तो उसे तथा जिस व्यक्तिको उसकी जमानत ली हो और जमानतकी शर्त उपयुक्त धाराके अनुसार टूट गई हो तो उसे भी बिना वारंटके गिरफ्तार किया जा सकता है। गुनाह साबित होनेपर मजिस्ट्रेट उन्हें कमसे कम एक महीने और अधिकसे अधिक ६ महीनेकी सरत अथवा सादी कदकी सजा दे सकता है। साथ ही वह उसे ५०० पौंड जुर्माना कर सकता है। तथा जुर्माना न देनेपर ६ महीने तक की अतिरिक्त कैदकी सजा दे सकता है।
- ८ उपयुक्त धाराके मुताबिक जेलकी सजा भोगकर छूटनेपर यदि कोई व्यक्ति [उपनिवेश-सचिवसे लिखित^१ आज्ञा लिये बिना] उपनिवेशमें ७ दिनसे अधिक रहेगा, तो उसपर फिरसे मुकदमा चलाया जायेगा और उसे कमसे कम ६ महीने और अधिकसे अधिक १२ महीनेकी जेलकी सजा देने अथवा ५०० पौंड तक जुमाना करने और यदि वह न दे तो अतिरिक्त ६ महीने तक की जेलकी सजा देनेका मजिस्ट्रेटको अधिकार है।
- ९ जो व्यक्ति
 - (१) झूठे तरीकेसे अनुमतिपत्र लेगा अथवा दूसरेको लेनेमें मदद करेगा,
 - (२) और झूठे ढंगसे लिये हुए अनुमतिपत्रका उपयोग करेगा अथवा दूसरेसे करवायेगा,
 - (३) अथवा झूठे ढंगसे मिले हुए अनुमतिपत्रके सहारे, अथवा जो अनुमतिपत्र बाकायदा नहीं मिला हो उसके सहारे दाखिल होगा, अथवा दाखिल करानेका प्रयत्न करेगा, उस मनुष्यको ५०० पौंड तक का जुर्माना होगा, अथवा २ वर्ष तक की जेलकी सजा दी जायेगी, या दोनों सजाएँ मिलेंगी।
- १० जब वाजिब कारणोंसे लेफ्टिनेन्ट गवर्नरको सतोषजनक ढंगसे इस बातका विश्वास हो जायेगा कि अमुक व्यक्ति उपनिवेशमें शांति अथवा सुशासनको खतरा पहुँचानेवाला है, तब वह उस व्यक्तिको निश्चित अवधिके भीतर उपनिवेश छोड़नेको हुक्म दे सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अवधि बीतनेपर उपनिवेशमें देखा जायेगा तो उसके विरुद्ध ऊपर बताये गये खण्ड ७ और ८ के मुताबिक मुकदमा चल सकता है और उनके मुताबिक उसे सजा मिल सकती है।

१ ये शब्द अंग्रेजी पाठके आधारपर जोड़े गये हैं।

खूनी विनियम

यह कानून एक पुस्तिकाके आकारमें प्रकाशित हुआ है। कीमत है ६ पेनी, डाकखच आधा पेनी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०९ पत्र उच्चायुक्तके निजी सचिवको

२१-२४ कोट चेम्बर्स

नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्ट्रीट

पो० आ० बॉक्स ६५२२

जोहानिसबग

दिसम्बर ३, १९०७

निजी सचिव

परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त

जोहानिसबग

महोदय,

श्री डेविड पोलकने मुझे अभी श्री हास्केनका एक सदेश दिया है जिसमें मुझे सुझाया गया है कि एशियाई कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमें जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके विषयमें मैं परमश्रेष्ठसे निजी रूपमें मिलूँ और उनके सम्मुख वह बात रखूँ, जो मेरी समझसे एशियाई जातियोंकी माय हो और साथ ही सरकारके मुख्य उद्देश्यकी भी पूरा करे।

मैं अब जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसकी प्रस्तावनामें यह कहना शायद जरूरी नहीं है कि इस मामलेमें मुझे जो रख अपनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है उसमें मेरी इच्छा जितनी अपने देशवासियोंकी सेवा करनेकी है उतनी ही सरकारकी सेवा करनेकी भी है। मैंने जिन बातोंको इस साम्राज्यकी खूबी समझा है, उनके कारण मैं अपनेको उसका भक्त मानता हूँ। इसीलिए मैंने यह देखकर—चाहे मेरा देखना सही हो या गलत—कि एशियाई कानून सशोधन अधिनियममें साम्राज्यके लिए खतरेके बीज छिपे हुए हैं, अपने देशवासियोंको किसी भी कीमतपर, अत्यंत शांतिपूर्ण और, कहूँ तो, शिष्ट ढंगसे इस अधिनियमका विरोध करनेकी सलाह दी है।

सरकारका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक भारतीयकी, जो इस उपनिवेशमें रहने और प्रवेश करनेका अधिकारी है, शिनाख्त करना है। मेरी विनम्र सम्मतिमें यह उद्देश्य प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियममें सशोधन करके पूरा किया जा सकता है। इस अधिनियमपर अभी सम्राट्की स्वीकृति नहीं मिली है और मेरा विश्वास है कि उसके वर्तमान स्वरूपमें उसे स्वीकृति

१ इसके बाद खूनी धाराओका ब्योरा और फॉर्म दिये गये हैं, जिनके लिए देखिए “खनी कानून”, पृष्ठ ७५ ८० और परिशिष्ट ४।

नहीं मिलेगी। मेरी विनम्र सम्मतिमें स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव शांति रक्षा अथवा देशके रद्द हो जानेकी सम्भावनाको देखते हुए, अधिक उपयोगी न होगा, क्योंकि जो भी पजीयन प्रमाणपत्र लिये जायेंगे वे शांति रक्षा अध्यादेशके बिना बेकार होंगे। इसलिए मैं निम्न सुझाव देनेका साहस करता हूँ।

(क) सरकारी 'गजट' में इस अधिनियमके अंतर्गत पजीयनके सम्बन्धमें प्रकाशित सूचनाएँ वापस ले ली जायें,

(ख) सदनके अगले अधिवेशनमें प्रवासी-प्रतिबंधक अधिनियममें ऐसा संशोधन कर दिया जायें कि जो भारतीय उपनिवेशमें शांति रक्षा अध्यादेशके अंतर्गत रहने या प्रवेश करनेके अधिकारी हों, या जिनके पास १८८५ के कानून ३ के अंतर्गत तान पौड़ी पजीयन प्रमाणपत्र हों और जो उनके सम्बन्धमें अपना अधिकार सिद्ध कर सकें, उनको अधिवास प्रमाणपत्र देनेकी व्यवस्था हो जायें। अधिवास-प्रमाणपत्र पजीयन प्रमाणपत्रका स्थान लेंगे और उनमें पूरी शिंनारत — हुलिया — दर्ज होगी। इसमें अधिवासी एशियाइयोंके अवयस्क बच्चोंके प्रमाणपत्रोंका समावेश नहीं होता, किंतु किसी प्रकारकी जाली कारवाई न हो इसके लिए उनके नाम और आयु अधिवास प्रमाणपत्रोंमें दे दिये जायेंगे। इससे ज्यादासे ज्यादा जो भी हों लेकिन उपनिवेशमें एशियाई बच्चोंकी सरयामें अवध वृद्धि कदापि नहीं हो सकती बल्कि सम्भवतः छद्म परिचय भी बहुत थोड़े से मामलोंमें होगा और उसके विरुद्ध भी प्रवासी-प्रतिबंधक अधिनियमके अंतर्गत कड़ी कारवाई की जा सकती है। संशोधनमें उन एशियाइयोंके लिए भी जो शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा पास कर सकेंगे, अधिवास-प्रमाणपत्र लेनेकी बात शामिल नहीं है। जैसी उपधारा इस समय है उसके अंतर्गत यह परीक्षा काफी कड़ी है और इसलिए यह अपने आपमें शिंनारतका पूरा साधन प्रस्तुत कर देती है। संशोधनसे एशियाई अधिनियम भी रद्द हो जायेगा।

यह देखते हुए कि पजीयनके बिना पंद्रह महीने बीत गये हैं, कदाचित् तीन या चार महीने और बीतनेसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किंतु यदि सरकारका विचार दूसरा हो, तो सादर निवेदन है कि सूचनाएँ वापस लेनेपर वहां, भारतीय समाजकी सदाशयताकी परीक्षा करनेके लिए ही सही, वर्तमान कागजोंकी जगह पजीयन प्रमाणपत्र जारी कर सकती है। ये प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियममें संशोधनके समय अधिवास प्रमाणपत्र मान लिये जा सकते हैं।

मेरी सम्मतिमें, एशियाई अधिनियमको स्वीकृत करनेका मुख्य कारण "बड़े पैमानेपर" चोरीसे प्रवेश करनेका आरोप था। चकि मैंने एकके बाद एक अनेक अधिकारियोंके अधीन एशियाई विभागके संचालनको सदा निकटसे देखा है इसलिए मुझे यह बात सदा ही बहुत खटकी है। कप्तान फाउलने जिन प्रमाणोंके आधारपर यह माना था कि बहुत कम भारतीय चोरी छिपे आते हैं, उही प्रमाणोंका प्रयोग करके श्री चैमनेने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिया। मेरा अब भी विश्वास है कि श्री चैमने जिस पदपर हैं उसके लिये वे सवथा अयोग्य हैं, क्योंकि उनमें प्रमाणोंकी सूक्ष्म जांच करनेकी कानूनी योग्यता बिल्कुल नहीं है। मेरे मनमें व्यक्तिशः उनके विरुद्ध कुछ नहीं है। वे शिष्ट और सन्देशों परे हैं, किन्तु इन दोनों गुणोंसे उस अतिरिक्त योग्यताकी कमी पूरी नहीं होती जो उस पदके लिए, जिसपर वे हैं, अनिवार्य है। इसलिए

मैं वतमान प्रमाणपत्रोंके परिवर्तनके विकल्पके रूपमें यह सुझानेका साहस करता हूँ कि चोरी-छिपे प्रवेशके आरोपकी जाचके लिए सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशको, या विटवॉटसरड जिलेके मुख्य न्यायाधीशको या किसी दूसरे ऊँचे अधिकारीको जिसे कानूनी ज्ञान हो, नियुक्त किया जाये। वह ऐसी प्रत्येक बातके सम्बन्धमें, जो एशियाई विभागके अधिकारी उसके सामने रखे, प्रतिवेदन दे सकेगा, और यदि जाच जनताके लिए खुली हो और गवाहोंसे खुली पूछताछ की जाये तो उससे ट्रांसवालके लोगोंकी चिन्ता दूर होगी जो प्रतिवेदन दिया जायेगा उस पर कोई सन्देह न कर सकेगा एवं उससे कदाचित इस पत्रमें मुझाये गये सशोधनका माग प्रशस्त हो जायेगा।

मैं शिनारतके तरीकोंकी जाच करने और अँगुलियोंके निशानोंके प्रश्नपर जानबूझ कर नहीं विचार कर रहा हूँ क्योंकि वह एक गौण प्रश्न है। यदि एशियाई अधिनियमको रद्द करने और भारतीय समाजका सहयोग लेनेका विचार मान लिया जाये तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अथ कठिनाइया दूर हो जा सकती ह।

यदि आवश्यकता होगी तो मैं कानूनी भाषामें प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमके सशोधनको प्रस्तुत करनेके लिए तैयार हूँ। मेरी विनम्र सम्मतिमें इनमें एशियाई अधिनियमका उद्देश्य जहातक शिनारतका सम्बन्ध है, बिल्कुल पूरा हो जाता है और ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंको भी किसी तरह ठेस नहीं पहुँचती।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

आकाइन्ज ऑफ ट्रांसवाल गवर्नर, प्रिटोरिया फाइल ५३/११/१९०७।

३१० मुहम्मद इशाकका मुकदमा^१

[फोक्सरस्ट

दिसम्बर ६, १९०७]

श्री गाधीने जो अपराधीके वकील थे, सोचा कि कानूनके महकमेके अनिणयका उसके मुवक्किलके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और विशेषकर उस दशामें, जब वह गिरफ्तार है और जमानतपर छूटनेमें इनकार करता है। यदि उसके विरुद्ध कोई निश्चित अभियोग नहीं लगाया जा सकता तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। सरकारके लिए

१ मुहम्मद इशाक, जो पेशेसे एक बावर्ची था, भारतसे लौटनेपर फोक्सरस्टमें गिरफ्तार किया गया। बोअर युद्धसे पहले वह ट्रांसवालमें चार वर्ष रह चुका था। शान्ति रक्षा अध्यादेश और १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत उसे एक अनुमतिपत्र और एक पजीयन प्रमाणपत्र दिया गया था। वह डी'विलियर्स सहायक अधिवासी मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश किया गया और उसने जमानतपर छूटनेसे इनकार किया। परन्तु सार्वजनिक अभियोगता श्री मैज्ज उम अपराधीके विरुद्ध अभियोग लगाये नानेके बारेमें द्वितीयतरीकी तब भी प्रतीक्षा कर रहे थे।

उसको पुनः गिरफ्तार करनेका माग तब भी खुला रहेगा, क्योंकि उनके मुवक्किलकी यह देश छोड़नेकी इच्छा नहीं है, वरन् यहाँ बने रहनेके अपने अधिकारका दावा करनेकी है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३११ पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबर्ग

दिसम्बर ७, १९०७ के पूर्व

सेवामे

माननीय उपनिवेश सचिव

[प्रिटोरिया

महोदय,]

मेरे सघने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपका ध्यान परिवहन-उपनियमोंके उस सशोधनकी ओर आकर्षित करूँ, जो जोहानिसबर्ग नगरपालिकाने प्रथम श्रेणीकी घोडागाड़ियोंके सम्बन्धमे पास किया है।^१ यदि सरकार इस सशोधनको स्वीकार कर लेती है तो इससे ब्रिटिश भागतीयों द्वारा प्रथम श्रेणीकी घोडागाड़ियोंके उपयोगपर रोक लग जायेगी। मेरे सघका निवेदन है कि इस प्रकारका भेदभाव सवथा अनावश्यक और क्षोभकारी होगा।

कुछ विशेष धधोमे लगे एशियाइयोंको जो छूट दी गई है उससे तो समाजने अपमानका ही अनुभव किया है, और कुछ नहीं। प्रसंगवश, मेरा सघ आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि जहाँ किसी उदात्त धधोमे लगे लोग प्रथम श्रेणीकी घोडागाड़ियोंका उपयोग कर सकते हैं, उनकी पत्निया तथा उनके बच्चे स्पष्टतः इस सुविधासे वंचित हैं।

मेरा सघ यह विश्वास करनेका साहस करता है कि सरकार कृपाकर उस समाजके साथ, जिसका मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है, याय करनेके लिए उक्त सशोधनको अस्वीकार कर देगी।

[आपका, आदि,

ईसप मियाँ

अध्यक्ष,

ब्रिटिश भारतीय सघ]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

१ और आगे वइसके बाद मजिस्ट्रेटने इस मामलेको जोहानिसबर्ग वापस भेज दिया जिससे खर्च और देरी बचाई जा सके। उसने मुहम्मद इशाकको स्वयं अपने विबधपर छोड़ दिये जानेकी आज्ञा दी। जब ११ दिसम्बरको जोहानिसबर्गमे यह मामला श्री जॉर्डनके समक्ष सुनवाईके लिए लाया गया तब उसी धाराके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया जिसके अन्तर्गत ९ दिसम्बरको ३७ भारतीयोंका मुकदमा सुना गया था। (देखिए "भारतीयोंका मुकदमा", पृष्ठ ४१९-२०)। जो गवाहियों गुजरी वे भी उसी प्रकारकी थी। इंडियन ओपिनियनने १४-१२-१९०७ को इसका यह विवरण छपा। श्री गांधीने अपराधीकी ओरसे बिना कोई गवाह पेश किये उसकी रिहाईकी माँग की। श्री जॉर्डनने एक विचारपूर्ण फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने शान्ति रक्षा अध्यादेशकी उन धाराओंकी पूर्ण व्याख्या की जिनका इस मामलेसे सम्बन्ध था, और अपराधीकी रिहा कर दिया। अदालत भारतीयोंसे ठसाठस भरी थी।

२ देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको", पृष्ठ २०९।

३१२ पत्र उच्चायुक्तको

[जोहानिसबग
दिसम्बर ७, १९०७ के पूव]

[उच्चायुक्त
प्रिटोरिया

महोदय]

इस पत्रके साथ मैं परमश्रेष्ठके विचाराथ सादर एक प्राथनापत्र^१ भेज रहा हूँ। इसपर जमादार नवाबखा और फजले इलाहीने उन लोगोकी ओरसे हस्ताक्षर किये हैं, जिनका ये प्रति निधित्व करते हैं। उन लोगोके नाम भी प्राथनापत्रसे सलग्न सूचीमें दिये गये हैं। यह प्राथना-पत्र मैं उन पजाबी, पठान, और सिखोके अनुरोधपर भेज रहा हूँ, जो ट्रांसवाल निवासी ब्रिटिश प्रजाजन ह।

इस प्राथनापत्रको भेजने हुए मैं जानता हूँ कि यदि, कदाचित् परमश्रेष्ठने इसमें हस्तक्षेप किया भी तो वह बड़ी कठिनाईसे ही ऐसा करना स्वीकार करेगे। परन्तु ये प्रार्थी पुराने सैनिक हैं, जो ब्रिटिश सरकारके लिए लड़े हैं और वेशक आज भी उसके लिए और ब्रिटिश झंडेके नीचे लड़नेको तैयार ह। जहातक इनका सम्बन्ध है, मुझे यह स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं कि इनकी स्थिति कितनी गम्भीर है। मेरी तुच्छ रायसे यह आवश्यक है कि जिन कष्टोसे वे गुजर रहे हैं उन्हें दूर करनेके कुछ कदम उठाये जायें। उन्हें स्थानीय सरकार द्वारा अथवा साम्राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।

मैंने इनकी अर्जी लिखनेका काम बड़े ही असमजससे हाथमें लिया था। परन्तु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस साम्राज्यसे मेरा नाता है उसके प्रेमीकी हैसियतसे मेरा यह कतव्य है कि उनकी भावनाओको उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान करूँ। उनमें से कुछ लोग दक्षिण आफ्रिकामें अपने सम्राटके सर्वोच्च प्रतिनिधिके समक्ष अपने दुःख व्यक्तिगत रूपसे रखनेको आतुर थे, और अब भी हैं। तथापि मैंने उन्हें समझा दिया है कि ऐसी प्राथना स्वीकार होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। इसका कारण न केवल परमश्रेष्ठपर कामका बहुत अधिक भार है, बल्कि शायद प्रार्थियों द्वारा ऐसी कोई प्राथना करनेका अनौचित्य भी है।

[आपका इत्यादि,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१३ रिचकी सेवाएँ

श्री रिच विलायतमें रहकर भारतीयोंके लाभके लिए जो अथक परिश्रम कर रहे हैं उसका सारे भारतीयोंको कदाचित ही पूरा अनुमान होगा। अभी अभी ट्रांसवालके भारतीयोंकी मुसीबतोंकी हूबहू तस्वीर एक छोटी-सी पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित करके उन्होंने हमारे समाजका और भी अधिक उपकार किया है। प्रत्येक भारतीय जानता है कि श्री रिचकी सेवाका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। २३ पृष्ठकी अठपेजी पुस्तिकामें सारे विवरणका समावेश कर दिया है और सन् १८८५ से पढ़नेवाली सारी विपत्तियोंका संक्षेपमें बड़ी खूबीसे सुंदर वर्णन किया है। फिर हमें श्री रिचके परिश्रमका ही लाभ मिलता हो सो बात नहीं उनकी प्रतिष्ठाका भी लाभ मिलता है। अर्थात् श्री रिच जैसे १८ वष पुराने गोरे उपनिवेशवासी भारतीयोंके पक्षमें लड़ते हैं इस बातका गोरोपर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और इसी कारण उन्होंने यह बात पुस्तिकाकी प्रस्तावनामें बताई है। इतनी छोटी पुस्तिकामें श्री रिचने जित्त विस्तृत जानकारीका समावेश किया है उससे श्री रिचका परिश्रम प्रकट होता है।

सन् १९०३ में लॉड मिलनरने भारतीय समाजको जो वचन दिये थे श्री रिचने उनकी याद दिलाई, यह ठीक किया। लॉड मिलनरने कहा था ^१

एक बार पजीयन करवा लो, जिससे फिर कोई आपका नाम न ले सके। और न आपको फिरसे कभी पजीयन करवाना पड़े, न अनुमतिपत्र ही लेने पड़े। इस समय पजीयन करवानेसे आपका यहा रहनेका अधिकार पक्का हो जायेगा। इसके बाद आप लोग आने जानेके हकदार हैं।

अनिवाय पजीयन और स्वेच्छया पजीयन दोनोंकी तुलना करके श्री रिचने उनके बीचका अन्तर दिखा दिया है। “स्वेच्छया पजीयनमें अनिवायताका डक नहीं रहता। गोरोकी भावनाओंके निर्वाहके लिए स्वेच्छया पजीयन करवानेमें निश्चय ही भारतीय समाजकी भलमनसाहत मानी जायेगी। अनिवाय पजीयन करवाया गया तो भारतीयमें और आफ्रिकीमें भेद नहीं रहता। फिर उस उदाहरणके आधारपर पड़ोसी उपनिवेशी भी ट्रांसवालके कदमोंपर चलना सीखेंगे। इसके अलावा अनिवाय रूपसे पजीकृत होना पथक बस्तियोंमें निकाल दिये जानेके लिए बीज बोनेके समान हो सकता है।

श्री रिचने अपने लेखमें लम्बी दलीलोमें उतरनेके बदले महत्वपूर्ण घटनाओंको जगह-जगहपर इतनी अच्छी तरह रखा है कि पाठक भारतीय लड़ाईके औचित्यको स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। अपनी पुस्तिकाके अन्तमें श्री रिचने जो बताया है उसके अनुसार युद्ध पूर्व वचन

१ देखिए परिशिष्ट ८।

२ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ ३२७-२८।

और युद्धोत्तर कालके कामके बीचका अंतर देखकर पता चल जाता है कि सरकार किस प्रकार गोलमोल बात करनेवाली है। इसके अलावा श्री रिचके कथनानुसार

मताधिकार रहित लोगोकी रक्षा करना ट्रांसवालका कतव्य है। इस बातको छोड़ दे तो भी ट्रांसवालको चाहिए वह सारे राज्यके हितकी बातोको पहला स्थान दे। केवल ढाई लाखके लगभग गोरोके लिए जान बूझकर तीस करोड़ भारतीय प्रजाके लोगोपर अपमान ओर मुसीबतें बरसानसे बड़ी सरकारके राज्य और कीर्तिको कितना बट्टा लगा है यदि इसी बातका गोरे लोग विचार कर ले तो काफी होगा।

श्री रिचकी पुस्तिकासे विलायतमें ओर अन्य गोरे लोगोके लिए ट्रांसवालकी भारतीय समस्याका समझना आसान होगा और भारतीय समाजके लिए वह बहुत ही लाभदायक है।

इस प्रकार जबरदस्त टक्कर ली जा रही है और जान पड़ता है कि समझोतेकी चर्चा भी शुरू हुई है। इसलिए यह कहनकी अब शायद ही आवश्यकता है कि सभी भारतीय दब रहेगे और सरकार द्वारा जो भी जाल बिछाया जाये उससे सतक रहकर बेवडक जेल जानेके लिए तैयार रहेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१४ कानून स्वीकार करनेवालोंका क्या होगा ?

इस प्रश्नका उत्तर हम तो अनेक बार दे चुके हैं। किंतु अब श्री हिलने दिया है। श्री हिल एशियाई विरोधी मण्डलके एक नेता है। उनके लिखे हुए पत्रका सारांश हमने दिया है। वह सबके पढ़ने योग्य है। श्री हिल कहते हैं कि नया कानून तो एशियाइयोको निकाल बाहर करनेका आरम्भ मात्र है। कानून तो और भी बनाने ही है। इसलिए नये कानूनके विरुद्ध भारतीयोंने जो लड़ाई शुरू की है उसका सरकारको सीधा उत्तर देना है। अर्थात् इस कानूनको पूरी तरहसे अमलमें लाकर एशियाइयोको पछाड़ा जाये। उन्हें पछाड़नेके बाद गोरे जो भी करना चाहेंगे कर सकेंगे। ऐसे पत्रके बाद भी क्या कोई मान सकता है कि नये कानूनके सामने झुकनेवाला ट्रांसवालमें सुखसे रह सकेगा ?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१५ रामसुन्दर पण्डित

हमारे पास ऐसे पत्र आये हैं जिनमें पण्डितजीके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। उन पत्रोंको हम प्रकाशित करना नहीं चाहते। क्योंकि उनमें लेखकोने बड़ी गलतफहमीसे काम लिया है। पत्रोंमें एक प्रश्न ऐसा उठा है, जिसका हम यहाँ खुलासा करेंगे। किसीने पूछा है कि पण्डितजी मीयादी अनुमतिपत्रकी मीयाद पूरी हो जानेपर भी यही रहे और जेल गये, इससे समाजका क्या फायदा? इस प्रश्नके पूछे जानेमें बड़ी भूल हुई है। सभी मीयादी अनुमति पत्रवाले पण्डितजीके समान लड नहीं सकते थे। मीयाद बीत जानेपर वे ट्रान्सवाल छोड़नेके लिए बचे हुए थे। कि तु धमगुहका काम करनेवाले मोहलत न मिलनेपर भी रह सकते थे। इसलिए, और समाजकी मांग थी इसलिए, वे यहाँ रहे। उनके लिए जर्मिस्टनकी जमातने पत्र भी लिखा था। और उनपर जो मुकदमा चलाया गया वह नये कानूनकी १७ वी धाराके आधारपर। हमारा खास मत है कि उनके मुकदमेसे कौमको बहुत ही लाभ पहुँचा है। उनके जेल जानेसे सबको जोश आ गया है। यह समय ऐसा है कि कानूनकी लड़ाईमें जो भी भारतीय जेल जायेगा उससे फायदा ही होगा। क्योंकि यह पहला अनुभव है। कि तु पण्डितजी जैसे व्यक्ति जेल जाये, उसका असर और ही होगा, और हुआ है। इस असरके कारण ही शाहजी साहब आदि उनके पीछे जेल जानेको छटपटा रहे हैं, इसीलिए जर्मिस्टनमें सैकड़ों भारतीयोंकी सभा भी हुई जिसमें पण्डितजीकी बहादुरीकी तारीफ की गई। कहना सबको आता है कि तु करना तो अबतक पण्डितजीको ही आया है। इतना काफी है कि उन्होंने कोमके हितमें अपना स्वाथ त्याग किया और बाहर निकलनेके बाद और भी ज्यादा करनेको तैयार है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१६ नेटालमें युद्ध-स्वयसेवक

जूलैडमें फिर काफिरोकी बगावत शुरू हो गई है। इसलिए गोरी सेनाके हजारों आदमियोंको भेजा गया है। ऐसे समयमें भारतीय समाजको आगे आना चाहिए। आगे बढ़नेमें अधिकार प्राप्त करनेपर नजर नहीं रखनी चाहिए। उसमें हमें केवल इस बातका विचार रखना चाहिए कि समाजका कतव्य क्या है। हक तो बादमें अपने-आप आते हैं। यह सामान्य नियम जान पड़ता है। भारतीय समाज इस बार फिर पिछले वर्षके समान प्रस्ताव^१ करेगा तो ठीक ही होगा। इस समय जो लोग युद्ध स्वयसेवक नहीं बने हैं उनसे अमुक कर लेनेकी प्रवृत्ति चल रही है। इस करका बोझ केवल भारतीयोंपर ही पड़ेगा। ओर उतना कर देनेके बाद भी भारतीय समाजकी भलमनसाहत नहीं मानी जायेगी। इससे हमें निश्चय हो

गया है कि भारतीय समाजको फिरसे सहायताका प्रस्ताव करना चाहिए। हम मान लेते हैं कि इस समय वैसा करनेके लिए बहुत से भारतीयोंमें उत्साह होगा। जो लोग पिछले वर्ष लडाईमें गये थे वे फिरसे जा सकते ह। वे बहुत कुछ प्रशिक्षित हो चुके हैं और उन्हें कामकी जानकारी है। हमें आशा है कि यह काम तुरन्त ही हाथमें ले लिया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

विगत सार्वजनिक सभा

भारतीयोंकी आम सभाओका पार नहीं है। और वे सभाएँ एकके बाद एक ज्यादा बडी होती जा रही हैं। प्रिटोरियामें जो पिछली सभा हुई थी वह उसके पहलेकी सभासे ज्यादा बडी थी। रविवारको जो सभा^१ जोहानिसबर्गमें हुई उसने प्रिटोरियाकी सभाको भी मात कर दिया — लोगोमें इतना जोश था, भीड़ इतनी अधिक थी। अब सभाएँ अपने आप होती हैं और सभीको उनकी हौस रहती है। किसी भी तरह देशकी सेवाकी जाये, यह उत्साह लोगोमें दिखाई दे रहा है।

दो हजारसे ज्यादा

इस सभामें २,००० से ज्यादा लोग उपस्थित थे। बहुत से गावोंसे प्रतिनिधि आये थे। प्रिटोरियासे करीब चालीस थे। पाचेफस्ट्रूमस लगभग सोलह थे। इसी तरह सब जगहोंसे प्रतिनिधि आये थे।

सूरती मसजिदके प्रागणमें

सभा सूरती मसजिदके प्रागणमें हुई थी। मसजिदके चबूतरेपर, चादनीपर, छप्परपर लोग बैठे हुए थे। पहला विचार श्री ईसप मियाके नये मकानमें सभा करनेका था। किन्तु सभाके समयसे पहले ही इतने ज्यादा लोग आ गये कि उस घरमें सभा नहीं सके। इसलिए तुरन्त खुलेमें सभा करनेका विचार किया गया।

ईसप मियाँ

अध्यक्षका आसन श्री ईसप मियाने ग्रहण किया था, यद्यपि उस समयकी परिस्थितिमें वे और जोहानिसबर्गके बहुत से लोग पूरे समय खडे ही रहे थे। आये हुए प्रतिनिधियोंका श्री ईसप मियाने स्वागत किया और धरनेदारोंका उनके कामके लिए आभार माना।

अन्य भाषणोंका सारांश

दिसम्बर महीनेमें क्या हो सकता है, इसका श्री गांधीने खुलासा किया और गोरोंकी बढती हुई सहानुभूतिके सम्बन्धमें वस्तुस्थितिका वर्णन किया। भारतीयोंके लिए यह समय स्वतंत्र होनेका है, इसलिए कोई भी व्यक्ति नेताकी ओर न देखे, बल्कि सभी अपने आपको नेता समझे और जेल वगैरहका जो भी कष्ट आये उसे निभयतापूर्वक सहन करे।

इमाम कादिरने बताया कि ईमानदारोंके लिए डरनेका कोई कारण नहीं है। वे स्वयं धरना देनेवाले हैं और यदि सरकारने सबसे पहले उन्हें पकड़ा तो वे खुश होंगे।

श्री मणिभाई देसाई (प्रिटोरिया) बोले कि धरना देनेवालोंको यदि पहले गिरफ्तार किया गया तो वे उस बोझको बहुत खुशीसे झेल लेंगे।

एक धरनेदार कानमियाने, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, कहा कि वे स्वयं बिल्कुल नहीं डरेंगे।

श्री अब्दुल गनीने कहा कि इस लड़ाईमें खुदाकी मदद है, क्योंकि लड़ाई सच्ची है। हमें जेल जानेसे जरा भी नहीं डरना चाहिए।

श्री नायडूने तामिल भाषामें समझाया।

हजरत इमाम हुसैनको जो कुछ सहना पड़ा था उसका जिक्र करते हुए श्री शाहजी साहबने कहा कि रामसुंदर पण्डितपर जो बीता है वह मुल्ला मौलवियोंके साथ भी हो सकता है।

ऐसा सोचकर उनसे रहा नहीं गया, और वे पण्डितजीके पीछे जेल जानेको तैयार हो गये।

श्री उमरजी सालेने कहा कि वे स्वयं जेलसे डरनेवाले नहीं हैं।

श्री कुवाडियाने कहा कि सरकार दूकानदारोंपर हाथ डाले और उन्हें दूकानें बन्द करनी पड़े तो हज़ नहीं। इससे और भी जल्दी छुटकारा मिलेगा।

श्री खुरशेदजी देसाई (कूगसडॉप) ने बताया कि काफिराको पास प्राप्त करनेमें कितनी कठिनाई होती है।

श्री अब्दुल रहमान (पांचेफस्ट्रूम) ने कहा कि पांचेफस्ट्रूम एकदम जोरमें है और सब लोग जेलमें जानेको तैयार हैं।

श्री उस्मान लतीफ (पांचेफस्ट्रूम) बोले कि वे भी अपने स्त्री बच्चोंको छोड़कर जेल जानेको तैयार हैं।

श्री क्विन (चीनी सघके अध्यक्ष) ने अंग्रेजीमें कहा कि यह लड़ाई एशियाइयोंको मुक्ति दिलानेवाली है। सारे चीनी मृत्युपयन्त लड़नेको तैयार हैं।

श्री इब्राहीम अस्वातने कहा कि यदि भारतीय समाज इस समय धीरज छोड़ दे और डरके मारे पजीयन करवा ले तो उसे खुदाके दरबारमें आत्महत्या करनेवाले चीनीको जवाब देना होगा। क्योंकि उक्त चीनीने भारतीयोंमें पाये हुए उत्साहके कारण ही अपनी जान लड़ाई थी।

श्री नवाबवाने कहा कि समाजके कल्याणके लिए और वमके लिए हर भारतीयका अतक लड़ना कतव्य है।

श्री हाजी हबीबने अपने भाषणमें मेमन लोगोंने जो पजीयन करवाया है उसके लिए खेद व्यक्त किया और सलाह दी कि जोश कायम रखा जाये।

श्री पोलकन कहा कि खरा समय अब आनेवाला है। श्री गांधीके जेल चले जानेके बाद उन्हें जितना भी करना चाहिए उसमें वे नहीं चूकेगे।

कुछ प्रश्नोंके उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि यदि किसीको गिरफ्तार किया जाये और जेलमें दस अँगुलियोंकी निशानी मांगी जाये तो वह दे दी जाये। यह लड़ाई दस अँगुलियोंकी निशानीकी नहीं, गुलामीसे छूटनेकी है। दस अँगुलियोंकी छाप देनेका कानून जेलमें सबपर लागू होता है। हमें उसका विरोध नहीं करना है। किन्तु जेलमें यदि कोई पजीयन करानेको कहे तो वह नहीं कराना चाहिए। यदि स्वयं मुझे गिरफ्तार किया गया तो श्री पोलक तार

वगैरह भेजनेका सब काम कर सकेंगे। किसी भी व्यक्तिको नया पजीयनपत्र न लेनेके कारण गिरफ्तार किया जाये तो उसे वकील नहीं करना चाहिए।

श्री मनजी लाखानी (प्रिटोरिया) ने कहा कि कुछ लोगोंने तो “कोडी” [कोडी] खेली, कुछ लोगोंने “चैमने” [चिमनी] का घुआ लिया, किन्तु वे स्वयं भिखारी भले बन जाये, पजीयनपत्र नहीं लेंगे।

श्री काछलियाने कहा कि नेता लोग तत्पर रहे या न रहे किंतु जो लोग गुलामी नहीं चाहते वे तो जूझते ही रहेंगे।

‘ट्रांसवाल लीडर’ के सम्पादक श्री काटराइट सभाका पता चल जानेसे खास तोरसे देखनेके लिए आ गए थे। उहे भारतीयोंसे बहुत ही सहानुभूति है। वे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और खुद भी सरन लेख लिखनेके कारण जेल भोग चुके हैं। वे खुद बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, ओर सच्चेका बचाव करनेमें डरनेवाले नहीं हैं।

रामसुन्दर पण्डितका सन्देश

सोमवारको विशेष अनुमति लेकर श्री गांधी श्री रामसुन्दर पण्डितसे मिले। गवर्नरका हुक्म था कि बातचीत अंग्रेजीमें की जाये, इसलिए सारी बातचीत मुरय सतरीके सामने अंग्रेजीमें हुई। पण्डितजीने बहुत-सी बातें की। उनमें से केवल आवश्यक बातें यहा देता हूँ

सबको खबर दीजिए कि मैं यहा सुखी हूँ। यदि सरकार कड़ी सजा देती तो अधिक अच्छा होता। छूटनेके बाद मैं समाजके लिए फिरसे जेलमें जानेको तयार हूँ। जेलमें मैं जेल सम्बन्धी सभी कविताएँ पढ़ी ह। उन काव्योंसे मुझे बहुत उत्साह मिला है। श्री मेहताबकी कविताओका असर मेरे मनपर अधिक पडा है। मुझे आशा है, जेलसे छूटनेपर इन कविताओकी पुस्तके प्रत्येक हाथमें देखूंगा। दिसम्बर लग गया है फिर भी अभीतक दूसरे भारतीय क्यों नहीं पकड़े गये? पकड़े जायेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सबसे कहिए कि जेलमें कुछ भी कष्ट नहीं है। मैं तो जेलमें स्त्रियोंको भी देखता हूँ। मेरी कोई चिन्ता न करे। मैं अपने आपको महलमें बैठा हुआ मानता हूँ। चाहता इतना ही हूँ कि कोई भारतीय कानूनको स्वीकार न करे। गवर्नर और मुख्य सतरी मेरी बड़ी फिक्र रखते हैं।

इसमें जेल सम्बन्धी कविताओके बारेमें पण्डितजीका कथन देते समय मुझे सकोच हुआ है। किंतु उन्होंने इस बातपर बहुत जोर डाला इसलिए फज समझकर मैंने यह सन्देश दिया है। किंतु इसका कोई यह अर्थ न निकाले कि उसमें ‘इंडियन ओपिनियन’ में काम करनेवाले लोगोका पैसेका स्वाथ है। वह अबबार बड़ी मुसीबतसे प्रकाशित होता है और उसमें काम करनेवाले लोग आज भी इतना लाभ नहीं कमा रहे हैं जो वह कुछ गिनतीमें आ सके।

पजाबियोंका प्रार्थनापत्र

पिछले सप्ताह मैंने पजाबियोंके प्रार्थनापत्रका अनुवाद दिया था। उसके साथ श्री गांधीने निम्नलिखित पत्र^१ लॉर्ड सेल्बोनके नाम लिखा है।

१ पत्रके पाठके लिए देखिए ‘पत्र उच्चायुक्तको’, पृष्ठ ४०९। गुजराती अनुवादमें पत्रका पहला अनुच्छेद छोड़ दिया गया था।

नवम्बर महीनेके गद्दार

नवम्बर महीनेमें धरना देनेवालोंने प्रिटोरियामे जोहानिसबगके समान ही काम किया। उनकी सावधानीसे बहुत ही कम भारतीय पजीकृत हुए थे। ओर प्रिटोरियासे तो एक भी नहीं हुआ, ऐसा माना जा सकता है। किन्तु उपनिवेशसे कुछ कुछ लोग आ गये। इसमें हाइडेलबर्गने पहल की है। यह काम श्री रतिलालने किया जो पढे लिखोकी गिनतीमें आते हैं। उनके बाद श्री अबू मिया कमरुद्दीनके कुछ लोग गये और आखिरमें श्री खोटाके लोग। श्री खोटाके लोगोके जानेसे सबको अफसोस हुआ। और उनका जाना सूरती समाजने कलक माना है। श्री रतिलालके जानेसे गुजराती हिंदुआमें खलबली मची है। गुजराती हिंदू बिल्कुल साफ बच्चे मालूम होते थे। लाग मानते थे कि श्री लक्ष्मीचन्दके सिवा कोई नहीं जायेगा। किन्तु रतिलालने उनके इस विश्वासको भग कर दिया है। अपने नौकरोके सम्बन्धमें श्री खोटाने लिखा है कि नौकरोका दोष नहीं है। उन्होंने स्वयं दबाव डाला था इसलिए नौकरोको जाना पडा। नौकरोने साफ इनकार किया था किन्तु श्री खोटाके आप्रहसे वे गये। अब श्री खोटाको अफसोस है और वे लज्जित हैं। इसके अलावा, उन्होंने लिखा है कि उनकी चार दूकानें हैं इसलिए उनके मनमें बहुत भय पडा हो गया था। किन्तु अब वे नहीं जायेगे। इतना ही नहीं, जेल जाने तक लडत भी रहेंगे। श्री खोटाने अपने आचरणके बचावमें कुछ नहीं कहा इसलिए अब टीका करने जैसी स्थिति नहीं रहती। किन्तु उनके भयके लिए सबको खेद अवश्य होगा। उन्होंने पूरी हिम्मत रखी होती तो बहुत ही शोभनीय होता। मुझे आशा है कि श्री खोटाके उदाहरणका कोई अनुकरण नहीं करेगा।

अन्य गद्दारोंमें गरीब मद्रासी ओर कलकतिया लोगोका समावेश हो जाता है। उनका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि वे एकदम अजनबी हैं और गुलामा-जैसी स्थितिमें रह रहे हैं। इसलिए नवम्बर महीनेमें पजीयन जारी रखनेके लिए कुछ नेताओकी मागकी जो बात निकली थी, वह भी गलत साबित हुई है।

‘सडे टाइम्स’

‘सडे टाइम्स’में यह टीका है कि यदि पहलेके अनुमतिपत्र अधिकारी रिश्ततखोर नहीं होते तो सरकारको नया कानून बनाना नहीं पडता। अर्थात्, इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार अपने अधिकारियोंके अपराधके लिए भारतीय समाजको सजा दे रही है।

दूसरे अखबार

दूसरे अखबारोंमें जो लेख आते हैं उनसे हँसी आती है। सभी अखबार साफ लिख रहे हैं कि यह नहीं दिखाई देता कि सरकार किसीको जेलमें बन्द करेगी। ‘स्टार’ तो साफ कहता है कि जेलमें बन्द करनेकी जरूरत नहीं है। सिर्फ परवाने रोककर लोगोको तंग करके धीरे-धीरे पजीयनपत्र लेनेपर मजबूर कर देगे। ‘स्टार’ साफ कहता है कि मजिस्ट्रेटके सामने किसी भारतीयको खडा किया जायेगा तो वहा भी जेलकी सजा देनेके बजाय मजिस्ट्रेट उसे पजीयन करानेके लिए समय देगा। ‘स्टार’ का लेख सरकार-प्रेरित जान पडता है इसलिए सभी भारतीय ठीक तरह सावधान रहें।

सावधान रहो

मजिस्ट्रेटके सामने खडे होनेवाले भारतीय यदि डर जायेगे तो ठीक नहीं होगा। वैसे भारतीयको देश निकालेका नोटिस देनेकी अपेक्षा मजिस्ट्रेट पजीयनकी अर्जी देनेके लिए

सिफारिश करेगा। यदि सरकार इस प्रकार जालमें फसाना चाहती हो तो भारतीयोंको सावधान रहना चाहिए। एक 'नहीं' छत्तीस रोगोंको दूर करता है। वैसा 'नहीं' ही मुहसे निकलना चाहिए। अब सरकारकी निबलताकी सीमा नहीं रही। सरकारको उसका जालिम-पना ही डरा रहा है। कहा गई जनरल स्मट्सकी धमकी? कहा गया उनका देश निकाला? सरकार इतनी कमजोरी दिखाती है, फिर भी कुछ भारतीय तो डरते ही रहते हैं।

दूसरी चेतावनी

किसी भी भारतीयके पास बिना पोशाकके जासूस आकर नया अनुमतिपत्र मागे या दूकान बंद करनेको कहे तो भारतीयको उसकी बात नहीं माननी चाहिए। जासूस होनेके बहाने कोई दूसरा ही आदमी आ सकता है।

समझौतेके लिए हलचल

बहुत से प्रसिद्ध गोरे समझौतेके लिए हलचल कर रहे हैं। सर पर्सी फिट्जपैट्रिक तथा दूसरे लोगोंकी मुलाकात होती रहती है। अभी तो लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि सरकार किसीको नहीं पकड़ेगी, और ऐसे ही समझौता हो जायेगा। यदि ऐसा हो तो उसका यश रामसुंदर पण्डितको ओर आत्मघात करनेवाले चीनीको मिलेगा। उस घटनासे सबका भय छूट गया है और एशियाइयोंको जोश चढ़ा है। जो-जो बातें हो रही हैं उनकी हकीकत देनेका अभी समय नहीं आया है, इसलिए लाचार होकर यही बंद करता हूँ। सभी अखबार अब लिखने लगे हैं कि सरकार इस कानूनको अमलमें नहीं लायेगी। जनवरीमें कुछ न कुछ करेगी। इस प्रकार वह सीढ़ी-दर-सीढ़ी उतरती जा रही है। अब काले हो या गोरे, ऐसी बात तो कोई नहीं करते कि सरकार सभी लोगोंको जेलमें बंद कर सकती है।

ठीक हुआ !

कुछ कलकतिया तथा मद्रासी फोक्सरस्टकी ओरसे दबाव आनेके कारण अथवा नौकरी चली जायेगी इस भयसे पजीकृत हुए, किंतु अब वे नौकरी खो बैठे हैं। उनकी नौकरी छूटनेका कारण मालूम नहीं पड़ा। किन्तु लोग प्लेगकी छूतका विरोध करनेपर भी नहीं बच सके, यह जानने लायक बात है। वे अब बहुत पछताते हैं। नौकरी भी गई और लाज भी गँवाई। एक उदाहरण और भी मुझे मिला है। एक दो भारतीय इसलिए पजीकृत हुए कि उन्हें माल बगरह मिल जायेगा। उन्होंने अब अपने बहीखाते (माल देनेवाले) व्यापारीको सौंप दिये हैं। खुदाकी कुदरत कोई जान नहीं सकता।

एक कोकणी अनाक्रामक प्रतिरोधी

श्री मुहम्मद इशाक नामक कोकणीके पास पुराने पजीयनपत्र तथा अनुमतिपत्र है। फिर भी उसे नये कानूनके अंतर्गत नेटालसे फोक्सरस्ट आते हुए पकड़ा गया है और उसने जमानतपर छूटनेसे इनकार किया है। श्री गांधीने सरकारी वकीलको तार भेजा है कि उस आदमीको पकड़ा नहीं जा सकता। किन्तु यदि बिना मुकदमा चलाये नहीं छूटेगा, तो वे स्वयं उसका बचाव करेंगे। इस आदमीपर मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि वह अभी हालमें ही ट्रासवालसे नेटालमें दाखिल हुआ है। उसे आठ दिन तक गिरफ्तार करनेका अधिकार सरकारको नहीं

है। इस मुकदमेमें ऐसा ही बचाव किया जाना चाहिए। क्योंकि बाहरसे आनेवाले आदमीको इस प्रकार आठ दिन खुले रहनेका मौका मिलना चाहिए। इस स्थितिमें मुकदमा जोहानिसबगमें ही चल सकता है और इससे अनाक्रामक प्रतिरोधको बल मिलेगा। यह अनाक्रामक प्रतिरोधी कोकणी है, इसलिए मैं सब कोकणियोंको बधाई देता हूँ। मुकदमा जुम्मेके दिन चलेगा। मजिस्ट्रेटने १० पौडकी जमानत तय की है। किंतु किसीने जमानत नहीं दी। फोक्सरस्टसे तार आया है। उसमें कहा गया है कि श्री मुहम्मद इशाक बहुत ही हिम्मतवाला और बहादुर है।

समझौतेके बारेमें

समझौतेकी बातचीत चलती रहती है। लोगोमें जोश इतना ज्यादा है कि वे अब स्वेच्छया पजीयनसे भी मुक्त होना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सरकारसे अब बिल्कुल कोई समझौता न करके लड़ाई ही लड़ ली जाये और जो कागज मिले है उन्हें जमा कर बैठे रहे। यह जोश बहुत ही प्रशंसनीय है। समाजके लिए अब बहुत समझदारीसे चलनेका समय आया है। समझौतेके लिए जो बातें आज बारह महीनेसे कही जा रही हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। बुधवारको हमीदिया सभाभवनमें सभा हुई थी। किन्तु उस सभामें बहुतोका उत्साहपूर्ण आग्रह यही रहा कि पुराने पजीयनपर दब रहे और स्वेच्छया पजीयन न कर वाये। मुझे आशा है कि जब लोगोका यह जोश उतर जायेगा तब ठंडे होनेपर वे फिर विवेकपूर्ण माग करेंगे। कानूनके टूटनेको मैं महान विजय मानता हूँ। और यदि लोग एकमत रहेगे तो कानून टूटेगा ही। किन्तु इसीके साथ हमें यह भी बताना होगा कि हम ठीक रास्तेपर चलनेवाले और वचनका निवाहनेवाले हैं। जैसे हम ली हुई शपथको तोड़ना अपराध मानते हैं, वैसे ही स्वेच्छया पजीयनका वचन देकर उससे मुकरनेमें भी शम है।

रविवारको सभा

फिरसे विचार करनेके लिए रविवारको सभा होनेवाली है। अन्तमें समाज समझदारीसे काम लेगा तो यह जोश, जो दीख रहा है, शुभ लक्षण माना जायेगा।

पण्डितजी

श्री रामसुन्दर पण्डित तारीख १३ को सवेरे ९ बजे जोहानिसबग जेलसे छूटनेवाले हैं। आशा है उस समय जोहानिसबगके बहुत से भारतीय उनका स्वागत करनेके लिए उपस्थित होंगे। उनका स्वागत करनेके बाद सभा करनेका विचार है।^१ दूसरे शहरके लोगोके लिए उचित होगा कि वे बधाईके तथा ऐसे तार भेजे जिनमें कहा गया हो कि आवश्यकता पडनेपर वे फिर जेल जानेकी बहादुरी दिखायेंगे।

पजाबी

एक गोरेने लॉड सेल्बोनको लिखा है कि वे पजाबी आदि लोगोको जूलू लड़ाईमें नौकरी दे। लॉड सेल्बोनने पजाबियोंके प्राथनापत्रका यह जवाब दिया है कि वह प्राथनापत्र स्थानीय सरकारको भेज दिया गया है।

भूल सुधार

मैंने पिछले सप्ताह जब पत्र लिखा तब कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके लिए केवल २५ पौंड भेजनेकी बात थी। किन्तु बादमें ३५ पौंड भेजनेका फैसला हुआ था, इसलिए ३५ पौंडकी हुडी श्री अमीरुद्दीनको भेज दी गई है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१८ भारतीयोका मुकदमा'

[फोक्सरस्ट]

दिसम्बर ९, १९०७

जिरहमें गवाहने स्वीकार किया कि एशियाइयो द्वारा पेश किये गये अनुमतिपत्र अबतक के निर्देशके अनुसार उन्हें प्रवेश और पुन प्रवेशका अधिकार देनेके लिए पर्याप्त माने गये ह। उसे नही मालूम था कि पुन प्रवेश अनुमतिपत्रके अनुसार था या शान्ति रक्षा अध्यादेशके अनुसार। उसने एशियाइयोको पुन प्रवेश करने दिया। क्योंकि उसे ऐसा ही निर्देश मिला था।

[गांधीजी] आपको अब क्या निर्देश दिये गये है ?

[गवाह] मुझे ये निर्देश दिये गये ह कि १६ वर्षसे अधिक आयुके सब एशियाई पुरुषोको, जो एशियाई अधिनियमके अतगत पजीयन प्रमाणपत्र या ऐसे अस्थायी अधिकारपत्र पेश न कर सकें जिनसे उनको पुन प्रवेशकी अनुमति प्राप्त होती हो, रोक लिया जाये और गिरफ्तार कर लिया जाये।

क्या ये निर्देश ऐसे एशियाइयोपर भी लागू होते हैं जिनके बारेमें आप जानते हो कि वे पुराने अधिवासी हैं, जिहोंने अनुमतिपत्र दिखाये होंगे और हाल ही में उपनिवेश छोडा होगा ?

हा, क्योंकि इन निर्देशोके अनुसार मेरा कतव्य यही है। यदि एशियाई नये अधिनियमके अतगत अधिकारपत्र प्रस्तुत नही कर सकते तो मुझे उन सबको किसी भेदभावके बिना गिरफ्तार करना है।

१ फोक्सरस्टमें आनेपर ६ दिसम्बरको २० भारतीय और उससे अगले दो दिनोंमें अय १७ भारतीय गिरफ्तार किये गये थे। उनपर सहायक आवासी न्यायाधीश श्री डी' विल्यम्सके न्यायालयमें मुकदमा चलाया गया। पहले २० भारतीयोका मुकदमा लिया गया। सरकारी वकील श्री मेंजकी जिरहमें साजट मैसफील्डने बताया कि सब अभियुक्तोके पास अनुमतिपत्र और शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत पजीयन प्रमाणपत्र थे उनके अँगूठेके निशान विधिवत् हैं और उनको अनुमतिपत्रोंके अनुसार उपनिवेशमें प्रवेशका अधिकार है, किन्तु पुन प्रवेशका अधिकार नही है। अभियुक्तोंने उसे कहा था कि वे एशियाई अधिनियमको मानना नही चाहते। गांधीजीने उससे जिरह की।

आगे प्रश्न करनेपर सार्जेंट मॅसफील्डने अनुमतिपत्र और पजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये और कहा कि ये १८८५ के कानून ३ के अंतगत लिये गये ह। इसके साथ सरकारी पक्षकी कारवाई समाप्त हो गई।

श्री गांधीने जोर देकर कहा कि सरकारी गवाहने उनके मुवक्किलोका पक्ष सिद्ध कर दिया है। 'यायाधीशके सम्मुख जो प्रश्न है वह विशुद्ध रूपसे यह है कि डाके मुवक्किलोके पास शांति-रक्षा अध्यादेशके अंतगत जारी किये गये अनुमतिपत्र ह या नहीं। ये अनुमतिपत्र सार्जेंट मॅसफील्डने प्रस्तुत किये और यह स्वीकार किया कि वे विधिवत् ह।

श्री डी विलियस तब आपका तक यह हे कि प्रश्न विशुद्ध कानूनी बहसका हे ?

[श्री गांधी] हा श्रीमान्, बिल्कुल यही।

तब श्री मेजने बहस की कि इन लोगोके पास जो अनुमतिपत्र ह उनमे केवल उपनिवेशमे आने और रहनेका अधिकार दिया गया है, किंतु उपनिवेशसे जाने और फिर वापस आनेका नहीं। उन्होंने यह तक दिया कि जब एक बार ये लोग उपनिवेशसे चले गये तब उनके अनुमतिपत्र रद्द हो गये ह।

श्री गांधीने उत्तरमे कहा कि प्रश्न फिर वापस आनेका भी नहीं हे। यायाधीशको आरोपपत्रकी मर्यादाके भीतर रहना है। इसमे उनके मुवक्किलोपर शांति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ५ के अंतगत बिना अनुमतिपत्रके प्रवेश करनेका आरोप लगाया गया है। 'यायाधीशके सम्मुख जो साक्षी हे उससे निर्विवाद रूपसे सिद्ध होता है कि प्रवेश करनेपर उनके पास वस्तुतः उनके अनुमतिपत्र थे। इसके अतिरिक्त वे सब १८८५ के कानून ३ के अंतगत ३ पोड दे चुके ह। सरकारी वकीलका तक भी उचित नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च 'यायालयने भाभा बनाम ताजके मुकदमेमें यह निणय दिया था कि उपनिवेशमे आनेके अनुमतिपत्रमे उससे जाने और वापस आनेकी अनुमति भी सम्मिलित होती हे। उस मामलेमे 'यायमूर्ति ब्रिस्टोवने करीब-करीब इ-ही शब्दोका प्रयोग किया है। इसलिए चाहे जिस प्रकारसे इस मुकदमेपर विचार किया जाये, उनके मुवक्किल बरी होनेके अधिकारी ह। न्यायाधीशको विधि विभागके निर्देशोसे या उसने शांति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ५ की जो व्याख्या की है उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरी सम्मतिमे, निश्चय ही उचित माग यह होता कि यदि उनके मुवक्किलोने नये अधिनियमका उल्लंघन किया था तो एशियाई विभाग उनपर उसके अंतगत मुकदमा चलाता।^१

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

१ न्यायाधीशने गांधीजीके तर्कको मान लिया और अभियुक्तोंकी बरी कर दिया। तब अय १७ व्यक्ति न्यायालयमें लाये गये, किंतु उनपरसे आरोप उठा लिया गया।

३१९ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को

जोहानिसबग

दिसम्बर १२ १९०७

सेवामे

सम्पादक

'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

शायद आप मुझे अपने पत्र द्वारा जनताका ध्यान भारतीयोंके उन ३८ मुकदमोंसे^१ मिलनेवाले पाठकी ओर आकर्षित करनेकी सुविधा देगे जो देखनेमें शांति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत चलाये जानेपर भी वास्तवमें एशियाई पञ्जीयन अविनियमके अनुसार चलाये गये ह।

पाठ यह मिलता है कि एशियाई दफ्तरकी कायवाहिया एकदम गुप्त हुआ करती है। इस बातका पता पूनियाकी गिरफ्तारीसे चला कि भले ही भारतीय स्त्रिया अपने वैध रूपसे उपनिवेशमें प्रवेश करनेके हकदार पतियोंके साथ हो, स्वयं उन औरतोंके पास अनुमतिपत्र न होनेपर उनकी गिरफ्तारीकी गैरकानूनी आज्ञाएँ दी गई थी।

एक बारह वर्षके लड़केकी गिरफ्तारीसे ही यह पता चला कि इस बातकी गुप्त तथा गैर कानूनी हिदायते जारी की गई थी कि अबोध बच्चोंके पास अलग अनुमतिपत्र होने चाहिए।

यह बात पण्डित रामसुन्दरके^२ जेल जानेसे मालूम हुई कि एशियाईयोंके खिलाफ तहकीकात करनेके लिए एशियाई दफ्तरपर साधारण तथा सवविधित नियम लागू नहीं होते।

अन्तमें यह रहस्योद्घाटन अड़तीस भारतीयोंकी गिरफ्तारी और उनकी दोसे चार दिन तक की हिरासतसे हुआ कि एशियाई दफ्तरको, पांच सालसे चले आ रहे रिवाजके खिलाफ, अचानक यह पता लगा कि शांति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत जारी किये हुए अनुमतिपत्रोंकी सीमामें उपनिवेशसे अस्थायी रूपसे चला जाना तथा वहा लौट आना शामिल नहीं है। कानूनकी नई व्याख्याके बारेमें गुप्त रूपसे हिदायते जारी की गई थी और भारतीयोंको उनके बारेमें पहलेसे कोई खबर नहीं दी गई। लोग यह नहीं जानते कि डबनमें तैनात ट्रान्सवालके एशियाई अविकारीने वास्तवमें उही आदमियोंकी जाच की थी और उन्हें पास कर दिया था। इनमें से छत्तीस आदमी 'सुल्तान' जहाज द्वारा लौटे हुए यात्री थे। मुझे बतलाया गया है कि एशियाई कार्यालयने उन आदमियोंकी जाच करनेमें तीन दिन लगाये थे।

और इतनेपर भी श्री लिङ्गे, जिन्हें वकील होनेके कारण अधिक जानकारी होनी चाहिए, कह सकता हूँ, इस बातको सोचनेका कष्ट किये बिना कि उस बातका कोई भारतीय पक्ष भी हो सकता है, बड़ी आसानीसे चोरी छिपे घुस जानेकी बातें करते हैं।

अनाक्रमक प्रतिरोधी जनमतका निर्माण करनेपर निर्भर करते हैं लेकिन अगर वे जनमतको अपने पक्षमें न कर सकें तो भी वे अपने शुद्ध सकल्पसे पीछे हटनेवाले नहीं हैं। इस

१ देखिए "मुहम्मद इशाकका मुकदमा", पृष्ठ ४०७ ८ तथा पिछला शीर्षक।

२ देखिए "पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को", पृष्ठ ३५९ ६०।

बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके कष्टसहनसे उपनिवेशके कुछ नेताओंको अतमे सोचना पड़ा है। क्या मैं उनसे, और अभी तक भारतीय दृष्टिकोणकी उपेक्षा करनेवाले दूसरे लोगोंसे, पूछ सकता हूँ कि क्या भारतीयोंका यह पवित्र कतव्य नहीं है कि वे एक ऐसे अधि नियमके सामने सिर झुकानेसे इनकार कर दे जो एक अकेले आदमीके हाथमें ऐसे निरकुश अधिकार देता है कि वह खुफिया तौरसे पूछताछ करता है, खुफिया तौरसे हिदायते जारी करता है और लोगोंकी बातें सुने बिना ही उन्हें सजा दे देता है। यद्यपि कनल मैकेजीको^१ जूलूलडमें जगी कानूनकी घोषणाके अतगत निर्विवाद रूपसे पूरे अधिकार मिल गये हैं तथापि दीनूजूलूको^२ भी, जिसपर विद्रोही इरादोंका सदेह है केवल सदेहपर, उसकी सुनवाई किये बिना, सजा नहीं दी गई। तब भारतीयोंसे यह आशा क्यों की जाये कि वे बिना शिकायत किये सगठित जाली प्रवेशके गलत इल्जामको सहते रहे और इस देशमें रहनेके अपने अधिकारके बारेमें एशियाई अधिनियमके अतगत गैर अदालती जाचको मान लें? अगर उनका इस आरोपका खण्डन करना खोखला होता तो क्या वे बार बार सारे मामलेकी खुली अदालती जाचकी माग करनेके बजाय यह पसंद न करते कि उसे दबा दिया जाये?

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३२० स्वर्गीय आराथून

पिछले हफ्तेकी डाकसे श्री आराथूनकी शोकजनक मृत्युका समाचार प्राप्त हुआ है। श्री आराथूनने पूव भारत सघके अवैतनिक मंत्रीके रूपमें उसकी कई वर्ष तक सचार्डके साथ और भली भांति सेवा की थी। 'एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू' के सम्पादकके रूपमें उनकी सेवाओंका उन सभीको पता है, जिनका भारतके साथ कुछ भी सम्बन्ध है। लेकिन दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके बीच उनका नाम सबसे अधिक इसलिए है कि उनके प्रति श्री आराथूनको बहुत ज्यादा हमदर्दी थी और साथ ही जिस सघसे उन्होंने अपनेको इतना एकरूप कर दिया था उसके कार्योंके सिलसिलेमें वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रश्नमें बराबर दिलचस्पी लेते थे। वे इस प्रश्नको सघके और सघके द्वारा अधिकारियोंके ध्यानमें लानेका मौका कभी नहीं चूकते थे। पिछले साल उन्होंने शिष्टमण्डलकी अपने हार्दिक सहयोग द्वारा बहुत मूल्यवान सहायता की थी। हम श्री आराथूनके परिवारके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

१ एक धर्म प्रचारक (मिशनरी), जिसे १८८४ में बेचुआनालेडका आयुक्त नियुक्त किया गया था।

२ जूलूओंका एक मुखिया, जिनपर यकिन कर सम्बन्धी विद्रोहमें शामिल होनेके आरोपपर मुकदमा चलाया गया था।

३२१ फोक्सरस्टके मुकदमे

फोक्सरस्टमे श्री मुहम्मद इशाक तथा दूसरे भारतीयोंके जो मुकदमे चले वे बहुत जानने योग्य हैं। उन मुकदमोंको सरकार पहले तो नये कानूनके अतगत चलाना चाहती थी, किन्तु आखिर वह डर गई और वे शांति रक्षा अध्यादेशके अतगत चलाये गये। इसमें श्री मुहम्मद इशाक सबसे आगे रहे इसलिए दूसरे भारतीय भी अनुसरण कर सके। उन्होंने कोकणियोंका नाम रख लिया है, और यदि कोकणियोंपर कोई कलक आता है तो वह अब टिक नहीं सकता। मजिस्ट्रेटने निणय दिया है कि श्री इशाकको उनके अनुमतिपत्रके आधारपर रहनेका हक है और इस तरह उन्हें निर्दोष मानकर छोड़ दिया है।

इन मुकदमोंसे लोगोंकी हिम्मत अधिक प्रकट हुई है। जमानतपर नहीं छूटे, यह ठीक हुआ। और गिरफ्तार किये जानेवालोंमें कई कौमोंके लोग हैं, यह भी ठीक हुआ।

यह मुकदमा सरकारकी बहुत बड़ी कमजोरी प्रकट करता है। सरकार हिम्मत हार गई है। क्या करना चाहिए, यह उसे नहीं सूझता। उसकी हालत क्रोधसे पागल व्यक्तिके समान है। यदि ऐसे मुकदमे और चलाये जाये तो हमारा फायदा ही है।

यदि सरकारमें सच्चा बल होता तो वह उन भारतीयोंको पकड़ती जो ट्रान्सवालमें बसे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। किन्तु सो तो सरकार कर नहीं सकती। इसलिए बाहरसे आनेवालोंको रोकनेका व्यर्थ प्रयास कर रही है। किन्तु उसमें सरकार बिना हारे नहीं रह सकती। क्योंकि नये कानूनमें जबरदस्त गुजाइश रह गई है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२२ नेटाल परवाना अधिनियम

इस अधिनियमके अतगत सरकारने नये खण्ड बनाये हैं। उनमें तीन खण्ड जानने योग्य हैं। एक तो यह कि इसके बाद अब परवानेकी अर्जीकी विज्ञप्ति समाचारपत्रमें प्रकाशित करनी पड़ेगी। परवानेके कागजपर निशानी लेनेका अधिकारीको हक है। ओर अपीलके समय १२ पौड १० शिलिंग पेशगी चाहिए। यह सब बुरा है। परन्तु अब देखना यह है कि इनमें किस बातमें बचा जा सकता है। ऐसा नहीं लगता कि समाचारपत्रमें विज्ञप्ति देनेकी बात रद्द हो जायेगी। इस प्रकारका कानून केपमें है। अँगूठा निशानी लेनेकी बात अधिकारीकी मर्जीपर है। इसलिए ऐसा अर्थ हो सकता है कि जिन्हें हस्ताक्षर करना आता हो उनसे अँगूठा निशानी न ली जाये। उपर्युक्त दोनों विषयोंके सम्बन्धमें सरकारको कुछ लिखा जाये, यह हम नहीं कह सकते। क्योंकि इसे हम व्यर्थ समझते हैं। १२ पौड १० शिलिंग देनेकी बात नई नहीं है। इसका उपाय केवल यही है कि जब भी किसीके लिए अपील करनेका प्रसंग आये वह बिना रकम दिये अपील करे। हम मानते हैं कि यह शुल्क अवयव है, और सम्भव है कि

यायालय इसे अवैध करार देगा। सही माग यह है कि इस कानूनकी परवाह न करके इसका विरोध किया जाये। जहा सामूहिक रूपसे परवाने न दिये जाये वहा मालके बिकनेकी परवाह न करके बिना परवानेके व्यापार किया जाये। ऐसे कष्टोके लिए अनाक्रमक प्रतिरोध सर्वोत्तम उपाय है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२३ स्वर्गीय नवाब मोहसीन-उल-मुल्क

नवाब मोहसीन उल मुल्कके जनतन्शीन होनेकी खबर हम पहले दे चुके हैं।^१ इस अकमे उनका सक्षिप्त जीवन वृत्तात दे रहे हैं।^१ उन्होंने शिक्षाके क्षेत्रमे जो सेवा की है वह प्रत्येक भारतीयके लिए, और विशेषतः प्रत्येक मुसलमानके लिए, अनुकरण करने योग्य है। उन्होंने शिक्षाको राजनीतिके मुकाबले पहला स्थान दिया। यह दृष्टिकोण बहुत हद तक, और विशेषकर उनके समयमे यथाथ ही था। जहा शिक्षा सदाचरण तथा नैतिक जीवनकी सीखके साथ साथ मिलती है वहाका समाज बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन उच्च आचरण तथा उच्च नैतिकताके अभावमे शिक्षा भयकर है। वह वैसी ही है जैसी बिना बाइकी बेल — जो ऊपर नहीं चढ़ सकती। ऐसी नैतिकतापूर्ण शिक्षा लेना सभीका कतय है, और यह हम स्वर्गीय नवाबके जीवनसे सीख सकते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२४ जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन

आजकल जब कि भारतीयोमे मान मर्यादाकी हवा बह रही है तब श्री पीरन मुहम्मदपर जो बात गुजरी है वह जानने जैसी है। उन्होंने उपयुक्त कम्पनीके यूरोपकी ओर जानेवाले जहाजका पहले दर्जेका टिकट मांगा था, सो उन्हें नहीं मिला। इसे हम बहुत अपमानजनक मानते हैं। यह बात जमन कम्पनीको शोभा देनेवाली नहीं है। उमे भारतीय यात्रियोसे बहुत बड़ी कमाई होती है। किन्तु इसका खयाल न करके, भारतीय यात्री पहले दर्जेका टिकट मांगते हैं तो उन्हें देनेसे इनकार किया जाता है। यह हमारे लिए लज्जाजनक है। वह कम्पनी हमारी जीवन विधिसे परिचित है। हम ऐसे लोग नहीं जो कुछ कर सके, इसलिए वह हमारा अपमान करती है। गोरे यात्रियोके साथ ऐसा बरताव करनेकी उसकी हिम्मत नहीं होती। इसके तीन उपाय हैं। ये तीन उपाय एक साथ किये जाने चाहिए

(१) कम्पनीको सरत पत्र लिखा जाये।

(२) उसके एजेंट श्री उस्मान अहमद कम्पनीको सूचना दे कि ऐसा करनेसे कम्पनीको नुकसान पहुँचेगा।

(३) और यात्रियोको उसमे यात्रा करनेसे रोका जाये।

१ यहाँ नहीं दिये गये हैं।

तीसरी बात सबसे उत्तम है और वह की जा सके तभी पहली दो बातें शोभा देंगी। हममें नई ताकत आई है। उसे हमें हर चीजमें आजमाना चाहिए। ट्रान्सवालके कानूनका विरोध कर लेना काफी नहीं है। उसे तो अपने कामका केवल प्रारम्भ समझना चाहिए।

जापानका उदाहरण लीजिए। स्वाभिमान आ जानेपर वह जाति अपनी शिक्षा व्यापार, आबरू सबका खयाल रखने लगी है। हमारा भी चहुँमुखी विकास होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-२९०७

३२५ भारतीयोपर हमला^१

नये कानूनकी धूमधाम चल रही है। इसमें सन्देह नहीं कि लोग अब तो जेल जानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले शुक्रवारको सवेरे डबनसे नौ भारतीय आये। उसी दिन शामको ग्यारह और आये, और शनिवार तथा रविवारको सत्रह आये। इन सबके पास अपने अपने अनुमतिपत्र और पजीयनपत्र थे। इनमें से पैंतीस 'सुल्तान' जहाजसे उतरे। शेष दोमें से एक मद्रासी थे जो कायबश जोहानिसबग जा रहे थे, और एक गुजराती थे जो अक्टूबरसे डबन गये हुए थे और अब लौटकर जोहानिसबग जा रहे थे। पहली बात तो यह थी कि ये सब नये कानूनके अनुसार अनुमतिपत्र न होनेके कारण गिरफ्तार किये गये थे। शुक्रवारको श्री गांधी न्यायालयमें उपस्थित हुए थे, तब इन लोगोंको न्यायालयमें नहीं लाया गया था। परन्तु पुलिस प्रिटोरियामें आदेशकी प्रतीक्षा कर रही थी। इन्हें शनिवारको हाजिर किया गया था और सोमवार तक मुकदमा स्थगित रहा। सोमवारको श्री गांधी फिर जोहानिसबग आये। पुलिस यह मुकदमा नये कानूनके अन्तर्गत चलाना चाहती थी। किन्तु प्रिटोरियासे यह आदेश आया कि अनुमतिपत्र अध्यादेशके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाये। इसलिए अनुमतिपत्र अध्यादेशकी पाचवीं धाराके अन्तर्गत यह कहकर मुकदमा दायर किया गया कि इन लोगोंके पास अनुमतिपत्र नहीं है।

सार्जेंट मैन्सफील्डकी गवाही

मैंने इन भारतीयोंको गिरफ्तार किया। क्योंकि मुझे ऐसे भारतीयोंको गिरफ्तार करनेका प्रिटोरियासे आदेश है। इन लोगोंके पास अपना अपना अनुमतिपत्र था, किन्तु इन्हें लौटकर आनेका हुक्म नहीं है। इनके पास नये कानूनके अनुसार अनुमतिपत्र नहीं है, इसलिए गिरफ्तार किया।

जिरह

प्र० — इन लोगोंके अनुमतिपत्रोंकी आपने जाच की ?

उ० — हा, जाच करनेपर मुझे मालूम हुआ कि इनके अँगूठेकी निशानिया मिलती हैं।

१ यह लेख इन उप शीर्षकोंके साथ प्रकाशित हुआ था “नेटालसे ट्रान्सवाल जाते हुए सैंतीस व्यक्ति गिरफ्तार — न्यायालय द्वारा रिहा ।

प्र० — इन लोगोके पास १८८५ के कानूनके अनुसार लिये हुए पजीयनपत्र भी हैं ?

उ० — इन सबके पास वे पजीयनपत्र ह ।

प्र० — प्रिटोरियासे आपको क्या आदेश है ?

उ० — मुझे यह आदेश है कि बाहरसे आनेवाले प्रत्येक भारतीयको यदि उसके पास नये कानूनके अनुसार पजीयनपत्र या दूसरा अधिकार न हो तो गिरफ्तार किया जाये ।

प्र० — यह आदेश जिस भारतीयको आप पहचानते ह उसे भी पकड़नेके लिए है ?

उ० — हा अपने कतव्यके अनुसार मुझे तो सभीको पकड़ना चाहिए ।

प्र० — जिन अनुमतिपत्रोको आपने इन मुवक्किलोके पास देखा उस प्रकारके अनुमति पत्रोके आधारपर भारतीय अबतक बेरोक टोक आ जा सकते थे क्या ?

उ० — हा, उस समय मुझे ऐसा आदेश था कि ये अनुमतिपत्र पर्याप्त हैं ।

इसके पश्चात सरकारी वकीलने मुकदमा रोक दिया । श्री गांधीने मागकी कि सबूतके अभावमे इन लोगोको छोड़ देना चाहिए ।

सरकारी वकीलने स्वीकार किया कि उसका मुकदमा कमजोर है । परन्तु सरकारके आदेशसे उसने सम्मत्स बनाया है । जो अनुमतिपत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधारपर लोग प्रवेश करके रह सकते हैं, परन्तु जाकर लौट नहीं सकते ।

श्री गांधीने कहा कि सरकारी गवाहने ही मेरे मुवक्किलोके मुकदमोको सिद्ध कर दिया है । उन्होंने जो अनुमतिपत्र प्रस्तुत किया है, वही मेरे मुवक्किलोका प्रविष्ट होनेका अधिकार पत्र है । सम्मत्समे उनके विरुद्ध अनुमतिपत्रके बिना प्रवेश करनेका आरोप है । वह साबित नहीं हुआ । भाभाके मुकदमेमे न्यायालयने फैसला दिया है कि जिसे दाखिल होनेका अधिकार है उसको बाहर जाकर वापस लौटनेका भी अधिकार है । इसलिए मुवक्किलोको छोड़ देना चाहिए । इनमे से बहुत से तो आज चार दिनसे कष्ट भोग रहे हैं ।

यायाधीशने उपयुक्त दलीलको स्वीकार करके सबको छोड़ दिया । जिनपर मुकदमा चलाया गया था उनके नाम निम्न प्रकार हैं

उमर यूसुफ, नाथु गोविंद माधा गलाल, लाला माधव, गोविन्द दादी [दाजी ?], रतनजी महाराज कुवरजी मनोर, काला पेमा, नागर भवान, मोरार भीखा, समदरखा काना गोपाल, नाना वल्लभ, बाबा सुखा, परभु नारण, जसमत फकीर, फकीर लाखा हरि दाजी प्रेमा भाणा परभु छना, लल्ल खुशाल, रामसामी चोकलीग पिल्ले, मणि डाह्या, भीमा वसन, झीणा कीडिया, डाह्या पाँचा, वल्लभ गोविन्द धना हीरा, हरि भीखा, दयाल वल्लभ, मकन मोरार, मावव जीवण, गोविन्द डाह्या, बुधिया लाला, दाजी भाणा, रणछोड गोपाल, भीखा रतनजी ।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इनमे एक पठान, एक कोकणी, एक मद्रासी और अन्य गुजराती हिन्दू इस तरह सभी जाति लोग हैं ।

मुहम्मद इशाकका मुकदमा

यह मुकदमा फोक्सरस्टमे शुक्रवारको चला । सरकारी वकीलने कहा कि किस आरोपके सम्बन्धमे मुकदमा चलाया जाये, इसका उसे पता नहीं है । खबर मिलनेपर बताया जा सकता है । बहसके बाद न्यायाधीशने वह मुकदमा जोहानिसबग भेजना स्वीकार किया और यह आदेश दिया कि उसे बुधवारको जोहानिसबगमे चलाया जाये ।

श्री मुहम्मद इशाक और दूसरे भारतीयोंने जमानतपर छूटनेसे इनकार कर दिया। इसलिए सबको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इन मुकदमोंके कारण न्यायालयमें सरकारी हँसी हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२६ नेटालमें परवाना सम्बन्धी अर्जीके विनियम

नेटाल 'गजट'में नये परवानेके लिए अथवा परवानेके नवीनीकरण (प्रतिवष नये करवाने) के लिए अथवा परवानेके हस्तांतरणके लिए अर्जी देने और अपील करनेसे सम्बन्धित विनियम प्रकाशित हुए हैं। उनमें से सब उपयोगी खण्डोंका सारांश नीचे दिया जा रहा है

२ अर्जी निश्चित फामके अनुसार निर्धारित न्यायाधीश अथवा नगर कायालयमें दी जाये, तथा आवेदक उसे अपने क्षेत्रके लिए समाचारपत्रमें प्रति सप्ताह कमसे कम एक दिनके हिसाबसे दो सप्ताह प्रकाशित कराये।

४ अर्जी मिलनेके बाद उसमें बताये गये मकानके सम्बन्धमें परवाना अधिकारीको स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सफाई निरीक्षकसे स्वास्थ्य विभागकी रिपोर्ट प्राप्त करनेका अधिकार होगा।

५ आवश्यक हो तो अजदार स्वयं परवाना अधिकारीके पास उपस्थित हो ओर उसे दिखाये कि वह अंग्रेजीमें बहीखाते रखने सम्बन्धी ७वी धाराकी शर्तें पूरी करनेकी योग्यता रखता है। इस सम्बन्धमें सन्तोष करवानेके लिए वह परवाना अधिकारीको अपने बहीखाते अथवा अन्य आवश्यक कागज पत्र भी दिखाये।

६ प्रत्येक अर्जीकी स्वीकृति या अस्वीकृति सम्बन्धी निणय परवाना अधिकारी प्रत्येक अर्जीपर लिख दे।

८ जबतक आवश्यक टिकट न लगाये जाये अथवा उनके बदलेमें पैसे न जमा किये जाये, तबतक परवाना नहीं दिया जायेगा।

९ परवाना अधिकारी जिस अजदारसे चाहेगा उससे परवाना देते समय, हस्ताक्षर, अथवा अँगूठेकी निशानी, अथवा अँगुलियोंकी निशानिया ले सकेगा।

अपीलके विनियम

१० परवाना अधिकारी द्वारा निणय दिया जानेके पश्चात् दो सप्ताहके अन्दर अपील करने सम्बन्धी अपने इरादेकी निकाय या नगर-परिषदके क्लकको सूचना दी जाये। परवाने सम्बन्धी अपीलकी अर्जीके साथ निकायके सदस्योंके खचके लिए १२ पौड १० शिलिंग क्लकके पास जमा करने होंगे। अजदारोंकी सख्या एकसे अधिक होगी तो अपील निकायका खच हिस्सेके अनुसार आयेगा।

११ अपीलकी मुनवाईकी तारीखकी सूचना और अपीलकी सूची न्यायालय अथवा नगर-कार्यालयके दरवाजेपर निश्चित तिथिसे कमसे कम पांच दिन पहले चिपकाई जायेगी।

१३ लोगोकी जानकारीके लिए निकाय खुले रूपमे मुकदमेकी सुनवाई करेगा।

१६ अजदारको और अर्जिसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिको ऐसे प्रतिनिधिके द्वारा, जिसे व्यक्तिगत अथवा लिखित रूपसे अधिकार दिया गया हो सबूत पेश करनेका अधिकार है। अपीलका विरोध करनेवालेको भी वैसे ही अधिकार ह।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पजाबियोंकी याचिका

इस याचिकाके जवाबके बारेमे सरकार अभी विचार कर रही है। किन्तु दुनियाने इसका जवाब दे दिया है। इससे बहुत अग्रेजोका मन पजाबी सैनिकोके पक्षमे उत्तेजित हो उठा है। और सब चर्चा कर रह है कि उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। अभी इस याचिकाकी बात चलती ही रहती है। विलायतके 'डेली ग्राफिक' मे इस सम्बन्धमे सख्त टीका की गई थी। इसका हम उल्लेख कर चुके ह।

वापस ले लेता हूँ

श्री पारेखके जोशके बारेमे मैं लिख चुका हूँ।^१ लेकिन मैं देखता हूँ कि वह जल्दीमे लिखा गया था, इसलिए उसे वापस ले लेता हूँ। जब वह लेख लिखा गया तब श्री पारेख यूकैसिलमे थे। ठपते समय वही होंगे या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। किन्तु मैंने उहे खास रूपसे शूरोमे शामिल करके उदाहरण दिया था कि दूसरे लोग उनका अनुसरण करे, किन्तु उसमे भूल हो गई। शूर वह हे जो पहले रणमे चढे। श्री पारेख अभी ट्रांसवालके बाहर हैं। इसलिए मेरे लेखसे जो यह भाव निकलता था कि वे हम सबमे विशेष बहादुर ह वह अब नहीं रहा।

सरासर झूठ

श्री हसन अहमद कालाने सावजनिक रूपसे यह कहा था कि पजीयनकी अर्जी देकर वे स्वयं पठताये हैं, और उसे वापस लेना चाहते हैं। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन अर्जी वापस लेनेके विचारके सम्बन्धमे उन्होंने पत्र लिखा उसी दिन उन्होंने अपने भाई बंदोको ऐसा भी खानगी पत्र लिखा कि उहे जट्दीसे गुलामीके पट्टे मिल जाये तो अच्छा हो। उन लोगोको इतने दिन तक पट्टे नहीं मिले उसके लिए उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। हमारे बीच ऐसी बातें न हो इस दृष्टिसे मैं इस झूठको कतव्य समझकर प्रकट कर रहा हूँ। मुझे खेद है कि श्री काला पीटसबर्गमे धरनेदार रहे हैं। इसलिए श्री चैमनेको यह कहनेका मौका मिला है कि धरनेदारोने भी पजीयनके लिए अर्जी दी है।

स्वेच्छया पजीयन यानी क्या ?

इस सम्बन्धमे इस अखबारमे कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज भी सब भारतीय उसका अर्थ नहीं समझते। जैसे गोरे तबतक नहीं समझते थे कि नया

कानून क्या है, जबतक कि समय नहीं आया, वैसा ही हाल हमारा है। स्वेच्छया पजीयन ओर कानूनके अनुसार पजीयनमें मुख्य अंतर यह है कि कानून गुलाम बनाता है ओर स्वेच्छया पजीयन मनुष्य बनाता है। सरकारके दबावके कारण पजीकृत होना गवैकी सवारी है, जब कि स्वेच्छया पजीयन हाथीकी सवारी है। स्वेच्छया पजीयनमें भले ही अनिवाय पजीयनक जितनी ही बात लिखनी पड, फिर भी उसे स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु अनिवाय पजीयनकी गुलामी सम्बन्धी कोई खास बात छोड देनेसे गुलामी समाप्त नहीं होती। कानून बहुत कडा है। इसीलिए स्थानीय सरकार उससे जाकके समान चिपटी हुई है। ओर इसीलिए हम पद्रह महीने हो गये उसे चिपटने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम गोरोके साथ एक धरातलपर रहना चाहते हैं और गोरे हमें नीचे उतारना चाहते हैं। कानूनको स्वीकार करनेसे शपथ टूटती है और हमेशाके लिए काला टीका लगता है। कोई पूछ सकता है कि स्वेच्छापूवक भी हम अपने पजीयनपत्र क्यों बदलाये? इसका उत्तर बहुत ही सरल ओर सीधा है

- (१) जिस प्रकार कानूनका विरोध करनेकी हमने शपथ ली है, उसी प्रकार दस्तावेजको स्वेच्छापूवक बदलवानेकी बात भी हम कहते आये हैं। अत यदि अब हम वसा नहीं करते तो हमारी टेक जाती है, ओर हम झूठे ठहरते हैं।
- (२) भारतीय समाजपर यह आरोप है कि उसके बहुत-से लोग झूठे अनुमतिपत्रोंके द्वारा अथवा बिना अनुमतिपत्रोंके प्रविष्ट हुए हैं। यह आरोप गलत है। इसे हम स्वेच्छया पजीयनके द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ओर वैसा सिद्ध करना कतव्य है। और चूकि हम सिद्ध करनेको तयार हैं, इसीलिए दुनियाकी सहानुभूति अपनी ओर खींच सके हैं।
- (३) स्वेच्छया पजीयनसे इनकार करनेका मतलब यह स्वीकार करना है कि हम झूठे हैं।
- (४) हमने जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है स्वेच्छया पजीयनसे हम उससे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह नियम याद रखना चाहिए कि जब लोग अपने आप कोई काम नहीं करते, अर्थात् कमजोरी बताते हैं, तभी कानून बीचमें आकर वह काम करनेके लिए मजबूर करता है। बहुतेरे काफिर अपने आप शराब पीनेसे नहीं रुकते, इसलिए जहा रोकना जरूरी जान पडता है वहा कानून बीचमें आकर विवश करके रोकता है। जो आदमी कतव्य समझकर नहीं, बल्कि कानूनके बंधनके कारण ही शराब नहीं पीता वह गुणी नहीं कहा जाता, जो अपने आप नहीं पीता वह गुणी माना जाता है। इसी प्रकार अनिवाय और स्वेच्छया पजीयनके बारेमें समझा जाये।
- (५) स्वेच्छया पजीयनसे हम सदा खुले रह सकते हैं। क्योंकि उसमें हम जितना बंधना चाहे उससे ज्यादा हमें कोई बाध नहीं सकता। स्वयंसेवक-सिपाहीको अच्छा लगता है तभी वह लडाईमें जाता है और भूखका मारा वेतनभोगी सिपाही हमेशा लडाई करनेके लिए बंधा हुआ है।

इसी प्रकार स्वेच्छया पजीयनके ओर भी बहुत से फायदे बताये जा सकते हैं। फिलहाल इतने काफी हैं। अँगुली आदिकी बातोंका समावेश इसमें नहीं होता। क्योंकि वह हमारी मर्जीकी बात है। किंतु दस अँगुली और दो अँगूठोंके बीच त्रैज्ञानिक दृष्टिसे क्या अंतर है इसपर अगले सप्ताह विचार करेंगे। अभी तो स्वेच्छया पजीयन क्या है, यह ठीक तरहसे समझना है।

एक आपत्ति

अब किसी भी समय समझौता हो जाये, इसलिए सधने स्वेच्छया पजीयनके बारेमें चर्चा शुरू की है। उसपर कुछ सज्जनोंने यह आपत्ति की है कि सबकी सलाह क्यों नहीं ली जाती। यह बात ठीक नहीं है। यदि स्वेच्छया पजीयनकी बात नहीं होती तो अवश्य ही विभिन्न जगहोंसे प्रतिनिधियोंको बुलाना पड़ता। किन्तु एम्पायर नाटकघरमें जो सावजनिक सभा हुई थी उसमें सभी जगहोंसे बुलाये गये प्रतिनिधियोंने स्वेच्छया पजीयन-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया था तथा उसके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली थी। इसलिए अब सब जगहोंके प्रतिनिधियोंको बुलानेकी बात नहीं रहती। न उसके लिए समय ही है। फिर भी हर भारतीय चाहे जब अपने विचार प्रकट कर सकता है। इस कानूनकी लड़ाईके अंतमें हम चाहते हैं कि हमें राजकीय मामलोंकी बूझ हो जाये। सभाएँ किस प्रकार की जाती हैं, दूसरे सगठन किस प्रकार काम करते हैं और कौमी कामका किस प्रकार संचालन किया जाता है एवं उसे निभाया जा सकता है, यह भी आ जाना चाहिए। हम दरअसल सभ्य हैं यह कहकर हम नये कानूनको रद्द करानेका महा प्रयत्न कर रहे हैं, तब उपयुक्त बातोंका ज्ञान भी सच्ची सभ्यताका चिह्न है।

परीक्षात्मक मुकदमा क्यों न चलाया जाये ?

कुछ लोग आपसमें पूछताछ कर रहे हैं कि हम नये कानूनके सम्बन्धमें परीक्षात्मक मुकदमा क्यों न दायर करें। उसके बारेमें मैंने अपना जो विरुद्ध मत जाहिर किया है, उसके दो कारण हैं

एक तो यह कि हमारी लड़ाई मुकदमा लड़नेकी नहीं बल्कि जेल जाकर अपना बल दिखानेकी है। आत्मबलके समान दूसरी कोई चीज नहीं है। तब यदि परीक्षात्मक मुकदमा चलाया जाये तो उसमें हमारी लड़ाई बिगड़ जायेगी और हमारी हँसी होगी। गोरे तुरन्त कहने लगेंगे कि “जेल जानेवाले कहा गये ?” इसलिए परीक्षात्मक मुकदमा लड़ना अपनी कमजोरी दिखानेके समान है।

दूसरा यह कि, नये कानून ओर उपनिवेशके दूसरे कानूनोंको सम्राटकी न्याय परिषद शायद ही रद्द कर सकती है। श्री लेनड, श्री एसेलेन, श्री ग्रेगरोवस्की, श्री डक्सबरी, श्री वाड और श्री डी' विलियस हमारे विरुद्ध मत व्यक्त कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालयने तो ऐसे फैसले बहुत किये हैं। यदि नया कानून सम्राटकी न्याय परिषद रद्द कर दे तो उसका अर्थ यह होगा कि काफ़ीरोंके खिलाफ जो कानून बनाये गये हैं वे भी रद्द हो जायेंगे। यह कभी होनेवाला नहीं है। और यदि हो भी तो उस स्थितिको सुधारनेके लिए तुरन्त ही दूसरे कानून बनाने होंगे। यानी यह आगे जाकर पीछे फिरनेके समान होगा। विलायतसे हमने राय मँगवाई थी, किन्तु श्री रिच अभीतक नहीं भेज पाये। क्योंकि सर रेमंड वेस्टके सिवा और कोई राय देता नहीं है। इसके अलावा, हमें याद रखना चाहिए कि सर रेमंड वेस्टने हमें कानूनका विरोध करनेके बजाय परीक्षात्मक मुकदमा लड़नेकी सलाह दी थी। अब वे भी अनाक्रमक प्रतिरोधियोंके पक्षमें आ गये हैं। इसलिए परीक्षात्मक मुकदमा कैसे हो ? इसके अलावा, किसीको यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षात्मक मुकदमेमें १,००० पौंडकी बात है। उतनी रकम इकट्ठा करनेकी ताकत किसमें है ? इसीके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि

परीक्षात्मक मुकदमेके दिनोमे सरकार किसीको परेशान नहीं करेगी, सो बात नहीं है। उस अवधिमे कानून बंद नहीं रह सकता।

हमीदिया अजुमनकी सभा

रविवारको फिर एक जोरदार सभा हुई थी। लोग इतने आये थे कि वे सभा भवनमे समा ही न सकते थे। इसलिए बाहर मैदानमे सभा हुई थी। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री सूज, श्री मणिभाई देसाई, श्री पिल्ले, श्री गोपाल, श्री बेग तथा श्री व्यास खास तोरसे इसीलिए आये थे। इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। उन्होंने तथा श्री सूज, श्री बेग, श्री काछलिया, श्री नायडू, श्री हजूरसिंह, श्री अहमद खा, श्री अलीभाई आकूजी, आदि सज्जनोने भाषण दिये। श्री गांधीने हकीकत समझाई। श्री मोलवी अहमद मुरत्यारने भी, जो किसी कामसे डेलागोआ-बे जाकर अभी लौटे थे, लोगोको समझाया। अतमे सबने स्वीकार किया कि स्वेच्छया पजीयन तो करवाया ही जाये। किन्तु अँगूठोकी निशानी देनेमे पजाबी भाइयोको विरोध था। दूसरोका कहना था कि दोनो अँगूठोकी निशानी मर्जीसे देनेमे हज नहीं है। लोगोका यह जोश प्रशंसनीय है। इससे प्रकट होता है कि लोग अपने विचार जाहिर करनेमे डरते नहीं हैं और हिम्मतसे बोलते हैं। जो छ महीने पहले कानूनको जरा भी नहीं समझते थे वे अब कुछ कुछ समझने लगे हैं। यह सब आत्मबल आजमानेका फल है। मैं जानता हूँ कि अतमे सब समझने लग जायेगे, क्योंकि दो अँगूठोकी निशानी देनेमे अप्रतिष्ठा नहीं है। किन्तु यदि वही काम अनिवार्य रूपसे करना पड़े तो उसमे अप्रतिष्ठा है। कानून समाप्त हुआ कि हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हो गये हैं।

डेलागोआ-बेकी दीन स्थिति

मौलवी साहब डेलागोआ बेसे खबर लाये हैं कि जब सारे दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाज जाग गया है और इज्जतके लिए लड़ रहा है तब डेलागोआ-बेके नेता सो रहे हैं। वहाकी सरकार उन्हें जितना मारती है उतना सब वे चुपचाप सहन करते हैं। लोगोको इज्जतकी परवाह नहीं है। वे तो यही समझते हैं कि पैसा मिला तो परमेश्वर मिल गया। ओर सरकारके सामने तो जी हजुरी करते हैं। इस दीन स्थितिसे क्या डेलागोआ-बेके भारतीय उठेगे नहीं?

भारतीयोका जोर

नये कानूनके सम्बन्धमे सरकार ढीली ही होती जा रही है। यह बात अब गोरे भी देख रहे हैं। 'रेड डेली मेल' तथा 'सडे टाइम्स'मे दो व्यंग्य चित्र दिये गये हैं। एकमे दिखाया गया है कि स्मट्स साहब भारतीयोपर नया कानून रूपी पिस्तौल छोड़ रहे हैं। भारतीय कहते हैं — "आपसे जितना बने उतना करे। हम तो कानूनके सामने नहीं झुकेगे।" तब स्मट्स साहब बोल उठते हैं, "अरे यार, ऐसा मत कहो, मेरी पिस्तौल काम नहीं देती।" दूसरे व्यंग्य चित्रमे जनरल स्मट्स और अन्य सरकारी अधिकारी भारतीय समाजके नेताओके सिर भालासे उडाना चाहते हैं। परन्तु उनकी मेहातसे उनके घोड़े थककर चूर चूर हो गये हैं, और सवारोका दम निकला जा रहा है, फिर भी नेताओके सिर तो अभी कायम ही हैं। ये दोनो चित्र गोरोके मनकी स्थिति बताते हैं। 'इंडियन ओपिनियन' के सम्पादक महोदय वे दोनो चित्र अपने ग्राहकोके लिए प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा।

सधकी विजय

पहले बगकी बगधीमे भारतीयोको न बैठने देनेके सम्बन्धमे नगरपालिकाने नियम बनाया था। श्री ईसप मियाने उसके खिलाफ पत्र^१ लिखा था। यह पाठकोको याद होगा। अब स्मट्स साहब लिखते हैं कि सरकार वह नियम मजूर नहीं करेगी। क्या स्मट्स साहब भी बदले हैं? इससे प्रकट होता है कि भारतीय समाजके जोरसे लाभ ही होता है।

पासपोर्ट नहीं मिलेगे

श्री मूसा इस्माइल मिया तथा श्री दावजीको पासपाट न मिलनेसे उन्होंने उस सम्बन्धमे लाड सेल्बोनको अर्जी दी थी। लॉड सेल्बोनने उसके जवाबमे लिखा है कि यदि सरकार पासपाट दे देती है तो इसका अर्थ इसके बगबर होगा कि दोनों भारतीय पजीकृत नहीं हुए, फिर भी सरकारने उनका वापस आनेका अधिकार स्वीकार कर लिया है। यह बात यही खतम नहीं होगी। श्री गांधीने फिर लाड सेल्बोनको पत्र^२ लिखा है कि यदि उपयुक्त फैसला कायम रहा तो यह साबित होगा कि भारतीय समाज ब्रिटिश प्रजा बिलकुल नहीं है। यदि ऐसा हो तो वह भी अच्छा है। इससे हमारी लड़ाईको अधिक बल मिलता है।

नये कानूनकी एक धारा

नये कानूनकी एक उपधारा स्वर्गीय श्री अबूबकरके उत्तराधिकारीके लिए लाभप्रद मानी जाती थी। उसपर लॉड सेल्बोन और लाड एलगिन सबने जोर दिया था। अब वह भो उड़ गई है। उस उपधाराके अंतगत जमीन उत्तराधिकारियोके नामपर करनेका प्रयत्न किया गया तो स्मट्स साहबने आपत्ति की और कहा कि वह उपधारा इस केसमे लागू नहीं होनी, क्योंकि जमीन तो गोरोके नामपर ही चढ़ी हुई है। अदालतने इस आपत्तिको माय कर लिया है, यद्यपि उसने सहानुभूति व्यक्त की है। किंतु वह सहानुभूति किस काम की? अतः कानूनकी एक धारा भी अभी तो बेकार हो गई है। यह बात भी इतनेपर ही समाप्त हो जायेगी, सो नहीं। उत्तराधिकारियोका विचार आगे बढ़कर न्याय प्राप्त करनेका है। किंतु इस बीच इस मामलेका विपक्षमे निणय हो जानेके कारण कानूनके खिलाफ एक दलील और बढ़ गई है और उस सम्बन्धमे लिखा पढी शुरू हो गई है।

कानूनका शिकार

नया कानून ऐसा काल-रूप है कि हमेशा भक्ष्य लता रहता है। भारतीयोका खून इस राक्षसको प्रिय है। कई हजूरिये बे रोजगार होकर बठे हैं। मजदूरोके पास काम नहीं है। सिपाहियोकी पुकार हमने सुन ही ली है। अब श्री मोहनलाल जोशीपर आ बीती है। श्री मोहनलाल जोशी प्रिटोरिया न्यायालयमे अच्छे वेतनपर दुभाषियोकी नौकरी करते थे। पजीयन न करवानेके कारण सरकारने उहे काय विरत कर दिया है। यह जुल्म कम नहीं है। उनके बाल बच्चे हैं फिर भी श्री जोशीने देशके खातिर नौकरीकी परवाह नहीं की। परन्तु उन्होंने अपनी और समाजकी आबरू रखी इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस प्रकार बेरोजगार होनेवालोको नौकरी देना भारतीयोका काम है। जिन भारतीयोको मुशीकी जरूरत हो उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि वे श्री जोशी तथा उसी तरह बेरोजगार होनेवाले लोगोको काम दे।

१ देखिए “पत्र उपनिवेश सचिवको पृष्ठ ४०८।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

शोक

यहाके प्रसिद्ध व्यापारी श्री दादाभाइका स्वदेशसे खबर मिली हे कि उनके बड़े लडकेका प्लेगसे देहात हो गया। इससे वे अत्यंत शोक ग्रस्त हो गये हैं। उहे बहुत-से लोगोकी ओरसे समवेदना प्राप्त हुई है। उनमे मै भी शामिल होता हूँ।

मुहम्मद इशाकका मुकदमा

यह मुकदमा^१ बुधवारको श्री जोडनकी अदालतमे पेश हुआ था। सैतीस भारतीयोपर जो आरोप लगा था वही श्री मुहम्मद इशाकपर भी लगाया गया। श्री चैमने भी उपस्थित थे। उनके विरुद्ध बयान देनेवाले अविकारीने वैसा ही बयान दिया, जसा सतीस आदमियोके मुकदमेमे दिया था। श्री गाधीने श्री मुहम्मद इशाकको बिना बयान लिये छोड देनेकी माग की। श्री जोडनने लम्बा फैसला देते हुए कहा कि श्री मुहम्मद इशाकको अपने अनुमतिपत्रके आधार पर रहनेका पूरा हक हे। शांति-रक्षा अध्यादेशके आधारपर उन्हे बिलकुल निर्वासित नही किया जा सकता। इसलिए उहे निर्दोष मानकर छोड दिया गया।

लिड्जेका भाषण

श्री लिड्जे प्रगतिशील दलके एक नेता है। उहोने भाषण देते हुए कहा कि सरकार भारतीयोपर कोई सरती नही बरतेगी। प्रवासी कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किये जानेके लिए नही बनाया गया है। भारतीयोको निकालनेका एक ही रास्ता है कि उनके परवाने बद किये जाये। यह काम जनवरी महीनेसे किया जा सकेगा। किन्तु इस सबको मै बकवास समझता हूँ। पहली बात जेलकी थी। फिर देश निकालेकी चली। अब परवानेपर आये हैं। इस तरह यदि भारतीय समाज अतक हिम्मत और एकतासे रहा तो कानून अपने आप सो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

१ देखिय 'मुहम्मद इशाकका मुकदमा', पृष्ठ ४०७ ८ ।

३२८ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जोहानिसबग
दिसम्बर १४, १९०७]

[सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,]

निवेदन है कि कल मैं जोहानिसबग जेलसे छोड़ दिया गया। मुझे एशियाई कानून सशोधन अधिनियम तथा शांति रक्षा अध्यादेशके अंतर्गत एक मासका कारावास हुआ था, क्योंकि गत तीस सितम्बरके बाद भी, जो मेरे अनुमतिपत्रकी अवधिका अंतिम दिन था, मैं उपनिवेशमें बना रहा। मैंने एशियाई पजीयककी इस आज्ञाका कि मैं उपनिवेशसे चला जाऊँ, उल्लंघन किन कारणोंसे किया, इसका उल्लेख मैंने उनके नाम लिखे अपने पत्रमें किया है। जर्मिस्टनका हिंदू मंदिर आज जिस रूपमें है सो मेरी ही बदौलत है। मैं उस मंदिरका एकमात्र पुरोहित था और अब भी हूँ। कल वहाँ जानेपर मने उसे उजड़ी हुई दशामे पाया। मंदिर पूरे माह बन्द पड़ा रहा। कल उस मंदिरकी हालत देखकर मेरी जो मनोदशा हुई उसे मैं यहाँ पर्याप्त रूपसे व्यक्त करनेमें असमर्थ हूँ।

मैं जानता हूँ कि यदि मैं कारावाससे बचना चाहता हूँ तो उपनिवेशके कानूनके अनुसार मुझे सात दिनोंके अंदर उपनिवेश छोड़ देना चाहिए। परंतु उपनिवेशके कानूनोसे भी उच्चतर एक अन्य कानून मुझे दूसरा ही माग ग्रहण करनेको प्रेरित करता है। वह माग यह है कि एक ब्रिटिश प्रजा और जर्मिस्टनके हिंदू मंदिरका पुरोहित और धर्मोपदेशक होनेके नाते, परिणामोका विचार किये बिना, मैं अपने कतव्य पथपर दबूँ रहूँ। अतः अत्यंत विनय और आदरके साथ साम्राज्य सरकारके तथा स्थानीय सरकारके प्रति अपने कतव्योंका पूरा खयाल रखते हुए मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि उपनिवेशसे बाहर चले जानेका मेरा इरादा नहीं है। यदि सरकार अनुमतिपत्र प्रदान करके मुझे अपने मन्दिर तथा मंदिरमें आनेवाले भक्त-समाजके प्रति अपने कतव्यका पालन करने दे — और मैं इसके निमित्त इसीके द्वारा आवेदन भी कर रहा हूँ — तो उक्त समाज और मैं स्वयं सरकारकी शक्तिकी सराहना करेगे।

इस सम्बन्धमें मैं यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि जिन आरोपोंका इशारा एशियाइयोंके पजीयकने किया था और जिनकी बिनापर मेरे अनुमतिपत्रकी अवधि बढ़ानेसे इनकार किया गया है, उनका अबतक मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जहातक मैंने उनका अनुमान किया है, वे निरावार थे। यदि मेरे विरुद्ध कोई आरोप हो तो मेरी प्रार्थना है कि वे सूत्रबद्ध कर लिये जायें और मुझपर मुकदमा चलाया जायें, और यदि मैं अपने किसी भी काममें अपने धर्मसे, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, अथवा धर्मोपदेशकके कर्तव्यसे डिग गया होऊँ तो मुझे तुरन्त और स्वयमेव उपनिवेश छोड़ देना चाहिये। यदि मुझपर लगाये गये आरोप इस प्रकारके हैं जिनके बलपर कानूनन मुझपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता तो भी मैं

ऐसे किसी निष्पक्ष कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिके सामने, जिसे सरकारने खास इसी कामके लिए नियुक्त किया हो, उनका जवाब देनेको तैयार हूँ। यह कमसे कम है, जो मैं एक सभ्य और शिष्ट सरकारसे मागनेकी धष्टता कर सकता हूँ।

[आपका, आदि,
रामसुन्दर पण्डित]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३२९. पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबग
दिसम्बर १८, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव

[प्रिटोरिया]

महोदय,

सदभ स्वर्गीय अबूबकर आमद [की] जायदाद

जैसा कि सरकारको मालूम है, एशियाई कानून सशोधन अधिनियमकी धारा १७ इसलिए जोड़ दी गई थी कि इस जायदादके उत्तराधिकारियोंको राहत मिले और वे न० ३७३, चच स्ट्रीट, प्रिटोरियाकी जायदाद, जिसे स्वर्गीय अबूबकर आमदने १८८५ के कानून ३ के पास होनेसे पहले खरीदा था, अपने नाम रख सके। गत वर्ष इस धाराका मसविदा तैयार होनेसे पहले वे परिस्थितिया, जिनके अतगत यह जायदाद श्री पोलकको हस्तांतरित की गई थी, तत्कालीन महायायवादीके सामने रखी गई और ऐसा समझा गया कि यह धारा इस मामलेको सुलझानेके लिए प्रस्तुत की गई है। इस जायदादका पट्टा उत्तराधिकारियोंके पक्षमें, जो भारतीय है, पजीयनके लिए तैयार किया गया और पट्टोके पजीयकके समक्ष पेश किया गया। परंतु उन्होंने हस्तांतरणको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनकी सम्मतिमें यह मामला इस धाराके अतगत नहीं आता था। तब यह मामला यायमूर्ति वैसेल्सकी अदालतमें पेश हुआ। उन्होंने पजीयकके मतको बहाल रखा। इस तरह सम्बंधित धारा उत्तराधिकारियोंको राहत देनेमें बेअसर साबित हुई है। क्या मैं भरोसा करूँ कि सरकार इन उत्तराधिकारियोंको राहत देगी? मेरी विनम्र रायमें इसे करनेकी सबसे सत्वर विधि होगी उक्त स्ट्रीटको भारतीयों द्वारा कब्जा करने योग्य करार देना।^१

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-२-१९०८

१ किन्तु इसे अधिकारियोंने अस्वीकार कर दिया था।

३३० पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको

[जोहानिसबग]

दिसम्बर, २०, १९०७

महाप्रबन्धक

म० द० आ० रेलवे

जोहानिसबग

महोदय,

मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेमे नोकरी करनेवाले स्टैडनके भारतीयोंके जिस मामलेके बारेमे मैंने आपसे टेलीफोनपर बात की थी वह, जितना अधिक मैं सोचता हूँ, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण दिखलाई देता है। फलतः मेरे सघका यह कतव्य होगा कि वह प्रयत्नपूर्वक सावजनिक सदाचार तथा, आवश्यकता पडनेपर, कानूनके प्रश्नके रूपमे उसका समाधान ढूँढे। लेकिन मेरा सघ कानूनी सघषको टालनेके लिए अत्यधिक उत्सुक है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि सम्भव हो तो आप उनको नोटिसके बदलेमे एक मासका वेतन दे दें। मेरी नम्र सम्मतिमे इन लोगोंको कमसे कम इतनी सी सुनवाईका हक्क जरूर है। शायद मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि मैंने स्टैडनकी समितिको तार भेजकर उन आदमियोंको यह सलाह दी है कि वे एक माहके नोटिसके बदलेमे मजदूरीका दावा करेका अपना अधिकार सुरक्षित रखत हुए, जो कुछ भी उन्हें दिया जाये, उसे स्वीकार कर लें।

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

अवैतनिक मंत्री

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३३१ अधीरता

हम देखते हैं कि ट्रान्सवालके कुछ भारतीय अब लडाईका अंत देखनेके लिए उतावले हो रहे हैं। किंतु अभी लडाईका अंत जरा दूर दिखाई देता है। बड़े बड़े काम एकाएक नहीं बन जाते। दक्षिण आफ्रिकामे सब जगह सब लोग समझते हैं कि यह लडाई भारतीयोंकी प्रतिष्ठा रखनेके लिए है। हम सब एक प्रजा हैं, हमें हक मिलने चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, यह सब बातें दिखाना इस लडाईमें निहित है। इतनी बड़ी विजय प्राप्त करनेके लिए उतावली करनेसे क्या होगा? बहुत से जेल जाकर अपने आपको गढ़ेंगे और बाकी लोग प्रबल रहेंगे, तभी किनारा लगेगा।

हमारी इस बारकी जोहानिसबर्गकी चिट्ठीसे मालूम होगा कि स्मट्स साहब अभीतक डिग्रे नहीं है। इससे प्रकट होता है कि उनके पास अब भी छिपी खबर है कि भारतीय अंतमें हार जायेंगे। परवानोका इलाज अभी उनके पास है जो आजमाना बाकी है। सारी बातें आजमाये बिना वे भारतीयोंको परेशान करना क्यों छोड़ दें? लडाईमें सैनिक विवश हो जानेपर ही आत्मसमर्पण करते हैं। हमारी लडाईमें खून खराबी नहीं होती और सच्चे गोला-बारूदका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए कोई यह न समझ ले कि यह लडाई नहीं है। है तो हमारी भी लडाई ही। अंतर केवल इतना है कि इस लडाईमें हमारी ओर सत्य है। इसलिए परिणाम एक ही हो सकता है। किंतु यदि हम अंधीर बनें, तो समझ लीजिए कि सत्य उतना ही कम हो जायेगा। और जब सत्यको जीतना है तो वह धीरे धीरे ही जीता जा सकता है। वास्तवमें वह जीत बहुत ही कम समयमें मिली यही माना जायेगा। किंतु ऊपर ऊपर देखनेसे हमें आभास होता रहता है कि उसमें हमें ज्यादा समय लगता है। जो अपना सब कुछ बलिदान करनेको तैयार है तथा अपनी शपथ और प्रतिष्ठाकी प्राणके समान रक्षा करते हैं उन्हें समय जानेसे कुछ खोना है ही नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३२. रामसुन्दर पण्डित

पण्डितजी छूट गये, और जबतक यह अक हमारे पाठकोके हाथमे पहुँचेगा तबतक फिर पकड़े भी जा सकते हैं। पण्डितजीका जीवन अब अपना नहीं रहा, वह सावजनिक है। उन्होंने अपना जीवन समाजको समर्पित कर दिया है। अब वापस नहीं ले सकते। पण्डितजीका उत्साह बहुत ही प्रशंसनीय है। उनपर बड़ी जिम्मेदारी है। वे खुद पुजारी ह और ब्रह्मकी शिक्षा देते हैं। इसलिए हम उनमे वैराग्य या फकीरीका दशन पानेकी आशा करते हैं। वैसे पुरुषको वीतराग, सहज सुशील, शांत, सत्यवादी और अपरिग्रही होना चाहिए। जबतक ऐसे लोग बड़ी सरयामे पदा नहीं होते तबतक भारतकी मुक्ति भी नहीं होगी। पण्डितजीने जबरदस्त कदम उठाया है और जो सम्मान प्राप्त किया है उसे वे सदा ही बनाये रखेंगे, ऐसी आशा है और ईश्वरसे प्रार्थना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३३ हाजी हबीब

श्री हाजी हबीबने ट्रान्सवाल छोड़ दिया है और अब वे डबनमे रहनेवाले हैं। इसलिए प्रिटोरियामे उन्हें भोज दिया गया था। उसका हाल हम इस अकमे छाप रहे हैं। समाजका यह समय इतना खराब है कि ऐसे समयमे मान-सम्मान आदिका खयाल हो, यह सम्भव नहीं। नहीं तो क्या श्री हाजी हबीबकी विदाई भोजसे ही हो जाती? श्री हाजी हबीबकी [समाज] सेवा बहुत ही दीर्घकालीन है। श्री हाजी हबीबने सकड़ो लोगोका इतना काम किया है कि उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। और इतना सब करनेमे उन्होंने अपना लाभ नहीं देखा। समाजके कामके लिए वे सदा तैयार ही रहे। उनमे जितनी आतुरता है उतनी ही होशियारी भी है। उनके साथ बहस करनेमे गोरे अधिकारी मुसीबतमे आ पड़ते थे। हमे आशा है कि श्री हाजी हबीबने ट्रान्सवालमे जैसा काम किया है वसा ही वे डबनमे भी करेंगे, और सावजनिक काममे पूरा हिस्सा लेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३४ रामसुन्दर पण्डित^१

श्री रामसुन्दर पण्डित १३ तारीखको जेलसे छूट गये। उनका स्वागत करनेके लिए बहुत-से भारतीय जेलके दरवाजेपर हाजिर थे। उनमें श्री ईसप मिया, मौलवी साहब, श्री फैन्सी, श्री थम्बा नायडू, श्री उमरजी, श्री गावी आदि थे। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री पिल्ले तथा श्री गोपाल आये थे। वे ठीक साढ़े आठ बजे जेलसे बाहर आये। चीनी सघकी ओरसे श्री क्विन आदि उपस्थित थे। पण्डितजीका स्वागत फूल मालाओं और गुलदस्तोंसे किया गया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

गदारोकी सख्यामे वृद्धि

एक बार तो एशियाई कार्यालय सच ठहरा है, उसके कथनानुसार कुल मिलाकर ५११ भारतीयोंने गुलाम बननेके लिए अर्जिया दी है। भारतीयोंके हिसाबसे केवल ३९९ लोगोंने ही अर्जिया दी है। किन्तु मेरे पास वास्तविक खबर पहुँची है। उससे मैं देखता हूँ कि ५११ ही सही सरया है। किन्तु उसमें जो ज्यादा खेदजनक खबर है सो यह है कि सेठ एम० सी० कमरुद्दीनकी पेनीके श्री हसन मिया कमरुद्दीन झटाम भारतीय विरोधी कानून-निधिके कोषाध्यक्ष श्री गुलाम मुहम्मद दुरजुग तथा प्रिटोरियाके श्री हाजी कासिम, हाजी जूसब तथा श्री अली हबीब ये सब काला मुह करवा चुके हैं। श्री हसन मियाकी बात में छोड़ देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस कानूनके बारेमें उनके मनमें एक पागलपन समाया हुआ है। किन्तु श्री गुलाम मुहम्मदकी बात बहुत ही खेदजनक है। जान पड़ता है, इन दोनोंने बहुत ही गुप्त तरीकेसे काला काम किया है। इनके बारेमें कुछ समय पहले एक अफवाह उड़ी थी। किन्तु मैंने उसपर भरोसा नहीं किया। वह अफवाह सच निकली यह देखकर मैं लज्जित हूँ। श्री हाजी कासिम तथा श्री अलीने भी बहुत ही छिपे तरीकेसे अपनेको पजी-कृत किया जान पड़ता है। उनके शब्द मुझ यह लिखते समय भी याद आते हैं। उन्हें यहाँ लिखना यद्यपि बकार मानता हूँ, फिर भी इतना कहना तो अपना कतव्य समझता हूँ कि श्री हाजी कासिम तथा श्री अली जैसे लोगोंको पजीकृत होना ही था तो हिम्मतके साथ सामने आकर होना चाहिए था। सूचीमें उनका नाम मैं देखता हूँ। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने अन्तमें हाथ धिसे हैं। मेरे लिखनेसे उन्हें चोट पहुँचेगी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी नामर्दीकी खबर सुनकर मुझे जो चोट पहुँची है उससे अधिक चोट उन्हें नहीं लगी होगी। समाजके भीतरसे झूठी शम, झूठा डर और झूठा काम निकल जाये, यही

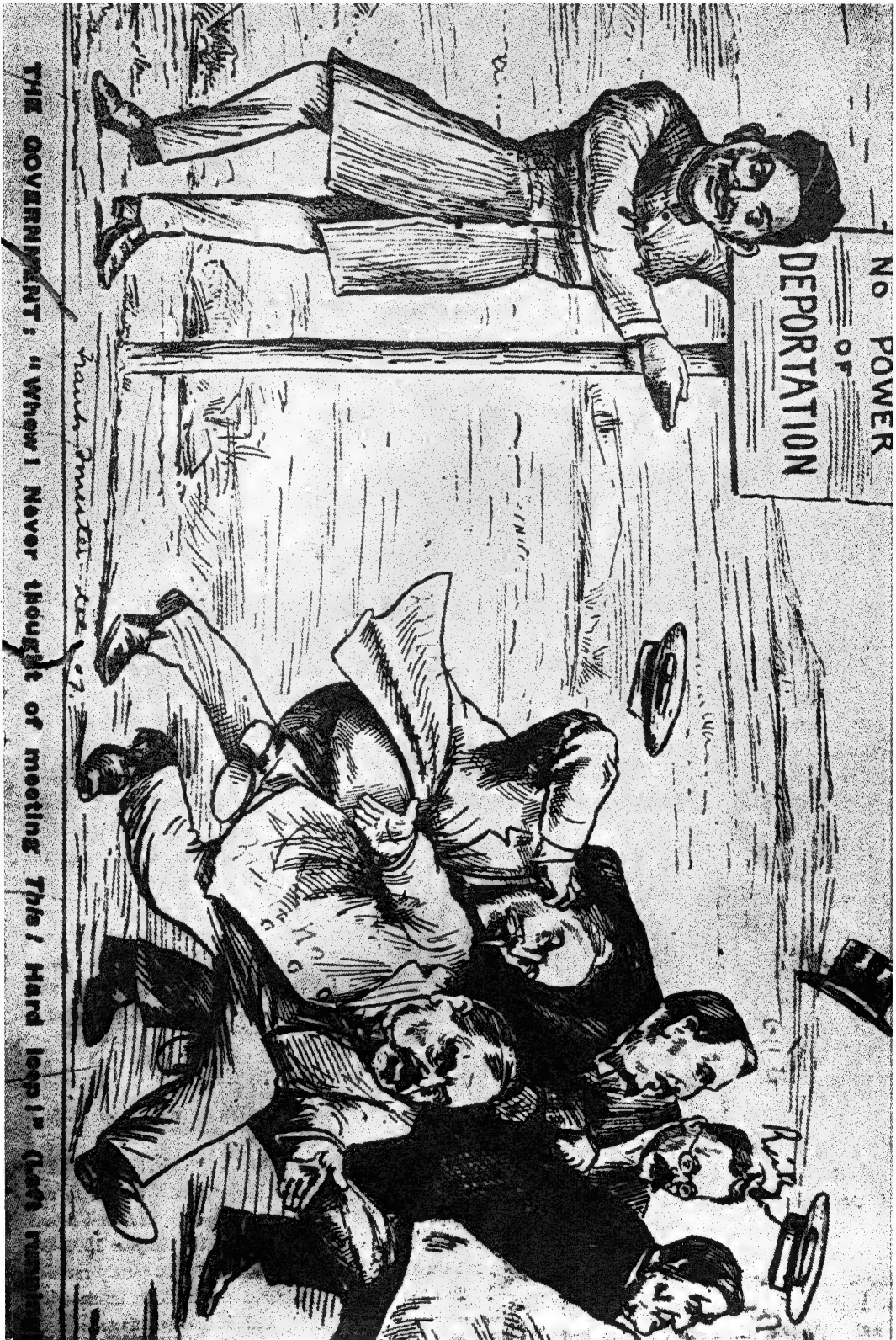
सोचकर मुझे ये नाम सावजनिक तौरसे प्रकट करने पड़े हैं। इनके अलावा खोजा वेलजी केशवजी तथा खोजा मनजी केशवजीके नाम भी देखता हूँ। दूसरे नाम भी मेरे पास पहुँचे हैं, लेकिन उहे बादमे दूंगा। विशेष तौरसे उल्लेखनीय नाम ही इस समय दे रहा हूँ।

गद्दारोसे विनती और उन्हें सलाह

दुनियाका रिवाज दुखोको भूल जानेका है। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि कलसे गद्दारोके काले कारनामे हम भूल जायेंगे। उनका अपराध समाजके विरुद्ध है। फिर भी वे भारतीय हैं, इस बातको हम याद रखेंगे। यदि उहे सच्ची शम आई हो और वे समाजका भला चाहते हों, तो जनवरीमे शुरू होनेवाली लड़ाईमे वे भाग ले सकते हैं। परवाना लेते समय उहे गुलामीका पट्टा दिखाना होगा। यदि वे वह पट्टा न दिखाये तो उन्हें पट्टा न लेनेवाले भारतीयों-जसा दुख उठानेका लाभ मिल सकता है। जिन गद्दारोको पश्चात्ताप हो वे इस प्रकार कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी हिम्मतवाले कुछ तो निकलेगे ही।

जनवरीमे क्या होगा ?

उपयुक्त सलाह देते समय जनवरीका प्रश्न तुरत उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार हमने दिसम्बरका विचार किया उसी प्रकार जनवरीका भी करना है। दिसम्बरमे सरकारने जोर नहीं दिखाया — वह दिखा नहीं सकी। मैं तो समझता हूँ वैसा ही जनवरीमे होगा किन्तु यह तो माना नहीं जा सकता था कि दिसम्बरमे वह किसीको नहीं पकड़ेगी। उसी प्रकार जनवरीमे किसीको परेशानी नहीं होगी यह भी मैं नहीं मानता। इतना तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि जो लोग गुलामीका पट्टा नहीं दिखा सकेगे उन्हें परवाना नहीं मिल सकेगा। उसमे सरकारके लिए ढील देनेकी भी बात नहीं रहती। वैसी विज्ञप्ति निकाली गई है, इसलिए वह तो अमलमे आयेगी ही। तब क्या किया जाये ? उत्तर कई बार दिया जा चुका है और वह है बिना परवानेके व्यापार किया जाये और जब सरकार पकड़े तथा जुर्माना हो तब जुर्माना न देकर जेल जायें। जेल ही रामबाण दवा है। सभी परवानोका काम सरकारके हाथमे नहीं है। काफिर भोजनगहो तथा फेरीवालोके परवानो नगरपालिकाके हाथमे हैं। अर्थात् काफिर भोजनगहवालो और फेरीवालोको पकड़नेका सरकारको अधिकार नहीं है। नगरपालिका जो हुकम देगी उसके अनुसार होगा। अतः यह सम्भव है कि कोई न कोई नगरपालिका तो वार करेगी ही। जैसे, वाक्सवगकी नगरपालिका। इससे डरना नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए। सरकारन आजतक हमपर हाथ नहीं डाला, उसे मैं अच्छा नहीं मानता। यह लड़ाई ऐसी है कि इसमे हमारा छुटकारा हमारे हाथ है। फिर जबतक बहुत लोगोंने जेलका कष्ट नहीं भोगा तबतक हममे सच्ची हिम्मत नहीं आयेगी। इस प्रकार गिरफ्तार किये जानेवाले लोगोका बचाव श्री गांधी मुफ्त करेंगे, यह लिखा जा चुका है। बचानेका अर्थ इतना ही है कि उस जैसे बहादुरको जेलके लिए बिदाई देने जायेंगे। मुझे खेद है कि परवानेके बारेमे यदि कोई जुर्माना न दे तो उसे जेलकी सजा होगी। लालच बुरी चीज है और यदि कोई उस लालचमे आकर जुर्माना दे देगा तो बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सब भारतीय अन्तःकरणसे यह शपथ ले लेंगे कि इस सम्बन्धमे वे अपना या दूसरोका जुर्माना नहीं देंगे।



THE GOVERNMENT: "Whew! Never thought of meeting This! Hard loop!" (Last meeting)

Hard meeting see?

श्री गांधी : देशनिकाला देनेका अधिकार मुझे नहीं है।
 सरकार : "अरे ! इसका सामना करना पड़ेगा, यह तो सोचा ही नहीं था ! बुरे फैसे ! " (भाग गये)

Resister.



DO :—Prepare to meet your end !

RESISTER (Mr. Gandhi) :—Yea, brother Smuts, I am prepared. Pray do your worst.

DO :—Heavens, man ! Don't say that. The blooming gun won't work !

Reproduced by kind permission of the *Rand Daily*

समझौता कहाँ गया ?

जनवरीका विचार बताया इसलिए साधारण सवाल यह उठता है कि समझौता कहा गया ? उसके खुलासेके लिए कहना हूँ कि मैंने तो पानी आनेके पहले बाध बाधा है। समझौतेकी बात तो चल ही रही है। किंतु मैं देखता हूँ कि सरकारके हाथमें जनवरीमें जो हथियार आनेवाला है उसकी आजमाइश हुए बिना समझौता नहीं होगा। इस बीच भारतीयोंका जोर प्रबल बढ गया है, यह तो किसीको भी दिखाई दे सकता है। गोरोके सारे अखबार सरकारको बहुत फटकारते हैं और भारतीयोंकी जय बोलते हैं। तीन महीने पहले यदि कोई ऐसी बात कहता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। किंतु जैसे गोरोके अखबार हमारे पक्षमें बोलने लगे हैं, उसी प्रकार यदि जनवरीमें बहुत से भारतीय जेल चले जायेंगे तो गोरे स्वयं भी तोबा करेंगे, और सरकारसे भारतीयोंके छुटकारेकी माग करेंगे। समझौता तो केवल नाम है। समझौतेकी डोर हमारे हाथमें है। हम लायक — मद साबित होंगे तब सभी समझौता करना चाहेंगे। सत्य और मदानगाकी यही महिमा है।

‘क्रिटिक’ में व्यंग्यचित्र

‘क्रिटिक’ में इस बार हँसने योग्य व्यंग्यचित्र आया है। एक तरफ एक भारतीय कोड़ा दिखाता हुआ कह रहा है कि आपको निर्वासित करनेकी सत्ता नहीं है दूसरी ओर जनरल बोथा और उनके मन्त्री भाग रहे हैं। इसको मिलाकर ‘अनाक्रामक प्रतिरोध’ सम्बन्धी कुल व्यंग्यचित्र निकल चुके हैं।

सरकारकी जिद

मात्रूम होता है कि समझौता करनेवालोंको स्मट्स साहबने टका सा जवाब दिया है। वे कहते हैं कि कानून रद करने या नोटिस वापस लेनेका उनका कोई इरादा नहीं है। स्मट्स साहबके इस कथनसे किसीको डरना नहीं चाहिए। उन्हें तो बोलनेकी आदत पडी हुई है। जय कानूनको अमलमें लायेंगे तब पता चल जायेगा।

जूटनिक [यूटनहेग] से सहायता

जूटनिकके भारतीयोंसे लड़ाईमें जो मदद मिली है उसके लिए सधने उनका आभार माना है। मुझे आशा है कि दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे। पोर्ट एलिजाबेथके भारतीयोंने चढ़ा इकट्ठा किया हो तो वह [सधको] भेज देना चाहिए।

द० आ० ब्रि० भा० समितिको मदद

पाचेपस्टुमसे श्री रतनजी लखमीदासकी मारफत वहाके हिंदुओंकी ओरसे १६ पौड ८ शिलिंग और ६ पैस तथा श्री नानजी घेलाकी ओरसे ५ पौड दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके लिए मिले हैं। इसी प्रकार दूसरे भारतीयोंकी ओरसे भी मदद मिलती रहे तो समितिके काममें अडचन नहीं आयेगी। हालमें श्रीमती रिचकी सरत बीमारीके कारण श्री रिचको जो खच करना पड रहा है, वह समितिके कोषसे किया गया है, यह सबको याद रखना चाहिए।

भीखा नारण

इस व्यक्तिके बारेमें कुछ बातें लिखी जा चुकी हैं। यह श्री डेल लेमके यहा नौकर था। इसे अब बहुत ही पश्चात्ताप हुआ है। इसने अपनी अर्जोंकी रसीद सधको भेज दी है।

स्वयं भारत चला गया है, परन्तु गुलामीका पट्टा लेने नहीं गया। इसकी गद्दारीसे इसके सगे-सम्बन्धी सब उत्तेजित हो गये थे और वे इसके साथ अपना व्यवहार बन्द करनेवाले थे। किन्तु अब यह स्वदेश चला गया है इसलिए मासूम होता है कि वे शांत हो गये हैं। इस उदाहरणसे प्रकट होता है कि “पराधीन सपनेहुँ मुख नाही।” प्रायः यह पाया गया है कि गोरोकी निम्न नौकरी करनेसे स्वाभिमान खत्म हो जाता है। यह आदमी श्री लेसके महा कपड़े धोनेकी नौकरी करता था।

प्रिटोरियाकी मसजिदमें सिपाही

प्रिटोरियाकी मसजिदमें बनतखान और हाजी इब्राहीमवाली घटना हो जानेके बाद, झगडा न हो, इसलिए हर शुक्रवारको पुलिस आती है। इस प्रकार पुलिसके आनेसे कौमकी बदनामी होती है। और यह मसजिदके मुतवल्लियोंकी कमजोरी मानी जाती है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्धमें यदि कुछ भी उपाय न किया गया हो तो वह तुरत करके मुतवल्लि पुलिसका आना बन्द करा देंगे।

नये भारतीय वकील

श्री जॉज गाडफ्रेने १३ तारीखको सर्वोच्च न्यायालयमें न्यायवादीके रूपमें प्रवेश किया है। बहुत करके वे जोहानिसबगमें वकालत करेंगे। मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूँ। श्री जॉज गाडफ्रेको मिलाकर श्री सुभान गाडफ्रेके तीन लडकोंने विलायतमें शिक्षा प्राप्त की है। अन्ध चोथेको डॉक्टरकी लिए भेजनेकी तजवीज की जा रही है।

एशियाई कार्यालय

श्री बर्जेसको ३१ जनवरी [१९०८]से छुट्टी दे दी गई है। इसी प्रकार प्रिटोरियामें तीन कारकुनोको छुट्टी मिली है। (उनके नाम बादमें दूगा)।

कांग्रेसके प्रतिनिधि

श्री अमीरुद्दीन फजदारका तार आया है कि वे १७ तारीखको सकुशल बम्बई पहुँच गये।

जोहानिसबर्गका गेरा व्यापारी सघ

इस सघकी बैठक इस सप्ताह हुई थी। उसमें इस प्रकारका प्रस्ताव किया गया कि कानूनको अमलमें लानेमें सघको सरकारकी मदद करनी चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। एक वक्ताने कहा कि बड़ी सरकारकी ओरसे इस सम्बन्धमें बड़ा दबाव डाला जा रहा है। इसलिए जोहानिसबर्गके लोगोको मदद करनी चाहिए।

एशियाई कार्यालय

एशियाई कार्यालयमें श्री बर्जेसके अलावा जिन कारकुनोको काय मुक्त किया गया है वे हैं श्री डॉबसन, श्री बारकर, श्री फाल्क, और श्री स्वीट।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३६ पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको

[जोहानिसबग]

दिसम्बर २१, १९०७

महाप्रबन्धक

म० द० आ० रेलवे

जोहानिसबग

महोदय,

आज प्रातःकाल मुझे स्टैडनकी स्थानीय भारतीय समितिका पत्र मिला, जिसका स्वतंत्र अनुवाद नीचे दिया जा रहा है

रेलवे कमचारियोंको महीनेके शुरूमें जो खुराक दी गई थी उसका साराका सारा अवशिष्ट भाग कल (इस मासकी १९ तारीखको) उनसे ले लिया गया और जिन कमरोंमें वे रहते थे उनकी छत्ते हटा दी गई। इसलिए वे सभी यहाँ आ गये हैं। समितिने उनके रहनेका प्रबंध कर दिया है। उन्होंने कल दोपहर तक काम किया था, लेकिन उनको कलका कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया। उन्होंने प्रार्थना की कि उनको निवासस्थान तलाश करने और बादमें अपने स्त्री-बच्चोंको ले जानेके लिए नगरमें जानेकी अनुमति दी जाये, मगर बच्चों तक को बाहर निकाल दिया गया है।

आपने कृपापूर्वक मुझे यह आश्वासन दिया था और समाचारपत्रोंके नाम आपकी विज्ञप्तिमें भी मैंने यही आश्वासन देखा है कि आपका महकमा किसी प्रकार “सख्तीसे कायवाही करना या किसी रूपमें अपने अधिकारोंका फायदा उठाना नहीं चाहता”। इसलिए अगर उपर्युक्त सूचनापत्रमें कोई सच्चाई हो तो जो अधिकारी हिदायतोंपर अमल कर रहे थे वे स्पष्टतया गम्भीर रूपसे कतव्यच्युत हो गये हैं। क्या आप इसके बारेमें आवश्यक जाँच करके मुझे सूचित करनेकी कृपा करेंगे ?

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

अवैतनिक मंत्री

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३३७ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें

[जोहानिसबग

दिसम्बर २२ १९०७]

हमें इस विजयके कारण फूल नहीं जाना चाहिए।^१ युद्धके दिनमें डच लोगोंने पहले मैदान छोड़ भागनेका ढोंग रचा, बादमें वे ज़मेज़ोपंग टूट पड़े। उसी प्रकार सरकार शापद पहले यह दिखाये कि वह हार गई है और आगे चलकर वार कर बैठे। इसलिए हमें तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा सघप आज ही शुरू हुआ है। अगर सरकार परवाने न दे तो हम लोग बिना परवानेके ही व्यापार करते रहे और गिरफ्तार हो जानेपर ज़ुर्माना अदा न करे जेल भले चले जाय। इसके अतिरिक्त हमें एक एकता-भवनका निमाण अवश्य करना चाहिए। यह काम बहुत शीघ्र में हो जायेगा। उसके द्वारा हम ऐसे भारतीयोंको, जो बेरोजगार हो गये हैं काम दे सकते हैं। परवानाके बारेमें जो स्थिति है उसे ठोसताके समझानेके लिए फिर एक सावजनिक सभा करनी चाहिए।

चूँकि मोलवी मुरतार साहबके परवानेकी मियाद समाप्त हो रही है इसलिए श्री गांधीने उसमें सम्बन्धित कुछ बातोंकी चर्चा की और फिर सघपके बारेमें बताया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१७-१९०७

३३८ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें^२

[फ्रीडडॉप

दिसम्बर २७, १९०७]

श्री गांधीने कहा जब मैंने आज प्रातः काल प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियम सम्बन्धी घोषणा पढ़ी, तब पहली बात, जो अपने आप मेरी जुबानपर आई, यह थी कि लॉर्ड एलगिनने भारतीयोंकी राजभक्तिपर अनुचित भार डाल दिया है। भारतके भूतपूर्व वाइसराय लॉर्ड एलगिन भारतीय परम्पराओंको बिल्कुल भूल गये हैं। वे महामहिम सम्राटको इस कानूनपर मज़ूरी देनेकी सलाह देते समय यह बात बिल्कुल भूल गये कि वे भारतके लाखों लोगोंके न्यायी हैं। वे बिल्कुल भूल गये कि भारत एक ऐसे मागपर पण रखनेवाला है जो भारतीय इतिहासमें अज्ञात है। भारत कभी क्रांतिकारी नहीं रहा, किन्तु आज हम देखते हैं कि कुछ भारतीयोंके मस्तिष्कमें क्रांतिकारी भावना प्रविष्ट हो गई है। जिस दिन भारतमें तीव्र

१ गांधीजीने रामसुंदर पण्डितकी रिहाईका जिक्र करते हुए हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें भाषण दिया था, देखिए 'रामसुंदर पण्डित', पृष्ठ ४३८ और ३९ भी।

२ हमीदिया इस्लामिया अजुमनके भवनमें गांधीजीने शामको एक भरी सभामें भाषण दिया। उसी दिन सुबह उन्हें टेलीफोन द्वारा ट्रान्सवालके कार्यवाहक पुलिस आयुक्त श्री एच० एफ० डी० पेपेनफसका सन्देश मिला था कि गांधीजी उनसे जाकर मिलें। वहाँ पहुँचनेपर उन्हें बताया गया कि उनकी तथा थम्बी नायडू (मुख्य धरनेदार जोहानिसबर्ग) पी० के० नायडू (धरनेदार, जोहानिसबर्ग) सी० एम० पिस्ले, जमादार नवाबखॉ

क्रांतिकारी भावना पर्याप्त जड़ पकड़ लेगी वह दिन भारतके लिए एक बुरा दिन होगा, किंतु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि लाड एलगिनने उसका बीज बो दिया है। यदि यह बीज छात्र जगत तक ही सीमित होता तो कदाचित् भारतीय भूमिमें कदापि न पनपता। किंतु मैं आज देखता हूँ कि व्यापारी, जो अंग्रेजीका एक शब्द नहीं जानता, एशियाई कानूनके सम्बन्धमें नई भावनामें सराबोर हैं। मुझे इस बातपर गव है कि मैंने इस मामलेमें इतना भाग लिया है। किंतु इसके साथमें इतना और कहता हूँ कि मेरे विचार लोगोंके विचार ह और उनको प्रकट करते समय मैंने अगर कुछ किया है तो नरमी बरती है। इस कारणसे ही मैंने यह भावना व्यक्त की है कि लाड एलगिनने इस प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमको मजूर करके भारतीयोंकी राजभक्तिपर अनुचित भार डाला है। मेरे विचारसे यह विधान एक बबर विधान है। यह एक सभ्य सरकारका, जो अपने आपको ईसाई सरकार कहनेकी हिम्मत करती है, जगली कानून है। यदि ईसा जोहानिसबग और प्रिटोरियामें आये और जनरल बोथा, जनरल स्मट्स और अन्य लोगोंके हृदयोंको टटोले तो मेरा खयाल है कि उन्हें कोई अजीब, ईसाइयतकी भावनाके सवथा विपरीत, बात मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा “मैं मानता हूँ कि इस कानूनके अनुसार कारवाई करनेके लिए जनरल स्मट्सने जिनको चुना है वे जाने माने लोग ह और गरीब लोगोंपर हाथ नहीं डाला है। मुझे इसमें तनिक भी सदेह नहीं है कि यदि उन लोगोंको, जिन्हें यायाधीशके सामने पेश होना है, कदकी या देश निकालेकी सजाएँ दी गईं तो बाकी लोग, जो पीछे रहेंगे, पजीयन अधिनियमका विरोध दबतासे करेंगे। किंतु इस पजीयन अधिनियमसे ऐसे अधिकार मिलते ह जिनसे बेचारे पतियोपर बहुत सकट आयेगे। उनको अपने परिवारोंसे पृथक् किया जा सकता है। हम श्री नायडूके, जो सारे आंदोलनमें खूब चमके ह, मामलेका उदाहरण ही ले। उनके पत्नी और पांच बच्चे ह, जो उपनिवेशमें पाँच सालसे रह रहे ह। यदि श्री नायडूको देश निकाला दे दिया गया तो क्या होगा? उनकी पत्नी और उनके बच्चोंकी देखभाल कौन करेगा? मुझे कानूनमें एक भी ऐसी धारा नहीं मिल सकी है जिससे निर्वासितोंके परिवारोंकी रक्षा होती हो। सरकार करना क्या चाहती है? उसमें भारतीयोंसे इतना कहनेकी ईमानदारी क्यों नहीं है कि देशमें उनकी आवश्यकता नहीं है? वह अपने अधिकारोंको लागू करनेके लिए यह अप्रत्यक्ष तरीका क्यों काममें लाती है? मैंने कानूनकी कुछ धाराओंको जगली और केवल एक असभ्य सरकारके योग्य कहा है। यदि इन अधिकारोंका इस प्रकार प्रयोग किया जाये और हम सबको निर्वासित

(धरनेदार, जोहानिसबग) करवा (भूतपूर्व सिपाही जोहानिसबग) ल्यूग विन (अध्यक्ष चीनी सब जोहानिसबग), जॉन फोर्तोइन (चीनी धरनेदार), मार्टिन इस्टन (जोहानिसबग), रामसुन्दर पण्डित (जर्मिस्टन), जी० पी० व्यास (प्रिटोरिया), ए० एफ० सी० बेग (प्रिटोरिया), एम० आई० देसाई (मुख्य धरनेदार प्रिटोरिया), ए० एम० काळिलिया (प्रिटोरिया), इस्माइल सुलेमान सूज (प्रिटोरिया) गुलाम मुहम्मद अब्दुल रशीद (प्रिटोरिया), बी० गगाराम (प्रिटोरिया) बी० यू० सेठ (प्रिटोरिया) इस्माइल जूमा (प्रिटोरिया) रहमत खॉं (प्रिटोरिया), एम० एम० खडेरिया (पीटर्सबर्ग), अमरशी गोकुल (पीटर्सबर्ग), और अम्बालाल (पीटर्सबर्ग), की गिरफ्तारीके हुक्म हो चुके हैं। गांधीजीने वचन दिया कि सभी दूसरे दिन शनिवार दिसम्बर २८ को सुबह १० बजे अपने अपने यायाधीशोंके सामने हाजिर होंगे। श्री पेपेनफ्सने यह जमानत स्वीकार कर ली। देखिए इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८।

या कद कर दिया जाये तो यह हमारे लिए सम्मानकी बात है। हमारे लिए सम्मानजनक यह नहीं होगा कि हम अपने पुनीत कर्तव्योंको त्याग दे और अपने मनुष्यत्व और आत्म सम्मानको तिलाजलि दे दें — केवल इसलिए कि हम कुछ तुच्छ पैसे या पौड कमा रहे ह। मने आपको जो सलाह दी है उसपर मुझे कभी खेद न होगा। आपने यह लडाई, जो १५ महीनेसे चालू है, अच्छी तरहसे लड़ी है।^१ यह एक ऐसा कानून है जिसको कोई भी आत्म सम्मानी राष्ट्र या व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता — सो इसके नियमोंके कारण नहीं, बल्कि इस कारण कि यह निकृष्टतम ढंगका वर्गीय कानून है, जिसका आधार है समाजके प्रति सरासर अविश्वासका भाव और निराधार दोषारोपण। हमने लाड सेल्बोन और जनरल स्मटसेसे कहा है कि इन आरोपोंको एक निष्पक्ष 'यायालयके सम्मुख सिद्ध किया जाना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाये गये ह जो पक्षपातमें डूबा हुआ है और तथ्यको परख सकनेमें असमर्थ है। सरकार यह बात क्यों नहीं मान रही है कि उन्हें जो कमसे-कम दिया जा सकता है, वह है निष्पक्ष जाच। "श्री गांधीने इस तथ्यके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा कि भारतीयोंको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, किंतु उन्होंने यह चर्चा अवश्य की कि सरकार उन लोगोंकी भावनाओंके सम्बन्धमें इतनी कठोर क्यों है जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। (उन्होंने आगे कहा,) "मुझे यह मालूम होता है कि अब हमारे अलग अलग होनेका वक्त आ गया है। यदि साम्राज्य सरकार भारतके लोगोंपर, सगीनकी नोकके बल नहीं, बल्कि उनके प्रेमके बल अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहती है तो उसको शिक्षकना चाहिए। इंग्लंडको भारत और उपनिवेश दोनोंमें से एकको चुनना पड सकता है। सम्भव है, ऐसा आज या कल न करना पडे, किंतु मेरा खयाल है कि लॉर्ड एलगिनके कायसे इसके बीज वपित हो गये ह। मने जब एशियाई अधिनियममें प्रवासी अधिनियम ऊपरसे जोडा हुआ देखा तब नम शब्द चुनना या अपनी आलोचनाको सयमित करना मेरे लिए सम्भव नहीं रहा। एक कहानी है कि मुहम्मद और उनके दो^२ अनुयायी एक बड़ी शत्रु-सेना द्वारा पीछा किया जानेपर एक गुफामें आश्रय ले रहे थे। उनके साथी निराश होकर पूछने लगे कि इतने बड़े सैन्य बलके मुकाबले हम तीन क्या कर सकेंगे। मुहम्मदने कहा "तुम कहते हो, हम तीन ह, म कहता हूं हम चार ह, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, और उसके हमारी ओर होनेसे हम जीतेगे।" ईश्वर हमारे साथ है, और जबतक हमारा उद्देश्य अच्छा है, तबतक हम यह खयाल तनिक भी नहीं करते कि सरकारको क्या अधिकार दिये जाते ह, या वे अधिकार कितनी बबरतासे प्रयोगमें लाये जाते ह। म तो तब भी यही सलाह दूंगा जो मने पिछले १५ महीनेसे देनेकी हिम्मत की है।^३

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

१ यह सत्र सितम्बर १९०६ में आरम्भ किया गया था। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४२८-३४।

२ मूलमें तीन है।

३ सभामें सवसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमका विरोध किया गया था और जिसकी नकल उच्चायुक्तकी मारफत साम्राज्य-सरकारको भेजी जानेवाली थी।

३३९ डेलागोआ-बेके भारतीय

हम अयत्र उन उल्लेखनीय नियमोका^१ पूण पाठ प्रकाशित कर रहे ह, जिहे डेलागोआ बेकी स्थानीय सरकारने एशियाइयोके आब्रजनपर प्रतिबन्ध लगानेके लिए बनाया है। ये नियम तीन प्रकारके प्रवासियो, अथवा यो कहिए कि एशियाई पयटकोके बारेमे हे (१) डेलागोआ बेको छोडकर जानेवालोके बारेमे, (२) डेलागोआ बेमे बाहरी जिलोसे आनेवालोके बारेमे, (३) एशियाकी पुतगाल बस्तियोसे आनेवाले एशियाई लोगोके बारेमे। इन नियमोमे अवश्य ही ट्रान्सवालकी गंध है। गवनर जनरलके पास डेलागोआ बेके जो एशियाई गये उनसे कहा गया कि ये नियम इसलिए आवश्यक है “कि प्रातपर आसपासके उपनिवेशोसे एशियाई प्रवासियोकी भारी भीडके आनेका खतरा है, ओर ये नियम केवल अस्थायी ह।” हमको विश्वास है कि गवनर जनरलके इस स्पष्टीकरणसे डेलागोआ बेके भारतीय सतुष्ट होकर नही बैठ जायेगे। वास्तवमे पुतगाली इलाकेमे ट्रान्सवालसे कोई भीड नही आती और यदि आती भी हो तो उस प्रातमे पहलेसे बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोको तग करनेमे कोई औचित्य नही हे। उदाहरणार्थ, वे बाहर जानेके लिए अपने पास एक विशेष अनुमतिपत्र क्यो रखे ? हमे मालूम हुआ हे कि उनको स्थायी दस्तावेज पहले ही दिये जा चुके ह। फिर, भारतीय लोग परवानोके बिना अथवा इस बातका प्रमाण दिये बिना, कि वे न तो अपराधी ह और न दिवालिए, डेलागोआ बेसे क्यो नही जा सकते ? यह हो सकता है कि एक खास परिस्थितिमे इस प्रकारकी दूरदेशी सम्भवत सावजनिक यायकी दष्टिसे उचित हो, किन्तु एशियाइयोने अपराध तथा दिवालियेपनका ठेका तो नही ले लिया है। यूरोपीय बिना यह साबित किये, कि उन्होने न तो अपराधीके रूपमे कानूनोको तोडा हे और न दिवालिये बने है, डेलागोआ-बेसे चाहे जितनी बार आ जा सकते ह। इन कठोर नियमोका एकमात्र अच्छा पहलू यह हे कि पुतगाल सरकारने उन एशियाइयोमे भेदकी विभाजक रेखा खीचना जरूरी समझा हे जो उसकी अपनी प्रजा है तथा जो उसकी अपनी प्रजा नही है। अय उपनिवेशोकी ब्रिटिश सरकारोने ऐसा नही किया है। हमारा विश्वास हे कि डेलागोआ बेके एक विदेशी राज्य होनेके कारण लाड एलगिन इन परेशान करनेवाली पाबन्दियोसे छुटकारा दिलानेका कोई न कोई तरीका खोज निकालेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४० बेरोजगार लोगोका क्या किया जाये ?

हमारे इस बारके अकमे पाठक देखेंगे कि स्टैंडटन तथा हाइडेलबर्गमे रेलवेमे काम करने वाले भारतीय बेरोजगार हो गये हैं। और उसका कारण यह है कि उन्होंने खूनी कानूनके सामने झुकनेसे इनकार किया है। इस प्रकार यदि बहुतसे लोग बेरोजगार हो जाये तो क्या किया जाये यह विचार हर भारतीयको करना चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं कि जेल जानसे जो आर्थिक नुकसान हो वह जेल जानेवालेको स्वयं बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उसमे समाज मदद नहीं कर सकता। किन्तु जब सैकड़ो लोग भूखो मरने लगे तब हम कुछ विचार न करे तो यह बड़ी क्रूरता होगी। इसके अलावा, हमने पढा है कि “पेट कराये बेगार, पेट बाजा बजवाये।” पेटके लिए भारतमे अकालग्रस्त लोग अपने बच्चोको बेच देते हैं। तब इस पापी पेटके लिए लोग पजीयनपत्र लेनेको तैयार हो जाये तो उसमे अनोखी बात नहीं होगी। यानी, यदि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाये तो उनकी मदद करना बिलकुल जरूरी हो जायेगा। इस विचारका समझकर हर भारतीयको, जितनी हो सके उतनी सहायता, सघके नाम जोहानिसबग भेजनी चाहिए। पैसा प्राप्त होनेके बाद क्या किया जाये यह दूसरा प्रश्न है जिसपर हमे सोचना है। यदि लोगोको, बिना कुछ काम लिये, रोजाना पैसा या भत्ता दिया जाता रहे तो उससे पाप बढेगा, और इतना निश्चित है कि उसका असर पसा या भत्ता लेनेवालेपर बुरा होगा। इसलिए हम मानते हैं किसी न किसी सावजनिक काममे उनकी मदद अवश्य ली जाये। श्री गांधीने एक बड़ा सभा-भवन बनानेका सुझाव रखा है। यह काम बड़ा है करने योग्य है और अधिकांश भारतीय मदद करे तो सहज ही हो सकता है। इससे तीन काम बनते ह। ट्रान्सवालमे कौमको राजकीय कामोके लिए एक बड़ा भवन मिल जायेगा, बेरोजगार भारतीयोका पोषण होगा और वैसा भवन बनानेसे भारतीय लडाईको जबर दस्त विज्ञापन मिलेगा। यदि ट्रान्सवालके भारतीय सभा-भवन बनवाये तो उसका लाभ उन्हें ही होगा यह समझकर ट्रान्सवालसे बाहरके भारतीय हाथपर हाथ धरे न बैठे रहे। सभा भवन बने या न बने, बेरोजगार लोगोको काम तो देना ही होगा। इसलिए हर भारतीयको इस बातका ध्यान रखना चाहिए। यदि सभा भवन बनाया जाता है तो बहुत-सा खर्च ट्रान्सवालके भारतीयोको स्वयं ही उठाना होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४१ बहादुर स्त्रियाँ

इंग्लैंडकी स्त्रियोने हृद कर दी है। भारतीय समाजकी लडाई जब ट्रांसवालके खूनी कानूनके खिलाफ शुरू हुई तब इंग्लैंडकी स्त्रियोकी मताधिकारकी लडाईको चले कई महीने बीत चुके थे। उन स्त्रियोकी लडाई अभी चालू है और वे जरा भी थकी नहीं हैं। उनकी बहादुरी और धीरजके सामने ट्रांसवालके भारतीयोकी लडाई कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इंग्लैंडकी स्त्रियोको तो बहुत सी स्त्रियोके भी खिलाफ जूझना पड़ता है। मताधिकार मागने वाली स्त्रियोसे न मागनेवाली स्त्रियोकी सरया बहुत ज्यादा है। इतना होनेपर भी वे मुट्ठी-भर स्त्रिया हार नहीं मान रही ह। रोज ब रोज वे जितनी ठोकरे खाती ह उनकी ताकत उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। उनमें से बहुत सी जेल जा चुकी ह। घणित और नामद मर्दोंकी ठोकरो और पत्थरोकी मार ये स्त्रिया खा चुकी हैं। पिछले सप्ताह तार था कि उन्होंने अपनी लडाईको और भी व्यापक बनानेका निणय किया है। स्त्रियो या उनके पतियोको सरकारको मकान आदिके कई कर देने होते हैं। यदि कर न दे तो उनका माल नीलाम किया जा सकता है और जेलमे भी जाना पड़ता है। अब स्त्रियोन निणय किया है कि “जबतक हमे अपने अधिकार नहीं मिलते तबतक हम कर वगैरा नहीं देगी, बल्कि अपना माल नीलाम होने देगी और जेल जायेगी।”

यह बहादुरी और धय ट्रांसवालके भारतीय तथा सारे भारतीय समाजके लिए आदर्श है। बिना परवानेके व्यापार करनेके कारण यदि नेटालके भारतीयोका माल नीलाम हो जाये तो वह उन्हें भारी मालूम होगा। किन्तु इस प्रकार सोचनेवाले यह नहीं समझते कि बहुत लोगोका माल सरकार नीलाम नहीं कर सकती। और नीलाम करे भी तो क्या हुआ? स्त्रिया मताधिकार जैसे हकके लिए अपनी जायदाद कुर्बान कर देती हैं तब हम जीविकाके लिए लड़ते हुए मोहके कारण लडाईमे इतना कष्ट भी नहीं सहन कर सकते? स्त्रियोकी लडाई कई वर्ष चलेगी, परंतु वे बिना हारे या बिना थके लड़ती रहेगी। आज लड़नेवाली स्त्रिया उस अधिकारका उपयोग नहीं कर पायेगी, फिर भी ऐसा मानकर कि अगर वह बादकी पीढीको मिले तब भी हमे ही मिलने जैसा हुआ, वे सत्यके आधारपर जूझ रही ह। भारतीयोको भी इसी दृष्टिसे लड़ना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४२ डेलागोआ-बेके भारतीय

डेलागोआ बेमे भारतीयोंको रोकनेके लिए बनाये गये सारे कानून इस अकमे छाप रहे हैं। इसकी धाराएँ बहुत ही बुरी हैं। जान पड़ता है इस सम्बन्धमे भारतीय लोग गवर्नरसे मिल चुके हैं। परन्तु इसका कोई सतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यह कानून यदि कायम रहा तो प्रतिष्ठित भारतीयोंको भी डेलागोआ-बे जाते समय अपनी तस्वीरवाला अनुमतिपत्र रखना पड़ेगा। ट्रान्सवालसे जानेवाले व्यक्तिको तभी अनुमतिपत्र दिया जाता है जब यह साबित हो जाये कि उसे वापस ट्रांसवाल लौटनेका अधिकार है। यह सारा पाखण्ड प्रिटोरियासे पैदा हुआ है। किसी भारतीयको यदि सदाके लिए डेलागोआ-बे छोड़ना हो, तो भी वह बिना अनुमतिपत्रके नहीं छोड़ सकता। छोड़ तभी सकता है जब वह साबित कर दे कि उसने स्वयं कभी अपराध नहीं किया और वह दिवा लिया नहीं है। यह एक और तथा अलग प्रकारके जुल्मका श्रीगणेश माना जायेगा। इस कानूनसे भारतकी पुतगाली प्रजाको मुक्त रखा गया है।

क्या डेलागोआ बेके भारतीय ऐसे कानूनके सामने झुकेगे ? मौलवी साहब अहमद मुख्तार जब डेलागोआ-बेसे लौटे, उन्होंने वहाके भारतीयोंके आलस्य और लापरवाहीका बढिया चित्र खींचा था। यदि डेलागोआ-बेका भारतीय समाज अब भी आलस्य नहीं छोड़ेगा और आवश्यक कारवाई नहीं करेगा तो वह सारे भारतीयोंके तिरस्कारका पात्र बन जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४३ दाउद मुहम्मदकी बधाई

श्री दाउद मुहम्मदकी लडकी आशाबीबीका विवाह उनके भतीजे श्री गुलाम हुसैनके साथ हुआ। इसका सक्षिप्त विवरण हम पिछले सप्ताह दे चुके हैं। अब हम उन्हें, उनकी लडकीको और दामादको बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि दम्पती सुखी और दीर्घायु हो। किंतु सच्ची बधाई तो, श्री दाउद मुहम्मदने विवाहके समय जिस सादगीसे काम लिया और जो भाईचारा बरता, उसके लिए दी जानी चाहिए। धर्मके साधारण नियमोंका लोग पालन करे तो उससे वे सुखी हो सकते हैं, सादगीका पालन किया जा सकता है और बेकार खर्चकी परेशानियोंसे बचा जा सकता है। श्री दाउद मुहम्मदने विवाह शरीअतके अनुसार किया। नतीजा यह हुआ कि इस विवाहमे बेकारका आडम्बर बिल्कुल नहीं था। इस उदाहरणका मतलब यह है कि गलत रिवाजोंको छोड़कर धार्मिक रीतिसे विवाह करे। यह सबके लिए अनुकरणीय है। श्री दाउद मुहम्मदने निकाहके समय जो भाईचारा बरता उसे भी हम ऐसा

ही मानते हैं। यदि इसी प्रकार सब करने लगे तो विभिन्न धार्मिक या राजकीय सगठनोंको पैसेकी जो तंगी होती है वह नहीं भोगनी पड़ेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४४ कुछ अंग्रेजी शब्द

स्वदेशाभिमानकी एक शाखा यह भी है कि हम अपनी भाषाका मान रखें, उसे ठीक तरहसे बोलना सीखें और उसमें विदेशी भाषाके शब्दोंका उपयोग यथासम्भव कम करें। गुजरातीके कोई अच्छे शब्द हमें नहीं सूझे, इसलिए हम कुछ अंग्रेजीके शब्द जैसेके तैसे काममें लाते रहे हैं। उनमें से निम्नांकित कुछ शब्द हम पाठकोंके सामने पेश करते हैं। जो कोई उनके लिए अच्छे शब्द बतायेगा और जिसके शब्द स्वीकार किये जायेंगे उसका नाम हम प्रकाशित करेंगे, और कानूनकी जो पुस्तक हमने प्रकाशित की है उसकी दस प्रतियां उसे भेंटमें देंगे, जिससे वह उनका प्रचार कर सके। पुस्तक भेंट करनेका उद्देश्य प्रलोभन देना नहीं, बल्कि सम्मान देना और खूनी कानूनके बारेमें जानकारीका प्रचार करना है। हम चाहते हैं कि हमारे पाठक वह भेंट पानेके लिए नहीं, बल्कि स्वदेश हितके लिए कष्ट उठाकर हमें इन शब्दोंकी जानकारी दें। शब्द निम्नानुसार हैं

पैसिव रेजिस्ट्रेस, पैसिव रेजिस्टर, काटून, सिविल डिसओबिडिएंस।

इनके अलावा और भी शब्द हैं। किन्तु उनपर फिर विचार करेंगे। उपयुक्त अंग्रेजी शब्दोंका हम शब्दाथ नहीं उनका भावाथ चाहते हैं। यह बात पाठक ध्यानमें रखें। शब्द संस्कृतसे निकले हुए हों या उर्दूसे, वे काम आयेगें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४५. भारतकी दशा

जोहानिसबगवाले श्री दादाभाईके बड़े लड़केकी मृत्युके समाचारसे हमारे मनमें कई तरहके विचार आये हैं। भारतमें ऐसी मृत्युएँ हर वर्ष लाखोंकी सरयामें होती हैं। प्लेगसे गावके गाव उजड़ गये हैं। कुटुम्बके-कुटुम्ब नष्ट हो गये हैं। मा बाप और बच्चे — सभीके महामारीसे खत्म हो जानेके समाचार बहुधा हमारे पढ़नेमें आया करते हैं।

और जगहोंमें भी महामारी होती है, किन्तु वहां भारत जितना नाश नहीं करती। इसका कारण क्या है? यह प्रश्न हर भारत हितेच्छुके मनमें आये बिना नहीं रहता होगा। हमारी रायमें इस प्रश्नके उत्तरमें भारतके सभी हितोंका समावेश हो जाता है। प्रश्न करना सरल है किन्तु उत्तर देना कठिन है। और उत्तर देकर सुननेवालोंका समाधान कर देना और भी मुश्किल है।

फिर भी कुछ हदतक उत्तर देनेका प्रयत्न करना ठीक समझकर उत्तर दे रहा हूँ। कई पहलुओंसे विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि भारतमें महामारी, भुखमरी वगैरह बढ़ गई है। इसका कारण भारतीय प्रजाका पाप है। यदि कोई कहे कि राज्यकताओंका पाप है तो यह बात हमें माय है। उनके पापके कारण प्रजा दुखी होती है, यह सदाका अनुभव है। किंतु याद रखने योग्य बात यह है कि पापी सरकार पापी प्रजाको ही मिलती है। इसके अलावा, सच्चा नियम यह है कि दूसरोंको दोष देनेके बदले अपने दोषोंकी छानबीन करना अधिक लाभप्रद होता है।

हिंदू-मुसलमानके बीच फूट और कटुता पाप है। किंतु ये असल पाप नहीं हैं। फूट मिट जाये और दोनों कौम मिलकर रहने लगे तो विदेशी शासन हट जायेगा अथवा उसकी नीतिमें परिवर्तन होगा। किन्तु उससे प्लेग और अकाल भी मिट ही जायेंगे, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं।

मुख्य पाप तो भारतीय प्रजाका असत्य है। महामारीके समय हम सरकारको तथा अपने आपको धोखा देते हैं। ऊपरसे सफाई रखनेका दिखावा करते हैं, किंतु सच्ची स्वच्छता नहीं रखते। घरको बुआ देकर झुड़ करना हो तो उसका केवल दिखावा किया जाता है। यदि उसके बिना चल सकता हो, सिपाहियोंको रिश्वत दी जा सकती हो, तो वह देकर हम आवश्यक कामोंसे बच जाते हैं। यह रोग बचपनसे ही चलता रहता है। शालामें एक बात सिखाई जाती है। वहां बच्चा 'हा' कह देता है। घर आनेपर उससे उलटा ही बरतता है। वैसा करनेमें माता पिता सम्मत रहते हैं। स्वच्छता रखनी चाहिए या नहीं, इस सम्बन्धमें नियम बनाये जाते हैं। किन्तु उनका पालन किया जाये या नहीं, इस बातको हम ताकपर रख देते हैं। उसके बारेमें मतभेद भले हो, किन्तु यहाँ जो बात सिद्ध करना चाहता हूँ सो यह है कि हम असत्यका सहारा लेते हैं। बहुतेरी बातोंमें हम केवल आडम्बर करते हैं। इससे हमारे तन्तु ढीले पड़ जाते हैं, हमारा खून पापकी गन्दगीसे विगड़ जाता है और हर तरहके कीटाणुओंके वशमें हो जाता है। देखनेमें आता है कि अमुक वर्णोंको महामारी वगैरह नहीं होती। इसका कारण यह है कि वे स्वच्छताका या और किसी प्रकारका आडम्बर नहीं करते, बल्कि वे जैसे हैं वैसा ही दिखते हैं। उन्हें आडम्बर करनेवालोंकी अपेक्षा उस हद तक हम ऊँचा समझते हैं। उपयुक्त कथनका मतलब यह नहीं कि सभी इसी तरह करते हैं। लेकिन अधिकतर वैसा होता है।

उपयुक्त पापमें से एक दूसरी लत पैदा हुई है और वह सभी वर्गोंमें है, और भयानक है, वह है विषय लोलुपता — व्यभिचार। इस विषयमें संक्षेपमें ही लिखा जा सकता है। सामान्यतः इसकी चर्चा करते हुए लोग हिचकते हैं, हम भी हिचकते हैं। फिर भी अपने पाठकोंके सामने यह विचार रखना हम अपना फज समझते हैं। पर-स्त्री सग ही केवल व्यभिचार नहीं है। स्व-स्त्री सगमें भी व्यभिचार है। यह सब धर्मोंकी शिक्षा है। स्त्री सग केवल प्रजा उत्पन्न करनेके लिए ही ठीक है। सामान्यतः देखनेमें आता है कि व्यभिचार भावनासे सग किया जाता है, और उसके परिणामस्वरूप सत्तान उत्पन्न होती है। हम मानते हैं कि भारतकी दशा इतनी खराब है कि इस समय बहुत ही कम सन्तान उत्पत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सग हो तो वह बहुत-कुछ व्यभिचारमें ही शामिल होगा।

यदि यह मान्यता ठीक हो तो समझदार भारतीयका कतव्य है कि या तो वह बिल्कुल शादी न करे और यदि वह उसके वशकी बात न हो तो स्त्री सग करनेसे मुक्त रहे। यह सब कठिन काम है, फिर भी बिना किये छुटकारा नहीं है।

नहीं तो पाश्चात्य प्रजाका अनुकरण करना होगा। पाश्चात्य प्रजा राक्षसी उपाय बरतकर सन्तान निरोध करती है। वह युद्धमे बहुत लोगोका नाश होने देती है, ओर ईश्वरपर से आस्था छोडकर दुनियाई सुखोमे ही रची पची रहनेकी तजवीज करती है। इस तरह करके भारतीय भी उनकी ही तरह महामारी आदिसे मुक्त रह सकते हैं। किन्तु हम मानते हैं कि भारतमे पश्चिमका राक्षसी रग प्रवेश नहीं कर सकता।

यानी भारत या तो खुदा — ईश्वर — की ओर एक नजर रखकर पापमुक्त होगा और सुखी रहेगा या सदा गुलामीमे रहकर, जनाना बनकर, मौतसे डरते हुए, महामारी वगैरह बिमारियोमे सडकर बिना मौत मरता रहेगा।

ये विचार किसीको आश्चर्यजनक, किसीको हास्यास्पद, किसीको अज्ञानपूर्ण मालूम होंगे। फिर भी हम बेधडक लिख रहे हैं और समझदार भारतीयोंसे प्रार्थना करते हैं कि वे इनपर पूरी तरह विचार करे। पागलपनके हो या सयाने, ये विचार लेखकने अपने गहरे अनुभवके आधारपर लिखे हैं। इनके अनुसार आचरण करनेसे नुकसान तो होगा ही नहीं। सत्यके मेवन और ब्रह्मचयके पालनसे किसीको नुकसान नहीं होता। कोई यह भी न माने कि एक दो व्यक्तियोंके पालनसे प्रजाको क्या लाभ होगा। ऐसा कहनेवाले व्यक्तिको नादान समझना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४६ अरबी ज्ञान

प्राच्य देशोके ज्ञानके विषयमे कतिपय पुस्तकोपर हम इसके पहले विचार^१ कर चुके हैं। सूचित विषयपर उन्हीं लेखकोकी लिखी हुई उपयुक्त पुस्तक हमे देखनेको मिली है। यह बताना शायद ही आवश्यक है कि वह पुस्तक अग्रेजीमे है। उसकी कीमत सिर्फ एक शिलिंग है। उसमे बहुत-से फिकरे 'कुरान शरीफ' से लिये गये हैं। विभिन्न विषयोपर अरबी विद्वानोके वचन दिये गये हैं। उदाहरणके लिए कुलीनताके विषयमे लिखा है कि "जो मनुष्य अपने मानकी रक्षा नहीं करता, उसकी कुलीनतापर कलक लग जाता है। नीच घरमे जन्म लेनेका दोष विद्या और उत्तम आचरणसे दूर हो जाता है"।^२ मानपर आधारित सवषपर लागू होनेवाले वचन रत्न इस पुस्तकमे हैं। कवि कहता है, "जो व्यक्ति अपने सम्मानको अक्षुण्ण रखता है, लोग उसके दोष नहीं देखते।" फिर कहा है, "यदि मनुष्योकी दष्टिमे लज्जाके योग्य कोई बात तुम्हारे दिलमे हो तो उससे शरमाओ।" फिर कहा है, "जो मनुष्य अपने सम्मानकी रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरेको सम्मान नहीं दे सकता।" आगे चलकर दूसरी जगह लिखा

१ देखिए 'पूर्वका ज्ञान' पृष्ठ ४२ ४३ और 'पूर्व ज्ञान माला', पृष्ठ ९९।

२ यहाँ दिये गये उद्धरणोकी इंडियन ओपिनियनमे प्रकाशित अग्रेजी समीक्षासे मिला लिया गया है।

है, “जो व्यक्ति अपने सम्मानको अक्षुण्ण नहीं रखता और बेशम होकर जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है और उसे इस जीवनमें सुख नहीं मिलता।” आचरणके विषयमें कहा है कि “जो मनुष्य सचमुचमें नीतिवान नहीं है, वह धार्मिक नहीं कहा जा सकता।” ज्ञानके विषयमें लिखते हुए कहा है, “जिस प्रकार बिना हथियारके वीर पुरुष लाचार हो जाता है, उसी प्रकार साधारण मनुष्य बिना विद्याके निकम्मा होता है।” “राजा मनुष्योपर राज्य करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य राजाओपर।” “बुद्धिमान मनुष्य वह है जो गलत रास्तेपर पाव नहीं रखता। वह नहीं जो पहले दोषमें पड़कर बादमें उससे निकलनेका रास्ता ढूँढता है।” सत्यके विषयमें कहा है कि “जिस मनुष्यका मन साफ नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है और जिसकी वाणी निर्दोष नहीं है उसका हृदय स्वच्छ नहीं है।” “जो नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है, पर साथ साथ झूठ भी बोलता है, वचनकी रक्षा नहीं करता, वह अपना कतव्य पूरा नहीं करता। उस मनुष्यको ढोंगी समझो।” इस छोटी-सी पुस्तिकामें ऐसे स्वर्ण वचन समायें हुए हैं। जो अंग्रेजी समझ सकते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियोंको हम यह पुस्तिका खरीदनेकी सलाह देते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सार्वजनिक सभा

बुधवार, जनवरी १ को चार बजेसे सूरती मसजिदके सामने भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा होगी। उसमें जनवरी तथा उसके बादकी परवाने आदि सम्बन्धी लड़ाईकी बाबत विचार किया जायेगा। आशा है हर जगहके भारतीय आकर उसमें शामिल होंगे।

परवानेके बारेमें विचार

इस विषयमें कुछ विचार तो हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। किन्तु अभी और भी विचार करना चाहिए। सच्ची लड़ाई परवानेकी होगी, यह माना जा सकता है। इतना निश्चित है कि परवानेके बिना व्यापार करना होगा। विचार करनेपर मालूम होता है कि सभी धंधोंके लिए परवाना लेनेके पहले पंजीयनपत्र दिखाना आवश्यक नहीं है। कानूनमें ट्रेडिंग लाइसेन्स यानी व्यापारिक-परवाना शब्द काममें लाया गया है। इस परवानेमें सायकिलके या धोबीके परवानेका समावेश नहीं होता। इसलिए धोबी पंजीयनपत्रके बिना परवाना ले सकता है। जरूरत अधिकतर व्यापारियों और फेरीवालोंको होगी। इन दोनों वर्गोंके भारतीय बहादुरी दिखायेंगे तो समाजकी मुक्ति जल्दी होगी। कानूनका अध्ययन करके यह भी देखता हूँ कि जनवरीके महीनेमें भारतीयोंपर बहुत करके मुकदमा नहीं चल सकेगा। जिस व्यक्तित्वने परवाना न लिया हो उसपर एक महीने तक मुकदमा नहीं चल सकता। इसलिए जान पड़ता है कि मुकदमे केवल फरवरीके महीनेमें चलेगे। जिन व्यापारियोंको डर हो और वे शादीशुदा हो तो वे अपनी पत्नीके नाम परवाना ले सकते हैं। इस तरह परवाना लेनेपर वे जेलसे बच सकते हैं। किन्तु हमारी लड़ाई बहादुर बनने और बहादुरी दिखानेकी है। इसलिए इस तरह बचनेकी सलाह मैं नहीं दे सकता। मेरी सलाह है कि परिपाटीके अनुसार

हर भारतीयको परवानेकी अर्जी देनी चाहिए। उसके लिए वकीलका खच उठानेकी जरूरत नहीं है। अर्जी देकर, पैसे भर देनेका वादा करके, बैठे रहना चाहिए।

मौलवी साहब

मौलवी साहब अहमद मुस्त्यारका मीयादी अनुमतिपत्र दिसम्बर ३१ को समाप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने मीयाद बढ़ानेके लिए अर्जी दी है। मैं आशा करता हूँ कि मीयाद नहीं बढ़ेगी और मौलवी साहब जनवरी महीनेमें जेलमें विराजमान होंगे। किन्तु मेरी यह आशा व्यर्थ दिखाई देती है। सरकारमें इतना दम नहीं है। समय ऐसा है कि वह मीयाद दे भी दे, और न दे तब भी स्वतन्त्र रहने देगी।

पण्डितजीको जवाब

स्मटस साहब पण्डितजीके पत्रका जवाब दे चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि पण्डितजीको अनुमतिपत्र नहीं दिया जा सकता। इसके सिवा और कुछ नहीं लिखा। इसका अर्थ मैं यह करता हूँ कि अनुमतिपत्र भी नहीं देंगे और पकड़ेंगे भी नहीं।

स्टैंडर्टनके भारतीय

स्टैंडर्टनमें रेलवेमें काम करनेवाले मजदूरोंने पजीयन नहीं करवाया, इसलिए उन्हें कायमुक्त कर दिया गया है। वे लगभग ४० व्यक्ति होंगे। उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। श्री पटेल लिखते हैं कि जिस दिन उन्हें अलग किया गया उस दिनका वेतन नहीं दिया गया। उन्हें एक महीनेका खच दिया गया है। जितना बचा वह रेलवेवाले ले गये। और स्त्री बच्चोंके लिए बिचारे मजदूर मिन्नते करते रहे, फिर भी उन्हें उसी दिन शोपडियोसे निकालनेके लिए छप्पर उतार लिये गये। इस सम्बन्धमें महाप्रबन्धकसे पत्र व्यवहार चल रहा है। महाप्रबन्धकने चालू महीनेके अन्ततक का वेतन चुकानेका हुक्म दिया है। सघने एक महीनेके वेतनकी माग की है। यह मामला हर भारतीयका खून खौलानेवाला है। स्वतन्त्र और बलवान भारतीयोंसे सरकार डरती है, इसलिए गरीबोंको डराती है। यह तो जुल्मकी हद हो गई। ये गरीब मजदूर व्यापारियों और ऐसे ही दूसरे प्रमुख भारतीयोंके भरोसे बेरोजगार हो गये हैं। अतः अब यदि आखिरी घड़ीमें वही व्यापारी और नेता पस्तहिम्मत हो जायेंगे और जेल या नुकसानके डरसे गुलामी स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें गरीब भारतीयों और उनके बालबच्चोंकी हाय लगेगी।

हाइडेलबर्गमें भारतीय मजदूर

हाइडेलबर्गमें भारतीय मजदूरोंको डराकर मजिस्ट्रेटके सामने ले गये थे। तब अफवाह फैली कि वहाँ उन्होंने पजीयन करवानेकी इच्छा व्यक्त की है। इसपर पण्डितजी और श्री नायडू वहाँ पहुँचे। लोगोंसे मिले। उन लोगोंका सरदार अब्दुल नामक एक पठान है। उसने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा कि एक भी व्यक्ति पजीकृत नहीं होगा। फिर पण्डितजी और नायडू फॉरच्यु गये। वहाँ रातमें श्री मोगलियाके घर रहे और सबेरे काम शुरू किया। दिन भर पैदल घूम कर भारतीयोंको कानूनकी जानकारी दी। कहीं-कहीं उन्हें नदी नाले पार करने पड़े। वह कष्ट उठाया। इन मजदूरोंको भी कायमुक्त किया जायेगा या किया जा चुका होगा। विशेष

समाचार अगले सप्ताह मिलनेकी सम्भावना है। इस प्रकार जेलसे छूटनेके बाद पण्डितजी एक घड़ी बेकार नहीं बैठे।

‘सडे टाइम्स’ में व्यंग्य चित्र

‘सडे टाइम्स’ हमारी लड़ाईका बहुत प्रचार कर रहा है। उसमें ‘श्री गांधीका स्वप्न’ शीर्षकसे कानून और श्री स्मट्सके बारेमें व्यंग्य किया गया है। चित्रमें एक स्मट्सका भी है। वे दोनों कुहनिया मेजपर रखे सिरसे हाथ लगाकर निम्नानुसार विचार कर रहे हैं

“रजिस्ट्रेशन” भारी कज़ा,
“रेजिस्ट्रेंस” है उससे बड़ी,
सी० बी० बुडडा तग किये है,
गांधीने पागल बना दिया।

इस प्रकार स्मट्स बडबडा रहे हैं। सी० बी० यानी कैम्बेल बैनरमन, इंग्लैंडके प्रधानमंत्री। दूसरे चित्रमें श्री गांधीको कवच पहनाया गया है। कवचमें सब जगह नुकीली कीलिया लगी हुई है। चित्रपर नोटिस चिपका हुआ है कि “मुझे छुड़ए मत” और नीचे सही है। ‘मैं हूँ आपका दीन (पसिवली) गांधी।’ कहनेका तात्पर्य यह है कि कहीं भी स्पष्ट करनेपर जब काटे चुभते हैं तब ‘दीन कहकर सही करनेसे क्या मतलब? मतलब यह कि अनाक्रामक प्रतिरोध रूपी काटोके चुभते ही कानूनका जोर एकदम खत्म हो जाता है।

जर्मिस्टनके भारतीयोपर आक्रमण

जर्मिस्टनकी नगरपालिकाने सभा की थी। उसमें उसने भारतीयोको मार्केट स्क्वेअरमें अधिकार न देनेके प्रस्तावपर विचार किया है। श्री प्रैडीने उसका विरोध किया है। शेष सदस्य, जिनमें श्री ह्वाइट मुख्य है, हलचलके पक्षमें बोले।

गद्दारोकी सूची^१

पिछले सप्ताह मने जो सूची देनेका वादा किया था, नीचे दे रहा हूँ। वहा दिये गये नाम यहा दुबारा दिये जा रहे हैं। ये नाम १९ अक्टूबरके बादके पञ्जीकृत लोगोके हैं। उनके पते भी मेरे पास हैं। खेद है कि उनकी क्रमसरयाएँ मालूम नहीं ह। किन्तु, उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सूची प्रामाणिक है। इसमें मद्रास और कलकत्ताके लोगोके नाम नहीं हैं, लेकिन उनकी सरया बहुत कम है।

प्रिटोरियाके गद्दार [इसके आगे ८४ नामोकी एक सूची है], जोहानिसबर्गके [१०], पीट्सबर्गके [३५], लुई ट्रिचाटके [८] हाट्सवाटरका [१], क्रिश्चियानाके [२], पौचेप्स्ट्रूम के [११], स्टैडनके [५] मिडेलबर्गके [८], अरमीलोका [१] लीडेनबर्गके [२], हाइडेलबर्गके [८]।

अँगुलियो और अँगूठेमें भेद

इस सम्बन्धमें मैने बादमें लिखनेको कहा था।^२ इसलिए अब लिखता हूँ। भारतमें अँगूठेका उपयोग दीवानी कामोंमें बहुत होता है। विलायतमें तो उसका फैशन चल पडा है। दोस्त

१ इस उपशीर्षककी सामग्री मूल गुजरातीके अग्नेजी अनुवादसे ली गई है

२ देखिए ‘जोहानिसबर्गकी चिट्ठी’, पृष्ठ ४३०।

आपसमे अँगूठेकी निशानी भेजते हैं। पेशन पानेवाले आदि लोगोसे रसीदपर अँगूठेकी निशानी ली जाती है। नेटालमे पी० नोट^१ पर अँगूठा लगानेका रिवाज हो गया है। इस तरह अँगूठे लगानेका यह उद्देश्य है कि उससे मनुष्यकी पहचान तुरत की जा सकती है। एककी जगह दो अँगूठे लगवानेका हेतु यह है कि यदि एक अँगूठा बराबर न उठा हो या उसकी निशानी घिस गई हो अथवा ओर कोई दोष हो तो दूसरे अँगूठेकी निशानी काम दे सके। शिनारतमे इसके सिवा अँगुलियोकी निशानीकी जरूरत नहीं होती। दस अँगुलियोकी निशानी अपराधियोसे ली जाती है। क्योंकि अपराधी स्वयं अपनी पहचान कराना नहीं चाहते। वे छिपकर रहना चाहते हैं। जिसकी दस अँगुलिया लगवाई गई हो उसका नाम न होनेपर भी उसे अँगुलियोके आधारपर पहचाना जा सकता है। अवेषकोने एक कोष्ठक तैयार किया है। उसके आधारपर अमुक प्रकारकी अँगुलीवालोको अमुक विभागमे रखा जा सकता है। कोई व्यक्ति अपना नाम रामजी दे ओर वह सरकारी बहीमे न हो तो भी यदि उसकी अँगुलियोकी निशानी हो तो अँगुलियोके कोष्ठकके आधारपर उसका पता लगाया जा सकता है। इस तरहसे भारत तथा अय देशोमे बहुत से अपराधी पकडे गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपराधी होनेके नाते दस अँगुलियोकी निशानी ली जाती है।

भारतीयोको तो अपनी पहचान करवाना है। यदि वे स्वयं अपनी शिनाख्त न देगे तो वे इस मुल्कमे रह नहीं सकते। इसलिए उनका सच्चा स्वाथ इसीमे है कि वे अपना सही नाम व पता दे। यदि उनका नाम पुस्तिकामे नहीं होगा तो वे इस देशमे रह नहीं सकते। इसलिए उनसे दस अँगुलिया लगवाना बेकार है। यह दलील इतनी मजबूत है कि इससे आखिर सरकारके समक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि दस अँगुलिया लगवाना बेकार और निकम्मा खर्च है। यह विज्ञान भी कहता है। इसलिए कानूनके समाप्त हो जानेके बाद भी सरकारसे दस अँगुलियोके सम्बन्धमे तय किया जा सकता है और उसमे भारतीय समाजकी नादानी नहीं मानी जायेगी। दो अँगूठेके बारेमे यह दलील नहीं की जा सकती। हर लडाई महत्त्वपूर्ण बातपर होनी चाहिए, नहीं तो लोकमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा।

एक जापानी सज्जन

श्री नाकामूरा नामक एक जापानी आये हुए हैं। वे विज्ञानके विद्यार्थी हैं। उनके पास लाड एलगिनका पत्र था। फिर भी अनुमतिपत्र अधिकारीने उन्हें तकलीफ दी थी। वे सारी दुनियाकी खानोकी जाच करते हैं। उनसे श्री पोलककी मुलाकात हुई। उसका विवरण अंग्रेजीमे दिया गया है।^१ उन्होंने कहा है कि वे अपनी सरकारको खूनी कानूनके बारेमे सारी बातें बतायेगे।

संशोधन

एक लेखकने सूचना दी है कि पिछली सावजनिक सभामे प्रिटोरियासे श्री इसे अली और बगस अमीजी आये थे। उनके नाम नहीं दिये गये थे। वे अब देता हूँ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

१ प्रामिसरी नोट या कर्ज पटानेके वायदेका खूका।

२ यहाँ नहीं दिया गया।

३४८ जोहानिसबर्गमे मुकदमा^१

[जोहानिसबर्ग
दिसम्बर २८, १९०७]

गत शनिवारको ठीक १० बजे सवेरे जोहानिसबर्गके सभी व्यक्ति बी फौजदारी अदालत, श्री एच० एच० जोडनके इजलासमे हाजिर हुए। अधीक्षक वरनॉनने उनसे पूछा कि क्या उनके पास १९०७ के कानून २ के अंतगत बाकायदा जारी किये गये पजीयन प्रमाणपत्र ह। उनसे नकारात्मक उत्तर मिलनेपर, वे सब तुरत गिरफ्तार कर लिये गये और उनपर १९०७ के अधिनियम २, खण्ड ८, उपखण्ड २ के अंतगत अभियोग लगाया गया कि वे अधिनियमके अंतगत जारी किये गये पजीयन प्रमाणपत्रके बिना ट्रान्सवालमे ह। अदालत खचाखच भरी थी, और एक समय तो ऐसा जान पड़ता था कि जगला टूट जायेगा।

उपस्थित व्यक्तियोंमें श्री जाज गाडफ्रे, डा० एम० ए० पेरेरा, 'इंडियन ओपिनियन'के सम्पादक और अभियुक्तोके दूसरे अनेक मित्र तथा हितचिंतक थे।

ताजकी ओरसे श्री पी० जे० शूरमनने मुकदमा पेश किया।

अभियुक्तोमे सबसे पहले इनर टेम्पलके बरिस्टर और ट्रान्सवाल भारतीय सघके अवतनिक मंत्री 'यायवादी श्री मो० क० गाधीका मामला पेश हुआ।

टी० टी० पी० विभागेके, अधीक्षक श्री वरनॉनने गिरफ्तारीके बारेमें बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभियुक्त १६ वर्षसे अधिक आयुका एशियाई है और ट्रान्सवालमें रहता है। वे उस दिन प्रातः काल १० बजे श्री गाधीके यहाँ गये और उनसे अपना पजीयन प्रमाणपत्र दिखानेको कहा। किंतु वे दिखा नहीं सके और कहा कि उनके पास प्रमाणपत्र नहीं है।

श्री गाधीने कोई प्रश्न नहीं पूछा और वक्तव्य देनेकी तैयारीसे कठघरेमें गये। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वह बयान नहीं है, किंतु इस अदालतका एक कमचारी होनेके नाते मैं आशा करता हूँ कि अदालत बरायमेहर मुझे सफाईके रूपमें कुछ शब्द कहनेकी अनुमति प्रदान करेगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने इस आदेशको क्यों नहीं माना।

श्री जोडन मैं नहीं समझता कि मामलेसे इसका कोई सम्बन्ध है। कानून है और आपने उसे तोड़ा है। मैं यहाँ किसी तरहका राजनीतिक भाषण नहीं चाहता।

श्री गाधी मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता।

श्री जोडन सवाल यह है कि आपने पजीयन कराया है या नहीं। यदि आपने पजीयन नहीं कराया है तो मामला खत्म है। मैं जो फंसला सुनाने जा रहा हूँ, यदि आपको उसके

^१ अदालतमें गाधीजीपर चलाया गया यह पहला मुकदमा था। यह विवरण "श्री गांधीकी ट्रान्सवालसे निकल जानेका आदेश" शीर्षकसे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था।

बारेमे, दया याचनाके रूपमे कुछ कहना हो तो बात अलग है। कानून मौजूद है जो ट्रासवाल विधान मण्डल द्वारा पास किया जा चुका है और साम्राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मुझे जो कुछ करना चाहिए और मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह केवल इतना है कि कानून जसा भी हो उसे अमलमे लाऊँ।

श्री गांधीने कहा कि मैं सफाईके लिहाजसे कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ कि कानूनके मुताबिक मैं कोई बयान नहीं दे सकता।

श्री जोडन मुझे सिर्फ कानूनी बयानसे सरोकार है। मेरे खयालसे आप यही कहना चाहते हैं कि आपको यह कानून नापसंद है और आप अपनी आत्माके आधारपर इसका विरोध करते हैं।

श्री गांधी यह बिल्कुल ठीक है।

श्री जोडन यदि आप यह कहे कि आपको आत्मिक आपत्ति है तो मैं बयान ले लूँगा।

श्री गांधीने बताया कि वे ट्रासवालमे कब आये थे और यह भी कहा वे ब्रिटिश भारतीय संघके मंत्री हैं। इसपर श्री जोडनने कहा मेरी समझमे नहीं आता कि इससे मुकदमेमे क्या फल पड़ता है।

श्री गांधी यह तो मैं पहले कह चुका हूँ। मैंने अदालतसे केवल पांच मिनटकी अनुकम्पा चाही थी।

श्री जोडन मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मामला है जिसमे अदालत रियायत दे। आपने कानून तोड़ा है।

श्री गांधी बहुत अच्छा, श्रीमान, तब मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री शूरमैनने सूचित किया अभियुक्तको और दूसरे सब एशियाइयोको पजीयन करानेके लिए पर्याप्त समय दिया गया था। जान पड़ता है, अभियुक्त पजीयन नहीं कराना चाहता और इसलिए मैं नहीं समझता कि उसे देशसे चले जानेके लिए कोई लम्बा वक्त दिया जाये। यह निवेदन करना मेरा कतव्य है कि अभियुक्तको ४८ घंटेके भीतर देश छोड़नेका हुक्म दिया जाये।

श्री जोडनने अपना निणय देते हुए कहा सरकार अत्यंत नरम रही है और फिर भी जान पड़ता है कि इन लोगोमें से किसीने पजीयन नहीं कराया। उपनिवेशके कानूनकी अवज्ञाके परिणामस्वरूप सरकारने यह कारवाई की है। मुझे एशियाई पजीयन अध्यादेश, शांति रक्षा अधिनियम और प्रवास-अधिनियमके अंतर्गत अभियुक्तको एक निश्चित अवधिके अंदर उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा देनेका अधिकार है। फिर भी इस मामलेमे कठोरता बरतनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मैं श्री शूरमैनके ४८ घंटे सम्बन्धी सुझावको स्वीकार करना नहीं चाहता। मुझे 'यायसगत आदेश देने चाहिए। श्री गांधी और अन्य लोगोको अपना सामान और चीजे बटोरनेका समय देना चाहिए। साथ ही मुझे श्री गांधीको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कानूनमे कुछ सजाओकी व्यवस्था है। यदि आज्ञाका

पालन न किया जाये तो कमसे कम सजा एक महीनेकी सादा या सरत कदकी है, और यदि अपराधी उस सजाके खत्म होनेके सात दिन बाद फिर उपनिवेशमें मिलता है तो कमसे कम सजा छ महीनेकी है। मुझे यह आशा जरूर है कि इन मामलोमें थोड़ी समझदारी दिखाई जायेगी उपनिवेशके एशियाई यह समझ ले कि वे सरकारके साथ खिलवाड नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करे तो उन्हें पता चल जायेगा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यकी इच्छाके विरोधमें खड़े होनेकी जरूरत करता है तो व्यक्तिसे अधिक शक्तिशाली होनेके कारण क्षति राज्यकी नहीं, व्यक्तिकी होती है।

श्री गांधीने यायाधीशकी बातके बीचमें कहा कि वे ४८ घंटेकी आज्ञा दे और यदि यह अवधि इससे भी कम की जा सके तो उन्हें अधिक सतोष होगा।

श्री जोडन यदि ऐसी बात है तो मैं आपको कदापि निराश नहीं करूँगा। आप उपनिवेशसे ४८ घंटेके अंदर चले जाये, यही मेरा आदेश है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३४९ श्री पी० के० नायडू और अन्य लोगोका मुकदमा^१

[जोमानिनगरा
दिसम्बर २८ १९०७]

[गांधीजी] क्या आप ब्रिटिश प्रजा हैं ?

गवाह जी हा।

क्या आप लडाईसे पहले ट्रान्सवालमें थे ?

जी हाँ, १८८८ से हूँ।

क्या आपने डच सरकारको ३ पौंड कर दिया था ?

मने कुछ नहीं दिया।

आपने कानूनके अंतगत पजीयन-प्रमाणपत्र नहीं लिया है ?

नहीं, किसी भी कानूनके अंतगत नहीं।

क्यों नहीं लिया ?

मेरे खयालसे उस कानूनके अंतगत अनुमतिपत्र लेना मेरे लिए उचित नहीं था। वह मेरे लिए अत्यंत अपमानजनक होता ।

१ गांधीजीने पहले अपने मुकदमेकी पैरवी की थी (देखिए पिछला शीर्षक) और फिर अन्य अभियुक्तोंके मुकदमोकी। अन्य अभियुक्तोंमें सबसे पहले श्री पी० के० नायडूसे जिरह की गई थी।

श्री जोडन क्यो ?

यदि अधिनियम मेरे सम्मुख होता तो म उसमे कुछ प्रविधिया बताता जिनको स्वीकार करना, मेरे खयालसे, ब्रिटिश प्रजाके लिए उचित नही। कानूनमे स्पष्ट कहा गया है कि हम अपनी दसो अँगुलियोके निशान दे, और फिर अपनी आठ अँगुलियोके निशान अलग अलग दे, तथा उनके अतिरिक्त अँगूठोके निशान भी। फिर हमे अपने मा बाप और बच्चोके नाम भी बताने पडते ह ।

श्री शूरमन द्वारा जिरह आप यहा कबसे ह ?

१८८८ से। १८९९ के १८ अक्टूबरको म चला गया था और १९०२ मे वापस आ गया। म नेटाल गया और जुलाई १९०७ मे लौटा।

आपने इस अधिनियमके सम्ब धर्मे सभाएँ की ?

मेरे लौटनेके बाद सभाएँ की गई थी।

क्या आपने भारतीयोसे पजीयन न करानेका आग्रह किया ?

मने शपथ ली कि पजीयन न कराऊँगा।

शपथ कहा ली ?

यदि म भूलता नही तो शपथ बगसडॉपके इनडिपेण्डे स्कूलकी सभामे ली थी।

आप पजीयन कराना नही चाहते ?

नही।

श्री जोडन देशमे आनेके लिए आपके पास अनुमतिपत्र था ?

नही, मेरे पास एशियाई पजीयकका अधिकारपत्र था।

श्री शूरमनने वह अधिकारपत्र देखनेको मागा, जिसे श्री जोडनने मजूर कर लिया।

श्री नवाबखा और समदरखाके मुकदमे ३ जनवरीके लिए स्थगित कर दिये गये, क्योकि कोई दुभाषिया नहीं था।

इसके बाद श्री सी० एम० पिल्लेका मुकदमा लिया गया। उन्होने कहा, म ट्रांसवालमे १८८३ मे आया था, और लडाईसे पहले एशियाई पासो और परवानोका निरीक्षक था। लडाईके दिनोमे म रसद विभागमे एक अधिकारी और यायालयका सदेशवाहक भी था।

श्री गाधी आप पजीयन क्यो नही कराते ?

मेरा खयाल है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अधिनियमकी धाराओका पालन नहीं करेगा, क्योकि उससे हमारी स्वतंत्रता पूणत एशियाई पजीयकके, जो मेरी विनम्र सम्मतिमें इस पदके लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं हे, हाथमे चली जाती है

यायाधीशने यहाँ टोका ओर कहा, म ऐसी बेतुकी बातें नही सुनना चाहता।

मेरा खयाल है कि कोई व्यक्ति यहा आये और इस प्रकार एक सरकारी अधिकारीको गालिया दे, यह निता त घटता है। म इस प्रकार अपना समय नष्ट करना और यायालयकी प्रतिष्ठा घटाना नहीं चाहता। यह अत्यंत अनुचित है।

श्री गाधीने कहा, म अभियुक्तके कथनके अनौचित्यके सब धमे न्यायाधीशसे सहमत हूँ और मेरा इरादा पजीयक पदके लिए पजीयककी अयोग्यताके सम्ब धमे गवाही कराना नही हे।

(अभियुक्तसे) आपकी आपत्ति अधिकारीके विरुद्ध है या अधिनियमके विरुद्ध ?

मुरयत अधिनियमके विरुद्ध ।

सरकारी वकीलकी प्राथनापर वसा ही आदेश दिया गया ।

थम्बो नायडूने कहा, पजीयनपर आपत्ति इसलिए है कि वह मुझे काफिरसे भी नीचे दर्जेमें रख देता है और वह मेरे धर्मके विरुद्ध है । मैं विवाहित हूँ और मेरे पाच बच्चे ह । इनमें सबसे बड़ा तेरह बषका है और सबसे छोटा डेढ़ बषका । मैं माल दुलाईके ठेकोका व्यवसाय करता हूँ ।

श्री गांधीने प्राथना की कि अभियुक्तको केवल अडतालीस घटेका नोटिस दे दिया जाये । वह बस यही चाहता है

श्री जोडनने कहा, प्रश्न यह नहीं है कि अभियुक्त क्या चाहता है, बल्कि यह है कि मैं क्या चाहता हूँ । अभियुक्त व्यवसायी है और मुहलतकी मियाद चौदह दिन निश्चित की जायेगी ।

करवाने कहा, मैं ट्रांसवालमें १८८८ से हूँ । मैं लडाईके दिनोमें सैनिक विभागका ठेकेदार था और सर जाज व्हाइटके साथ लेडीस्मिथमें रहता था । मैं ट्रांसवालमें एक सैनिक दस्तेके साथ हैरीस्मिथके रास्ते प्रविष्ट हुआ था । मैंने १८८५ के कानून ३ के अंतगत एक पजीयन प्रमाणपत्रपर मात्र अपने एक अँगूठेका निशान लगाया था । मैं अँगुलियोंके निशान देनेसे इसलिए इनकार करता हूँ कि यह मेरे धर्मके विरुद्ध है

‘यायाधीश किंतु आपने एक निशान लगाया है ?’

अभियुक्त (विरोधस्वरूप अपना हाथ हिलाते हुए) एक निशान देना ठीक है, किंतु दस निशान देना मेरे धर्मके विरुद्ध है । (हँसी)

न्यायाधीश वास्तवमें मेरे खयालसे आप दस निशान देते हैं या पाच, इसकी आप कोई परवाह नहीं करते । आपसे उसके लिए कहना-भर चाहिए ।

पहले चीनी अभियुक्त एम० ईस्टनने कहा, मैं हागकागवासी ब्रिटिश प्रजा हूँ । मैं यहाँ लडाईसे पहले था और मैंने प्रमाणपत्रके लिए डच सरकारको ३ पौंड कर दिया था । मैं एक दूकानमें सहायकका काम करता हूँ । मैं पजीयनके विरुद्ध इसलिए आपत्ति करता हूँ कि वह अत्यंत पतनकारी और मेरे धर्मके विरुद्ध है । मेरे धर्म, ताओवादमें कोई निशान देनेकी अनुमति नहीं है । उनको ४८ घटेके भीतर देश छोड़ देनेकी आज्ञा दी गई ।

चीनी सघके अध्यक्ष श्री लिअग क्विनने कहा, मैं ब्रिटिश प्रजा नहीं हूँ, किंतु मैं ट्रांसवालमें १८९६ में आया था और मैंने डच सरकारसे अनुमतिपत्र लिया था । १९०१ में मैं चला गया था और फिर १९०३ में शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अंतगत अनुमतिपत्र लेकर लौट आया । मैं दूकानदार हूँ । मैंने अनुमतिपत्र नहीं लिया, क्योंकि वह एक ऐसा कानून है जो मेरे लिए और मेरी जातिके लिए अपमानास्पद है । मैंने अपने देशवासियोंके लिए इस कानूनका अनुवाद किया है और मैं ऐसे मुकदमेकी प्रतीक्षा बराबर करता रहा हूँ । मुझे ४८ घटेके नोटिससे पूरा सन्तोष होगा, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ।

यायाधीशने क्विनको भी १४ दिनका नोटिस, जसा उन्होंने भारतीय दूकानदारको दिया था, देनेपर जोर दिया।

गवाहोके कठघरमे जानेवाले अंतिम व्यक्ति थे जान फोर्तेन। उन्होंने कहा, म ट्रा सवालमे लडाईसे १३ वर्ष पहलेसे रहता हूँ, म अपने चाचाके साथ छुटपनमे ही आया था। म नहीं जानता कि मेरे चाचा कहा ह और न मुझे यही ज्ञात है कि मेरे माता पिता जीवित ह या नहीं। म छात्र हूँ और केप कॉलोनीके (ह्यमसडापके पास स्थित) हकी ई स्ट ट्यूशनसे अभी आया हूँ। वहा म १९०४ से हूँ। म दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर मानता हूँ और चीनमे किसीको नहीं जानता। म पजीयन प्रमाणपत्र लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरे देश और सम्मानके लिए अपमानजनक है। मेरी आयु २१ वर्ष है।

श्री गाधीने कहा, यह अदालतके सम्मुख कुछ कहनेका मेरा अंतिम अवसर होगा। म कुछ सामा य बातें कहना चाहता हूँ। मने अपने मुवक्किलोको जान बूझकर यह सलाह दी है कि वे अपने आपको निर्दोष बताये, ताकि अदालत स्वयं उहीकी जुबानी उनको जो कुछ कहना है, सुन सके। उन सभीने अँगुलियोके निशानोकी प्रणालीके सम्बन्धमे थोडा बहुत कहा है। न्यायाधीश इस विचारको मनसे निकाल दे कि ये लोग क्या कर रहे ह, यह नहीं जानते। म जानता हूँ कि म जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे न्यायाधीशके निष्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता। किन्तु मने यह स्पष्टीकरण देना अपने प्रति और अपने मुवक्किलोके प्रति अपना कतव्य समझा है। इस सप्ताहमे कुछ ऐसी बातें ह जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और इस कानूनमे भी कुछ ऐसी बातें ह जिनको लोग अनुभव करते ह, किन्तु व्यक्त नहीं कर सकते। म अँगुलियोके निशान देनेकी प्रणालीके सम्बन्धमे अभियुक्तोकी भावनाओको समझना न्यायाधीश महोदयपर छोडता हूँ

श्री जोडनने अपने उत्तरमे कहा, अभी जो मामला हमारे सामने प्रस्तुत है उसीके सम्बन्धमे भारतीयोका एक शिष्टमण्डल साम्राज्य सरकारसे निवेदन करने इंग्लैंड गया था, कि तु वह शिष्टमण्डल व्यर्थ रहा। जिस अधिनियमपर इतनी आपत्ति की गई थी उसको ट्रान्सवालकी वर्तमान विधानसभाने पास कर दिया है और उसपर सम्राट्की स्वीकृति मिल गई है। अय सारी भावनाओकी बात छोडकर, मुझे अपनी शक्ति भर कानूनपर अमल करनेके सिवा और कुछ नहीं करना है, और ऐसा करनेके लिए मने शपथ ली है। इन लोगो (अभियुक्तो)ने जानबूझकर सरकारको चुनौती दी है और एक बहुत ही गम्भीर रख अपनाया है। मुझे इस देशमे किसीको भी ऐसा रख अपनाते देखकर दुःख होता है। मुझे इसमे कोई सन्देह नहीं है कि यह कारवाई करके भूल की गई है और यह इंग्लैंडमे शिक्षा सम्बन्धी विधेयकके अनाक्रामक प्रतिरोधियोका अनुकरण मात्र है। मुझे यह रख किसी भी रूपमे कभी पसन्द नहीं आया। प्रत्येक देशके कानूनका उसके निवासियो द्वारा पालन होना चाहिए और यदि वे ऐसा न कर सके तो केवल एक माग रह जाता है—ऐसे लोग कहीं अयत्र चले जाये। किन्तु मेरी समझमे एक बात किसी भी तरह नहीं आ सकती कि जब एक व्यक्ति एक पजीयन प्रमाण पत्रपर अँगूठोका निशान लगा चुका, जसा पिछले सालोमे किया गया था, तब प्रत्येक हाथकी चार अँगुलियोके निशान लगानेपर उसके धमपर आघात कसे होता है।

आगे उहोने शान्ति रक्षा अध्यादेशके अतगत जारी प्रथाका उल्लेख किया और जोर देकर कहा, यदि उहोने उस समय अँगूठेकी निशानीके विरुद्ध आपत्ति की होती तो उनकी स्थिति आज ज्यादा मजबूत होती। उनकी शिनायतका एकमात्र तरीका पजीयन प्रमाणपत्र है, जिसपर अँगूठेकी निशानी आवश्यक होती है। ऐसा पिछली सरकार द्वारा जारी किये गये पीले पासोके दिनोमे भी होता था, किन्तु जब एशियाइयोको नये रूपमे पजीयन कराना पडा तब वे अकस्मात कानूनको सीधी चुनौती दे बठे। श्री गांधीको जानना चाहिए कि ट्रासवालमे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अतगत मेरा अनुभव अय सब 'यायाधीश'से अधिक है। और श्री गांधीको यह भी मालूम होना चाहिए कि तब पीले प्रमाणपत्रोकी अनुचित बिक्री बडे जोरोसे चल पडी थी, जिससे प्रमाणपत्रके असली मालिकका पता लगाना कठिन हो गया था और बहुत परेशानी और खच उठाना पडा था। उसके बाद 'यायाधीश'ने 'यायालय'मे पेश युवकके मामलेपर वापस आते हुए यह आज्ञा दी कि वह उपनिवेशसे सात दिनके भीतर चला जाये।

श्री गांधीने सक्षेपमे उत्तर देते हुए कहा कि पुराने अनुमतिपत्रपर दी गई अँगूठेकी निशानी और नये कानूनके अन्तगत दी जानेवाली अँगुलियोकी निशानियोमे सदा अंतर किया गया है। एक अनिवाय है और दूसरा स्वेच्छाधीन था। 'यायाधीश' भली भांति जानते ह कि जिन मामलोमे अँगूठेकी साफ निशानी ली जाती थी, उनमे आदमीको पहचाना जा सकता था और अनुमतिपत्रोकी नाजायज बिक्री असम्भव हो गई थी।

उहोने 'यायाधीश', सरकारी वकील और पुलिसको मुकदमेमे दिखाई गई शिष्टताके लिए धन्यवाद दिया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५० भाषण सरकारी चौकमे^१

[जोहानिसवग

दिसम्बर २८, १९०७]

मुझपर या दूसरोपर चाहे जो भी बीते, हम लड़ाई बराबर जारी रखेंगे। मैं अपने विचार हरगिज नहीं बदलूंगा और एशियाई समुदायोसे अनुरोध करता हूँ कि वे पजीयन अधिनियमके विरोधमें अपना सघष जारी रखें, चाहे इसके लिए उन्हे देशसे निर्वासित ही क्यों न होना पडे। हो सकता है, मैं बराबर गलतीपर ही होऊँ। यह भी सम्भव है कि आगे चलकर आप सब मुझे कोसैं। परन्तु अभी तो मैं अपने उन्हीं विचारोपर दृढ़ हूँ जो मैंने बताये हैं। यदि ईश्वरकी तरफसे मुझे ऐसा सकेत मिला कि मैंने भूल की है तो मैं अपनी

१ मुकदमेकी सुनवाई समाप्त होनेपर गांधीजीने सरकारी चौकमें भारतीयों, चीनियों और यूरोपीयोंकी एक विराट् सभामें भाषण दिया था। पहले हिन्दुस्तानीमें बोलते हुए उन्हेने मुकदमेकी कार्यवाहीके बारेमें बताया। उनके भाषणके उस अंशकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह रिपोर्ट भाषणके उस अंशकी है जो उन्हेने यूरोपीय श्रोताओंके लिए अंग्रेजीमें दिया था।

भूल स्वीकार करनेवाला सबसे पहला व्यक्ति हूँगा, और आपसे क्षमा याचना करूँगा। पर तुम समझता हूँ, ऐसा सकेत कभी नहीं मिलेगा। मेरा निश्चित मत है कि उपनिवेशों में गुलामों की तरह रहकर अपना सम्मान और स्वाभिमान खोने के बजाय अच्छा है कि हम उपनिवेश छोड़कर चले जायें। यह एक धमयुद्ध है और मैं आपको वही सलाह देता हूँ, जो सदैव देता रहा हूँ, अर्थात् जान लगाकर आखिर तक लड़ते रहिए।

[अंग्रेजी से]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५१ पत्र 'स्टार' को

जोहानिसबग

सेवामें

सम्पादक

'स्टार'

[जोहानिसबग]

महोदय,

सरकार को इस बात के लिए बधाई मिलनी चाहिए कि उसने साहस और ईमानदारी के साथ मुरबूत रूप से उन लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चलाया है जिन्होंने एशियाई कानून के अनाक्रमक प्रतिरोध के आंदोलन का नेतृत्व किया है। वास्तव में यही एक तरीका है जिससे एशियाई भावना की व्यापकता और असह्यता की परख हो सकती है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आन्दोलन में कभी सक्रिय भाग नहीं लिया है, और साथ ही कुछ उल्लेखनीय लोग छोड़ भी दिये गये हैं। ये दोनों तथ्य अपनी कहानी आप कहते हैं। कुछ लोगों ने यह भी सकेत किया है कि एक या दो गिरफ्तारियाँ निजी द्वेष के कारण हुई हैं। परन्तु, आपके सौजन्य का लाभ लेने में, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि प्रश्न के इस पहलू पर बहस करूँ।

ये गिरफ्तारियाँ कानून पर राजकीय स्वीकृति की घोषणा के साथ ही हुई हैं। इससे जान पड़ता है कि सरकार को जो नये अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनका वह प्रयोग करना चाहती है। उसके धनुष में अब तीन प्रत्यक्षाएँ लग गई हैं, अर्थात् गिरफ्तारी, व्यापारिक परवानों की मनाही और निर्वासन। ये सभी अधिकार इसलिए नहीं लिये या दिये गये हैं कि सरकार एशियाई की बढ़ती रोक, क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहता और पजीयन अधिनियम इसे रोक भी नहीं सकता। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को टालना भी इनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो भी भारतीय इस कानून को स्वीकार करता है वह जितने चाहे उतने, जहाँ चाहे वहाँ, परवाने ले सकता है। ये अवि

१ यह ४-१-१९०८ के इंडियन ओपिनियन में सम्पादक के नाम पत्र के रूप में छपा था।

कार इसलिए दिये गये हैं कि सरकार भारतीयोंको अपनी मर्जीके मुताबिक झुका सके, उन्हें अपने अंतःकरणके विरुद्ध काम करनेपर मजबूर कर सके, सक्षेपमे इनका उद्देश्य है एक घातक प्रहार करके भारतीयोंको पुस्तकहीन बना देना जिससे वे उसके हाथोमे मोम जैसे बनकर रह जायें।

क्या उपनिवेशी जानते हैं कि प्रवासी अधिनियमके अंतर्गत होनेवाला निर्वासन साधारण निर्वासनकी अपेक्षा बहुत बुरा है? यदि मैं हत्या करूँ और मुझे आजम निवासनकी सजा मिले तो मैं एक ऐसे स्थानको भेजा जाऊँगा जहा मुझे रहनेका घर और खानेको दाने मिलेंगे, जैसी सुविधा नेटालसे सेट हेलेनाको भेजे गये थोडे-से वतनी विद्रोहियोंको भी दी जाती है। किन्तु यदि मैं एशियाई अधिनियमको सिर न झुकाऊँ और फलतः मुझे निर्वासित कर दिया जाये तो उसका अर्थ यह होगा कि मुझे बिना एक पाईके सीमा पार कर दिया जायेगा और अगर मेरे पास व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो तो ऊपरसे, जैसे बने-बसे, निर्वासन व्यय चुकानेका प्रबन्ध करनेकी जिम्मेदारी लाद दी जायेगी। और यदि ट्रांसवालमे मेरा परिवार है तो जहातक सरकारकी बात है, उसे भूखो मर जाने दिया जायेगा। और सोचिए कि यह सब उन लोगोपर बीतेगी जिन्होंने जीविकोपाजनकी दृष्टिसे ट्रांसवालको अपना घर और भारतको विदेश मान लिया है। गिरफ्तार किये गये भारतीयोंमे से कुछ पन्द्रह वष पुराने व्यापारी ह, उनकी पत्निया दक्षिण आफ्रिकामे जन्मी हैं और ट्रांसवालमे रह रही हैं। एक चीनी है जो बिल्कुल छुटपनमे ही दक्षिण आफ्रिका आया और चीनका नाम भर जानता है। वह पाश्चात्य रीति रिवाजोके बीच जन्मा और पला है। गिरफ्तार किये गये सभी एशियाई यहाके कानूनी अधिवासी हैं और उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधारपर उन्हें इस देशमे रहनेका हक है। ये लोग चूँकि अपनी आत्माकी उपेक्षा न करके एशियाई अधिनियम का उल्लंघन करते हैं इसलिए इन्हें न केवल जेलकी सजा दी जा सकती है बल्कि उपनिवेश-सचिवके हस्ताक्षरसे जारी किये गये वारंटके बलपर उपर्युक्त तरीकेसे देश-निकाला भी दिया जा सकता है। मैं नहीं कहता कि जो लोग कानूनको नहीं मानते, चाहे ऐसा वे अपनी आत्माकी पुकारपर ही करते हों, उन्हें बिल्कुल सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि जब सजा जुमके अनुपातमे नहीं हो तो उससे बबरताकी तेज बू आती है। और यदि प्रवासी कानूनके अंतर्गत प्राप्त अधिकारोका प्रयोग एशियाई अधिनियमके सद्व्यवहारमे किया जाता है तो इसका अर्थ होगा ट्रांसवालके मतदाताओके नामपर एक बबर काय करना। क्या इस देशके लोग एक सम्पूर्ण जातिके विनाशपर प्रसन्नतासे मुस्करायेगे? राजभक्त महिलाओका सच (गिल्ड ऑफ लॉयल विमेन) पत्नियोंको अपने स्वाभाविक सरक्षकोके बिना रखनेके बारेमे क्या कहेगा? मैं अपनेको ब्रिटिश साम्राज्यका प्रेमी तथा ट्रांसवालका एक नागरिक (चाहे मताधिकारहीन ही सही) मानता हूँ, और और देशके सामान्य हित-साधनमे पूरी जिम्मेदारी निभानेको तयार हूँ। और मेरा दावा है कि अगर मैं अपने देश भाइयोको इस कारण एशियाई अधिनियमके आगे न झुकनेकी सलाह देता हूँ कि वह उसके पुस्तकके लिए अकीर्तिकर और उनके धर्मके लिए अपमानजनक है तो यह बात सबथा सम्मानपूर्ण और मेरे उपयुक्त कथनसे मेल खाती हुई होगी। मैं यह भी दावा करता हूँ कि इस बुराईका विरोध करनेके लिए अपनाया गया अनाक्रमक प्रतिरोधका माग सबसे स्वच्छ और निरापद है, क्योंकि यदि प्रतिरोधियोंका पक्ष सच्चा नहीं होगा तो इसका फल उन्हें और केवल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं यह भली भाँति जानता हूँ कि एक ऐसे देशमे, जहा असमान रूपसे विकसित

अनेक जातिया रहती ह, किसी ईमानदार नागरिक द्वारा वहाके कानूनका विरोध करनेकी सलाह दिये जानेमे सुशासनको क्या खतरे है। किंतु मैं यह नहीं मानता कि विधायकोसे गलती हो ही नहीं सकती। मेरा विश्वास है कि प्रतिनिधि विहीन वर्गोंके साथ व्यवहार करनेमे वे सदा उदार या कमसे कम 'यायपूण भावनासे भी परिचालित नहीं होते। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि अनाक्रामक प्रतिरोधकी नीति आम तौरपर स्वीकार कर ली जाये तो हमारे विधायकोकी मूखतापूर्ण भूलके कारण बतनी लोगोके बैय खो देनेपर (जो असम्भव नहीं है) भयानक मृत्यु सवष और रक्तपातका जो खतरा रहता है वह सदाके लिए टल जा सकता है।

यह कहा गया है कि जिन लोगोको कानून पसन्द न हो, वे देश छोडकर बाहर जा सकते हैं। गद्दीदार कुर्सीपर बैठकर यह सब कह देना बहुत सहज है, लेकिन लोगोके लिए न तो यह सम्भव है और न शोभनीय ही कि अपने विरुद्ध बने कुछ कानूनोंको न माननेके कारण वे अपने घर बारको छोड दे। बोअर कालमे जब डच्चेतर गोरोने कानूनके सरत होनेकी शिकायतकी थी तब उनसे भी यही कहा गया था कि यदि कानून पसन्द नहीं है तो वे देश छोडकर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने न जाना ही बेहतर समझा। क्या भारतीय जो अपने आत्म सम्मानके लिए लड रहे हैं, कैद या उससे भी कडे दण्डसे डरकर देशसे भाग जायेंगे।

नहीं श्रीमन्, यदि मेरा बस चले तो पशु बलके सिवा और कोई शक्ति भारतीयोको इस देशसे हटा नहीं सकती। नागरिकका यह कोई कतव्य नहीं है कि अपने ऊपर लादे गये कानूनोंका वह आख मूदकर पालन करे। और यदि मेरे देशवासियोका ईश्वरमे और आत्माके अस्तित्वमे विश्वास है तो उनके मस्तिष्क, इच्छाशक्ति तथा आत्माएँ आकाशके परिदोकी भाति उमुक्त और तेजसे तेज तीरकी पहुँचसे परे रहेगी, भले ही वे अपने शरीरपर राज्यकी सत्ता स्वीकार कर जेल जाये, देश निकाला भोगे। जनरल स्मट्स, जिनकी एक नेकदिल उपनिवेश मन्त्री द्वारा मजूर किये गये दमनकारी कानूनोंमे बडी आस्था है, यह भूल जाते हैं कि जो एशियाई अत करणकी पुकार-पर आज लड रहे हैं, वे उनके किसी उपायसे झुकेगे नहीं। यदि नेताओके हटते ही मेरे देशवासी झुक गये, तब तो हम ऐसे ही कानूनके योग्य होंगे। लेकिन तब भी अनाक्रामक प्रतिरोधकी अर्थात् ईसा मसीहकी "बुराईका विरोध मत करो" वाली शिक्षाकी शुद्धता प्रमाणित हो ही जायेगी।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

स्टार, ३०-१२-१९०७

३५२ भाषण चीनी सधमे^१

[जोहानिसबग
दिसम्बर ३०, १९०७]

जो लोग समझते ह कि यह लडाई धमकी लडाई नहीं हे या इसमे धम नहीं है, वे नहीं जानते कि धमका क्या अर्थ है। मेरा विश्वास है कि मने बहुत से धर्मोंके सम्बन्धमे कुछ न-कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। हर धमकी यह शिक्षा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा कुछ करता है जिससे उसके पुस्त्वपर बट्टा लगता है, तो उसमे कोई धम नहीं हे। अगर धमका अर्थ ईश्वरकी उपासना है, उसमे विश्वास रखना हे, तो मुझे यह कहनेमे जरा भी सकोच नहीं कि ट्रांसवालमे कुछ पौंड या पेस पानेके लिए अपने आपको गिराना सबथा अधार्मिक कृत्य है। ऐसा करते हुए भी हम यह तो स्वीकार करेगे कि यह ठीक, उचित और "याययुक्त नहीं हे। अगर इस देशके एशियाई आँखे बन्द करके अपने नेताओके पीछे चले, और जैसे ही नेता मदानसे हटे, वे अधिनियमको स्वीकार कर ले, तो मेरे विचारसे वे इस कानूनके पात्र ह। इसलिए स्थितिकी कुजी स्वयं हमारे अपने हाथोमे है। अगर हमने अपने पक्षके औचित्यमें विश्वास है और हम मानते ह कि हम आगे बढ़ रहे ह तो परवाह नहीं कि आगे क्या होने-वाला है। जनरल स्मट्स इस उपनिवेशमे जो चाहे करते रहे, और साम्राज्य सरकार भी महामहिमके नामपर जिस बातके लिए चाहे मजूरियाँ देती रहे, जिस पथपर हमने कदम बढ़ाया है, उससे रचमात्र पीछे नहीं हटेंगे।

ट्रांसवालके अधिवासी एशियाइयोंको सरकार सीमासे बाहर निकाल सकेगी, इसमे मुझे तो बड़ा सदेह है, परन्तु अब ट्रांसवालके सबसे बड़े वकीलके^१ युक्तियुक्त मतसे मेरा अपना मत और भी पुष्ट हो गया है।

परन्तु एकबार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप श्री लियोनाडकी रायका अथवा किसी अन्य कानूनी रायका भरोसा न करे। इस लडाईमे जिसपर आप अपनी श्रद्धा केन्द्रित कर सकते हैं, सम्भवत वह केवल आपके अपने विवेककी राय और परमात्माका साथ है। अगर आपने अन्य किसीका भरोसा किया तो वह बालूकी भीतका सहारा लेना होगा।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

१ ट्रांसवालमे एशियाइयोंपर आयी मुसीबतमे गांधीजोने उनकी जो सेवाएँ की थीं, उनके लिए उन्हें धन्यवाद देनेके हेतु यह सभा आयोजित हुई थी। उसमें अ य लोगोंके अतिरिक्त लगभग ४०० स्थायी निवासी चीनी उपस्थित थे। चीनी सक्षे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री जे० एल० वेंसी इसके समापति थे।

२ जे० डब्ल्यू० लियोनाड

३५३ भेंट रायटरको^१

[जोहानिसबर्ग
दिसम्बर ३०, १९०७]

शिनाख्तके मामलेमें भारतीयोंने सरकारको बराबर सहायता देनेका प्रस्ताव किया परंतु सरकारने उनकी सहायताके प्रस्तावकी उपेक्षा की। भारतीय सब इस बातसे सहमत रहे ह कि ट्रांसवालको भावी प्रवासके नियमन और नियंत्रणका अधिकार है। सबसे अधिक चिंता उहे उन भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें हे जो अब ट्रांसवालके वध निवासी ह।

श्री गांधीने इस आरोपको अस्वीकार किया कि भारतीयोंने सरकारके अधिनियमोका अत्यन्त सतापजनक अथ लगाकर सरकारका अपमान किया है। वे हृदयसे इस बातका स्वागत करेगे कि उनका मामला साम्राज्यीय सम्मेलनमें उठाया जाये। उहे विश्वास है कि इसका परिणाम एक मानवीय सतोषजनक व्यवस्थाके रूपमें होगा, जिसका दोनों पक्ष पालन करेगे। श्री गांधीने शिकायत की कि अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके साथ पेश आनेके लिए सरकारको प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमके द्वारा अत्यधिक अधिकार दे दिये गये ह। उनके खयालसे अपराधको देखते हुए यह अधिकार सबथा असंगत है। उन्होंने आशंका प्रकट की कि जिन भारतीयोंने पजीयन करानेसे इनकार किया है उनके व्यापारिक परवाने १ जनवरीको अस्वीकृत हो जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वे बिना परवानेके व्यापार जारी रखेंगे।

श्री गांधीने कहा कि यहाँके भारतीयोंको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सूरत अधिवेशन और अय क्षेत्रोंसे सहानुभूति और सहायताके तार मिले ह। — रायटर।

[अग्रेजीसे]

इंडिया, ३-१-१९०८

१ गांधीजीने यह भेंट सर रेमंड वेस्के उद्गारोपर टीका करते हुए दी थी। सर रेमंड वेस्के लन्दनमें कहा था कि दोनों पक्ष 'बहुत दूर' चले गये हैं। ट्रांसवाल सरकारने 'रक्षतासे' भारतीयोंकी भावनाओंकी उपेक्षा की है और भारतीयोंने सरकारके अधिनियमका क्रमसे क्रमसे बजाय अधिकसे अधिक अपमानजनक अर्थ लगाया है। उन्होंने समझौतेका सुझाव दिया। भारतीयोंको चाहिए कि वे "निर्दोष दग" से शिनाख्त करनेके कार्यमें सहायता करें उपनिवेशके अधिवासियोंके "निर्दोष पजीयन" की शर्तपर प्रवासके नियमनमें सहयोग करे। "एक सयुक्त समिति स्थापित की जाये और भारतीय नेताओंपर कुछ उत्तरदायित्व सौंपा जाये। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो भारतीयोंको चाहिए कि वे ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे इस कुप्रथाके विरुद्ध सम्राट्से रक्षाकी माँग करे, जो कि महामहिम उन्हें विदेशमें देनेके लिए बाध्य हैं।

३५४ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[दिसम्बर ३१, १९०७]

मंगलवार,

एक साथ धर पकड़

प्रिटोरिया, पीटसबर्ग, जोहानिसबर्ग और जर्मिस्टनमे सरकारने दिसम्बर खाली नही छोडा। प्रिटोरियामे १२, जोहानिसबर्गमे ९, पीटसबर्गमे ३, और जर्मिस्टनमे १ वारंट निकाले गये। प्रिटोरियामे श्री मुलेमान सूज, श्री ए० एम० काछलिया, श्री अर्देसर बेग, श्री गौरीशकर व्यास, श्री गुलाम मुहम्मद रशीद, श्री इस्माइल जुमा, श्री रहमत खा, श्री चुनीलाल शेठ, श्री तुलसी, श्री गंगादीन तथा श्री मणिलाल देसाई, जोहानिसबर्गमे श्री गाधी, श्री थम्बी नायडू श्री सी० एम० पिल्ले, श्री नवाब खा, श्री समदर खा, श्री कडवा, श्री क्विन, श्री ईस्टन और श्री फोर्तोएन, पीटसबर्गमे श्री मोहनलाल खडेरिया, श्री अमरशी गोकल और श्री अम्बालाल^१ तथा जर्मिस्टनमे रामसुंदर 'पण्डित' के नाम वारंट निकाले गये थे। इनमे श्री रहमतखा नगरसे बाहर होनेके कारण गिरफ्तार नही हुए। श्री काछलिया खबर मिलते ही अपने कामको अधूरा छोडकर सम्मनके स्वागतके लिए फोक्सरस्टसे प्रिटोरिया दौड़े गये, जब कि रामसुन्दर भाग गया। श्री चुनीलाल और तुलसीने मुकदमा स्थगित करवाया।

रामसुन्दरकी कहानी बताना आवश्यक है। शुक्रवारको जब पुलिस कमिश्नरकी सूचना आई तब उक्त भाई साहब श्री गाधीके कार्यालयमे मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि वे शनिवारको अदालतमे उपस्थित हो ही जायेंगे। लेकिन जर्मिस्टन जाकर उन्होंने अपने जो दो एक शिष्य थे उहे बुलाकर उनसे कह दिया कि वे और अधिक जेल स्वयं बर्दाश्त नही कर पायेंगे। इसलिए उनका विचार चले जानेका है। शिष्योंने बहुत समझाया किन्तु राम सुंदरपर भय सवार हो गया था, इसलिए किसीकी न मानकर औरोको खबर दिये बिना ही उन्होंने चुपकेसे नेटालकी ट्रेन पकड़ ली। इस प्रकार वे जैसे चढे थे वैसे ही गिर गये हैं। उनके सम्बन्धमे मैंने इस पत्रमे बहुत लेख लिखे। वे अब गलत हो गये। उनके सम्बन्धमे जो कविताए थी वे व्यर्थ हो गई। खोटा रुपया खरा हो ही नही सकता। यह लडाई ऐसी है कि सबका सत्त्व अन्तमे जाकर प्रकट हो ही जायेगा। कौमके हिसाबमे रामसुंदर अब जीवित नही हैं। अब हमे उनको भूल जाना है।

इसके अतिरिक्त और सब तो दढ दीखते हैं। गिरफ्तार होनेवालोमे प्राय सभी जातिया आ जाती हैं। अर्थात् चार सूरती मुसलमान, एक मेमन, दो पठान, एक पारसी, एक ब्राह्मण, तीन बनिये, एक कलकत्तेका हिन्दू, एक सिक्ख, दो ईसाई, एक लुहाणा, तीन मद्रासी हिन्दू और तीन चीनी इस प्रकार मिलकर तेईस एशियाई गिरफ्तार हुए हैं। उनमे से श्री सूज, श्री देसाई, श्री व्यास, श्री खडेरिया, श्री नायडू, इन सबके बाल बच्चे ट्रान्सवालमे हैं। इनमे कई व्यापारी हैं, कई नौकर ह। इस प्रकार प्रत्येक कौमके लिए प्रसन्न होनेकी बात है।

व्यापारी अधिक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए ?

यह प्रश्न उठा है। मेरा खयाल है कि सरकारको परवानेके सम्बन्धमें व्यापारियोंको सताना है, इसीलिए शायद श्री ईसप मिया आदिको फिलहाल छोड़ दिया है। फिर उन्हें छोड़ देनेका यह कारण भी हो सकता है कि कुछ व्यापारियोंने सरकारको लिखा है कि यदि धरनेदार आदि उपद्रवी लोग हट जाये तो वे कानूनके अधीन होनेको तैयार हैं। इस कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ऐसा जान पड़ता है। कुछ ऐसोको पकड़ा है जि होने लड़ाईमें कोई भाग नहीं लिया है। इसके कारण खोजनेकी इस समय मुझे आवश्यकता नहीं दीखती।

प्रवासी कानूनपर हस्ताक्षर क्यों हुए ?

वर पकड़ हो जानेके कारण प्रवासी कानून मजूर होनेकी बात कुछ पीछे पड़ गई है। और उसके बारेमें लोगोका डर काफूर हो गया है। उस कानूनपर हस्ताक्षर होनेका कारण हम स्वयं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, कई व्यापारियोंने पत्र लिखा है कि यदि कुछ व्यक्ति हट जाये तो वे कानूनके अधीन हो जायेंगे। फिर और कोई पजीयकके पास किसीकी दो-चार बातें कह आता है। यह सब बढ़ा-बढ़ाकर लाड एलगिनके पास पहुँचाई जाती है कि यदि प्रवासी कानून पास हो जाये तो सभी लोग पजीयन करा लेंगे। ऐसी बातें लाड एलगिनके पास पहुँचे और कानूनपर हस्ताक्षर हो जाये तो इसमें क्या आश्चर्य ? सतोपकी बात यह है कि भारतीय कौम कानूनको डकार गई दीखती है।

कुछ डरपोक

फिर भी कुछ डरपोक निकल आये हैं। इनमें से कुछ थोड़ेसे भेमन पीटसबर्गमें बाकी रह गये थे, उनमेंसे कुछकी ओरसे अर्जी पहुँच गई है कि वे अब झुकनेके लिए तैयार हैं। मैं तो ऐसा ही मानूँगा कि ज्यो ज्यो कष्ट बढ़ेगा त्यो त्यो इस प्रकारका कूड़ा छँटता जायेगा और जो बच रहेगा वह खरा सोना रहेगा। वे ही कौमकी नावको बन्दरगाहपर पहुँचायेंगे। जो लिहाजके मारे शूर बनते हैं किन्तु असलमें डरपोक हैं वे टिक पायेंगे ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है।

भय व्यर्थ है ?

परन्तु ऐसा भय अकारण है। हजारों आदमियोंको देश निकाला होनेवाला नहीं है। और सभी गोरे मानते हैं कि इस कानूनको माननेवालोंकी ट्रान्सवालमें बुरी गत होगी।

प्रवासी कानूनके विनियम

इस अधिनियमके अन्तर्गत जो विनियम बनकर प्रकाशित हुए हैं उनका अनुवाद सम्पादक अन्यत्र देगा। इस समय तो उस अधिनियमकी एक ही अनोखी बातकी चर्चा कर रहा हूँ। उसके अन्तर्गत जो अनुमतिपत्र, पास इत्यादि निकलनेवाले हैं उन सबपर दसो अँगुलिया लगानी है। ये विनियम गोरे काले सबपर लागू होते हैं। विलायतसे आनेवाले गोरे नौकरोके पास इस प्रकारका पास होगा तभी वे ट्रान्सवालमें आ सकेंगे। अब सही सही समझमें आ सकेगा कि खूनी कानूनकी लड़ाई अँगुलियोंकी लड़ाई नहीं है, बल्कि वह कानूनके गुप्त प्रहारके विरोधमें है। हम प्रवासकी वाराका विरोध करें सो तो है ही नहीं। फिलहाल तो वह कानून

हमारे लिए बेकार है। जो लोग खूनी कानूनके अधीन हुए हैं, वे ही उसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोगोका तो इसके निर्वासनवाले खण्डसे ही सम्बन्ध है। लेकिन ऊपरकी बात ध्यान देने योग्य है। अँगुलियोकी बात हटा दी जाये तो भी खूनी कानून हम मजूर कर ही नहीं सकते। वह कानून ही विष रूप है। उसकी तुलना और कानूनोंके साथ हो ही नहीं सकती।

गांधीकी अनुपस्थितिमें कौन ?

श्री गांधीकी अनुपस्थितिमें काम करनेवालेके बारेमें सवाल उठा है। मेरी मान्यता है कि श्री पोलकने भारतीय कौमको अपना जीवन अपण कर दिया है। उन्हें इस प्रश्नकी अच्छी जानकारी हो गई है। वे कुलीन व्यक्ति हैं। उनकी लेखनीमें तेज है। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। वे बहुत-से अंग्रेजोंके सम्पर्कमें आ चुके हैं। और हर भारतीय उन्हें जानता है। कई बातोंमें उनसे सहायता मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ब्रिटिश भारतीय सघके नाम जो पत्रादि आयेगे उनकी व्यवस्था भी वे कर सकेंगे। यह अधिक ठीक होगा कि जहातक बने उन्हें पत्र अंग्रेजीमें लिखे जायें।

अनाकामक प्रतिरोधका प्रचार

भारतीय मुकदमोंका विवरण समाचरपत्रोंमें बहुत आ रहा है और दीख पड़ता है कि हरएक अखबारका रख पूरी तरहसे हमारे पक्षमें है। बहुत-से गोरे तो अब जनरल स्मट्सके कारण शर्मिन्दा हो रहे हैं। 'ट्रान्सवाल लीडर' ने इन नये मुकदमोंको चलानेपर भारतीयोंके पक्षमें सहानुभूतिपूर्ण आलोचना की है।

अब क्या सम्भव है ?

जान पड़ता है, अब लडाईका अन्त जल्दी ही आनेवाला है। जो गिरफ्तार किये गये हैं उनके अतिरिक्त फिलहाल औरोंको गिरफ्तार किया जायेगा, ऐसा नहीं दीखता। परवाना सम्बन्धी अडचने, एव श्री गांधी और दूसरोंकी अनुपस्थितिसे उत्पन्न प्रभावको सरकार परखेगी और इसपर भी अगर कौम अधिकतर दब रही तो जान पड़ता है माच महीनेमें निबटारा हो जायेगा। इसका सारा दारोमदार हमपर है।

'जाको राखे साँझों'

जनरल स्मट्सने भारतीयोंके लिए जो जाल बिछाया था उसे हटाना पड़ा है। आज (मंगलवारके) प्रातः काल श्री नायडू, श्री पिल्ले, श्री ईस्टन, श्री कडवा तथा श्री गांधी जेल-महलमें पधारनेवाले थे। परंतु दस बजेसे पहले टेलीफोन आया कि अदालत जानेकी बिलकुल जरूरत नहीं है। जब नोटिस मिले तब अदालतमें हाजिर हो। इसलिए इस समय तो ऊपर बताये हुए भारतीय जवान कारावासके सुखका स्वाद नहीं ले पायेंगे। इससे फूल नहीं जाना चाहिए। अब तो सभी भारतीय समझ गये होंगे कि सघर्ष कठिन होगा। जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कुछ सदेह नहीं है। जिनको अभीतक गिरफ्तार नहीं किया है उनको आगे चलकर गिरफ्तार किया जायेगा, ऐसा ही मानना चाहिए।

अब तो सभीको अपने हथियार सँभालकर, तैयार होकर प्रतीक्षा करनी है। जनरल क्रॉज़ी और उनकी फौज एक बार चौबीसो घंटे बस्तर पहनकर तैयार रहा करती थी,

वैसा ही हमें करना है। गिरफ्तार नहीं किये जायेंगे, यह खबर आनेपर लोग जोशमें आ गये श्री गांधीका कार्यालय घिर गया। भाषण हुए। इसी बीच रास्तेपर यह सभा हुई। इसपर सिपाहीने आकर सूचना दी कि नगरपरिषदकी इजाजतके बिना रास्तेपर सभा नहीं करनी चाहिए। इससे सब बिखर गये। इस समय तो सभी भारतीयोंमें जोश दीख पड़ता है।

देश निकालेकी आशा ही नहीं

प्रवासी कानूनके अंतर्गत दिये जानेवाले देश निकालेपर श्री लेनडने जो राय दी है, पूरी तरह हमारे पक्षमें है, और उससे जाहिर होता है कि भारतीयोंको हरगिज देश निकाला नहीं दिया जा सकेगा। देनेका विचार किया गया, तो लड़ेंगे। भारतीय अधीर न होकर घरमें जमकर बैठे रहेंगे और जो हानि होगी उसे सहन कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जायेगा।

हॉस्केनकी सहानुभूति

मंगलवारको श्री हॉस्केन विशेष रूपसे श्री गांधीके कार्यालयमें आये, और उन्होंने गद्गद् होकर अपनी सहानुभूति प्रकट की। वे भली भांति समझ गये हैं कि हमारी लड़ाई धार्मिक है। अनेक नामांकित गोरे आपसमें ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं। अब तो प्रायः सभी गोरे हितैषी डटकर लड़नेको ही कह रहे हैं।

धोखेबाज भारतीय

डेलगोआ बेसे खबर आई है कि दो लुटेरे भारतीय ट्रांसवालसे डेलगोआ बे गये हैं। वे लोगोसे कहते हैं कि प्रति व्यक्ति १२ पौंड १० शिल्लिंग मिले तो वे श्री चैमनेको डेलगोआ बे बुलाकर अनुमतिपत्र दिला देंगे। इसे मैं बिल्कुल झूठ मानता हूँ। श्री चैमने इस प्रकार कभी पजीयन नहीं कर सकते। मैं प्रत्येक भारतीयसे ऐसे व्यक्तियोंसे सतक रहनेकी सिफारिश करता हूँ। ऐसे लोग अनुमतिपत्र नहीं दिला सकते और इस प्रकारके मनुष्य कौमको सरकारकी अपेक्षा अधिक हानि पहुँचाते हैं।

डबनमें सरकारकी दगाबाजी

तार आया है कि अपने देशसे आनेवाले भारतीयोंको डबनमें ही गुलामीका चिट्ठा दे दिया जाता है और [तब] वह भारतीय यहाँ आता है। डबनके भारतीय बहुत तार करते हैं, बातें करते हैं। मैंने अनेक बार कहा है कि किसी व्यक्तिको देशसे आनेवाले सभी भारतीयोंसे मिलना चाहिए, और उनको कानून समझाना चाहिए। फिर भी कोई इतना आसान काम करता हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। तब फिर उनका ट्रांसवालको ढाढस बँधाना किस काम का? मुझे आशा है कि डबनमें ऐसा एक भारतीय तो होगा ही कि जो स्टीमरसे उतरनेवाले भारतीयोंसे मिलकर [उनकी योजनाके बारेमें] पूछताछ कर सके। आवश्यक जान पड़े तो ऐसे भारतीयोंसे डेलगोआ बेमें भी मिलना चाहिए।

पोट एलिजाबेथ

पोट एलिजाबेथके सघने २५ पौंडकी सहायता ब्रिटिश भारतीय सघको भेजी है। यह सघन्यवाद स्वीकृत की जाती है।

भारतीयोंकी सभा

शुक्रवारकी शामको हमीदिया भवनमें एक विशाल सभा हुई। करीब १,००० आदमी उपस्थित थे। लोगोमें बड़ा उत्साह था। प्रवासी कानूनकी निंदाका प्रस्ताव पास किया गया और तार द्वारा विलायत भेजा गया।

चीनियोंकी सभा

उसी शाम चीनियोंकी सभा हुई। श्री विवनने अपने देश निकालेकी सम्भावनाके कारण अपनी मण्डलीके स्थानापन्न अध्यक्षके रूपमें श्री पोलकको नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया,^१ जो स्वीकृत हो गया। श्री पोलकने भाषण दिया। सबके सब साहससे भरे हुए थे और सभीके मनोमें अन्ततक लड़नेका उत्साह था।

अधिक सभाएँ

जोहानिसबगमें जगह जगह सभाएँ हुई हैं। सोमवारकी शामको चीनियोंकी सभा हुई, इसके बाद मद्रासी लोगोकी सभा थी। दोनों सभाओका वातावरण जोश और हौसलेसे भरा हुआ था। श्री गांधी उपस्थित थे। सोमवारकी रातको भारतीयोंकी एक विशाल सभा हुई। उसमें चीनी प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री ईसप मियाने व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने लोगोको दब रहने और नेताओकी जगह भरनेकी सिफारिश की।

प्रिटोरियामे सभा

प्रिटोरियामे सोमवारको सभा की गई। ३०० आदमी उपस्थित थे। श्री हाजी हबीब प्रमुख थे। श्री गांधी और चार चीनी नेता खास तोरपर आये थे। श्री गांधीने भाषणमें कहा कि हमे चीनियोंके ऐक्यका उदाहरण ग्रहण करना है। यदि हम अपना कतव्य पूरा करते रहे और ट्रान्सवाल सरकार या सारा राज्य हमारे खिलाफ रहा तो भी कुछ बिगड़नेवाला नहीं है। मुझे तो जीतका विश्वास है। सही लड़ाई तो अब, इसी समय शुरू होने जा रही है। श्री सूजनने कहा कि चाहे जो हो, मैं इस कानूनको नहीं मानूंगा। श्री देसाईने बतलाया कि वे देश निकालेके लिए राजी हैं। श्री बेग बोले कि कुर्बानी देनेसे ही जीत मिलती है, इतिहासमें इसके उदाहरण मिलते हैं। उपस्थित सज्जनोमें से श्री मनजी और दूसरे लोग भी बोले। श्री हाजी हबीबने कहा कि श्री गांधीके वचन सुननेका यह अन्तिम अवसर है। फिर भी देश निकाला हो जानेपर हम दब रहकर उनको वापस बुला सकेंगे। हम देश निकालेसे या परवाना रोके जानेसे डरनेवाले नहीं हैं।

इस सभामे ज्यादा आदमी नहीं थे यह बात गोरे अखबारवालोकी निगाहसे छूटी नहीं दीखती।

प्रिटोरियामे बाडेका मुकदमा

श्री रतनजी मकनके लिए एशियाई बाजारमें बाडेके पट्टेके वास्ते अर्जी दी गई थी। उसके उत्तरमें टाउन क्लकने कहलाया है कि “प्रार्थी पजीकृत न होनेके कारण ट्रान्सवालका

^१ यह उस विवरणसे भिन्न पड़ता है जो इसी तारीखके इंडियन ओपिनियनके अंग्रेजी विभागमें दिया गया है। उक्त विवरणके अनुसार श्री विवनने अपनी अनुपस्थितिमें एक कार्यवाहक अध्यक्षकी नियुक्तिकी घोषणा करते हुए बताया कि श्री एच० एस० एल० पोलक सबके अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किये गये हैं।

अवैध निवासी माना जायेगा।” इस प्रकार सरकार एशियाई कानूनका विरोध करनेवालोको अधिक तग करना चाहती है। ये सब हमारी अवदशाके लक्षण हैं। और इसे समझकर ट्रांसवालके भारतीय अपना बंधन तोड़नेके लिए अधिक दब हुए बिना नहीं रहेंगे।

कैनडलका पत्र

श्री जाडनने फैसला देते हुए जो आलोचना की थी उसके उत्तरमे श्री कैनडलने ‘लीडर’ मे पत्र लिखा है कि “पहले भारतीयोंने एक अँगूठा लगाया था — और वह स्वेच्छासे। इस समय १८ निशान मागे जाते ह और सो भी अनिवाय रूपसे। इसे भारतीय सचमुच धार्मिक आपत्ति मान सकते हैं। सच्चा मुसलमान कभी अपनी सभी अँगुलिया नहीं लगायेगा। ऐसा करना मूर्ति चित्रित करनेके समान होगा और इस बातकी मुसलमानी मजहबमे मनाही है।”

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५५ पत्र एशियाई-पजीयकको

[जोहानिसबग]

दिसम्बर ३१, १९०७

सेवामे

एशियाई पजीयक

[प्रिटोरिया

महोदय,]

मुझे डेलागोआ-बेसे अभी अभी एक पत्र मिला है। उससे ज्ञात हुआ है कि ट्रांसवालके कोई दो भारतीय इस समय डेलागोआ-बेमे लोगोको बरगला रहे हैं। उनका कहना है कि जो भारतीय ट्रांसवालमे प्रवेशका अनुमतिपत्र पानेके इच्छुक हैं वे यदि उनको प्रति व्यक्ति १२ पौंड १० शिलिंग दे तो आप उ हे डेलागोआ बेमे ही अनुमतिपत्र देनेको राजी हो जायेंगे।

मुझे कहना न होगा कि मैं उपयुक्त कथनको, जहातक आपका सम्बन्ध है, अपमानजनक मानता हूँ। परन्तु यह निश्चित है कि उक्त भारतीय इस प्रकारकी बात सीधे सादे लोगोको अपना शिकार बनानेके लिए ही कहते रहे हैं। अतएव क्या मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप जिस प्रकार भी मुनासिब समझे, डेलागोआ बेके ब्रिटिश भारतीयोको सूचित कर दें कि वे ऐसे किन्हीं भी लोगोकी बात सच न मानें। यह भी बता दें कि अनुमतिपत्र या प्रमाणपत्र केवल प्रिटोरियामे आपके कार्यालयमे ही प्राप्त किये जा सकते हैं। अपनी तरफसे मैंने ‘इंडियन ओपिनियन’ के स्तम्भो तथा अन्य जरियोसे लोगोको सावधान करनेकी पूरी कोशिश की है।

[आपका, आदि,

मो० क० गाधी]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एशियाई कानून सशोधन अधिनियम

१८८५ के कानून ३ में सशोधनार्थ

(२२ मार्च, १९०७ [को] स्वीकृत)

द्रा-सवाल सरकार द्वारा प्रकाशित पूरा अधिकृत पाठ नीचे दिया जाता है

महामहिम सत्राट्ट द्वारा ठा सवाल विधान परिषद और विधान सभाकी सलाह और अनुमतिसे निम्नलिखित कानून बनाया जाता है

निरसन

१ ससदके प्रस्तावो द्वारा १२ अगस्त १८८६ की धारा १४१९ और १६ मई १८९० की धारा १२८ से सशोधित सन् १८८५ के कानून ३ की धारा २ का उपखण्ड (ग) इसके द्वारा रद किया जाता है ।

परिभाषाएँ

२ इस अधिनियममें, जबतक वह मूल पाठसे असंगत न हो,

एशियाई ' का अर्थ होगा १८८५ के कानून ३ की धारा एकमें बताया गया पुरुष जो मलायामें उत्पन्न और दक्षिण आफ्रिकाके किसी ब्रिटिश उपनिवेश या अधिकृत प्रदेशका अधिवासी न हो और न ही १९०४के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तर्गत लाया गया व्यक्ति अथवा चीनी वाणिज्य दूतावासकी सेवामें नियुक्त कोई अधिकारी हो,

“एशियाई पजिका” (रजिस्टर ऑफ़ एशियाटिक्स) का अर्थ होगा वह पजिका जो इस कानूनके अन्तर्गत विनियममें बताई गई विधिसे रखी जायेगी,

“पजीयक” का अर्थ होगा वह अधिकारी जो गवर्नर द्वारा एशियाई पजिका रखनेके लिए नियुक्त किया जाये और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानूनके अनुसार उस पदका कार्य वहन करे,

“आवासी न्यायाधीश” में सहायक आवासी न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा,

“विनियम” का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड अठारहके अन्तर्गत बनाया गया कोई भी विनियम,

“अभिभावक” का अर्थ होगा सोलह वर्षसे कम आयुके एशियाइके पिता माता अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसके संरक्षण या नियंत्रणमें ऐसा एशियाई उस समय रहता हो, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे एशियाईका मालिक,

“पजीयन प्रार्थनापत्र” का अर्थ होगा ऐसा प्रार्थनापत्र जो एशियाई पजिकामें रखा जायेगा, वह विनियम द्वारा बताई गई विधिसे और विहित रूपमें दिया जायेगा और उसके साथ इस अधिनियम या विनियम द्वारा विहित विवरण और शिनाख्तके निशान होंगे,

“प्रार्थी” का अर्थ होगा वह व्यक्ति, जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है या जिसकी ओरसे उसका संरक्षक प्रार्थनापत्र देता है,

“पजीयन प्रमाणपत्र” का अर्थ होगा इस अधिनियमके अन्तर्गत विनियमों द्वारा विहित रूपमें पजीयनका प्रमाणपत्र,

“वैध धारक”, किसी पजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें प्रयुक्त अर्थमें वह व्यक्ति होगा जिसका पजीयन उसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

उपनिवेशके सब वैध अधिवासी एशियाइयोका पजीयन आवश्यक

- ३ (१) इसके बाद दिये गये अपवादोको छोड़कर प्रत्येक एशियाई जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी है एशियाई पजिकामें पजीकृत होगा और उसके आधारपर पजीयन प्रमाणपत्र पानेका अधिकारी होगा एवं उससे इस अधिनियमके खण्ड बारहमें फी गई व्यवस्थाके अतिरिक्त इस पजीयनका या पजीयन प्रमाणपत्रका कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (२) निम्न व्यक्ति इस अधिनियमकी उद्देश्यपूर्तिके लिए इस उपनिवेशके वैध एशियाई अधिवासी समझे जायेंगे,
 - (एक) कोई भी एशियाई जिसे १९०२ के क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत दिये गये परवानेके द्वारा इस उपनिवेशमें आने और रहनेका विधिवत् अधिकार दिया गया हो, या जिसने १ सितम्बर १९०० और कथित अध्यादेशके पास किये जानेकी तारीखके बीचमें परवाना लेकर बशर्ते कि वह परवाना बोलाथडीसे न लिया गया हो उक्त अधिकार प्राप्त किया हो, व्यवस्था की जाती है कि जिस परवानेमें किसी एशियाईको सीमित अवधि तक रहनेका निर्देश किया गया हो वह परवाना इस उपखण्डके अथके अन्तर्गत परवाना नहीं समझा जायेगा।
 - (दो) कोई भी एशियाई जो इस उपनिवेशमें रहता हो और ३१ मई १९०२को प्रत्यक्ष यहाँ मौजूद हो।
 - (तीन) ३१ मईके बाद उत्पन्न कोई भी एशियाई, जो इस उपनिवेशमें १९०४के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तर्गत लाये गये किसी श्रमिककी सन्तान न हो।

एशियाइयोको निश्चित समयके भीतर पजीयनका आवेदन देना आवश्यक

- ४ (१) प्रत्येक एशियाई जो इस उपनिवेशमें इस अधिनियमके लागू होनेके दिन रहता हो उस तारीख या उन तारीखोंसे पहले, उस स्थान या उन स्थानोंमें और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियोंके सम्मुख जिसका या जिनका निदेश उपनिवेश सचिव गजट में सूचना निकाल कर करे पजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देगा।
- (२) प्रत्येक एशियाई, जो इस उपनिवेशमें इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद प्रविष्ट हो और जो इस अधिनियमके अन्तर्गत पहले पजीकृत न हुआ हो इस उपनिवेशमें प्रवेश करनेपर आठ दिनोंके भीतर निर्धारित व्यक्तिको और निर्धारित स्थानपर पजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दे, बशर्ते कि वह खण्ड सत्रहके अन्तर्गत दिये गये परवानेके अनुसार प्रविष्ट न हुआ हो।
व्यवस्था की जाती है कि
 - (क) जिस तारीख तक पजीयनका प्रार्थनापत्र दिया जाना है उसकी समाप्तिपर किसी एशियाई बच्चेकी आयु आठ वर्षसे कम हो तो इस खण्डके अन्तर्गत उसके लिए पजीयन प्रार्थनापत्र देनेकी आवश्यकता नहीं होगी,
 - (ख) उस एशियाई बच्चेके मामलेमें, जो इस अवधि की समाप्तिपर आठ वर्षका हो, किन्तु सोलह वर्षसे कम आयुका हो ऐसा प्रार्थनापत्र उम बच्चेकी ओरसे उसका सरक्षक देगा, और यदि इस प्रकार प्रार्थनापत्र न दिया जाये तो सोलह वर्षकी आयु पूरी होनेके बाद एक महीनेके भीतर उस बच्चेको स्वयं देना होगा।

पजीयक मजूर करेगा तो प्रार्थियोंको पजीकृत करेगा और नामजूर करनेकी हालतमें नोटिस देगा

- ५ (१) पजीयक इससे पिछले खण्डके अन्तर्गत पजीयनके प्रत्येक प्रार्थनापत्रपर विचार करेगा और प्रत्येक प्रार्थीको जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी हो या जिनका प्रार्थनापत्र उसने मजूर किया हो पजीकृत करेगा और ऐसे प्रार्थीको या सरक्षकको जिसने उसकी ओरसे प्रार्थनापत्र दिया हो पजीयन प्रमाणपत्र जारी करायेगा।

- (२) यदि पजीयकको यह प्रतीत हो कि कोई प्रार्थी इस उपनिवेशका वैध अधिवासी नहीं है तो वह उसको पजीकृत करनेसे इनकार कर सकता है, और इनकारकी हालतमें, प्रार्थीकी आयु सोलह सालकी या ज्यादा होनेपर उसको प्रार्थनापत्रपर दिये गये पतेसे डाक द्वारा इनकारकी सूचना भिजवायेगा, और इस सूचनाकी एक प्रतिलिपि जिस जिलेमें वह प्रार्थनापत्र दिया गया था उस जिलेके 'यायाधीशके कार्यालयके मुख्य द्वारपर चिपका दी जायेगी, और पजीयक इस सूचना द्वारा प्रार्थीको जिलेके आवासी 'यायाधीशके सम्मुख उसमें निर्धारित किये गये समयपर, जो इस सूचनाकी तारीखसे कमसे कम चौदह दिन बाद होगा उपस्थित होने और यह बतानेका निर्देश देगा कि उसको उस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा क्यों न दी जाये, और यदि प्रार्थी उस सूचनामें दिये गये समयपर उपस्थित न हो या उपस्थित होनेपर आवासी 'यायाधीशको यह सन्तोष न दिला सके कि प्रार्थी उपनिवेशका वैध अधिवासी है तो आवासी 'यायाधीश यदि प्रार्थी सोलह साल या उससे अधिक आयुका हो, लिखित आज्ञा देकर उसे निर्दिष्ट अवधिके अन्दर उपनिवेशसे चले जानेका आदेश देगा। यह व्यवस्था सदा रहेगी कि यदि यह आदेश प्रार्थीको अनुपस्थितिमें दिया जाये तो अवधिका आरम्भ उसको आदेश मिलनेकी तारीखसे होगा और यह आज्ञा १९०३ के शांति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत दी गई समझी जायेगी और इस अध्यादेशके खण्ड सात और आठ भी इसी प्रकार लागू होंगे। यह व्यवस्था भी की जाती है कि यदि आवासी 'यायाधीशको प्रार्थीके उपनिवेशका वैध अधिवासी होनेका विश्वास हो जायेगा तो वह पजीयकको प्रार्थीका पजीयन करने और उसे पजीयन प्रमाणपत्र देनेका आदेश दे देगा।

सरक्षकको द्वारा विवरण देने और प्रार्थनापत्र भेजनेकी व्यवस्था

- ६ (१) कोई भी एशियाई जो आठ वर्षसे कम आयुके किसी एशियाई बच्चेका सरक्षक हो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देनेपर नियमके अनुसार बच्चेका विवरण और शिनाख्तके निशान देगा, और यदि सरक्षक स्वयं पजीकृत है तो उसके द्वारा दिया गया पूर्वकथित विवरण अस्थायी रूपसे पत्रिकामें दर्ज कर लिया जायेगा और सरक्षक बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर अपने निवासके जिलेके आवासी 'यायाधीशके कार्यालयमें उस बच्चेकी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देगा,
- (२) इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद उपनिवेशमें पैदा हुए प्रत्येक एशियाई बच्चेका सरक्षक, बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर, उसकी ओरसे अपने निवासके जिलेके आवासी 'यायाधीशके कार्यालयमें पजीयनका प्रार्थनापत्र देगा,

व्यवस्था की जाती है कि

- (क) जहाँ कोई सरक्षक किसी एशियाई बच्चेकी ओरसे, जिसका वह सरक्षक है, इसके द्वारा निर्धारित समयके भीतर पजीयनका प्रार्थनापत्र नहीं देता, वहाँ वह सरक्षक पजीयक या किसी आवासी 'यायाधीश द्वारा मॉगे जानेपर किसी बादकी तारीखमें यह प्रार्थनापत्र देगा,
- (ख) जब कोई प्रार्थनापत्र, जो इस खण्डके अन्तर्गत एक एशियाई बच्चेके सरक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है, या जब ऐसा प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तब पजीयनका प्रार्थनापत्र ऐसे एशियाई बच्चेको सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद एक मासके भीतर अपने निवासके जिलेमें आवासी 'यायाधीशके कार्यालयमें देना चाहिए।

वह आवासी 'यायाधीश, जिसके कार्यालयमें इस खण्डके अन्तर्गत कोई प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उस प्रार्थनापत्रके कागजात और उससे सम्बन्धित सब दस्तावेज पजीयकको भिजवा देगा, जो उसके नियमानुसृत होनेके सम्बन्धमें सन्तोष कर लेनेपर प्रार्थीका पजीयन कर देगा, और उसको या उसके संरक्षकको पजीयन प्रमाणपत्र जारी करा देगा।

जिन एशियाईयोके सरक्षक विवरण नही दे सके है उनके द्वारा सोलह वर्षकी आयु होनेपर प्रार्थनापत्र

७ जब सरक्षक द्वारा विवरण न देनेके कारण किसी एशियाई बच्चेके सम्बन्धमें, जो आठ वर्षसे कम आयुका है, ऐसा विवरण जिसका विधान पिछले खण्डमें किया गया है, पंजिकामें अस्थायी रूपसे दर्ज न किया गया हो तो भी पंजीयनका प्रार्थनापत्र बच्चेकी ओरसे सरक्षक द्वारा ही उस बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर दे दिया जाना चाहिए, और यदि यह न दिया जाये तो वह उस एशियाई बच्चेको सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद एक मासके भीतर अपने निवासके जिलेके आवासो यायाधीशके कार्यालयमें स्वयं देना चाहिए, उस प्रार्थनापत्रके कागजात और उससे सम्बन्धित सब दस्तावेज पंजीयकको भिजवा दिये जायगे जो अपने विवेकाधिकारके अनुसार प्रार्थना पंजीयनका निर्णय करेगा और उसको या उसके सरक्षकता पंजीयन प्रमाणपत्र देगा।

प्रार्थनापत्र न देनेपर दण्ड

- ८ (१) जो व्यक्ति किसी एशियाई बच्चेके बारेमें अपनी ओरसे या उस बच्चेके सरक्षकके रूपमें इस अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र न देगा, वह अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकसे अधिक सौ पौंड जुर्माना और जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक तीन मासके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा।
- (२) जो व्यक्ति इस उपनिवेशमें सोलह वर्षसे कम आयुके ऐसे एशियाई बच्चेको लायेगा जो यहाँका वैध निवासी न हो और जो ऐसे बच्चेको किसी व्यापार या व्यवसायमें नियुक्त करेगा, वह अपराधी होगा और अपराध सिद्ध होनेपर नीचे लिखे दण्डोका पात्र ठहरेगा
 - (क) इस खण्डके उपखण्ड (१) में बताये गये दण्डोका, और
 - (ख) यदि ऐसे व्यक्तिको पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त हो तो पंजीयक उसके पंजीयनको रद्द कर सकेगा, इसपर उपनिवेश सचिव उसको उपनिवेशसे चले जानेका आदेश दे सकता है। ऐसी आज्ञा सन् १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत जारी की गई आज्ञा समझी जायेगी और तदनुसार उक्त अध्यादेशके खण्ड सात और आठ लागू होंगे।
- (३) सोलह वर्षसे अधिक आयुका कोई भी एशियाई, जो उपनिवेश सचिव द्वारा 'गज़ट' में घोषित की गई तारीखके बाद उपनिवेशमें पाया जाये और आगे बताई गई माँग करनेपर अपना पंजीयन प्रमाणपत्र जिसका वह वैध अधिकारी हो, प्रस्तुत न कर सके, बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और आवासी न्यायाधीशके सम्मुख पेश किया जा सकता है एवं यदि वह उस न्यायाधीशको यह सन्तोष करानेमें असमर्थ रहे कि वह पंजीयन प्रमाणपत्रका वैध धारक है और जिस अवधिके भीतर उसको ऐसे प्रमाणपत्रके लिए प्रार्थनापत्र देना है, वह समाप्त नहीं हुई है, तो न्यायाधीश यदि अगले उपखण्डकी स्थिति लागू न होती हो तो उसको लिखित आज्ञा देकर उसमें दिये गये समयके भीतर उपनिवेशसे चले जानेका निर्देश करेगा और वह आज्ञा शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत दी गई आज्ञा समझी जायेगी और तदनुसार उक्त अध्यादेशके खण्ड सात और आठ लागू होंगे।
- (४) यदि कोई एशियाई इस अधिनियममें दिये समयके भीतर पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेमें असमर्थ रहा हो और यदि वह न्यायाधीशके सम्मुख प्रस्तुत किया जानेपर उसको यह सन्तोष दिला सके कि उसकी इस असमर्थताका कोई न कोई सन्तोषजनक और पर्याप्त कारण था तो न्यायाधीश पहले बताई गई आज्ञा देनेके बजाय ऐसे एशियाईको तुरन्त पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेका निर्देश कर सकता है, और यदि ऐसा एशियाई उस निर्देशका पालन करेगा तो उसका प्रार्थनापत्र सब बातोंमें वैसा ही माना जायेगा मानो वह अधिनियममें दी गई अवधिके भीतर ही दिया गया हो, और इस अधिनियमकी सब धाराएँ वैसे ही लागू होंगी, जैसे प्रार्थनापत्र देनेपर लागू होती। किन्तु यदि वह ऐसे निर्देशका पालन करनेमें असमर्थ रहेगा तो न्यायाधीश उसके निष्कासनकी आज्ञा दे देगा जिसका उल्लेख ऐसे एशियाईके सम्बन्धमें पहले किया जा चुका है।

पजीयन प्रमाणपत्र मागनेपर पेश किया जाये

९ सोलह वर्ष या उससे अधिक आयुका प्रत्येक एशियाई, जो इस उपनिवेशमें प्रवेश करता या रहता है, उपनिवेशके कानून द्वारा स्थापित पुलिस दलके किसी भी सदस्य या उपनिवेश सचिव द्वारा अधिकार प्रदत्त किसी दूसरे व्यक्तिकी मौगपर अपना पजीयन प्रमाणपत्र जिसका वह वैध धारक है, दिखायेगा और वैसे ही मौगनेपर विनियममें बताये गये विवरण और शिनास्तके निशान देगा।

सोलह वर्षसे कम आयुके प्रत्येक एशियाई बच्चेका सरक्षक पहले कहे गये अनुसार मौग करनेपर पजीयन प्रमाणपत्र, जिसका वह बच्चा वैध धारक है प्रस्तुत करेगा और उस अधिनियमके अनुसार या ऐसे बच्चेके सम्बन्धमें बनाये गये नियमके अनुसार आवश्यक विवरण और शिनास्तके निशान देगा।

पजीयन प्रमाणपत्रोंके प्रमाण

१० प्रत्येक पजीयन प्रमाणपत्र सर्वत्र इस बातका निर्णयात्मक प्रमाण माना जायेगा कि उसका वैध धारक १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशमें आई किसी बातके बावजूद इस उपनिवेशमें आने और रहनेका हकदार है, सदा व्यवस्था यह रहेगी कि यह खण्ड उन लोगोपर लागू न होगा जिनको १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड दसके अन्तर्गत उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जा चुकी हो।

खोये हुए पजीयन प्रमाणपत्र पानेवालेका कर्तव्य

११ जिस व्यक्तिको कोई पजीयन प्रमाणपत्र या अथ कोई अनुमतिपत्र मिले, जो खण्ड सत्रह के अन्तर्गत निकाला गया हो और जिसका वह वैध धारक न हो वह उसको यथासम्भव शीघ्र एशियाई पजीयक, प्रिटोरियाको दे देगा या ढाकसे पहुँचा देगा।

जो व्यक्ति इस खण्डके अनुसार कार्रवाई करनेमें अमर्त्य रहेगा, वह अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकतम पचास पाँड जुमाने या जुर्माना न देनेपर अधिकतम एक मासके सदे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा।

पजीयन प्रमाणपत्र खोने या नष्ट होनेपर व्यवस्था

१२ यदि कभी किसीका पजीयन प्रमाणपत्र खो जाये या नष्ट हो जाय तो उसके वैध धारकको तुरन्त उसे नया करनेके लिए पजीयकको प्राथनापत्र देना चाहिए और पजीयक, ऐसे व्यक्ति द्वारा पजीयन प्रमाणपत्रोंको नये करनेके प्राथनापत्रोंसे सम्बन्धित नियमोंकी पूर्ति की जानेपर, और पाँच शिल्लिंग शुल्क दिया जानेपर, उस प्रमाणपत्रको नया कर देगा। उक्त शुल्क प्राथनापत्रपर राजस्व टिकट लगाकर दिखाया जायेगा। और उस टिकटपर उस प्राथनापत्रको छेनेवाला अधिकारी मुहर लगा देगा।

एशियाइयोंको प्रमाणपत्र पेश करनेपर व्यापारिक परवाने दिये जायेंगे, अन्यथा नहीं

१३ उपनिवेश सचिव द्वारा 'गजट' में घोषित की गई तारीखके बाद किसी एशियाईको १९०६ के माल परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधन या नगरपालिकामें लागू किसी उपनियमके अन्तर्गत व्यापारिक परवाना तबतक न दिया जायेगा, जबतक वह उस परवानेको देनेके लिए नियुक्त व्यक्तिके सामने अपना वैध पजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करेगा और नियममें बताये गये विवरण और शिनास्तके निशान न देगा।

एशियाईकी आयुका प्रमाण

१४ जब कभी इस अधिनियमके अन्तर्गत किसी मुकदममें या किसी कारवाईमें किसी एशियाईकी आयुका प्रश्न उठे, तब वह एशियाई, जबतक उसकी आयु अथवा सिद्ध न कर दो जाये तबतक, उसी आयुका माना जायेगा जिसे पजीयकने अपने द्वारा दिये गये किसी प्रमाणपत्रमें अपने मतसे उसकी प्रत्यक्ष आयु प्रमाणित की हो।

शपथपत्र या शपथपूर्वक की गई घोषणा विनियम द्वारा स्टाम्प-करसे मुक्त

१५ विनियमके अन्तर्गत किसी व्यक्तिको, जो अपनी ओरसे या किसी अन्य व्यक्तिकी ओरसे पजीयन प्रमाणपत्रका प्राथनापत्र देता है, कोई शपथपत्र देना हो या शपथपूर्वक घोषणा करनी हो तो वे स्टाम्प-करसे मुक्त होंगे।

पजीयनके प्रार्थनापत्रो और पजीयन प्रमाणपत्रोसे सम्बन्धित अपराध

१६ कोई भी व्यक्ति जो

- (१) पजीयनके प्रार्थनापत्रके उद्देश्यसे या उसके सम्बन्ध धर्म या पजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके उद्देश्यसे कोई जालसाजीका काम करता है या कोई झूठा बयान देता है या कोई झूठा बहाना करता है या किसी व्यक्तिको ऐसे काम या बयान या बहानेके लिए उत्तेजित करता सहायता देता या प्रेरित करता है,
- (२) कोई जाली पजीयन प्रमाणपत्र बनाता है,
- (३) किसी पजीयन प्रमाणपत्रको, जिसका वह वैध धारक नहीं है या किसी जाली पजीयन प्रमाणपत्रको अपने प्रमाणपत्रके रूपमें काममें लाता या काममें लानेका प्रयत्न करता है,
- (४) किसी व्यक्तिको उस पजीयन प्रमाणपत्रको जिसका वह वैध धारक नहीं है या किसी जाली पजीयन प्रमाणपत्रको अपने प्रमाणपत्रके रूपमें काममें लानेके लिए उत्तेजित करता सहायता देता और प्रेरित करता है, अधिकसे अधिक पाँच सौ पौंड जुर्माने या जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक दो वर्षके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका या जुर्माने और कारावास दोनों दण्डोंका पात्र होगा ।

उपनिवेशमें एशियाईको सीमित काल तक रहनेके परवाने देनेका अधिकार

- १७ (१) मन् १९०३ के शांति रक्षा अध्यादेशके किसी भी विधानके बावजूद उपनिवेशमें प्रवेशका परवाना देना न देना पूर्ण तरह उपनिवेश सचिवके निणयपर छोड़ दिया गया है, वह विनियमों द्वारा बताये गये रूपमें दिया जा सकता है एवं उसके द्वारा किसी एशियाईको उपनिवेशमें प्रवेश करने और परवानेमें बताई गई अवधिकत निवास करनेका अधिकार होगा । इस अवधिकी समाप्तिपर यह माना जायेगा कि जिस व्यक्तिको उस परवानेके द्वारा उपनिवेशमें प्रवेशका अधिकार दिया गया है अब उपनिवेशमें रहनेका उचित अधिकारी नहीं है और यदि वह उसमें रहता हुआ मिलेगा तो बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जायेगा और उक्त अध्यादेशके खण्ड सात और आठका विधान उस व्यक्तिपर ऐसे लागू होगा, मानो उसको निदिष्ट अवधि बीत जानेपर उक्त अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी गई हो और वह उस आज्ञाका पालन करनेमें असमर्थ रहा हो ।
- (२) उक्त अध्यादेशके खण्ड नौका विधान इस खण्डके अन्तर्गत दिये गये सब परवानोंपर लागू होगा ।
- (३) इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखसे पहले किसी एशियाईको क्षतिपूर्ति और शांति रक्षा अध्यादेश १९०२ या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत जो परवाना दिया गया हो और जिसमें उसे उपनिवेशमें केवल एक सीमित समयतक रहनेका अधिकार बताया गया हो वह इस खण्डके अन्तर्गत दिया गया परवाना समझा जायेगा ।
- (४) उपनिवेश सचिव अपने निर्णयसे आज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति जिसे इस खण्डके अन्तर्गत दिये गये परवानेसे उपनिवेशमें प्रवेश और निवासका अधिकार मिला हो उस परवानेकी अवधिमें मध्य परवाना अध्यादेश १९०२ या उसके संशोधनके प्रयोजनके लिए रगदार व्यक्ति नहीं समझा जायेगा और ऐसी आज्ञा ऐसे परवानेपर दर्ज की जायेगी और वह ऐसे प्रयोजनोंके लिए पूरी तरह लागू होगी ।
- (५) उपनिवेश सचिव ऐसी आज्ञा जैसी पिछले उपखण्डमें बताई गई है, ऐसे किसी भी व्यक्तिके सम्बन्धमें निकाल सकता है जो एशियाई प्रजातिका हो और जो इस अधिनियमकी धाराओंके अन्तर्गत न आता हो ।

विनियम बनानेका अधिकार

१८ सपरिवर्द्ध गवर्नर नीचे दिये गये किसी भी प्रयोजनके लिए समय समयपर विनियम बना सकता है उनमें परिवर्तन कर सकता है और उनको रद्द कर सकता है

- (१) इस अधिनियमक अतर्गत रखी जानेवाली पत्रिकाका रूप निर्देश करनेके लिए,
- (२) पजीयनके लिए जो प्राथनापत्र दिया जायेगा उसकी विधि और उसका रूप और किसी प्रार्थी या प्रार्थिके सरक्षक द्वारा ऐसे प्राथनापत्रके उद्देश्यसे या उसके सम्बन्धमें जो विवरण या शिनारतके निशान दिये जायेंगे उनका निश्चय करनेके लिए,
- (३) पजीयन प्रमाणपत्रका रूप निर्देश करनेके लिए,
- (४) यह निर्धारित करनेके लिए कि निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने विवरण और शिनास्तक चिह्न कैसे दिये जायेंगे,
 - (क) इस अधिनियमके खण्ड छ के अन्तर्गत आठ वर्षसे कम आयुके एशियाई बच्चेके सरक्षक द्वारा,
 - (ख) इस अधिनियमके खण्ड नौमें उल्लिखित मोंगपर किसी एशियाई द्वारा,
 - (ग) किसी एशियाई द्वारा जिसने अपने ग्योरे हुए या नष्ट हुए पजीयन प्रमाणपत्रको नया करनेके लिए प्रार्थनापत्र दिया हो,
 - (घ) किसी एशियाई द्वारा जिसने यापारिक परवानके लिए प्राथनापत्र दिया हो,
- (५) इस अधिनियमके खण्ड सत्रहके अन्तर्गत दिये जानेवाले परवानेका रूप निश्चित करनेके लिए ।

सामान्य दण्ड

१९ कोइ भी एशियाई या किसी एशियाईका सरक्षक जो इस अधिनियमकी किसी शर्तको पूरा करनेमें असमर्थ रहा हो जहाँ अथ विधान है उसके परे अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकतम सौ पौंड जुमानेके या जुर्माना न देनेपर अधिकतम तीन मासके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा ।

कुछ सेवा सम्बन्धी शर्तनामोंके अन्तर्गत आये हुए

एशियाइयोंके सम्बन्धमें व्यवस्था

२० सन् १९०४ के श्रम आयात अध्यादेशमें जो बात दी गई है उनके बावजूद ऐसे किसी भी एशियाइको जिसके पास वैध पजीयन प्रमाणपत्र है और जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी है एवं जिसे उक्त अध्यादेशकी तारीखसे पहले उचित परवानेके अनुसार प्रवेशका अनुमति दी गई है इसलिए उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहने या उसमें लाये जानेसे न रोका जायेगा कि वह सेवा सम्बन्धी शर्तनामोंके अन्तर्गत वहाँ है और उसने उक्त अध्यादेशके खण्ड आठमें उल्लिखित शर्तनामा नहीं किया है ।

अचल सम्पत्तिके स्वामित्वके सम्बन्धमें व्यवस्था

२१ ससदके १२ अगस्त १८८६ के प्रस्तावकी वारा १४१९ द्वारा सशोधित रूपमें १८८५ के कानून ३ की धारा दोके (ख) उपखण्डमें टी गई किसी भी बातके बावजूद इस उपनिवेशमें किसी एशियाईने उस कानूनके लागू होनेसे पहले जो भी अचल सम्पत्ति ले ली है और जिसका पजीयन उस कानूनके लागू होनेके पहले या पीछे उस एशियाइके नाम हो चुका है वह सम्पत्ति उस एशियाई द्वारा दूसरे एशियाइको वसीयतनामसे या अन्य उत्तराधिकारके रूपमें हस्तान्तरित की जा सकता है ।

नाम और लागू होनेकी तारीख

२२ यह अधिनियम सब प्रयोजनोंके लिए एशियाई कानून सशोधन अधिनियम १९०७ कहा जा सकता है और यह तबतक लागू न होगा जबतक गवर्नर गजट में यह घोषणा न करें कि महामहिम सम्राट् इसको अस्वीकृत करना नहीं चाहते, और उसके बाद यह उस तारीखको जिसको गवर्नर घोषणा द्वारा सूचित करेंगे लागू हो जायेगा ।

शान्ति-रक्षा अध्यादेश

उक्त अधिनियममें १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेश सख्या १ के जिन खण्डोंका उल्लेख है वे निम्न हैं
गिरफ्तार लोपोपर यायाधीशके सम्मुख मुकदमा

६ प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकार गिरफ्तार किया जायेगा, जितनी जल्दी हो सके, एक यायाधीशके सम्मुख पेश किया जायेगा और यदि वह न्यायाधीशको सन्तोष न दिला सकेगा कि इस यायादेशकी धाराओंके अन्तर्गत उसको इस उपनिवेशमें प्रवेश करने और रहनेका उचित अधिकार है, तो यायाधीश उसको लिखित आज्ञा देकर उतने समयमें जिसका उल्लेख उस आज्ञामें होगा, उपनिवेशसे चले जानेका आदेश दे सकता है। यह व्यवस्था की जाती है कि यदि ऐसा व्यक्ति परवाना ले चुकनेका शपथपूर्वक बोधना करता है और उसको पेश करनेमें असमर्थताका सन्तोषजनक कारण देता है, या वह शपथपूर्वक यह कहता है कि वह सन्तोषजनक प्रमाण दे सकता है कि वह उन वर्गोंका है जो इस कानूनके खण्ड दोका व्यवस्थाके द्वारा परवाना लेनेकी शर्तसे मुक्त हैं तो वह मानती या गैरजमानती मुचलका देनेके बाद छोड़ा जा सकता है वह किसी भी न्यायाधीशके सामने जिसका उल्लेख मुचलकेमें किया गया हो, और उसमें बताये गये समयमें ऐसा परवाना या सबूत जो भी हो, पेश करेगा। यदि वह व्यक्ति अपने मुचलकेकी शर्तोंको पूरा करनेमें असमर्थ रहेगा तो उसका मुचलका जप्त कर लिया जायेगा।

उपनिवेशसे जानेकी आज्ञाका पालन न करनेपर दण्ड

७ उस व्यक्तिको जिसे उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जाये और जा आज्ञापत्रमें दिये गये समयके भीतर न जाये और उस व्यक्तिको, जिसका मुचलका पिछले खण्डकी व्यवस्थाके अनुसार जप्त कर लिया गया हो बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और यायाधीशके सामने पेश किया जा सकता है, एवं उसका अपराध सिद्ध होनेपर कमसे कम एक मासकी और अधिकसे अधिक छ मासकी सजा या सख्त कैदकी सजा जुर्मानेके बिना या जुर्मानेके साथ जो ५०० पौण्डे अधिक न होगा, दी जा सकती है एवं जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक छ महीनेकी अतिरिक्त कैदकी सजा दी जा सकती है।

उपनिवेशमें रहनेपर अतिरिक्त दण्ड

८ यदि कोई व्यक्ति जो पिछले खण्डके अन्तर्गत कैदकी सजा पाता है, अपनी कैदकी या उसके बाद इस खण्डके अन्तर्गत दी गई कैदकी मियाद पूरी होनेके बाद उपनिवेश सचिवसे उपनिवेशमें रहनेकी लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना सात दिनसे अधिक समय तक रहता है—और लिखित इजाजत प्राप्त कर ली है, यह सिद्ध करनेका भार उसपर ही होगा—उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और यायाधीशके सामने पेश किया जा सकता है, एवं अपराध सिद्ध होनेपर उसको कमसे कम छ मासकी और अधिकसे अधिक बारह मासकी कैद, जुर्मानेके बिना या जुर्मानेके साथ जो पाँच सौ पौण्डे अधिक न होगा, दी जा सकती है, एवं जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक छ महीनेकी अतिरिक्त कैदकी सजा दी जा सकती है।

जाली परवाने

९ कोई व्यक्ति जो

- (१) किसी धोखाधड़ी, गलतबयानी, झूठे बहाने, झूठ, या किसी दूसरे अनुचित साधनसे, परवाना प्राप्त करता है, प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है या किसी व्यक्तिको उसे प्राप्त करनेके लिए उत्तेजित करता है, या प्राप्त करनेमें सहायता या सहमति देता है,
- (२) ऐसे प्राप्त किये गये किसी परवानेका प्रयोग करता या प्रयोग करनेका प्रयत्न करता है, या किसी व्यक्तिको प्रयोग करनेके लिए उत्तेजित करता है या प्रयोग करनेमें सहायता या सहमति देता है।
- (३) ऐसे प्राप्त किये गये परवानेसे या उचित अधिकारी द्वारा न दिये गये परवानेसे इस उपनिवेशमें प्रवेश करता या प्रवेश करनेका प्रयत्न करता है उसको जुर्मानेकी, जो पाँच सौ पौण्डे अधिक न होगा

या सादी या सग्त कैदकी जा दा सालसे ज्यादा न होगी, या जुमाने और कैद दोनोकी मजा दी जा सकेगी ।

शांति और सुशासनके लिए खतरनाक व्यक्ति

१० अगर लेफ्टिनेंट गवर्नरको यह विश्वास हो जाये कि किसी व्यक्तिको उपनिवेशको शांति और सुशासनके लिए खतरनाक माननेके लिए पर्याप्त कारण मौजूद ह, तो उसके लिए उस व्यक्तिको उपनिवेश सचिवके हस्ताक्षरोसे यह आज्ञा देना वैध होगा कि वह उपनिवेश छोड़कर चला जाये । उस व्यक्तिको उस आज्ञाके मिलनेके बाद उस समयके भीतर, जिसका उल्लेख आज्ञामें किया जायेगा, चला जाना होगा । यदि दिये गये समयको समाप्तिपर वह व्यक्ति उपनिवेशमें रहता हुआ मिलेगा तो उसके विरुद्ध इस अव्यवस्थाके एण्ट सात और आठमें बताई गई विधिते कारवाही की जायेगी और उसको व सजाए दी जा सकेगी जिनका विधान उन एण्डोमें है ।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

परिशिष्ट २

प्राथनापत्र चीनी राजदूतको

जोहानिसबर्ग,

अक्टूबर १४, १९०७

सेवामें

परमश्रेष्ठ राजप्रतिनिधि असाधारण

और पूर्ण अधिकार-सम्पन्न मंत्री राजदूत

महामहिम चीन सम्राट

लन्दन

ट्रान्सवालके चीनी सवके अध्यक्षकी हैसियतसे श्री लिअग किन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र सचिनय निवदन है कि

१ आपका प्रार्थी उन चीनी सवका अध्यक्ष है जो ट्रान्सवालको स्वतंत्र चीनी आवादीको प्रतिनिधित्व करनेके लिए चार वर्ष पूर्व जोहानिसबर्गमें स्थापित किया गया था ।

२ इस समय स्वतंत्र चीनी आवादी अनुभावन ११०० से ऊपर हैं । उनमेंसे अधिकांश जोहानिसबर्गमें बसे हैं ।

३ ट्रान्सवालमें रहनेवाले अधिकांश चीनी अच्छे स्थितिके दूकानदार हैं और सभी इस उपनिवेशके पुराने अधिवासी हैं ।

४ प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान एशियाई कानून सहायन अधिनियमकी ओर आकषित करता है । इसे ट्रान्सवाल विधान सभाने पास किया है । इसको प्रति सल्लय है ।

५ यह विधान पहले गत वर्षके अन्तिम भागमें पास हुआ था और ट्रान्सवालका चीनी समाज इसपर इतना क्षुब्ध हुआ था कि परमश्रेष्ठके पूर्वाधिकारीके समक्ष चीनी पक्ष रखनेके लिए उसके एक विशेष प्रतिनिधिको लन्दन भेजना ठीक समझा गया था, जिससे कि ब्रिटिश सरकारके सामने उचित रूपसे सब मामला पेश किया जाये । और आपके प्रार्थीको यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि परमश्रेष्ठके पूर्वाधिकारीके प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप महामहिम सम्राटने इस विधानको स्थगित कर दिया था ।

६ अब टान्सवालकी नव निर्वाचित ससदने इसे बड़ी जल्दीमें सर्वसम्मतिसे पुन पास कर दिया था ।

७ चीनी सचकी वित्त सम्पत्तिमें यह विधान हमारा प्राचीन सम्यताको और इस तथ्यको स्वीकार करनेमें सवथा असफल है कि हमारा राष्ट्र एक स्वतन्त्र और प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र है ।

८ यह चीनी प्रजाजनोंको उसी स्तरपर रख देता है जिसपर भारतसे आनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन हैं । जहाँ ब्रिटिश सरकारके लिए यह उचित हो सकता है कि वह अपने भारतीय प्रजाजनोंके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर वहाँ प्रार्थी सादर निवेदन करता है कि चीनी साम्राज्यके प्रजाजनोंके साथ ऐसे ढङ्का व्यवहार नहीं होना चाहिए जो उस साम्राज्यको शानके खिलाफ हो जिससे सम्बन्धित होनेका परमश्रेष्ठके प्रार्थीको सम्मान प्राप्त है और विशेषकर इस तथ्यको सामने रखते हुए कि चीन एक ऐसा राज्य है जिसकी ग्रेट ब्रिटेनसे मैत्री है और ग्रेट ब्रिटेनके प्रजाजनोंको चीनमें अतिप्रिय राष्ट्रका व्यवहार प्राप्त है ।

९ एशियाई अधिनियमका मश्रा है कि अन्योके बीच टान्सवालका प्रत्येक चीनी अधिवासी अपमान और भारी जुर्मानोका शिकार बने और उसके पास पहलेसे जो दस्तावेज है उनके स्थानपर नया पजीयन प्रमाणपत्र ले । यह चीनियोंको निरीक्षणकी एक ऐसी पद्धतिके अधीन करता है जो सर्वथा पतनकारा है । इसका मश्रा है कि माता पिता अपने १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोका भी पजीयन अत्यन्त अपमानजनक ढङ्गसे कराये । इसका मश्रा है कि बालिंग चीनी पुरुष और उनके बच्चे अपनी अंगुलियोंकी अठारह छापे दें । यह एक ऐसी मौँग है निम्नके लिए स्वाभाविक अपराधियोंके बारेमें हा जोर दिया जाता है । यह विधान इस धारणापर आगे बढ़ता है कि चीनियोंमेंसे बहुतेरे छलपूर्ण आवेदनपत्र देनेमें सिद्धहस्त हैं । चीनी सभ इससे सर्वथा इनकार करता है । यह चीनियोंको एक ऐसे स्तरपर गिरा देता है जा कि दक्षिण आफ्रिकाके वतनियों और दूसरे रगदार लोगोंसे भी नीचा है । संक्षेपमें यह एक ऐसा विधान है जिसे स्वतन्त्र मनुष्य नहीं केवल गुलाम ही स्वीकार कर सकते हैं ।

१० चीनी समाजका भाव ऊपर लिखे अनुसार होनेके कारण, इसने निश्चित किया है कि यह इस अधिनियमके सामने नहीं झुकगा और कानूनको इस प्रकार भंग करनेके जो भी परिणाम हो सकते हैं उनको यह सहन करेगा । समाजका समझमें इन कानूनोंके प्रति सत्याग्रह करनेसे उनका पूर्ण सामाजिक विनाश हो सकता है और प्रत्येक चीनी निर्वासित भी किया जा सकता है । समाजके ९०० से ऊपर सदस्योंने एक दृढ़ प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये हैं कि वे इस अपमानजनक कानूनको स्वीकार नहीं करेंगे ।

११ चीनी सभ स्वीकार करता है कि ट्रान्सवालमें प्रवास नियमित होना चाहिए और ट्रान्सवाल उपनिवेशमें नियम विरुद्ध प्रवेशको प्रभावशाली ढङ्गसे रोक होनी चाहिए । और स्थानीय सरकारको इस कार्यमें सहायता करनेके लिए चीनी समाजने स्वेच्छया पजीयन करानेका प्रस्ताव किया है केवल इसलिए कि चीनी समाजकी सत्यताकी परीक्षा हो जाये । इसके पीछे यह स्वीकार करनेकी भावना नहीं है कि ऐसा कोई पुन पजीयन आवश्यक है ।

१२ यदि स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता और ठोस सहायता नहीं दी जा सकती तो चीनी समाजकी रायमें ब्रिटिश सरकारको नारदार निवेदनपत्र भेजा जाना चाहिए कि प्रत्येक चीनी इस शतपर चान देशको वापस भेज दिया जाये कि उनके निहित अधिकारों जैसे व्यापार, निवास इत्यादिकी हानिके बदले उसे पूर्ण मुआवजा दिया जाये ।

१३ अतमें प्रार्थी सादर भरोसा करता है कि परमश्रेष्ठ द्वारा ट्रान्सवालमें रहनेवाले चीनी प्रजाजनोंके अधिकारोंकी पूर्ण रूपसे रक्षा होगी और न्याय तथा श्वाक इस कार्यके लिए प्रार्थी कर्तव्याधीन होकर सदा दुआ करेगा ।

[आपका, आदि,]

लिअग क्विन

अध्यक्ष

ट्रान्सवाल चीनी सभ

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

परिशिष्ट ३

ट्रांसवाल प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक

नीचे एक विधेयकका मसविदा दिया जाता है जो ट्रांसवालके 'गवर्नमेंट गज़ट' में प्रकाशित किया गया है। यह "इस उपनिवेशमें प्रवासपर प्रतिबन्ध लगाने, इससे निषिद्ध प्रवासियोंको और अन्य लोगोंको निकालनेकी व्यवस्था करने और एक एशियाई विभाग स्थापित करने और चलानेके लिए है।

महामहिम सम्राट द्वारा और ट्रांसवालकी विधान परिषद और विधान सभाकी सलाह और अनुमतिसे निम्न विधान बनाया जाता है

१ १९०३ का शान्ति रक्षा अ यादेश इसके द्वारा रद किया जायेगा और रद किया जाता है, शर्त यह है कि इस कारवाईसे १९०७ के एशियाई कानूनकी कोई सत्ता या कानूनी अधिकार क्षेत्र जो उस कानूनको अमलमें लानेके उद्देश्यसे दिया गया हो, प्रभावित या कम न होगा।

- २ इस अधिनियममें या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियममें, जबतक संदर्भसे असगत न हो,
- विभाग" का अर्थ होगा इस अधिनियमकी धाराओंके अन्तर्गत स्थापित और कायम प्रवासी विभाग,
- "गवर्नर" का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो उस समय इस उपनिवेशका शासन चला रहा हो और कार्यकारिणी परिषदकी सलाहसे कार्य कर रहा हो,
- 'कैद' का अर्थ होगा कड़ी या सारी कैद जो अपराधीको क़ेदकी सजा देनेवाले यायालय द्वारा दी जाये,
- 'यायाधीश' शब्दमें उपनिवेशके किसी भी जिलेका आवासी न्यायाधीश और सहायक आवासी यायाधीश भी सम्मिलित होंगा,
- "मन्त्री" का अर्थ होगा उपनिवेश सचिव या ऐसा कोई अन्य मन्त्री जिसे गवर्नर समय समयपर इस अधिनियमपर अमल करानेका काम सौंपे,
- "अवयस्क" का अर्थ होगा सोलह वर्षसे कम आयुका कोई व्यक्ति,
- "पुलिस अधिकारी" का अर्थ होगा उपनिवेशमें वैध रूपसे स्थापित पुलिस दलका कोई भी सदस्य,
- 'निषिद्ध प्रवासी' का अर्थ होगा और उसके अतगत सम्मिलित होगा, निम्न वर्गोंका ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद उपनिवेशमें प्रवेश करना चाहता हो, या प्रवेश कर रहा हो

३ कोई भी व्यक्ति जो उचित रूपसे अधिकृत अधिकारी द्वारा इस उपनिवेशमें भी इसके बाहर निर्देश देनेपर अपर्याप्त शिक्षाके कारण इस उपनिवेशमें प्रवेशको अनुमतिके लिए किसी यूरोपीय भाषामें आवेदनपत्र या कोई अन्य कागज जिसे उक्त अधिकारी लिखाना चाहे न लिख सके या उसपर हस्ताक्षर न कर सके, विधान किया जाता है कि इस उपखण्डके प्रयोजनोंसे यीडिश यूरोपीय भाषा मानी जायेगी, यह भी विधान किया जाता है कि,

- (क) यदि मन्त्री 'गज़ट' में यह नोटिस प्रकाशित करे कि किसी देशकी सरकारसे उसके प्रजाजनों या नागरिकोंके इस उपनिवेशमें प्रवेशको नियमित करनेके सम्बन्धमें व्यवस्था की जा चुकी है, तो उन प्रजाजनों या नागरिकोंको जबतक वह नोटिस जारी रहे तबतक इस उपखण्डकी धाराओंका पालन करनेकी आवश्यकता न होगी,
- (ख) मन्त्री ऐसा नोटिस तबतक न निकालेगा जबतक ऐसी व्यवस्था संसदके दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत न कर ली जाये
- (ग) ऐसा नोटिस तभी अमलके बाहर हो जायेगा जब मन्त्री 'गज़ट' में दूसरा नोटिस निकाल कर उसे रद कर दे,

- (२) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास या जिसके अधीन इस उपनिवेशमें उचित समय तक अपना निर्वाह करनेके साधन न हो, या जिसे उपनिवेशमें आने दिया जाये तो जिसका खर्च सरकारपर पढ़नेकी सम्भावना हो,
- (३) कोई भी वेश्या या ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति की कमाईसे या अनैतिक कार्योंके लिए स्त्रियाँ उपलब्ध करके अपना गुजारा करता हो या कराता हो ।
- (४) कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें अपने प्रवेशकी या प्रवेशके प्रयत्नकी तारीखको लागू किसी कानूनके अन्तर्गत यदि उपनिवेशमें मिले तो, उपनिवेशसे निष्कासित किया जा सके या जिसे उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जा सके, फिर चाहे उसे उम्र कानूनके विरुद्ध अपराध करनेपर सजा दी जाये या उसकी धाराओका पालन न करनेपर या अथवा, बशर्ते कि उसको वह सजा उसके द्वारा इस उपनिवेशके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किये गये अपराधपर जिसके लिए वह क्षमा पा चुका है न दी गई हो,
- (५) कोई व्यक्ति जो १९०२ के उम्रद घोषणा [अधिनियम] या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत पागल हो,
- (६) कोई व्यक्ति जो कोढ़ी हो, या किसी घृणित या खतरनाक रूतकी या उड़ा बीमारीसे, जिसको विनियम द्वारा समय समयपर बताया जाये, पीड़ित हो,
- (७) कोई व्यक्ति, जिसे मंत्री किसी भी राज्य सचिवसे या किसी (ब्रिटिश या विदेशी) उपनिवेशी सरकारके सदस्यसे या किसी दूसरे देशके अधिकारीसे कूटनीतिक सूत्र द्वारा प्राप्त सूचनाके कारण अवाञ्छनीय समझता हो,
- (८) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्धमें मंत्रीका उचित आधारपर विश्वास हो कि वह यदि उपनिवेशमें प्रविष्ट होगा तो वह उसकी शान्ति व्यवस्था और उसके सुशासनके लिए खतरनाक होगा,

किंतु उसमें ये लोग सम्मिलित न होंगे

- (क) महामहिमकी नियमित सेनाओके सदस्य,
- (ख) दूसरे देशके किसी सरकारी जहाजके अधिकारी और नाविक,
- (ग) कोई व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें महामहिमकी सत्ता द्वारा या किसी दूसरे देशकी सरकार द्वारा अपनी पत्नी अपने परिवार और नौकरो सहित प्रमाणित हो,
- (घ) कोई व्यक्ति जो दक्षिण आफ्रिकामें महामहिमकी स्वयंसेवक सेनामें सेवा कर चुका हो और सेनासे नेमनामीके साथ मुक्त हुआ हो एवं जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३) (४), (५), (६) (७) या (८)के अन्तर्गत न आता हो,
- (ङ) किसी व्यक्तिके जो निषिद्ध प्रवासी न हो पत्नी और अवयस्क बच्चे,
- (च) भूमध्य रेखाके दक्षिणकी आफ्रिकी मूल जातियोंके वंशज जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३), (४) (७) या (८)के अन्तर्गत नहीं आते ।
- (छ) यूरोपीय लोग जो किमान या घरेलू नौकर कुशल कारीगर मिस्त्री मजदूर या खनक हैं, जो इंग्लैंडमें या अन्यत्र गवर्नर द्वारा इसके लिए नियुक्त इस उपनिवेशके ऐजेंट जनरलके हस्ताक्षरयुक्त इस आशयका प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सके कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति इस उपनिवेशमें आते ही उसके किसी प्रख्यात नियोजककी सेवा पर्याप्त मत्तदूरीपर और उचित अवधिके लिए करनेके उद्देश्यसे नियुक्त किया गया है,

विनियम का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड प द्वाहके अन्तर्गत बनाया गया विनियम ।

- ३ (१) गवर्नर मसद द्वारा स्वीकृत धनसे एक विभाग स्थापित कर सकता है और कायम रख सकता है जो प्रवासी विभाग कहा जायेगा और मंत्रीके नियन्त्रणमें और एक अधिकारीके अधीन रहेगा जिसकी नियुक्ति समय समयपर की जायेगी।

- (२) इस विभागका कार्य उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे सब काम करना होगा जो इस उपनिवेशमें निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकनेके लिए या उनको निष्कासित करनेके लिए आवश्यक हो या उससे सम्बंधित हो । वह उन अधिकारियोंका प्रयोग या कर्तव्योका पालन भी करेगा जो उसको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा दिये जायें ।
- (३) गवर्नर समय समयपर ऐसे अधिकारियोंको नियुक्त कर सकता या हटा सकता है जिनका नियुक्त करना या हटाना वह इस विभागकी व्यवस्थामें सहायता देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे और उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे एवं वे उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे कतव्योंका पालन करेंगे जो उनको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा सौंपे जायें ।

४ गवर्नर ऐसा काम या ऐसी बातें करनेके लिए जो इस अधिनियमके उद्देश्यों और अभिप्रायोंको कार्य रूप देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त हों दक्षिण आफ्रिकाके किसी उपनिवेश या प्रदेशकी सरकारसे समय समयपर समझौता कर सकता है ।

५ ऐसा प्रत्येक निषिद्ध प्रवासी जो उपनिवेशमें प्रवेश कर रहा हो या उसके भीतर मिले अपराधी होगा और उसको ये सजाएँ दी जा सकेंगी

- (१) जुमनिकी, जो सौ पौंडसे अधिक न होगी या जुर्माना न देनेपर कैदकी जो ६ महीनेसे अधिककी न होगी, या जुर्माने और कैद दोनोंकी, और
- (२) किसी भी समय मन्त्रोंके हस्ताक्षरयुक्त वारंट द्वारा उपनिवेशसे निष्कासित किये जाने और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियममें बताये गये अनुसार नजरबन्द रखे जानेकी, पर तु
- (क) यदि ऐसा निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें माय (सौ मौ पौंडकी) दो जमानते इस उपनिवेशसे एक मासके भीतर चले जानेके सम्बन्धमें दे दे तो वह नजरबन्दीसे मुक्त हो सकता है,
- (ख) यदि ऐसे निषिद्ध प्रवासियोंको कैदकी सजा दी जाये तो उसकी वह कैद उसको उपनिवेशसे निष्कासित करते ही समाप्त हो जायेगी ।

६ कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियमके अमलमें आनेके बाद १९०३ के अनैतिकता अध्यादेशके खण्ड तीन, नेरह या डक्कीसके या उनके किसी संशोधनके उल्लंघन करनेके अपराधमें सजा दी गई हो और कोई व्यक्ति जिसे मंत्री यदि वह उपनिवेशमें रहता है तो उपनिवेशकी शान्ति व्यवस्था और सुशासनके लिए उचित आधार पर खतरनाक मानता है मन्त्रीके हस्ताक्षरयुक्त वारंटसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियम द्वारा बताई गई विधिसे नजरबन्द रखा जा सकता है ।

७ कोई व्यक्ति जो

- (१) जानबूझकर किसी निषिद्ध प्रवासीको इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेके लिए सहायता देता या उकसाता है, या
- (२) जानबूझकर किसी व्यक्तिको जिसे खण्ड छ के अन्तर्गत निष्कासित किये जानेकी आज्ञा दी गई है इस उपनिवेशमें रहनेमें सहायता देता है या उसके लिए उकसाता है, या
- (३) इस उपनिवेशसे बाहरके किसी व्यक्तिते नियोजकके रूपमें उस इरादेसे कोई समझौता करता है, या करना चाहता है कि इस अधिनियमकी धाराओंसे बचा जाये या जो ऐसा समझौता करते समय या उसका श्राद्ध करते हुए उन धाराओंका अपना हिस्सा पूरा न कर सकेगा या जिसे ऐसी कर सकनेकी कोई उचित आशा नहीं है,

वह अपराधी होगा और दोषी पाये जानेपर जुमनिका जो सौ पौंडसे अधिक न होगी, या जुर्माना न देनेपर कैदका, जो छ महीनेसे अधिककी न होगी या जुर्माने और कैद दोनोंका पात्र होगा ।

८ कोई निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें कोई व्यापार या धंधा करनेका परवाना लेने या उसमें कोई भूमि-सम्बन्धी स्वार्थ, लीजपर या जङ्ग खरीद या अन्य स्वार्थ प्राप्त करनेका अधिकारी न होगा, और ऐसा कोई परवाना

(यदि प्राप्त किया गया है तो) या कोई करार या अथ दस्तावेज जिसे ऐसा स्वाथ इस खण्डके विरुद्ध प्राप्त किया जाता है, इस अधिनियमके पाँचवें खण्डके अन्तर्गत ऐसे प्रवासीके दण्डित होनेपर अवैध हो जायेगा।

९ प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें मिलता है और जिसपर उचित रूपसे निषिद्ध प्रवासी होनेका सदेह है किसी भी यायाधीश नगर यायाधीश पुलिस अधिकारी या विभागके अधिकारी द्वारा वारंट बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और वह यथासम्भन्ध शीघ्र कानूनके अनुसार कारवाई करनेके लिए प्रवासी यायाधीशके यायालयमें लाया जायेगा।

१० कोई भी निषिद्ध प्रवासी इस अधिनियमकी धाराओंसे इस कारण मुक्त न होगा और उपनिवेशमें रहने दिया जायेगा कि वह उपनिवेशमें प्रविष्ट नहीं हो सकता यह सूचना उसको नहीं दी गई हो या उसको सम्भवतः असावधानीसे आ जाने दिया गया हो या यह कारण हो कि उसके निषिद्ध प्रवासी होनेकी बात मारुस न हुई हो।

११ उस व्यक्तिको जिसे इस अधिनियमके अन्तर्गत इस उपनिवेशसे निकालनेको आज्ञा दी गई हो और उस अथ व्यक्तिको जिसे खण्ड सातके अन्तर्गत उस व्यक्तिको इस अधिनियमके विरुद्ध इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेमें सहायता देने या उकसानेके जुर्ममें सजा हो चुकी हो वह सब खर्च दना होगा जिसे सरकार उस व्यक्तिको उपनिवेशसे या दक्षिण आफ्रिकासे निष्कासित करनेमें या निष्कासनसे पूर्व उपनिवेशमें या अथ नजरबन्द रखनेमें करे, और उस खर्चकी रकम विभागके अधिकारीका ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें उसकी विगन और पूरी रकम बताई गई हो शेरिफके सामने प्रस्तुत करनेपर उस व्यक्तिकी उपनिवेशमें जो सम्पत्ति होगी उसकी कुर्मीसे वसूल की जायेगी। उस कुर्मीकी विधि वैसी होगी जैसी सर्वोच्च न्यायालयेके निर्णयमें दी गई हो और उस कुर्मीसे जो रुपया मिलेगा शेरिफ द्वारा उपनिवेशके कोषाध्यक्षको सौंप दिया जायेगा जो उक्त खर्चको रकम और कुर्मीका खर्च काटनेके बाद शेष रुपया उस व्यक्तिको भेज देगा जिसके विरुद्ध कारवाई की गई हो या जो उस व्यक्ति द्वारा उस रुपयेको लेनेके लिए नियुक्त किया गया हो।

१२ (१) होटलो भोजन गृहो निवास गृहो या अथ स्थानोंके जहाँ लोगोको रुपया देकर या अथ मूल्यवान कारणोंसे सोनेका स्थान दिया जाता है मालिको या व्यवस्थापकोका कर्तव्य होगा कि वे एक पुस्तिका रखवाये जिसमें ऐसा स्थान प्राप्त करनेवाला व्यक्ति पहले आते ही अपना नाम स्थायी निवास जन्म स्थान और वह जहाँसे अभी आया है उस स्थानको दर्ज करेगा।

(२) इस प्रकारकी प्रत्येक पुस्तिकाको पुलिसका या विभागका कोई भी अधिकारी सब उचित समयोपर देख सकेगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो इस खण्डकी शर्तोंको पूरा न करेगा या ऐसे अधिकारीको उसके अन्तर्गत अपने अधिकारोंका प्रयोग करनेसे रोकेंगा या उसमें बाधा डालेगा या उस पुस्तिकामें कोई बात गलत लिखेगा वह अपराधी होगा और दण्डित होनेपर जुर्माना, जो बीस पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर कैदका जो एक माससे अधिककी न होगी, या जुर्माना और कैद दोनोंका पात्र होगा।

१३ कोई व्यक्ति इस अधिनियमके या किसी नियमके विरुद्ध इस उपनिवेशमें नहीं आया है या नहीं रहा है इसे सिद्ध करनेका भार प्रत्येक ऐसे मुकदमेमें जो इस सम्बन्धमें चलाया जाये अभियुक्तपर होगा।

१४ प्रत्येक आवासी यायाधीशके यायालयको इस अधिनियम या विनियमका उल्लंघन करनेपर अधिकतम सजा देनेका अधिकार होगा।

१५ गवर्नर निम्न सब उद्देश्योंसे या किसी एक उद्देश्यसे समय समयपर इस अधिनियमसे सगत नियम बना सकता है, उनको बदल सकता है या रद्द कर सकता है —

(क) विभागके अधिकारियोंके अधिकार और कर्तव्य निश्चित करनेके लिए,

(ख) इस उपनिवेशमें निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकनेके लिए

(ग) जिन लोगोको इस अधिनियमके अन्तर्गत उपनिवेशसे निकालनेकी आज्ञा दी जाये उनको निकालनेके लिए,

- (घ) जिन लोगोको उपनिवेशसे निकालनेकी आज्ञा दी गई है वे जबतक निकाले न जायें तबतक उनकी नजरबन्दीके लिए,
- (ङ) निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (६) के प्रयोजनसे जो बीमारियाँ छूत की हैं या उड़ा हैं उनको बतानेके लिए,
- (च) (१) जो लोग निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषासे निकाल दिये गये हैं उनके वर्गोंके सम्बन्धमें उपखण्ड छ में उल्लिखित प्रमाणपत्रों, (२) खण्ड पाँच और छ के अन्तर्गत मन्त्री द्वारा निकाले जानेवाले वारंटों और (३) खण्ड बारहके अन्तर्गत रखी जानेवाली पुस्तिकाके फार्म निर्धारित करते हुए
- (छ) जिन स्थितियोंमें निषिद्ध प्रवासी उपनिवेशसे बाहर जाते हुए उपनिवेशमेंसे गुजरने दिये जा सकते हैं उनको निश्चित करते हुए,
- (ज) सामान्यतः इस अधिनियमके उद्देश्यों और प्रयोजनोंको अधिक अच्छी तरह पूरा करनेके लिए, और वे ऐसे कि ही विनियमोंसे उनके भग्न करनेकी सजायें बता सकते हैं जो जुर्मानेके रूपमें सौ पाँचसे या जुमाना न देनेपर कदके रूपमें छ महीनेकी कैदसे ज्यादा न होगी या जुर्मानेकी और कैदकी दोनों होगी ।
- १६ यह अधिनियम सब उद्देश्योंसे १९०७ का प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियम कहा जा सकता है और यह उस तारीखको लागू होगा जिसका ऐलान गवर्नर गजट में घोषणा द्वारा करे ।

परिशिष्ट ४

विनियम

एशियाई कानून सशोधन अधिनियम, १९०७ के खण्ड १८ के अन्तर्गत रचित

- १ जबतक प्रसंगसे असंगत न हो तबतक इन विनियमोंमें —
- ‘अधिनियम’ का अर्थ होगा एशियाई कानून सशोधन अधिनियम, १९०७,
- ‘वयस्क’ का अर्थ होगा १६ वर्ष या उससे अधिक आयुका एशियाई पुरुष,
- ‘प्रार्थी’ का अर्थ होगा कोई व्यक्ति जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है या वह व्यक्ति जिसकी ओरसे उसका संरक्षक पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है,
- ‘पजीयन प्रार्थनापत्र’ का अर्थ होगा वह प्रार्थनापत्र जो एशियाईयोकी पजिका (रजिस्टर) में दर्ज करा दिया हो और जो उस विधिसे ओर उस रूपमें एवं उन विवरणों और शिनायतके निशानोंके साथ दिया गया हो, जो नियम सख्या ३ के अनुसार आवश्यक है,
- ‘क्षेत्र’ का अर्थ होगा यायापीशका जिला या उसका वह भाग जिसे उपनिवेश सचिव ‘गजट’ में इस अधिनियमके खण्ड चारके उपखण्ड (१) के अंतर्गत सूचना निकाल कर निर्धारित कर,
- ‘एशियाई’ का अर्थ होगा ऐसा कोई भी पुरुष जैसा कि १८८५ के कानून ३ की धारा एकमें बताया गया है जो मलायामें जमा और दक्षिण आफ्रिकाके किसी ब्रिटिश उपनिवेश या अधिकृत प्रदेशका अधिवासी न हो, और न कोइ ऐसा व्यक्ति हो जो उपनिवेशमें श्रम आयात अध्यादेश, १९०४ के अन्तर्गत लाया गया हो या चीनी वाणिज्य दूतके कर्मचारी मण्डलमें अधिकारी पदपर नियुक्त हो,
- ‘पजीयन प्रमाणपत्र’ का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड तीनके उपखण्ड (१) के अन्तर्गत दिया गया पजीयन प्रमाणपत्र,
- ‘संरक्षक’ का अर्थ होगा सोल्ह वर्षसे कम आयुके किसी एशियाईका पिता या उसकी माँ या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी देखरेख या जिसके नियन्त्रणमें उक्त एशियाई फिलहाल रहता हो या यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो तो उस एशियाईका मालिक,

- “वैव पत्र धारक” शब्द यदि किसी पजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें प्रयुक्त हो तो इसका अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसका पजीयन उस प्रमाणपत्रके द्वारा प्रमाणित किया गया है,
 ‘अवयस्क’ का अर्थ होगा ८ सालसे अधिक और १६ सालसे कम आयुका एशियाई पुरुष,
 ‘पुलिस दल’ का अर्थ होगा इस उपनिवेशमें कानून द्वारा स्थापित पुलिस दल,
 ‘पुलिस अधिकारी’ का अर्थ होगा पुलिस दलका कोई सदस्य
 ‘पजीयक’ का अर्थ होगा वह अधिकारी जो गवर्नर द्वारा एशियाइयोंका पंजिका रखनेके लिए नियुक्त किया गया हो, और उस हैसियतसे वैधरूपमें कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति,
 “आवासी यायाधीश” शब्दके अन्तर्गत सहायक आवासी यायाधीशका समावेश होगा ।

२ एशियाई पजीयनका फार्म वह होगा जो इसकी अनुसूची क में दिया गया है ।

- ३ पजीयन प्रार्थनापत्रका फार्म निम्न प्रकार होगा,
 (अ) वयस्क प्रार्थीके लिए इसकी अनुसूची ख’ में दिया गया फार्म,
 (आ) अवयस्क प्रार्थीके लिए इसकी अनुसूची ग में दिया गया फार्म,

४ (क) प्रत्येक वयस्क जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देगा उस व्यक्तिके सम्मुख प्रस्तुत होगा जिसे उपनिवेश सचिव गजट में सूचना निकालकर उस क्षेत्रके लिए नियुक्त करे जिसमें वह प्रार्थी रहता है, और वह उक्त व्यक्तिको वे सारे विवरण देगा जो इसकी अनुसूची ‘ख’ में दिये गये फार्मके द्वारा आवश्यक बताये गये हैं, और उक्त व्यक्तिके सामने ये चीजे पेश कराए और उसके सुपुर्द करेगा

१ कोई भी परवाना जो उसकी क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश (१९०२) या उसके सशोधनके विधानके अन्तर्गत ट्रान्सवालम प्रवेश करने और रहनेके लिए दिया गया हो,

२ कोई पजीयन प्रमाणपत्र या १८८५ के कानून ३ की, जिसका सशोधन बादमें हुआ धाराओंके अन्तर्गत पजीयनके लिए निर्धारित शुल्कके भुगतानकी रसीद,

३ उसके पास मौजूद कोई अन्य कागजात जिन्हें वह अपने पजीयन प्रार्थनापत्रके समर्थनमें प्रस्तुत करना चाहे ।

(ख) प्रत्येक संरक्षक, जो एक अवयस्ककी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र दे रहा हो उस अवयस्कको लेकर पूर्वोक्त व्यक्तिके सम्मुख पेश होगा और उस व्यक्तिको अपने सम्बन्धमें और उस अवयस्कके सम्बन्धमें इसकी अनुसूची (ग) में बताये गये फार्ममें निर्दिष्ट आवश्यक विवरण देगा और उस व्यक्तिको उस अवयस्कके सम्बन्धमें इससे पहले उपखण्डमें बताये गये कागजात देगा ।

(ग) पजीयनका प्रत्येक प्रार्थनापत्र उस स्थानमें और उस तारीखसे पहले दिया जायगा जिसको उपनिवेश सचिव गजट’ में सूचना निकाल कर निर्धारित करेगा,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रार्थनापत्र लेनेके लिए पहले कहे अनुसार नियुक्त किया जायेगा किसी प्रार्थीके सम्बन्धमें प्रार्थनापत्रका फार्म पूरा होते ही प्रार्थीको या उसके संरक्षकको अपने हस्ताक्षरोसे पजीयन प्रार्थनापत्र और उसके समर्थनमें पेश किये गये कागजातकी प्राप्तिकी लिखित स्वीकृति देगा । प्राप्तिकी स्वीकृति इसका अनुसूची घ में दिये गये फार्ममें दो प्रतियोंमें होगी और उसकी दूसरी प्रति तुरत उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थनापत्र और उसके समर्थनमें प्रस्तुत किये गये कागजातके साथ पजीयकको भेज दी जायेगी ।

५ यदि पजीयक अधिनियमके खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के अनुसार कारवाई करते हुए किसी वयस्कका पजीयन करना अस्वीकार करता है तो अस्वीकृतिकी सूचना उसी उपखण्डके अनुसार भेजी जायेगी और उसकी प्रतिलिपि आवासी यायाधीशको उसके कार्यालयके मुख्य द्वारपर चिपकानेके लिए भेजी जायेगी यह सूचना अनुसूची ‘ड’ में दिये गये रूपमें होगी ।

६ पजीयन प्रमाणपत्र इसकी अनुसूची ‘च’ में दिये गये रूपमें होगी ।

७ प्रत्येक अवयवकिसी पुलिस अधिकारी या उपनिवेश सचिव द्वारा इसके लिए उचित रूपसे अधिकार दिये गये किसी भी व्यक्ति के माँगनेपर अपना वैध पञ्जीयन प्रमाणपत्र पेश करेगा और इसके अतिरिक्त उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त व्यक्ति के माँगनेपर निम्न विवरण देगा

- (१) अपना पूरा नाम,
- (२) अपना वर्तमान निवास स्थान,
- (३) पञ्जीयनका प्रार्थनापत्र देनेके दिन अपना निवास स्थान,
- (४) अपनी आयु,

और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अथवा व्यक्तिको या उनकी उपस्थितिमें ये चीजें देगा

- (१) यदि लिख सकता हो तो अपने हस्ताक्षरोंका नमूना,
- (२) अपने अँगूठोंके या अँगूठों और अँगुलियोंके निशान ।

८ प्रत्येक अवयवस्कका सरक्षक जिसे ऐसा पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त दूसरा व्यक्ति उस अवयवस्कका वैध पञ्जीयन प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कहे ऐसे प्रमाणपत्रको पेश करनेके अतिरिक्त पूर्वोक्त माँग करनेपर निम्न विवरण देगा

- (१) अपना पूरा नाम,
- (२) अपना वर्तमान निवास स्थान,
- (३) उस व्यक्तिकका पूरा नाम, जो अवयवस्ककी ओरसे पञ्जीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेकी तारीखको उसका सरक्षक था, और उस तारीखको उस व्यक्तिकका निवास स्थान,
- (४) उस अवयवस्ककी आयु,

और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अथवा व्यक्तिको या उनकी उपस्थितिमें उस अवयवस्कके अँगूठोंके या अँगूठों और अँगुलियोंके निशान देगा ।

९ आठ वर्षसे कम आयुके एशियाई बच्चोंका प्रत्येक सरक्षक पञ्जीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेपर ऐसे सब बच्चोंके सम्बन्धमें निम्न विवरण देगा

- (१) उनके पूरा नाम,
- (२) प्रत्येककी आयु,
- (३) प्रत्येकका सरक्षकसे सम्बन्ध,
- (४) प्रत्येकका जन्म स्थान
- (५) यदि अथवा जमा हो तो प्रत्येककी टाँसवालोंमें आनेकी तारीख ।

१० प्रत्येक एशियाई अपने वैध पञ्जीयन प्रमाणपत्रके या सरक्षकके रूपमें अवयवस्कके वैध प्रमाणपत्रके होने या नष्ट हो जानेपर उसे नया करनेका प्रार्थनापत्र दते समय पञ्जीयकको निम्न विवरण देगा

- (१) उस पञ्जीयन प्रमाणपत्रकी संख्या,
- (२) अपना पूरा नाम,
- (३) अपना वर्तमान निवास स्थान,
- (४) अवयवस्कका पूरा नाम और उसकी आयु, (यदि प्रार्थनापत्र अवयवस्ककी ओरसे सरक्षकने दिया हो तो) ।

और वह पञ्जीयकको या उस व्यक्तिको जिसे पञ्जीयक इस कार्यके लिए नियुक्त कर निम्न चीजें देगा,

- (१) अपने अँगूठों और अँगुलियोंके निशान, या
- (२) यदि प्रार्थनापत्र अवयवस्ककी ओरसे उसके सरक्षकने दिया हो तो अपने पञ्जीयन प्रमाणपत्रकी संख्या, अपने दायें हाथके अँगूठका निशान और उस अवयवस्कके अँगूठों और अँगुलियोंके निशान ।

११ प्रत्येक एशियाई, जो १९०५ के राजस्व परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधन या नगरपालिकाके किसी चाबू उपनियमके अन्तर्गत अपनी ओरसे व्यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है, उसे परवाना देनेके

१२ प्रत्येक एशियाई जो ट्रान्सवाल्से अस्थायी रूपसे अनुपस्थित दूसरे एशियाईकी ओरसे यापारिक परवानके लिए प्राथनापन देता है ऐसा परवाना देनेके लिए नियुक्त व्यक्तिको नीचे लिखी चीज देगा,

- (१) अपना निजी पंजीयन प्रमाणपत्र,
- (२) जिन एशियाईकी ओरसे प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है उसका पूरा नाम,
- (३) उस एशियाईका पूरा वर्तमान पता
- (४) मुरत्यारनामा या अथ अधिकारपत्र जिसके अंतगत उसको इस परवानेको लेने या अनुपस्थित व्यक्तिके यापारको चलनेका अधिकार दिया गया हो और उस मुरत्यारनामे या अन्य अधिकारपत्र पर अनुपस्थित व्यक्तिके दाये हाथके अंगुठेका साफ निशान हो,

और वह उस व्यक्ति को और उसके सम्मुख आवश्यकता हो तो अपने दाँयें हाथका निशान भी देगा ।

१३ अधिनियमके खण्ड सत्रहमें उल्लिखित उपनिवेशमें सीमित अवधिके लिए आने और रहनेका परवाना इसकी अनुसूची, छ में दिये गये रूपमें होगा ।

अनुसूची 'क'

एशियाई पत्रिका

[illegible]

[अग्र भाग]

अनुसूची 'ख'

वयस्क एशियाईके पजीयनका प्रार्थनापत्र

पूरा नाम

जाति या सम्प्रदाय

निवास स्थान

शारीरिक विवरण

प्रजाति

आयु

ऊँचाई

वधा

जन्म स्थान

दूर सवालमें पहली बार आनेकी तारीख

३१ मई १९०२ को कहाँ रहते थे

पिताका नाम

माताका नाम

पत्नीका नाम

रहनेका स्थान

आठ वर्षसे कम आयुके पुत्र और आश्रित बालक

नाम	आयु	निवास स्थान	सरक्षकसे सम्बन्ध
-----	-----	----------------	---------------------

प्रार्थकी हस्ताक्षर

प्रार्थनापत्र लेनेवाले व्यक्तिके हस्ताक्षर

तारीख

कार्यालय

[पृष्ठ भाग]

नाम

दायें हाथके निशान

अँगूठा	तजनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
--------	------	--------	---------	-----------

बायें हाथके निशान

अँगूठा	तजनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
--------	------	--------	---------	-----------

एक साथ निशान

बायाँ हाथ	चार अँगुलियों	दायाँ हाथ	चार अँगुलियों
-----------	---------------	-----------	---------------

वयस्कके निशान लेनेवाला

तारीख

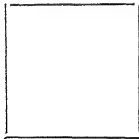
[अग्रभाग]
अनुसूची 'ग'
अवयस्क एशियाईकी ओरसे दिया गया पजीयनका प्रार्थनापत्र
सरक्षकका विवरण

पूरा नाम प्रजाति
 निवास स्थान
 सरक्षकका अवयस्कसे सम्बन्ध
 प्रमाणपत्रकी सख्या

अवयस्कका विवरण

पूरा नाम प्रजाति
 जाति या सम्प्रदाय आयु
 निवास स्थान धन्धा
 ३१ मई १९०२ को कहाँ रहता था
 पिताका नाम माताका नाम
 शारीरिक विवरण

ज म स्थान
 टाँसवालमें आनेकी तारीख
सरक्षकके दाये हाथके अँगूठेका निशान



सरक्षकके हस्ताक्षर
 अवयस्कके हस्ताक्षर
 प्रार्थनापत्र लेनेवाले
 व्यक्तिके हस्ताक्षर
 कार्यालय
 तारीख

[पष्ठ भाग]

नाम

दायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
--------	--------	--------	---------	-----------

बायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
--------	--------	--------	---------	-----------

एक साथ निशान

बायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ	दायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ
-----------	---------------	-----------	---------------

अवयस्कके निशान लेनेवाला

तारीख

अनुसूची 'घ'
प्रार्थनापत्र प्राप्ति की स्वीकृति

१९०

सेवामें

मुझे आपके द्वारा की
ओरसे १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अंतर्गत दिये गये पंजीयनके प्रार्थनापत्रको और उस प्रार्थनापत्रके
समयनमें पेश किये गये कागजातकी जिनका ब्यौरा नीचे दिया है, पहुँच स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त है ।

हस्ताक्षर
कार्यालय
कागजातका ब्यौरा —

अनुसूची 'ङ'
प्रार्थनापत्र अस्वीकृतिकी सूचना

१९०

सेवामें

चूँकि आपने (महोना) को तारीख को (स्थान) में
वध रूपसे ट्रान्सवालवासो एशियाईयोकी पंजिकामें दर्ज किये जानेका प्रार्थनापत्र दिया था ।

और चूँकि प्रार्थनापत्रपर विचार करनेके बाद मुझे यह प्रतीत होता है कि आप ट्रान्सवालके वैध निवासी नहीं हैं,
इसलिए आपको इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि मैं आपको ट्रान्सवालके वैध निवासीके रूपमें पंजीयित
करना अस्वीकार करता हूँ और १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके खण्ड पाँचके उपखण्ड (२) के
अनुसार आवासी यायाधीशके सम्मुख में

की की तारीख सन् १९०७ को १० बजे दोपहरको उपस्थित होने और यह बतानेका
निर्देश देता हूँ कि आपको उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा क्यों न दी जाये ।

हस्ताक्षर

एशियाई पंजीयक

अनुसूची 'च'
पजीयन प्रमाणपत्र

पूरा नाम
प्रजाति
विवरण

आयु

ऊँचाई

दाये हाथके अँगूठेका निशान

एशियाई पजीयक



जारी करनेकी तिथि
धारकके हस्ताक्षर

इस प्रमाणपत्रके अग्रभागपर एशियाई पजीयकके अतिरिक्त अन्य किसीको न कोई परिवर्तन करना चाहिए और न कुछ लिखना चाहिए ।

अनुसूची 'छ'
अस्थायी अनुमतिपत्र

इसके द्वारा
आने और

को, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है, ट्रान्सवालमें
की अवधितक रहनेकी अनुमति दी जाती है जिसका आरम्भ से होता है ।

विवरण

प्रजाति

जाति या सम्प्रदाय

ज म स्थान

आयु

ऊँचाई

निवास स्थान

ट्रान्सवालका नगर या स्थान जहाँ जा रहे हैं

शारीरिक विवरण

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दाये हाथके अँगूठेका निशान

एशियाई पजीयक



निशान छेनेवाला
स्थान
तारीख

परिशिष्ट ५

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

२८, क्वीन ऐ स चेम्बर्स, ब्रॉडवे

वेस्टमिन्स्टर, एस० डब्ल्यू०

अगस्त १४, १९०७

सेवामें

परममाननीय सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैन जी० सी० बी०, पी० सी०, ऐड सी०

प्रधान मंत्री

महोदय

मेरी समितिका एक शिष्टमण्डल आपकी सेवामें उपस्थित होनेका इच्छुक है। उसके नामोकी सूची में साथ बढ़ कर रहा हूँ। उसका उद्देश्य यह है कि टान्सवाल उपनिवेशमें अपने साथी भारतीय प्रजाजनोंकी स्थिति और उनके प्रति होनेवाले व्यवहारके बारेमें अपने विचार सादर आपके समक्ष रखे।

वे चाहते हैं कि मैं प्रस्तावनाके रूपमें निम्नलिखित तथ्य आपके सामने रखूँ

इस उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या हालकी जनगणनाके अनुसार १०,००० है। और जैसा कि आगे चलकर दिखाया जायेगा यह लगभग स्थिर है। इसमें अबिक सरया यापारी वर्गकी है और वे दूकानदार और फेरीवाले हैं। शेष माली, देशी सुतार दर्जी इत्यादि दिखाये गये हैं। भारतीय कुली, खनिक या कारीगर नहीं से हैं।

आपकी मादूस होगा कि 'एशियाई' (ब्रिटिश भारतीयों सहित) भूतपूर्व टा सवाल सरकार द्वारा कतिपय नियोग्यताओंके शिकार बनाये गये थे। ये उनके अतिरिक्त थी जिनके गैर एशियाई विदेशी भी भागीदार थे, और १८८५ का कानून ३ यथपि राज्यमें एशियाई प्रवासपर रोक नहीं लगाता था तथापि ३ पौडका पजीयन शुल्क लादता था नागरिकता प्राप्त करनेके अधिकारसे वंचित रखता था उनके अपने नामोपर अच्छे सम्पत्तिक पजीयन वर्जित करता था और कतिपय बाजारों कक्षों और बस्तियोंमें निर्वासित होकर रहनेके लिए जवाबदेह बनाता था। ये नियोग्यताएँ विशेषकर नागरिकता प्राप्त करनेके अधिकारसे वंचित रखा जाना निस्संदेह बहुत कुछ रंग विद्वेषके कारण थी। प्राचीन कानूनके अधीन श्वेत और रंगदार लोगोंके बीच स्पष्ट रूपसे एक रेखा खींची गई थी। उसमें यह लिखा है कि रंगदार और श्वेतके बीच कोई बराबरी नहीं बरती जायेगी।

इस भेद करनेवाले विधानके विरुद्ध महामहिमके मंत्रियोंने, जिनमें लॉर्ड डर्बी और श्री चैम्बरलेन उल्लेखनीय हैं टान्सवालकी सरकारके पास समय समयपर विभिन्न प्रस्ताव और प्रतिवाद भेजे हैं। २० जुलाई, १९०४ के एक खरीतेमें, जिसे परममाननीय अल्फ्रेड लिटिल्टनने उच्चायुक्तके नाम भेजा था, ये बहुत अच्छी तरह संक्षिप्त रूपमें वर्णित हैं

“इसलिए युद्धके आरम्भ तक ब्रिटिश सरकारने लगातार पहले अधिकारके रूपमें और फिर १८९५ के पंच फौसलेके अनुसार कूटनीतिक प्रयत्नोंसे टान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोंके हितोंको कायम रखा, और सहप्रजाजनोंके प्रति व्यवहार विगत दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके विरुद्ध ब्रिटिश मामलेका एक अंग था।”

बेशक आपकी यह स्मरण दिलाना भी अनावश्यक है कि युद्धके दिनोंमें दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंने स्वेच्छापूर्वक कौसी महत्वपूर्ण चिकित्सा-सेवा और अन्य सेवाएँ की थी। जो टान्सवालमें रहते थे

स्वभावतः यह निश्चित आशा रखते थे कि दूा सवाल प्रदर्शके साम्राज्यमे सयोजित ह। जानेसे अपनी नियोग्यताओको तुरन्त दूर होते और अपने साथी प्रजाजनोंके साथ अपने आपको समानताका दर्जा प्राप्त करते देखेंगे। यद्यपि दूा सवालपर अधिकार होनेके साथ ही गणतंत्रके बहुत से पुराने कानून रद्द कर दिये गये, तथापि १८८५ का कानून ३ इस नये उपनिवेशकी कानूनकी पुस्तकमें बना रहने दिया गया। इससे उन्हें अवर्णनीय निराशा हुई। और फिर प्रवेश युद्धसे पूर्वके निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया, शान्ति रक्षा अध्यादेश जिसे नई सरकारने नये राज्यके शत्रुओको बाहर रखनेके उद्देश्यसे पास किया था, भावी नवागंतुक एशियाइयोंको बाहर रखनेके लिए प्रयुक्त होने लगा। अधिवासी एशियाइयोंकी वापसीको नियमित और व्यवस्थित करनेके लिए प्रथम बार एक खास महकमेकी स्थापना की गई और उन्हें अपने घरों और व्यवसायोंमें वापस जानेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमें विभिन्न और शोचनीय अड़चनोंका अनुभव हुआ। १९०३में उच्चायुक्तने १८८५ के कानून ३ की दफाओको कड़ाईके साथ लागू करनेका निश्चय किया जो कि महामहिमकी सरकारकी लिखा पढीके कारण बोअर शासनमें बड़ी सीमा तक मृत प्रलेख बना हुआ था। उन समस्त एशियाइयोंको, जो अधिकारियोंको यह सन्तोष नहीं दिला सके कि वे ३ पौडका पजीयन शुल्क पहले दे चुके हैं रकम देनेके लिए मजबूर होना पडा। पाँच हजार छियासठ भारतीयों और पाँच सौ पन्द्रह चीनियोंने कुल ९,०५९ पौड दिये। पजीयनका सम्पूर्ण स्वरूप ही बदल गया। गणतंत्रमे यह यदि आवश्यक था भी तो केवल इतनेके लिए कि प्रदाताको ३ पौडकी रसीद दे दी जाये। एशियाइयोंके पजीयनके १९०४में घोषित किया कि भूतपूर्व बोअर सरकार द्वारा संकलित कोई एशियाइ पजीयन प्रलेख (यदि ऐसे प्रलेख कमी रखे जाते रहे हों) किसी जिलेमें नहीं पाये गये। इसके तीन अपवाद मिलते हैं। पुनः पजीयनने अब प्रथम बार गिनास्तका रूप धारण कर लिया है। अब जो प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे हैं वे केवल ३ पौडकी रसीदें नहीं हैं। उनमें उनके मालिकोंके नाम, उनकी पत्नियों बच्चोंकी सट्या मालिकोंकी आयु उनका स्पष्ट ड्रिलिंग और अँगूठोंके निशान दिये रहते हैं। इस प्रस्तावित कदमका ब्रिटिश भारतीयोंने इस आधारपर दृढ़ विरोध किया कि कानूनकी आवश्यकताओंकी पहले ही पूर्ति कर चुकनेके बाद वे पुनः पजीयनके लिए बाध्य नहीं हैं। उच्चायुक्तको सिफारिश द्वारा इसका खण्डन हो गया और उसमें उन्होंने इसके लिए नई जरूरतके बाग़मे अपनी सहमति प्रकट की। महानुभावने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा

‘ मेरा खयाल है कि पजीयनसे उनकी रक्षा होती है। उस पजीयनके साथ ३ पौडका शुल्क जुडा हुआ है। यह केवल एक बार माँगा जाता है। जिन्होंने उसे पुरानी सरकारको अदा किया है उन्हें केवल यह सिद्ध करना है कि उन्होंने देसा किया है और उन्हें यह शुल्क दुबारा नहीं अदा करना होगा। फिर पजीपर एक बार नाम आ जानेपर उनका दर्जा कायम हो जायेगा और आगे पजीयन करानेकी आवश्यकता नहीं होगी और न नये अनुमतिपत्रकी आवश्यकता होगी। वह पजीयन आपको यहाँ रहनेका, यहाँ आने जानेका अधिकार देता है। ’

इसपर ब्रिटिश भारतीय समाजने नये पुनः पजीयनको स्वेच्छया स्वीकार कर लिया और बिना किसी कानूनी या अर्थ बाध्यताके एक ओरसे सवने आवश्यक परवाने ले लिये। इन परवानोंपर पूर्व वर्णित शिनास्तके चोरे अंकित हैं और आज बिना किसी अपवादके लगभग प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय अधिवासीके पास ये परवाने हैं।

अचल सम्पत्ति रखनेके विरुद्ध पुराने नियंत्रणोंमें वस्तुतः कोई ढिलाई नहीं हुई।

एशियाइयोंको (ब्रिटिश भारतीयों सहित) बाजारों या बस्तियोंमें, जो उनके लिए खास तौरसे अलग बना दी गई हैं पृथक् करके रखने और उपनिवेशमें जहाँ चाहें वहाँ यापार करनेके लिए परवानोंकी माँग करनेके उनके अधिकारको घटानेके विचारसे भी १९०२ और १९०३ में महामहिमकी सरकार और ट्रान्सवाल उपनिवेशकी सरकारके बीच यथेष्ट पत्र व्यवहार हुआ था।

प्रिटोरिया और पीटर्सबर्गके हबीब मोटनके दूकानके परवानोंको १९०४ में बदलनेसे इनकार करनेके फलस्वरूप सर्वोच्च यायालयको एक निर्णय देना पडा, जिसमें वस्तियोंके बाहर व्यापार करनेके उनके अधिकारको उचित माना गया।

१९०३ में, ट्रांसवालकी खानोंमें काम करनेके लिए कुलियोके विषयमें ट्रांसवाल सरकार और भारत सरकारके बीच पत्र व्यवहार हुआ। वह असफल रहा। भारत सरकारका आग्रह था कि उसकी स्वीकृतिके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि पहले वे कतिपय नियोग्यताएँ दूर की जायें जो उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीय व्यापारी समाजको मंहनी पड़ रही हैं। ट्रांसवाल सरकार इससे सहमत होनेमें अपनेकी असमर्थ पा रहा थी।

उसी वर्ष ट्रांसवालकी सरकारने महामहिमकी सरकारके समक्ष एक खास प्रकारके विधानका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारोके और भी कम कर दिये जानेका खतरा पैदा हो गया था, जो उस समय एशियाई समाजके पास बच रहे थे। इसका महामहिमकी सरकारने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया था

‘परन्तु इस देशमें अब जो ब्रिटिश भारतीय हैं जिनकी सरया स समय अपेक्षाकृत कम है और प्रवासके बारेमें प्रस्तावित नियमोंके कारण उसी अनुपातसे घटती जायेगी उनके साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका भय इस प्रस्तावित विधानके लिए यथेष्ट कारण नहीं माना जा सकता। भूतकालमें महामहिमकी सरकारने इस भय द्वारा अपने विचारोको दृढ़ताके साथ प्रभावित नहीं होने दिया। इसके विरुद्ध वर्षों तक उसने इस विषयके सम्बन्धमें भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रको नीति और कानूनोंके विरुद्ध साम्राज्य और सम्य ससारके समक्ष बराबर प्रतिवाद किया है।

‘ये कानून केवल आंशिक रूपसे लागू थे, जब कि महामहिमकी सरकारसे अब इनको कड़ाईके साथ केवल लागू करनेकी मजूरी ही नहीं माँगी जाती बल्कि एक विधान द्वारा सर्वोच्च यायालयके उन फेसलको भी रद्द करनेके लिए कहा जा रहा है जिसने ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार दिये थे जिनका महामहिमकी सरकार बड़ी लगनके साथ समर्थन करती रही थी।

“महामहिमकी सरकार इस बातका विश्वास नहीं कर सकती कि ट्रांसवालका ब्रिटिश समाज उस प्रस्तावके सच्चे स्वरूपकी कद्र करता है जिसके लिए, कुछ सदस्य आपपर दबाव डाल रहे हैं। ब्रिटिश होनेके नाते वे ब्रिटिश नामके सम्मानके उतने ही बड़े हिमायती हैं जितने कि स्वयं हम हैं, और उस सम्मानकी रक्षामें कुछ भौतिक बलिदानकी आवश्यकता पड़े तो, मुझे निश्चयपूर्वक लगता है कि, वे सानद उसे करेंगे। महामहिमकी सरकारका मत है कि अधिवासी ब्रिटिश प्रजाजनोंपर उन नियोग्यताओंको लादना, जिनके विरुद्ध हम प्रतिवाद कर चुके हैं, और जिनका शिकार, सही व्याख्याकी जानेपर, भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रके कानून भी उन्हें नहीं बनाने थे, राष्ट्रीय सम्मानको आघात पहुँचाने वाला है। और महामहिमकी सरकारको इसमें सन्देह नहीं है कि जब यह बात समझमें आ जायेगी तब उपनिवेशका लोकमत उस माँगका समर्थन नहीं करेगा, जो पेश की गई है।

ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीयोंने अपने मनमें अत्यधिक विश्वास जमा रखा था कि वर्तमान शासनके अधिकारमें जानेके साथ यदि उनकी नियोग्यताएँ दूर न हुई तो भी समाजकी कमसे कम उसके शेष अधिकारोंपर और आक्रमण होनेसे, दृढ़ताके साथ रक्षा की जायेगी।

आपको उन परिस्थितियोंका स्मरण होगा जिनके कारण १९०६ का एशियाई कानून सशोषण अध्यादेश वर्जित कर दिया गया था, और इसी तरह आपको यह भी पता होगा कि, विभिन्न प्रार्थनाओं और प्रतिवादोंके बावजूद, ट्रांसवालकी वर्तमान उत्तरदायी सरकारने, महामहिमकी सरकारकी स्वीकृतिसे बिल्कुल वसा हाँ विधान पास कर लिया है।

महामहिमकी सरकार और जनरल बोथाको मेरी समितिके जो प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूपसे दिये गये उनका इस आश्वासनके साथ स्वागत किया गया कि ट्रांसवालकी सरकार द्वारा सम्बन्धित कानूनका अधिकसे अधिक नरमोंके साथ और कमसे-कम कष्टदायी रूपमें प्रयोग होगा। यह दुःखकी बात है कि सरकारने प्रत्यक्षतः न तो उस कड़ाईको कम करना उचित समझा, जो मूल अध्यादेशमें विद्यमान थी और जिसकी स्वीकृति नहीं दी गयी थी, और न अभी उन नियमोंको नरम बनाया जिनके अन्तर्गत इसका प्रयोग होना है।

नये अधिनियमसे सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतीय समाजमें अत्यधिक रोष पैदा हो गया है और इसने इस साधारणतया विनम्र और कानून माननेवाली जातिको बिल्कुल अमृतपूर्व ढंगसे उमाड़ दिया है। वह समाज सुरक्षितता निम्नलिखित आधारोंपर इसका विरोध करता है

(१) यह उस आश्वासनको तोड़ता है जो उच्चायुक्तने, उन्हें १९०३ में दिया था जब कि वे स्वेच्छया पुनः पञ्जीयनके लिए तैयार हो गये थे।

(२) यह उनके इस देशमें रहनेके वर्तमान अधिकारको रद्द कर देता है और कलमके एक आघातसे वर्तमान अनुमतिपत्रों और प्रमाणपत्रोंको बेकार बना देता है, और जिनके पास वे हैं उनके ऊपर उनके अधिकारी होनेका सबूत देनेकी जिम्मेदारी डालता है।

(३) श्वेत उपनिवेशियोंके पूर्वग्रहोंका ध्यान रखते हुए उन्होंने जो स्वेच्छया पञ्जीयन स्वीकार किया था उसके स्थानपर यह उनके ऊपर अत्यन्त अपमानजनक स्थितिमें अनिवार्य पञ्जीयन लादता है। ब्रिटिश भारतीय जो कि भावुक हैं उनको यह विद्रोही बनाता है और समाजके रूपमें उन्हें दक्षिण आफ्रिकी जंगलियोंके स्तरपर ला देता है। वे कानून द्वारा एक निम्न कोटिकी अपराधी जातिके बना दिये जाते हैं।

(४) उन्हें भय है कि यह उनके ऊपर और उनकी स्वाधीनताके ऊपर और भी अधिक नियन्त्रण लागू करनेका प्रारम्भ है और दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे उपनिवेशोंमें इसी प्रकारके विधान लागू करनेका बहाना है।

(५) यह पहलेसे ही उन्हें इस अपराधमें शामिल होनेका मुलजिम मान लेता है कि उन्होंने इस उपनिवेशको एशियाइयोंसे भर दिया है। इस झूझामसे उन्होंने बराबर इनकार किया है और इसके बारेमें उन्होंने जॉच आयोगकी माँग की है।

(६) यह एक प्रतिक्रियावादी विधान है और सर्वोच्च ब्रिटिश परम्पराओंके विरुद्ध है।

इस प्रकार इस समाजकी आपत्ति पुनः पञ्जीयन करानेपर नहीं है। उसके लिए तो उन्होंने स्वेच्छया पञ्जीयन करानेका वचन दिया है। दरअसल उन्हें आपत्ति है ऐसे भेदभावपूर्ण वर्ग विधानके परिणामस्वरूप उन्हें जो जातीय अपमान और पतनका अनुभव होता है, उसके विरुद्ध।

हाल ही में ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाएँ हुई हैं जिनमें उपस्थिति दो हजार तक गई है। उनमें अच्छी स्थिति और महत्त्वके दूकानदारोंने और अच्छे व्यापारियों और फेरीवालोंने गम्भीरतापूर्वक प्रतिज्ञाएँ की हैं कि वे इस कानूनके अन्तिम दण्डकी स्वीकार करेंगे और अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता ही नहीं बल्कि उनके पास जो कुछ भी सांसारिक सम्पत्ति है उसका, नये विधानकी शर्तोंके अनुसार पुनः पञ्जीयन करानेके बजाय, बलिदान कर देंगे। प्रिटोरियाके एशियाइयोंकी सूचना दी गई थी कि उन्हें वर्तमान मासके प्रारम्भ होनेसे पहले नये प्रमाणपत्रोंके लिए अवश्य ही प्राथनापत्र दे देना चाहिए। उन्होंने भारी जुर्मानों और निर्वासनकी सजा भोगना पसन्द किया है परन्तु इससे कड़ाईके साथ दूर रहे हैं।

मेरी समितिके प्रतिवेदनके अतिरिक्त स्वयं ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रांसवालकी सरकारके समक्ष विभिन्न प्रार्थनापत्र भेजे हैं जिनमें उन्होंने प्रार्थनाएँ की हैं कि इस मामलेपर उनके दृष्टिकोणसे विचार किया जाये, परन्तु इसका कुछ परिणाम नहीं हुआ।

मेरी समितिका मत है कि वह समय आ गया है जब साम्राज्य सरकारको हस्तक्षेप करना चाहिए और उसका सादर निवेदन है कि उसकी विनम्र सम्मतिमें ट्रांसवालके ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार अभीतक नहीं दिये गये हैं जिनके वे साम्राज्यकी मन्थ प्रजा होनेके नाते अधिकारी हैं और न अभी उन्हें महामहिमकी सरकारसे वह संरक्षण मिला है जो ट्रांसवालपर ब्रिटेनका अधिकार हो जानेके बाद और अधिक नियोग्यताओंके लोदे जानेसे मिलना चाहिए।

ब्रिटिश भारतीयोंकी माँगें अत्यन्त साधारण हैं

(१) उस नये कानूनका रद्द किया जाना जिसके अनुसार नये सिरेसे पञ्जीयन अनिवार्य है, और उसके स्थानपर उनके स्वेच्छया पञ्जीयनके वचनका स्वीकार किया जाना। वर्तमान प्रमाणपत्रोंका नये प्रलेखके बदलेमें जो कि आपसी समझौते अनुसार हो, दे दिया जाना। स्वेच्छया पञ्जीयन न करानेकी

दशमे (यदि ऐसा कोई हो जिसकी सम्भावना बिल्कुल नहीं है) एक छोटा सा अधिनियम होना चाहिए जिससे जिन एशियाइयों के पास नये प्रमाणपत्र न हों, वे निर्वासित किये जा सकें।

(२) १८८५ का कानून ३ जहाँतक इसका ब्रिटिश भारतीयों से सम्बन्ध है, रद्द कर दिया जाये, परन्तु

(क) यूरोपीय उपनिवेशका एशियाइयों की बाढको रोकनेका अधिकार स्वीकार किया जाता है। ऐसा नियंत्रण अब शांति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत हो रहा है और राजपत्रमें एक प्रवासी प्रतिबंधक विधेयककी सूचना छप चुकी है। इससे ऐसा प्रवास और भी सीमित किया जा सकेगा।

(ख) परवाना निकाय द्वारा (उसके निर्णयके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकारके साथ) व्यापारी परवानोंके जारी करनेपर नियंत्रणका सिद्धान्त इसी प्रकार स्वीकार किया जाता है।

(ग) श्वेत उपनिवेशियोंके वर्तमान पूर्वग्रहोंको ध्यानमें रखते हुए न तो राजनीतिक और न नगर पालिका सम्बंधी किसी अधिकारकी माँग की जाती है।

कदाचित् यहाँ यह कहना अनावश्यक होगा कि यह मामला केवल ऐसा घरेलू नहीं है कि इससे उपनिवेशका ही सम्बन्ध हो बल्कि यह सर्वोच्च साम्राज्यीय महत्त्वका है और इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं।

हमें आशा और भरोसा है कि इस मामलेमें ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे महामहिमकी सरकार द्वारा टान्सवालकी सरकारके साथ मैत्रीपूर्ण लिखा पढ़ी वाञ्छनाय प्रभाव पैदा करगी। मुझे यह भी निवेदन करनेके लिए कहा गया है कि यदि आप शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार करें, तो कृपापूर्वक वैकल्पिक तारीख दे, क्योंकि समितिके कुछ सदस्योंके पास विभिन्न व्यवसाय हैं जिनको स्थगित करना उनके लिए असम्भव हो सकता है।

आपका आदि,

एल० डब्ल्यू० रिच

मन्त्री

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफिस रेकर्ड्स, जे० एंड पी० ३९२७/०७

परिशिष्ट ६

दस गिन्नियोका पारितोषिक

‘अनाक्रामक प्रतिरोधका नीतिशास्त्र’ पर एक निबन्धके लिए

भारतीय इस समय टान्सवालमें एक ऐसे अधिनियमके विरुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोध सग्राम लड़ रहे हैं जो उनकी सम्पत्तिमें उनकी आत्माको चोट पहुँचाता है और इस पत्रने उम अनाक्रामक प्रतिरोध सग्रामको एक विनम्र तरीकेसे रास्ता दिखलाया है, दूसरे इस पत्रकी नांतिक नियंत्रक अनाक्रामक प्रतिरोध सिद्धान्तकी सामान्य उपयोगिता प्रदर्शित करनेको इच्छुक हैं। इन दोनों कारणोंसे इसके प्रबंधकोंने ‘अनाक्रामक प्रतिरोधके नीतिशास्त्र’ पर सर्वोत्तम निबंधके लिए १० गिन्नियोका पुरस्कार देनेका निश्चय किया है। इस पुरस्कारकी घोषणा इस लेख द्वारा की जाती है। वार्षिक रूपसे विचार करें, तो इस सिद्धान्तका अर्थ है, इसके इस प्रसिद्ध उपदेशका पालन करना कि ‘पापका प्रतिरोध मत करो।’ इस तरह यह सनातन और विश्वव्यापी प्रयोगकी बात है और यदि इसका अभ्यास बड़े पैमानेपर किया जाये तो यह पूर्णतया नहीं तो बड़ी हद तक कष्टोंसे मुक्ति प्राप्त करने या सुधारोंकी स्थापना करनेमें पशुबल और वैसे ही तरीकोंका स्थान ले लेगा। इसलिये प्रबंधकोंको आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके अच्छेसे अच्छे लोग, जिनके पास अवकाश हो, इस पुरस्कार प्रतियोगितामें भाग लेंगे। ये इस पुरस्कारके आर्थिक महत्त्वकी

दृष्टिसे नहीं बल्कि इस दृष्टिसे इसमें भाग लेंगे कि जीवनके एक ऐसे सिद्धान्तको स्पष्ट करना है जिसे, ससारके सर्वश्रेष्ठ विचारोका बल प्राप्त होनेपर भी, बहुत कम समझा जाता है, और उससे भी कम व्यवहारमें लाया जाता है।

इस प्रतियोगिताकी शत नीचे लिखे अनुसार है

(१) निबंध साफ कागजके एक ही तरफ लिखा होना चाहिए। टाइट किया हो तो और अच्छा। हस्तलिपिपर प्रतियोगीका नाम नहीं होना चाहिए।

(२) वह चार परिच्छेदोंमें विभक्त किया जा सकता है और “इंडियन ओपिनियन” के दस स्तम्भोंसे अविकला नहीं होना चाहिए।

(३) उसमें योरिके उच्च साहित्य ‘सविनय अवज्ञाका धर्म’, टॉल्स्टॉयकी कृतियों विशेषकर स्वर्गका राज्य आपके अन्दर है, की याद दायी होनी चाहिए, उनमें बाइबिल तथा अय धर्म ग्रंथोंके प्रमाण और उदाहरण और इस प्रश्नपर ‘सुकरातकी सफाई’ का भी प्रयोग होना चाहिए। इस सिद्धांतके समर्थनमें आधुनिक इतिहासके उदाहरण भी देने चाहिए।

(४) यह सम्पादक इंडियन ओपिनियन, फीनिक्स नेटालके नाम भेजा जाना चाहिए और इस मासकी ३० तारीख तक पहुँच जाना चाहिए।

(५) प्रबंधकोको अधिकार होगा कि प्राप्त लेखोंमेंसे जिसे भी चाहे प्रकाशित करे, और उसका अनुवाद करे, और यदि कोई भी उपर्युक्त न प्रतीत हो तो सबको अस्वीकार कर दे।^१

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

१ उक्त घोषणा निम्नलिखित परिवर्धनके साथ ३०-११-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें दोहराई गई थी, ‘पूज्यपाद डॉ० जे० लैडो पीएच० डी० (बीएन) एम० ए० (केप) ने कृपापूर्वक इसका निर्णायक होना स्वीकार कर लिया है। इसके लिए जो समय दिया गया था वह बजाय ३० नवम्बरके, जैसा कि पहले घोषित किया गया था, ३१ दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। डॉ० लैडो चाहते हैं कि यह बात अच्छी तरह समझ ली जाये कि इसका निणय करनेमें वे सत्याग्रह के सिद्धांतके राजनैतिक प्रयोगके गुण दोषके विवेचनमें नहीं पड़ेंगे। उनका कृत य पूर्णतया प्राप्त निबंधोंके साहित्यिक और यथाय मूल्यांकन तक ही सीमित रहेगा।

किंतु उनके इनकार करनेपर उन निबंधोंको केन्द्रीय वपतिस्मा गिर्जाके पादरी पूज्यपाद जे० जे० डोक्लेने देखा और जनवरी १७ १९०८ को उनपर अपना निर्णय दिया, देखिए इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९०८।

परिशिष्ट ७

ब्रिटिश भारतीय सघ, जोहानिसबर्ग

मार्च १९०६ से अगस्त १९०७ तकके आय व्ययके हिसाबका सारांश

क	पौ० शि० पे०	ख	पौ० शि० पे०
नकद लन्दन समिति	२८० ६ ६	नकद नायडूसे	१८ ० ०
' तार	२७ १० ११	तमिल समाजसे	२० ० ०
" समुद्री तार	१९२ १ ९	" हिंदू समाजसे	२५ ० ०
" लिखतनस्टाइन और लैक्का		रैडर समितिसे	२० ० ०
ट्राम सन्ध धी मुकदमा आदि	८८ १६ १०	' हमीदिया इस्लामिया अजुमनसे	१४ ० ०
कागज पेंसिल पत्र, आदि	१ ३ ६	" सी० एस० ए० आर० ^१ से वापसी	१ ८ २
' अखबार जिनमे रोजाना 'केप		' रायटरसे वापसी	१ २ ६
गजट और प्रति सप्ताह 'इंडियन		" वेस्ट एण्ड हालके बाबत वापसी	१ १० ०
ओपिनियन की ३० प्रतियाँ लन्दन		" गुजरात हिंदू समाजसे	२२४ १० ९
समितिको भेजना शामिल है	१६ १४ ११	" अलीभाई आकूजी द्वारा एकत्रित	१७ ० ०
" टाइपिस्ट	४७ १० ०	नायडू व क० द्वारा एकत्रित	१ ४ ०
" प्रार्थनापत्रो आदिकी छपाई	४१ ११ ४	' एम० ई० गाट्टसे	० ८ ०
बैठकोके लिए सभा भवनोका भाड़ा	२४ १६ ६	" शिष्टमण्डलके हिसाबसे बचा	१६७ ९ ६
' टिकट	४ ७ ४	' सी० एम० वाल्वसे	३९ १० ०
' किराया (रेल्वे अनेक शिष्ट		' बैठकमें इकट्ठे किये	३० १० ०
मण्डलोके लिए)	२९ २ २	" ए० ए० पिल्लेसे	१ ० ०
अखबारी तार	२ ० ३	" आई० वी० टैमसे	० १० ०
' अलेक्जेंडर	० १० ६	" सुलेमान आई० मियाँ व क० से	१ १० ०
' फुटकर, जिसमें विज्ञापन आदि		" नानजी घेलासे	७ ० ०
शामिल है	२४ ८ ३	स्पेलोनकेनमे चन्दा	१० ० ०
पौड ७८१ २ ९		' व्याससे प्राप्त	० २ ४
		' पहले प्राप्ति स्वीकृत	१०८ १० ७
		' शेष उपलब्ध	९४ १७ ५
		पौड ७८१ २ ९	

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

आय व्ययका सक्षिप्त हिसाब

सितम्बर [१, १९०७] से नवम्बर २३, १९०७ तक

क	पौ० शि० पे०	ख	पौ० शि० पे०
विज्ञापन-शिष्टमण्डल तथा सब सम्बन्धी हिसाबमें	४ १५ ०	बचा पिछले हिसाबसे	९४ १७ ५
समुद्रो तार-प्रवासी विधेयक, दादाभाईके जम दिवसपर, प्रोफेसर गोखले व एस० बैनर्जीको तथा सम्राटके जम दिवसपर	१५ ७ ६	कुनबियो द्वारा नकद समग्र दूल्ह भागाके हत्ये	११ ० ०
जर्मिस्टन तथा प्रिटोरिया तक का किराया	३ ७ ८	कडक्टरने चेक नही भुनाह	० १० ०
सिन्हा वासा रगास्वामाके मामलेमें वकील ग्रेगोवस्कीको रायके लिये	२ २ ०	नकद चिंदेक भारतीयोसे	३३ १५ ९
समाचारपत्र-केप गवर्नमेंट गजट, 'लीडर' मेल तथा लन्दन समितिको प्रति सप्ताह इटियन ओपिनियन की ३० प्रतियाँ	१० १ ०	नकद [टान] अल्बर्ट व क० से	२५ ० ०
छपाई-के० डिकिन्सन व क० प्रार्थना पत्रकी छपाई तथा जिल्द बँधवाई	१४ १ ६	नकद जी० पो० नाससे-बाबत	१ ० ०
टिकट	३ ४ ८	प्रिटोरियाका किराया	१८ १५ ०
फुटकर	० १५ ५	सबके खातेसे नकद वापस	१३ ५ ९
तार-पण्डितके मुकदमे आदिके सम्बन्धमे	८ १२ ४	हिंदू समाजको कुरसियोकी बिक्री	१५ १ ३
टाइपिस्ट, सितम्बर व नवम्बरमें	१० ० ०	रस्टेनबर्गको सयुक्त सभा (युनाइटेड असेम्बली) से	२१३ ५ २
पहलेका शेष	१४० १८ १		
	२१३ ५ २		

[अग्रेजोसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

परिशिष्ट ८

ब्रिटिश भारतीय और ट्रान्सवाल

एल० डब्ल्यू० रिच

भूमिका

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंके एक संक्षिप्त विवरणकी माँग बार-बार की गई है, इसीसे इस विषयका एक संक्षिप्त इतिहास लिखनेका खयाल आया। इस मामलेमें लोगोंकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। उनके सम्मुख संक्षेपमें तथ्योंको रखनेका यह एक प्रयत्न है।

लेखक ट्रान्सवालमें अपने आगमनसे पूर्वके इतिहासके लिए सरकारी रिपोर्टोंका ऋणी है। पीछेके अठारह वर्षोंके तथ्य उसके अनुभूत तथ्य हैं।

इस लघु कृतिमें साहित्यिक योग्यताका कोई दावा नहीं है। इसकी शैली और रचना निस्सन्देह असत्य दोषोंसे युक्त है। उनके सम्बन्धमें लेखक पहलेसे अपना दोष स्वीकार करता है। केवल तथ्योंकी ओर सादर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

२८, क्वीन ऐन्स चैम्बर्स, एस० डब्ल्यू०

७-११-१९०७

ब्रिटिश भारतीय और ट्रान्सवाल^१

बीअर गणराज्यमें

ट्रान्सवालके भारतीय जिन नियोग्यताओसे पीड़ित हैं उनका इतिहास १८८५ से आरम्भ होता है जब महामहिम सम्राट्की सरकार और ट्रान्सवालकी गणतन्त्रीय सरकारमें झगड़ा शुरू हुआ था। उस समय यूरोपीय व्यापारियोंने जिनमेंसे बहुतसे न तो ट्रान्सवालके नागरिक थे और न तबतक ब्रिटिश प्रजाजन ही थे, अपने प्रतिस्पर्धी उन कथित अरब व्यापारियोंके विरुद्ध कानून बनानेके लिए ट्रान्सवाल सरकारपर दबाव डाला जिनमें से बहुतसे वस्तुतः ब्रिटिश भारतीय थे।

लन्दन समझौतेकी धारा १४ में कहा गया था कि वतनियोंके अलावा बाकी सब लोगोंको, जो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके कानूनका पालन करते हो

- (क) अपने परिवारों सहित दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके किसी भी भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने या रहनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी,
- (ख) मकानों, कारखानों, गोदामों, दूकानों और अन्य स्थानोंकी मिल्कियत रखने या उनको किरायेपर लेनेका अधिकार हागा, और
- (ग) स्वयं या कारखानोंके द्वारा जिनको वे नियुक्त करना ठीक समझें व्यापार व्यवसाय चलानेकी अनुमति होगी।

१८८५ में ट्रान्सवालके राज्य सचिवने (तत्कालीन उपनिवेश मंत्री) लॉर्ड डर्बाको पत्र लिखा कि उनकी सरकार प्राच्य देशीय लोगोंके जो प्रायः दूकानदार हैं और जो गणराज्यमें बस गये हैं, नियन्त्रणके लिए कानून बनाना चाहती है। उन्होंने महामहिम सम्राट्की सरकारसे इस सम्बन्धमें अपनी सम्मति व्यक्त करनेकी प्रार्थना की कि क्या उक्त धारा १४के अन्तर्गत ऐसा कानून बनाना विधानसम्मत् होगा।

तत्कालीन उच्चायुक्त सर हर्क्युलीज रॉबिन्सनने राज्य सचिवके पत्रकी पुष्टि इस सिफारिशके साथ की कि पूर्वोक्त धारा १४ में वतनियों शब्दको जगह 'आफ्रिकी वतनी या चीनी कुली प्रवासी' भर दिया जाये। इसमें खयाल यह था कि 'अरब व्यापारियोंके जो स्वार्थ स्थापित हो चुके हैं उनका सुरक्षित रखा जाये और गणराज्यके हीन वर्गके एशियाइयों जैसे कुली प्रवासियोंके विरुद्ध कानून बनानेकी स्वतन्त्रता दे दी जाये। फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्री सरकारने १८८५ का कानून ३, जो बादमें १८८६ में संशोधित किया गया, स्वीकृत किया। यह 'एक एशियाई' आदिम जातिके लोगोंपर लागू होता था। और उसके अन्तर्गत उन्हें

- (क) गणतन्त्रमें रहने या व्यापार करनेके अधिकार प्राप्त करनेके लिए ३ पौंड शुल्क देना आवश्यक था,
- (ख) नागरिक अधिकारके उपयोगसे वंचित कर दिया गया था,
- (ग) अपने नाम स्थावर सम्पत्ति खरीदनेकी मनाही थी, और
- (घ) केवल उन गलियों मुहल्लों और बस्तियोंमें रहनेकी अनुमति थी जिनका निर्देश किया जाये।

इसके विरुद्ध तुरन्त ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें सुनाई दी क्योंकि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य इस कानूनको बिना किसी भेदभावके गणराज्यमें रहनेवाले सब एशियाइयोंपर लागू करना अपना अधिकार मानता था। यह लाभग निश्चित है कि खास ट्रान्सवालमें भारतीय कुली कभी नहीं आये हैं। इसलिए १८८५ का कानून ३ अरब व्यापारियोंपर लागू करनेकी दृष्टिसे ही बनाया गया होगा और यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि ऊपर बताये गये ६ जनवरीके प्रस्तावपर मजूरी देनेमें साम्राज्य सरकार और गणतन्त्री सरकारका आशय एक न था।

साम्राज्य सरकारने बार बार कहा कि कानून ३ की 'यारया उस समझौतेके विरुद्ध है जिसके अन्तर्गत साम्राज्य सरकारने कानूनको पास करनेकी मजूरी दी और उससे लन्दनका समझौता भी भग होता है। इसके फलस्वरूप एक समझौता हुआ और गलियों मुहल्लों और बस्तियोंमें निवाससम्बन्धी धारामें शर्तके रूपमें "सफाईके उद्देश्यसे"

श द जोड़ दिये गये और इन ' सफाई के उद्देश्यसे निश्चित गलियो आदिमें स्थावर सम्पत्ति खरीदनेका अधिकार भी मान लिया गया । कि तु यहाँ फिर, "महामहिम सम्राटकी सरकारने यह समझा कि सशोधित कानून सफाई सम्बन्धी कानून है और इसलिष् यापारियो और उन अन्य यक्तियोपर लागू न किया जायेगा जिनका रहन सहन ऊँचा है, बल्कि कुलियोपर लागू किया जायेगा ।" * इसके अनुसार उसने सशोधित कानूनको मान लिया और लंदन समझौतेकी धारा १४ के उल्लंघनकी बात छोड़ दी ।

कि तु गणराज्य सरकार इस बातपर अडों रही कि कानून ' सब एशियाइयोपर समान रूपसे लागू हो इसलिष् उसने 'याख्या की कि निवास स्थान शब्दोंमें 'यापारकी और रहनेकी दोनों जगहें शामिल हैं । दोनों सरकारोंके बीच फिर बातचीत चली और उसके फलस्वरूप मामला पचको सौंप दिया गया । इसके परिणाम स्वरूप यह फैसला दिया गया ' गणराज्यकी सरकारको इस कानूनको पूर्ण तरह अमलमें लानेका पूरा अधिकार है । कि तु उसे सामान्यतः देशके यायालयोंकी एकमात्र और विशिष्ट 'याया माननी होगी । चूँकि यह मान लिया गया था कि इससे दो सरकारोंके बीचके विवादग्रस्त कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नका समाधान हो जाता है, इसलिष् यह फैसला मजूर कर लिया गया । किन्तु श्री चैम्बरलेनने भारतीय 'यापारियोंका ओरसे जिनके साथ उन्होंने सहानुभूति प्रकट की गणराज्यकी सरकारसे लिखा पढ़ी करने और सम्भव हो तो उसको यह विचार करनेके लिए निमन्त्रित करनेका अधिकार निश्चित रूपसे अपने पास रखा कि

' क्या स्थितिपर नये दृष्टिकोणसे पुन विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा । और क्या यह तय करना भी कि उसके अपने नागरिकोंके हितकी दृष्टिसे भारतीयोंसे अधिक उदारताका बर्ताव करना और प्रकटतः 'यापारिक ईर्ष्याको बढ़ावा देनेसे मुक्त होना अधिक अच्छा न होगा । उनके पास यह विश्वास करनेके कारण है कि यह 'यापारिक ईर्ष्या गणराज्यके शासक दलसे उत्पन्न नहीं हुई । *

१८९८ में ट्रान्सवालके सर्वोच्च यायालयने यह 'यायाकी कि निवास में 'यापार सम्मिलित है । फलस्वरूप तैयब हाजी मुहम्मद खॉ नामके एक ब्रिटिश भारतीयको अपने निवास और 'यवसायके स्थानके रूपमें प्रिटोरिया 'यागनेका नोटिस दिया गया और यह अप्रत्यक्ष रूपसे सब ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू होता था ।

दोनों सरकारोंके बीच आगे फिर पत्र व्यवहार हुआ । ट्रान्सवाल सरकार स्पष्ट रंग सम्बन्धी विचारोंके आधारपर कानून बनानेका प्रयत्न कर रही थी जैसा कानून ३ के अमलमें केपके रगदार लोगे और एशियाइयो की सम्मिलित करनेके प्रस्तावसे प्रकट होता है । दूसरी ओर साम्राज्य सरकारके प्रयत्नोंमें यह इच्छा प्रतिक्रियित होती है कि उन सबको, जो केवल कुली नहीं हैं, कानूनके अपमानजनक प्रभावोंसे बचाया जाये, श्री लिटिलटनके शब्दोंमें

" इसलिष् युद्धके आरम्भतक ब्रिटिश सरकारने पहले अधिकारके रूपमें और १८९५ के पच फौसलेके अनुसार कूटनीतिक प्रयत्नोंसे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोंके हितोंको कायम रखा, और इन सहप्रजाजनोंके प्रति 'यवहार भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके विरुद्ध ब्रिटिश मानलेका एक अंग था । *

लॉर्ड लेसडाउन और लॉर्ड सेल्बोर्नके भाषणोंसे जिनका अब ऐतिहासिक महत्व हो गया है, यह समझा जा सकता है कि अय प्रमुख राजनयिक ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोंके विरुद्ध भेदभावकारी कानूनको कैसा समझते थे । नये ट्रान्सवाल उपनिवेशके अपेक्षाकृत अधिक नये कानूनको ध्यानमें रखते हुए इन शब्दोंको दुहराना सम्भव ठीक होगा । मार्च १९०९ में शेफील्डमें भाषण देते हुए कहा था

' महारानीके भारतीय प्रजाजनोंकी खासी सरया ट्रान्सवालमें है । उनके विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके यंत्रहारसे मेरे मनमें जितना रोष उत्पन्न होता है उतना मैं नहीं जानता कि उसके किसी अन्य कुण्ठत्यसे उत्पन्न होता है । और इससे जो हानि होती है वह स्थानीय पीड़ितों तक ही सीमित नहीं है । जब ये गरीब लोग अपने देशको लौटेंगे और अपने मित्रोंको यह बतायेंगे कि महामहिम सम्राटकी सरकार जो ३० करोड़ आबादीके देश भारतमें ऐसी शक्तिशाली और दुर्धर्ष है दक्षिण आफ्रिकाके एक छोटे से राज्यसे उनकी शिकायत दूर करानेमें असमर्थ है तब आपके खयालसे भारतमें क्या प्रभाव होगा ?

* श्री लिटिलटनका वाइकाउट मिलनरकी पत्र जुलाई २० १९०४, सी० डी० २,२३९ ।

लॉर्ड सेल्बोर्न के विचार भी कम प्रभावकारी नहीं हैं

लॉर्ड महोदय ने प्रश्न किया है यह देखना हमारा कर्तव्य है या नहीं कि हमारे काले सहप्रवाजनों से ट्रान्सवाल में जहाँ उन्हें जानेका पूरा अधिकार है वैसा बताना किया जाये ऐसा व्यवहार करनेका महारानी हमारी ओरसे वचन दिया है ? यदि आप मुझसे सहमत हैं और यह मानते हैं कि हमें इन प्रश्नोंका उत्तर अपने देशवासियों और इतिहासके सम्मुख 'यासियोंके रूपमें देना है तो आप मुझसे इस बातमें भी सहमत होंगे कि कर्तव्यका पथ भावनासे नहीं बल्कि विशुद्ध तथ्योंसे नियंत्रित होना चाहिए हम समस्त ससारमें अपने बंधुओंके 'यासा हैं हम अपने विभिन्न जातियों और रंगोंके सह प्रवाजनोंके भी 'यासा हैं इन सबके ओर इनके बच्चोंके जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है । इसलिए हमें ऐसे सकटकालमें जैसा यह है जो कसौटी लगानी है वह कर्तव्यकी सीधी सादी कसौटी है । यह देखना हमारा कर्तव्य है या नहीं कि इन लोगोंके, जिनका हमने उल्लेख किया है अधिकारों और भावी हितोंकी रक्षा की जाय क्या ब्रिटिश सरकार अपने नामका मान रखेगी और जो वचन उसने दिये हैं उनको सचाईसे पूरा करेगी ? क्या वह यह देखेगी कि ब्रिटिश प्रवाजन चाहें ससारमें कहीं भी जायें और चाहें वे गोरे हों या काले उनको उनके वे अधिकार दिये जायेंगे जो उनकी महारानीने उनके लिए सुनिश्चित किये हैं ?

किन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए कि गणतन्त्रकी सरकारके शासनमें कानून ३ का अमल इतनी नरमीसे किया जाता था कि वह लगभग अमल न होनेके बराबर ही था । जब ३ पौंड शुल्क दे दिया जाता था तो उसकी रसीद अवश्य दी जाती थी और उस शुल्कके अंकित होनेसे ही पंजीयन हो जाता था, किन्तु उसको अमलमें लानेका गम्भीर प्रयत्न कभी नहीं किया गया । कुछ भी हो, वह केवल व्यापारियोंसे लिया जाता था और उनमें भी सबसे नहीं । किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात मुरात वर्तमान पंजीयन विवादकी देखते हुए यह है कि यद्यपि 'पंजीयन' शब्दका प्रयोग इस ३ पौंडी शुल्ककी अदायगी और वसूलीके सम्बन्धमें किया जाता था, किन्तु उसमें व्यक्तिगत शिंनारत जैसी कोई बात जो ट्रान्सवाल विलयके बाद उत्पन्न होनेवाली एक बिल्कुल नई बात है कभी नहीं होती थी । इसके अतिरिक्त दिलाईके साथ लगाये गये ३ पौंडके करके सिवा एशियाई प्रवासियोंपर कोई प्रतिबंध न था । इस सम्बन्धमें कप्तान हैमिल्टन फाउलकी, जो १९०३ में एशियाई पंजीयक थे रिपोर्ट ज्ञानवर्धक है । रिपोर्टमें कहा गया है कि

तीनको छोड़कर, एशियाईयोकी कोई पंजीका या उनके कोई अय कागजात, जो पिछली बोअर सरकारने रखे थे (यदि ऐसे कागजात कभी रखे गये हों तो) किसी जिलेमें नहीं मिले ।

ट्रान्सवालके वे ब्रिटिश भारतीय जिनमें से अधिकतर निस्सन्देह युद्धकालमें देशसे चले जानेके लिए बाध्य कर दिये गये थे प्रिटोरियापर ब्रिटिश ध्वज लहराते ही इस्मीनानके साथ कानून ३ का वापसकी आशा करते थे । यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । सचमुच अपनी ब्रिटिश नागरिकताके कारण वे बोअरोंके कानूनके कई तत्त्व समझ परिणामोंसे बच गये थे, किन्तु कानून ३ फिर भी परेशान करता था क्योंकि उसने उनपर हीनताका छाप लगा दो था और सिद्धांततः ही सही उनको केप और नेटालमें जहाँ से उनमेंसे बहुतसे लोग आये थे, जो दर्जा प्राप्त था उससे उनका दर्जा नीचा कर दिया था ।

यद्यपि १८८५ के कानून ३ की जिस वारसे भारतीयोंका नागरिकताके अधिकार प्राप्त करनेसे वंचित किया जाता था उसका निस्सन्देह कठोरतासे अमलमें लाया जाता था तथापि उनको उन गलियों, मुद्दलों और बस्तियोंमें, जिनका निर्देश किया जाये, हटानेकी बात गणतन्त्रीय सरकारके शासनमें कभी लागू नहीं की गई ।

विलयके बाद

ट्रान्सवाल विलयका सबसे पहला प्रभाव जो ब्रिटिश भारतीयोंपर हुआ, उन एशियाईयोका निष्कासन था जो यह न सिद्ध कर सकें कि वे युद्ध पूर्वके वैध अधिवासी हैं । १९०२ में नई सरकारने "सुव्यवस्था और सुशासन एवं सार्वजनिक सुरक्षाको कायम रखने" के लिए शान्ति रक्षा अध्यादेश (१९०३ के कानून ५ द्वारा संशोधित रूपमें १९०२ का ३८वाँ कानून) के नामसे एक कानून बनाया । फौजी शासन वापस ले लिया गया था और

रान्द्राह एव देशद्रोहक विरुद्ध नया अध्यादेश लागू कर दिया गया था । १९०३ के सशोधनके अनुसार उपनिवेशमें जो लोग आये उन सबके लिए परवाने लेनेका नियम था । उसकी आवश्यक शर्त थी कि ये परवाने उन नागरिकोंका नहीं दिये जायेंगे जो राजभक्तिकी शपथ न ले सकें । इससे पर्याप्त रूपसे प्रकट हो जाता है कि अध्यादेशका उद्देश्य क्या था । किंतु इस नये कानूनका प्रयोग भारतीय प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमके रूपमें किया गया । देशके इतिहासमें पहली बार एक एशियाई विभागकी स्थापना की गई । परवाने देनेमें अनुचित कार्रवाई और अष्टाचारके परिणामस्वरूप दो प्रवात अधिकारियोंपर मुकदमे चलाये गये और उसके बाद एशियाई विभाग भंग कर दिया गया । उसका काम मुख्य परवाना अधिकारीकी सौंप दिया गया एव अतः एशियाई सरक्षक नामका एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया । १९०२ में उच्चायुक्तने उपनिवेश मंत्रीको ट्रान्सवाल सरकारके कुछ विधिवत् प्रस्ताव तारसे भेजे । इनमें ये प्रस्ताव थे कि सब एशियाई चाहे वे तब ट्रांसवालमें रहते हों या बाहरमें प्रविष्ट हुए हों पचीस प्रमाणपत्र लें और ये प्रमाणपत्र ३ पौंड देकर प्रति वर्ष नये कराये जाय, ऐसे पजीकृत एशियाई (यदि यूरोपीय मालिकके साथ न रहते हों तो) अपने लिए विशेष रूपसे व्यापार और निवासके निमित्त निश्चित की गई बस्तियोंमें चले जायें, शिक्षित और सभ्य एशियाई पजीयनसे मुक्त हों एशियाइयोंको शहरी क्षेत्रोंमें वास्तविक जमान जायदाद खरीदने और रखनेका अधिकार हों । इन प्रस्तावोंका उत्तर उपनिवेश मन्त्रीने यह दिया

इसका समर्थन करना असम्भव है, यह तो लगभग दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी प्रणालीकी जारी रखना होगा जिसके विरुद्ध महामहिम सम्राट्की सरकारने बार बार इतनी जोरदार आपत्ति की थी । *

१९०३ में ट्रांसवाल सरकारने भारतसे १० ००० कुली मँगानेके लिए कुछ प्रस्ताव किये जिसे भारत सरकारने इस शर्तपर मान लेनेका वचन दिया कि ट्रांसवालमें इस समय जो भारतीय रहते हैं उनको प्रभावित करनेवाला वर्तमान नियोग्यताएँ हटा दी जायें ।

इसी वर्ष उच्चायुक्तने उपनिवेश मंत्रीको एक अय खरीता भेजा और उसके साथ सरकारी नोटिसकी एक प्रति भी भेजी । नोटिसमें कहा गया था कि सरकारने १८८५के बोअरोक बनाये गये कानून ३ की उस धाराको लागू करनेका निश्चय किया है जो एशियाइयोंकी विशेष गलियों सुहल्लो और बस्तियोंमें हटानेके सम्बन्धमें है इनमें केवल एशियाई ही रह सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे एशियाइयोंकी इन बस्तियोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें व्यापार करनेके परवाने न दिये जायेंगे, निन एशियाइयोंके पास युद्धसे पूर्व इन (एशियाई) बाजारोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने थे, उनके परवाने उन्ही शर्तोंपर उपनिवेशमें वे जबतक रहे तबतक नये किये जा सकते हैं, किन्तु वे हस्तांतरित नहीं किये जा सकेंगे, शिक्षित और सम्मानित एशियाई इन सब प्रतिबंधोंसे मुक्त होंगे । वर्तमान नियोग्यताओंमें ये परिवर्तन प्रत्यक्ष है, भारत सरकारको सन्तुष्ट करने और उसे ट्रांसवालके सार्वजनिक कामोंके लिए कुली मन्दूर मँगानेकी मजूरी देनेके लिए राजी करनेके उद्देश्यसे किये गये थे । ट्रान्सवाल सरकारने इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव किया था कि प्रवासका नियंत्रण केंप और नेटालमें लागू कानूनोंसे मिलते जुलते कानून द्वारा किया जाये और अधिनियमके अन्तर्गत लागू की गई शिक्षा परीक्षामें भारतीय और यूरोपीय भाषाएँ स्वीकार की जायें । यह सुझाव भारत सरकारने भेजा था । किंतु ट्रान्सवाल सरकारने आगे विचार करनेपर अपना यह अंतिम प्रस्ताव वापस ले लिया और समय आनेपर उसका विरोध किया । उसने विकल्पके रूपमें यह सुझाव दिया

(क) केंप और नेटालके अधिनियमोंके आधारपर प्रवासी प्रतिबंधक कानून बनाया जाये जिसमें अन्य बातोंके साथ साथ भावी प्रवासियोंके लिए शिक्षा परीक्षाकी व्यवस्था हो, किंतु इसके लिए भारतीय भाषाएँ स्वीकार न की जायें,

(ख) भारतीयोंके सम्बन्धमें सरकारके नोटिस (१९०३ का ३५६) के आधारपर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है एक कानून बनाया जाये । इसमें यह व्यवस्था हो

(१) वे एशियाई जो उपनिवेशिक औपनिवेशिक सचिवको यह सतोष दिला सके कि उनके रहन सहनका तरीका यूरोपीय विचारोंके अनुसार है, अपने नौकरो सहित बस्तियोंके बाहर रहने दिये जायें, किन्तु उनको बस्तियोंके बाहर यापार न करने दिया जाये बशत कि वे (२)के अतगत न आते हो,

(२) जो एशियाई युद्धसे पूर्व बस्तियोंके बाहर अपना व्यवसाय जमा चुके थे उनको न छेड़ा जाये,

(३) उक्त दो अपवादोंके अतिरिक्त सब एशियाईको के लिए बस्तियोंमें यापार करने और रहनेका नियम हो, एवं उनके लिए बाहर जमीन खरीदना निषिद्ध हो यह व्यवस्था उस जमीनपर लागू न हो जो अलग कर दी गई है और धार्मिक कार्योंके लिए प्रयुक्त होती है,

(४) ट्रांसवालमें आनेवाले सब एशियाई जबतक उनको विशेष रूपसे मुक्त न किया जाये, ३ पौंड देकर पंजीयन प्रमाणपत्र लें,

(५) यदि ऊपर बताया गया प्रवासी कानून पास न हो तो फेरीवालोंको परवाने देनेपर कोई रोक न लगाई जाये ।

इसके उत्तरमें उपनिवेश मन्त्रीने उन ब्रिटिश भारतीयोंमें जो इस समय ट्रांसवालके अधिवासी हैं, और जो भविष्यमें आयेगे अन्तर किया । उन्होंने सावजनिक स्वास्थ्यको रक्षाके लिए आवश्यक बुद्धि सगत सावधानियोंके अतिरिक्त अब सब कारवाइयोंकी निन्दा की और यह निर्देश किया

‘ इस समय देशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है और प्रवासपर प्रस्तावित प्रतिबंधोंके अन्तर्गत कम होती जायेगी, इसलिए उनसे आशंकित यापारिक स्पर्धा प्रस्तावित कानूनकी बनानेका पर्याप्त कारण नहीं मानी जा सकती । महामहिम सम्राट्की सरकारने भूतकालमें लगातार यह प्रयत्न किया है कि उसके विचार इस भयसे प्रभावित न हो । इसके विपरीत उसने इस सम्बन्धमें पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी नाति और उसके कानूनोंके विरुद्ध साम्राज्य और सम्य सत्तारके समुख बारबार विरोध किया है । दरअसल वे अशत ही लागू किये गये थे । किन्तु अब महामहिम सम्राट्की सरकारसे उनको केवल कड़ाईसे लागू करनेकी माँग ही नहीं की जा रही है बल्कि कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालयके उस निर्णयको भी रद्द करनेके लिए कहा जा रहा है जिससे ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार दिये गये हैं जिनके लिए महामहिम सम्राट्की सरकारने अत्यन्त सवर्ष किया है । महामहिमकी सरकार यह मानती है कि अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंपर ऐसी नियोग्यताएँ लागू करना जिनके विरुद्ध हमने आपत्ति की थी और जिन्हें यदि ठीक व्याख्या करें तो पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यने भी उनपर लागू नहीं किया था, हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके विरुद्ध है । इस सरकारको इसमें कोई सदेह नहीं है कि जब यह बात ध्यानमें आयेगी तो उपनिवेशका लोकमत इस माँगका समर्थन करेगा जो प्रस्तुत की गई है ।

इसलिए दूसरा प्रस्तावित अध्यादेशसे जो १८८५ के कानून ३ का स्थान लेगा, उनके बस्तियोंके बाहर व्यापार करनेके अधिकारोंमें हस्तक्षेप न होना चाहिए जो इस समय देशमें है । जमीन खरीदनेके प्रश्नके सम्बन्धमें, जिन ब्रिटिश भारतीयोंको बस्तियोंसे बाहर रहनेका अधिकार है उनको कमसे कम उन स्थानोंमें जायदाद लेनेका अधिकार होना चाहिए जिनपर व्यवसायके निमित्त उनका कब्जा है ।

उन्होंने दूसरे प्रश्न अर्थात् भावों प्रवासियोंके प्रश्नपर कहा

‘ महामहिम सम्राट्की सरकारका अत्यन्त खेद है कि साम्राज्यक भीतर ब्रिटिश भारतीयोंके स्वतन्त्र आवागमनको रोकनेकी आवश्यकता है, इसलिए वह अनुभव करती है कि वह ट्रांसवालकी विधान परिषदमें उन कानूनोंके आधारपर प्रवासपर प्रतिबंध लगानेका कानून अभी पेश करनेके बारेमें लगाई गई अपनी रोक वापस नहीं ले सकती । ” यह निश्चित प्रतीत होता है कि जो लोग अब भी प्रस्तावित प्रवासी प्रतिबंधक अध्यादेशकी हदमें आते हैं, और वे बहुत कम होने चाहिए, वे निम्न वर्गके एशियाई न होंगे, और इसलिए ऐसे लोग न होंगे जिन्हें सफाईके ख्यालसे विशेष बस्तियोंमें रखा जाना जरूरी हो । मेरी रायमें जबतक यह सिद्ध न हो कि प्रवासी प्रतिबंधक अध्यादेशसे प्रवासियोंकी बाढ़ न्यूनतम

नहीं हो सकी है नसी उसते होनेकी आशा की जाती है, तबतक, और यह देखते हुए कि केप कालोनी या नेटालमें तो वैसा कानून बन नहीं रहा है, वर्तमान अधिवेशनमें जो अध्यादेश पास किया जाता है उससे नवागंतुकोका व्यापार सम्बन्धी अधिकार कम नहीं किया जाना चाहिए । *

यह बताना शायद आवश्यक हो कि करीब करीब १९०३ के अलीरम प्रिटोरियाक एक व्यापारी हबीब मोटने 'निवास स्थान' शब्दोंके सम्बन्धमें १८८५ के कानून ३ की पहले जो व्यापारी की गई थी उसपर न्यायालयसे अपने पक्षमें निर्णय प्राप्त किया था । नये निर्णयका प्रभाव यह हुआ कि एशियाइयोंको बस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेका (किंतु रहनेका नहीं) अधिकार मिल गया ।

इसी वर्ष ट्रान्सवाल सरकारने निर्णय किया कि १८८५ के कानून ३ की ३ पैरा प्रवेश शुल्ककी अदायगीसे सम्बन्धित धारा कड़ाईसे लागू की जाये । इसका नतीजा यह हुआ कि ५,०६६ भारतीयों और ५१५ चीनियोंसे १६,७४३ पैरा वसूल किये गये, क्योंकि ये लोग अधिकारियोंको यह विश्वास न दिला सके कि उन्होंने पहले गणराज्यकी सरकारको वह शुल्क अदा कर दिया था । इसी प्रकार समस्त एशियाई वर्गके पुनः पंजीयनका निश्चय किया गया, किंतु भारतीयोंने इसपर आपत्ति की । उनका कहना था कि वे पहले ही कानूनके अनुसार कार्रवाई कर चुके हैं । किंतु उच्चन्यायिकोंने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी आपत्तियोंपर आग्रह न करें । उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि पंजीयनसे उनकी रक्षा होगी । उन्होंने यह भी कहा कि

एक बार पंजीकामें नाम दर्ज होनेपर उनकी स्थिति मजबूत हो जायेगी और उसके बाद पंजीयनकी आवश्यकता न होगी, और न उहें नया पत्रवाना लेना होगा । इस पंजीयनसे उनको यहाँ रहनेका अधिकार मिल जायेगा और साथ ही आने और जानेका अधिकार भी ।

चूंकि भारतीय समझौतेके लिए सदा उत्सुक रहते हैं और उन्हें ब्रिटिश उच्चन्यायिक जैसे ऊँचे अधिकारियोंके वचनपर विश्वास भी था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया । जो नये प्रमाणपत्र दिये गये उनमें ये बातें थी प्रमाणपत्रोंके मालिकोंके नाम, जन्म स्थान और धर्म । इसके पहलेका पता और हस्ताक्षर, उनकी पत्नियोंके नाम, बच्चोंकी संख्या, प्रमाणपत्रोंके मालिकोंकी उम्र उनकी विशेष हुलिया और अगूठा निशानियाँ ।

इस प्रकार 'पंजीयन' पहले तो एशियाइयोंकी जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी थे शिनायतका एक तरीका हो गया, किंतु वह अमीतर ऐच्छिक पंजीयन था । वह भेदभावकारी कानूनसे लागू नहीं किया गया था जैसा वह उसके बाद १९०७ के एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके रूपमें लागू किया गया है ।

एशियाई कानून सशोधन अध्यादेश (१९०६ का कानून २९) जो बादमें ट्रान्सवालकी उत्तरदायी सरकारने फिर बनाया ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेको कम करनेकी दिशामें अगला कदम था । इसके अंतर्गत एशियाइयोंके पंजीयनसे सम्बन्धित १८८५ के बोअर कानून ३ की धारा २ का खण्ड-ग रद्द कर दिया गया है । इस धाराके अनुसार उन 'एशियाइयोंकी ही पंजीयन कराना लाजिमी था जो एशियाक किसी बतनी जानिके लोग थे और 'गणराज्यमें व्यापार करनेके लिए या अन्य उद्देश्यसे बसना चाहते थे । इनमें कथित कुली अरब, मलायी और तुर्की राज्यके मुसलमान सम्मिलित थे । उन्हें 'पंजीयन' गणराज्यमें प्रवेशके बाद आठ दिनोंके भीतर कराना था और जो लोग गणराज्यमें इस कानूनके लागू होनेसे पहले आबाद हो चुके हैं उनको इसका कोई पैसा नहीं देना था । इस प्रकार 'एशियाइयोंके' प्रवासपर कोई प्रतिबंध न था, बल्कि केवल तभी ३ पैरा शुल्क देना और 'पंजीयन कराना' आवश्यक था जब प्रवासी बसना चाहे । इस उपखण्डको रद्द करनेसे एशियाइयोंका इस रकमके बदले ट्रान्सवालमें प्रवेशका निहित अधिकार समाप्त हो गया । यह स्मरणीय है कि अंग्रेजोंका अधिकार होनेके बादसे शान्ति रक्षा आध्यादेशका प्रयोग एशियाइयोंको अवाञ्छनीय प्रवासी मान कर प्रवेशसे रोकनेके लिए प्रभावपूर्ण ढंगसे किया गया है ।

अब उपनिवेशक सभी वैध निवासी एशियाई १९०७ के कानूनसे नये सिरेसे पंजीयन कराने के लिए पश हाने, एशियाई पनायकको उपनिवेशमें अपने रहनेके अधिकारके सम्बन्धमें सतृप्त करने और यदि उसमें सफल हो जाय तो जा कानून छोटा छोटा बातोंमें इतने अपमानकारी ढङ्का है कि उसके कारण अबतक नम्रतासे रहनेवाले लोगोको खुला विद्रोह करना पड़ा है उससे सलस नियमोके अन्तर्गत दी हुई विधिसे निजा जौच बरांके लिए बा व है । प्रार्थानो अपना पूरा नाम प्रजाति जाति या सम्प्रदाय आयु हुलिया निवास स्थान धधा, जम स्थान, ट्रान्सवालमें पहली बार आनेकी ताराख, ३१ मई १९०२ को जहाँ थे उस स्थानका नाम, पिताका और माँका नाम पत्नाका नाम बेटे और आठ वर्षसे कम आयुके आश्रित बालक उनके नाम उनकी आयु और सरक्षकके साथ उनका सम्बन्ध, यह सब "घोरा देना लाजिमो होता है । इसके अतिरिक्त उसको अपने दोनो हाथोके अंगूठे, अपनी तन्ना म यमा, अनामिका और कनिष्ठिका अंगुलियोकी निशानियाँ और प्रत्येक हाथको चारो अंगुलियोका एक साथ निशानो देनेका नियम है । इसका अर्थ यह है कि एशियाई अधिवासियोके वर्तमान अधिकार, जो उन्हें ट्रान्सवाल सरकारके अधीन मिले थे और जिनके सम्बन्धमें लॉर्ड मिलनरने १९०३ में फिर आश्वासन दिया था बिना विचारे अवैध कर दिये गये थे और उनकी सत्यता पुन सिद्ध करनेका भार उनके मालिकोपर डाल दिया गया है । उच्चायुक्तकी सलाहपर स्वेच्छासे लिये गये पंजीयन प्रमाणपत्र लौटा दिये जाने चाहिए और उनके स्थानपर दूसरे प्रमाणपत्र ल लेने चाहिए । ये दूसरे प्रमाणपत्र सोलह वष या अधिक आयुके प्रत्येक एशियाईको सदा साथ रखने चाहिए और उपनिवेशमें कानून द्वारा सस्थापित पुलिस दलके किसी भी सदस्य या उपनिवेश सचिव द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्तिके माँगनेपर दिखाने चाहिए । आठ वर्षसे अधिक आयुके सब कानूनी अधिवासी एशियाइयोके लिए पंजीयन अनिवार्य है और सोलह वर्षसे कम आयुके ऐसे प्रत्येक बच्चेके सरक्षकको ऐसा न करनेकी अवस्थामें १०० पौंड जुर्मानिका या तान मासका कड़ी कैदको सजा दी जा सकती है । उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायत है कि ट्रान्सवाल गणराज्यके भेदभावकारी कानूनके कारण उनके दर्जेमें जो कमी हुई थी वह ब्रिटिश उपनिवेशमें बनाये गये इस कानूनके अन्तर्गत होनेवाली वर्तमान अप्रतिष्ठाकी तुलनामें कुछ नहीं है । उनका कहना है कि उससे उनपर सदाके लिए हीन और अवाछनीय होनेकी छाप लग जाती है । तब व ऐसे अविश्वसनीय मान लिये जाते हैं कि उन्हें सदिग्ध और अपराधी व्यक्तियोके समान अपनी शिनाख्त करने और निगरानोंमें रहनेको आवश्यकता होती है । यह स्मरण रहे कि यह अधिनियम उपनिवेशके वैध निवासी ' एशियाइयो पर लागू होता है और केवल वे एशियाई जो ट्रान्सवालमें उसके विलयसे पहले बस चुके थे ' वैध निवासी ' है । इस कानूनको उसके निर्माताओने इस आधारपर आवश्यक बताया था कि उनके कथनानुसार देशमें भारतीय बड़ी संख्यामें अवैध रूपसे आ रहे हैं । अधीतक ऐसी बड़ी सरयामें प्रवेशका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । जब सन् १९०३ के अन्तमें तत्कालीन एशियाई पंजीयक कप्तान हैमिल्टन फाउलसे इस कथित अवैध प्रवेशके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण माँगा गया था तो उन्होंने उत्तर दिया था ' यह विश्वास करनेका कोई कारण नहीं है कि एशियाई लोग उपनिवेशमें अनधिकृत रूपसे आ रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया था कि १९०३ के प्रारम्भमें एशियाई बड़ी सरयामें आवश्यक अधिकारपत्रक बिना प्रवेश करनेमें सफल हो गये थे, किन्तु वे तुरन्त गिरफ्तार कर लिये गये थे और निर्वासित कर दिये गये थे । उन्होंने आगे कहा था ' किसी अनधिकृत एशियाईका उपनिवेशमें बिना गिरफ्तार हुए अधिक समय तक रहना लगभग अममभव है । ' इससे ताजा श्री चेम्बेनेकी रिपोर्टमें चोरीसे प्रवेशका अनिश्चित और अविश्वसनीय आरोप है और स्पष्ट है कि उसके पीछे उस समय अध्यादेश लागू करनेके ओचित्यको मिट्ट करकेका खयाल था । मन्त्रेपमें यह बताती है कि " ३१ दिसम्बर १९०६ को समाप्त होनेवाले वर्षमें ३७५ ऐसे एशियाइ पुरुष उपनिवेशमें आये या रहते हुए पाये गये जिनके पास निवसित प्रवेशपत्र नहीं थे । " इससे इनकार नहीं किया गया है कि ये ' अवैध प्रवासी ' सम्भवत १९०२ के बादके चार वर्षोंमें किसी भी समय आ गये होंगे । और यह महत्वपूर्ण बात है कि उनमेंसे केवल २१३ मामलोंमें न्यायाधीशोंके सम्मुख अभियोग चलाये गये और उनकी सजाएँ दी गई ।

"खासी संख्यामें अवैध भारतीय प्रवास" की जो चिल्लाहट की गई और उसके साथ जो ये आरोप लगाये गये कि अधिवासी एशियाई और चोरीसे देशमें आनेके इच्छुक लोगोकी मिलीभगत है, उनके उत्तरमें

भारतीय नेताओं ने बार बार अपील की कि एक जाँच आयोग की नियुक्ति की जाये और यदि कोई सन्देह वस्तुतः हा तो उनका उस जाँच से सदाके लिए निराकरण करा दिया जाये। किसी अज्ञात कारणसे इस बहुत ही विवेकपूर्ण सुझाव की लगातार उपेक्षा की गई है।

नये पजीयन अधिनियम की आवश्यकता और पर्याप्तता का अंदाज करते समय यह स्मरण रखा जाये कि शान्ति रक्षा अध्यादेश, जिसके द्वारा कप्तान हैमिल्टन फाउल नये एशियाइयों के प्रवेश को प्रभावपूर्ण ढंग से रोक सके, अब भी अमल में आ रहा है और उसके अंतर्गत अवैध प्रवेशकर्ताओं को भारी सजाएँ दी जाती हैं, पुनः प्रवेश के लार्थ एशियाई तबतक उपनिवेश के बाहर रोक रखे जाते हैं जबतक उनके पुनः प्रवेश के अधिकार की कड़ी खोजबीन नहीं कर ली जाती। तर्क के लिए मान लीजिए यदि इस तरह चोरी से अधिक सरयामें प्रवेश होता है जैसा बताया जाता है तो उसको रोकने के लिए नये कानूनमें कोई अतिरिक्त साधन नहीं दिया गया है। कानून से केवल वैध अधिवासी एशियाइयों पर छाप लगाई जाती है। इससे अनधिकृत प्रवेशकर्ता पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है कि देश में चोरी से आने के बाद उसका पता लगा जायेगा, किंतु इससे यह मान लिया जाता है कि अपराधी शिनारत के लिए बुलाये जाने पर पेश हो जायेगा। यदि वह ऐसा न कर सके तो पजीयन अधिनियम के अंतर्गत उसका पता लगाने के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता जितना शान्ति रक्षा अध्यादेश के अंतर्गत किया जा सकता था, और तब केवल शस्त्र यह रह जाता है कि जिनके पास नया पजीयन प्रमाण पत्र न हो उन्हें व्यापारिक प्रमाण न दिये जायें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि थोड़े से चोरी से आने वाले लोगों को खोज निकालने के लिए वैध अधिवासी भारतीयों के समुदाय पर — जिसमें व्यवसायी, छोटे व्यापारी वीबी आदि अच्छी ख्याति वाले और देश में बहुत समय से रहने वाले लोग हैं हीनता की छाप लगा दी जायेगी और उनका दर्जा प्रतिबंधों के साथ रिहा अपराधियों का बना दिया जायेगा। सदृश अपराध का पता लगाने में सुविधा देने के लिए निरपराध लोग कष्ट भोगेंगे।

अधिनियम का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए उसके साथ अपमानजनक नियम जोड़ दिये गये हैं और उनको जो प्रमुखता दी गई है उसका प्रयोग भारतीयों की मुख्य दलील की ओर से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। उनकी भावुकता के सम्बन्ध में अत्युक्ति की जाती है और उसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि उनसे एक कागज पर अंगुलियों के निशान माँगने पर ही उनकी अपनी भावना का तिरस्कार अनुभव होता है। यद्यपि वकील, डॉक्टर प्रसिद्ध और पुराने व्यापारी और वैसे ही सच्चरित्र फेरिष भी सम्भवतः इस प्रकार अपमानजनक ढंग से की जाने वाली बारीक और व्यक्तिगत शिनास्त को, जो उनकी ईमानदारी और सुरायाति पर गम्भीरतम लालच लगाती है अकारण ही आक्षेपजनक मानते हैं ऐसा नहीं है तथापि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विनियम — स्वयं भले ही अप्रिय हो — किन्तु वे केवल आकस्मिक माने जाते हैं और ब्रिटिश भारतीयों ने जो आपत्ति की है उसका मूल कारण उसके अमल की तफ्ती में नहीं बल्कि स्वयं अधिनियम ही है। ऐसा पहले कहा जा चुका है, भारतीय कानून की मान लेने से यह समझते हैं मानो ब्रिटिश भारतीयों के इस विशेष भाग पर अनिवार्य कानूनी छाप लगा देने से उनका जातीय दर्जा गिर गया हो। ट्रांसवाल ब्रिटिश भारतीयों के अध्यक्ष श्री ईसप इस्माइल मियाने सार रूप में मामले को इस प्रकार पेश किया है

“यदि अंगुलियों की निशानियों की जगह हस्ताक्षर कर दिये जाते तो भी मेरे सचका रूप किसी प्रकार बदल न होता। अधिनियम में बाध्यता का जो डक समाया है उसी से समाज में इतना रोष उत्पन्न होता है और उसे वह इतना दुस्सह लगता है। उसमें जो सजा और कठोरता है उस पर रोष प्रकट नहीं किया जाता, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई उस मान्यता पर किया जाता है कि समस्त भारतीय समाज ही अपना व्यक्तित्व छिपाने में और इस देश में चोरी से अनधिकृत प्रवासियों को लाने में सक्षम है। सबसे अधिक आपत्ति इस बात पर की जाती है, और मेरा खयाल है कि यह उचित ही है। यह भली भाँति जानते हुए कि ब्रिटिश भारतीय एक वर्ग के रूप में ऊपर बताये गये कार्यों के अपराधी नहीं हैं, वे मर्दानगी के साथ उस मान्यता से बचने के लिए मग्न करते हैं जो कानून में निहित है और जिसकी घोषणा कानून के निर्माता अपने विश्वास के रूप में खुल्लम खुल्ला करते हैं।

इस सिद्धांतकी रक्षाके लिए अपनी व्यक्तिगत और जातीय प्रतिष्ठाकी कायम रखनेक उद्देश्यसे महामहिम सम्राट्के लगभग १३ ००० राजमवल प्रजाजन गम्भीरतापूर्वक जेल जाने और अपनी सासारिक सम्पत्तिकी एवं स्वयं स्मृत तत्ताकी भी हानि सहनेकी शपथ ले चुके हैं। प्रायः यह व्यस्य किया जाता है कि भारतायाम अपनी दूकानों और अपने लाभके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं होती। क्या इस यका इससे अधिक ज़ोरदार काइ दूसरा उत्तर दिया जा सकता है?

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक एशियाई विरोधी कानूनाक रूपमें ट्रांसवालकी नवीनतम उपज है। जा शांति रक्षा अ वादेश मुद्रवस्था और सुशासन एवं जन पुरस्कारों कायम रखनेक लिए सनिक कानूनकी वापसीकी यानम रखकर बनाया गया था, उसको एक ऐसे ब्रिटिश उपनिवेशकी जहाँ अब वे मन्नी राज्य करते हैं जो अभी कुछ पहले हमसे लड़ रहे थे विधान संहितामें कायम रखना असंगत है और इसी असंगतिक कारण उसका जल्दी रद्द किया जाना आवश्यक हो गया। यह कार्य प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकक एण्ड (१) से सम्पन्न हाता है, किन्तु इस खण्डके अन्तमें यह यान देने योग्य शर्त है

१९०७ क एशियाई कानून सशोधन विधेयकसे ऐसे कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र रद्द या कम न होंगे जो उस अधिनियमकी 'कायरूप देनेक उद्देश्यसे दिये गये हैं, बल्कि उक्त अव्यादेश उस अधिनियमके सब उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए पूर्णतः लागू माना जायेगा।

दूसरा शब्दमें शान्ति रक्षा अध्यादेशकी शत केवल एशियाइयोपर लागू करनेक लिए कायम रखी गई हैं।

इस विधेयकसे पजीयन कानूनकी स्वायत्तत्व मिलता है। उसमें उन ब्रिटिश भारतीयोंके निवासके अधिकारकी उपेक्षा का है जो युद्धसे पूर्व ट्रांसवालमें बस गये थे और जिनमेंसे बहुतसोंने १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत उस निवासके मूल्यके रूपमें ३ पौंड भी दे दिये थे, किन्तु जो किसी न किसी कारणसे अभी देशमें नहीं लौटे हैं।

इसमें देशमें प्रवेशको योग्यताएँ बताते हुए शिक्षा परीक्षाके रूपमें यूरोपीय भाषाओं और यहूदी भाषा यीडिशके अतिरिक्त अन्य सब भाषाओंको छोड़ दिया है।

इसके अनुसार उन भारतीय प्रवेशार्थियोंकी भी जो विधेयकमें दो हुई परीक्षाम उचीण हवा जाय एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत पजीयन कराना होगा — उस एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत जिसके पजीयन सम्बन्धी नियम प्रकट अधिकांश देशवासी एशियाइयोंकी कल्पित निरक्षरताके कारण बनाये गये थे।

विधेयकके विरोधी बहुत सी युक्तियोंके साथ यह तर्क देते हैं कि जो भारतीय यूरोपीय भाषा शिक्षा परीक्षा पास करने योग्य पर्याप्त रूपसे जानते हैं वे भी अपने साथ शिनामत्तके काफी निशान रख और चूकि सांस्कारिक शिक्षण प्राप्त किसी भी भारतीयका उसकी शर्तोंकी मानना कल्पनागम्य नहीं है यह नियम भारतीयोंका विधेयककी शिक्षा सम्बन्धी धाराके लाभसे वंचित करने और इस प्रकार उनको देशमें आनेसे रोकनेका एक अप्रत्यक्ष तरीका है।

विधेयकमें उन भारतीय व्यापारियोंको जो ट्रांसवालमें बस गये हैं अपने मुनाम मद्दायक और अपने व्यवसाय और घरेलू कामकाजको चला देनेके लिए आवश्यक नौकर लानकी सुविधाएँ देनेको कोर व्यवस्था नहीं है। खण्ड (द) के उपखण्ड (ग) में एशियाई कानून सशोधन अधिनियममें अप्रत्यक्ष सुधार करनेका एक चालाकी भरा प्रयत्न किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है। अधिनियममें कानूनकी न माननेवाले एशियाइयोंका उपनिवेशसे जानेका नोटिस देनेक बाद जुर्माने और कैदकी सजाएँ देनेकी व्यवस्था है वैसे ही शांति रक्षा अध्यादेशमें ऐसा ही देशसे जानेका नोटिस देनेका अधिकार दिया गया है। इस विधेयकके उपखण्ड (ग) में इन दोनोंसे आगे बढ़कर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसमें स्थानीय सरकारको किसी भी व्यक्तिकी, जो एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत दिये गये नोटिसको भग क उसक खचपर जखरदस्ती निर्वासित करनेका अधिकार दिया गया है। इस कानूनके वास्तविक स्वरूपका तबतक उचित रूपसे नहीं समझा जा सकता जबतक विधेयकमें 'निषिद्ध प्रवासी' की परिभाषापर एक संक्षिप्त दृष्टि न डाली जाये। जो एशियाई पुरुष या स्त्री बोलकर लिखाने पर या अन्यथा किसी यूरोपीय भाषामें लिखनेमें असमर्थ हो उसका वर्गीकरण निरक्षरों, कंगालों, वेश्याओं और ऐसे ही व्यक्तियोंके साथ किया गया है और उस व्यक्तिके साथ भी जो, यदि उपनिवेशमें आये तो, "उस

नारीखको लागू किसी भी कानूनके अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उसके अन्तर्गत वह, यदि उपनिवेशमें मिले तो, निष्कासित किया जा सकता है या उसको उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जा सकती है चाहे उसे उस कानूनको तोड़नेपर सजा दी गई हो या उसकी धाराओंका पालन न करनेपर सजा दी गई हो या अथवा सजा दी गई हो।” अतः विधेयके खण्ड (३) के अन्तर्गत वह ‘निषिद्ध प्रवासी’ हो जाता है और उस रूपमें

किसी भी व्यक्तिको जिसे मंत्री उचित कारणसे शांति व्यवस्था और उपनिवेशक सुशासनके लिए खतरनाक समझता है यदि वह वहाँ रहता है तो, बलात् निर्वासित किया जा सकता है।

यह आपत्ति की जाती है और बिना कुछ कारण बताये नहीं, कि अतः बताई गई धाराएँ एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध सत्याग्रह करनेवाले लोगों और उनके नेताओंके विरुद्ध लागू की जाती हैं।

बुद्धिमत्तापूर्वक यह व्यवस्था भी की गई है कि इस कानूनके पीड़ितोंको वह सब खर्च भी देना होगा जिसे सरकार उनको उपनिवेशसे या दक्षिण आफ्रिकासे निकालनेमें या निकालनेसे पूर्व उपनिवेशमें या अन्यत्र किसी नजरबंदी शिविरमें रखनेमें करेगी। इस खर्चकी रकम विभागके किसी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें उस खर्चकी विगत और पूरी रकम हो शेरिफके सामने पेश करनेपर उक्त दण्डित व्यक्तिकी उपनिवेशमें जो सम्पत्ति होगी उसकी कुर्कीसे वसूल की जायेगी और उसकी कुर्की करनेका तराका सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयके अनुसार होगा।

कारण

यदि यह पूछा जाये कि सम्मानित ब्रिटिश एशियाइयोंके प्रति इस अनुचित शत्रुताकी जनक शक्ति क्या है, तो उसका उत्तर केवल एक ही हो सकता है। १८८५ से अबतकके कानूनोंके और इस विषयमें जो कुछ कहा या लिखा गया है उसके निरीक्षणसे यह पर्याप्त रूपसे स्पष्ट हो जाता है कि यह चिल्लाहट मुरयत व्यापारिक इश्याका प्रकट रूप है। यह यानमें आ जायगा कि अबतक आक्रमणका लक्ष्य व्यापारिक परवाने रहे हैं। गणराज्यक विधायकोंको उन यूरोपीय दूकानदारोंने १८८५ का कानून ३ बनानेके लिए उकसाया जो अपने इन अरक्षित प्रतिस्पर्धियोंसे मुक्त होनेके लिए चिंतित थे। बॉक्सबग, क्रूसर्डॉर्फ, पॉन्सेफ़स्टूम और ऐसे ही अन्य नगरोंके श्वेत सधियों की चिल्लाहटसे ऊपर ‘कुलियोंको परवाने नहीं’ की पुकार गूँजती है। १९०३ में एशियाइयोंको बाजारोंमें भेजनेका प्रयत्न ट्रान्सवाल सरकारके विरुद्ध हबीब मोटनके उस परीक्षात्मक मुकदमेके बाद लम्बग त्याग दिया गया जिसमें बाजारों और बस्तियोंके बाहर एशियाइयोंका व्यापार करनेका अधिकार स्थापित हो गया था। नये पजीयन अधिनियमसे उन एशियाइयोंके जो उसकी धाराओंका पालन न करें व्यापारिक परवाने नये न किये जानेका खतरा है।

किन्तु केवल व्यापारिक स्पर्धा कदाचित् विधानमण्डलको कारवाहीकी प्रेरणा देनेके लिए पर्याप्त न होती। इसलिए रंग विद्वेषसे अपील की गई है जो प्रत्यक्षतः दक्षिण आफ्रिकाकी ही उपज है और वर्तमान रंगदार आबादीके कारण जो स्थिति इस समय भी खतरनाक है वह रंगदार आबादीके अतिरिक्त एक स्थायी एशियाई तत्त्वको उपस्थितिसे और भी उलझ जायेगी यह संकेत देकर उपनिवेशियोंकी कल्पनाको भड़काया गया है। यह तब प्रत्यक्षतः युद्ध पूर्वके वचनों और दायित्वोंकी समाप्तिको और उसके फलस्वरूप सस्ती बुद्धिमत्ताकी वेदीपर ब्रिटिश भारतीयोंकी छाटी सी आबादीको उत्पीड़नको उचित सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हुआ है। एक मताधिकार विहीन अल्पसंख्यक समाजकी, जो ट्रान्सवालकी गारा आबादीके पाँच प्रतिशतसे भी कम है और जिसे नगर पालिकाओंमें या राजनीतिक सस्थाओंमें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है साम्राज्यके सभ्य नागरिकोंके रूपमें उचित बतावकी सामान्य माँग भी निर्दयतापूर्वक अमाय कर दी गई है। सर आयर लालीके कथनानुसार उन्हें युद्धसे पहले उनके मामलेके माने हुए हिमायतियोंने जो आशाएँ बँधाई थी और जो वचन दिये थे उनको पूरा करनेके बजाय तोड़ा गया है यह कहना अधिक ठीक होगा।

भारतीय विरोधी कानूनकी गुरुता कम बतानेके उद्देश्यसे यह जोर देकर कहा गया है कि इसको समस्त गारी आबादीकी सर्वसम्मत स्वीकृति प्राप्त है। किन्तु इस वचनपर गम्भीर सदेह किया जा सकता है। दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि जो लोग स्वार्थपूर्ण कारणोंसे भारतीय प्रतिस्पर्धियोंको हटानेमें दिलचस्पी

रखते हैं वे ही कोइ ऐसी निश्चित सम्मति देकर उससे बँध सकते हैं। कुछने विशुद्ध तटस्थ भावनासे निजेता पक्षका बहुत बड़ी बहुसंख्याका, खानो और कारखानोके लोगोंका साथ देना नहीं चाहा है। किन्तु ऐसी सर्वसम्मति स्वातंत्र्यकी बात मान भी ले तो भी क्या यह गम्भीरतासे कहा जा सकता है कि युद्धसे पूर्व दिये गये वचन और वादे प्रकट और निहित, जिनसे यह देश बँधा है उल्लंघनपूर्वक त्याग दिये जाने चाहिए और ट्रान्सवालक जनवर्गका एक भाग जो दुर्बल है, हमारे हाथ क्षणिक नीचे दूसरे भागके कहनेसे जो मजबूत है, निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाना चाहिए और उसका कतई कोइ दर्जा न रहने दिया जाना चाहिए?

जो लोग एशियाइयोंके निष्कासनके लिए शोर मचाते हैं, उनके आरोपोंकी विस्तृत जाँच यदि हम लघु पुस्तिकाकी मर्यादामें करनी सम्भव होती तो वह दिलचस्प होती। उनके आरोपोंमें ऐसे तर्क हैं जैसे 'रहने सहनेके दजर्म गिरावट और अनुचित स्पर्धा' एवं यह कि "एशियाई यूरोपीय उपनिवेशियोंमें कभी खुल मिल नहीं सकते और फलतः इस राष्ट्रशरीरमें गुँथे नहीं जा सकते। पहले आरोपके सम्बन्धमें यह संक्षेपमें कह दें कि ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालक खनन वर्गसे स्पर्धा नहीं करते, और न इस उपनिवेशमें भारतीय कुली ही हैं। एशियाई आबादीमें बहुसंख्या दूकानदारों और व्यापारियोंकी है जिनमेंसे ८८-१/२ प्रतिशत ब्रिटिश भारतीय हैं। यह सच है कि ये दूकानदार और व्यापारी चतुर व्यवसायी धैर्यवान लगेनवाले और उद्योगी हैं, किन्तु अपने गोरों प्रतिस्पर्धियोंके समान उन्हें कर और किराया देना होता है, वे अपनी आयक बढ़े भागसे यही थोक (यूरोपी) आयातकोंमें लेनदेन करते हैं और प्रायः चिकित्सकों वकीलों और मिस्त्रियों आदि सेवाएँ प्राप्त करते हैं। यह सच है कि वे खानपानमें सयमाँ होते हैं मुख्यतः मद्यके सम्बन्धमें, वे अपेक्षाकृत अलग अलग रहते हैं और अपनी सम्पत्तिका व्यवस्था नहीं करते। उनका व्यापार मुख्यतः समाजके अपेक्षाकृत निर्धन वर्गोंसे होता है और यह मानी हुई बात है कि उनकी स्पर्धाके कारण जीवन निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओंका मूल्य नीचा रहा है।

भारतीयोंका रहने-सहने निरुद्ध होता है, यह एक मूर्खतापूर्ण भ्रम है। यह भ्रम इस कारण उत्पन्न हुआ है कि सामान्य यूरोपीय लोग पूर्वीय देशोंके भोजनके उत्तम व्यञ्जनकों सराह नहीं पाते। ऐसे मामलोंमें तुलना विशेष रूपसे घृणास्पद होती है और जो तुलना करते हैं प्रायः उनके लिए खतरनाक भी होती है। तथ्योंकी निरन्तर जानकारीसे प्रकट हो जायेगा कि भारतीय आहार महँगा नहीं है। कदाचित् यह उचित रूपसे पूछा जा सकता है कि क्या निर्धनतम भारतीय फेरीवालोंका भी मुख सुविधाका स्तर निर्धन गोरोंके दुखजनक रूपसे बढ़े हुए समुदायकी अपेक्षा नीचा है। उन निर्धन गोरोंमें विजवानर, सीरियाइ और अकुशल रूसी उल्लेखनीय हैं और इनमें जो रूसी अधिक पुराने गोरों व्यापारियोंसे स्पर्धा करते हैं उनका संख्या कम नहीं होती। और न हम बातसे ही इनकार किया जा सकता है कि भारतीय दूकान हर तरह यूरोपीय पड़ोसियोंकी दुकानोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी हाती हैं। भारतीय जिन व्यापारियोंसे व्यापार करते हैं उनके साथ बर्तावमें उनकी इमानदारीपर और उनकी ऊँची प्रतिष्ठापर निश्चय ही आश्रय नहीं किया जा सकता। उनकी आदतोंकी गन्दा बनाया गया है और उनपर आश्रय किया गया है। लेवन्को इस आश्रयकी अमृत्यताके सम्बन्धमें अपनेको आश्चर्यकरनेके अमाधारण अवसर मिले हैं। १९०३-४ के प्लेगके दिनोंमें यह आरोप खास जोर शरसे लगाया गया था और विशुद्ध आत्मरक्षायी दृष्टिसे स्वतन्त्र चिकित्सा विशेषज्ञोंसे निष्पन्न जाँच कराना आवश्यक हो गया था। उनके प्रमाण पत्रोंसे निश्चित रूपसे सिद्ध हो गया था कि भारतीयोंकी दुकानों और मकानोंकी बनावट और उनकी सामान्य व्यवस्था कमसे कम सामान्य व्यापारियोंके अच्छी थी। यह सत्य है कि जोहानिमगकी सोमापर स्थित पुरानी बस्ती, जो बादमें नष्ट कर दी गई, उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सफाईके मामलोंमें इतने लज्जाजनक रूपसे उपेक्षित रही थी कि वह सचमुच प्लेगका घर ही बन गई थी किन्तु वहाँ प्लेगका उन्मूलन कर दिया गया जो बहुत-कुछ उसके निवासी भारतीयोंके अथक प्रयत्न, त्याग और सहयोगका परिणाम था।

भारतीय श्रेष्ठ समाजमें न मिलेंगे, यह तर्क तो उस लड़केकी कहानीकी पुनरावृत्तिमात्र है जिसने मेंढककी इसी अपराधमें दण्ड देकर मार दिया था कि वह मेंढक है। ट्रान्सवालके भारतीयोंपर कानून द्वारा अस्पृश्यताकी छाप लगा दी गई है। उनके साथ अमलमें अछूतोंका सा व्यवहार किया जाता है। स्पष्ट शाब्दिक अर्थार्थताका

खयाल किये बिना वे सभी 'कुली' कहे जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों तकमें ऐसे शब्दप्रयोग मिलते हैं जैसे, 'कुली वकील', 'कुली डॉक्टर', और 'कुली व्यापारी'। उनकी स्त्रियाँ 'कुली स्त्रियाँ' हैं। जैसा बताया जा चुका है, उनका जीवनमें कोई स्थान नहीं है यदि है तो मेहरबानीके तौरपर वे भले ही अपने नाम किसी अचल सम्पत्तिकी रहन करा लें, किन्तु फिर भी वे उसके स्वामी नहीं हो सकते। उनको नगरपालिकाकी जिन ट्रामोंमें और सरकारकी जिन रेलोंमें गोरे बैठते हैं उनमें कभी कभी बैठनेका साधारण अधिकार भी नहीं दिया जाता। उनके बच्चे काफ़ीरोंके लिए निर्धारित स्कूलोंमें पढ़ने जाते हैं इसके अतिरिक्त उनको शिक्षाकी कोई सुविधाएँ नहीं दी जाती। क्या भारतीयोंको समाजके बहतर जीवनमें अधिक निकटतासे धुलने मिलने और सम्मिलित होनेमें इससे अधिक भी हतोत्साहित किया जा सकता है?

इस निष्कर्षसे बच निकलना कठिन है कि भारतीयोंके प्रति रोषका निचोड़ इस तथ्यमें आ जाता है कि उनमें उन लक्षणोंकी बहुलता है जो यदि उनके निन्दकोंमें हुए होते तो अनुकरणीय और सराहनीय गुण माने जाते। दुभाग्यसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अपनी शांति और सुरक्षाको कायम रखनेके लिए केवल लकड़हारे और पनिहारे बनकर रहनेमें सतृप्त नहीं हैं। परिस्थितियाँ विपरीत होनेपर भी वे छोटेसे आरम्भसे अपेक्षाकृत सवृद्धि प्राप्त करनेमें सफल हो जाते हैं। प्रायः वे अपने बेटोंको हमारे विश्वविद्यालयोंमें भेज सकते हैं। उनकी सच्ची रोष उत्पादक बातें ये ही हैं। वे अपनी स्थितिसे आगे बढ़नेका साहस करते हैं। यदि वे केवल अकुशल मजदूरोंकी कमी पूरी करके या अपने गोर सह उपनिवेशियोंके लिए लाभ कमाकर सतृप्त हो जाते एवं अपनी कमाईको खर्च करते रहते जिससे गोरोंकी लगातार उतने ही मजदूर मिलते जाते तो उनकी उपस्थितिका स्वागत ही न किया जाता वरन् उनकी प्रशंसाके पुल बाँध दिये जाते। यदि इसमें कुछ सदेह हो तो समीपस्थ नेटाल उपनिवेशमें देखें, एक ओर तो अच्छी स्थितिके भारतीयोंके विरुद्ध चीख पुकार बढ़ती जाती है दूसरी ओर उपनिवेशकी सरकार भारतीय कुली मजदूरोंका आयात बन्द करनेसे लगातार इनकार कर रही है।

ट्रांसवालकी गणतन्त्रीय सरकारके विरुद्ध उत्तरदायी अग्रेज मंत्री हमारी ओरसे जो मॉर्ग कर रहे हैं, उनकी तुलनामें हमारे इन मुट्ठी भर भारतीय सह प्रजाजनोकी मॉर्गे बहुत ही कम है। अपने गोरे साथी उप निवेशियोंके पूर्वग्रहोंका खयाल करके भारतीय लोग नगरपालिका मताधिकार या राजनीतिक मताधिकारकी माँग नहीं करते। विशाल दृष्टिसे जो अधिक सद्बानुभूतिपूर्ण सराहनाके योग्य है, भारतीय लोग, विस्तृत वतनी आबादीपर राज करनेवाली थोड़े से गोरे अल्पसंख्यकोंकी सरकारके सम्मुख प्रस्तुत कठिनाइयोंकी स्वीकार करते हैं। फलस्वरूप वे उपनिवेशको गोरोंके दिमागोंपर और हाथोंमें छोड़नेके लिए रजामन्द हैं। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि उनके साथ साम्राज्यके सभ्य, भले ही वे रगदार हो, नागरिकोंके योग्य सम्मान और लिहाजके साथ बर्ताव किया जाये एवं उनको अपमान अप्रतिष्ठा और विनाशसे बचाया जाये। उनकी माँग यह नहीं है कि एक नये उपनिवेशके द्वार एशियाई प्रवासियोंकी अन्वाधुनिक भ्रमणोंके लिए खोल दिये जायें। किन्तु उनका कहना यह अवश्य है कि भावी प्रवासियोंके लिए जो शिक्षाकी कसौटी लागू की जाये वह उचित हो और वह विशेष रूपसे भारतीयोंके ही विरुद्ध प्रयुक्त न की जाये। उदाहरणार्थ उनकी माँग यह है कि हिन्दुस्तानी और गुजरातीकी कमसे कम यीडिशके समान आधारपर तो रखा जाये। किन्तु वे एक मूल अधिकारके रूपमें यह चाहते हैं कि जो भारतीय वैव निवासी हैं उनको पहलेसे ही जन्मत हीन और अपराधी मानकर बनाये गये भेदभावकारी कानूनोंसे बचाया जाये। वे 'यापारिक परवाने जारी करनेका नियमन और नियंत्रण एवं सफाईके अत्यन्त कड़े नियम लागू करनेका अधिकार नगरपालिकाओंको देनेकी बात मानते हैं, किन्तु वे यह पूछते हैं कि अचल सम्पत्तिका स्वामित्व प्राप्त करनेकी उनकी असमर्थता किस आधारपर स्थायी बनायी जा रही है? उदाहरणार्थ वे उस स्थानको क्यों नहीं खरीद सकते जिसमें वे अपना व्यवसाय चलाते हैं? निःसदेह ट्राम और रेलके कानून कायदे जिनके अनुसार वे उन डिब्बोंका और गाड़ियोंका उपयोग नहीं कर सकते जिनका उपयोग गोरे करते हैं एवं वे उपनियम जिनके अंतर्गत उनके लिए पैदल पटरियोंका प्रयोग निषिद्ध है निश्चय ही एक ब्रिटिश उपनिवेशके अयोग्य हैं। पजीयनके मामलेमें भी भारतीयोंने समझौतेकी स्वाभाविक इच्छाके साथ समझौतेका प्रस्ताव किया। चूँकि ट्रांसवाल सरकारने अपनी एशियाई आबादीके पुनः पजीयनको इतना महत्त्व

दिया है, इसलिए और अपनी नेकनीयती सिद्ध करनेके लिए भी, भारतीय ममाजने आगे आने और स्वेच्छासे पुन पजीयन करानेका प्रस्ताव किया है। उन्हें जो अधिकारपत्र प्राप्त है उनको दूसरे प्रमाणपत्रोंसे बदलनेके लिए और अति महत्वपूर्ण अंगूठा निशानी देनेके लिए भी वे तैयार हैं। उसके अतिरिक्त उनका यह कहना है कि सरकार बादमें एक छोटा अधिनियम भी बना सकती है जिसमें केवल नये प्रमाणपत्र ही वैध माने जाये जो इस प्रकार दिये गये हों।

इस प्रस्तावित समझौते और अधिनियमके अनुसार किये गये पुन पजीयनका अन्तर पर्याप्त स्पष्ट ही है। स्वेच्छया पजीयनमें बाध्यताका डक नहीं होगा और वह एक सम्मानास्पद कार्य होगा, जिसे एशियाई समाज गोरोकी भावनाके सम्मानार्थ सम्पन्न करेगा और उनकी यह भावना कालान्तरमें बदल सकती है। यह माना जाता है कि अनिवार्य पजीयन भारतीयोंका दजा काफ़ीरोंके बराबर होनेका सूचक है, उससे कमका सूचक नहीं और यह बहुत सम्भव है कि उसको पड़ोसी उपनिवेश भारतीय विरोधी कानून बनानेके लिए उदाहरणके रूपमें काममें लाये एवं रगदार बस्तियोंमें वह अनिवार्य पृथकरणकी सम्मानित भूमिका बन जाय।

बोअर गणराज्यमें और उसके विलयके बाद ब्रिटिश भारतीयोंकी जो स्थिति थी, तुलनात्मक स्तम्भोंके रूपमें यहाँ उसका साराश अप्रासंगिक न होगा बल्कि उससे ज्ञान वृद्धि ही होगी

बोअर शासनमें

एशियाई उपनिवेशमें स्वतंत्रतासे आ सकते थे और १८८५ के बाद ३ पाँड कर देनेपर रह सकते और व्यापार कर सकते थे।

१८८५ के कानून ३ (१८८६ में संशोधित) के अन्तर्गत 'पजीयन' में डुलिया देना सम्मिलित न था उसमें केवल ३ पाँड शुल्ककी अदायगी और उसकी रसीद रखनेकी बात थी।

एशियाइयोंको नागरिक अधिकार नहीं दिये गये थे।

एशियाई उन गलियों और बस्तियोंसे हटाये जा सकते थे जो इसके लिए विशेष रूपसे निश्चित की गई हों।

जब कि उक्त नियोज्यताएँ जिस कानून ३ के अन्तर्गत लागू होती थीं वह तत्काल अमलमें नहीं लाया जाता था, महामहिम सम्राट्की सरकार उनकी रक्षा करती थी।

ब्रिटिश अधिकारके बाद

केवल वे एशियाई पुन प्रविष्ट किये गये हैं जो यह सिद्ध कर दें कि वे युद्धसे पूर्व यहाँ रहते थे।

एशियाइयोंने १९०३ में जो स्वेच्छया 'पजीयन' लॉर्ड मिलनरकी सलाहसे स्वीकार किया था, उसमें बहुत विस्तृत डुलियाकी बात सम्मिलित थी।

१९०७ के अधिनियमके अन्तर्गत पुन पजीयन अनिवार्य है और उसकी तफ़सील और भी अपमानजनक है। यह आठ वर्षसे अधिक आयुके सब बच्चोंपर लागू होता है। पुन पजीयन न करानेपर जुर्माना, कैद और निष्कासनकी सजाएँ दी जाती हैं।

एशियाइयोंकी, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी हैं राजनीतिक और नगरपालिकाके अधिकारोंसे वंचित कर दिया गया है। एशियाई अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते। अब भी यही स्थिति है।

एशियाई, जिनमें भारतीय भी हैं अब भी हटाये जा सकते हैं और उनको इस प्रकार पृथक् किय जानेकी धमकी दी भी जा चुकी है।

विलयके बाद और विशेष रूपसे उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके बाद, ब्रिटिश भारतीयोंको सम्राट्का यह संरक्षण नहीं मिल सका है।

उत्तरदायी ब्रिटिश मंत्री ब्रिटिश भारतीयोंके लिए साम्राज्यके सभ्य प्रजाजनोके बराबर अधिकारोका दावा करते थे । ब्रिटिश सरकारने तत्त्वतः वचन दिया था कि वह या सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको उनके उचित अधिकार दिलायेगी ।

साम्राज्य सरकार बोअर कानूनके विरुद्ध भारतीयों की शिकायतोका समर्थन करती थी और जिन कारणोंसे लड़ाई हुई उन कारणोंमें एक मुख्य कारण गणतन्त्रीय सरकारका अपनी सीमाओंके भीतर रहनेवाले एशियाईयोंके विरुद्ध भेदभावकारी कानून बनानेके अधिकारपर आग्रह करना था ।

सामान्यतः ब्रिटिश भारतीयोंपर जब कि सिद्धांततः ये नियोग्यताएँ लगी हुई थी, व्यवहारमें इस कानूनको कड़ाईसे लागू नहीं किया जाता था ।

अतमें इससे यह बात भली भाँति समझमें आ जायेगी कि इन सब बातोंकी ओर संकेत करनेकी और युद्धसे पहले दिये गये वचनों एवं युद्धके पश्चात् किये गये कार्योंकी असंगतिपर विचार करनेका लोभ क्यों हुआ । जिस सरकारको एक शक्तिशाली बहुसंख्याका समर्थन प्राप्त है उसका कर्तव्य है कि वह एक नितांत प्रतिनिधित्वहीन रंगदार अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा करे । इसके अतिरिक्त भी यह लुभावना प्रश्न उठता है, साम्राज्य परिवारके प्रत्येक सदस्यका कर्तव्य है कि वह विशुद्ध स्थानीय स्वार्थोंको — पक्षपात और पूर्वग्रहकी तात्बाल ही क्या — समस्त साम्राज्यके कल्याणक्षेत्रमें गौण माने । किन्तु यहाँ यह बताना काफी होना चाहिए कि ट्रान्सवालकी नीतिमें ऐसे विचारोंको प्रत्यक्षतः कोई स्थान उपलब्ध नहीं हुआ । ट्रान्सवालमें मुश्किलसे ढाई लाख गोरे होंगे, किन्तु फिर भी वह भारतके तीस करोड़ लोगोंके प्रतिनिधियोंका अपमानपर-अपमान करके साम्राज्यकी सत्ता और प्रतिष्ठाको खतरोंमें डालनेसे नहीं हिचकिचाया है ।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया आफिस रेकर्ड्स, जे० ऐंड० पी० ३९२७/०७ ।

ब्रिटिश सरकारने प्रत्यक्षतः उन्ही भारतीयोंको जो उपनिवेशोंको मिलानेसे पूर्व उसमें रहते थे उनके व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों और उस सरकारके अत्याचारोंपर छोड़ दिया है जो बहुत कुछ उन्ही विधायकोंकी बनी है, जिन्होंने १८८५ का बोअर कानून ३ बनाया था ।

उपनिवेशोंकी सरकारकी धमकियोंके अनुसार पर्जीयन अधिनियमके विरुद्ध भारतीयोंके सत्याग्रहका परिणाम उपनिवेशोंसे उनका निष्कासन होगा । सरकारको इसके लिए आवश्यक अधिकार प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमसे प्राप्त होंगे

ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगे हुए हैं और ब्रिटिश भारतीय इसके निकृष्टतम दुष्परिणामोंसे केवल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि १८८५ के कानून ३ में दण्डात्मक धारा नहीं है ।

सामग्रीके साधन-सूत्र

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमे सुरक्षित कागजात । देखिए, खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय और पुस्तकालय । देखिए, खण्ड १, पृष्ठ ३५९ ।

इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके पुस्तकालयमे सुरक्षित भारतीय मामलोसे सम्बन्धित कागजात और प्रलेख, जिनका सम्बन्ध भारत मंत्रीय था ।

‘इंडियन ओपिनियन’ (१९०३-६१) साप्ताहिक पत्र, जिसका प्रकाशन डबनमे आरम्भ किया गया, किन्तु जो बादमे फीनिक्समे ले जाया गया । यह पत्र सन् १९१५ मे गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेतक लगभग उन्हीके सम्पादकत्वमे रहा । इसमे अंग्रेजी और गुजराती दो विभाग थे, आरम्भमे हिन्दी और तमिल विभाग भी थे ।

नेटाल आर्काइव्स पीटरमैरिट्सबर्गमे दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात ।

प्रिटोरिया आर्काइव्स प्रिटोरियामे दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात । इसमे, अन्योके साथ-साथ, प्रधानमंत्री और ट्रान्सवाल गवर्नरके अभिलेख संग्रहालय भी हैं ।

‘रैड डेली मेल’ जोहानिसबर्गका दैनिक पत्र ।

साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद पुस्तकालय और संग्रहालय, जिसमे गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० ।

‘स्टार’ जोहानिसबर्गसे प्रकाशित सान्ध्य दैनिक पत्र ।

‘ट्रांसवाल लीडर’ जोहानिसबर्गसे प्रकाशित दैनिक पत्र ।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(जून दिसम्बर १९०७)

- जून १ गांधीजीने ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठकमे भाग लिया जिसमे यह निश्चय किया गया कि प्रधानमंत्री जनरल बोथाके पास एक शिष्टमण्डल भेजकर उनसे समझौतेका प्रस्ताव स्वीकृत करनेका अनुरोध किया जाये।
- जून ४ जनरल बोथाने शिष्टमण्डलसे मिलनेसे इनकार कर दिया।
- जून ६ भारत मंत्री जान मार्लेने लोक सभामे भारतके प्रस्तावित वैधानिक सुधारोका स्वरूप बतलाया।
- जून ८ ट्रांसवाल 'गवर्नमेण्ट गजट' मे एशियाई पजीयन अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति मिलनेकी घोषणा की गई।
- जून १४ ट्रांसवाल ससदका दूसरा अधिवेशन आरम्भ हुआ।
- जून २८ गांधीजीने 'रैड डेली मेल' से एक भेटमे कहा कि भारतीयोंने अधिनियमको न माननेका सकल्प किया है।
- जून २९ अधिनियमके विरोधमे आयोजित फोक्सरस्टकी सभामे भाषण दिया।
- जून ३० अधिनियमके फलिताथ बताते हुए प्रिटोरियामे भारतीयोकी सभामे भाषण दिया।
- जुलाई १ अधिनियम प्रिटोरियामे लागू किया गया। पहला परवाना-दफ्तर खुला। भारतीयोको एक मासमे पजीयन करानेकी सूचना दी गई। पजीयनके विरुद्ध आंदोलन आरम्भ किया गया।
- गांधीजीने सावजनिक सभामे भाषण दिया, 'रैड डेली मेल' को पत्र लिखा कि चाहे जो परिणाम हो, प्रिटोरियाके भारतीय अनिवाय पुन पजीयन कराना स्वीकार न करेगे।
- जुलाई २ फोक्सरस्टकी सभामे भाषण दिया, जिसमे जेल-प्रस्तावपर कायम रहनेका निश्चय किया गया।
- जुलाई ३ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक प्रकाशित किया गया।
- जुलाई ४ गांधीजीने 'स्टार' को पत्र लिखा जिसमे प्रवासी विधेयककी निन्दा की गई।
- जुलाई ६ 'रैड डेली मेल' को लिखा कि भारतीय अधिनियमके सम्मुख झुकनेकी अपेक्षा अपने सवस्वकी आहुति देना पसंद करेगे।
- जुलाई ७ प्रिटोरियाकी सभामे भाषण दिया।
- जुलाई ८ ट्रांसवाल पजीयन विधेयक ब्रिटिश लोकसभामे स्वीकृत हुआ।
- जुलाई ९ ब्रिटिश भारतीय सघने ट्रांसवाल विधानसभाको प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धमे प्रार्थनापत्र दिया।
- जुलाई १४ गांधीजीने जोहानिसबगमे हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया और भारतीयोसे अनिवाय पुन पजीयनको स्वीकार न करनेका अनुरोध किया।
- जुलाई १५ ट्रांसवाल फुटबॉल सघकी बैठकमे भाषण दिया।
- जुलाई १६ प्रिटोरियामे भारतीय व्यापारियोकी सभामे भाषण दिया।

- जुलाई २० डबनमे नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामे ट्रांसवालके मधपके लिए वन देनेकी अपील की।
- जुलाई २२ ब्रिटिश भारतीय सघने प्रवासी प्रतिवधक विवेकके सम्बन्धमे ट्रांसवाल विधान सभाको प्राथनापत्र दिया।
- जुलाई २४ गांधीजी प्रिटोरिया पहुँचे, ओर खमीसाकी दूकानपर गये जहा रातको गुप्त रूपसे पजीयनके लिए प्राथनापत्र लिए जाते थे।
- जुलाई २५ जनरल बोथा द्वारा एशियाई अधिनियमको लागू करनेके सम्बन्धमे उपनिवेश मंत्रीको दिये गये आश्वासनके बारेमे प्रश्न किया जानेपर ब्रिटिश लोकसभामे कहा गया कि अधिनियमको लागू करने ओर अमलमे लानेकी कारवाई यथासम्भव कम कष्ट-प्रद बनानेका पूरा प्रयत्न किया जायेगा और अँगुलियोंकी छाप लेनेकी प्रथा कायम रखी जायेगी।
- जुलाई २७ ब्रिटिश भारतीय सघने उपनिवेश-सचिवको पत्र लिखकर भारतीयोपर लगाये गये डराने-धमकानेके आरोपका खण्डन किया।
- जुलाई २८ जोहानिसबर्गमे हमीदिया इस्लामिया अजुमनके भवनमे भारतीयोकी सभा हुई। ट्रांसवालमे हडताल की गई।
- जुलाई ३० 'इंडिया' और 'हिन्दुस्तान' समाचारपत्रोके सम्पादकोको पाच पाच वर्षकी कड़ी कैदकी सजाएँ दी गई।
- जुलाई ३१ गांधीजी सुबह विलियम हॉस्केनसे मिले, प्रिटोरियाकी सावजनिक सभामे भाषण दिया, भारतीयोको कानूनका विरोध करनेकी सलाह देनेकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अनाक्रामक प्रतिरोधका महत्त्व बताया। लोगोको अधिनियमके सामने सिर झुकानेके खतरोंके विरुद्ध चेतावनी दी।
- 'रैड डेली मेल' के सवाददाताको मुलाकात दी।
- अगस्त ५ से पूर्व परवाना दफ्तर पीटसवग गया,
- अगस्त ७ भारतमे स्वदेशी आन्दोलनका वार्षिक दिवस मनाया गया, २०,००० भारतीयोंने एक सभामे निश्चय किया कि बग-भगके विरुद्ध बहिष्कार तबतक जारी रखा जाये जबतक वह वापस न लिया जाये या बदला न जाये।
- अगस्त ८ गांधीजीने जनरल स्मट्सको पत्र द्वाग एशियाई अधिनियममे सशोधन सुझाये।
- अगस्त ११ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।
- अगस्त १४ सुलेमान वाडीकी ओरसे, जिनपर वतनियोको शराब बेचनेका आरोप था, पैरवी की।
- अगस्त १५ जनरल स्मट्सका लिखा कि भारतीयोके लिए अधिनियमका पालन न करनेका परिणाम उतना बुरा नहीं होगा जितना बुग उमे पालन करनेका परिणाम होगा।
- अगस्त १७ जनरल स्मट्सके साथ किया गया पत्र व्यवहार प्रकाशित किया।
- अगस्त १९ जनरल स्मट्सके सम्मुख रखे गये प्रस्तावके सम्बन्धमे 'स्टार' को पत्र लिखा।
- अगस्त २१ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।
- अगस्त २३ ब्रिटिश भारतीय सघने उपनिवेश मंत्रीको प्राथनापत्र भेजा।
- अगस्त २४ से पूर्व परवाना दफ्तर पाचेपस्टूम और क्लाक्सडॉपमे कार्य रत।
- अगस्त ३१ से पूर्व परवाना दफ्तर नाईल्स्टूम और रस्टेनबग गया।

अगस्त ३१ गांधीजी और अय लोगोने श्री हाजी वजीर अली और उनके परिवारको विदाई दी। वे टासवालसे इसलिए चले गये कि वे अधिनियमको मानना नहीं चाहते थे।

सितम्बर ४ नेटाल भारतीय कांग्रेसने दादाभाई नौरोजीको उनके जन्म दिवसपर समुद्री तारसे बवाई भेजी।

गांधीजीने डबनमे नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामे भारतीय सघपके सम्बन्धमे भाषण दिया।

सितम्बर ७ से पूर्व सनातन वदिक धर्म सभा, जर्मिस्टन द्वारा आयोजित भगवान कृष्णके जन्मोत्सवमे भाग लिया।

सितम्बर ११ एशियाई पजीयकको कोमाटीपूटमे रोके गये भारतीयोके सम्बन्धमे पत्र लिखा।

सितम्बर १७ परवाना दफ्तर बाक्सबग गया।

सितम्बर २१ से पूर्व उपनिवेश सचिवको भेजा जानेवाला भीमकाय प्राथनापत्र हस्ताक्षरोके लिए घुमाया गया।

सितम्बर २२ गांधीजीने हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।

सितम्बर २४ परवाना दफ्तर जर्मिस्टन चला गया।

सितम्बर २९ गांधीजीने हमीदिया इस्लामिया अजुमन जोर चीनी सघकी सभाओमे भाषण दिया।

अक्तूबर ६ ब्रिटिश भारतीय सघकी सभामे भाषण देते हुए कहा कि वे गिरफ्तार धरने दारोकी पैरवी करेगे।

अक्तूबर ९ 'रैड डेली मेल' को पत्र लिखा।

अक्तूबर १३ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाग लिया।

अक्तूबर १४ हैलूने भेट की और पजीयनका प्राथनापत्र देनेपर खेद प्रकट किया।

अक्तूबर १५ न्यायालयमे धरनेदारोपर लगाये गये डराने-धमकानेके आरोपका खण्डन किया और पुलिस कमिश्नरको पत्र लिखा।

अक्तूबर १७ भारतमे बग भग दिवस शोक दिवसके रूपमे मनाया गया।

अक्तूबर १८ गांधीजीने 'स्टार' को पत्र भेजकर डराने धमकानेके आरोपका खण्डन किया।

अक्तूबर २० हमीदिया इस्लामिया अजुमन और दक्षिण भारतीयोकी सभाओमे भाग लिया।

अक्तूबर २३ ब्रिटिश भारतीय सघ और भारतीय विरोधी कानून-निधिकी बैठकोमे भाग लिया।

अक्तूबर २४ एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमे 'स्टार' को पत्र लिखा।

अक्तूबर २७ जोहानिसबगके पुलिस कमिश्नरसे धरनेके सम्बन्धमे भेट की।

हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे पुलिस कमिश्नरसे हुई भेटका हाल बताया।

मुहम्मद शहाबुद्दीनसे, जिसपर मुल्लाने हमला किया था, भेट की।

अक्तूबर भारतमे विपिनचन्द्रपालको अरविद घोषके विरुद्ध राजद्रोहके मुकदमेमे गवाही देनेसे इनकार करनेपर छ मासकी कैदकी सजा दी गई।

नवम्बर १ ब्रिटिश भारतीय सघने ४,५२२ भारतीयोके हस्ताक्षरोसे युक्त भीमकाय प्राथनापत्र उपनिवेश सचिवको भेजा।

गांधीजीने 'ट्रासवाल लीडर' को भारतीयोके पजीयनके सम्बन्धमे पत्र लिखा।

नवम्बर ९ कैक्सटन हॉल, लंदनमे मुसलमानोकी सभा हुई जिसमे ट्रान्सवालमे भारतीयोके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहारका विरोध किया गया।

नवम्बर ११ गांधीजीने जर्मिस्टनमे गिरफ्तार किये गये पहले भारतीय रामसुंदर पण्डितकी पैरवी की।

पण्डितजीकी रिहाईके बाद की गई सभामे भाषण दिया।

‘ट्रान्सवाल लीडर’ के सवाददाताको भेट दी।

नवम्बर १३ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।

नवम्बर १४ जर्मिस्टनमे रामसुंदर पण्डितके, जिन्हें एक महीनेकी कैदकी सजा दी गई थी, मुकदमेमे पैरवी की।

ट्रान्सवालमे हड़ताल की गई।

नवम्बर १५ प्रिटोरियामे धरनेदारोके मुकदमेमे पैरवी की, ‘इंडियन ओपिनियन’ को राम सुंदर पण्डितके सम्बन्धमे पत्र लिखा।

नवम्बर १७ जोहानिसबर्ग जेलमे रामसुंदर पण्डितसे मिले, हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।

नवम्बर १८ भारतमे लाला लाजपतराय रिहा किये गये।

नवम्बर १९ गांधीजीने जर्मिस्टनमे शाहजी साहब ओर अयोके मुकदमेमे पैरवी की।

नवम्बर २१ मणिलाल गांधीको ‘रामायण’ और ‘गीता भेजी।

नवम्बर २२ गोपालकृष्ण गोखलेको पत्र लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अगले अधिवेशनमे हिंदू मुस्लिम एकतापर विशेष जोर दिया जाये।

नवम्बर २४ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे बोले।

सोसायटी हालमे कोकणियोंकी सभा हुई।

नवम्बर २७ चीनी सघकी सभामे भाषण दिया।

नवम्बर ३० पजीयनकी अंतिम तारीख, १३,००० भारतीयोंमे से केवल ५११ ने पजीयन कराया।

इस महीनेमे पहली बार सघको ‘सत्याग्रह’ का नाम दिया गया।

दिसम्बर १ गांधीजी जेलमे रामसुन्दर पण्डितसे मिले।

दिसम्बर ३ विलियम हॉस्केनका यह सदेश मिला कि एशियाई कानून सशोधन विवेकके सम्बन्धमे उच्चायुक्तसे मिले। उच्चायुक्तको पत्र द्वारा सुझाव दिया कि चोरीसे भारतीयोंके प्रवेशके आरोपकी जाच करनेके लिए यायाधीशकी नियुक्ति की जाये।

दिसम्बर ६ मुहम्मद इशाकके मुकदमेमे पेश हुए।

भारतमे आतंकवादियोने मिदनापुर (बंगाल) मे लेफ्टिनेंट गवर्नरकी गाडीको उडानेका प्रयत्न किया।

दिसम्बर ७ से पूर्व गांधीजीने उच्चायुक्तको पत्रावियो, पठानो और सिखोका प्राथनापत्र भजा।

दिसम्बर ८ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।

दिसम्बर ९ फोक्सरस्टमे ३८ भारतीयोंके मुकदमेकी पैरवी की।

दिसम्बर ११ मुहम्मद इशाककी पैरवी की। फलस्वरूप वे बरी कर दिये गये।

दिसम्बर १२ भारतीयोंपर मुकदमे चलानेके बारेमे ‘इंडियन ओपिनियन’ मे लिखा।

दिसम्बर १३ रामसुन्दर पण्डितके जेलसे रिहा होनेपर उनके स्वागत समारोहमे भाग लिया, बादमे सभामे भाषण।

दिसम्बर १५ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया ।

दिसम्बर २० स्टडटनके भारतीय कमचारियोके सम्बन्धमे मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेके मुख्य प्रबन्धकको टेलीफोन किया ।

दिसम्बर २२ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया ।

दिसम्बर २३ भारतमे ढाकाके भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट श्री एलेनपर ढाका ओर कलकत्ताके बीच एक रेलवे स्टेशनपर गोली चलाई गई ।

दिसम्बर २६ जनरल स्मटसने गांधीजी ओर अन्य धरनेदारोपर मुकदमे चलानेका निणय किया ।

सुरतमे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । नमदल और गमदल अलग अलग हो गये ।

दिसम्बर २७ ट्रान्सवाल प्रवासी अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति 'गजट' मे घोषित की गई । गांधीजी ट्रान्सवालके कायवाहक पुलिस कमिश्नरसे मिले ओर उसने उन्हें सूचित किया कि उनको और दूसरे धरनेदारोको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी गई है । बादमे जोहानिसबगमे सावजनिक सभामे भाषण दिया और 'स्टार' के सवाददाताको मुलाकात दी ।

दिसम्बर २८ अपनी पैरवी खुद की और धरनेदारोकी ओरसे पेश हुए, ४८ घंटेमे ट्रान्सवालसे चले जानेकी आज्ञा दी गई । बादमे गवनमेट स्क्वेयरकी सभामे भाषण दिया ।

दिसम्बर ३० जोहानिसबगमे चीनी सघकी सभामे भाषण दिया । रायटरके प्रतिनिधिको मुलाकात दी ।

प्रिटोरियाकी सावजनिक सभामे भाषण दिया ।

दिसम्बर ३१ गांधीजीको सूचना दी गई कि जबतक आगे निर्देश न दिया जाये, उनको न्यायालयमे आनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यूरोपीय मित्रोंने उनसे भेट की ओर उनके साथ सहानुभूति प्रकट की ।

गांधीजीने भारतीयोकी सावजनिक सभामे भाषण दिया ।

शीर्षक-साकेतिका

अगदवाता, ६३-६४
 अंगूठा निशानीका कानून २४४
 अवीरता ४३७
 अनाक्रामक प्रतिरोधके लाभ २१७-१८
 अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके लिए, ३०५-६
 अफगानिस्तानमें मुसलमानोंकी हालत ३४-३५
 अब क्या होगा? १५४
 अरबी ज्ञान, ४५३-५४
 अलोक पत्र १५६
 अलीकी भूल १२४-२५
 आगमें घी, ७१-७२
 आदम-नी मियाँल्लोंका शोकजनक अवमान १२२
 आपदनपत्र उपनिवश मन्त्रोंकी १८३-८८
 इस्लामकी बहादुर स्त्रियाँ, ६५
 इंडियन ओपिनियनका परिशिष्टाक २१६
 इंडियन ओपिनियनके बारेमें २७८-७९
 ईट मुबारक, ३३८
 ईस्ट इन्डियाकी चेतावनी १२८
 उमर हाजो आमद शबरी १५९
 एक टेक ७२-७३
 एक पारसी महिलाकी हिम्मत, १६०
 एक पौडका इनाम ५
 एशियाई पञ्चायत अधिनियम १६-१९
 एस्टकोम्पका अपील, १५८, १९४
 कचो उम्रमें बाँड़ा पीना राकनेका कानून १७
 क याओकी शिक्षा, ६६
 काग्रसके लिए प्रतिनिधि, ३७८
 कानूनका अलाचार, ४०
 कानूनका विराय — एक कत य [१] २२०-२२, — [२]
 २३१-३३
 'कानूनके सामने मोम २२९-३०
 कानून स्वीकार करनेवालोंका क्या होगा? ४११
 कुछ अंग्रेजी शब्द, ४५१
 केपका प्रवासी कानून १५-१६
 केपके भारतीय, २६, १२५-२६, १५७ २०१, २७७-७८,
 २८२-८३

केपके भारतीय कब जागरे? ३७८
 केप टाउनके भारतीय, २०६
 केपमें मव २६८
 केक्सटन हॉलकी सभा, ३६०
 कैसी दशा! ७४
 क्या नेटालमें खूना कानून बन सकता है? १९३
 क्या भारत जाग गया? २६१
 क्या दशा होगी? २२८-२९
 क्या हम यय परिषदमें जा सकते हैं? १९२
 खुदाई कानून १२२-२४
 खुले दिल्ली सहायुभूति, १९०
 खूनी कानून ७५-८०
 खूनी कानून तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियम
 ४००-५
 गरीब किन्तु बहादुर भारतीय २६७
 गिरमिटिया प्रवासी १०९
 गिरमिटिया भारतीय ११३
 गिरमिटिया भारतीय मजदूर, ४१
 घोर मान हानि १०६-७
 जनरल बोधा और एशियाई कानून २५८-५९
 जनरल बोधाका अनुकरण, २९३-९४
 जनरल स्मट्सका उत्तर १५५
 जनरल स्मट्सकी बहादुरी (?) ३२४-२५
 जनरल स्मट्सका हठ ११०
 जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन, ४२४-२५
 जॉज गॉडफ्र २६६
 जूरियाका कमीटो १-२
 जोहानिसबर्गमें मुकदमा, ४५८-६०
 जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ९-१३ २८-३४ ४३-४६,
 ५१-५४ ५६-६० ८३-८५, ८९-९२ १००-४
 १२९-३३ १३५-३९, १४५-४७, १७२-७६,
 १९५-९८ २०७-८, २२३-२६, २३३ ३५, २४५
 ५० २५३-५६ २६८-७३, २८४-८९, २९६-३००,
 ३१०-१८, ३२८-३२, ३४०-४७ ३६७-७१,
 ३७९-८२ ३८६-९४, ४१३-१९ ४२८-३३,
 ४३९-४२ ४५४-५७, ४७०-७५

जोहानिसबगके ताजे समाचार, ६९
 ट्रांसवालका नया प्रवासी विधेयक ९३-९५
 ट्रांसवालकी लड़ाई १४३-४४ २४१
 ट्रांसवालके भारतीय १५३-५४
 ट्रांसवालके भारतीयोंका कतय, ३०७
 ट्रांसवालके भारतीयोंकी सूचना, ३७४
 ट्रांसवाल प्रगामी विधेयकपर बहस १०७-८
 ट्रांसवालमें दूकान बन्द करनेके समझका कानून २९५
 डबनका कतय, ९८
 डबनकी कृषि समितिका ओछापन १५९
 डबनमें अंगुलियोंकी छाप देनेका आतक २२२
 डबनमें दीवाली महोत्सव ३७१
 डॉक्टर नडीकी पुस्तिका २२०
 डेलगोआ बेके भारतीय, ४४७ ४५०
 तार, -गो० कृ० गोखलेकी २३७, -तैयबकी, १४, -द०
 अ० त्रि० भा० समितिकी १८८ -दादाभाई
 नौरोजीकी, २१०, -पेंचैफ़्ट्सडूमके भारतीयोंकी १६२,
 -प्रिगरिया समितिकी १५१, -पाठसर्वके भारतीयोंकी,
 १६२, -सी० दर्बेकी १४८, -सुरेद्रनाथ बनर्जीकी २५६
 दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति १९१, २७९-८०,
 दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिका काम ११०-११
 द० आ० त्रि० भा० समितिकी पत्र २८९
 दक्षिण आफ्रिकामें अकाल, ६४
 दाउद मुहम्मदकी बवाई ४५०-५१
 दादाभाई जयन्ती, २०२
 धोखा १६९
 धरना देनेवालोंका कतव्य २५७-५८
 धरनेदारोंका मुकदमा, ३७७
 धरनेदारोंके विरुद्ध मुकदमा, ३५७-५८
 धर्मपर हमला १२६-२७
 न धरके न धाटके २२८
 नेटालका परवाना कानून २४२
 नेटालके भारतीयोंमें जागृति १४४
 नेटालके व्यापारियोंकी चेतावनी १६८
 नेटाल तू जागता है या सोता? ७५
 नेटाल नगरपालिका मताधिकार अधिनियम २१९
 नेटाल परवाना अधिनियम ४२३-२४
 नेटाल भारतीय कांग्रेस ४९
 नेटालमें जेलका कानून ५०
 नेटालमें परवाना सम्बन्धी अर्जकी विनियम ४२७-२८

नेटालमें परवाने और टिकटका विधेयक ११२
 नेटालमें युद्ध स्वयंसेवक ४१२-१३
 नया खूनी कानून १९-२५
 नया वर्ष शुभ हो, ३३८
 नये कानूनसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता ४७-४९
 पण्डितजीका जीवन चरित्र ३६३
 पण्डितजीकी देश सेवा ३७७
 पत्र -अखबारोंकी ३३४-३७, -अखिल भारतीय मुस्लिम
 लीगके अध्यक्षोंकी ३८५ ८६, -इंडियन ओपिनियनकी,
 १७७ ३५९-६० ४२१-२२, -उच्चायुक्तके निजी
 सचिवकी ४०५-७, -उच्चायुक्तकी ४०९, -उपनिवेश
 सचिवकी ४७ १०५ १३४ २१३ २७४-७५
 ३२०-२१ ४०८, ४३४-३५, -एशियाई पत्रिकाकी,
 २२७ ४७५, -गो० कृ० गोखलेकी, ३५७ ३७५
 -छगनलाल गांधीकी ३८ ९५-९६, -जनरल स्मट्सके
 निजी सचिवकी १४८-५० १६४-६५, -जनरल
 स्मट्सकी, ३८९-५० -जे० ए० नेसरकी २५२ २६२
 ६४, -जोहानिसबग नगरपालिकाकी १९९ २०९,
 -ट्रांसवाल लीडरकी ३०२-४ ३२२-२३ ३४८
 ४९ ३७६, -प्रवानमन्त्रीके सचिवकी १४-१५ ३७
 २५०-५१, -पुलिस कमिश्नरकी ५९०-९१, -भारतके
 वाइसरायकी, ३७२-७३, -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी
 ३३२-३४, -मगनलाल गांधीकी २७३ २९०,
 -मणिलाल गांधीकी ३७४-७५, -म० द० आ० रेलवेके
 महाप्रबन्धककी ४३६ ४४३, -रैड डेली मेलकी
 ६७-६८, ८६-८७ १६३-६४ १८२ २६४-६५,
 २७६-७७, -सर विलियम वेडरबनकी ३१९ ३२३-
 २४, -स्टारकी ३५-३७, ७०-७१ ८८-८९
 १७८-७९ १८१ २९१-९३, ३०१-२ ४६५-
 ६७ डब्ल्यू० वी० हल्लेस्टेनकी २३५-३६
 परवाना कार्यालयके बहिष्कारका भित्तिपत्र ११८
 पाठकोंकी सूचना १९०
 पीटर्सबर्गकी बवाई १६७
 पीट्सके मुकदमोंसे लेने योग्य मील २९४
 पूवका ज्ञान ४२-४३
 पूर्व ज्ञान माला ९९
 पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा ५४-५५
 प्रधान मंत्रीके विचार २१८-१९
 प्रवास प्रार्थनापत्र १९९-२०१
 प्रस्ताव सावजनिक सभामें ३५६

प्रस्ताविन समझौता १८९

प्रायनापन -उच्चायुक्तको, ३८४-८५, -गायकवाड़को

३८३, -ट्रान्सवाल विधानसभाको ९२-९३, -ट्रान्सवाल

विधान परिषद्को ११५-१६, -तुर्कीके महा वाणिज्य दूतको

२६६, -नेपाल विधानसभाको, ११७

प्रिटोरियाकी लड़ाई ११८-१९

प्रिटोरियाकी आम सभा ८०-८२

प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभाके प्रस्ताव, १४२

फोक्सस्ट्रेक मुकदमे ४२३

बचे हुए मेमन ३६३

बढ़ाई गई अवधि ३४०

बहादुर नियाँ, ४४९

बहादुरी किसे कहा जाये? २०६

बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता २०३-४

बीच रह ज़रि जाय २६१

बेरोजगार लोगोका क्या किया जाये? ४४८

ट्रान्सवालकी भिन्न, फिर भारतीयोंकी सहायतापर

३२५-२८

भारत और ट्रान्सवाल ६२

भारतकी दशा ४५१-५३

भारतके राष्ट्र पितामह ३०९

भारतके खालाजाने क्या किया? ३६३-६४

भारतके सेवक, १३-१४

भारतमें उथल पुथल ६-७

भारतसे कुमुक २४३-४४

भारतसे सहायता २५७

भारतीय प्रस्तावका क्या अर्थ? १६६-६७

भारतीय फेरीवालोंके खिलाफ लड़ाई २५९

भारतीय मतदाता २६७-६८

भारतीय मुसलमानोंसे अपील १७९-८०

भारतीय राजा ७-८

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चन्दा, ३६२

भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय, २४३

भारतीयोंका मुकदमा, ४१९-२०

भारतीयोंकी कसौटी, ९७

भारतीयोंकी परेशानी, २३०

भारतीयोंपर हमला, ४२५-२७

भाषण, -कांग्रेसकी सभामें २११-१३, -चीनी सभमें

३९४ ९५, ४६८, -डर्बनमें, २१०, -नेपाल भारतीय

कांग्रेसकी सभामें, ११४-१५, -प्रिटोरियामें, १३९-

४१, -प्रिटोरियाकी सभामें ६६-६७, -सरकारी

चौकमें ४६४-६५, -हमीदिया अजुमनकी सभामें,

३८२, -हमीदिया दस्लामिया अजुमनमें, ९९ १६०-

६१ २६५ ३७२, ४४४ ४४४-४७

भीमकाय प्रायनापन २३७-३९ २३९-४०

मठ -ट्रान्सवाल लीडरको ३५१-५२, -रेड डेली

मेलको ६०-६१ १४३, -रेड डेली मेलक प्रति

निधिको ८२-८३, -रायटरको, ४६९

मानव जातिका विस्मय ११९-२०

मिस्रमें स्वराज्यका आन्दोलन, २६२

मुहम्मद दशाकका मुकदमा ४०७-८

मेमन लोगोकी विपरीत बुद्धि ३०६-७

मोरक्कोमें उपद्रव १७०

यूसुफ अली और स्त्री शिक्षा ५१

रामसुन्दर पण्डित ४१२ ४३८ ३९, -का मुकदमा, ३५१,

३५२-५६ ३६५-६७

राष्ट्र पितामह ३०६

रॉसका पत्र, १५८

रिचका प्रयास, २३०

रिचकी संघर्ष २९३, २९५, ४१०-११

रूसका उदाहरण, १२८-२९

रोडे़शिया और ट्रान्सवाल ४१

लन्दनमें मुसलमानोंकी बैठक, ३२८

लन्दनमें मुसलमानोंकी सभा ३६२

लाजपतरायकी रिहार्ड ३६१

लॉर्ड एम्प्टहिल ६२-६३ ६५

लेटास्थिमक परवाने, २०४-७

लेडीमिथक भारतीय व्यापारी ३०८

लेडीमिथक व्यापारी २०१-२

लेबिटी-वे, १११

वा-बर्गीका भाषण, २८२

वानेन परवानको अपील २४०

वीर क्या करे? ३-५

शाही रवाकृति, ३९

श्री अलीका विराट १५३

श्री आदम-नी मियाँखोंकी मृत्यु १२१

श्री गांधीका सूचना, १९१-९२

श्री दाजद मुहम्मदको बधाई ४५०-५१

श्री पारसी रस्तमजीकी उदारता, १२०-२१

श्री पी० के० नायडू और अन्य लोगोका मुकदमा, ४६० ६४

श्री लैबिस्टर, ३३७

श्री हॉस्केनकी ' अवश्यम्भावी ', १५१-५२
 सच्चा मित्र, १९३
 सच्ची मित्रता ३२५
 सच्ची राये १५
 समझदारके लिए इशारा, ३३९
 सम्राट्की सालगिरह ३६१-६२
 समितिकी भूल २५-२६
 समितिकी लड़ाई १५५
 समितिकी सलाह, ७४
 सविनय अवज्ञाका धर्म २१४-१५
 सुस्वागतम्, २१६
 स्मट्सका भाषण २८०-८१
 स्वयंसेवकोका कर्तव्य, २६०
 स्वर्गीय अधीक्षक अलेक्जेंडर ३०९
 स्वर्गीय आराध्यून ४२२

स्वर्गीय काल ब्लाड २७
 स्वर्गीय नवाब मोहसीन उल मुल्क, ४२४
 स्वर्गीय श्री अलेक्जेंडर, ३०४
 हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन वृत्ता त क्यो बन्द
 हुआ? २०५-६
 हनुमानकी पूछ १६८
 हम कानूनके विरुद्ध क्यो है? ३९७-९९
 हम विरोध क्यो करते है ३९६-९७
 हमारा कर्तव्य १५६
 हमारा परिशिष्ट २६०, ३९९-४००
 हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र १९४
 हाजी हबीब ४३८
 हिंदू विधवाएँ क्या कर सकती है? २७-२८
 हेगर साहबका नया कदम १७०
 हेजाज रेलवे, ५०

साकेतिका

अ

अगद ६३

अंगुलियो —और अंगूठमें भेद, ४५६-५७, —की निशानोंका नया कानून, ४७

अंग्रेजी राज्य —की बुराईयों, ७

अंग्रेजी शब्दों, —के लिए गुजराती शब्द, ४५१

अकबर ४९

अकबारी, —की पत्र ३३४

अखबारों सौदागर, —द्वारा उमर हाजी आमद शेखरीका समयन, १५९

अखिल इस्लामिया अजुमन ५०

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, —को अजुमनका पत्र, ३९२

अजीतसिंह ३६१

अधिकारियों, —की यह दौड़धूप, ३३२

अधिनियम, —तथा स्वेच्छया पजीयनमें अंतर, १४१

अधिवास प्रमाणपत्र २२२

अनाक्रामक प्रतिरोध, १६३, ४१८ ४४१, —अपनी मच्ची शिकायतोंको दूर करनेका सही तरीका १५२, —भारतीयोंके लिए एक नया मार्ग, ८६, —सितम्बर १९०६ से प्रारम्भ ३३५, —का नेतृत्व करनेवालोपर मुकदमा चलानेके लिए सरकारको बधाई, ४६५, —का प्रचार, ४७२, —का मार्ग अन्याय दूर करनेके लिए, ३३३, —का मार्ग सबसे अच्छा और निरापद, ४६६, —की नीति, ४६७, —के लाभ २१७-१८, —के लिए भारतीय मुसीबतें झेलनेको तैयार, ३२१, —पर काँ गई न्यिष्णीकी आलोचना, ६७, —पर योग्य चित्र, ३१६

अनाक्रामक प्रतिरोधी, —के रूपमें मुहम्मद दशाक, ४१७ १८, अनाक्रामक प्रतिरोधियों —की ओर बहुत से गोरे आकर्षित, ३३२, —द्वारा पजीयन नहीं, ३२२

अनिवार्य पजीयन ६३, —और स्वेच्छया पजीयन २७१,

—और स्वेच्छया पजीयनकी श्री रिच द्वारा तुलना, ४१०

अनुमतिपत्र, २९२, —और पजीयनपत्र साजेंट मैन्सफील्ड द्वारा प्रस्तुत, ४२०, —खो जानेपर कर्तव्य, ४४,

—न लेनेक सम्बन्धमें श्री लेनटका मत, ५६-५७, —प्रवेश और पुन प्रवेशका अधिकार देनेके लिए पर्याप्त, ४१९, —लेनेसे चैमनेक पजाबों नौकर द्वारा इनकार ९७, —शान्ति रक्षा अध्यादेशके अंतगत अनुपलब्ध ११६, —का फिस्सा, ३३, —का मुकदमा १२-१३, ३३, —के लिए ३० पौड, १३, अनुमति पत्रों —की जाँच ३८६, —की सहाय जो शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत भारतीयोंको दिये गये, ३२१, —पर निशान, १८०

अनुमतिपत्र अधिकारी —द्वारा एक निजी मकानमें पजीयनके लिए रातको अर्जियों उपलब्ध ११८

अनुमतिपत्र अध्यादेशके अंतर्गत मुकदमा, ४२५

अनुमतिपत्र कानून, ५७

अनुमतिपत्र कार्यालय १०, ८९ १३३ १४५ १६२, २५३, —का गाँव गाँव भ्रमण, १६६, —का ट्रान्सवालमें बहिष्कार ९८, —का पीटर्सबर्गमें शत प्रतिशत बहिष्कार १६७, —का बहिष्कार, १४५ २३४, —का बहिष्कार करनेका मतलब, ९, —की महामारी, २२३, —के बहिष्कारके प्रति भारतीयोंमें जोश २५३, —के बहिष्कारको उचित साबित करनेवाला फिस्सा ३३, —में एक भारतीयको ले जानेके कारण इमामपर मारपीट ३०१, —में एक भी अर्जी नहीं, ११८, —में जबरदस्ती अँगुली लगावनेका प्रयत्न, १७६, —से भारतीय समाजको धब्बा १७२, —से व्यवहार मान बन्द ४४

अनैतिकता अध्यादेश, ९२

अपील, —के विनियम ४२७-२८

अफगानिस्तान, ३४, —का अमीर, ४९

अबा हाजी, ८१

अब्दुर्रहमान अमीर, —भारतीय राजाओपर, ७ ७२,

—का शासन १०१, —द्वारा अफगानिस्तानकी राज्य

व्यवस्थामें सुधार, ३४

अब्दुल, सरदार, ४५५

अब्रेसलाम, यूसुफ, १२३, —की खुदासे प्रार्थना, ८१

अमीजी, बगस, ४५७

अमीरुद्दीन, देखिए फजन्दार, अमीरुद्दीन मुहम्मद हुसैन

अम्बाई लाल, देखिए अम्बालाल

अम्बादास १९८

अम्बाराम, —का देश सेवापर प्रभातशाली भाषण, ३७२

अम्बालाल, ३७१ ४४५ पा० टि०, ४७०

अयूब, नूर मुहम्मद —का भाषण ८१

अर्नेस्ट एवर्टकी पेढी २०८

अर्नेस्ट, डेविड, १०२

अरबी ज्ञान, ४५३

अरमिली, ३२० ३३० ३५०, ४५६, —में श्री केरसवील

२४५

अरमुगम, ३००

अर्जुन,

अलइस्लाम, ३१०

अली अमीर ३६० ३६२, —की इस्लाम सम्बन्धी पुस्तकका
प्रकाशन ५४

अली इसे ४५७

अलीगढ ६६

अलीमाई ३६७

अली, युसुफ —द्वारा स्त्री शिक्षापर पुस्तक ५१

अली, सैयद —का मुसलमानी प्रशासनपर लेख ३४-३५

अली, हाजी वजीर, ८० १२३ पा० टि०, १२५, २०७,

—का अमीर अलीको पत्र, १२४, —का विरोध १५३,

—का समाचार पत्रोको पत्र, १५६, —की भूल, १२४

अलेक्जेंडर, २९० ९१ २९९, ३०४, —की मृत्युपर गाधीजी,
२०९

अस्वात, इब्राहीम १३७, १९८ २५४ ३६५, ३६७,
४१४

अहमदखौं ४३१

अहमद, अली, २८८

अहमद उस्मान, ४२४

अहमद मूसाजी, २४४

अहमद, मुख्तार मौलवी १७४, २२३, २२५ २८०,

२९६ ३१० ३६५-६६ ३७१, ४३१, ४३९ ४४४
४५०, —एशियाई अधिनियमपर १४१, —जमन पूर्व

आफ्रिका लाइन कम्पनी द्वारा भारतीयोंके साथ किये
जानेवाले दुर्घटनपर, ३१३, —का जोशीला भाषण,

२५३ २६९, ३२९ ४८१, —का मियादी अनुमति
पत्र ४५५, —की मददसे तुर्कों वाणिज्य दूतको एक

अर्जी, २७०, —द्वारा म य दक्षिण आफ्रिका रेलवेका
एक पत्र पेश करनेपर सनसनी ७१

अहमदाबाद, १२१-२२

आ

आँगलिया एम० सी० ११७, १४४ ३७३

आकुजी, अलीमाई ३१, २४४, ३१० ३६५, ४३१

आजम गुलाम मुहम्मद, ३८७

आठवले श्रीमती, २८

आत्मकथा, ४ पा० टि०, ९५ पा० टि०

आदमजी, मुहम्मद २४४

आनन्दजी, नीमजी ८१

आनन्दजी मूसा १३७

आफ्रिकी भारतीय सच (केपटाउन), —का ब्रिटिश भारतीय

सचके नाम सहानुभूतिका तार, ३८१

आब्जर्वर, २४१

आमद, अबूबकर, ४३२, —को जायदाद, ४३५

आमद मूसाजी ऐड कम्पनी, १६३

आयलड, —में हकीके लिए हलचल, २१७

आराधन, —की मृत्युपर गाधीजी ४२२

आर्कबिशप, २१५

आलब्रेट, गी०, ३८६, —का पत्र दर्जियोंके नाम, ३६७ ६८,

—की ग्राहकोसे क्षमा याचना, ३६८-६९, —के नाम

२१ यत्तियोंका पत्र ३६८

आशाबीबी —का विवाह ४५०

इ

इंग्लिशमैन, २५७

इग्लैड, —की बहादुर खियों ६५, ४४९

इंडियन ओपिनियन, ९ पा० टि०, १० १४

पा० टि०, ३१, ३५ पा० टि०, ३८, ५५ पा० टि०,

५६ ६० ८० पा० टि०, ८२, ९५ पा० टि०,

१०३ १०५ पा० टि०, ११०, ११४, १३३ १३९,

पा० टि०, १६५ पा० टि०, १७८ पा० टि०,

१७९ पा० टि०, १८१ पा० टि०, १८३ पा० टि०,

१९०, १९८, २०५ पा० टि०, २१२, २३३ पा० टि०,

२१६ २२० पा० टि०, २२७ पा० टि०, २४८-५०

२६९ २७० पा० टि०, २७८-७९ २८४ पा० टि०,

२८५-२८६ पा० टि० २८८, २९९, ३०१ पा० टि०,

३०५, पा० टि०, ३०९ पा० टि०, ३१५-१६ ३२०

पा० टि०, ३४१, ३५९ पा० टि०, ३८३ पा० टि०,

४०८ पा० टि०, ४१५ ४२१ पा० टि०, ४३१,

४४५ पा० टि०, ४५३ पा० टि०, ४५८, ४६५

पा० टि०, ४७४ पा० टि०, ४७५, —का क्षेत्र

दक्षिण आफ्रिका भारतीयोंपर असर करनेवाले प्रश्नोंतक ही सीमित नहीं १, —को पत्र १७७, ३५९-६०, ४०१-२२

इंडियन रिव्यू, ३४

इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, १३

इंडिया, २१६ ३०६

इनर टेम्पल, ४५८

इब्राम २४०

इब्लीस, ४२

इब्राहीम जुसब १६३, ३६५

इब्राहीम मुहम्मद २२७, २७०

इब्राहीम हाजी ८०, २०३ ४४२, —एक गद्दार ३९३, —का भाषण ८१, —द्वारा मेमन लोगोके नामपर बन्ना १४५

इमाम, २४९

इमासुदीन १३७

इर्विंग, वाशिंगटन, २०५, —का परिचय ५५, —द्वारा रचित पैगम्बरका जीवन-चरित्र, ५४

इरानी सूफी, ४२

इलाही, फजले, ३८५, ४०९

इवान् १०९

इशाक, मुहम्मद, ८० ४०८ पा० टि०, ४१८, ४२१ पा० टि०, ४२३, —एक अनाकामक प्रतिरोधीक रूपमें, ४१७ १८, —का मुकदमा, ४०७ ४२६, ४३३, —द्वारा जमानतपर टूटनेसे इनकार, ४२७

इशाक शेख मुहम्मद, २४६, —का उदाहरण याद रखने लायक, ३४६

इस्माइल, अलीभाई, १३७

इस्माइलखॉ, ३८८

इस्माइल, मुहम्मद, १३७

इस्माइल, ईसा, २२७, २७०

इस्माइल, ए० जी० —भारतीयोंके जेल जानेपर, १०

इस्माइल, गनी, —का पश्चाताप, ३४६

इस्माइल, दाऊद, २४४

इसाक, मूसा, १९८

ई

ईद, —की सुवारकवादी, ३३८

ईसप, मुहम्मद, १७४

ईसा, ३६, १२०, १२३

ईसा, इस्माइल, —पर फरेबका आरोप, २०८

ईसे, अहमद २४४

इस्टन, मार्टिन ४४५ पा० टि०, ४६२ ४७० ४७२

ईस्ट लन्दन १०, —में पैदल पटरियो तथा वस्तियोंके विशेष नियम १५७, —से प्रोत्साहन १०

उ

उगत, एम० एच०, ९९ पा० टि०

उच्चायुक्त —के नाम तार, ३८१, —के निजी सचिवके पत्र ४०५-७, —को गांधीजीका पत्र ४०९, —के प्रायनापन २८४-८५

उपनिवेश मंत्री, —को आवेदनपत्र, १८३-८६, —के तार ३७३

उपनिवेश सचिव, —का प्रिटोरियाके सोलिसिटोके पास उत्तर, ३३६, —के नाम भेना गया मामकाय प्रार्थनापत्र ३४९-५०, —के नाम हाजी हथीबका पत्र १३६ —को किसी भां एशियाके मुहती पजीयन पत्र देनेके अधिकार २२, —का गांधीजीका पत्र, ३३५, —के पत्र, ४८ १०५, १३४, २१३, २७४ ७५, ३२० २१ ४०८, ४३४ ३५, —को प्रायनापन भारतीय समाजके ओरसे नहीं, ३३४, —को प्रिगेरिया, स्टैण्डन, पीटर्सबर्ग और मिडेलबर्गके व्यक्तियोंका प्रार्थनापत्र ३३४, —के ब्रिटिश भारतीय सचका प्रार्थनापत्र ३३५, —द्वार भारतीयोंकी प्रार्थना स्पष्ट शब्दोंमें अस्वीकार ११०

उमर, अली, १३७, २४४

उमरजी, ८०-८१, १३७, ३१८, ३२५, ३६६, ४३९ —का जोशीला भाषण १०१, —का रायमें खून कानूनके सामने आत्म समर्पण असम्भव २६९

उमर, हाजी, —पर बोखेवाजीका इलजाम ९०

उलु, —और मलिक परिवर्द्ध, ३४

उस्मान, दादा, ११७, १४४ ३७३

उस्मान, सेठ दाउद, ३७०

उस्मान, हाजी, ८०-८१

ऊ

ऊर्ण विधेयक (लोन बिल), २४१

ए

ए० एफ० केमे एंड कंपनी, १६३

एडवर्ड सम्राट, ४९, ७१, १२०, —की सालगिरहप भारतीयोंकी ओरसे सुवारकवादीका तार ३६१, —वे पौत्रकी तालीम,

एबनेजर विद्यालय, १०१

एमटोगा -का मुकदमा, १

एम० सी० कमरुद्दीन एंड कम्पनी, १६३, १८०

एमपायर नाटकघर ६१ १४६ २४६ ४३०, -की सभा, ८३, -में ली गई शपथ, १७२

एलगिन लॉर्ड, ६२-६३, ६७, ७२ ८६, ९४, ९७
१३८, २०० २२२, ४३२ ४४५ ४७ ४५७, ४७१,
-का उत्तर, २८, -का वक्तव्य १०७, -को जनरल
बोथा द्वारा आश्वासन ३९, -को प्रवासी प्रतिबंधक
विधेयक के बारे में प्रार्थनापत्र, १९९-२०१, -द्वारा
नगरपालिका मताधिकार कानून नामजूर २१२,
-द्वारा नेटाल नगरपालिका अधिनियम अस्वीकृत,
२१९, -द्वारा प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमको मजूर
करके भारतीयों की राजभक्ति पर अनुचित भार ४४४
४५, -से अध्यादेश के सम्बन्ध में मुलाकात १५३

एल्फिस्टन, जनरल माउंट स्टुअर्ट -का एक पठान से
प्रश्न, ३४

‘एशियाई’, -शब्द का अर्थ, २९

एशियाइयो, -का पतराज श्री डफन द्वारा दबा देने की
सलाह १५३, -के आग्रजन पर डेलागोआ बैकी सरकार
द्वारा प्रतिबंध, ४४७, -के कानून मान लेने पर
उनकी गुलामों की सा स्थिति १४०, -के पजीयन के
आवेदन पर १३४, -के लिए द्रा सवाल में कानून ४१,
-को गोरे केवल अपनी गधा मजूर करवाने के लिए
रखने को तैयार, ३९९, -द्वारा गांधीजी की सीख पर
पजीयन पत्र लेने से इनकार २४९, -से अधिनियम का
विरोध करने के बारे में प्रश्न ३५९

एशियाई आबादी -का प्रायः आधा भाग जोहानिसबर्ग में
२५७

एशियाई कार्यालय, ३५२, -की कायबाही गुप्त, ४२१, -की
सचिवाई ४३९, -से श्री बर्जेस को छुट्टी, ४४२

एशियाई पजीयक -को कतिपय भारतीयों द्वारा पत्र २२८,
-की गांधीजी का पत्र ४७५, -को पत्र, २२७

एशियाई पजीयन कार्यालय, देखिए एशियाई कार्यालय

एशियाई प्रतिस्पर्धा, -का डर उचित, २७२

एशियाई प्रश्न ३२७, -की पुनर्चर्चा, ८६

एशियाई भोजनालय ९१, -में यूरोपियन मैनेजर रखना
अनिवार्य, ६९, एशियाई भोजनालयों -के सम्बन्ध में
सफाई अर्जी ३८७

एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, ४२२

एसेलेन, स्त्रैगमान, २२४ पा० टि०, २३७, २३९ पा० टि०,

३२०, ३३४-३६ ३४९ ४३०

एस्टकोर्ट, १३७ २१३, -के निकाय द्वारा अपील करने की
माँग, २१३, -के भारतीयों की अपील १५८, -के
स्थानिक निकाय की अपील, १९४

ऐ

ऐंडर्सन, आल्फ्रेड, ३५८ पा० टि०

ऐफ्रिकांडर बॉड, १२६ पा० टि०

ऐम्स्टहिल लॉर्ड, २८ ६३ ११०, २६१ २९३, -दक्षिण
आफ्रिका के ब्रिटिश भारतीयों के कष्टों पर, २५७, -नये
कानून पर ३०, -का लॉर्ड्स में भाषण, ६५, -की
माँग पर एशियाई अधिनियम सम्बन्धित पत्र व्यवहार
सदन में पेश १०५, -के दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश
भारतीय चिरकृतज्ञ, ६२, -को जनरल बोथा का
आश्वासन ७१

ऐयबजी, अब ३१६

क

कड़ोदिया, १९८

कड़ोदिया, गुलाम, ३१८

कमरुद्दीन अबूमिर्या, ३८०, ४१६

कमरुद्दीन, अहमद कासिम ३९९

कमरुद्दीन सेठ एम० सी०, -की पेंढ़ी, ४३९

कमालखॉ, ३८०

कमाली इमाम २९८, ३१२, ३१८, ३३०, ३७६ ३८१
कम्पेनियन (दि आर्डर ऑफ) सेट माइकेल एंड सेट जॉन,
१४८ पा० टि०

करवा, ४४५ पा० टि०, ४७०, ४७२, -का बयान, ४६२

करीम सेठ अब्दुल ३७१

करोड़िया, एम० ए० १६३

कर्जन, लॉर्ड, ७२

कर्त्ति, ५८, २२०, -और नया कानून ५०, -का
पॉचेफस्ट्रूम व्यापार मण्डल को उत्तर, ५७-५८, -का
वक्तव्य, २००

कबला, १२३ पा० टि०

कर्वे, आचार्य धोंडो केशव, २७

कॉक्स, १९८ २४१, -का भारतीयों के हकों की रक्षा के
सम्बन्ध में नोटिस, १५५

काछलिया, ए० एम० ६९ ८०-८१ ८९ १३५, ३५८
पा० टि०, ३६५ ३६७, ३७० ४१५, ४३१,

४३९, ४४५ पा० टि०, ४७०, —की रूजसे
 बातचीत ३४१
 काजी, ६९ ९५
 काजी आई० ए०, १९८
 काजी, एम० ई०, २०८
 कादिर इमाम अब्दुल देरिए वावजीर, इमाम अब्दुल कादिर
 कानमिया, मुहम्मद इस्माइल २५०, ३६७, ४१४
 कानून ३ १८८५, १६ १९ २३ १०७ ४०० ४०६,
 ४२०, ४२६ ४३५, ४६२
 काफिर भोजनगृहो — और फेरीवालेक परवाने नगर
 पालिकाके हाथमें ४४०
 काफिरो सम्बन्धी कानून — और बीयर विधेयक पास, ३२४
 काबुल ७२
 काबुली, मीर अफजुल्ला १३७
 कामा, नादिरशाह, ८०, २४४, २४९, —का भाषण,
 ८१, —के प्रश्न, १०१
 कामा और कम्पनी, १७३
 कामा श्रीमती भीकाईजी हस्तमज्जाक० आर० —का जोरदार
 पत्र १६०
 कामेल पाशा, मुस्तफा, —के कामका प्रभाव २६२
 कारा बूसा, २२७
 कारा, मूसा, २७०
 कारा, बली, २२७ २७०
 कार्टराइट ४१५
 कार्डीज, ९६
 काला, इसन अहमद ४२८
 काला, हासिम मुहम्मद १७२, —का पश्चात्ताप, ३४४
 कालिकाप्रसाद, ३६३
 कासाल्लेका, १७०, २०६
 कासिम, सुलेमान मुदजी २७१
 कासिम, हाजी, १४७ २३०, ३२८-२९, ४३९,
 —प्रियोरियामें पजीकृत, २५६, —मुख्य दोषी, २२९,
 —का भाषण, ८२, —का स्पष्टीकरण, २८५-८६
 किदवई, —का उत्तर ५०
 किमनिंग, —का स्टारको पत्र, ५९
 किम्बलैं, ११, —की गलतफहमी १०-११
 कीकाभाई, गुलाबभाई, ८०
 कीडिया, शीणा, ४२६
 कुरान शरीफ, ३२९, ४५३
 कुरान शरीफका सार, ४३
 कुरान शरीफको सार, ९९ पा० टि०

कुवाडिया ३१, २४३ २४६, २४९, २८८ २९८,
 ३२९, ३६७ ३७० ३७४ ४१४, —को उत्तर, २८८
 कुवाडिया अहमद (आमद) सालेजी १७५ ३७१
 कुवाडिया, इब्राहीम सालेजी १८० २१० २६९
 कुवाडिया, एच० ए० २९६
 कुवाडिया एम० एस० ८० १६३, २२५, ३१०, ३४०,
 ३६५, —की पत्नीका स्वगवास, १७४, —द्वारा अन्य
 वक्ताओंका समयन ८१
 कृषि समिति डर्बन, —का ओछापन, १५९
 कृष्ण श्री ३३८
 केप —का प्रवासी कानून २८२, —का सच, २६८, —के
 भारतीय लापरवाह, १२५
 केप टाइम्स, २७७
 केप टाउन —से सहानुभूतिका तार, ३८१
 केप समद, —का नया चुनाव १२५
 केशवजी खोजा वेलजी ४४०
 कैवस्टन हॉल —में मुसलमानोंका सभा ३६०
 कटरबरी, —के आर्क बिशप २१५, —के सदेश २१४
 कैनेडल, —का जॉर्डनके फैसलेपर लीडरमें पत्र ४७५
 कैम्बेल, लॉर्ड फॉलिन ४
 कैरोलिना, —में श्री जॉन २४५
 कैलनबैक, हरमान, ५२-५३, —एशियाई पजीयन अधि
 नियमपर, २५, —को गांधीजीकी बधाई, ३१, —का
 जेलके निगयको बल देनेके लिए स्टारको पत्र, ३०-३१
 कोकणी, —और मेमन कानूनकी लड़ाईमें पस्त हिम्मत,
 २०३, कोकणियों, —की सभा, ३८८
 कोकाटी, अब्दुल कादिर २९६
 कोठारी, —का पत्र, ११०
 कोइथा, इस्माइल हाजी आमद, ३४६
 कोडी, १००, २२०, २६५ ३८२, —की जिरह, ३५८
 कोडी, जेम्स, २४५
 कोडी रिचर्ड टेरेन्स ७९, २४५
 कोमाटीपूर २२७, —से लोटे हुए चार भारतीय, २७०
 कोजी, अनरल, ४७२
 क्राउन डॉक्टर, ४
 क्रॉमवेल, १२३
 क्रॉस, —के सामने भाणा छीनियाका सुकदमा, २८९
 क्रिटिक, —में व्यंग्य चित्र, ४४१
 क्रिश्चियाना, ३२०, ३३१, ३५०
 क्रिस्टन, ४५६
 क्रोमिया-युद्ध, ४ पा० टि०

गूर ४, -राष्ट्रपतिसे ट्रान्सवालके भारतीयोंकी तुलना ११९
कूटसर्वोप १५१, १७६, २४५ ३२०, ३५० ३६५ ४१४
कूट ४२

क्लाक्सवोर्प १६१ २५२ २५४, ३२० ३३०, ३५०,
-और पॉचेम्स्ट्रूमपर धावा १७२, -और पॉचेम्स्ट्रूममें
पजीयन कार्यालयकी असफलता १९५, -का अखबार,
३१६-१७, -के अखबारके सम्पादककी भारतीयोंको
सीख ३१७, -में पजीयन कार्यालय १६८, -में
श्री नेसरका भाषण २५५

क्वाई चाऊ ३९४ पा० टि०, -का चीनी सवको पत्र,
३६९, -के पत्रपर श्री क्विनकी टीका, ३७०

क्वाजानशाही -और दरबारेशाही ३५

क्विन लिअग २६९, ३६०, ३९३, ४१४ ४३९, ४४५
पा० टि०, ४७० ४७४, -का अखबारोंको पत्र, ३६९-
७०, -का बयान ४६२, -की चाऊ क्वार्डके पत्रपर टीका
३७०, -को १४ दिनके अन्दर ट्रान्सवाल छोड़नेका
नोटिस ४६३

ख

खडेरिया मोहनलाल, २२४ ४४५ पा० टि०, ४७०
खमीसा, अली १४५ २०३ ३४६, -शतरजकी बाजीमें
एक प्यादा, ३१६ -का दूकानमें गुप्त तरीकेसे
पजीयनपत्र वितरित ३६९, -की दूकानमें षडयन्त्र,
१३५, -की नये अनुमति पत्रके लिए अर्जों न देनेवाले
भारतीयोंकी धमकी १३७

खान मजदूरी -की हडताल, १०

खान, हवीबुल्ला ३५

खुशाल खल्द ८०, ४२६

खोटा, ३८०, -का पश्चात्ताप, ४१६

खोल्लाड भदरमा, ३८७

ग

गगादीन, ४७०

गगाराम, वी०, ४४५ पा० टि०

गजनवी, महमूद १२०

गद्दार् -की सल्यामें अभिवृद्धि ३३१, ४३९, -की सूची,
३४७, ४५६, -से गांधीजीकी विनती और उन्हें
सलाह ४४०

गनी अब्दुल, २७ ३१, १३९ १८०, १९८ २९८
४१४, -और गुलाम मुहम्मदपर गाढीसे प्रिडोरिया
जानेके लिए रोक, २०७, -का भाषण, ३८८

गफूर, अब्दुल ३३०, ३८८, -का श्री कमरुद्दीनके नाम
तार ३८२

गलाल, माथा, ४२६

गवर्नर -का नियम बनाने और रद्द करनेका अधिकार
क्षेत्र २२-२३

गांधी खुशालचंद, ३८ पा० टि०

गांधी छगनलाल -को गांधीजीका पत्र ३८ ९५ ९६

गांधी मगनलाल ३७४, -को पत्र २७३ २९०

गांधी मणिलाल, -को गांधीजीका पत्र ३७४-७५

गांधी मोहनदास करमचन्द ९ ३० ३५ पा० टि०,

६९ ८० ८४ ९० पा० टि०, ९५ पा० टि०,

९६, १००-१ ११८ १४२ पा० टि०, १४९ ५०

१६० पा० टि०, १६२ पा० टि०, १७६ १७९

पा० टि०, १९८ २०५ पा० टि०, २०७ २१४

पा० टि०, २२० २२३ २३० २३१ पा० टि०,

२४६ २५३ २६४ पा० टि०, २६९, २७३

पा० टि०, ३०५ पा० टि०, ३०७ पा० टि०,

३१० ३१६, ३२९ ३३१ पा० टि०, ३४०, ३४३,

३५१, ३५३-५५ ३५६ पा० टि०, ३६५-६६,

३७०-७१, ३७४-७५, ३८४ पा० टि०, ३७९,

३९० ३९३, ४०७, ४०८ पा० टि०, ४२०,

४२२ ४२५ ४३१ ४४६ ४५६ ४७०, ४७३-

७४, -अंगुलियोंकी निशानीपर ८४, -अनाक्रामक

प्रतिरोध आंदोलनके नेता १७४, -अपने द्वारा दी

गई जेल जानेकी सलाहपर ११४ -आदमजी मियाँ

खोंकी मृत्युपर, १२१-२२, इंग्लैंडकी स्त्रियोपर ६५,

-ईसापर १२०, -एशियाई अधिनियमके फलितार्थोंपर,

११४ पा० टि०, -कन्याओंकी शिक्षापर ६६, -कानूनके

प्रभावपर, ८०, -कानूनपर २६९, -खुदाई कानूनपर

१२२, -खूनी कानूनपर, १०१, -गोरोंकी बढ़ती हुई

सहानुभूतिपर ४१३, -जूरी प्रणालीपर, १२,

-जेल जानेवाले लोगोंके बाल-बच्चोंकी रक्षापर, १७५,

-डेविड योरोपर, ३०५, -दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश

भारतीय समितिकी आवश्यकतापर २८८, -दक्षिण

आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकी भूलपर, २५,

-दादाभाई नौरोजीकी जयन्तीपर २०२, दादाभाई

नौरोजीकी बीमारीपर ३०९, -धरनेदारोंके कत'बपर

२८७, -नये कानूनपर, ६६ ६७ ८३, -माननीय

अमीरपर, ७२-७३, -मारपीटके खिलाफ ३३१,

-श्री अराथूनकी मृत्युपर ४२२, -श्री काल लाइवके

निधनपर, २७, -श्री रामसुंदर पण्डितके जेलसे

डूटनेपर, ४३९, -रामसुंदर पण्डितपर, ४३८, -श्री
 लेबिस्टरकी मृत्युपर ३३७, -श्री वाइवर्गके भाषणपर,
 १०७-८, -श्री स्मट्सके उत्तरपर, २८५, -श्री हाजी
 हबीबपर, ४३८, -सुपरिटेण्डेंट अलेक्जेंडरकी मृत्युपर,
 ३०९, -स्टार की संपादकीय टिप्पणीपर १७८,
 -स्वर्गीय नवाब मोहसीन उल मुल्ककी जनतनशीनीपर
 ४२४, -स्वेच्छया पजीयनके अर्थपर १६६, -फा
 इंडियन ओपिनियनको पत्र, १७७ ३५९ ६०, ४२१
 २२, -फा उच्चायुक्तके सचिवको पत्र, ४०५-७, -फा
 उच्चायुक्तको पत्र ४०९ -फा एम्पायर नाटकपरमें
 भाषण ६१, -फा एशियाई पजीयनको पत्र २२७,
 ४७५, -फा कांग्रेसकी सभामें भाषण, २११-१३,
 -फा जनरल स्मट्सके नाम पत्र १९५, -फा जनरल
 स्मट्सके निजी सचिवको पत्र १४८-४९ १६४-६५,
 -फा ट्रान्सवाल लीडरको पत्र, ३२२ २३, ३४८-४९,
 -फा डब्लूमें भाषण २१०, -फा दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश
 भारतीय समितिको पत्र २८९, -फा नेटाल भारतीय
 कांग्रेसकी सभामें भाषण ११४-१५, -फा न्याया
 धीशको उत्तर, ४२०, ४६४, -फा पत्र, ५३, -फा
 पत्र उपनिवेश सचिवको, ४३५, -फा पत्र स्टार की
 टीकाके जवाबमें १९७-९८, -फा पत्र, -स्टार
 के नाम २९-३० ७०-७१ ९०, १७८-७९,
 १८१, २०१-२ २९२-९३, ३१४-१५, ४६५-६७,
 -फा पुलिस कमिश्नरको पत्र, २९०-९१, -फा
 प्रिटोरियामें भाषण ६६-६७, १३९-४१, ४७४,
 -फा भाषण, ३६६, -फा भाषण चीनी सभमें ४६८,
 -फा मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेके जनरल मैनेजरको
 पत्र ४३६, ४४३, -फा मुकदमा ४५८, -फा
 रैड डेली मेलको उत्तर ८५, -फा रैड डेली मेल
 को पत्र ६७-६८ ८६-८७ १८२, -फा लॉड
 सेल्वोर्नको पत्र ४३२, -फा श्री गोपालकृष्ण गोखलेको
 पत्र, ३५७ ३७५, -फा श्री छानलाल गांधीको पत्र,
 ३८, ९५-९६, -फा श्री मणिलाल गांधीको पत्र,
 ३७४-७५, -फा श्री रूजको उत्तर, १३३, -फा
 श्री सी० बर्डको बर्वाईका तार, १४८, -फा सर
 विलियम वॉन हल्स्टेनको पत्र, २३५-३६, -फा
 हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामें भाषण, ९९
 ३७२, ३८२, ४४४-४५, -फा अदालतसे अपील,
 ४६३, -फा अदालतसे तुरन्त मुकदमा चालू करनेकी
 प्रार्थना, ३६६, -फा अनुस्थितिमें काम करनेके लिए
 श्री पोलकके नामका सुझाव, ४७२, -फा अपने देश

छोड़नेके लिए ४८ वट्टेसे भी कम अवधि देनेकी
 सिफारिश ४६०, -फा अभियुक्तको केवल ४८ घंटेका
 नोटिस देनेकी विनती, ४६२, -फा अभियुक्तको छोड़
 देनेकी मलाह ४७६, -फा अम्बाराम मंगलजी ठाकरको
 बर्वाई ४८, -फा उपस्थितिका मुख्य हेतु १०, -फा
 कैलनवैफको बर्वाई, ३१, -फा गद्दारोसे विनती और
 उन्हें सलाह ४४०, -फा गवाहको विरोधी गवाह
 माननेमें आपत्ति, ३५८, -फा गवाहसे जिरह ४१९-
 २०, ४६०, -फा जनरल स्मट्स द्वारा भेजे गये पत्रपर
 टिप्पणी १९१, -फा जेलमें श्री रामसुन्दर पण्डितसे
 मुलाकात ४१५, -फा टा सवालके भारतीय समाजको
 टेक रखनेकी सीख, ७२, -फा प्रत्येक भारतीयको
 खेती करनेकी सलाह ६४, -फा फोक्सरस्टसे आनेवाले
 भारतीयोंको सलाह ८४, -फा भारतीय यापारियोंको
 सलाह १९६, -फा भारतीय समाजको कानूनके
 सामने न झुकनेकी सलाह १९६ २९४, -फा
 भारतीयोंको चेतावनी, १३२ ४१७, -फा भारतीयोंको
 जीतके कारण फूल न जानेकी सलाह, ४४४, -फा
 भारतीयोंको जुर्माना न देनेकी मलाह १३०, -फा
 भारतीयोंको सलाह, ४१४-१५, -फा भारतीयोंसे
 अधीर न होनेकी अपील, ४३७, -फा रायटरको मेंट,
 ४६९, -फा रायमें निकायको अपीलकी स्वीकृति
 मिलना असम्भव, २१३, -फा रायमें भारतीय समाजको
 अँगुलियों लगाणा कभी भी स्वीकार नहीं, ३४५,
 -फा लेडीस्मिथके भारतीय व्यापारियोंको दूकान
 बन्द न करनेको सलाह ३०८, -फा लेडीस्मिथके
 व्यापारियोंको सलाह, २०४-५, -फा लोगोको नये
 कानूनके सामने न झुकनेकी सलाह १३३, -फा
 यापारियोंको जुर्माना न देनेकी सलाह, २१२, -फा
 श्री दाउद मुहम्मदको उनकी लड़कीके विवाहपर बर्वाई,
 ४५०, -फा सर हेनरीक कथनपर टिप्पणी, ८७,
 -फा सीखसे पशियाइयो द्वारा पजीयनपत्र लेनेसे
 इनकार, २४९, -फा गिरफ्तार होनेकी सम्भावना,
 ९१, -फे जेल जानेपर अन्य लोगोका कर्तव्य, ९-१०,
 १३१, -फे बयान, ४५९, -फे मतमें अँगुलियों
 लगवाना अनिवार्य तो नहीं, १९८, -फे मतमें जीतका
 श्रेय लन्दन समितिको, २१२, -फे मतानुसार ६,०००
 भारतीय जेल जानेके लिए तैयार, ८४, -फे सुझाव
 जनरल स्मट्स द्वारा अस्वीकृत, १८९, -फे निर्वासित
 करना सरकार द्वारा तय, ३४१, -फे प्रिटोरियाकी
 घटनापर खेद, १३५, -फे धरनेदारों द्वारा बहिष्कारकी

धमकी २९६, -को श्री डेविड पोलक द्वारा श्री
हॉस्केनका संदेश ४०५, -द्वारा अधिनियमोका सन्ताप
जनक अर्थ लगानेका आरोप स्वीकार, ४६९, -द्वारा
अनाक्रामक प्रतिरोधपर की गई टिप्पणीकी आलोचना
६७-६८, -द्वारा एक बड़ा सम्भावन बनानेका सुझाव
४४८, -द्वारा गिरफ्तार किये जानेवाले लोगोका
बचाव, ४४०, -द्वारा ट्रांसवालके भारतीयोंसे दृढ़
रहनेकी अपील, १९३, -द्वारा धरनेदारोके मुकदमेकी
पैरवी ३५७, -द्वारा रामसुंदर पण्डितके मुकदमेमें
जिरह ३५२ -द्वारा प्रश्नका उत्तर, २१२, -द्वारा
बिना शुल्क बचाव करनेकी जिम्मेदारी स्वीकृत, १३०,
-द्वारा भारतीयोंको स्वयंसेवकोंके कार्यका अनुकरण
करनेकी सलाह, ८९, -द्वारा रैड डेली मेलके
प्रतिनिधिको भेंट, ८२-३, -द्वारा रैड डेली मेलको
संक्षिप्त भेंट १४२, -द्वारा शान्ति रक्षा अध्यादेशके
संशोधनार्थ सुझाव ४०६, -पर पजीयन करानेके
सम्बन्धमें झूठा दोषारोपण ३३०, -पर सबसे पहले
वार ३४१, -से रैड डेली मेलके प्रतिनिधिकी
मुलाकात ६०, -से श्री जॉर्डनकी वृद्ध ४५८

गांधी सुशीला बहन ३७५

गोंडके, जॉज २६६ ४४२, ४५८

गोंडके, श्रीमती सुमान २६६

गोंडके सुमान २६६ ४४२

गायकवाड, -को याचिका ३८८, -को पत्र ३८३

गिंसन -से श्री ईसप मियाँकी बातचीत २५३

गिरमिटिया कानून ४९

गिरमिटिया भारतीय -पर एक गोरे द्वारा मारपीट, ४१,
गिरमिटिया भारतीयों -के प्रवासमें भारतीय सिद्ध
कारणोंसे सहमत १०९, -के मालिकोंके नाम पर
११३, -को गिरमिट पूरा होनेपर वापिस भेजनेकी
योजना, ५१, -को दाखिल करवानेका खर्च सेठोंकी
भारी, ११३, -पर होनेवाले कष्टसे सारे भारतीय
समाजको सहानुभूति, ११३

गीत, -लिखवानेके लिए पुरस्कारकी योजना, ४७

गीता, देखिए भगवद्गीता

गुजराती, २६९

गुप्ते, डी० के०, १४४

गुल १४

गुलाबभाई १७२, ३६५

गुलामहुसैन मियाँ खों ऐड कम्पनी १२१

गुलिस्ताँ ४३, -और शेख सादी ४

गंड्टी नाटकधर १४६, २४६

गैरीबाल्डी ज्युवैपी २७ पा० टि०

गोकुल अमरशी, १७२ ४४५ पा० टि०, ४७०

गोकुलदास, ३८

गोखले प्रो० गोपाल कृष्ण, २४९ २५३ २५७ २६१,

-का समुद्री तार २४३, -को गांधीजीका पत्र,

३५७, ३७५, -को तार २३७

गोपाल ४३१, ४३९

गोपाल, काना ४२६

गोपाल, रणछोड़ ४२६

गोबर नाफ १२८

गोरा, इस्माइल, १४४

गोरे, -एशियाइयोंको केवल अपनी गथा मजबूती करवानेके
लिए रखनेकी तैयार, ३९९, -की लड़ाई निशानी
लगानेके विरुद्ध, १४६, -की शरारत १००, -पर
मुकदमा ४१, गोरो -का शिष्टमण्डल ३९२, -की
भारतीयोंकी सीख ९१, -में खलबली ३७०

गोरा यापारी स्व, -जोहानिसवर्गका ४४२

गोरी ब्रिटिश प्रजा, -को स्वतंत्रता देनेका अर्थ एशियाई
ब्रिटिश भारतीय प्रजापर पाबन्दियों, २००

गोरे व्यापारी -के साथ गांधाजोकी बातचीत, ९९

गोविन्द -को मारनेके सम्बन्धमें दयालजी प्रागजी देसाईपर
मुकदमा, ३४७

गोविंद, नाथु ४२६

गोविंद वल्लभ, ४२६

आहम ३५८ -द्वारा सरकारकी ओरसे पैरवी ३५७

ग्रिफिथ पेढ़ी -के ऐजेंटोंकी मारफत उत्तर, १११

ग्रेगरावस्की, ४३०

ग्रेडी ओ० २४१

ग्लासगो हेरल्ड, २७७

घ

घेला नानजी ४४१

घोष रासबिहारी, ३३२

घोषणा, १८५८, १२५

च

चर्चस्टीट, ७९ ४३५

चर्चिल, -का उत्तर, १३८, -का खुनी कानूनके सम्बन्धमें
उत्तर १७६, -का श्री रॉबर्टको जवाब १५५, -की
नये कानूनके बारेमें घोषणा, ५८

चार्ल्स टाउन १४७, ३८६

चिंदे, -से सहायता, ३१५

चित्राल -की चढ़ाई ३८४

चीनी -की मृत्युपर शोक समा ३९३, चीनियो, -का जोर, ९१, -की एकता ४५ २९७, -की लड़ाई, ५९, -की समा, ९१, ४७४, -की समा हर रविवारकी, ३४०, -से सम्बन्धित नौकरीका कानून [लेबर इम्पोज़िशन ऑर्डिनेस] २३

चीनी सव, ४५ पा० टि० ५९, २८७, ३६९-७० ४३९ ४४५ पा० टि०, ४६२, ४९४, -की समा २६९ ३९३, -में गांधीजीका भाषण, ४६८, -में भाषण ३९४-९५

चेनटांग ३४६

चैपमन २०७

चैमने १३, १६१ १७३ २२० २४५, २९२, २९९ ३१४, ३६६ ३८०, ३९३, ४०६, ४२८ ४३३ ४७३, -और एक बहादुर भारतीय, ३३, -का उत्तर २७०, -का प्रतिवेदन, ६३, -का बयान १२, -क तरीक, ३५४, -के पंजाबी नौकर द्वारा नया अनु मतिपत्र लेनेसे इनकार, ९७, -की गवाही ३५३, -की पंजीयकके रूपमें नियुक्ति ५६, -के हस्ताक्षरकी जल्दतर परवानिके लिए ४४, -द्वारा डेलगोआ बे जाने वाले भारतीयोंपर मुसीबतें डालनेकी व्यवस्था, ३८६

चैमने, फौटन २०८

चैमने मॉटफोर्ड, ३५२ पा० टि०

छ

छना परमु ४२६

छीता, खुशाल, ८२, ८९

छीनावाला, नारायणजी करसनजी देसाई, २८८

ज

जंगी कानून, ४२२

जमाल, अब्दुल करीम, ३८२, -पर मुकदमा, १३६, १४६, ३९६

जमीन सम्बन्धी कानून (पंजाब), -रद, ३६१

जरथुस्त्राके उपदेश, ४३

जरथुस्त्राना शिक्षण, ९९ पा० टि०

जमन आफ्रिका, ११४

जमन उपनिवेश-समिति, -की बैठक भारतीय व्यापारियोंके बारेमें, ११

जर्मन पूर्व आफ्रिका, -तक खूनी कानूनका असर २८, -में भारतीय ११

जमन पूर्व आफ्रिका लाइन, ३१३ ४२४

जर्मिस्टन, १० १०१, २१२ २४५ २५३ ३१२ ३२०, ३५०, ३५३ ३९०, ३७२, ४१२, ४४५, ४७०, -का हिंदू मन्दिर ४३४, -की नगरपालिकाकी समा, ४५६, -में धरनेदारोंकी बुझकी धमकीसे भारतीयोंका पंजीयन नहीं २६४, -में पंजीकृत न होनेके कारण भारतीय नौकरोंसे अलग, २१४, -में ब्रिटिश भारतीयोंकी महत्वपूर्ण सार्वजनिक समा १०२ ३५६ ३६५, -में भारतीयोंपर आक्रमण ४५६, -में हिंदू पुरोहित द्वारा उपद्रव, ३११

जामाशाह, १३७

जामे जमशेद १६०

जार, - द्वारा ड्यूमाकी स्थापना, १२८

जॉडन २९२ २९९, ४०८ पा० टि०, ४६२ ४५८, -का उपनिवेश छोड़ जानेके लिए भारतीयोंको नोटिस ३१५, -का गवाहसे प्रश्न, ४६१, -का गांधीजीको उत्तर ४६३, -की अदालतमें श्री मुहम्मद इशाकका मुकदमा ४३३, -की आपत्ति, ४५९, -की गांधीजीसे बहस, ४५८, -क फैसलेपर श्री कैनडलका लीडरमें पत्र ४७५

जीरस्ट २४५, ३२० ३३१, ३५०

जीवण, माधव ४२६

जुबर्ट, जनरल, -की लड़ते लड़ते मृत्यु, ४

जुमा, डी० एच०, १७२

जुम्मा इस्माइल, ८१, ४४५ पा० टि०, ४७०

जूटनिक (यूटन हेग), -क भारतीयोंसे सहायता ४४१

जूटपासबर्ग रिव्यू, -भारतीय समाजपर १६१

जूरी प्रणाली, -पर गांधीजी, १, -२

जूसब, हाजी कासिम, ८०, ४३९

जेमिसन डॉ० -का टान्सवालपर हमला, ३६, ७४

जेल, -के प्रस्तावसे सरकार सोचमें ४३

जैक्सन -का मुकदमा, ५८

जेल, सैयद मुस्ताफा अहमद, -का तुर्कीके महा वाणिज्यदूतको प्रार्थनापत्र, २६६

जोजेफ, २४७, २८८, -का प्रश्न, २८८

जोशी, प्रभाशकर, ८०

जोशी, मोहनलाल, ८०, -पंजीयन न करानेके कारण कार्यविरत ४३२

जोहानिसबर्ग —का गोरा यापारी सब ४४२, —के निवासियोंको चेतावनी ४५, —में कानूनके विरोधका निणय १७३, —में जगह जगह सभायें ४७४, —में त्रिमूर्तिको नियुक्ति, २४६ —में समा १०१
जोहानिसबर्ग नगरपालिका —को पत्र, १९९ २०९, —द्वारा नाइयोंके लिए नियम बनानेका प्रस्ताव ३४४-४५, —द्वारा भारतीयोंको पहले दर्जेकी बग्गीमें न बैठने देनेके नियम पास करनेकी सम्भावना २२६, —में हलचल २०८

झ

झटाम, हसनमियाँ कमरूद्दीन ४३९
झवेरी, अबुल करीम हाजी आदम —काग्रेसकी पूँजी बढ़ानेमें सहायक १२२
झवेरी उमर हाजी आमद, १५९, ३७१, —की माँगका अखबारे सौदागर द्वारा समर्थन १५९
झीणा भाई, ८०
झूठे अनुमति पत्र, —के कार्यालय बम्बई, जोहानिसबर्ग तथा डबैनमें २८०

ट

टाइम्स, ५०, २३० २४१, —में ट्रान्सवाल सरकारकी निंदा २३०
टाइम्स आफ इंडिया, २५७, —के सवाददाता द्वारा हेजाज रेलवेकी व्यवस्थापर आक्रमण ५०
टाइलर, १२३
टॉमसन १३
टॉल्स्टॉय, —सच्चे ईसाईपर ३७५
टी० टी० पी० विभाग ४५८
टैनेरी ३३२
टोगाट १३७
ट्रान्सवाल —का नया कानून, ३, —का नया प्रवासी विधेयक, ९३-९४, —की भारतीय आवादीमें ५० प्रतिशत द्वारा कानूनका विरोध करनेकी आशा ८२, —की लडाई १४३, —के ब्रिटिश भारतीय कानून परायण २१५, —के ब्रिटिश भारतीयोंका कर्तव्य ३०७, —के भारतीयोंका नेटाल्के भारतीयोंसे प्रश्न ७५, —के भारतीयोंकी क्रूर राष्ट्रपतिते तुलना, ११९, —के भारतीयोंसे हड़ रहनेकी अपील, १९३, —के भारतीय गम्भीर लडाईमें सलझ १९४, —में अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार, ९८, —में एशियाइयोंके लिए कानून ४१, —में दूकान बन्द

करनेके समयका कानून २९५, —में भारतीय समाजके सिर बहुत बड़ा काम ४०, —में भारतीयोंकी कसौटी ९७
ट्रांसवाल एशियाई कानून मशौधन अधिनियम ११६ १४९ १७७-७९ १८१ १८३ १८५ १८७ २३० २७४ २९०, ३३४ ३५१ पा० टि०, ३८३ ३९४ पा० टि०, ४०५ ४३४, —और कर्टिस ५७-५८, —प्रत्येक भारतीयकी हृष्टिमें दासताका चिह्न, ३६, —भारतीयोंके लिए सन्तापदायक १८४, —का विरोध क्यों ३९६-९७, —के विरुद्ध आन्दोलन, १४८, —के विरुद्ध भारतीय समाजकी तीव्र भावना ३२१ ३३६, —के विरोधके कारण, ३९७-९८, —में कुछ बातें स्वाभिमानी यवितके सहन करनेके अयोग्य ३०, —में साम्राज्यके लिए खतरेके बीज ४०५
ट्रांसवाल एशियाई पजीयन अधिनियम १४, १६ ३७ ६२ ६६ पा० टि०, २७ ७१ ८६-८८ ९२, १०३ १०७ ११०, ११४ पा० टि०, ११९ १२२ १२९ १३८, १४०, २०१ २०८ २११, २१३-१५ २२८ २३० २३९, २५८ २६३ २७१-२७२, २८९ पा० टि०, ३०१-२, ३१९-२० ३२४, ३२७, ३३३ ३४९, ३५४, ३६१ ३६३ ३८४-८५, ३९२-९३ ३९५, ४२१ ४४५ ४४९, ४५७, ४६५-६६ ४७५, —असह्य ३२३ ३५५ ३५९, ४०७ ४१९, पा० टि०, ४२२ ४४६, —एक जुलाईसे लागू ७५, —एशियाइयोंके लिए असह्य, ३३३, —एशियाइयोंको निकाल बाहर करनेका आरम्भमात्र ४११, —और १८८५के कानून ३ का तुलनात्मक निरीक्षण, १६-१८, —और उसके विनियम ४०३-४०५, —ट्रान्सवाल गजट' में प्रकाशित, ८२ —तुर्कीके मुसलमानोंके लिए अपमानजनक २६६, —देशकी रक्षाके लिए २८६, —धन जेल तथा निर्वासनकी जोखिम बिना रद नहीं १९६, —धर्मके विरुद्ध होनेके कारण असहनीय ३५२, —नासमझी भरा ३२७, —बुरा है, २८१, —लागू करनेकी तारीख ८० ८२, —लॉर्ड ऐल्फिंजकी माँगपर सदनमें पेश १०६, —लोकसभामें, १३८, —सम्बन्धी कठिनाईको हल करनेके लिए प्रस्ताव, १४९-५०, —का जर्मन पूर्व आफ्रिकातक असर २८, —का पालन करना नितान्त अपमानजनक १४२, —का प्रभाव २३-२५, —का सारांश १९-२३, —की कुछ ध्यान देने योग्य अतिरिक्त बातें, १८-१९, —की ताकत देखनेका समय, १२२, —की वाराओका

प्रभाव ७९-८०, -की धाराओका साराश ७५-७७, -की भर्तृनाके भाषण ३६०, -की भूलको सुधारनेका एक अवसर १९९, -के अतर्गत रामसु दर पण्डितको सत्ता, ३५६, -के कारण भारतीयोंकी नाजुक स्थिति, ३३२, -के खिलाफ जेलके प्रस्तावके रूपमें लड़ाई, ३, -के पीछे गोरे निवासियोंके लोकमतका बल १३९, -के बारेमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सवकी सलाह, २३६, -के बारेमें श्री जे० ए० नेसरके विचार २५२, -के मातहत पजीयन असम्भव २१५, -के विरोधके मुख्य कारण, २५०-५१, -के विरोधमें मुसलमानोंकी सभा, ३२८, -के सम्बन्धमें भारतीय सभ द्वारा सरगर्मीसे काम ३२३, -पर गलत वक्तव्य देनेका आरोप ब्रिटिश भारतीय सभपर, ३२२, -पर गांधीजी, ८३ ३९४-९५, -पर गांधीजीका भाषण, ३९४, -पर फ्रेंड में कड़ी टीका ३२५, -पर रैड डेली मैगज़ीनमें लेख १६३, -पर श्री डकन, २००, -पर सडे टाइम्सकी टीका ४१६, -पर सम्राटकी स्वीकृति ३५, -से गहरा आघात, ३५०, -से लन्दनमें हलचल, १७६, -से विलायतमें उत्तेजना, ६५, -से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार लॉर्ड ऐम्बेड्जिलकी मौनपर सदनमें पेश १०५

ट्रा सवाल एशियाई पजीयन अध्यादेश, ३६२ ४५९

ट्रा सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम ७०, ९०, १०२, १०५, १२५, १५७, १९१, १९८, २०१, २०४, २७७ ३१४ ३२३, ३३० ३४३, ३४८ ४०६-७, -४३३, ४४६, ४४७ पा० टि०, ३७८, ४६६, ४६९, ४७१ ४७३ -दोनों ससदोंमें पास १९७, -भारतीयोंके लिए अहितकर १८८, -सम्बन्धी घोषणापर गांधीजी, ४४४-४५, -का अर्थ, ९४, -का दूसरा वाचन, १०४ १०७, -का संशोधित मसविदा १४९, -की पहली धारा २७८, -के कुछ पदों गम्भीर रूपसे आपत्तिजनक, ९२, -के खिलाफ की गई अपील रद्दीकी टोकरीमें, ११५, -के बारेमें लॉर्ड एलगिनकी प्रार्थनापत्र, १९९-२०१, -के बिना देश निकाला मुमकिन नहीं, २९२, -के विनियम, ४७१, -के विषयमें निवेदन, १८३, -के सम्बन्धमें आपत्तियाँ, ९२-९३, -को मजूर करके लॉर्ड एलगिन द्वारा भारतीयोंकी राजभक्तिपर अनुचित भार ४४५, -में संशोधन, ४०५-६

टान्सवाल फुटबॉल सभ, २०१

टान्सवाल भारतीय सभ ४५८

ट्रा सवाल लीडर ९० २५३ २९९, ३३४ पा० टि०, ३३९ ३४५, ३८०, ४१५ ४८२ ४७५, -भारतीयों द्वारा की गई मारपाटपर २११, -का भारतीयोंकी प्रोत्साहन देनेवाला लेख ४४२-४४, -की भूल ३४४, -की सरकारकी पीछे हटने और न्याय करनेकी सलाह, ३४४, -को सलाह, ३८१, -के लेखका तात्पर्य ३४९, -को ईसप मियाँका सन्तपत्र, ३४७, -को पत्र, ३०२-४ ३२२-२३ ३४८-४९, ३७६, -को मेट, ३५१-५२, -द्वारा भारतीयोंकी सहायता, ३४२, -द्वारा सरकारकी चेतावनी, ३३९, -में गांधीजीके पत्रकी आलोचना १९५

टान्सवाल विधान परिषद्, -को प्रार्थनापत्र, ११५-१६

ट्रा सवाल विधानसभा, -को प्रार्थनापत्र, ९२-९३

ट्रा सवाल-सरकार -का ईसप मियाँको उत्तर ५६, -का धा अनैतिकता पूर्ण, ३२६, -के मुकदमा चलानेपर भारतीय जेलके लिए तैयार ६१, -को जेलके प्रस्तावसे चिंता, ४३

ट्राम, -का कानून १५५

ट्रिब्यून, ६६

ठ

ठाकर, अम्बाराम मगलजी, -का गीत, ४८, -की कवितापर पुरस्कार, ४७-४८, -को गांधीजीकी बधाई, ४८

ड

डकन, पैट्रिक १०७ पा० टि०, २००, -पजीयन अधि नियमपर १९९-२००, -की एशियाइयोंका एतराज दवा देनेकी सलाह १५३, -की प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें मान्यता, १०७

डडी, १३७

डक्सबरी, ४३०

डच पजीयन पत्र, -का प्रश्न, ५६

डच पजीयन पत्रवालो -का कर्तव्य, ९

डबैन, -के अनुमति कार्यालयका तीन तरहसे बहिष्कार करनेकी सम्भावना, ९८, -के स्वयंसेवकों द्वारा प्रिटोरियाक स्वयंसेवकोंकी बधाईके तार, १३७, -के हम्दर्त माइयोकी ओरसे ढेरके ढेर तार, ११९, -में अँगुलियोंकी छाप देनेके कारण आतक, २२२, -में गांधीजीका भाषण, २१०, -में गिने चुने भारतीयोंका

मत न देनेका निश्चय १२५ २६, -में सरकारकी
दगाबाजी, ४७३, -से आनेवालोंको चेतावनी, १३८
डर्बन इस्लामिया अजुमन ३६५
डर्बन मेमन समिति ३६५
डालनिंग स्ट्रीट -के हस्तक्षेपपर अन्तिम उपायके रूपमें
भारतीयोंका विश्वास ३२२
डॉवसन ४४२
डाह्या गोविन्द ४२६
डाह्या मणि ४२६
डिक -का आ दोलन हंगरीमें २१७
डिल्क सर चार्ल्स १९८, -के अनुसार बड़ी सरकारका
बीचमें आना आवश्यक २४१
डीसोजा २०८
डेलागोआ वे ११०-११ १३७, १९१ २११, २२८,
२७०, ३८०, -जानेवाले भारतीयोंपर श्री चैमन द्वारा
मुसीबतें डालनेकी व्यवस्था ३८६, -की सरकार द्वारा
एशियाईयोंके आब्रजनपर प्रतिबंध ४४७, -में दो
भारतीयोंकी दगाबाजी, ४७३, -में भारतीयोंकी दीन
स्थिति ४३१, -में भारतीयोंकी सुस्ती, ३८८, -में
भारतीयोंकी रोकनेके लिए बनाये गये कानून, ४५०

डेन्लीग्राफ, ४२८

डेली प्रेस, २१४

डेविड -द्वारा पजीयन करानेसे इनकार, १०२

डोमन, श्रीमती, २९०

डच्यूमा, -की जार द्वारा स्थापना, १२८

त

ताज बनाम भाभा, -का मुकदमा ३५५ ४२०

तार -अमीरुद्दीनको, ३८२, -उच्चायुक्तके नाम ३८१,

-उपनिवेश मंत्रीको, ३७३, -कासिम हाजीको, २४७,

-दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकी, ५९,

-ब्रिटिश भारतीय सभके नाम ३८०, -रायटरकी,

१४७

तालेवन्तसिंह, २२४

तीरा, -का युद्ध, ३८४

तुर्की -के महा वाणिज्य दूतको प्रार्थनापत्र, २६६

तुलसी, ४७०

तेजियर, -में टूटपाट १७०

तैयब, -को तार, १३

त्र्यम्बकलाल, ८१

थ

थार्न विल ४९

थॉर्न विल ज्वक्शन ४१ २१४ पा० टि०

थोरो हेनरी डेविड २१५ २२० २६९ २८५,

-अमरीकी सरकारपर २१५, -का प्रभाव २२१, -का

लेख, २२०-२२, २३१-३३, -पर गांधीजी ३०५

द

दक्षिण आफ्रिका — के ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टसे भारतीयों
की भावनाकी गहरी आघात, २५७, -के भारतीयोंकी
मुक्तिकी डोर टू सवालके भारतीयोंके हाथमें १२७,
-में भारतीयोंके दुखकी कथाका प्रकाशन ५४

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, ६९ पा० टि०,
३५१ पा० टि०

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति ७४, ११०-११,
१३४, १४७, १४९ १५६ १५८ १९२, १९८
पा० टि०, २०४, २११ २१३, २१८-२१९ २२८,
२३०, २३९, २६८, २७९, २९३ ३१८ ३५६
पा० टि०, ४४१, -का जनरल बोथाके नाम पत्र,
२५ १५५, -का नये कानूनके सम्बंधमें जोर,
६५, -का स्थानीय सरकारपर ब्रिटिश भारतीयोंको
गिरानेका आरोप, ६८, -का हर सदस्य लड़ाईमें
भारतीयोंके साथ, ३०७, -की अमूल्यनिधि १६१,
-की आवश्यकतापर गांधीजी २८८, -की कानूनके
खिलाफ लड़ाई २९, -की भूल २५ ५९, -के
सदस्योंको जेलका प्रस्ताव नापसन्द ४३, -की जीतका
श्रेय १७४, -को तार १८८, -द्वारा फिरसे कानून
सम्बंधी लड़ाई शुरू, १५५

दक्षिण आफ्रिकी प्रश्न ३३३

दण्डपाणि, आर० १३८

दरबारेशाही — और क्वाजानशाही, ३५

दरवेश साहब २९६

दाऊद, मुहम्मद, ११७

दाजी, गोविंद, ४२६

दाजी, हरि, ४२६

दादलानी के० एन०, १३८

दादाभाई, २९८, ४१५, -के पुत्रका देहान्त, ४३३

दावजी, ४३२

दासू ईसप, १३७

दीक्षित, ओ० पी०, २४४ पा० टि०

दीनदार, हाजी इब्राहीम अहमद, ३७१

दीवान, मोतीलाल, १४७ २४३

दीवान्नी महात्म्य, ३७१

देववर, श्रीमती काशीबाई २८

देशपाण्डे श्रीमती २८

देसाई ४७४

देसाई प०, १७२

देसाई एम० आई०, ४४५ पा० टि०

देसाई, खुरशेदजी, ४१४

देसाई, गुलाब रुद्र ८२, ८९

देसाई जे० के० १३८

देसाई दयालजी प्रागनी, -पर मुकदमा ३४७

देसाई, प्रागजी खड्डुभाई, ९६

देसाई बापू २०८

देसाई मणिमाई ४१४ ४३१

देसाई मणिलाल ३५८ पा० टि०, ४७०, -का पत्र ३९४

देसाई महादेव, २०५ पा० टि०

देसाई, मोरारजी, ८०

घ

घरनेदारो -का काम, २९८, -का मुकदमा ३७७, ३८०, -की आफत, २९९, -की ओरसे कदापि धमकी नहीं ३११, -के कारण भारतीय 'प्लेग' कार्यालय जानेमें असमर्थ ३४८, -के बारेमें पुलिस आयुक्तका पत्र ३१३, -के मुकदमेपर प्रिटोरिया न्यूजकी टीका ३८०, -के विरुद्ध मुकदमा ३५७-५८, -को आतङ्ककी कहानियाँ गढ़कर बदनाम करनेकी कोशिश, २९२, -को कुलियोंके धरनेदार की उपाधि, ३०१, -को बहादुरीके लिए वधाई, ३४०, -द्वारा पजीयन करनेवालोंके सामने कानूनके सही रूपपर प्रकाश, ३०३, -पर धमकीका इन्जाम बिलकुल झूठ, ३१४

घारशी, -की अर्जी नामजूर, २८३

धार्मिक भेदभाव, -के कारण अपमान, २७१

न

नडी, पडवर्ब, २२० पा० टि०

नडी, डोंक्टर, -की नये कानूनपर पुस्तक, २२०

नई धर्मपुस्तिका, (न्यूटेस्टामेंट), १२०

नगरपालिका, -के हाथमें काफिर भोजनगृहों तथा फेरी वालोंके परवाने, ४४०

नगरपालिका मताधिकार अधिनियम, २१९, -लॉड एलगिन द्वारा नामजूर २१२

नगरपालिका विधेयक १५८

नथू मनजी ८१

नया प्रवासी विधेयक, ६९ ९३-९४, -अत्यन्त भयकर, ९४

नये पजीयनपत्र -सम्बन्धी सूचना ७९

नवाबखौं २५४ २६९, २८८ ३६५, ३८५ ४०९, ४१४, ४४४ पा० टि०, ४७०, -का भाषण १०१, १३७, -का मुकदमा ४६१

नवाब दाख २५४ पा० टि०

नाइयो -की लपरवाहीसे बीमारियों ३४५, -के लिए जोहानियनवर्ग नगरपालिका द्वारा नियम बनानेका प्रस्ताव, ३४४-४५

नाइलस्टूम, २०७

नाकामूरा ४५७

नागरिक शासनका प्रतिरोध (रेजिस्टेस टू सिविल गवर्नमेंट) २१४ पा० टि०

नाजरथ १०८

नानजी, डॉ० १४४

नामजोशी, श्रीमती, २८

नायडू ३१, ८०, १०१, १९८, ३१८, ३२२, ४१४ ४३१, ४४५ ४५५, ४७२, -का भाषण, ८१

नायडू, आर० के० १३८

नायडू टी०, २८८

नायडू, डी० एन०, १३८

नायडू डब्ल्यू०, जे० आर०, १३८

नायडू यम्बी, १३८, ३६५ ३६६, ४३९, ४४४ पा० टि०, ४६२, ४७०

नायडू, पी० के०, १३८, ३४८, ४४४ पा० टि०, -पर मुकदमा ४६०

नारण, परसु ४२६

नारण भीखा, ४४१

नारुड, ९९ पा० टि०

नॉर्मल गर्ल्स स्कूल ६६

नारायणजी, ३६५

निधि, -की बच्चोंके भरण पोषणके लिए, १०

निर्वासन कानून, -के खिलाफ ब्रिटिश भारतीय संघकी अर्जी, १९७

नीछाभाई रणछोड़, ८०

नीति सुधारक मण्डल, -की एक बहनका पत्र, २४९

नूर, इब्राहीम, ८९

नूरुद्दीन १३७ २६८

नेटाल —का परवाना कानून २४२, —का परवाने और टिकटका विधेयक ११०, —के भारतीयोंकी गांधीजीकी जागृत रहनेकी सलाह, १४४, —के भारतीयोंसे टान्सवालके भारतीयोंका प्रश्न ७५, —के व्यापारियोंकी चेतावनी, १६८, —में गोरोंकी दो पक्षोंकी खीचातानी २६१, —में परवाना सम्बन्धी अर्जोंके विनियम, ४२७-२८, —में फेरीवालोंके परवानोंकी फीस बढ़ानेका प्रस्ताव, २५९

नेटाल कानून, —और टान्सवाल कानून ३२

नेटाल गवर्नमेंट रेल प्रणाली २५९

नेटाल परवाना अधिनियम २०१ ४२३-२४

नेटाल भारतीय कांग्रेस ४९, ७४, १३२, १४४ १५९ पा० टि०, १९१, २२२, ३६५ ३७३, —का दादाभाई नौरोजीकी शुभकामनाओंका तार २१०, —का प्रार्थनापत्र, ११७, —की सभामें गांधीजीका भाषण ११४-१५, —की सहानुभूति ८५, —द्वारा टान्सवालके लोगोंको आर्थिक सहायता, ९८

नेटाल मन्त्रिणी, १

नेटाल रेलवे, —के मुख्य प्रबंधकका पत्र, १०७

नेटाल विधान सभा —को प्रार्थनापत्र ११७

नेटाल सनातन धर्म —सभा ४७-४८

नेथन कुमारी २१६

नेथन, सर मैथ्यू —का नेटालके गवर्नरके रूपमें स्वागत, २१६

नेपोलियन ४९

नेशन, —की रायमें भारतकी हलचलका कारण दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंपर होनेवाले जुलूम २२९

नेसर जे० ए० १०२, —एशियाई अधिनियमपर, २५२, —का उत्तर, १७०-७१, —का क्लाइसर्वोंपमें भाषण, २५५, —के मतमें बिना मुकदमा चलाये निर्वासनका अधिकार देना खतरनाक १०७, —को पत्र २५२, २६२-६४

नैतिक समिति सच, २८१

नौरोजी दादाभाई, २१६, ३०६, —की जयन्ती, २०२, —की जयन्तीपर शुभ कामना, २१३, —की बीमारी, ३०९, —को शुभकामनाओंका तार, २१०

नौरोजी पास २२७

न्यूकैसिल ३८७ ४२८

न्यूक्लेयर, ३२० ३५०

न्यूयॉर्क ५५

प

पंजाब केसरी देखिए लाजपतराय लाल

पंजाब भूमि कानून, ३६३, —रद ३६१

पंजाबियों, —की याचिका, ४२८, —द्वारा लॉर्ड सेल्बोर्नके पास याचिका, ३९२-९३

पंजाबी पत्र, —पर मुकदमा, ६

पंजीयक —की श्री हेल्डका पत्र ३९१

पंजीयन —की अन्तिम तिथि ३१९, —की अर्जों न देनेपर मुकदमा १३०, —के लिए एक भी अर्जा नहीं, ११८, —के लिए चार भारतीयोंकी अर्जा ३४८

पंजीयन कार्यालय १६१, २३४, २५६ २९० २९१, २९९ ३२० ३४०, ३४२ ३५७-५८ ३६७, —महामारी स्वरूप ३४१, —का पीटर्सबर्गमें बहिष्कार १७२, —का बहिष्कार करना आसान २०७, —का भारतीय समान द्वारा बहिष्कार २४१ २५८ ३००, —की पंचिफस्टम और क्लाइसर्वोंपमें असफलता १९५, —की पूछ विशालसे विशालतर १६८, —की बैचैनी २४७, —के एक सुशी द्वारा जाली अनुमतिपत्र व्यवसाय, २७४, —के बेकार प्रयत्न, ३८२, —के स्वयंसेवकोंका कतव्य, २५३

पंजीयनपत्र, २९१-९२, —और अनुमतिपत्र साजट मैन्सफील्ड द्वारा प्रस्तुत, ४२०, —दिखाये बिना यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारतीय व्यापारियोंको उधार देना बन्द, ३३३, —न लेनेके कारण भारतीयोंकी घर पकड़, १२९, —न लेनेपर जबदस्ती निर्वासन २००, —लेनेकी अवधिमें अभिवृद्धि ३४०, —लेनेसे ६००० व्यक्तियोंके इनकार करनेकी सम्भावना ८३, —लेनेसे भारतीयोंकी हार, १३१, —सम्बन्धी कुछ हिदायते २२, —का मुकदमा, ३१, —की अर्जा देकर गनी इस्माइल और हासिम मुहम्मद कालाको पश्चात्ताप ३४६, —के बिना धोबी परवाना पानेमें समर्थ, ४५३, पंजीयनपत्रों —का खमीसाकी दूकानमें गुप्त तरीकेसे वितरण, ३६९, —के लिए अर्जियाँ देनेवाले चार भारतीय, ३२२, —के सम्बन्धमें गोरोंकी भारतीय व्यापारियोंको धमकी २९७, —को बदलवानेके लिए सरकार द्वारा भारतीयोंको विवश करना सम्भव, १६६

पंजीयन प्रमाणपत्र, देखिए पंजीयनपत्र

पटेल २५४, —स्टैडर्टनमें रेलवेमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरोंको काय विरत कर देनेपर, ४५५

पटेल, आदम मामूजी, ३८०

पेटेल ई० एन० १९५

पेटेल गुलाबभाइ, ८०

पेटेल दावजी २९६

पेटेल मणिभाइ चतुरभाइ ३८७

पेटेल मुहम्मद दावजी -क पजीयन सम्ब धी प्रश्न ९

पठान, -का जनरल एल्फि स्टनको उत्तर, ३४

पडियाची एस० पी० १३८

पण्डित रामसुंदर, १०२ १७४ ३१० ३६१ ३६६
३७२-७३, ३७६, ३८०-८२, ३९०, ३९५, ४१२
४१४, ६१७-१८ ४२१ ४३८, ४४४ पा० टि०,
४४५ पा० टि०, ४५६ ४७०, -का उपनिवेश
सचिवको पत्र, ४३४-३५, -का जीवन, ३६३ -का
जेलसे भारतीयोंको सदेश ४१५, -का जोशीला
भाषण १०१, २६९, -का डेली मेलके नाम पत्र,
२६४-६५ -का मुकदमा, २९६ ३५१-५२, ३६५,
३७९, ३९६, -की देश-सेवा, ३७७, -की रायमें
अधिनियमके सम्ब धमें सच्ची बातें अपने देशवासियोंके
सामने रखना उनका वार्षिक कर्तव्य, ३५६, -के
जेल जानेपर कइ जगह समाएँ, ३८७ -के जेलसे
छूटनेपर गांधीजा, ४३९, -के मुकदमेकी जाँच, ३७२,
-के मुकदमे सम्ब धी तथ्य ३५९, -के सम्ब धमें
ट्रान्सवाल लीडरकी सूचना ३५१ पा० टि०, -को
अधिनियमके अन्तर्गत सजा, ३५६, -को श्री स्मट्सका
जवाब ४५५, -पर बधाईके तारोंकी वर्षा ३६५

पत्र -चाऊ क्वाईका चीनी सभके नाम, ३६९, -शाहजी
साहबका अखबारोंको, ३८१, -श्री विनका अखवा
रोके नाम, ३६९, -श्रीमती भीकाई रुस्तमजी क०
आर० कामाका, १६०, -श्री रुस्तजी पारसीका १२०
२१, -स्टेडर्टनकी भारतीय समितिका, ४४३

परवाना, -सम्ब धी अर्जकि विनियम ४२७-२८, परवाने,
-काफिर भोजनगृहों और फेरीवालोंको, ४४०,
-खानवाले क्षेत्रमें, ३८८, -का मुकदमा वीरा दुर्लभपर,
३१७, -के बिना व्यापार करनेवालेका माल नीलाम,
३२, -के लिए श्री चैमनेके हस्ताक्षरोंकी जरूरत ४८,
-परवानों, -के बारेमें भारतीयोंको लिखित सूचना, ३१३

परवाना-अधिकारी, २४

परवाना-कार्यालय, -का बहिष्कार, ११८

परवाना निकाय, -का निर्णय परिस्थितिके मुताबिक अयाय

पूर्ण नहीं, २४२

परिवहन-उपनिषय, -का सशोधन, ४०८

परीक्षात्मक मुकदमा, १९२, २०७ २८८, ४३०

पलशिन डीमिट्रिअस १२९

पाँचा ढाढा ४२६

पाइन स्ट्रीट ३७२

पॉचेक्स्ट्रूम १०१, १५१, १६१ १६८, ३२०, ३३०

३३१, ३४७, ३५०, ३६३, ४१४, ४४१, ४५६,

-और क्लार्क्सडॉर्पका निर्णय, १७३, -और क्लार्क्स

डॉर्पपर धावा १७२, -और क्लार्क्सडॉर्पमें पजीयन

कार्यालयको असफलता, १९५, -क भारतीयोंको तार,

१६२, -से तार, ९०

पॉचेक्स्ट्रूम यापार मण्डल, -द्वारा श्री कटिसके प्रति आभार
प्रकाशन, ५७

पारसी समिति, ३६५

पारेख मुहम्मद मूसा, ४२८, -का यूकैसिलसे पत्र ३८७

पाल माल गज्जट, २४१, २१८

पाश्चात्य प्रजा, -का राक्षसी उपायसे सन्तान निरोध, ४५३

पिल्ले ३१, ८२ ३६५, ४३१ ४३९, ४७२

पिल्ले, प० एस०, ८०

पिल्ले, रामस्वामी चोकलिंग, ४२६,

पिल्ले, सी० एम० ४८८ पा० टि०, -का मुकदमा, ४६१

पीट रिटोफ ३२०, ३५०, ३६३, -में श्री लेवी २४५

पीटर्स, वेंयनी, २९७, -क साथ पुलिस अधिकारीका

दुर्व्यवहार, २७६, -पर मुकदमा, २९४, २९६

पीटर्सबग, १००, १४३, १५४, १६१, १६८, २३७, २४७,

२७६, ३१४, ३२०, ३२८, ३३१, ३३४, ३४६

४७, ३५०, ३८०, ४४५ पा० टि०, ४५६, ४७०,

-और जूटपांसबर्गके भारतीयों द्वारा पजीकृत होनेसे

इन्कार, १७३, -का तार, १७२, -का मुख्य धरनेदार,

हासिम मुहम्मद ३१६, -की बहादुरी १६७, -की

बहादुरीकी प्रशंसा, १७२, -के भारतीयोंको तार, १६२,

-के सम्ब धमें सूचना, १५३, -पर बला, १४५

पुनसामी, -पर मुकदमा, ११

पुरस्कार, -की शत, गीत रचनेपर, ५

पुरानी धर्म पुस्तिका, (ओल्ड टेस्टामेंट), ११९

पुलिस आयुक्त, -का पत्र धरनेदारोंके बारेमें ३१३, -की

सूचना, ४५, -को पत्र, २९०-९१

पूनिया, -और सुलेमान मगाके मामले, २७६-७७; -का

मामला, २४८, -की गिरफ्तारी, ४२१

पूर्वका ज्ञान, ४२

पूर्व भारत सव, ४२२

पैकहर्स्ट, एमलिन ६५ पा० टि०

पेयर्सन, २९७

पेमा, काला ४२६

पेररा, डॉ० एम० ए०, ४५८

पेपनफस, एच० एफ० डी०, ४४४ पा० टि०, ४४५

पा० टि०

पोरबन्दर, ११४

पोर्ट एलिजाबेथ ५६ ४४१

पोर्ट एलिजाबेथ सब ४७३

पोल्क, एस० एल०, १०, ८५ ६१, १०१ १३७, १७५

१९८ २०७ २२३ २६५-६७ ३९३ ४१४ ४३५,

४५७, -का भाषण १०२, -का लम्बा पत्र, २३४,

-के नामका मुद्राव गांधीजीकी अनुपस्थितिमें काम

करनेके लिए, ७२, -के हस्ताक्षरसे रेलवे अधिकारोंकी

पत्र, १३८, -को चीनी सबका स्थानापन्न अध्यक्ष

नियुक्त करनेका प्रस्ताव ४७४

पोल्क डेविड -द्वारा गांधीजीकी श्री हॉस्कनका सदेश ४०५

प्रताप राणा ४९

प्रदर्शनी समिति, ३२

प्रधानमन्त्री, -के सचिवको पत्र, १४-१५, ३७, २५०-५१

प्रवासी अध्यादेश, २००

प्रवासी यास निकाय १०९

प्रवामी विधेयक, -के उद्देश्यपर १०२

प्रस्ताव -एशियाई पजीयन सम्बन्धी कठिनाई हल करनेके

लिए, १४९-५०, -जेल सम्बन्धी, ४३, -प्रिटोरियाकी

सार्वजनिक सभामें, १४२, -भारतीयोंकी सावजनिक

सभामें, ३५६, ३७३, -श्री हाजी हबीबका १३३,

-स्टैगरके भारतीयोंका, ३८७, -स्वेच्छया पजीयनका ३७

प्रह्लाद १२३

प्राग, गोविन्द ८९, ३५७

प्रिटोरिया, १३-१४, ३१, ३८ ४५, ४७, ६० पा० टि०,

६१ पा० टि०, ६८, ७१ ७९ ८२ ८५ ८९-९०,

९५ ९७-८ १०२ १२१ १३४, १३९, १४३,

१४८ १५१ १५६, १६०, १७९, २०८, २३७

३२०, ३३०-३१ ३३४ ३४७ ३५० ३५८,

३६३ ३६५ ३९१ ४१४-१६ ४२५, ४३१-२

४३५, ४३९ ४४५ पा० टि०, ४५० ४५६,

४७०, -की घटना, १३५, -की टेक १००, -की

मस्जिदमें सिपाही ४४२, -की लड़ाई, ११८-१९,

-की सभा, १३३, ३७२, -के कुछ लोगोका जनरल

स्मट्सको पत्र, १६६, -के गद्दार १६९, -के

धरनेदारोका मुकदमा ३८०, -के प्रमुख भारतीयोंके

नाम तार १३७, -के बहादुर स्वयंसेवक, ९८ २६०, -के

भारतीयोंमें जोश ६९, -के लिए अवसर, ८४, -के

सवाददाता द्वारा भारतीय समाजको श्रेय प्रदान ८८,

-को गांधीजीकी हार्दिक बधाई १४४, -को रियायत

१४५, -में एक हिंदू द्वारा एक भारतीयपर

मारपीट २२५, -में कासिम पजीवृत, २५६, -में

की गृह ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा, १४२

-में गांधीजीका भाषण १३९-४१, -में गुप्त रूपसे

कायरोसे प्रार्थनापत्र उपलब्ध ३३७, -में गोरी

महिलाओं द्वारा भारतीय फेरीवालोके खिलाफ

आन्दोलन करनेका प्रस्ताव २६९-७७, -में मारपीट,

३९३, -में शेरगुल ३७०, -में श्री हाजी हबीबको

विदाई भोज ४३८, -में स्वयंसेवको द्वारा स्वदेशा

भिमान व्यक्त, १०१, -से प्रार्थना १२९

प्रिटोरिया न्यूज, -१४६ २९८, -की धरनेदारोके

मुकदमेपर टीका ३८०, -की रामसुंदर पण्डितके

मुकदमेपर टीका ३७९

प्रिटोरिया समिति, -का रायपरको लम्बा तार १४७, -को

तार १५१

प्रीवी कौंसिल १९२

प्रेडि -द्वारा नगरपालिकाके प्रस्तावका विरोध, ४५६

प्लेग कार्यालय, ३२८

फ

फकीर जसमत, ४२६

फजन्दार अमीरखीन मुहम्मद हुसैन १९८ २०७ ३५७,

३७१, ३७५ ३७८, ३८८, ३९९, ४४२, -को

गफूरका तार, ३८२, -को ३५ पौंड भेजनेका

फैसला ४१९

फरामजी, अर्देशर, ८९

फर्ग्युसन कॉलेज २७

फाउल, कप्तान हैमिल्टन २९२ ३१४ ४०६

फातिमा १२३ पा० टि०

फाफर्टन, ३८०

फारब्यू ४५५

फाल्क ४४२

फिट्जपैट्रिक, सर पर्सी ४१७

फिफील्ड, आर्थर सी०, ३०५

फिलिप्स, ३७९

फीनिस्, ३८ पा० टि०

फीरोजपुर, २५३

फेरार सर जॉज ६२, —का जनरल बोधासे प्रश्न, ५४,

—द्वारा एशियाई पजीयन अधिनियमका समर्थन, ७१

फेरीवालो, —तथा काफिर भोजनगृहोंके परवाने नगरपालिकाके

हाथमें ४४०, —का कानून ३३, ४५, —की फीस

वढ़ानेका प्रस्ताव नेटालकी विधानसभामें, २५९,

—के लिए कानून, ९०, —पर आक्रमण ५७, —पर

बौक्सबर्गमें मुकदमा २८८

फैन्सी एम० पी० १०१ १६३ १८० १९८ २४३

२४९, ३१८ ३७० ३७२, ४३९

फोक्सरस्ट ८४, १३८ २०८ २२३ २७६ ३२० ३४०

४१९ पा० टि०, ४७०, —की ओरसे कलकतियो

तथा मद्रासियोंपर पजीकृत हानिके लिए दवाव ४१७,

—के मुकदमे ४२३, —में सभा ६९, —से आनेवाले

भारतीयोंकी गांधीजीकी सलाह, ८४

फोर्तोन, जॉन, ४४५ पा० टि०, ४७०, —का बयान, ४६३

फ्यूज मेजर ३८२

फ्रीडवॉर्प ८५, —के भारतीयोंकी चार सालकी छूट, १७४,

—के व्यापारी, ५३-५४

फ्रीडवॉर्प अ यादेश, १३८ १७४, —कुछ गोरोको नापसन्द,

५४

फ्रच, जनरल ७३

फ्रेंजर स्टाफिन १०१, —को शरारत, १००

फ्रेनीखन (वेरीनिगिंग) १५१, ३२०, ३५०, ३६

फलीट स्टीट ३०५

ब

बगाली, २५४

बहारिया, २०८

बस्तावर —की बहादुरी, १७६

बग्गी, —के नियम

बद्री, २७३, २९०

बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, २५७, २६१, —का तार, २५३, २५४,

—को तार २५६

बनुतखॉ, ४४२, —का मुकदमा, ३९३

बम्बई, ९५, १५९, १९२, २५७

बम्बई गज़ट, २४४ पा० टि०

बर्क, २९

बर्गसटॉर्प २डिपेंडेंट स्कूल ४६१

बजस ३२९, —को एशियाई कार्यालयसे जुड़ी ४४२

बर्न्स सी०, —को गांधीजीका बवाइका तार १४८

बर्डवुड सर जॉज ३०७

बलेर, १३७

बहादुर जोसफ, २६५

बहादुर भारतीय —का किस्सा, ३३

बॉक्षवाला, नरोत्तम अमथाभाइ पटेल २८८

बॉक्सवग ४४, २४५, ३२०, ३५०, ४४०, —में फेरा

वालोपर मुकदमा, २८८

बाजार, —में छुआछूत ५६

बाटरबाल, ३५०

बारकर ४४२

बाबटन, ३००, ३५०

बालफर, ३००, ३००

बावजीर रमाम अब्दुल कात्रि मलीम ३१, ५०, ८०,

१३७ १४४, १७४ १८०, १९८, २४३, २४९,

२५३, २६९ २८८ २९६, ३१० ३३१, ३४०,

३६५-६६, ३७१, ३८६, ४१४, ४३१, —का

भाषण ८१ १०१, —का सर विलियम वेडरबर्नकी

पत्र २२३-२४

बिबाम, देखिए ब्रिटिश भारतीय मद्य

बीबा, हुमैन ८५

बीबी राबिया ४२

बीयर विषेयक ३२५, —और काफिरों मध्य धा कानून

बापस ३२४

बुवर, एस० ३१०

बुद्ध, १२३

बुद्ध शिक्षा, ४२ ४३, ९५ पा० टि०

बुलसर, विलियम, ११०, १३८, —द्वारा भारतीयोंपर

होनेवाले जुल्मोंका शिकायत, १११

बूथ विलियम, ८६ पा० टि०

बगुल्ला, १११

बेग, आर्दसर १३५, २९९, ४३१ ४४५ पा० टि०, ४७०,

४७४, —का आभार प्रदर्शन २६९, —का पत्र २५६,

२६९, २९८

बेग, चाउल, ८९

बेचुआनालैंड, ४२२ पा० टि०

बेनोनी, २४५, ३२०, ३५०

बेलफास्ट ३२०, ३५०, -के मजिस्ट्रेटको सरकारका पत्र,
२५४

बैसैट श्रीमती एनी, ९५ पा० टि०, २३४

बैंगले, २४५

बैथल २४५, ३२०, ३५०

बैनरमैन सर हेनरी कौन्सेल ७४ १४७ २९८-९० ४५६,

-का श्री रिचको उत्तर २१८

बोअर युद्ध ३६ २४८ पा० टि०, -में डचो और

अग्नेजोकी कुर्बानियाँ ४

बोया, जनरल ३, ४ १५ २९ ३१-३२ ४९ ७२

७४ ९७ १२४ १३९ पा० टि०, १४७ २५२

२५५, २५७ २९३ ३२७ ४४१, ४४५, -और

एशियाई कानून २५८-५९, -का अधिनियमोमें

सुधार करनेका वचन १०७, -का लॉर्ड एलगिनको

आश्वासन ३९, -का लॉर्ड ऐस्टहिलको आश्वासन

७१, -का ससदमें भाषण, ५१, -का सर जॉर्ज

फेराको उत्तर ५४, -की गलतफहमी, २५४, -की

वषाँठ, २६८, -के नाम दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश

भारतीय समितिका पत्र २५ १५५, -को लॉर्ड

मिलनरकी धमकी २९४, -को श्री ईसप मियाँका पत्र

५३, -द्वारा शिष्टमण्डलसे मिलनेसे इनकार ४३

बोस्ताँ, ४ पा० टि०

बोनरला २४१

ब्रिटलबैक २९९

ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कम्पनी ३१३

ब्रिटिश भारतीय -कानूनपरायण २१५, -ट्रान्सवाल

सरकारके मुकदमा चलानेपर जेल जानेको तैयार, ६१,

-बेरोजगार स्टैंडर्टन और हाइडेलबर्गमें, ४४८, -लडाईका

अन्त देखनेके लिए अधीर ४३७, -सदाके लिए केपमें

पराधीन, २८२, -को एशियाई पजीयन अधिनियमके

बारेमें सक्ती सलाह, २३६, -ब्रिटिश भारतीयो

-का जोर, ४३१, -का ट्रान्सवालमें कर्तव्य,

३०७, -का धर्म और प्रान्तके हिसाबसे वर्गीकरण

३२१, -का मुकदमा ४१९-२०, -का शिष्टमण्डल,

४६२, -का शिष्टमण्डल ब्रिटिश सरकारके पास जानेके

बावजूद कानून पास, २८७, -का स्वेच्छया पजीयनका

प्रस्ताव, २१०, -का स्वेच्छया पजीयन करानेका वचन,

६१, -का स्वेच्छया पजीयनपत्र बदलवानेके कारण

४२९, -की आम सभा ४१३, -की आम सभा हाजी

दबीके मकानपर ६८, -की गम्भीर घोषणा १६५,

-की गिरफ्तारी ९०, -की जर्मिस्टनमें महत्वपूर्ण

सार्वजनिक सभा, ३५६, -की ट्रान्सवालमें कसौटी

९७, -की धरपकड़ पजीयनपत्र न लेनेके कारण,

१२९, -की बर्खास्तगी २९२, -की राजभक्तिपर

लॉर्ड एलगिन द्वारा अनुचित दबाव ४४४-४५, -की

सार्वजनिक सभा, ४५४ ४७४, -की सार्वजनिक सभामें

४ प्रस्ताव, १४२, -की सार्वजनिक सभामें पारित

२ प्रस्ताव, ३७३, -की सुस्ता डेलगोआ बेमें, ३८८,

-के गुप्त प्रवेशके आरोपोकी जाँच २३८, -के

ट्रान्सवाल निवासका प्रश्न ६१, -के विरोधका मौलिक

कारण अनिवार्यताका सिद्धान्त, २७४, -के स्वत्वकी

सरकार द्वारा उपेक्षा १८६, -को अन्तिम उपायके रूपमें

डाउनिंग स्ट्रीटके हस्तक्षेपपर विश्वास ३२२-को कानूनका

विरोध करनेपर भी ट्रान्सवालमें बसनेका अधिकार ३२६,

-को गोरो द्वारा सीख ९१, -को जनरल स्मट्सकी

चेतावनी २८७, -को ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश

२३०, -को ट्रान्सवाल छोड़नेपर हर्जाना देनेका

सवाल ब्रिटिश लोकसभामें १९८, -को ट्रान्सवालमें

मताधिकार नहीं, १३९, -को नये पजीयनके लिए

अर्जी न देनेके कारण गिरफ्तार करनेकी सम्भावना

१३०, -को पहले दर्जेकी बर्षीमें न बैठने देनेके

नियम, २२६, -को श्री वाइबर्गकी धमकीकी जरा

भी परवाह नहीं १०८, -को श्री हॉस्केनकी अनुचित

सलाह १५२ -को सूचना, ३३२ ३७४, -द्वारा

लेडीस्मिथके तालुकेमें दूकाने बन्द, ३०८, -पर कुत्तेको

जहर देनेका आरोप निन्द्यतापूर्ण ३१२, -पर खतरनाक

होनेका आरोप लगाना अनुचित, ३१२, -पर गोरोका

कज १७३, -पर जर्मिस्टनमें आक्रमण, ४५६, -पर

हमला ४२५, -में थोड़े बहुत नामर्द, ३२६

ब्रिटिश भारतीय अधिनियम, १३४

ब्रिटिश भारतीय लीग २०६

ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको -गांधीजीकी सलाह, ९०,

-को यूरोपीय व्यापारियों द्वारा पजीयन प्रमाणपत्र

दिखाये बिना उधार देना बन्द ३३३

ब्रिटिश भारतीय सभ, ४७, ५४, ६२-६३ ९१, ९३,

१०३, ११५-१६ १२४ १३०, १३२ १३८ ३९

१४६, १५१, १६४, १७२ १७४-७५, १८८,

२०७-९ २१३-१४, २२४-२५, २३५-३८ २४६,

२४९-५० २५१, २५४-५५, २५८ २६२-६३

२७१ २७५ २८० २८५, २९१ ३०० ३०२

३११, ३१३ ३१९, ३२१, ३३३-३५ ३३७
 ३४० ३४८-४९ ३७३-७४ ३८९-९० ४०८,
 ४३६ ४४१, ४४३, ४४८-४९ ४७२-७३, -अना
 क्रामक प्रतिरोधके लिए मुसीबते झेलनेको तैयार,
 ३२१, -प्रवासी अधिनियमपर २००, -का आन्दोलन
 सच्चा ३८६, -का प्रार्थनापत्र, उपनिवेश सचिवको
 १०५, -का भोजनगृह सम्बन्धी नियमोपर सरकारका
 पत्र ३२९, -का शिष्टमण्डल १५, -का हिसाब
 ३८६, -की अर्जी, १०२, -की आर्थिक स्थिति, १०,
 -की एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमें सरगर्मा,
 ३२२, -की ओरसे जनरल बोधाको पत्र ५३, -की
 कानूनके खिलाफ अर्जी १९७, -की कार्य विरत
 किये गये मजदूरोंके लिए एक महीनेके वेतनकी माँग
 ४५३, -की बैठक ३१, १९८, २४३, ३१८,
 ३७०-७१, -की बैठकमें समितिको तार भेजनेका
 निर्णय, ५९, -की विजय ४३२, -की सभा, २८७,
 -की समिति १८४ १९९, २७४, ३२०, -की
 समितिके प्रवासी प्रतिबन्धक विषयकपर एतराजके
 कारण, ११३-८४, -के नाम श्री इब्राहीम हाजी
 सुलेमानका पत्र, ३१५, -के शिष्टमण्डलसे मिलना
 प्रधानमन्त्रीकी दृष्टिमें अनावश्यक, ३७, -को अधि
 नियमकी वैधता आरम्भसे ही अमान्य, ३३५, -द्वारा
 एशियाई भोजनालयके नियमोंके सम्बन्धमें अर्जी, ३८७,
 -द्वारा केपकी मसदको निवेदनपत्र २०१, -द्वारा
 प्रवासी प्रतिबन्धक विषयकके बारेमें लॉड एलगिनको
 प्रायनापत्र, १९९, -द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें
 प्रतिनिधि भेजनेका निर्णय उचित, ३७८, -द्वारा लेडा
 स्मिथके यापार सव्के विरुद्ध सरकारसे कार्यवाही
 करनेका दबाव, २०२, -द्वारा सवर्षमें १५०० पौंड
 खर्च, २११, -द्वारा सरकारको चुनौती, ३२२,
 -द्वारा स्वेच्छया पजीयनके बारेमें चर्चा ४३०, -पर
 ट्रान्सवाल लीडर द्वारा एशियाई पजीयन अधिनियमपर
 गलत वक्तव्य देनेका आरोप ३२२

ब्रिटिश भारतीय समाज -स्वेच्छया दस अंगुलियों
 लगानेको तैयार नहीं १९८, -का काफ़िरोकी
 बगावतके समय कर्तव्य, ४१२, -की ट्रान्सवाल
 सरकारके विरुद्ध लड़ाईकी तैयारी, ४६, -के लिए
 ईंग्लैंडकी स्त्रियोंकी बहादुरीका आदर्श, ४४९, -के सिर
 ट्रान्सवालमें बहुत बड़ा काम, ४०, -को प्रिटोरियाके
 संवाददाता द्वारा श्रेय प्रदान, ८८, -द्वारा पजीयन-

कार्यालयका बहिष्कार २१४, -पर आपत्ते २४२
 ब्रिटिश भारतीय समिति ८९, १६१, -को पत्र, २८९,
 -पर धमकी देनेका आरोप झूठा १३६
 ब्रिटिश भारतीय स्वयंसेवको -का प्रिटोरियामें जाश ९८,
 -द्वारा प्रिटोरियामें स्वयंसेवाभिमान व्यक्त, १०१
 ब्रिस्टोव, न्यायमूर्ति, ४२०
 ब्रूस सर चार्ल्स, २४१
 ब्लाइड कार्ल, -के निधनपर गांधीजी २७
 ब्लूमफ़ोर्टीन १९०, १९३, -में नाइबर्गका भाषण, २८२
 ब्लूमफ़ोर्टीन फ़्रेड, १९३, २३५ २४७ ३३९,
 -एशियाई पजीयन कानूनपर, ३२५, -की एशियाई
 कानूनपर कड़ी टीका, ३२५, -के अनुसार कानून
 नासमझीभरा और अवायपूर्ण, ३२५, -के सम्पादककी
 सरकारको सलाह ३२५, -द्वारा ब्रिटिश भारतीयोंको
 सहायता ३४२, -द्वारा भारतीयोंका समर्थन, १९०
 ब्लूमहाफ -में श्री हल २४५

भ

भगवद्गीता, ९५, ३७४
 भट ६९, -का पत्र, १४६, ३६५
 भवान नागर, ४२६
 भाणा छीनिया, -पर मुकदमा, २८९
 भाणा, दाजी, ४२६
 भाणा, प्रेमा ४२६
 भाभा -बनाम ताजका मुकदमा ४२०, -के मुकदमेका
 फैसला, ४२६
 भायात, -का मामला, २४०, २४२, -की अपील, २४२
 भारत, -के वाइसरायको पत्र ३७२-७, -में महामारी, ४५२
 भारतकी धार्मिक समस्या (रिलीजस प्रॉब्लेम ऑफ
 इंडिया), २३४ पा० टि०
 भारत-सेवकों, -का एक मण्डल स्थापित करनेके सम्बन्धमें
 लेख, १३, -का कर्तव्य, १३
 भारतीय धरनेदार, -पूर्णतया निर्दोष २९१
 भारतीय प्रवासी न्यास निकाय, ११३
 भारतीय बाजार, ५७
 भारतीय भोजनगृहो -के सम्बन्धमें नियम, ३२९
 भारतीय मुस्लिम लीग, -के अध्यक्षको पत्र, ३८५-६
 भारतीय राजाओं, -पर अमीर अब्दुर्रहमान, ७
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ६ पा० टि०, ४१, ३१०, ३३३,
 ३५७, ३७५, ३९९, ४१९, ४४२, -का वन्दना, ३६२,

३८८, -का सूरत अधिवेशन ४६९, -की ब्रिटिश
समिति ३२३, -की ल दन समितिको पत्र ३३१-३२,
-के अधिवेशनमें प्रतिनिधि भेजनेका निर्णय उचित
३७८, -के सूरत अधिवेशनके लिए प्रतिनिधि ३७१,
-को पत्र, ३३२-४
भारतीय विरोधी कानून निधि ४३९, -की सभा, ३१८
भारतीय वापारियो -का कर्तव्य ३३, -पर श्री स्मट्सका
आक्रमण २८१
भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय २४३
भावनगरी सर मचरजी मेरवानजी २५ ७० ११०
२७९ ३०६
भित्तिपत्र -परवाना कार्यालयक बहिष्कारका, ११८
भीखा, मोरार, ४२६
भीखा, हरि, ४२६
भीमकाय प्रार्थनापत्र -पर किये गये हस्ताक्षरोका विवरण,
३५०
भूला ८०
भोज ४९

म

मगा सुलेमान -और पुनियाके मामले, २७६
मसर मूसा इब्राहीम, २४८
मकनजी ८०, -का भाषण ८१
मकन रतनजी -का मुकदमा ४७४
मक्का १७४
मजदूर रक्षक कानून, ५२
मदी २०८
मणिभाई ३६५ ६६
मतदान -का सवाल, २६७
मद्रास, २८ पा० टि०, -में १०००० भारतीयोंकी सभा ६६
मद्रासियो -की सभा १३७ ३८, ३१०
मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवे (सी० एस० ए० आर०),
-का पत्र ७२ ७३, -के महाप्रबन्धककी गांधीजीका
पत्र, ४३६, ४४३
मनजी ४७४
मनिक, -का जनरल स्मट्ससे भारतीय व्यापारियोंको अलग
बस्तीमें खेदे देनेके लिए कानून बनानेका निवेदन, १९६
मनोर, कुंवरजी, ४२६
मलायी बस्ती -मम्बयी लेख स्टारमें प्रकाशित ४६
मलिक -और उलु परिषदे ३४
महमूदी ४९

महायायवादी -द्वारा भारतीयोंकी बड़ाई, ८८
महाराज केशवलाल, ३७१
महाराज रतनजी ४२६
मॉंटग्यू जायदाद ३८
माडले, -से लालाजीका पत्र ३६४
माडरफोटीन ३२० ३५०
माणिक डॉ० हीरा, १४४
माधव लाला, ४२६
मार्फेट स्वेयर, -में भारतीयोंको अधिकार न देनेके प्रस्तावपर
विचार ४५६
मोल्लै, ७२, ३०७
माल्टी फीता ३३२
मिटो लॉर्ड ७२ २५७
मिडेलबर्ग १५१ २३७ ३२०, ३३१ ३३४ ३४७
३५० ४५६, -के भारतीय, १३२
मिडेलबर्ग नगर परिषद्, -द्वारा भारतीयोंपर मुकदमा ५९
मिडेलबर्ग बस्ती, ५९
मियाँ ईसप इस्माइल ३१, ६६, पा० टि०, ८० ८२ १०४,
११६ १३० १३३, १३७ १४१ १८० १९८-९९,
२०९ २१४ २२६ २४३, २४६ २५५ २७०,
२९८ ३१८, ३२१ ३३० ३१ ३६५-६६ ३६९ ७०,
३७४ ४१३ ४३९ ४७१, ४७४, -कानूनसे उत्पन्न
होनेवाले मुद्दोंपर १९९, -निर्वासनपर २००, -का
अखबारोंको पत्र ३३४-३७, -का उपनिवेश मंत्रीको
आवेदन पत्र, १८२-८६, -का उपनिवेश सचिवको
पत्र ४७, १०५, २७४-७५, ४०८, -का जनरल
बोथाको पत्र, ५३, -का जनरल स्मट्सको उत्तर
२८०, -का जवाब १७३ २५४, -का नगरपालिकाके
नियमके खिलाफ पत्र, ४३२, -का पत्र ५३, -का
पत्र अत्यन्त समर्थित ३९, -का पत्र ट्रान्सवाल
लीडरको, ३०२-४, ३११-१२, -का प्रधान मंत्रीके
सचिवको पत्र, १४-१५ २५०-५१, -का प्रार्थनापत्र
११५-१६, -का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको पत्र,
३३२-३४, -का रैंड डेलीमेलको पत्र १६३-६४,
-का शोक २९८, -का श्री नेसरको उत्तर, २७१-७२,
-का श्री जे० ए० नेसरको पत्र, २५२, २६२-६४,
-का समितिमें भाषण २२६, -का सर विलियम
वेडरबर्नको पत्र, ३१९, -का स्टारको पत्र, ३५-३७,
-की श्री गिब्सनसे बातचीत, २५३, -के पत्रका
सारांश ३४९-५०, -को टान्सवाल सरकारका उत्तर,

५६, -द्वारा जनरल स्मट्सके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें
लीडर और स्टार्को सख्त पत्र ३४७, -द्वारा श्री
स्मट्सके भाषणका उत्तर, २८७
मियाँखौं आदमजी १२२, -की मृत्युपर गांधीजी, १२१,
-की मृत्युपर शोक, १२१
मियाँ, मूसा इस्माइल ४३२, -का, ट्रान्सवाल विधान
सभाको प्रार्थनापत्र ९२-९३
मियाँ, हसन, ३८८
मिराडा -को ट्रान्सवाल छोड़नेका हुक्म ३४७
मिलनर, लॉर्ड, १८१ २९३, -की जनरल बोधाको
धमकी २९४, -के समयमें भारतीय समाज द्वारा
स्वेच्छया अँगूठा लगाना स्वीकार, १९८, -द्वारा
भारतीय समाजको दिये गये वचन, ४१०
मिल्ल, -में स्वराज्यका आंदोलन, २६२
मीठा, अहमद ३८७
मीराबाई ५१
मुकदमा, -अनुमतिपत्रका, ३३, -अनुमतिपत्र अध्यादेशके
अन्तर्गत ४२५, -अब्दुल करीम जमालपर, १६६, -ईल्द
मुथुपर २९७, -इस्माइल ईसापर, २०८, एमटोगापर,
१, -जैयनी पीटसपर २९६, -करीम जमालपर
१४६, -गोरेपर, ४१, जैक्सनपर, ५८, -जोहानिसबर्गमें
४५८-६०, -ताज बनाम भाभाका, ३५५, -दयालजी
प्रागजी देसाइपर ३४७, -दुर्लभ वीरापर, ३१७,
-धरनेदारोका, ३७७, धरनेदारोके विरुद्ध ३५७-५८,
-धारशीपर, २८२, -नवाबखौंपर, -पजाबी पत्रपर, ६,
-पजीयनकी अर्जी न देनेपर, १३०, -पजीयनपत्रका,
३१, -पी० के० नायडूपर, ३९२, -पीटसपर, २९४,
-पुनसामीपर, ११, -प्रवासी कानूनके अन्तर्गत, २७७,
प्रिटोरियाके धरनेदारोपर, ३८०, -फेरीवालोपर नॉक्स
बर्गमें, २८८, -बनुतखौंपर ३९३, -भाणा छीनिया
पर २८९, -भाभापर, ४२६, -भायातपर, २४२,
-भारतीय हजूरिपर, ४५, -भारतीयोपर, ४१९
२०, मिलेबर्ग नगर परिषद् द्वारा भारतीयोपर, ५९,
-मुहम्मद इशाकपर, ४२६, ४०७, -मोहनदास
करमचन्द गांधीपर, ४५८, -रतनजी मकनपर, ४७४,
-राम मकनपर, ३३१, -रामसुन्दर पण्डितपर, ३५२,
३६५, ३७९, ३९६, -लालापर १२-१३, -लुटका ५
भारतीयोंपर, २७२, -शाहजी साहबपर, ३७०, -श्री
पी० के० नायडूपर, ४६०, -श्रीमती एम० हेन्रिकका
२ -श्री मुहम्मद इशाकका, ४३३, -समन्दरखौंपर

४६१, -मी० एम० पिल्लेपर, ४६१, -सुलेमान वाडी
पर, १७६, -स्वण कानूनके अन्तर्गत २७३,
-मुकदमे -फोक्सस्टेके ४२३
मुक्ति सेना ८६
मुत्त्यार, हाजी अब्दुल -का भाषण, १३७
मुत्त्यार, आमद -का वक्तव्य, ८२
मुथु, ईल्द, २६९ ३००, -का मुकदमा २९७
मुद्दी अनुमतिपत्र -देनेका उपनिवेश सचिवको अधिकार, २२
मुरगन, ३००
मुत्ला -पर हमला, ३०२, ३०३
मुसलमानो, -की सभा कानूनके विरोधमें ३२८, -की
सभा लन्दनमें, ३६२
मुहम्मद, ३१
मुहम्मद अयूबवेग १३३
मुहम्मद, बलीभाई, १३७
मुहम्मद, इब्राहीम, ९५
मुहम्मदखौं, ३४०, ३६६
मुहम्मद, गुलाम ८२ ८९, १०४ १३९, १९८ २०७,
-और अब्दुल गनीपर गांधीसे प्रिटोरिया जानेके
लिष्ट रोक २०७
मुहम्मद, तैयब एन०, १७२
मुहम्मद दाउद, ११४ पा० टि०, १४४, -की लड़कीका
विवाह ४५०, -को उनकी लड़कीके विवाहपर
गांधीजीकी बधाई, ४५०
मुहम्मद, पीन, १२६, १४४, ३७१-७२, ४२४
मुहम्मद पैगम्बर, ५४, ५५ पा० टि०, ९९ पा० टि०,
१२३, -और उनके दो अनुयायी, ४४६
मुहम्मद, मालिम, १९८, ३८८
मुहम्मद, मूसा, १३७
मुहम्मद, शहाबुद्दीन -द्वारा शाहजीके खिलाफ कोई
कार्रवाई न करनेका निश्चय, ३३१
मुहम्मद, शाह इस्माइल १३७
मुहम्मद हासिम, -पीट्सबर्गमें मुख्य धरनेदार, ३१६
मुहम्मद हुसैन जेड कम्पनी, १६३, ४००
मूबर, -का हेगर साहबको उत्तर १९३
मूनलाइट, ३१
मूनलाइट, पीटर, ८०
मूसा, कासिम, २४४
मूसाजी, अहमद, २४३, ३१८, ३६५-६ ३७०
मूसा, तैयब, १४४

मूसा, पैगम्बर, ९७ २५३
मज, ४१९ पा० टि०, ४०७ पा० टि०, -द्वारा बहस, ४२०
मेकाडोडोर्प ३२०, ३५०
मेतर, अहमद मूसा ३८७
मेथे डॉक्टर ३०१
मेफेकिंग, ४ १५ २६ २०६, २४७ ३३१ ३४६
मेमन, -और कोकणी कानूनकी लडाईमें पस्त हिम्मत २०३,
-मेमनो, -द्वारा कानूनके अतर्गत पजीयनकी दररवास्त,
३२१
मेरीको, ३५०
मेलर ३५८
मेहता, छबीलदास बी०, १४४
मेहता नरसिंह ९७ ३०७ पा० टि०, ४१५
मैकिंटायर, २२४, -१० अंगुलियोकी छापपर, ३८०
मैकेजी, कनेल, ४२२
मैक्लीन, सर हेनरी, १७०
मैजिनी, जोजफ, १४ पा० टि०, २७ १२३
मैथ्यूज, पस०, १३८
मैन्सफील्ड, साजेट ४१९ पा० टि०, -की गवाही
४२५-२६, -के सामने श्री पीटर्म पेश २७६, -द्वारा
अनुमतिपत्र और पजीयनपत्र प्रस्तुत, ४२०
मैरित्सबग, १४४
मैसडोर्प, २७८
मैसाचुसेट्स, २३१
मोगलिया, ४५५
मोमणियात, २४४
मोरक्को, -में उपद्रव, १७०
मोरार, मकन, ४२६
मोहसीन उल मुल्क नवाब, -की जन्नतनशीनीपर, ४२४

य

यजीद १२३
याचिका, गायकवाडको, ३८८
यातायात उपनियम, २०९
यॉर्कशायर पोस्ट, २४१
यूसुफ उमर ४२६

र

रतनजी, भीखा, ४२६
रतिलाल, ४१६
रदरफोर्ड, डॉ० ११०, २०५

रलियातबेन ३८ पा० टि०
रशीद, अब्दुल ८९
रशीद गुलाम मुहम्मद अब्दुल ४८०, ४४५ पा० टि०
रसूली -का मोरक्कोमें आतक १७०
रस्टेनबर्ग, २०७, ३२० ३५० ३८६, -का पत्र २०८,
-के भारतीय पजीयनके खिलाफ दृष्ट १९७
रहमतखॉ ४४५ पा० टि०, ४७०
रहमान अब्दुल २८८ ४१४
रहीमभाई २०८
राइक्राफ्ट -का पत्र १०९
गिरमिटिया भारतीयों -के मालिकोंके नाम पत्र ११३
राजभक्त महिलाओका सघ, (गिल्ड ऑफ लॉयल विमेन)
४६६
राजस्व कानून २२
राजस्व परवाने, -में कुछ सशोधन, ११२
रॉबर्ट, -को श्री चर्चिलका जवाब १५५
रॉबर्ट्स लॉर्ड, -का इकलौता बेटा युद्धमें मृत ४
रॉबिन्सन सी० पी० १०९, १९७, -का अपने भाषणमें
गिरमिट द्वारा भारतीयोंका आना बंद करनेका सुझाव,
४१, -की रायमें परवाना अधिकारियोंका भारतीय
प्रार्थियोंके साथ भेद करना अन्यायपूर्ण, १५
रावियाबी, ५१
रामचंद्र, श्री ६३, १२३
राममकन, -का मुकदमा ३३१
रामलगन, १३७
रामवल्लभ १९८
रामा, डाह्या, २४४
रामायण, ९५, ९६, ३७४-७५
रायटर १७० २१८, ३६०, ४६९, -को गावीजीकी
सेट, ४६९, -को तार १४७
रावण ६३
राष्ट्रीय दल २६२ पा० टि०
रॉस, २२४ पा० टि०, २३९ पा० टि०, -का पत्र,
१२७, १५८
रिच, एल० डब्ल्यू०, २५, ५० ५३, ७४, १११, ११६
पा० टि०, १७३ १८८ पा० टि०, १९१-९२
२२७ पा० टि०, २२८, २४१ २७९, २८८-८९,
२९५, ३०७, ३७२ ३८३ पा० टि०, ३८४ पा० टि०,
४३०, -द्वा सवालके कतव्यपर ४११, -का पत्र
लॉर्ड ऐम्प्टिलके नाम, ११०, -का पत्र टाइम्सके
नाम, २०३, -का प्रयास २००, -का लकापोस्टको
पत्र २३९-४०, -का लॉर्ड एलगिनके नाम पत्र

२१९, -का श्री अमीर अलीको पत्र, १२४, -की दक्षिण आफ्रिका भारतीयोंको अनाक्रमक प्रतिरोधपर दृढ़ रहनेकी सलाह २६, -का सेवापत्र ४१० ११, -के विषयमें दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके एक सदस्य २९३, -को जीतना श्रेय, १७४, -को सर हेनरी कैम्बेलका उत्तर, २१८

रिच, श्रीमता, ४४१

रिचड, ३, -की कहानी १००

रिपन लॉर्ड, -को १० हजार भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे एक अर्जी २४९

रिपन कॉलेज, २५४

रीज, जे० डी०, २६

रकनुदीन १४४

रस्तमजी, पारसी, १३७, १४४, १७५, -का पत्र, १२० २१, -की उदारता, १२० २१

रूज, २८४-८५ ३२० ३३४-३६ ३४९, -का भाषण, १३३, -को श्री ईसप मियाँका जोरदार पत्र २४६, -से श्री काछलियाकी बातचीत, ३४१

रूडीयूट ३१६, ३२० ३५० ३८८

रूमी जलालुद्दीन, ३४२, ९९ पा० टि०, ३३८

रूस, -की जेलें १२९

रूसी लोगो, -की दृढ़ता, १२९

रेड डेले मेल्, ७१, पा० टि०, ९०, १५३ १७३, १५१ २२० २६२, २५३, २८८, ३४५, ४३१, -की टोका, ८४ ८५, -की भारतीयोंको कानून स्वाकार करनेकी सलाह ८५, -के प्रतिनिधिकी गांधीजीसे भेट, ८३ १४, -को गांधीजीका पत्र ८६ ८७, -का गांधीजी द्वारा संक्षिप्त भेंट, १४३, -को पत्र, ६७-६८, १६३ ६४, १८२, २६४ ६५, २७६ ७७, -को भेंट, ६०, -में प्रकाशित भेंटका विवरण ८२ ८३

रोडेशिया ४१, १११, ११४ १२६

रोड्स, १२६

ल

लंका, १६८

लकाशायर डेन्की पोस्ट, २३९, -को श्री रिचका पत्र, २३९-४०

लक्ष्मीचन्द, ४१६

लखमीदासजी, रतनजी, ४४१

लछमन, ३५८, ३७०, ३७२, ३७७, ३८२

लछमन, फ्रैन् ३५७

लजारस, २४७

लताफ, अब्दुल, ३७१

लताफ, उरमान, ४१४

लाखा फकीर ४२६

लाखानी मनजी, ४१५

लाजपतराय लाला, ६, ३६४, -की रिहाई, ३६१, -के

भाषणोका साराश २६३-६४, -द्वारा पंजाबके भूमि कानूनके विरुद्ध युद्ध, ३६३

लालबहादुरसिंह, ३६६-६७

लाला -के बयान १२, -पर अनुमतिपत्र सम्बन्धी मुकदमा, १२-१३, -से वकीलके प्रश्न, १३

लाला बुधिया, ४२६

लाली, सर आर्थर, ५८

लाली स्नान, ५६

लिंगम, पस०, १३८

लिट्टे, १०२, ४२१, -का भाषण, ४३३

लिखतनबग्गे, ३२० ३५०, -में श्री ज्यूटा, २४५

लिटिल्टन २९३, -भारतीयोंके कष्टोपर, १९८, -द्वारा भारतीयोंके हकोंका समर्थन, २४१

लियोनार्ड, जे० डब्ल्यू० ४६८

लिमरपूल, १

लीडर, देखिए ट्रा सवाल लीडर

लीडनबग्गे, ४५६

लुईट्चार्ट, ३३१, ३४७ ४५६

लुट -का मुकदमा, पॉच भारतीयोंपर २७२

लेडीस्मिथ १३७ २१२, ४६२ २६७, -का व्यापार सव, २०१, -के परवाने २०४, -के भारतीय व्यापारियोंको गांधीजीकी दूकान बन्द न करनेकी सलाह, ३०८

लेनर्ड ३४३, ४३०, -पंजीयन कानूनपर ३३०, -का मत अनुमतिपत्रके सम्बन्धमें, ५६-५७, -की राय भारतीयोंके पक्षमें, ४७३, -के अनुसार सरकार अपजीकृत लोगोको जबरदस्ती निर्वासित करनेमें असमर्थ, ३३०

लेफ्टिनेंट गवर्नर, -का किसी भी व्यक्तिको देश छोड़नेके लिए आदेश देनेका अधिकार, ४०४

लेस, डेल, ४४१ ४४२

लैम्सडाउन, लॉर्ड, ६६, -की दृष्टिमें कानून अत्यन्त शर्मनाक, ३०, -की रायमें भारतीयोंके सारे समाजका अपमान करना खतरनाक, २८

लैब्रिस्टर २०४
लोकसभा, —में एशियाई कानून १३८
लोगन २७३
लोविटोवे —के मजदूरोकी हालत १११

व

वकील सव, ३३७
वदे मातरम, ६
वरनों १३ ४५८, —का बयान १२१३
वली, जुसब हाजी, १६१
वली मुहम्मद ८९
वल्लभ दयाल ४२६
वल्लभ, नाना ४२६
वसन भीमा ४२६
वाडरर सभाभवन, —में भारी सभा, २९३ ९४
वाइर्ग १०२ १०८, —का भाषण ट्मसफॉटीनमें २८२,
—के गैरजन्मेदारपूर्ण रोषभरे उद्गार १०७ ८
वॉकरस्टूम ९ २०८ ३२० ३५० ३८७
वॉगल श्रीमती, २७७
वाजा ३६५
वाड़ी सुलेमान, —पर मुकदमा १७६
वॉन ब्रैंडिस स्क्वेअर २८८ २९०, ३०१ ३१३ ३३८,
—में भारतीयोपर दिन दहाड़े धमकी देनेका आरोप २९२
वाशबैक १४६
वाशिंगटन, २३१, —में भारतीय मजदूरोकी पिटाई २३३
वाशिंगटन, जॉर्ज, १२३
विंटरडॉप ३५०
विंटरवॉटम फ्लोरेस, २४९ पा० टि०
विक्टोरिया इंडियन थियेटर ११४ पा० टि०
विक्रम, ४९
विद्रोता परवाना अधिनियम ३३७
विटबैक, ३५८
विटवाट्सरेड, ४०७
विनियम, —परवाना सम्बन्धी अर्जीक, ४२७-८
विनेन वॉन, —का पत्र ५२-५३
विलियस, डी ४ १४८, २०८ २९९ ४०७ पा० टि०
४१९ पा० टि०, ४२०
वीनेन, २४२
वीरा दुर्लभ —का मुकदमा ३१७-८
वीरास्वामी, एस०, १३८

बुलमरनस्टाड, —में श्री हॉग २४५
वेम्सी जे० एल० ४६८ पा० टि०
वेडर्सडॉप, ३२०
वेडरवन १२ २७२
वेडरवर्न, सर विलियम २३१, —को पत्र ३१९, ३२३ ४
वेरीनिंगिग देखिए फ्रेनिखन
वेस्ट अल्बर्ट एच० ९५
वेस्ट सर रेमड १९२, ४३०, ४६९ पा० टि०, —की
रायमें पजीयन कानून ब्रिटिश नीतिके विरुद्ध ३४३
वेस्ट सुपरिटेण्डेंट, ३५८
वेसेल्स यायमूर्ति ४३५
व्यक्रटाप्पन ३००
व्यग्य चित्र —क्रिटिकमें ४४१
व्यग्य चित्र —जनरल स्मट्सके बारेमें, ४५६, —सडे टाइम्स
और डेली मेरुमें ४३१, —सडे टाइम्समें, ४५६
व्यापार कानून, १८९७ ११२
व्यापार सव —द्वारा लेडीस्मिथके भारतीयोपर मुकदमा
चलानेकी सिफारिश २०४
व्यापारिक परवाने २१९, —के सम्बन्धमें विचार, ४५४
व्यापारिक परवानो —के बिना व्यापारी परेशान ४९
यास गौरीशकर, ३८ ८०-८१ ८९ १३५ ३५७
३६५, ३६७ ३७० ४३१, ४७०, ४४५ पा० टि०,
—का एक प्रभावशाली पत्र, २९७

व्हाइट, ४५६
व्हाइट, सर जॉन, ४६२
व्हाइट, साइड, १०२

श

शरफुद्दीन ३५७ ३७०
शरीअत, ४५०
शहाबुद्दीन मुहम्मद, १०१, १९८ २०७, ३३० ३७०
३७६ ३८१, —की श्री शाहजी द्वारा पिटाई ३३०
शांति रक्षा अध्यादेश, ६२ १०५-६ ११६ १४९
१८३-८४ १८७ २००, २९२ ३१५ ३५५ ३८४
४०१-३ ४०६ ४०७ पा० टि०, ४०८ पा० टि०,
४१९, ४२१, ४३३-३४, ४५९, ४६२ ४६४, —के
अन्तर्गत अनुमतिपत्र ४२०, —के अन्तर्गत निर्वाचन
२२७, २६४, —के अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयोको दिये
गये अनुमतिपत्रोकी सख्या, ३२१ —के अन्तर्गत
भारतीयोपर मुकदमे ४२०, —के कुछ खण्ड ४००-१,
—के प्रशासनके विरुद्ध सर्वोच्च यायालयका मत, ३५५

शाहजी साहब, २४४, २४९, ४१२, ४१४, —का मुकदमा
 ३१८, ३७०, —के खिलाफ शहाबुद्दीन मुहम्मद द्वारा
 कोई कार्रवाई न करनेका निश्चय ३३१, —द्वारा
 श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनकी पिटाई ३३०
 शाह, मुहम्मद —का ट्रा सवाल लीडरको पत्र ३७६
 शिक्षा, —का कानून ४६
 शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, ४६२
 शिष्टमण्डल —ईस्ट लन्दनके भारतीयोंका १२८, —गोरोंका,
 ३९२, ब्रिटिश भारतीय सवका १५ ३७, ४६२,
 —से भेट करना जनरल बोया द्वारा अस्वीकार, ४३
 शुभाशा अन्तरीप, १६
 शर्मन, पी० जे०, ४५८-५९, —की गवाहसे जिरह ४६१
 शेठ चुनीलाल ४७०
 शेल्त, यू० एम० १४४, २४३
 श्रम आयात अध्यादेश, ४०३, —के नये कानूनमें लिये
 गये खण्ड ४०४

स

‘सडे टाइम्स,’ २१९, २९०, ४३१, —का प्रश्न १३२,
 —की नये कानूनपर टीका ४१६, —में व्यंग्य चित्र ४५६
 सरक्षक समिति २८१
 सलग्न पत्र ३७३
 सटरडे रिव्यू, —द्वारा भारतीयोंकी श्रद्धा, २२८
 सनातन वेद धर्म समा २२३
 सन्धि पत्र, १९०५, ३५
 समझौता, ४४१, —समझौते —के बारेमें बातचीत, ४१८,
 —के लिए हलचल, ४१७
 समन्दरखोँ, ४२६, ४७०, —का मुकदमा, ४६१
 सयाजीराव, ३८८
 सर्वोच्च न्यायालय, १९४, —का मत शान्ति-रक्षा अध्यादेशके
 प्रशासनके विरुद्ध, ३५५, —के निर्णयके खिलाफ शाही
 न्याय परिषदमें अपीलकी माँग २१३, —के न्याया
 धीशकी जाँचके लिए नियुक्ति, ४०७, —द्वारा वीरा
 दुर्लभकी अपीलका फैसला, ३१६, —में दुर्लभ वीरा
 द्वारा की गई अपीलके कारण, ३१६
 सविनय अवज्ञाका धर्म (ऑन ड्यूटी ऑफ सिविल
 डिस् ओबिडिएन्स), २१४ पा० टि०
 साँझ वर्तमान, २४४ पा० टि०
 साझेदारी, १२८
 सादाजीवन, ३०५

सानी शेख —और गुलिस्ताँ, ४, ४३
 सामलदास, जगमोहनदास, १५९
 सामी के० के० १३८
 साख्जी, २५४ ३२९
 साले, उमरजी, ३१ ८० १३३, १९८ २२५ २४३,
 २६९, २८८, २९६, ३१० ३४०, ३६५ ४१४,
 —का भाषण, ८१
 सॉलोमन, —द्वारा पजीयनकी अवधि न बढ़ानेकी घोषणा ३४२
 साहब, शाहजी —का अखबारोंको पत्र, ३८१
 साहेबदीन, १३७
 सिकन्दर, ४९
 सिद्धू कासिम ८९
 सिनफेन’, २१७
 सिम्बमक १२८
 सीदत, दाउद मुहम्मद, ३८७
 सुखा, बाबा, ४२६
 सुधावा १२३
 सुमार, तार मुहम्मद २४३
 सुलेमान इब्राहीम हाजी, —का सबके नाम पत्र ३१५
 मुलेमान इस्माइल, २४४
 सुलेमान इस्माइल मियाँ पेंड कम्पनी ३५, १६४
 सुलेमान, कासिम, १७२
 सुलेमान, मूसा, ८९, —का भाषण, ८२
 सुल्तान, ४२१, ४२५
 सूचना, —टान्सवालेके भारतीयोंको ३७४
 सूज, इस्माइल मुलेमान, ४३१, ४४५ पा० टि०, ४७०
 ४७४, —द्वारा श्री हाजी इब्नीबके प्रस्तावका समर्थन,
 १३३
 सुरत, ३७१, ३७५
 सुरत हिन्दू सभ ३६५
 सुरती मसजिद, —की सभा, ४१३, —के सामने भारतीयोंकी
 सार्वजनिक सभा, ४५४
 सुरती, सुलेमान आमद, १३७
 सेंट जॉर्ज, १४८ पा० टि०
 सेंट माइकेल, १४८ पा० टि०
 सेंट हेलेना, ४६६
 सेठ, रस्तमजी, ३७१
 सेठ, वी० यू०, ४४५ पा० टि०
 सेल्बोर्न, लॉर्ड, १५५, २००, २२०, ३८२, ४१५, ४४६,
 —शान्ति रक्षा अध्यादेशके वापस लेनेपर, ६२, —का

पजाबियोंको जवाब, ४१८, -के उद्गार, १०६,
-को अर्जी पासपोट न मिलने पर, ४३२, -को
गांधीजीका पत्र ४३२, -को पजाबियों द्वारा याचिका,
३९२ ९३

सेवाग्राम, ९६ पा० टि०

मैयद हाफिज अब्दुल १०१

सैलिस्वरी लॉट ४

सोशियॉलॉजिस्ट, १६०

स्ट्रेंक स्टूम, -का हाइडेलबर्गमें भाषण, २५५

स्टार, ११ ३१ ३९ ४५ ५२, १५५ ३१४ पा० टि०,
३३१, ३३४ पा० टि०, ४१६, -का भारतीयोंको
ताना २३९, -की टीका १७३, -की टीकाके
जवाबमें गांधीजीका पत्र, १९७-९८, -की टीकापर
गांधीजी, ८५, -के नाम गांधीजीका पत्र, २९-३०,
६९-७०, ३१४-१५, -के सवाददाता द्वारा भारती
योंको धमकी ८८, -को किमसिंग्का पत्र, ५९, -को
कैलनबैकका पत्र ३०-३१, -को पत्र ३५-३७,
८८-८९, १७८-७९, १८१, २९१-९३, ३०१-२,
४६५-६७, -को श्री ईसप मियाँका पत्र ५३ ३४७,
-को हाजी हबीब द्वारा सूचना १००, -में गांधीजीका
पत्र, ९०, -में गांधीजीके पत्रकी आलोचना १९५,
-में भारतीयोंकी विश्वसनीयतापर लेख, २३४, -में
मलायी बस्तीके सम्बन्धमें एक लेख ४६

स्टीफन यायमूर्ति २

स्टैगर, -के भारतीयोंका प्रस्ताव ३८७

स्टैडटन २२३ २३७ ३२०, ३३४, ३४७, ३५०, ४३६,
४५६, -की स्वानीय भारतीय समितिका पत्र, ४४३,
-के रेल्वे भारतीय मन्दूरोपर भारी विपत्ति, ४५५,
-में रेल्वेमें काम करनेवाले भारतीय बेरोजगार
४४८

स्टैगमान १७६ २३९ पा० टि० ३२० ३३४-३६ ३४९
स्त्री शिक्षा -पर श्री यूसफ अली द्वारा पुस्तक, ५१

स्टेलोनेकेन, ३२० ३५०

स्मट्स, जनरल ४ १०२ १४७ १४९, १५३, १७४
१७७, १७८ पा० टि०, १८१ पा० टि०, १८२,
२०३-४ २१० २१८, २८५ २९२-९४ २९८
३००, ३१४-१५, ३२३-२५ ३२८, ३३० ३४३,
३४७, ३४९, ३७२ ३७९, ३९४-९५ ४३२,
४४५-४६, ४६७ ४७२, -अपने पत्रका असर
जाननेके लिए आकुल, १३३, -अब भी अडिग

४३७, -का इरादा १३३, -का उत्तर,
१०३ ४ २७३ १९५, -का दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश
भारतीय समितिको उत्तर, १५५, -का यान
भारतीयोंकी गम्भीर घोषणाकी ओर आकषित १६५,
-का प्रिटोरियामें भाषण २८०, -का श्री रामसुंदर
पण्डितको जवाब ४५५, -का समझौता करनेवालोंको
टका सा जवाब ४४१, -का हठ ११०, -की ओरसे
भारतीयोंको अन्तिम उत्तर ६३ ६४, -की कमजोरीपर
बहादुरी, ३२४, -की जोरदार चेतावनी १७७, -की
धमकी ३२२ ३४८ ४१७, -की नये कानूनपर
टीका २८६ ८७, -की भारतीयोंकी चेतावनी २८७,
-की भारतीयोंपर नया कानूनरूपी पिस्तौल ४२१, -की
रायमें यूरोपीय यापार बैठनेका एक कारण भारतीय
यापार २८६, -के उत्तरसे याद रखनेवालों बात
१९२, -के निजी सचिवको गांधीजीका पत्र १४८
४९, -के निजी सचिवको पत्र १६४ ६५, -के
बारेमें यग्य चित्र ४५६, -के मतानुसार सारी
अड़चने भारतीयोंकी भलाईके लिए २०७, -को
बरपोक भारतीयोंकी ओरसे एक पत्र, २२४, -की
पत्र, ३४९-५०, -को प्रिटोरियाके कुछ लोगोंका
पत्र १६६, -द्वारा गांधीजीके सुझाव अस्वीकृत,
१८९, -द्वारा गांधीजीको भेजे गये पत्रपर टिप्पणी,
१९१, -द्वारा टुच्चे पत्रका उत्तर २८४, -द्वारा
प्रवामी विवेक सदस्यमें सरसरी तौरपर पेश,
१०७, -में भारतीयोंको देशनिकाला देनेकी हिम्मत
नहीं, ३४१, -से लोगोंकी ९ माँगें १०३, -से
श्री मनिकका भारतीय व्यापारियोंको अलग बस्तीमें
खदेड़नेके लिए कानून बनानेका निवेदन १९६

स्मिथ, सर विलियम, -के पास पुनसामाजीका मुकदमा, ११
स्वयसेवको -का कर्तव्य २६०, -का मुकदमा, ३७८,
-के नाम, ८९

स्वण कानून, ३८८, -का मुकदमा २७३, -के अतगत
व्यापार परवाना नहीं, २७३

स्वामी एस० कुमार १३८

स्वोट २४५, ४४२

स्वेच्छया पजीयन, -और अधिनियमका अतर, १४१, -और
अनिवार्य पजीयन, २७१, -और अनिवार्य पजीयनकी
श्री रिच द्वारा तुलना, ४१०, -और कानूनके
अनुसार पजीयनमें अतर ४२९, -का अर्थ १६६,
-का प्रस्ताव ३७ ४०६, -से अपराधी होनेसे
बचाव २५२

ह

हसराम १७२

हजरत मुहम्मदका जीवन वृत्तान्त (लाइफ ऑफ द प्रोफिट) २०५

हजूरसिंह, ४३१

हजूरसिंह —पर मुकदमा ४५, हजूरियो, —की सभा १०१

हड़ताल —खान मजदूरीकी १०, —टान्सवालमें ३८०

हनुमान, १६८

हबीब अली, ४३९

हबीब हाजी, ३१, ८०, ८२ १३५ १४५, २९८-९९, ३१०, ३४० ३७३ ४१४ ४७४, —नये कानूनपर ८०, —का उपनिवेश सचिवकी पत्र, १३४, —का पत्र, १३६, —का प्रस्ताव, १३३, —का भाषण, ४७४, —का स्टारकी पत्र, ८८-८९, —के मकानपर ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभा ६८, —को प्रिटोरियामें भोज ४३८, —द्वारा पीटर्सबर्गके नेताओंको उत्साह प्रदान, ३ १४५, —द्वारा स्टारकी सूचना १००, —पर गांधीजी ४३८

ह शी भोजनालयों, —के नये नियम, ३२९

हमीदिया इस्लामिया अनुमन, ९९, १०१ १७९, १९०, २०७, २१२, २२३-२५, २५०, २६५, ३८६ ३०७ ३१३ ३२४ ३६०, ३८५, ३८८, —का अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी पत्र, ३९२, —का जनरल बोधाकी बधाईका तार २६८, —का तार, १७२, —का भारतीय मुसलमानोंके नाम पत्र, १९४, —की सभा २५३, २९६, ३१०, ३२९, ३४० ४३१, —की सभामें गांधीजीका भाषण, ९९, —के सभाभवनमें सभा २८७, ४१८, —द्वारा पीटर्सबर्गके भारतीयोंकी बधाईका तार, १६२, —नये कानूनके विरुद्ध, १७४, —में भारी सभा, १३७, ४७४, —में गांधीजीका भाषण, ३७२, ३८२, ४४४-४५, —में भाषण १६०

हरिश्चंद्र १२३

हल, १४७

हल्टेन, विलियम वॉन, —का भाषण, २५५, —को पत्र, २३५-३६

हमन, इमाम, १२३

हसन, उमर १३७

हसन, शहाबुद्दीन २०५, ३८८

हलीम, अहमद, २४४

हाँगकॉंग ४६२

हाइडेलबर्ग, १५१ २२३, ३२०, ३५०, ३८० ४५६, —में स्टाके स्ट्रमका भाषण, २५५, —में रेलवेमें काम करनेवाले भारतीय बरोजगार, ४४८, —में भारतीय मजदूरीका जबरदस्ती पजीयन, ४५३

हॉटोट ५०

हाफिजी, —का मामला, २१३

हार्डसवाटर ४५६

हार्विन, २९७

हासिम, —का मामला, ११४

हॉस्कन विलियम, ९२ पा० टि०, १०२-३, १४०-४१, १४७ १५१ ३४३, ३७२, ४७३, —भारतीयोंके जेल जानेपर, ११५, —का गांधीजीकी पत्र, ४०५, —का भाषण, १४७, —की भारतीयोंकी अध्यादेश मान लेनेकी सलाह, १३९, —की भारतीयोंकी अनुचित सलाह १५२, —द्वारा श्रीवाङ्मयके भाषणकी भर्त्सना, १०८

हिन्दू धर्म सभा, ३६५-६६

हिंदू मुसलमान, ६, —के बीच फूट और कड़ता, ४५२

हिल, ४११

हीरा, धना, ४२६

हुजुग गुलाम मुहम्मद, ४३९

हुसैन गुलाम, १२३, —का विवाह, ४५०

हुमैन, मुहम्मद, १२७

हुसैन, हजरत इमाम, ४१४

हेजाज रेलवे ५०

हेनरी, सग, २४१, —का अगुलियोंके निशानके प्रयोगके सम्बन्धमें कथन, १७

हेल्, ३१०, ३१२, ३३०, —का पजीयनका पत्र, ३९१, —द्वारा क्षमा याचना, ३९१, —द्वारा पजीयनकी अर्जी देकर अपना मुँह काला, २९६

हेकी इस्ट्यूशन, ४६३

हैगर १०९ २११, —का नया कदम, १७०, —का प्रस्ताव, २५९, —का मूरर साहबसे प्रश्न, १९३, —की भारतीय कुलियोंकी हटाकर गोरोंकी नियुक्त करनेकी सलाह, २६१

हैत्रिक, श्रीमती एम०, —का मुकदमा, २

हैमिल्टन, लार्ड जॉर्ज, ४

हैम्बन, जॉन ४, १२३

हैरी, ३००

हैरिस, १३